

संग्रह जायता दीवानी

अर्थात्

दीवानी अदालतोंकी कार्य-प्रणाली,
मसविदे तथा अन्य क़ानूनों सहित ।

Civil Court Practice

with

Model Pleadings and other Acts.

Z,7,11

5405

152 F7

Shukla, Chandrashekar

Pub.

Sangraha zablā
deevanees.

5405

[illegible]

2013

11/1/13
8/1/13

B नं. २१४

संग्रह जाबता दीवानी

ऐकटनं० ५ सन १९०८ ई०



प्रकाशक

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

संग्रह ज़ाबता दीवानी

ऐक्ट नं० ५ सन १९०८ ई०

अर्थात्

भारतीय दीवानी अदालतों की कार्यप्रणाली, व्यवहार,

एवं उपयोगी मसविदों, क़ानूनों तथा

सूचनाओं सहित

प्रकाशक

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

मुद्रित

क़ानून प्रेस, कानपुर

सन १९२७ ई०

प्रथम संस्तरण २०००]

[मूल्य ५) डा० ॥१]

Z, 7, 11
152 F7

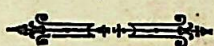
SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY.

Jangamwadi Math, VARANASI,

Acc. No. ~~2259~~.....

5405

प्राक्कथन



हिन्दी प्रेमी पाठकोंकी सेवामें विल्कुल नये ढंग और नये संकलनसे यह ज़ाबता दीवानी हिन्दीमें उपस्थित करता हूँ । ज़ाबता दीवानी अर्थात् (Civil Procedure Code) सिविल प्रोसीज़र कोडमें प्रायः प्रत्येक विषय भिन्न भिन्न स्थानों में कई रूपसे फैला हुआ है दफाओंका सम्बन्ध आर्डरोंसे या आर्डरोंका सम्बन्ध दफाओंसे बहुत कुछ अभिन्न है । वकील लोग कायदेसे पढ़ने और नित्यके प्रयोग करनेसे अभ्यसित होनेके कारण विषयको उसमेंसे ढूँढ निकालते हैं । हमारे हिन्दी प्रेमी भाइयोंके लिये यह कठिनही नहीं बल्कि दुस्तर और असाध्य कार्य है कि वे उस प्रकारसे क़ानूनका ज्ञान हर समय रख सकें । एक या दो बार ज़ाबता दीवानी पढ़ जानेसे न तो भली प्रकार विषयका ज्ञान होता है और न फैले हुए विषयका स्मरणही रह सकता है । हमने बड़े ही परिश्रमसे इस क़ानूनको ऐसे नये ढंग और नये संकलनसे बनाया कि प्रत्येक विषयका तत्सम्बन्धी ज्ञान पाठकों को एक ही जगह पर हो जाय । इधर उधर ढूँढना न पड़े और संक्षिप्तसे वे सब बातें जो उस विषयके लिये जानना आवश्यक हैं उसी जगह पर मालूम होजाया ।

ज़ाबता दीवानीका अर्थ है दीवानी अदालतोंकी कार्यवाही अर्थात् दीवानी अदालतोंकी कार्यप्रणालीकी विधि । जैसे ज़ाबता फौजदारी, फौजदारी अदालतों की कार्य प्रणालीका विधान है उसी प्रकार दीवानी अदालतोंके लिये ज़ाबता दीवानी भी है । दीवानी अदालतोंमें काम करनेके लिये इस क़ानूनका जानना बहुत ज़रूरी है । आपको इस ग्रन्थके पढ़ते ही यह बात मालूम हो जायगी कि आपके लिये यह क़ानून हर समय पास रखना कितना ज़रूरी और लाभदायक है । दीवानी अदालतोंमें काम आने वाले दूसरे क़ानून और नमूने आदि हजारों बातोंका विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है । हम अधिक इस विषयमें कहना नहीं चाहते क्योंकि आप इस क़ानूनकी प्रधानता जानते हैं । सूचीपत्रसे ही आप हमारे परिश्रमका अनुभव कर सकेंगे क़ानून पेशा भाइयोंके लिये इससे बड़ी सहायता मिलेगी हमें विश्वास है कि हमारे हिन्दी प्रेमी भाई इसके द्वारा लाभ उठाकर हमारे परिश्रमको सफल करेंगे ।

ता० १ मार्च सन १९२७ ई०

निवेदक

चन्द्रशेखर शुक्ल

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

संग्रह जाबता दीवानी

ऐक्ट नं०५ सन् १९०८ ई०

विषयानुक्रमणिका

विषय	पेज
मवकिल और वकीलके कर्तव्य	
उद्देश्य ऐसे जाबता दीवानीके बनानेका	३
नोटबुक मवकिलोंको किस वास्ते बनाना चाहिये	३
—नोटबुक या चौपत्तियामें मामलेकी बातोंको कैसे लिखना	३
—कोरे कागज़की क्रिफायत करना मवकिलके लिये क्यों बुरा है	४
समयके अनुसार मामलेकी बातोंका विवरण	५
—मुकद्दमेकी बातोंका खाता तैयार करनेकी विधि	५
विषय और समयके अनुसार विवरण	६
वकील को समझाना और नकलें	६
अदालत का खर्चा—खर्चा ठीक या ठीक समय में न देने के परिणाम	६
मुद्दर्रि का कर्तव्य	७
वकील की कार्य प्रणाली और कर्तव्य	७
—सुवूतके कागजातोंकी तकमील	८
प्लीडिङ्स अर्थात् मसविदा	
मसविदा तैयार करना	९
—नये वकीलोंके लिये सूचनाएं	९
—चीफ जस्टिस 'मियर्स' की राय	१०
—मसविदा कैसा होना चाहिये	११
—प्लीडिङ्सका अर्थ	११
—मुद्दई और मुद्दाभलेहके अधिकारोंको काममें लाना	१२
दस्तखत और तस्दीक	१३

विषय	पेज
—कौन शख्स दस्तखत कर सकता है और कैसे करना चाहिये	१३
—तस्दीकका नमूना	१४
—दस्तखत करनेसे अर्जीदावा नाजायज़ नहीं हों जाता	१४
—ग़लत तस्दीक करने पर क्या करना चाहिये	१४
प्लीडिंगसूका सशोधन और उसका नष्ट कर दिया जाना	१५
—अदालतके अधिकार	१५

वकालतनामा

वकीलकी नियुक्ति कैसीकी जायगी	१६
वकालतनामा कैसे मंजूर किया जा सकता है	१७
तस्दीक का नमूना	१७
—वकालतनामों पर स्टाम्प	१८
—वकीलको चिट्ठी लिखकर अधिकारका पैदा होना	१८
—वकीलका नाम न होना या अधूरा नाम होना	१८
—वकालतनामा कैसे मंसूख किया जायगा	१९
—वकीलको अपीलमें अधिकार न होनेका परिणाम	१९
वकालतनामाके सम्बन्धमें जिम्मेदारी	१९
वकालतनामा मंजूर कर लेनेमें जिम्मेदारी	२०
मुकद्दमेमें वकीलके अधिकारोंकी हद्द	२१
—वकालतनामा दाखिल होने के बाद मंजूरी	२१
—रुपया उठानेकी शर्त	२१

फरीकैन और दावाकी बिनाय मुखासमत

फरीकैन और बिनाय मुखासमत दावाका शामिल किया जाना	२१
कौन लोग मुद्दई बनाये जा सकते हैं	२२
—जब नालिश किसी ग़लत मुद्दईके नामसे दायर हो जाय	२३
शामिल न किया जाना या बेजा शामिल किया जाना	२३
कौन लोग मुद्दाभलेह बनाये जा सकते हैं	२४
कौन कौनसी बिनाय मुखासमत एक ही मुकद्दमेमें शामिल करदी जा सकती हैं	२४
बिनाय मुखासमतके बेजा शामिल किये जानेकी हालतमें काररवाई	२५

अर्जीदावा

अर्जीदावाका मजमून और उसमें क्या होना चाहिये	२६
जब मुद्दई प्रतिनिधिकी हैसियतसे दावा करे	२७

विषय	पेज
अर्जीदावेमें क्या क्या बातें होनी चाहिये	२७
—दावाकी मियाद खतम होने पर दावा करनेमें क्या दिखलाना चाहिये	२७
—धोखा देनेके सम्बन्धमें क्या लिखना चाहिये	२८
अर्जीदावाकी भाषाके सम्बन्धमें	२९
अर्जीदावा वगैरह किस कागजमें लिखना चाहिये	३०
—दस्तखत करना कैसे चाहिये सिर्फ कुछ हरफ बनाना ठीक नहीं है	३०
—जेलखानेमें जो शख्स हो उसके दस्तखतका ज़ाबता	३१
तस्दीकका तरीका और उसका फार्म	३२
अर्जीदावा पर स्टाम लगाना	३२
उन दस्तावेज़ोंका पेश करना और शामिल मिसिल करना जिसके आधार पर मुद्दईका दावा है	३४

भाग २.

—८०:०:००—

नालिशका दायर करना

अर्जीदावाका पेश करना	३७
अर्जीदावामें पेश करनेका अधिकार	३७
नालिश वहीं दायरकी जायगी जहाँ जायदाद मुतवाजा चाक़े हो	३८
—सकूनतका वर्णन और विनाय मुख़ासमतका अर्थ	३९
अधिकार क्षेत्रके सम्बन्धमें, अधिकार	४०
प्लीडिंगसका निकाल देना और उसका संशोधन	४०
संशोधन और संशोधनकी किस्में	४०
—संशोधनसे मियाद पर असर न पड़ना	४१
हुक्म मिलनेके बाद संशोधन करनेका परिणाम	४१
अर्जीदावाका ख़ारिज किया जाना	४२
अर्जीदावाकी वापिसी	४२

अर्जीदावा मंजूर कर लिये जानेके बादकी कार्रवाई समनकी तामीली

अर्जीदावाकी रजिस्ट्री	४३
मुद्दाअज़ेदके नाम समन जारी करना	४४

विषय	पेज
तलबाना दाखिल करना	४५
समनकी तामीली	४६
हुकमनामाके फार्मको दाखिल करना	४६
—हुकमनामोंकी भाषा क्या होनी चाहिये	४६
तामीलका तरीका समन और हुकमनामोंके सम्बन्धमें	४७
दूसरे जिलोंमें समनकी तामीली	५०
दूसरी हाइकोर्टोंमें समन तामील करनेका तरीका	५१

समन तामील होजानेके बादकी कार्रवाई

जब मुद्दईके खर्चा न देने पर समनकी तामील न हो सकी हो	५३
—तलबाना आदि दाखिल करनेकी भियाद	५४
जब सिर्फ मुद्दई ही गैर हाजिर हो	५
जब सिर्फ मुद्दाभलेह ही गैर हाजिर हो	५६
बढ़ाई हुई पेशीकी तारीखको फरीकैनका हाजिर न होना	५८
जब मुद्दई या मुद्दाभलेह असालतन हाजिर होनेको हुकम होने पर हाजिर न हो	६०
एकतर्फा डिकरीका मंसूख किया जाना	६०
अपील एकतर्फा डिकरीके हुकमके मंसूख होनेकी	६१
कौनसी अदालत डिकरी मंसूख कर सकती है	६२
एकतर्फा डिकरी मंसूख करनेका परिणाम	६२
साधारण नालिशके जरिये डिकरीका मंसूख करना	६२

समनकी तामील होजाने और हाजिर होजानेके बादकी कार्रवाई

बयान तहरीरी और मुजराई	६३
बयान तहरीरीका लिखना	६४
मुजराई का मांगना बयान तहरीरी में	६५
अदालतका फरीकैनके बयान लेना	६६
उमूर तनकीह तलबका फैसल करना और खतम करना पहली पेशी पर	६७
तनकीहोंका तैयार करना	६७
पहले, कःतूनकी तनकीहें तयकी जागी चाहिये	६९
तनकीहोंका संशोधन करने और खारिज कर देनेके सम्बन्धमें अदालतका अधिकार	६९

उमूर तनक्रीहतलब का फैसला होजानेके बादकी कार्रवाई

तनकीहोंके होजाने पर फरीकैतका कर्तव्य	६९
बंद सवालोंके जरिये जांच करना	७०
सवालोंनेका मसविदा करनेके सम्बन्धमें नियम	७१
सवालातके जवाब	७१
कागजातकी खोज	७२
कागज़का पेश किया जाना	७२

गवाहोंका तलब किया जाना, और उनकी हाजिरी तथा पेशीका बढ़ाया जाना

गवाहोंका तलब करना	८२
—समनमें क्या क्या लिखा जाना जरूरी है	८३
समनकी खिलाफ वर्जि	८४
—जान वृद्ध कर समनकी तामील न होने देना	८४
—पेशीकी तारीखोंका बढ़ाया जाना	८५
—तारीख बढ़ानेकी काफी वजह क्या है	८५
मुकद्दमेंकी पेशी और गवाहोंके बयान लिये जाना	८६
मुकद्दमेंका आरंभ और शहादतका पेश किया जाना	८६
गवाहोंके बयान लिये जाना	८९
गवाहोंके पेश किये जाने और बयान लिये जानेका हुक्म	८९
अदालतसे बाहर चले जानेकी आज्ञा	९०
हलफ और इकबाल	९०
गवाहोंकी हाजिरीका रखना	९०
कागज़ी शहादत	९१
—फर्मीशनकी शहादतका माना जाना	९२

बहस और नजीरोंका पेश किया जाना

बहस करनेका तरीका और हिदायतें	९२
नजीरों या प्रमाणोंका पेश किया जाना	९६
—नजीरका हवाला देते समय उसकी बहसका पढ़ना	९७
—कैसी नजीरें पेश न करना चाहिये	९७
—जो फैसला रिपोर्टमें छपा न हो उसकी नकल पेश करना	९७
—अच्छे और खराब वकीलका फरक देखो नोट	९८

फैसला - डिकरियां - खर्चा

फैसला लिखनेकी विधि	९८
डिकरी क्या है और उसके बनानेकी विधि	९९
रेहनुकी डिकरी	१००
—हिस्साब किताब, बटवारा, हकशिक, हिस्सा रसदी आदिकी डिकरी	१०१
डिकरियां तैयार करनेके सम्बन्धमें हाईकोर्टके नियम	१०१
घ.स.ल.ता.की डिकरीके बारेमें नियम	१०३
व्याज दिलवाने और उसके सम्बन्धमें नियम	१०४
खर्चा मुकदमा और व्याजके सम्बन्धमें नियम	१०४
मावजेके किस्मके खर्चे	१०४

डिकरियों और हुक्मोंकी इजरा

डिकरीके रुपयेकी अदायगी	१०६
—जब रुपया डिकरीका अदालतके बाहर दिया गया हो या घर पर तो कार्रवाई	१०६
—अगर रुपया दे दिया गया हो और अदालतमें तस्दीक न कराया गया हो तो वह रुपया मुजरा नहीं मिलेगा	१०६
डिकरीका रुपया अदा होने पर भी डिकरी जारी कराना	१०७
मियाद दरखवास्त देनेकी जब रुपया अदा कर दिया गया हो	१०८
रेहनुनामेकी डिकरी	११०
कई डिकरीदारोंमेंसे किसी एकको रुपयाका अदा किया जाना	११०
इजरा होने वाली डिकरियां	११०
इजराकी दरखवास्त कहाँ देना चाहिये	११०

इजराकी दरखवास्त

इजराकी दरखवास्तका फार्म और उसमें क्या लिखना चाहिये	१११
—अदालत, जबानी हुक्म गिरफ्तारीका कब दे सकती है	१११
नकद रुपयेकी डिकरीमें कुर्की	११२
गैर मजकूल जायदादकी कुर्की	११२
इजराकी दरखवास्त पाने पर कार्रवाई	११३
कौन सी अदालतें डिकरी इजरा कर सकती हैं और डिकरियोंकी मुंतकिली	११५
कूच विहार और बरौदाकी दीवानी और मालकी अदालतोंकी डिकरियों की ब्रिटिश इण्डियामें इजरा	११६
ब्रिटिश भारत की अदालतों में प्राप्त की हुई डिकरियों की देशी रियासतों की अदालतों में इजरा	११६

विषय	पेज
अंगरेजी अदालतोंमें प्राप्तकी हुई डिकरीकी फ्रांसीसी राज्यमें इजरा	११६
अदालत इजराके अख्तियारात	११६
इजराकी दरख्वास्त कौन दे सकता है	११७
—अगर डिकरीका इन्तकाल कर दिया गया हो	११७
डिकरीके मुन्तकिलअलेहकी ओरसे दरख्वास्त	११८
बेनामीदार किसे कहते हैं ?	११९
एक ही साथ इजराकी कई दरख्वास्तें	१२०
दूसरी अदालतके नाम हुक्म जारी करके इजरा	१२०
मुखालिफ डिकरियों और मुखालिफ दावोंकी इजरा	१२०
किसके विरुद्ध इजराकी दरख्वास्तें दी जा सकती हैं	१२०
—कानूनी प्रतिनिधि शब्दका अर्थ	१२१
इजराका हुक्म देनेके पहले नोटिस	१२२
नोटिस जारी करनेके बादकी कार्रवाई	१२३
इजरा की मुलतबी	१२३
इजराकी मियादकी मुद्दत	१२४
तदवीर मुआविन इजरा और इस शब्दका अर्थ	१२५
वे दरख्वास्तें 'तदवीर मुआविन इजरा' नहीं है	१२७
मदियून डिकरीके जिरमके खिलाफ इजरा	१२८
—वारण्ट तैयार करनेसे पहले गिरफ्तारीका हुक्म	१२८
—औरतोंकी गिरफ्तारी कब न की जायगी	१२८
—गिरफ्तार होकर आने पर अदालत दीवालियकी दरख्वास्त देनेको	१२८
कह सकती है	१२९
कैदमें बनाये रखनेकी मियाद	१२९
जायदादके खिलाफ इजरा	१२९
जायदाद काबिल कुर्की व नीलाम क्या है	१३०
जायदाद मनकूलाकी कुर्कीका तरीका	१३२
खेतीकी पैदावार-हिस्से-तनख्वाह-साझेकी जायदाद-दस्तावेज़ आदि	
की कुर्की	१३३
वासिलातकी डिकरीका नीलाम	१३४
२०) से कमकी चीजका नीलाम	१३४
जायदाद गैर मनकूलाकी कुर्कीका तरीका	१३४
ऐसी रियासतकी कुर्की जिसकी मालगुजारी माफ है	१३५
कुर्कीका बन्द होजाना	१३६
कुर्कीके बाद मुन्तकिली	१३६
फरीकौनकी ओरसे कुर्कीकी निस्वत उज्रदारी	१३७

विषय	पेज
जायदाद मकूलाकी निस्वन्न दावा	१३७
नीलाम आमका तरीका	१३९
—नीलाममें कौन लोग खरीद सकते हैं और कौन नहीं	१४१
कलकत्ता हाईकोर्टके बनाये हुए रूल नीलामके सम्बन्धमें	१४१
इलाहाबाद हाईकोर्टके बनाये हुए रूल नीलामके सम्बन्धमें	१४४
जायदाद मनकूलाके नीलामका मंसूख किया जाना	१४७
जायदाद गैरमनकूलाके नीलामका मंसूख किया जाना	१४७
रूल ८९ के अनुसार नीलामका मंसूख किया जाना	१४८
रूल ९० के अनुसार नीलामका मंसूख किया जाना	१५०
नीलाम मंसूखीकी दरख्वास्त कौन शरूब दे सकता है	१५१
आर्डर २१ रूल ९० का विस्तार	१५२
भारी वे कायदगी और भारी क्षति क्या है ?	१५३
किसी हकका छोड़ देना	१५४
नीलाम मंसूख करापानेकी मियाद	१५५
नीलाम मंसूखीके हुक्मकी अपील	१५६
नीलाम मंसूखीकी दरख्वास्त देनेके बाद समझौता-राजीनामा-नोटिस	१५६
नीलामके रुपयेकी वापिसी-सारटीफिकट	१५७
नीलामके सारटीफिकटमें लिखी जानेवाली बातें	१५७
नीलाममें वसूल हुई रकम हिस्सा रसदी बटवारा	१५८
—एक ही जायदाद जब कई अदालतोंमें कुर्क हो तो अधिकार	१५९
—हिस्से रसदी बटवारेकी अपील	१५९
खरीदारको कब्ज़ा देनेका तरीका	१६०
खरीदार द्वारा बेदखल किया जाना और असली मालिकको कब्ज़ा वापिस मिलना	१६१
नालिश वापिसी जायदाद	१६३
वापिसी जायदादकी दरख्वास्त कौन शरूब दे सकता है	१६४
वापिसी जायदादकी दरख्वास्त किसके विरुद्ध दी जा सकती है	१६५
प्रयोग और विस्तार वापिसी जायदादके सम्बन्धमें	१६५
वापिसी जायदादकी किस्म और मियाद	१६७
वापिसी जायदादकी नालिशमें कोर्टफोस	१६७
खास खास हालतोंकी नालिशें	
सरकार या सरकारी कर्मचारियोंकी ओरसे तथा उनके विरुद्धकी जानेवाली नालिशें, जब कि वे सरकारी कर्मचारियोंकी हैसियतमें हों	१६८
—नोटिस देनेकी आवश्यकता	१६८
—ऐसी नालिशोंमें सरकारी चकोलका मेमोरेण्डम	१६९

विदेशियोंकी ओरसे तथा विदेशी और देशी राजाओंकी ओरसे अथवा उनके विरुद्ध नालिशें	१६९
फौजी आदमियोंकी ओरसे या उनके विरुद्ध नालिशें	१७०
क्वापेरेशनकी ओरसे अथवा उनके विरुद्ध नालिशें	१७०
बिना रजिस्ट्री की हुई सभाओंकी ओरसे नालिशें	१७०
फर्मों और ऐसे लोगोंकी ओरसे जो अपने नामसे व्यापार न करते हों या उनके विरुद्ध नालिशें	१७०
टैस्टियों, मृतलेख प्रवर्तकों और प्रवन्धकोंकी ओरसे या उनके विरुद्ध नालिशें	१७०
नाबालिश या ऐसे लोगोंकी ओरसे या उनके विरुद्ध नालिशें जिनके दिमाग में दोष हो	१७०
—नाबालिशके बलीके सम्बन्धमें नियम	१७१
—नाबालिशके राजीनामाके सम्बन्धमें नियम	१७३
मुफलिसकी ओरसे नालिशें	१७३
—मुफलिसके सम्बन्धमें नियम	१७४
रेहननामोंके सम्बन्धमें नालिशें	१७५
—लादा रेहननामा और रेहननामोंका फरक	१७६
—रेहननामा बशर्त बयनामा	१७६
—रेहननामा दखली	१७७
—रेहन अंगरेजी	१७८
—रेहन गैर माभूली	१७८
—रेहननामेके फरीक मुकद्दमा कौन हैं ?	१७९
—बेनामीदारका हक नालिशका	१८१
—बयबातकी नालिशका ज़ाबता	१८१
रेहनके मामलेमें अदालतके बाहर रुपयेकी अदायगी	१८२
मुलहकी डिकरी	१८३
कतई डिकरीके लिये मियाद	१८३
रेहनमें जात ख़ाल पर डिकरी और गिरफ्तारी कब और कैसे होगी	१८३-१८४
रेहनके रुपयेका अदालतमें जमा किया जाना	१८४
नालिश और तस्फीया	१८५
दस्तावेज़ात काबिल बय व रेहन वगैरा के ऊपर की जानेवाली सरसरी कार्रवाई	१८६

प्रासंगिक कार्यवाही

किन हालातोंमें कमीशन अदालत जारी करेगी	१८७
गवाहोंके बयान लेने के लिये कमीशन	१८७
—परदानशीन औरलोंका बयान लेना	१८९

मुकामी तहकीकातके लिये कमीशन	१८९
हिसाब किताबकी जांच करनेके लिये जारी किया गया कमीशन	१९०
बटवारा करानेके लिये कमीशन	१९१
हलफनामे के द्वारा किसी बातके सुबूत मांगनेका अधिकार अदालतको	१९१
फरीकैनकी मृत्यु उनका व्याह और दिवालिया हो जाना	१९२
मुकद्दमोंका वापिस लिया जाना	१९३
राजीनामा मुकद्दमेंके दौरानमें	१९६
—घकीलका अधिकार राजीनामेमें	१९६
अदालतमें रुपयेकी अदायगी	१९७
खर्चके लिये जमानत मुद्दईसे	१९७

रेफरेन्स-नज़रसानी और निगरानी

अदालत अपनी तरफसे या फरीकैनकी दरख्वास्त पर हाईकोर्टको रेफरेन्स भेज सकती है	१९८
नज़रसानी कौन कर सकता है	१९९
—नज़रसानीकी तीन अवस्थाएं	२००
निगरानीमें हाईकोर्टके अधिकार	२०१

अपीलें और मुकद्दमेंकी वापिसी

प्रारम्भिक डिकरियोंकी अपीलें	२०१
—कई मुद्दई या मुद्दाभलेहोंमेंसे एक ही कुल डिकरी या हुक्मको मंसूख करा सकता है	२०२
दूसरी अपील, पहली डिकरीके विरुद्ध होगी	२०३
कौनसे हुक्मोंकी अपीलें हो सकती हैं	२०४

न्यूनता पूरक कार्रवाई

फैसलेसे पहले, गिरफ्तारी, कुर्की, हुक्म इम्तनाई और रिसीवर	२०६
फैसलेके क़व्ल कुर्की	२०७
हुक्म इम्तनाईका जारी करना, तामील आदि	२०८
मुआहिदेका तोड़ देना	२०८
रिसीवरकी नियुक्ति, अधिकार, प्रकार, एवं कार्रवाई	२११
रिसीवर पर दावा, इजाजत लेना आदि	२१२

हुक्म दर्मियानी और विविध विषय

दर्मियानी नीलाम	२१३
फौरन क़ब्जे का पा जाना	२१३
असालतन हाजिरीसे माफी	२१३

विषय	पृष्ठ
अदालतके अधिकार क्षेत्रके बाहर की जानेवाली कुर्की या मिरपत्तारी	२१४
हुक्म और नोटिस लिखित होंगे	२१५
सम्मन, जारी करनेवालेके खर्चसे वे तामील किये जायेंगे	२१५
तामीलका खर्च-पोस्टेज-समय बढ़ाया जाभा-कमी कोर्ट फीस-संशोधन	२१५
संशोधन में अदालतोंके अधिकार	२१६

भाग २

(ज़मीना और रूलस)



षष्ठई हाईकोर्टसके रूलस	२१७
—आर्डर ३ में मुख्तारनामेके द्वारा काम करनेकी इजाजत	२१७
—आर्डर ५ में डाकके द्वारा समन भेजेजानेका नियम	२१७
—आर्डर १६ में सरकारी कर्मचारियोंकी शहादतमें खर्च न देनेकी व्यवस्था	२१८
—आर्डर २१ में खेतीकी पैदावारकी कुर्कीके लिये कलकूर को इत्तला देना	२१८
—बोली बोलनेकी इजाजतमें रकमका कायम करना	२१९
—अपीलेट साइड में रजिस्ट्रारके अधिकार कोर्ट फीसके बारेमें	२१९
इलाहाबाद हाईकोर्टसके रूलस	२१९
—रेलवे या दूसरे सरकारी नौकरीके नाम समन जारी करनेका तरीका	२१९
—कानूनगो या पटवारीके नाम समन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटके द्वारा जाना	२२०
—अर्जीदावा या इन्तिदाई अर्जीके साथ रूवकारका ज़ाबता	२२०
—वकील पर कब सम्मन या हुक्मनामें तामील किये जायेंगे	२२१
—पता बदलनेका ज़ाबता	२२१
—जवाब दहीमें अपना पता लिखना रूल ११ देखो	२२१
—रूल १२ दस्तावेजोंका अनुवाद अदालती भाषामें	२२२
—रूल १३ अदालतमें साचित हो जानेपर कागज़ों पर निशानी डालना	२२२
—रूल २२ (१) सफर खर्च और दूसरे खर्च किस निखसे दिलाये जायेंगे	२२३
—(क) काश्तकार या मजदूरी पेशेको । २) रोज	२२३
—(ख) ऊंचे दर्जेके गवाहको । १) रोजसे २) रोज तक	२२३
—(ग) बहुत ऊंचे दर्जेके गवाहको या जो २००) मासिकसे ज़्यादा वेतन पाते हों तो ३) से ५) ६० रोज तक	२२३
—(२) अगर गवाह ज़्यादा रुपया चाहता है तो जो अदालत हुक्म दे	२२३
—डाकखानेके किसी व्यक्तिका खर्च ओहदे और दूसरे खर्चोंके ख़यालसे	२२३

विषय	पेज
—गवाहके रोके जानेपर जो खर्च पड़े वह अदालतके हुक्मसे दिया जायगा	२२३
—कानिस्टबिलोंके अलावा जिनका वेतन १०) से ज्यादा है और ५ मीलकी दूरीसे अधिक है उन्हें सर्टिफिकेट दिया जायगा	२२३
—हलफनामोंके दाखिल करनेका तरीका	२२४
—डिकरी और हुक्मका तरीका तैयार करनेका और ज़ाबता रूल २१ देखो	२२६
—आर्डर २१ रूल २५ में हुक्मकी तामील न कर सकनेकी असमर्थता	२२७
—रूल ५५ नीलामके अफसरके पास रसदी पानेवाली सब दरखवास्तें भेजे जानेके लिये ज़ाबता	२२८
—जायदाद गैरमनकूलाके नीलाममें अदालतकी कार्रवाई व दफ्तरका ज़ाबता-मौरूसी जायदाद आदिका वर्णन	२२९
—जायदादके नीलामके सम्बन्धमें कलकुरके कर्तव्य, दफ्तरकी कार्रवाई	२३०
—रूल ११५ बंदूक या हथियारोंका नीलाम और ज़ाबता	२३०
—रूल ११६ जानवरोंकी कुर्कीमें १५ दिन की खुराकका रुपया जमा करना	२३१
—रूल ११७ जानवरोंका उसी जगह छोड़ देनेका ज़ाबता जहां वे कुर्क किये गये हैं	२३१
—रूल ११८ कांजीहाउसमें जानवरोंका भेजना	२३१
—कांजीहाउसके सम्बन्धमें ज़ाबता जब कि जानवर वहां भेजे जाय	२३२
—रूल १२५ जब जानवर किसीके सिपुर्द किये गये हों तो उसे दो आनेसे तीन आना प्रति दिन दिलाया जासकता है	२३२
—रूल १२६ सहनाको कैसे रुपया अदा किया जायगा	२३३
—रूल १२७ अगर रुपया खर्चसे बचे तो वापिस कर दिया जायगा	२३३
—रूल १३० कुर्क की हुई जायदाद नीलामके स्थान तक पहुंचानेका खर्च डिकरीदार, भमीनको देगा	२३३
—रूल ९ सरकारी वकीलको सिर्फ चिट्ठी लगा देना होगी जब वह किसी सरकारी अफसरकी तरफसे जवाबदही कर रहा हो	२३४
—रूल ३ याददाश्त अपीलका खारिज कर दिया जाना	२३४
—आर्डर ४१ के अनुसार अपीलमें कौन कौन बातें होना चाहिये	२३५
—अपीलकी डिकरियोंकी अपीलें और उनका ज़ाबता तथा कार्रवाई	२३५
—रूल ३ एकतर्फा डिकरीके तैयार करनेका ज़ाबता	२३५
पटना हाईकोर्टके रूल्स	२३६-२३७

संग्रह जाबता दीवानी

ऐक्ट नं० ५ सन १९०८ ई०

पारिशिष्ट २

पंचायत

दफावार सूची

दफा	विषय	पेज
१	फरीकैन मुकद्दमा पंचायत में मामला भेज देने के लिये अदालत में दख्वास्त दे कर हुक्म ले सकते हैं	२४१
२	पंच अर्थात् सालिस की नियुक्ति	२४१
३	मामला पंचायत में पेश करने के लिये हुक्म	२४१
४	जब दो अथवा अधिक पंचों के सामने मामला पेश किया गया हो तो उनके मतों में होने वाले भेद के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के धारे में हुक्म	२४२
५	कुछ मामलों में पंच नियुक्त करने के सम्बन्ध में अदालत का अधिकार	२४२
६	पैरा ४ अथवा ५ के अनुसार नियुक्त किये गये पंच अथवा सरपंच के अधिकार	२४३
७	गवाहों के नाम सम्मन जारी करना और उनकी पाबन्दी का न किया जाना	२४३
८	पंचायत का फैसला देने के लिये समय का बैठाया जाना	२४३
९	पंचायत के बजाय सरपंच मामला कब तक कर सकता है	२४४
१०	फैसले पर हस्ताक्षर किये जाने और उसका अमल में दाखिल किया जाना	२४४
११	पंचों अथवा सरपंच द्वारा किसी मामले को बतौर खास मामले के पेश किया जाना	२४४
१२	फैसले में काट छांट करने अथवा उसके दुरुस्त करने का अधिकार	२४४
१३	पंचायत के खर्च के सम्बन्ध में हुक्म	२४५
१४	फैसला अथवा पंचायत में पेश किया हुआ मामला कब वापिस किया जा सकता है	२४५
१५	पंचायती फैसला रद्द करने के कारण	२४५

विषय	पेज
१६ अदालतका फैसला पंचायती फैसलेके आधार पर होगा	२४६
१७ पंचायतमें मामला पेश किये जाने के सम्बन्धमें किये गये इक्करार- नामे को अदालतमें पेश करनेके लिये दरखास्त	२४६
१८ मुकद्दमेका मुस्तवी किया जाना जबकि मामलेको पंचायतमें पेश करनेके लिये इक्करारनामा लिखाया गया हो	२४७
१९ पैरा १७ के अनुसारकी जाने वाली कार्रवाईके सम्बन्धमें लागू होने वाले नियम	२४८
२० उस मामलेमें जो किसी अदालतके विना हस्तक्षेप किये हुए पंचा- यतमें पेश किया गया हो दिये गये पंचायती फैसलेका अदालत दाखिल किया जाना	२४८
२१ ऐसे फैसलेका दाखिल किया जाना और उसका अमलमें लाया जाना	२४८
२२ स्पेसिफिक रिलीफैक्ट सन् १८७७ ई० मेंसे कुछ शब्दों का निकाल दिया जाना	२४९
२३ फार्म	२४९

जमीमा नं० १

—पंचायतमें मामला पेश किये जाने का हुक्म हासिल करनेके लिये
दरखास्त

२५०

जमीमा नं० २

—पंचायतमें मामला पेश किये जाने की बावत हुक्म

२५१

जमीमा नं० ३

—नये पंचकी नियुक्तिके सम्बन्धमें हुक्म

२५२

जमीमा नं० ४

—खास मामला

२५३

जमीमा नं० ५

—पंचायतका फैसला

२५४

व्याख्या और नजीरें

विषय	पेज
जब मुकद्दमा चल रहा हो तो उस समय पक्षकारों को पंचायत की दरखास्त करनेका अधिकार	२५५
तीन प्रकारकी पंचायतें	२५५
—१ चलते हुये मुकद्दमे	२५५
—२ मुकद्दमा न चलता हो और किसी मामले को पंचायत द्वारा तय करनेके लिये इकरारनामा लिखा गया हो और उसे अदालतमें पेश करके पंचायत बंदी गई हो	२५५
—३ जब आपसी तौर पर इकरारनामोंके द्वारा पंचायत की गई हो और उस पंचायत की अमल दरामद अदालतसे चाही गई हो	२५५
ऊपरकी तीनों पंचायतों का फरक	२५६
चलते हुये मुकद्दमें में सब फरीकों का राजी होना	२५६
—अगर कोई मुद्दा अलेह हाजिर न हो तो यह न माना जायगा कि वह पंचायत से राजी था	२५६
—बिना खास अधिकारके वकील पंचायत मंजूर नहीं कर सकता	२५६
—अपीलमें भी पंचायत हो सकती है	२५६
—अगर फरीकैतने जवानी रजांमदी दी हो और अदालतने उस पर मामला पंचायत सुपुर्द किया हो तो हुकम जायज़ है	२५७
—पंचायत का हुकम देने के बाद अदालत फिरसे मुकद्दमा चलाने का हुकम नहीं दे सकती	२५७
—चलते हुए मुकद्दमेमें पंचायती कार्यवाही का ज़ावता	२५७
—अगर नियत समयके भीतर पंच फैसला न दे सके तो अदालतके अधिकार	२५७
—पंचोंके नियत करनेका अधिकार अदालतको कब प्राप्त होता है	२५७
—पंचों को अदालतमें फैसला दाखिल करना	२५७
—पंचायती फैसले को अदालत कब तरमीम और सही कर सकती	२५७
(क) जो मामला पेश न किया जा सकता हो	२५७
(ख) जाबते की या कमीभारी भूल	२५७
(ग) लिखने की गलती	२५८
पंचायती फैसला रद्द होने पर अदालतका विचार करना	२५८
मियादके बाद पंचोंने फैसला दिया नाज़ायज़ माना गया	२५८
मियादके बाद फैसला दिया गया ऐसा एतराज फरीकैत नहीं कर सकते	२५८
—मतभेद के सम्बन्धमें विचार	२५९

विषय

—जब बहुमतके बारेमें कोई हुक्म न हो तो बहुमत का फैसला नाजायज होगा	पेज २५९
—अदालत की तरफसे नियुक्त	२५९
—पंचायतका रद्द किया जाना	२५९
—पंचोंका दस्तखत करना दाखिल करना और नोटिश	२६०
—पंचायती फैसलेमें काट छांट करना	२६०
—पंचोंको कैसे मामला तय करना चाहिये	२६१
फैसलेका रद्द किया जाना और वे बातें जिनसे रद्द होगा	२६१
रद्द करनेकी मियाद	२६२
बिना मुकद्दमा चले मामला पंचायत में देनेका इकरार	२६२
—आपसमें इकरारनामेके द्वारा पंचायत नियत करना	२६२
—सब झगड़ोंका फैसला पंचायत सेहोगा	२६२
—ऐसे इकरार नामे में कौन बात होना चाहिये	२६२
बिना अदालतके हस्तक्षेप किये मामले का पंचायतमें जाना	२६३
—खानगी फैसलेके अनुसार डिकरी का बनाया जाना	२६३
—पंचायत करना मंजूर करनेपर पीछे इनकार करना	२६३
—ऐसी दरखास्त पर स्टाम्प	२६३
—निजी तौरसे पंचायती फैसले को अमलमें लाने के लिये नालिश दायर होगी	२६३

सवालात और जिरह

गवाहकी प्रारम्भिक कार्यवाही	२६५
जिरहकी प्रवीणता कैसे प्राप्त होती है	२६६
बयान लेनेका क्रम	२६६
गवाहोंको अदालतके बाहर चले जानेका हुक्म .	२६६
बयान खास—जिन्होंने उसे तलब किया हो	२६६
—बयान खासकी महत्त्वता	२६७
—गवाहोंको पहले जांच कर लेना	२६७
—बयानोंको क्रमबद्ध करना और तैयार करना	२६७
—पथ प्रदर्शक प्रश्नोंका न पूछा जाना	२६८
—दस्तावेजके मजमूनमें गवाहको उसे सामने रखना चाहिये	२६८
—विश्वासपात्र होनेकी शहादत	२६८

विषय

पेज

—अपने गवाह पर कब अभियोग चल सकेगा	२६९
बयान लेनेके सम्बन्धमें कोल ब्राउनके बताये हुए नियम	२६९
१ दबंग गवाहके साथ व्यवहार	२६९
२ भयभीत, सन्देहित, और विस्तृखलित गवाहके साथ व्यवहार	२६९
३ अपने गवाहोंकी साक्षी अनुकूल होने पर कर्तव्य	२६९
४ अपने गवाहके विरुद्ध हो जाने पर व्यवहार	२६९
५ ऐसे गवाहका तलब न करना जिसे विरुद्ध पक्ष तलब करनेको मज़बूर हो	२७०
६ बिना किसी उद्देश्यसे प्रश्न न पूछना	२७०
७ ऐसा प्रश्न न पूछा जाय जिसके बेकायदा होनेका प्रश्न उठने पर समर्थन न हो सके	२७०
८ विरोधी प्रश्न पर कब तक उत्तर करना चाहिये	२७०
९ अपने गवाहसे साफ भाषामें प्रश्न पूछना चाहिये	२७०
१० आवाज़की घटाते बढ़ाते रहना	२७१
११ खास जवाब लेनेके मतलबसे प्रश्न करना	२७१
काकस साहबका मत	२७१
—बयान लेनेके समय वकीलका ढंग	२७१
—शहादतसे साचित्त हुई बातको कभी न पूछना	२७३
—बयानमें पूछी जाने वाली बातें	२७३
—प्रासंगिक बातें	२७३
—जो बातें बयानकी जांय गवाह जानता हो सुना न हो	२७३
—राय, विश्वास, नतीजा न पूछा जाना चाहिये	२७३
—विज्ञानकी बातें बयान की जा सकती हैं	२७३-२७४
—कैसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं	२७४
—जवाबकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न	२७४
स्वयं अपने गवाह पर दोषारोपण करना	२७४

जिरह

—जिरह किसे कहते हैं ?	२७४
—जिरहका प्रारम्भ	२७५
—जिरहके लिये मानव स्वाभाविकाविज्ञान होना ज़रूरी है	२७६
—जिरहका ढंग	२७७
—डाटना, घुडकना, भटकाना, मुंह बनाना	२७८
—वकीलकी अपने आप सम्हाल रखना चाहिये	२७८
—आवाज़, मुख बनानेसे प्रभाव पड़ना	२७८
—मि० रैसलका तर्ज	२७९

विषय

—मि० वेल्मैनकी राय जिरह करनेमें	२७९
—सर चार्ल्स रसेलका अनुभव और सिखांत	२७९
श्रीयुत पं० पृथ्वीनाथ वकीलकी जिरह	२८०
—जिरहका ढंग	२८१
मि० पालब्राउनके नियम जिरहके सम्बन्धमें	२८१
—अपनी आंखें गवाहकी आंखोंके सामने रखो	२८१
—गवाहकी आवाज़का ध्यान रखो	२८१
—कोमल स्वभाव वालोंके साथ नम्रता रखो	२८१
—जब तक अपनी हानि न हो कम प्रश्न करो	२८१
—गोल माल प्रश्न और उत्तरको बचाये रखो	२८१
—अपने आपको खूब सम्हाले रहो	२८१
—प्रत्येक प्रश्न और उत्तरमें गंभीर विचार रखना चाहिये	२८१
—अपने विपक्षीको कभी कम मत समझो	२८१
—अदालत और जूरीका सन्मान करते रहो	२८१
जिरह करनेका अधिकार और उसका उत्तरदायित्व	२८१
जिरहमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं ?	२८१
जिरह सिर्फ उन्हीं बातों पर नहीं होगी जो गवाहने पहले बताई हों	२८१
जिरहमें किन प्रश्नोंके पूछे जानेकी मुमानियत है	२८१
कुछ बातोंके ऊपर जिरह न करना	२८१
बेपरवाहीकी जिरहका भयंकर परिणाम	२८१
आवश्यकतासे अधिक जिरह मत करो	२८१
ऐसे अभियुक्तों और गवाहों पर जिरह जिनपर मामला एकमें चलता हो	२९०
अभिलिखित उत्तर संकेत करने वाले प्रश्न	२९१
संकेतार्थक प्रश्न कब पूछे जाना चाहिये और कब नहीं	२९१
अदालतको इजाजत देना संकेतार्थक प्रश्नोंके लिये	२९१
—प्रारम्भिक अथवा ऐसा मामला जिसमें कुछ झगड़ा नहीं है	२९१
—खंडन करना	२९१
—स्मरणशक्तिको सहायता देना	२९१
—वह सवाल जो खिलाफ होगया हो	२९१
—पेचीदा मामला	२९१
जिरहमें संकेत करनेवाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं	२९१
—पहलेके बयानोंके सम्बन्धमें जिरह	२९१
—समर्थन करनेके लिये पहले दिया गया बयान	२९१
जिरहमें प्रश्नोंसे गवाहको अविश्वासी सिद्ध करना	२९१
श्विवास पात्रता सम्बन्धी जिरहका दुरुपयोग	३०१

दफा	विषय	पेज
—मि० टेलरकी राय		३०१
फरीकैनके आचरण सम्बन्धी शहादत		३०२
स्वयं अपने गवाह पर ही जिरह करना		३०३
क्या कोई फरीक अपने ऊपर जिरह कर सकता है जब कि विपक्षीने उसे अपनी शहादतमें तलब किया हो		३०४
अदालतके प्रश्नोंके उत्तरमें कही गई बातोंके ऊपर जिरह		३०५
लम्बी जिरहमें हस्तक्षेप करनेके सम्बन्धमें अदालतका अधिकार		३०५
बयान मुकर्रर (फिर बयान) का लिया जाना		३०६
अंतिम चकत्तब्य		३०७

इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट

नं० १६ सन १९०८ ई०

दफावार सूची

प्रथम प्रकरण

१ संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ	३१३
२ परिभाषा	३१३

दूसरा प्रकरण

(शिरस्ता रजिस्ट्री)

३ रजिस्ट्रीके इन्स्पेक्टर जनरल	३१५
४ सिंध ब्रांचका इन्स्पेक्टर जनरल	३१५
५ जिला और परगना	३१५
६ रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार	३१५
७ रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रारके दफ्तर	३१६
८ रजिस्ट्रीके दफ्तरोंके इन्स्पेक्टर	३१६
९ फौजी छावनियां जिले या परगने घोषित किये जा सकते हैं	३१६
१० रजिस्ट्रारकी अनुपस्थिति या उसके आफिसका खाली होना	३१६
११ रजिस्ट्रारकी अनुपस्थिति जब वह अपने जिलेमें गया हो	३१७
१२ सब रजिस्ट्रारकी अनुपस्थिति या दफ्तरका खाली होना	३१७

दफा	विषय	पेज
१३	अफसरोंकी कुछ नियुक्तियों, मुअत्तिली, अलहदगी वखास्तगीकी रिपोर्ट	३१७
१४	रजिस्ट्री करने वाले अफसरका वेतन और संस्थापन	३१८
१५	रजिस्ट्री करने वाले अफसरकी मोहर	३१८
१६	रजिस्टर और न जलाने योग्य सन्दूकें	३१८

तीसरा प्रकरण

(रजिस्ट्रीके योग्य दस्तावेजोंके विषयमें)

१७	वे दस्तावेज जिनकी रजिस्ट्री अनिवार्य है	३१९
१८	दस्तावेज जिनकी रजिस्ट्री वैकल्पिक है	३२१
१९	दस्तानेज जिनकी भाषा रजिस्ट्री कराने वाले अफसरकी समझमें न आवे	३२१
२०	वे दस्तावेज जिनमें सतरोंके ऊपर लिखा हो, जगह छूटी हो, काट पीट या रद्द बदलकी गई हो,	३२१
२१	जायदाद नकशों और खाकोंका वर्णन	३२२
२२	सरकारी नकशों या पैमाइशका हवाला देकर मकानों और जमीनका वर्णन करना	३२२

चौथा प्रकरण

(रजिस्ट्रीके वास्ते दस्तावेजोंके पेश किये जानेके समयके विषयमें)

२३	दस्तावेजोंके पेश किये जानेका समय	३२४
२३ (ए)	कुछ दस्तावेजोंका दुबारा रजिस्ट्री किया जाना	३२४
२४	वे दस्तावेज जो बहुत आदमियों द्वारा भिन्न समयों पर लिखे गये हैं	३२५
२५	उस समयके लिये व्यवस्था, जब कि दस्तावेजके पेश करनेमें बिलम्ब होना अनिवार्य है	३२५
२६	वे दस्तावेज जो ब्रिटिश भारतके बाहर लिखे गये हों	३२५
२७	वसीयतनामे, किसी समय भी लिये और जमा किये जा सकते हैं	३२६

पांचवां प्रकरण

(रजिस्ट्री किये जानेके स्थानके विषयमें)

२८	जमीनसे सम्बन्ध रखने वाले दस्तावेजोंकी रजिस्ट्रीका स्थान	३२७
२९	दूसरे दस्तावेजोंकी रजिस्ट्रीका स्थान	३२७
३०	कुछ दशाओंमें रजिस्ट्रारों द्वारा रजिस्ट्री किया जाना	३२७
३१	रजिस्ट्री करना या जमानतमें रखनेके लिये दस्तावेजोंका लेलिया जाना	३२८

छठवां प्रकरण

(रजिस्ट्रीके लिये दस्तावेजोंके पेश किये जानेके विषयमें)

३२	वे शख्स जो रजिस्ट्री किये जाने के लिये दस्तावेज पेश कर सकते हैं	३२९
३३	वे मुख्तारनामा जो दफा ३२ के प्रयोजनके लिये मान्य हैं	३२९

दफा	विषय	पेज
३४	रजिस्ट्री किये जानेसे पहले रजिस्ट्री करने वाले अफसर द्वारा जांच	३३०
३५	दस्तावेज़ की तकमील करनेको इनकार या स्वीकार करनेकी दशामें कार्रवाई	३३१

सातवां प्रकरण

(दस्तावेज़ लिखनेवालों तथा गवाहोंकी हाजिरीके विषयमें)

३६	उस दशामें कार्रवाई जब कि दस्तावेज़ लिखने वाले गवाहकी हाजिरीकी आवश्यकता हो	३३३
३७	हाकिम या अदालतका सम्मन जारी करना तथा उनकी तामील करवाना	३३३
३८	वे लोग जो रजिस्ट्रीके दफतरमें हाजिरीसे बरी हैं	३३३
३९	समनों कमीशनों तथा गवाहों सम्बन्धी कानून	३३४

आठवां प्रकरण

(वसीयतनामों और गोद लेनेके इजाजतनामाके पेश किये जानेके सम्बन्धमें)

४०	वे लोग जिनको वसीयतनामों और गोद लेनेके इजाजतनामोंके पेश करनेका अधिकार है	३३५
४१	वसीयतनामों और गोद लेनेके इजाजतनामोंकी रजिस्ट्री	३३५

नवां प्रकरण

(वसीयतनामोंके अमानतमें जमा करनेके विषयमें)

४२	वसीयतनामोंका अमानतमें जमा किया जाना	३३६
४३	वसीयतनामोंके जमा करने पर कार्रवाई	३३६
४३	मोहर लगे हुए उस लिफाफेका वापिस लेना जो कि दफा ४२ के अनुसार जमा किया गया है	३३६
४५	दाखिल करनेवालेके मर जाने पर कार्रवाई	३३६
४६	कुछ नियमों तथा अदालतके अधिकारोंका बचाव	३३७

दसवां प्रकरण

४७	रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेज़ोंके अमल करनेका समय	३३८
४८	जायदादसे सम्बन्ध रखने वाले रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेज़ जवानी इकरारनामोंके मुकाबिलेमें कब अमलमें लाये जायेंगे	३३८
४९	जिन दस्तावेज़ोंकी रजिस्ट्री आवश्यक है उनकी रजिस्ट्री करानेका परिणाम	३३८
५०	भाराजी सम्बन्धी कुछ दस्तावेज़ बिना रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेज़ोंके मुकाबिलेमें व्यापक होने	३३८

दफा

विषय

पेज

ग्यारहवां प्रकरण

(रजिस्ट्री करने वाले अफसरके कर्तव्यों तथा अधिकारोंके विषयमें)

- ५१ वे रजिस्ट्र जो सभी दफ्तरोंमें रखे जाने चाहिये ३४०
- ५२ दस्तावेज पेश किये जाने पर रजिस्ट्री करनेवाले अफसरका कर्तव्य ३४०
- ५३ इन इन्दराजातका सिलसिलेवार नम्बर छोड़ना ३४१
- ५४ वर्तमान फेहरिस्त और इन्दराज ३४१
- ५५ रजिस्ट्री करने वाले अफसरों द्वारा तैयार की जाने वाली फेहरिस्तें और उनमें लिखी जाने वाली बातें ३४१
- ५६ फेहरिस्त नं० १—२—३ में दर्ज की गई बातोंकी नकलका सब रजिस्ट्रारके पास भेजा जाना और उसका दाखिल दफ्तर करना ३४२
- ५७ रजिस्ट्री करने वाले अफसरों को कुछ किताबों और फेहरिस्तोंके मुलाहिजा करने की आज्ञा और इन्दराजात की तस्दीक की हुई नकलें देनेका अधिकार ३४२
- ५८ रजिस्ट्री के लिये मंजूर कर लिये गये दस्तावेजोंकी पुस्त पर लिखी जाने वाली बातें ३४३
- ५९ तस्दीकके ऊपर रजिस्ट्री करने वाला अफसर अपने दस्तखत करे और तारीख डाले ३४४
- ६० रजिस्ट्री किये जाने का सर्टीफिकेट ३४४
- ६१ तस्दीक और सर्टीफिकेटकी नकल करके दस्तावेज वापिस दिया जाना ३४४
- ६२ ऐसे दस्तावेज पेश किये जाने पर कार्रवाही जो ऐसी भाषामें हो जिसे रजिस्ट्री करनेवाला अफसर नहीं जानता ३४५
- ६३ हलफ लेने और बयानका सारांश लिखने का अधिकार ३४५
- ६४ उस दशामें कार्रवाही जबकि दस्तावेज उस आराज़ीसे सम्बन्ध रखता हो जो कई परगनेमें हैं ३४५
- ६५ उस दशामें कार्रवाही जब कि दस्तावेज उस आराज़ीसे सम्बन्ध रखता हो जो कई जिलोंमें है ३४६
- ६६ आराज़ी सम्बन्धी दस्तावेज़ीकी रजिस्ट्री हो जानेके बाद कार्रवाई ३४६
- ६७ दफा ३० उपदफा २ के अनुसार रजिस्ट्री हो जानेके बाद कार्रवाई ३४७
- ६८ सब रजिस्ट्रारोंके कार्यका निरीक्षण करने तथा उन पर शासन करनेके सम्बन्धमें रजिस्ट्रार के अधिकार ३४७
- ६९ रजिस्ट्रीके दफ्तरों का शासन करने और नियम बनानेके सम्बन्ध में इन्स्पेक्टर जनरलके अधिकार ३४७
- ७० जुर्माना माफ करनेके सम्बन्धमें इन्स्पेक्टर जनरलका अधिकार ३४८

दफा

विषय

पेज

बाहरवां प्रकरण

(रजिस्ट्री किये जाने से इनकार किये जानेके विषयमें)

७१	रजिस्ट्री करनेसे इनकार किये जानेके कारण लिखे जाने चाहिये	३४९
७२	उन दस्तावेजोंके अतिरिक्त जबकि दस्तावेजोंके लिखे जानेसे इनकार करदी गईहो उसकी अपील	३४९
७३	जब सब रजिस्ट्रार दस्तावेजोंके लिखे जानेसे इनकार करनेकी कारण रजिस्ट्री करनेसे इनकार करे उस समय रजिस्ट्रारको दरखास्त	३५०
७४	ऐसी दस्तावेजोंके ऊपर रजिस्ट्रार द्वारा की जाने वाली कार्रवाही	३५०
७५	रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री किये जानेके हुक्म का दिया जाना और उसके ऊपर कार्रवाई	३५१
७६	रजिस्ट्रार द्वारा इनकारी के हुक्मका दिया जाना	३५१
७७	रजिस्ट्रार द्वारा इनकारीका हुक्म दिये जाने पर तालिश दायर करना	३५५

तेरहवां प्रकरण

(रजिस्ट्री, खोज और नकलोंकी फीसके विषयमें)

७८	फीस स्थानीय सरकार नियत करेगी	३५३
७९	फीसका प्रकाशित किया जाना	३५३
८०	दस्तावेजोंके पेश किये जाने पर अदा की जाने वाली फीस	३५३

चौदहवां प्रकरण

(दण्डके विषयमें)

८१	हानि पहुँचानेके हरादेसे गलत तौर पर दस्तावेजोंकी तस्दीक करने नकूल करने अनुवाद तथा रजिस्ट्री करनेके लिये दण्ड	३५४
८२	गलत बयान करने झूठी नकलें और अनुवाद देने, झूठ मूठ कोई दूसरा आदमी बन जाने तथा किसीको अपराधके लिये उद्यत करने के लिये दण्ड	३५४
८३	रजिस्ट्री करने वाले अफसर को सुकृदमा चलानेका अधिकार	३५५
८४	रजिस्ट्री करने वाले अफसर सार्वजनिक नौकर समझे जायंगे	३५५

पंद्रहवां प्रकरण

(विविध)

८५	जिन दस्तावेजोंका कोई दावेदार न हो उनका नष्ट किया जावा	३५६
----	---	-----

दफा	विषय	पेज
८६	रजिस्ट्री करने वाला अफसर किसी ऐसी बातके लिये उत्तरदायी नहीं है जिसे उसने बहसियत ऐसे अफसरके नेकनीयती से किया हो या इनकार कर दिया हो	३५१
८७	इस तरह पर की गई कोई भी बात नियुक्ति अथवा कार्रवाईमें किसीं त्रुटिके कारण नाजायज नहीं समझी जायगी	३५१
८८	उन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री जिन्हे सरकारी अफसरों या सार्वजनिक कार्यकर्ताओंने लिखा हो	३५६
८९	कुछ हुक्मों साटीफिकेटों तथा दस्तावेजोंकी नकलोंका रजिस्ट्री करने वाले अफसरके पास भेजा जाना और उनका फाइल किया जाना	३५७
९०	सरकार द्वारा या उसके हकमें लिखे गये कुछ दस्तावेजोंका अलगवा	३५८
९१	ऐसे दस्तावेजातका निरीक्षण और नकलें	३५९
९२	ब्रह्माके रजिस्ट्रीके नियमोंकी स्वीकृति	३५९
९३	मंसूखी	३५९

व्याख्या और नजारे



जिन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री लाजिमी है	३६१
जिन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री इच्छा पर निर्भर है	३६२
रजिस्ट्रीके लिये दस्तावेज पेश करनेका समय	३६५
रजिस्ट्री करनेका स्थान	३६५
रजिस्ट्रीके लिये दस्तावेज कौन पेश कर सकता है	३६६
रजिस्ट्री करनेसे इन्कार	३६७
रजिस्ट्रारके रजिस्ट्री कर देने पर दीवानी नालिश	३६८
जिन दस्तावेजोंका रजिस्ट्री अनिवार्य है	३६८
जिन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं है	३७३
जिनकी रजिस्ट्री लाजिमी है मगर कराई नहीं गयी	३७६
दस्तावेजका पेश किया जाना	३७७
बिना रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेजों पर, रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेजों को तरजीह	३७८
जबरदस्ती रजिस्ट्री करानेके लिये दीवानी नालिश	३७८
दूसरी अवस्थाएं	३७९
रजिस्ट्रीके फीसकी शरह सं० प्रा०	३८१ से ३९२

इण्डियन लिमिटेड एक्ट

नं० ९ सन १९०८ ई०

दफावार सूची

प्रथम प्रकरण

दफा	विषय	पेज
१	संक्षिप्तनाम, विस्तार, और आरम्भ	३९४
२	परिभाषा—सायल, हुँडी, तमस्तुक, मुद्दाअलेह, हक आसायश, विदेश, नेकनीयती, मुद्दई, इन्दुलतलब रुक्का, नालिश, दूस्टी शब्दों का अर्थ	३९४

दूसरा प्रकरण

(नालिशों, अपीलों, और दरखवास्तोंकी मियाद)

३	मियादकी मुद्दत खतम होजानेके बाद दायर कीगई नालिशोंका खारिज कर दिया जाना	३९६
४	जब मियाद खतम होनेके समय अदालत बन्द हो	३९६
५	कुछ अवस्थाओंमें मियादकी मुद्दतका बढ़ाया जाना	३९६
६	कानूनी नाकाबलियत	३९७
७	कई एक मुद्दइयों या सायलोंमेंसे किसी एक का नाकाबिल होना	३९८
८	कुछ विशेष अवस्थाओंमें इन नियमोंका लागू न होना	३९८
९	समयका बराबर चलता रहना	३९९
१०	ट्रस्टियों और उनके प्रतिनिधियोंके विरुद्ध की जाने वाली नालिशें	४००
११	ब्रिटिश भारतसे बाहर लिखे गए मुआहिदोंकी बाबत नालिश	४००

तीसरा प्रकरण

(मियादकी मुद्दतका शुमार)

१२	कानूनी कार्रवाईमें समयका निकाल दिया जाना	४०१
१३	ब्रिटिश भारतसे तथा अन्य देशोंसे मुद्दाअलेहकी अनुपस्थितिके समय का निकाल दिया जाना	४०१
१४	उस समयका निकाल दिया जाना जिसमें नेकनीयतीके साथ उस अदालतमें कार्रवाई कीगई हो जिसे उस मामलेकी समाप्त करनेका अधिकार न भी हो	४०१

- | दफ़ा | विषय |
|------|--|
| १५ | उस समयका निकाल दिया जाना जिसमें कार्रवाई मुकद्दमा मुस्तबी रही हो |
| १६ | उस समयका निकाल दिया जाना जिसमें किसी डिक्करीकी इजरा होनेवाली नीलामको रद्द कर दिये जानेके लिये दायर किया गया मामला फैसल नहीं हुआ था |
| १७ | नालिश करनेका हक पैदा होनेके पहिले मौत होजानेका असर |
| १८ | फरेबका परिणाम |
| १९ | लिखित स्वीकृति पत्रका असर |
| २० | ब्याज का, बतौर ब्याजके अथवा मूलके किसी अन्शके अदा कर देने का असर |
| २१ | जो शक़्स नालिश वगैरः के नाकाबिल है, उसका सुखतार |
| २२ | नये मुद्दई या मुद्दाअलेहके बढ़ाये जाने या किसी दूसरे मुद्दई या मुद्दाअलेहकी जगह पर शामिल किये जानेका असर |
| २३ | शिकस्त मुआहिदा और फेल बेजाका बराबर जारी रहना |
| २४ | किसी ऐसे कामके लिये मुआहिदोंकी नालिश जो बिना कोई खास हुक़सान पहुँचाये न की जासकती हो |
| २५ | दस्तावेज़में बतलाई हुई मुद्दतका शुमार |

चौथा प्रकरण

(दखलके जरिये मिलिकियतका हासिल करना)

- | | |
|----|---|
| २६ | हक आस्नायशका हासिल करना |
| २७ | मिलिकियत ताबेके वारिस, माबादके हकमें मुद्दतका निकाल दिया जाना |
| २८ | जायदाद सम्बन्धी अधिकारका जाल्ता रहना |

पाँचवा प्रकरण

(बचत और मंसूखी)

- | | |
|----|--|
| २९ | बचत |
| ३० | उन नालिशोंके सम्बन्धमें व्यवस्था जिनके सम्बन्धमें नियत मियाद की मुद्दत, उस मुद्दतसे कम हो, जो भारतीय कानून मियाद सन् १८७७ ई० में निश्चित की जा चुकी है |
| ३१ | परिशिष्ट २ में बतलाये हुए प्रान्तोंमें कुछ मुर्तद्दिनोंकी ओरसे की जानेवाली नालिशोंके सम्बन्धमें व्यवस्था |
| ३२ | ऐक्ट नं० १७ सन् १९१४ ई० में सू किया गया |

परिशिष्ट नं० १

- ४८—नालिशोंकी किस्म, मियादकी मुद्दत और मियाद शुरू होनेकी
अवस्था ११४ से ४५१

परिशिष्ट नं० २

- ४८—वे प्रांत जिनका उल्लेख दफा ३१ में है ४५२

परिशिष्ट नं० ३

- ४८—मंस्खु हो गया ४५२

व्याख्या और नजीरें

- दफा ३ नालिशें जिनकी मियाद आरिज हो गई है ४५३
—मियादकी बात चाहे न कही गयी हो तो भी मामला खारिज हो जायगा ४५३
—मियादका प्रश्न न पेश करनेका सुआहिदा नाजायज़ है ४५३
—रज़ामन्दीसे मियादमें कोई अस्तर नहीं पड़ना ४५३
—अपीलमें मियादका प्रश्न उठाया जासकता है चाहे नीचे न भी उठाया
गया हो ४५३
—अपीलकी अर्जीमें अगर मियादका प्रश्न न लिखा गया हो तो बहसके
लिये अदालतसे हुक्म लेना चाहिये ४५३
दफा ५ मियादकी मुद्दतका बढ़ाया जाना ४५४
—‘काफी वजह’ होनेपर अदालत मियाद बढ़ा सकती है ४५४
—यह दफा इजरा व नीलामकी मंस्खु, और पंचायती फैसलेके रद
करानेके लिये लागू होती है ४५४
—एकतर्फा डिकरीकी मंस्खुमें भी लागू होगी ४५४
—‘काफी वजह’ मामलेके अनुसार विचारकी जायगी तथा कुछ उदाहरण ४५४
—वकीलकी लापरवाहीसे अगर मियाद चली जाय तो उसपर नालिश ४५५
दफा ६, ७, ८, और ९ अयोग्य पुरुषोंके लिये मियादकी मुद्दतका बढ़ाया
जाना ४५५
—नाबालिग, पागल, मूर्ख, आदि तो कब दावाकी मियाद बढ़ेगी ४५५
—हकशिकासे दफा ६, और ७ का कोई सम्बन्ध नहीं है ४५५
—जब मियाद एक बार शुरू हो जाय तो फिर बन्द नहीं होती ४५५

विषय

- दफा ६ के मतलबके लिये सिर्फ ३ तरहकी अयोग्यता मानी जायगी
- अगर दावाकी विनाय मुखासमत जन्मसे पहिले पैदा हुई हो तो नाबालिगकी अपनी नाबालिगीकी मियाद नहीं मिलेगी
- नाबालिगीकी मियाद दूसरेको नहीं दी जासकती
- अयोग्यताके भीतर भी दावा किया जासकता है
- दफा ६ इजराकी दरख्वास्त और परिशिष्ट १ के तीसरे खानेकी मियाद में लागू है
- स्थानीय खास कानूनकी मुद्दतमें दफा ६ लागू न होगी
- अयोग्यता दूर होनेसे तीन सालसे अधिक मियाद किसीमें न मिलेगी
- जब साधारण मुद्दत, नाबालिगीमें समाप्त होती हो
- जब साधारण मुद्दत बालिग होनेके बाद समाप्त होती है
- नकल, तस्दीक, प्रोवेट, के लेनेका समय मियादमें मुजरा होगा
- अयोग्यता और असमर्थका भेद
- दफा १० ट्रस्टियोंके ऊपर नालिश
 - ट्रस्टियों या ट्रस्टके सम्बन्धी व्यक्तियों पर मियादका असर नहीं पड़ता
 - जिसके पास माल अमानतमें रक्खा गया हो ट्रस्टी नहीं है
 - मुख्तार, गुमास्ता, कर्ता, या प्रबन्धक आदि ट्रस्टी नहीं हैं
 - यह दफा कम्पनीके डायरेक्टरोंसे लागू नहीं होती
 - तामील कुनिन्दा ट्रस्टी माना गया है
 - ट्रस्टी कौन है यह बात हरएक मामलेके वाकियातसे मालूम होगी
 - इस दफाका प्रयोग खास ट्रस्टियों पर ही हो सकता है
 - ‘खास काम’ के अर्थके लिये
- दफा १२ सिर्फ मियाद समाप्तकी मुद्दतका शुमार
 - मियादका शुमार अंग्रेजी तारीखसे होगा, देशी महीने या मितिसे नहीं
 - विनाय मुखासमत पैदा होनेवाले दिनका शुमार मियादमें न किया जायगा
 - एक ही तारीखके दो दिन, मियादमें शामिल नहीं होते
 - रुपया अदा करनेकी तारीख निकाल दी जायगी
 - तमस्सुक आदि प्रोनोटमें मियादका शुमार
 - ‘जरूरी’ और ‘प्रचलित प्रथा’ का मतलब
 - नकलकी दरख्वास्त देनेकी तारीखसे मिलनेकी तारीखके बीचका समय मुजरा पाना
 - नकल लेनेका जरूरी समय
 - वह समय जो नकल लेनेके लिए जरूरी है
 - कौन समय नकल लेनेके लिये मुजरा होगा

विषय	पेज
—कलकत्तेमें फैसला देने और डिकरी पर दस्तखत करनेके बीचका समय मिलता है	४६०
—मियाद डिकरीसे शुरू होगी फैसलेसे नहीं	४६०
—कलकत्ता हाईकोर्ट की राय	४६०
—इस दफा के लिये नकल लेनेकी मियाद कौन मुजरा होगी कौन नहीं	४६१
—कौन समय मुजरा न होगा	४६१
—डिकरीमें दख्खवास्त होनेवाले दिनके दूसरे दिनसे यदि छुट्टी हो और अदालत खुलनेवाले दिनको नकलकी अर्जी दी गयी हो तो मियाद	४६१
—जब फैसला लम्बी छुट्टी होनेके दिन दिया गया हो और नकल अर्जी अदालत खुलने पर उसी दिन दी गई हो या कुछ दिन बाद	४६१
—जब छुट्टियोंमें नकल देनेका हुक्म हो गया	४६१
—अपीलाण्टको दोनों समय मुजरा मिलना। डिकरी व फैसलेकी नकल अलग अलग लेनेमें जो लगा हो	४६२
—पंजाब हाईकोर्ट की राय विरोध और पक्षमें	४६२
दफा १४ उन नालिशों अथवा दख्खवास्तोंके सम्बन्धमें समयका निकाल दिया जाना जिसमें नेक नीयतीके साथ गलत अदालतमें कार्रवाई की गई है	४६२
—इस दफाका उद्देश-बचाव	४६२
—अपीलोंके सम्बन्धमें लागू नहीं होगी-केवल प्रारम्भिक अदालतोंमें लागू है	४६२
—जिन मामलोंकी गलत समाअत अदालतोंमें हुई है उनसे यह दफा लागू है	४६२
—इजरासे इस दफाका सम्बन्ध है-आवश्यक बातें	४६२
—जब लापरवाहीसे अर्जीदावा गलत अदालतमें पेश कर दिया गया हो	४६३
—किसी बात को गलत समझानेसे मियाद मुजरा नहीं मिलती	४६४
—नेकनीयती प्रत्येक मामलेके ऊपरसे विचारकी जायगी और मिशालें	४६४
—“अख्तियार समाअत” का अर्थ	४६५
—पहिली और दूसरी नालिशके मुद्दाअलेहोंमें जब फरक हो तो	४६५
—दूसरे मामलोंमें समयका निकाल देना हुक्म इस्तनाई या मुत्तवी	४६५
—खरीदार नीलामका कब्ज़ा	४६६
—मौत हो जानेसे असर	४६६
—फरेब करनेका असर	४६६
दफा १५ हुक्म इस्तनाई या दूसरा हुक्म	४६६
—यह दफा हुक्म इस्तनाईसे सम्बन्ध रखती है	४६६
—डिकरीकी इजरा मुत्तवी कर देना या बन्द कर देनेका समय मुजरा होना	४६६
—कुर्की और हुक्म इस्तनाई आदिमें फरक है	४६७

विषय	पेज
—जब कई आदमियोंके खिलाफ डिकरी हो और एक के ऊपर खारी की गयी हो तो मियादका असर सबपर होना	४६७
—मदियूनके गिरफ्तार करनेके बाद किये गये इकरारनामेंसे मियाद	४६७
—डिकरीदारके कारण नीलाम मुलतबी होनेसे दफा १५ नहीं लागू होती	४६७
—दीवालियाके सम्बन्धमें मियाद	४६७
—प्रिवी कौंसिलमें अपीलके दौरानमें, जमानत लेकर इजराका असर	४६७
दफा १६ की 'कार्रवाई' शकमें नालिश और हरखवास्त शामिल है	४६७
—आर्थिकल १४४ यदि लागू होगी तो दफा १६ की मियाद मुजरा न होगी	४६८
दफा १८ फरेब	४६८
—किसका फरेब होना चाहिये	४६८
—यह दफा उस व्यक्तिसे लागू होगी जब फरेबसे मुद्दैके हकको जानने न दिया गया हो	४६८
—अदालतके बाहर डिकरीकी बेवाकीमें फरेब	४६८
—इस दफाके लिये फरेब केवल सन्देह न किया जाता हो	४६९
—फरेबकी बात मालूम होनेकी तारीखसे मियाद शुरू होगी	४६९
—अधिकार पैदा होनेसे पहले यदि फरेब किया गया हो	४६९
—नीलामका इश्तहार प्रकाशित न करवाना फरेब नहीं है	४६९
—जब नीलामकी बात फरेबसे जानने न दी गयी हो	४६९
—मदियूनको जब नोटिस न मिला हो और दखलके समय फरेब मालूम हुआ हो	४७०
दफा १९ लिखित स्वीकृत-पत्रका असर	४७०
—जब फियाद खतम होनेसे पहले लिखी हुई मंजूरी दे दी गयी हो	४७०
—इस दफाकी आवश्यक बातें	४७०
—कर्जामें मंजूरी रुपया वसूल होनेसे	४७०
—जिस दर्जेकी मियाद खतम हो गयी है बादको मंजूरी लिखी हो वह रद्द होगी	४७०
—मियाद खतम होनेके बादकी मंजूरी, मुआहिदेके भीतर आसकेगी	४७०
—छुट्टियोंमें मियाद खतम हो जानेके बाद मंजूरी हुई और पीछे छुट्टी खतम हुई तो भी मंजूरी काफी नहीं है	४७०
—स्वीकृत पत्रमें उस खास कर्जेका हवाला होना चाहिये	४७१
—स्वीकृतकी ज़बानी शहादत न मानी जायगी	४७१
—इस दफाका मंशा यह है कि साफ साफ बातें मालूम हों	४७१
—कर्ज़ा स्वीकार करनेमें कौन बातें होना कौन न होना चाहिये	४७१
—कर्जेकी तारीख गलत लिख देनेसे स्वीकृत पत्र नाजायज़ न होगा	४७१
—हिचाबकी असलियत मान लेनेसे, स्वीकार समझा जासकता है	४७१

धिव्य

पेज

- प्रोनोट पर वसूल लिखनेसे मियाद ४७२
- पंचायतमें कर्जोंका स्वीकार करना ४७२
- सम्मिलित हिन्दू छुट्टीका छोटा व्यक्ति स्वीकृति पत्र नहीं लिख सकता ४७२
- बहुतसे शरीक कर्जदारोंमेंसे एक के पत्र लिखनेका असर ४७३
- स्वीकृति पत्र कैसा होना चाहिये ४७३
- कोई निशानी बना देना अनपढ़के लिये दस्तखत माने जायेंगे ४७४
- कर्ज अदा करनेके लिये यदि किसी पत्रमें समय मांगा गया हो ४७४
- अगर किसी कर्जोंके एकही हिस्सेको स्वीकृति दी गई हो तो ४७४
- दफा २० व्याजकी रकम या मूलधनकी अदायगीका असर और मिसालें ४७४
- मुख्तार, बली, कमेटी, मेनेजर, इस दफाके लिये ४७५
- मुआहिदादारोंमेंसे एक की स्वीकृति ४७५
- अगर स्वीकृति पत्रसे तारीखका पता न लगता हो तो साबित करना चाहिये ४७५
- व्याजकी अदायगी और व्याजका अर्थ ४७५-४७६
- कर्जोंकी मंजूरी और अदायगीका अन्तर क्या है ४७७
- अदायगीकी क्रिमें ४७७
- दस्तखत—“इन्दराज”—दूसरेके दस्तखत ४७८
- वहीखातेमें अगर दो आदमी कर्जके देनदार हों तो एक कर्जोंकी मंजूरी लिखें दूसरा दस्तखत कर दें तो जायज होगा ४७८
- किस्तकी अदायगीपर कर्जदारको चिट्ठी लिखना ४७८
- क्या दफा १९, २० कानून मियादके लिये गुमास्ता मुनीम, बली है ४७९
- दफा २१ अदायगी केवल एक कर्जदार द्वारा इत्यादि ४७९
- विधवाके रहननामाकी अदायगी या उसके भावी वारिषोंमेंसे एक ने की हो ४७९

नये मुद्दइयान या मुद्दाअलेहोंके शामिल करनेका असर

- दफा २२ नये फरीक बनानेका असर उसी तारीखसे होगा ४८०
- यह दफा कहाँ लागू नहीं होती तथा असर ४८०
- अदम इस्तेमाल (Nonjoinder) का असर ४८०
- अनावश्यक फरीकैनके शामिल करनेसे मुकद्दमा खारिज न किया जायगा ४८१
- मियाद खतम होनेके बाद फरीकैनका शामिल किया जाना ४८१
- जब किसीने पहले अपने नामसे मुकद्दमा दायर किया पीछे यह जाहिर किया कि वह किसी दूसरेकी तरफसे लड़ रहा है तो मियाद नहीं जायगी ४८१

- जब देवमूर्तिके मेनेजर की ओरसे पहले मुकुटमा दायर हो पीछे देव-
मूर्तिके नामपर हो तो मियादका सवाल ४८१
—अगर ऐसी तरमोम हो जितसे नये मुकुटमेंकी उत्पत्ति होती हो ४८१
—नीलाम मन्सूख करानेकी नालिशमें, खरीदारका पीछे शामिल
करना ४८१, ४८१

इण्डियन वालिंटियर्स ऐक्ट

नं० २० सन १८६९ ई०

दफावार सूची

दफा	विषय	पेज
१	संक्षिप्त नाम	४८१
२	ऐक्टका विस्तार	४८१
३	ऐक्टकी मंजूरी	४८१
४	परिभाषा	४८१
५	कोरका सङ्गठन	४८१
६	कमांडिंग अफसरका सर्टीफिकेट, भरती कर लिये जाने का प्रमाण	४८६
७	कोरको तोड़ देने अथवा उसके सदस्योंको अलग कर देने का अधिकार	४८६
७(ए)	कुछ अवस्थाओंमें कमांडिंग अफसरको रजिस्टरसे वालिंटियरों का नाम काट देनेका अधिकार	४८६
८	वालिंटियरोंके ऊपर आर्मी ऐक्टका प्रयोग किया जायगा जहां तक कि उसका सम्बन्ध अधिकारियोंसे है	४८७
९	जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजायें	४८७
१०	जनरल कोर्ट मार्शलमें कौन कौन शामिल होंगे	४८७
११	रेजिमेन्टल कोर्ट मार्शल	४८८
१२	इस ऐक्टके अनुसार बुलाई गई कोर्ट मार्शलकी कार्यवाही	४८८
१३	कोर छोड़ देनेका अधिकार	४८८
१४	अफसरोंको दिये गये अधिकार उस समय बंद हो जायंगे जब कि वे अपनी खुशीसे कामसे अलग हो जाय या बरखास्त कर दिये जाय	४८८
१५	कोरको तोड़ देनेवाले मेम्बरों द्वारा सरकारी हथियारोंका उसके हवाले कर दिया जाना	४८८

दफा	विषय	पेज
१६	कार्य करनेकी स्थानीय सीमा	४८९
१७	कमांडिंग अफसरको नियम बनानेका अधिकार	४९०
१८	डिल अथवा परेडके अलावा असली ड्यूटी पर हाजिर न होना	४९०
१९	डिल अथवा परेडमें हाजिर न होना	४९०
२०	जुर्माना न देने पर संज्ञा	४९१
२१	वालिंटियरोंको अपनी ड्यूटी करते समय रोकने या उनपर आक्रमण करनेके लिये दण्ड	४९१
२२	जुर्माना वसूल किया जाना	४९१
२३	लोगोंको निःशस्त्र करनेका अधिकार	४९१
२४	सार्वजनिक शांति भंग होनेको रोकना, गैर कानूनी संस्थाओंको भंग करने और कुछ ऐसे आदमियोंके पकड़ लेनेका अधिकार जिन पर सन्देह किया जाता हो	४९२
२५	घोड़ा—करसे छुटकारा	४९३
२६	इस ऐक्टके अनुसार की जाने वाली बातोंके लिये नालिश	४९३
२७	युद्धक्षेत्र कार्यके लिये वालिंटियर कोरका बुलाया जाना	४९३
२८	वालिंटियरोंको अलाउन्स देनेके सम्बन्धमें नियमोंके बनाने का अधिकार	४९४
२९	उन वालिंटियर कोरोंके सम्बन्धमें, जिनके सदस्य एकसे अधिक प्रान्तोंमें भर्ती किये गये गये हों, कार्यवाई करनेके लिये स्थानीय सरकारकी नियुक्ति	४९५
३०	वालिंटियरोंके साथ सम्मिलित होनेकी दशामें स्थलसैनिकोंके साथ इस ऐक्टके नियम लागू होंगे	४९५

न्यूज पेपर ऐक्ट

नं० ८ सन १९०८ ई०

दफावार सूची

१	संक्षिप्त नाम विस्तार	४९६
२	परिभाषा	४९६
३	कुछ अवस्थाओंमें प्रेस ज़ब्त कर लेनेका अधिकार	४९७
४	जत्ती का अधिकार	४९८

विषय

दफा

- ५ अपील
- ६ दूसरी कार्रवाईका न हो सकना
- ७ प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ् बुक्स ऐक्ट सन् १८६७ ई० के अनुसार दाखिल किये गये डिक्लेरेशनके रद्द करनेका अधिकार
- ८ दण्ड
- ९ जाबता फौजदारीका प्रयोग
- १० दूसरे कानूनों का अमलमें लाया जाना

स्टेट आफेंसेज ऐक्ट

नं० ११ सन १८५७ ई०

— :: —

दफावार सूची

- १-२ कानूनोंकी मसूखी
- ३ किसी घोषित रकबेमें किये गये अपराधोंके दोषी बतलाये हुए लोगों के मामलेकी जांच करनेके लिये कार्यकारिणी समिति को कमीशन जारी करनेका अधिकार
- ४ सरकार अदालतोंको कुछ अधिकार दे सकती है
- ५ इस ऐक्टके अनुसार बैठी हुई अदालतके सामने मजिस्ट्रेट भावमियोंको उनके मामलेकी जांच करनेके लिये पेश कर सकता है
- ६ यह ऐक्ट इंग्लैंडमें पैदा हुई ब्रिटिश प्रजाके और उनके लड़कोंके सम्बन्धमें लागू न होगा
- ७-१० हथियारों का पास रखने वाले कानूनकी मसूखी
- ११ मजिस्ट्रेट शब्दका अर्थ

भाग ३

प्लीडिङ्ग्स, अर्जियों और दस्तावेजों
आदिके नमूने

—:०:—

अर्जीदावा और बयान तहरीरी

विषय

पेज

१ आम अर्जीदावा

५०३

—आम जवाब दावा या बयान तहरीरी

५०५

२ नालिश बाबत बकाया लगान

५०७

—उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

५०९

३ नालिश बाबत तमस्सुक सादा

५१०

—उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

५११

४ नालिश बाबत रुक्का (प्रोनोट)

५१२

—उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

५१३

५ नालिश बाबत उस मालके जो बेचा और हवाले किया गया

५१३

—उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

५१४

६ नालिश बाबत इस्तेमाल और कब्ज़ा

५१५

—उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

५१५

७ नालिश बाबत तोड़े जाने साझीदारीके

५१६

—उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

५१७

८ नालिश बाबत हक आशाइस वास्ते निकलने रास्ता और हुक्म इस्तनाई

५१८

—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा

५१९

९ अदावतन मुकद्दमा चलाये जानेके लिये नालिश

५२०

—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा

५२१

१० बस्तीके ऊपर नालिश, बाबत दिलापाने उस आमदनीके जो बस्ती-यतनामेमें बताई गयी है

५२१

—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा

५२२

११ दस्तावेज रेहननामाके ऊपर नीलाम या बैचातकी नालिश

५२३

—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा

५२५

१२ नालिश बाबत दस्तावेज रेहननामा दखली या गैर मामूली

५२६

विषय

- उपरोक्त मुकद्दमेमें बयान तहरीरी
- १३ नालिश बाबत इन्फिकाक रेहन
—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा
- १४ न.लिश बाबत बेदखली
—उपरोक्त मुकद्दमेमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी
- १५ कानून दादरसी खासकी दफा ९ के अनुसार नालिश
—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा
- १६ नालिश बाबत दिलापाने उस रुपयेके जो किसी शख्सको उसके हक्के अनुसार मिलना चाहिये था
—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा
- १७ नालिश वास्ते बटवारा
—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा
- १८ मय वासलात जायदाद पर कब्ज़ा दिलापाने की बाबत हकी-यतकी न लिश
—उपरोक्त मुकद्दमेमें जवाब दावा
- १९ मालिककी ओरसे कारिंदोंके हिसाबकी बाबत नालिश
—उपरोक्त मुकद्दमेका बयान तहरीरी

जरूरी जरूरी अर्जियोंके नमूने

- २० कुर्क किये हुए मालकी निस्वत दावा
- २१ प्रोवेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिये अर्जी
- २२ प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रके वास्ते नालिश
- २३ प्रोवेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिये दीगई अर्जीकी नोटिस
- २४ बली मुर्करर किये जानेके लिये अर्जी
- २५ वरासतके सार्टीफिकेटके लिये दरख्वास्त
- २६ किसी पागलका बली मुर्करर किये जानेके लिये दरख्वास्त
- २७ ऋणीकी दरख्वास्त वास्ते दिवालिप्रा करार दिये जानेके
- २८ जबती भाराजीके मामलेमें दावा (बंगाल)
- २९ कानून ज़बती भाराजी की दफा १८ के अनुसार दीवानीमें मामले का दिया जाना
- ३० याद दास्त अपील
- ३१ आम मुख्तार नामा
- ३२ मुख्तारनामा खास
- ३३ पट्टा बंगाल
- ३४ दिवानामा (दानपत्र)

विषय

३५ वयनामा	५५४
३६ रेहननामा	५५५
३७ इकरारनामा	५५६
३८ वस्तीयतनामा	५५७
३९ तक़सीमनामा	५५८
४० खास किस्मका वयनामा अर्थात् खर्चके बद्दले जीतने पर जाय- दाद मिलनेका वयनामा	५५९
—इन्दुलतलब रुक्का	५६२
—मकान खाली करा पानेका नोटिस	५६२



कोर्टफीस ऐक्ट

नं० ७ सन १८७० ई०

—:—:—

शिड्यूल नं० १

अदालतमें नालिश करनेके लिये कोर्टफीसकी शरह

५६७ से ५७१

सिविल जनरल रूल्स

३१ जनवरी सन् १९२७ ई०

नकलौकी फीसें

डिकरी, सप्रवीज़ या अन्य कागज़

५०३

तलबाना आदिकी फीसें

तलबाना, गवाह तलबी, कुर्की, वारंट, नीलाम, आदिकी फीसें

५७४

दस्तावेजों पर स्टाम्प

इन्डियन स्टाम्प ऐक्ट नं० २ सन १८६६ ई०

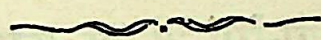
दस्तावेजों व अन्य कागज़ों पर लगने वाले स्टाम्प

५७५ से ५९४

इति ।

बम्बई पुस्तकालय

चौक-कानपुर



आपको जब कभी किसी संस्कृत या हिन्दी पुस्तककी जरूरत हो, फौरन एक चिट्ठी लिखकर बी० पी० से मंगा लीजिये । प्रायः हिन्दुस्थान भरकी पुस्तकें हमारे पास रहती हैं । आपको सब तरहकी पुस्तकें एकही जगह मिल जावेंगी तथा खर्चकी बचत होगी । मूल्य बिल्कुल उचित लिया जायगा । वेद, वेदान्त, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पुराण, व्याकरण, काव्य, कोष, ज्योतिष, वैद्यक, मन्त्रशास्त्र, कर्म-काण्ड, नीति, माहात्म्य, व्रतकथा, स्तोत्र, महाभारत—आदि ऐतिहासिक, उपन्यास, सांगीत—राग—भजन, नाटक, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायणादि, जीवनचरित्र, दिग्विजय, आल्हा स्त्रियोपयोगी, बालकोपयोगी, महात्माओंके ग्रन्थ, होमियोपैथिक ग्रन्थ, मत्तावलम्बी ग्रन्थ, स्कूली पुस्तकें, खेल—तमाशों—किस्से की किताबें, कानूनी पुस्तकें, आदि विविध विषयकी, पुस्तकें, आपको एक ही जगह पर प्राप्त हो जायंगी ।

पता याद रखिये—बम्बई पुस्तकालय, चौक-कानपुर

छपाईका उत्तम और सहज साधन

कानून प्रेस

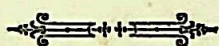


सुन्दरताके लिये भारतमें प्रसिद्ध बम्बईके नये टा
और बिल्कुल नयी मशीनोंमें अपना काम छपवाइये। चि
लिफाफा, फार्म, बिल, रसीद, रजिस्टर, परचा, नकशा, नोटि
और किताबें आदि हिन्दी, अङ्गरेजी तथा उर्दूमें बड़ी सा
धानी और सफाईसे छापी जाती हैं। छपाईकी सुन्दरता अ
आर्डरके अनुसार काम पूरा करानेमें बड़ी खबरदारीके सा
ध्यान रखा जाता है। आपको जो काम छपवाना हो डा
से भेजकर घर बैठे छपा लीजिये आपको प्रतिदिन पत्र लिख
की तकलीफ न उठाना पड़ेगी। बढ़िया काम छपानेकी या
इच्छा हो तो एक बार परीक्षा कर देखिये।

मैनेजर—‘कानून प्रेस’ कान

संग्रह जाबता दीवानी

ऐक्ट नं० ५ सन १९०८ ई०



अर्थात्

भारतीय दीवानी अदालतों की कार्यप्रणाली व्यवहार,
एवं उपयोगी मसविदों, क़ानूनों तथा
सूचनाओं सहित ।

प्रकाशक

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल



सवकिल और वकीलके



कर्तव्य

उद्देश्य—आज हम जाबता दीवानीको हिन्दीमें लिखनेके लिये उद्यत होते हैं। यह केवल अनुवाद नहीं है बल्कि भिन्न भिन्न स्थानोंमें फैले हुए विषय एक जगह करके तत्सम्बन्धी विषयको भाइयोंके लिये सरल हिन्दी द्वारा परम उपकारी एक नये ढंगका ग्रन्थ है। अंगरेजीके अच्छे विद्वान वकीलोंके लिये हम इस ग्रन्थके लिखनेका परिश्रम नहीं कर रहे हैं, हमारा परिश्रम हिन्दी जानने वाले तथा अदालती काम करने वाले भाइयोंके निमित्त है।

नोटबुक—हमारे देशमें जनता अंगरेजी कानूनसे बहुत कुछ अज्ञान है अदालतोंमें जो लोग किसी मुकद्दमेके सम्बन्धमें आते हैं वे बहुधा होशियार और कानून जानने वाले नहीं होते इसी लिये वे दलावों, अयोग्य सुहरिरीं तथा वकीलों द्वारा खूब ठगे जाते हैं उनके हितका वास्तवमें काम बहुत कम होता है। यदि भाग्यवश उनको किसी काम या मामलेमें सफलता मिल गई तो लोग अपनी योग्यता या पैरवीका फल बताकर शुकुराना या इनाम आविष्कार कर पेश करते हैं। नीचे हम अपने भाइयोंके हितके निमित्त कुछ बातें संक्षेपमें लिखते हैं जिनके जान लेनेसे और उन पर अमल करनेसे उनके मामलेको अच्छी तरह विधि पूर्वक लड़े जानेके लिये बहुत सहायता मिलेगी।

अगर आप कोई भी भाषा लिखना पढ़ना नहीं जानते तो अपने किसी अभिन्न हृदय मित्रसे, और यदि आप लिखना पढ़ना किसी भाषाका जानते हैं तो स्वयं, जो मामला अदालतमें जानेवाला है उसकी सब बातें एक साफ कोरे फागर्जमें पहले लिखते जाय। ज्यादा अच्छा यह होगा कि आप नोटबुक अर्थात् जेब या खलीतमें रखने लायक चौपतिया बनाकर उसमें अपने मामलेकी सब बातें लिखें। वह नोटबुक अपने पास रखें उसमें एक पेंसिल भी लगी रहे रास्तेमें या जहां कहीं आपके ध्यानमें कोई नई बात याद आजाय उसी समय उस नोटबुकमें लिखें। इस तरहकी लिख-घट रीतिस्तीब होगी इस बातका आप जरा भी ध्यान न दें। जहां तक हो सके नोटबुकके अन्दर जहां पर मामलेकी बातों का लिखन

आपने शुरू किया है उसी जगहसे आगेके पेजोंमें सब बातें लिखें। कभी ऐसा हो जाता है कि समयपर उस जगहपर लिखी बातें देखनेसे छूट जाती हैं। सिलसिलेको छोड़कर इधर उधर लिखी गई हैं इसलिये मामलेकी सब बातें ही सिलसिलेमें होना चाहिये। आप पहले यह खयाल न करें कि अमुक बात मतलबकी नहीं है या अमुक बात हमारे खिलाफ है या अमुक बात इस मामले सम्बन्ध नहीं रखती। पहले जो जो बातें आपको अपने पक्ष या अपने विरुद्ध आती जावें सबकी सब उस नोटबुकमें सिलसिलेसे लिखते रहें। आप जब किसी से अपने मामलेकी कोई बात पूछें या कोई अपनी तरफसे उस मामलेकी कहें और ऐसी बात जो नोटबुकमें उस समय तक नहीं लिखी गई है आप फौरन उस बातको या उन बातोंको नोटबुकमें लिख लें। साथ ही यह लिख लें कि वे बातें किसके जरिये आपको मालूम हुयीं और तारीख भी जगह लिख लें। आप तारीख और नाम लिखना सम्भवतः निरर्थक समझें परन्तु निरर्थक नहीं है। आपको उसके देखनेसे समय और उस व्यक्तिका सम्बन्ध आजायगा और बहुत सम्भव है कि उन बातोंमेंसे कोई ऐसी बात फिर आप जाननेकी ज़रूरत पड़े जाय या उन बातोंमेंसे कोई अपूर्ण बात रह गई हो या विशेष घटना पैदा हो जाय जिसके कारण आपको उस व्यक्ति और सम्बन्ध खोज करना पड़े। मेरा कहना तो यह है कि आप अपने मामलेके बारेमें रोचक जो काम करें उसकी एक जानने योग्य सूची नित्य लिख लिया करें। ऐसी रिपोर्ट अर्थात् दिनचर्यासे बड़ा भारी काम निकलता है कभी कभी ऐसा निकलता है कि जो हजारों रुपया खर्च करनेसे नहीं निकलता। मामले इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। आपको वाकिफ़कारी हर समय ठीक बनी रहेगी। सच्ची घटनाओंका चिट्ठा हर समय सामने रहेगा। अब जबानी बातें वकीलको समझाते समय भूल जाती हैं, पीछे याद आनेसे कुछ नहीं होता।

मवक्किल अक्सर कोरे कागजकी बहुत क़िफ़ायत करते हैं। कोरे कागजका खर्च उनको प्रायः अच्छा नहीं लगता। अपने मामलेकी बातें पर कागज़में बड़ी संकेतीके साथ लिखते हैं चाहे फिर उन्हींसे पढ़े न चले या पीछे समझ न सकें। हम आपको सलाह देते हैं कि कोरे कागजकी क़ादर अपेक्षा आपका मामला बहुत कीमती होता है और यह क़िफ़ायत बेहद बहुत खराब और बहुत ही निंदनीय है। मवक्किलों की बातें तो हैं ही हमने कतिपय वकीलोंको ऐसा करते देखा है। वकीलोंकी बातका हम प्रसङ्गमें उल्लेख करेंगे यहां पर हमें अपने भाइयोंसे कहना है कि आप कागजकी क़िफ़ायतको कभी दिल पर न आने दें। अपने पास आवश्यक कुछ अधिक अच्छे कागज हर समय रखें और अपने वकीलको भी अपने मतलबसे देते रहें। सरकारी छपा प्रत्येक फार्म अपने पास रखें।

नोटबुक उपरोक्त असंख्य रीतिसे जैसी जैसी तय्यार होती जाय वैसे वैसे नोटबुकसे अपने मामलेकी बातोंका खाताकी रीतिसे खतियान शुरू करते चलना चाहिये। एक बड़ा रजिस्टर बना लेना अच्छा होता है। यदि बहुत छोटा मामला है तो रजिस्टरकी ज़रूरत नहीं है सादे अलग अलग कागज़ों पर ही यह काम हो जायगा।

समयके अनुसार मामलेकी बातोंका विवरण—नोटबुकमें लिखी या न लिखी सब बातोंकी घटनाओंको समयके अनुसार तरतीबवार लिखलेना चाहिये। जिसबात या घटनाके पीछे जो बात या घटना हुई हो उसको उसके पीछे क्रमसे लिखें। जैसे सन् १९०१में जो बातें हुई हों उसके पीछे १९०२ या बाद वाले सनकी बातोंको लिखें। सनसे मतलब दिन, तारीख और महीनासे हैं। यदि अंगरेजी सन याद न हो तो तिथि और मास तथा सम्बत लिखिये। यदि यह भी याद न हो तो और निश्चित होना सम्भव न हो तो आप पहिलेकी घटनाको पहिले लिखें उसके बादकी घटना को पीछे लिखें। यदि आपको किसी घटनाकी तारीख या सन दोनों याद हैं और पीछेकी घटनाओंको याद नहीं है तो जो याद हैं उसके आगे पीछे जो घटना हुई उसे उसी प्रकारसे लिखलें। ऐसा न करें कि एक या कई घटनाओंकी तारीखें आदि याद हैं और कईकी नहीं याद हैं तो सबकी तारीखें छोड़ जाय। लिखनेमें जहां सन और तारीखका जिक्र करना चाहिये और आपको उस वक्त याद नहीं है तो थोड़ीसी जगह इसी मतलबसे उस जगह पर छोड़ दें ताकि जब याद आजाये तब उस जगह पर लिख दी जाय। ज्यादा अच्छा हो कि जहांपर इस मतलबसे जगह छोड़ी जाय उस छोड़ी हुई जगहमें ऐसी (.....) बिंदिया लगा दें ताकि दूरसे फौरन भालूम हो जाय कि इस जगह कुछ लिखनेसे छूटा है।

समयके अनुसार मुकद्दमेका विवरण लिखना सहज काम नहीं है। विवरणमें समयके क्रमसे मामलेकी आजतककी सब बातें ऐसे ढंगसे आजाना चाहिये कि पढ़नेवाला मामलेकी असलियतको फौरन समझ जाय। हम जानते हैं कि सब मवक्किल यह विवरण नहीं लिख सकते किन्तु बहुतेरे हिन्दी जानने वाले परम चतुर और योग्य हैं तथा हमारी सूचनाओंसे उन्हें मदद मिलेगी। जिस कागज़ पर यह विवरण लिखा जाय उसके बायें तरफ हिन्दी और अङ्गरेजी लिखनेमें व दाहिनी तरफ उर्दू लिखनेमें एक चौथाई कागज़ लम्बाईमें छोड़ दिया जाय। ऐसे छूटे हुए कागज़को हाशिया कहते हैं। जिस समयकी बात आप लिखें उस समयकी तारीख व सन आदि हाशिये पर लिख दें। लेकिन हाशिये पर सिवाय तारीख व सनके और कुछ न लिखें ताकि फौरन निगाह उसपर पड़ जाय। वाकियातको अन्दर लिखें। जहां कागज़ोंका हवाला आवे वहां उस कागज़की तारीख व सन व वह कागज़ कहाँ का है इसका जिक्र बराबर करते जाय। एक बात जो पहले लिख चुके हैं उसे फिर दुबारा न लिखें यदि भूल गये हों तो फौरन काट कर ठीक कर दें जिस घटनाका जिक्र करें उसे वहीं खतम

कर दें। यदि उसका सम्बन्ध पीछे आवश्यक हो तो कोष्टके अन्दर उसी जगह पर संकेत कर दें। इस तरह पूरा मुकदमा लिख जाने पर बार बार उसे पढ़ें, विचारें और सोचें फिर उसे ठीक करते रहें। इस ढंगसे काम करने पर आपका मामलेकी कोई बात नहीं छूटेगी।

विषय और समयके अनुसार विवरण—समयके अनुसार मामलेकी बातोंका विवरण बन जाने पर आप विषयवार एक विवरण और तैयार करें। ऊपर सब विषयोंको समयके अनुसार क्रमबद्ध किया गया। अब वाकियातों और कागजोंको विषयवार कर दें जैसे—पटवारी या कोई खास किसमके कागजात हैं तथा समयके अनुसार बीच बीचमें आगये हैं तो उन्हें एक एक किसमको उनके समयके अनुसार इसी तरह पर कर दीजिये। यह विषयवार खाता बन जायगा।

वकीलको समझाना और नकलें—मवक्किलको चाहिये कि विश्वासनीय वकीलसे सब बातें कह दे। जितनी बातें वे अपनी बात या दावाके समर्थनमें समझते हों चाहे वे कानूनी हों या न हों सब बातें वकीलसे कहें। यदि उपरोक्त रीतिसे लिख लिया है तो उसे दें। अपने खिलाफ भी सब बातें बता दें, कागजात दिखा दें, नोट करा दें, क्योंकि खिलाफ बात जाननेसे शत्रु पक्षका बल मालूम होता है और बचाव ठीक सोचा जा सकता है।

मवक्किलको जरूरी है कि अपने सब कागजातकी नकलें कर ले या करा ले। नकलोंमें इस बातका पूरा ध्यान रहे कि असल कागजमें जैसा जहाँपर लिखा हो वैसे ही नकल की जावे। नकलके बाद मिलान कर ले। एक हरफका या निशानका फरक न पड़े। असल कागजकी पुश्तपर जो इबारत हो उसको उसी तरह पर लिखले। नकल बड़ी होशियारीसे करना चाहिये कितने ही मुहर्रिर ऐसी नकल नहीं करते, वे इस कौशलको नहीं जानते इसलिये मवक्किलको इन बातोंसे सचेत रहना चाहिये। अपने और शत्रुके सब कागजोंकी ठीक नकलें जो अदालतमें दाखिल हों लेना जरूरी है। सब मिसिल एक तरतीबसे इकट्ठा रहना चाहिये। मवक्किलको एक ऐसी मिसिल अपने पास रखना भी चाहिये।

अदालतका खर्चा—खर्चा समय पर न देनेसे बड़ा मुकसान हो जाता है वही दशा कम खर्च दाखिल करनेमें होती है इसलिये मवक्किलको चाहिये कि अदालतका खर्चा वकीलके पास जमा कर दे ताकि ठीक समय पर दाखिल करनेकी जिम्मेदारी वकील पर हो जाय। ज्यादा अच्छा यह है कि रजिस्टर बनवाकर वकील साहबको दिया जाय जिसमें मुकदमेके नोट और अन्य सब बातें तथा खर्चा वगैरहका हिसाब लिखा रहे इससे कागजोंको खो जानेका डर नहीं रहता खर्चाकी रसीद प्रायः वकील लोग अपनी बचतके खयालसे नहीं देते खर्चा आदिका सब काम प्रायः मुहर्रिर करते हैं। रजिस्टरमें अपने सामने लिखवा देना चाहिये और वकीलको इत्तला कर देना योग्य होगा।

वकील पर विश्वास—मवक्किलका यह विश्वास गठित है कि बड़े वकील कमजोर मुकद्दमा जीत लेते हैं। बात यह है कि अच्छे वकीलके हाथसे अच्छा मुकद्दमा खराब नहीं होता और अयोग्य वकीलसे अच्छा मुकद्दमा बरबाद हो सकता है। अच्छा वकील कर लेनेके बाद यह न सोच लेना चाहिये कि बस अब सब काम वकील साहब कर लेंगे। वकीलके पास बहुत मामले रहते हैं इससे प्रत्येक बातमें उसे याद दिलाकर आज्ञानुसार सब कामबड़ी मुस्तैदीसे टाइम पर कर देना चाहिये, वकीलको बराबर सूचित करते रहना चाहिये जरूरी बातोंके नोट उसी रजिस्टर या नोटबुकमें कराते रहना चाहिये।

मुहरिरका कर्तव्य—यदि मवक्किलने ऊपर बताये हुए नियमोंका ठीक पालन नहीं किया या कुछ नहीं किया तो मुहरिरको चाहिये कि वह उपरोक्त विधिसे मामलेको तय्यार कर ले ताकि उसके वकीलका टाइम नष्ट न हो। आजकल अक्सर मुहरिर, तहरीर या फीसकी फिकरमें ही रहते हैं मामलेकी बातको समझना या तय्यार करना वे वकीलका काम समझते हैं। वे अपना धर्म सिर्फ यह समझते हैं कि जो कुछ वकील साहब मसविदा लिखदेंगे, हम साफ करके दाखिल कर देंगे या जो वे बोलदेंगे हम लिख देंगे। हम अपने भाई मुहरिरोंसे विनय करते हैं कि उनका पेशा बहुत ऊंचा है, वे वकीलके प्रधान अङ्ग हैं, वकीलको वे खतरेसे बचाये रख सकते हैं। इन्हीं लियाकत, कानूनकी जानकारी, कार्य कौशलता, मवक्किलके प्रति सद्ब्यवहार, ईमानदारी, काम करनेकी योग्यता आदि उन्हें यश और आमदनीका स्रोत खोल देती है।

वकीलकी काय प्रणाली—जब मवक्किल वकीलके पास आये तो उसे चाहिये कि मामलेके वाकियातको अच्छी तरह समझ ले मवक्किलकी सब बातोंको बगौर सुने और यह देखे कि क्या जो वाकियात वह बतला रहा है उससे स्पष्ट विनाय मुखासमत दावाकी पैदा होती है? या क्या उन वाकियातोंके आधार पर अदालतमें उसके सफल होनेकी आशा है? मामलेको समझते हुए वकीलको यह न भूल जाना चाहिये, अक्सर मवक्किल अपने वकीलको अपने पक्षके समर्थन की बातें बताते समय उमंगमें बिना इरादेके भी कमजोर बातें बताना भूल जाता है जिनका जानना कानूनी वकीलके लिये बहुत जरूरी है ताकि वह सही राय कायम कर सके। मवक्किलकी बातोंको आवश्यकतासे अधिक विश्वास न कर लेना चाहिये। वकीलके लिये न तो यह जरूरी है कि वह मवक्किलकी बातका विश्वासही न करे और न यह कि सबपर विश्वास ही करले। अक्सर मुकद्दमेंवाज सही सही वाकियात वकीलको नहीं बताते बल्कि जोशमें आकर गलत बयान करते हैं, बहुत सी बातें छिपाते हैं, इससे वकीलको बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं। ऐसे मवक्किलसे वकीलको चाहिये कि वह जिरहकी तौर पर सवालान्त करता जाय जिससे असलियतका पता चल जाय। इसके लिये यह जरूरी है कि वह सहाजुभूति प्रकट करे, उसकी तारीफ करे और निश्चय दिलावे कि मैं तुम्हारे

मामलेकी हृदयसे पैरवी करूंगा। अपने ऊपर विश्वास दृढ़ करावे और किसीतप से मुवक्किलके मामलेकी कमजोरी या उसकी गलत बयानीका पता लगावे। ऐसा कर लेनेसे फैसला वकीलके विश्वासके विरुद्ध न होगा। कमजोरी मालूम होजाने पर उसका उपाय ढूंढा जा सकता है। वकीलको सच्चे वाक्यातोंके जवाब लेनेकी पूरी कोशिश करना चाहिये। मामलेकी खास खास बातें पहले सामने रख लेना चाहिये। पीछे शहादत पर विचार करना चाहिये कागज़ी सुबूत जो उसके मुवक्किलके पास है कुल पढ़ जाना चाहिये। छांट कर पेश करने लायक कागज़ अलग कर देना चाहिये, पीछे यह देखना चाहिये कि किस कागज़से कौन बात साबित होगी। कागज़ोंकी तकमीलके बारेमें विचार करना चाहिये कि कानूनन सही हैं या नहीं, स्टाम्प ठीक है या नहीं। मुवक्किलकी इस बात पर विश्वास न करना चाहिये कि अमुक कागज़में अमुक बात लिखी है जब तक कि खुद न देख ले। पेश करने वाले कागज़ोंका खुलासा वकीलको खुद नोट कर लेना चाहिये जैसे—१ उस दस्तावेज़के फ़रीक़ २—मजमूनका खुलासा ३—तारीख़ तकमील और अन्दरकी तारीख़ें ४—किस बातका कतर्ता और किस बातका सामान्य सुबूत है ५—अन्य ज़रूरी बातें।

जबानी सुबूतको, कागज़ी सुबूतके सम्बन्धमें लेवे। यदि न हो तो पहले यह चुन ले कि कितनी शहादत दरकार है। जबानी सुबूतमें शहादतकी किस्मका ख़याल रखना चाहिये। गवाहोंकी तादादका नहीं। यह बात ग़लत है कि ज़्यादा गवाहोंसे बात साबित हो जाती है। गवाह थोड़े हों मगर वे असङ्गत न हों, विश्वासनीय हों। गवाहकी हैसियत, चालचलन, और विश्वासपात्रताका ध्यान रखना चाहिये। कौन गवाह क्या साबित करेगा इस पर मुवक्किलकी बातका विश्वास न मान लेना चाहिये, स्वयं जांच करके उसका बयान तय्यार कर लेना चाहिये। गवाहोंसे सवालात और जिरह करनेका कौशल पेज २६५ में तथा बहसका कौशल पेज ९२ में संक्षेप रीतिसे बताया गया है।

वकालतका पेशा प्राचीन है स्मृतियोंमें वकीलको 'प्राविट' नामसे कहा है यदि वकीलको झूठा और जालका मामला देख पड़े तो उसे चाहिये कि मुवक्किलको समझाकर वापिस कर दे या वह न माने तो स्वयं न ले। अदालती अमलाकी तहरीर या हक़से मुवक्किलको बचावे।

प्लीडिङ्स



(अर्थात् मसविदा)



मसविदा तैयार करना—मामलेके वाकियातको अच्छी तरह समझ लेनेके बाद वकीलको चाहिये कि वह ज्ञातता दीवानीके आर्डर ६ और ७ में बतलाये हुये नियमोंके अनुसार अर्जीदावाका मसविदा तैयार करे।

केवल अनुभव और अभ्याससे ही मसविदा तैयार करनेकी योग्यता प्राप्त की जा सकती है। एक नये वकीलके लिये सबसे अच्छा तो यह होगा कि वह कार्यारम्भ करनेके समयसे बराबर अर्जीदावा, बयान तहरीरी, अर्जियां वगैरा स्वयं लिखा करे और अदालतमें पेश करनेके पहले उसे किसी अपनेसे बड़े वकील को दिखा ले और दुरुस्त करा ले। जो वकील सब काम अपने हाथसे करनेका अभ्यास करेगा, वह उस वकीलकी अपेक्षा जो गैर-जुम्मेदार मुद्दारियों और दूसरे आदमियोंसे मसविदा कराता है, अच्छा मसविदा तैयार करनेका ज्ञान बहुत शीघ्र प्राप्त कर सकता है। अगर वह तमाम अर्जीदावा, बयान तहरीरी, अर्जियां वगैरा, ज्ञातता दीवानीमें बतलाये हुये नियमों तथा दूसरे कानूनोंके अनुसार तैयार करता है तो यह आशा की जाती है कि वे सब अच्छी तरहसे काममें लाये जानेके योग्य होंगे। उसे परिभाषिक शब्दों और कानूनी भाषाके लिये अधिक व्यग्र न होना चाहिये। अगर वे और सब तरहसे ठीक हैं और कानूनके मुताबिक तैयार किये गये हैं, तो उनमें इन कानूनी और परिभाषिक शब्दोंके न होनेसे कोई खराबी बाकै न होगी। ज्यों ज्यों अपने काममें उसका अनुभव बढ़ता जायगा उसे परिभाषिक शब्दों और स्थानीय भाषाका ज्ञान धीरे धीरे होता जायगा जो प्लीडिङ्समें अक्सर देखी जाती हैं।

एक बात और है जो एक नौसिखिया वकीलको करना चाहिये। वह यह है कि वह उन तमाम मसविदोंकी नकलें जमा करे और अपने पास रख छोड़े जो उसे होशियारीके साथ तैयार की गई मालूम हों और जो भिन्न भिन्न विषयोंके सम्बन्धमें हों। इनसे उसे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और आरम्भमें होनेवाली बहुत सी दिक्कतोंसे छुटकारा मिल जायगा। प्लीडिङ्स अर्थात् अर्जीदावा, बयान तहरीरी इत्यादि, के सम्बन्धी वे नियम जो ज्ञातता दीवानीमें बतलाये गये हैं उनके तैयार करते समय, स्मरण रखने चाहिये।

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि मुफसिलमें प्लीडिङ्स तैयार करनेकी कला अभी अपनी असली हालतको नहीं पहुँची है। अर्जीदावा और जवाब दावा अभी उसी तरहपर तैयार किये जाते हैं जैसे पहले किये जाते थे। बहुधा देखनेमें आता है कि प्लीडिङ्समें ऊट-पटांगकी बातें भरी रहती हैं, और जिनमें एकही

बात कई बार लिखी हुई होती है और बहुत सी असंगत बातें लिखी रहती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अक्सर उनका मसविदा तैयार करनेवाले वकीलोंके मुहरिरे हुआ करते हैं जिनको कानूनका उतना ही कम ज्ञान होता जितना कि और बातोंका। प्लीडिङ्स हिन्दुस्तानी भाषामें लिखी जाती हैं, मुहरिरे लोग, जिन्होंने कुछ प्रचलित फिकरे और महाविरे रट लिये हैं, उन हर एक मामलेके अन्दर प्रयोगमें लानेकी कोशिश करते हैं और उसमें अपने कृत को खूब दौड़ाते हैं। नतीजा यह होता है कि इससे मामलेके असली वाकियात एकत्र करने और उमूर तनकीह ढूँढ़नेमें बहुत सा समय नष्ट होजाता है। कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी भूलें और अशुद्धियां रह जाती हैं। यह परमावश्यक है कि प्लीडिङ्सका मसविदा स्वयं वकीलोंको ही तैयार करना चाहिये और अदालतमें पेश करनेके पहले बगौर देख जाना चाहिये। वकीलोंकी इस माफ़ी बहुत बड़ी जुम्मेदारी होती है, क्योंकि उसका सुवक़िफ़ प्लीडिङ्समें लिखी हर एक बातसे बाध्य होगा और उसमें ग़लती अथवा भूलका परिणाम बहुत भयङ्कर होजाता है। मैंने बहुत से अवसरोंपर वकीलोंको प्लीडिङ्समें लिखी बातोंके आवश्यक और अश्वयम्भावी परिणामोंको यह कहकर टालते हुये देखा कि इससे हमारा मतलब उस मतलबसे बिल्कुल भिन्न था जो इस समय लगा जा रहा है। लेकिन जिस शख्सने असलमें वे शब्द लिखे हैं उसने भूलकी है वह वह मंशाको ठीक तौरसे ज़ाहिर नहीं कर सका है। वास्तवमें मुकद्दमेंके समय तरहकी कोशिश बिल्कुल बेसूद है। इससे केवल वकीलके नामपर धब्बा ही आता है बल्कि सारा मुकद्दमा मिट्टीमें मिल जाता है, क्योंकि इससे ज़ाहिर होता है कि वह अपनी जुम्मेदारियोंसे बचना चाहता है। प्लीडिङ्स तैयार करनेमें बहुत बड़ी होशियारी रखनी चाहिये, क्योंकि वही उस मामलेका असली दाता है और इन्हीं प्लीडिङ्सके कारण मुकद्दमेंकी बहुत कुछ कामयाबी और नाकामयाबी रहती है। अभी एक हालके मुकद्दमेंमें चीफ़ जस्टिस मियर्सने कहा है:-

“इस अदालतमें वकालत करनेवाले सभी वकील साहबान इस बात सहमत होंगे कि गत दो वर्षोंमें एक भी सप्ताह खाली नहीं गया है जिसमें कि न किसी ओरके वकीलने यह बात स्वीकार न की हो कि वह जिस ढङ्गसे नीचे अदालतमें मुकद्दमा चलाया गया है उसके कारण बड़ी कठिनाईमें पड़ गया। और उनकी यह शिकायत केवल किसी कानूनी बुनियादपर ही नहीं होती बल्कि एक बहुत बड़े महत्वकी और आवश्यक बातके आधारपर, जैसे मामले बारमें बहस करनेमें बहुत बड़ी कमीका होना आर्डर ६—रूल ४ और ५। अलुसार जाबता दीवानीका आवश्यक बातों का प्राप्त न कर सकना, मुहरिरे मुद्दाअलेह अथवा और किसी ज़रूरी गवाहको तलब करनेमें असावधानी करना या जानबूझकर दस्तावेज़ात (कागज़ात) या हिसाबकी किताबोंका ख़र्च रखना।” देखो शिवदयाल बनाम जगन्नाथ, 68 I. C. 812 F. B., 20 L. J. 674.

प्लीडिङ्स:—जाबता दीवानी सन १९०८ ई० का आर्डर ६, जो प्लीडिङ्स के सम्बन्धमें है, बिल्कुल नया है। इसमें प्लीडिङ्सके सम्बन्धी कुछ नियम हैं जो प्लीडिङ्स लिखने के उसी ढङ्गके आधारपर जारी किये गये हैं जो इङ्ग्लैण्डमें न्यायालय सम्बन्धी कानूनों (Judicature Acts) द्वारा रायज़ किया गया है। वकील को चाहिये कि वह उसे खूब ध्यानपूर्वक पढ़ जाय और उसमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार ही अपना मसवेदा तैयार करे। अक्सर यह देखा जाता है कि प्लीडिङ्समें बहुत सी व्यर्थकी और असङ्गत बातें भरी रहती हैं और ऐसी दशा में इन व्यर्थ और ऊट-पटांगकी बातोंसे असली वाकियातको अलग करना मुश्किल होजाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उमूर तनकीह बढ़ जाते हैं और उस समय प्लीडिङ्ससे जो मन्शा होता है वह सबका सब नष्ट होजाता है। मुकद्दमाके फैसल होनेमें देर होजाती है और फरीकैनको व्यर्थका खर्च उठाना पड़ता है और कभी कभी उनका मुकद्दमा खारिज भी होजाता है। प्लीडिङ्सके सम्बन्धमें नियमोंके बनानेका उद्देश्य यह है कि मौजूदा हालतको और अधिक उन्नत बनाया जाय। और यह आशा की जाती है कि प्लीडिङ्स तैयार करनेमें विशेष ध्यान रखा जायगा। प्लीडिङ्स संक्षिप्त (सुक्ष्मसर) और ठीक ठीक होना चाहिये। इस व्यवस्थाका असली प्रयोजन यह है कि फरीकैनको तनकीहों का जवाब दूढ़नेमें आसानी हो और उनका व्यर्थमें धन और समय नष्ट न हो, खासकर उस शहादतके सम्बन्धमें जो दोनों ओरसे मुकद्दमोंके वक्त पेशकी जानी चाहिये।

प्लीडिङ्सका अर्थ है अर्जीदावा, बयान तहरीरी, आर्डर ६ के रूल ४ और ५ के अनुसार लिखी जानेवाली बातें, किसी दावा मुतकाबिलका जवाब, ज़ायद बयान तहरीरी इत्यादि। प्लीडिङ्समें असली वाकियातका संक्षिप्त वर्णन होना चाहिये जितके ऊपर फरीकई मुकद्दमा अपने दावा या सफाईको पेश करना चाहता है, वह शहादत नहीं जो उनको साबित करनेके काममें लाई जानेको है; और आवश्यकता पड़नेपर यह ऐसे पैराग्राफोंमें बांट दी जायगी जिनमें सिलसिलेवार नम्बर डाल दिये जायेंगे। तारीख, रकम और नम्बर अंकोंमें लिखे जाने चाहिये शब्दोंमें नहीं (देखो, आर्डर ६, रूल २)। नमूनाके सम्बन्धमें देखो जाबता दीवानीका परिशिष्ट (ए)। ज़रूरी बातोंमें वे वाकियात शामिल नहीं हैं जिनको साबित करनेका मुकद्दमोंके समय किसी फरीकईको हक है (देखो 22 C. L. J. 245)। आर्डर ७, रूल १ (ई) का कहना यह है कि अर्जीदावामें वे बातें होनी चाहिये जो कि दावाकी बिनाय-मुखासमत पैदा करती हैं। इसलिये अर्जीदावाके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसमें हानि इत्यादिकी सम्बन्धी बातें बढ़ाकर दर्ज की जायें और न यही आवश्यक है कि बयान तहरीरीमें हानि (मुकसान) को घटाकर बतलाया जाय (देखो, आर्डर ८, रूल ३)। प्लीडिङ्स में कोई बात ऐसी न लिखी जानी चाहिये जो विरोधी पक्षके उत्तरके बारेमें पहले से ही सोच लीगई हो। फरीकैनको वही बातें लिखनी चाहिये जो मुकद्दमोंके प्रारम्भमें आवश्यक हैं (देखो 1893. 1 Q. B. 571) प्लीडिङ्समें विरोधी पक्षके

इकबालको नहीं लिखना चाहिये, क्योंकि यह इकबाल सिर्फ शहादत ही (देखो 7 Ch. D. 473) ।

मुद्दईको यह अधिकार है कि वह बहुतसे भिन्न भिन्न अधिकारोंको काम लावे, फिर चाहे वह असंगत ही क्यों न हों देखो लार्ड जस्टिस ब्रेटका फैसला 4 Q. B. D. 127, 134—इसी तरह मुद्दाअलेह भी जितनी चाहे उतनी तरह और असंगत सफाई पेश कर सकता है । अगर दो अलग अलग मुकदमें काफ किये गये हैं तो उन दोनोंके वाकियात एकमें शामिल न कर देने चाहिये, इसलिये कि विरोधी पक्ष हर एक मामलेसे सम्बन्ध रखनेवाले वाकियातको छांट लेगा किन्तु वाकियात अलग अलग बतलाये जाने चाहिये ताकि उनसे यह जाना जासके कि किन वाकियातके ऊपर किस दादरसीके लिये दाखवास्त की गई है (देखो 3 Ex. D. 251, 255 में लार्ड चीफ जस्टिस थे सीजरका फैसला तथा आर्डर ८, रूल ७) । हिन्दुस्तानमें इसके लिये कोई दूसरा नियम नहीं है । मुद्दा अलग अलग अपने बहुतसे अधिकारोंका प्रयोग कर सकता है, यद्यपि वे असंगत ही क्यों न हों (देखो 34 Cal. 51 F. B; 24 C. W. N. 145.) । लेकिन जैसा 15 Cal. 684 में जुडीशल कमेटीने बतलाया है, मुद्दईको बिल्कुल एक दूसरेके विरोधी वाकियातको अपने दावामें लिखनेकी इजाजत न दी जायगी, जिनमें एक दूसरेका घातक हो (देखो, 22 C. L. J. 254; 21 C. W. N. 939; 22 C. L. J. 309) अगर सफाई ऐसी है, जिससे मामलेमें बड़ी गड़बड़ी पड़ती हो तो अदालतको यह अधिकार होगा कि वह आर्डर ६, रूल १६ के अनुसार यह हुक्म दे कि उन दो असम्बद्ध सफाईके बयानोंमेंसे एक उड़ा दिया जाय (देखो 7 I. C. 167; 15. I. C. 382.) ।

उन प्लीडिङ्सके पेश करनेकी इजाजत तो है जो एक दूसरेसे असम्बद्ध हैं, लेकिन वह मुद्दई या मुद्दाअलेह, जो अपने असम्बद्ध बातोंको पेश कर सकनेके अधिकारका प्रयोग करना चाहता है और उन दोनों बातोंको ऐसे जवानी सुबूतसे साबित करना चाहता है जो बिल्कुल प्रतिकूल पड़ता है तो वह अपने आपको ऐसे सड़कके गढ़में डालना चाहता है जिसमेंसे उसका निकलना असम्भव नहीं तो कष्ट सम्भव तो अवश्य ही होजाता है; क्योंकि जो शहादत ऐसे दो मामलोंका समर्थन करनेके लिये पेश कीगई हो जो एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न हैं और एक दूसरेके नाशकहैं, उसपर मुश्किलसे विश्वास किया जासकता है (देखो 28 C. W. N. 131) ।

उन तमाम हालतोंमें, जिनमें प्लीडिङ्स पेश करनेवाला फरीक किसी गलत बयानी, धोखा, खयानत, जानबूझकर किये गये कसूर अथवा अनुचित दबाव डालनेके आधारपर अपना मामला चलाना चाहता है, और उन तमाम हालतों में, जिनमें मामलेकी खास खास बातें सविस्तार लिखी जाना आवश्यक हैं, वे तमाम बातें प्लीडिङ्समें तहरीरकी जानी चाहिये (देखो, आर्डर ६, रूल ४); अदालतको अधिकार होगा कि वह उस प्लीडिङ्समें कोई और विशेष बात और उससे अच्छी बात लिखे जानेके लिये इजाजत देसके (देखो आर्डर ६, रूल ५) । कोई भी

ऐसी शर्त, जो पहले की है और जिसके पूरा करनेके ऊपर वाद-विवाद किया जानेको है, साफ साफ लिखी जानी चाहिये (देखो आर्डर ६, रूल ६) । किसी सुआहिदेका इनकार कर दिया जाना सिर्फ उस तहरीर या फेलसे इनकार कर देना है । इससे यह कदापि न समझा जाना चाहिये कि यह इनकारी उसके जवाज़ (Legality) से या इस बातकी इनकारी है कि उसपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती (देखो, आर्डर ६, रूल ९) । लेकिन कभी कभी ठीक ठीक शब्दोंका लिखा जाना आवश्यक है अर्थात् किसी की ज़बानी या तहरीरके जरिये हतक-इज्जती (मान-हानि) करनेके मामलेमें वे शब्द लिखे जाने चाहिये जो मान-हानि करनेके लिये प्रयोगमें लाये गये हैं । अगर मामलेकी बुनियाद अदावत, खराब मनशा या ऐसी ही और किसी बातपर हो तो उनके अलग अलग वाकियात की तरहपर तहरीर किया जाना चाहिये (देखो आर्डर ६, रूल १०) । अगर किसी नालिशकी बुनियाद कोई नोटिस है तो उसे बतौर एक वाकियेके दर्ज किया जाना चाहिये (देखो आर्डर ६, रूल ११) । अगर बहुत से पत्रों (चिट्ठियों) या ज़बानी बात चीत आदिसे कोई सुआहिदा या कोई सम्बन्ध साबित होता हो तो ऐसे सुआहिदा या सम्बन्धको बतौर वाकियाके तहरीर करना चाहिये (देखो आर्डर ६, रूल १२) ।

दस्तखत और तस्दीक

हर एक प्लीडिङ्ग के ऊपर फरीक और उसके वकीलके (अगर कोई हो) हस्ताक्षर (दस्तखत) होंगे । लेकिन जब फरीक गैर हाज़िर होने या और किसी कारण से दस्तखत नहीं कर सकता तो उस पर किसी ऐसे आदमीके दस्त-खत होंगे जिसको उस पर दस्तखत करने, नालिश दायर करने या उसकी ओर से किसी मुकदमेंमें सफाई बग़ैरा पेश करने के लिये बाकायदा इजाज़त दी गई हो (आर्डर ६, रूल १४) ।

१—हर एक प्लीडिङ्गके नीचे प्लीडिङ्ग दाखिल करने वाले फरीक की या उनमें से किसी एक फरीककी या किसी दूसरे ऐसे शख्सकी तस्दीक होगी जिसकी निस्वत अदालत को यह यकीन दिला दिया जाय कि वह मामलेके वाकियात से बखूबी वाक़िफ है ।

२—तस्दीक करने वाले शख्स को चाहिये कि वह प्लीडिङ्गके नम्बर शुदा पैरा ग्राफोंका उल्लेख करते हुये उनमें यह लिखे कि कितने की तस्दीक वह अपनी ज़ाती जानकारीसे करता है और कितनेकी तस्दीक उस इत्तला के ऊपर करता है जो उसे मिली है और जिसके सही होनेकी निस्वत उसे यकीन होगया है (देखो 6 C. 675; 7 C. L. R. 413; 15)

३—इस तस्दीक के ऊपर तस्दीक करने वाले के दस्तखत होंगे और उसमें तस्दीक करने की तारीख और मुकाम भी लिखा रहना चाहिये, (देखो, आर्डर ६, रूल १५) ।

जब कि तस्दीक करने वाला शख्स फ़रीक मुकदमा या दरखवास्त कुनि
न्दाके अलावा कोई दूसरा शख्स होतो एक हलफनामा इस बातका दाखिल
किया जाना ज़रूरी है कि वह शख्स मामलेके वाक्यातको बखूबी जानता
है। साधारणतः यह भी हुआ करता है कि तस्दीक करने के लिये अदालतसे इजाजत
जत मांगने के लिये दरखवास्त दी जाय लेकिन यह कोई लाज़िमी बात नहीं है
(देखो 28 C. W. N. 687) । यही बात इजरा की दरखवास्त की तस्दीक
के सम्बन्धमें है देखो आर्डर २१, रूल ११ (२) आम तौर पर तस्दीक इस
तरह पर होना चाहिये:—

मैं..... (मुद्दई या उत्तका बाज़ाबता मुक़रर किया हुआ वकील या मुख्तार) इस मामलेके वाक्यातसे बखूबी वाकिफ हूँ और इस तहरीरके ज़रिये यह
इज़हार करता हूँ कि पैरा... .. में बतलाये गये वाक्यात और उसमें लिखी गयी
बातोंकी निस्वत मुझे खुद इल्म है कि सही हैं और यह कि पैरा में लिखी
हुई बातोंको मैं इतला और यकीनसे (जैसा कुछ हो,) जानता हूँ कि वे सही हैं और
मैं अपने मकान मुक़ाम (या अपने वकीलके मकान)
ऊपर आज तारीख ... माह ... सन् ... ई० को बवक्त ... बजे दिनके इस
पर दस्तख़त करता हूँ ।

दस्तख़त

(या अलामत या निशानी अंगूठा) नाम ...

बक़लम

दस्तख़त और तस्दीक कर चुकने पर बयान तहरीरी और अर्जीदावावाक्यात
एक मुख्तार दाखिल या पेश कर सकता है, लेकिन उनमें से किसी पर
दुबारा उसके दस्तख़त नहीं हो सकते । यदि अर्जीदावा या बयान तहरीरीमें दस्तख़त
न हों तो सिर्फ दस्तख़त न करने से ही अर्जीदावा नाजायज़ नहीं हो जाता
कभी ज़ाबते की है और वह किसी समय भी संशोधनके ज़रिये ठीक की जा सकती
है, (देखो 22 A. 55; 19 C. W. N. 1159; 19 C. W. N. 220 Notes; 17 C. W. N. 989; 2 C. L. J. 11.) । जब मुद्दई
सिर्फ तस्दीकके ऊपर दस्तख़त कियेहों लेकिन अर्जीदावाकेऊपर दस्तख़त न कियेहों
हों, तो वह अर्जीदावा दस्तख़त करने के लिये वापस कर दिया जाना चाहिये
या खुली अदालतमें दस्तख़त करा लेना चाहिये, परन्तु वह खारिज नहीं किया जा सकता,
(देखो 165 P. W. R. 1911; 1912 M. W. N. 1207.) ।

अगर तस्दीक ग़लत कीगई है तो उसके लिये ज़ाबता दीवानीकी १९१
१९१ के अनुसार दण्ड दिया जाना चाहिये, देखो 6 A. 626 किसी कारोरे
की ओरसे या उसके खिलाफ़ की जाने वाली नालिशोंमें प्लीडिंगके ऊपर
कारोरेषनके सिक्रेटरी या किसी डाइरेक्टर अथवा किसी दूसरे प्रधान अधिकारी
के दस्तख़त होने चाहिये जो मामले के वाक्यातसे वाकिफ हो ।

प्लीडिंगस का संशोधन और उसका नष्ट कर देना—

अदालत मुकद्दमेंके दौरानमें किसी भी समय प्लीडिंगमें लिखी हुई किसी भी बातको नष्ट कर दिये जाने या उसका संशोधन कर दिये जानेका हुक्म दे सकती है जो आवश्यक या निन्दित हों या जिनसे उस मुकद्दमेंमें स्वतन्त्र न्याय होनेमें कोई बाधा पड़ती हो अथवा दिक्कत या देर होती हो (आर्डर ६, रूल १६)। अदालत मुकद्दमें की किसी भी अवस्थामें दोनों फरीकैन में से किसी को भी यह आज्ञा दे सकती है कि वह अपनी प्लीडिंगस को इस तरह पर और ऐसी शर्तों पर बदल दे या उनका संशोधन कर दे जो उचित हों और ऐसे समस्त संशोधन इस तरहके होंगे जो फरीकैनके दर्मियानी झगड़ेके असली प्रश्नको तय करने के लिये आवश्यक होंगे (देखो आर्डर ६, रूल १७)। अगर कोई फरीक नियत समयके भीतर संशोधन न कर देगा तो उसको उस समयके खतमहो जानेके बाद या अगर कोई समय निश्चित नहीं हुआ है तो हुक्मकी तारीखसे चौदह दिनके भीतर संशोधन न कर देने पर उसे फिर दुबारा मौका इसके संशोधन कर देनेके लिये न दिया जायगा। अदालत इस मुद्दतको बढ़ा सकती है (देखो आर्डर ६, रूल १८)।

यद्यपि अदालत मुकद्दमेंकी किसी भी अवस्थामें संशोधन करनेकी इजाजत दे सकती है तो भी दरखवास्त जहां तक हो सके मुनासिब वक्त के अन्दर ही दे देनी चाहिये और जैसा कि नियम है प्लीडिंगस खतम होनेके पहिले ही, क्यों-कि यह बात अदालतकी इच्छा पर है कि वह चाहे प्रार्थना स्वीकार करे चाहे न करे। अगर संशोधन देरमें पेश किया गया हो तो अदालतको अधिकार होगा कि वह संशोधनको नामंजूर कर दे। जिस संशोधनके लिये प्रार्थना की जाय वह (१) ऐसा न हो जो दूसरे पक्ष (फरीक) के साथ अन्याय करता हो और (२) ऐसा होना चाहिये जो फरीकैन के दर्मियानी झगड़े के असली प्रश्न को तय कराने के लिये आवश्यक हो और (३) वह नेकनीयतीके साथ किया जाना चाहिये। अदालत इस संशोधन की बाबत दूसरे फरीकको खर्चा दिला सकती है। 'फरीकैनके दर्मियानी झगड़ेका प्रश्न' कानूनी नहीं बल्कि वाक्याती है तथा उसका तात्पर्य ऐसे प्रश्नसे है जिसको दोनों फरीक वास्तवमें तय करना चाहते हों, ऐसे प्रश्न से नहीं जो मुकद्दमेंके दौरानमें किसी एक फरीककी ओरसे पहले पहल पैदा किया गया हो, (देखो, रोलस बनाम डेविस 28 L. J. Ex. 287.) अगर संशोधन करने का अभिप्राय एक किस्म की नालिश को दूसरे किस्मकी नालिशमें तबदील कर देनेका है तो ऐसा संशोधन नामंजूर कर दिया जासकता है, फिर चाहे जिस अवस्था में उसके लिये प्रार्थना की गई हो इससे कोई मतलब नहीं, (देखो 19 B. 303; 9 C. 526; 12 B. 431.)

जब किसी अर्जीदावामें कोई संशोधन किया जाय तो मुद्दाअलेहको भी अपने बयान तहरीरीमें संशोधन करने या नया बयान तहरीरी दाखिल करने और नये दावा का खण्डन करनेके लिये, तथा शहादत पेश करनेके लिये

मौका दिया जाना चाहिये (देखो 16 I. C. 785; 12 C. L. J. 556; 24 I. C. 822; 20 C. W. N. 547)

जो संशोधन अदालतकी आज्ञासे किया गया हो वह कानून मियादकी दफा २२ के अर्थमें इजाफा या किसी दूसरे नये मुद्देका बना दिया जाना समझा जायगा, (देखो 19 C. W. N. 1913) । ऐसे संशोधन की इजाजत नहीं दी जा सकती जिससे किसी फरीफका अमने ऊपर चले गये दावाकी मियादके आधारपर पैरवी करनेका अधिकार नष्ट होजाय (देखो-20 C. W. N. 475; 36 A. 370; 29 M. L. J. 464.) ।

दूसरी अपीलमें संशोधनकी इजाजत न दी जानी चाहिये जबकि उसमें नई शहादत और नए सवालत शामिल हों (देखो 12 I.C. 200; 36 C. 481) कभी कभी फरीफकेनको बढ़ाये जानेके लिये दूसरी अपीलमें संशोधन करनेकी इजाजत दी जा सकती है (देखो 12 B. 158; 6 B. 670.) ।

नोट—एक बात और भी वकीलको ध्यान रखना चाहिये कि जिस मुकद्दमेंकी पैरवी वह बाजमत तहरीर के अनुसार कर रहा है उसमें कोई ऐसी निजा या झगडा है जिसका सम्बन्ध उस वकीलकी किस्म खास जायदाद या हक से है और वह वकील उस मामले में अपनी जायदाद सम्बन्धी या हक सम्बन्धी प्रश्नको न उठावे और पीछे से नए मामले में भिन्न रूप से पैदा करे तो वह वकील ऐसा मामला ही नहीं उठा सकता इस विषय पर अनेक मामले फैसल हो गए हैं ।

वकालत नामा

वकीलकी नियुक्ति

१—जायदादीवानीके अनुसार किसी शख्सकी ओरसे किसी मुकद्दमें हाज़िर होने, कोई दख्ख्वास्त वगैरा दाखिल करने या कोई नालिश दायर करने के लिये किसी वकीलकी नियुक्ति बज़रिये एक तहरीरी वकालतनामाके होगी और उस पर उस शख्सके या उसके मुखतार मजाज़के या किसी ऐसे दूसरे आदमीके दस्तखत होंगे जिसको बज़रिये मुखतारनाम उसकी ओरसे ऐसा करनेका अधिकार दिया गया हो । (२) ऐसा हर एक वकालतनामा अदालतमें दाखिल होना चाहिये और वह उस समय तक जारी समझा जायगा जब तक कि वह अदालतकी इजाजत से किसी ऐसी तहरीरके ज़रिये उसको मंसूख न कर दिया जाय जिस पर उस मुवक्किल या वकील (जैसा कुछ हो) के दस्तखत होंगे और जो अदालत दाखिलकी जायगी, या जब तक कि मुवक्किल या वकील मर न जाय या जाय तक कि उस मुवक्किल के सम्बन्धकी उस मुकद्दमेंकी सारी कार्यवाई खतमा हो जाय । (३) किसी हाईकोर्ट या चीफकोर्ट के ऐडवोकेट या किसी वैरिस्टर ऐसा कोई वकालतनामा दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है, (देखो आर् ३, रूल ४) ।

नोट—मदरास में आर्डर ३, रूल ४ में सब-रूल (४) भी जोड़ दिया गया है ।

वकालतनामा कैसे मंजूर किया जा सकता है ?

किसी वकालतनामा को मंजूर करते समय जिसकी तकमील स्वयं किसी मुवक्किलने ही की है वकीलके लिये यह लाजिमी है कि वह इस बातका इतमीनान कर ले कि उसकी तकमील उसीने की है और जब उस मुवक्किलकी ओरसे किसी तीसरे आदमीने उसे लिखा हो तो उसके लिये इस बातका निश्चय कर लेना लाजिमी है कि उस शख्सको मुवक्किलने वकील मुकर्रर करने के लिये बाज़ाबता इजाज़त दे दी है और यह कि उसीने यह 'वकालतनामा' लिखा है। वकालतनामा दाखिल करते समय प्लीडर या वकीलको चाहिये कि वह उसकी पुस्त पर (अ) वकालतनामा मंजूर करनेकी तारीख (ब) उस शख्सका नाम जिससे वह प्राप्त हुआ है और (स) अगर वह ऐसा शख्स है जो न तो मुवक्किल है और न वकील, प्लीडर या मुख्तार तो उस शख्सके अधिकारके बारेमें (ध) मय तारीखके लिख दे। अगर 'वकालतनामा' की तकमील करने वाला शख्स पढ़ा लिखा आदमी है तो उस वकालतनामाके ऊपर अलामत या अंगूठेका निशान बना देना चाहिये और उस पर कोई दूसरा आदमी उसका नाम लिख देगा और अपना वकलम लिखकर उसपर दस्तखत करनेकी तारीख डाल देगा।

जो वकालतनामा किसी एक वकीलने दाखिल किया है उसे बादमें दूसरा वकील ले सकता है, जिसका नाम उस 'वकालतनामा' पर पहले से मौजूद हो, अगर उसे ऐसा करनेके लिये वह शख्स अधिकार दे जिसने कि वह वकालतनामा लिखा हो। उसकी तकमीलकी हो, (देखो V Rule. C. No. 5 of 1916 Post.)। लेकिन ऐसे बाद वाले वकालतनामा की मंजूरी करनेकी दशामें उसकी पुस्त पर तस्दीक की जाने वाली बातें वही रहेंगी जो पहली बार लिखी गई थीं।

तस्दीक का फार्म

१—मुसम्मा से, जिसके बारे में मुझे यह यकीन हो गया है कि वह मुद्दई। मुद्दाअलेह नं० है और जिसने बाज़ाबता इस वकालतनामा को लिख दिया है वसूल पाया और उसे मंजूर कर लिया।

... .. वकील
... .. (तारीख)

२—वह वकालतनामा, जिसे मुसम्मा मुद्दई। मुद्दाअलेह नं० ने बाज़ाबता लिख दिया है, मुसम्मा से, जो, मुझे यकीन होगया है, उसका मुख्तार मज़ाज़ या बाज़ाबता मुकर्रर किया हुआ कारिन्दा है, पाया और उसे मंजूर किया।

... .. (वकील)
... .. (तारीख)

३—यह 'वकालतनामा' जिसे मुसम्मा ...
 मुद्दाअलेह नं० ... ने बाज़ाबता लिख दिया है, मुसम्मा ...
 से, जो मुझे यकीन हो गया है उसका भाई या नौकर है और जिसके पास तारीख
 ... तहरीरी अक़्त्यारनामा उसे पेश करने का दिया गया है, पाया
 उसे मंज़ूर किया ।

... (वकील)

... (तारीख)

४—बाद में वकालतनामा का मंज़ूर करना मुसम्मा ...
 से, जो, मुझे यकीन हो गया है, मुद्दई । मुद्दाअलेह नं० ...
 जिसने बाज़ाबता वकालतनामा लिख दिया है [या मुसम्मा ...
 जो, मुझे यकीन हो गया है, मुद्दई । मुद्दाअलेह नं० ...
 कुनिन्दा का भाई या नौकर है और जिसके पास तारीख ...
 तहरीरी अक़्त्यारनामा मौजूद है] वकालतनामा मंज़ूर किया ।

... (वकील)

... (तारीख)

—हार्दकोटोंको छोड़ भिन्न प्रान्तोंके लिये दीवानी या फौजदारी अदालत
 वकालतनामा पर लगाया जाने वाला मुनासिब कोर्ट फीस एक रुपया या
 आना या दो रुपया भिन्न भिन्न है ।

उस चिट्ठी के ऊपर जो मुवक्किलने अपने वकीलको अपील दायर करने
 लिये लिखा था, मुनासिब कोर्ट फीस लगाया गया था और वह दाखिल की
 थी । तब हुआ कि यह माकूल अधिकार पत्र (इजाज़त नामा है) देखो 1 C. W.
 N. Coviii.

अगर कोई वकील बीमार या और ज़रूरी कामोंकी वजहसे हाज़िर न
 सके तो वह अपने मुवक्किलके मुकद्दमेंको ज़बानी दूसरे वकीलके हवाले
 सकता है, जो उसकी ओरसे उस मुकद्दमेंमें पैरवी करेगा, यद्यपि चाहे उसका नाम
 वकालतनामामें पहिले से मौजूद न हो, (देखो 9 A. 613; 22 B. 654; 23
 C. 799; 12 C. W. N. 888; देखो 20 B. 293; 20 C. W. N. 283)

जिस 'वकालतनामामें' वकीलका नाम न हो वह अधूरा है और जो कोई
 भी कार्रवाई उसके अनुसार की जायगी वह नाजायज़ होगी, देखो 36 A. 411
 11 C. L. J. 285; और 37 C. 399 में यह तय किया गया है कि अगर
 तारनामा में कोई भूल मालूम हो तो अदालतको पूर्ण अधिकार है कि वह उस
 संशोधन करनेकी इजाज़त दे देवे तथा उसका पहले जैसा ही असर होगा ।

आर्डर ३, रूल ४ के अनुसार, किसी वकील की नियुक्त बज़रिये तहरीर
 के होनी चाहिये, परन्तु उसका मंज़ूर करना तहरीरी होना आवश्यक नहीं है
 देखो 5 C. W. N. 816—जिस वकीलका नाम वकालतनामामें है उसका मंज़ूर

करना या उसका कार्य, अगर अदालत जिसके लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे आज्ञा दे दे, तो जायज़ और असर रखने वाला होगा, चाहे वकीलने उस वकालतनामाके प्रश्न पर तहरीरके जरिये तस्दीक नभी की हो। लेविज हाईकोर्टके रूल ४६ की, जिसमें तस्दीक करके मंजूर करनेकी व्यवस्था कीगई है, पाबन्दी करना आवश्यक है। यह रूल बहुत मुफीद है और बतलाई हुई रीतिसे सब जगह उसकी पाबन्दी की जानी चाहिये। मुफस्सिलकी अदालतोंको राजीनामा या रुपया अथवा कागज़ात की वापसीमें इस रूलका प्रयोग करने में विशेष सावधानीका ध्यान रखना चाहिये। अदालतोंको चाहिये कि वे उन वकीलों द्वारा इस रूलकी पाबन्दी किये जाने पर जोर दें जो उनकी इजलासमें आकर वकालत करते हों, और जो वकील उसकी पाबन्दी न करे तो उसकी बातोंकी समात न करें, (देखो 20 C. W. N. 287; 23 C. L. J. 297; 43 Cal. 884.

जब कि एक वकीलने, जिस पर बिना इजाज़त एक मुकद्दमाको फिरसे दायर करनेके लिये दरख्वास्त देनेका इल्ज़ाम लगाया गया था, अपनी सफाईमें यह कहा कि मुझे फरीकके मुख्तार के एक मुहरिरने ऐसा करनेके लिये कहा था और यह कि मुझे ग़लतीसे यह बतलाया गया कि जो वकालतनामा प्रारम्भिक मुकद्दमोंमें लिखा गया था उसमें मेरा नाम भी मौजूद था, तब हुआ कि उसने लीगल पैक्टिशनर्स ऐक्टकी दफा १३ (ए) को उल्लंघन किया। यह कि अगर 'वकालतनामा' में वकीलका नाम था तो भी सिर्फ़ ज़बानी मंजूरी हाईकोर्ट रूलके रूल ४६, क्लॉज़ (ई) की पाबन्दी न होगी।

जस्टिस रिचर्डसन:—वकालतनामा सम्बन्धी जो नियम हैं उनकी नीचेकी अदालतोंमें तामील किया जाना आवश्यक है। जजको अख्तियार रहता है कि वह किसी ऐसे वकीलकी बातोंको सुनने या उसको काम करने देनेसे इन्कार कर दे जिसने बतलाये हुये नियमोंके अनुसार वकालतनामा दाखिल नहीं किया है। जजका यह भी एक कर्तव्य है कि वह इस रूलका उल्लंघन करनेके सम्बन्ध में, जो उस समय उसे मालूम न हो सके, और जिसकी सूचना उसे बादको मिले जो कुछ उचित कार्रवाई समझे करे देखो 20 C. W. N. 283 तथा 2 Pat. L. J. 259.

यह नियुक्ति अदालतकी इजाज़त लेकर एक तहरीरके जरिये मंसूख की जा सकती है जिस पर मुवक्किलके दस्तख़त होंगे और जो अदालतमें दाखिल कर दी जायगी, देखो 36 C. 609.

डिकरीकी इजरा करनेके लिये लिखे गये 'वकालतनामा' में अदालतके बाहर रुपया लेने का भी अधिकार रहता है, देखो 22 I. C 277

वकालतनामाके सम्बन्धमें ज़िम्मेदारी

वकालतनामोंकी, चाहे उन्हें असली फरीकैन मुकद्दमा ने लिखा हो या उसके मुख्तारों और कारिन्दोंने, और उन मुख्तारनामोंकी जिनके अधिकारियों

के आधार पर ये वकालतनामों लिखे जाते हैं, हलफ़ के ज़रिये से तस्दीक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तमाम दस्तावेज़ों की, जो बाकायदा और सही लिखे गये हों, पूरी पूरी ज़िम्मेदारी वकीलों और प्लीडरों की होती है। यह कि उन अवस्थाओं में लागू नहीं होते जिनमें मुख्तार या एजेण्ट नियुक्त किये हैं। ऐसी सभी दशाओं में मुख्तारनामों की हलफ़ पर तस्दीक किया आवश्यक है, सिवाय उन मुख्तारनामों के जो उन मुख्तारों को लिखे गये जिन्होंने उस समय प्रचलित कानून के अनुसार सर्टीफ़िकेट प्राप्त किया हो, के R. 46 Ch. XI. G. R. C. O.

हाईकोर्ट में वकालत करनेवाले वकील अपने वकालतनामों के ऊपर मुख्तार या दूसरे आदमियों के नाम नोट कर लेंगे जिनसे उन्हें वकालतनामों प्राप्त हुए हैं।

वकालतनामा मंजूर कर लेने में ज़ुम्मेदारी—तमाम डिस्ट्रिक्ट जज और बाकी के तमाम मुत्सिफ़ सभी दर्जों के वकीलों को यह समझा देंगे कि जिन अदालतों में वे वकालत करते हैं उनमें स्वयं फ़रीक़ैन मुकद्दमा या उन लोगों की ओर से, जिनसे यह कहना है कि उनको आम या खास मुख्तारनामा के ज़रिये से दूसरे लोगों की ओर से कार्य करने का अधिकार दिया गया है, दिये गये वकालतनामों के मंजूर करने में उनकी क्या ज़ुम्मेदारी है (देखो, R. 46 A.)

वकीलों की ज़ुम्मेदारी पर अदालतें 'वकालतनामा' ले सकती हैं। वकील को जो कोई ऐसा 'वकालतनामा' मंजूर कर रहा हो जिसे स्वयं मुवक्किल ने ही लिखा हो, लज़िम है कि वह इस बात का इतमीनान कर ले कि उस तकमील वास्तव में मुवक्किल ने ही की है। जब उसके मुवक्किल की ओर से किसी तीसरे आदमी ने वकालतनामा लिखा हो तो उसे यह देख लेना ज़रूरी है कि उस शख्स को मुवक्किल, वकील मुक़रर करने के लिए बाकायदा इजाज़त दी है और यह कि उसी ने वकालतनामा लिखा है।

कोई भी वकील या प्लीडर फ़रीक़ मुकद्दमा, या उसके मुख्तार मजलस या उस शख्स के, जिसको उसकी ओर से काम करने के लिए बज़रिये मुख्तारनामा अधिकार दिया गया है, या उसके तौकर या रिश्तेदार या प्लीडर या वकील मुख्तार के सिवा जिसको इस सम्बन्ध में तहरीर के ज़रिये से खास इजाज़त दी गई है किसी दूसरे शख्स के दिये हुए वकालतनामा को मंजूर नहीं कर सकता (देखो R. 46 C. Rule no. 5 of 1916)।

जब एक से अधिक फ़रीक़ हों और वे अलग अलग वकालतनामा लेकर आवें तो उनमें से किसी एक का 'वकालतनामा' मंजूर किया जा सकता है जिसके उसके लिखने का अधिकार हो लेकिन अगर वे एक ही वकालतनामा लेकर आवें वह उनमें से किसी एक की ओर से या किसी ऐसे आदमी की ओर से लिया जा सकता है जिसको उनमें से किसी एक ने, जिसको दूसरों की ओर से काम करने का अधिकार है, बाज़ाबता अधिकार दिया हो, देखो R. 46 d—Rule no. 9 of 1916

जब वकालतनामा किसी वकील या प्लीडरने दाखिल किया हो, तो वह उसकी पुस्तपर उसके मंजूर करनेकी तारीख, उन लोगोंके नाम लिखेगा जिनसे वह मिला है और अगर ऐसा शर्खस, न तो खुद मुवकिल है और न वकील, प्लीडर या मुख्तार तो वह तारीखके सहित उस शर्खसका अधिकार कैसा और क्या है यह लिखेगा (देखो R. 46 e.)

जो 'वकालतनामा' अदालतमें दाखिल किया गया है उसको बादमें कोई वकील या प्लीडर मंजूर कर सकता है जिसका नाम उस 'वकालतनामा' में उस समय मौजूद था जिस समय वह पहले पहल दाखिल किया गया था; बादमें वकालतनामा मंजूर करनेपर उसकी पुस्तपर उसी तरह तस्दीक करनी चाहिये जैसी कि पहलेवार कीगई थी (देखो R. 46 F.) ।

मुकद्दमोंमें वकीलोंके अधिकारकी हद—मुकद्दमोंमें वकील और प्लीडर बिना किसी खास अधिकारके वह रकम नहीं लेसकता जो डिकरियोंकी इजरामें वसूल कीगई हो। डिकरीके अमलमें आते ही अर्थात् अदालतमें रुपया अदा कर दिये जानेपर (अगर डिकरी रुपयेकी बाबत है) वकील या प्लीडरको दिये गये अफ्तयारात खतम होजाते हैं । अदालतके बाहर रुपया लेना, इसके बादकी और दूसरी बात है और किसी वकील या प्लीडरको वह रुपया वसूल करनेकी इजाजत नहीं देनी चाहिये सिवाय उस दशाके जबतक कि उसके 'वकालतनामा' में कोई खास फिकरा या कोई दूसरी तहरीर ऐसी न हो जो उसे ऐसा करनेकी इजाजत देती हो। बाहरकी अदालतोंके सम्बन्धमें अगर वे कागजात जिनके साथमें वकालतनामा या वह दूसरी तहरीर नत्थी है, जिलेके मुहाफिज़खानेको भेज दिये गये हैं और ऐसे अधिकारको बिना उनके साबित न किया जासकता हो तो, उससे सम्बन्ध रखनेवाले वकील या प्लीडरके लिए यह आवश्यक है कि वह डिकरीका मतालवा वसूल पानेके लिये दीगई अर्जीपर इस बातका एक सार्टिफिकेट लिख दे कि उसे इसके दाखिल करनेके लिये आवश्यक अधिकार दिया गया है (देखो R. 47 Ch. XI G. R. C. O.)

नोट—आज कल अदालतोंमें वकील साहबान जो वकालतनामा दाखिल करते हैं उनमें रुपया उठाने की शर्त लिख दिया करते हैं। इस कारवाई में वकालतनामे के स्टामकी बचत जरूर है मगर यदि किसी अष्ट-चरित्र वकील से काम पड़ा तो मुवकिलको रुपयेके लिए खतरा भी है। समझ वृक्ष कर यह शर्त लिखी जाना चाहिए।

फरीक़ैन और दावा की बिनाय मुख़ासमत

फरीक़ैन और बिनाय मुख़ासमत दावा का शामिल किया जाना

ज़ाबता दीवानी ऐक्ट नं० ५ रून १९०८ ई० का आर्डर नं० १ रूल १ शामिल किया जाना मुद्दइयानका, और आर्डर १ रूल ३ शामिल किया जाना मुद्दालेहुमका, तथा आर्डर २ रूल ३ शामिल किया जाना दिनाय मुख़ासमत

दावा की व्यवस्था करता है। वकील साहबान को चाहिये कि वे इन कायदों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनमें बतलाये सिद्धान्तों को खूब समझ कर प्रत्येक वेदामामलेमें निश्चय करलें जो फरीकैन बनाने और दावा की विनाय मुखासम कायम करनेके बारे में बनाये गये हैं। हम नीचे संक्षेप से सबके समझानेका प्रयत्न करते हैं।

कौन लोग मुद्दई बनाए जा सकते हैं ?—एक मुकद्दमेंमें तमाम ऐसे आदमी मुद्दई बनाये जा सकते हैं जिनको एकही मुकद्दमें या किसी मामले के सम्बन्धमें हक दादरसी हासिल हो, फिर वह चाहे एक में हो या अलग, या ऐसा न होने की दशामें उस समय जब, अगर ऐसे लोगों ने अलग अलग मुकद्दमें दायर किये हों तो, कानून या वाक्यात का कोई मुश्तरक सवाल पैदा हो, (देखो, आर्डर १, रूल १) या यों कहिये कि आर्डर १, रूल १ एकही हक दादरसी रखने वाले बहुत से मुद्दइयों को यह अधिकार देता है कि वे अलग अलग मुकद्दमें दायर करने के बदले एकही मुकद्दमें में शामिल हो जायें।

इस रूल की 31 M. 252 में स्पष्ट व्याख्या करदी गई है। किन्तु यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि जब किसी मुकद्दमें में बहुत से आदमियों का सम्मिलित स्वार्थ हो तो उनका स्वार्थ एकसा ही समझा जायगा, एक दूसरेका विरोधी नहीं (देखो 16 B. 119; 28 B. 91; 22 C. 833 and 33 C. 367.) अगर उनका हक दादरसी एकही दावा या मामले से पैदा नहीं होता या अगर कानून अथवा वाक्यात का प्रश्न भिन्न भिन्न है, तो वे एकही मुकद्दमेंमें बतौर मुद्दई शामिल नहीं हो सकते। उन्हें उस दशा में अलग अलग अपनी नालिशें दायर करनी चाहिये।

यह वर्तमान रूल ज़ाबता दीवानी सन १८८२ ई० की दफा २६ से, जिससे इसका सादृश्य है, अधिक विस्तृत है। यह आवश्यक नहीं है कि विनाय मुखासम दावा एकही और एकही समान हों। बहुत से आदमी जिनके विनाय मुखासम दावा अलग अलग हैं, एकही नालिश में शामिल हो सकते हैं, अगर

(१) हक दादरसी एकही फेल या मामले से पैदा होता हो। और

(२) कानून या वाक्यात का कोई मुश्तरक सवाल पैदा हो।

इफ्तारनामा (मुआहिदा) के बारेमें यह हो सकता है कि किसी मुआहिदा के सम्बन्धमें ज़िम्मेदारी—

(१) अलग अलग

(२) एक में और अलग अलग और

(३) एक में हो।

आर्डर १, रूल ६ में यह बतलाया गया है कि मुद्दई एकही मुकद्दमें में उन तमाम आदमियोंको फरीक बना सकता है जो किसी करारदाद (मुआहिदा) के सम्बन्धमें, जिसमें बिल आफ् इक्सचेंज, हुण्डियां और प्रोनोट शामिल हैं, अलग

अलग, अथवा एक साथ और अलग अलग ज़िम्मेदार हैं। ऐसे मामलोंमें शामिलतामें या अलग अलग नालिशें दायर करनेमें कानूनी परिणाम क्या होता है, इस सम्बन्धमें देखो 3 C. 353; 5 M. 37; 25 B. 378; 22 A. 307; जब मदयुनान की ज़िम्मेदारी सिर्फ शामिलता में ही हो तो मुद्दईको चाहिये कि वह उस मुआहिदा मुश्तर्का लिखने वाले सभी आदमियों के ऊपर नालिश दायर करे, 5 C. 291; देखो कानून मुआहिदा की दफा ४३.

जब ग़लती से नालिश किसी ग़लत मुद्दईके नामसे दायर की गई हो तो अदालतको अधिकार है कि वह दूसरे अन्य लोगों के नाम मुद्दइयान में दर्ज कर दिये जाने या जोड़ दिये जाने के लिए इजाज़त दे दे। अदालतको यह भी अधिकार होगा कि वह अपनी मज़ी से या किसी फ़रीक के दरख़वास्त देने पर किसी ऐसे आदमी का नाम निकाल दे जिसका नाम ग़लत तौर से शामिल कर दिया गया है या किसी ऐसे आदमीका नाम बढ़ा दे जो शामिल किया जाना चाहिये था। देखो आर्डर १, रूल १०.

जहाँ पर कुछ आदमी किसी तरहका कोई हक़ रखते हों और दूसरे कुछ आदमी उस हक़की मुखालिफ़त करते हों, तो इनमें से एक या अधिक आदमी आर्डर १ के रूल ८ के अनुसार अदालतकी आज्ञा (इजाज़त) लेकर नालिश कर सकते हैं या उन पर नालिश दायरकी जा सकती है या वे अपनी बचतके लिये पैरवी कर सकते हैं। इस तरहके मुक़द्दमें की, जो बाकी हक़ रखने वाले आदमियोंकी ओर से दायर किया गया है, घोषणा कर देनी चाहिये।

शामिल न किया जाना या बेजा शामिल किया जाना—बेजा शामिल किया जानेका अर्थ है किसी ऐसे शख्सका शामिल किया जाना जो मुद्दई या मुद्दाअलेहकी तौर पर शामिल नालिश नहीं किया जाना चाहिये था, या किसी ऐसे शख्सको बतौर मुद्दई शामिल कर लेना जिसको बतौर मुद्दाअलेह शामिल करना चाहिये था और ऐसाही इसके विपरीत भी समझना चाहिये। फ़रीक़ैनका बेजा शामिल किया जाना उसी हालतमें होता है जब आर्डर १ के रूल और २ का ठीक ठीक पालन नहीं किया जाता है। अगर कोई ऐसा शख्स, जिसका शामिल करना आवश्यक था, शामिल न किया गया हो तो यह शामिल न किया जाना कहा जायगा।

बेजा शामिल किये जानेकी ग़लतीका सुधार आर्डर १ रूल १० के अनुसार किया जा सकता है और इससे बिनाय दावा या बिनाय जवाब-दही पर कोई खास असर नहीं पड़ता (देखो 34 B. B. P. 20) शामिल न किया जाने का सुधार आर्डर १ रूल ९ के अनुसार किया जाना चाहिये। फ़रीक़ैनका बेजा शामिल किया जाना और शामिल न किये जाने के सम्बन्धमें उज़्रदारी जहाँ तक जल्द हो सके करनी चाहिये, जब तककि बादमें कोई वजह पैदा न होगई हो (देखो आर्डर १, रूल १३)। यह उज़्रदारी अपीलमें नहीं की जा सकती देखो 14 M. 498; 16 B. 119; 6 A. 632.

कोई भी नालिश किसी फरीक के बेजा शामिल किये जाने या न शामिल किये जाने की वजह से नाकामयाब हो जायगी और अदालत को यह अधिकार होगा कि वह उस मामले को, जहां तक कि इसका सम्बन्ध फरीक के हकूक और हितों है, जो उसके सामने पेश किया गया हो, तय करे (आर्डर १, रूल ९) अदालत उन फरीक के हकूक को तय कर देगी जो उसके सामने पेश होंगे, बशर्ते कि वे तय किये जा सकते हों। यह रूल उस जगह पर लागू नहीं हो सकता जहां पर बहुतसे आदमियों के विरुद्ध विनाय मुख़ासमत साथ साथ पैदा होती हो (देखो 33 A. 630; 6 C. 815) आर्डर १, रूल ९; आर्डर ३४, रूल १ के आधीन है। अगर किसी बेहननामा के ऊपर की गई नालिश में ज़रूरी फरीक, मुकदमें में शामिल किये गये हों, तो वह नालिश ख़ारिज कर दी जा सकती है, देखो 9 A. L. J. 86; 1 Pat. L. J. 468; और देखो 10 A. L. J. 1341. भी आर्डर ३४ रूल १ में यह छूट रखी गई है कि अगर मुरतहिन अव्वल को नालिश में फरीक न बनाने का दावा चल सकता है।

कौन कौन लोग मुद्दाअलेह बनाये जा सकते हैं ? एकही मुकदमें में वे सभी आदमी मुद्दाअलेह बनाये जा सकते हैं अगर वह हक़ दादरसी, जो उनके विरुद्ध चलाई जाती है, एकही फेल या मामले से पैदा होती हो फिर वह चाहे एक साथ हो या अलग अलग अथवा किसी दूसरी बात के बदले में हो; और अगर उनके ऊपर अलग अलग नालिशें दायर की गई होतीं तो क़ानूनी या बाक़याती सबत एकसां पैदा होता (देखो, आर्डर १, रूल ३)।

एकही मुकदमें में भिन्न भिन्न विनाय मुख़ासमत के ऊपर जो एकही नालिश में शामिल कर दी गई है, बहुत से मुद्दाअलेहों को शामिल कर देने के पहले दो शर्तों का पूरा किया जाना ज़रूरी है, अर्थात् (१) यह कि उन तमाम मुद्दाअलेहों के खिलाफ़ हक़-दारसी एकही फेल या मामले से पैदा होता हो। और (२) यह कि अगर उन लोगों पर अलग अलग नालिशें दायर की गई थीं तो, क़ानून या वाक़यात सम्बन्धी कोई ऐसा सवाल पैदा हुआ हो जिससे उन सबका सम्बन्ध है (अर्थात् मुश्तरक सवाल पैदा हुआ हो) देखो, 13 Bom. L. R. 1061. मुद्दा को अधिकार होगा कि वह एक मुकदमें में बहुतसे मुद्दाअलेहों के विरुद्ध पैदा हो बहुतसे विनाय मुख़ासमत को शामिल करदे, अगर वे "इन विनाय मुख़ासमत में से किसी एक के लिए या सबके लिये शामिल करने में ज़िम्मेदार हैं"—उनका उन मुकदमें के मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध हो। यह आवश्यक नहीं है कि उन तमाम दादरसियों से, जिनके लिये दरख़वास्त की गई है, हर एक मुद्दाअलेह का सम्बन्ध हो (देखो आर्डर १, रूल ५); लेकिन यह आवश्यक है कि एक ऐसी विनाय मुख़ासमत हो जिससे उन सभी मुद्दाअलेहों का कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य हो, चाहे उनके खिलाफ़ जिस दादरसी का दावा किया गया है वह भिन्न भिन्न हो; देखो 34 B. 358; 31 B. 516.

कौन कौनसी विनाय मुख़ासमत एकही मुकदमें में शामिल कर दी जा सकती है ?—
(१) जब किसी मुकदमें में एक मुद्दाई हो, एक मुद्दाअलेह और दो अथवा अधिक

उन सभी विनाय मुख़ासमतों को एकही मुक़दमें में शामिल करदे, (देखो आर्डर २, रूल ३); लेकिन जहां पर विनाय मुख़ासमतें ऐसी हैं, जिनपर एक ही मुक़दमेंमें सुविधाके साथ विचार न किया जा सकता हो, तो उस दशामें अदालत उनके मामलेकी अलग अलग समागत किये जाने का हुक्म दे सकती है (देखो आर्डर २, रूल ६)

(२) जहांपर दो या अधिक मुद्दें हों और दो या अधिक विनाय मुख़ासमतें हों, तो उस दशामें वे सभी मुद्दें ऐसी तमाम विनाय मुख़ासमतोंको एकही मुक़दमेंमें शामिल कर सकते हैं, अगर उन सब मुद्दइयोंका या एक ही मुद्दाअलेह या कई मुद्दाअलेहों के विरुद्ध सम्मिलित दावा है। अगर उन सभी का सम्मिलित सम्बन्ध उन सभी विनाय मुख़ासमतोंमें है, तो ऐसी दशामें मुद्दइयान और विनाय मुख़ासमतका बेजा शामिल किया जाना कहा जायगा।

(३) जहां पर दो या अधिक मुद्दाअलेह या अधिक विनाय मुख़ासमतें हैं तो मुद्दें उन सभी मुद्दाअलेहोंके ऊपर एक ही में नालिश कर सकता है, अगर विनाय मुख़ासमतें एक ही हैं और अगर मुद्दाअलेहों के ऊपर मुत्तरका जिम्मेदारी है।

अगर किसी मुक़दमेंमें भिन्न भिन्न विनाय मुख़ासमतें भिन्न भिन्न ऐसे मुद्दाअलेहोंके खिलाफ़ शामिल कर दी जायं जो एक दूसरेसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते तो इस तरह मुद्दाअलेहों और विनाय मुख़ासमतका शामिल करना इस्तेमाल बेजा (Misjoinder) होगा (देखो आर्डर २, रूल ३ तथा आर्डर १, रूल ३),

निःसन्देह रूल ३ मुद्देंको यह अधिकार देता है कि वह एक ही नालिश में एकही मुद्दाअलेह या मुद्दाअलेहोंके विरुद्ध बहुत सी विनाय मुख़ासमतोंको शामिल कर सके; लेकिन यह मुद्देंको बहुत सी ऐसी विनाय मुख़ासमतोंको एक ही मुद्दाअलेह या मुद्दाअलेहोंको शामिल करने का अधिकार नहीं देता, जिनमें उन सबका कोई सम्मिलित सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि ऐसी दशामें उनका स्वार्थ भिन्न भिन्न और अलग है, 'सम्मिलित' शब्दका अर्थ यह है कि किसी मुक़दमेंके सभी मुद्दाअलेह ऐसे प्रत्येक और सभी विनाय मुख़ासमत के सम्बन्धमें एक ही साथ जिम्मेदार हों जिन्हें मुद्दें उन मुद्दाअलेहोंके विरुद्ध एक ही नालिश में शामिल करता है। मुद्दइयानको बहुत से मुद्दाअलेहोंके खिलाफ़ एकही नालिश में कई एक विनाय मुख़ासमतें शामिल करनेकी आज्ञा दिये जानेके पहिले शर्त यह है कि इन सभी मुद्दाअलेहोंका उस प्रश्नमें सम्मिलित स्वायं हो जो उस मुक़दमेंमें उठाया गया है। देखो 6 A. 106; 5 A. 163; 23 C. 821; P 826; 34 B. 358; 8 W. R. 15 (P. C.).

विनाय मुख़ासमतके बेजा शामिल किए जाने की हालतमें कार्यवाही:—विनाय मुख़ासमतके बेजा शामिल किए जाने के सम्बन्धमें उज़्रदारी जहां तक जल्द मुमकिन हो की जाली चाहिए और तमाम उन हालतोंमें जब उमूर तनकीह का फैसला हो गया हो तो ऐसे फैसले पर या उससे पहिले जबकि उज़्रदारीकी बिना

बादको पैदा हुई हो। और जो उज्रदारी इस तरह पर पेश न की जायगी तो उसके सम्बन्धमें यह समझा जायगा कि उज्रदारने अपना हक छोड़ दिया। देखो आर्डर २ रूल ७ जो आर्डर १ रूल १३ के ही समान है।

अगर ऐसे बिनाय मुख़ासमतके बेजा शामिल किये जानेकी वजहसे कोई अर्जीदावा सही नहीं है तो अदालत आर्डर ६ रूल १७ और १८ के अनुसार उसमें संशोधन किये जाने के लिये आज्ञा दे सकती है। तरीका कार्रवाईके बारे में देखो 34 C. 662; 9 A. 221. या वह आर्डर २३ रूल १ के अनुसार उन्हें उठा लेनेके लिए आज्ञा दे सकती है, जब कि उसमें बतलाई हुई वजहें वहां पर मौजूद हों। एक मुकद्दमा, जो बिनाय मुख़ासमतके बेजा शामिल किये जानेकी वजहसे ग़लत था, दूसरी अपीलमें भी अर्जीदावा में संशोधन किये जानेके लिए वापस कर दिया गया देखो 2 C. L. J. 602; 20 W. R. 240; 18 A. 131. उज्रदारी ज़ाया हो जाने के सम्बन्धमें देखो 13 Bom. L. R. 1061 and. 30 I. C. 24.

बिनाय मुख़ासमतके बेजा शामिल किये जाने का सुधार ज़ावता दीवानों की दफ़ा ९९ के अनुसार किया जा सकता है, अगर इससे मुकद्दमोंके ख़याद या अदालतके अख़्तियार समाप्तके ऊपर कोई असर न पड़ता हो।

पञ्चाबमें रूल ८ आर्डर ७ में शामिल कर दिया गया है यह बात छोड़ कर कि जहां पर आर्डर २, रूल ७ के अनुसार उज्रदारी कीगई हो, अदालत मुद्दोंको ऐसी बिनाय मुख़ासमत चुन लेने की, जिसके ऊपर वह कार्रवाई करेगा, और संशोधित अर्जीदावा पेश करनेकी इजाज़त दे देगी।

अर्जीदावा

अर्जीदावाका मतलब—अर्जीदावामें नीचे लिखी बातें लिखी जानी चाहिये—

- (१) उस अदालतका नाम जिसमें नालिश दायर कीगई है;
- (२) मुद्दोंका नाम, बलिदयत, उमर, कौम पेशा और सकूनत वगैरा;
- (३) मुद्दाअलेहका नाम, बलिदयत, उमर, कौम पेशा और सकूनत वगैरा, जहां तक वे मालूम हो सकें;
- (४) जब कोई मुद्दों या मुद्दाअलेह नाबालिग हो या उसका दिमाग़ सही न हो, तो इस बातका विवरण; तथा बलीका नाम, बलिदयत, कौम, पेशा, रिश्ता व सकूनत वगैरा।
- (५) वे बातें जिनसे दावा पैदा होता है (बिनाय मुख़ासमत दावा) और यह कि वह कब और कहां पर पैदा हुआ;
- (६) वे बातें जिनसे यह मालूम होता हो कि अदालत को अख़्तियार समाप्त हासिल है—
- (७) वह दादरसी जिसके लिये मुद्दों दावीदार है;

(८) जब मुद्दईने कुछ रकम मुजरा दे दी हो या अपने दावाका एक हिस्सा छोड़ दिया हो, तो मुजरा दीगई या छोड़ दीगई रकम, और तारीख आदि;

(९) अद्वयार समाप्त या कोर्ट फीस की गरजसे दावाकी मालियतकी तफ़्सील, जहां तक उस मामलेमें आती हो [देखो आर्डर ७ रूल १]

जब मुद्दई प्रतिनिधिकी हैसियतसे दावा करे—अर्जीदावामें सिर्फ़ यही नहीं दिखलाया जायगा कि उसके दावाकी मालियतसे वास्तवमें कोई सम्बन्ध है बल्कि उसमें यह बात भी लिखी रहेगी कि उसने तमाम आवश्यक कार्रवाई कर ली है जिसके कारण अब उसे उसके सम्बन्धमें दावा करने का अधिकार प्राप्त होता है [देखो आर्डर ७ रूल ४]

अर्जीदावामें क्या क्या बातें रहनी चाहिये—(१) अर्जीदावामें यह बात होनी आवश्यक है कि जिस सम्बन्धमें दावा किया जाता है, उससे मुद्दाअलेहका क्या सम्बन्ध है और उसे दावाका जवाब देनेके लिये क्यों तलब करना चाहिये [देखो आर्डर ७, रूल ५]

२ जब दावा मियादकी मुद्दत ख़तम होनेके बाद दायर किया गया हो, तो अर्जीदावामें यह बात दिखलाई जानी चाहिये कि किस बिना पर मियाद ख़तम होनेके बाद दावा दायर किया जा रहा है [देखो आर्डर ७ रूल ६]

नोट—जिन सूतोंमें दावाकी मियाद ख़तम हो जानेके बाद दावा दायर किया जा सकता है उनका वर्णन कानून मियादकी दफ़ा ५-२१ में किया गया है। अगर अर्जीदावामें मियाद ख़तम होनेके बाद दावा दायर करनेकी कोई खास वजह न दिखलाई जायगी और उस अर्जीदावामें जो कुछभी लिखा गया है उससे यह मालूम होगा कि दावाकी मियाद आरंज हो गई है तो अर्जीदावा ख़ारिज कर दिया जायगा [देखो आर्डर ७ रूल ११]; अगर मुद्दईने अर्जीदावामें ऐसा कोई कारण नहीं दिखलाया है तो बादमें वह उसे पेश नहीं कर सकता और न उस से कोई लाभ उठा सकता है [देखो 31 C. 195; 8 C. W. N. 171]; अगर अर्जीदावामें वजह दिखलाई तो गई है लेकिन उसकी निस्वत खास तौरसे दावा नहीं किया गया है तो अर्जीदावा ख़ारिज न किया जायगा [देखो 12 C; W. N. 617; 14 C. W. N. 128; 60 I. C. 772 (Lah)] अगर एक वजह दिखलाई गई हो तो मुद्दई दूसरी वजह भी पेश कर सकता है बशर्ते कि वह असङ्गत न प्रतीत हो [देखो 10 B. L. R. 346; 13 C. L. J. 139] आर्डर ७ रूल ५ का शब्दार्थ लेना चाहिये [देखो 46 I. C. 495 (Lah)]

३ अर्जीदावामें संक्षेपमें सिर्फ़ उन खास खास बातोंका वर्णन होना चाहिये जिनके आधार पर मुद्दईने अपना दावा दायर किया है। किन्तु उसमें वह शहादत न होगी जिससे उन बातोंकी पुष्टि होती है [देखो आर्डर ६ रूल २];

४ अगर ज़रूरत हो तो अर्जीदावाके अलग अलग पैरा-ग्राफ़ किये जा सकते हैं, जिनपर सिलसिलेवार नंबर पड़े होंगे, और उसमें कुछ तारीखें रकम और नम्बर अङ्कोंमें लिखे जाने चाहिये [देखो आर्डर ६ रूल ३]

५ अर्जीदावाका प्रसविदा तैयार करते समय पीछे दिये हुए परिशिष्टमें फ़ार्मों का या इसी तरहके फ़ार्मोंका इस्तेमाल किया जाना चाहिये [देखो आर्डर ६ रूल ३]

६ जब सुद्धई, मुदाअलेहकी गलत बयानी (Misrepresentation) धोखा (Fraud) ख़यानत, जान बूझकर गलती करने, नाजायज़ दबाव वगैराकी बिनापर का दावामें दादरसी का दावीदार हो, तो अर्जीदावामें ऐसी गलत बयानी, धोखा वगैराकी तफ़सील और उसकी ख़ास ख़ास मिसालें मय तारीख़ और मक़ान अगर ज़रूरत हो तो, हर तरह पर साफ़ साफ़ लिखी जानी चाहिये [देखो आर्डर ६ रूल ४]

नोट—धोखा देनेके सम्बन्धमें साधारणतया कोई बात लिख देनाही काफी नहीं है। इसके बिना यह ज़रूरी है कि जिस धोखा Fraud की निश्चित बयान किया जाता है वह साफ़ साफ़ और सही मय उन बातोंके लिखा जाना चाहिये जिनके आधार पर ऐसा कहा जाता है [देखो 23 C. W. 1045; 30 C. L. J. 475] अगर एक तरहका धोखा देनेका इल्जाम लगाया गया है तो उसे साबित न हो सकने की हालतमें दूसरा धोखेका इल्जाम नहीं लगाया जा सकता [देखो 20 W. N. 638].

७ अगर सुद्धई किसी मुआहिदे के ग़ैर क़ानूनी होने या उसमें क़ानूनकी क़ाबिल होने के आधार पर दावा करता है, तो उसे चाहिये कि वह इस बेक़ायदगी की क़ानूनकी डुटिकी बातको साफ़ तौरसे अपने अर्जीदावामें लिख दे। ऐसी सूचना में ख़ाली उस मुआहिदेसे इन्कार कर देना ही काफी नहीं है (देखो आर्डर ६ रूल ८)

८ जहां कहीं किसी दस्तावेज़में लिखी हुई बातें दावेमें लिखना ज़रूरी हो तो अर्जीदावामें संक्षेपसे उन बातोंका असर क्या हुआ है या क्या होगा, अर्ज लिखना चाहिये। जब तक कि उस दस्तावेज़के ठीक शब्दों या उसके किन्तु अंश का लिखा जाना ज़रूरी न हो (देखो आर्डर ६, रूल ९)

९ जहां कहीं अदावत, धोखा देने के इरादे, जानकारी या दूसरी दिमाग़ हालतका लिखना ज़रूरी हो, तो यह काफी होगाकि उसको, बिना उन कारणोंके दिखलाए जिनसे कि उसका अनुमान किया जाता है, उसे बतौर वाक़्याके अर्ज दावामें लिख दे (देखो आर्डर ६ रूल १०)

१० जहां कहीं नोटिसकी बात लिखना ज़रूरी हो, तो केवल इतना ही लिख देना काफी होगाकि ऐसा नोटिस अमुक तारीख़ या तारीख़ोंमें दिया गया लेकिन जो नालिशें सरकार या सरकारी अफ़सरोंके विरुद्ध, उनकी सरकारों हैसियतमें दायर की गई हैं, उन मामलोंमें नोटिसका ठीक ठीक मज़मून लिख देना चाहिये (देखो आर्डर ६, रूल ११ और दफ़ा ८०)

११ किसी शख़्सके साथ अगर कोई मुआहिदा किया गया है या कोई रिश्ता जोड़ा गया है, तो बिना कुल बातोंको विस्तारके साथ लिखे केवल के मुआहिदे या रिश्ताका होना बतला दिया जाय। (देखो आर्डर ६, रूल १२)

१२ कोई भी वाक़यात सम्बन्धी बात, जिसे क़ानूनने मान लिया है या जिसके साबित करनेका भार (बार सुबूत) दूसरे फ़रीक़ेके ऊपर है, अर्जीदावामें लिखे जानेकी ज़रूरत नहीं है (देखो आर्डर ६ रूल १३) क़ानूनके ऐसे अनुमान क़ानून शहादतकी दफ़ा ७९-९० में मिलते हैं।

१३ सिवाय नीचे लिखे दावोंको, अर्थात्—(क) वासिलात या बकाया लगन के दावे; (ख) किसी मुआहिदेके, जिसके अनुसार जायदाद पर कब्ज़ा किया गया है, तोड़ देनेकी वादत नुकसान वसूल पानेके दावे; (ग) दूसरा कोई दावा जिसके सम्बन्धमें उसी दिनाय मुखसमतके ऊपर दादरसी मांगी गई है। कोई भी दावा जायदाद गैर-मनकूला की वसूलयावी को दिलापानेके लिये दूसरी नालिशके साथ शामिल नहीं किया जा सकता है, जब तक कि इसके लिये अदालतसे मंजूरी न ले ली गई हो (देखो आर्डर २, रूल ४)

१४ जब कि दावा किसी तामील कुनिन्दा, प्रबन्ध कर्ता (मुहतमिम तर्का) या वारिसके ऊपर या उसके द्वारा उसके प्रतिनिधिकी हैसियत में दायर किया गया हो, तो उसके साथ स्वयं उस शख्सके ज्ञात खासके द्वारा या उसकी ज्ञात ऊपर किए जाने वाला दावा शामिल न किया जायगा। इस तरह से दावा शामिल करनेकी इजाजत सिर्फ उस वक्त दी जा सकेगी जब कि उसका खुदका दावा उस जायदादके सम्बन्धमें पैदा होता हो जिसके सम्बन्धमें वह बहैसियत तामील कुनिन्दा, प्रबन्धक या वारिसके या प्रतिनिधिके नालिश करता है या उसके विरुद्ध कीजाती है (देखो आर्डर २ रूल ५)

१५ जिस दादरसीके लिये दावा किया गया है उसको अर्जीदावामें डाफ़ साफ़ लिख देना चाहिये और यह आदश्यक न होगा कि आम दादरसी के लिये दावा किया जाय [देखो आर्डर ७, रूल ७; 17 C. W. N. 100; 8 M. L. T. 463.]

१६ जब मुद्दई कई अलग अलग दावों या दिनाय मुखसमत के सम्बन्धमें दादरसी चाहता हो जो अलग अलग और साफ़ साफ़ वजहों के ऊपर दायर किए गए हों, तो जहां तक सम्भव है वे अलग अलग और साफ़ साफ़ लिखे जाने चाहिये (देखो आर्डर ७, रूल ८)

अर्जीदावाकी भाषा—अर्जीदावा अङ्गरेजीमें या उस अदालतकी भाषामें लिखा जाना चाहिये जिसमें दावा दायर किया गया है। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई फ़रीक़ मुक़दमा या वकील अङ्गरेजी नहीं जानता है, तो उसके प्रार्थना करने पर उसकी एक नक़ल उस अदालतकी भाषामें उसे दे दी जायगी (देखो दफ़ा १३७) मुफ़स्सिलकी अदालतोंमें अर्जीदावा उस भाषामें लिखा जाता है जो साधारणतः उस ज़िले में प्रयोग की जाती है जिसमें वे अदालतें बाँके हैं।

स्थानीय सरकारको अधिकार होगा कि वह इस बातकी घोषणा कर दे कि हाईकोर्टकी मातहत अदालतोंमें किस भाषाका प्रयोग किया जाना चाहिये और ऐसी उन सब अदालतोंमें दी जाने वाली दरख़वास्तें आदि और की जाने वाली कार्रवाइयां उसी भाषा में लिखी जानी चाहिये

यहां पर 'भाषा' का अर्थ है लिपि और बोल चालकी भाषा। भारतकी प्रत्येक प्रान्तीय अदालतोंमें प्रांतिक लिपि और भाषाका प्रयोग होता है। गुज-

रातमें गुजराती, महाराष्ट्रमें मराठी, बङ्गालमें बङ्गाली, बिहारमें बिहारी, संयुक्त प्रान्तमें उर्दू लिपि और भाषाका प्रयोग बहुतायतसे होता है। ग्रीक प्रान्तीय लिपि और भाषा हिन्दी है एवं श्री लार्ड मेकडानल्ड महोदयके प. 2 सरकारी आज्ञासे अदालतोंमें हिन्दी लिपि की बकावट दूर हो चुकी है तथा लतोंमें हिन्दी लिपि और भाषाके जन्म सिद्ध अधिकारियों तथा हिन्दी के बाले वकील और अमलाकी अधिक संख्या है तिसपर भी शोक है कि अर्जी लिपिका प्रयोग इस प्रान्तमें नहीं हो रहा है। प्रातःकालके नक्षत्रोंकी तात्पर्य सज्जन अपने कागज़ात हिन्दी लिपिमें दाखिल करते हैं। एक ओर हिन्दीकी तात्पर्य भाषा बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है और हिन्दीका अधिकार क्षेत्र देखे बढ़ रहा है। देशी हिन्दू राज्योंमें सब जगहों पर हिन्दी है और जहाँ पर थी वहाँ भी अब हिन्दीका प्रयोग होने लगा। श्री जोधपुर श्री बेकानेर नक्षत्र विषयमें अधिक प्रशंसाके पात्र हैं। सी० पी० में पहले ही से हिन्दीका के श होता है। इस किताबके पाठकोंसे हम नम्र निवेदन यही करेंगे कि कोई के श कोई साध्य हिन्दीमें अपना काम काज करके हिन्दीको राष्ट्र भाषा बनानेमें सहायता दे। उस

अर्जीदावा बैरा किस कागज़के ऊपर लिखा जाना चाहिये और दस्तखतः—वे दस्तखत प्लीडिङ्स और अर्जियां, जो दीवानी मुकद्दमोंके दौरानमें दाखिल की जायें 110 फुलस्केप आकारके एक सादे वाटर मार्क कागज़पर लिखी जानी चाहियें या टाइप की जानी चाहिए या छापी जानी चाहिए। कागज़के सिर्फ़ ऊपर और चौथाई हाशिया और ऊपर नीचे कमसे कम एक इंच की जगह अधिक लिखी छोड़कर लिखना चाहिये। उन

जिस कागज़का ऊपर जिक्र किया गया है, वह आमतौर पर वाटर मार्क कागज़के नामसे प्रसिद्ध है और हर एक स्टाम्प फ़रोशके पास एक पैसा वाटर मार्क के हिसाब से बिका करता है। यह वाटर मार्क कागज़ सरकारी स्टाम्प फ़रोश या वकीलोंके बस्तेमें टिकट लगाने वाले अपना कमीशन सवकिल को दिया करते हैं। आम तौरसे यह कागज़ खजानेमें रहता है कहीं कहीं पर अदालतोंमें रहता है। उन

अर्जीदावेके ऊपर दस्तखत करना और उसकी तस्दीक ठीक तरी चाहिए तथा समन्सकी तामील आर्डर ५ के रूल १४ और १५ की पूर्ण के की जानी चाहिए। तस्दी

“दस्तखत” शब्द में अपने नामके केवल आदिके अक्षर ही न लिखे चाहिए पूरा नाम लिखना ठीक है देखो 23 C. 896. साधारणतः मुद्दा उसके वकीलके दस्तखत अर्जीदावाके हर एक सफाके सिरे पर दाखिल होने चाहिये। उसकी तस्दीक आखिरी सफाके नीचेकी जानी चाहिए। तस्दी

यह जरूरी है कि दस्तखत होनेके पहले अर्जीदावा लिखकर तैयार किया गया हो। किसी सादे कागज़के ऊपर दस्तखत कर देना काफी न

हारी, और नाजायज़ माना जायगा (देखो 15 A. 59; 25 A. 442 तथा 19 C. W. 220).

जिस अर्जीदावाके ऊपर किसी ऐसे शख्स ने हस्ताक्षर (दस्तखत) किये हों जिसके पास हस्ताक्षर करनेके लिये बाज़ाबता आम मुक़्तारनामा है, वह अर्जीदावा वाक़ायदा दस्तख़त किया हुआ माना जायगा, लेकिन अदालतको इस बातका इतमीनान हो जाना ज़रूरी है कि मुद्दईके अलावा जो शख्स अर्जीदावा की तस्दीक़ कर रहा है, वह उस मुक़द्दमेंके हालातको अच्छी तरहसे जानता है, देखो 4 B. 468; 25 A. 435]

जो अर्जीदावा कोई मुक़्तार मजाज़ पेश करे उस पर भी उस मुक़्तारके दस्तख़त होने चाहिये [देखो 3 C. L. R. 579; 3 C. L. R. 15]

यह ज़रूरी नहीं है कि वे कुल आदमी, जो किसी मुक़द्दमेंमें बतौर मुद्दई के शामिल हैं, अर्जीदावाके ऊपर दस्तख़त और उसकी तस्दीक़ करें, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई शख्स जो किसी मुक़द्दमेंमें शामिलाली मुद्दई है, उस समय तक मुद्दई न समझा जायगा जब तक कि वह अर्जीदावाके ऊपर दस्तख़त और उसकी तस्दीक़ न कर दें [देखो 17 C. 580; 1 B. L. R. 100; 10 W. R. 145] मगर जहां तक हो सके सबके दस्तख़त होना चाहिये, खास तौरतोंके अलावा ।

जो शख्स जेलख़ानेमें हैं, वह किसी दूसरे शख्स को दस्तख़त करनेका अधिकार देसकता है [देखो 40 A. 147] जो नालिशें भारतमन्त्रीके द्वारा या उनके विरुद्ध दायर की जायं, उनमें अर्जीदावा या बयान तहरीरीके ऊपर ऐसे शख्सके दस्तख़त होंगे जिसे सरकार, ख़ास या आम हुकूमके ज़रिए, ऐसा करने के लिये नियत (मुक़रर) करे, और कोई भी ऐसा शख्स उसकी तस्दीक़ कर सकेगा जिसे सरकारने इस कामके लिये मुक़रर किया हो और जो उस मामलेके वाक़यातको पूरी तौरसे जानता हो [देखो आर्डर ३७ रूल १, तथा 8 C. L. J. 34.]

जो नालिशें किसी कारपोरेशनकी ओरसे या उसके विरुद्ध दायर कीजायं, उनमें किसी प्लीडिंगके ऊपर उस कारपोरेशनकी ओरसे कारपोरेशनका सिक्रेटरी या उसका कोई डाइरेक्टर या उसका दूसरा खास अफ़सर, जो उस मामले के वाक़यात को बयान कर सकता है, दस्तख़त कर सकता है और उसकी तस्दीक़ भी कर सकता है [देखो आर्डर २९, रूल १]

दस्तख़त करते समय यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि दस्तख़त इस तरह से किए जायं कि जिस तरह वह आम तौरसे पहले सब कागज़ों पर करता है जिसकी लिखावट एक सां हो हरफोंमें फरक न हो । अर्थात् दस्तख़तकी गति विधि उसी तरह की हो जैसी हमेशा होती है । दस्तख़त करनेके लिए शब्द 'दस्तख़त' लिखना ज़रूरी नहीं है । अक्सर लोग अपने नामके पहले शब्द 'दस्तख़त' लिखकर पीछे अपना नाम लिखते हैं और अन्तमें लिखते हैं 'बक़लम खुद'

या 'खास'। दस्तखतसे मतलब नाम का है देखो जायता दीवानीकी दफा २ (२०) अकसर लोग अपने दस्तखत उस लिपिमें करते हैं जिस लिपिमें कागज़ लिखा होता है। अङ्ग्रेजी के लिखे कागज़ पर अङ्ग्रेजीमें और उर्दूमें लिखे कागज़ पर उर्दूमें एवं। मगर ज़्यादा अच्छा यह है कि दस्तखत उस लिपिमें किए जायें जिस लिपिमें उन्हें सबसे ज़्यादा अभ्यास हो और जिस लिपिमें वे प्रायः दस्तखत करते रहते हों।

कुछ लोगोंको ऐसा देखा है कि वे अङ्ग्रेजी लिखे कागज़ पर अङ्ग्रेजीमें दस्तखत करते हैं और उर्दू लिखे कागज़ पर उर्दूमें मगर उन्हें अङ्ग्रेजी और उर्दू का ज्ञान नहीं है वे हिन्दी जानते हैं। वे इसलिए ऐसा करते हैं कि उन्हें लोग अङ्ग्रेजी और उर्दू जानने वाला जाने। ऐसा करना केवल भूल नहीं है बल्कि बहुत बड़ी छाराबी का कारण है। उन्हें उसी लिपिमें दस्तखत करना चाहिए जिसमें उन्हें सर्वोपरि अभ्यास हो।

तस्दीक़ा तरीक़ा और उसका फार्म—तस्दीक़ करने वाले शख्सको चाहिये कि वह यह लिखे कि किन पैरा ग्राफ़ों (दफाओं) की तस्दीक़ वह अपने इल्मसे करता है और किनको वह दूसरोंके बतलाने पर सही मानता है।

जब अर्जीदावामें अपमान सूचक वाक्य भरे हों तो मुद्दईको स्वयं उस अर्जी दावा पर दस्तखत और उसकी तस्दीक़ करना चाहिये [देखो 6 C. 268 I. P. जब मुद्दई भारी धोखेका इल्ज़ाम लगाता हो या जब कि मामलेका सारा दामदार उस मुद्दईकी निजी जानकारीके ऊपर हो, तो उसकी तस्दीक़ उसीको करनी चाहिये [देखो 8 C. 885; 24 W. R. 215 और 9 A. 505]

जिन कागज़ोंपर तस्दीक़ लिखना ज़रूरी कर दिया गया है उनमें तस्दीक़ लिखते समय, तस्दीक़ करने वाले व्यक्तिको खुद बड़े गौरसे हर एक दफा या मजमून पढ़ते जाना चाहिये और हर एक दफा या मजमूनके टुकड़ेको दो भागों में विभक्त करके लिखते जाना चाहिये। यदि तस्दीक़ करने वाला व्यक्ति पढ़ा नहीं है या इतनी समझ नहीं रखता तो वकील या मुहर्निरको धीरे धीरे दफाओं को पढ़ते और उसे समझते तथा यह समझाते हुये कि वह उसे समझ गया है, इल्म और यकीनके वाक्योंको तरतीबवार लिख लें। तस्दीक़ बड़ी होशियारीसे करना ज़रूरी है कभी कभी तस्दीक़ पर से ही सारा मुकद्दमा उलटा हो जाता है भविष्यकी बातों पर विचार करके तस्दीक़ लिखना चाहिये।

तस्दीक़में यह लिखना चाहिये कि इतनी दफाएं या मजमून और इतनी दफाएं या मजमूनका इतना हिस्सा मेरी ज़ाती इल्मसे सच है तथा इतनी दफाएं या मजमून और इतनी दफाएं या मजमूनका इतना हिस्सा मैं दूसरोंके बतलाने पर सही मानता हूँ एवं यह तस्दीक़ अमुक मुकामपर आज ता०.....में कीगयी।

अर्जीदावा पर स्टाम्प लगाना—इसके बाद कोर्ट फीस की रकम, जो कोर्ट फीस ऐक्टके अनुसार लगाई जाना चाहिये, स्टाम्पकी शकलमें अदा किया जाना चाहिये जो छापा हुआ स्टाम्प हो या टिकटके रूपमें चिपकाया गया हो या दोनों तरहका हो देखो कोर्ट फीस ऐक्ट सन् १८७० ई० की दफा २५-२६।

जब कोर्ट फीसकी रकम १०) २० से कम हो और वह अकेला एक स्टाम्प चिपका कर लगाई जा सकती हो, तो ऐसा कोर्ट फीस उतने रूपथेका एक स्टाम्प चिपका कर लगा दिया जायगा। अगर स्टाम्प फरोशके पास उतनी कीमतका एक स्टाम्प न हो तो कई स्टाम्प भी उसकी कैफियतके साथ लगाये जा सकते हैं। जब कोर्ट फीसकी तादाद १०) २० या उससे ज्यादा हो और उस रकमका एक अकेला स्टाम्प मिल सकता है तो उतनी रकमका छपा हुआ स्टाम्प अर्जीदावा पर लगा दिया जायगा। अगर यह कोर्ट फीस एक छपे हुये या चिपकाये हुये स्टाम्पकी शकलमें न लगायी जा सकती हो तो उससे कम कीमत वाले छोटे छोटे एक या अधिक स्टाम्प लगा कर वह कमी पूरी कर दी जायगी।

अर्जी दावा, कोर्ट फीस ऐक्टकी दफा ६ में बतलाया हुआ कागज़ (Document) है (देखो 24 C. W. N. 38 P. C.) और कोई भी किसी किस्मका कागज़, जिस पर उस ऐक्टके परिशिष्ट (१) और (२) में बतलाये अनुसार स्टाम्प लगाया जाना चाहिये, किसी अदालतमें उस वक्त तक न दाखिल किया जायगा और न लिया जायगा जब तक कि उस पर पूरा कोर्ट फीस अदा न कर दिया जाय [देखो दफा ६] इस लिये किसी भी शख्सको अधिकार नहीं है कि वह बिना काफी कोर्ट फीस लगाये कोई अर्जीदावा अदालतमें दायर करे और न अदालत उसे लेनेके लिये बाध्य ही है। लेकिन अदालतको अधिकार है कि उचित कारणों के होते हुये वह किसी अर्जी दावा को, उस पर बिना काफी कोर्ट फीस लगाये हुये, दाखिल करनेकी इजाज़त दे दे और उस कमीको पूरा करनेके लिये वक्त दे [देखो ज़ायता दीवानीकी दफा १४९] अगर कोई अदालत किसी ऐसे अर्जी दावा को मंजूर कर ले जिस पर काफी स्टाम्प नहीं लगा है, तो वह इस बातके लिये बाध्य है कि आर्डर ७ रूल ११ (सी) के अनुसार अर्जी दावाको खारिज करनेके पहिले उस कमीको पूरा करनेके लिये वक्त दे [देखो 27 C. W. N. 566.] अदालत एकसे अधिक बार वक्त बढ़ा सकती है [देखो 34 C. 20 F. B.; 45 A. 518; 51 I. C. 154.] पुराने ज़ायता दीवानीमें बहुतसी विरोधी नज़ीरें थीं और वर्तमान ज़ायतेकी दफा १४९ ने इस प्रश्नको हल कर दिया है। समय बढ़ानेके सम्बन्धमें अदालतोंके अधिकारको बढ़ा दिया है [देखो 21 I. C. 866; 16 C. L. J. 34] समय बढ़ानेके लिये जो खास वजह होगी वह धोखेसेकी हुई ग़लती होगी [देखो 57 I. C. 215] नालिश दायर करनेकी तारीख, वह तारीख है जब कि अर्जीदावा दाखिल किया गया था, वह तारीख नहीं जब कि कमी कोर्ट फीस लगाया गया था [देखो 1 I. C. 780] इस बातके झगड़े अक्सर पड़ जाते हैं, तमादीका खवाल पैदा हो जाता है इस लिये इस बातको याद रखना चाहिये; जहां तक हो पूरा कोर्ट फीस साथ ही लगाया जाय यदि धोखेसे रह जाय तो जिस तारीखको मियादके अन्दर वह कमी पूरी की जायगी तो दूसरा पक्ष तमादी (यदि पैदा होती होगी) का उजुर पेश कर सकता है।

जब समय बढ़ा दिया गया हो लेकिन हुक्मकी तामील न की गई हो, तो दफा १४९ मुद्देकी कुछ भी सहायता न कर सकेगी और अगर कमी कोर्ट फीस

मियादकी मुदत खतम होनेके बाद लगाया गया हो तो नालिश खारिज कर दी जानी चाहिये (देखो 13 C.L.J. 78)

उस हुक्मकी अपील हो सकेगी जिससे अर्जीदावा इस बिना पर खारिज कर दिया गया हो कि उस पर काफी स्टाम्प नहीं लगा हुआ है (देखो 12 C.L.R. 148)

21 C. W. N. 934 में यह तय किया गया है कि जायदादी दीवानी के आर्डर ७ रूल ११ (सी) ताकीदी है अगर मुकदमे में मियादके अन्दर मुद्दे का कोर्ट फीसको पूरा नहीं कर सकता तो अर्जीदावा अवश्य खारिज कर देना चाहिये। अदालतको यह अख्तियार न होगा कि वह किसी अर्जीदावाकी निस्का यह हुक्म दे सके कि उसमेंसे कोई दादरसीकी मांग निकाल दी जाय जिससे कि वह अर्जीदावा एक ऐसे कागज पर लिखा हुआ समझा जा सके जिस पर काफी स्टाम्प लगा हुआ है, माना जा सके।

उन दस्तावेजोंका पेश करना और शामिल मिसिल करना जिसके आधार पर मुद्दे का दावा है—अगर मुद्दे किसी दस्तावेजके ऊपर नालिश करता है तो उसे चाहिये कि वह उस दस्तावेजको या उसकी एक नकल इस लिये दाखिल करे कि वह शामिल मिसिल की जाय।

अगर मुद्देके पास शहादतमें पेश करनेके लिये कोई दूसरा दस्तावेज हो (चाहे वह उसके कब्जेमें या अधिकारमें हो अथवा न हो), तो उसे चाहिये कि वह दस्तावेजका इन्दराज उस फेदबिस्तमें कर दे जो अर्जी दावाके साथ नथी कर दी जायगी (देखो आर्डर ७ रूल १४)

इस रूलके (युस्तनियान) रूल १८ (२) में मिलेंगे। जो रूल इस रूलके साथ पढ़ा जाना चाहिये इसमें उन दस्तावेजों (कागजात) के निस्वत जिक्र किया गया है जो मुद्दाअलेहके गवाहके ऊपर जिरह करने या मुद्दाअलेहकी ओरसे कही गई किसी बातके जवाब देनेके लिये या कानून शहादतकी दफा १५९ के अनुसार याददास्तको ताजा करनेके लिये पेश किये गये हों)

(२) अगर ऐसा कोई दस्तावेज (कागज) मुद्देके कब्जे या अधिकारमें न हो, तो वह अगर मुमकिन होगा तो, यह लिखेगा कि वह किसके कब्जे या अधिकारमें है (देखो आर्डर ७ रूल १५)

(३) अगर वह दस्तावेज (कागज), जिसके आधारपर मुद्देने नालिशकी है, किसी दूकानकी किताब (बहीखाता) या दूसरी किताबका इन्दराज है, तो मुद्देको चाहिये कि वह अर्जी दावा पेश करते वक्त उस किताब या हिसाबको मय उसकी एक नकलके दाखिल करे। अदालत या ऐसा अफसर जिसे अदालत नियुक्त करे और उस कागजके ऊपर पहिचानके लिये निशान डाल देगा और उस नकलकी जांच करने और असलसे उसका मिलान करनेके बाद, अगर वह

सही मालूम हो तो, उसके ऐसा होनेका सर्टीफिकेट दे दे और असल मुद्दईको वापस कर दे तथा नकलको दाखिल दफ्तर करनेका हुक्म दे दे (देखो आर्डर ७, रूल १७)

वकीलके मुहर्रिरको चाहिये कि जब वही खाते या ऐसी किताबके आधार पर नालिश की जाय किस किताबका जिक्र ऊपर किया गया है तो एक साफ नकल उस खातेकी या नकल वहीकी या खाते, नकल और रोकड़ वहीकी जहां तक कि हिसाब दावासे सम्बन्ध रखता हो अदालतमें पेश करे और मिलान कराकर असल वापिस ले ले। नकलमें गलती न रहने पाये। बाज़ू दफ्ता ऐसा देखा गया है कि हरफ तो कुछ नहीं छूटे अगर जगह ऐसे ठगसे उसके हिसाबमें छोड़ी गयी थी कि जिससे हाकिमको आइन्दा जाल बनानेका शक मजबूत हो नया था असलमें जहां पर कटा हुआ शब्द हो तो नकलमें भी वैसा ही होना चाहिये।

अर्जीदावाकी नकलों या दावाके संक्षिप्त विवरणका दाखिल करना—अगर अर्जी दावा मंजूर कर लिया जाय, तो मुद्दईको चाहिये कि वह सादे कागज़के ऊपर लिखकर उसकी उतनी प्रतियां दाखिल करे जितने कि मुद्दाभलेह हों। अगर अर्जीदावा बहुत बड़ा हो या मुद्दाभलेहोंकी संख्या अधिक हो या कोई दूसरे पर्याप्त कारण हों, तो मुद्दई अदालतकी आज्ञासे, उपरोक्त प्रतियोंके बदले उसकी उतनी ही संक्षेपमें लिखी हुई प्रतियां दाखिल कर सकता है। इस संक्षिप्त विवरण में दावाकी किस्मका या दादरसीकी किस्मका वर्णन होना चाहिए (देखो आर्डर ७, रूल ९)

जब मुद्दई किसी प्रतिनिधिकी हैसियतसे दावा करे या जब किसी मुद्दा-भलेहके ऊपर प्रतिनिधिकी हैसियतमें दावा किया जाय, तो इस संक्षिप्त विवरणमें यह बात लिखी जानी चाहिये कि किस हैसियतसे मुद्दईने दावा किया है या किस हैसियतमें मुद्दाभलेहके ऊपर दावा किया गया है (देखो आर्डर ७, रूल ९)

अदालतका शिर्षितेदार इन नकलों या संक्षिप्त विवरणकी प्रतियोंपर, अगर वे सही मालूम हों, अपने दस्तखत कर देगा (देखो आर्डर ७, रूल ९)

यद्यपि जायता दीवानीके आर्डर ७ रूल ९ में यह बतलाया गया है कि नकलें और संक्षिप्त विवरण अर्जीदावा मंजूर हो जानेके बाद दाखिल की जानी चाहिये, लेकिन आम रिवाज यह है कि वे अर्जी दावाके साथ नथी कर दी जाती हैं और उसीके साथ दाखिल की जाती हैं।

अर्जीदावाकी नकलोंके दाखिल करनेमें इस बातका ध्यान मुहर्रिर या वकीलको भले प्रकार रखना चाहिये कि वे सब नकलें सही हों, उनमें कोई बात किसी जगह पर छुट न गई हो, साफ साफ लिखी हों, ऐसे कागज़ पर लिखी हों कि वह मायूलीसे खराब न हो। अक्सर मजकिलके कहने सुननेमें आकर या अपनी मेहनत बचानेके लिये देगारकी तौर पर मुहर्रिर अर्जी दावाकी ऐसी नकलें दाखिल कर देते हैं कि जो सही होने पर भी पढ़ी नहीं जातीं। कभी तो वे इसी इरादेसे ऐसा लिखते हैं कि प्रतिपक्षी पढ़ न सके और कभी वे किसी नातजुर्वेकार

या किसी लड़केसे लिखा लेते हैं जिनमें ऐसे दोष हो जाते हैं कभी मवक्किलके खुश करनेके लिये जान बूझ कर न पढ़ा जाने वाला हरफ लिखते हैं और कहते हैं “देखो मैंने ऐसा लिखा है कि वे पढ़ी नहीं सकेंगे” । मूर्ख मवक्किल चाहे ऐसी हरकतोंसे प्रसन्न हो मगर उन्हें सोचना चाहिये और ध्यान रखना चाहिये कि इससे मुकद्दमेंमें बड़ा बुरा असर पड़ता है । दूसरे फरीक को मोहलत मिल सकती है । दुबारा नकलें दाखिल करनेका हुक्म हो सकता है हाकिमका मिजाज विग्न सकता है और अन्य बातें भी हो सकती हैं । इसलिये अर्जीदावाकी नकले, सही, साफ़ और योग्य रीतिसे लिखकर दाखिल करना ज़रूरी है । नकलें अकसर मुर्रिर ही लिखते हैं इसलिये उन्हें सचेत रहना चाहिये कि अपने मुकद्दमें और अपने वकीलके यशको रक्षित रखें ।

भाग २



नालिशका दायर करना

अर्जीदावाका पेश करना—ऊपर बतलाये अनुसार अर्जीदावा लिख जाने, उसकी तस्दीक हो जाने और उसपर काफ़ी स्टाम्प लग जाने के बाद, उस अर्जीदावाको अदालत या किसी ऐसे अफसरके पास, जिसे वह इस सम्बन्धमें नियुक्त करे, पेश करके नालिश दायर कीजानी चाहिये (देखो दफा २६ और आर्डर ४, रूल १ जाबता दीवानी)।

‘पेश करने’ का अर्थ यह नहीं है कि अर्जीदावा बजरिये डाक भेज दिया जाय बल्कि इसका मतलब यह है कि वह अदालतन या वकीलके जरिये अदालतमें पेश किया जाय देखो 18 M. 354. अदालत किसी अर्जीदावाको एतवार या दूसरे छुट्टी के दिन ले सकती है। अगर अर्जीदावा मजिस्ट्रेट अथवा जजके मकान पर या किसी दूसरे स्थानपर पेश किया जाय और वह उसे मंजूर कर ले, तो वह जायज़ होगा (देखो 79 I. C. 1017.) अगर मियाद खतम होती हो या दूसरी कोई ऐसी ही ज़रूरत हो तो उस हाकिमके घर पर या जहाँ पर हाकिम हो अर्जीदावा दाखिल किया जा सकता है।

अर्जीदावापेश करनेका अधिकार—अर्जीदावाको या तो मुद्दै खुद पेश कर सकता है या उसका वकील अथवा मुख्तार मजाज़ (आर्डर ३, रूल १)

जिन लोगोंके पास ऐसा मुख्तारनामा हो, जिसमें उन्हें फ़रीकैनकी ओरसे हाज़िर होने दरख़वास्त वगैरा पेश करने और काम करनेका अख़्तियार दिया गया हो या जो लोग ऐसे हों जिनके पास मुख्तारनामा नहीं है मगर वे उन फ़रीकैनकी ओर से या उनके नाम से व्यापार अथवा कारबार करते हों जो उस अदालतके अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर रहने वाले नहीं हैं, वे अधिकार प्राप्त मुख्तार माने जावेंगे (देखो आर्डर ३, रूल २)

आर्डर ३ रूल २ (ए) के अनुसार कोई भी ऐसा शख्स, जिसके पास आम या खास मुख्तारनामा है, मुख्तार मजाज़ है (इसमें मुख्तार तथा दूसरे ऐसे ही लोग शामिल हैं) खास मुख्तारनामा के ऊपर कोई भी शख्स अदालतमें हाज़िर होकर कार्य कर सकता है। अगर कोई शख्स खुद जाकर कोई अर्जीदावा पेश करे, तो उसके लिये इस बातकी ज़रूरत है कि कोई योग्य व्यक्ति उसकी शिनाख़त करे। किसी मुख्तार मजाज़ का यह अख्तियार न होगा कि वह मामलेमें बहस कर सके और गवाहों पर ज़िरह कर सके।

ऐसे मुख्तारोंके ऊपर हुक्मनामोंकी तामीलका यही असर होगा मानों वह स्वयं फ़रीक़के ऊपर ही तामील हुआ है (देखो आर्डर ३ रूल ३ और ५)

नालिश वहीं दायर की जायंगी जहाँ जायदाद मुतनाज़ा बाँके हो—(१) नीचे लिखी नालिशें उन अदालतोंमें दायरकी जायंगी जिनके अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर वह जायदाद बाँके हो जिसकी निस्वत दावा है—

(क) वे नालिशें, जो बाबत कब्ज़ा जायदाद ग़ैर-मनकूलाके दायर कीगई हों,

(ख) जो जायदाद ग़ैर-मनकूलाके बटवारा के लिये कीगई हों,

(ग) रेहन-नामाकी हालतमें या जायदादके ऊपर किसी तरह का कोई बार होने पर जो बयबात, नीलाम या फ़क़रेहनी की बाबत दायर कीगई हों,

(घ) जो किसी जायदाद ग़ैर-मनकूलामें किसी हक़ या हिस्सेको तय करनेके लिये दायर कीगई हों,

(ङ) जो जायदाद ग़ैर-मनकूलाको पधुँचाये गए लुक़्तानका सुआविज़ा दिलापानेके लिये दायर कीगई हों,

(च) जो उस जायदाद ग़ैर-मनकूलाके दिलापानेके लिए दायर कीगई हों, जो जुक़ या ज़ब्त करली गई हों (देखो ज़ाबता दीवानीकी दफ़ा १६)

ज़ाबता दीवानीकी दफ़ा १६ में यह व्यवस्था कर दीगई है कि जब, जिस दादरसीके लिये दावा किया गया है, वह मुद्दाअलेह की ज़ात खाससे ही हासिल हो सकती हो, तो ऐसी नालिश उस अदालतमें दायर की जासकती है जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर मुद्दाअलेह रहता है। उदाहरणार्थ हुक्म इम्तनाई जारी करनेके लिए कीगई नालिश (देखो 13 C. W. N. 346)

(२) वे नालिशें, जो ऐसी दादरसी के लिए दायर कीगई हों जिसका सम्बन्ध ऐसी जायदाद ग़ैर-मनकूला से है जो कई एक अदालतोंके अधिकार-क्षेत्र की सीमामें बाँके हों, उन अदालतोंमें दायर की जा सकती हैं जिनके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर उस जायदादका कोई हिस्सा बाँके हो (देखो ज़ाबता दीवानीकी दफ़ा १७)

(३) जहाँपर इस बातमें सन्देह हो कि दो अथवा अधिक अदालतोंमें से किस अदालतके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर कोई जायदाद ग़ैर-मनकूला बाँके है, तो उनमें से कोई भी अदालत, इस बातका इतमीनान हो जाने पर कि

इस सन्देहके लिए कोई कारण हैं, इस सम्बन्धमें एक तहरीर लिख देनेके बाद उस नालिशकी समाप्त करेगी (देखो दफा ६८)

अदालत समाप्तके सम्बन्धमें सन्देह होनेके लिए उचित कारण होना चाहिए । देखो C. L. J. 154.

(४) वह नालिश जो किसी हानिके लिये सुआदिजा दिलानेकी बाबत की गई हो जो किसी शख्सको या जायदाद मनकूलाको पहुँचाई गई हो, या तो उस अदालतमें दायर की जायगी, जिसके अधिकार क्षेत्रमें वह हानि पहुँचाई गई थी, या उस अदालतमें जिसके अधिकार क्षेत्रमें मुद्दाअलेह रहता है या व्यापार करता है (देखो दफा १९)

५ बाकी सभी नालिशें [सिवाय उनके जो ऊपर बतलाई जा चुकी हैं] उस अदालतमें दायर की जायगी जिसके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतर—
(अ) मुद्दाअलेह या हर एक मुद्दाअलेह या कोई भी मुद्दाअलेह (जब कि एक से अधिक मुद्दाअलेह हों) रहता हो या रोजगार करता हो या मुनाफेके लिए खुद कोई काम करता हो, या बिनाय सुखासमत, कुल या किसी अंशमें पैदा हुई हो [देखो दफा २०]

“सकूनत” से मतलब ऐसे स्थान से है जहाँ पर कोई शख्स खाता, पीता और सोता हो, या जहाँ उसके घर वाले अथवा नौकर खाते, पीते और सोते हों, देखो 13 C. L. J; 221. “रोजगार करता हो” और “मुनाफेके लिए खुद कोई काम करता हो” के अर्थके लिए देखो 40 C. 308; 18 B. 290; 8 C. 678; 14 C. 256 रोजगारका मतलब सिर्फ व्यापार ही नहीं है, देखो 14 B. 541; 18 B. 294 “रोजगार करता हो” से “खुद कोई काम करता हो” बिल्कुल भिन्न अर्थमें प्रयोग किया गया है । इससे यह तात्पर्य नहीं कि वह शख्स अपने शरीर से ही उपस्थित (हाज़िर) हो या कोशिश करता हो । कोई शख्स बिना उस स्थान पर स्वयं गए हुए अपने नौकरों या एजेन्सीके द्वारा ‘रोजगार’ कर सकता है, देखो 19 A. L. J. 696.

‘बिनाय सुखासमत’ का अर्थ यह है कि जहाँ पर नालिश करनेकी बिना पैदा हुई हो । उदाहरणार्थ — एक शख्स ने स्थान ‘अ’ से मालके मंगानेके लिये आर्डर दिया और माल स्थान ‘ब’ से बज़ारिये ची० पी० भेजा गया और उसकी कीमत स्थान ‘ब’ पर अदा की गई ऐसी दशामें दोनों जगह पर नालिश हो सकेगी । और देखिए जैसे—महेशदत्त एक व्यापारी कानपुरमें है, रामचन्द्र कलकत्तेमें कारबार करता है रामचन्द्रने कलकत्तेसे महेशदत्तको लिखा कि आदृत पेटे इतना माल रेलसे भेजो । महेशदत्तने उसके अनुसार माल रेलके हवाले किया तो कानपुर और कलकत्ते में दोनों जगह नालिश रुपया वसूल करने की हो सकती है । देखो 42 A. 619.

कार्पोरेशनकी सकूनत उस स्थान पर समझी जायगी जहाँ पर उसका कारबार होता हो । अगर किसी बैंक की पचास ब्रांच भिन्न भिन्न स्थानों में

हों, तो उसपर इनमें से किसी भी अधिकारक्षेत्रके अन्दर नालिश दायर की जासकती है, देखो 48.I. C. 943.

अधिकार क्षेत्रके सम्बन्धमें एतराज—अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी उच्च प्रारम्भिक अदालतमें पेश किए जायेंगे और वह भी जहां तक जल्द सुमकिन हो । अन्यथा अदालत अपीलमें ऐसा उच्च खारिज कर दिया जायगा ।

जो नालिशें एकसे अधिक अदालतोंमें दायर की गई हों उनको सुन्तकिल करने सम्बन्धी अधिकारोंके बारेमें देखो ज़ाबता दीवानीकी दफा २२ और २३, और हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्टकोर्ट (अदालत ज़िला) द्वारा मुकद्दमोंका सुन्तकिल किये जाने और उनको वापस लिये जाने के सम्बन्धमें देखो दफा २४ ।

प्लीडिंग्सका निकाल देना और उसका संशोधन—(१) अदालतको अधिकार होगा कि वह किसी भी समय किसी प्लीडिंगकी उन बातोंको निकाल दे या उनका संशोधन कर दे जो आवश्यक अथवा अपमान सूचक हों अथवा जिससे मामलेमें निष्पक्ष जांच होनेमें किसी तरह की हानि, रुकावट अथवा विलम्ब होने की सम्भावना हो [देखो आर्डर ६, रूल १६]

२ अदालतको अधिकार होगा कि वह किसी भी समय पर किसी फरीफ को अपनी प्लीडिंग्सका इस तरह और ऐसी शर्त पर संशोधन करने या उसको बदल देनेकी इजाज़त दे देवे जैसी मुनासिब मालूम हो और ऐसे तमाम संशोधन कर दिए जायेंगे जो झगड़े सम्बन्धी कुल प्रश्नोंको तय करनेके लिये काफ़ी होंगे [देखो आर्डर ६ रूल १७ और दफा १५३]

संशोधन—रूल १६ उन संशोधनोंके सम्बन्धमें है जो कोई फरीफ अपने विरोधी पक्षकी प्लीडिंग्समें करना चाहता हो और रूल १७ उन संशोधनोंके सम्बन्धमें है जो कोई फरीफ स्वयं अपनी प्लीडिंग्समें बनाना चाहता हो ।

संशोधनकी किस्में—नीचे लिखे किस्मके संशोधनोंके लिये ज़ाबता दीवानी में इजाज़त दी गई है:—

(क) फैसलों, डिकरियों या हुक्मोंमें लिखनेकी अथवा अङ्कोंका संशोधन [देखो दफा १५२]

(ख) किसी मुकद्दमोंमें की जाने वाली किसी कार्रवाई में हुई किसी ग़लती या भूल का इस गरज़ से कि फरीफ़के बीच पैदा हुए झगड़ेका निपटारा हो जाय, संशोधन करनेका आम अख्तियार (देखो दफा १५३)

(ग) फरीफ़को निकाल देने या शामिल करने सम्बन्धी अदालतका अख्तियार (देखो आर्डर १, रूल १०)

(घ) विरोधी पक्षकी प्लीडिंग्सका खारिज कर देना या उसका संशोधन करना [देखो आर्डर ६, रूल १६]

(ङ) किसी फरीफ़की खुदकी प्लीडिंग्सका संशोधन करना [देखो आर्डर ६, रूल १७]

रूल १७ अदालतको इस सम्बन्धमें बहुत विस्तृत अधिकार देता है कि वह क्लीडिंगसमें संशोधन करनेके लिये इजाजत दे सके, देखो 15 C. L. J. 439. जब यह रूल दफा १५२ के साथ शामिल कर दिया जाता है, तो इससे संशोधन की इजाजत देने सम्बन्धी अदालतोंके अधिकार बढ़ जाते हैं। इसलिये बहुतसे मामले जो दफा ५२ के अनुसार फैसल किए गए हैं वे कानूनकी दृष्टिसे ठीक नहीं हैं। अन्तिम वाक्यके आज्ञासूचक शब्दोंसे यह स्पष्ट है कि सुकदमेंके दौरानमें किसी भी समय संशोधनोंके लिये इजाजत दी जा सकती है, जो दो शर्तोंको पूरा करता है, अर्थात् (१) यह कि दूसरे पक्षके साथमें अन्याय न होना और (२) यह कि वास्तविक झगड़ेके प्रश्नको तय करने के लिए आवश्यक होना, देखो 33 B. 644. प्रत्येक वकीलको इस नज़ीरको पढ़ जाना चाहिए, देखो 16 C. W. N. 128; 14 C. L. J. 188; 22 C. W. N. 611. संशोधनकी नामजुरी उस समय देनी चाहिए जब कि (१) कोई दावा या दादरस्ती जान बूझकर छोड़ दीगई हो, (२) जब कि दख्वास्त नेकनीयतीसे न दीगई हो, (३) जब कि इससे सुकदमेंकी असलियत बिल्कुल बदल जाती हो और (४) जब कि वह गैर-कानूनी हो और अनावश्यक हो, [देखो 17 C. W. N. 311; 11 I. C. 827; 10 C. W. N. 622; 14 C. L. J. 83.] पलकी गलती चाहे जितनी ही लापरवाहीसे क्यों न कीगई हो और इसके लिए मायना चाहे कितनी ही देरमें क्यों न कीगई हो, संशोधनके लिए इजाजत अवश्य दी जानी चाहिए, जब तक कि दूसरे पक्षको ऐसी हानि न पहुंच रही हो, जिसका सुआ-विज्ञा खर्चसे पूरा न किया जा सकता हो।

जब संशोधन करनेकी इजाजत दे दीगई हो तो दूसरे पक्ष को भी इस बातका मौका दिया जाना चाहिए कि वह संशोधन के द्वारा या नई शहादत तलब करके उसका जवाब दे सके [देखो 16 I. C. 785; 12 C. L. J. 556; 20 C. W. N. 547]

संशोधनका सम्बन्ध उसी तारीखसे होगा जिस तारीखको नालिश दायर कीगई थी [देखो 62 P. R. 1914; 19 C. W. N. 1193.] जिस संशोधनसे किसी पक्षका, मियादके आधार पर अपनी पैरवी करनेका अपहरण होता हो, उस संशोधनके लिए इजाजत न देनी चाहिए [देखो 25 C. W. N. 289, P. C; 20 C. W. N. 475; 26 C. W. N. 73)

मियाद—संशोधन करने से वह अर्जीदावा या बयान तहरीरी आदिका दाखिल होना उसी तारीखसे समझा जायगा जिस तारीखको वह असलमें पहिले दाखिल हुआ है मगर अर्जीदावामें किसी मुद्दाअलेहके नए सिरेसे बढ़ानेकी दशा में उस बढ़े हुए मुद्दाअलेह के मुकाबिलेमें वह अर्जीदावा उस तारीखमें दाखिल हुआ समझा जायगा कि जिस तारीखको उसका नाम नए सिरेसे बढ़ाया गया है।

हुक्म मिलनेके बाद संशोधन करनेका परिणाम—(१) अगर कोई शख्स हुक्म होने के बाद निश्चित समय के भीतर अथवा जहां पर ऐसा समय निश्चित नहीं

किया गया है वहां १४ दिनके भीतर संशोधन नहीं कर देता, तो उसे जब तक कि अदालत समयको बढ़ा न देवे संशोधन करने का अधिकार न होगा [देखो आर्डर ६, रूल १८] लेकिन इस रूलसे अदालतोंके संशोधन करने सम्बन्धी साधारण अधिकारोंके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता जो उन्हें जाबता दीवानीकी दफा १५३ के अनुसार प्राप्त हैं । संशोधन करनेकी इजाजत, अपील या खास अपीलमें दी जा सकती है [देखो दफा १०८]

२ दफा १४८ जाबता दीवानी के अनुसार अदालतको अधिकार है कि वह उस मुद्दतको बढ़ा दे जो जाबता दीवानीके अनुसार निर्धारित या अज्ञात (आज्ञा प्राप्त) कार्योंके करनेके लिए मुकर्रर की गई हो [देखो 17 C. W. N. 515]

अर्जीदावाकी वापसी—मुकद्दमोंके दौरानमें किसी भी समय अर्जीदावा मुनासिब अदालतमें पेश किए जानेके लिए इस कारणसे वापस किया जा सकता है कि जिस अदालतमें वह पेश किया गया है उसे उसकी समाप्त करनेका अधिकार नहीं है (देखो आर्डर ७ रूल १०)

किसी मुनासिब अदालतमें पेश किए जाने के लिए किसी अर्जीदावाको वापस करते हुए, जजको चाहिए कि वह उसकी पीठ पर ये बातें लिख दे:— (१) पेश किए जाने और वापसीकी तारीख, (२) पेश करने वाले शख्स या शख्सोंका नाम, (३) वापस करनेके कारणों का एक संक्षिप्त विवरण [देखो आर्डर ७, रूल १०]

उस हुक्मकी अपील हो सकती है जिसके अनुसार मुनासिब अदालतमें पेश किए जाने के लिए अर्जीदावा वापस किया गया हो देखो आर्डर ४३

अर्जीदावा का खारिज किया जाना—नीचे लिखी हालतों में अर्जीदावा खारिज किया जा सकता है:—

१ जब कि उसमें बिनाम सुखसमत ज़ाहिर न की गई हो,

२ जब कि दादरसी की मालियत मुनासिब से कम लगाई गई हो और मुद्दई, अदालत से इस बात का हुक्म मिलने पर कि यह उसकी रकम को ठीक करे, ऐसा न कर सके,

३ जब कि अर्जीदावा किसी ऐसे कागज़ पर लिखा गया हो जिसपर काफी स्टाम्प न लगाया गया हो और मुद्दई अदालत द्वारा मुकर्रर किए गये समय के अन्दर कमी कोर्ट-फीस को पूरा न कर सके,

४ जब कि नालिश के बारे में यह मालूम होता हो कि ' किसी कानून ' के अनुसार उसकी मियाद आरिज़ होगई हो [देखो आर्डर ७, रूल ११]

क्लॉज़ (१)—कोई नालिश इस बिनापर खारिज कर दी जा सकती है कि अर्जीदावा में बिनाय-सुखसमत दावा दिखलाई नहीं गई है, यद्यपि ऐसी बिना वकील की बहस में दिखलाई गई है, मुद्दा-अलेह के बयान तहरीरी में नहीं, देखो 3 C. W. N. 220. अदालत किसी अर्जीदावा को अंशतः खारिज नहीं कर सकती है, देखो 29 A. 325.

क्लॉज़ (२) —अगर जिस दादरसी के लिए दरखवास्त की गई है, उसकी मालियत कम लगाई गई है, तो अदालत को चाहिए कि वह मुद्दे को यह हुक्म दे कि वह अपनी दादरसी की, जो कि वह चाहता है, मालियत ठीक करे और इसके बाद, अगर मुद्दे दादरसी की तादात कम दिखलावे तो, अदालत इस दफा का प्रयोग करके उसका अर्जीदावा खारिज कर सकती है। लेकिन अदालत को खुद दादरसी की मालियत ठीक करने का अधिकार नहीं है [देखो 13 B. 517; 33 M. 262.]

क्लॉज़ (३) —अगर मुद्दे उस मुद्दत के अन्दर जो अदालत ने निश्चित की है, स्टाम्प, जो उससे तलब किया गया है अदा नहीं करता है, तो अदालत को रूल १२ के अनुसार यह अधिकार है कि अर्जीदावा को उस समय भी खारिज कर दे जब कि उसपर नम्बर डाले जा चुके हों और वह बतौर नालिश के रजिस्टर में चढ़ा लिया गया हो देखो 12 A. 553; 27. C. 376; 18 M. 338; 11 C. W. N. 38. जब कि अर्जीदावा किसी ऐसे कारण से खारिज कर दिया गया हो, जिसका वर्णन आर्डर ७, रूल ११ में किया गया है, तो मुद्दे उसी चीज़ की बाबत आर्डर ७, रूल १२ के अनुसार फिर से दावा दायर कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी तमादी आरिज़ न होगई हो, देखो 14 W.R. 289; 12 A. 553; 21 B. 91; 6 B. 447.

क्लॉज़ (४) —“किसी कानून” शब्दों में संग्रहीत कानून और केस-लॉ (नज़ीरों का कानून) दोनों शामिल हैं। अर्जीदावा किसी समय खारिज किया जा सकता है, 12 A. 553. 18 M. 388; 34 Cal. 20 F. B.

इस रूल के अनुसार दिये हुए हुक्म की अपील डिकरी की तरह पर की जा सकती है, देखो जावता दीवानी की दफा २ (२).

अर्जीदावा मंजूर कर लिए जाने के बाद की कार्रवाई

सम्मन की तालीली

अर्जीदावा की रजिस्ट्री—नालिश दायर होने के बाद अदालत उसके सम्बन्ध की कुल बातों को दीवानी मुकद्दमों के रजिस्टर में दर्ज करवा देगी। नालिशों का नम्बर उसी सिलसिले में होगा जिसमें अर्जीदावा लिए गए हैं (देखो आर्डर ४, रूल ४).

अर्जीदावा के दर्ज रजिस्टर होजाने के बाद हर एक वकील को फर्द हुक्म देख लेना चाहिए और अपनी डायरी में मुकद्दमों के आखिरी फ़ैसला या तनकीहों के तय करने के लिये मुकद्दमों की गई तारीख और मुकद्दमों के नम्बर को नोट कर लेना चाहिये।

जिन हुकमों में फरीकैन या उनके वकीलों की ओर से कोई बात किए जाने की हिदायत की गई हो उनपर वहीं पर फरीकैन या उनके वकीलों के दस्त खत हो जाने चाहिए [देखो G. R. and C. O. Vol. 1 Chap. 3 R. 18).

मुद्दाअलेह के नाम सम्मन जारी करना—(१) अर्जीदावा के दर्ज रजिस्टर हो जाने के बाद, मुद्दाअलेह के नाम इस बात का सम्मन जारी किया जा सकता है कि वह उसमें बतलाए हुए समय पर हाज़िर होकर दावा की निस्वत अपना जवाब पेश करे (देखो दफा २७ और आर्डर ५, रूल १)

(२) सम्मन जारी करने के वक्त अदालत यह तय करेगी कि वह सम्मन सिर्फ तनकीहों के तय करने के लिए ही होगा, या मुकद्दमें का अन्तिम निर्णय (आखिरी फैसला) करनेके लिए, और इसीके अनुसार सम्मन जारी किया जायगा [देखो आर्डर ५, रूल, ५.]

(३) अदालत खफीफा में दायर की गई नालिशों में सम्मन मुकद्दमें का आखिरी फैसला करने के लिए होगा [देखो आर्डर ५, रूल ५] लगान की नालिशों में सम्मन मुकद्दमें के आखिरी फैसले के लिए होगा, जब तक कि अदालत की यह राय न हो कि सम्मन सिर्फ तनकीहों तय करने के लिए होगा (देखो दफा १४८ 'सी') रुपये पैसे की नालिशों में सम्मन प्रायः आखिरी फैसले के लिए ही होता है। हकीमत रेहल नामा या दूसरे मुकद्दमों में सम्मन तनकीहों को तय करने के लिए होता है।

(४) सम्मन में मुद्दाअलेह को यह हुकम दिया जायगा कि वह वे कुल क़ागज़ात जोकि उसके क़ब्ज़े या अधिकार में हों और जिनके आधार पर वह अपना दावा पेश करता है, पेश करे और अगर सम्मन मुकद्दमें के आखिरी फैसला के लिए हो, तो उसमें मुद्दाअलेह के लिए यह भी हुकम होगा कि वह अपनी हाज़िरी के दिन, जो मुकर्रर किया गया है, अपने गवाह भी हाज़िर करे [देखो आर्डर ५, रूल ७ और ८]

(५) मुद्दाअलेह या तो असालतन हाज़िर हो सकता है या वज़रिये किसी वकील के जिसको बाकायदा मामले के हालात समझा दिए गए हों और जो मुकद्दमें से सम्बन्ध रखने वाले तमाम आवश्यक प्रश्नों का उत्तर दे सकता हो, या वज़रिये किसी ऐसे वकील जिसके साथ, कोई दूसरा आदमी हो जो ऐसे तमाम खयालों का जवाब दे सकता हो [देखो आर्डर ५, रूल १, क्लॉज़ २]

(६) जहां पर अदालत की राय में मुद्दाअलेह की असालतन हाज़िरी आवश्यक हो, वहां पर सम्मन में यह हुकम होगा कि वह असालतन हाज़िर हो [देखो आर्डर ५, रूल ३]

(७) हर एक सम्मन के साथ अर्जीदावा की एक नक़ल या अगर ऐसा हुकम हो तो, एक संक्षिप्त विवरण भी भेजा जायगा। [देखो आर्डर ५, रूल (२)]

(८) किसी भी शरूस्को असाहतन हाज़िर होनेका हुक्म न दिया जायगा जब तक कि वह अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर न रहता हो या इस सीमा के बाहर किन्तु ऐसे स्थान पर, जो अदालत से ५० मील या जहां पर कि रेल या स्टीमर त्रगौरा की आमदरफ्त है वहां २०० मील से कम फासले पर न रहता हो ।

(९) मुद्दाअलेहकी हाज़िरीका दिन इन बातोंका खयाल रखकर मुक़र्रर किया जायगा—(१) यह कि अदालत के पास इस समय कितना काम है, (२) मुद्दाअलेह की सकूनत कहां है और (३) यह कि सम्मन की तामीली के लिए कितने समय की जरूरत है [देखो आर्डर ५, रूल ६] इस रूल के अनुसार मुद्दाअलेह काफी बक्त पाने का हक़दार है जिससे कि वह असाहतन या बज़रिये वकील के हाज़िर हो सके ।

जब सम्मन बिना तामील हुए वापस आये और उसके बाद तीन महीने तक मुद्दई दूसरे सम्मन के लिए दरखवास्त न दे, उस समय क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इसके लिए देखो आर्डर ९, रूल ५, जिसका सशोधन एक्ट नं० २४ सन १९२० ई० के अनुसार हो चुका है । सम्मन अदालत से जारी किये जाते हैं संयुक्त-प्रान्त की अदालतों का काम कम करने के लिये अब यह हुक्म जारी किया गया है कि सम्मन की खाना पूरी पेशी की तारीख आदि को छोड़ कर सब उस वकील के द्वारा की जाये जिसकी दरखवास्त पर सम्मन जारी होना है ।

तलबाना दाखिल करना—ज़ाबता दीवानी के अनुसार जो भी हुक्म नामा जारी किया जायगा वह उस फ़ीक़ के खर्च से जारी किया जायगा जिसकी ओर से वह जारी कराया जा रहा है, जब तककि अदालत इससे विपरीत कोई आज्ञान दे उसपर जो कोर्ट फ़ीस लगाया जाना चाहिए, वह उस मियादके अन्दर अदा किया जाना चाहिए जो हुक्म नामा जारी किये जाने के पहले मुक़र्रर की जायगी [देखो आर्डर ४८, रूल १]

जब कि सम्मन डाक द्वारा भेजा जाय, तो पोस्टेज और रजिस्टरी का खर्च उस मियाद के अन्दर अदा कर दिया जाना चाहिए जो उसके भेजे जाने से पहिले मुक़र्रर हो [देखो दफ़ा १४३],

अर्जीदावा के दर्ज रजिस्टर होजाने और मुद्दाअलेह के ऊपर सम्मन जारी किए जाने का हुक्म दिए जाने के बाद मुद्दई के वकील का यह काम होगा कि वह खयाल रखे कि सम्मन की तामीली का खर्चा जहां तक जल्द हो सके भुदा करदे । आर्डर ९, रूल २ के अनुसार नालिश खारिज हो जा सकती है, अगर मुद्दई खर्चा अदा नहीं करता है ।

सम्मन तामीली की दरखवास्त देने के समय तलबाना का रुपया पहिले ही जमा कर दिया जाना चाहिए और वह स्टाम्प की शकल में होगा जो उसी अर्जीपर उस स्टाम्प के अलावा लगाया जायगा जो कि उस अर्जी के लिए ही ड़ाक़री है ।

वकीलों के मुहरिरी का यह काम हुआ करता है कि वे तलवाना आदि लगावें। अक्सर वे बेपरवाही कर जाते हैं या मवक्किल से लेने में ग़फ़लत का जाते हैं जिससे पीछे हानि होती है। मवक्किलों को चाहिए कि वह अदालत का कुल खर्चा वकील साहब को दे दें ताकि देरी होने के कारण या न दाखिल होने के कारण जो हानि हो उसकी जिम्मेदारी उनपर न रहे। यह बड़ी मुश्किल है कि प्रायः वकील लोग खर्चे के पाने की रसीद नहीं देते बल्कि महवताना का भी देने में उन्हें शोभ होता है। जब कभी मुहरिर साहब कुछ ग़बन करके भाग जाते हैं तो मवक्किलों के पास कोई आधार नहीं रहता कि उन्होंने कितना रुपया उसे दिया था। उचित तो यही है कि रसीद दी जाय।

सम्मन की तामीली—सम्मन की तामीली की फीस अदा हो जाने और सम्मन के छपे हुए फार्म (जिनकी खाना-पुरी हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार बाकायदा तौर पर कर दी गई है) दाखिल कर दिये जाने के बाद, एक वकील का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बातकी जांच करे कि क्या सम्मन तामील के वास्ते नाज़िर के दफ़तर को भेज दिये गये हैं। और तामील करने के लिए वे मज़कूरी (चपरासी) को दे दिए गए हैं। इससे वह अपने मवक्किल को इस बात की सूचना दे सकेगा कि वह किसी शिनाख़्त करने वाले को, जिसे प्रायः “निशादिहिन्दा” कहते हैं, लेकर तैयार रहें जो मुद्दाअलेह की शिनाख़्त कर सके, और उस चपरासी की इस बारे में सहायता करे ताकि वह मुद्दाअलेह पर असालतन सम्मन की तामील कर सके।

हुक्मनामा के फार्म को दाखिल करना—फरीकैन को चाहिए कि वे हाजिरी के लिए हुक्म नामा जारी करने की दरख़ास्त के साथ साथ उसके छपे हुए फार्म भी दाखिल करें जिनकी खाना-पुरी हाईकोर्ट के तलबी सम्बन्धी नियमों के अनुसार कर दी गई हो। हाजिरी की तारीख और हुक्म नामा की तारीख का ख़ाना खाली छोड़ देना चाहिए। इनकी खाना-पुरी दफ़तर में की जायगी। फरीकैन या उनके वकील उस फार्म पर नीचे की तरफ़ बाईं ओर अपने दस्तख़त करेंगे और वे इस बात के लिए ज़ुम्मेदार रहेंगे कि वह सब ठीक और सही है। फार्म में मोटे, साफ़ और ऐसे अक्षरों को लिखना चाहिए जो अच्छी तरह से और जल्दी पढ़े जा सकें।

तलबी के लिए आवश्यक फार्म फरीकैन या उनके वकीलों को बिना खर्चे के मुफ़्त दिए जायेंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्टकी सीमाकेअन्दरमें सम्मनके लिए दरख़ास्त एक इसके लिए मुकर्रर फार्म में लिखी जायगी। दूसरे फार्म में दरख़ास्त न ली जायगी।

भाषा—जो हुक्मनामों अदालत दीवानी से जारी किए जाय वे प्रायः उस भाषा में लिखे जाने चाहिए जो उस ज़िले में प्रचलित है जिसमें कि वह अदालत वाकै है, अर्थात् (कुछ हालतों को छोड़कर) उस भाषा में जिसमें ऐसी अदालतों का काम होता है। लेकिन जब हुक्मनामा तामील के लिए किसी

जिला की अदालत को भेजा जाता हो, जहां पर आमतौर से उससे भिन्न किसी दूसरी भाषा का प्रयोग होता हो, तो उस हुक्मनामा के साथ किसी दूसरी वैसे भाषा या अंग्रेजी में अनुवाद (तर्जुमा) भी रहेगा जिसके ऊपर वह अदालत जो, उसे भेज रही है, यह तस्दीक करेगी कि वह सही है। किन्तु ऐसी अवस्थाओं में इस हुक्म-नामा के साथ अंग्रेजी में लिखा हुआ एक पत्र (खत) होना चाहिए जिसमें उसकी तामीली की निश्चत लिखा गया हो। जिन हुक्मनामों का अंग्रेजी मजदून हाईकोर्ट ने निश्चित किया है, उनके लिए यह ज़रूरी है कि वे यूरोपियन लोगों के पास उसी भाषा में भेजे जाय।

तामीलका तरीका — (१) सम्मनकी तामील उस सम्मनकी एक प्रति (नक़ल) देकर या चरपा करके की जानी चाहिये [देखो आर्डर ५, रूल १०] जहां कहीं ऐसा सम्भव होगा, सम्मनकी तामील मुद्दा-अलेहके ऊपर असालतन की जायगी, जब तक कि उसका कोई मुखतार ऐसा न हो जिसे सम्मन लेनेका अधिकार दिया गया हो। जब एकसे अधिक मुद्दा(अलेह हों, तो हर एक मुद्दा(अलेहके ऊपर अलग २ तामील की जायगी सिवाय उस दशाके जब कि इससे भिन्न कोई व्यवस्था की गई हो (देखो आर्डर ५, रूल ११)

पंजाबमें मुद्दई पहिले रजिस्टर्ड पोस्टसे सम्मनकी तामील करनेकी कोशिश कर सकता है (देखो परिशिष्ट आर्डर ५, रूल १० की शर्त)

(२) जब तामील करनेवाला अफसर सम्मनकी एक प्रति स्वयं मुद्दाअलेह को देता है या उसके मुखतार अथवा किसी दूसरे शख्सको, जिसे उसकी ओरसे ऐसा करनेका अधिकार प्राप्त है, तो वह उस सम्मनके पानेकी रसीद असली सम्मनकी पीठ पर लिखवा कर उसके दस्तखत करवा लेगा; और तामील करने वाले अफसरको चाहिये कि वह सभी हालतोंमें असली सम्मनके ऊपर या उसके साथ तामीलका समय तरीका तथा शिनाख्त करनेवाले और गवाहोंके नाम लिख कर, या लिखवा कर भेज दें (देखो आर्डर ५, रूल १६, और १८)

(३) जबकि मुद्दाअलेह या उसका मुखतार रसीद पर दस्तखत करनेसे इन्कार करे या जब कि वह सभी "उचित और सम्भव उपायों" का प्रयोग करने पर भी मिल न सके, तो आर्डर ५ रूल १७ के अनुसार उसके मकानके बाहरी दरवाजा पर चरपा करके सम्मनकी तामील की जायगी।

(४) जब आर्डर ५ रूल १७ के अनुसार कोई सम्मन वापस आजाय तो अदालत अगर ज़रूरी होगा तो, मुनासिब तामीलीकी निश्चत इतमिनान कर लेगी और फिर या तो यह घोषित कर देगी कि सम्मन बाकायदा तौरसे तामील हो गया है या ऐसी दूसरी तामीलका हुक्म देगी जिसे वह मुनासिब समझेगी (देखो आर्डर ५, रूल १९)

(५) जब कि मुद्दाअलेह भाग रहा हो या और किसी कारणसे सम्मनकी तामीली न होती हो, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह यह हुक्म दे देवे कि इसकी जगह सम्मन कचहरीमें और उस स्थान पर जहां पर आखिरमें मुद्दा-

अलेहकी सकूनत रही हो, चरपां करके तामील किया जाय (देखो आर्डर ५, रूल २०)

(६) जब कि मुद्दाअलेह दूढ़े न मिलता हो और उसका कोई मुख्तार भी न हो तो सम्मनकी तामील उसके घरके किसी भी बालिग आदमी पर की जा सकती है जो उसके साथ रहता हो। नौकर, उस घरका आदमी नहीं माना जाता है (देखो आर्डर ५, रूल २०)

(७) जबकि मुद्दाअलेह उस अदालतके अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके बाहर रहता हो, लेकिन मैनेजर या एजेण्टके जरिये ऐसी स्थानीय सीमाके भीतर कारबार करता हो, तो ऐसे मैनेजर या एजेण्टके ऊपर की गई तामीली काफी समझी जायगी (देखो आर्डर ५, रूल १३)

(८) जायदाद गैर-मनकूला सम्बन्धी नालिशोंमें, तो मुद्दाअलेहके किसी भी एजेण्ट पर, जिसकी सिपुर्दगीमें वह जायदाद गैर-मनकूला है, की गई तामीली काफी समझी जायगी, जब कि सम्मनकी तामील मुद्दाअलेहके ऊपर असालतन न की जा सके और उसका कोई ऐसा मुख्तार (एजेण्ट) न हो, जिसे सम्मन लेनेका मजाज़ हो (देखो आर्डर ५, रूल १४)

(९) जब कि नालिश किसी कारपोरेशनके ऊपर दायर की गई हो, तो सम्मनकी तामीली (अ) कारपोरेशनके सेक्रेटरी, या किसी डाइरेक्टर या दूसरे खास अफसरके ऊपर अथवा (ब) कारपोरेशनके पतेसे उसके रजिस्टर्ड आफिसमें या (स) अगर रजिस्टर्ड आफिस नहीं है, तो उस स्थान पर, जहां वह कारपोरेशन अपना कारबार करता है, छोड़ देने या बजरिये डाक भेज देनेसे की जा सकती है (देखो आर्डर २९, रूल २)

अगर नालिश किसी रेलवे कम्पनी पर की जावे तो आम तरीकेसे सम्मन तामील करनेके साथ साथ आर्डर २९, रूल २ (बी) के अनुसार सम्मनकी एक प्रति (नक़ल) बजरिये डाक भेज देनी चाहिये [देखो G.R. & C.O.Ch. 1 R. 22]

(११) अगर किसी साझेदारीमें काम करनेवालोंके ऊपर दावा किया जाय तो सम्मनकी तामील या तो (अ) एक या ज्यादा हिस्सेदारों (साझीदारों) के ऊपर की जायगी या (ब) उस मुकाम के ऊपर, जहां पर कार-बार (व्यापार) किया जाता है, किसी ऐसे आदमी पर, जो उस कारबारका प्रबन्धकर्ता हो [देखो आर्डर ३०, रूल ३]

जिन मामलोंमें सम्मनकी तामीली असालतन हो सके उन सबमें असालतन ही तामीली करनी चाहिये (देखो 29 M. 324.) फ़रीक़ेंको चाहिये कि वे तामील करने वाले चपरासी (मज़दूरी) को असालतन तामीली करनेमें सहायता दें, क्योंकि अगर अदालतको सम्मनकी तामीलीकी निस्वत इतमिनान न हुआ तो उनको नए सिरेसे तामीली करनेमें दिक्कत और खर्चा उठाना पड़ेगा। शिनाख्त करनेवालोंको चाहिये कि वे इस बातका हलफ़-नामा दाखिल करें कि तामीली वाक़ायदा तौर पर हो गई है। उनको इस पर कोई-फ़ीस नहीं लगानी पड़ेगी।

जो लोग मुद्दा-अलेहका कार-बार देखते हों, वे मुद्दतार नहीं कहे जा सकते (देखो 17 W. R. 33) मुद्दतार लोगोंको सम्मन लेनेका अख्तियार होना चाहिये। 'बालिग' का मतलब उस आदमीसे है जिसकी उमर १६ सालसे ज्यादा हो (देखो 35 C. 286)। 'बालिग' मर्दमें बालिग औरत नहीं आती है। इस बात बतला देंगी जो उसकी अदम-मौजूदगीमें हुई हैं (देखो 21 B. 223)। इस बातका भी कोई अनुमान नहीं हो सकता कि लड़का अपने बापको सूचित कर देगा (देखो 35 C.L.J. 205)।

सम्मन चरुपां उसी समय किया जा सकता है, जब "मुनासिब और सम्भव कोशिश" करने के बाद मुद्दाअलेह "मिल न सके"। सिर्फ इस बातसे कि मुद्दाअलेह थोड़े समयके लिए मकानसे बाहर गया हुआ है, सम्मनका उसके दर-वाज़ेपर चरुपां कर देना ठीक न होगा। सम्मनकी तामील करने वाले मजकूरी (चपरासी) को चाहिए कि वह कोशिश करके उस शख्सको तलाश करे (देखो 26 C. 101; 19 C. 201; 5 C. L. J. 12 n; 30 B. 623; 38 C. 394; 21 M. 419; 24 A. 302; 21 B. 223; 23 C. L. J. 183; 3 C. W.N.307). 19 C. 201 में चीफ़ जस्टिस पेथेरमने कहा है:—"यह सच है कि तुम (चपरासी) किसीके मकानके ऊपर जाते हो और उसे वहां पर नहीं पाते हो, परन्तु यह उसको तलाश करनेकी कोशिश करना नहीं है; तुम उसके मकान पर जाओ, वहां उसे दरयापत करो और अगर ज़रूरी हो तो जहाँ वह गया है वहां पर जाओ। तुम्हें इस बातका पता लगाना चाहिए कि वह मकान पर कब तक आ जायगा और तुम उसके मकान पर उस समय जाओ जब उसके मिलने की सम्भावना हो।" जो हलफनामा मजकूरी (चपरासी) दाखिल करे उसमें यह बात अवश्य दिखलाई जानी चाहिए कि सम्मन चरुपां करनेके पहिले मुद्दा-अलेहको ढूढ़नेके लिए काफी कोशिश कर लीगई थी [देखो 26 C. 101]। अगर चपरासी इस सम्बन्धमें अपने कर्तव्यका पालन न कर सका, तो इस बातकी इत्तला अदालतको मिलनी चाहिए, ताकि फिरसे सम्मन तामील करनेका हुकम दिया जा सके और उसका खर्चा मुद्दईको दुबारा फिर न देना पड़े, अगर किसी तरहका उसका कोई कुसूर नहीं है।

आज कल अदालतें प्रायः यह किया करती हैं कि, अगर सम्मन चरुपां हो जानेके बाद मुद्दाअलेह हाज़िर नहीं होता है तो वे रजिस्ट्री डाकसे सम्मन तामील किया करती हैं। चिट्ठी भेजने का खर्चा वगैरा सब मुकर्रर मियादके अन्दर दाखिल किया जाना चाहिए। जस्टिस मुक़र्जीने 19 C. W. N. 1231 में जो फैसला दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत, रजिस्ट्री डाकसे सम्मनकी तामीली कर सकती है। पंजाबमें आर्डर ५, रूल १० का संशोधन कर दिया गया है और मुद्दई पहिले रजिस्ट्री डाकसे सम्मन तामील करने की कोशिश कर सकता है।

किसी अपीलान्तको इस बातके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह शिनाख्त करने वालेको पेश करे। जिस शिनाख्त करने वाले का ज़िक्र आर्डर १०, रूल १८ में है, उसके लिए यह ज़रूरी है कि वह फ़रीक़का दिया हुआ हो। ऐसा आदमी उसी गांवका रहने वाला होना चाहिए और जो मुद्दाभलेह जानता हो, देखो 64 I. C. 49.

जाबता दीवानी में पर्दा नशीन औरतोंके ऊपर सम्मनकी तामीलीकी निश्चित कोई खास व्यवस्था नहीं कीगई है और जहां पर देशके रस्म-रिवाजकी वजहसे उन तक पहुँचना असम्भव हो, वहां पर चरपां किए जाने का हुक्म दिया जा सकता है, देखो 2 M. L. A. 263; 19 C. W. N. 1231.

इस सम्बन्धमें, कि आर्डर ५, रूल १० के अनुसार सम्मन चरपां किस समय किया जासकता है, देखो 38 C. 394; 13 C. L. J. 221; 9 C. L. J. 244; 11 Ch. J. 580; 1 C. W. N. 104.

जो हलफ़नामा तामील करने वाला चपरासी या शिनाख्त करने वाला शख्स तामीलीकी निश्चित दाखिल करे, उसमें यह बात लिखी होनी चाहिए कि सम्मनोंकी तामील उसी तरहसे कीगई है जिस तरह आर्डर ५ में बतलाया गया है, अर्थात् अगर सम्मनको मुद्दाभलेहने स्वयं ले लिया है और उसकी रसीद लिख दी है, तो जिस अफसरने तामील की है वह हलफ़नामासे उसकी तस्दीक करेगा और उस शख्सकी शिनाख्त का सुबूत भी उस शख्सके हलफ़नामासे मिल जाना चाहिए जो उस शख्सने दाखिल किया है जो उस शख्सको, जिस पर सम्मन तामील किया गया है, अच्छी तरहसे जानता था। अगर रूल १२ के अनुसार सम्मनकी तामीली किसी मुख्तार (ऐजण्ट) के ऊपर कीगई है, तो हलफ़नामासे यह बात साबित की जानी चाहिए कि मुख्तार (ऐजण्ट) को सम्मन लेनेका अख्तियार था; अगर तामीली रूल १५ के अनुसार कीगई है, तो हलफ़नामासे यह बात साबित होनी चाहिए कि वह शख्स मिल नहीं सका और न उसका कोई मुख्तार ही था, और यह कि जिस शख्सको सम्मन दिया गया है वह उस शख्स (फ़रीक़) के घरका आदमी है जो बालिग़ है और उसीके साथ रहता है; अगर तामीली रूल १७ के अनुसार कीगई है तो हलफ़से यह बात साबित की जानी चाहिए कि माकूल कोशिश करने के बाद भी मुद्दाभलेह नहीं मिल सका और यह कि उसका कोई मुख्तार वगैरा भी नहीं था और इसी तरह दूसरे रूलोंके निश्चित भी है।

दूसरे जिलोंमें सम्मनकी तामीली—इस बातके लिये कि, जब मुद्दाभलेह किसी दूसरी अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें रहता हो, उस समय सम्मनकी तामीली किस तरह पर की जानी चाहिये, देखो आर्डर ५, रूल २१.

आर्डर ५, रूल २१ के अनुसार जारी किया हुआ सम्मन आम तौरसे उस मुंसिफ़की अदालतको भेज दिया जाना चाहिए जिसके अधिकार-क्षेत्रमें मुद्दाभलेह या गवाह रहता हो (देखो G.R.&C.O.Chap. I. R. 40). सम्मन भेजने वाली अदालत अक्सर अपने से कम दर्जे की अदालतमें या, यदि कम दर्जे की

अदालत न हो तो बराबरकी अदालतमें भेजती है। यदि ऐसा भी न हो तो बड़े दर्जेकी अदालतको भी भेज सकती है।

प्रेजीडेन्सी टाउन्स या दूसरे स्थानोंमें सम्मनकी तामीली—जब कोई सम्मन, जो किसी ऐसी अदालत द्वारा जारी किया गया हो जो कलकत्ता, मदरास, बम्बई और रङ्गून शहरकी सीमाके बाहर वाकै है, और किसी ऐसी सीमाके भीतर तामील किए जानेको हो, तो वह उस अदालत खफ़ीफ़ा के पास भेज दिया जाना चाहिए जिसके अधिकार-क्षेत्र में उसकी तामीली की जानेको हो। [देखो आर्डर ५, रूल २२]

प्रेजीडेन्सी टाउन्समें तामील किए जानेके लिए हुक्मनामा जारी करते समय, हर एक अदालतके प्रिज़ाइडिंग अफ़सरको इस बातका इतमीनान कर लेना चाहिए, कि हुक्मनामामें उस शख़्सका, जिसे तलब किया गया है, वह कुल ध्योरा लिखा हुआ है जिससे अब इस बातकी सम्भावना नहीं है कि प्रेजीडेन्सी टाउन्सका चपरासी उस आदमीकी हुलिया पहिचाननेमें ग़लती कर जायगा। अगर तलब किया हुआ शख़्स यूरोपियन या यूशेशियन है, तो उसका पूरा ईसाई (क्रिश्चियन) नाम, अगर सम्भव हो तो उसके नानके अक्षर, पेशा या रोज़गार और पूरा पता (अर्थात् सड़क या महल्ला का नाम, और मकानका नंबर), सही सही लिखा जाना चाहिए। अगर वह शख़्स हिन्दुस्तानी है, तो सम्मनमें उसका नाम, बापका नाम, जात, पेशा और पता लिखा जाना चाहिए तथा इसके साथ दूसरी और बातें भी लिखी जानी चाहिए जो प्रिज़ाइडिंग अफ़सरकी रायमें सम्मनकी तामीलीमें सहायता करेंगी। सम्मन उस समय तक जारी नहीं करना चाहिए जब तक कि वह शख़्स, जिसकी ओरसे सम्मन जारी किया जा रहा है, कुल बातें बतला न दे (देखो G. R. & C. O. Chap. 1 R. 38.)

बम्बईमें रूल २२ के साथ एक शर्त जोड़ दी गई है, जिसमें रजिस्ट्री डाकसे सम्मन तामील करनेका हुक्म दिया गया है।

दूसरी हालतोंमें सम्मन तामील करनेका तरीका—जब मुद्दाअलेह जेलखानेमें हो, उस समय तामील किस तरह कीजाय, इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ५, रूल २४ और २९। सम्मन जेलके अफ़सर इन्चार्जके पास भेजना चाहिये, देखो प्रिज़ेन्स ऐक्ट नं० ३ सन् १९०० ई० की दफ़ा ३४ से ४८ तक।

जब मुद्दाअलेह दूसरे प्रान्त (सूबे) में रहता हो उस समय सम्मनकी तामीली के तरीकेके बारेमें देखो ज़ाबता दीवानीकी दफ़ा २८ और २९। दफ़ा २८ यह है कि सम्मन तामीलके वास्ते किसी दूसरे सूबेकी अदालतमें ऐसे तरीके पर भेजा जायगा जो उस सूबेके नियमोंके अनुकूल हो और सूबेकी अदालत वैसे ही कार्रवाई करेगी मानो सम्मन उसीने जारी किया है। तथा रिपोर्ट लिखकर सम्मन भेजने वाली अदालत को वापस कर देगी।

जब मुद्दाअलेह ब्रिटिश भारतके बाहर रहता हो और उसका कोई भी मुख्तार भारत-वर्षमें न हो जो सम्मन ले सकता हो, उस समय सम्मन तामील

करने के लिये लिफाफेमें बन्द होकर मुद्दाअलेहके पास उसके घरके पतेसे डाकसे भेजा जायगा। अगर उसके मकानसे उस मुकाम तक, जहां अदालत चाकै है, डाक जारी हो, देखो आर्डर ५, रूल २५। किसी दूसरेके राज्यमें पोलिटिकल ऐजण्ट अथवा अदालत द्वारा सम्मन तामील किये जावेंगे जो हिन्दुस्तानमें चाकै हैं। इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ५, रूल २६ तथा G. R. & C. O. Ch. 1 R. 42. ब्रिटिश भारतकी अदालत द्वारा जारी किये हुये सम्मन की तामील मैसूरकी किसी भी दीवानी अदालत के ऊपर की जा सकती है। निज़ाम हैदराबाद के राज्यमें जारी किये हुये सम्मन बंगाल प्रेज़ीडेंसी और आसाममें बिना किसी खर्चके तामील किये जा सकते हैं (देखो G. R. & C. O. Ch. & V. 9.)

किसी सिविल पब्लिक अफसर या किसी रेलवे कंपनी अथवा स्थानीय अधिकारीके ऊपर सम्मन तामील करने के तरीके के सम्बन्धमें देखो आर्डर ५, रूल २७। इसका सारांश यह है कि, अगर मुद्दाअलेह अफसर सरकारी हो या किसी रेलवे कंपनीका मुलाज़िम हो तो सम्मन उसके प्रधान दफतरमें भेजा जायगा जिसमें मुद्दाअलेह मुलाज़िम हो, और सम्मनकी एक नक़ल मुद्दाअलेहको दी जायगी।

इलाहाबादमें आर्डर ५, रूल २७ के साथ में दो नोट—नं० १ और २ जोड़ दिये गये हैं।

फौजी सिपाहियोंके ऊपर सम्मनकी तामीलीके तरीके के बारेमें देखो आर्डर ५, रूल २८ अर्थात् सिपाहीका सम्मन उसके कमांडिङ्ग अफसरके पास भेजा जायगा। भारत मन्त्री इस बातकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि वह आर्डर ५, रूल २८ के अनुसार किसी फौजी अफसरके ऊपर, जो यूरोपमें रहता है, जारी किये हुये सम्मनकी तामीली करवा देंगे, देखो G. R. & C. O. Ch. 1 R. 43.

फ्रांस, स्पेन, इंग्लिजयम, रूस इत्यादिसे आने वाले या वहांको जाने वाले विदेशी सम्मनोंकी तामीलीके सम्बन्धमें देखो G. R. & C. O. Ch. 1. R. 44 & 45

इङ्ग्लैण्डमें सम्मनकी तामीलीके तरीकेकी निश्चत देखो 9 C. L. J. 244

सुवत—जो सम्मन रजिस्ट्री डाकसे भेजा गया है उसकी तामीली साबित करनेके तरीकेके सम्बन्धमें देखो कानून शहादतकी दफा १६ और ११४ (एफ) तथा 16 W. R. 223; 15 C. 681; 21 B. 412 P. 416; 35 B. 219 and. 23 A. 99

सम्मन तामील हो जानेके बाद की कार्रवाई।

जो तारीख सम्मनमें मुद्दाअलेह की हाज़िरी और दावाका जवाब देनेके लिए सुक़रर की गई है, उस तारीख को फ़रीक़ेन मुक़दमा असालतन या बज़रिय वकीलके कचहरीमें हाज़िर होंगे। और इसके बाद मुक़दमें की सुनवाई की जायगी।

जब तक कि फरीकैनकी दरखवास्त के ऊपर अदालत पेशीकी तारीख किसी आगे दिनके लिये न बढ़ा दे (देखो आर्डर ९, रूल १)

जब मुद्दईके खर्चा न देनेके कारण सम्मनकी तामील न हो सकी हो--अगर उस रोज़, जो सम्मनमें मुक़रर किया गया है, यह मालूम हो कि वह सम्मन, मुद्दईके कोर्ट फीस अथवा डाक खर्च वगैरा, जो उसे सम्मन की तामीली के लिये अदा करना चाहिये था, अदा न करने के कारण, तामील नहीं हो सका है, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह नालिश खारिज कर दे, जब तककि मुद्दाअलेह असा-लतन या अपने वकीलके मास्फत हाज़िर न हो जाय (देखो आर्डर ९ रूल २)

मुद्दाअलेहकी हाज़िरीके लिये जो तारीख़ मुक़रर की गई है उस रोज़ मुद्दई के वकील का सबसे पहले और ज़रूरी काम यह होगा कि वह तामील करने वाले चपरासी (मज़दूरी) का रजिस्टर देखे या मिसिल, मुक़द्दमामें उसकी रिपोर्ट देखे और यह देखे कि मुद्दाअलेह पर सम्मनकी तामील हुई है या नहीं। अगर उसे यह मालूम हो जाय कि सम्मन बिना किसी उचित कारणके बिना तामील हुये ही वापस आया है या यह कि वह तामील किये जानेके लिये नाज़िर के अखिस्तेसे जारी ही नहीं किया गया है, यद्यपि तलबाना समयके भीतर जमा कर दिया गया था, तो वकीलको चाहिये कि वह फौरन् इस बातकी इत्तला अदालतको करे और उससे जल्दी सम्मन तामील करने के लिये प्रार्थना करे। अगर सम्मन कतई तामील ही नहीं हुआ है या यह कि मुद्दईके कोई शिनाख्त करने वाला न देने के कारण या उसकी किसी दूसरी भूलके कारण वह जायज़ तौरसे तामील नहीं हुआ है, तो मुद्दईको चाहिये कि वह फिर से सम्मन तामील किये जानेके लिये अदालतसे प्रार्थना करे। उपरोक्त नियम (रूल) के अनुसार कोई भी सम्मन की तामीली न की जा सकेगी, जब तक कि मुद्दई फिरसे तलबाना दाखिल न करेगा, जो ऐसी तामीलीके लिये ज़रूरी हो। जहाँ पर यह मालूम हो कि तामीलके लिये सम्मन जारी ही नहीं किया गया था, यद्यपि तलबाना समय के अन्दर ही दाखिल कर दिया गया था, तो फिरसे तलबाना दाखिल करनेकी ज़रूरत नहीं होगी। अगर सम्मनकी तामीली, मुद्दईके तलबाना न अदा करने या सम्मन न देनेके कारण, नहीं हुई है, तो इस बातका कारण बतलाना चाहिये कि तलबाना क्यों नहीं दाखिल किया गया अथवा सम्मन क्यों नहीं दिया गया, और तलबाना अदा करने और सम्मन दे देने के बाद सम्मनकी तामीलीके लिये अदालतसे दरखवास्त करनी चाहिये।

अगर सम्मन मुद्दईकी ग़लतीसे तामील नहीं हो सका है, तो अदालत, अगर वह फिरसे सम्मन तामील करनेकी दरखवास्त मंज़ूर न करे तो, नालिश खारिज कर देगी। यह रूल उस समय लागू होता है जब सम्मन की तामीली कुल मुद्दाअलेहों या किसी एक मुद्दाअलेह के ऊपर न हुई हो।

आर्डर ९ का रूल २, आर्डर ४८, रूल १ (२) के साथ पढ़ा जाना चाहिये जिसमें यह बतलाया गया है कि तलबाना जमा करने के लिये एक तारीख़

मुकर्रर कर दी जानी चाहिये। अदालत तलवाना न जमा करने के कारण कोई नालिश खारिज नहीं कर सकती, जब तक कि वह इसके लिये कोई समन नियत नहीं कर देती। देखो 3 B. L. R. Ap. 25; 11 W. R. 290.

आर्डर २ के अनुसार दिया हुआ खारिजीका हुक्म काविल अपील है; देखो 9 C. 627; 38 A. 357.

उस समय भी न लिश खारिज कर दी जायगी, अगर तामील करने वाले अफसर के द्वारा सम्मन बिना तामील किया हुआ वापस आनेके बाद तीन महीनेके अन्दर (देखो ऐक्ट नं० २४ सन् १९२० ई०) मुद्दई फिर से सम्मन जानेके लिये दख्वास्त न दे (देखो आर्डर ९, रूल ५)।

बम्बईमें यह मुद्दत ६ मास है।

मियादका हिसाब उस तारीखसे लगाना चाहिये, जिस तारीखको आखिरी बार सम्मन बिना तामील हुये वापस आया हो, देखो 2 Lah. L. J. 774.

जब कोई नालिश उपरोक्त रूलके अनुसार खारिज होगई हो, तो कानून मियादकी पाबन्दी में रहते हुये मुद्दई नये सिरेसे नालिश दायर कर सकता है।

जब मुद्दई और मुद्दाअलेह कोई भी हाजिर न हो—जब मुकद्दमेंकी पेशी को न मुद्दई हाजिर हो और न मुद्दाअलेह, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह मुकद्दमा खारिज किये जानेके लिये हुक्म दे दे (देखो आर्डर ९, रूल ३)

जज इस बातके लिये बाध्य नहीं है कि वह किसी फरीकका अदालत बन्द होने तक इन्तज़ार करे, देखो 7 M. 356.

रूल ३ के अनुसार दिया हुआ हुक्म, जिसके अनुसार कोई नालिश खारिज कर दीगई हो, काविल अपील नहीं है, क्योंकि दफा २ में 'डिकरी' की जो परिभाषा कीगई है उसमें यह कहा गया है कि, उसमें अदम पैरवीमें नालिश खारिज करने का हुक्म शामिल नहीं है (देखो 18 C. W. N. 604; 33 C. 341.) और न उस समय उसकी नज़रसानी ही हो सकती है जब मुद्दई रूल ४ के अनुसार दख्वास्त न देवे (देखो 2 C. W. N. 318; 26 C. 598. लेकिन अदालतको इस बातका इतमीनान दिलाने पर, कि उसके हाजिर न हो सकनेके पर्याप्त कारण थे, मुद्दई आर्डर ९, रूल ४ के अनुसार नये सिरेसे नालिश दायर कर सकता है या उसकी फिरसे समाअत किये जानेके लिये प्रार्थना कर सकता है। कानून मियादके आर्टि० १६३ के अनुसार मियादकी मुद्दत ३० दिन है। जिस हुक्मसे अपीलकी खारिजी रद्द करने से इन्कार कर दीगई हो, उसकी अपील नहीं हो सकती (देखो 27 C. L. J. 117.) और जिस हुक्मसे मुकद्दमा फिर मंजूर कर लिया गया हो, उसकी भी अपील न हो सकेगी, देखो 10 M. 270; 35 A. 427.

जब सिर्फ मुद्दई ही हाजिर होवे—अगर मुकद्दमेंकी पेशीपर सिर्फ मुद्दई ही हाजिर होता है, मुद्दाअलेह हाजिर नहीं होता, तो नीचे लिखी कार्यवाही की जायेगी:—

(क) अगर यह साबित हो जाय कि सम्मन बाकायदा तौरसे तामील होगया है, तो अदालत एक-तरफ़ा कार्रवाई शुरू कर देगी ।

(ख) अगर यह साबित हो जाय कि सम्मन तामील तो हुआ लेकिन समय इतना नहीं था कि मुद्दाअलेह पेशीकी तारीख़ पर हाज़िर होकर मुकद्दमे की जवाब-देही कर सकता, तो अदालत पेशीकी तारीख़ किसी आगे दिनके लिये बढ़ा देगी और यह हुक्म देगी कि इस पेशीकी तारीख़ बढ़ाये जाने की इत्तला मुद्दाअलेहको की जाय ।

(ग) अगर अदालतको यह मालूम हो जाय कि सम्मन बाकायदा तामील नहीं हुआ या मुद्दईकी ढिलाईके कारण ठीक समयमें तामील नहीं हो सका, तो अदालत मुद्दईको इस तारीख़ बढ़ाये जाने के कारण कुल खर्चोंको अदा करनेका हुक्म देगी (देखो आर्डर ९, रूल ६)

उप-नियम (क) के अनुसार मुद्दाअलेह के ऊपर कानूनन एक-तरफ़ी डिक़री न दी जा सकेगी, जब तक कि अदालतको इस बातका इतमीनान न हो जावे कि सम्मन बाकायदा तौरसे तामील किया गया है । किसी मुकद्दमेंमें एक-तरफ़ी कार्रवाई करनेमें अदालत सिर्फ़ इसी बातको देखनेके लिये बाध्य नहीं है कि मुद्दाअलेह के ऊपर सम्मनकी बाकायदा तामिली साबित होगई है बल्कि उसे यह बात भी देखनी चाहिये कि मुद्दईका मुकद्दमा साबित होगया है । सिर्फ़ मुद्दाअलेहके हाज़िर न होनेसे ही यह अनुमान नहीं कर लिया जा सकता कि मुद्दई जो कुछ कहता है वह सब ठीक ही है । एक तरफ़ी कार्रवाई का मतलब है मुद्दाअलेहके अनुपस्थित होने की दशामें शहादतकी सहायता से मुद्दईके दावा का तय करना ।

अगर तामील करने वाला चपरासी (मज़कूरी) पेशी की तारीख़ को जवाब लेकर न आये, तो अदालत एक-तरफ़ी कार्रवाई न करेगी, यद्यपि मुद्दाअलेहके ऊपर सम्मनकी तामिलीकी बात और तरह पर साबित हो जाय । ऐसी हालतोंमें अदालतको अधिकार है कि वह मुद्दईके दख्खास्त देने पर आगे दिनके लिये पेशीकी तारीख़ बढ़ा दे । एक-तरफ़ी मामलोंमें, फैसला सुनाये जानेके पहिले मुद्दईको, शिनाख़्त करने वाले का हलफ़नामा पेश करके या उसके ज़बानी बयान लेकर, यह साबित करना होगा कि सम्मन की बाकायदा तामिल होगई है ।

अगर पेशीकी तारीख़से १४ दिन पहिले सम्मनकी तामिल न हुई हो, तो वक़ाया लगानकी बाबत कीगई नालिशकी एक-तरफ़ा पुकार और समाअत नहीं की जा सकेगी, (देखो G. R. & C.O.Ch. 1 R. 6) इसी तरह जिस नालिश की समाअत अदालत ख़फ़ीफ़ा द्वारा की जानी चाहिये, उसकी एक-तरफ़ी समाअत उस समय तक न की जा सकेगी जब तक कि पेशीकी तारीख़ से ७ दिन पहिले सम्मनकी तामिल न होगई हो ।

अगर नालिशकी एक तरफ़ी समाअत करनेमें ऊपर लिखी हुई कोई रुकावटें नहीं हैं, तो अदालतको अधिकार है कि वह उस नालिशकी एक-तरफ़ा समाअत करना शुरू कर दे ।

जब पेशी बढ़ाई हुई तारीख को मुद्दाभलेह हाज़िर हो जावे—अगर अदालतमें मुद्दामेंकी एक-तरफ़ा समाप्त करना मुल्तवी कर दिया हो और पेशीकी तारीख बढ़ा दी हो, तथा ऐसी तारीख को या उससे पहिले मुद्दाभलेह हाज़िर होकर अदालतको इस बातका इतमीनान दिला देता है कि उसके पहिली पेशी पर हाज़िर न हो सकने के लिये काफ़ी वजूहात थे, तो अदालत दावाके जवाबमें उसके बयान ले सकती है और उसे अपना बयान तहरीरी दाखिल करने का हुक्म दे सकती है (देखो आर्डर ९, रूल ७).

उपरोक्त नियम (रूल) के अनुसार वह मुद्दाभलेह जो मुक्दमोंकी पहिली पेशीकी तारीख को हाज़िर न हो सका हो, बादकी किसी तारीख को, जिसके लिये पेशीकी तारीख बढ़ा दी गई है, हाज़िर होकर अपने मुक्दमोंकी पैरवी कर सकता है, अगर वह अदालतको इस बातका विश्वास दिला सके कि पहिली पेशीकी तारीख को उसके हाज़िर न हो सकनेके लिये पर्याप्त कारण थे । अगर वह इसका कोई उचित कारण न बतला सका, तो दूसरी पेशी की तारीख को उसे हाज़िर होने और अपने बयान दाखिल करने का हक नहीं रहता और उसे इसके लिये इजाज़त नहीं दी जा सकती और उसके खिलाफ मामलेमें एक-तरफ़ी कार्रवाई की जायगी [देखो 18 W. R. 400 refd. to. in. 1 B. 217]. कानून उसको यह इजाज़त नहीं देता कि वह जिस समय चाहे, हाज़िर होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल कर सकता है ।

किन्तु अगर मुद्दाभलेह पेशीकी बढ़ाई हुई तारीख को हाज़िर होकर मुद्दों के मवाहोंके ऊपर जिरह करके और उस शह्दादतको पेश करके, जो कि उस समय उसके पास मौजूद है, दावाके खिलाफ लड़ना चाहता है, जब कि उसकी इस बातके लिये दी गई दरख्वास्त, कि उसकी पेशीकी तारीख बढ़ाई जाय, खारिज कर दी गई हो, तो कोई भी कारण नहीं कि उसको ऐसा करने की इजाज़त न दी जाय ।

अगर मुद्दाभलेहकी यह दरख्वास्त, कि उसके मामले की फिरसे समाप्त की जाय, खारिज हो जानेके बाद एक तरफ़ी डिकरी दे दी जाय, तो वह आर्डर ९, रूल १२ के अनुसार दरख्वास्त दे सकता है या अपील कर सकता है (देखो 21 M. 324; 8 C. 272; 9 M. 445.).

जब अकेले मुद्दाभलेह ही हाज़िर हो—अगर मुक्दमोंकी पेशीके दिन सिर्फ़ मुद्दाभलेह ही हाज़िर होवे, मुद्दई हाज़िर न हो, तो अदालत नालिशको खारिज किये जानेका हुक्म दे देगी, जब तक कि मुद्दाभलेह मुद्दईके दावाको या उसके किसी हिस्सेको मंज़ूर न कर ले, जिस हालतमें कि अदालत मुद्दाभलेहके इक्बाल के अनुसार डिकरी दे देगी । अगर दावाका एक हिस्सा ही मंज़ूर किया गया है तो बाकी हिस्सा खारिज कर दिया जायगा (देखो आर्डर ९, रूल ८) । अदालत को यह भी अधिकार है कि वह आर्डर १२, रूल ६ के अनुसार, मुक्दमोंमें किसी भी समय, दूसरे झगड़ेके प्रश्नों को बिना तय किये हुये ही, इक्बाल के ऊपर फंसला दे देवे ।

अगर मुद्दईके हाज़िर न हो सकनेके कारण किसी नालिशका कुल या एक अंश खारिज कर दिया गया है, तो आर्डर ९, रूल ८ के अनुसार वह यह दरखास्त दे सकता है कि खारिजीका यह हुक्म रद्द किया जाय और अगर वह अदालतको इस बातका विश्वास दिला सके कि उसके गैर-हाज़िर होनेकी काफी वजह थी, तो अदालत उस हुक्मको मंसूख कर देगी जिसके अनुसार उसने उसकी नालिश खारिज कर दी है (देखो आर्डर ९, रूल ९)

किसी नालिशके खारिज करने वाले हुक्मको मंसूख करनेके लिये दी जाने वाली दरखास्तकी मियाद ३० दिन है, देखो कानून मियाद ऐक्ट नं० ९ सन् १९०८ ई० का आर्टि० १६३ ।

उपरोक्त नियम (रूल) के अनुसार अदालत नालिश खारिज करने वाले हुक्मको मंसूख न कर सकेगी, जब तक कि मुद्दईकी दरखास्तकी नोटिस मुद्दाअलेहके ऊपर तामील न कर दी गई हो ।

हाज़िर होना क्या है, इस सम्बन्धमें देखिये 23 B. 414; 34 C. 403 जब किसी वकीलको सिर्फ़ इननी ही हिदायत की गई हो कि वह पेशीकी तारीख़ बढ़ाए जानेकी दरखास्त दे जिसके इन्कार कर दिये जाने पर वह वापस चला आता है, तो यह हाज़िर होना न कहा जायगा देखो 23 B. 414; 34 C. 403; 22 A. 66; 30 M. 276; 68 I. C. 942; 47 I. C. 27; 54 I. C. 715.

कौन सी “वजह काफी” है और कौन सी काफी नहीं है, यह बात हर एक मामलेके वाक्यात के ऊपर निर्भर करती है । घरमें किसी आदमीका सख्त बीमार हो जाना काफी वजह है किन्तु गाड़ीका छूट जाना काफी वजह नहीं है, देखो 19 I. C. 234—भाई की बीमारी काफी वजह नहीं है, देखो 74 I. C. 847 (P. C.) एक फ़रीक़ उस समय, जबकि अदालतमें एक दूसरे आदमीका मुक़द्दमा पेश था, यह समझ कर, कि “आज मेरे मुक़द्दमोंकी पेशी न होगी” अदालतसे चला गया । उसके अदालतसे चले जानेके बाद मुक़द्दमा खारिज कर दिया गया । तो यह काफी वजह नहीं थी, देखो 19 C. W. N. 25; 13 B. 12; 2 C. W. N. 490—वकीलका हाज़िर न होना काफी वजह नहीं है । फ़रीक़नकी अपेक्षा वकीलोंके साथ कम रियायत करनी चाहिये, क्योंकि वकीलोंका यह काम है कि वे अदालतोंमें ठीक समय पर आ जाया करें और अपने रोज़ानाके कामको ठीक तौर से किया करें [देखो 62 I. C. 253; 33 B. 475; 66 I. C. 789; 62 I. C. 378]

आर्डर ९, रूल ८ के अनुसार किसी नालिशके खारिज हो जाने से उसी बिनाय मुख़ासमतके ऊपर नई नालिश नहीं दायर की जा सकती । अगर दो नालिशोंमें मांगी गई दरख़ास्त अलग अलग है तो इससे उनकी बिनाय मुख़ासमत की समानतामें कोई अन्तर नहीं पड़ता, देखो 15 C. 422. P. C; 14 C. W. N. 298—जब दो मुक़द्दमोंमें बिनाय मुख़ासमत एक जैसी ही नहीं है बल्कि

अलग अलग है, तो नई नालिश दायर की जा सकती है। रूल ८ के अनुसार किसी नालिशका खारिज कर दिया जाना प्राङ्गन्याय (Resjudicata) नहीं है, देखो 16 C. 98 P. C. तथा 10 B. 28; 9 C. 426; 12 C. L. R. 29.

जब आर्डर ९, रूल ८ के अनुसार कोई मुकद्दमा खारिज कर दिया गया हो तो बिना आर्डर ९, रूल ९ के अनुसार पहिले से दरख्वास्त दिये ही उसकी नज़रसानी की जा सकेगी, देखो 26 Cal. 598; 58 I. C. 191 (P.C.)

कई मुद्दई या मुद्दाभलेहोंमें से बहुतों या किसी एक का हाज़िर न होना—जब एक से अधिक मुद्दई या मुद्दाभलेह हों, और उनमें से एक अथवा अधिक हाज़िर हो तो वह या वे बाकी आदमियोंकी तरफसे जो कि हाज़िर नहीं हैं, मुकद्दमोंकी पैरवी कर सकता है या कर सकते हैं, [देखो आर्डर ९, रूल १० और ११]

आर्डर ९, रूल ११ में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे आर्डर ९, रूल ११ के प्रयोगमें कोई विरोध पड़ता हो या जो उसके प्रयोगको सीमाबद्ध करती हो, और इस पिछली दफाका प्रयोग उस मामलेके लिए सीमाबद्ध नहीं कर दिया गया है जिसमें एक ही मुद्दाभलेह है और वह हाज़िर नहीं हुआ है या जहां पर एक से अधिक मुद्दाभलेह हों और उनमें से कोई भी हाज़िर न हुआ हो, देखो 8 C. W. N. 621; 10 C. W. N. 40.

बढ़ाई हुई पेशीकी तारीखको फरीक़ैनका हाज़िर न होना—पहिली पेशीकी तारीख को मुद्दई या मुद्दाभलेह अथवा दोनों के हाज़िर न होने का जो परिणाम होता है, उसकी व्यवस्था आर्डर ९, में की गई है। आर्डर १७, रूल २ और ३ में उसकी कार्रवाई का वर्णन किया गया है जो उस समय की जानी चाहिये जब कि पेशी की बढ़ाई हुई तारीख को फरीक़ैन मुकद्दमा हाज़िर न हों।

अगर पेशीकी बढ़ाई हुई तारीखको फरीक़ैन मुकद्दमा या उनमें से कोई एक फरीक़ हाज़िर न हो सके, तो अदालतको अख्तियार है कि वह आर्डर ९ में बतलाए हुए किसी एक तरीक़ेसे फैसला कर दे या जैसा वह मुनासिब समझे वैसा हुकम दे देवे (देखो आर्डर १७ रूल २)

जब पेशीकी तारीख किसी फरीक़के दरख्वास्त करने पर बढ़ाई गई हो, इसलिये कि वह शहादत पेश कर सके या अपने गवाहोंको हाज़िर कर सके या कोई दूसरा काम कर सके जो उसके दावा की पुष्टि करने के लिये आवश्यक हो, और वह फरीक़ उस कामको या उन कामोंको नहीं करता जिसके लिये या जिनके लिये समय दिया गया था, तो अदालतको अधिकार है कि, इन सब बातोंके होतेहुये भी, वह फ़ौरन् उस मामले का फैसला कर दे (देखो आर्डर १७, रूल ३)

“हाज़िर न हो सके” शब्दका अर्थ जाननेके लिये देखो 23 B. 414; 23 A. 66. रूल २ में उस कार्रवाईका जिक्र किया गया है जो उस समयकी जानी चाहिये जब कि फरीक़ैन पेशीकी बढ़ाई हुई तारीखको हाज़िर न होवें अगर

दोनों फरीक हाज़िर न होसकें तो आर्डर ९, रूल ३ के अनुसार नालिश खारिज कर दी जायगी। अगर मुद्दई गैर-हाज़िर हो तो नालिश इस रूल और आर्डर ९, रूल ८ के अनुसार खारिज की जा सकती है और आर्डर ९, रूल ९ के अनुसार वह फिर दायर की जा सकेगी (देखो 1 M. 287; 36 C.189) —अगर मुद्दा-अलेह गैर-हाज़िर हो तो आर्डर १७, रूल २ तथा आर्डर ९, रूल ६ के अनुसार मुकदमें में एक तरफ़ी डिकरी दे दी जायगी और आर्डर ९, रूल १३ के अनुसार दरख़वास्त देने पर वह डिकरी रद्द की जा सकेगी [देखो 23 C.738 F. B.; 20 B. 380; 20 A. 195]—रूल ३ उस समय लागू नहीं होता जबकि पेशीकी तारीख़ अदालतकी इच्छासे बढ़ाई गई हो। रूल ३ में उस समय की जाने वाली कार्रवाईका वर्णन है जब किसी फरीकको उसीके दरख़वास्त देने पर मुहलत दी गई हो, इसलिये कि वह अपने मुकदमेंकी पैरवीमें कुछ ज़्यादा कोशिश कर सके अर्थात् शहादत पेश कर सके या अपने गवाहोंको हाज़िर कर सके। और वह उस कामको न कर सके, ऐसी दशामें, अगर कुछ ज़रूरी ज़रूरी बातें दर्ज काग़-ज़ात हो चुकी हैं, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह इन्हीं बातोंके आधार पर मुकदमेंका फैसला कर दे और मुकदमेंकी जायदाद के ऊपर फैसला सुना दे (देखो 41 C. 956; 19 C. L. J. 535; 6 Pat. L. J. 313.)—ऐसा भी मामला हो सकता है जिसमें रूल २ और ३, दोनों का कुसूर किया गया हो, अर्थात् जिस मुद्दईने मियाद बढ़ाने का समय लिया वह सिर्फ़ यही करनेमें कुसूर नहीं करता बल्कि पेशीकी तारीख़ पर खुद भी हाज़िर नहीं होता। तो अब ऐसी दशामें अदालतको किस रूलके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिये? बम्बई और मद्रासमें यह तय किया गया है कि ऐसे मामलेमें रूल २ लागू होता है (देखो 20 B. 736; 33 M.241; 41 M. 286)—इलाहाबाद और कलकत्तामें यह तय किया गया है कि ऐसी दशा में रूल ३ लागू होता है (देखो 25 A. 194; 34 C. 235; 41 C. 956.) कलकत्ता हाईकोर्ट ने 34 C. 235 में यह तय किया है कि अगर काग़ज़ातसे कोई मामला नहीं मिलता तो रूल २ के अनुसार कार्रवाई करना मुनासिब होगा लेकिन अगर फैसला देने भरको सामान है तो अदालतको चाहिये कि वह रूल २ के अनुसार कार्रवाई करे। इन रूलोंमें क्या भेद है यह बात ध्यानमें रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके विस्तारमें भेद है और उनके लिये उपाय भी भिन्न भिन्न होता है। अगर रूल २ के अनुसार कोई नालिश खारिज कर दी जाय, तो उस नालिशको बहाल करने के लिये आर्डर ९, रूल ९ के अनुसार उसी अदालतमें दरख़वास्त दी जा सकेगी। अगर रूल ३ के अनुसार नालिश खारिज की गई हो तो उस फैसलेकी अपील या नज़रसानी की जा सकेगी।

“मुकदमेंकी पेशी” के सम्बन्धमें देखो 57 I.C. 748 P.C. जबकिसी मुकदमेंकी बढ़ाई गई पेशीकी तारीख़को मुद्दई तारीख़ बढ़ाये जानेके लिये दरख़वास्त दे और इस दरख़वास्तके खारिज हो जाने पर वकील चला जाता है (बैरू

रहता है) तो यह खारिज करना रूल २ के अनुसार है [देखो 34 C. 235, 30 M. 274; 74 I. C. 942; 46 I. C. 488]

यह रूल इजराकी कार्रवाईमें लागू नहीं होता और उसके खारिज हो जाने पर नई दरखास्त दी जा सकेगी देखो 18 M. 131; 18 B. 429; 15 A. 84; 20 C. 755.

जब मुद्दा या मुद्दाअलेह असालत न हाजिर होने को हुक्म होने पर हाजिर न हों—जब कोई मुद्दा या मुद्दाअलेह, जिसे असालतन हाजिर होने का हुक्म दिया गया है [आर्डर ५, रूल ३] हाजिर नहीं होता या हाजिर न हो सकने की कोई काफ़ी वजह नहीं दिखलाता जिसमें अदालत को इतमीनान हो जाय, तो (अगर वह मुद्दा है तो) आर्डर ९, रूल ८ के अनुसार उसकी नालिश खारिज कर दी जायगी तो (अगर वह मुद्दाअलेह है तो) आर्डर ९, रूल ६ [आर्डर ९, रूल १२] के अनुसार उस मुकद्दमें में एक तरफ़ी डिकरी दे दी जायगी ।

जब बली दौरान मुकद्दमा नालिश को हाजिर न कर सके, तो उस समय अदालत को रूल १२ के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, देखो 55 I. C. 945. जब रूल १२ के अनुसार मुकद्दमा खारिज कर दिया गया हो या एक तरफ़ी डिकरी दे दी गई है, तो उस समय इसके निरुद्ध में यही कार्रवाई की जा सकती है जो आर्डर ९ में बतलाई गई है ।

एकतरफ़ा डिकरी का मंसूख किया जाना—अगर किसी मुद्दाअलेह के ऊपर एक तरफ़ी डिकरी दे दी गई हो, तो वह उसी अदालत को, जिसने वह डिकरी दी है, उस डिकरी को मंसूख करने के लिए दरखास्त दे सकता है, और अगर वह अदालत को इस बात का इतमीनान करा देता है कि “उसपर वाक़ायदा सम्मन तामील नहीं किया गया था या यह कि किसी काफ़ी वजह के सबब मुकद्दमें की पेशी के समय हाजिर न हो सका” तो अदालत (क) उसके ऊपर दी गई डिकरी को, अदालत में खर्चा दाखिल करने सम्बन्धी या दूसरी ऐसी शर्तोंपर, जिन्हें वह मुनासिब समझे, मंसूख करने का हुक्म दे देगी, और (ख) मुकद्दमें की समाप्त के लिए कोई तारीख मुक़रर कर देगी । लेकिन शर्त यह है कि, जब डिकरी ऐसी है कि वह सिर्फ़ उतने ही अंश में मंसूख नहीं की जा सकती जिसका सम्बन्ध सिर्फ़ ऐसे मुद्दाअलेह से है, तो उसका वह अंश भी मंसूख कर दिया जा सकेगा जिसका सम्बन्ध कुल मुद्दाअलेहों से या उनमें से किसी एक मुद्दाअलेह से है, [देखो आर्डर ९, रूल १३]

ऊपर बतलाए अनुसार कोई भी एक तरफ़ी डिकरी मंसूख न की जा सकेगी, जबतक कि मुद्दाअलेह की दरखास्त की नोटिस मुद्दा पर तामील न हो जाय [देखो आर्डर ९, रूल १४]

जिस शर्त के ऊपर एकतरफ़ी डिकरी दी गई है, वह या तो जाबता दीवानी की (१) दफ़ा ९६ के अनुसार इसकी अपील कर सकता है, या (२) दफ़ा ११४ के अनुसार फैसले की नज़रसानीके लिए दरखास्त कर सकता है, या

(३) आर्डर ९, रूल १३ के अनुसार उसके मंसूख किए जाने के लिए दरखास्त कर सकता है। किसी भी मुद्दाअलेह को, यद्यपि उसने कोई बयान तहरीरी दाखिल किए हों, इस बात का अधिकार है कि वह इस रूल के अनुसार किसी एकतरफ़ा डिकरी को मंसूख किए जाने के लिये दरखास्त कर सके। "मुद्दाअलेह" शब्द में "कानूनी प्रतिनिधि" भी शामिल है जो दफ़ा १४६ के अनुसार प्रतिनिधि बनाया गया हो। "काफी वजह के सबब हाज़िर न हो सका" के अर्थ के सम्बन्ध में देखो 13 B. 12. काफी वजह की बात ऐसी है जो हर एक मामले के वाक्यात के ऊपर निर्भर करती है। "हाजिरी" शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ है और इससे तात्पर्य है मुकद्दमें की पैरवी करने के लिए असालतन या वज़रिये वकील के हाज़िर होना। जब कोई वकील मुकद्दमें की तारीख बढ़ाए जाने के लिए दरखास्त दे जो खारिज हो जाय लेकिन उसे अपने मुवकिल की तरफ़ से मुकद्दमें की पैरवी करने का हुक्म न मिला हो, तो जायता दीवानी के अर्थ में यह हाज़िर होना नहीं है, यद्यपि यह फ़रीक असालतन हाज़िर था; देखो 1 Pat. 188.

इस सम्बन्ध में बहुत सी विरोधी नज़ीरें थीं कि, कई एक मुद्दाअलेहों में से सिर्फ़ एक मुद्दाअलेह के दरखास्त देने पर कुल डिकरी मंसूख कर दी जानी चाहिए, या उसका सिर्फ़ उतना ही हिस्सा जिसका सम्बन्ध उस दरखास्त देने वाले से है। सन् १९०८ ई० के जायता दीवानी में दी गई शर्त (Proviso) से यह कठिनाई दूर हो जाती है। यह प्रश्न कि डिकरी कुल मुद्दाअलेहों के खिलाफ़ मंसूख कर देनी चाहिए या सिर्फ़ दरखास्त देने वाले ही के खिलाफ़, हर एक मुकद्दमें के वाक्यात के ऊपर निर्भर करता है। मुमकिन है कोई डिकरी ऐसी हो जिसके छण्ड न हो सकते हों या अगर वह एक मुद्दाअलेह के सम्बन्धमें मंसूख की जाय तो सम्भव है उससे एक दूसरी डिकरी में विरोध पड़ जाय, या सम्भव है बिना सब की पक हो। इन दशाओं में डिकरी कुल मुद्दाअलेहों के सम्बन्ध, में खारिज कर दी जानी चाहिए, देखो 6 C. L. J. 226 और 31 Mad. 454 जिनमें सिद्धान्त के ऊपर बहस की गई है।

अपील—एकतरफ़ी डिकरी को मंसूख करने वाले हुक्म की अपील हो सकती है, देखो 16 C. 426; 19 A. 355; 23 W. R. 147. उस हुक्म की अपील हो सकती है जिसके अनुसार एकतरफ़ा डिकरी मंसूख करनेसे इन्कार कर दी गई हो, देखो 2 Bom. 644, आर्डर 43, रूल १ क्लॉज़ (डी)

मियाद—किसी एकतरफ़ी डिकरी को मंसूख करने के लिये किसी मुद्दाअलेह की ओर से दी जाने वाली दरखास्त की मियाद डिकरी की तारीख़ से से ३० दिन है या जब सम्मन की बाकायदा तामील न हुई हो तो उस समय से जब कि सायल (दरखास्त देने वाले) को डिकरी का पता मिला हो।

एकतरफ़ी डिकरी में मुद्दाअलेह की ग़ैर-हाज़िरी में मुकद्दमें का खारिज होना शामिल नहीं है, देखो 2 C. W. N. 639. इसमें वह डिकरी शामिल है

जो मुकद्दमें की बढ़ाई गई पेशी की तारीख को मुद्दाभलेद के हाजिर न होने की वृथा में आर्डर १७ रूल २, के अनुसार दी गई हो, देखो 23 Cal. 73 (F. B.).

एकतरफ़ी डिकरी में वह एकतरफ़ा हुक्म शामिल है जो जाबता दीवार की दफ़ा ४७ के अनुसार की जाने वाली इजरा की कार्रवाई में जो दफ़ा २ कलॉन (२) में दिए "डिकरी" शब्द की परिभाषा में आती है, दिया गया हो, देखो 3 C. L. J. 276.

कौनसी अदालत डिकरी मंसूख कर सकती है—जिस अदालत ने एकतरफ़ी डिकरी दी हो उसे यह अधिकार नहीं है कि वह उस डिकरीको मंसूख कर सके, जहाँ अपील में यह डिकरी बहाल रखी गई हो या और किसी तरह पर उसका फैसला कर दिया गया हो, देखो 12 C. L. J. 53; 30 M. 535; 37. A. 208; 71 I. C. 383. लेकिन सिर्फ़ इस बात से कि अपील दायर की गई है उस अदालत का यह अधिकार नष्ट नहीं होता जिसने कि डिकरी दी है, देखो, 13 C. W. N. 846; 15 C. W. N. 799; 38 C. 394; 37 A. 208; 39 A. 13 P. C. 39 A. 143; 28 C. W. N. 795; 44 M. 731; 30 M. 535 में इसके सिद्ध रूप कायम की गई है। जब कि वह शख्स, जो किसी एकतरफ़ी डिकरी को मंसूख करने के लिये दरखास्त दे रहा है, अपीलमें फ़रीक़ नहीं बनाया गया था और उसके मामलेका फैसला नहीं हुआ है, तो यह भी दरखास्त देनेका अधिकार रखता है, 39 A. 13; 17 C. W. N. 133; 48 C. 153.

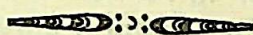
एकतरफ़ी डिकरी मंसूख करने का परिणाम—परिणाम यह होता है कि इन्तदाम मुकद्दमा बहाल रहता है और अदालत को उसकी समाप्त करनी होती है, देखो 21 M. 324; 41 I. C. 956 (C.); 78 I. C. 427 (C.); 21 C. W. N. 794.

साधारण नालिश के जरिये डिकरी का मंसूख करना—आर्डर ९, रूल १३ के अनुसार दी गई दरखास्त खारिज होजाने के बाद भी, धोखे-बाजीकी बुनियाद पर किसी एकतरफ़ा डिकरी के खारिज किए जाने के लिये नालिश दायर की जा सकती है, देखो 24 C. 546; 28 C. 475 P. C. 21 A. 289; 27 C. 197; 29 C. 895 P. C.; 17 C. W. N. 219. उस समय भी नालिश दायर की जा सकती है अब आर्डर ९, रूल १३ के अनुसार दरखास्त न भी दी गई हो, देखो 21 C. 605; 34 I. C. 264.—लेकिन अगर किसी नालिश में बतलाई हुई धोखे की बात सिर्फ़ सम्मन का तामील न होना है और मुद्दई ने आर्डर ९, रूल १३ के अनुसार जो दरखास्त दी है वह नाकामयाब रही है, तो ऐसी नालिश काबिल समाप्त के न होगी, देखो 29 A. 212; 37 C. 197; 27 A. 608; 20 C. W. N. 845; 36 I. C. 128.

धोखे से दो हुई डिकरी को मंसूख करने के लिए की गई नालिश उक्त अदालत में दायर की जा सकती है जिसके अधिकार-क्षेत्र में धोखा किया गया था या जिसके अधिकार-क्षेत्र में आमतौर पर मुद्दाभलेद रहता है; देखो 11 C.

L. J. 636; 25 A. 48; 41 I. C. 161. कोई छोटी अदालत किसी बड़ी अदालत द्वारा धोखे से दी गई डिकरी को मंजूर कर सकती है, देखो 68 P.L. R. 1917; 24 M. L. T. 254; 41 M. 213; 59 I.C. 20 झूठी शहादत देना या झूठा दावा पेश करना किसी डिकरी को मंजूर करने की कोई वजह नहीं है, देखो 23 C. W. N. 133; 24 C. W. N. 133; 50 I. C. 451; 60 I. C. 124; 1 J. L. T. 386.

सम्मनकी तामील होजाने और हाजिर हो जाने के बाद की कार्रवाई ।



बयान तहरीरी और मोजरार्ह—(१) सम्मन तामील होजाने के बाद मुद्दा-अलेह उस रोज़, जो दिन कि उसकी हाज़िरी के लिए मुक़र्र किया गया है, (अ) अदालतन या (ब) किसी वकील की मारफ़त, जिसे बाकायदा मुक़द्दमें के हालात बतला दिए गये हों और जो उस मुक़द्दमें से सम्बन्ध रखने वाले सभी ज़रूरी ज़रूरी सवालों का जवाब दे सकता हो, या (स) किसी ऐसे वकील के मारफ़त जिसके साथ में दूसरा कोई आदमी हो जो ऐसे सवालों का जवाब दे सकता हो, हाजिर हो सकता है और अपने दावा के जवाब में एक बयान तहरीरी दाख़िल कर सकता है [देखो आर्डर ८, रूल १] या अपना बयान तहरीरी तैयार करने और पेश करने के लिए समय के वास्ते दरख़ास्त दे सकता है ।

(२) अदालत के तलब करने पर मुद्दाअलेह बयान तहरीरी दाख़िल करने के लिए बाध्य है ।

(३) यह बयान तहरीरी पहली पेशी को या उससे पहले या ऐसे समय के भीतर पेश किया जायगा जिसके लिए अदालत इजाज़त दे ।

(४) जब कोई फ़रीक़, जिससे अदालत ने तहरीरी बयान तलब किया है नियत समय के भीतर, उसे दाख़िल नहीं करता, तो अदालत को अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध फैसला दे देवे [आर्डर ८, रूल १०]

आर्डर ८ के रूल १० के अनुसार मुद्दाअलेह के लिए यह लाज़िमी नहीं है कि वह बयान तहरीरी ज़रूर दाख़िल करे । अगर वह चाहे तो ऐसा कर सकता है [देखो 11 C. W. N. 871] । हरएक मुक़द्दमें में, अर्थात् चाहे वह रुपये की नालिश हो या हकीयत अथवा और बात की, वह ख़य या वकील की मारफ़त अपना ज़वानी इज़हार पेश कर सकता है । लेकिन अगर अदालत

ने तलब किया हो, तो वह अपने बचाव में बयान तहरीरी दाखिल करने के लिये बाध्य है।

अदालतत खफीफ़ा में दायर की गई नालिशों में बयान तहरीरी दाखिल करना आवश्यक नहीं है।

इलाहाबाद में आर्डर ८ में रूल ११ और १२ जोड़ दिए गये हैं।

बयान तहरीरी का लिखना—जो रूल अर्जीदावा का मसविदा तैयार करने के सम्बन्ध में लागू है उन्हीं में से बहुत से रूल बयान तहरीरी का मसविदा तैयार करने में लागू होते हैं। आर्डर ६ के जो रूल फ्लीडिङ्स के सम्बन्ध में हैं, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए (देखो इस किताब के पेज ९ से १६)—बयान तहरीरी में वे सभी बातें बतला दी जानी चाहिए जो इस बात को ज़ाहिर करती हों कि नालिश काबिल समाप्त है या यह कि वह लिखा-पढ़ी कानून की दृष्टि से या तो नाजायज़ है या नाजायज़ ठहराए जाने के काबिल है और बचाव की ऐसी तमाम वजहें जिनसे अगर वे उठाई न जायें तो, दूसरे पक्षवालों को धोखा हो सकता हो, या उसमें वक़यात सम्बन्धी तनकीहें बतलाई जायेंगी जो अर्जीदावा से पैदा न होती हों, अर्थात् धोखा, मियाद, बेबाकी, अदायगी या मुआहिदा अथवा शर्त की तामील अथवा वे बातें जिनसे बेक़ायदगी का पता चलता हो (देखो आर्डर ८, रूल २)

धोखा (रूल २) अथवा नाजायज़ दवाव की बातों का विस्तार के साथ वर्णन किया जाना चाहिए। सभी मामलों में मियाद की बात दिखलाई जानी चाहिए। लेकिन ख़ास कर उस समय जब कि किसी ख़ास कानून के अनुसार तमादी-आरिज़ हुई बतलाई जाती हो, अन्यथा अदालत मामले पर विचार नहीं करेगी (28 C. L. J. 216)—केवल इतना ही कह देना, कि दावा की तमादी आरिज़ होगई है, इस बात के लिए काफी नहीं है कि इस सम्बन्ध में कोई तनकीह उठाई जाय। जिन बातों से तमादी का सवाल पैदा हो, वे बतलाई जानी चाहिए और कानून मियाद की तथा दूसरी कानून की दफाओं का भी वर्णन कर दिया जाना चाहिए जिनके आधार पर मियाद का सवाल उठाया गया है। अर्जीदावा में बतलाई गई बातों का एकदम इन्कार कर देना काफीन ही है। मुद्दा-अलेह को चाहिए कि वह वाक़यात सम्बन्धी हर एक बात का अलग अलग जवाब दे जिसकी सत्यता को वह स्वीकार नहीं करता, सिवाय एक 'लुकसान' के। अगर कोई बात अन्य बातों के साथ कही जाती है तो उन बातों के साथ साथ उसका इन्कार कर देना काफी न होगा (देखो आर्डर ८, रूल ३. ४)—जो बातें प्रत्यक्ष रूप से इन्कार न करदी जायगीं या जिनके बारे में यह न कह दिया जायगा कि वे स्वीकार कर ली गई हैं, वे स्वीकार करली गई समझी जायगी, सिवाय उस शक़्त के सम्बन्धमें जो किसी तरहपर अयोग्य है। लेकिन शर्त यह है कि अदालत को अधिकार है कि वह इस तरह स्वीकार की गई किसी बात की निश्चत सिवाय इस स्वीकृति के दूसरा सुबूत तलब करे [देखो आर्डर ८, रूल ५]।

जो बयान-तहरीरी कोई मुद्दाअलेह पहिली पेशी को या उससे पहिले दाखिल करे, उसपर कोर्टफीस नहीं लगाया जायगा और वह सादे वाटर मार्क पेपर (Cortidge) पर लिखा जा सकता है [देखो 12 C. L. R. 367. 5 Bom. 400.] जो अर्जीदावा अदालत पहिली पेशीके बाद तलब करे उसपर भी ऐक्ट नं० ७ सन् १८७३ की दफा १९ कलॉज (३) के अनुसार कोर्टफीस लगाए जानेकी जरूरत नहीं है। यह बात फरीकनकी मर्जीपर है कि वे अपनी अर्जियां और बयान तहरीरी अंग्रेजी में दाखिल करें या हिन्दुस्तानी भाषा में, किन्तु, उन्हें उसके साथ अनुवाद दाखिल करना पड़ेगा जिसके लिए जायता दीवानी की दफा १३७ (३) में व्यवस्था की गई है। बयान-तहरीरी पर उसी तरह देस्तखत किए जाने चाहिए और उसकी तस्दीक उसी तरह पर की जानी चाहिए जैसा कि अर्जीदावों के सम्बन्ध में बतलाया गया है [देखो आर्डर ६, रूल १४-१५ और देखो इस किताब का पेज १३-१४]

मुजराई—आर्डर ८ के रूल ६, ७, ८ और ९ में ऐसे नियम बतलाए गए हैं जिनके अनुसार, दी गई रकम को मुजरा पाने का दावा किया जा सकता है। शर्तें ये हैं (क) दावा बाबत वसूली रुपये के हो, (ख) मुजराई की रकम एक निश्चित रकम होनी चाहिए जो कानूनन वसूल की जा सकती है, (ग) रकम अदालत के अख्तियार समाख्त माली के अन्दर हो; (घ) जिस कर्ज के लिए मुद्दाई दावा करे या उसपर दावा किया जाय उसकी तहरीर एक जैसी ही हो। जिस बयान तहरीरी में मुजरा रकम के लिए दावा किया गया है, उसका असर वही होता है जो किसी दावा मुतकाबिलमें दाखिल किए गए अर्जीदावाका होता है [देखो आर्डर ८, रूल ६]। मुजराई देने के समय दीजाने वाली डिकरी के सम्बन्ध में देखो आर्डर २० रूल १९। जरां पर मुद्दाअलेह के दावा या जवाब के कारण अलग अलग हों तो मुजराई अलग अलग और स्पष्ट लिखी जानी चाहिए [देखो आर्डर ८, रूल ७] जो बिना नालिश दायर होने या उस बयान तहरीरी के दाखिल होने के बाद पैदा हुई हो, जिसमें मुजराई रकम की बाबत दावा किया गया है, उसे मुद्दाई अथवा मुद्दाअलेह, जैसी कुछ अवस्था हो, अपने बयान तहरीरी में उठा सकता है (देखो आर्डर ८, रूल ८)—फिजी मुजराई की रकम के सम्बन्ध में बाद में पेश की जाने वाली जो प्लीडिङ्स हैं जवाब दावा को छोड़ कर, वे अदालतके हुक्मसे पेश की जा सकती हैं (देखो आर्डर ८, रूल ९)।

जिस बयान तहरीरी में मुजराई की रकम का दावा किया गया हो या कोई दावा मुखालिफ दायर किया गया हो, उस पर उसी प्रकार स्टाम्प लगाया जाना चाहिये जिस प्रकार अर्जीदावा पर लगाया जाता है (देखो जायता दीवानी का परिशिष्ट (शिड्यूल) ४ तथा 17 C. L. J. 365 F. B.) यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि आर्डर ८ के रूल ६ में दावा मुतकाबिल की जिसकी रकम बतौर मुजराई के दिखाई जा सकती है, वर्णन पूर्णरूप से नहीं किया गया है। इसमें केवल कानूनी रकम मुजराई का जिक्र है। इससे फरीकनका कोई भी ऐसा हक जाया नहीं होता जो उन्हें मुजराई रकम दिलवाने के सम्बन्ध में इस रूल के अन्वया, हासिल है,

फिर वह कानूनी हो या अदालत की मर्जी से दिया हुआ (देखो 2 Mad. H. C. 296; 19 C. W. N. 1183; 2 C. L. J. 73; 9 C. W. N. 178; 17 C. W. N. 1060; 18 C. W. N. 426 P. C. 19 C. W. N. 1183; 19 C. W. N. 1060.).

अदालत का फरीकैन के बयान लेना

अदालत को चाहिए कि वह पहिली पेशीकी तारीखको हर एक फरीक या उसके वकीलसे यह बात अच्छी तरह जांच करलेकि, जो बातें अर्जीदावा या बयान तद्दरीरीमें लिखी गई हैं उनसे इकबाल किया गया या इन्कार । अदालत ऐसे इकबाल या इन्कार को लिख लेगी (देखो आर्डर १०, रूल १)—यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि कोई भी फरीक अपने वकील की इन्कारी या इकबाल के लिए बाध्य नहीं है जो कानून की किसी बात के ऊपर किया गया हो, देखो 9 B. L. R. 377 P. 401 P. C; 18 W. R. 357; 21 All. 285 and 27 Cal. 156 pp. 162-63.)—वकील जो कुछ बयान बहैसियत वकीलके देगा, अदालत उसे स्वीकार करेगी, लेकिन वह उसे हलफ के लिए बाध्य नहीं कर सकती (देखो 3 C. W. N. 694). अदालत को अधिकार है कि वह मुकद्दमें की पहिली अथवा बाद की किसी पेशी के दिन किसी फरीक या उसके साथी के (अगर अदालत में हाजिर हो तो) जबानी बयान ले सके । अदालत ऐसे सवालान्त पूछ सकती है जो किसी फरीक ने तजवीज़ किए हों। ऐसे बयान का सारांश अदालतका जज लिखलेगा (देखो आर्डर १०, रूल २ और ३)

आर्डर १०, रूल २ अदालतको सिर्फ यह बात तय करनेमें सहायता करता है कि फरीकैनमें किस बातका झगड़ा है, और उसके बनानेका मंशा हलफके ऊपर आम तौरसे लिये जाने वाले बयानके स्थानकी पूर्ति करनेका नहीं है। जो बयान कोई शख्स इस रूल के अनुसार बयान लेते वक्त देवे, उससे वही शख्स बाध्य होगा जिसने वह बयान दिया, देखो 2 A. L. J. 777. जब वकील या ऐसा कोई साथी, जिसका उल्लेख उपरोक्त रूलमें कर दिया गया है, किसी जरूरी सवालका जवाब देनेसे इन्कार करे या जवाब न दे सके और अदालत यह समझती हो कि अगर उस फरीकके असालतन बयान लिये जाय तो सम्भव है कि वह उसका जवाब दे सके, तो उसे अधिकार है कि वह पेशीकी तारीख बढ़ा दे और यह हुक्म कर दे कि वह फरीक उस रोज अदालतमें असालतन हाजिर हो । अगर वह फरीक बिना किसी जायज़ (कानूनी) उज्रके उस तारीख मुकद्दरा पर हाजिर न हो सके, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह उसके खिलाफ फैसला दे दे या और कोई दूसरा हुक्म कर दे (देखो आर्डर १० रूल ४)

उम्र तनकीह तलबका फैसल करना और खतम करना पहिली पेशी पर

यह आवश्यक नहीं है कि सब हालतोंमें उम्र तनकीह तैयार किये जाय और उनका फैसला किया जाय। साधारण लगान और रुपयेकी नालिशोंमें तथा खफीफाकी नालिशोंमें आम तौरपर तनकीहें तैयार करनेकी जरूरत नहीं होती है। इस बातकी जरूरत केवल हकीयत वाली तथा दूसरी नालिशोंमें ही है, जिनमें कानूनी या वाक्यातके पेचीदा सवालत पैदा होते हैं, कि तनकीहें तैयार की जानी चाहिये। कलकत्ता हाईकोर्टके एक सल्लर आर्डरके अनुसार, मजिस्ट्रेटोंको यह हिदायत कीगई है कि वे मुकदमा करने के पहिले रुपयेकी नालिशों और रेहननामाकी नालिशोंमें तनकीहें तैयार कर लें।

मुद्दाअल्लेहके ऊपर सम्मन जारी कराने के समय, अदालतको चाहिये कि वह यह तय करे कि सम्मन वास्ते तय करने उम्र तनकीहके होगा या मुकदमें का आखिरी फैसला करने के लिये, और उस सम्मनमें इसीके अनुसार लिख दिया जायगा। (देखो आर्डर ५, रूल ५)।

तनकीहें तैयार करने का उद्देश्य यह है कि हर एक फरीक यह बात अच्छी तरहसे समझ जावे कि किन किन सवालोंके ऊपर बहस की जानी है, ताकि वे उन तनकीहोंसे सम्बन्ध रखने वाली शहादत पेश कर सके (देखो 22 Cal. 324; P. C. 30 Bom. 173; 12 C. L. R. 174)।

तनकीहोंका तैयार करना—तनकीहें उस समय पैदा होती हैं जब कानून या वाक्यात सम्बन्धी किसी जरूरी बातको एक फरीक तो मान ले, लेकिन दूसरा फरीक उससे इन्कार कर दे। प्रत्येक जरूरी बातके आधार पर, जिसे एक फरीक ने मान लिया है लेकिन दूसरे ने इन्कार कर दिया है, अलग अलग तनकीहें कायम की जा सकती हैं। तनकीहें दो प्रकार की होती हैं—(१) वाक्यात सम्बन्धी और (२) कानून सम्बन्धी (देखो आर्डर १४, रूल १)।

अदालत इन तनकीहोंको (क) अर्जीदावा और बयान तहरीरीमें बतलाई हुई बातों से, (ख) उन बयानोंसे जो हलफ पर फरीकैनने या उन आदमियों ने दिये हों जो उनकी ओरसे हाज़िर हुये हैं या जो उनके बकीलोंने दिये हैं, (ग) सवालोंके जवाबमें कही हुई बातोंसे, (घ) फरीकैनके पेश किये हुये दस्तावेज़ों के मजमून से तथा, (ङ) उन बयानोंसे तैयार करैगी जो फरीकैन ने अदालतके बयान लेने पर दिये हों (आर्डर १४, रूल १, ३)—अगर अदालत यह समझती है कि किसी शख्सके बयान लिये बिना या किसी दस्तावेज़का मुलाहिजा किये बिना तनकीहें तैयार नहीं की जा सकतीं, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह उस शख्सको हाज़िर किये जाने या उस दस्तावेज़के पेश किये जानेका हुक्म दे सके (देखो आर्डर १४ रूल ४)।

जिस बातको किसी फरीकने अपनी प्लीडिंग्स में स्वीकार कर लिया हो उसके साबित किये जानेकी आवश्यकता नहीं है और उसके ऊपर किसी तनकीहके तैयार करने की भी आवश्यकता नहीं है। तनकीहें सिर्फ उन बातोंके सम्बन्धमें ही तैयार की जानी चाहिये जिन्हें एक फरीकने स्वीकार कर लिया हो लेकिन दूसरेने इन्कार कर दिया हो। किन्तु यह आवश्यकता नहीं है कि तनकीहें उन तमाम बातोंके ऊपर तैयार की जाय जिनके ऊपर झगड़ा है, बल्कि सिर्फ उन बातोंके ऊपर ही जिनके ऊपर उस मुकद्दमेंका सही फैसला निर्भर करता है। आम तौर पर तनकीहोंका मसविदा दोनों फरीकोंके वकील तैयार करते हैं और जजके सामने उसे पेश करते हैं जो आवश्यक जांचकर लेनेके बाद जज उनको तैयार कर देता है। मुद्दई या उसके वकीलके लिये यह जरूरी है कि वह तनकीहोंके तय करने के लिये मुकद्दरे हुये दिनको अदालतमें हाज़िर हो। तनकीहें तैयार उसी समय की जायंगी जब दोनों फरीकैन हाज़िर हों। अदालत उस समय तनकीहें तैयार करने के लिये बाध्य नहीं है जब कि मुद्दाअलेह हाज़िर न हो बल्कि उसे चाहिये कि वह अपने मामलेमें एक तरफ़ा कार्रवाई शुरू कर दे (देखो 15 W. R., 145) इसी प्रकार यदि मुद्दाअलेह हाज़िर हो और मुद्दई हाज़िर न हो तो बिना किसी तनकीहके तैयार किये हुये नालिश खारिज कर दी जानी चाहिये। तनकीहें तय करने के लिये मुकद्दरे की हुई तारीख़ आर्डर ९ रूल ८ के अर्थमें पेशीकी तारीख़ होती है (देखो 48 I. C. 192.)—जब पहिली पेशीकी तारीख़ को यह मालूम हो जाय कि फरीकैन किसी भी कानूनी या वाक्यात सम्बन्धी बातके ऊपर कोई सवाल उठाना नहीं चाहते हैं तो अदालतको चाहिये कि वह फैसला सुना दे (देखो आर्डर १५, रूल १) जब तनकीहें तय होजाने के बाद यह मालूम हो जाय कि सिवाय उस सुवूत या दलीलके जो फरीकैन उस समय पेश कर सकते हैं ऐसी तनकीहोंके सम्बन्धमें जो उस मुकद्दमेंके फैसले के लिये काफी हैं और किसी सुवूत या दलीलकी जरूरत नहीं है, तो अदालतको अधिकार होगा कि वह फौरन उन तनकीहोंका तय करना शुरू करदे और मुकद्दमेंका फैसला सुना दे, फिर चाहे सम्मन सिर्फ तनकीहें जारी करने के लिये ही जारी किया गया हो या मुकद्दमेंके आखिरी फैसलाके लिये। लेकिन शर्त यह है कि फरीकैन या उसके वकील हाज़िर हों और उनमें से किसीको भी उसपर एतराज न हो (देखो आर्डर १५, रूल ३)—लेकिन अगर काफी सुवूत नहीं है और कोई फरीक सुवूत पेश करना चाहता है, तो उसे चाहिये कि वह मुकद्दमेंकी तारीख़ बढ़ाये जाने के लिए दरखास्त दे और गवाहों पर सम्मन तामील करने के लिए जरूरी कार्रवाई करे। अगर तनकीह तैयार करने से इन्कार कर दांगई हो तो ऐसे हुक्मकी अपील न हो सकेगी (देखो 4 C. 531; 35 M. 1)

जब कि सम्मन वास्ते इनफिलाल मुकद्दमेंके हो और कोई भी फरीक शहादत पेश न कर सके तो अदालतको अधिकार होगा कि वह फौरन फैसला सुना दे या तनकीहें तैयार करके शहादत पेश करने के लिए मुकद्दमेंकी तारीख़ बढ़ा दे (देखो आर्डर १५, रूल ४) —जब कोई नालिश इस रूलके अनुसार खारिज हो

जाय तो मुनासिब कार्रवाई, जो करनी चाहिए अपील करना है। आर्डर ९, रूल ९ के अनुसार दरखास्त देना नहीं है (देखो 8 C. W. N. 97)

पहिले कानूनकी तनकीहें तयकी जानी चाहिये—जब किसी मुकद्दमेंमें अदालत की राय यह हो कि वह मुकद्दमा या उसका कोई हिस्सा सिर्फ कानूनकी तनकीह के ऊपर ही फैसल किया जा सकता है, तो वह इस बातके लिये बाध्य है कि पहिले उन्हीं तनकीहों पर विचार करे और उसे वह अधिकार होगा कि वह कानूनकी तनकीहोंके तय न हो जाने तक वाक्यात सम्बन्धी तनकीहोंपर विचार करना स्थगित रखे (देखो आर्डर १४, रूल २)

तनकीहोंका संशोधन करने और खारिज कर देनेके सम्बन्धमें अदालतका अधिकार—अदालत को अधिकार है कि वह डिकरी देनेके पहिले किसी भी समय तनकीहोंमें तस्मीम कर दे या और जायद तनकीहें तैयार कर दे; और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह किसीभी ऐसी तनकीहको खारिज कर दे जो उसे ग़लत तौर पर तैयार किया हुआ या पेश किया गया मालूम होवे (आर्डर १४, रूल ५)

उम्र तनकीह तलबका फैसला होजानेके बादकी कार्रवाई

वकीलको चाहिये कि फैसले के लिये पैदा हुए भिन्न भिन्न प्रश्नोंके तय होजाने और तनकीहें बन जानेके बाद वह उस शहादत के ऊपर विचार करे जिससे वह अपने दावाको साबित कर सकता है या अपने विरोधीके दावाका जवाब दे सकता है। उसे चाहिये कि वह उन तमाम दस्तावेज़ोंको और उस तमाम शहादतको अपने पास जमा कर ले जो उसके मवकिलके पास मौजूद हों। लेकिन साथ ही इसके मुकद्दमेंकी मज़बूती के लिये उसे चाहिये कि वह अपने मुखालिफ़ फरीकसे तमाम ज़रूरी ज़रूरी बातोंकी जानकारी हासिल करले और इस बातको अच्छी तरह से जान ले कि उसके मुखालिफ़ फरीकके पास कोई ऐसे कागज़ात तो नहीं है जिससे उसके मुकद्दमेंमें कोई मदद मिलती हो या जो उसके मुकद्दमेंमें कोई ख़राबी पैदा करता हो। यह बात जायता दीवानीमें बतलाये हुये "Discovery and Inspection" तथा Admission (अर्थात् इन्किशाफ़ और मुआइना दस्तावेज़ तथा उसका इक़बाल कर लेना) के अनुसार बड़ी आसानीसे की जा सकती है (देखो आर्डर ११ और १२)—अगर ठीक समय पर इसका प्रयोग कर लिया जाय तो मुकद्दमें बाज़ी बहुत कुछ कम हो सकती है और बहुत सा वक्त मेहनतका और बहुत सा रुपया बच सकता है। लेकिन बद-किस्मतीसे प्रेज़ीडेन्सी टाउन्सके बाहर रहने वाले वकील बहुत कम इन ऊपर बतलाये हुये नियमोंका पालन करते हैं। अगर वकील साहबान इन

नियमोंका पालन करें तो उनको फौरन मालूम हो जायगा कि उनसे कितना लाभ होता है।

बन्द सवालोंके जरिये जांच करना—किसी भी मुकदमेंमें मुद्दै या मुद्दाओंको अधिकार है कि वह अदालतकी आज्ञासे मुखालिफ फरीकके बयान लेने लिये मुकदमेंसे सम्बन्ध रखने वाली बातोंके सम्बन्धमें लिखित सवाल पेश करे (देखो आर्डर ११ रूल १)—रूल १-११ जांचकी पहिली शाखा से सम्बन्ध रखते हैं, अर्थात् सवालोंका जवाब देने से। सवाल करनेका मुख्य उद्देश्य यह है कि मुखालिफ पार्टी से जवाब पानेके कारण खर्चासे बचना। १२ से १९ तकके रूल जांचकी दूसरी शाखा से सम्बन्ध रखते हैं जो कागजातके सम्बन्धमें हैं।

किसी मुकदमेंके हर एक फरीक को यह अधिकार है कि वह इस बात को जाने कि उसके मुखालिफ फरीकके मामलेकी हालत क्या है, ताकि उसे पता चले कि यह बात मालूम होजाय कि उसे कितन कितन बातोंका सामना करना है। मुद्दा मुद्दाअलेह पर इस लिये सवाल कर सकता है कि उसे ऐसी बातोंका पता चले जाय जो उसके मुकदमेंकी ताईद करती हों। मुद्दैके वकीलको चाहिए कि जहां कहीं उसे इस बातका इतमीनान होजाय कि मुद्दाअलेह को कोई ऐसी बात मालूम है या उसके पास कोई ऐसा कागजात है जिनके मिल जानेसे उसके मुकदमेके निकलका मुकदमा जोरदार हो जायगा, मुद्दाअलेह से सवालात करे। दूसरी तरफ मुद्दाअलेहके वकीलको चाहिये कि वह बयान तहरीरी दाखिल हो जाने के बाद जहां कहीं उसे ऐसा करनेकी जरूरत मालूम पड़े, मुद्दैके पास सवाल भेजने के लिये दरखास्त दे। इंग्लिश-लॉके अनुसार सवालात इस बातका इतमीनान करने के लिये पूछे जाते हैं कि फरीक मुखालिफके मुकदमेंकी हालत क्या है। लेकिन 17 कलकत्ता 840 में (जो सन् १८८२ ई० के ज़ाबत दीवानी अनुसार फ़ैसल किया गया है), यह तय हुआ था कि सवालात एलीटिंगस की कमी को पूरा करने या इस बातका निश्चय करने के लिये तैयार नहीं किये जाते हैं कि फरीक मुखालिफके मुकदमें की हालत क्या है, देखो 23 Cal. 111 लेकिन, जैसा कि 41 कलकत्ता 6 में बतलाया गया है, कि इंग्लैंड और हिन्दुस्तान में रिवाजमें अब कोई भेद नहीं रखा गया है। यद्यपि हर एक फरीकको यह अधिकार है कि वह अपने मुकदमेंके सम्बन्धमें जानकारी हासिल करनेकी गरज दूसरे फरीकसे सवालात पूछे, उसे यह इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वह दूसरे बातोंके सम्बन्धमें जानकारी हासिल करनेके लिये सवाल पूछे, जो उसके विरोधी पक्ष वाले के मुकदमेंकी शहादतमें पेश की जायंगी। ऐसे सवालात करनेकी इजाज़त नहीं दी जा सकती जो सिर्फ इसी गरजसे किये जाते हों कि उसे अपने विरोधी पक्ष (फरीक मुखालिफ) के मुकदमेंमें कोई मुकस मिलता है या नहीं (देखो 17 Cal. 840.)

“फरीक मुखालिफ” का अर्थ केवल उसी फरीकसे नहीं है जिसका नाम मिसिलमें बतौर फरीक मुखालिफके दर्ज है। अगर उनके दर्मियान कोई ऐसी बात है तो एक एक मुद्दाअलेह दूसरे मुद्दाअलेहसे सवाल पूछ सकता

(देखो 18 Q. B. D. 193) “फरीक मुखालिफ” का मतलब उस मुद्दाअलेह से भी नहीं है जो किसी दावा की जवाब-देही करने के लिये हाज़िर नहीं होता है। मुद्दा ऐसे शख्सों या मुद्दाअलेहांसे सवाल नहीं कर सकता जो उसके पक्ष का समर्थन करते हों (देखो 63 I. C. 258) आर्डर ११ नावालिफोंके सम्बन्धमें है (देखो आर्डर ११, रूल २३)

सवालोंका मसविदा करनेके सम्बन्धमें नियम— [१] सवालात उन बातोंके सम्बन्धमें होने चाहिए जिनकी बाबत झगड़ा है और नालिश की गई है। वे मुकद्दमों के लिए तैयार किए जाने चाहिए और जिन बातोंके निस्बत जांच की गई है वे ऐसे होने चाहिए जिनका पूछा जाना उस समय आवश्यक है जिस समय वे पूछे गये हैं (देखो आर्डर ११, रूल १)। (२) किसी भी फरीकको, अदालत की आज्ञाके बिना एक से अधिक सेट सवालातके एक ही फरीकसे पूछनेकी इजाज़त नहीं है (देखो आर्डर ११, रूल १)। (३) जब एक से अधिक आदमी ऐसे हों जिन पर सवाल किए जाते हों, तो उन सवालातमें यह बात लिख दी जायगी कि उनमें से किसका जवाब कौन दे (देखो आर्डर ११, रूल १), (४) ऐसे सवालात जांचता दोधानीके परिशिष्ट (Appendix) (सी) में बतलाए हुए फार्म नं० २ के नमूनेके होंगे और अवस्थानुसार उसमें परिवर्तन एवं परिवर्धन कर दिये जायेंगे (देखो आर्डर ११, रूल ४)। (५) ये सवालात मामलेको बहुत तूल देने वाले, तकलीफ देने वाले और अनावश्यक अथवा वाहियात न होंगे (देखो आर्डर ११, रूल ७)

सवालातके जवाब—(१) सवालातोंके जवाब बयान हलफ़ीमें दिये जायेंगे जो दस रोजके भीतर या ऐसे समय के भीतर दाखिल किया जायगा जिसके लिये अदालत इजाज़त दे (आर्डर ११ रूल ८)

[२] जो हलफ़ नामा सवालोंके जवाबमें दाखिल किया जायगा वह परिशिष्ट (सी) के फार्म नं० ३ में होगा और उसमें आवश्यक परिवर्तन एवं परिवर्धन (इज़ाफ़ा) कर दिया जायगा (देखो आर्डर ११, रूल ९)। [३] सवालोंके जवाबमें पेश किये हुये किसी हलफनामा की निस्बत कोई एतराज़ न किया जा सकेगा, लेकिन अगर ऐसे किसी हलफनामा के काफी होने की निस्बत कोई एतराज़ किया जायगा तो अदालत उसे तय करेगी (देखो आर्डर ११, रूल १०)। [४] अगर वह शख्स, जिसे सवालात किये गये हैं, किसी सवालका जवाब नहीं देता है या ऐसा जवाब देता है जो काफी नहीं है तो उस शख्सके दखलाने देने पर, जिसने कि सवालात किये हैं, अदालत उसे हुक्म देगी कि वह बज़रिये हलफनामा या ज़ुजानी उस सवालका जवाब दे या बाकी और जवाब दे (देखो आर्डर ११, रूल ११) [५] जिस शख्ससे सवाल पूछे गए हैं वह किसी भी सवालका इस बिनापर जवाब देने से इनकार कर सकता है कि वह (अ) तोहमत लगाने वाला, या (ब) असंगत है, अथवा (स) वह दावाकी गरज़के लिए पूछा नहीं गया है, या (द) यह कि जो बातें पूछी गई हैं उनका मुकद्दमोंकी इस अवस्था में पूछा जाना अनावश्यक है (देखो आर्डर ११, रूल ६)। [६] अदालत

को अधिकार होगा कि वह, उस शख्सके दरख्वास्त देने पर, जिससे कि लालत पूछ गये हैं, किसी भी सवालको इस बिनायपर खारिज करदे कि वह कि ज़रूरत या हंगाम करने के लिए पूछा गया है, या उसे इस बिनाय पर उड़ा कि वह मामले को तूल देने वाला, तड़क करने वाला, अनावश्यक या तोहफा लगाने वाला है (देखो आर्डर ११, रूल ७)

कागजातकी खोज—अदालतको अधिकार होगा कि वह किसी फरीकके दरख्वास्त देने पर उस मुकद्दमेके किसी भी दूसरे फरीकको यह हुक्म दे देवे कि वह हलफके साथ उन कागज़ तकी खोज करे जो उसके कब्जे या अधिकारमें और उन बातोंसे सम्बन्ध रखते हैं जिनकी वाबत झगड़ा है। लेकिन शर्त यह है कि अगर अदालतकी यह राय हो कि, मुकद्दमेका इन्साफ के साथ फैसला होने खर्चकी बचतके लिये ऐसी खोजकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी खोजका हुक्म दिया जायगा (देखो आर्डर ११, रूल १२)

जिस शख्सको कागज़ात पेश करने के लिए हुक्म दिया गया है वह पालफनमेंके साथ परिशिष्ट (सी) के फार्म ५ में उन कागज़ातको तफसीलत दर्ज करेगा और अगर किसी कागज़ के पेश करनेमें कोई एतराज़ होगा तो भी लिख दिया जायगा (देखो आर्डर ११, रूल १३)

नोट—यह हो सकता है कि किसी मुकद्दमेके किसी फरीकके कब्जे या अधिकारमें ऐसे कागज़ हों, जो उन बातोंसे सम्बन्ध रखते हों जिनका वाबत झगड़ा है। यह रूल उसके मुखालिफ फरीकको अधिकार देता है कि वह मुलाहिजाके लिये उन कागज़ातको हासिल कर सके और उस कार्यवाही विधान करता है जो ऐसी अवस्थामें की जानी चाहिए। वह कार्यवाही संक्षेपमें इस प्रकार है—शख्स कागज़ात चाहता है, वह बिना कोई हलफनामा दाखिल किये हुए अदालतसे यह प्रार्थना सकता है कि वह उस शख्सको, जिसके कब्जे या अधिकारमें वह कागज़ है, बयान हलफी दाखिल करे। का हुक्म दे जो “बयान हलफी कागज़ात” के नामसे प्रसिद्ध है [आर्डर ११ रूल १३] और कि यह बात लिखी होगी कि उस मुकद्दमेसे सम्बन्ध रखने वाले कौन कौनसे कागज़ात उसके कब्जे या अधिकारमें हैं। ज्यों ही अदालत ऐसा हुक्म दे देगी, त्यों ही वह शख्स, जिसके कब्जे या अधिकारमें “कागज़ात” हैं, अपना बयान हलफी कागज़ात दाखिल करनेके लिये बाध्य होगा। जो कागज़ात उसके कब्जेमें नहीं है बल्कि पहले किसी समय थे उनके सम्बन्धमें उसे यह लिखना चाहिये कि वे कहाँ हुए, ताकि फरीकसानी उन्हें उस शख्ससे हासिल कर सके जिनके कब्जेमें वे अब हैं। अगर वह हुक्मकी तामील नहीं करता, तो वह आर्डर ११, रूल २१ में बतलाए हुए दण्डका भारी होगा।

कागज़ातका पेश किया जाना—कागज़ातके सम्बन्धमें बयान हलफी (देखो आर्डर ११ रूल १३) दाखिल करने के बाद वह शख्स, जिसकी दरख्वास्त के ऊपर कागज़ात पेश किए जानेका हुक्म दिया गया है, अपने मुखालिफ फरीक को इस बातके लिए बाध्य कर सकता है कि वह उसके मुलाहिजे के लिए कागज़ात पेश करे जिनके देखने के लिये वह कानूनन अधिकारी है (देखो आर्डर ११, रूल १४)

कागज़ात पेश करने का हुक्म उभूर तनकीह तैयार करने के पहिले दिया जा सकता है (देखो 14 C. W. N. 147.) कागज़ात पेश करने के

हुक्म सिर्फ इस रूल के अनुसार ही दिया जा सकता है । मुलाहिजा हुक्म आर्डर १८ के अनुसार दिया जाना चाहिए (देखो 14 I. C. 51).

अगर कोई ऐसे कागजात हैं जिनके पेश करने के सम्बन्धमें उस शख्सको एतराज है, तो उसे चाहिये कि वह रूल १३ के अनुसार अपने बयान-हलफोंमें उन्हें उस एतराज की वजूहात के साथ बतला दे । इस सम्बन्धमें यह स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी फरीक अपने मुखालिफ फरीकके मुलाहिजाके लिए (अ) कोई ऐसा कागज, जो खुद उसके दावा या हकीयतकी शहादत है (ब) कोई भी गुप्त लिखा-पढ़ी जो उसके और उसके कानूनी सलाहकारके दरमियान हुई हो (देखो कानून शहादतकी दफा १२६ और १२९) और कोई भी ऐसा सरकारी कागज, अगर उसके प्रकट हो जाने से सार्वजनिक हितमें कोई बाधा उपस्थिति होती हो, पेश करने के लिए बाध्य नहीं है (देखो कानून शहादतकी दफा १२३—१२४)

कागजातका मुलाहिजा—मुकद्दमेंके किसी फरीकको किसी भी समय उन तमाम कागजात के देखनेका अधिकार है जिनका उल्लेख फरीकसानीके अर्जी-दावा, बयान तहरीरी, या बयान हलफोंमें किया गया गया है और उस फरीकके ऊपर इस बातकी नोटिस तामील करने के बाद, कि वह उसके मुलाहिजाके लिये कागजात पेश करे, उनकी नकलें पानेका अधिकार है । नोटिस परिशिष्ट (सी) फार्म नं० ७ में होनी चाहिए । जो शख्स नोटिस तामील होने के बाद भी कागजात पेश नहीं करता, वह उनके न पेश किए जानेके लिए माकूल वजह बतलाए बिना उन कागजातको शहादतमें पेश कर सकने का अधिकारी नहीं है (देखो आर्डर ११ रूल १५, १६) । इसी तरह की व्यवस्था कानून शहादतकी दफा १६४ में की गई है । जब नोटिस दिए जानेके बाद कोई फरीक किसी दस्तावेजको पेश करे और दूसरा फरीक उसका मुलाहिजा करे तो वह फरीक उसे बतौर सुबूतके देनेके लिये बाध्य है, अगर उसका मुखालिफ ऐसा चाहता है तो (देखो कानून शहादतकी दफा १६३) ।

नोट—आर्डर ११ के १५ से १८ तक के रूल, केवल उन कागजात से सम्बन्ध रखते हैं जिनका जिक्र किसी फरीक के अर्जीदावा, बयान तहरीरी, या बयान हलफोंमें किया गया हो । १२ से १४ तक के रूलों में तमाम ऐसे कागजात की खोज और उनके पेश किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है जो किसी फरीक के कब्जे या अधिकार में हों और जो उस मुकद्दमें से सम्बन्ध रखते हों, चाहे ऐसे कागजात का उल्लेख प्लीडिंग्स में किया गया हो या नहीं । रूल १५ में उन तमाम कागजात के फौरन ही मुलाहिजा करने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है जिनका उल्लेख प्लीडिंग्स या बयान हलफों में किया गया है । रूल १५ के अनुसार दरखास्त मुकद्दमें के आरम्भ में दीजानी चाहिए । यह बात भी याद रखनी चाहिए कि सिवाय किसी फरीक या उसके वकील के और किसी भी शख्स को रूल १५ के अनुसार कागजात का मुलाहिजा करने का अधिकार नहीं है । “फरीक” शब्द में उसका मुस्तार मजाज भी शामिल है, लेकिन अदालत ऐसे मुस्तार को मुलाहिजा करने की आज्ञा नहीं देगी, अगर वह पहिले फरीकसानी के पास नौकर था और उसके कागजात का इंचार्ज था (देखो 25 C. 294). उस कार्यवाही को जानने के लिए, जो कागजात के मुलाहिजा (मुआइना) के

लिए व्यवस्था करती है, अर्थात् मुआइना का समय, मुआइना का हुक्म, व्यापार का तस्दीक मुद्रा-प्रतियों का मुआइना इत्यादि, देखो रूल १६, १७, १८ और १९। अगर जिस मुलाहिजा के लिए दरखास्त की गई है उसका समय अभी नहीं आया है और अदालत को इस बात का इतमीनान होगा है कि मुलाहिजा करने का हुक्म उस समय पैदा होता है जब कोई ऐसी तनकीह या सवाल तय होजाय जिसकी निश्चित झगड़ा है, तो अदालत को चाहिए कि वह उस तनकीह या सवाल के फैसल न होने तक मुलाहिजा करने की इजाजत न दे [देखो आर्डर ११ रूल २०]। मुद्दाअलेह उन कायजात का मुलाहिजा करने का हकदार नहीं है जिन्हें मुद्दई ने बयान तदरीरी दाखिल करने के पहिले अपने दावा का आधार माना था, देखो 24 C. W. N. 302.

मुलाहिजा (मुआइना) के लिए दिए हुए हुक्म की अपील नहीं हो सकती [देखो 11 Bom. L. R. 248; 9 B. H. C. 298].

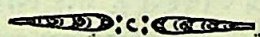
खोज या मुलाहिजा के हुक्म की तामील न करने के लिए दण्ड—जब कोई शख्स, जिसे सवालात का जवाब देने अथवा कागजात की खोज या मुलाहिजा के सम्बन्ध में हुक्म दिया गया है, ऐसे हुक्म की तामील न करे, तो उसका, अगर मुद्दई है तो, मुकद्दमा अदम मुब्रूत में खारिज कर दिया जायगा, और अगर वह मुद्दाअलेह है तो उसकी सफाई मंसूख कर दी जायगी। इस रूल के अनुसार दिए गए हुक्म की अपील हो सकती है।

इकबाल—कागजात और वाक्यात के इकबाल के सम्बन्ध में जाबते का बर्णन आर्डर १२ के रूल १ से ७ तक में किया गया है। इस जाबते के अनुसार कार्य करना अनिवार्य (लाज़िमी) नहीं है, लेकिन यह सम्भव है कि इस अनुसार कार्य करने से मामले का फैसला जल्द हो सके। इसलिए यह मुनाविह मालूम होता है कि हर एक वकील को वह सब तलब मामलों में इस जाबते के अनुसार कार्य करना चाहिए। “इकबाल” (Admission) शब्द की परिभाषा के लिए देखो कानून शहादत की दफा १७। भिन्न भिन्न प्रकार के इकबालों और उनके सुबूत के लिए देखो कानून शहादत की दफा १८---२२। दीवानी मुकद्दमों में इकबाल जायज़ न माना जायगा, अगर वह इस प्रकट अथवा अप्रकट शर्त के ऊपर किया गया है कि वे शहादत में पेश न किए जायंगे [देखो कानून शहादत की दफा २३]। ऐसे इकबाल को “इकबाल बिना तरफदारि (Admission without prejudice)” कहते हैं। आमतौर पर वह लिखा-पढ़ी या बात-चीत, जो फ़रीक़ेन के बीच, नालिश दायर होने के पहिले इस इरादे से की गई हो कि आपस में राज़ीनामा हो जाय या मामला पंचायत से फैसल करा लिया जाय, इसी के अन्तर्गत मानी जाती है जिन बातों का इकबाल मुद्दाअलेह ने नालिश दायर होने से पहिले और नालिश दायर होनेकी तारीख़ को मुद्दईके वकील से किया था, वह क़ाबिल तस्लीम माना गया, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रकट अथवा अप्रकट शर्त नहीं थी कि वे शहादत में पेश न की जायंगे [देखो 20 C. W. N. 1217].

जाबते का इकबाल नीचे लिखे तरीकों से किया जा सकता है:—(१) प्लीडिंग्स के ऊपर, फिर वह चाहे प्रकट हो अथवा अप्रकट, (देखो आर्डर ८, रूल ३, ४, ५) (२) सवालों के जवाब में (देखो आर्डर ११, रूल २२); (३) पेशा होने के पहिले तहरीरी इकरारनामा के जरिये; (४) नोटिस के जरिये (देखो आर्डर १२, रूल १, २, ४); (५) पेशी के वक्त फरीफ मुकदमा या उसके वकील की ओर से (देखो कानून शहादत की दफा ५८) .

इकबाल करने का जाबता—(१) मुकदमें का कोई भी फरीफ लिखित नोटिस के जरिये दूसरे फरीफ को यह इतला दे सकता है कि वह उसके कुल या कुछ हिस्से दावा को सही मानता है [देखो आर्डर १२, रूल १] . कोई भी फरीफ लिखित नोटिस के जरिये, दूसरे फरीफ को किसी ऐसे कागज़ (आर्डर १२, रूल २) या किसी खास बात या बातों को स्वीकार करने के लिए लिख सकता है जिसकी नोटिस पेशी की तारीख से अधिकसे अधिक ९ दिन पहिले दी जायगी (देखो आर्डर १२, रूल ४) । अगर कागज़ात या वाक्यात का इकबाल करने के लिए नोटिस न दी गई हो, तो ऐसे कागज़ात को साबित करने का खर्चा न दिलाया जाय [देखो आर्डर १२, रूल २, ४] . (२) वाक्यात का इकबाल करने के लिए दी जाने वाली नोटिस फार्म नं० १० में होनी चाहिए और वाक्यात का इकबाल जाबता दीवानी के परिशिष्ट (सी) के फार्म नं० १० में होना चाहिए । (४) जब आर्डर १२, रूल ४ के अनुसार वाक्यात का इकबाल कर लिया गया हो तो कोई भी फरीफ मुकदमें की किसी भी अवस्था में अदालत से उसी इकबाल के ऊपर फैसला देने के लिए प्रयत्न कर सकता है [देखो आर्डर १२, रूल ६] .

कागज़ातका पेश करना, उनका अदालत के कब्जेमें रखना, वापस और तलब करना



कागज़ी शहादत पेश करने सम्बन्धी नियम—(१) फरीफैन या उनके वकीलों को चाहिये कि वे मुकदमें की पहिली पेशी को (क) वह तमाम कागज़ी शहादत पेश करें जो उनके कब्जे या अधिकार में है और जो वे अपने दावा की ताईद (समर्थन) में पेश करना चाहते हैं और जो पहिले पेश नहीं की गई थी, तथा (ख) तमाम ऐसे कागज़ात पेश करें जिनके पेश करने के लिये अदालतने हुकम दिया है (२) इस तरह पेश किये गए कागज़ात के साथ साथ उनकी एक सही फेहरिस्त दाखिल की जानी चाहिये जो एक मुकर्रर नमूने की तैयार की जायगी [देखो आर्डर १३, रूल १] . (३) जो कागज़ात पेश तो किये जाने चाहिए था लेकिन जो (आर्डर १३ रूल १) नियमानुसार पेश नहीं किये गए हैं, वे मुकदमें की किसी भी वाद की अवस्था में शहादत में पेश न किये जाय

सकेंगे, जबतक कि मुनासिब समयपर उनके पेश न किए जाने की काफ़ी वजह न दिखला दी गई हो [देखो आर्डर १३, रूल २]।

अदालत को किसी भी ऐसे कागज़ के खारिज कर देने का अधिकार है जो ग़ैर ज़रूरी है या और किसी तरह नाकाबिल तस्लीम है।

उन कागज़ात में, जिनके आधार पर दावा किया गया है, तथा उन कागज़ात में, जो दावा के सबूत में पेश किये जाने को हैं, बहुत बड़ा अन्तर है। ऐसा देखा गया है कि पहिली किस्म वाले कागज़ात अर्जी-दावा के साथ ही पेश किये जाते हैं [देखो आर्डर ७, रूल १४, १८ (१)]। लेकिन दूसरे तमाम कागज़ात, जो सबूत में पेश किए जाने को हैं, अर्थात् जिन्हें वे अपने मुकद्दमें की ताईद में बतौर जायद शहादत के पेश करना चाहते हैं, मुकद्दमें की पहिली पेशी के दिन पेश किए जाने चाहिए (रूल १), और रूल २ के अनुसार जो कागज़ात उस रूल की शर्तों के अनुसार पेश नहीं किए गए हैं, उन्हें अदालत बाद में किसी भी वक्त शहादत में पेश किये जाने की इजाज़त न देगी, जब तक कि उसे यह बात अच्छी तरह से मालूम न हो जाय कि पहिले उनके पेश न किये जाने की कोई माकूल वजह थी। सन् १९०८ ई० के जावता दीवानी ने इस रूल को बहुत कुछ बदल दिया है, और आर्डर १३, रूल १ और २ के अनुसार, जो सन् १८८९ ई० के जावता दीवानी की दफ़ा १३८ से मਿन्न है, किसी भी ऐसे कागज़ के लेने की क़तई मनाही कर दी गई है जो पहिली पेशी के दिन पेश नहीं किया गया था। जब तक कि उसके उस समय पेश न किये जा सकने का समुचित कारण न बतलाया जाय (देखो 70 I.C. 278)। इस लिये हर एक वकील को उपरोक्त रूल की शर्तों ध्यान में रखनी चाहिये, क्योंकि अगर बिना समुचित कारण के फ़रीक़ेन पहिली पेशी की तारीख़ को वह तमाम कागज़ी सबूत पेश न कर सके जो वे अपने दावा भी सफ़ाई की ताईद में पेश करना चाहते थे, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल अधिकार न रहेगा कि वे उसे बाद में किसी भी समय पेश कर सकें।

आर्डर १३ का रूल १, आर्डर ८ के रूल १८ (२) के साथ पढ़ा जाना चाहिये जिसमें इस रूल से मिन्न व्यवस्था है और जिसमें यह इजाज़त दी गई है कि कुछ कागज़ात किसी भी समय पेश किये जा सकते हैं। “पेश करना” शब्द का अर्थ है निगाह के सामने या इत्तला में लाना, इसका मतलब दाख़िल करना नहीं है। फ़रीक़ेन के लिये यह ज़रूरी है कि वे कागज़ात अदालत में अपने साथ लावें लेकिन उन्हें उस समय तक पेश करने की इजाज़त नहीं है जब तक कि वे तलब न किये जायं, देखो। B.L. R. 120; 10 W.R. 179; 12. C.W.N. 312; 8C. L. J. 174. अगर कोई कागज़ (Document) ऐसा है जिसका इन्फ़राज किसी ख़त, किताब या दूकान की किताब अथवा किसी दूसरी हिसाब की किताब में है जो उस समय रोज़ाना काममें लाई जाती है, तो उसकी एक नक़ल पेश की जानी चाहिए जिसका आर्डर ७, रूल १७ में बतलाए तरीक़े से मिलान और उसकी तस्दीक़ किए जायंगे [देखो आर्डर १३, रूल ५] “पहिली पेशी” का, उस मुकद्दमें में, जिसमें मुकद्दमें का आखिरी फैसला करने की रायज़ने बरामन जारी किया गया है

साधारणतः अर्थ उस तारीख पेशीसे होगा जो उस सम्मनमें दी गई है, और जिस मुकद्दमें सम्मन उमूर तनकीहका फैसला करनेके लिए जारी किया गया है, उसमें उसका अर्थ होगा वह तारीख जो तनकीहांका फैसला हो जाने के बाद मुकर्र की गई है।

पहिली पेशीका अर्थ जाननेके लिए देखो 14 A. 524 P. 526. कलकत्ता हाईकोर्टके एक मुकद्दमें यह तय किया गया है कि "पहिली पेशी" का अर्थ है वह तारीख जब पहिले पहल मुकद्दमा विचारके लिए पेश किया गया हो, और वास्तव में उस पर विचार भी किया गया हो वह तारीख नहीं जो मुकद्दमेंकी पेशीके लिए मुकर्र की गई है लेकिन जिस रोज उस पर विचार नहीं किया गया है (देखो 50 I. C. 296)। अगर इन शब्दोंका यही अर्थ हो तो वास्तवमें इसका अर्थ आखिरी तारीख पेशीसे होगा अर्थात् वह दिन जिस दिन मुकद्दमेंकी सचमुच समाप्त की जायगी। इस अर्थसे रूल १ और २ की शर्तें रद्द हो जाती हैं, क्योंकि इस रूलका उद्देश्य यह है कि फरीकतको मजबूर किया जाय कि वे कुल कागजात पहिली पेशी की तारीखको पेश कर दें, वरना वे वापस दिए जायेंगे, अगर किसी बादकी तारीखको पेश किये गये। इस रूल का मुख्य उद्देश्य है मुश्तबा कागजात पेश करने के रूलसे बचाता, जावतेकी शहादतको शुभा किये जानेसे बचाना नहीं, जैसे सरकारी कागजात या अदालतोंके कागजातकी तरह सरकारी कागजात (Public documents)की तस्दीक शुद्ध नकलें। इसलिये ऐसे कागजात शहादतमें लिये जा सकते हैं, अगर वे पहिली पेशीके दिन पेश नहीं किये गये हैं (देखो 23 W.R. 29; 6 C.L.J. 621; 12 C.W.N. 312. 12 C.W.N. 31 में यद्यपि पहिली पेशीकेवक्त कागजात पेश न करने के लिये कोई भी जायज दजह नहीं दिखलाई जा सकी थी, अदालतने अपने अख्यारसे सरकारी कागजात बादको भी कुबूल कर लिये थे। इसे इस बातके लिये प्रमाण न मान लेना चाहिये कि सरकारी कागजात मुकद्दमेंकी किसी भी अवस्था में पेश किये जा सकते हैं, फिर चाहे कितनी ही देर क्यों न होगई हो। जैसा कि चीफ जस्टिस मिलरने कहा है "उस मुकद्दमेंके सिद्धांतको ज़रूरतसे ज्यादा विस्तार न देना चाहिये और यह कि सिर्फ यह बात, कि नालिश दायर होने के बहुत पहिले से वह कागज मौजूद था, इस बातके लिये काफी वजह नहीं है कि बादमें किसी भी समय उसके पेश करने की इजाज़त दे दी जाय (देखो (78 C.L.J. 489))"। अदालत को अख्यार है कि, अगर वह चाहे तो, बाद में किसी भी समय कागजात ले सकती है (देखो 27 C. L. J. 119; 22 C. W. N. 50 P. C.) लेकिन इस अधिकारका प्रयोग में लाना एक मात्र पहिली पेशीके समय उसके पेश न कर सकने के लिये अच्छी वजह दिखलाने पर निर्भर करता है।

"उनके कब्जे या अधिकारमें" शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उपरोक्त रूलों में सिर्फ उन्हीं कागजात के फौरन पेश किये जाने के लिये व्यवस्था की गई है जो असलमें उस फरीकके कब्जे या अधिकार में हों। अगर कागजात उस

फरीक के कब्जे या अधिकार में नहीं है और इसलिये वे पहिली पेश के दिन पेश नहीं किये जा सकते तो अदालतको अधिकार है कि वह उनके बादमें पेश किये जाने के लिये इजाजत दे देवे। वे उस फरीक के कब्जे या अधिकारमें न समझे जायेंगे, अगर वे किसी दूसरे मुकद्दमेमें दाखिल किये गये हैं या अगर वे उस अदालतकी मिसिलमें नहीं हैं जहां से उनकी नकलें ली जाती हैं। ऐसी दशमें फरीकैनको चाहिये कि वे उन कागजात की एक सही फेहरिस दाखिल करें और अदालतसे यह दरखवास्त करें कि उन्हें उनके बादमें दाखिल करने की इजाजत दी जावे।

कागजातकी पुस्तके ऊपर कुछ बातोंका लिखा जाना—उन कागजातके ऊपर, जो या तो शहादत में कुबूल कर लिये गये हैं या नाकाबिल तस्लीम समझकर वापस कर दिये गये हैं, उनकी पुस्त पर अदालतको कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिये और वे किस प्रकार लिखी जानी चाहिये, इस सम्बन्धमें देखो आर्डर १३ के रूल ४ से ७ तक।

अदालतोंकी ओरसे कागजातको अपने कब्जेमें लिया जाना—अदालतको अधिकार है कि, अगर वह माकूल वजह मालूम पड़े तो, किसी भी ऐसे कागज या किताबके सम्बन्धमें, जो कि उसके सामने किसी मुकद्दमेमें पेश किया गया है, यह हुक्म दे देवे कि वह हिफाजतमें रखा जावे और अदालतके किसी भी अफसर की सिफारशीमें उतनी मुद्दतके लिए और उन शर्तों के साथ दे दिया जावे जिसे अदालत मुनासिब समझे [देखो आर्डर १३, रूल ८]

नोट—हर एक वकीलको चाहिये कि वह, केहि कागज दाखिल करने से पहले, यह देख ले कि उसपर काफी स्टाम्प लगा है या नहीं और उसकी तकमील ठीक तौर से कीगई है। अगर उस कागज पर काफी स्टाम्प नहीं लगा है तो अदालत उसे उस समय तक न लेगी जब तक कि उसके सम्बन्धमें वह कुल रसूम और तावान, जिसका विधान स्टाम्प ऐक्ट (सं० २ सन १८९९ ई०) में किया गया है, अदा न करें दिये जायें।

वर्तमान स्टाम्प ऐक्टके जारी होनेसे पहले लिखे गए दस्तावेज—ऐसे बिना स्टाम्प लगे या नाकाफी स्टाम्प लगे हुये दस्तावेजोंके ऊपर विचार करनेमें, जो इस वर्तमान स्टाम्प ऐक्टके जारी होने के पहिले लिखे गये थे, जो कार्रवाई की जानी चाहिए और जो तावान उस पर लगाया जाना चाहिए, उनके लिए पुराने कानूनों के अनुसार नियम नहीं बनाने चाहिये, जो मसूख कर दिये गये हैं, बल्कि नये कानूनोंके अनुसार बनाने चाहिये (देखो G. R. & C. O. Chap. II. R. 46)

हकवाल कर लिए गए कागजातका वापस करना—कोई भी शख्स जो किसी भी ऐसे कागजको वापस लेना चाहेगा जो कुबूल कर लिया गया है और दर्ज कागजात कर लिया गया है, उसके वापस पानेका हकदार होगा, (क) जहां पर मुकद्दमा ऐसा हो जिसकी अपील नहीं हो सका, जब कि मुकद्दमा फैसला हो गया है और (ख) जिसमें अपील हो सकती है उसमें उस समय जब अपील का बक खतम होगया हो या अगर अपील दायर कीगई है तो अपीलका फैसला

होनेके बाद कोई कागज़ वक्त मुकदमोंके पहिले भी वापस दिया जा सकता है, अगर उसकी एक तस्दीक शुद्ध नकल उसकी जगह नथी कर दी जाती है और सायल इस बातका इफ़रार कर देता है कि ज़रूरत पड़नेपर वह असली दस्तावेज़ (कागज़) को अदालतमें पेश कर देगा। ऐसा कोई भी दस्तावेज़ (कागज़) वापस न किया जायगा जो किसी डिकरीकी वजहसे नाजायज़ या बेकाम हो गया है। जो दस्तावेज़ (कागज़) शहादतमें कुबूल कर लिया गया है, उसे वापस पाने वाले शख्सको उसकी रसीद देनी होगी (देखो आर्डर १३ रूल ९)

कागज़ातका तलब करना—(१) अदालतको अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से या किसी फ़रीक़ के दरखास्त देने पर, अपनी मिसिलों से, या दूसरी अदालत की मिसिलों से, किसी भी कागज़ या दस्तावेज़को तलब कर सके और उसका मुलाहिज़ा कर सके [देखो आर्डर १३, रूल १०], (२) उपरोक्त रूल के अनुसार दी जाने वाली दरखास्तके साथ में उसकी तारीख़ के लिये एक हलफ़-नामा होगा जिसमें लिखा होगा (क) कि यह कागज़ इस मुकदमेके लिये ज़रूरी है (ख) यह कि बिना अनुचित विलम्ब या खर्चाके सायल उसकी एक बाकायदा तस्दीकशुद्ध नकल नहीं पा सकता और (ग) यह कि न्याय (इंसाफ़) के लिए असली कागज़का पेश किया जाना ज़रूरी है (देखो आर्डर १३ रूल १०)

कागज़ात एक फ़ेहरिस्त के ज़रिये से दाखिल किये जावेंगे और जब ऐसा कागज़, जिसका इन्दराज उपरोक्त फ़ेहरिस्त में है, शहादत में पेश किया जाय तो, अगर वह खारिज कर दिया गया है तो, उसकी पुश्त पर वे तमाम बातें लिख दी जानी चाहिये, जिनका बर्णन ज़ाबता दीवानी के आर्डर १३ रूल ६ में किया गया है, और वह उस शख्स के पास भेज दिया जाना चाहिये जिसने उसे पेश किया था और वह शख्स उस फ़ेहरिस्त के खाना ४ में उसके पानेकी रसीद लिख देगा। अगर वह शहादत में कुबूल कर लिया गया है, तो वह उस फ़ेहरिस्त से निकाल लिया जायगा और आर्डर १३ के रूल ४ में बतलाई हुई बातें उसकी पुश्तपर लिख दिये जाने के बाद वह उस फ़ेहरिस्त में नथी कर दिया जायगा जिसका उल्लेख आगे वाले रूल में किया गया है (देखो G. R. & C. O. Chap. III R. 23).

सभी मातहत अदालतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे सरकारी कागज़ात, जिनका बर्णन कानून शहादत की दफ़ा ७४ में किया गया है, बिना ज़रूरतपेश न किये जायं। लेकिन जब कोई कलक्टर या दूसरा कोई सरकारी अफ़सर ज़ाबता दीवानी के आर्डर १६ रूल १ और ६ के अनुसार अदालत में कोई कागज़ पेश करने के लिये तलब किया गया हो, तो उसका यह कतव्य होगा कि वह ऐसे कागज़ को उस अदालत में भेज दे; परन्तु साथ ही इसके ऐसे अफ़सरको अधिकार होगा कि वह असालतन जाकर या बज़रिफ़ खतके उस कागज़के पेश किये जानेके सम्बन्धमें अपना उज्र जाहिर कर दे और उस उज्र के वजूहात भी लिख दे, और तब यह अदालतका काम होगा कि वह उस उज्र के ऊपर विचार करे और फ़रीक़नके बयान लेने के बाद, अगर ऐसा करना ज़रूरी

मालूम हो तो, यह तय करे कि उसे उस कागज़को पेश किए जाने का हुक्म या न दे (देखो G. R. and. C. O Chap III. note 1 to 23)

अगर कोई कागज़ ऐतिहासिक या प्राचीन हो, तो अदालतको चाहिये कि वह उस पर इकिजविट नम्बर डाल कर या अपनी अदालतकी मोहर छाप कर उसे सुराख होने से बचानेका यथाशक्ति प्रयत्न करे (देखो G. L. No. 1917; Note 2 to rule 23). जो कागज़ात हर एक फ़रीक़की ओर से शहदात में कुबूल किये गये हों उनकी अफ़सर इन्चार्ज रेकर्ड, फार्म नं० (M) 171V. II G. R. & C. O. में एक अलग फेहरिस्त तैयार करेगा और उस पर प्रिन्टिंग जजके दस्तख़त होंगे। इस फेहरिस्त में वे कागज़ात उसी क्रम से दर्ज किए जायेंगे जिस क्रम से वे लिये गये हैं और उन पर निशान डाले गये हैं (देखो G. R. & C. O Chap. III R. 24). (अ) जो कागज़ात सुद्दी या सुद्दियातकी ओर से पेश किये गये हैं, उनपर अदालत उसी क्रम से नम्बर डालेगी जिस क्रम से वे स्वीकार किये गये हैं, जैसे १, २, ३, ४ इत्यादि, और जो कागज़ात सुद्दाअलेहकी ओर से पेश किये गये हैं उन पर अंग्रेज़ीके बड़े अक्षर डाल दिये जायेंगे, जैसे A. B. C. इत्यादि। (ब) जब दो या दो से अधिक लोग सुद्दाअलेह हों, तो पहिले सुद्दाअलेहके कागज़ात पर A 1, B 1, C 1 इत्यादि निशान डाले जाते हैं और दूसरे के कागज़ात पर A 2, B 2, C 2 इत्यादि निशान (देखो G. R. & C. O. Chap. III. R. 25)। जो कागज़ात दाख़िल किये गये हैं उन्हें अदालत के हाकिमों को सुराख नहीं करना चाहिये, सिवाय उसके जिसके लिये क़ानून उन्हें आज्ञा देता है, अर्थात् उस पर यह लिख देंगे कि अमुक मुक़द्दमें में वह पेश किया गया है [देखो G. R. & C. O. Chap. III Note to rule 25].

जब एकही किस्मके बहुत से कागज़ात पेश किये गये हों, उदाहरणार्थ लगान की बहुत सी रसीदें, तो उन कुल कागज़ात के ऊपर एक निशान बड़ा अङ्क या अक्षरसे डाला जायगा और मुख्य अङ्क या अक्षरके नीचे एक छोटा अङ्क या अक्षर लिख दिया जायगा और उनके बीचमें एक लकीर खींच दी जायगी ताकि उनमें से हर एक कागज़ अलग किया जा सके (देखो G. R. & C. O. Chap. III R. 26).

जब कोई असली कागज़, उस पर पहचान के लिये निशान डाल दिए जाने के बाद, वापस कर दिया जाय और आर्डर ७, रूल १७ अथवा आर्डर ११ रूल ५ ज़ावता दीवानी में बतलाये अनुसार उनकी एक नक़ल रख ली जाय, तो उस फेहरिस्त में, जिसका उल्लेख उपरोक्त रूल में किया गया है, यह लिख दिया जायगा कि असली कागज़ वापस कर दिया गया है (देखो G. R. & C. O. Chap. III R. 27)।

जब कोई भी सरकारी कागज़ (जो किसी मुक़द्दमें की मिस्सिल या अदालत की कार्रवाईका कागज़ नहीं है) अथवा कोई ऐसा कागज़, जो सरकारी दफ़्तर ज़त में है किसी सम्मनकी तामील में अदालत में पेश किया गया हो और जिस हाकिमकी मुहाफ़िज़त में वह कागज़ था वह उसे जल्द से जल्द वापस मांगता हो, तो उस कागज़का मुआइना हो जाने या शहादत में उसके पेश हो जानेके बाद

अदालतको चाहिये कि वह उसकी नकल लेकर, जिसकी अदालतको ज्ञावता दीवानी के आर्डर १३, रूल ५ (२) के अनुसार ज़रूरत हो, उसे जहाँ तक जल्द मुमकिन हो उस अफसरके पास वापस कर दे। उस नकलके तैयार करनेका खर्चा वह शख्स देगा जो उसे शहादत में पेश करना चाहता है (देखो G. R. & C. O. Chap. III Note to rule 27) । जिस कागज़को मुकद्दमें के किसी फरीक ने पेश किया हो लेकिन वह शहादत में दाखिल न किया गया हो, वह मुकद्दमा खतम होने पर उस शख्सको, जिसने उसे पेश किया है, अथवा उसके वकील को वापस कर दिया जायगा । वकील इस बात के लिये बाध्य है कि वह उन कागज़ात को वापस ले जिन्हें उसके मक्किलने दाखिल किया हो और जिन्हें वापस किये जाने के लिए अदालत ने इस रूलके अनुसार, हुक्म दे दिया हो, और उनके लिये फेहरिस्तके मुनासिब खाने में रसोद लिख दे (देखो G. R. & C. O. Chap. III R. 28 A.) ।

(क) अगर कोई बाहरी आदमी, जो मुकद्दमें में फरीक नहीं है, सम्मन की पाबन्दी करते हुये अदालत में कोई कागज़ दाखिल करे, तो उसे वह पता लिख देना होगा जिस पते से वह कागज़ वापस किया जाना चाहिये, अगर वह उसे खुद आकर नहीं ले लेता ।

(ख) अगर कोई कागज़ शहादत में पेश न किया जाय या कुबूल न किया जाय, तो वह उस शख्सको, जिसने उसे पेश किया है, असालतन या बज़रिये रजिस्ट्रीछुदः डाकके फौरन् वापस कर दिया जायगा ।

(ग) अगर कोई कागज़ शहादत में, कुबूल कर लिया जाय तो उसकी एक तस्दीकछुदः नकल मिसिल में नथी करदी जानी चाहिये । इसके बाद वह असली कागज़, असालतन या बज़रिये रजिस्टर्ड डाकके, उस शख्सको वापस कर दिया जायगा जिसने उसे पेश किया है, जब तककि उस कागज़की असलियतके बारेमें कोई झगड़ा न हो, जिस दशामें असल कापी मुकद्दमा फैसल हो जाने के बाद वापस की जायगी, अगर अदालतने इसके लिये कोई और हुक्म न दे दिया हो, अथवा अगर मुकद्दमेंकी अपीलके लिये इजाज़त दी गई है तो अपीलके लिये काफी मौका देने के बाद वापस किया जायगा, या अगर अपील दायर की जा चुकी है तो उस अपीलका फैसला हो जाने के बाद वापस किया जायगा ।

(घ) अगर कागज़ात, जो पेश किए गये हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हिसाब की बहियाँ, या ज़मींदारी के कागज़ात, जो सुविधा के साथ रजिस्टर्ड डाक से वापस नहीं किए जा सकते, तो जिस शख्स ने उन्हें दाखिल किया है उसे, अगर वे कागज़ात उसे फौरन् वापस नहीं कर दिए गए हैं तो, रजिस्टर्ड डाक से यह सूचना दी जायगी कि वह किसी भी समय उन्हें ले जा सकता है, और यह कि उसे मुनासिब सफ़र खर्च वगैरा दिया जायगा । यही कार्रवाई उस समय भी की जायगी जब कागज़ात दाखिल करने वाले शख्स ने यह तहरीर लिख दी हो कि कागज़ात बड़े कीमती हैं और वह उन्हें खुद आकर ले जायगा ।

(ड) अगर कागजात दाखिल करने वाले शख्सके कोई ऐसा वकील या मुख्तार है जिसे कागजात वापस लेने का अख्तियार है, तो वे कागजात उस वकील या मुख्तार को वापस कर दिए जायेंगे, जब तककि उस शख्सने कागजात दाखिल करते समय लिखकर यह इजहार न कर दिया हो कि वे असात-तन या रजिस्टर्ड डाक से उसी को वापस दिए जायें ।

(च) मुकद्दमेंके किसी फरीककी ओर से उपरोक्त उप-नियम (क) में बतलाए हुए किसी कागज के तलब किए जाने के पहिले उस फरीक को उसमें होने वाला खर्चा जमा कर देना होगा, जिसमें रजिस्टर्ड डाक से उस कागज की वापसी का खर्च, उप-नियम (ग) के अनुसार तस्दीक शुद्ध नकल तैयार करने का खर्च और उप-नियम (घ) की दशा में उस शख्स के सफर का खर्च शामिल है जिसने कागजात दाखिल किए हैं । उप-नियम (घ) में बतलाई हुई अवस्था में सफर खर्च मय उस रजिस्टर्ड खत के, जिसका उल्लेख किया गया है, उस शख्स को दे दिया जायगा जिसने कागज दाखिल किया हो (देखो G. R. & C. O. Chap. III. R. 30-Rule No. 6 of 1924.)

वे नियम जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दफा १२२ के अनुसार तय किए हैं—आर्डर १२ के साथ रूल १२ और १३ और जोड़ दिए गए हैं ।

गवाहों का तलब किया जाना, और उनकी हाजिरी तथा पेशी का बढ़ाया जाना

गवाहों का तलब करना—मुकद्दमा दायर किए जाने के बाद किसी भी समय फरीकैन, शहादत देने के लिए या कागजात पेश करने के लिए गवाहों की हाजिरी के वास्ते सम्मन जारी किए जाने के लिये दरखवास्त दे सकते हैं (देखो आर्डर १६, रूल १)।

सम्मन जारी करने की दरखवास्त हमेशा जहां तक जल्द मुमकिन हो दी जानी चाहिये । इसमें सन्देह नहीं कि किसी मुकद्दमें के फरीकको मुकद्दमेंका आखिरी फैसला होने के पहले किसी भी समय अपने गवाहों के नाम सम्मन जारी कराने का अधिकार है, लेकिन अदालत को यह अधिकार है कि वह गवाहों के हाजिर न हो सकने की वजह से मुकद्दमें की पेशी बढ़ाने से इन्कार कर दे जो जायज़ होगा, अगर सम्मन जारी करने के लिये मुनासिब वक्त के अन्दर दरखवास्त नहीं दी गई है, देखो 16 A. 218; 15 B. 86; 20 C. 740; 63 I.C. 736; 8 I.C. 418. उस समय भी सम्मन जारी करने से इन्कार कर दी जा सकती है जब दरखवास्त ठीक तौर से न दी गई हो (देखो 28 M. 28) या जब उस दरखवास्त का मंशा न्याय में बाधा पहुँचाने का हो । (देखो 4 I.C. 797).

सम्मन जारी होने के पहले गवाहों के सफर वगैरह का खर्च अदालत में एक मुनासिब मियाद के अन्दर दाखिल कर दिया जाना चाहिये, जो मियाद अदालत तय करेगी। अदालत को अधिकार है कि वह किसी Expert (वह शख्स जो किसी के दस्तखत या निशान अंगूठाकी पहचान करता है) को मुनासिब मुआबिजा उसकी मेहनत का दिला देवे (देखो आर्डर १६, रूल २; आर्डर ४८ रूल १)। भिन्न भिन्न प्रान्तों की हाईकोर्टों ने भिन्न भिन्न श्रेणियोंके गवाहोंके लिए खर्चकी भिन्न भिन्न किस्में मुकररकी हैं और इसलिये जो रुपया जमा किया जावे वह इस सम्बन्ध में बने हुए नियमों के अनुसार ही जमा किया जाना चाहिये [देखो आर्डर १६, रूल २]। इस तरह पर जमा किया हुआ रुपया सम्मन की तामील के वक्त गवाह को अदा कर दिया जायगा (देखो आर्डर १६, रूल ३)।

जब कोई सिविल सरकारी अफसर या किसी स्थानीय अधिकारी वर्ग का नौकर या किसी रेलवे कम्पनी का नौकर शहादत में तलब किए जानेको हो, तो सम्मन उस मोहकमेंके आला अफसरके मारफत जारी किया जायगा जिस मोहकमें में वह गवाह काम करता है (देखो आर्डर ५, रूल २७)। अगर कोई सरकारी नौकर शहादत में तलब किया जाय, तो सम्मन की एक नकल उसके अफसर के पास भी उसकी जानकारी के लिए भेज दी जानी चाहिये [देखो Cal. H. C. C. O. No. 1 of 17. 1. 1883] जब कोई सरकारी नौकर शहादत में तलब किया जावे तो वह अपनी तनख्वाह पाने का हकदार नहीं है, देखो 38 C. L. J. 149. कलकत्तामें आर्डर १६, रूल २ (१) के साथ नीचे लिखी शर्त जोड़ दी गई है:—“लेकिन शर्त यह है कि जब कोई सरकारी नौकर सरकार की ओर से तलब किया जावे तो इस रूलके अनुसार अदालत को उसके सफर वगैरहका खर्च अदा करने की ज़रूरत न होगी” और यह शर्त, आगे लिखी दूसरी शर्त आर्डर १६, रूल ३, के साथ, जोड़ दी गई है लेकिन शर्त यह है कि इस रूल के अनुसार उस सरकारी नौकर को रुपया न दिया जायगा जिसकी माहवारी तनख्वाह १० रुपये से अधिक होगी या जिसका हेडक्वार्टर अदालत से ५ मील से अधिक फासले पर वाक़े हो, जब कि ये किसी ऐसे मामले में, जिसमें सरकार मुद्दई या मुद्दाअलेह है, ब-हैसियत सरकारी नौकर के तलब किए गए हों।”

तलबी के सम्मन के साथ साथ या ऐसे वक्त के अन्दर, जिस में तामील की जा सके, तलबाना और सम्मनके लिये दी गई दरख्वास्त भी दाखिल कर दिये जाने चाहिये, नहीं तो सम्मन जारी न किया जायगा। अक्सर सम्मन पेश करने में बड़ी दिक्कत की जाती है जिसका नतीजा यह होता है कि पेशी की तारीख को यह देखा जाता है कि मुद्दई-मुद्दाअलेह सम्मन तामील न हो सकने के कारण हाज़िर नहीं हो सके। उस के कारण इस बात की आवश्यकता और बढ़ जाती है कि पेशी की तारीख को एक दूसरी दरख्वास्त दी जाय जिसमें इस बात की माकूल वजह दिखलाई जावे कि सम्मन हुकमनामा जारी करके क्यों तामील किया जावे और अगर वह दरख्वास्त मंजूर करली जायगी तो सारी कार्रवाई

मुलतवी कर दी जायगी। लेकिन अदालत को अधिकार है कि वह सम्मन तामील करने में गफलत होने की वजह से पेशी की तारीख बढ़ाने के लिये दी गई दख्खास्त को ना-मंजूर कर दे। अगर सम्मन और तलवाना पेशी की तारीख से थोड़े ही दिन पहिले दाखिल किये गये हों तो यह समझा जायगा कि सम्मन उस फरीककी ज़िम्मेदारीपर जारी किया गया है और पेशीकी तारीख फिर बढ़ाई न जायगी (देखो 1 Pat. L. J. 173), जब कोई गवाह किसी खास कागज़ के पेश करने के लिये तलब किया गया हो, तो सम्मन में इस का साफ़ तौर से और सही सही हवाला होगा (देखो आर्डर १६ रूल ५) ताकि गवाह को यह मालूम हो जाय कि कौनसा कागज़ तलब किया गया है। ऐसा हुक्म जारी करना कि असुक्त मामले से सम्बन्ध रखने वाली कुल चिट्ठियां या कुल कागज़ात पेश किये जाने चाहिये, बिल्कुल वाहियात होगा।

अगर कोई शख्स अदालत में हाज़िर है, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह उसे वहीं पर उसी समय शहादत देने या दे कागज़ात पेश करने का हुक्म देदेवे जो उस समय वहां पर उस के पास मौजूद हों (देखो आर्डर १६ रूल ७)।

सम्मनकी खिलाफ वजी—जब जान-बूझ कर किसी सम्मनके हुक्मकी तामील न की गई हो या तामील बचाई गई हो तो अदालतको अधिकार होगा कि वह उसको हाज़िरी के लिये इशतहार जारी करे और साथही गवाहकी गिरफ्तारीके लिये जमानती या गैर-जमानती वारण्ट जारी करे तथा उसे यह भी अधिकार होगा कि वह उसकी जायदाद की कुर्की के लिये भी हुक्म देदे जो कुर्की के खर्च और उस जुर्माने के रुपये से जायद न हो जो कि उसपर लगाया जावे (देखो आर्डर १६ रूल १०)।

किसी गवाह की हाज़िरी के वास्ते ये कार्रवाइयां किये जाने के लिये दख्खास्त देने का काम उस शख्स का है जो उस शख्स की शहादत चाहता है, अदालत का यह काम नहीं है (देखो 11 W. R. 99; 13 W. R. 324) जब ऐसा आदमी हाज़िर न हो या हाज़िर तो हो पर अपने पहिले हाज़िर न हो सकने की कोई कानूनी वजह न दिखला सके, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह उस पर जुर्माना, जो ५००) रु० से अधिक न हो, कर दे और उस जुर्माने को उसकी जायदाद की कुर्की या नीलाम से वसूल करे [देखो आर्डर १६ रूल १२]।

रूल ११ में ऐसे मामले के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है जिसमें अदालत को उस शख्स ने यह इतमीनान करा दिया हो कि हुक्म की तामील न कर सकने में उसका कोई खास इरादा ऐसा न कर सकने का नहीं था। रूल १२ उस दशा में लागू होता है जब कि वह इस बात का इतमीनान न दिला सके कि वह जवाबदेही के लिये हाज़िर हो रहा है या नहीं। लेकिन दोनों हालतों में, चाहे वार्त रूल ११ में आती हों या रूल १२ में, अदालत जायदाद कुर्क हो जाने के बाद

काररवाई कर सकती है, देखो 31 C. L. J. 363; 57 I. C. 302 (C) और 55 I. C. 425 (C).

अगर मुद्दई या मुद्दाअलेह को इस बात का भय हो कि जो गवाह उसने पेश किया है और जो पहिली पेशी को हाज़िर हो गया है वह बाद में बढ़ाई जाने वाली किसी पेशी के रोज़ हाज़िर न होगा, तो वह अदालत से इस बात की दरखास्त कर सकता है कि दूसरी पेशी पर हाज़िर होने के लिए उससे ज़मानत या मुचलका ले लिया जाय (देखो आर्डर १६, रूल १६) ।

किसी भी गवाह के अदालत न हाज़िर होने के लिये उस समय तक हुक्म नहीं दिया जायगा, जब तक कि वह शर्क्स अदालत के अधिकार-क्षेत्र की सीमा के भीतर न रहता हो या, अगर उस सीमा के बाहर भी रहता हो तो, ५० मील से कम की दूरी पर या (जहां पर रेलवे, स्टीमर या ऐसी ही कोई दूसरी सवारी हो) २०० मील से कम फासले पर न रहता हो (देखो आर्डर १६, रूल १९) ।

जब किसी मुकद्दमें का कोई फ़रीक, जो अदालत में हाज़िर है, बिना किसी जायज़ वजह के शहादत देने या किसी ऐसे कागज़ को पेश करने से, जो उस समय उसके पास मौजूद है, इन्कार करता हो, तो अदालत को अधिकार है कि वह उसके खिलाफ़ अपना फैसला सुना दे (देखो आर्डर १६ रूल २०) । जो नियम उन गवाहों के सम्बन्ध में लागू होते हैं जो शहादत देने या कागज़ात पेश करने के लिए तलब किये गए हों, वे ही नियम मुकद्दमें के फ़रीक़न के सम्बन्ध में लागू होते हैं (देखो आर्डर १६ रूल २१) ।

पेशी की तारीखों का बढ़ाया जाना—काफी वजह दिखलाने पर अदालत किसी भी समय एक समय से दूसरे समय के लिए मुकद्दमें की पेशी की तारीखें बढ़ा सकती है । पेशी बढ़ाने से जो खर्च पैदा होजाय उनके सम्बन्ध में अदालत जैसा उचित समझे नियम बनावेगी । जब शहादत का लिया जाना एक बार शुरू हो जायगा तो वह, जब तक कि अदालत किसी कारणसे, जो लिख दिए जायंगे, पेशी की तारीख़का बढ़ाया जाना ज़रूरी न समझ ले, हर रोज़ बराबर जारी रहेगा [देखो आर्डर १७ रूल १] ।

फ़रीक़न या उनके वकीलों को चाहिए कि जब वे मुकद्दमें की तारीख़ बढ़ाए जाने के लिए दरखास्त दें तो उसमें उन वजहों को दिखलावें जिन पर वे पेशी की तारीख़ बढ़वाना चाहते हैं । आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अपनी दरखास्त की ताईद में हलफ़नामें या किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनरके सारटीफ़िकेट पेश करने होंगे । मुकद्दमें की तारीख़ बढ़ाना या न बढ़ाना अदालतकी मर्ज़ी पर है, फ़रीक़न अपनी इच्छा से तारीख़ नहीं बढ़वा सकते (देखो 10 I. C. 748).

“काफी वजह,, क्या है. यह बात हर एक मुकद्दमें की हालत पर निर्भर करती है । अदालत को उन खर्चों के सम्बन्ध में पूरा अख़्तियार रहता है जो मुकद्दमें की तारीख़ बढ़ाये जाने के कारण पैदा हुये हों । वह तारीख़ बढ़ाने की बात को ना-मंजूर कर सकती है, जब तक कि दूसरे फ़रीक को फ़ौरन् ही खर्चा

अदा न कर दिया जाय। वह यह भी कर सकती है कि मुकद्दमें की बढ़ाई हुई तारीख के सम्बन्ध में यह शर्त लगा दे कि वह तारीख के पहिले खर्चा अदा कर देने पर ही मुकद्दमें की समाप्त और अगर खर्चा अदा न किया जाय तो वह मुकद्दमा खारिज कर सकती। (देखो 36 C. 566; 13 C. W. N. 525; 49 I.C. 272; 14 C.W.N. 40)

जब किसी फरीकने मुकद्दमें की तारीख से केवल दो रोज ही पहिले तलवाना जमा किया हो, तो यह समझा जायगा कि सम्मन उस फरीक की जिम्मेदारी पर ही जारी किया गया है और ऐसी दशा में मुकद्दमें की पेशी बढ़ाई जा सकेगी, देखो। Pat. L. J. 173.

जब मुकद्दमें की बढ़ाई हुई तारीख को दोनों फरीकैन या उनमें से कोई एक हाज़िर न हो सके या शहादत पेश न कर सके अथवा कोई दूसरा ऐसा काम पूरा न कर सके जिसके लिये तारीख बढ़ाई गई थी, तो अदालत को अख्तियार होगा कि वह आर्डर ९ के साथ पढ़े गए आर्डर १७ रूल २, ३ के अनुसार कार्यवाही शुरू कर दे।

पेशी बढ़ाये जाने के जिस खर्च के लिये आर्डर १७ रूल १ (२) में यह हुक्म दिया गया है कि उसे अमुक (फर्ला) फरीक अदा करे वह उन कामों से बाहर न खर्च किया जाना चाहिये जिन में खर्च किये जाने का उनका मंश था अर्थात् दूसरे फरीक के उस खर्च को भरने में खर्च किया जाय जो मुकद्दमें की तारीख बढ़ाये जाने के कारण उसे उठाना पड़ा हो। किसी फरीक या किसी उसके मुक़्तार मजाज़ द्वारा की गई अदायगी या वसूली रकम की बात मुकद्दमें की मिसिल में दर्ज कर दी जानी चाहिये (देखो G.R.&C.O.Chap.VI.R.3). जब कि अदालतों को हर एक मुकद्दमें में अपने अख्तियार बर्तने का पूरा पूरा अधिकार है, हाईकोर्ट की राय यह है कि अगर कोई ख़ास बात नहीं है तो, और जब जो रुपया दिलाया गया है वह सिर्फ थोड़ा सा ही रुपया है तो, यह उचित है कि जो फरीक मुकद्दमें की तारीख बढ़ाना चाहता है वह अपने मुखाखिफ़ फरीक को उन तमाम बातों के लिये मुआविज़ा देने के लिये तैयार हो जाय जो उस पेशी के बढ़ाये जाने के कारण पैदा हुई हैं, और यह कि अदालत का इस शर्त पर मुकद्दमें की पेशी बढ़ाना बिल्कुल ही उचित होगा कि रुपया वहीं अदा कर दिया जाय।

मुकद्दमें की पेशी और गवाहों के बयान लिए जाना

मुकद्दमें का आरम्भ और शहादत का पेश किया जाना—जिस तारीख को वाक़ा मुकद्दमें की समाप्त शुरू होनेको हो उस तारीख को उस शख्सके वकीलको, जिसे मुकद्दमा शुरू करने का हक है, चाहिए कि वह मुकद्दमें की कार्यवाही शुरू करे, अर्थात् यह कि वह संक्षेप में वे तमाम ज़रूरी ज़रूरी बातें बतला दे जिनसे उसकी विनाय मुखासमत दावा या सफाई, जैसा कुछ हो, पैदा होती है। उसे उस शहा

दत्त का भी सारांश बतला देना चाहिए जिससे वह अपने दावा की मंजूरी करना चाहता है। उसे आरम्भ में कोई भी ऐसी बात न बतलानी चाहिए जिसको वह समझता हो कि वह साबित नहीं कर सकेगा। चूंकि मुकद्दमें का आरम्भ करने वाले फरीक को इतना लाभ रहता है कि मुकद्दमें की कुल शहादत गुजर जाने पर वह आमतौर पर कुल मामले के सम्बन्ध में जवाब दे सकता है, इसलिए उसे इस बात की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वह आरम्भ में ही सारी बातें बयान कर दे। उसे अखीर में जवाब देने का जो हक रहता है उससे उसे इस बात का मौका मिल जाता है कि वह अपने विरोधी पक्ष की शहादत कितनी ज़ोर-ज़ार है, इस बात का अनुमान कर सके, और उसे इस बात में मदद देता है कि वह अपने विरोधी पक्ष के मुकद्दमें की कमज़ोर बातों की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट कर सके।

मुकद्दमा आरम्भ हो जाने के बाद, जिस फरीक ने मुकद्दमा शुरू किया है उसे चाहिए कि वह अपना तमाम सुवूत, ज़बानी हो या कागज़ी, उन बातों की तार्किक में पेश करे जिनके साबित करने का भार उसके ऊपर है।

दूसरे फरीक को (अर्थात् वह शख्स जिसने मुकद्दमा शुरू नहीं किया है) चाहिए कि उसी तरह से अपना मुकद्दमा पेश करे और कुल मुकद्दमें के ऊपर बहस करे।

इसके बाद मुकद्दमा शुरू करने वाले फरीक को हक है कि वह कुल मुकद्दमें के सम्बन्ध में अपना आखिरी जवाब दे देवे [देखो आर्डर १८, रूल २].

आमतौर पर मुकद्दमें के आरम्भ करने का हक मुद्दई को होता है; मुद्दा-भलेह को सिर्फ उसी दशा में मुकद्दमा शुरू करने का हक है जब उसने मुद्दई के दावा को स्वीकार कर लिया हो और उसका यह कहना हो कि कानूनी बिना पर या किसी दूसरी बिना पर मुद्दई उस दादरसी के किसी भी हिस्से के लिए हकदार नहीं है जिसके लिए वह दवेदार है (देखो आर्डर १८, रूल १)। "आरम्भ करने का हक" का अर्थ है मुकद्दमें के शुरू करने का अधिकार। जो सिद्धान्त इस प्रश्न के सम्बन्ध में लागू होते हैं कि, "आरम्भ करने का हक" किसे हासिल है या यह किसका कर्तव्य है, उनका प्रयोग बहुत ही कठिन है। पहिला तो नियम यह है कि, जिस शख्स के ऊपर मुकद्दमें के सुवूत का भार हो वही उस मुकद्दमें को शुरू करे (देखो Taylor on Evidence Vol. I P. 293). कानून शहादत की १०१ से ११३ तक की दफ़ाएं बार-सुवूत के सम्बन्ध में हैं। मुकद्दमें का बार-सुवूत उस शख्स पर होता है, जिसका मामला नाकामयाब हो जाने की सम्भावना हो, अगर किसी ओर से कोई भी शहादत न गुजरे (देखो कानून शहादत की दफ़ा १०२). अगर किसी दावा का कोई जुज़ ही इकबाल (स्वीकार) किया जाय तो उस दशा में मुकद्दमें का आरम्भ करने का हक नहीं रहता है, देखो 7 C.L. R. 274. जब कोई मुद्दाभलेह कोई ऐसा उज्र इन्तदाई

पेश करे कि प्राइन्साय (resjudicata) के सिद्धान्तानुसार मुकद्दमा आगे
मियाद होगया है, तो मुकद्दमें के आरम्भ करने का हक उसका होगा (के.
12 B. 454) । उस शख्स के लिए, जिसका मुकद्दमा ज़ोरदार है और बिना
पास अच्छी शहादत भी है, मुकद्दमें के आरम्भ करने का हक एक और वही भ
और प्रत्यक्ष सहायता है, क्योंकि उस हालत में वह न्यायाधीश (मजिस्ट्रेट)
दिमाग में पहिले से अपनी सारी बातें जमा दे सकता है, और अगर शहाद
फरीक़ खानी की ओर से पेश कर दी गई, तो इससे उसे जवाब देने का ह
मिलता है और इस तरह पर वह अपनी अन्तिम बात उस न्यायाधीश के क
तक पहुंचा देता है । लेकिन अगर किसी फरीक़ का मुकद्दमा कमज़ोर हो, अ
उसके पास बिल्कुल मामूली शहादत है या बिल्कुल कोई शहादत नहीं है,
वह उसके सुबूत में पेश करे, और वह, अगर मुद्दाअलेह है तो, अदालत में ह
आशा से जाता है कि शायद मुद्दई का दावा अदम-पैरवी में खारिज हो जाय,
यह कि शायद फरीक़ खानी का मुकद्दमा अपनी ही कमज़ोरियों से गिर जाय
या उसे इस बात का विश्वास है कि वह ज़ूरी को समझा लेगा, तो यह सम्भव है
कि उसका मुकद्दमें का आरम्भ करना उसके मुकद्दमें के लिए वात
सिद्ध हो ।

जब एक से अधिक बातें साबित करने को हों, और उनमें से किसी एक
के साबित करने का भार दूसरे फरीक़ पर हो, तो मुकद्दमा आरम्भ करने वा
फरीक़ को अधिकार होगा कि वह (क) या तो उन बातों के सम्बन्ध में स्व
शहादत पेश करे या (ख) दूसरे फरीक़ की ओर से पेश की जाने वाली शहा
दत का जवाब देने के लिए उसे रख छोड़े (देखो आर्टिकल १८, रूल ३) ।

कभी कभी एक अथवा अधिक बातों के सुबूत करने का भार मुद्दई के
ऊपर होता है और बाकियों के सुबूत करने का भार मुद्दाअलेह के ऊपर । ऐसी
दशा में मुद्दई को अधिकार है कि वह या तो सारे मामले के ऊपर पहिलेही क़ार
वाई कर दे या सिर्फ़ उतनी ही बातों के सम्बन्ध में सुबूत पेश करे जिनके लिए
वह स्वयं बाध्य है, और अपने विरोधी पक्षवाले की बातों का खण्डन करने का
अपना अधिकार रख छोड़े, अगर कहीं वह उन बातों के समर्थन में, जिनको
साबित करने का भार उसपर है, कोई बात ज़ाहिरा में पेश करना चाहता हो।
आमतौर पर यह अखीर में बतलाया हुआ तरीका ही अख्तियार किया जाता है,
और अगर इसका अनुकरण किया गया, तो मुद्दाअलेह को मुद्दई की हर एक
नई शहादत पर जवाब देने का अधिकार होगा और मुद्दई कुल मुकद्दमें के
सम्बन्ध में जवाब देने का हकदार होगा । लेकिन अगर शुरू में मुद्दई मुद्दाअलेह
के मुकद्दमें को रद्द करने की गरज़ से कोई शहादत तलब करना चाहता है, तो
उसे जवाब के तौर पर आगे और शहादत पेश करने की इजाज़त न दी जा
सकेगी । दूसरे शब्दों में, वह अपने मुकद्दमें की सारी बातें फिर खोलकर उनका
प्रकटीकरण नहीं कर सकता; क्योंकि अगर किसी मुद्दई को ऐसा अधिकार है

दिया जाय, तो सम्भव है कि मुद्दागलेह भी इसके लिये दावा करे, जिसका नतीजा यह हो कि मुकदमें की सारी कार्यवाही किसी अनिश्चित समय तक के लिए स्थगित हो जाय (देखो Taylor on Evidence 10th. Ed. Vol. I. p. 298.).

गवाहों के बयान लिए जाना—मुकदमा शुरू हो जाने के बाद फरीकैन अपने अपने गवाह तलब करेंगे और खुली अदालत में उनके ज़बानी बयान लिए जायेंगे [देखो आर्डर १८, रूल ४).

यह अदालत का काम नहीं है कि वह तय करे कि किन किन गवाहों के बयान लिए जाने चाहिए। फरीकैन को चाहिए कि वे अपने अपने गवाहों का चुनाव स्वयं करें और अदालत से सिर्फ उन लोगों के बयान लेने की दरखवास्त करें जिन्हें वे इस काम के लिए पेश करें। हर एक फरीक को अख्तियार है कि वह मुकदमें के वक्त बयान लिए जाने के लिए गवाहों को तैयार रखे, देखो 6 W. R. 231; 13 W. R. 185; 8. W. R. 364; 8 W. R. 505; 17 W. R. 172; 9 B. 146. किसीका नाम गवाहोंकी उस फेहरिस्तमें नहीं लिखा गया था जो अदालत में पेश की गई थी, इस बात की कोई वजह नहीं है कि उसका बयान बाद में क्यों न लिया जाये, देखो 12 W. R. 455. इसके लिए साधारणतः नियम यह है कि उसके बयान लेने के लिए एक दरखवास्त दी जाय।

खुली अदालत में बयान लिए जाने के बदले गवाहों के बयान “कमीशन” के ज़रिये भी लिए जा सकते हैं और किसी भी अदालत को अधिकार है कि वह किसी भी मुकदमें में किसी ऐसे शख्स के बयान लेने के लिए “कमीशन” जारी कर दे जो उसके अधिकारक्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर रहता है और जो इस जायता के अनुसार अदालत में हाज़िर होने से मुस्तसना कर दिया गया है या जो बीमारी या कमज़ोरी की वजह से अदालत में हाज़िर हो सकने के काबिल नहीं है, (देखो आर्डर २६, रूल १). किन किन लोगों के बयान लेने के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में देखो आर्डर २६, रूल ४ और ५.

गवाहों के पेश किए जाने और बयान लिए जाने का हुक्म—उस कानून के अनुसार दिया जायगा जो क्रमशः जायता दीवानी और फौज़दारी के सम्बन्ध में उस समय प्रचलित हो, और अगर ऐसा कोई कानून न हो तो अदालत की मर्जी से (देखो कानून शहादतकी दफा १३५)। साधारणतया यह बात वकील की इच्छा पर निर्भर है कि वह अपने गवाहों के बयान लिए जाने के क्रम को निश्चित कर दे, लेकिन कानून शहादत की दफा १३५ के अनुसार अदालत को अधिकार है कि वह उस क्रम को निश्चित कर दे जिस क्रम में किसी फरीक के गवाहों के बयान लिए जाने चाहिए, देखो 16 C.W.N. 265; 37 Cal. 245.

अदालत से बाहर चले जाने की आज्ञा—अदालत अपनी इच्छा से या किसी फरीक के हुक्म देने पर तमाम गवाहों को, सिवाय उस शख्स के जिसका बयान लिया जा रहा है, अदालत से बाहर चले जाने का हुक्म दे सकती है। कहा जाता है कि यह नियम अदालत में उपस्थित फरीकैन या मुकदमों में लगे हुए घकीलों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता। जो गवाह इस हुक्म को न मानेगा, उसके बारे में यह समझा जायगा कि उसने अदालत की तौहीन की; लेकिन इस बिना के ऊपर जज उसके बयान लेने से इन्कार नहीं कर सकता, यद्यपि जूरी के सामने इसपर यह रिमार्क दिया जा सकता है, देखो *Best on Evidence* sec. 636.

हलफ और इक़रार—क़ानून हलफ़ (*Oaths Act*) (नं० १० सन् १८७३ ई०) की दफ़ा ६ में यह खासतौर पर बतला दिया गया है कि कोई भी शख्स बहसियत गवाह के किसी बात की तस्दीक नहीं कर सकता, सिवाय हलफ़ या इक़रार सालेह के ऊपर, देखो 10 All. 307; 11 All. 183.

हलफ़ या इक़रार सालेह के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो फ़ार्म मुक़रर किया है, उसके सम्बन्ध में देखो *G. R. & C. O. Ch. I P. 61*.

कौन से गवाह काबिल शहादत लिए जानेकें हैं और कौनसे नहीं, इसके लिए देखो क़ानून शहादत की दफ़ा ११८। गवाहों को गुप्त पत्र-व्यवहार व्यापारिक पत्र-व्यवहार, कागज़ात वगैरा दिखलाने के सम्बन्ध में क्या अधिकार हैं इस सम्बन्ध में देखो *M. C. Sarkar's Evidence Act*, 2 nd. Ed. SS 122-132 (pp. 1092—1139).

गवाहों की हाज़िरी का रखना—(१) फरीकैन को नाज़िर के पास उन गवाहों की एक फ़ेहरिस्त (जो आमतौर पर अदालत की भाषा में “हाज़िरा” कहलाती है) दाख़िल करनी होगी जो उनकी ओर से शहादत देने के लिए हाज़िर हैं। नाज़िर या नायब-नाज़िर उन फ़ेहरिस्तों की तस्दीक कर लेने और उनपर अपने दस्तख़त कर देने के बाद उन्हें उस अदालत के देखच बलर्क के पास भेज देगा जिसकी इजलास में मुकदमा हो रहा है। अदालत के प्रिज़ाईडिंग अफ़सर गवाहों की इन फ़ेहरिस्तों के दाख़िल करने के लिए कोई न कोई समय नियत कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जहां पर एक से अधिक इजलास हों, वहां पर सीनियर अफ़सर ही यह वक्त मुक़रर करेगा।

(२) अगर कोई नया आदमी, जिसका नाम उस फ़ेहरिस्त में नहीं है जो नाज़िर ने अदालत के पास भेजी है, शहादत में पेश किया जाय, तो केवल इस कारण से कि उसका नाम फ़ेहरिस्त में नहीं है, वह शहादत देने से रोका नहीं जा सकता; लेकिन किसी शख्स को उसकी उस दिन की हाज़िरी का खर्चा न दिखाया जायगा, जिसका न तो उस फ़ेहरिस्त में नाम है और न वाकई उसके बयान लिए गए हैं।

उपरोक्त नियम से गवाहों की इस ज़म्मेदारी पर कोई असर नहीं पड़ता कि, उन्हें हर रोज़ अदालत में उस समय हाज़िर रहना चाहिए जिस समय के लिए वे तलब किए गये हैं (देखो G. R. & C. O. Chap. I Rule 5.)

शहादत लिखने का तरीका—देखो आर्डर १८ के रूल ५ से १४ तक। अदालत को अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से या दरखवास्त देने पर, अगर कोई खास कारण हो तो, किसी खास सवाल और जवाब या किसी उज्रदारी को लिख ले (देखो रूल १०)। जब किसी ऐसे सवाल पर जो पूछा गया है कोई एतराज़ किया गया हो और अदालत ने उसके पूछे जाने की इजाज़त दे दी हो, तो वह उस सवाल को, उसका जवाब, उस उज्र (एतराज़) और उस शख्स के नाम को लिख लेगी जिसने वह उज्र किया है, मय उस फैसले के जो अदालत ने उस पर दिया है (देखो रूल ११)। गवाहों आचरण और ढंग के सम्बन्ध में अदालत जैसे आवश्यक समझे रिमार्क लिख सकती है (देखो रूल १२)। दूसरे जज के सामने ली गई शहादत के ऊपर विचार करने सम्बन्धी अधिकार के बारे में देखो रूल १५। उसकी आयन्दा वक़्त के खयाल से किसी शहादत के लेने (de ben eesso examination) के सम्बन्ध में देखो रूल १६। गवाहों के फिर तलब किये जाने के सम्बन्ध में देखो रूल १७।

कागज़ी शहादत—जो कागज़ात गवाहों द्वारा साबित किये जाने को हैं और जो उनके बयान के दौरान में सुनूत होगये हैं, उन पर उसी क्रम से इक्विविट नम्बर डाल दिया जाता है जिस क्रम से वे पेश किये गये हैं। वकील को चाहिये कि अपने गवाहों के बयान खतम हो जाने के बाद, तमाम ऐसे कागज़ात पेश कर दे जिन्हें वह अपने मुकद्दमें के सुनूत में पेश करना चाहता है और जो बिना किसी सुनूत के कानून शहादत हिन्द या किसी दूसरे कानून के अनुसार क़ाबिल तस्लीम हैं। उदाहरणार्थ, खेवट, डिकरियों की तस्दीक शुदः नकलें इत्यादि, २० (तीस) साल पुराने कागज़ात इत्यादि इत्यादि। हर एक ऐसा कागज़, जो शहादत में कुबूल कर लिया गया है, या उसकी नकल, जब कि आर्डर १३ रूल ५ के अनुसार असल के बजाय उसकी एक नकल ही नत्थी कर दी गई हो, उस मुकद्दमें की मिसिल में शामिल कर दिया जायगा। जो कागज़ात शहादत में लिए नहीं गपहैं, वे मिसिल में शामिल नहीं किये जायंगे और उन उन लोगों को वापस कर दिये जायंगे जिन जिन लोगों ने उन्हें पेश किया है (देखो आर्डर १३ रूल ७)। वकीलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कागज़ात जज ने ख़ारिज (नामंजूर) कर दिए हैं उनकी पुस्त (पीठ) के ऊपर उसने आर्डर १३ रूल ६ में बतलाए अनुसार सब बातें लिख दी हैं यानहीं, ताकि इस पेश किए जाने और ख़ारिज किये जाने की बात का उल्लेख अदालत अपील में किया जा सके। अमूमन् इस आशय की एक दरखवास्त दे दी जाती है कि कागज़ात पेश किए गए हैं। किसी कागज़ के क़ाबिल तस्लीम होने के सम्बन्ध में किया जाने वाला कोई भी उज्र उस समय कुबूल किया जा सकता है जिस समय मुख़ालिफ़ फ़रीक़ ने उसे पेश किया हो (देखो 9 C. W. N. 111), मातहत अदालत द्वारा कागज़ों और दस्तावेजों का

लिया जाना, जब तक कि उसी समय पर उज्रदारी पेश न कर दी गई हो, खास अपीलके बिना नहीं हो सकती (देखो 11 W. R. 465; 36 C. 833. P.C.) । किसी कागज़ की किसी ऐसी नक़ल के काबिल तस्लीम होने के सम्बन्ध में कोई भी उज्रदारी अदालत अपील में कुबूल न की जायगी जो नीचे की अदालत में बिना किसी उज्रके ले ली गई थी (देखो 9 C. 666, 670; 31 C. 155, 158; 19. A. 76; P.C. 23. C. 335. 338; 8 C.W. N. 101) । ग़लती से किसी ऐसी शहादतके ऊपर उज्र न करने से जो कि क़ानून शहादतके अनुसार नाकाबिल तस्लीम है, वह शहादत काबिल तस्लीम नहीं हो जाती, देखो 19 A. 76. P.C. 40 C.L. J. 39; 34 C. L. J. 107; 35 C. L. J. 473.) । कोई भी मुद्दा, जो किसी कागज़ को दाख़िल कर रहा हो, उसके नाकाबिल तस्लीम होने की निस्वत कोई उज्र नहीं कर सकता (देखो 24 Mad. 427) । अगर किसी कागज़ के पेश करते समय ही, जिस के सबूत की ज़रूरत है, अदालतें फ़रीक़सानी से यह दर्याफ़्त कर लिया करें कि वह उसे बिना बाज़ाबता सुबूत के कुबूल करेगा अथवा नहीं तो बहुत कुछ दिक्कत दूर हो सकती है, देखो 15 W. R. 490.

क़ानून शहादत की दफ़ा ६५ के अनुसार कागज़ात शहादत मनकूली में पेश किए जा सकते हैं, अगर वे क़ानून शहादत की दफ़ा ६६ के अनुसार पेश किए जानेके लिए दी गई नोटिस के बाद भी पेश न किये जायें ।

जो शहादत किसी कमीशन के ज़रिये ली गई हो, वह उस शख्स की ओर से दी गई शहादत की तरह पर पेश की और पढ़ी जायगी जिसकी ओर से वह ली गई थी (देखो 30 Cal. 999; 7 C. W. N. 784; 9 C. W. N. 794.) दूसरे बहुत से मुक़द्दमों में यह तै किया गया है कि जो शहादत न तो पेश की गई है और न पढ़ी गई है वह उस मामले में दी गई शहादत समझी जानी चाहिये (देखो 26 C. 591; 35 C. 28; 15 C. W. N. 525)

कागज़ात साबित करने के तरीके के सम्बन्ध में देखो क़ानून शहादत की दफ़ा ६१ से ७८ तक ।

बहस और नज़ीरेंका पेश किया जाना

बहस—फ़रीक़ैतके अपने अपने सुबूत और सफ़ाई ख़तम कर चुकनेके बाद और कुल शहादत—ज़बानी और कागज़ी—गुज़र जानेके बाद, उनके वकीलोंके चाहिये कि वे ज़ाबता दीवानीके आर्डर १८, रूल २ में बतलाये क्रमानुसार अदालत को सम्बोधन करें। यह कहना बिल्कुल व्यर्थ है कि मुक़द्दमोंके दौरानमें अदालत को सम्बोधन करते समय वकीलको बहुत ही शिष्टता और विनम्रतासे काम लेना चाहिये। यह बात अवश्य है कि किसी भी समय उसे आपे से बाहर न होना चाहिये। अगर कोई बात ऐसी है जिसका विरोध करना है, तो उसे उसका विरोध हड़ता पर नम्रताके साथ करना चाहिये। यह भाव मुक़द्दमोंके आरम्भसे अन्त तक

बना रहना चाहिये, चाहे वह गवाहोंके बयानोंके समय हो या अदालतको सम्बोधन करते समय। दंडुओंकी नज़ीरें हमेशा प्रमाण मान ली जाती हैं। अच्छे वकीलके लिये यह आवश्यक है कि उसका मिजाज़ बहुत ही शांत और बिगड़ उठने वाला न हो। उसे चाहिये कि वह अदालतको सम्बोधन करते समय हमेशा शिष्ट भाषा का व्यवहार करे। उसके बात करनेका ढङ्ग भी बहुत ही शिष्टता-पूर्ण, सभ्य और शान्त होना चाहिये। उसे इस बातका विशेष ध्यान रखना चाहिये कि वह अश्लील शब्दोंका प्रयोग करके या अनुचित रीतिसे व्यवहार करके अदालतमें बैठे हुए न्यायाधीश (जज) को रुष्ट या अप्रसन्न न कर दे। अगर उसे यह मालूम हो जाय कि अदालत उसकी बातोंसे सहमत नहीं है या किसी विषयपर उसके तर्कको माननेके लिये तैयार नहीं हैं, तो उसे बिगड़ न उठना चाहिये या ऐसी कोई बात कह या कर न देना चाहिये जो अदालतका अपमान करने वाली समझी जाय। ऐसी दशाओंमें उसे बड़े ही धैर्य और आत्म-संयमसे काम लेना चाहिये और अदालतको, जहां तक स्पष्ट हो सके, अपने तर्कसे अपनी बातोंकी सत्यता समझानेकी कोशिश करनी चाहिये।

ऐसी बहस करने के लिये, जिसका कि कुछ प्रभाव पड़ सके, यह आवश्यक है कि वकीलको मुकद्दमेंके हालात की पूरी पूरी वाकफ़ियत (जानकारी) हो और उसे उसमें लागू होने वाले कानूनके सिद्धान्तोंका भी पूरा पूरा ज्ञान हो। अगर उसने अपने मुकद्दमेंके हर एक पहलूको अच्छी तरहसे समझ लिया है और अच्छी तरह से तैयार होकर अदालतमें आया है तो उसे अपने मुकद्दमेंके साबित करने में कोई भी कठिनाई न होगी और वह उसे ऐसी अच्छी तरह साबित कर सकेगा जैसे कोई रेखागणितकी किसी साध्य(शकल)को सिद्ध करता है। यह बात अक्सर देखने में आई है कि जब मुद्दै या मुद्दाअलेहका वकील अदालतको कुछ समझाता होता है तो उसका विरोधी हर बार उसकी बातमें बाधा डालनेकी कोशिश करता है। इसकी जितनी ही निन्दा की जाय थोड़ी है। हर एक फरीक को अपनी अपनी बात कहनेका मौका मिलता है और इसलिये जिस समय एक शख्स मामलेमें बहस कर रहा हो उस समय दूसरे शख्सको कोई बात कहने या टीका-टिप्पणी करनेका मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इससे जजको भी गुस्सा मालूम होता है, जो बात कही जा रही है उसका भी हिसलिसला बिगड़ जाता है, विरोधी पक्ष वाले को भी बुरा लगता है और व्यर्थमें समय भी नष्ट होता है। इस प्रकार बीच में बाधा देना उस समय उचित समझा जायगा जिस समय कोई ग़लत बात कह कर या मामले को तोड़-मरोड़ कर जज को धोखा देने की कोशिश की जा रही हो या जब वकील किन्हीं ऐसी बातों का हवाला दे रहा हो जिनका इन्दराज उस मुकद्दमें की मिसिल में नहीं है।

जब उमूर तनकीह तैयार हो जाय, तो पहिले उनके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू करनी चाहिए जिनके ऊपर ज्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है और उन्हीं के ऊपर एक एक करके बहस शुरू करनी चाहिये। जिन उमूर तनकीहका एक दूसरे

के साथ सम्बन्ध है, उन पर एकही साथ में विचार करना चाहिये। प्रारम्भिक अदालत के सामने मुकद्दमें में बहस करते समय यह आवश्यक नहीं है कि कुछ शहादत पढ़कर सुनाई जाय क्योंकि जज के हाथ की लिखी होने के कारण उसे क़रीब क़रीब याद रहती है। शहादत के सिर्फ़ उसी हिस्से की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट करना काफी होगा जो उसके मुकद्दमें का समर्थन या विरोधी पक्ष वाले का खण्डन करता है। जो बातें सन्देह-युक्त या अस्पष्ट होने के कारण उसके विरुद्ध में जा रही हों, उनको वहीं पर होशियारी के साथ स्पष्टीकरण कर देना चाहिये, ताकि उनका वास्तविक भाव ठीक तौर से समझ में आजाय।

जिन बातों पर आप विशेष ज़ोर देना चाहते हैं, उनकी एक याददाश्त या नोट रख लेना अच्छा होगा, ताकि जिन बातों को आप बहस करते समय अदालत के दिमाग़ में भर देना चाहते हैं वे छूट न जायं। इनमें उन बातों को तो ज़रूर और ख़ास तौर पर नोट कर लेना चाहिये जिन पर आप ख़ास ज़ोर देना चाहते हैं ताकि कोई ऐसी बात छूट न जाय। आपको वह याददाश्त या नोट अपने सामने रखना चाहिये जिससे किसी ख़ास बात के ऊपर टीका-टिप्पणी करना आप भूल न जायं। स्मरणशक्ति अक्सर धोखा दे जाया करती है और इसलिये जब तक इस तरह याददाश्त ताज़ा बनाए रखने के लिए यह उपाय काम में न लाया जायगा पेचीदा और बड़े मुकद्दमों में कुछ बातें छूट जानेकी पूरी सम्भावना रहती है। जब आप को अपने विरोधी पक्ष की बातों का जवाब देना हो और अन्त में मामले में बहस करना हो, तो आपको चाहिये कि आप अपने विरोधी की बातें बड़े ध्यान-पूर्वक सुनें और उन बातों को नोट करते जायं जिनका खण्डन करने की ज़रूरत है और उस नोट में एक हेडिंग कायम करते जायं तथा उनमें कोई ऐसा निशान बनाते जायं जिससे आपकी निगाह पड़ते ही वह ज़रूरी बात फ़ौरन् समझमें या स्मरणमें आ जाय मुद्दाअलेहके मामलेमें बड़ी होशियारीके साथ काम करनेकी ज़रूरत होती है। विरोधी पक्ष वाले की कमज़ोर बातों को ख़तम कर चुकने और ज़ोरदार बातों का बड़ी सतर्कता के साथ खण्डन कर चुकने के पश्चात् मुद्दाअलेह का मुकद्दमा सफ़ाई के साथ एक क्रम में पेश किया जाना चाहिये मुकद्दमें की ऐसी बातों की ओर भी जिनके होने की सम्भावना है, तथा उससे सम्बन्ध रखने वाली परिस्थिति की ओर भी, अदालत का ध्यान दिखाना चाहिये। चूंकि आम क़ायदा यह है कि मुद्दों को जवाब देने का हक़ रहता है, इस लिये आप के विरुद्ध जो जो बातें कही जानेकी हों उनका आप पहिलेसे ही अनुमान कर लें। इसी के साथ साथ जो बातें ज़ोरदार हों वे जज को ख़ूब अच्छी तरह समझा दी जानी चाहिये।

बहस में जो कुछ भी बातें कही जायं, वे साफ़ हों, माकूल हों, साबित कर देने वाली और थोड़ी हों और यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि वक्तव्यशक्ति परमोपयोगी है तथापि यह उचित नहीं कि कोई व्यक्ति केवल अपनी वक्तव्य-शक्ति

का परिचय देने के लिए ही लम्बी-चौड़ी बहस शुरू कर दे । व्यवस्था-शक्ति से ही कोई सफल कानून जानने वाला नहीं हो जाता । उसे अपने व्यवसाय की कला का पूर्ण ज्ञान रखने की परमावश्यकता है । वहस उन्हीं बातों के आधार पर होनी चाहिये जो साबित हो गई हैं और स्वीकार कर ली गई हैं और जिनका इन्दराज मिसिल में हो चुका है । मुकद्दमें की ज़रूरी ज़रूरी बातें पहिले लेना चाहिये और इसके बाद छोटी छोटी बातों को, ताकि अदालत बातें सुनते सुनते अधीर न हो उठे । अगर अदालत के सामने सिर्फ़ वही बातें पेश की जायें जिनसे उसके मुकद्दमेंका समर्थन और विपक्षीकी बातोंका खण्डन होता है, तो भी काफी होगा सारहीन, ठिक न सकने वाली बातोंके ऊपर बहस न करना एक बड़ा अच्छा गुर है । यह बात हमेशा स्मरण रखिये कि बहुत सी सन्देहयुक्त, भ्रमपूर्ण बातों की अपेक्षा एक बात कहीं अच्छी है, यदि वह अच्छी और सारपूर्ण है । जो बातें अपने विरुद्ध जा रही हों, उनका फौरन स्पष्टी-कारण कर देना चाहिये ताकि उनकी वास्तविकता (असलियत) प्रकट हो जाय । लेकिन बहस करने के पहिले आपको इस बात को देख लेना चाहिये कि आप की कौनसी बात सब से ज़्यादा कमज़ोर है ।

सबसे बड़ी ज़रूरी बात है बातों का ठीक ठीक एक ढंग और क्रम से रखना । आपको मुकद्दमें की वे तमाम बातें समझ लेनी चाहिये जो जांच के वक्त बतलाई गई हों । जब तक कि आप को मुकद्दमें के वाक्यात और उससे सम्बन्ध रखने वाली कानून अच्छी तरह से मालूम न होंगे, आपको उस समय बहुत ही शर्मिन्दा होना पड़ेगा जिस समय जज किसी खास विषय के सम्बन्ध में आप से कोई बात पूछेगा या किसी खास सवाल की निस्वत आप से जवाब तलब करेगा । उभर तनकीह और उस शहादत को, जिसके आधार पर वह तैयार किया गया है, अच्छी तरह से याद रखना चाहिए । वाक्यात को वाक्यात साफ़ साफ़ और क्रमानुसार बयान करना अभ्यासके ऊपर निर्भर करता है, जिसका अभ्यास करना उन लोगों के लिए परमावश्यक है, जो ऐसा करने के अभ्यस्त (आदी) नहीं हैं । जहां कहीं किसी घटना या कागज़ात की तारीखों की आवश्यकता हो, तो उन्हें एक ऐतिहासिक क्रमानुसार दिखलाना चाहिये, ताकि उन्हें नोट करके तजवीज़ मुकद्दमा तैयार करते समय जज उनको चेक कर सकें । उन बातों को बड़ी सावधानीके साथ बचा देना चाहिये जो असंगत हों । अच्छे कानून-दां की चतुरता हर्षा में है कि वह अपने मुकद्दमें की जोदरार बातों को चुन ले और जितनी जल्दी हो सके जज को वे बातें समझा दे ।

वकील को चाहिये वह किसी भी हालत में उन बातों के बाहर कोई बात न करे जिनका इन्दराज मिसिल में हो गया है या अदालत को कोई भी ऐसी बात न समझावे जो उसमें (मिसिल में) पाई न जावे । किसी मामले में बहस करते समय उसे हमेशा सच्ची और न्याय-पूर्ण बात ही कहनी चाहिये, कभी भी वह अदालतसे कोई ऐसी बात न छिपावे जिसका जानना अदालत के लिये उस मुकद्दमें का सही फैसला करने की गरज़ से ज़रूरी है । उसे यह अधिकार है कि

वह किसी बात का अपना मित्र अर्थ लगावे, किन्तु उसे कभी भी कोई बात गुप्त बयान करने या अदालत को धोखा देने के लिये नहीं करनी चाहिये। अगर कोई तर्क-विरुद्ध बहसकी जायगी या कोई ऐसी बात कही जायगी जो शहादतसे साबित नहीं होती है, तो जज या उसका विपक्षी उन बातों को चेक करके उनका परिणाम आपके विरुद्ध लगा सकता है। तवालत बढ़जाने के अलावा इससे हाकिम अदालत के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा, जिसका परिणाम केवल यही न होगा कि एक मुकद्दमें में सफलता की आशा बहुत कुछ कम होजाय बल्कि इससे उस वकील के नाम को भी बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। जज का उसपर से विश्वास उठजायगा जिससे मुकद्दमें में कामयाबी या नामवरी कोई भी हासिल नहीं हो सकती।

लार्ड एशर एम०आर० ने एक बड़ेही प्रसिद्ध मुकद्दमें में कहा था:—“वकील की स्थिति बड़ी ही नाजुक है। उसे वह सब बातें नहीं कह देना चाहिये जो सच जानता है, वह इन बातोंका जवाब देने के लिये नहीं आता है, जिन बातोंके ऊपर वह विचार कर रहा है वे सही हैं अथवा ग़लत। उसे चाहिये कि वह सिर्फ जहां तक अच्छी तरहसे वह बहस कर सके, अपने मामलेमें बहस करे और कभी भी बात ऐसी न कहे जिसका कहना उसके लिये उचित नहीं है, ताकि अपने मवकिलके लिये वह जिस बातको चाहता है उसे वह हासिल कर सके। अगर मार्गमर्ग बहसके दौरानमें उससे यह पूछ दिया जाय कि, जो बात आप कहते हैं वह सही है अथवा ग़लत, यह कि जो कुछ भी आप कहते हैं वह संगत है अथवा असंगत, तो उस समय उसका दिमाग इस कदर उलझनमें पड़ जायगा कि वह उस कामको न कर सकेगा जिसके लिये वह बुलाया गया है। वह मामलेमें अदालतसे रक्षा चाहता है। अगर कानूनका रूल विपरीत है, तो बेचारे निर्दोष वकीलको व्यर्थके लिये हैरान होना पड़ेगा और इसलिये अच्छा हो कि कानूनका रूल इतना विस्तृत और बड़ा बनाया जाय कि नये वकीलोंको कभी दिक्कत न उठानी पड़े, यद्यपि उसको इतना बड़ा बना,नेसे उसमें वे वकील भी आ जाते हैं जो अदावत और खराब चाल-चलनके अपराधी सिद्ध हुये हैं।”

प्रमाणोंका पेश किया जाना—प्रमाण (नज़ीरों) के पेश करने में वकीलोंके बहुत बड़ी सावधानी रखनी चाहिये। उन्हें चाहिये कि वे सिर्फ वेही नज़ीरें पेश करें जो साफ़ तौरसे उनके पक्षमें हों। आम तौरपर ऐसा देखा जाता है कि वकील लोग किसी बातके समर्थनमें पेश की जाने वाली नज़ीरोंको सिर्फ मुकद्दमों के हेड नोटको देखकर ही चुन लेते हैं जैसे कि वे भिन्न भिन्न डाइजेस्टों, लैंग रिपोर्टों और कानूनकी किताबों या उनके सटीक संस्करणोंमें दिये हुये होते हैं। ऐसा कभी भी न करना चाहिये, क्योंकि इन हेड-नोटोंसे अक्सर लोगोंको धोखा होजाता है और उनपर पूरा पूरा भरोसा करने से इस बातका भय रहता है कि वे कहीं ऐसी नज़ीरें न पेश कर जायं जिनमें बहुत कम ऐसी बातें हैं जो उसके मामलेका समर्थन करती हैं या जो, सम्भव है, उसकी बातोंके विरुद्ध सिद्ध होती हों। सबसे उत्तम ढंग यह होगा कि पहिले उन हेड-नोटोंको, जो डाइजेस्टों या कानूनकी किताबोंमें

दी हैं, देखकर कुछ नज़ीरें चुन ली जाय और उसके बाद लाँ रिपोर्टोंमें दी हुई उन मुकद्दमोंकी पूरी रिपोर्टें ध्यान पूर्वक पढ़ ली जाय। रिपोर्टोंमें जिन मुकद्दमों की रिपोर्टें छपी हैं उनके वाक्यातको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये, क्योंकि मुकद्दमोंके वाक्यात ही से फैसलेमें अन्तर पड़ जाता है।

महारानी बनाम लेथम 1901 A. C. 495; 506, में कही हुई लार्ड हाव्स-वरीकी बातोंका ध्यानमें रखना बहुत ज़रूरी है:—“एक ही प्रकारकी दो बातें हैं जिनमें मैं कहना चाहता हूँ—एक यह, कि हर एक फैसला उन्हीं [बातोंके] सम्बन्ध में लागू समझना चाहिये जो साबित होगई हैं या साबित हुई मान ली गई है क्योंकि जो जो बातें उसमें बतलाई जाती हैं वे पूरे कानूनका प्रकटीकरण नहीं हैं, बल्कि वे केवल उन्हीं बातोंके सम्बन्धमें लागू होती हैं जिनके बारेमें वे कही गई हैं। दूसरी यह कि कोई मुकद्दमा उन्हीं बातोंके सम्बन्धमें नज़ीर माना जासकता है जिन्हें उसमें तय किया गया है। मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करता कि यहां उन बातोंके सम्बन्धमें भी नज़ीर माना जायगा जो उससे सिद्ध होती हैं।”

रिपोर्ट में वकील की बहस भी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ हालतों में फैसलों का निश्चय उस बहस के सम्बन्ध से किया जाता है जो पैदा हुए प्रश्नों के सम्बन्ध में की गई है। किसी मुकद्दमे के सम्बन्ध में किसी जज की इजहार राय को उस समय तक प्रमाण न मान लेना चाहिए जब तक कि वह बिल्कुल ठीक लागू न होती हो। अथली रिपोर्ट को ग़ौर के साथ पढ़ लेने से मुकद्दमा साफ़ तौर से उसकी समझ में आ जायगा, जिससे उसको इस निर्णय करने में कोई कठिनाई न होगी कि उस प्रमाण (नज़ीर) को पेश करने से मेरे मवक्किल का मुकद्दमा ज़ोरदार हो जायगा या नहीं।

ऐसी नज़ीरें पेश नहीं करनी चाहिए जिनमें प्रिवी कौंसिल ने रद्द या खारिज कर दिया है या जो कानून बदल जाने से रद्द या बेकार होगई हैं। जब किसी विषय के ऊपर कई भिन्न भिन्न नज़ीरें हों, तो इस बातको तय करने में, कि वह इस मामले में लागू होती है या नहीं, उन प्रमाणों में कौनसी प्रधान है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब कोई मुकद्दमा विपरीत फैसल हुआ हो, तो उनमें से सब से हाल वाली नज़ीर या ऐसी नज़ीर पेश की जानी चाहिए जिसका दूसरी हाईकोर्टें समर्थन करती हों। जब किसी फ़सले के सम्बन्ध में सभी हाईकोर्टों का मत एक न हो, तो वकील को उस हाईकोर्ट की नज़ीर पेश करना चाहिए जिस हाईकोर्ट के मातहत वह अदालत है जिसमें वह मुकद्दमा चल रहा है, क्योंकि हर एक जज उस हाईकोर्ट का फैसला मानने के लिए बाध्य है जिसके कि वह मातहत है (देखो 10 C. 82 P. 85; 13 C. L. R. 256; 15 B. 410; 17 B. 355 और 25 C. 488; 1 C. W. N. 172)

जिस फैसले की रिपोर्ट नहीं निकली है, वह भी एक ऐसी नज़ीर माना जायगा जिसको मानने के लिए अदालत बाध्य है (देखो 28 Cal. 289; 5 C.

W. N. 326 Contra 4 C. W. N. 732). इण्डियन लॉ रिपोर्ट्स । एक्ट की ३७ सन् १९७५ ई० की दफा ३ । किसी जज को किसी प्राइवेट रिपोर्ट में नई हुई किसी नज़ीर को मानने से मना नहीं करती । उसमें सिर्फ़ यही बतलाया गया है कि जज उस नज़ीर को मानने के लिए बाध्य नहीं है जो इण्डियन रिपोर्ट्स में नहीं निकली है । जज को यह अधिकार है कि वह किसी रिपोर्ट में आई हुई हाईकोर्ट नज़ीर को न माने या उसपर दूसरी नज़ीर को तर्जिह दे, लेकिन वह उसे रद्दी नहीं समझ सकता (देखो C. W.N.) किसी फुलबेंच कैंसला घानने के लिए तमाम डिविज़न कोर्ट्स बाध्य हैं, जब तक कि किसी स्पेशल बेंच का न हो या जबतक कि प्रिवी कौंसिल इसके विपरीत अपर कोई फैसला न दे दे, (देखो 5 C. L. J. 42).

अगर जज को वकील की बहस का नोट मिल जाय, तो वह नोट किसी तरफ़ का वकील, बिना दूसरी तरफ़ के वकील के सामने पढ़िले पेश किए, जो के सामने पेश नहीं कर सकता (देखो 37 C. L. J. 42).

नोट—लोग कहते हैं कि अच्छे वकील मुकदमा जीत दिया करते हैं । भाइयो यह बात का ध्यान से निकाल दें । मेरी समझ में यह बात इस प्रकार है कि अच्छा मुकदमा अच्छे वकील के हाथों देने से खराब होने की आशंका बहुत कम होती है और अच्छा मुकदमा खराब वकील के हाथों देने से खराब हो जान की आशंका ज्यादा रहती है । तजस्विकार वकील को चाहिये कि वह बहस करते समय अगर यह देखले कि उसके विरुद्ध पक्ष का वकील बेतजस्विकार और नया है तो यदि वह मुद्दा वकील है या उसे पहले बहस करने की इजाजत जज ने दी है तो मुकदमों के वाकियात कानूनी शहादत को इस ढंग से संक्षेप में पेश करे कि बातों को तो निर्देश कर जाय पर विस्तार न करे क्योंकि जवाब देने का मौका मिलेगा । विपक्षी वकील अपने कम तजस्व के कारण उन बातों पर ज्यादा जोर देगा जिनपर उसे विश्वास है जो पहली बहस में संक्षेप की गयी है वह समझेगा कि पहली बहस में लिये वकील ने जोर नहीं दिया कि वह बातें उसके ध्यानमें कमजोर हैं । जब मौका जवाब का मिले उन बातों को जो नहीं प्रकाशित की गयी हैं या नये तरहसे उसके अर्थ किये गये हैं या अन्य तौरों पर बात खूब याद रखना चाहिये कि अगर विपक्षी ने आपके संक्षेप का जवाब ही न दिया तो मुश्किल पैदा होगी दुबारा उसे खोल न सकेगा । बड़ी तर्कणा से काम लेना उचित है ।

अगर जज ने पहले ही से खिलाफ़ राय कायम करली है चाहे वह किसी कारण हो और जज ने कानूनी फैसला करने पर तुला हुआ है तो वकील को चाहिये कि बहुत ही कम बहस को वाकियात जाहिर करके अर्जी दे दे कि मैं इसमें बहस करना बृथा समझता हूं जब कि जज ने पहले खिलाफ़ राय कायम करली है ।

फैसला—डिकरियां—खर्चा

फैसला—मुकदमों की समाप्त हो जाने के बाद फौरन् या बाद को किसी दिन जिसकी बाकायदा नोटिस फरीकैन या उनके वकीलों को दे दी जायगी, खुले

अदालत में मुकदमों का फैसला सुना दिया जायगा [देखो आर्डर २० रूल १], फैसला सुना देनेके बाद जज, उसपर तारीख डाल कर अपने हस्ताक्षर कर देगा और इसके बाद सिवाय ज़ाबता दीवानी की १५२ में बतलाए अनुसार या निगरानीमें उसमें किसी तरहकी कोई रद-बदल या इज़ाफ़ा (परिवर्तन या परिवर्धन) न किया जा सकेगा [देखो आर्डर २०, रूल ३]।

अगर किसी फैसला, डिकरी या हुक्म में लिखने अथवा अंकोंमें कोई ग़लती होजाय या किसी तरह ग़लत कलम चल जाने या कुछ लिखनेमें छूट जानेसे कोई ग़लती हो जाय तो वह अदालत की मर्ज़ी से या फ़रीक़ैन के दरख़वास्त देने पर किसी भी समय दुरुस्त की जा सकेगी (देखो ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १५२) लिखने की ग़लती या इसी तरह संयोग बश भूल से होजाने वाली किसी ग़लती को हाकिम अदालत का उत्तराधिकारी भी दुरुस्त कर सकता है (देखो 63 I. C. 840; 55 I. C. 963.)—दूसरी वजूहात पर डिकरियों की दुरुस्ती या तरमीम (संशोधन) वज़रिये निगरानीके ही की जा सकती है। अदालतको यह भी अधिकार है कि यह ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १५१ के अनुसार किसी डिकरी का संशोधन करदे या उसे बदल दे ताकि वह फैसलेसे मेल खा जाय (देखो 37 Cal. 649; 14 C. L. J. 481; 23 I. C. 906). अगर किसी फैसले डिकरी या हुक्ममें कोई लिखनेकी भूल या अशुद्धि होजाय तो उसकी दुरुस्ती वह अदालत न कर सकेगी जो उसकी इजरा कर रही हो, उसका संशोधन स्वयं नालिशमें ही कर दिया जाना चाहिये (देखो 19 C. L. J. 517). डिकरी की दुरुस्ती के पहिले फैसलेकी दुरुस्ती हो जानी चाहिए (देखो 11 I. C. 896) जो डिकरी अपील में बहाल रखी गई हो तो उसका संशोधन अदालत अपील ही कर सकती है मातहत अदालत नहीं (देखो 11 A. 667 F. B.; 11 C. L. J. 155; 11 C. L. J. 8; 11 C. L. J. 560 P. C.; 18 M. 214 F. B.) लेकिन 21 B. 548; 9 M. 854 और 10 All 51 में यह तय हुआ है कि किसी अपील के ख़ारिज हो जाने से मातहत अदालत की डिकरी ज्यों की त्यों बनी रहेगी और उस समय उसका संशोधन मातहत अदालत ही कर सकेगी देखो 62 I. C. 910. दफ़ा १५२ के अनुसार किए गए संशोधन से उस डिकरी की इजरा की मुद्दत नहीं बढ़ सकती, देखो 27 A. 575 किसी डिकरीमें हुई भूल का संशोधन करने के लिये नालिश दायर की जा सकती है देखो 8 C. W. N. 473. बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद में ऐसा होता है कि फैसला शार्ट-हैंण्ड राइटर को बोल दिया जाता है। आर्डर २० रूल १ के साथ सब-रूल २ अलग से जोड़ दिया गया है।

डिकरी—फैसले में जो हुक्म दिया जाता है उसी के अनुसार डिकरी तैयार की जाती है। वह फैसले के अनुकूल होगी तथा उसमें उन बातों की तफ़सील रहेगी जिनकी बाबत दावा किया गया है और उसमें साफ़ तौर पर यह लिख दिया जायगा कि कौन सी दादली दी गई है। उसमें खर्चोंकी तादाद लिखी होगी और यह भी लिखा होगा कि किस शख्स द्वारा अथवा किस जायदाद में से और किस अनुपात (हिस्से-रसदी) वह खर्चा अदा किया जायगा। (देखो दफ़ा

३५) अदालत को अधिकार होगा कि वह इस बात का हुक्म दे देवे कि जो रुपया किसी एक फरीक से दूसरे फरीक को वावत खर्चा वाजिबुल्ल अदा है वह उस रुपय में मोजरा दिया जायगा जो उस पहिले फरीक का दूसरे फरीक पर बाका है (देखो आर्डर २० रूल ६) अदालत डिकरीमें ऐसी शर्हपर ब्याज अदा करने का हुक्म दे सकती है जो उसे मुनासिब मालूम पड़े (देखो दफा ३४) डिकरी के ऊपर वह तारीख पड़ी होनी चाहिये जिस तारीख को कि फैसला दिया गया था [देखो आर्डर २० रूल ७]

डिकरी में सारी बातें पूरी और साफ़ साफ़ लिखी होनी चाहिये और वह इस तरह पर तैयार की जानी चाहिये कि बिना किसी दूसरे कागज़ का हवाला दिये हुये ही उसकी इजरा की जा सके (देखो 8 C. 975; 12W. R. 99) दोनों पक्ष वालों का यह काम है कि वे देख लें कि डिकरी वाक़ायदा तौर पर तैयार की गई है अथवा नहीं (देखो 8 C. 687). अगर कोई ऐसे नक़शे या दूसरे कागज़ात हैं जिनमें हुक्म की शर्तें लिखी हैं और जो उस डिकरी का एक अंग हैं तो वे सब उसी के साथ नथी रहने चाहिये । जब डिकरियां तैयार की जाती हैं तो दोनों पक्षों के वकीलों को इसकी इत्तला दी जाती है और उनसे यह कहा जाता है कि वे उनको देख लेनेके बाद उनपर अपने हस्ताक्षर कर दें । वकीलों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि वे डिकरी के ऊपर जज के दस्तख़त हो जाने के पहिले अच्छी तरह से यह देख लें कि डिकरी फैसले में दिये हुये हुक्म के अनुसार है या नहीं । इसमें असावधानी करने से सम्भव है कि मवक्किलों को कोई नुक़सान पहुंच जाय । अगर डिकरी की इजरा के समय कोई ग़लती पकड़ मिले तो केवल निगरानी में ही दुस्त की जा सकती है सिवाय उस दशा के जबकि वे ग़लतियां लिखनेकी अथवा अंकों की ही हों । यह दिक्कत और परेशानी दूर हो सकती है अगर जज के दस्तख़त होने के पहिले वकील महाशय उन डिकरियों को पढ़ जाया करें । आज कल वकील साहवान प्रायः अपने दस्तख़त कर देते हैं उनका कर्तव्य तो यह है कि डिकरी पर तब दस्तख़त करें जब वे सिरे से अन्त तक उसे पढ़ जायं, और जांच कर जायं, और मिलान कर जायं । अपने मवक्किलके लाभकी बातें और वे बातें जिनसे डिकरी सही माना जाय सब गौरसे देखें । यह भी ज़रूरी है कि वे नोट कर लें और अपने मुहरिर को पीछे नोट करा दें । मुहरिर साहवान फौरन् मिसिल में नोट कर लें । और यदि ज़रूरी हो तो मवक्किल को सूचित कर दें ।

रेहनकी डिकरी—रेहन नामा के मुक़द्दमें में पहिले एक प्रारम्भिक डिकरी तैयार की जाती है और इसके बाद मुर्तद्दिन के दरख़वास्त देने पर क़तई डिकरी तैयार की जाती है प्रारम्भिक डिकरी द्वारा दिये गये समय की तारीख़से ६ महीने तक मियाद की मुद्दत है । हिसाब-किताब के मुक़द्दमों में ऐसी प्रारम्भिक डिकरी भी दी जाती है जिसमें हिसाब किताब लिखने और कागज़ात हवाले कर देने के लिये हुक्म दिया गया हो । इसके बाद क़तई डिकरी दी जाती है । बटवारा के मुक़द्दमों में प्रारम्भिक डिकरी में यह हुक्म दिया जा सकता है कि बटवारा करा

देने के लिए कमिशनर नियुक्त किया जाय (देखो आर्डर २० रूल १८ और आर्डर २६ रूल १३) अदालत कमिशनर की रिपोर्ट को या तो ज्यों की त्यों मान लेती है या उसे बदल देती है और कृतई डिकरी दे देती है। कृतई डिकरी स्टाम्प ऐक्टकी दफा २ (१५) के अनुसार स्टाम्प लगे हुये कागजों पर लिखी जानी चाहिये। हक शिफा की नालिश में या किसी मुआहिदा की तामीली की वावत नालिशों में कुछ शर्तों पर डिकरी दी जाती है और अदालत एक ऐसी मुद्दत मुक़रर कर देती है जिसके अन्दर रुपया अदा कर दिया जाना चाहिये। “हिस्से-रसदी की अदायगी” की वावत की गई नालिशों में डिकरी में उस रकम की तफ-सील होनी चाहिये जो हर एक मदिथून डिकरी को अदा करना चाहिये। जायदाद गैर-मनकूला वापस दिला पानेकी डिकरी में लिखी जाने वाली बातों के सम्बन्ध में आर्डर २०, रूल ९, जायदाद मनकूला के लिये रूल १८, और कब्ज़ा और वासि-लातकी डिकरियों के सम्बन्ध में देखो रूल १२, मदरास में रूल १२ के साथ कलॉज (३) जोड़ दिया गया है। “प्रबन्ध सम्बन्धी” नालिशों में (रूल १३) “हक-शिफा की नालिशों में (रूल १४), “हिस्सेदारी तोड़ देने सम्बन्धी नालिशों” में (देखो रूल १५). और मालिक और ऐजण्ट के बीच होने वाली नालिशों के सम्बन्ध में (देखो रूल १६). “रुपयेकी नालिशों में” अदालत को अधिकार होगा कि वह डिकरी देते समय यह हिदायत कर दे कि रुपया किस्तों में अदा किया जायगा, (देखो आर्डर २० रूल ११), यह रूल लगान सम्बन्धी डिकरियों में लागू नहीं होता (देखो 11 C. W. N. 857). प्रारम्भिक (इन्तदाई) या कृतई डिकरी के फार्म वगैरा के लिये देखो ज़ाबता दीवानी के परिशिष्ट १ का ज़मीमा (डी)।

ज़ाबता दीवानी का कभी भी यह मंशा नहीं है कि नालिश या कार्रवाई इजरा के दौरान में दिये गये किसी अस्थायी हुक्म के बाद डिकरियां तैयार की जायं। ज़ाबता दीवानी की दफा १०४ (आर्डर ४३, रूल १) के अनुसार दिये गये हुक्म अधिकांश में इसी तरह के हुक्म हैं और उनमें डिकरियां तैयार करनेकी हिदायत नहीं है।

आर्डर ९ के रूल ९ और १३—आर्डर २१ के रूल ५८, ९१, ९२, ९९, १००, १०१—आर्डर ४१ के रूल १९, २१, २३ और आर्डर ४७ के रूल १ के अनुसार दिये हुये हुक्म हकीयतों के सम्बन्ध में या दावा के जवाब में पेश की गई सफाई के सम्बन्ध में दिये गये फैसले के उदाहरण हैं, लेकिन इन सभी हालतों में डिकरियां तैयार करनेकी आवश्यकता नहीं है। वे खाली हुक्म हैं और ज़ाबता दीवानी इस बात के लिये बाध्य नहीं करता कि डिकरियों की किस्म में हुक्म दिये जायं। जो हुक्म वास्तव में फैसलों के लिये दिए गए हैं, वे कृतई फैसला समझे जा सकते हैं।

डिकरियां तैयार करने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट के नियम—कलकत्ता हाईकोर्ट ने नीचे लिखे हुये नियम बनाए हैं:—

दीवानी अदालतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह डिकरियों को इस तरह पर तैयार करें कि उनके समझने और उनकी इजरा करने में किसी

तरहके किसी दूसरे दस्तावेज या कागज़ का हवाला देने की ज़रूरत बाकी न रहे।
 सिवाय उस दशाके जब कोई नक़्शा वगैरा उस अदालतकी आज्ञासे तैयार किया
 गया हो या अदालतने उसे क़बूल कर लिया हो और जिसका हवाला उस हुक्म
 की शर्तोंको बतलानेके लिये ज़रूरी हो। ऐसा कोई भी कागज़ या दस्तावेज बिक्री
 के साथ नरखी रहेगा और उस पर जजके हस्ताक्षर होंगे (देखो G. R. & C.
 O. Chap. I. R. 78).

जजोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि जो डिकरी उन्होंने दी है
 उसमें साफ़ तौर पर किस्म दादर्सी या मुकदमोंका दूसरा तस्फ़िया लिखा हुआ
 है, जिसका लिखा जाना ज़ाबता दीवानीके आर्डर २०, रूल ६ के अनुसार ज़रूरी
 है, और यह कि डिकरीके आरम्भमें दावाकी खास खास बातें साफ़ तौर पर
 लिख दी गई हैं जैसा उस नालिशके रजिस्टरमें लिखी हुई हैं, (देखो G. R. & C.
 O. Chap. I. R. 78)

नोट—जहां भी व्हीं पर भी सारीकी सारी प्लॉडिंगकी डिकरीमें नकल देने की प्रथा
 हो वहां से वह मिया दी जाना चाहिये।

ज़ाबता दीवानीके आर्डर २२ के ६ से १९ तकके रूलोंको ध्यान पूर्वक पढ़ने
 से जजोंको, बहुतसे मामलोंमें, बहुत सी ऐसी बातें मिल जायंगी जिनकी आवश्यकता
 डिकरियोंको तैयार करने के लिए पड़ती है और जहां पर किसी मामलेके
 लिए स्पष्ट विधान न भी किया गया हो वहां भी उसमें दिए हुए नियम लागू
 होंगे (देखो G. R. & C. O. Chap. I. R. 80)

दोनों पक्षके वकीलोंके लिये यह आवश्यक होगा कि वे मुफ़स्सिलकी अदालतोंकी
 डिकरियों पर, जजके दस्तख़त होनेसे पहिले, अपने हस्ताक्षर (दस्तख़त)
 कर दें। अगर कोई वकील किसी डिकरी पर हस्ताक्षर न करेगा, तो उस
 डिकरी पर उसके हस्ताक्षर न करनेका कारण लिख दिया जायगा (देखो G. R.
 & C. O. Chap. I. R. 81)

हस्ताक्षर करते समय जजको उस डिकरी पर हस्ताक्षर करनेकी तारीख़
 भी डाल देनी चाहिये (देखो G. R. & C. O. Chap. I. R. 82)

यह एक साधारण नियम बना दिया जा सकता है कि ज़ाबता दीवानी
 का मंशा यह है कि किसी हक़, जिसकी निस्वत दावा किया गया है, या दावाके
 विरोधमें पेश की गई सफ़ाई के ऊपर दिए गए फैसलोंका प्रदर्शन करने के लिये
 डिकरी तैयार की जाय, जब कि इन फैसलोंमें कोई नालिश या अपील फैसला
 की गई हो। रजिस्टर पर चढ़ा लिखे जानेके बाद किसी अर्ज़ीदावाके ख़ारिज हो
 जाने पर भी डिकरी दी जा सकती है, अगर मुद्दाअलेह हाज़िर हो जाय और
 ख़र्चा अदा कर दिया जाय।

(१) जायदाद ग़ैर मनकूलाका क़ब्ज़ा वापस दिलानेकी बाबत की गई
 नालिशोंमें और लगान या वासिलातकी नालिशों, प्रबन्ध सम्बन्धी नालिशों, और
 बदवाराकी नालिशों में, जिनमें आर्डर २० के रूल १२ से १८ तक के रूलोंके अन्तर्गत

सार प्रारम्भिक डिकरियां दी गई हैं, कतई डिकरी उस कार्रवाई से होने वाले नतीजे के अनुसार तैयार की जानी चाहिये जो उस प्रारम्भिक डिकरी के ऊपर की गई हो। इसी तरह, जब आर्डर ३४ के अनुसार कोई प्रारम्भिक (इन्तर्दाई) डिकरी किसी रेहनकी देवात, या किसी जायदाद मरहूनाकी नीलाम या फूक-रेहनी के लिये दी गई हो तो कुछ समय के बाद उस प्रारम्भिक डिकरी की कतई डिकरी बन जायगी।

(२) ज़ाबता दीवानी यह आज्ञा नहीं देता कि किसी नालिश या इजरा की कार्रवाई के दौरान में दिए गए किसी अस्थायी हुक्म के बाद डिकरी तैयार कर दी जाय। ज़ाबता दीवानी की दफ्ता १०४ (आर्डर ४३, रूल १) के अनुसार दिए गए हुक्म ज्यादातर इसी किस्म के हुक्म हैं और इसलिए इनमें डिकरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

(३) आर्डर ९ के रूल ९ और १३—आर्डर २१ के रूल ५८, ९१, ९२, ९९, १००,—१०१ आर्डर ४१ के रूल १९, २१, २३, और आर्डर ४७ के रूल १ के अनुसार दिए गए हुक्म उन फैसलों के उदाहरण हैं जो हकूक या दावा के जवाब में कही हुई बातों के सम्बन्ध में दिए गए हों, लेकिन इनमें डिकरी तैयार किए जाने की ज़रूरत नहीं है। वे हुक्म हैं और ज़ाबता दीवानी इस बात के लिए बाध्य (मज़बूर) नहीं करता कि कि डिकरी की किस्म में हुक्म दिए जायें। जो हुक्म वास्तव में फैसले हैं, वे कतई फैसला समझे जा सकते हैं।

(४) लेकिन अगर ऊपर बतलाया हुआ कोई हुक्म या ज़ाबता दीवानी के आर्डर २१, रूल २ के अनुसार दिया हुआ हुक्म, इजरा किए जाने के क़ाबिल हो या इजरा करता हो, जैसे कि किसी एक फरीक़ द्वारा किसी दूसरे फरीक़ को अदा किए जाने वाले खर्चों के सम्बन्ध में दिया हुआ हुक्म, तो ऐसी हालातों में यह आवश्यक नहीं है कि बाज़ाबता तौर पर उस फैसले का वर्णन किया जाय। अगर कोई शख्स किसी हुक्म की इजरा कराना चाहे, तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि यह तज़वीज़ फैसले की तक़ल ले। खर्चों की निस्वत दिए हुए हुक्म में, जैसे कि यह डिकरी की तरह पर दिया गया हो, संक्षेप में अदालत का फैसला रहना चाहिए, खर्च की तादाद, और अगर आवश्यक हो तो, उसकी तफ़सील लिखी होनी चाहिए।

वासिलात (Mesne Profits)—पुराने ज़ाबता दीवानी के अनुसार अगर किसी क़ब्ज़ा दिलापाने की नालिश में वासिलात आइन्दा दिलाए जाते थे, तो वे इजरा की कार्रवाई में तय किए जाते थे। अब आर्डर २०, रूल १२ के अनुसार वासिलात, अगर दिलाए जावें तो, बाद में जांच करके डिकरी से ही तय कर दिए जाते हैं, इजरा में नहीं। अगर वासिलात तय करने के लिए दी गई दर-ख़्वास्त अदम परची में ख़ासिज हो जाय, तो फिर दुबारा दरख़्वास्त नहीं ली जा सकती (देखो 16 C. L. J. 3; 62 I. C. 747). अगर कब्ज़े की बाबत पहिले कोई नालिश की गई हो, तो इससे वासिलात के लिए की जाने वाली दूसरी

नालिश की मियाद आरिज़ नहीं होती, क्योंकि इस नालिश की विनाय-मुसलमत दूसरी है (देखो 8 I. C. 445; 60 I. C. 65) अदालतको इस बात का अख्तियार है कि वह वासिलात के ऊपर सूद (ब्याज) दिलावे या न दिलावे (देखो 27 C. 951 P. C. 34 C. L. J. 415; 44 A. 479) रुल १२ में तीन साल की मुद्दत का शुमार आखिरी डिकरी की तारीख से करना चाहिए (देखो 34 C. L. J. 415). इस मामले में सभी हाईकोर्टों का मत एक नहीं है कि उस हालत में अदालत को वासिलात की रकम तय करने का अधिकार है अथवा नहीं, जब कि वह रकम उसके अख्तियार समाभत माली से बाहर हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ मामलों में इसका जवाब "हां" में दिया है (देखो 21 C. 550; 40 C. 50), 13 C. L. J. 493; 43 C. 650; 38 C. L. J. 142 में इससे विपरीत फैसल हुआ था। पटना हाईकोर्ट ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट के अनुसारही अपनी राय कायम की है, देखो (2 Pat. L. T. 648; 2 P. L. J. 394; 60 L. C. 346). मियाद के सम्बन्धमें यह तय हुआ है कि नए ज़ाबतेके अनुसार, आर्डर २०, रुल १२ (सी) के अनुसार दी हुई वासिलात की डिकरी एक ऐसे मुकद्दमें की जांच के समान है जिसकी अभी आधी ही समाभत की गई हो, और इसलिए उसमें आर्टि० १८१ लागू नहीं होती (देखो 77 I. C. 497).

ब्याज—रुपएकी अदायगीके सम्बन्धमें दीगई डिकरियोंमें अदालतको अधिकार है कि वह नालिश दायर होनेकी तारीख से डिकरी की तारीख तक किसी भी मुनासिब तरह पर जो कि वह ठीक समझे, मूलधन (असल रकम) के ऊपर ब्याज दिला दे और साथ ही इसके वह ब्याज भी दिला दे जो नालिश दायर होनेके पहले उस असल रुपए पर लगाया गया हो, मय उस कुल रुपयेके सूद आइन्दाके, उस शरह पर जो वह मुनासिब समझे, जो डिकरीकी तारीखके रुपयेकी अदायगी तक या इससे पहले किसी वक्त तकके लिये, जो अदालत मुनासिब समझे, लगाया जायगा (देखो दफा ३४).

नोट—नालिशकी तारीख से डिकरीकी तारीख तकके और डिकरीकी तारीख से रुपएके वसूल का तारीख तक के ब्याज (सूद) की दर (शरह) तय करना अदालतके अख्तियारमें है (देखो 12 C. 569 18 C. 164) दफा ३४ उसी समय लागू होती है जब डिकरी रुपयेकी अदायगी के लिये हो। किसी रेहननामामें रेहनकी हुई जायदादके ऊपर दायर कीगई नालिशके सम्बन्धमें लागू नहीं होती।

खर्चा—कुल मुकद्दमेंके फैसलेका खर्चा अदालतकी मर्जी पर है। अगर अदालत यह हुक्म दे कि खर्चेका तस्फिया फैसले पर नहीं होगा, तो उसे इसके लिए लिखित कारण बतलाना चाहिए। अदालत खर्चेके ऊपर ब्याज भी दिला सकती है जिसकी शरह ६) रु० सैकड़ा सालानासे अधिक न होगी (देखो दफा ३५).

माविजेके किस्मके खर्चे—एक्ट नं० ९ सन् १९२२ ई० की दफा ३५ (ए) के अनुसार अब अदालतोंको यह अधिकार दिया गया है कि झूठा या तोहमत लगाने

वाला दावा या सफाई पेश करनेकी हालतमें वह एक हजार रुपये तकका मुआविजा दिला सके। यह दफा ज़ाबत फौजदारीकी दफा २५० के समान है।

दफा ३५ (ए) इस प्रकार है:—

१ अगर किसी नालिश या दूसरी कार्रवाईमें, जो कि अपील नहीं है, कोई फरीक इस बिनाके ऊपर किसी दावा या सफाईके ऊपर आपत्ति करता है कि दावा या सफाई या उसका कोई हिस्सा, जो उज्रदारसे सम्बन्ध रखता है, झूठा या तोहमत लगाने वाला है और जिस शख्सने उसे पेश किया है उसको इस बातका इल्म है, और अगर उसके बाद वह दावा या सफाई, जिसका सम्बन्ध उज्रदारसे है, कुल या किसी अंशमें नामंजूर कर दिया जाय या छोड़ दिया जाय अथवा वापस लिया जाय, तो अदालतको अधिकार है कि वह, अगर उज्रदारी पहिले ही पेश कर दी गई है और अगर उसे उसके न्यायानुकूल होनेका इतमीनान हो जाय तो, इस बातकी वजह लिखनेके बाद कि वह ऐसे दावा या सफाईको क्यों झूठा या तोहमत लगाने वाला समझती है, उस शख्सको, जिसकी ओरसे वह दावा या सफाई पेश किया गया हो, यह हुक्म दे कि वह उसे बतौर मुआविजा खर्चा अदा करे।

२ कोई भी अदालत किसी ऐसी रकमकी अदायगीके लिये ऐसा हुक्म नहीं दे सकेगी, जो रकम एक हजार रुपये से ज्यादा हो या उस अदालतके अख्तियार समाप्त मालीसे जायद हो, फिर इनमें से जो रकम भी कम हो।

लेकिन शर्त यह है कि जब किसी ऐसी अदालतके, जो प्रान्तीय क़ानून अदालत खफ़ीफ़ा सन् १८८७ ई० के अनुसार अदालत खफ़ीफ़ाके अधिकार बर्त रही हो और जो उस क़ानूनके अनुसार तैयार की हुई अदालत न हो, अख्तियार समाप्त मालीकी रकम २५०) (दो सौ पचास) रुपये से कम हो, तो हाईकोर्ट ऐसी अदालतको अधिकार दे सकती है कि वह इस दफाके अनुसार कोई भी रकम, जो २५०) रु० से अधिक न हो और उस रकमसे एक सौ रुपयेसे ज्यादा न हो, वाबत खर्चके दिला दे।

यह भी शर्त है कि हाईकोर्ट को उस रकमकी तादाद सुकरर कर देनी चाहिये जो कोई अदालत या किसी अदालत इस दफाके अनुसार खर्चकी वाबत दिला सकती है।

३ कोई भी शख्स, जिसके विरुद्ध इस दफाके अनुसार कोई हुक्म दिया गया है, इस हुक्मकी वजहसे, किसी दूसरे फौजदारी जुर्मसे छुटकारा नहीं पा जाता जिसके लिए वह किसी दूसरे दावा या सफाईके सम्बन्धमें, जो उसने पेश किया है, ज़िम्मेदार ठहरता है।

४ इस दफाके अनुसार किसी झूठे या तोहमत लगाने वाले दावा या सफाईकी वाबत दिलाए गए मुआविजे की रकमका वादकी किसी भी नालिशमें खयाल रखा जायगा जो ऐसे दावा या सफाई की वाबत हर्जा या मुआविजा के लिये दायर की जायगी।

नोट—यह उज्र, कि अमुक दावा या सफाई झूठा या तोहमत लगाने वाला जहां तक जल्द हो सके पेश किया जाना चाहिये। अगर उज्रदार मुदा (अर्दे) तो बयान तहरीरीमें ही इसका लिख देना काफी होगा लेकिन अगर वह सही है तो बयान तहरीरी दाखिल कर चुकनेके बाद फौरन् ही उसे एक दरख्वास्त में लिखकर यह उज्रदारी पेश करनी होगी।

डिकरियों और हुक्मों की इजरा

डिकरी के रुपये की अदायगी—डिकरी का रुपया नीचे लिखे अनुसार बरकिया आना चाहिए:—

(क) उस अदालत में जिसका काम उस डिकरी की इजरा करना है।
(ख) अदालत से बाहर; या (ग) किसी दूसरे तरीके से जिसके लिए अदालत आज्ञा दे।

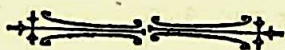
जब कलॉज (क) के अनुसार रुपया जमा किया गया हो, तो इससे इत्तला डिकरीदार को अवश्य कर दी जानी चाहिए (देखो आर्डर २१, रूल १)

जब रुपया अदालत के बाहर अदा किया जाय, या और किसी तरह डिकरी का मतालबा चुकता किया जाय, तो डिकरीदार उसपर अपना सर्टीफिकेट देगा और अदालत उसी के अनुसार इसका इन्दराज कागज़ात में कर लेगी। मदीयून डिकरी को भी अधिकार है कि वह अदालत को डिकरीदार के नाम इस बात की नोटिस निकालने की दरख्वास्त दे कि अदायगी या बेबाकी तस्दीक की हुई (Certified) क्यों समझी जाय। जिस अदायगी या बेबाकी के निस्बत ऊपर बतलाए अनुसार तस्दीक न की जायगी या जिसका इस तरह पर इन्दराज न कर लिया जायगा, उसे इजरा करने वाली कोई भी अदालत स्वीकार न करेगी [देखो आर्डर २१, रूल २]।

रूल २, जाबता दीवानी सन् १८८२ ई० की दफा २५८ के समान है जिसमें यह व्यवस्था कर दी गई है कि जिस अदायगी की तस्दीक न की जायगी, “उसे कोई भी अदालत, जो उस डिकरी की इजरा कर रही हो, उस डिकरी की अदायगी या बेबाकी तस्लीम न करेगी”। “अदायगी या बेबाकी” शब्द के, न होने से यह बात साफ हो जाती है कि डिकरी की इजरा करने वाली कोई भी अदालत या किसी भी कामके लिए ऐसी अदायगी या बेबाकीको तस्लीम न करेगी जिसकी तस्दीक नहीं की गई है। पुराने जाबता दीवानी बहुत से मामलों में यह तय हुआ था कि, यद्यपि ऐसी अदायगी जिसकी तस्दीक न की गई हो, डिकरी की बेबाकी न समझी जायगी, तो भी डिकरीदार मियाद सम्बन्धी उज्रदारी का जवाब देने के लिए उसे साबित कर सकता है (देखो 28 A. 36; 17 A. 42; 21 C. 542; 21 B. 122) उपर्युक्त शब्दों को निकाल देने से यह बात साफ हो जाती है कि जिस अदायगी या

बेबाकी की तस्दीक नहीं की गई है, उससे कानून मियाद के अनुसार इजरा की दरख्वास्त देने के लिए मियाद की मुदत नहीं बढ़ सकती (देखो 12 C. L. J. 312; 16 C. W. N. 396; 15 C. L. J. 88; 15 C. L. J. 423; 24 I. C. 215; 30 I. C. 51; 18 A. L. J. 666) किन्तु इजरा करनेवाली अदालत को छोड़ बाकी सब अदालतें ऐसी अदायगी को तस्लीम कर सकती हैं जिसकी तस्दीकन की गई हो । इसलिए बिना तस्दीक शुद्ध अदायगी या बेबाकी को वह अदालत स्वीकार (तस्लीम) कर सकती है जिसमें ऐसी अदायगी या बेबाकी के आधार पर कोई नालिश दायर की गई हो (देखो 7 A. 124; 20 C. 32; 16 B. 419; 16 C. 504; 25 B. 252).

डिकरी का रुपया अदा होने पर भी डिकरी जारी कराना



सम्भव है किसी डिकरी की अदायगी या बेबाकी अदालत के बाहर हुई और डिकरीदार ने अदालत में उस डिकरी की अदायगी या बेबाकी की तस्दीक करने का वादा कर देने पर भी ऐसा न किया और जालसाजी करके मदियून-डिकरी के ऊपर इजरा करा दी । क्या ऐसी दशा में मदियून-डिकरी जाबता दीवानी की दफा ४७ के अनुसार इस बिना पर इजरा का विरोध कर सकता है कि डिकरी की बेबाकी अदालत के बाहर की गई थी । लगभग सभी हाईकोर्टों का इस मामले में मतैक्य है कि जाबता दीवानी के आर्डर २१ रूल २ में जो व्यवस्था है वह बिल्कुल स्पष्ट है और अदालत इजरा इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वह अदालत के बाहर की गई अदायगी या बेबाकी को तस्लीम करे और दफा ४७ के अनुसार उसकी जांच करे, चाहे डिकरीदार की ओर से कितनी ही जालसाजी क्यों न की गई हो (देखो 15 C. L. J. 423; 24 C. L. J. 462; 36 M. 357; 17 M. L. J. 527; 29 M. 312; 21 M. 409; 16 C. W. N. 923; 15 C. L. J. 451; 15 C. L. J. 88; 14 A. L. J. 370; 63 I. C. 535; 1921 Pat. 360; 63 I. C. 328; 76 I. C. 311; 46 B. 226; 12 C. W. N. 485 और 30 C. L. J. 248 में इससे भिन्न फैसला हुआ है । बम्बई हाईकोर्ट ने यह तय किया है कि जहां पर जालसाजी की गई हो, वहां पर अदालत को चाहिए कि वह बिना तस्दीक की हुई अदायगियों को मान ले और दफा ४७ के अनुसार उनकी जांच करे (देखो 40 B. 303; 34 B. 579; 68 I. C. 924). 21 M. 356; 12 C. W. N. 485 और 30 C. L. J. 248. में इसी रायका समर्थन किया गया है । 21 C. 437 में यह तय हुआ था कि दफा २५८ दफा ४७ को अमल में लाने से नहीं शकती । तो फिर उस हालत में, जब कि डिकरी की बिना तस्दीक की हुई अदायगी या बेबाकी हो जाने पर भी डिकरीदार इजरा की दरख्वास्त दे, क्या किया जाना चाहिए ? दफा ४७ के अनुसार मदियून-डिकरी को इस बात

का प्लान करने के लिए, कि डिकरी का रुपया बेबाक हो गया है, और की इजरा की बाबत डिकरीदार के नाम हुक्म इस्तनाई जारी करने के लिए नालिश करने की इजाजत नहीं है (देखो 31 C. 480; 21 C. 437; 15 M. 302 तथा 25 Cal. 718; 17 Bom. 23; 16 P. R. 1910; 42 P. R. 1914). डिकरी की इजरा में की जाने वाली नीलाम को इस बिना पर मुल्य करने के लिए भी, कि डिकरी का रुपया अदालत के बाहर अदा कर दिया गया है, नालिश दायर नहीं की जा सकती (देखो 20 All. 254). तस्दीक करने के लिये किये गये सुआहिदे तोड़ देने से होने वाले नुकसान के लिये मदीयून-डिकरी दावा दायर कर सकता है (देखो 21 M. 409; 23 B. 394; 1 C. 354; 30 A. 464) उस रुपये के वापस पाने के लिए दावा दायर हो सकता है जो अदालत के बाहर अदा किया गया हो और जिसके लिए सार्टीफिकेट न दिया गया हो, देखो 11 I. C. 1; 13 W. R. 69 F. B. अदालत के बाहर डिकरी का रुपया ले लेने के बाद जालसाजी से उस डिकरी की इजरा करने पर फौजदारी मुकद्दमा चलाया जा सकता है, (देखो 16 C. 126; 10 B. 253; 34 B. 374).

मियाद—मदीयून-डिकरीको चाहिए कि वह रुपया अदा होने के बाद के (९०) दिन के भीतर दख्वास्त दे, जैसा कि कानून मियाद के आर्टि० १७४ में बतलाया गया है, अन्यथा इजरा की कार्रवाई में उसकी उत्तरदायी की समाप्त न की जायगी। डिकरीदार आर्टि० १८२ के अनुसार, अदायगी की तारीख तीन साल के भीतर किसी भी समय दख्वास्त दे सकता है (देखो 35 C. L. J. 71; 20 C. W. N. 272; 50 I. C. 364; 20 C. L. J. 131; 10 C. L. J. 467; 21 B. 122). यह तय किया गया है कि कानून मियाद की सधारण कानूनकी पाबन्दी में रहते हुए, कि सार्टीफिकेट ऐसे समय के भीतर दिया जाना चाहिये जिससे दख्वास्तकी मियाद आरिज न हो जाय, डिकरीदार किसी भी समय अपना सार्टीफिकेट दे सकता है (देखो 23 C. W. N. 320). जरडिकरीके एक हिस्सेकी अदायगी और उसकी तस्दीक (Certification) इजरा की दख्वास्त की तमादी आरिज हो जाने के पहिले दी जानी चाहिए (देखो 35 C. L. J. 566; 26 C. W. N. 534; 24 C. 215; 12 A. L. J. 825).

अगर किसी डिकरी के रुपये का कुछ हिस्सा डिकरी की तारीख से तीन साल के अन्दर अदा कर दिया जाय और अगर इस अदायगी की तारीख तीन सालके अन्दर इजराकी दख्वास्त दी गई हो, तो वह दख्वास्त अन्दर मियाद है और कानून मियाद के आर्टि० १८५ (२) के अर्थ में डिकरीदार को मियाद नई तारीख मिल जाती है देखो 46 C. 22. इस मुकद्दमे में जो हेड-नोट दिया हुआ है उसकी शब्द-योजना ठीक नहीं है, क्योंकि यह दख्वास्त अदायगी की तस्दीक करने के लिए है, एक हिस्से अदायगी की तस्दीक के लिए नहीं, जो अदायगी कि तद्वीर सुआविन इजरा है। अदा की हुई रकमोंकी तस्दीक के लिए दी जाती

वाली ऐसी दख्वास्त इजरा की दख्वास्त के ही साथ, सिर्फ उसमें उन रकमों को दिखला कर, जो कि अदा की गई हैं, दी जा सकती है। अगर 46 C. 22 में दी हुई नज़ीर का यह अर्थ है, जैसा कि ज़ाहिरा में मालूम होता है, कि अदालत के बाहर एक हिस्सा ज़र-डिकरी के अदा हो जाने से मियाद के लिए एक नई तारीख़ मिल जाती है, तो इसपर भारी आपत्ति की जा सकती है; क्योंकि किसी डिकरी के अनुसार अदा की जाने वाली कुल रकमों, जो मियाद की मुद्दत बढ़ाने के लिए अदा की जाती हैं, क़ानून मियाद की दफ़ा २० के अनुसार अदा की जानी चाहिए। सन् १९०८ ई० के क़ानून मियाद के अनुसार दफ़ा २० के साथ जो 'विवरण' जोड़ दिया गया है उसमें साफ़ तौर से यह बतला दिया गया है कि "क़र्ज़ में वह रकम शामिल है जो अदालत की किसी डिकरी या हुक्म के बमूजिब वाजिबुल्ल अदा है।" इसलिए अगर डिकरी में कोई ब्याज नहीं लगाया गया है और उसका थोड़ा सा हिस्सा अदा किया जाता है, या अगर डिकरी में ब्याज है और थोड़ा सा रुपया असल की बाबत अदा किया गया है, तो वह रकम ऋणी के हस्ताक्षर से अदा की जानी चाहिए। अगर थोड़ा सा हिस्सा ज़र डिकरी का अदा किया गया है और अगर दफ़ा २० के नियमों का पालन किया जाता है, तो डिकरीदार इजरा के लिए दख्वास्त देने से पहिले या खुद इजरा की दख्वास्त में ही उस थोड़ी सी अदा की हुई रकम की निस्वत अपना सर्टीफ़िकेट दे सकता है। लेकिन इससे क़ानून मियाद की दफ़ा २० के ऊपर किसी तरह का भी कोई असर नहीं पड़ता, (देखो 22 C. W. N. 325; 26 C. W. N. 534).

46 C. 22 में सिर्फ यह तय हुआ है कि सर्टीफ़िकेट देने के लिए दख्वास्त का दिया जाना तदबीर मुआविन इजरा है। मुक़दमों का हेड-नोट भ्रमोत्पादक है।

मदयून डिकरी ने ज़र-डिकरी की बाबत कुछ रकम अदा की, लेकिन यह रकम न तो ब्याज की मद् में अदा की गई थी और न इस अदायगी में ऋणी के दस्तख़त थे। इसके अलावा कोई सर्टीफ़िकेट भी नहीं था। तय हुआ कि चूंकि इस रकम की अदायगी में वे शत पूरी नहीं की गई हैं जो क़ानून मियाद की दफ़ा २० में बतलाई गई हैं इसलिए वह अदायगी तदबीर मुआविन इजरा नहीं है, देखो C. M. S. A. 92 of 1922; 46 M. L. J. 57.

रकम की अदायगी की तस्दीक (Certification) की निस्वत ज़ाबता दीवानी में कोई खास नमूना नहीं रखा गया है। यह तस्दीक इजरा की दख्वास्त में की जा सकती है और इसकी इत्तला कर देना ही काफी है, देखो 20 C. W. N. 272; 20 C. L. J. 131; 20 C. L. J. 632; 22 C. W. N. 325; 4 Pat. L. J. 159; 41 M. 251; 35 C. L. J. 71; 45 B. 91; 55 P. L. R. 1919.

ज़ाबता दीवानी का आर्डर ९, रूल ९. आर्डर २१ रूल २ के अनुसार दी गई दख्वास्त के सम्बन्धमें लागू नहीं होता जो कि ख़ारिज कर दी गई हो, देखो 63 I. C. 855; 28 C. W. N. 32 n.

रेहननामा की डिकरी—नए ज़ाबता के अनुसार डिकरी कतई बनाने के लिए दी गई दरखास्त इजरा की कार्यवाई नहीं है बल्कि वह नालिश की कार्यवाई है (देखो 25 C. W. N. 595; 40 A. 235) और कतई डिकरी देते समय अदालत उस अदायगी को सही मान सकती है जो अदालत के बाहर की गई है और जिसके लिए कोई सर्टीफिकेट दाखिल नहीं किया गया है (देखो 57 L. C. 473 (P); 44 A. 668 तथा 25 C. L. J. 553; 42 M. 61).

कई डिकरीदारों में से किसी एक को रुपया का अदा किया जाना—अगर कई डिकरीदारों में से सिर्फ एक ही आदमी इस बात का सर्टीफिकेट दे देवे कि डिकरी का कुल रुपया अदा हो गया है, तो उसके लिए बाकी लोग बाध्य नहीं हैं, देखो 26 A. 334; 15 M. 343; 3 A. L. J. 49. एक डिकरीदार सिर्फ अपने हिस्से की बेबाकी का ही सर्टीफिकेट दे सकता है, देखो 26 A. 318; 9 C. 831.

इजरा होने वाली डिकरियाँ—जिस डिकरीकी इजरा किए जानेको है वह एक बाज़ाबता और सही डिकरी होनी चाहिए । जो डिकरी ज़ाहिरामें बेज़ाबता मालूम होती हो, उसकी इजरा नहीं हो सकती । उसकी मियाद आरज़ नहीं होने देना चाहिए । जिस डिकरीकी इजरा की जानेको है, वह अन्तिम अदालतकी डिकरी होनी चाहिए । जब कोई अपील खारिज हो जाय, तो जिस डिकरीकी इजरा हो सकती है वह वह डिकरी होगी जिसके खिलाफ़ अपील की गई है (देखो 36 All. 350 P.C.) अगर अदालत अपील डिकरीको बहाल रखे, तो मियादकी तारीख़ उस अदालतकी डिकरीकी तारीख़से शुरू होगी, जब अदालत अपीलको बदल दे, मसूख़ कर दे या उसमें कोई संशोधन कर दे, तो जो डिकरी काबिल इजरा है वह अदालत अपीलकी डिकरी होगी ।

इजराकी दरखास्त—इजराकी दरखास्त या तो,

(अ) उस अदालतको दी जानी चाहिये जिसने डिकरी दी है या उस अफसरको (अगर कोई हो) जो इस बातके लिये मुक़रर किया गया हो या,

(ब) अगर डिकरी दूसरी अदालतको भेज दी गई है तो उस अदालतको या उसके किसी मुनासिब अफसरको (देखो आर्डर २१, रूल १०)

“उस अदालतको, जिसने डिकरी दी है” के अर्थके लिए देखो ज़ाबता दीवानीकी दफ़ा ३७ ।

इजरा की दरखास्त

इजरा की हर एक दरखास्त लिखी हुई होनी चाहिये और उसपर सायल (दरखास्त देने वाले) या किसी दूसरे शख्स के दस्तख़त और तस्दीक़ होनी चाहिये जिसकी निस्वत अदालत के इतमीनान के लिये यह साबित होगया हो कि

वह उस मुकदमें के हालात को बखूबी जानता है, और उसमें नीचे लिखी बातें लिखी रहनी चाहिये, अर्थात्

(क) मुकदमें का नम्बर ;

(ख) फरीकैन के नाम ;

(ग) डिकरी की तारीख ;

(घ) यह कि क्या डिकरी की अपील की गई है;

(ङ) यह कि क्या डिकरी के बाद कोई रकम और (अगर हां तो) कितनी रकम उस मामलेकी अदायगी या बेबाकीकी निश्चित तय की गई है जिसकी निश्चित फरीकैन के बीच झगड़ा है ;

(च) यह कि क्या इससे पहिले डिकरी की इजरा के लिये कोई और (अगर हां तो) कौनसी दरखास्तें दी गई हैं, उन दरखास्तों की तारीखें और उनका परिणाम ;

(छ) रकम मय उस ब्याज के जो डिकरी के ऊपर वाजिब हो या उससे जो दादरसी दी गई है, मय उस डिकरी के हालात के जो मुखालिफ में दी गई है, चाहे वह उस डिकरी के दिये जाने के पहिले या बाद में दी गई हो जिसकी इजरा कराई जानी है ;

(ज) उस खर्च की तादाद जो दिलाया गया है (अगर कोई हो) ;

(झ) उस शख्स का नाम जिसके खिलाफ इजरा की दरखास्त है ;

(ञ) यह कि किस किस तरह पर अदालत की सहायता चाही जाती है—

१—किसी जायदाद को दिला कर जिसके लिये खास तौर से डिकरी दी गई है ।

२—किसी जायदाद को कुर्क और नीलाम कराके या बिना कुर्क किए हुये ही नीलाम करा के ;

३—किसी शख्स को गिरफ्तार करवा के जेलखाने में रखकर ;

४—रिस्ीवर को नियुक्त करके ;

५—और किसी तरहसे जैसाकि दी हुई दादर्सों की वजह से आवश्यक जान पड़े ।

अदालत दरखास्त देने वालेको यह हुक्म देनेका अधिकार रखती है कि वह डिकरी को सर्टीफिकेट शुद्ध नकल दाखिल करे [देखो आर्डर २१ रूल ११ (२)]

जब डिकरी बाबत अदायगी ज़रूर नक़द के हो और डिकरी दिए जाने के समय मदियून-डिकरी अदालत की सीमाके अन्दर हो, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह डिकरी दिए जाने के समय डिकरीदार की ज़बानी दरखास्त पर उस डिकरी की फौरन् इजराके लिए हुक्म दे, कि मदियून डिकरी बिना वारंटके

गिरफ्तार किया जाय [देखो आर्डर २१ रूल ११ (१)] । जो डिकरी बकाया लगानकी बाबत दीगई हो उसमें भी अदालत डिकरीदारकी ज़बानी दरख्वास्त पर इजराका हुक्म जारी कर सकती है [देखो बंगाल टिनेंसी ऐक्ट की दफा १४८ (१)] ।

आर्डर २० रूल ७ के अनुसार डिकरी की तारीख का मतलब उस तारीख से है जिसको फैसला सुनाया गया हो ।

अगर किसी जायदाद मनकूला की, जो मदियून डिकरी की मिल्कियत है (लेकिन जो उसके कब्जेमें नहीं है), कुर्कीके लिये दरख्वास्त दी जाय, तो उसके साथ जायदाद मक़रूका (कुर्कीकी हुई जायदाद) की एक फ़ेहरिस्त भी नत्थी कर देनी चाहिये जिसमें उस जायदादका तफ़सीलवार ठीक २ हवाला दिया हुआ हो । इसे फ़र्द ताल्लुका कहते हैं (देखो आर्डर २१, रूल १२) । फ़ार्मके लिये देखो ज़ाबता दीवानीके परिशिष्ट १ के ज़मीमा (ई) का फ़ार्म नं० ६ ।

जब वह जायदाद मनकूला मदियून डिकरीके कब्जेमें हो, तो उन चीज़ों की जो डिकरीदार कुर्क करवाना चाहता है, एक फ़ेहरिस्त भी दाख़िल करना चाहिये [देखो ज़ाबता दीवानीके ज़मीमा (ई) का फ़ार्म नं० ८] जिसमें उनकी अन्दाज़न कीमत लिखी हुई हो और खाना १० में यह बात लिख दीजानी चाहिये कि अमुक अमुक जायदाद ही कुर्क की जानी चाहिये ।

नक़द रुपयेकी डिकरीमें कुर्की

नक़द रुपयेकी डिकरीमें कुर्कीकी जाने वाली जायदाद की मालियत जहाँ तक हो सके उस रुपयेके लगभग ही होनी चाहिये जो बाक़ी है (देखो आर्डर २१, रूल १७) जब तक फ़ेहरिस्त न दाख़िलकी जाय, अदालत इस बातको नहीं तब कर सकती कि कुर्क की जाने वाली जायदाद की मालियत क़रीब क़रीब उतनी है जितनी कि डिकरीके रुपये की तादाद है । अगर उन चीज़ोंकी, जिनकी कुर्की किये जानेके लिये दरख्वास्त कीगई है, कीमत २०) २० से अधिक है, तो ज़ाबता दीवानीके आर्डर २१ रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार जारी करनेका खर्चा दरख्वास्तके साथ ही अदा कर दिया जाना चाहिये ।

ज़ाबता दीवानीके आर्डर २१, रूल १० के अनुसार उस जायदाद मनकूला की कुर्कीके लिये दरख्वास्त देते समय, जोकि मदियून डिकरीके कब्जेमें है, डिकरीदारको चाहिये कि वह उसी आर्डरके रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार जारी करनेका खर्चा अदालतमें जमा कर दे, सिवाय उस हालतके, जबकि जिस जायदादको वह कुर्क करवाना चाहता है उसकी कीमत वह बीस २०) २० अधिक न बतलाता हो । इस हालतमें, अगर जायदादकी कीमत, जो कि रूल १३ के अनुसार तय हुई है, बीस रुपयेसे अधिक मालूम हो तो, अदालत डिकरीदारको यह

हुकम देगी कि वह कुर्कीकी नोटिस पाते ही फौरन इशतहार नीलामका खर्चा जमा कर दे (देखो G. R. & C. O. Chap. I. R. 91).

गैर मनकूला जायदादकी कुर्की

उस जायदाद गैर मनकूलाकी, जो कि मर्दियून डिकरीकी मिल्कियत है, कुर्कीके लिये दी जाने वाली दरख्वास्तमें इतनी बातें लिखी जानी चाहिये:— (क) उस जायदादका विवरण जो उसकी शिनाख्तके लिए काफी हो और (ख) उस जायदादमें मर्दियून डिकरीका कितना हक या हिस्सा है (देखो आर्डर २१ रूल १३)

लेकिन शर्त यह है कि नकद रुपयेकी डिकरीमें कुर्क होने वाली जायदाद की कीमत करीब करीब उस रकमके बराबर होनी चाहिये जो उस डिकरीकी बाबत वाजिबुल वसूल है (देखो आर्डर २१ रूल १७ की शर्तें)

जब कुर्कीकी जाने वाली आराजी ऐसी आराजी है जिसकी मालगुजारी अदा की जाती है तो अगर अदालत ऐसा ज़रूरी समझे तो कलक्टरके रजिस्टरसे एक सर्टीफिकेट शुद्ध नकद पेश की जानी चाहिये जिसमें रजिस्टरमें दर्ज मालिकोंके नाम और उस जायदादमें उसका क्या हिस्सा है यह लिखा रहेगा (देखो आर्डर २१ रूल १४)

जब दरख्वास्त किसी मालगुजारी-माफ, आराजीकी या उस आराजीके किसी हिस्सेकी कुर्कीके लिये हो, उस समय ज़ाबता दीवानीके आर्डर २१ रूल १३ के अनुसार लिखी जाने वाली बातोंके साथ साथ उन सभी हालतोंमें, जिनमें ये सारी बातें कलक्टरके रजिस्टरमें दर्ज कर ली गई हैं, दरख्वास्तमें वह सारी बिना तथा मालगुजारी आराजीका रकबा लिखा जाना चाहिये।

जब अदालत दीवानीको किसी ऐसी आराजी या हिस्से आराजीकी कुर्कीके लिये दरख्वास्त दी गई हो, जिसका किसी ज़िले के रजिस्टर मालगुजारी में इन्दराज है तो ज़ाबता दीवानीके आर्डर २१ रूल १४ के अनुसार लिखी जाने वाली बातोंके अलावा वह सालाना मालगुजारी भी लिखी जायगी जो उस कुल आराजीकी बाबत वाजिबुल अदा है। इसके लिये कलक्टरके दफ्तरके रजिस्टरकी एक तस्दीक शुद्ध नकल पेश करनी पड़ेगी (देखो G. R. & C. O. Chap. I. R. 92).

इजराकी दरख्वास्त पानेपर कार्रवाई—इजराकी दरख्वास्त पाने पर अदालत इस बातको तय करेगी कि वह ज़ाबता दीवानीके आर्डर २१ के रूल ११ से रूल १४ तक की शर्तोंको पूरा करती है या नहीं। अगर वह इन शर्तोंको पूरा करती है तो अदालत, इजराका हुकम जारी करनेकी आज्ञा दे सकती है (देखो आर्डर २१ रूल १४), अगर वह इन शर्तोंको पूरा नहीं करती है तो अदालतको अधिकार

है कि वह वहीं पर और उसी समय या किसी खास वक्तके अन्दर जिसे वह मुकदमा करेगी उस दरखास्तकी कमीको पूरा करनेकी आज्ञा दे दे या उसे खारिज कर दे। जब इस तरह किसी दरखास्तका संशोधन कर दिया जाय तो उसको निश्चित यह समझा जायगा कि वह कानूनके अनुसार तैयार की हुई दरखास्त है और "उस तारीखको दाखिल कीगई है जिस तारीखको कि वह पहिले दाखिल कीगई थी" (देखो आर्डर २१ रूल १७ (२))—अदालत दरखास्तके इस नुक्सको दूर करने के वक्त को बढ़ा सकती है (देखो दफा १४८)—अगर दरखास्त खारिज कर दी जाय तो डिकरीदारको यह अधिकार है कि वह बाकायदा तैयार की हुई एक दूसरी दरखास्त दे, अगर उसकी मियाद खारिज नहीं होगई है।

जब दरखास्त मंजूर कर ली गई हो तो अदालतको चाहिये कि वह दरखास्तके मुताबिक डिकरीकी इजराका हुक्म दे दे (देखो आर्डर २१ रूल १७)।

नोट—इजराकी दरखास्त देनेके पहले वकीलको इस बातका पूरा २ इतमीनान कर लेना चाहिये कि उसमें वे तमाम बातें लिख दीगई हैं जिनके लिखे जानेकी जरूरत है और कुछ खानाबक़ायदा खानापूरी कर लीगई हैं। अगर उसमें कोई नुक्स हो या कोई बात छूट गई हो तो अदालतके इतना अख्यार है कि वह उस दरखास्तको खारिज कर दे और उसे दुस्त किये जानेके लिये वापस मांग कर दे। अगर किसी डिकरीकी इजरा की कोई ऐसी दरखास्त खारिज कर दी जाय जिसकी मियाद मुदत करीब आगई है तो सम्भव है कि दूसरी दरखास्त पेश किये जानेके पहले उसकी मियाद खारिज हो जाय और जिस डिकरी की मियाद दरखास्त देनेके बाद खतम हो जाती है उसकी इजरा न हो सकेगी।

जो दरखास्त दफा २३५ (आर्डर २१ रूल ११) में बतलाये नियमावली सारदी गई है लेकिन नीचे जायदादका हवाला नहीं दिया है जो दफा २३७ (आर्डर २१ रूल १३) में बतलाया गया है, वह दफा २३० (आर्डर ३० रूल १०) में बतलाई हुई दरखास्तें हैं। अगर ऐसी दरखास्त उस मियादके अन्दर दुस्त न कर दी जाय जो अदालतने इसके लिये दिया है तो वह कानूनके अनुसार दरखास्त न समझी जायगी जिससे मियादकी मुदत की नई तारीख मिलती हो (देखो 17 C. 631; F. B. 14 C. 124 Over-Ruled; और 18 C. L. J. 538 V.) एक डिकरी तारीख १८-११-१९११ ई० को दीगई और उसकी इजरा दरखास्त तारीख २३-११-१९१४ ई० को दीगई जो कानूनके मुताबिक थी। लेकिन मदीयून डिकरीके उज्रदारी करने पर यह मालूम हुआ कि जो चीजें बतलाई गई हैं वे कुर्क नहीं की जा सकतीं और डिकरीदारने तारीख १४-१-१९१५ ई० को यह दरखास्त दी कि उस दरखास्त की तस्वीर करने की इजाजत दी जाय और जायदाद की नई फेहरिस्त ले ली जाय। तब हुआ कि फेहरिस्त उस पहिली दरखास्त का ही हिस्सा समझ कर ले ली जाय, देखो 22 C. W. N. 540 इस सम्बन्धमें 17 I. C. 631 और 18 C. L. J. 538 के मुकदमोंमें इस बिनापर भिन्न माने गये कि चीजोंकी कोई फेहरिस्त दाखिल न कीगई थी और जो दरखास्त दी गई थीं वे कानूनके मुताबिक

नहीं थी। 2 P. 328 में यह तय किया गया है कि जब डिकरी जिन्दा हो तो पहिली फेहरिस्त के साथ दूसरी चीजें शामिल करके उसकी तरमीम करनेकी इजाजत दी जा सकती है। 74 I. C. 144 (P.) में तय हुआ है कि जहां आर्डर २१ रूल १७ के अनुसार दरख्वास्त दर्ज रजिस्टर कर ली गई है तो इसके बाद उसकी तरमीम मुमकिन नहीं है और असबाब (जायदाद) की नई फेहरिस्त दाखिल करनेकी दरख्वास्त इजराकी दरख्वास्तकी तरमीम नहीं है। यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि आर्डर २१ रूल १७ यह अधिकार देता है कि तरमीम सिर्फ रूल ११—१४ के ही नियमानुसार की जानी चाहिये और इसमें रूल १५ या किसी दूसरे रूलमें होने वाला नुक्स शामिल नहीं है (देखो 53 I. C. 803).

कौनसी अदालतें डिकरीकी इजरा कर सकती हैं और डिकरियोंकी मुन्तकिली—किसी डिकरीकी इजरा या तो वह अदालत करती है जिसने वह डिकरी दी है या वह अदालत जिसके पास वह इजरा के लिए भेजी गई है (देखो ज़ाबता दीवानीकी दफा ३८)

जिस अदालतने डिकरी दी है वह डिकरीदारके दरख्वास्त देने पर, उसे ज़ाबता दीवानीकी दफा ३९ में बतलाई हुई किसी भी बिनाके ऊपर उसकी इजरा के लिए दूसरी अदालतको भेज सकती है या अपने ही इच्छा से उसे इजराके लिए किसी मातहत अदालतके पास, जिसे ऐसा करनेका अफ़्तयार हो भेज सकती है (देखो ज़ाबता दीवानीकी दफा ३९)

जब कोई डिकरी इजराके वास्ते किसी दूसरी अदालतमें भेज दी गई हो तो डिकरी भेजने वाली अदालत को उस डिकरीकी एक नक़ल साथमें भेज दी जानी चाहिए; और डिकरीके बेबाक न होने पर या उसका कुछ हिस्सा बेबाक होनेका सार्टीफ़िकेट और इजराके किसी हुक्मकी नक़ल या इस बातका सार्टीफ़िकेट दे दें (देखो आर्डर २१ रूल ६) तथा उस अदालतको भेज दिया जाना चाहिए जिसके द्वारा डिकरीकी इजरा होने को है।

जब वह अदालत जिसके पास इजराके वास्ते कोई डिकरी भेजी जाने को हो, उसी ज़िलेमें वाक़े हो जिसमें कि वह अदालत जिसने डिकरी दी है, तो वह उसीके पास भेजी जायगी। अगर वह दूसरे ज़िलेमें वाक़े है तो वह ज़िलेकी अदालतमें भेजी जायगी (देखो आर्डर २१ रूल ५), वह अदालत उसे किसी भी मातहत अदालतके पास भेज सकती है (देखो आर्डर २१ रूल ८)।

जब कोई जायदाद गैर मनकूला ऐसी रियासत या हकीयत हो जो दो या अधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र की स्थनीय सीमा के भीतर वाक़े है, तो इनमें से कोई भी अदालत उस कुल रियासत या हकीयत को कुर्क और नीलाम कर सकती है (देखो आर्डर २१ रूल ३)।

प्रांतीय ख़फ़ीफ़ाकी अदालतों को इजराके वास्ते डिकरियों की मुन्तकिली के सम्बन्ध में देखो आर्डर २१ रूल ४। हाई कोर्ट द्वारा डिकरियों की इजरा के सम्बन्ध में देखो रूल ९।

उपरोक्त बातें हो जाने के बाद डिकरीदार उस अदालत को इजरा के दरखास्त दे सकता है (देखो आर्डर २१ रूल १०)

जो अदालत ज़ाबता दीवानी की दफा ३९ के अनुसार दूसरी अदालत को इजरा के वास्ते डिकरियां भेज रही हो उसे ज़ाबता दीवानी के आर्डर २१ रूल १ के क्लॉज़ (सी) की शर्तोंको भूल न जाना चाहिये [देखो G. R. & C. O. Chap. I. R 85]

जो डिकरियां दफा ३९ के अनुसार हाईकोर्ट के पास इजरा के लिये भेजी जायंगी और जिन सर्टीफिकेटों द्वारा दफा ४१ के अनुसार इजरा की कार्रवाई के नतीजे की इत्तला हाईकोर्ट को दी जाती है वे सब चंद लिफाफे के अन्दर भेजी जानी चाहिये [देखो G. R. & C. O. Chap. I. R 86]

कूचबिहार और बरौदाकी दीवानी और माल की अदालत की डिकरियों की ब्रिटिश इंडिया में इजरा—ज़ाबता दीवानी की दफा ४४ के अनुसार सपरिषद् गर्वनर जनरल ने घोषणा निकालने की कृपा है कि कूचबिहार की दीवानी और माल की अदालतों की और बरौदा की दीवानी अदालतों की इजरा ब्रिटिश भारत में उसी प्रकार की जा सकती है मानो कि वे ब्रिटिश भारत की ही अदालतों द्वारा दी गई हों (देखो G. R. & C. O. Chap. I. R. 88).

ब्रिटिश राज्य की अदालतों में प्राप्त की हुई डिकरियों की देशी रियासतों की अदालतों में इजरा—इस सम्बन्ध में भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव नं० २४० तारीख २८ अगस्त सन् १८६८ ई० में दी हुई हिदायतों को देखो जो G. R. & C. O. Chap. I R. 89 में प्रकाशिक की गई हैं ।

आम क़ायदा यह है कि अंग्रेजी राज्यकी डिकरी की तामील देशी रियासतों में, देशी रियासतों के राज्य क़ानूनके अनुसार होती है । अकसर जिस क़दर स्थाप उस देशी रियासत में उस किस्म की डिकरी की इब्तिदाई नालिश में लगाना जरूरी था उस क़दर स्टांप्प दाखिल करके एक प्रकार नये खिरे से मुक़हफ़ा चलाकर वहां की डिकरी हो जाती है और अंग्रेजी राज्य की डिकरी बतौर सुवत के मान ली जाती है । पीछे उस डिकरी को राज्य के क़ानून के अनुसार इजरा कराया जाता है कभी कभी अंग्रेज़ी डिकरी को ही इजरा कर देते हैं ।

हर एक राज्यमें भिन्न भिन्न क़ानून हैं हम इसका वर्णन अन्यत्र विस्तार से करेंगे ।

अंग्रेजी अदालतों में प्राप्त की हुई डिकरियों की फ़्रांसीसी राज्यमें इजरा—दीवानी अदालतों को इजरा के लिये डिकरियां फ़्रांसीसी अदालतों में नहीं भेजना चाहिये बल्कि उन्हें उन फ़रीकैन को जो उन डिकरियों से सम्बन्ध रखते हैं इस बात की हिदायत कर देनी चाहिये कि वे खुद उन अदालतों में दरखास्त दें ।

अदालत इजरा के अख्तियारात—जिस अदालत को इजराके वास्ते कोई डिकरी भेजी गई हो उसे उसकी इजरा करने में वही अख्तियारात हासिल होंगे मानो वह डिकरी उसी अदालत से दी गई थी (देखो ज़ाबता दीवानी की दफा ४२)

यह एक बिलकुल तय बात है कि अदालत इजरा को डिकरी की नये सिरे से जांच परताल करने का अख्तियार नहीं है वह डिकरी के जायज़ होने में कोई एतराज़ नहीं कर सकती और न उसके क नूनी होने के सम्बन्ध में ही कोई एतराज़ कर सकती है [देखो 23 A. 181 P. C; 11 B. 528; 31 C. 922; 24 C. L. J. 375; 20 C.L.J. 512; 14, C.L.J. 83; 30 M. 402; 5A. 53; 15A. 334; 15 C. W. N. 725; 10 M. 283 13 C. W.N. 1182 P. C.; 21 C. W. N. 1104]—अदालत इजरा किसी डिकरी की इस बिना पर इजरा करने से इनकार नहीं कर सकती कि वह एक नाबालिग के खिलाफ दी गई है जिसका कोई बड़ी मुकदमें में उसका प्रतिनिधि नहीं बनाया गया था देखो 78 L. C. 460 लेकिन 50 L. C. 529; 4 Pat L. J. 240. F. B. और 26 M. 31 में यह तय किया गया है कि अदालत इजरा उस डिकरी पर ऐसा विचार करने के लिये बाध्य नहीं है जो बिलकुल नाजायज़ और बे ज़ाबता है। अदालत इजरा उस अदालतके अख्तियार समाप्तकी निश्चित कुछ नहीं कह सकती जिसने डिकरी दी है (देखो 28 B. 378; 17 A. 478; 10 B. 65; 43 M. 475 F. B.) और न वह जालसाज़ी के ही विषय में कुछ कह सकती है (देखो 15 B. 216; 4 M. 324)

इजरा की दरखास्त कौन दे सकता है—(१) इजरा की दरखास्त डिकरीदार या डिकरीदारों को देनी चाहिये ।

(२) अगर डिकरी एक से अधिक लोगों के हक में शामिलता में दी गई है तो (जब तक डिकरी में इससे भिन्न कोई व्यवस्था न की गई हो) उनमें एक अथवा अधिक आदमी उन सब लोगोंकी या उनके कानूनी प्रतिनिधियोंकी ओर से उस सारी की सारी डिकरी की इजरा की दरखास्त दे सकते हैं ।

(३) अगर डिकरीदार ने तहरीरी वसीयतके जरिये या कानूनकी रू से डिकरी को मुन्तकिल कर दिया हो तो मुन्तकिलअलेह उस अदालत में इजरा की दरखास्त दे सकता है जिसने डिकरी दी है। लेकिन शर्त यह है कि इस दरखास्त की इतला इन्तकाल कुनिन्दा और मदीयून डिकरी दोनों को दी जानी चाहिये और उसपर उम्प्रदारी, अगर कोई हो तो सुनी जायगी। यह भी शर्त है कि जब दो या अधिक आदिमियों के ऊपर दी गई रुपये की अदायगी की डिकरी उन में से किसी एक शख्स के हक में मुन्तकिल कर दी जाय तो बाकी लोगों के खिलाफ उसकी इजरा न हो सकेगी [देखो आर्डर २१ कल १६]

(४) अगर डिकरीदार मर जाय तो उसके कानूनी प्रतिनिधियों को उस डिकरी की इजरा की दरखास्त देने का हक होगा [देखो दफा १४६]

(५) अगर किसी महाजन को कुर्की में कोई डिकरी मिली हो तो वह महाजन उस डिकरी की इजरा के लिये दरखास्त दे सकता है [देखो आर्डर २१ कल ५३ (२)]

नोट—शामिलाती डिकरी का मतलब ऐसी डिकरी से है जो दो या अधिक आदिमियों के हक में दी गई हो। यद्यपि ज़र-डिकरी या जायदाद डिकरी में उनका हक या हिस्सा अलग अलग हो ।

जहां पर शामिलती डिकरीदारों में से सिर्फ कुछ ही आदमी इजरा को दरखास्त दें उस हालत में अदालत को अख्तियार है कि वह उस दरखास्त को मंजूर करे या ना मंजूर, देखो 7 C. L. R. 537—अदालत के लिये जरूरी लाजिमी नहीं है कि वह इस रूल के अनुसार हुक्म देने के पहिले एक डिकरी के बाकी शामिलती डिकरीदारों के नाम नोटिस जारी करे, देखो 33 C. 306. यद्यपि अदालत की इजाजत लेकर कई डिकरीदारों में से सिर्फ एक ही डिकरीदार शामिलती डिकरी की इजरा करा सकता है पर इजरा उस कुल डिकरीकी होनी चाहिये उसके किसी एक हिस्सेकी नहीं और अदालत को अधिकार होगा कि बाकी डिकरीदारोंके हक्क की हिफाजत (रक्षा) का प्रबन्ध करने के बाद वह इजरा की दरखास्त को मंजूर करले देखो 7 W.R. 10; 22 W. R. 354; 15 W.R. 159—अकेला एक डिकरीदार सिर्फ अपने ही हिस्सेकी इजरा नहीं करा सकता। इजरा की इजाजत उसी समय दी जा सकती है जब वह कुल डिकरीदारों के फायदे के लिये की गई हो। अगर यह बात लिख न दी जायगी तो इजरा की दरखास्त ठीक न मानी जायगी और फिर रूल १७ के अनुसार उसकी इजरा भी न हो सकेगी [देखो 53 I. C. 803]—शामिलती डिकरी के डिकरीदारों में से सिर्फ एक ही डिकरी दार अपने हिस्से की ही बात उस डिकरी की इजरा नहीं करा सकता देखो 7 W. R. 535; 5 All. 27.

कई मुश्तरका मदियूनान-डिकरीमें से किसी एक द्वारा किसी रूपका डिकरी के खरीद लिये जाने पर बाकी मदियूनान-डिकरीकी कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रह जाती, देखो 5 A. 27; 10 A. 570; 11 C. 393; 31 B. 303; 15 C. 187.

इस रूलके अनुसार कई मुश्तरका डिकरीदारोंमें से किसी एक को किसी मुश्तरका (शामिलती) डिकरीके इजरा करनेकी इजाजत देने या न देने सम्बन्धी जो हुक्म है वह दफा ४७ के अनुसार डिकरी है और डिकरीदार और मदियूनान डिकरीमें झगड़ा हो जानेकी दशामें उसके खिलाफ अपील की जा सकेगी, देखो 17 M. 394. लेकिन जब झगड़ा खुद डिकरीदारोंमें ही हो तो ऐसे हुक्मकी अपील न हो सकेगी, देखो 23 B. 623.

डिकरीदारको अधिकार है कि वह अपनी इच्छानुसार कुल डिकरीकी इजरा किसी भी एक मदियूनान-डिकरीके खिलाफ करा दे। अगर किसी मुश्तरका डिकरीमें कोई मदियूनान-डिकरी, जिसे बरी कर दिया जाय, तो इससे दूसरा मदियूनान डिकरी बरी नहीं हो सकती, देखो 14 C. L. J. 354.

डिकरीके मुन्तकिल अलेहकी ओरसे दरखास्त—पुराने ज़ावता दीवानीकी दफा २३२, जो आर्डर २१, रूल १६ के बराबर है, पुराने ज़ावते से “अगर अदालत उचित समझे” इन शब्दोंके निकाल देने से यह बात स्पष्ट होगई है कि किसी डिकरीके मुन्तकिल अलेहको अब डिकरीकी इजरा करा पानेका अधिकार है। पुराने ज़ावताके अनुसार जो फैसले दिये गये थे उनकी इस बातसे सहमति नहीं है।

कि कई एक मुश्तरका डिकरीदारोंमें से एक शख्सका हक मुन्तकिल हो सकता है। नीचे दिये हुये मामलोंमें कुछ सन्देह प्रकट किया गया और यह तय हुआ कि किसी डिकरीके एक हिस्सेकी मुन्तकिली से मुन्तकिल-अलेहका हक पैदा नहीं होता; (देखो 24 W. R. 11; 28 M. 64; 5 A. 27; 25 W. R. 343; 10 A. 570.) कुछ दूसरे मुकदमोंमें इससे भिन्न फैसला दिया गया है (देखो 24 W. R. 245; 17 C. 341; 19 M. 306.)

नये ज़ावता दीवानीके आर्डर २१ रूल १६ में "डिकरीमें किसी डिकरीदार का हिस्सा" शब्दोंके जोड़ देने से यह बात साफ़ हो जाती है कि "किसी डिकरी के एक हिस्सेकी मुन्तकिली जायज़ है (देखो 19 M. 306; 33 M. 80; 44 M. 919.) रुपये और खर्चोंकी अदायगीकी डिकरी एक डिकरी है और उसके टुकड़े नहीं किये जा सकते और सिर्फ़ खर्चा वसूल करनेके हक की मुन्तकिलीसे मुन्तकिल अलेहको डिकरीकी इजरा का हक पैदा नहीं होजाता; देखो 35 A. 204. डिकरीकी जो मुन्तकिली की जाय वह बज़रिए तहरीर की जानी चाहिये देखो 15 B. 307.

आर्डर २१ रूल १६ की शर्तें ताकीदी हैं, देखो 63 I. C. 884. "मुन्तकिली" का अर्थ है इन्तकाल कुनिन्दाके कुल हकूककी मुन्तकिली। इसमें रेहंन नामा द्वारा किसी डिकरीके हकूक की मुन्तकिली शामिल नहीं है, देखो 66 I. C. 679. जायदादका मुन्तकिल अलेह, डिकरीका मुन्तकिलअलेह नहीं, डिकरी की इजरा पानेका हकदार नहीं है, देखो 66 I. C. 878; 17 I. C. 512; 3 Pat. L. T. 625.

इन्तकाल कुनिन्दा और मदियून डिकरीको दरख्वास्तकी नोटिस देना निहायत ज़रूरी है, देखो 11 C.L. J. 354; 57 I. C. 250. जब कोई मदियून डिकरी इजराकी पहिली दरख्वास्त के ऊपर, उसकी नोटिस न देने के सम्बन्धमें कोई एतराज़ न करे, तो वह बाद में होने वाली इजरा के सम्बन्धमें कोई एतराज़ नहीं कर सकता; देखो 57 I. C. 707.

इस बातकी जांच करनेकी इजाज़त दीगई है कि मुन्तकिल-अलेह मदियून डिकरीका 'बयनामीदार' तो नहीं है। अगर वह 'बयनामीदार' है, तो रूल १६ के अनुसार अदालत इजराकी दरख्वास्त नामंजूर कर देगी, देखो 54 I. C. 944; 40 M. 296. 'बयनामीदार' कमसे कम उन सूरतोंमें इजरा करा सकता है जब जायदाद गैर-मनकूलाकी हकीयतकी निस्वत कोई झगड़ा न हो, देखो 43 I. C. 801.

बयनामीदार—बयनामीदार उसे कहते हैं कि जब किसी शख्सने अपने रूप से अपने लिए कोई जायदाद ख़रीदी हो या ली हो मगर ख़रीदी हो और ली हो दूसरे के नामसे। अर्थात् उसका नाम फ़र्ज़ी हो मालिक असली दूसरा हो। इसी तरहपर डिकरी ख़रीदारको भी समझना। जब किसी ने दूसरेके नामसे डिकरी ख़रीदी हो तो उस डिकरीकी इजरा न होगी। ज़रूरी बात यह है कि बयनामीदार वह शख्स

न हो जिसके हकमें डिकरी मुन्तकिल कीगई है। बेनामीका मामला विस्तार देलो, चन्द्रशेखर कृत हिन्दू-लॉके 'बेनामी' प्रकरणमें।

बंगाल टिर्नेसी ऐक्टकी दफा १४८ क्लॉज़ (एच) के अनुसार किसी लगानी डिकरीका मुन्तकिल-अलेह उस डिकरीकी इजराके लिए दरखास्त कर दे सकता जब तक कि ज़मींदारका वह हक जो उसे आराज़ीमें हासिल है, उस हकमें मुन्तकिल न कर दिया जाय।

लगानी डिकरी क्या है, इस सम्बन्धमें देखो 4 C. W. N. 357, F.B. C.W. N. 605; 18 C. W. N. 747; 31 C. 550; 3 C. W. N. 60, 35 C. 737.

एक ही साथ इजराकी कई दरखास्तें—रूपयेकी अदायगीकी हर एक डिकरीकी इजरा मदियून-डिकरीको कैदमें बन्द रख कर या जायदादकी कुर्की को नीलाम कराके या दोनों तरहसे की जा सकती है (देखो आर्डर २१, रूल ३, दफा ५१) लेकिन अदालतको अख्तियार है कि वह, मदियून डिकरीके विरुद्ध और जायदाद दोनोंके खिलाफ़ चाही जाने वाली इजराको नामंजूर करे (देखो आर्डर २१, रूल २१)

दूसरी अदालतके नाम हुक्म जारी करके इजरा—जब किसी डिकरीदारको इस बात का भय हो कि मदियून डिकरी, अपनी जायदाद किसी दूसरी अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें हटाकर उसे अपनी डिकरीके फलसे बेचि़त कर देगा, तो वह उस अदालतसे, जिसने डिकरी दी है, यह दरखास्त कर सकता है कि वह मदियून डिकरीकी जायदाद कुर्क कर लेनेके लिये उस दूसरी अदालतको हुक्मनामा भेजे (देखो दफा ४६)

केवल खास खास हालतोंमें ही डिकरीदार को यह आज्ञा दी जा सकती है कि वह एक ही साथ कई अदालतोंमें इजराकी कार्रवाई जारी रख सके, जैसे 14 M. L. A. 529 p. 540; 8 C. 687; 37 M. 231.

मुखालिफ़ डिकरियों और मुखालिफ़ दावोंकी इजरा—मुखालिफ़ डिकरियाँ (Cross decrees) और एकही डिकरीके सम्बन्धमें मुखालिफ़ दावों (Cross Claims) की इजराके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल १८ और १९, रूल १८ और १९ नियम रेहननामाकी डिकरियोंके सम्बन्धमें भी लागू होंगे [देखो आर्डर २१ रूल २०] 'मुखालिफ़ डिकरी' उसे कहते हैं कि जो डिकरी एक फ़रीक़ पर दूसरेकी ओर दूसरे पर उसकी हो।

किसके विरुद्ध इजराकी दरखास्त दी जा सकती है—(१) इजराकी दरखास्त मदियून डिकरी या मदियूनान-डिकरीके विरुद्ध दी जानी चाहिये।

२ अगर डिकरीकी बेबाकी होनेके पहिले मदियून-डिकरी की मृत्यु हो जाय तो डिकरीदार उसके कानूनी प्रतिनिधियोंके विरुद्ध इजरा के लिए दरखास्त कर सकता है (देखो दफा ५०) ऐसी दशामें नोटिस कानूनी प्रतिनिधियोंके आर्डर २१ रूल २२ के अनुसार जारी की जानी चाहिये।

(३) जब कानूनी प्रतिनिधिके खिलाफ इजराकी दरखवास्त दी गई हो, तो वह मुतौफी मदियून डिकरीकी सिर्फ उसी कदर जायदादकी निस्वत जिम्मेदार होगा जो उसको मिली है और जिसका बाकायदा तौरसे तस्फिया नहीं हुआ है । ऐसी दशामें अदालत ऐसे कानूनी प्रतिनिधिसे ऐसा हिसाब किताब जायदादका पेश करवा सकती है जैसा कि उसे मुनासिब मालूम पड़े (देखो दफा ५०)

(४) जब किसी शख्सके ऊपर किसी मुतौफीके कानूनी प्रतिनिधिकी हैसियतसे, मुतौफीकी जायदादमें से रुपया अदा करनेकी बाबत, डिकरी दी गई हो, तो उसकी इजरा ऐसी जायदादकी कुर्की और नीलाम कराके की जा सकती है । अगर जायदाद उसके कब्जेमें नहीं है और वह इस बातका इतमीनान नहीं दिला सकता कि उसने जायदादको अच्छी तरह पर लगा दिया है, तो उस डिकरीकी इजरा उसके खिलाफ उसी कदर जायदादकी निस्वत की जा सकती है जिसके बारेमें वह इतमीनान नहीं दिला सकता है, मानों वह डिकरी खुद उसीके ऊपर दी गई थी (देखो दफा ५२) हिन्दू लॉ के अनुसार "मुतौफी की जायदाद" कौन है इस सम्बन्धमें देखो ज़ाबता दीवानी की दफा ५३ ।

दफा ५० उस समय लागू होती है जब डिकरी दिये जानेके बाद और उसकी चेवाकी होजाने के पहिले मदियून-डिकरीकी मृत्यु हो जाय । दफा ५२ उस समय लागू होती है जब मुद्दाअलेहकी मौत मुकदमोंके दौरानमें होजाय और उसके कानूनी प्रतिनिधि फरीक मुकदमा बना दिये जाय या जब असली ऋणीके मर जानेके बाद कानूनी प्रतिनिधियोंके ऊपर नालिशकी गई हो और उनके ऊपर प्रतिनिधिकी हैसियतमें डिकरी दे दी गई हो, और यह कि डिकरी मुतौफीकी जायदादमें से रुपयेकी अदायगी करनेके लिये दी गई हो । अगर कोई मुद्दाअलेह मुकदमा खतम होने और फंसला सुनाए जानेके बीच मरजाय, तो वह डिकरी उसके मरनेके पहले दी गई डिकरी समझी जायगी (देखो आर्डर २२ रूल ६); और वह दफा ५० के अनुसार इजराके काबिल है । लेकिन अगर मुद्दाअलेह, मुकदमा खतम होनेके पहले ही मर जाय और बिना उसकी जानकारीके डिकरी दे दी जाय तो वह डिकरी नाजायज़ समझी जायगी और उसकी इजरा नहीं हो सकती (देखो 17 C. L. J. 634; 50 I. C. 529 F. B.; 20 B. 317; 48 I. C. 859.)

दफा ५० का "दरखवास्त देसकता है" वाक्य "दरखवास्त देगा" के समान है देखो 68 I. C. 667. "कानूनी प्रतिनिधि" का अर्थ केवल प्रबन्धकर्ता (Administrators) तामील कुनिन्दा (Executors) और वारिस (Heirs) ही नहीं है बल्कि उसमें कोई भी ऐसा शख्स आ जाता है जो कानूनके अनुसार मुतौफी की जायदादका प्रतिनिधि हो (देखो 8 C. W. N. 843; 11 C. W. N. 593 F. B.); इसलिये अगर कोई दूसरा बाहरी आदमी जायदाद पर काबिज़ होजाय तो उसपर सिवाय बाकायदा नालिश दायर करके, इजरा की कार्रवाई नहीं की जा सकती (देखो 17 M. 186).

दफा ५० उस समय भी लागू नहीं होती जब मर्दियून-डिकरी जायदाद कुर्क होने के बाद और नीलामके पहले मर जाय। कुर्की उसकी मौतके साथ ही खतम नहीं हो जाती और नीलामके पहले उसके कानूनी प्रतिनिधियोंका नाम दर्ज कागजात न करनेसे नीलाम नाजायज़ नहीं होजाता, देखो 12A.440F.B.;23C.686;19B.276;17A.162;11C.W.N.163;23C.W.N.608; और 6M.180; 15M.399;22M.119. हालमें मद्रास हाईकोर्टके एक मुकदमेंमें यह तय हुआ है कि मुतौफी मर्दियून-डिकरीके कानूनी प्रतिनिधियोंके बिना इजराकी कार्रवाई नाजायज़ होगी और उस हालतमें नीलाम मंसूख किए जाने की ज़रूरत नहीं है। यह बतलाया गया है कि हुकमके पहले की मौत और हुकमके बादकी मौतमें कोई अन्तर नहीं है, देखो 68 I. C. 667 लेकिन एक दूसरे मुकदमेंमें यह तय किया गया है कि जब मर्दियून-डिकरी इजराकी कार्रवाईके दौरानमें मर जाय, तो उस दशामें डिकरीदारके लिए यह अनिवार्य (लाज़िमी) नहीं है कि वह उसके चारिखोंको फ़रीक बनावे, नहीं तो उसकी डिकरी रुक जायगी। कानूनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इस बातकी व्यवस्था करती हो कि किसी मर्दियून-डिकरीके मर जाने पर उसके ऊपर होने वाली इजराकी कार्रवाई बन्द होजायगी, देखो 42 A. 570.

इजराका हुकम देनेके पहले नोटिस—नीचे लिखी सूरतोंमें वजह ज़ाहिर करने के लिए इजराकी नोटिस दिया जाना ज़रूरी है:—

(क) जब इजराकी दरख्वास्त डिकरीकी तारीख़से एक सालसे ज़्यादा समय में दीगई हो, या

(ख) डिकरी के किसी फ़रीक के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ़ दीगई हो।

लेकिन शर्त यह है कि नीचे लिखी हालतोंमें नोटिस देनेकी ज़रूरत न होगी:—

(क) अगर दरख्वास्त उस तारीख़ से एक सालके भीतर दीगई हो जिस तारीख़को इजराकी पहले वाली किसी दरख्वास्तके ऊपर अन्तिम हुकम दिया गया हो, या

(ख) अगर उसी शख्स के विरुद्ध दी गई इजरा की पहिली दरख्वास्त पर अदालत ने इजरा का हुकम दे दिया है।

लेकिन अगर अदालत को यह यकीन हो जाय कि नोटिस से अनावश्यक विलम्ब होजाने या न्याय में बाधा पहुँचने की सम्भावना है, तो वह नोटिस को जारी करना बन्द कर सकती है।

जब डिकरी रुपये की अदायगी की बाबत हो और मर्दियून-डिकरी के गिरफ्तारी से उसकी इजरा चाही जाने को हो, तो अदालत अपने अधिकार से इजरा का हुकम देने के पहिले उसके नाम यह नोटिस जारी कर सकती है कि वह आकर वजह ज़ाहिर करे कि उसकी गिरफ्तारी क्यों न की जाय।

आर्डर २१, रूल ३७] हाज़िर होने के बाद होने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में देखो रूल ४० ।

नोटिस न देने से बाद में होने वाली नीलाम नाजायज़ हो जाती है । नोटिस से अदालत इजराको नीलाम करनेका अधिकार मिल जाता है (देखो 20 C. 370; 42 C. 72 P. C. 27 C. L.J. 528; 19 C. W. N. 152; 24 C. L. J. 523; 2 Pat. L. T. 401). कुछ मुकद्दमों में जो राय कायम की गई है, कि नोटिस न देने से नीलाम नाजायज़ हो जाता है, वह 42 C. 72 में प्रिवी कौंसिल के दिए फैसले के बाद से, अच्छा फैसला नहीं माना जा सकता ।

केवल नोटिस का जारी कर देना ही काफी न होगा । उसकी तामील हो जाना ज़रूरी है, देखो 25 C. W. N. 972; 61 I. C. 822; एक बार किसी नोटिस के तामील हो जाने पर रूल २२ में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि इजरा की हर एक ऐसी दरखवास्त के लिए, मदियून-बिकरी के खिलाफ़ आखिरी हुक्म की तारीख़ से एक साल से ज्यादा समय में दी गई हो, नई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, देखो 74 I. C. 838. नोटिस के जारी करने से मियाद के लिए नई तारीख़ मिल जाती है, देखो 15 A. 84; 25 C. 594 F. B.

नोटिस जारी करने के बाद की कार्रवाई—जिस शख्स के नाम रूल २२ के अनुसार नोटिस जारी किया गया है, वह बिकरी की इजरा के सम्बन्ध उज़्जदारी कर सकता है और अदालत ऐसी उज़्जदारी पर विचार करके जैसा हुक्म वह मुनासिब समझे देगी, [देखो आर्डर २१, रूल २३:].

उपरोक्त प्रारम्भिक कार्रवाई खतम होजानेके बाद अदालतको जब तककि उसे इसके विपरीत कोई कार्रवाई करने का कोई कारण न मालूम हो, बिकरी की इजराके लिए हुक्मनामा जारी कर देगी [देखो आर्डर २१, रूल २४].

ऐसे समय में अदालत हुक्मनामा जारी करेगी अर्थात् वह या तो जायदाद ग़ैर-मनकूला या मनकूला की कुर्क़ों का हुक्म देगी या बिकरीदार की दरखवास्त के अनुसार गिरफ़्तारी का वारंट जारी करेगी (देखो आर्डर २१, रूल २४, २५), वकीलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तलबाना और सम्मन अदालत द्वारा नियत (मुक़रर) किए हुए समय के भीतर दाख़िल कर दिए गए हैं या नहीं, नहीं तो इजरा की कार्रवाई ख़ारिज हो जाने की सम्भावना है ।

इलाहाबाद में आर्डर २१, रूल २५ (२) की जगह रूल २५ (२) कर दिया गया है ।

इजरा की मुल्तवी—जिस अदालत में इजरा के लिए बिकरी भेजी गई है, वह काफी वजह दिखलाए जाने पर इजरा मुल्तवी कर सकती है जिससे मदियून-बिकरी उस अदालत से, जिसने बिकरी दी है, या अदालत अपील से इजरा करने की मुल्तवी का हुक्म ला सके । इजरा मुल्तवी करने के पहिले, अदालत काफी ज़मानत तलब कर सकती है [देखो आर्डर २१, रूल २६-२७ और २८].

डिकरीदार और मदियून-डिकरी के बीच होने वाले मुकदमों के दौरान में इजरा की कार्यवाई सुलतवी करने के सम्बन्ध में देखो २१, रूल २९

कोई अपील किसी ऐसी डिकरी या ऐसे हुक्म के अनुसार, जिसकी अपील की गई है होने वाली इजरा की कार्यवाई की सुलतवी न समझी जा सकेगी, सिवाय उस हद तक जिसके लिए अदालत अपील हुक्म दे, और न अपील दायर होजाने से ही इजरा सुलतवी कर दी जायगी; लेकिन अदालत अपील, काफी वजूहात होने पर, इजरा सुलतवी किए जाने के लिए हुक्म दे सकती है। "जिस अदालत ने डिकरी दी है" वह आर्डर ४१, रूल ५ की पावन्दी में रहते हुए, काफी वजूहात दिखलाए जाने पर, इजरा सुलतवी कर सकती है। उस डिकरी की इजरा के हुक्म के सम्बन्ध में, जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है, देखो आर्डर ४१, रूल ६। "जिस अदालत ने डिकरी दी है" इसके अर्थ के सम्बन्ध में देखो दफा ३७। पंजाब में आर्डर २१ के साथ एक रूल २९ (ए) और जोड़ दिया गया है।

इजरा की मियाद की मुद्दत—हर तरह की डिकरियों की, जिनमें रेहननामा की डिकरियां भी शामिल हैं, सिवाय उन डिकरियों के जो वास्ते हुक्म इम्तनाई के दी गई हैं, इजरा की मियाद जाबता दीवानी की दफा ४८ के अनुसार १२ साल है, सिवाय उस दशा में जब कोई धोखेबाज़ी (जालसाज़ी) या जवर्दस्ती की गई हो। बारह साल की इस मुद्दत का शुमार (क) डिकरीकी तारीख से या (ख) जब डिकरी या बादवाले किसी हुक्म से किसी खास समय पर, किसी रुपये की अदायगी या जायदाद के हवाले करने के लिए हिदायत की गई हो तो, उस तारीख से किया जाना चाहिए, जिस तारीख को वाजिब होने पर भी अदायगी न की गई हो या माल हवाले न किया गया हो। इस दफा से क़ानून मियाद के आर्टि० १८० पर कोई असर नहीं पड़ता और न इससे उसकी कोई सीमा ही बंध जाती है।

वकील साहवान को चाहिए कि वे नए जाबता दीवानी की दफा ४८ को ध्यान पूर्वक पढ़ जायें। "रुपये की अदायगी या दूसरी जायदाद के हवाले किए जाने की डिकरी" शब्दों को निकाल देने से इसका क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया गया है। इसके बाद पहिले वाली दफा के अनुसार मियाद सम्बन्धी नियम का मयोग करने के लिए यह आवश्यक था कि 'इजरा की दर' रुखास्त इसके 'अनुसार' दी और "मंजूर" की जाय। अब ये दोनों शब्द निकाल दिए गए हैं। इसलिए इसका परिणाम यह हुआ कि दफा ४८ में जो मियाद सम्बन्धी नियम दिया हुआ है वह लागू हो सकता है, चाहे दररुखास्त मंजूर करली जाय या खारिज कर दी जाय अथवा चाहे दररुखास्त इस दफा के अनुसार हो या न हो। क्या इस दफा से, पहिले होगई बातों के ऊपर भी कोई असर पड़ता है? इस सम्बन्ध में देखो 40 C. 704; 45 B. 365; 47 I. C. 143; 21 I. C. 923 जिनमें इस प्रश्न का उत्तर 'हां' में दिया गया है। इसके विपरीत फैसले के लिए देखो 32 A. 499.

“बाद वाला हुक्म” उसी अदालतका दिया हुआ होना चाहिये जिसने डिकरी दी है और उसे उसने उसी अदालत की हैसियत से, अदालत इजरा की हैसियत से नहीं, दिया हो, देखो 58 I. C. 393; 40 A. 198 । १२ साल की मियाद डिकरी की तारीख से शुरू होती है जैसा कि आर्डर २० रूल ६१ द्वारा सुकरर किया गया है, देखो 34 C. L. J. 167; 22 C. W. N. 145—जब कोई डिकरी तर्मीम की गई हो तो तर्मीम की तारीख उस डिकरी की तारीख समझी जायगी, देखो 60 I. C. 318. बारह साल की इस मियाद को अदालत इजरा, क़ानून मियाद की दफ़ा १५ के अनुसार उसमें वह मुद्दत शामिल करके, जिसमें अदालत का पहिले से हुक्म लेकर इजरा मुलतवी करा दी गई थी, बढ़ा नहीं सकती, देखो 70 I. C. 396.

“तदवीर मुआविन इजरा”—तदवीर मुआविन इजरा से मियाद की नई तारीख मिल जाती है। क़ानून मियाद के आर्टि० १८२ (५) में जो यह बात लिखी हुई है उसके सम्बन्ध में बहुत से फैसले हैं पर यह बात अवश्य मान लेनी पड़ती है कि इस विषय में जितनी भी नज़रें (केस-लॉ) हैं, वे भ्रमोत्पादक हैं और अच्छी तरह से समझ में नहीं आतीं। “तदवीर मुआविन इजरा” का अर्थ है डिकरी की इजरा जारी रखने के लिए अदालत से किसी हुक्म का हासिल करना, देखो 30 C. 761. नीचे लिखे कुछ उदाहरण तदवीर मुआविन इजरा के सम्बन्ध में दिए जाते हैं:—

डिकरी के एक हिस्से की बेबाकी का इन्दराज करने के लिए आर्डर २१, रूल २ के अनुसार डिकरीदार की ओर से दरखास्तका दिया जाना, (देखो 12 A. 399; 12 C. 608; 2 C. 696)

पेशी की तारीख बढ़ाए जाने की दरखास्त ताकि डिकरीदार नोटिस की तामील का सुबूत पेश कर सके (देखो 14 C. W. N. 486), खर्चा वसूल पाने की दरखास्त (देखो 15 B. 245).

उन लोगों के खिलाफ़ इजरा की दरखास्त जिनमें से कुछलोग मर गए हैं (देखो 2 C. L. J. 544).

कलक्टर के रजिस्टर से उद्धरण प्राप्त करने के सम्बन्ध में दरखास्त (देखो 14 C. W. N. 481).

मदियून-डिकरी की ओर से इस बात की दरखास्त कि इस बिना पर इजरा की कार्यवाई खारिज कर दी जाय कि डिकरीदार के साथ कुछ समझौता कर लिया गया है (देखो 5 C. 515; 3 A. 320). बोली बोलने की इजाज़त देने के सम्बन्ध में दरखास्त (देखो 10 C. W. N. 209; 22 A. 399; 21 B. 331; 30 C. 761; 12 C. W. N. 626).

किसी डिकरी के एक हिस्से की इजरा की दरखास्त (देखो 26 C. 888; 15 B. 242).

कुर्क की हुई रकम को वसूल पाने की दरखास्त (देखो 16 M. 10 C. W. N. 354; 35 M. L. J. 575).

रुपया की अदायगी के लिए डिकरीदार की ज़बानी दरखास्त (देखो 22 B. 340).

नीलाम में खरीदी हुई जायदाद पर कब्ज़ा दिलापाने के लिए दरखास्त (देखो 19 All. 477; 13 C. W. N. 694). नीलाम का सूर जारी करने के लिए दी गई दरखास्त (देखो 10 C. 851 F. B.; 15 B. 405; 28 M. 399).

मुतौफी मदियून डिकरी के वारिसों को फ़रीक बनाने के लिए दरखास्त (देखो 1 C. W. N. 676).

डिकरी की मुन्तकिली के लिए दरखास्त (देखो 2 C. W. N. 1 A. 625 F. B.; 20 C. 29; 35 A. 389).

बिना डिकरी की नकल के इजरा के लिए दरखास्त (देखो 40 C. 209; 5 Pat. L. W. 205).

उन चीज़ों को अलग करने के लिए दी गई दरखास्त जिनके बिना इजरा न की जायगी; सिलसिले में पेश की गई कोई सहायक (ज़मीनी) दरिस्त पहिली दरखास्त के सिलसिले में समझी जायगी (देखो 22 C. N. 540).

लेकिन अगर इजरा की दरखास्त के साथ चीज़ों की फेहरिस्त बिना दाखिल ही न की जाय, तो वह दरखास्त कानून के अनुसार न समझी जाय (देखो 17 Cal. 631 F. B.; 18 C. L. J. 538; 37 A. 527).

डिकरी की इजरा के सम्बन्ध में की गई उज्रदारी ख़ारिज करने के लिए दी गई दरखास्त (देखो 40 A. 668).

डिकरीदार की ओर से मदियून डिकरी की उज्रदारी की समाप्त करने के लिए, गवाहों की फेहरिस्त का दाखिल करना (देखो 22 C. W. 1027).

आर्टि० १८२ कलॉज़ ६ में नोटिस जारी करने की तारीख़ वह तारीख़ जिस तारीख़ को असल में नोटिस जारी किया गया हो अर्थात् वह तारीख़ जिस तारीख़ को उसपर शिर्शतेदार के दस्तख़त हुए हों, वह तारीख़ जिसको अदालत ने नोटिस जारी करने का हुक़म दिया हो। देखो 10 C. N. 303; 6 C. W. N. 656; 23 B. 35; 30 M. 30; 3 Pat. L. J. 45 I. C. 203; 42 B. 553).

इशतहार का मसविदा दाखिल करने के लिये और पेशी की तारीख़ जानने के लिये दी गई दरखास्त (देखो 38 M. 695; 33 I. C. 79).

डिकरीदार की ओर से पेश की गई वह दरखास्त जिसमें जूर डिकरी के एक हिस्से की अदायगी का सर्टीफिकेट दिया गया हो (देखो 20 C. W. N. 615; 46 C. 22).

ऐसे शख्स के खिलाफ इजरा की दरखास्त जिसका पता मालूम नहीं है (देखो 36 A. 482).

वे दरखास्तें तदवीर मुआविन इजरा नहीं हैं—नीलाम की तस्दीक करने के लिये दी गई दरखास्त (देखो 31 C. 1011; 11 C. L. J. 356).

नीलाम बन्द कर देने की दरखास्त (देखो All. 757).

एक शिलिंग प्रति पौंड के हिसाबसे ली जाने वाली फीस (Poundage fee) लेने के लिये दरखास्त (देखो 22 C. 827; 23 C. 196).

डिकरीदार की ओर से जायदाद मकूरका (कुर्क की हुई जायदाद) के किसी हिस्से को छोड़ देने के लिये दरखास्त (देखो 20 C. 255; 8 C. W. N. 251).

दाखिल की हुई डिकरी की नकल की वापसी के लिये दरखास्त (देखो 23 Bom. 311).

वक्त के लिये दी गई दरखास्त (देखो 8 C. L. J. 193; 27 C. 285 3 C. L. J. 240).

नीलाम मुलतवी करने के लिए मदियून डिकरी की ओरसे दी गई दरखास्त की मंजूरी देना (देखो 28 M. 40).

मदियून-डिकरी की शिनाख्त करने के लिए तामील के चपरासी के साथ जाना (देखो 20 C. L. J. 15; 13 C. W. N. 1288).

कानूनी प्रतिनिधि की ओर से उत्तराधिकार (विरासत) का सर्टीफिकेट पाने के लिये दी गई दरखास्त (देखो 37 B. 559).

भिन्न भिन्न प्रकार की डिकरियों की इजरा के तरीके

[१] (क) रुपये की अदायगी की डिकरी की इजरा के ज़ाबते और तरीके के सम्बन्ध में देखो आर्डर २१ रूल ३०,

(ख) जायदाद मनकूला-खास की डिकरी की इजरा के ज़ाबता और तरीके के सम्बन्ध में देखो रूल २१,

(ग) तामील मुखत्तस (Specific Performance) की पतिपत्नी सम्बन्धी अधिकारों की वापसी (Restitution of Conjugal rights) की और हुक्म इस्तनाई की डिकरी की इजरा के ज़ाबता और तरीके के सम्बन्ध में देखो रूल ३२ और ३३;

(घ) दस्तावेज़ की तकमील या दस्तावेज़ात काबिल बय व शरी (Negotiable instrument) की तस्दीक की डिकरी की इजरा के ज़ाबते और तरीके के सम्बन्ध में देखो आर्डर २१ रूल ३४;

(ङ) जायदाद गैर-मनकूला के दखल खास की, जायदाद गैर-मनकूला के कब्ज़ा मुश्तरका और किसी इमारत पर कब्ज़ा की, जब कि उस शख्स ने उस मकान पर काबिज़ है निकलने की आम इजाज़त न रखी हो । डिक्री इजरा के ज़ाबते और तरीक़े के सम्बन्ध में देखो रूल ३५;

(च) जायदाद गैर-मनकूला पर कब्ज़ा अदालत देने की डिक्री इजरा के ज़ाबते और तरीक़े के सम्बन्ध में जबकि वह किसी असामी के कब्ज़े हो देखो रूल ३६ और आर्डर २१, रूल ९६;

(छ) उस जायदाद की हवालगी की, जो मदियून डिक्री की मिलिकियन डिक्री के इजरा के ज़ाबते और तरीक़े के सम्बन्ध में देखो आर्डर २१ रूल ९७;

[२] किसी ऐसी डिक्री की इजरा करते समय, जो किसी मालगुज़्ता अदाकरने वाली मुश्तरका रियासत के बटवारा के लिए दी गई हो, ज़ाबता दीन की दफा ५४ में बतलाई हुई कार्रवाई करनी चाहिए ।

[३] डिक्रीयों की इजरा सम्बन्धी नियम, हुकम जो इजरा के सम्बन्ध में लागू होंगे (देखो दफा ३६) ।

मदियून डिक्री के ज़िस्म के खिलाफ इजरा—जब डिक्री रुपये की अदायगी सम्बन्ध में हो, तो डिक्री दिये जाते समय ज़बानी दरख़वास्त करने पर अदालत वारण्ट तैयार किए जाने के पहले, फ़ौरन गिरफ्तारी का हुकम दे सकती है, अतः मदियून डिक्री अदालत की सीमा के अन्दर है [देखो आर्डर २१ रूल ११ (१)] बाकी सभी हालतों में दरख़वास्त आर्डर २१ रूल ११ (२) के अनुसार होगी । गिरफ्तारी के तरीक़े और वक्त के सम्बन्ध में देखो दफा ५५ । दूसरी तरह की डिक्री अर्थात् जायदाद मनकूला खास की तामील मुख्तसस की और हुकम इम्तनाज़ के डिक्रीयां इत्यादिकी इजरा में भी मदियून डिक्री गिरफ्तार और क़ैद किया जा सकता है (देखो आर्डर २१ रूल ३१, ३२, ३३,) । ज़ाबते के सम्बन्ध में देखो आर्डर २१ रूल २४ ।

रुपय की डिक्री की इजरा में औरतों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, (देखो दफा ५६) । अदालत को यह भी अधिकार है कि पति पत्नी सम्बन्धी अधिकारों की वापसी की डिक्री की इजरा में किसी शख्स को क़ैदखाने में बनाए रखने सम्बन्ध में दरख़वास्त को नामंजूर कर दे (देखो आर्डर २१ रूल ३३); अदालत वारण्ट निकाल देने के पहले वजह ज़ाहिर करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है (देखो आर्डर २१ रूल ३७); अगर वह हाज़िर होकर आर्डर २१ रूल ४० के अनुसार वजह ज़ाहिर कर दे जिससे अदालत को इतमीनान हो जाय, तो अदालत गिरफ्तारी का वारण्ट निकालने से इन्कार कर देगी । अगर वह शख्स हाज़िर न हो तो वारण्ट निकाल दिया जायगा [देखो रूल ३७ (२)]

अगर मदियून डिक्री गिरफ्तारी के वक्त डिक्री का मतालबा अदा करे तो वारण्ट की तामील न की जायगी (देखो आर्डर ३८, दफा ५५)—अगर रुक

अदा न कीगई तो वह गिरफ्तार किया जाकर जितनी जल्दी हो सकेगा अदालत के सामने हाज़िर किया जायगा, (देखो दफा ५५)—वारण्ट की तामीली के तरीकेके सम्बन्धमें देखो दफा ५५ (१)—कोई भी मदियून-डिकरी उस समय तक गिरफ्तार न किया जायगा जब तक कि उसके लिए काफी खूराक जमा न कर दी जाय (देखो आर्डर २ रूल ३९) ।

अदालतके सामने लाए जाने पर अदालत उसे दीवालिया करार दिए जाने की दरख्वास्त देनेके लिए कहेगी और दफा ५३ (४) के अनुसार जमानत दाखिल कर देनेके बाद वह उस मदियून डिकरीको रिहा करदेगी। अगर मदियून डिकरीको गिरफ्तारीके विरुद्ध कुछ भी कहना होगा, जैसे गरीबी वगैरा, तो अदालत उसे सुनेगी और आर्डर २१ रूल ४० के अनुसार उस उज्रदारीका फैसला करदेगी। अगर उज्रदारी नामंजूर करदी जाय तो, अदालत उसे दीवानी जेलमें भेज देगी। डिकरीदार आर्डर २१ रूल ३९ के अनुसार खूराक वगैरा जमा कर देगा।

कैदमें बनाए रखनेकी मियाद—अगर रुपयेकी तादाद ५०) ६० से अधिक हो तो ६ महीने और दूसरी हालतोंमें ६ हफ्ता है (देखो दफा ५८)—मतालया डिकरीके अदा कर देने पर (देखो दफा ५८) ; सख्त बीमार होनेकी हालतमें मदियून डिकरी जेल से रिहा कर दिया जाता है (देखो दफा ५९)—जो मदियून डिकरी दफा ५८ के अनुसार कैदसे रिहा करा दिया जायगा, वह इस रिहाकी वजहसे कुँसे छुटकारा न पा जायगा लेकिन वह उस डिकरीकी इजरामें दुबारा फिर न गिरफ्तार किया जा सकेगा, जिसकी इजरामें वह दीवानी जेलमें बन्द रखा गया था (देखो ५८, क्लॉज़ २)—जब तक डिकरीकी रकम बेबाक न होजाय तब तक डिकरीदारको अधिकार है कि वह उसकी जायदादकी कुर्की और नीलामके लिए दरख्वास्त दे सके, जैसा कि आर्डर २१ रूल ३१, ३२ में बतलाया गया है। जो मदियून-डिकरी दफा ५९ के अनुसार रिहा कर दिया गया हो, वह दुबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसके कैदमें रखे जानेकी मियाद कुल मिलाकर उस मियादसे ज्यादा न होनी चाहिए जो दफा ५८ में बतलाई गई है। यानी अगर डिकरीके अनुसार ६ मासकी कैद है और वह एक बार १ मास जेलमें रहा पीछे किसी कारणसे छोड़ दिया गया तो फिर दुबारा या तीसरे मरतबा भी वह जेलमें रखा जा सकता है मगर उस दशामें ५ मास से अधिक जेलमें न रखा जायगा ।

जायदादके खिलाफ इजरा—कौनसी जायदाद कुर्ककी जासकती है और कौनसी नहीं—किसी डिकरीकी इजरा मदियून डिकरीकी जायदाद (मनकूला या गैर-मनकूला) की कुर्की और नीलामसे की जा सकती है। जायदादकी कुर्की और कुर्ककी हुई जायदाद की नीलाम अदालतका कोई अफसर अदालत इजरासे जारी किए हुए वारण्टके अनुसार कर सकता है ।

जो जायदाद किसी डिकरीकी इजरा में कुर्क और नीलाम किए जानेके काबिल है और जो इस काबिल नहीं है, उन सबका वर्णन ज़ाबता दीवानी की

दफा ६० में किया गया है और उस दफा की पाबन्दी में रहते हुए कुल जायदाद जो नीलाम किये जाने के काबिल है चाहे मनकूला हो या गैर मनकूला, जो मदीयून डिकरी की मिलिकियत है या जिसके रेहन, बय या और किसी वस्तु पर मुन्तकिल कर देने का अख्तियार उसे हैं जिसका इस्तेमाल वह अपने कामों लिये कर सकता है, मदीयून-डिकरी के खिलाफ डिकरी की इजरा में कुंफे नीलाम कर दिये जाने के काबिल है ।

जायदाद दीवानी की दफा ६० इस प्रकार है—

दफा ६० जायदाद काबिल कुर्की व नीलाम बद्दलत इजरा डिकरी—(१) जो जायदाद कि बद्दलत इजरा डिकरी काबिल कुर्की और नीलाम के हैं तफसील उसकी यह हैं—यानी आराजियात या मकानात या दीगर इमारात और असबाब और ज़रनक़ और बेङ्ग नेट और चिक यानी रक्का और बिल आफ़ एक्सचेंज और हुण्डर और प्रामेसरी नेट और नेट सरकारी और तमस्सुकात या दीगर क्रिफालत न जानत ज़र नक़द और ज़र क़र्ज़ और हिस्सा किसी जमाअत सनदयाफ़तका और सिवा उन अशिया के जिनका ज़िक्र आइन्दा है, तमाम दीगर जायदाद मनकूला गैर-मनकूला काबिल फ़रोख़्त जो मदीयून-डिकरी की हो या जिसपर या जिस मुनाफ़े पर उसको ऐसा अख्तियार तसर्फ़का पहुँचता हो कि वह उसको अपने मुनफ़ियत के लिये अमल में ला सके ख़्वाह वह उसके नामसे हो या बतौर उसके अमानत के या मिनजानिब उसके दूसरे शख्स के पास हो ।

मगर शर्त यह है कि अशियाय मुन्दर्ज़ा ज़ैल काबिल कुर्की या नीलाम न होगी यानी—

(ए) ज़रूरी पोशाक और पकाने के बरतन और पलंग और विस्तर मदीयून-डिकरी और उसकी ज़ौजा और अतफ़ाल के और ऐसे ज़ेवर जिनको औरत मुताबिक अपने रसूम-मज़हबी के जुदा न कर सकती हो—

(बी) अहल हर्फ़ा के औज़ार और अगर मदीयून-डिकरी ज़राअत पेशा तो ज़राअत के आलात और ऐसे मवेशी और तुख़म ग़ल्ला जो बदानिस्त अहल मदीयून-डिकरी की वजह मआश के लिये ज़रूरी हों और उस क़दर हिस्सा पेशा वार ज़राअत या किसी किसम ख़ास की पैदावार ज़राअत का जो दफा ६१ के तहत ज़िब कुर्की व नीलाम से मुस्तसना कर दिया गया है—

(सी) मकानात व दीगर इमारात (मय उनके माल मसाला और आराम मौक़ा के और उस आराज़ी के जो उनसे बिल्कुल मुत्तसिल हो और उनके इस्तेमाल लिये ज़रूरी हो) ममलूका व मकबूजा काइतकार—

(डी) बहीखाता—

(ई) महज़ हक़ रज़ूअ नालिश ख़िसारा—

(एफ़) हर हक़ ज़ाती ख़िदमतका—

(जी) वजीफा और अतीयात पिंशनदारान सरकारी या वह जो सर्विस फेमिली पिंशन फण्डसे मिलते हैं जिसकी वाचत इस बारेमें गज़ट आफ़ इण्डियामें इस्तहार मिनूजानिब नब्वाब गवर्नर जनरल बहादुर इजलास कौंसिल शायी हो गया हो और पिंशन सींगः पोलिटिकल—

(एच) अलाउन्स यानी ज़र मबाजिब (जो तनख्वाहसे कम हो) किसी ओहदेदार सरकारीका या किसी रेलवे कम्पनी या हाकिम मुकामीके मुलाज़िम का जब कि अपने कामसे गैरहज़िर हो—

(आई) तनख्वाह या अलाउन्स बराबर तनख्वाहके किसी ऐसे ओहदेदार सरकारी या मुलाज़िम का जिसका जिक्र फिकरे (एच) में है जब कि वह काम पर हो ताहद मुफ़स्सिला ज़ैल यानी—

१ कुल तनख्वाह अगर बीस रुपये माहवारसे ज़्यादा न हो—

२ बीस रुपये माहवार, जब कि तनख्वाह बीस रुपये माहवारसे ज़्यादा हो मगर चालीस रुपये से ज़्यादा न हो—

३ निस्फ़ तनख्वाह किसी और सूरतमें—

(जे) तनख्वाह और अलाउन्स उन लोगोंके जिनसे आईन लश्करी हिन्दुस्तानी मुतअल्लिक हैं—

(के) जुम्ला ज़रूरी डिपाज़िट व दीगर रकूम जो किसी ऐसे फण्ड (सर्माया) में जमा हैं या ऐसे फण्डसे हासिल की जाय जिससे ऐकट मुतअल्लिक प्राविडेण्ट फण्ड मजरीया सन् १८९७ ई० बरवक्त मुतअल्लिक हो जहां तक कि रकूम मज़कूर ऐकट मज़कूरके ज़रिये से गैर-काबिल कुर्की करार दीगई हो—

(एल) उज़रत मज़दूरान और मुलाज़िमान ख़ानगीकी ख़्वाह रुपया या कोई चीज़ दीजाय—

(एम) उम्मेद विरासत वहालत पस्मांदिगी या और हक़ या इस्तिहकाक़ जो महज़ मौकूफ़ बचकूअ अम्र दीगर या बहैयज़ इम्कान हैं ।

(एन) हक़ नान व नफ़का आइन्दा का ।

(ओ) वह अलाउन्स जो किसी कानून मजरीया तहत ऐकट कौन्सिलहाय हिन्द सन् १८६१ ई० व सन् १८९२ ई० की रू से कुर्की व नीलाम बइल्लत इन्राय डिकरीसे मुस्तसना कर दिया गया हो ।

(पी) अगर मदियून-डिकरी मालगुज़ार सरकार हो तो कोई जायदाद मनकूला जो किसी कानून नाफिजुलवक्त मुतअल्लिक शख्स मज़कूरकी रू से ऐसे नीलामसे मुस्तसना कर दीगई हो जो बग़रज वसूली बकायाय मालगुज़ारी अमलमें आये ।

तशरीह—वजीफा वगैरा मुतज़िक्करा फिकरात (जी) व (एच) (आई) व (जे) व (एल) और (ओ) कुर्की व नीलामसे मुस्तसना हैं कबल ख़्वाह बाद वाकई धाजिबुल अदा होने के—

(२) इस दफाकी किसी इबारतसे यह मफहूम न होगा कि—

(ए) मकानात व दीगर इमारत (मय उनके माल मसाला और आराज़ी मौकाके और उस आराज़ीके जो उनसे बिल्कुल मुत्तसिल हो और उनके इस्तेमाल के लिये ज़रूरी हो) डिकरी ज़र लगानके इजरामें जो उसी मकान या इमारत या आराज़ी मौका या आराज़ी मुत्तसिलकी निस्वत हो कुर्की व नीलामसे मुस्तसना ।

(बी) न इबारत मज़कूर ऐकट मुत्तअल्लिक़ा फौज या उस किस्मके और कानून नाफिज़ुल वक्तमें खलल अन्दाज़ होगी ।

जो जायदाद कुर्क नहीं की जा सकती है, उसका वर्णन दफा ६० (१) की शर्त (ए) से लेकर शर्त (बी) तक में किया गया गया है । खेती करीब कामोंमें लगे हुये जानवर कुर्कीसे बरी (मुस्तसना) न समझे जायंगे जब तक कि अदालत उसे ऐसा होनेकी घोषणा न कर दे (देखो 10 C. 397)—अदालतसे यह बात तय करनी चाहिये कि वे खेतीके कामोंके लिये आवश्यक हैं या नहीं । इस बातसे कि मवेशी किसीके पास रहन है, दफा ६० की कार्रवाईमें कोई रुकवट नहीं पड़ती (देखो 61 I. C. 777)—खेती की पैदावारका कौन सा अंश बरी है कौनसा नहीं, इस सम्बन्धमें देखो दफा ६१, बेसार (बोआईके लिये रखा हुआ गह्ना), गह्ना और मवेशी कुर्कीसे बिल्कुल मुस्तसना नहीं है । जब मदिपू डिकरी बिल्कुल गरीब (निर्धन) न हो और उनकी जगह नई चीज़ें खरीद सकता हो तो वे कुर्क किये जा सकते हैं, देखो 25 I. C. 117—किसी दर्जीकी कपड़ा सीने वाली मशीन कारीगरीका एक औज़ार है, देखो 65 I. C. 416 । जब किसी मदिपू-डिकरीकी जीविका का साधन सिर्फ खेती ही न हो तो वह किसान न समझा जायगा और इसलिए दफा ६० (सी) के अनुसार किसी भी मुस्तस्नियात का (छूटका) मुस्तहक नहीं है, देखो 63 I. C. 681,—दफा ६० (ग) ऐसी जायदादकी नीलाम को नहीं रोकता जो खास तौरसे रहन कर गई हो यद्यपि वह जायदाद किसी ऐसे मकानका सामान हो जो किसी किसानके कब्ज़ेमें हो या जिसपर कोई किसान काबिज़ हो, देखो 4 B. 25; 34A. 25 P. B. इसके विपरीत देखो 33 A. 136; 51 I. C. 553 (A.) 1.

जायदाद मनकूलाकी कुर्कीका तरीका—उस जायदाद मनकूलाकी, जो मदिपू डिकरी के कब्ज़ेमें है और जो खेतीसे होने वाली पैदावार नहीं है, कुर्की उस जायदाद पर वास्तविक कब्ज़ा करके की जा सकती है । जब जायदाद अपने आप और जल्द खराब हो जाने वाली हो, या जब उसके रखनेके खर्चके उसकी कीमत से बढ़ जाने की सम्भावना हो, तो वह फौरन् बेच दी जा सकती है (देखो आर्डर २१, रूल ४३)—किसी रहनेके मकानमें रखी हुई जायदाद मनकूलाकी कुर्की (ज़ब्तीके सम्बन्धमें देखो दफा ६२)

२ ज़िराअती (खेतीसे होने वाली) पैदावार और खड़ी हुई फसलकी कुर्की के तरीके के सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ४४-४५; ज़िराअती पैदावारके किसी हिस्सेको कुर्कीसे बरी कर देने सम्बन्धी स्थानीय सरकारके अधिकारोंके सम्बन्धमें देखो ज़ाबता दीवानीकी दफा ६१ ।

३ किसी कर्जें, किसी कार्पोरेशनकी पूंजीके हिस्से और दूसरी जायदाद मन-कूलाकी, जो मदियून डिकरीके कब्जेमें नहीं है, कुर्कीके तरीकेके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ४६।

४ मदियून डिकरीके उस जायदाद मनकूला के हिस्सेकी, जो उसकी और उसके दूसरे शरीकदारकी मिलिकयत है, कुर्कीके तरीकेके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ४७।

५ सरकारी नौकर, किसी रेलवे कम्पनीके या स्थानीय अधिकारी वर्ग के नौकरके वेतन (तनखाह) या भत्ता की कुर्कीके तरीके के सम्बन्धमें देखो आर्डर २१, रूल ४८; दफ्ता ६०, कलॉज (एच), (आई) और (जे)

६ साझेदारीकी जायदाद की कुर्कीके तरीके और किसी फर्म (दूकान) के ऊपर दीगई डिकरीकी इजराके तरीकेके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१, रूल ४९-५०।

७ दस्तावेज़ात काबिल बय व शरी की कुर्कीके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ५१।

८ अदालत या सरकारी अफसरकी सिपुर्दगीमें रखी हुई जायदादकी कुर्कीके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ५२।

९ कर्जें या रेहनकी डिकरियोंकी कुर्की के सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ५३

‘कर्जा’ से मतलब उस कर्जें से है जो असलियतमें कर्जेंकी सूरत रखता हो अर्थात् ऐसा कर्जा जो किसी खास मुद्दतके लिये बतौर कर्जेंके दिया गया हो, ऐसा रुखा नहीं जो भविष्यमें किसी समयमें दिया जा सकता है या नहीं या जिसका अदा करना किसी विशेष अवस्थापर निर्भर करता है। जो सम्भव है कभी आए अथवा न आए, देखो 4 C. W. N. 87; 9 C. W. N. 703; 30 A. 246. सालाना मिलने वाला वजीफा (वसीका) जिसका रुपया अभी वाजिबुल अदा नहीं है, कर्जा नहीं है, देखो 14 C. L. J. 129.—वह माहवारी भत्ता जो किसी मदियून-डिकरीको वाजिबुल अदा वसूल हो, कर्जा है, देखो 9 C. W. N. 703. गुजाराकी बकाया कर्जा है, देखो 8 W. R. 41.—लेकिन गुजाराका ऐसा हक जो पैदा होनेवाला है (जिसके पैदा होनेकी आशा है) कुर्क नहीं किया जा सकता, देखो 23 W. R. 427.—जो कर्जा बना हुआ है लेकिन जिसका रुपया आगे चलकर अदा किया जाने को है, वह कुर्क किए जानेके काबिल है, देखो 14 M. I. A. 40, 50—जो कर्जा मदियून डिकरीको ऐसे शर्तसे मिलना हो जो अदालत इजराके अधिकार क्षेत्रमें नहीं है, उसकी कुर्की वह अदालत नहीं कर सकती, देखो 39 C. 104.

किसी खानगी नौकर की तनखाह उस वक्त कुर्क नहीं हो सकती जबतक कि वह वाजिबुल वसूल होकर कर्जा न बन जाय, देखो 21 M. 393. लेकिन एक सरकारी नौकर की तनखाह कुर्क हो सकती है, परन्तु उसमें दफ्ता ६० (१) (आई) में बतलाई हुई रुकावटें अवश्य लागू होंगी। आर्डर २१ रूल ४८ के अनुसार अदालत को अब पूरा अख्तियार है कि वह किसी सरकारी

नौकर, किसी रेलवे कम्पनी के नौकर या किसी स्थानीय अधिकारी वगैरे नौकरकी तनख्वाह कुर्क करले, चाहे मदियून डिक्ली या रुपया देने वाला अफसर अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाके भीतर रहता हो या न रहता हो।

वासिलातकी डिक्ली नीलाम—दफा ६० के अनुसार वासिलातकी डिक्ली नीलाम नहीं की जा सकती। इसके लिए ज़ाबता सिर्फ यह है कि वह कुर्क करली जाय और फिर आर्डर २१, रूल ५४ के अनुसार उसकी इजरा करा दी जाय, देखो 48 I. C. 183.

२८) से कमकी चीज़का नीलाम—जब उस अफसर का, जिसने आर्डर ११ के रूल ४३ से ४५ तकके रूलोंके अनुसार जायदाद कुर्क की है यह विश्वास है कि जायदाद मक़रूका (कुर्क की हुई जायदाद) २०) ६० से ज्यादा कीमतकी नहीं है, तो उसे चाहिए कि वह मदियून-डिक्ली को या, उसके न होनेकी दशामें, उसके घरके किसी बालिग़ शख्सको, जो मौजूद हो, सूचना दे देवे कि वह जायदाद आर्डर २१ के रूल ६६ के अनुसार इश्तहार जारी किए बिना ही नीलाम आम में फ़ौरन् बेच दी जायगी। अगर डिक्लीदार या मदियून-डिक्ली या उसकी ओर से कोई दूसरा शख्स इसबात के ऊपर एतराज करे, तो कुर्की करने वाला अफसर उस गिर्द-नवाह के कम से कम तीन बाशि और प्रतिष्ठित बाशिन्दों की एक पंचायत इकट्ठा करेगा जिसमें से एक आदमी तो उस गांव का मुखिया होगा, और उन लोगों से उस जायदाद की कीमत ठहराने को कहेगा। अगर वे यह तय करदें कि उसकी कीमत २०) ६० से ज्यादा है, तो वह उसमें उन नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा जो स्थानीय सरकार (जाबता दीवानी, ऐक्ट नं० १४ सन् १८८२ ई०, की दफा २६९ के, जो कि आर्डर २१, रूल ४३ के समान है) तैयार करेगी, अन्यथा वह फ़ौरन् उस जायदादको जायदाद खरीदने का इरादा रखने वालों को ऐसा नोटिस देने के बाद जो कि वह उस दशा में दे सकता है, नीलाम में फ़रोख्त कर देगा (देखो G. R. & C. O. Chap. I. R. 93).

रूल १—१४ के लिए, जिन्हें स्थानीय सरकार ने (जाबता दीवानी सन् १८८२ ई० की दफा २६९ के अनुसार, जो कि मौजूदा जाबता दीवानी के आर्डर २१, रूल ४३ के बराबर है) तैयार किया है, देखो G. R. & C. O. Chap. I. Note to Rule 93, p. p. 32-34.

जायदाद गैर-मनकूला की कुर्की का तरीका—अगर जायदाद गैर मनकूला हो तो उसकी कुर्की एक ऐसे हुक्म के ज़रिये की जा सकती है जिसमें मदियून-डिक्ली को इस बात की हिदायत कर दी गई हो कि वह किसी तरह से जायदाद को न मुन्तकिल करे और न उसके ऊपर कोई वार पैदा करे, और कुल आदमियों को ऐसी मुन्तकिली या वार-किफ़ालत से फ़ायदा उठाने से मना कर दिया गया हो।

इस हुक्म की मुश्तहरी उस जगह पर, जहां कि जायदाद है, या उसके करीब में ही की जानी चाहिए, और उस हुक्म की एक नक़ल उस जायदाद

खुले हुए हिस्से पर और इसके बाद कचहरी के खुले हुए हिस्से पर, जिस पर आम लोगों की निगाह पड़ती हो चर्रां कर दी जानी चाहिए (देखो आर्डर २१, रूल ५४)।

अगर कुर्की के दौरान में मदियून-डिकरी अदालतकी मारफत डिक्री का मतालवा चुकता कर दे, तो कुर्की वापस ले ली गई समझी जायगी, वरना जायदाद नीलाम करदी जायगी।

किसी रेहननामा की वाबत दी हुई नीलाम की डिक्री रूल ५४ के अर्थ में जायदाद गैर-मनकूला न समझी जायगी, देखो 8 A. L. J. 1327. फूक-रेहनी की डिक्री इस रूल के अनुसार नहीं बल्कि रूल ५३ (२) के अनुसार कुर्की जा सकती है, देखो 10 Bom 444. किसी राहिन का हफ-इन्फिकाक इस रूल के अर्थ में, जायदाद गैर-मनकूला है, देखो 21 B. 226.

किसी रेहननामा की डिक्री इजरा में जायदाद गैर-मनकूला के कुर्की किए जाने की ज़रूरत नहीं है। डिक्री में लिखा हुआ नीलाम का हुक्म खुद नीलाम के लिए काफी सुबूत है, देखो 4 B. 515; 26 C. 127; 9 B. 561; 15 B. 222 P. C.

कुर्की कर लेने के बाद आर्डर २१, रूल ६६ के अनुसार उसकी नीलाम का इश्तहार तैयार किया जाना चाहिए और फिर वह रूल ६७ के अनुसार प्रकाशित किया जाना चाहिए।

रियासतकी कुर्की—(अ) जब दरख्वास्त किसी ऐसी रियासतके किसी हिस्सेकी कुर्कीके लिए दी गई हो, जिसकी मालगुजारी माफ है, तो आर्डर २१, रूल १३के अनुसार लिखी जाने वाली बातों के अलावा हर ऐसी हालत में जब इस बात का इन्दराज कलक्टर के रजिस्टर में कर लिया गया हो, दरख्वास्त में उस रियासतका पूरा रकबा बगैरा लिखा जाना चाहिए। (ब) जब कोई दरख्वास्त किसी दीवानी अदालत को ऐसी रियासत या उस रियासत के हिस्से की कुर्की के लिए दी गई हो, जो किसी जिले की फेहरिस्त मालगुजारी में चढ़ी हुई है, तो उपरोक्त आर्डर के रूल १४ के अनुसार लिखी जाने वाली बातों के अलावा दरख्वास्त में वह मालगुजारी भी लिखी जानी चाहिए जो उस रियासत की वाबत हरसाल अदा की जाती है और उसके समर्थन में कलक्टर के रजिस्टर से उसकी एक तस्दीक खुदः नकल पेश करनी चाहिए, देखो G. R. & C. O. Chap. I R. 92 (यू०पी० में इसे खेवट कहते हैं)।

रियासतों और रियासतों के हिस्सों की कुर्की के सम्बन्ध में दिए हुए दीवानी अदालतों के कुल हुक्मों की इतला फौरन् उस जिले के कलक्टर को दे दी जानी चाहिए जिस जिले में कि वह रियासत या उसका कोई हिस्सा वाकै है (देखो G. R. & C. O. Chap. I, R. 94)

विवरण—उपरोक्त नियम (रूल) से वह हुक्म तहरीरी रद्द नहीं हो जाता जो ज़ाबता दीवानी के आर्डर २१, रूल ५४ के सब-रूल (२) के अनुसार कल-

कटर के दफ्तर में चरपां किया जाना चाहिये, जब कोई आराज़ी या उसका हिस्सा कुर्क कर लिया जाय ।

जब किसी रियासत या उसके हिस्से की कुर्की कानूनन और जायदाद वापस ले ली गई हो, तो उसी तरह इस वापसी की इत्तला कलक्टर को दी जानी चाहिये (देखो G. R. & C. O. Chap. I. R. 95).

इलाहाबाद में रूल ५५ की जगह रूल ५५ (१) कर दिया गया है ।

कुर्की का बन्द होजाना—किसी भी जायदाद की कुर्की उस समय बन्द होजाती है जब डिकरीदार की असावधानी के कारण अदालत इजरा की दरख्वास्त में कमी कार्रवाई करने में असमर्थ हो और इसलिये अदालत उसे खारिज कर दे (देखो आर्डर ११ रूल ५७) ।

इस नये रूल से अब उस विरोध का अन्त होजाता है जो इस सम्बन्ध में जजों की रायों में रहा करता था और उसमें यह व्यवस्था कर दी गई है कि किसी इजरा की दरख्वास्त के खारिज होजाने पर आप से आप कुर्की खतम होजाती है असावधानी, शब्द का बहुत संकुचित अर्थ न किया जाना चाहिये । इस मतलब सिर्फ हाज़िर होने या तलबाना जमा करने इत्यादिमें हो जानेवाली असावधानी की गई है, तो दरख्वास्त खारिज कर देनी चाहिये और कुर्की उस समय खतम होजाती है चाहे अदालत और फरीकैन का यही इरादा क्यों न हो कि वह बनी रहे (देखो 15 C. W. N. 428 तथा 44 A. 274) —

अगर असावधानी "असावधानी" से मतलब है उस काम का न करना जिसका करना डिकरीदार के लिये अपनी दरख्वास्त को जारी रखने और जायदाद को नीलाम करानेके वास्ते ज़रूरी था (देखो 67 I.C. 543);

खारिज कर देने से कुर्की चली जाती है (देखो 24 Bom. L. R. 442)

जब डिकरीदार डिकरीके बाबत थोड़ा रुपया ले लेवे और मद्दयून डिकरी को बाकी की अदायगी के लिये कुछ मौकादे और उस समय इजरा का मुकदमा खारिज होजाय तो कुर्की बनी नहीं रह सकती (देखो 71 I. C. 881)

रूल ५७ उन कुर्कियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता है जो फ़ैसला होने के पहिले करवा ली जाती हैं (देखो 16 C. L. J. 86; 22 I. C. 311; 42 M. 1 F. B. ; 80 I. C. 106.)

कुर्की के बाद मुन्तकिली—जायदाद कुर्क होजाने के बाद खानगी तौर पर किसी शख्स को जायदाद या रूपया की की गई मुन्तकिली या हवालगो, उन तमाम दावों के मुक़ाबिले में नाजायज़ समझी जायगी जो उस कुर्की की निस्वत किये किये जाने को हों (देखो दफा ६४);

मुन्तकिली में हर तरह से की जाने वाली जायदाद की अलाहदगी शामिल है जैसे बय, हिवा, रेहन, वगैरा । इस दफा का उद्देश्य क्या है इस सम्बन्ध में देखो 23 C. L. J. 111; दफा ६४ का जो विवरण है उसमें यह बतलाया गया है कि कुर्की की निस्वत किये जाने वाले दावों में दफा ७३ के अनुसार असावधानी (रूग्णति) हिस्से रसदी बटवारा भी शामिल है स्मरण, रखना चाहिये कि कुर्की

के बाद की गई मुन्तकिली विरुद्ध न जायज नहीं हो जाती बल्कि उसका सिर्फ उतना हिस्सा नाजायज हो जाता है जिसके लिये उस कुर्की के आधार पर दावा किये जाने को हो। जब एक डिकरीदार ने जायदाद कुर्क करवा ली और दूसरे डिकरीदारों ने बिना कुर्की के हिस्से-रसदी बटवारा के लिये दरखवास्त दी और मदियून डिकरी ने जायदाद मुन्तकिल कर दी और डिकरी की बेचाकी कर दी, तब हुआ कि दूसरे डिकरीदार मुन्तकिली के ऊपर कोई एतराज नहीं कर सकते (देखो 6 I. C. 846)।

फरीकैन की ओर से कुर्की की निस्वत उज्रदारी—वे तमाम सवालात जो उस मुकद्दमें के जिसमें वह डिकरी दी गई थी फरीकैन या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा हों और जो उस डिकरी की इजरा, बेचाकी या अदायगी से सम्बन्ध रखते हैं ज़ाबता दीवानी की दफा ४७ के अन्दर आते हैं। इसके सम्बन्धमें बहुत नज़ीरें हैं वकील साहबान को चाहिये कि वे दफा ४७ के अनुसार उज्रदारी दाखिल करने के पहिले ज़ाबता दीवानी का पूर्ण संस्करण ध्यान पूर्वक पढ़ जाय; दफा ४७ के अनुसार दिया हुआ हुक्म डिकरी का जैसा असर रखता है और इस लिये वह क़ाबिल अपील है। उसकी मुश्तहरी या उसके करने में की गई बेकायदगी या जालसाज़ी की बिना पर नीलाम मंखुल किये जाने के लिये दी गई दरखवास्त अब आर्डर २१ रूल ९० में आती है। दूसरी तरहकी जालसाज़ी दफा ४७ में आती है।

जायदाद मकरूका की निस्वत दावा—जब किसी डिकरी की इजरा में कीजाने वाली किसी जायदाद की कुर्की की निस्वत कोई उज्रदारी की गई हो या जायदाद मकरूका की निस्वत कोई दावा किया गया हो तो आर्डर २१ रूल ५८ के अनुसार अदालत इस मामले को जांच करेगी। दावा मुकद्दमें के फरीकैन या उनके प्रतिनिधि अथवा कोई बाहरी आदमी कर सकते हैं। जो दावा कोई बाहरी करेगा वह आर्डर २१ रूल ५८ के अन्दर आता है। फरीकैन या उनके प्रतिनिधियों की ओर से इजरा के खिलाफ़ की गई उज्रदारियां दफा ४७ के अन्दर आती हैं। जब अदालत को इस बात का इतमीनान हो जायगा कि जायदाद मदियून-डिकरी या उसकी ओर से किसी दूसरे शख्स के कब्जे में थी तो वह उस दावा को नामज़ूर कर देगी (देखो आर्डर २१ रूल ६१) —अगर दावेदार नाकामयाब हो जाता है तो वह आर्डर २१ रूल ६३ के अनुसार एक साल के अन्दर (देखो कानून मियाद का अर्दि० ११) अपनी हकीयत कायम करने के लिये बाकायदा नालिश दायर कर सकता है और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वह हुक्म जिससे दावा खारिज कर दिया गया है क़तई हो जायगा।

यह तय किया गया था कि दफा ६१ के अनुसार दिये जाने वाले हुक्म का तात्पर्य तहकीकात के बाद किये हुये हुक्म से है और अगर अदम पैरवीमें कोई दावा खारिज कर दिया जाय तो एक साल की मियाद लाज़ू नहीं होती (देखो 12 C. 108; 4 B. 21; 31 M. 5; 34 C. 491; 18 C. W. N. 770)। लेकिन बाद में यह तय पाया है कि रूल ६३ पहिले ज़ाबता दीवानी की दफा २८३ की अपेक्षा अधिक विस्तृत है और उसमें वे मुकद्दमें भी आजाते हैं जिन में कोई तहकीकात

नहीं की गई है (देखो 27 I. C. 944; 31 M. L. J. 241; 45 A. 438; 41 M. 985; 45 C. 785).—यह भी तय किया गया है कि आर्डर २१ रूल ५८ की शर्त के अनुसार दिया हुआ हुक्म रूल ६३ और कानून मियाद के आर्टि० ११ (१) में आता है (देखो 41 M. 895; F. B.).

जब किसी शख्स की दरख्वास्त सिर्फ यह हो कि बिना तहकीकात किये उसकी उज्रदारी दर्ज कागजात कर ली जाय और अदालत उसे स्वीकार कर ले तो वह हुक्म दफा ६३ के अनुसार नहीं है (देखो 52 I. C. 938).

कुछ जमीन तारीख ४-११-१९१० ई० को कुर्क कर ली गई । मदीयन डिकरीकी स्त्रीने उसकी निस्वत एक दावादायर किया जो खारिज होगया । और इसी तरह इसके थोड़े दिन बाद इजराकी कार्रवाई भी खारिज होगई । इसके बाद दूसरी इजरा में जायदाद फिर कुर्क कीगई जिसे डिकरीदारने खरीद लिया और उस पर अगरत सन् १९१८ ई० में अपना कब्जा कर लिया । दावेदार नेतारीख २३-११-१८ ई० को नालिश दायर की । तय हुआ कि ऐसी दशामें कानून मियाद का आर्टि० ११ लागू नहीं होता (देखो 51 C. 584).

रूल ६३ उन दावोंके ऊपर दिष्ट हुए हुक्मोंके सम्बन्धमें लागू होता है जो फ़ैसलेके पहले कुर्क की हुई जायदादकी बाबत दायर किए गए हों (देखो 41 M. 849; 41 M. 23 Overruled).

उस जायदादके ऊपर दावा नहीं किया जासकता जिसके लिए किसी रेहन नामाकी डिकरीके अनुसार नीलामका हुक्म हो गया हो (देखो 18 B. 98; 26 C. W. N. 50 5 I. C. 895; 50 I. C. 448), और न लगान (किराया) सम्बन्धी नीलाम के ऊपर ही दावा किया जा सकता है (देखो बंगाल दिनोंसे ऐक्टकी दफा १७०)—नीलाम से किसी मुर्तहिन के हकूक पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वह दरख्वास्त दे सकता है कि नीलामके वक्त उसके रेहननामाके सम्बन्धमें नोटिस निकाल दिया जाय [देखो आर्डर २१ रूल ६६ (सी)]—जो दरख्वास्त कोई मुर्तहिन किसी ऐसी जायदादके निस्वत दे जो नीलामके लिए कुर्क कर लीगई है जिसमें उसके रेहननामाकी घोषणा करदी जायगी वह आर्डर २१ रूल ५८ के अनुसार दी हुई दरख्वास्त समझी जायगी और अगर जांच (तहकीकात) के बाद या और किसी समय वह खारिज कर दीजाय तो एक सालके बाद फिर वह उस रेहननामाके अनुसार नालिश दायर न कर सकेगा (देखो 52 I. C. 720.).

नीलाम आम—(१) जायदाद कुर्क हो जानेके बाद, डिकरीकी इजरा करने वाली अदालतको अधिकार होगा कि वह उस जायदादके नीलाम किए जाने और नीलामसे वसूल हुई रकम उस शख्सको दे दिये जानेका हुक्म दे दे, जो उस डिकरीके अनुसार उसके पानेका हकदार है (देखो आर्डर २१ रूल ६४)

२ हर एक ऐसी नीलाम आम नीलाममें की जायगी और उसे अदालतका कोई अफसर या कोई दूसरा ऐसा शख्स करेगा जिसे अदालत इस कामके लिये नियत करे (देखो आर्डर २१, रूल ६५)

३ कुल मनकूला और गैर-मनकूला जायदादोंकी निस्वत सबसे पहली बात जो करनी है वह यह होगी कि उस होने वाली नीलाम की निस्वत इश्तहारका जारी करना जिसमें १—नीलामका वक्त और मुकाम २—नीलाम होने वाली जायदाद ३—उस जायदाद पर बांधी गई मालगुजारी (अगर कोई हो), ४—वह बार जो उस जायदाद पर है (अगर कोई हो तो), तथा ५—दूसरी ऐसी बातें लिखी होंगी जिन्हें अदालत खरीदारके लिये उस जायदादकी किस्म और मालियत जाननेकी निस्वत जानकारीके वास्ते जरूरी समझे। यह इश्तहार डिकरीदाग और मदियून डिकरी को नोटिस दे दिये जाने के बाद जारी किया जाना चाहिये ।

४ नीलामके हुक्म के लिये दीगई हर एक दरख्वास्तके साथ एक नक्शा पेश किया जाना चाहिये जिस पर तस्दीक और दस्तखत उसी तरह पर किये जाने चाहिये जिस तरह पर प्लीडिंग्सके ऊपर दस्तखत और उसकी तस्दीक करनेके लिये बतलाया गया है (देखो आर्डर २१ रूल ६६)

एक्ट नं० ५ सन् १९०८ ई० के अनुसार नीलामका इश्तहार उस समय तैयार किया जाना चाहिये जब मदियून-डिकरी और डिकरीदार को इसकी इत्तला (नोटिस) दे दीगई हो और उसमें वे सब बातें लिखी जानी चाहिये जिनका वर्णन रूल ६६ में किया गया है। इश्तहारमें, नीलाम होने वाली जायदाद की कीमत साफ़ साफ़ और सही तौर पर लिखी जानी चाहिये (देखो आर्डर २१ रूल १७ की शर्त) अन्यथा सिर्फ़ इसी बिना पर नीलाम मंसूख किया जा सकता है, (देखो 20 A. 412 P. C.; 2 C. W. N. 550; P. C. 23 M. 628 & 568; 6 C. W. N. 836; 8 C. W. N. 27; तथा 16 C. W. N. 704; P. 709 और 14 C. L. J. 541.)

जायदाद मनकूलाके सम्बन्धमें उस समय नीलाम का इश्तहार निकालने की जरूरत नहीं है जब जायदादकी कीमत २०) रु० से अधिक न हो ।

५ नीलामका इश्तहार तैयार हो जाने और तस्दीक शुद्ध नक्शा दाखिल कर दिये जानेके बाद वह इश्तहार आर्डर २१ रूल ५४ (२) में बतलाये अनुसार प्रकाशित कर दिया जायगा, [देखो आर्डर २१ रूल ६७].

अगर अदालत ऐसी इजाजत दे; तो वह इश्तहार स्थानीय सरकारी गज़ट अथवा किसी दूसरे स्थानीय समाचार पत्र (अखबार) में या दोनोंमें प्रकाशित कर दिया जायगा (देखो आर्डर २१ रूल ६७)—अदालत इस बातको तय करेगी कि ये बातें किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जायं अथवा नहीं; लेकिन अगर अदालत, समाचार पत्र में इन बातों के प्रकाशित करने की बातको तय कर दे तो, ज़िला जजको अधिकार होगा कि वह इस कामके लिये किसी खास अखबारको छांट ले (देखो G.R.&C. O. Chp. I. Rule 100C).

जब नीलाम की जाने वाली जायदाद कई एक टुकड़ोंमें बांट दीगई हो, तो यह जरूरी न होगा कि हर एक टुकड़े के लिये अलग अलग इश्तहार निकाला

जाय देखो आर्डर २१ रूल ६७ (३)—रूल ६७ का सब-रूल इस बातके लिये बनाया गया है कि 12 B. 368; और 12 C. W. N. 757; 11 C. 714 में दिये हुये विरोधी फैसलोंका समाधान हो जाय । 12 C. W. N. 757. में इस विषयसे सम्बन्ध रखने वाले कुल मुकद्दमोंका उल्लेख कर दिया गया है और उन पर बहस भी कर ली गई है ।

६ बिना मद्दियून-डिकरीकी लिखित स्वीकृति (मंजूरी) के कोई भी जायदाद, उस तारीखसे, जिस तारीखको नीलाम इशतहार अदालतकी इमारत पर चरपां कर दिया गयाहै, कमसे कम ३० दिन पहिले और अगर वह जायदाद न-कूला है तो कमसे कम १५ दिन पहले नीलाम न की जा सकेगी (देखो आर्डर २१ रूल ६८) .

७ काफी वजूहात होने पर अदालत को अख्तियार होगा कि वह किसी खास दिन या घण्टेके लिये किसी नीलामको मुलतवी कर दे; लेकिन अगर वह ७ (सात) दिनसे अधिक मुद्दतके लिये मुलतवीकी जाय तो एक नया इशतहार जारी किया जाना चाहिये सिवाय उस दशाके जब मद्दियून-डिकरी इस हकको छोड़ देनेके लिये तैयार हो । अगर नीलाम की बोली खतम होनेके पहले डिकरी की रकम और खर्चा अदा कर दिये जायें तो हर एक नीलाम बन्द हो जाये (देखो आर्डर २१ रूल ६९)

यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि रूल ६९ जायदाद सरहूना तथा दूसरी किस्मकी सभी जायदादोंके नीलामके सम्बन्धमें लागू होता है (देखो 31 C. 863; 8 C. W.N. 648) .

अगर रुपयेकी अदायगीके लिये वक्त दिया गया है और इस दरखास्त पर नीलाम मुलतवी कर दिया गया है कि उस नीलाम से सम्बन्ध रखने वाले शख्सको कोई पतराज नहीं है अगर नीलाम दूसरे दिन किया जाय तो ऐसी दरखास्त “सभी मद्दियून-डिकरी की ओर से होनी चाहिये नहीं तो नीलामका नया इशतहार जारी करनेकी ज़रूरत न होगी ।

८ जो खरीदार कीमत खरीद का रुपया अदा न कर सकेगा, वह मुकदमके लिये जवाबदेह होगा जो उसके दुबारा नीलामसे हो और अदालतको दरखास्त देकर कभी रुपया वसूल किया जा सकेगा (देखो आर्डर २१ रूल ७१)

९ बिना अदालतकी आज्ञाके किसी डिकरीदारको जायदादके खरीदने या उसके लिये बोली बोलनेका हक नहीं है लेकिन अगर वह बिना अदालतकी इनाज़त लिये हुये जायदाद खरीद लेगा तो मद्दियून डिकरी या किसी दूसरे शख्सके जिसको इस नीलामसे क्षति पहुँची हो, दरखास्त देने पर अदालत नीलामको मंसूख कर सकती है और दुबारा नीलाममें होने वाला खर्चा और घाटा डिकरीदारको देना पड़ेगा । जब डिकरीदार ही खरीदार हो तो खरीदका रुपया डिकरीमें मेजर्रा दिया जायगा या अगर खरीद का रुपया डिकरीके रुपये से ज्यादा है तो खरीदके रुपयेमें डिकरीका रुपया दे दिया जायगा (देखो आर्डर २१ रूल ७२)

इजाजत देते समय अदालत जो शर्त चाहे लगा सकती है अर्थात् यह कि डिकरीदार को सब से कम बोली डिकरी की रकम होनी चाहिये (देखो 15 C. W. N. 488; 5 C. W. N. 264) या यह कि इतनी रकम जो उस जायदाद की निम्नतम दूसरे शख्स की बाकी है अदालत में जमा कर दी जाय (देखो 1 Pat. 235)

बम्बईमें रूल ७२ (ए) और जोड़ दिया गया है जिसके अनुसार अदालत को मुतद्दिनको बोली बोलनेकी इजाजत देते समय एक खास रकम मुकर्रर कर देनी चाहिए ।

अगर डिकरीदार की ओरसे नीलाममें बोली बोलनेकी इजाजत मांगनेकी दरखवास्त खारिज कर दी जाय और उस हालतमें वह बिना इजाजत जायदाद खरीद कर ले तो वह खरीद नाजायज़ न होगी; लेकिन अगर मदियून-डिकरी या किसी दूसरे शख्सकी ओरसे, जिसका उस डिकरीसे कोई सम्बन्ध है, इसके लिए दरखवास्त दी जाय, तो वह खरीद नाजायज़ ठहराई जा सकती है (देखो 67 I. C. 914; P. C.)—जो मदियून-डिकरी दफा ७२ के अनुसार नीलाम मसूख करनेके लिए दरखवास्त देता हो, वह इस बातके लिये बाध्य नहीं है कि नुकसान को साबित करे (देखो 62 I. C. 854)—जो खरीद अदालतकी बिना इजाजत के कर ली गई है उसके खारिज करने के लिए की जाने वाली नालिश ज़ाबता दीवानीकी दफा ४७ के अनुसार दायर की जा सकेगी (देखो 22 B. 271; 5 M. 217; 11 B. 588; 16 M. 287, 21 C. 279 और 23 A. 478).

१० किसी भी ऐसे अफसर या दूसरे शख्स को, जो नीलामके सम्बन्धमें कोई काम कर रहा है, नीलाममें जायदादके खरीदने या उसके लिए बोली बोलनेकी इजाजत नहीं है, (देखो आर्डर २१, रूल ७३)

फरीकैनके वकीलोंको किसी डिकरीकी इजरामें नीलाम होने वाली जायदादके खरीदनेकी मुमानियत नहीं है (देखो 10 M. 111.) लेकिन जब वकील ने अनुचित कार्रवाई की तो नीलाम मसूख कर दिया गया, (देखो 15 M. 389; 23 C. 805.)—लेकिन वकील लोग उन डिकरियोंकी इजरामें होने वाली नीलाम में कोई चीज़ नहीं खरीद सकते जिनमें उनका कोई स्वार्थ हो, (देखो 13 W. R. 209).

कलकत्ता हाईकोर्टके बनाए हुए रूल

जायदादकी नीलामके सम्बन्धमें (देखो ज़ाबता दीवानीकी दफा ६५ से ६७ तक और आर्डर २१ के रूल ६६ से ७२ तक) कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा तैयार किए हुए नियम (रूल) (देखो Rule. 99 to. 116. of. G. R. & C. O. Ch. I.) इस प्रकार है:—नीचे 'क' से मतलब कलकत्ता हाईकोर्ट है ।

क० रूल ९९—अगर आर्डर २१ रूल ६६ के अनुसार नीलामका इश्तहार करने के बाद, नीलाम होने वाली जायदादके सम्बन्धकी कोई लिखा-पढ़ी अदालतको मिल जाय, जिसे वह खरीदारके ज.ननेके लिए ज़रूरी समझती हो, जिस समय जायदाद नीलामके लिए रखी जायगी उस समय अदालत उस लिखा-पढ़ीको पढ़कर सुनावेगी ।

क० रूल १००—(अ) अगर नीलाम होने वाली जायदाद कोई ऐसा इलाका या इलाक़ेका हिस्सा है जो सरकार (गवर्नमेण्ट) को मालगुजारी अदा कराये और ऐसे इलाके या इलाक़ेके हिस्से की जायदाद जाने वाली मालगुजारी ५०० से ज्यादा है, तो नीलामका इश्तहार स्थानीय सरकारी गज़टमें प्रकाशित किया जायगा ।

(ब) इस रूलसे अदालतके उन अधिकारों को कोई बाधा न पड़ेगी जो आर्डर २१ रूल ६७ (२) के अनुसार, जब कभी वह उचित समझे, किसी इजरा में कुर्ककी हुई किसी दूसरी जायदाद या किसी जायदादों की होने वाली नीलामके, इसी तरह प्रकाशित करने के सम्बन्ध में प्राप्त हैं ।

(स) हर एक ज़िलेमें ज़िला-जज उस स्थानीय समाचार-पत्र या समाचार-पत्रोंको तय करेगा जिसमें या जिनमें, उस कुल ज़िले या उस कुल ज़िले के भिन्न भिन्न भागोंके लिए, जायदाद दीवानीके आर्डर २१, रूल ६७ के अनुसार नीलामके इश्तहार प्रकाशित किए जाने चाहिए, और जनता तथा मातहत अदालतोंके कुल जजोंको इस तरह चुने हुए समाचार-पत्र या पत्रोंके नामसे सूचित कर देगा । इसके बाद जब कभी हर एक मातहत अदालतका जज अपने अधिकारोंका प्रयोग करके किसी स्थानीय समाचार-पत्रमें किसी नीलामके इश्तहार प्रकाशित किए जानेका हुक्म दे देगा, तो वह यह हिदायत कर देगा कि जिस समाचार-पत्रको ज़िला-जजने चुना है उसीमें उस ज़िले, या ज़िलेके उस हिस्सेके लिए नीलामका इश्तहार प्रकाशित किया जाय जिसमें वह अदालत बाँटी है ।

क० रूल १०१—(१) आर्डर २१ रूल ४३ की शर्तोंकी पाबन्दीमें रहते हुए किसी इजरा में होने वाली जायदादकी नीलाम हर एक ज़िलेकी हर जज अदालतोंमें (जो कि ख़फ़ीफ़ा की अदालतें नहीं हैं) हर महीनेकी किसी तारीख़को की जायगी ।

(२) अ—सदरकी अदालतोंके लिये ऐसे दिनको ज़िला-जज नियत करेगा—

ब—बर्दवान, मिदना पुर, हुगली, चौबीसपरगना, जैसोर, मैमनसिंह, फ़रीदपुर, बाकरगञ्ज, टिपरा, चटगाङ्ग और सिलहटके ज़िलोंमें जायदाद ज़िला-जजके अधिकारमें होगी कि वह सदरकी अदालतोंको कई श्रेणियोंमें विभाजित करदे और हर एक श्रेणीके लिए लगातार तारीख़ें नीलामके लिए नियत कर दे ।

३ बाहरकी अदालतोंके सम्बन्धमें नीलाम शुरू होनेका दिन ज़िला-जज अदालतोंके जजों या उनमें से किसी के साथ, जैसा कुछ वह उचित समझे परामर्श करके नियत करेगा ।

क०रूल १०२—कुल जायदाद, सिवाय उस जायदादके जिसका वर्णन जायदादीघानीके आर्डर २१ रूल ४३ की शर्त या नीचिके रूल १०६ में किया गया है जो नीलामके हर स्थान पर नीलाम किए जाने को है, हर एक स्थानकी फेहरिस्तमें चढ़ा ली जायगी और जायदाद मनकूला तथा जायदाद गैर-मनकूलाकी फेहरिस्तें अलग अलग होंगी। ये फेहरिस्तें इस तरह पर तैयार की जायंगी कि उनमें हर एक अदालतकी डिकरियोंकी इजरामें अलग अलग नीलाम होने वाली जायदादकी हर एक मद्द एक ठीक क्रमसे लिखी होनी चाहिये। ऐसी फेहरिस्तें उन अदालतोंमें, जिनमें नीलाम होनेको है, हर एक नीलामके शुरू होनेकी तारीख से कमसे कम ७ दिन पहले, अगर नीलाम होने वाली जायदाद गैर मनकूला है तो। और अगर ऐसी जायदाद मनकूला है तो कमसे कम १५ दिन पहले चिपका दी जानी चाहिये।

क०रूल १०३—प्रत्येक नियत तारीखको फेहरिस्तमें बतलाये हुये समय पर नीलाम शुरू होगा और यह नीलाम उसी क्रमसे किया जायगा जो क्रम उपरोक्त फेहरिस्तोंमें बतलाया गया हो। सूर्यास्तके बाद कोई भी नीलाम जारी न रह सकेगा; लेकिन नीलाम हर रोज जारी रहेगा सिवाय उस दशामें कि जब कचहरी बन्द हो या जब तक कि कुल फेहरिस्तें खतम न हो जायं। लेकिन शर्त यह है कि इस रूलसे किसी खास नीलामके कानूनके अनुसार मुन्तकिल किये जाने के सम्बन्धमें कोई बाधा न पड़ेगी (देखो आर्डर २१ रूल ६९)।

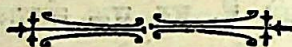
क०रूल १०४—साधारणतया जायदाद मनकूला और गैर-मनकूलाके नीलाम के लिये एक ही तारीखें मुकर्रर न की जायंगी।

क०रूल १०५—सिवाय उस किस्मकी जायदादके, जिसका वर्णन आगे वाले रूलमें किया गया है, सदरकी कुल अदालतोंकी डिकरियोंकी इजरामें होने वाला नीलाम जिला जजकी अदालतमें या किसी दूसरे चीफ जुडिशल अफसरकी अदालतमें किया जायगा। अगर दूसरे स्थानोंमें दो अथवा अधिक मातहत अदालतें हों, तो उस स्थानमें होने वाले नीलाम ऐसी किसी भी एक अदालतमें किये जायंगे जिसे जिला-जज साहब निश्चित करें। जब सिर्फ एक ही अदालत हो तो नीलाम उसी अदालतमें किये जायंगे। लेकिन शर्त यह है कि किसी डिकरीकी इजरा करने वाली अदालत, अगर बह उचित समझे तो, किन्हीं कारणोंसे, जो लिखकर बतलाए जायंगे, फरीकनके फायदेके खयालसे, यह हुक्म दे सकती है कि नीलाम किसी भी दूसरे समय और स्थान पर हो, जो उसके अधिकार-क्षेत्रमें है और इस अन्तिम शर्तके अनुसार फाईवाई करते समय, समय और स्थानका चुनाव करनेके सम्बन्धमें, मद्रियून-डिकरीकी इच्छाओं के अनुसार फाय करेगी सिवाय उस हालतके जब इसके विपरीत कार्य करनेके लिये माकूल वजह हो।

क०रूल १०६—जानवरों, खेतीकी पैदावार, उस स्थानमें बनी हुई चीजों तथा दूसरी चीजोंका जो आम तौर पर देहातके बाजारोंमें बिका करती हैं, नीलाम जब तक अदालत इसके विपरीत हुक्म न दे, उस स्थानके, जहां पर कि माल

कुर्क किया गया है, पड़ोसकी ऐसी बाजारोंमें किया जायगा जिनमें मन्दिर
डिकरी का अधिकसे अधिक लाभ होनेकी सम्भावना हो, और इस बातका ध्यान
रखा जायगा कि दाम अच्छा आवे और मालके लाने जानेके खर्चमें कम
हो जाय।

इलाहाबाद हाईकोर्टके बनाए हुए रूल



जायदादीवाणी की दफा १२२ के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दफा
२१ के साथ १०४ से १३० तक के रूल (नियम) जोड़ दिये हैं।

जायदाद मनकूलाका नीलाम—उगी हुई फसल और खेतीकी पैदावारके नीलाम
के तरीकेके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१, रूल ७४ से ७५। उगी हुई फसलके
खास व्यवस्थाके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ७५।

उस सालके जो मदियून डिकरी और दूसरे आदमियोंकी मुश्तरीका मिल
यत है, हिस्सेके नीलामके तरीकेके सम्बन्धमें देखो आर्डर २१, रूल ७७।

जायदाद मनकूला का नीलाम करने या उसके नीलाम की मुश्तरीका
में हुई बेकायदगीसे नीलाम नाजायज़ नहीं हो जाता; लेकिन जिस शर्त
इससे नुकसान हुआ हो वह नुकसानकी बाबत नालिश कर सकता है (देखो
आर्डर २१, रूल ७८)।

जायदाद मनकूला कर्जों और हिस्सोंकी, जो खरीदार-नीलामके हाथ में
दिए गए हैं, वापसीके तरीके के सम्बन्धमें देखो आर्डर २१ रूल ७९-८१।

“उगी हुई फसल (Growing Crop.)” की परिभाषा के लिये देखो
जायदादीवाणी की दफा २ (१३)

हथियारोंका नीलाम—जब कभी बन्दूकें या दूसरे हथियार, जिनके लिये
इण्डियन आर्म्स ऐक्ट नं० ११ सन् १८७८ ई० के अनुसार खरीदारों को लें
लेना पड़ता है, डिकरियोंकी इजरामें नीलाममें बेंचे जायं, तो नीलामका हुक्म
वाली अदालत उस जिलेके मजिस्ट्रेटको खरीदारोंके नाम और पताकी तथा खरी
दारोंको ऐसे हथियारोंकी, कीजाने वाली सिपुर्दगीके समय और स्थानकी सूचना
दे देगी, ताकि इण्डियन आर्म्स ऐक्ट के अनुसार की जाने वाली कार्रवाईके सम्बन्ध
में पुलिस सुनाखिब कार्रवाई कर सके (देखो G. R. & C. O. Chap
R. 107.)

जायदाद गैर-मनकूला का नीलाम—खफ़ीफ़ा की अदालतों को छोड़कर
सब अदालतें जायदाद गैर-मनकूला के नीलाम का हुक्म दे सकती हैं (देखो
आर्डर २१, रूल ८२)।

अदालत को अधिकार है कि वह जायदाद गैर-मनकूला के नीलाम
मुश्तरी कर दे, जिससे मदियून-डिकरी खानगी फ़रोख़्त, रेंदन या पट्टा के लिये

डिकरी के रुपये को अदा कर सके। लेकिन शर्त यह है कि वह कुल रुपया, जो ऐसी मुन्तकिली की निश्चित वाजिबुल अदा है, अदालत में अदा कर दिया जायगा, सिवाय उस हालत में जब कि रूल ७२ के अनुसार डिकरीदार रकम मोजरा पाने का हकदार हो। यह रूल उस जायदाद के सम्बन्ध में लागू नहीं है जिसकी नीलाम का हुक्म किसी रेहननामा की डिकरी की इजरा के सम्बन्धमें दिया गया है (देखो आर्डर २१, रूल ८३)

जायदाद गैर-मनकूला के हर एक नीलाम पर खरीदार को कीमत खरीद का चौथाई हिस्सा फौरन् जमा कर देना होगा (देखो आर्डर २१, रूल ८४) ५०) रुपये से कम के खरीदार को कुल रुपया उसी वक्त दे देना चाहिये और नीलाम करने वाले अफसर से रसीद ले लेना चाहिये और ऐसा न करने पर वह जायदाद फौरन् फिर नीलाम कर दी जायगी। बाकी कीमत खरीद नीलाम की तारीख से पन्द्रहवें दिन अदालत बन्द होने के पहिले अदाकर दी जायगी (देखो आर्डर २१, रूल ८५) और इस कीमत के अदा न कर सकने में, वह जमा हुआ रुपया, अगर अदालत ऐसी हिदायत करे, गवर्नमेंट जब्त कर लेगी और वह जायदाद फिर नीलाम कर दी जायगी (देखो आर्डर २१, रूल ८६)— जो खरीदार रुपया न अदा कर सकेगा, वह जायदाद के दुबारा नीलाम किए जाने पर नुकसान का जवाब-देह होगा (देखो आर्डर २१, रूल ७१)।

दुबारा नीलाम, नया इश्तहार जारी करने के बाद की जायगी (देखो आर्डर २१, रूल ८७)।

नोटिस—दफा ८५ और ८६ ताकीदी हैं। खरीदार डिकरीदार इस बात के लिए बाध्य है कि वह डिकरीका रुपया काट कर बाकी रुपया अदालत में दाखिल कर दे। रुपया न अदा कर सकने पर जायदाद दुबारा नीलाम कर दी जायगी (देखो 51 I.C. 316; 25 M. 535)—जो खरीदार रुपया अदा न कर सकेगा वह दुबारा होने वाले नीलाम से होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी (जवाब-देह) होगा (देखो 5 B. 575; 7 C. 387; 12 M. 474)— रूल ७१ जायदाद मनकूला या गैर-मनकूला के नीलाम और दफा ७१, ८४ और ८६ के अनुसार उनके दुबारा नीलाम किए जाने के सम्बन्ध में लागू होगा (देखो 7 C. 387; 5 B. 575)। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि रूल ८५ के अनुसार रुपया अदालत को पन्द्रहवें दिन अदालत के बन्द होने के पहिले पहुंच जाय। सरकारी खजाने में रुपया का जमा कर देना अदालत में जमा करने के बराबर है (देखो 7 M. 211) लेकिन समय के भीतर डाकखाने में रुपये का जमा करना ऐसा नहीं है (देखो 22 B. 415)। जब रुपया की अदायगी के दिन अदालत बन्द हो जाय, तो दूसरे दिन जब अदालत खुले रुपये का अदा कर देना अच्छा होगा (देखो 21 M. 385; 18 C. 231; 18 C. 631; 10 C. W. N. 535 और 20. B. 745)।

नया इश्तहार जारी करने की ज़रूरत सिर्फ उस समय है जब कि जायदादकी दुबारा नीलाम रूल ८५ में बतलाए हुए समयके भीतर कुल कीमत खरीद

अदा न की जा सके। दफा ८४ के अनुसार अदा की जाने वाली चौथाई क्रीम खरीद के अदा न होने पर दुबारा नीलाम किए जाने के लिए नए इश्तहार नीलाम की जरूरत न होगी, क्योंकि ऐसी दशा में जायदाद फौरन नीलाम कर दी जायगी (देखो 12 M. 454)।

ताल्लुकों (रियासतों) का नीलाम—(क) दीवानी अदालतों को, जिनमें किसी ताल्लुका या ताल्लुका के किसी हिस्से के नीलाम की सूचना कलक्टर को दी हो, चाहिए कि उसकी मंजूरी मिल जाने के बाद, हर महीने के पहिले हफ्ते में बराबर उस इलाके के उस हिस्से की नीलाम का ब्योरा कलक्टर के पास भेज दिया करे, जिनकी मंजूरी पहिले महीने में मिल चुकी है। अगर नीलाम की मंजूरी नहीं मिली है तो सादा नकशा ही भेज देना चाहिए।

(ख) यह नकशा फार्म नं० (M) 104 Vol. II G. R. & C. O. में तैयार करके कलक्टर के सामने पेश किया जाना चाहिए (देखो R. 108 G. R. & C. O.).

बिना बंटी हुई जायदाद गैर-मनकूला के किसी हिस्सेदार की बोली के किसी दूसरे शख्स की बोली पर तर्जीह दी जायगी, जब कि बोली की रकम बराबर ही हो (देखो आर्डर २१, रूल ८८)। यह रूल आर्डर २१, रूल ७७ (१) से समान है जो जायदाद गैर-मनकूला के सम्बन्ध में लागू होता है।

जायदाद मरहूना की नीलाम के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तैयार किए गए नियम (rules.) :—

(१) अगर अदालत कोई ऐसा हुक्म दे कि जायदाद या उसका हिस्सा नीलाम किया जायगा, तो वह नीलाम का एक इश्तहार जारी करेगा उस तरीके से, जैसा कि जायदाद गैर-मनकूला के सम्बन्ध में इश्तहार की तारीख के लिए बतलाया गया है, उसे तामील करावेगा।

(२) आर्डर ३४, रूल ५ (२) के अनुसार दीजाने वाली दरखास्त पर तर्दीक शुब्द: अर्जी के जरिए दी जायगी जिसमें कुल बातें दर्ज होंगी।

(३) ज़ाबता दीवानी के आर्डर २१ के ६५ से ६९ तक के और ७१ से ७५ तक के रूल, जिनमें ये दोनों रूल शामिल हैं, ऐसे नीलामों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(४) दफा ६५, ६६ और ७४ तथा ज़ाबता दीवानी के आर्डर २१ के ८२ से ८८ तक और ९० से १०३ तक जिनमें ये दोनों रूल शामिल हैं किसी भी नामा के अनुसार होने वाले नीलाम के बाद होने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(५) ज़ाबता दीवानी के आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दी गई डिक्लरेशन में, दी जाने वाली कार्रवाई वही होनी चाहिये जो उस ज़ाबते में बतलाई गई है।

नोट—उपरोक्त रूल पहिले कानून इन्तकाल जायदाद सन् १८८२ ई० (एक्ट नं० ४ सन् १८८२ ई०) के दफा १०४ के अनुसार तैयार किए गए थे । सम्भवतः अब उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं रही है क्योंकि उस कानून की दफा ८९ और ९० जाबता दीवानी में शामिल कर दी गई हैं, लेकिन उनमें ऐसी काट छांट करने के बाद वे प्रकाशित की गई हैं जिस काट छांट की आवश्यकता थी [देखो G. R. & C. O. Chap I. R. 109].

जायदाद मनकूला के नीलाम का मंसूख करना—किसी भी हालत में जायदाद मनकूला का नीलाम इस बिना पर मंसूख नहीं किया जा सकता कि उसके इशतहार देने या करने में कोई बेकायदगी की गई है । जिस शख्स को इस बेकायदगी से कोई नुकसान पहुंचा हो उसके लिये सिर्फ यही चारा है कि वह उस शख्स के ऊपर मुआविजे का दावा करे जो इस बेकायदगी के लिये उत्तरदायी है लेकिन अगर ऐसा शख्स खुद खरीदार ही हो, तो जिस शख्स को नुकसान पहुंचा है वह उस जायदाद के वापस पाने के लिये और जायदाद के वापस न किए जाने की दशा में मुआविजे के लिये दावा कर सकता है (देखो आर्डर २१ रूल ७८).

जाबता दीवानी में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि किसी भी हालत में जायदाद मनकूला का नीलाम मंसूख न किया जा सकेगा लेकिन रूल ७८ में ही सिर्फ यह व्यवस्था की गई है कि नीलाम में बेकायदगी हो जाने से वह नीलाम नाजायज़ नहीं होजाता, देखो 2 B. 258 P 266 तथा 6 C. W. N. 5.

जायदाद गैर-मनकूला के नीलाम का मंसूख किया जाना—

(१) (अ) कोई भी शख्स जो उस जायदाद का मालिक है या कोई शख्स जिसे किसी ऐसी हकीयत की वजह से जो नीलाम के पहिले हासिल की गई है ऐसी जायदाद में कोई हक हासिल है, नीलाम की तारीख से ३० दिन के भीतर ५) रु० सैकड़ा के मुआविजे के सहित डिकरी का रूपया अदालत में जमा करके नीलाम मंसूख किये जाने के लिये दरखवास्त दे सकता है (देखो आर्डर २१ रूल ८९).

(ब) डिकरीदार या कोई शख्स जो दफा ७३ के अनुसार सम्पत्ति (जायदाद) के हिस्से रसदी बटवारा में हिस्सा पाने का हकदार है या जिसके हकूक को नीलाम से नुकसान पहुंचा है इस बिना पर नीलाम मंसूख किए जाने के लिए दरखवास्त दे सकता है कि नीलाम की सुइतदारी या उसके करने में बहुत बड़ी बेकायदगी या जालसाजी की गई है (देखो आर्डर २१ रूल ९०) ।

(स) खरीदार इस बिना पर भी नीलाम की मंसूखी के लिए दरखवास्त दे सकता है कि मदियून-डिकरी को उस जायदादमें कोई भी ऐसा हक हासिल नहीं था जो नीलाम किया जा सके (देखो आर्डर २१ रूल ९१) ।

(२) रूल ८९, ९० और ९१ के अनुसार कोई नीलाम मंसूख किए जाने के पहिले उन तमाम लोगों को इसकी नोटिस दी जानी चाहिए जिनके ऊपर इससे कोई असर पड़ता हो (देखो आर्डर २१ रूल ९२ की शर्त और 11 C. L. J. 86).

(३) नीलाम मंसूख कर दिए जानेके बाद खरीदार ब्याज सहित या ब्याज के जैसा कुछ अदालत हुक्म दे उस शख्स से जिसको कि वह अदा किया गया है खरीद का रूपया वापस दिला पाने का हकदार है (देखो आर्दर रूल ९२).

रूल ८९ के अनुसार नीलाम का मंसूख किया जाना—रूल ८२ सन् १८६० के जायदादीवाणी में अधिक विस्तृत कर दिया गया है । पहिले “कोई भी शख्स जिसकी जायदाद गैर-मनकूला नीलाम की गई है” दरखवास्त दे सकता था । अब (अ) कोई भी ऐसा शख्स जो जायदाद का मालिक है या [ब] कोई भी ऐसा शख्स जिसे नीलामके पहिले हासिलकी हुई किसी हकीयतकी वजह से जायदादमें कोई हक हासिल हो दरखवास्त दे सकता है । अगर जायदादका मालिक मदियून डिकरीके अलावा और कोई आदमी है तो पुराने ऐक्टके अनुसार वह बिना पर दरखवास्त नहीं दे सकता था कि नीलाम से उसके हक पर कोई असर नहीं पड़ता । अब वह शख्स नीलामकी मंसूखी की दरखवास्त दे सकता है । इस तरह पर नये रूल के अनुसार पहिले कोई खानगी तौर पर खरीद करने वाला शख्स मौदूब अलेह (Donee) मुतहिन, पहिले का खरीदार नीलाम का रिन्दार असामी, सब रैयत, बयनामीदार, वह मालिक, जिसको जायदाद फायदा उठाने का हक हासिल है इत्यादि नीलाम की मंसूखी के लिये दरखवास्त कर सकते हैं । यह तय हुआ है कि जिस शख्स ने कुर्की के बाद और नीलामके पहिले मदियून-डिकरी से जायदाद खरीद कर ली है उसे ऐसी दरखवास्त सकने का हक है (देखो 26 C. L. J. 127; 30 B. 575).

जिस शख्सने मदियून डिकरी से जायदाद नीलाम होनेके बाद (लेकिन उसकी मंजूरी मिलने के पहिले) खरीदी है, वह नीलाम की मंसूखी के लिये दरखवास्त नहीं दे सकता (देखो 49 C. 454; 26 C. W. N. 149). मद्रास हाईकोर्ट में यह तय हुआ है कि जिस शख्स ने नीलाम के बाद लेकिन उसकी मंजूरी मिलने से पहिले मदियून डिकरी से खानगी तौर पर जायदाद खरीद की है वह तो दरखवास्त दे सकता है लेकिन मदियून-डिकरी के अपने हक्क बेंच दिये हैं दरखवास्त नहीं दे सकता (देखो 54 I. C. 733). जिस मदियून डिकरी ने इजरा में अपनी जायदाद के नीलाम होजाने के बाद, जायदाद किसी दूसरे शख्स के हाथ बेंच दी हो वह मंसूखी नीलाम के लिये दरखवास्त दे सकता है (देखो 51 I. C. 873; 25 B. 631; 40 B. 559; 44 M. 554. F. B. Contra. 34 A. 186; 38 M. 775). खानगी करोख के बाद मदियून-डिकरी तो दरखवास्त दे सकता है लेकिन खरीदार ऐसी दरखवास्त नहीं दे सकता (देखो 53 I. C. 344,). नीलामके बाद खरीद करने वाला दूसरा आदमी भी दरखवास्त नहीं दे सकता (देखो A. I. R. 1922 (L. 302. अदालती नीलाम के बाद मदियून-डिकरी ने एक शख्स के हाथ जायदाद बेंच दी और रूल ८९ के अनुसार दरखवास्त दी । दरखवास्त देने की तारीख दस्तावेज बयनामा की रजिस्ट्री नहीं हुई थी । इसके बाद मदियून डिकरी ने हक

बयनामा लिखा और उसकी रजिस्ट्री करा दी। तब हुआ कि मदियून-डिकरी नीलाम की मंजूरी के लिये दरख्वास्त दे सकता है और बाद में लिखे गये दस्तावेज से इसमें कोई ख्फावट नहीं पड़ती (देखो 42. M. 503)। जिस शर्त के हक में जायदाद के बय कर देने का इकफार किया गया हो या जिस शर्त ने कुर्की के बीच में जायदाद खरीद कर ली हो वह ऐसी दरख्वास्त नहीं दे सकता देखो A. I.R. 1923 (Mad) 659—जिस शर्त के हाथ डिकरी की इजरा में होने वाली नीलाम के बाद मदियून-डिकरी ने जायदाद बेच दी हो या रेहन कर दी हो वह शर्त दरख्वास्त नहीं दे सकता (देखो 1 C. W. N. 279) क्योंकि नीलाम के पहिले वह कोई हकीयत हासिल नहीं कर सका था (देखो विपरीत फैसला 30 M. 214 तथा 30 M. 507)—वह मालिक जिसको जायदाद से फायदा उठाने का हक है उस समय दरख्वास्त दे सकता है जब वह नीलाम बेनामीदार के ऊपर दी गई डिकरी के सम्बन्ध में किया गया हो (देखो 1 C. W. N. 135;)—दखीलकार मुर्तहिन दरख्वास्त दे सकता है (देखो 25 O. C. 78; 35 B 288,)—किसी ऐसे कब्जा था जोतका मुर्तहिन दरख्वास्त दे सकता है जो बकाया लगान (किराया) की डिकरी की इजरा में नीलाम किया गया हो (देखो 5 C. W. N. 821 F. B.)—मुर्तहिन ऐसी दरख्वास्त दे सकता है यद्यपि नीलाम रेहन के काबिल भी हो (देखो 53 I. C. 958)—ऐसा मुर्तहिन जिसे मदियून डिकरी ने नीलाम के बाद जायदाद ट्रस्ट में दे दी है दरख्वास्त नहीं दे सकता है (देखो 58 I. C. 856 F. B.)

शिकमी हकदार कब्जा की दरख्वास्त दे सकता है (देखो 23 C. W. N. 597)। पट्टीदार ज़मींदार जिसके पास ऐसी डिकरी है जिसकी मियाद आरिज़ हो गई है उस नीलाम के सम्बन्ध में दरख्वास्त दे सकता है जो दूसरे पट्टीदारों की ओर से की गई हो (देखो 23 C. W. N. 619)।—कुर्क कराने वाला महाजन दरख्वास्त दे सकता है [22 C. W. N 899]—कब्जे में मदालिखत बेजा करने वाला शर्त दरख्वास्त दे सकता है (देखो 79 I. C. 874)

रुपया बिना किसी शर्त के ही जमा किया जाना चाहिए, देखो 16 C. W. N. 904; 72 I. C. 907—जब रुपया जमा किया जाने के बाद यह दरख्वास्त की जाय कि रुपया आर्डर ९, रूल १३ के अनुसार दी गई दरख्वास्त की समा-अत होने तक जमा रखा जाय, तो नीलाम मंख कर दी जानी चाहिए, देखो 8 C. W. N. 355—अदालत में रुपया जमा करने का मतलब अदालत दीवानी में रुपया जमा करने से है, देखो 40 A. 425—जहाँ पर अदा किए जाने वाले रुपये का तख्मीना अदालत के किसी हाकिम ने लगाया हो, तो नीलाम मंख कर दिया जाना चाहिए, यद्यपि बाद में यह बात मालूम भी हो गई हो कि वह रकम थोड़ी सी कम थी, देखो 18 C. 255; 25 C. 609; 11 C. W. N. 116—लेकिन जहाँ पर रुपया कम न हो और अदालत की कोई गलती न हो वहाँ पर रुपये का जमा करना नाजायज़ नहीं है, देखो 26 C. 449 F. B. ; 23 Bom. L. R. 847—जहाँ पर पाउण्डेज-फ़ीस (फ़ीस व हिसाब १ शिलिंग फी पौंड)

की बाबत कुछ रुपया वाजिबुल बसल था, वहां पर नीलाम मंसूख कर दिया गया, देखो 20. M. 158.—कोई मंदिथून-डिकरी उस जमा किए हुए रुपये के फायदा नहीं उठा सकता जो उसके शरीकदार मंदिथून-डिकरी ने उससे जमा किया है, देखो 65 I. C. 983; 39 M. 429.

तलब की हुई रकम के जमा करने के लिए, दीगई दरख्वास्त, किसी नीलाम के मंसूख किए जानेके लिए दीगई दरख्वास्त समझी जाती है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह दरख्वास्त लिखी हुई हो, देखो 63 I. C. 140—दरख्वास्त ज़बानी भी हो सकती है लेकिन, चाहे ज़बानी हो या तहरीरी वह मियाद के अन्दर होनी चाहिए। सिर्फ रुपये का जमा कर देना ही काफी नहीं है, देखो A. L. J. 12.—बिना ३० दिन के अन्दर ज़बानी या तहरीरी दरख्वास्त पेश किए हुए नीलाम मंसूख नहीं किया जा सकता, देखो 32 I. C. 783—यह तय हुआ है कि नीलाम की मंसूखी के लिए बाजाबता दरख्वास्त का दिया जाना ज़रूरी है, सिर्फ फेहरिस्त का दाखिल कर देना ही काफी नहीं है, देखो 63 I. C. 44.—३० दिन के अन्दर रुपया जमा किया जाना चाहिए, उस समय के भीतर दरख्वास्त दिए जाने की ज़रूरत नहीं है, देखो 7 Bom. L. R. 263.

आर्डर २१ रूल ८९ अब रेहननामों की डिकरियों की इजरा में होने वाले नीलाम के सम्बन्ध में लागू होता है (देखो 24 C. W. N. 1032.)

आर्डर २१ रूल ८९ के अनुसार दी जाने वाली दरख्वास्त की नोतिश उन कुल आदमियों को दीजानी चाहिए जिनका उससे सम्बन्ध हो, अर्थात् डिकरीदार, खरीदार नीलाम वगैरा को (देखो आर्डर २१, रूल ९२ की शर्त) रुपया जमा करने की मियाद नीलाम की तारीख से ३० दिन है (देखो कानून मियाद का आर्टि० १६६)—नीलामकी तारीख से मतलब उस तारीख से है जिस तारीखको जायदाद नीलाम में रखी गई हो और सब से ज्यादा बोली बोलने वाले शख्स के नाम खतम करदी गई हो। इसका मतलब मजूरी की तारीख (Date of conjuration) से नहीं है (देखो 29 C. 626).

आर्डर २१ रूल ८९ के शब्द “जो उस जायदाद का मालिक” का अर्थ है वह शख्स जो शख्स दरख्वास्त की तारीख को जायदाद का मालिक हो वह शख्स नहीं जो नीलाम की तारीख को उसका मालिक हो, देखो 54 I. C. 753; 38 M. 775.

रूल ९० के अनुसार नीलामों का मंसूख किया जाना—जालसाज़ी या नीलाम के करने या कराने या मुश्तहरी के सम्बन्ध में की गई बेकायदगी की बिना पर नीलामों की मंसूखी की बात अब आर्डर २१, रूल ९० के अन्दर आती है, जालसाज़ी की दफा ४७ में नहीं।

आर्डर २१ रूल ९० सिर्फ उस जालसाज़ी या बेकायदगी के सम्बन्ध में लागू होता है जो नीलाम के करने या उसकी मुश्तहरी करने में की गई हो। जो नीलाम किसी दूसरे तरह की बेकायदगी या जालसाज़ी, जैसे—इजरा की गई

डिकरी के देते समय सम्मन की तामील न किए जाने (देखो 23 C. 686), अफ़्तयार समाभत के न होने (देखो 18 A. 14; 36 M. 775), इत्यादि, की वजह से नाजायज़ हो गया हो; वह इस रूल के अन्दर नहीं आता। इस बिना पर नीलाम मंसूख कराने के लिए कि डिकरी जाल-फरेव से हासिल की गई थी, नालिश दायर की जा सकती है (देखो 26 C. 326)

नीलाम मंसूखीकी दरख्वास्त कौन शख्स दे सकता है—डिकरीदार या कोई भी शख्स जो दफ़ा ७३ के अनुसार हिस्से-रसदी बटवाराका हकदार है या “कोई शख्स जिसके हक़ को नीलाम से नुक़सान पहुँचा हो” दरख्वास्त दे सकता है। “कोई शख्स जिसकी जायदाद ग़ैर-मनकूला नीलाम कर दी गई हो” के स्थान में, जो सन् १८८२ ई० के ज़ाबता दीवानी में मौजूद था, उपरोक्त इस “ ” निशान के अन्दर लिखे हुए वाक्य के बदल देने से इस रूल का विस्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह परिवर्तन उस अर्थ के अनुसार किया गया है जो पुराने ज़ाबता दीवानी के शब्दों का 15 C. 488 F. B. और 16 M. 476 में किया गया है। इसलिए, जिन शख्सों के हक़ को नीलाम से कोई नुक़सान नहीं पहुँचा है, नीलाम मंसूखी की वे दरख्वास्त नहीं दे सकते। इस तरह पर जो शख्स मदियून डिकरी के खिलाफ़ हकीयत के लिए दावीदार हो या जिसकी हकीयत मदियून डिकरी की हकीयत से बड़ी हो, वह दरख्वास्त मंसूखी नीलाम की नहीं दे सकता, क्योंकि नीलाम से उसके हक़ पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार जिस शख्स ने कुर्की के पहिले मदियून-डिकरी से जायदाद ख़रीद की है, वह रूल ९० के अनुसार मंसूखी नीलाम की दरख्वास्त नहीं दे सकता, क्योंकि उस ख़रीद से हासिल हुए उसके हक़ पर नीलाम से कोई असर नहीं पड़ता (देखो 15 C. 488)—लेकिन वह रूल ८९ के अनुसार ऐसा कर सकता है। 22 C. 802 में यह तय हुआ है कि जिस शख्स ने कुर्की के पहिले कोई भी हकीयत किसी मदियून डिकरी से ख़रीद की हो जिसका उस हकीयत का हिस्सा किसी उस हिस्से के बाक़ीया लगान की डिकरी की इजरा में नीलाम कर दिया गया है, वह शख्स रूल, ९० के अनुसार नीलाम की मंसूखी के लिए दरख्वास्त दे सकता है, (देखो 15 C. 488)—वह शख्स जिसके हक़ में, डिकरी के पहिले किसी दख़ीलकारी जोत के हिस्सा की मुन्त-किली किसी बिना रजिस्ट्री शुदः इन्तकाल नामा के कर दी गई है, वह शख्स इन्दराज शुदः अस्सामी के ऊपर दी गई डिकरी की इजरा में होने वाली नीलाम की मंसूखी के लिए दरख्वास्त दे सकता है (देखो 13 C. W. N. 98)—किसी दख़ीलकारी जोत का मुर्तद्दिन दरख्वास्त दे सकता है (देखो 11 C. W. N. 312)

“जिनके हक़ पर नीलाम से कोई असर पड़ा हो” वाक्य से मतलब मौजूदा हक़ से है। इसका प्रयोग महाजनों के दावों के सम्बन्ध में नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें इजरा की कार्रवाई में किए गए दावा का सुबूत आ जाता है, देखो 35 I. C. 530; 19 C. W. N. 326.

“डिकरीदार” का मतलब उस डिकरीदार से है जो उस जायदाद को नीलाम पर चढ़ा सकता है, दूसरे डिकरीदारों से नहीं (देखो 4 C. W. N. 542; 15 C. 488).—जायदाद कुर्क कराने वाला डिकरीदार दरख्वास्त दे सकता है। “हक्क” शब्द का अर्थ सिर्फ हक्क-मिलिकियत या हक्क दखीलकारी से नहीं है बल्कि उसमें दूसरे हक्क भी शामिल हैं (देखो 28 C. W. N. 899).—इससे पहिले वाले एक मुकद्दमें में यह तय किया गया है कि कुर्की करने वाला महाजन नीलाम की मसूखी के लिए दरख्वास्त दे सकता है, देखो 4 C. W. N. 542; 8 C. W. N. 57.

खरीदार नीलाम दरख्वास्त दे सकता है, देखो 38 M. L. J. 228; 65 I. C. 875; 55 I. C. 33. इसके विपरीत फैसले के लिए देखो 74 I. C. 702; 19 C. W. N. 1291.—जब नीलाम किसी ऐसी डिकरीके सम्बन्धमें किया गया हो, जो किसी ज़ाहिरा मालिकके ऊपर दी गई है, तो वह मालिक दरख्वास्त दे सकता है जिसको जायदादसे फायदा उठा सकनेका हक्क है, देखो 20 C. 413; 19 M. 167.—किसी मुश्तरीका जायदादका हिस्सेदार दरख्वास्त दे सकता है देखो 5 A. 42—किसी हिन्दू बेवाका रिर्वेसनर (वारिस मावद) दरख्वास्त दे सकता है देखो 51 I. C. 359.—बेबात की डिकरी की जानेके बाद मुर्तहिन दरख्वास्त दे सकता है, देखो 13 C. 346; 8 C. L. J. 367.—किसी लगान (किराया) की डिकरीकी इजरामें नीलाम की गई जायदादका मुर्तहिन दरख्वास्त दे सकता है, देखो 1 C. L. J. 454.

इसी तरह किसी नाकाबिल इन्तकाल जोत (कब्ज़ा) का मुर्तहिन खरीदार भी दरख्वास्त दे सकता है, देखो 31 I. C. 859.

वह शख्स जिसने मुकद्दमेंका फैसला होनेके पहले जायदाद कुर्क करवाई दरख्वास्त नहीं दे सकता, देखो 17 C. W. N. 80.

रूल ९० का यह वाक्य कि “कोई भी शख्स जिसके हक्कको नीलाम मुकसान पहुँचा हो,” रूल ८९ के इस वाक्यसे कि, “वह शख्स जिसे नीलाम हुई जायदादमें कोई हक्क हासिल हो” अधिक विस्तृत है, देखो 19 C. W. N. 325.

आर्डर २१ रूल ९० का विस्तार—यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि रूल ९० के अनुसार किसी नीलामके मसूख किये जानेके लिये यह परमावश्यक है कि नीलामके करने या उसकी मुश्तहरी करने में (क) कोई भारी बेकायदगी फरेब किया गया हो; और (ख) यह बेकायदगी या फरेब नीलामकी मुश्तहरी या उसके करनेमें हुआ हो, (ग) कोई भारी क्षति पहुँची हो और (घ) ऐसी क्षति नीलाम की मुश्तहरी करने और नीलामके करनेमें की गई, भारी बेकायदगी या फरेबके कारण ही पहुँची हो। इन चार बातोंका होना निहायत ज़रूरी है।

“नीलामकी मुश्तहरी या नीलामके करनेमें” शब्द क्रमशः आर्डर २१ रूल ६६ और उस अफसरके कार्योंसे सम्बन्ध रखते हैं जिसने नीलाम की है (देखो 32 B. 572.—रूल ९० में वह फरेब भी आ जाता है जो इश्तहार नीलाम

प्रकाशित होने के बादमें किया गया हो—उदाहरणार्थ रुपया अदा करने के लिये समय देनेका इक़रार हो जानेके बाद कपटसे जायदाद का बेंच डालना, देखो 3 Pat. L. J. 645.—“बेकायदगी” शब्दमें “बेज़ाबतगी” शामिल नहीं है, (देखो 32 C. 1104; 16 C. W. N. 193; 20 A. 412 P. C.)—डिकरीकी इज़रामें होने वाला नीलाम फ़रेव की बिना पर मंसूख़ किया जा सकता है, यद्यपि यह न भी साबित हुआ हो कि उस फ़रेव-साज़ीमें ख़रीदार नीलामका भी कोई हाथ था, देखो 72 I. C. 625.—अदालत इज़राको, सिवाय उन उज़्रदारियोंके, जो कि दरख़वास्तमें साफ़ साफ़ लिख दी गई हैं, और दूसरी उज़्रदारियों पर विचार न करना चाहिए, देखो 53 I. C. 794.

भारी बेकायदगी—कुर्कीका न किया जाना या बेकायदा तौर पर कुर्कीका किया जाना भारी बेकायदगी है, लेकिन इससे कोई नीलाम बिल्कुल नाजायज़ नहीं हो जाता, देखो 2 Pat. 207; 18 C. 188; 34 C. 78; 18 M. 437; 30 M. 255; 68 I. C. 643; 21 A. 311; तथा 5 A. 86; 7 A. 38; 10 A. 506; 8 W. R. 415.

आर्डर २१ रूल ६६ के अनुसार नोटिसका जारी न करना बेकायदगी है, देखो 18 I. C. 715; 75 I. C. 103.—रूल ६७ के अनुसार नीलामका इशतहार न जारी करना भारी बेकायदगी है, देखो 18 C. 482.

अन्दाज़न कीमतका ग़लत लिखना एक भारी बेकायदगी है, देखो 52 I. C. 23; 20 A. 412. P. C; 8 C. W. N. 257.—कुछ मामलोंमें जान बूझकर ग़लत कीमत लिख देनेसे फ़रेवका सन्देह करना उचितही होगा, देखो A. I. R. 1922. (Pat.) 269.—कीमतका न लिखना कोई भारी बेकायदगी नहीं है, देखो 67 I. C. 885; 70 I. C. 308. किसी जोतका लगान या मकानका किराया न लिखना कोई भारी बेकायदगी नहीं है, (देखो 7 C. 723)—ज़मीनकी मालगुज़ारी न लिखना भारी बेकायदगी है, देखो 75 I. C. 546 P. C.

नीलामका समय न लिखना भारी बेकायदगी है, देखो 6 C. W. N. 48; 31 C. 815 P 818; 34 C. 709 P. C; 24 C. 291; 6 C. W. N. 44.

भारी बेकायदगी और भारी क्षति—भारी बेकायदगी या फ़रेव खुद उस डिकरी के मंसूख़ किए जाने के लिए काफी नहीं है। यह बात भी साबित की जानी चाहिए कि ऐसी बेकायदगी या फ़रेव के कारण कोई भारी क्षति हुई है। उदाहरणार्थ, सिर्फ़ कीमत का ठीक न लिखना या इशतहार नीलाम का चरप्पां न करना, या माल की कीमत कम लगाना किसी अदालत की इजाज़त से होने वाले नीलाम को मंसूख़ कर देने के लिए काफी नहीं है। अदालत को उन बातों के ऊपर जो कि साबित की गई हैं, इस बात का इतमीनान हो जाना चाहिए कि उस शख्स को, जो दरख़वास्त दे रहा है, इस बेकायदगी की वजह से भारी नुक़सान पहुंचा है। 21 C. 66 P. C. में यह तय हुआ था कि कोई प्रत्यक्ष

शहादत न होने की दशा में, साबित हो चुके बेकायदगी और नुकसान से अनुमान नहीं कर लेना चाहिए कि प्रत्यक्ष शहादत न होने की वजह से ही यह बेकायदगी और उसकी वजह से नुकसान हुआ। 11 C. 200 F. B; 7 C. 466; 3 C. 542; 9 C. 656; 20 C. 599 तथा दूसरे मुकद्दमों में यह तय हुआ था कि जहाँ पर माल नाकाफी कीमत पर बेच दिया गया है और अगर यह बात भी साबित हो जाय कि नीलाम की मुश्तहरी करने या नीलाम करने में भारी बेकायदगी की गई है, तो वहाँ पर ठीक नतीजा नहीं निकाला जा सकता है कि बेकायदगी की ही वजह से दाम कम आया है। प्रिवी कौंसिल के ऊपर बतलाए हुए मुकद्दमों (21 C. 66) में यह तय किया गया है कि शहादत न होने की दशा में ऐसा अनुमान नहीं करना चाहिए। इस प्रिवी कौंसिल के मुकद्दमों का उल्लेख 24 C. 291 में किया गया था जिसमें यह बतलाया गया था कि “प्रत्यक्ष शहादत” से मतलब ऐसी शहादत से है जिससे यह बतलाया गया हो कि यह भारी नुकसान बेकायदगी का ही परिणाम है। यही राय 20 M. 159 में भी जाहिर की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे भिन्न राय कायम की थी और उसमें प्रिवी कौंसिल के फैसले का जो अर्थ किया गया था वह यह था कि ‘प्रत्यक्ष शहादत’ ऐसी होनी चाहिए जो नुकसान का सम्बन्ध बेकायदगी के साथ स्थापित करती हो (देखो 18 A. 37; 18 A. 141)

सन् १९०८ ई० के जाबता दीवानी में “जब तक कि साबित हुई बातों के ऊपर अदालत को इतमीनान न होजाय” शब्दों के बढ़ा दिए जाने से अब सारा विरोध शान्त हो गया है। इसलिए नुकसान और बेकायदगी के बीच कारण वश होने वाले सम्बन्ध को स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष शहादत की किल्लु आवश्यकता नहीं है। जिस बात की ज़रूरत है वह सिर्फ यह है कि अदालत को चाहिए कि वह उन बातों के ऊपर जो उसके सामने साबित हुई हैं, खुद अपना नतीजा निकाले।

एक हालके मुकद्दमों में यह बतलाया गया है कि 22 C. 66 P. C. के जाबता दीवानी की पुरानी दफा ३११ का उल्लेख किया गया जिसका संशोधन अब “जब तक कि साबित हुई बातों के ऊपर अदालत को इतमीनान नहो जाय” शब्दों से कर दिया गया है, क्योंकि प्रिवी कौंसिल के मुकद्दमों में “प्रत्यक्ष शहादत” में जिस बात की ज़रूरत बतलाई गई है उसके लिए यह सम्भव है कि उसमें ग़लत अर्थ कर दिया जाय। अब इस बात की ज़रूरत नहीं है कि “प्रत्यक्ष शहादत” में यह दिखलाया जाय कि कम दाम भारी कीमत के कारण ही आया है, अगर साबित की गई बातों के ऊपर अदालत को यह इतमीनान होजाय कि एक दूसरे का स्वाभाविक परिणाम है (देखो 76 I. C. 168 Pat.)

किसी हक़ का छोड़ देना—अगर कोई शख्स जानता हुआ भी बेकायदगी के ऊपर कोई एतराज नहीं करता है, तो वह अपने हक़ के छोड़ देने के बराबर है।

और बाद में वह नीलाम की निस्वत कुछ भी न कह सकेगा (देखो 12 M. 19 P. C. ; 38 M. 387; 26 W. R. 44 P. C. ; 19 W. R. 227; 2 C. L. J. 584; 29 C. 577; 6 C. L. J. 176; 28 A. 273; 14 C. L. J. 549; 32 I. C. 990),—लेकिन बिना नया इश्तहार नीलाम जारी किए और जुग्गी पिटवाए अथवा बिना किसी बेकायदगी को बतलाए नीलाम की मुलतवी के लिए मदीयून-डिकरी की ओरसे दी गई दरख्वास्त से वह बेकायदगी की बिना पर नीलाम के निस्वत कुछ कहने से रोका नहीं जा सकता (देखो 6 C. W. N. 42; 6 C. W. N. 48; 7 C. 613; 17 M. 304)—इसकी परीक्षा सिर्फ यही है कि क्या वह उस बेकायदगी को जानता था जिसके ऊपर आपत्ति करने के लिए वह बाध्य था (देखो 6 C. L. J. 62; 13 C. L. J. 192; 14 C. L. J. 634; 6 C. W. N. 42)—जब मदीयून-डिकरी को ज़र-डिकरी अदा कर देने की शर्त पर समय दिया गया, तो उसकी निस्वत यह तय हुआ कि उसके लिए नीलाम के जायज़ होने के सम्बन्ध में एतराज करने की कोई रुकावट नहीं है, देखो 29 C. 577; 36 C. 422.

मियाद—चाहे नीलाम मसूख करने की दरख्वास्त आर्डर २१ रूल ९० के अनुसार दी गई हो या दफा ४७ के अनुसार अब मियाद का सवाल कानून मियाद के आर्टि० १६६ के अनुसार (नीलाम की तारीख से एक महीना) तय किया जाना चाहिये आर्टि० १८१ के अनुसार नहीं (तीन साल) देखो 77 I. C. 631; 46 C. 975; 77 I. C. 368; 61 I. C. 822; 28 C. W. N. 144. —संशोधित आर्टि० १६६ कानून मियादके अन्दर ज़ाबता दीवानीके अनुसार नीलाम की मसूखी के लिये दी गई कुल दरख्वास्तें आजाती हैं। अगर किसी तरह का कोई फरेब किया गया है तो मियाद की मुद्दत उस तारीख से शुमारकी जानी चाहिये जिस तारीख को दरख्वास्त देने वाले शख्स को पहिले पहल उस फरेब का पता चला था, देखो 17 C. 769 F.B. ; 30 C. 142—कानून मियादकी दफा १८ से फायदा उठानेके लिये उसे चाहिये कि वह यह दिखलावे कि फरेब करके उसे दरख्वास्त दे सकनेकी बात जानने नहीं दी गई देखो 51 I. C. 447; 1 C. W. N. 67.—ऐसे फरेब के मामले में, जिसमें सम्मन छिपा रखा गया है या ग़लत नक़शा दाखिल किया गया है मियाद की मुद्दत उस तारीख से शुरू होती है जिस तारीख को दरख्वास्त देने वाले शख्स को सिर्फ नीलाम की ही बात नहीं मालूम हुई थी बल्कि कुल बातें साफ़ साफ़ मालूम हो गई थीं जिससे फरेब (Fraud) भी शामिल है और यह बात दिखलाना दूसरे आदमी का काम है कि उस (दरख्वास्त देने वाले) शख्स को इन बातों का पता उस समय चल गया था जिससे दरख्वास्त की मियाद जाती रही, देखो 48 C. 119; 18 C. W. N. 1266; 3 P. L. T. 501—इस बात के साबित करने का भार उसी शख्स पर है जिसने फरेब किया है कि जिस शख्स को नुक़सान पहुंचा है उसे वे कुल बातें जिनसे फरेब की बात पैदा होती है इतने समय पहिले मालूम हुई थीं और वह अब अदालत से किसी तरह की मदद पाने का हक़दार नहीं है देखो 27 C. L. J. 528;

17 B. 141. P. C. में यह बतलाया गया था कि सिर्फ यह बात कि जिस शर्त को नुकसान पहुंचा है उसको कुछ ऐसी बातों का आभास मिल गया था कि अगर उनका दृढ़ता के साथ पीछा किया गया होता और वास्तवमें उनपर अमल किया गया होता तो यह सम्भाव था कि उस से पूरी पूरी बात मालूम होगई होती, इस बात के कहने के लिये काफी नहीं है कि उसको फरेब (छल) की बातों का पूरा पूरा पता नहीं हो गया था ।

अपील—जिस हुक्म से कोई नीलाम मंसूख कर दिया गया हो या नीलाम मंसूख कर देने से इन्कार कर दी गई हो वह आर्डर ४३ रूल १ कलॉज (एफ) के अनुसार दिए गये हुक्म की तरह पर काबिल अपील है और दूसरी अपील करने का अधिकार अब छीन लिया गया है [देखो दफा १८४ (२)]—जब दरख्वास्त दफा ४७ के अनुसार दी गई हो तो दूसरी अपील हो सकती है ।

जब कोई दरख्वास्त हाज़िर न हो सकने की वजह से खारिज हो गई हो और उसको फिर से समाअत किये जाने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई हो तो उस हुक्मके विरुद्ध अपील न की जा सकेगी (देखो 29 A. 596; 31 C. 207)

राजीनामा (समझौता)—किसी नीलाम के मंसूख किए जाने के लिए दी गई दरख्वास्त में किए गए राजीनामा का इन्दराज आर्डर २३ रूल ३ के अनुसार कर लिया जाना चाहिये देखो 62 I. C. 608 .

नोटिस—नीलाम मंसूख किये जाने के पहिले इस बात की नोटिस आर्डर २१ रूल ९२ के अनुसार उन सभी आदमियों को दी जानी चाहिये जिनके ऊपर उस नीलाम की मंसूखी से कोई असर पड़ता हो देखो 39 C. 687; 13 C. L. J. 533; 39 C. 881)—खरीदार नीलाम एक ज़रूरी फरीक है (देखो 50 I. C. 5; 3 L. L. J. 463; 62 I. C. 986) और खरीदार नीलाम को नोटिस दिये बिना नीलाम के मंसूख कर दिये जानेमें वह उस मंसूखी से बाध्य नहीं हो जाता [देखो 62 I. C. 113]—पटना हाईकोर्ट के एक हाल के मुकदमों में यह तय पाया है कि इस रूल में कहीं पर भी यह नहीं बतलाया गया है कि खरीदार नीलामको ज़रूर फरीक बनाया जाना चाहिये। यह काम दरख्वास्त देने वाले का है कि वह अदालत से इस बात की दरख्वास्त करे कि जिन लोगोंपर उस मंसूखी नीलामसे कोई असर पड़ता है उनके नाम वह नोटिस जारी करे, अदालत इस बातके लिये बाध्य नहीं है कि वह अपनी ओर से नोटिस जारी करे। अगर दरख्वास्त देनेवाला इस बारे में कुछ भी कार्यवाई नहीं करता तो अदालत को अधिकार है कि वह दरख्वास्त खारिज कर दे। नोटिस जारी करने के लिये कोई मुद्दत नहीं है देखो 75 I. C. 430—जो नीलाम मदीयून-डिकरी और डिकरीदार के बीच हुये सम्झौते के कारण मंसूख किया गया हो उसके माननेके लिये खरीदार नीलाम बाध नहीं है (देखो 62 I. C. 986)—रूल ८९ के अनुसार रुपया जमा कर दिया गया, लेकिन खरीदार नीलाम बाज़ाबता तौर पर फरीक नहीं बनाया गया यद्यपि दरख्वास्त में यह बतला दिया गया था कि जायदाद उसने खरीद की है। तय हुआ कि इतना कर देना नियम की पूरी पाबन्दी कर देना था और इसके

ऊपर खरीदार नीलाम के नाम नोटिस जारी किया जा सकता है, देखो A.I. R. 1923(Cal) 394 खरीदार नीलामको उसी समयके भीतर फरीक बना लेना चाहिये जो मियाद दरखवास्त देने के लिये मुकर्रर है, देखो 62 I. C. 61; 50 I. C. 5 Contra—रूल ९२ के अनुसार नोटिस दिये जाने के लिये कोई मियाद मुकर्रर नहीं है देखो 68 I. C. 238 तथा 75 I. C. 430.

रुपये की वापसी—आर्डर २१ रूल ९३ के अनुसार जब कोई नीलाम मंखू कर दिया जाय तो खरीदार अपना रुपया वापस पानेका हकदार है। नए जाबता दीवानी के अनुसार रुपया वापस पानेके लिये अलग दरखवास्त नहीं दी जा सकती देखो 27 C. W. N. 183; 28 C. W. N. 20 और 40 A. 411.— रुपया वापस दिला पाने के हुक्म की इजरा दफा ३६के अनुसार डिकरी की तरह पर ही की जा सकती है (देखो 47 I. C. 670).

नीलाम का सर्टीफिकेट—नीलाम कतई होजाने के बाद जैसा कि रूल ९२ में बतलाया गया है, खरीदार नीलाम सर्टीफिकेट पाने का हकदार है (देखो आर्डर २१ रूल ९४) नीलाम कतई होजाने के बाद नीलाम की तारीख से ही जायदाद में खरीदार का हक पैदा हो जाता है (देखो दफा ६५)

जाबता दीवानी की दफा ६६ में यह व्यवस्था की गई है कि सर्टीफिकेट पाये हुये खरीदार के ऊपर इस बिना पर नालिश नहीं की जा सकेगी कि जायदाद मुद्दई की ओर से खरीद की गई थी।

ज्योंही नीलाम कतई करार दे दिया जाय त्योंही ज़िलाके मुहाफिज़ खाने में कागज़ात भेजे जाने के पहिले नीलामके सर्टीफिकेट (क़िवाला) का मसविदा तैयार किया जायगा। जब किसी सर्टीफिकेट के लिये दरखवास्त दी गई हो तो इसमसविदे से असल सर्टीफिकेट तैयार किया जायगा उन मामलों के सम्बन्ध में जिन में नीलाम की मंजूरी की तारीख से छः साल के अन्दर सर्टीफिकेट के लिए दरखवास्त न दी गई हो, तैयार किया हुआ सर्टीफिकेट का मसविदा उस मुद्दत के खतम हो जाने पर नष्ट कर दिया जायगा।

नीलाम के सर्टीफिकेटों में लिखी जाने वाली बातें—न्यायालयों के अधिकारियों (जुडिशल अफसरों) को चाहिए कि वे अपने मातहत के लोगोंको यह हिदायत कर दे कि जायदाद ग़ैर मनकूला की नीलाम के कुल सर्टीफिकेटों (क़िवालों) में नीलाम हुई जायदाद को इतने ब्योरेवार लिख दिया करें जितना कि वे हर एक मामले में कर सकते हैं और उन्हें इस बात के लिए खास तौर पर हिदायत कर दें कि वे उस तारीख को उसमें ज़रूर लिख दें जिस तारीख को नीलाम कतई करार दिया गया था (देखो आर्डर २१ रूल ९४) [G. R. & C. O. Ch. 1 R. 112]

हर एक मामले में नीचे लिखी बातें लिखी जानी चाहिए—

१—उस शख्सका “पता व निशान” (जैसा कि ऐक्ट नं० १६ सन् १९०८ ई० की दफा २ में उसकी परिभाषा की गई है) जो खरीदार बतलाया जाता है।

२-वे बातें जो जायदादकी शिनाख्तके लिए काफीहों जैसाकि फेस १६ सन् १९०८ ई० की दफा २३ (२) के अनुसार आवश्यक है।

३-रजिस्ट्रीके हर एक हलके (Subdistrict) का नाम जिसमें जायदादका कोई हिस्सा वाकै है (देखो G.R.&C.O.Ch.L.R. 11)

नीलाममें वसूल हुई रकम-उसका हिस्से-रसदी बटवारा—जब किसी मालिक की जायदाद किसी अदालतके कब्जेमें हो और “जायदादके पाने नीलाम होनेके पहिले एक से अधिक आदमियोंने उस अदालतको “रुपयेकी अदायगीके लिए डिकरियों” की इजराकी दरख्वास्त दी हो जो उस एक ही मालिक की डिकरीके ऊपर दी गई हैं, तो दफा ७३ में बतलाए अनुसार वह जायदाद उनमें से हिस्से-रसदी बांट दी जायगी।

रामजस बनाम गुरुचरणके मुकद्दमें (देखो 11 C. L. J. 67 P. 73) में जस्टिस मुकर्जीने कहा:—“किसी डिकरीदारके, डिकरीदारकी हैसियतमें जाने और वसूल हुए रुपए में हिस्सा पाने का हकदार होनेके लिए, नीचे शर्तोंका होना ज़रूरी है:—

(क) जिस डिकरीदारने हिस्से-रसदी बटवाराके लिए दावा किया उसने अपनी डिकरीकी इजराके लिए उस अदालतको दरख्वास्त दी हो कि पास वसूल हुआ रुपया जमा है।

(ख) ऐसी दरख्वास्त असासा वसूल होनेके पहिले गई दी हो।

(ग) वह रुपया किसी डिकरीकी इजरा में नीलामके जरिए या और किसी तरह पर वसूल किया गया हो।

(घ) जायदाद कुर्क कराने वाले डिकरीदार और वे डिकरीदार, जो रुपएके हिस्से-रसदी बटवाराके लिए दावेदार हों, रुपएकी अदायगीकी लिखते हों।

(ङ) ऐसी डिकरियां एक ही मालिक-डिकरीके ऊपर दी गई हों।

इस दफाके अनुसार उस समय तक हिस्से-रसदी बटवारा न किया जा सकेगा, जब तक ऊपर बतलाई हुई सारी शर्तें मौजूद न हों।

सन् १९०८ ई० के ज़ाबता दीवानीमें “इजरामें नीलामसे या और किसी तरह पर वसूल हुआ रुपया” की जगह “वह रुपया जो किसी अदालतके कब्जेमें हो” कर देनेसे दफा ७३ का विस्तार बहुत कुछ बढ़ गया है और अब उसमें भी रकन शामिल समझी जा सकती है, चाहे वह किसी भी तरहसे अदालतके कब्जेमें आई हो, देखो 35 C. L. J. 327; 27 C. W. N. 169; 40 C. 614। इस वर्तमान क़लके अनुसार जिन बातोंकी ज़रूरत है, वह यह है कि वह अदालतके पास (कब्जेमें) हो, फिर चाहे वह कार्रवाई इजरामें वसूल की गई हो या और किसी तरह पर। 36 B. 156 जिसका 41 M. 616; 21 Bom. L. 995, 978 में खण्डन किया गया है तथा दूसरे बहुतसे मुकद्दमोंमें जो इस

विपरीत स्थिर किया गया है, वह वर्तमान कूलके शब्दोंके अनुकूल नहीं है । 41 M. 221. में जो फसला दिया गया है, वह 44 M. 100. में दिए हुए फसले से रद्द हो गया है ।

दरख्वास्त उस अदालतको, जिसके पास रुपया (माल) जमा है, उस मालके मिलनेसे पहिले दी जानी चाहिए (देखो 5 B. 198; 9 C. L. J. 210; 11 C. L. J. 69; 4 C. W. N. 27 —जिस बातकी ज़रूरत है वह सिर्फ यह है कि डिकरीकी इजरा की दरख्वास्त आर्डर २१ कूल ११ में बतलाये हुए फार्ममें दी जानी चाहिये । यह ज़रूरत नहीं है कि डिकरीदार उस जमा हुए माल (Assets) की कुर्कीके लिए भी दरख्वास्त दे, (देखो 9 C. L. J. 210.) — किसी इजराके मुकद्दमेंको मुन्तकिल करनेके लिए किसी बड़ी अदालतको दीगई दरख्वास्त दफा ७३ के अर्थमें खुद दरख्वास्त नहीं है, देखो 25 C. W. N. 872; 18 C. 242; 34 M. 25; 18 C. W. N. 1311. —अगर कुर्की तारीखसे पहिले करा लीगई है, तो इजरा कराने वाला डिकरीदार हिस्से रसदी बटवारे का हकदार है, यद्यपि उस अदालतको, जिसके पास माल जमा है, इजराकी दरख्वास्त न भी दीगई हो, देखो 63 I. C. 11.

माल उस समय मिल सकता है, जब कुल कीमत खरीद—(एक चौथाई नहीं)—जमा कर दीगई हो, (देखो 15 C. W. N. 872; 18 C. 242; 34 M. 25; 18 C. W. N. 1311)—जब कोई जायदाद कई बार करके नीलाम कीगई हो, तो रुपया उस समय वसूल किया जासकता है जब कुल कीमत खरीद अदा कर दी जाय (देखो 33 C. L. J. 7; 26 M. 179.)—कई तारीखोंमें जायदाद मनकूलाके नीलामके सम्बन्धमें दूसरे नियम लागू होते हैं, (देखो 44 C. 789).

इस रसदी बटवारेमें डिकरीका ही रुपया दिया जायगा, इजराका खर्चा न दिया जायगा, जब तक कि रुपया मिलनेसे पहिले इस बातका हुक्म न दे दिया गया हो कि डिकरीके रुपयके साथ खर्चा भी शामिल कर दिया जायगा, देखो 47 C. 515.

जब मुन्सिफ और सब-जजकी अदालतोंने एक ही जायदाद कुर्कीकी हो, तो नीलाम बड़ी अदालत करेगी । लेकिन जहाँ पर नीलाम मुंसिफने किया हो, उस समय सब-जज उन्हें इस बातका हुक्म नहीं दे सकते कि नीलामसे वसूल हुआ रुपया उनकी (सब-जजकी) अदालतको भेज दिया जाय, लेकिन वह जिला जजसे इस बातकी दरख्वास्त कर सकते हैं कि वह रुपया उनकी (सब-जजकी) अदालतको भेज दिया जाय और उसके बाद उसका बहिस्साब रसदी (हिस्से रसदी) बटवारा किया जाना चाहिए, देखो 27 C. L. J. 145.

अपील—जिस हुक्मके ज़रिये भिन्न भिन्न डिकरीदारोंके बीच झगड़ा होजाने के कारण हिस्से-रसदी बटवारा करनेसे इन्कार कर दीगई हो; वह इजराकी कार्रवाईमें दिया हुआ हुक्म है और इसलिए उसकी अपील नहीं हो सकती, (देखो

19 C. W. N. 1202;) लेकिन अगर जिस खालका फैसला हुआ है डिक्लीदार और मदीयून-डिकरीके बीच पैदा हुआ हो, तो उस समय दिया हुआ हुक्म, दफा ४७ के अन्दर आ जाता है और इसलिए उसकी अपील हो सकती है (देखो 36 B. 156; 327 M 570).

खरीदारको कब्जा देनेका तरीका—जब वह जायदाद गैर-मनकूला, जो कब्जा की गई है, मदीयून-डिकरीके कब्जेमें हो या उसकी ओरसे कोई दूसरा शख्स कोई ऐसा शख्स, जो कुर्कोके बाद हासिल की हुई हकीयतके जरिये दावेदार उस पर क़ाबिज़ हो, तो दरख़्वास्त देने पर अदालत उस जायदाद पर कब्जा दिला देगी. (देखो आर्डर २१ रूल ९५)

जब जायदाद किसी आसामी या दूसरे आदमीके कब्जेमें हो, जो उस कब्जा रखनेका हक़दार है, तो उस पर नीलामका एक सर्टीफ़िकेट चर्चों का और हुगगी पिटवा कर उस जायदाद पर कब्जा दिलाया जायगा (देखो आर्डर २१ रूल ९६ तथा आर्डर २१ रूल ३५)

रूल ९५ का मंशा यह है कि मदीयून-डिकरी या किसी दूसरे शख्स जो उसके जरिये दावेदार हो, जायदाद पर से कब्जा हटाकर खरीदारको कब्जा दिला दिया जाय। रूल ९६ का मंशा यह है कि कानूनी कब्जा दिलाया जाय, क्योंकि जायदाद किसी आसामीके, जो उसको अपने कब्जेमें बनाये रखे का हक़दार है, कब्जेमें होनेसे उस पर असली कब्जा (दखल) नहीं दिलाया जा सकता। इसलिये उस समय से खरीदार लगान (किराया) वगैरा बसूल कर उस जायदाद पर अपना कब्जा बनाये रख सकता है। और खरीदार के अपने कब्जे और कानूनी कब्जेसे उसके हक़ पर एक जैसा ही असर पड़ता है। रूल ९५ के अनुसार खरीदारको कब्जा मिल जाने के बाद मदीयून-डिकरीको दफ़्तरी एक मदखिलत बेजा करने वाले शख्स का जैसा रह जायगा, (देखो 66 C. 817).

कानून और असलियतकी दृष्टिसे यह कानूनी कब्जा फ़रीक़ैन्के बीच की पूरी मुन्तकिली का असर रखता है और इससे मदीयून-डिकरी तथा दूसरे आदमियोंके ऊपर जो डिक्लीके जरिये देनदार हैं मियादकी नई तारीख़ पैदा होती जाती है, यद्यपि जहां तक तीसरे फ़रीक़ का सम्बन्ध है इस कब्जेका कोई महत्व नहीं है (देखो 5 C. 584 F B.; 22 C. W. N. 330 P. C.; 7 C. 418; 8 C. W. N. 49; 19 A. 499; 24 C. 715; 21 A. 269; 23 A. 722; 17 M. L. J. 598; 2 Pat. L. T. 743; 71 I. C. 999; 46 B. 710; Contra. —परन्तु कुछ मुकदमोंमें यह तय किया गया है कि खरीदार जायदाद पर सिर्फ़ कानूनी कब्जा दिला देने से मदीयून-डिकरी के हक़में मियाद की मुद्दत का जारी रहना बन्द नहीं हो जाता जब कि वह (मदीयून-डिकरी) हकीकतमें उस जायदाद पर क़ाबिज़ रहा हो, देखो 36 B. 373 F. B.; 46 B. 559; 40 A. 520; 43 All. 520; 36 B. 373 के ऊपर 46 B. 710 सन्देह किया गया है।

जब खरीदारकी ओरसे कब्ज़ा दिला पाने के लिए दीगई दरख्वास्त रुकावट डाल देनेके कारण खारिज कर दीगई हो, तो वह आर्डर २१ रूल ९७ के अनुसार दरख्वास्त दिये बिना कानून मियादके आर्टि० १६७ में दी हुई मियादके अलावा नई मियादकी मुदत के लिये हकदार है, देखो 49 L.C. 150

आर्डर २१ रूल ९९ के अनुसार दिये हुये हुक्मकी अपील नहीं होसकती, देखो 40 A. 216.

जायदाद पर कब्ज़ा दिलापानेके लिये दिये जाने वाले हुक्मके फार्मके लिये देखो ज़ाबता दीवानीके ज़मीमा (ई) का फार्म नं० ३९ ।

कब्ज़ा दिये जानेका विरोध—जब किसी डिकरीदारको, जिसे कब्ज़ेके लिये डिकरी दीगई है, या खरीदार नीलामको जायदाद पर कब्ज़ा करने से रोका गया हो, तो वह शख्स इस बातकी रिपोर्ट अदालतमें कर सकता है और फिर इस मामलेकी जांच (तहकीकात) की जायगी (देखो आर्डर २१ रूल ९७)—जो शख्स कब्ज़ा करनेमें रुकावट डाल रहा है वह ३० दिन तक कैदमें रखा जा सकता है, (देखो आर्डर २१ रूल ९८; दफा ७४)—जब इस तरह रुकावट डालने वाला शख्स (जो कि मदीयून डिकरी नहीं है) ऐसा आदमी हो जो नेकनीयतीके साथ अपने बल पर या मदीयून-डिकरीके अलावा किसी दूसरे शख्सके बल पर, उस जायदाद पर कब्ज़ा दिला पानेका दावेदार है, तो वह दरख्वास्त खारिज कर दी जायगी, (देखो आर्डर २१ रूल ९९).

“अपने बल पर”, जो रूल ९९ में आया है, सिर्फ उसी आदमीके सम्बन्धमें लागू हो सकता है जो अपनी हकीयतके ऊपर कब्ज़े के लिये दावेदार हो । अगर किसी ज़मींदारको किसी आसामीके खिलाफ़ कब्ज़े की बाबत डिकरी मिले और उसे कोई ऐसा शख्स जो उस जायदादपर बतौर शिकमी आसामीके काबिज़ है कब्ज़ा करने से रोके, तो वह शख्स रूल ९९ के आधार पर अपना दावा पेश नहीं कर सकता, देखो 23 Bom. L. R. 1316—47 C. 907 में इससे विपरीत फैसला दिया गया है ।

अगर किसी डिकरीदार को डिकरी की इजरा में रोका गया हो, तो वह फिर कब्ज़ा दिला पाने के लिए दरख्वास्त दे सकता है और अगर वह फिर रोका गया तो वह इसके खिलाफ़ शिकायत कर सकता है, देखो 13 C. W. N. 724.

जिस हुक्म के ज़रिये कब्ज़ा दिलापाने की मंजूरी या इन्कार की गई हो, वह आर्डर ७७ के अनुसार दिया हुआ हुक्म नहीं है और उसकी अपील नहीं हो सकती, देखो 29 C. L. J. 48.

खरीदार द्वारा बेदखल किया जाना और कब्ज़ेका दिया जाना—जब मदीयून-डिकरी के अलावा कोई शख्स डिकरीदार या खरीदार नीलाम की ओर से जायदाद गैर-मनकूला से बेदखल कर दिया गया हो, तो वह शख्स इस आशय की दरख्वास्त देकर, अगर वह अदालत को इतमोनान दिला सके कि

वह अपने दफ़ के बलपर या मदियून-डिकरी को छोड़ दूसरे शख्स के बलपर उस जायदाद पर काबिज़ था, आर्डर २१, रूल १०० के अनुसार सरसरी कां-वाई से कब्ज़ा हासिल कर सकता है (देखो आर्डर २१, रूल १००, १०१) — १९ और १०१ उन मुन्तकिल अलेहां के सम्बन्ध में लागू नहीं होते जिनके नाम दौरान मुकदमा में जायदाद मुन्तकिल की गई हो (देखो आर्डर २१, रूल १०२) — जिस शख्स को रूल ९८, ९९ या १०१ के अनुसार दिए गए हुक्म में कुछ दुःख पहुंचा हो, वह अपनी हकीयत कायम करने के लिए नालिश दायर कर सकता है, लेकिन ऐसी नालिश के नतीजे के अनुसार वह हुक्म कतई इस होगा (देखो आर्डर २१, रूल १०३)

असली कब्ज़ा दे देना ही रूल १०० के अर्थ में बेदखल करना है, देखो 33 C. 487 — बांखों का लगाना और काबिज़ लोगों के नाम इस बातकी घोषणा निकाल देना कि उस जायदाद पर दूसरे शख्स को डिकरी दे दी गई है, काबिज़ बेदखली है, देखो 11 W. R. 191; 3 C. L. J. 293. — “मदियून डिकरी” उसका प्रतिनिधि और वे तमाम लोग शामिल हैं जो उस डिकरी का रूपया अदा करने के लिए ज़म्मेदार हैं, देखो 2 Pat. L. J. 478. — किसी मुतद्दिन के ज़रिये कब्ज़ा पाना इस रूल के अनुसार दावा दायर करने के लिए काफी है, देखो 20 W. R. 373; 33 C. 487. — जो मुतद्दिन किसी रेहननामा के अनुसार किसी जायदाद पर काबिज़ हो, उसके लिए यह कहा जायगा कि वह “अपने बलपर” काबिज़ है, देखो 2 A. 94. इसी तरह किसी अस्सामी का मुतद्दिन भी “अपने बलपर” काबिज़ समझा जायगा, देखो 19 C. L. J. 13.

जब कोई सोलह आने का ज़मींदार किसी लगानी डिकरी की इजरा में कोई दखीलकारी जोत को खरीद करे, तो अस्सामी से खरीद करने वाला शख्स रूल १०० के अनुसार दरख्वास्त दे सकने का हकदार नहीं है, देखो 43 L. C. 969.

रूल १०० के अनुसार दी गई दरख्वास्त के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई वैसी ही है जैसी कि आर्डर २१, रूल ५८ के अनुसार दी गई दावे की दरख्वास्त के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई। जिस प्रश्न पर विचार करता है वह सिर्फ दखल का प्रश्न है (देखो 2 A. 94; 19 C. L. J. 13) — कानून मियाद के आर्टि० १६५ के अनुसार दरख्वास्त बेदखली की तारीख ३० (तीस) दिन के अन्दर दे देनी चाहिए। रूल १०१ के अनुसार दिए गए हुक्म की अपील नहीं हो सकती (देखो 41 L. C. 891.) — रूल १०३ के अनुसार दायर की जाने वाली हकीयत की नालिश की मियाद, कानून मियाद के आर्टि० ११ के अनुसार, हुक्म की तारीख से एक साल है (देखो 26 B. 730) जब कोई दरख्वास्त अदम-पैरवी में खारिज कर दी गई हो, तो उसकी निश्चत कोई जांच नहीं होती और वहां पर एक साल की मियाद की बात लागू नहीं होती, देखो 34 C. 491; 1 P. L. T. 559.

आर्डर २१ रूल १०१ के अनुसार दिया जाने वाला हुक्म या तो सायल को कम्ज़ा दिए जाने के लिए हो सकता है या ऐसा करने से इन्कार के लिए हो सकता है, देखो 42 B. 10—जब रूल १०१ के अनुसार हुक्म एक तरफ़ा दिया जाय, तो आर्डर ९, रूल १३ लागू नहीं होता और इसके लिए इलाज सिर्फ़ यही है कि रूल १०३ के अनुसार बाकायदा नालिश दायर की जाय, देखो 41 C. इसके विपरीत फैसले के लिए देखो 2 P. 372; 71 I. C. 484; 43 I.C. 951.

वापसी जायदाद (Restitution)—(१) जब और जहां तक कोई डिकरी उलट दी गई हो या उसमें कोई रद्द-बदल कर दी गई हो, प्रारम्भिक अदालत, किसी ऐसे फ़रीक़ की दरख़वास्त पर जो वापसी जायदाद या और तरह पर किसी रियायत का हक़दार है, ऐसी वापसी के लिए हुक्म दे देगी, जिस हुक्म से, जहां तक सम्भव हो, फ़रीक़ैन उसी हालत में पहुँच जायेंगे जिस हालत में वे उस समय पहुँचे होते, अगर वह डिकरी या उसका हिस्सा उलट न दिया गया होता या उसमें रद्द-बदल न की गई होती। इस काम के लिए अदालत कोई भी हुक्म दे सकती है, जिसमें खर्च की वापसी और ब्याज, नुक़-सान, मुआविज़ा और वासिलात की, जो इस परिवर्तन (डिकरी के बदल देने) या रद्द-बदल के कारण अवश्य ही पैदा हो जाते हों, अदायगी के लिये दिये हुये हुक्म शामिल हैं।

(२) किसी भी ऐसी वापसी या दूसरी दादर्सों के पाने के लिए नालिश दायर नहीं की जा सकेगी जो उप-दफ़ा (१) के अनुसार दरख़वास्त देकर प्राप्त की जा सकती है (देखो दफ़ा १४४)।

जब कोई शख़्स, जिसके खिलाफ़ कोई डिकरी हासिल की गई हो और जिसकी कोई जायदाद या रुपया उस डिकरी की इजरा में ले लिया गया हो, बाद में जीत जाय और वह डिकरी उलट दी जाय, या उसमें कोई संशोधन या रद्द-बदल कर दी जाय, तो वह शख़्स क़ानूनन उस चीज़ के वापस पाने का हक़दार है जो उससे ले ली गयी थी। ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १४४ में वह ज़ाबता बतलाया गया है जिससे वह चीज़ वापस ली जा सकती है। इसीका नाम “वापसी जायदाद (Restitution)” है जिसका मतलब है किसी चीज़को फिर दे देना या वापस कर देना जो किसी शख़्स से क़ानून के खिलाफ़ ले ली गई हो। वापसी जायदाद के सिद्धांत के नियम के सम्बन्ध में देखो 23 M. 306; 32 A. 79; 13 C. L. J. 243 p 247; 15 C. L.J. 187; 9 W. R. 402; L. R. 3 P. C. 465; 28 A. 665.—नियम यह है कि यह वापसी जहां तक सम्भव हो सके इस तरहपर की जानी चाहिये कि फ़रीक़ैन अपनी उसी असली हालत पर आ जायें जिसमें कि वे ग़लती से दी गई उस डिकरी या हुक्म के पहले थे, देखो 26 C. W. N. 408; 37 I. C. 863; 21 C. W N. 564; 55 I. C. 356.—इसका उद्देश्य मुक़दमेंबाज़ी को कम करना और मामले को तय कर देना है; देखो 16 C. L. J. 135. दफ़ा १४४ के अनुसार वापसी जायदाद की इजाजत देना ताकीदी है, यह अदालत की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, देखो 42 I. C. 523.

जायदादकी वापसी करानेकी गरज से अदालत जायदादके हवाले कि जाने, खर्च की वापसी, सूद (ब्याज) की अदायगी, नुकसान, माविजा और वासिलात वगैरा की अदायगीके लिये हुक्म दे सकती है या कोई भी ऐसा हुक्म दे सकती है जिसका देना न्यायकी दृष्टि से आवश्यक हो ।

दफा १४४ उस समय लागू नहीं होती जब कि कोई ऐसा हुक्म उठा दिया गया हो जिससे किसी नीलाम की मसखी कीगई हो । यह उस समय अशुभ लागू होती है जब कोई डिकरी उलट दीगई हो (देखो 39 I.C. 763 (P) 41 M. 467.

सन् १८८२ ई०के ज़ाबता दीवानीकी दफा ५८३ के अनुसार किसी जीति हुई फरीक मुकद्दमेंको यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी डिकरीकी, जो अपील दीगई हो, डिकरियोंकी इजराके लिए निश्चित नियमोंके अनुसार इजरा कर सके । इस नये ज़ाबता दीवानीकी दफा १४४ ने सारी कार्रवाई दूर करके मामलेको बहुत कुछ संक्षिप्त करदिया । अब एक ऐसी दरख्वास्त दाखिल करके, जिसमें कुल बातों का सही सही वर्णन करदिया गयाहो, वापसी जायदादका हुक्म हासिल किया जा सकता है । पुराने ज़ाबतेके अनुसार भिन्न भिन्न अदालतोंमें इस बातपर मत-भेद था कि वापसी जायदादके लिए अलग अलग नालिश दायरकी जा सकती है या नहीं । दफा १४४ की उप-दफा २, जो नई है, इस बात की साफ़ व्यवस्था करती है कि अलग नालिश दायर नहीं की जा सकती । जहां पर वापसी जायदाद का हुक्म नहीं मिल सकता, वहां पर नुकसान का; जैसे किसी ऐसी नालिश दायर करने के लिए, जिससे कि नुकसान पहुंचता हो नालिश दायर की जा सकती है, देखो 44 A. 687.

“प्रारम्भिक अदालत”—वह अदालत है जिसको दरख्वास्त दी जाना चाहिए, अर्थात् वह अदालत जिसने वह डिकरी दी थी जिसके विरुद्ध अपील की गई है, देखो 5 C. W. N. 287; 18 B. 224; 44 A. 283, या वह अदालत जिसके पास कार्रवाई मुन्तकिल कर दी गई है, यद्यपि वह दूसरी अदालत अब नहीं रह गई है, देखो 61 I.C. 962. “प्रारम्भिक अदालत” शब्द अदालत अपील से भिन्न अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयोग किया गया है । इसमें वह अदालत भी शामिल है जिसके पास इजरा के लिए कोई डिकरी मुन्तकिल की गई हो, देखो 7 S. L. R. 19; 20 I. C. 540; 20 M. 448; 8 A. 545.

वापसी जायदादकी दरख्वास्त कौन शख्स दे सकता है—“फरीक” शब्द यहां पर फरीक मुकद्दमा के अर्थ में नहीं प्रयोग किया गया है, बल्कि उसका मतलब उस शख्स से है जिसने दरख्वास्त दी है, देखो 44 A. 553. “कोई फरीक” शब्दों का मतलब सिर्फ़ उस अपील के फरीक से ही नहीं है जिसमें डिकरी दी गई थी । कोई भी शख्स, जिसके खिलाफ़ वह डिकरी दी गई थी जिसके विरुद्ध अपील की गई है, दरख्वास्त दे सकता है, अगर अपील उसके पक्ष में की गई है, देखो 12 C. W. N- 642; 38 M. 36; 18 M. L. J. 34.

फरीक में वह शर्त भी आ जाता है जिसके नाम डिकरी मुन्तकिल कर दी गई हो, देखो 46 I. C. 465 (P)—कुर्को कराने वाला महाजन दरखास्त नहीं दे सकता, देखो 29 C. L. J. 360.

किसी डिकरीदार का मुन्तकिल-अलेह (assignee) उस शर्त का प्रतिनिधि और फरीक है और वह वापसी जायदाद का हकदार है, देखो 33 C. 857, चाहे मुन्तकिली उस अपीलेट-डिकरी के बाद ही क्यों न हुई हो जिसके आधार पर जायदाद की वापसी चाही जाती है, देखो 47 I. C. 47 (P.)

जायदाद वापसीकी दरखास्त किसके विरुद्ध दी जा सकती है—पुराने जाबता दीवानी की दफा ५८३ के अनुसार, उस शर्त को, जो वापसी जायदाद का हकदार है, अपील की डिकरी की इजरा करनी पड़ती थी, और चूंकि डिकरी की इजरा उस-डिकरी के फरीक के ही विरुद्ध कराई जा सकती है, इसलिए यह तय किया गया था कि डिकरी के मुन्तकिल अलेह के खिलाफ वापसी जायदाद का हुक्म नहीं दिया जा सकता, यद्यपि उसे इजरा का पूरा पूरा हक है, जब तक कि वह अपीलमें कोई फरीक न हो (देखो 19A. 136; 20 A. 139; 5 C. W. N. 426; 16 C. L. J. 83)—अब हाल के जाबता दीवानीकी दफा १४४ बिलकुल भिन्न है और वह अधिक विस्तृत है तथा उसमें यह शर्त लागू नहीं होती।; इसी तरह, यह तय किया गया है कि किसी डिकरी के मुन्तकिल अलेह के खिलाफ वापसी जायदाद का हुक्म दिया जा सकता है, यद्यपि वह अपीलमें फरीक न भी बनाया गया हो, देखो 38 M. 36; 23 M. 203; 24 A. 288.

किसी असली खरीदार नीलाम के खिलाफ वापसी जायदाद का हुक्म नहीं दिया जा सकता, यद्यपि अपील में वह डिकरी मंसूख भी कर दी गई हो, देखो 38 A. 240; 34 I. C. 760 (M.) ; 75 I. C. 238; 21 I. C. 570 Contra.—जिस शर्त ने अदालती नीलाम में जायदाद खरीद की है, वह डिकरी का फैसला बदल जाने पर जायदाद पर कब्जा वापस देने के लिए बाध्य है। अपील के दौरान में, मुद्दई के पास से मदियून-डिकरी को जायदाद मुन्तकिल करने के लिए, खरीदार मुद्दई का प्रतिनिधि समझा जाता है, देखो 27 C. L. J. 489; 46 I. C. 168.

जमीन्दार डिकरीदार ने, डिकरी की इजरा में होने वाले नीलाम में मदियून-डिकरी की जायदाद खरीद की और उसे तीसरे आदमी के हाथ उठा दिया। अपील में डिकरी के मंसूख हो जाने से मदियून-डिकरी, जो कि असामी है, उस तीसरे आदमी के मुकाबिले में उस जायदाद पर कब्जा और उस जमीन्दार से वासिलात की रकम दिला पाने का हकदार है, देखो 24 C. W. N. 50; 51 I. C. 959; 22 C. L. J. 409.

प्रयोग और विस्तार वापसी जायदादके सम्बन्धमें—वापसी जायदाद का हुक्म उस समय भी दिया जा सकता है जब डिकरीदार ने इजरा को छोड़

किसी और तरह से जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया हो, देखो 42 A. 568; I. C. 84 (C.); 29 A. 348; 16 C. L. J. 135.

मद्रास हाईकोर्ट में यह तय हुआ है कि जाबता दीवानी की दफा १४४ अनुसार की जाने वाली वापसी जायदाद, अपील में डिकरियों के उलट जाने तक ही सीमाबद्ध नहीं है बल्कि तमाम ऐसे मामलों में उसका एक ही प्रयोग किया जा सकता है जिनमें किसी दूरिवर्ती कारवाई के कारण डिकरी उलट दी गई हो, देखो 40 M. 299; 33 I. C. 739.—इसलिए किसी एकतर्फी डिकरी की इजरा में डिकरीदार को, डिकरी की रकम जाय और इस कारण बाद में वही अदालत उस डिकरी को मंसूख कर दे मदीयून-डिकरी उस जायदाद को वापस पाने का हकदार है जो इजरा में हाथ से निकल गई है, लेकिन इसपर विचार करना व्यर्थ है कि ऐसी दफा ४७ लागू होती है या दफा १४४, देखो 44 B. 702—एक दूसरे मुकदमे में यह तय हुआ है कि जिस हुकम के अनुसार वह नीलाम मंसूख किया जा हो जो किसी एकतर्फी डिकरी की निस्वत किया गया हो, वह हुकम जाय दीवानी की दफा ४७ या १४४ या १५१ के अनुसार दिया जा सकता है, देखो 43 B. 235.—लेकिन पटना हाईकोर्ट में यह तय किया गया है कि इस दफा १४४ के “प्रारम्भिक अदालत” शब्द साफ तौर पर यह जाहिर करते हैं कि इसका प्रयोग सिर्फ उन्हीं हालतों में किया जा सकता है जिनमें डिकरी बड़ी अदालत द्वारा बदली गई हो, देखो 34 I. C. 747; 1 Pat L. J. 43.

अदालत के वापसी जायदाद का हुकम देने सम्बन्धी अधिकार का प्रयोग सिर्फ उन्हीं मामलों तक सीमाबद्ध नहीं है जो दफा १४४ में आते हैं। अदालत यह अधिकार सदैव से प्राप्त है कि वह वापसी जायदाद का हुकम दे सके किसी सच्चे मामले में अन्याय होने से रोके। वह ऐसे हुकम दे सकती है जिनकी आवश्यकता उस मामले में पूर्ण न्यान करने के लिए हो, देखो 15 C.L.J. 15; 21 C. L. J. 624; 29 A. 153; 6 C. W. N. 710; 11 C. L. J. 32 A. 79.

उसे वह रुपया वापस मांगने का भी पूरा अधिकार है जो नामुनाबत तौर पर अदा किया गया है, देखो 35 C. L. J. 53. तथा उसे डिकरीदार उस मुद्दत के वासिलात की रकम दिला पाने का अधिकार है जिसमें वह अपनी की मुलतवी के लिए दिए गए हुकम के अनुसार जायदाद से अलग रखा गया देखो 63 I. C. 43 (L.)

जब प्रारम्भिक (इब्तदाई) डिकरी मंसूख हो गई हो, तो वह फरीक रुपया वापस पाने का हकदार है जो अन्तिम (कतई) डिकरी के आधार पर वसूल किया गया था, देखो 27 C. L. J. 451.

अगर वह जायदाद, जो ले ली गई है, इस काबिल न हो कि वापस जा सके, तो पहिले वाला डिकरीदार नुकसान का देनदार होगा, देखो 3 A. 443.

रूपये के, मय ब्याज वापस किए जाने का हुक्म दिया जा सकता है, देखो 63 I. C. 513 (A.); 19 I. C. 1; 15 Bom. L. R. 41; 40 M. 299; 41 M. 316; 2 Pat. L. J. 349.

जब रकम के हिस्से-रसदी बटवारों के लिए दिया हुआ हुक्म अपील में उलट दिया गया हो, तो वापसी जायदाद के लिए हुक्म नहीं दिया जा सकता, देखो 67 I. C. 546 (M.); 67 I. C. 369 (M.).

जायत! दीवानी कीदफा १४४ उस समय लागू नहीं होती, जब कब्ज़ा डिकरी के विरुद्ध और उससे बिल्कुल अलग हासिल किया गया हो, देखो 39 I. C. 933.

कार्रवाईकी किस्म औ. मिथादे—वापसी जायदाद की कार्रवाई न तो नालिश है और न इजरा में की जाने वाली कार्रवाई। यह एक सुतफरकात की कार्रवाई है जिसके सम्बन्ध में वे नियम लागू हैं। जबकि उस अपीलाएटने जिसकी अपील जीत गई थी, पहिले तो वापसी जायदाद के लिए दरख्वास्त दी और इसके बाद अपील की डिकरी से तीन साल के अन्दर वासिलात के लिए दूसरी दरख्वास्त पेश की, तब हुआ कि आर्डर २० रूल २ से अथवा कानून मियाद के आर्टि० १८१ के अनुसार वह मियाद बाहर नहीं है, देखो 47 I. C. 47 (P.)—लेकिन एक दूसरे सुक़द्वयों में यह तय किया गया था कि कानून मियादका आर्टि० १८२ लागू होता है, देखो 2 P. 277; 72 I. C. 912.—बर्मा हाईकोर्ट में यह तय किया गया है कि कानून मियाद का आर्टि० १८१ लागू होता है, देखो 30 I. C. 680, 8 Bar. L. T. 165.

बम्बई हाईकोर्टमें यह तय हुआ है कि वापसी जायदादके लिये दीगई दरख्वास्त डिकरीकी इजराकी दरख्वास्त है और इसलिये कानून मियादका आर्टि० १८२ लागू होना चाहिये, देखो 45 B. 1137; 62 I. C. 233; 41 B. 625; 43 B. 235.—यही फैसला पंजाब (देखो 67 P. R. 1918; 44 I. C. 301,) और मद्रास (देखो 33 M. L. J. 413; 42 I. C. 530; 40 M. 780.) की हाईकोर्टोंमें हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्टमें यह तय हुआ है कि जायत! दीवानी की दफा १४४ के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई इजराकी कार्रवाई है, देखो 44 A. 407.

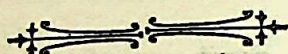
कोर्ट-फीस—वापसी जायदादके लिये दीगई दरख्वास्त पर कोर्ट-फीस स्टाम्प लगा होना चाहिये जिसका वर्णन कोर्ट-फीस ऐक्टके परिशिष्ट २ के आर्टि० १ में मामूली दरख्वास्तोंके ऊपर कोर्ट-फीस ऐक्ट लगाये जानेके सम्बन्धमें किया गया है। हाईकोर्ट में की जाने वाली अपीलके ऊपर लगाये जाने वाले कोर्ट-फीस स्टाम्प के लिये देखो 21 C. W. N. 544.

नोट—इजराका विषय बड़ा ही जटिल और पेचीदा है। यदि हम सब कानूनोंकी सब बातों का इसी जगह वर्णन करें तो एक भारी पुस्तक बन जायगी। जितनी ज़रूरी और हर समय काम पड़नेकी बातें थी उन्हें नई नज़ीरोंके साथ बड़े ही परिश्रमसे यथा स्थान उद्धृत कर दिया है। नया जायत! दीवानी

हम हिन्दीमें सबिस्तार व्याख्या और मुकम्मिल नजीगें सहित छाप रहे हैं। उसके साथ इस किताबमें कुछ से पाठकोंका काई दिक्कत कहीं पर नहीं पड़ सकती।

खास खास हालतों की नालिशें

सरकार या सरकारी कर्मचारियों की ओर से तथा उनके विरुद्ध की जाने वाली नालिशें, जबकि वे सरकारी कर्मचारीकी हैसियतमें हों



(१) सरकार की ओर से तथा उसके विरुद्ध की जाने वाली नालिशें संपन्न बहू भारत-मंत्री द्वारा या उनके विरुद्ध दायर की जानी चाहिये (देखो ज़ाबता दीवानी की दफा ७९)।

(२) कोई भी नालिश भारत-मंत्री या किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध उस कार्य के सम्बन्ध में जो कि ऐसे कर्मचारी ने सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किया हो उस समय तक नहीं दायर की जा सकती जब तक कि उस तारीख से, जिस तारीख को उसपर बाज़ाबता तरीके से नोटिस तामील की गई हो, महीने का समय बीत न जाय (देखो ज़ाबता दीवानी की दफा ८०)।

(३) सरकार तथा सरकारी कर्मचारियों की ओर से तथा उनके विरुद्ध की जाने वाली नालिशों के सम्बन्ध में की जाने वाली विस्तृत कार्रवाईके लिये देखो आर्डर २७ रूल १-८।

“उस कार्य के सम्बन्ध में” इस वाक्यका केवल सरकारी कर्मचारी ही सम्बन्ध है, भारत मंत्री से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये कोई भी नालिश (फिर वह चाहे जैसी ही क्यों न हो) भारत-मंत्री के विरुद्ध न दायर की जा सकेगी, जब तक कि उन्हें बाक़ायदा नोटिस न दे दी जाय। इसकी कोई परवाह नहीं कि वह कार्य उन्होंने भारत मंत्री की हैसियत से किया था अथवा नहीं (देखो 25 C. 239; 40 B. 392; 37 M. 113—सरकारी कर्मचारियों के लिये नोटिस देने की उसी समय आवश्यकता है जब नालिश किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में दायर की गई हो जो उसने सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किया हो उस समय नोटिस देने की आवश्यकता न होगी जब जिस काम की निस्वतः शिकायत है वह उसने सरकारी कर्मचारी की हैसियत से न किया हो। इस तरह पर कोई कर्मचारी किसी ऐसी जायदाद पर कब्ज़ा कर ले जिसके कब्ज़े का उसे कोई अधिकार नहीं है और मदाखिलत बेजा करे, तो नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं, देखो 36 C. 28—इसी प्रकार किसी मातहत अफसरके ऊपर आक्रमण करने के हर्जों की नालिशों के सम्बन्ध में भी नोटिस देनेकी ज़रूरत नहीं है, देखो 7 A. J. 301.

7 C. 499 में यह तय किया गया था कि नोटिस का देना सिर्फ उन्हीं हालतोंमें जरूरी है जब किसी सरकारी कर्मचारीने अपने कर्तव्य पालन में असावधानताके कारण कोई हानि पहुंचाई हो और 16 C. W. N. 145 में यह तय हुआ था कि किसी ऐसे काम के बारे में नोटिस देने की जरूरत नहीं है जो बदनीयती से किया गया हो लेकिन अब कई एक मुकद्दमों में यह तय किया गया है कि उस काम के सम्बन्ध में भी नोटिस देने की जरूरत है जो बदनीयती से किया गया हो और जो उसने सरकारी कर्मचारी की हैसियत में किया हो देखो 28 C. W. N. 10; 24 C. 584; 41 M. 792. F. B; 16 C. W. N. 145; 32 C. 1130; 7 C. 499—अन्त वाले इस मुकद्दमें में चीफ जस्टिस वेलिस ने तय किया था कि “ कोई काम जो उसने सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किया हो ” का अर्थ है “ कोई काम जिसका भंशा यह दिखलाने का हो कि उसने उसे सरकारी कर्मचारी की हैसियत से किया है ” ।

नोटिस की सिर्फ उसी काम के सम्बन्ध में जरूरत होती है जो किया गया हो और इसलिये जाबता दीवानी की दफा ८० ऐसी नालिश के सम्बन्ध में लागू नहीं होती जो किसी सरकारी कर्मचारी को किसी ऐसे काम के करने से रोकने के लिये हुक्म इम्तनाई जारी करने के वास्ते दायर की गई हो जिसके करने की उसने धमका दी हो देखो 3 I.C. 28; 37 B. 243; किन्तु भारत मंत्री के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है देखो 35 B. 362; 26 B. 424; 37 M. 113.

ऐसी नालिशों में सरकारी वकीलका मेमोरैण्डम—हर एक ऐसी नालिश में जिसमें सरकारी वकील सरकार की ओर से पेश हुआ हो चाहे उस समय जब कि सरकार स्वयं मुद्दा या मुद्दाअलेह हो या उस समय जबकि वह जाबता दीवानीके आर्डर २७ रूल ८ के अनुसार किसी ऐसी नालिश को जवाब देही करने के लिये खड़ी हुई हो जो किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर दायर की गई है । उसे चाहिये कि वह वकालतनामा के बदले एक बिना स्टाम्प लगे हुये कागज़ पर लिखकर मेमोरैण्डम पेश करे जिसपर उसके हस्ताक्षर हों और जिसमें यह लिखा हो कि किस की ओर से वह हाज़िर हो रहा है (देखो G. R. & C.O. Chap I. R. 142).

हर एक ऐसे मुकद्दमेंमें जिसमें सरकारी वकील किसी सरकारी अफसर या नौकरकी ओर से हाज़िर होगा सिवाय उन मुकद्दमों के जिनमें सरकारने जाबता दीवानी के आर्डर २७ रूल ८ के अनुसार किसी नालिश को जवाबदेही करने का भार अपने ऊपर ले लिया है ऐसे वकील को उसी प्रकार वकालत नामा दाखिल करना होगा जैसेकि किसी दूसरे वकीलको (देखो G. R. & C.O. Chap. I. R. 135 note)

इलाहाबाद में सरकारी वकील के हाज़िर होने सम्बन्धी नियमों के लिये देखो आर्डर २७ रूल ९ ।

विदेशियों की ओर से तथा विदेशी और देशी राजाओं की ओर से अथवा उनके बिरुद्ध नालिशों—विदेशियों की ओर से तथा विदेशी और देशी राजाओं की ओर से या

उनके विरुद्ध दायर की जाने वाली नालिशों के ज़ाबते के सम्बन्ध में देखो ज़ाबता दीवानी की दफा ८३ से ८८ तक ।

फौजी आदमियों की ओर से अथवा उनके विरुद्ध नालिशें—फौजी आदमियों की ओर से या उनके विरुद्ध दायर की जाने वाली नालिशों के ज़ाबते के सम्बन्ध में देखो ज़ाबता दीवानी का आर्डर २८ ।

कारपोरेशनों की ओर से अथवा उनके विरुद्ध नालिशें—प्लीडिङ्स की तारीखों और उस पर दस्तखत किये जाने तथा सम्मन की तामीलीके तरीके की ज़ाबता देखो ज़ाबता दीवानी; आर्डर २९ ।

बिना रजिस्ट्री की हुई समाजों की ओर से नालिश—किसी बिना रजिस्ट्री की संस्था की ओर से दायर की जाने वाली नालिशें उस संस्थाके कुल सदस्यों (मेम्बर्स) के नाम से दायर की जानी चाहिये (देखो 20 A. 167) अर्जी के ऊपर कौन शर्हें दस्तखत कर सकता है या कौन उसकी तस्दीक कर सकता है इस सम्बन्धमें देखो 21 C. 60.

फर्मों और ऐसे लोगों की ओरसे जो अपने नामसे व्यापार न करते हों, या उनके नालिशें—सम्मनों की तामीली के तरीके और आम ज़ाबते के लिये देखो ज़ाबता दीवानी आर्डर ३ ।

मुश्तर्का जायदाद की कुर्कियाँ और फर्मों के खिलाफ दी गई डिकारियों—इजरा सम्बन्धी नियमों के लिये देखो आर्डर २१ रूल ४९ और ५० ।

ट्रस्टियों, मृत लेख प्रवर्तकों (तामील कुनिन्दों) और प्रबन्धकों की ओरसे या उनके नालिशें—जब ऐसे लोग जिनको जायदाद से फायदा उठाने का हक हासिल फरीक बनाये जायं उस सम्बन्ध में और दूसरी बातों के सम्बन्ध में देखो आर्डर २१ ज़ाबता दीवानी । उन लोगों को जिन्हें जायदाद से फायदा उठाने का हक (मामूनअलेहों को) उस समय फरीक बनाना चाहिये कि जब ट्रस्टियों को लोगों के हक़ों के खिलाफ कोई हक़ हासिल हो (देखो M. A. 197) ।

पंजाब में आर्डर ३० रूल १ के साथ में कुछ विवरण जोड़ दिया गया है नावालिग या ऐसे लोगों की ओर से या उनके विरुद्ध नालिशें जिनके मन्तिक (द्वि-मै दौप (खलल) हो—किन्ती ना नावालिग की ओर से दायर की जाने वाली नालिशें उसके वलीजायज (Nextfriend) के नाम से दाखिल की जानी चाहिये तभी अर्जी दावा मिसिल से बाहर निकाल दिया जायगा और इन सबका खर्चा वह या उस शर्ह जो देना होगा जिसने उसे दाखिल किया है [देखो आर्डर रूल २)]

जब मुद्दालेह नावालिग हो तो मुकद्दमेंके दौरानके लिये एक वली मुकद्दम कर दिया जाना चाहिये । वली मुकद्दम करने के लिये हुक्म उस नावालिग के पास से और उसकी ओरसे या मुद्दई की ओर से दरख्वास्त देकर हासिल किया जा सकता है । उस दरख्वास्त के साथ उसकी ताईदके लिये एक बयान दिये

दाखिल किया जाना चाहिये कि जिस शख्स को वली मुक़रर करनेकी तजवीज़ की गई है उसका उस नालिशसे कोई भी ऐसा ताअल्लुक नहीं है जो उस वलीके खिलाफ पड़ता हो और यह कि वह शख्स इस कामके लिये निहायत माकूल आदमी हो। सिवाय उस नाबालिग, और किसी ऐसे वलीको, जिसे किसी मुनासिब अफसर ने मुक़रर किया हो या जहां कोई ऐसा वली नहीं है उसके बाप या दूसरे प्रकृति जन्य संरक्षक (वली) को या जहां बाप या कोई ऐसा प्रकृति जन्य संरक्षक नहीं हैं उस शख्स को जिसकी संरक्षता में वह नाबालिग है, नोटिस दिये जाने और उस उज्रदारी को सुन लेने के बाद, जो किसी ऐसे आदमीकी ओरसे पेश का गई हो, जिस पर इस तरह नोटिस तामील किया गया है कोई हुक्म न दिया जायगा (आर्डर ३२ रूल ३)।

कौन शख्स वली होने के क़ाबिल है इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ३२ रूल ४ और देखो हिन्दी में छपा हिन्दू-लॉ, का प्रकरण "नाबालिग और वली" कोई भी शख्स बिना उसकी मज़रीके वली न मुक़रर किया जासकेगा। जब कोई दूसरा क़ाबिल और वली का काम करने के लिये राज़ी होने वाला शख्स न मिल सके तो अदालत को अख्तियार है कि वह अपने में से किसी भी अफसर को मुक़रर कर दे और यह हुक्म देदे कि कुल खर्चा मुद्दई की ओर से अदा किया जाय (आर्डर ३२ रूल ४),

नाबालिग की ओर से रफ़ीक़ करीबतर (Nextfriend) या वली (Guardian) द्वारा ऐसी नालिश के लिये जिसमें सही सही आदमी फरीक़ बनाए गये हैं दी जाने वाली दरख़वास्तें और वकील की जिम्मेदारीके सम्बन्धमें देखो आर्डर ३२ रूल ५। रफ़ीक़ करीबतर (Nextfriend) या वली (Guardian) द्वारा नाबालिग की जायदाद लियेजाने के सम्बन्धमें देखो आर्डर ३२ रूल ६।

बिना अदालतकी इजाज़तके जो साफ़ साफ़ लिख दी जायगी कोईभी वली (Guardian) या रफ़ीक़ करीबतर (Nextfriend) मुक़द्दमोंमें राज़ीनामा न कर सकेगा जो इकरारनामा या अहदनामा बिना अदालत की इजाज़तके कर लिया जायगा वह नाबालिग के सिवा बाकी सभी लोगों के सम्बन्ध में जायज़ होगा देखो आर्डर ३२ रूल ७ (२)।

रफ़ीक़ करीबतर (Nextfriend) के अलग हो जाने या हटाये जानेके सम्बन्ध में देखो आर्डर ३२ रूल ८-१४। रूल १-१४ उन लोगों के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिनके दिमाग में खलल है देखो आर्डर ३२ रूल १५।

जब मुद्दाअलेह नाबालिग हो तो मुद्दई पहिले एक दरख़वास्त देकर किसी शख्स को वली मुक़रर किये जाने की तजवीज़ पेश करेगा और अपनी उस दरख़वास्त के समर्थन में एक हलफनामा दाखिल करेगा जिसमें यह दिखलायेगा कि जिस शख्स को वली बनाने की तजवीज़ पेश की गई है उसका उस मुक़द्दमें से कोई भी ऐसा सम्बन्ध नहीं है जो उस नाबालिग के खिलाफ पड़ता हो और यह कि वह शख्स वली मुक़रर किये जानेके लिये एक निहायत माकूल आदमी

है। अगर उस शख्स और उस नाबालिग के दरम्यान कोई रिश्तेदारी है तो भी लिख दिया जाना चाहिये। और यह भी लिख देना चाहिये कि किसकी देख में वह नाबालिग रहता है (देखो आर्डर ३२ रूल ३ कलॉज ३) — बाद उस शख्स के नाम इस बात का नोटिस निकाला जायगा कि वह मुकदमा पर (यह तारीख उसी नोटिसमें लिखी रहेगी) अदालतमें हाज़िर अपनी उज्रदारी, अगर कोई हो दाखिल करे या अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर करे। भी शख्स बिना उसकी रज़ामंदीके दौरान मुकदमाके लिये वली न मुकदमा जायगा। और यह तय हुआ है कि उस शख्स की गैर हाज़िरी से ही यह मान न कर लेना चाहिये कि वह वली बनाया जाने के लिये राज़ी है। आर्डर रूल ४ में रज़ामंदी का मतलब ऐसी रज़ामंदी से है जो ज़ाहिरा तौर पर दी गई हो। जिस शख्स के नाम नोटिस जारी किया गया है वह उस समय वली दौरान मुकदमा (Guardian ad litem) मुकदमा नहीं किया जा सकता तक कि वह हाज़िर होकर इस बात के लिये अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर न करे और कोई ऐसी ही बात न करदे जो रज़ामंदी के बराबर मान लिये जाने लगे हो, उदाहरणार्थ नाबालिग की ओर से बयान तहरीरी का दाखिल इत्यादि (देखो 17 C. W. N. 219; 29 I. C. 579; 15 C. L. J. 3; 15 C. W. N. 201 P. C.; 24 C. 25; 15 C. L. J. 3; 18 C. L. J. 15 C. L. J. 446; 16 C. L. J. 318; 20 C. L. J. 469; 26 C. L. 258; 13 C. W. N. 1182 P. C.; 17 C. W. N. 1165 P. C.; 24 C. W. N. 541; W. N. 525.) वलीकी मंजूरी सम्बन्धी जो व्यवस्था है वह ताकीदी है। जो बिना मंजूरीके वली मुकदमा कर दिया गया है वह नाबालिगका प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता, देखो 34 C. L. J. 293; 37 C. L. J. 496 — किसी सर्टिफिकेटयापता की ज़ाहिरा मंजूरी भी ज़रूरी है, देखो 34 C. L. J. 293 और इसके फ़ैजलेके लिए 2 Pat. 296। मद्रास हाईकोर्टमें यह तय हुआ है कि जहाँ सर्टिफिकेटयापता वली मौजूद हो और दूसरा शख्स मुकदमा कर दिया हो, तो ऐसी हालतमें वह हुक्म खिलाफ़ कानून होगा, देखो 43 M. 148.

कुछ मुकदमोंमें यह तय किया गया है कि ज़ाहिरा मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, वह ऐसी भी हो सकती है जो दूसरी बातोंसे समझ ली जाय, देखो 296; 43 I. C. 63; 59 I. C. 671; (43 A. 104; 71 I. C. 628 M.)

जब वह शख्स जो वली तजवीज़ किया गया है हाज़िर न हो और मंजूरी न दे तो अदालत इस बातके लिये बाध्य है कि वह अपने में से ही हाकिमको वली दौरान मुकदमा (Guardian ad litem) मुकदमा कर दे उसे आर्डर ३२ रूल ४ के अनुसार रुपया वगैरा दे दे ताकि वह मुकदमा जवाब देदी की निश्चय जांच कर सके या अगर ज़रूरी हो तो जवाबके लिये सके (देखो 37 A. 179.) कलकत्तेकी हाईकोर्टने यह हुक्म दिया है कि वली मुकदमा किए जाने चाहिए। किसी भी अदालतके अफसरको जो वली मुकदमामें मुकदमा किया गया है उसकी मेहनतका मुआमिज़ा न दिया

चाहिए, (देखो 3 M. I. A. 339)—अगर कोई शख्स वली दौरान मुकद्दमा मुकदर्र नहीं किया गया है और मुकद्दमेंकी डिकरी नाबालिगके खिलाफ दे दी गई है, तो वह डिकरी, जहां तक उसका सम्बन्ध उस नाबालिगसे है, नाजायज़ समझी जायगी और मंसूखीके लिए बिना कोई कार्रवाई किए हो, वह रद्द समझी जायगी, (देखो 17 C. W. N. 49.)—यहो नतीजा उस समय भी होगा जब कि वली नाम मात्रके लिए मुकदर्र किया गया हो लेकिन उसने ठीक तौर पर [उस नाबालिगके प्रतिनिधिका काम न किया हो (देखो 37 A. I 79; 39 C.L. J. 496 और 71 I. C. 70)—जब किसी नाबालिगकी ओरसे दायर की गई नालिशमें डिकरी इस बिना पर मंसूख या रद्द कर दी गई है कि उसकी ओरसे कोई प्रतिनिधि मुकद्दमेंमें नहीं था तो पहिली नालिश पर फिरसे विचार किया जा सकता है, देखो 2 C. L. J. 258; 78 I C. 427

रूपकी अदायगीके लिए दी गई डिकरियोंमें, पहिली नालिशमें मुकदर्र किया हुआ वली दौरान मुकद्दमा इजराकी कार्रवाईमें वली नहीं बना रह सकता जब तक वह फिरसे न मुकदर्र किया गया हो, देखो 28 C. W. N. 963.

राजीनामा—राजीनामा करनेके लिए हुक्म देते समय अदालतको चाहिए कि वह आर्डर ३२ रूल ७ (१) में बतलाए अनुसार अपना हुक्म लिखे। यह तय किया गया है कि ज़ाहिरा हुक्म लिखनेकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब कि अदालतने दरखास्तकी निश्चित नोट कर लिया है और डिकरी दे दी हो, देखो 72 I. C. 1049; 56 I. C. 97 और 35 I. C. 67. एक मुकद्दमेंमें यह तय हुआ है कि सिर्फ यह बात, कि राजीनामाके लिए दी गई दरखास्त से अदालतको इस बात का पता लग गया था कि नाबालिगके हकूकको नुकसान पहुंचेगा और यह कि उसने डिकरी दे दी, इजाज़त देना नहीं है। इस बातकी ओर अदालतका ध्यान विशेष रूपसे आकृष्ट किया जाना और उस सम्बन्धमें उसकी स्वीकृति ले लेना परमावश्यक है, देखो 60 I. C. 980—रिवाज़ यह है कि राजीनामाकी दरखास्तके साथ एक अलग दरखास्त दाखिल की जाय और जिस हुक्मसे इजाज़त दी गई हो वह फर्द हुक्ममें लिख दिया जाय।

मुफ़लिस (Pauper) की ओरसे नालिश—साधारण नियम तो यह है कि अदालत दीवानीमें नालिश करने वाला शख्स अर्जीदावा और नालिशमें बादको होने वाली कार्रवाईके लिए क़ानून द्वारा निश्चित किया हुआ कोर्ट-फीस अदा करे। लेकिन सम्भव है कि कोई शख्स इतना ग़रीब हो कि वह रसूम अदालत अदा नहीं कर सकता है और इसलिए आर्डर ३३ का यह मंशा है कि ऐसे शख्स को बिना रसूम अदालत (कोर्ट-फीस) अदा किये हुये नालिश दायर करने और उसके चलानेकी इजाज़त दी जाय, (देखो 20 C. 115)

आर्डर ३३ के रूल २ से ८ तक में उस ज़ाबतेका वर्णन है जो उस समय अमलमें लाया जाना चाहिये जब किसी नालिशके सीगा मुफ़लिसीमें दायर किये जानेकी तजवीज़ हुई हो।

मुफ़लिसोंकी नालिशोंमें दरख्वास्तमें लिखी जाने वाली बातों और उसकी तस्दीक क तरीकेकी निस्वत देखो रूल २ ।

सीमा मुफ़लिसीमें नालिश करनेकी दरख्वास्त सायलको असाबतन पेश करनी चाहिये, सिवाय उस हालतके जब कि वह हाज़िर होनेसे मुस्तसना कर दिया गया हो, देखो आर्डर ३३ रूल ३—यह दरख्वास्त आर्डर ३ रूल १ और आर्डर ११ रूल १४ में बतलाये अनुसार पेश नहीं की जा सकती, (देखो आर्डर ३३ रूल ४)

किन वजूहात पर अदालत दरख्वास्त खारिज कर सकती है, इस सम्बन्ध में देखो आर्डर ३३ रूल ५ । अगर रूल ५ के अनुसार दरख्वास्त खारिज नहीं कर दी गई है, तो अदालत शहादत लेनेके लिये कोई दिन नियत (मुकरर) करेगी (जिसकी नेटिस कमसे कम १० दिन पहिले सरकारी वकील और फ़रीक़सानीको दे दी जायगी) [देखो रूल ६]—शहादत लेनेके बाद, अदालत या तो मुफ़लिस की हैसियतसे नालिश दायर करने की इजाज़त दे देगी या ऐसी इजाज़त देनेसे इन्कार कर देगी (देखो रूल ७)—अगर दरख्वास्त मंज़ूर कर ली जायगी, तो उस पर नम्बर डालकर वह बतौर अर्जीदावाके रजिस्टर पर चढ़ा ली जायगी (रूल ८)—किन वजहोंपर मुद्दई मुफ़लिस नहीं करार दिया जा सकता है इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ३३ रूल ९ ।

अगर मुफ़लिस (Pauper) मुक़दममें जीत जायगा, तो सरकार कोई फ़ीसकी रक़म उस शख़्ससे वसूल कर लेगी जिसे डिकरीके ज़रिये इस रक़मके अदा करने का हुक़म दिया गया है, और यह रक़म उस नालिशके मतालिबा पर पहला बार होगा, (देखो रूल १०)

अगर मुद्दई मुक़दमा हार जाय या वह मुफ़लिस न करार दिया जाय या जब मुद्दाअलेहके ऊपर सम्मन तामील किये जानेके लिये मुद्दईकी ओरसे तलबना दाख़िल न किये जानेके कारण नालिश उठा ली गई हो या खारिज होगई हो, तो अदालत उसे उस कोर्ट-फीस के अदा करनेका हुक़म देगी जो उस पर बांकी है (देखो रूल ११)

तमाम ऐसे सवालात, जो रूल १०, ११, १२ के अनुसार सरकार और किसी फ़रीक़के बीच पैदा होंगे, ज़ाबता दीवानीकी दफा ४७ के अन्तर्गत सभ्य जायंगे (देखो रूल १३)—डिकरीकी एक नक़ल कलकूरके पास भेजी जानी चाहिए (देखो रूल १४)—सायलको बहैसियत मुफ़लिस नालिश करनेकी इजाज़त देनेसे इन्कार कर दिए जाने पर बादमें फिर उसी हैसियतसे नालिश करने के सम्बन्धमें दरख्वास्त न दी जा सकेगी, लेकिन सायलको आम तौर पर नालिश दायर कर सकनेका अक़्त्यार होना बशर्त कि वह पहले अपनी पहिले वाली दरख्वास्तका खर्चा (अगर कोई हो) सरकार और फ़रीक़सानी को अदा कर दे (देखो रूल १५)

जब बहैसियत मुफ़लिस नालिश करनेकी इजाज़त हासिल करने के लिये दी गई दरख्वास्त मंज़ूर कर ली गई हो, तो मुद्दई किसी भी अर्जीके, वकीलकी नियुक्ति

अथवा किसी दूसरी कार्यवाईके सम्बन्धमें किसी कोर्ट-फीसका देनदार न होगा । लेकिन सम्मनकी तामीलीके लिए फीस तलवानाकी अदायगीसे वह नहीं बच सकता (देखो आर्डर ३३ रूल ८)

जब रूल ४ के अनुसार मुद्दईके बयान लिये गये हों, तो बिरोधी पक्ष (फ्री कसानी) को यह अधिकार है कि वह उस पर उसके दावाकी असलियतके सम्बन्धमें जिरह कर सके, देखो 60 I. C. 738—तहकीकात (जांच) करने के वक्त अदालत रूल ४ के अनुसार उसके दावाकी असलियतके निस्वत सिवाय सायलके बयानों के और किसी की शहादत नहीं ले सकती, देखो 50 I. C. 676; 46 C. 651.

रूल ७ के अनुसार मुकद्दमेंकी समाप्त करते वक्त अदालत मियादके सवालात फंसल करने अथवा सायलकी मुफलिसीको छोड़ और किसी सवालको तय करने के लिए गवाहोंके बयान नहीं ले सकती, देखो 46 C. 651; 50 I. C. 520.

साधारण तौर पर दायर की हुई नालिश सीगा मुफलिसीमें जारी रखी जा सकती है, देखो 20 C. 319; 2 C. 130; 8 B. 615.

मुद्दाअलेहको सीगा मुफलिसीमें दायर कीगई किसी नालिशमें पैरवी करने की इजाजत दी जा सकती है, देखो 5 C. 819.

किसी नाबालिग का रफीक कुरीबतर (निकट वली Next friend) सीगा मुफलिसीमें नालिश दायर कर सकता है, देखो 3M.3; 4B.L.R.373.

कोई प्रबन्धक या तामील कुनिन्दा सीगा मुफलिसीमें नालिश कर सकता है, देखो 7 M. 390; 18 B.237.

किसी ऐसे शख्सके हकमें, जिसने सीगा मुफलिसीमें नालिश दायरकी है, फैसला दे देने के बाद जब उस तारीखसे, जिसमें दिन डिकरी पर दस्तखत किये गये थे, सात दिनके भीतर सरकारी वकीलको उस डिकरीकी एक नकल दे देगा, देखो G. R. & C. O. Chap. I. R.139.

रेहननामोंके सम्बन्धमें नालिशें—ऐसी नालिशें जाबता दीवानीके आर्डर ३४ रूल १ से १५ तकके अनुसारकी जा सकती हैं । पहले ऐसीही व्यवस्था कानून इन्तकाल जायदादमें कीगई थी लेकिन चूंकि रेहननामोंकी निस्वत कीगई नालिशोंकी इजरा के सम्बन्धमें जाबता दीवानी और कानून इन्तकाल जायदादमें कीगई व्यवस्थाके कारण कुछ गड़बड़ी पैदा होगई, इसलिये कुछ बातें जाबता दीवानीमें ही कर दी गई हैं । कानून इन्तकाल जायदादमें आखिरी (कतई) डिकरी देनेके सम्बन्धमें कोई व्यवस्था नहीं थी और नीलामके लिये कतई हुक्म दिये जानेके वास्ते दीगई दरखास्त इजराकी दरखास्त समझी जाती थी । अब आर्डर ३४ के रूल ३ (१); ५ (१) और ८ (१) से यह कमी पूरी कर दीगई है ।

कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ५८ में रेहननामा की परिभाषा कीगई है । रेहननामामें जिन बातोंका होना जरूरी है वे ये हैं:—

१ हकूककी मुन्तकिली,
 २ जायदाद गैर-मनकूला खासमें हकूका होना, और
 ३ कुर्जेके रुपयेकी अदायगीकी जमानत । कानून इन्तकाल जायदादमें चार
 किस्मके रेहननामें बतलाये गये हैं जैसे—

(अ) सादा रेहननामा—इसकी ज़रूरी बातें ये हैं:—

१. जायदाद गैर-मनकूला खासमें हासिल हकूककी मुन्तकिली वतौर जमानत
 वास्ते अदायगी कुर्जाके,

२ रुपया अदा कर देनेका वादा,

३ इस बातका प्रकट अथवा अप्रकट इकरार कि रुपया न अदा होनेकी हालत
 में मुर्तहिनको जायदाद नीलाम करानेका अधिकार होगा । जायदाद बिल्कुल
 हवाले नहीं कर दी जाती है ।

सादा रेहननामा रजिस्ट्री शुद्ध दस्तावेज़के ऊपर होना चाहिये यद्यपि कुर्जे
 का रुपया १०० रु० से नीचे ही क्यों न हो (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी
 दफा ५९) । बंगालमें इसे बंधकी या रेहनी खत कहते हैं; बम्बईमें 'दृष्ट बन्धक' या
 नज़र गहन या तरन गहन, मदरासमें दृष्ट बंधक या टणक (Taneka) और
 संयुक्त प्रांतमें रेहन या मुस्तगरक कहते हैं ।

बार किफालत और रेहननामामें सिर्फ अन्तर यह है कि बार किफालत
 (Charge) से हकीयतकी मुन्तकिली नहीं हो जाती है, बल्कि उसमें सिर्फ
 अधिकार रहता है कि किसी खास रकम या जायदादसे रुपयेकी अदायगी कर
 जाय, (देखो 33 C. 985; 25 M. 220; 35 C. 837; 36 A. 201; 1 Pat
 387. और कानून इन्तकाल जायदादकी दफा १००)

सादे रेहनकी बाबत दायर फौगई नालिशमें, जितने पर मुर्तहिन को फौ
 प्रारम्भिक डिकरी मिल जाती है जिसमें मुद्दाअलेहके लिये यह हुक्म दिया जाता
 है कि वह अधिकसे अधिक छः महीने के भीतर डिकरीका रुपया अदा करे
 (देखो आर्डर ३४ रूल ४) —और अगर निश्चित समय (वक्त मुकरर) के
 भीतर वह रुपया अदा नहीं कर दिया जाता तो मुर्तहिनके दरखवास्त देने पर
 आर्डर ३४ रूल ५ के अनुसार नीलामकी डिकरी मिल जाती है । अदालतको सवा
 बढ़ानेका कोई अधिकार नहीं है । इसमें बयचातका कोई हक नहीं है, (देखो कानून
 इन्तकाल जमयदादकी दफा ६७) । राहिन फकरेहनीके लिये दावा कर सकता है
 (देखो आर्डर ३४, रूल ७)

नालिश करनेकी मियाद की व्यवस्था अब कानून मियादके परिशिष्ट २ के
 आर्टि० १३२ से (रुपया वापस कर देने की तारीखसे १२ साल) होती है, आर्टि०
 १४७ से नहीं, (देखो 30 M. 426 P. C; 11 C. W. N. 1005)

(ब) रेहननामा बयाने बयनामा—इसमें होनेवाली ज़रूरी ज़रूरी बातें ये हैं—
 इस शर्तके ऊपर ज़ाहिरा बयनामा होता है कि (क) अगर अमुक तारीख

को रुपया न अदा कर दिया जायगा तो बयनामा कतई हो जायगा, या (ख) इस रुपयेके अदा हो जाने पर बयनामा नाजायज़ हो जायगा, या (ग) यह कि खरीदार इस रुपयेके अदा कर दिये जाने पर जायदाद वापस कर देगा ।

बंगालमें इसे "कोट किवाला" या "कोट बंधक" बम्बईमें "गहन लहन" मद्रासमें "मुदतक्रियम" या "मेदतु क्रियम" और संयुक्त प्रान्तमें "बय बिलवफा" कहते हैं । ऐसे रेहननामोंमें किसी खास तारीख का हाना निहायत ज़रूरी है जिसपर रुपयेकी अदायगी हो जानी ज़रूरी है (देखो 11 C. W.W. 400.)

इस किस्मके रेहननामोंके सम्बन्धमें जो कुछ भी विधायत हो सकती है वह सिर्फ बयबात के लिये नालिशका दायर करना है, (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६७)—पहले जायदादीवानोंके आर्डर ३४ रूल २ के अनुसार प्रारम्भिक डिकरी दी जाती है और अगर डिकरीका रुपया उस मुदतके अन्दर अदा न कर दिया गया जो अदालतने इसके लिये मुक़र्रर कर दी है, तो मुर्तहिनके दखलास्त देने पर रूल ३ के अनुसार कतई डिकरी दे दी जायगी जिससे फिर फ़क-रेहनीका हक़ मारा जायगा । अदालतको रुपयेकी अदायगीका समय बढ़ा सकने का अधिकार है, (देखो आर्डर ३४ रूल ३)

नालिश दायर करनेकी मियादकी व्यवस्था कानून मियादके आर्टि० १३५ के अनुसार होती है, (देखो 16 C. 639; P. C; 27 C. 185).

(स) रेहननामा दखली—इसकी ज़रूरी ज़रूरी बातें ये हैं:—

१ जायदाद मरहूना के ऊपर दखल (कब्ज़ा) का दे दिया जाना,

२ रेहन का रुपया अदा न कर देने तक मुर्तहिन अपना कब्ज़ा बनाए रखता है

३ मुर्तहिन ब्याजके बदले या रेहनके रुपयके बदले अथवा कुछ ब्याजके बदले और कुछ रेहनके रुपये के बदले लगान और मुनाफ़ेकी तहसील वसूल करता है, (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ५८)

दखली रेहननामोंमें आम तौरपर रुपये की अदायगी के लिए कोई खास तारीख़ मुक़र्रर नहीं की जाती है और रेहन के रुपयकी अदायगी न होने तक मुर्तहिन कब्ज़ा बनाए रखता है । जब रुपयेकी अदायगी के लिए कोई खास तारीख़ मुक़र्रर कर दी जाती है, तो वह लिखा-पट्टी रेहननामा दखली और रेहन सादा दोनों हो जाती है, (देखो Pat. 350; 3 P. L. T. 322; 12 A. 203)—अगर रुपयकी तादाद १०० रु० या अधिक हो तो दखली रेहननामा का रजिस्ट्री शुदः दस्तावेज़ पर होना निहायत ज़रूरी है । अगर वह रुपया १०० रु० से कम है, तो या तो इसके लिए रजिस्ट्री शुदः दस्तावेज़ लिखा जा सकता है या जायदाद पर दखल दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत में वह बिना रजिस्ट्री शुदः दस्तावेज़ के लिखा न जायगा (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ५९)—इस बातका स्मरण रखना ज़रूरी है कि, मुर्तहिन दखलीको इस हैसियतमें बयबात या नीलामके लिए दावा करने का हक़ नहीं है, (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६७; 24 C. 677; 11

A. 367; 12 M. 109); लेकिन उस हालतमें नीलामका हक पैदा होता है जब कि दस्तावेजमें इसके लिये कोई खास शर्त हो । 7 A. 553 F.B. में जस्टिस महमूदने कहा था कि रेहन दखली में हक-मिलिकयत की सुन्तकिली नहीं आती है । लेकिन उसी मुकद्दमेंमें चीफ जस्टिस पेथेरमने भिन्न राय कायम की है ।

बंगालमें रेहन दखलीको “खाय ख़लासी बंधक” या “भोग बंधक” अथवा “दामशुदी इजारा” या “गिरबी” या “सुध भरन” और मदरासमें ‘स्वाधीन ग़ामनुए’ कहते हैं संयुक्त प्रांतमें ‘दखली रेहन,’ रेहन ‘बाकब्ज़ा’ कहते हैं ।

मुर्तहिन को कर्ज़का रुपया अदा न होने तक पूराकब्ज़ा बनाए रखनेका हक बना रहता है । राहिनके जायदाद पर कब्ज़ा न देने पर वह रेहनके रुपयों या उस जायदाद पर कब्ज़ा दिलापाने के लिए नालिश कर सकता है और इसमें राहिन या और कोई आदमी कोई आपत्ति न कर सकेगा [देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६८ (सी)]—अगर दखल पा जावे ब.द. मुर्तहिन दखलीका कब्ज़ा छिन जाय तो यह समझना चाहिए कि उसने ऐसा कब्ज़ा हासिल नहीं किया था जिसमें कोई शख्स कोई आपत्ति न कर सकता, देखो 2 Pat. L. T. 229—मुर्तहिन दखलीको बयबात या नीलामका कोई हक नहीं है, जब तक कि मुआहिदेके अन्दर प्रकट अथवा अप्रकट कोई ऐसी बात न हो जो उसे ऐसा अधिकार देती हो (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ६७)—मुर्तहिन दखली जायदाद पर कब्ज़ा दिला पाने तथा उस लगान और मुनाफ़ाको वसूल पानेके लिए भी नालिश दायर कर सकता है जो राहिन ने उस बीचमें वसूल किया हो जब कि वह (मुर्तहिन) कब्ज़ेसे बाहर रखा गया है, देखो कानून मियादका आर्टि० १२०; दफा २० (२) दखली राहिन एक रेहनी के लिए नालिश कर सकता है ।

दखली राहिन बज़ात खुद कर्ज़ की अदायगी के लिए ज़ुम्मेदार नहीं है देखो 12 M. 109, 24 C. 677.

(ई) रेहन अङ्ग्रेजी—आवश्यक शर्तें ये हैं:—(१) राहिन किसी खास तारीख़ को रुपया अदा करने का वादा कर देता है और (२) जायदाद बिल्कुल मुर्तहिन को सुन्तकिल कर देता है, इस शर्त पर कि वह जायदाद तारीख़ मुक़रर पर रुपया अदा कर दिए जाने पर फिर उसको (राहिन को) वापस कर दी जायगी । यह करीब करीब रेहननामा बशर्त बयनामा के समान है जिसका हमारे हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा चलन है (देखो 25 M. 220) अन्तर केवल इतना ही है कि इस किसम के रेहननामा में इस बात की ज़रूरत नहीं है कि रुपया असालतन हाज़िर होकर जमा किया जाय ।

रेहननामा अंग्रेजी में बयबात की नालिश दायर की जा सकती है और मियाद का प्रश्न कानून मियाद के आर्टि० १४७ के अनुसार तय किया जाता है देखो 30 M. 426, P. C. ; 11 C. W. N. 1005.

(व) रेहन ग़ैर-मामूली—ऐसे भी रेहन होते हैं जो ऊपर बतलाए हुए किसी भी रेहन के अन्दर नहीं आते हैं लेकिन उनमें से दो अथवा अधिक

किस्म के रेहनों का मिश्रण (मिलाव) होता हैं। अधिकतर रेहननामों इसी तरह हुआ करते हैं और वे रेहन "गैर-मामूली" के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन रेहननामों के अनुसार होने वाले अधिकारों और जुम्मेदारियों का तस्फिया (निर्णय) फरीकैन के बीच हुए मुआहिदे से किया जाता है (देखो कानून इन्तकाल जायदाद की दफा ९८, 27 M. 600; 35 C. L. J. 468 p. C.; 43 M. 589 F. B.)

जब राहिन जायदाद पर कब्ज़ा दे देता है और किसी खास तारीख पर हय्या अदा कर देने का वादा करता है, तो ऐसा रेहननामा सादा और दखली मिला हुआ रेहननामा है और ऐसी दशा में जायदाद के बय का हक पैदा होता है, देखो 27 M. 526 F. B.—जब दखली रेहननामा बिल्कुल सादा हो, तो मुतद्दिन नीलाम के लिए नालिश दायर कर सकता है, देखो 14 M. 232—जो रेहन किसी खास मुद्दत मुकर्रर के लिए किया गया हो, वह रेहन दखली रेहन नहीं कहा जा सकता। बल्कि वह रेहन-गैर मामूली है, देखो 12 A. 203; 26 B. 252 F. B. रेहन दखली और बशर्त बयनामा में मुतद्दिन बयबात के लिए नालिश कर सकता है जिसके लिए किसी केवल दखली रेहननामा में इजाज़त नहीं है, देखो 12 M. 109.

कानून मियाद का आर्टि० १३२ उस रेहन गैर-मामूली के सम्बन्ध में लागू होता है जिसमें रेहन दखली और रेहन सादा दोनों की शर्त मौजूद हैं, देखो 2 P. L. T. 229.

फरीकैन—तमाम ऐसे आदमी जिनकी "जायदाद मरहूना" में या उस जायदाद का फूकरेहनी करने में कोई हक हासिल है, उस रेहननामा के सम्बन्ध में होने वाली नालिश में फरीक बनाए जा सकेंगे।

विचरण—मुतद्दिन माबाद (मुतद्दिन दोयम) उस नालिश में पहिले मुतद्दिन को बिना फरीक बनाए हुए बयबातके लिए नालिश कर सकता है, और किसी बाद में किए गए रेहन की फूकरेहनी की नालिश में पहिले मुतद्दिन को फरीक बनाने की ज़रूरत नहीं है [देखो आर्डर ३४, रूल १].

नोट—रेहननामों के सम्बन्ध में अर्जादावा तैयार करते समय जाबता दीवानी के जमीमा (ए) के, परिशिष्ट (१) के फार्म नं० ४५ और ४६ की शर्तों की तामील किया जाना निहायत ही ज़रूरी है। बय (नीलाम), बैबात या फूक-रेहनी की नालिश उसी अदालत में दायर की जानी चाहिए जिसके अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर बंध जायदाद वाकै हो (देखो जाबता दीवानी की दफा १६)

आर्डर ३४, रूल १ के साथ अब जो नया विचरण जोड़ दिया गया है, उसमें अब वह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ली गई है जो पहिले के बहुत से मुकद्दमों में तय की गई थी, अर्थात् यह कि दूसरे रेहननामा के ऊपर की जाने वाली नालिश में पहिले मुतद्दिन का फरीक बनाया जाना ज़रूरी नहीं है (देखो 36 C. 193; 1 C. L. J. 337, 30 C. 599 F. B.; 29 M. 84.)

ऐसे सभी लोग फरीक बनाए जाने चाहिये जिनकी जायदाद मरहूना या हक-इन्फ़काक-रेहन से कोई सम्बन्ध है। इसलिए आमतौर पर तमाम फ़ार आदमी, जिनका इन्फ़काक-रेहन से और इस कारण हिस्सा वगैरा के सम्बन्ध है, फिर चाहे वह बहैसियत राहिन के हो या उसे कानूनन हासिल हुए हकूक की वजह से, जैसे राहिन के हक-इन्फ़काक-रेहन के मुन्तकिलअलेह (Transferee) या मफूज़अलेह (Assignee) की हैसियत से हो उसका दीवख़ का ट्रस्टी या रिसीवर (देखो आर्डर ३१, रूल १) उसके वारिस और प्रतिनिधि मुनासिब, फरीक हैं। आर्डर ३४, रूल १ सिर्फ़ मुद्दाअलेहों के सम्बन्ध में ही नहीं है बल्कि वह मुद्दई लोगों के सम्बन्ध में भी लागू होता है (देखो 41 C. 727.) जिस शख्स ने बाद में जायदाद मरहूना की ख़रीद की हो चाहे इजरा में जाने वाली फ़रोख़्त में या ख़ानगी फ़रोख़्त में वह एक ज़रूरी फरीक है (देखो 22 A. 212; 21 A. 235, 2 M. 64.—असली मालिक और बयनामदार ज़रूरी फरीक हैं (देखो 18 A. 69; 21 A. 380; 24 C. 34; 22 B. 672) माल की कुर्की कराने वाला महाजन ज़रूरी फरीक है (देखो 23 A. 467, 25 A. 464; 37 M. 418; 17 C. W. N. 871).—अगर कोई ऐसा शख्स जिसका जायदाद मरहूना में हिस्सा है, फरीक नहीं बनाया जाता है और वह बयबात या नीलाम (फ़रोख़्त) के पहिले ज़ाहिर हो जाता है, तो उसको फ़क़रेहनी के लिए वे तमाम हकूक हासिल होंगे जो उसको उस हिस्से के कारण प्राप्त हो सकते हैं। वह मुर्तहिन की ओर से अपनी डिकरी की इजग में कराई गई नीलाम के बाद फ़क़रेहनी के लिए नालिश दायर कर सकता है (देखो 24 C. W. N. 954 P. C.)

जब कोई ज़रूरी फरीक छूट गया हो, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह आर्डर १, रूल १० (२) के अनुसार उसे फरीक बनाले या मुद्दई को यह हुकम दे दे कि वह उसका नाम फरीक़ैन में शामिल कर दे।

कुछ मुक़दमों में यह तय किया गया था, कि मिताक्षरा में बतलाए हुए कुटुम्ब के सभी लोगों का उस मुक़दमें में फरीक बनाया जाना निहायत ज़रूरी है जो मुर्तहिन ने दायर किया हो (देखो 28 C. 517; 25 A. 162; 24 A. 459; 41 C. 727; 40 C. 342). लेकिन इसके बाद में बहुत से मुक़दमों में यह तय किया गया है कि जब नालिश प्रतिनिधि की हैसियत में दायर की गई हो तो बाकी लोगों का फरीक बनाया जाना ज़रूरी नहीं है (देखो 34 A. 549 E. B.; 34 A. 572; 36 A. 383 P. C.; 21 C. L. J. 452; 2 P. L. J. 305; 71 I. C. 948; 63 I. C. 664.) सम्मिलित कुटुम्ब (परिवार) का प्रबन्धकर्ता (मैनेजर) बाकी सब लोगों का प्रतिनिधि है और 41 C. 727 में जो फैसला दिया गया है उसके सम्बन्ध में यह समझ लेना चाहिये कि वह अप्रकट रूप से 36 A. 383 P. C. में दिए गए फैसले से रद्द हो गया है (देखो 58 I. C. 849; 1 P. L. T. 582). प्रबन्धकर्ता के बारे में विस्तार से देखो हिन्दी में छपा हिन्दू-लों में मुश्तरका ख़ानदान।

आर्डर ३४, रूल १, आर्डर १, रूल ९ के अधीन है और जो नालिश पहिले मुर्तद्दिन की ओर से, बिना बाद वाले मुर्तद्दिन को फरीक मुकद्दमा बनाए, दाखिल की जायगी वह नाकाबिल कायम रहने के नहीं है, देखो 1922 (Pat.) 326 अगर किसी राहिन के कुल चारिस फरीक मुकद्दमा बनाए गए हैं, तो मुद्दै उन चारिसों के ऊपर जो फरीक मुकद्दमा बनाये गये हैं ज़र-रेहन की उस कदररकमकी बाबत डिकरी दिला पानेके हकदार हैं जो उन लोगोंके हिस्सेमें पड़ती है, देखो 25 C. W. N. 594; 29 C. W. N. 51.

बयनामीदार किसी रेहननामे की बाबत नालिश कर सकता है (देखो 42 M. 348. F. B; 41 M. 435; 36 M. L. J. 68 P. C; 29 C. L. J. 434)

वह शख्स जो राहिन और मुर्तद्दिन से बढ़कर हकीयतके लिये दाबेदार हैं ज़रूरी फरीक नहीं है। 'बढ़कर' हकीयत हासिल करनेके सवालका निपटारा ऐसी नालिशों से नहीं हो सकता देखो 40 A. 584; 12 C. 414 P. C; 33 C. 425; 30 A. 240; 31 A. 11; 44 B. 698; 34 C. W. N. 301.)

जाबता—बयबात की नालिश में (देखो आर्डर ३४ रूल २) नीलाम बय की नालिश (देखो आर्डर ३४ रूल ४), या फकरेहनीकी नालिशमें (देखो आर्डर ३४ रूल ७)—अदालत, अगर मुद्दै जीत गया है तो पहिले एक प्रारम्भिक डिकरी देगी जिसमें मुद्दाअलेह को यह हिदायत की जायगी कि वह एक मुकरर मियाद के अन्दर जिसकी मुद्दत छः महीने से ज्यादा न होगी, डिकरी का रुपया अदा करके जायदादको फकरेहन करा ले। अगर उस मियादके अन्दर अदालतमें रुपया दाखिल नहीं कर दिया जाता तो मियाद की मुद्दत के अन्दर मुद्दै की ओर से दरखवास्त दिये जाने पर अदालत कतई डिकरी दे देगी (देखो आर्डर ३४ रूल ३, ५, ८)—अगर मुद्दै या मुद्दाअलेह प्रारम्भिक डिकरीके बाद मर जाय तो कानून मियादका आर्टि० १७६ और १७७ में बतलाई हुई मियाद (अर्थात् ३ महीने) अन्दर उनकी जगह पर दूसरे लोगों को फरीक बनाए जाने के लिये ज़रूर दरखवास्त दे दी जानी चाहिये नहीं तो वह मुकद्दमा वहीं से ख़तम हो जायगा और फिर कतई डिकरी पाने का हक चला जायगा (देखो 25 C. W. N. 595; 33 C. L. J. 115; 40 A. 203; 68 I. C. 942; 50 I. C. 529)—छः महीने की इस मियाद का आरम्भ पहिली अदालत की डिकरीकी तारीख से होगा अगर अदालतने सिर्फ अपील को खारिज कर दिया हो तो उससे नहीं देखो 25 C. 311. 11 C. W. N. 679; 16 C. W. N. 440.

जाबता दीवानी में इस बात की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है कि कतई डिकरी देने के पहिले मुद्दाअलेह को इसकी इत्तला (नोटिस) दी जानी चाहिये। लेकिन यह उचित जान पड़ता है कि मुद्दाअलेह को ऐसी एक नोटिस अवश्य दे दी जाय ताकि अगर उसे कोई उज्रदारी करनी हो तो वह कर सके। यह एक पक्का सिद्धान्त है कि किसी शख्स के ऊपर बिना उसे नोटिस दिए हुये कोई भी ऐसा हुकम न दिया जाना चाहिये जिससे उसके ऊपर कोई असर पड़ता हो या उसे कोई नुकसान हो रहा हो। इसके अतिरिक्त किसी कतई हुकमका

मंशा यह होता है कि उससे राहिन को यह दिखलाने का मौका मिल सके कि प्रारम्भिक डिकरी का मतालवा अदा कर दिया गया है या नहीं। इसलिये कि हुक्म के लिये दी जाने वाली दरख्वास्त इस सिद्धान्त के ऊपर कि, जब कि डिकरी किन्हीं शर्तों के साथ दी गई हो तो मदीयून डिकरी को पलिले से कि दिये बिना डिकरी दार को इस बात के ऊपर इजरा के लिए न दे दी जानी स हिये कि वह शर्त पूरी होगई है, राहिन के फायदे के लिये होती है देखो 10C. L. 91, 100; 10 C. WN 306; 9 C. L. J. 271; 32 C. 250—जावता दीवानी के जमीमा (डी) परिशिष्ट १ फार्म १० में यह बतलाया गया है कि कतई डिकरी मुद्दई और मुद्दाअलेह के वकीलों की बातों को सुन लेनेके बाद दी जानी चाहिए इसलिए इस से यह मालूम होता है कि इसका मंशा मुद्दाअलेह को नोटिस देना का है। इलाहाबाद में पृथा तो यह है कि नोटिस दिया जाय और हाई कोर्ट ने इस बात का समर्थन भी किया है देखो 82 I. C. 184—188.

अदालतके बाहर रुपकी अदायगी—जावता दीवानीके आर्डर ३४ क्ल और ४ में “अदालत” में रुपया अदा करनेकी हिदायत कीगई है और इसीलिए मुकद्दमोंमें यह तय किया गया है कि अगर अदालतके बाहर अदा किए गए रुप के लिए आर्डर २१ रूल २ के अनुसार मियादके भीतर सर्टीफिकेट नहीं दिया गया है तो कतई डिकरी देते समय वह माना नहीं जा सकता, (देखो 21 W. N. 920; 25 C-L.J. 53; 42M. 61.)—लेकिन दूसरे मुकद्दमोंमें यह तय किया गया है कि कतई डिकरीके लिए दीगई दरख्वास्त इजराकी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक चलते हुए मुकद्दमोंमें कीगई कार्रवाई है। कतई डिकरी होनेके बाद अदालतको चाहिए कि वह उस रुपकी तादाद जान ले जो कि वाजिबुल है और वह अदालत के बाहर कीगई और तस्दीक न कीगई अदायगीको मान सकती है, (देखो 44 A. 668; 668; 57I. C. 473; 5P.L. J. 672; 25 L. J. 533,)—इसमें सन्देह नहीं कि यह अन्तिम राय ज्यादा मजबूत माना होती है, क्योंकि सन् १९०८ ई० के जावता दीवानी के अनुसार कतई डिकरी दी दिए जाने तक कुल कार्रवाई चलते हुए मुकद्दमोंमें कीगई कार्रवाई है और कतई दीगई कतई डिकरी की दरख्वास्त इजराकी दरख्वास्त नहीं है, (देखो 23 W. N. 595; 40 A. 235.

बयबातकी नालिशोंमें अदालतको समय बढ़ा सकने का अधिकार होता है (देखो आर्डर ३४ रूल ३ की शर्त)—लेकिन नीलाम या फकरेहनी की नालिशों में उसे ऐसा करनेका अधिकार न होगा। यद्यपि नीलाम (बय) की नालिशोंमें अदालत रियायती दिनोंकी मुद्दत बढ़ा नहीं सकती, तो भी मदीयून डिकरी आर्डर २१ रूल ८९ के अनुसार रुपया जमा करके, नीलामके बाद जायदाद बांटे ले सकता है, क्योंकि जावता दीवानीकी डिकरियोंकी इजरा सम्बन्धी नियम फकरेहनी डिकरियोंके बारेमें, किये जाने वाले नीलामके सम्बन्धमें भी लागू होते हैं। कतई डिकरी दे दिए जानेके बाद डिकरीदार आर्डर २१ के अनुसार इजरा की दरख्वास्त दे सकता है। रेहन सम्बन्धी डिकरियोंमें जायदादकी कुकी

वांना ज़रूरी नहीं है। आर्डर २१ में बतलाए हुए इजरा सम्बन्धी नियम अब पूरे तौर पर रेहन की डिकरियों को लागू होते हैं, (देखो 37 C. 907.)

यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि कानून इन्तकाल जायदादकी मसूख कीहुई दफा ८९ में से इन शब्दोंके "और इस पर मुद्दाअलेहका फ़क़ रेहनी कराने का हक़ और ज़मानत दोनों जाते रहेंगे" निकाल दिये जाने से यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि आर्डर ३४ रूल ५ के अनुसार सिर्फ़ क़तई डिकरी दिए जानेसे ही राहिन का हक़ चला नहीं जाता है जब तक कि सचमुच जायदाद नीलाम न हो जाय, (देखो 42 A. 517; 3 P. L. T. 232.)—इसलिए क़तई डिकरीके होते हुए भी राहिन को यह मौका मिलता है कि वह जब तक कि जायदाद नीलाम होकर ज़र नीलाम लोगों को तक़सीम न कर दिया गया हो, रुपया जमा करके अपनी जायदाद फ़क़ रेहन करा सके, (देखो 6 5I. C. 801; 42 A. 517; 56 I. C. 162)

सुलहकी डिकरी—इकवाली डिकरी, जिसमें किस्तवार रुपयेकी अदायगीके लिये हुक्म दिया गया हो, एक जायज़ रेहनी डिकरी है, लेकिन वह आर्डर ३४ रूल ५ में नहीं आती। इसलिए क़तई डिकरी देनेकी ज़रूरत नहीं है, देखो 2 Pat 538; 72 I. C. 1049; 10 C. L. J. 91; 2 Pat. L. T. 38 और 27 C. W. N. 621; 5 Lah. L. J. 67; 57 I. C. 473; 58 I. C. 299; 11 C. W. N. 1011 F. B.—अगर कोई ऐसी इकवाली डिकरी दीगई हो जिसमें मुद्दई को इजराके द्वारा कुल रुपया वसूल करनेका अधिकार दिया गया हो, तो इजरा के पहले नोटिस पर क़तई हुक्म हासिल कर लेना चाहिए, देखो 28 C. W. N. 550. पंचायती डिकरी की इजरा बिना क़तई डिकरीके भी हो सकती है. देखो 2 Pat. L. T. 694.

क़तई डिकरीके लिये मियाद—ऐसी दरखास्तमें कानून मियादका आर्टि० १८१ लागू होता है, अर्थात् क़तई डिकरीके अनुसार कीगई अदायगोकी तारीख़से ३ साल की मियाद लागू होती है, देखो 39 A. 641; 40 A. 203; 40 A. 235; 16 I. C. 794; A. I. R. 1922 (Mad) 65; 19 C. W. N. 470; 42 B. 309; 44 M. 714; 38 B. 32.—मियादकी सुदत अदालत अपीलकी प्रारम्भिक डिकरीकी तारीख़से शुरू होती है प्रारम्भिक अदालतकी डिकरीसे नहीं। अदालत अपीलकी डिकरी प्रारम्भिक अदालतकी डिकरीसे बढ़ जाती है, जब कि उसने उस डिकरी को बदल दिया हो या केवल उसको स्वीकार कर लिया हो, (देखो 44 M. 714; 40 A. 203; 1 Pat. 444; 42 I. C. 93; 37 C. L. J. 453]—वह तारीख़, जिसमें दरखास्त देने का हक़ पैदा होता है वह है जब रियायती सुदत ख़तम होती है देखो 4 P. L. J. 523.

रेहन में जाती डिकरी और गिरफ्तारी—जब जायदाद मरहूना के नीलाम से वसूल हुई रक़म उस रुपयेको अदा कर सकनेके लिए काफी नहो जो उस डिकरी की बाबत वाजिब है, तो मुद्दई उस रुपये को जो मुद्दाअलेह से कानूनन वाजिबुल

बसूल है और जो उसके जुम्मे बाकी रह गया है, राहिन की दूसरी जायदाद या उसके जिस्म (ज़ात) के खिलाफ़ इजरा करा के बसूल करा लेने की दिक्कत पाने का हक़ दार है (देखो आर्डर ३४ रूल ६)—मुर्तहिन को चाहिए कि पहिले जायदाद मरहूना को नीलाम करादे ताकि वह आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दरख़वास्त दे सके [देखो 10 A. 632; 17 C. W. N. 1039; 51 L. C. 84; 42, A. 519]—ऐसी ज़ाती डिकरी मियाद बाहर समझी जायगी अगर रेहन सम्बन्धी नालिश अदायगी की वाजिब तारीख़ से छः साल की मियाद शुरू जानेके बाद दायर की गई हो (देखो क़ानून मियाद का आर्टि० ११६) या क़ानून मियाद की दफ़ा १९ के अनुसार ब्याज का रुपया अदा होजाने की दशा में वह हुई तारीख़ से छ साल की मियाद खतम हो जाने के बाद दायर की गई हो (देखो 20 A. 336; 30 A. 383,)—छः साल की इस मुदत का शुमार करने में नालिश की तारीख़ का ख़याल रखना चाहिए आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार दी गई दरख़वास्त की तारीख़ का नहीं (देखो C. 672, 27, C. 762; 12 C. 339;) । रेहन के ज़मानत दार पर अगर दिक्कत है तो उसकी कार्रवाई राहिन जैसी देती है । ज़ाती डिकरी मिलनेपर राहिन फिर पतार व कैद कराया जा सकता है ।

रेहन की प्रारम्भिक डिकरी की मुन्तकिली (Assignment) में आर्डर ३४ रूल ६ के अनुसार डिकरी की मुन्तकिली भी शामिल है देखो 58 L. C. 46 हक़ इन्फ़िकाक़ रेहनके ख़रीदार की ज़ातके ऊपर मुर्तहिन कोई दावा नहीं रख सकता यद्यपि उसने रेहन का रुपया चुकता कर देने का वादा किया था देखो 26 L. W. N. 771- P. C.

रेहन के रुपये का अदालत में जमा किया जाना—किसी रेहन नामा के अर्ज रुपये के वाजिबुल अदा होजाने के बाद और फ़क़रेहनी की नालिश की तमाम आरिज होजाने के पहिले किसी भी समय राहिन या कोई भी दूसरा शख्स कि ऐसी नालिश दायर करने का हक़ है, उस रेहननामा की बाबत वाजिब रुपये मुर्तहिनके हिसाब में अदालतमें जमा कर सकता है ।

तब अदालत उस मुर्तहिन के ऊपर नोटिस तामील करावेगी और मुर्तहिन एक तस्दीक़ शुद्ध अर्ज़ी देगा जिस अर्ज़ीमें उस समय वाजिब रक़म का तादाद और उस जमा की हुई रक़म को, उस वाजिब रक़म की कुल बेबाकी मझते हुए मंज़ूर करने की इच्छा प्रकट की जानी चाहिए और अदालत में उस वेज़ रेहननामा को अगर वह उस समय उसके कब्ज़े या अधिकार में हो कर देने पर उस रुपये के लिये दरख़वास्त देकर उस रक़म को पा सकता है वह दस्तावेज़ रेहननामा राहिन को या ऐसे दूसरे शख्स को जिसका ऊपर किया गया है दे दिया जायगा (देखो क़ानून ज़ाबता दीवानी दफ़ा ८३)

क़ानून इन्तक़ाल जायदाद की दफ़ा ६० के अनुसार राहिन अदालत बाहर रुपया दे सकता है । ज़ाबता दीवानी की दफ़ा ८३ राहिनों और उनके उक्

किल अलेहों को यह एक विशेष अधिकार देती है, कि वे रेहननामा की बाबत वाजिव रुपये को अदालत में दाखिल कर सकें। अगर रुपया दाखिल करने का हक पैदा हो चुका है और कुल वाजिव रकम जमा कर दी जाती है, तो रुपया जमा कर दिये जाने के बाद उस रकम पर व्याज का चलना बन्द हो जाता है। जो रकम जमा की जाती चाहिये वह, वह रकम है जो रेहननामा की बाबत वाजिव हो और उसमें उसका व्याज भी शामिल है (देखो 16 C. 307; P. C.)— यह रुपया बिना किसी शर्त के जमा कर दिया जाना चाहिये (देखो 14 M. 49; 22B. 761)— यह रुपया कई किशतों में जमा किया जा सकता है, लेकिन मुर्तेहिन उस समय तक कोई नोटिस लेने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि वह रुपया उसके पूरे कर्ज को अदा करने के लिए काफी न हो (देखो 8 C. W. N. 216; 24 A. 461)— ज़ाबता दीवानी की दफा ८३ यह जुम्मेदारी अदालत के ऊपर डालती है कि वह नोटिस तामील करावे, राहिन के ऊपर नहीं। उसको इस बात के साबित करने की ज़रूरत नहीं कि अदालत ने अपने कर्तव्य का पालन किया या नहीं और नोटिस तामील कराई या नहीं (देखो 35 C. L. J. 202)।

अगर मुर्तेहिन रुपया ले सकता है तो ज़ाबता दीवानी की दफा ८३ के अनुसार उसे चाहिए कि वह उस रुपयको कुल बेबाकी मतालिवा दस्तावेज़ समझे। इस बात में सन्देह है कि क्या वह इस बात के ऊपर रुपया वापस ले सकता है कि उससे कर्ज का कुल रुपया बेबाक नहीं होता और वह बाकी रुपये की बाबत नालिश करने का अपना हक बनाये रखता है ?

दफा ८३ के अनुसार की जाने वाली अदायगी से होने वाली बातें केवल उसी समय पैदा होती हैं, जब कि ऐसा माहूम हो जाय कि मुर्तेहिन ने उस रुपये को लेकर रेहननामा की बाबत वाजिव कुल रुपये की बेबाकी कर दी है या उसने वास्तव में ऐसा ही किया भी हो, देखो 32 A. 142. ज़ाबता दीवानी की दफा ८३ के अनुसार की जाने वाली किसी भी कार्रवाई में कब्ज़ा दिलाए जाने या किसी दूसरे प्रश्न के जिससे फ़रीक़ैन के हकूक पर कोई असर पड़ता हो तय किये जाने के लिये कोई हुकम नहीं दिया जा सकता। अदालत मुर्तेहिनको सिर्फ दस्तावेज़ रेहननामा दे देने के लिये मजबूर कर सकती है। उससे कोई दूसरी सहायता नहीं मिल सकती (देखो 13 M. 316)— अगर मुर्तेहिन जमा किये हुये रुपये को लेने से इन्कार करता है तो राहिन अपने हकूक की निश्चय नालिश कर सकता है और जब तक कि वह इसमें सफलता (कामयाबी) प्राप्त नहीं कर लेता, रेहन ज्यों का त्यों बना रहता है (देखो 21 A. L. J. 545)— कानून इतना ज़ाबता दीवानी की दफा ९१ में उन आदमियों का वर्णन है जो फ़करेहनी के लिये नालिश दायर कर सकते हैं।

नालिश और तरफिया—कौन शख्स नालिश तरफिया दायर कर सकते हैं और ऐसी नालिशों के दायर करने के लिये कौन कौन सी शर्तें ज़रूरी हैं इस सम्बन्ध में देखो ज़ाबता दीवानी की दफा ८८।

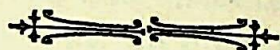
दूसरी और बातों के लिये जो नालिश तस्फ़िया के अर्ज़ीदावा में लिखी जानी चाहिये देखो ज़ाबता दीवानीका आर्डर ३५ रूल १ ।

विस्तृत ज़ाबते के लिये देखो आर्डर ३५ के रूल २ से ६ तक ।

विशेष अवस्था—अदालत की राय के लिये मुकद्दमें को भेज देने के अधिकार के सम्बन्ध में देखो आर्डर ३६ रूल १ से ५ ।

दस्तावेज़ात काबिल बय व रेहन वगैरहके ऊपरकी जाने वाली सरसरी कार्रवाई—किताफ़ एक्सचेन्ज (हुण्डियों) या प्रामिसरी नोटोंके ऊपरकी जाने वाली नालिशों में की जाने वाली सरसरी कार्रवाई के सम्बन्धमें देखो आर्डर ३७ रूल १-७ ।

प्रासंगिक कार्यवाही



कमीशन—कोई भी अदालत लिखे नीचे कामोंके लिये कमीशन जारी कर सकती है:—

(क) किसी शख्सके बयान लेनेके लिये, (ख) किसी मौके की राहकीकात करने के लिये, (ग) हिसाब की जांच करने या उसे ठीक करने के लिये, या (घ) बटवारा करने के लिये (देखो दफा ७५)। इसका विस्तृत जाबता, जाबता दीवानी के आर्डर २६ में बतलाया गया है।

आर्डर २६ के अनुसार नियुक्त किए गए कमिश्नरों के अधिकार क्या हैं इस सम्बन्ध में देखो आर्डर २६ रूल १६, १७, १८। कमीशन का खर्चा कमीशन जारी होनेसे पहिले नियत रुपये के भीतर अदालतमें जमाकर दिया जाना चाहिये (देखो आर्डर २६ रूल १५) —जाबता दीवानीकी दफा ३६के अनुसार कमिश्नर का खर्चा अदा करने के सम्बन्ध में दिये हुए अदालत के हुक्म की इजरा बतौर डिकरी के कराई जासकती है (देखो 28 C. W. N. 187; 10 C. W. N 234) मुआविज़ा सम्बन्धी प्रश्न का निपटारा उस जज को करना चाहिये जिसकी अदालत में मुकद्दमा चलता हो। ज़िला जज को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी ऐसे कमिश्नर द्वारा तलब किये गये मुआविज़ाके किसी हिस्से को नामंजूर कर दे जो किसी सब जज की अदालत में चलने वाले मुकद्दमें में नियुक्त किया गया हो, देखो 44 I. C. 496.

गवाहोंके बयान लेनेके लिये कमीशन—कोई भी अदालत किसी मुकद्दमें में पूछे गए प्रश्नों (सवालात) अथवा अन्य बातों के सम्बन्ध में नीचे लिखे आदमियों के बयान लेने के लिए कमीशन जारी कर सकती:—

किसी भी ऐसे शख्स के लिये जो उसके अधिकार क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके भीतरका रहने वाला है या जो अदालतमें हाज़िरीसे बरी कर दिया गया है या जो बीमारी अथवा निर्बलता (कमज़ोरी) के कारण हाज़िर होनेमें असमर्थ है (देखो आर्डर २६, रूल १)।

किसी भी ऐसे शख्सके लिये जो उसके अधिकार-क्षेत्रकी स्थानीय सीमाके बाहर रहता हो;

किसी भी ऐसे शख्स के लिये जो उस तारीख के पहिले ऐसी सीमा को छोड़ने वाला हो जिस तारीख को अदालत में उसके बयान लिए जाने को हैं,

सरकार के किसी भी मुल्की या फौजी अफसर के लिये, जो सरकारी कार्य को क्षति पहुंचाए बिना अदालत में हाज़िर नहीं हो सकता (देखो आर्डर २६, रूल ३)

अदालत के अधिकार-क्षेत्र के भीतर कमीशन, किसी भी ऐसे शख्स के पास भेजा जा सकता है जिसे अदालत प्राण-दण्ड देना उचित समझती हो (देखो

आर्डर २६, रूल ६) — अदालत के अधिकार-क्षेत्र से बाहर के स्थानों के जमाने की कमीशन किसी भी अदालत को भेजा जा सकता है जो कि हाईकोर्ट नदी और जिसके अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर वह रहता है, या किसी वकील अथवा दूसरे आदमी के पास भेजे जा सकते हैं जिसे कमीशन जमाने करने वाली अदालत नियत करे (देखो आर्डर २६, रूल ४)

ब्रिटिश भारत के बाहर गवाहों के बयान लेने के लिए कमीशन जमाने करने के सम्बन्ध में देखो रूल ५

कमीशन के द्वारा बयान लिए जाने के लिए हुक्म, अदालत या तो अपनी मर्जी से दे सकती है या किसी फरीक या गवाह के दखलाने देने पर, जिसका समर्थन हलफनामा से या और किसी तरह पर किया गया हो (देखो आर्डर २६, रूल २)

कमीशन के वाक्यावली काम कर चुकने के बाद, उसे गवाहों के बयानों के सहित उस अदालत को वापस कर देना चाहिए, जहां से कि वह जारी किया गया था और वे बयानों उस मुकदमे की मिसिल का हिस्सा समझे जायेंगे (देखो आर्डर २६, रूल ७)।

जो शहादत कमीशन के द्वारा ली गई है, वह उस मुकदमे में कब और शहादत के पढ़ी जायगी, इस सम्बन्ध में देखो आर्डर २६, रूल ८.

जो लोग अदालत में असालतन हाज़िर होने से मुस्तजना हैं उनमें से स्त्रियां (औरतें) भी हैं जो देश की प्रथा और वहां के व्यवहार के अनुसार सके साधारण के सामने बाहर निकलने के लिए बाध्य नहीं की जा सकतीं (देखो ज़ाबता दीवानी की दफा १३२)। कमिशनर को चाहिए कि वह किसी बयान को उसी भाषा में लिखले जिसमें कि वह दिया गया है।

इस सम्बन्ध में आर्डर १६, रूल १९ के नियम स्मरण रखने चाहिए जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी गवाह को असालतन हाज़िर होने का हुक्म न दिया जायगा जब तक कि वह असुक्त सीमा के भीतर का रहने वाला न होगा।

गवाहों के बयान लेने के लिए कमीशनों के जारी किए जाने और उनकी वापसी सम्बन्धी नियम, उन कमीशनों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे जो बाहरी (विदेशी) अदालतों द्वारा जारी किए गए हों (देखो ज़ाबता दीवानी की दफा ७८ और आर्डर २६, रूल ५)

जब किसी कमीशन के सामने कोई दस्तावेज़ पेश किया गया हो और उसके क़ाबिल तस्लीम होने के बारे में कुछ भी एतराज़ न किया गया हो, तो मुकदमे की समाप्त करने वाली अदालत के सामने ऐसा कोई भी एतराज़ न पेश किया जा सकेगा, देखो 6 C. L. R. 109.—लेकिन अगर किसी बिना ऊपर कमीशन के सामने उसके क़ाबिल तस्लीम होने के सम्बन्ध में कोई एतराज़

क्रिया जाता है तो उस शख्स को मुकद्दमें की समाप्त के समय किसी दूसरी बिना के ऊपर एतराज करने की मनाही न होगी (देखो 9 C. 939.)

कमीशन के द्वारा ली गई शहादत उस समय भी शहादत समझी जायगी, जब वह समाप्त करने वाली अदालत के सामने पेश हो यद्यपि वह बाजाबता तौर पर पेश और पढ़ी न भी गई हो, देखो 26 C. 591; 9 C. W. N. 794; 13 C. W. N. 325; 36 C. 566; 35 C. 28; 18 C. L. J. 150.

कमिशनर किसी फरीक के एतराज करने पर किसी भी सवाल को नाम-जूर नहीं कर सकता, लेकिन उसे उस एतराज को लिखलेना चाहिए, देखो 11 C. W. N. 305.—अदालत अपने न्याय सम्बन्धी अधिकार कमिशनर को नहीं दे सकती, देखो 15 C. L. J. 17.

किसी मुद्दई की ओर से स्वयं उसके बयान लिए जाने के लिए कमीशन जारी करने की दरखास्त में और मुद्दाअलेह की ओर से स्वयं उसके बयान लिए जाने के लिए दी गई दरखास्त में अन्तर है। मुद्दाअलेह की बातों पर उसी प्रकार कार्रवाई नहीं की जायगी जिस प्रकार कि मुद्दई की बातों पर जिसने अपनी अदालत चुनली, देखो 35 C. L. J. 78; 57 I. C. 955.—मुद्दाअलेह के यह कहने पर कि, मेरा गवाह, जो एक पर्दानशीन औरत है, उसके बयान उसी स्थान पर लिए जाय जहां पर मैं बतलाऊं या जहां पर कि वह कमीशन जारी किए जाने के समय उपस्थित हो। तय हुआ कि उसे ऐसा कहने का अधिकार नहीं है, देखो 48 C. 448.—पर्दानशीन औरतों का कमीशन के द्वारा उनके बयान लिए जाने का अधिकार इसलिए नष्ट नहीं होता कि कुछ अवसरों पर उन्होंने पर्दा का नियम भङ्ग कर दिया है, देखो 16 C. W. N. 300—यही बात एक बड़े घराने की ऐसी स्त्री के सम्बन्ध में भी लागू होती है जिसने पर्दा तोड़ दिया है, देखो 22 C. W. N. 147.—पर्दानशीन औरतों को अपने रहन-सहन का ढङ्ग पूरा पूरा बदल देने का अधिकार है। जब इस प्रकार परिवर्तन हो जाय, तो वह जाबता दीवानी की दफा १३२ में बतलाए हुए अदालत में हाजिर न होने के अधिकार की निस्वत, बतौर अधिकार के कोई दावा नहीं कर सकती। लेकिन अगर वह वास्तव में एक पर्दा नशीन औरत है, तो उसका अधिकार इसलिए नहीं चला जाता कि वह इससे पहिले एक फौजदारी मुकद्दमें में हाजिर हो चुकी है, देखो 45 C. 697; 22 C. W. N. 197; 26 C. 650; 26 C. 651; 3 C. W. N. 753.—पर्दानशीन औरतों की तरह रहने वाली औरतें वही हक नहीं रखतीं जो कि पर्दा नशीन औरतें रखती हैं। (Quasi Pardanashin) के अर्थ के लिए देखो 5 C. W. N. 1 P. C.

मुकामी तहकीकात के लिये कमीशन—अगर अदालत को मुकामी तहकीकात की जरूरत मालूम हो, तो वह किसी ऐसे मामले की जांच करने के लिए जिसकी निस्वत झगड़ा है, अथवा किसी जायदाद की बजारू कीमत या किसी वासिलात या मुकसान या असल सालाना मुनाफा की रकम तय करने के लिए, कमीशन जारी कर दे (देखो आर्डर २६, रूल ९)

कमिशनर की रिपोर्ट और वह शहादत, जो उसने ली है (बिना लिखी खाली शहादत नहीं) मुकद्दमों में शहादत होगी । फरीकैन में से कोई भी अदालत में कमिशनर के बयान ले सकता है । जब रिपोर्ट असन्तोषजनक अदालत और भी जांच करने का हुक्म दे सकती है (देखो आर्डर रूल १०)

अदालत किसी भी जायदाद या चीज़ का मुलाहिज़ा कर सकती जिसके सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठ खड़ा हो (देखो आर्डर १८, रूल १८)

इस वर्तमान रूल के अनुसार जज बिना अपनी असुविधाओं का ध्यान किए कमीशन जारी कर सकता है । आर्डर २६, रूल ९ जज द्वारा किसी चीज़ का मुलाहिज़ा किए जाने की मनाही नहीं करता, देखो 44 M. 640. — १८, रूल १८ एक नया रूल है और वह अदालत को यह अधिकार देता है वह किसी भी समय मौके की जांच करे इस सम्बन्ध में देखो कानून शहादत दफ़ा ६० की शर्त । मौके की तहकीकात के लिए कमीशन प्रायः आराजी पैमाइश करने अथवा नकशे तैयार करने के अभिप्राय से जारी किए जाते हैं ।

मौके का मुलाहिज़ा करने का उद्देश्य, उस प्रश्न को समझना है जो उठाया गया है, और उसकी निस्वत शहादत का लेना और उसकी जांच करना है । लेकिन कोई फ़ैसला अकेले मौके की तहकीकात से मालूम हुई बातों के आधार पर नहीं दे दिया जाना चाहिए, देखो 29 I. C. 60; 58 I. C. 61 I. C. 794; 61 I. C. 712. मौके की तहकीकात से जो कुछ भी मालूम हो उन्हें दर्ज कागज़ात कर देना चाहिए, देखो 16 C. W. N. 42.

हिसाब-किताब की जांच करनेके लिए जारी किया गया कमीशन—अदालत हिसाब-किताब की जांच और उसके ठीक करने के लिए कमीशन जारी कर सकती है (देखो आर्डर २६, रूल ११)—अदालत कमिशनर को आवश्यक कागज़ात और ऐसी हिदायतें दे देगी जो उसे आवश्यक जान पड़ेंगी (देखो आर्डर २६, रूल १२)

किसी माली लिखा-पढ़ी (मामले) में हिसाब किताब तैयार करने के लिए की गई नालिश में अदालत, कृतई डिकरी देने के पहिले, एक प्राप्ति डिकरी दे देगी जिसमें वह हिसाब-किताब तैयार करने के लिए हिदायत देगी (देखो आर्डर २०, रूल १६)

साझेदारी के मुकद्दमों में तथा प्रबन्ध सम्बन्धी मुकद्दमों में अदालत हिसाब-किताब तैयार करने की हिदायत कर सकती है (देखो आर्डर २०, १५, १३)

अदालत को अधिकार है कि वह डिकरी द्वारा या इसके बाद हुक्म के द्वारा, उस तरीके के सम्बन्ध में खास हिदायतें कर सकती है कि तरीके से कि हिसाब-किताब तैयार किया जाना चाहिए (देखो आर्डर रूल १७)

प्रबन्ध सम्बन्धी और साझेदारी के मुकद्दमों में दी जाने वाली डिकरियों के फार्म के सम्बन्ध में देखो ज़ाबता दीवानी का ज़मीबा (डी)

बटवारा कराने के लिए कमीशन—जबकि डिकरी किसी ऐसी मुश्तरका इलाके के बटवारे या अलग कब्ज़े की बाबत दी गई हो जिसपर सरकार को अदा की जाने वाली मालगुज़ारी बांधी गई है, तो बटवारा कलक्टर करावेगा (देखो आर्डर २०, रूल १८)—अगर डिकरी किसी दूसरी जायदाद गैर-मनकूला या जायदाद मनकूला के सम्बन्ध में हो, तो अदालत एक प्रारम्भिक डिकरी दे सकती है जिसमें वह उस जायदाद में हफ़ रखने वाले तमाम लोगों के अधिकारों के सम्बन्ध में घोषणा कर सकती है (देखो आर्डर २०, रूल १८)

प्रारम्भिक डिकरी दे दिए जाने के बाद अदालत ऐसे शख्स के नाम कमीशन जारी कर सकती है जिसे वह बटवारा कर सकने के योग्य समझती हो, (देखो आर्डर २६, रूल १३)

आवश्यक जांच कर लेने के बाद कमिशनर, अदालत द्वारा बतलाए गए ढंग से जायदाद का बटवारा कर देगा, और, अगर उसे ऐसा अधिकार दिया गया है, तो वह हिस्सों की मालियत बराबर करने के लिए रुपया भी विलवा सकता है। कमिशनर की रिपोर्ट दाखिल हो जाने के बाद, जिसमें नाप-जोख करके और सीमा (हद) निश्चित करके बटवारा किए जाने की बात हो, अदालत, उज़्रदारी, अगर कोई हो तो, सुन लेने के बाद उसे मंज़ूर कर लेगी, बदल देगी या रद्द कर देगी। अगर रिपोर्ट रद्द कर दी जाय, तो एक नया कमीशन जारी किया जा सकता है (देखो आर्डर २६, रूल १४)

जब कोई ऐसा फ़रीक़, जिसे प्रारम्भिक डिकरी से हानि पहुंचती है उस डिकरी के विरुद्ध अपील नहीं करता है, तो किसी ऐसी अपील में, जो कि कृतई डिकरी के विरुद्ध की गई हो, उसके सही होने के सम्बन्ध में, आपत्ति करने का उसे अधिकार न होगा (देखो दफ़ा ९७)—बटवारे की डिकरी स्टाम्प लगे हुए कागज़ के ऊपर लिखी जानी चाहिए, जैसा कि स्टाम्प ऐक्ट (नं० २ सन् १८९९ ई०) के परिशिष्ट १ के आर्टि० ४५ और दफ़ा २ (१५) में बताया गया है (देखो 32 C. 483; 29 B. 366.)

हलफनामा—अदालत को अधिकार है कि वह किसी समय यह हुक्म दे देवे कि कोई बात या कोई बातें हलफनामा के ज़रिये साबित की जाय (देखो आर्डर १९, रूल १)

ज़ाबता दीवानी के अनुसार दाखिल किए जाने वाले हलफनामा में (क) कोई भी अदालत या मजिस्ट्रेट या (ख) कोई अफसर अथवा दूसरा आदमी जिसे हाईकोर्ट इस काम के लिए नियत करे या (ग) कोई अफसर जिसे किसी दूसरी अदालत ने मुक़रर किया हो, स्थानीय सरकार की ओर से अधिकार दिए जाने पर, बयान देने वाले शख्स को हलफ़ दिला सकता है (देखो दफ़ा १३९)

हलफनामा दाखिल करने वाले शख्स की, उसके ऊपर जिरह किए जाने के लिए, हाज़िरी का हुक्म दिए जाने और इस बात का हुक्म दिए जाने के

सम्बन्ध में, कि हलफनामों में कौन कौनसी बातें कही जायंगी, अदालत अधिकार क्या है, इसके लिए देखो आर्डर १९, रूल २ और ३।

आर्डर १९, रूल ३ के ऊपर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार किया चाहिए। हर एक हलफनामा में यह बात साफ साफ ज़ाहिर कर दी जा चाहिए कि हलफनामा दाखिल करने वाले ने कौन कौन सी बातें अपनी जानकारी से लिखी हैं और कौन कौन सी बातें सिर्फ विश्वास से। और उस विश्वास के लिए कौन कौन से कारण हैं। यह बात पूर्ण विस्तार के साथ लिख जानी चाहिए, देखो 37 C. 259; 9 Bom. L. R. 540.—सिर्फ यह लिख देना कि “जहां तक मैं जानता हूँ और जहां तक मेरा विश्वास है” और यह बात लिखना कि उसे अमुक बात अमुक स्थान से प्राप्त हुई है, हलफनामा नहीं देखो 23 I. C. 377.—अपने विश्वास के कारण अवश्य लिख देना चाहिए नहीं तो हलफनामा खारिज कर दिया जायगा, देखो 10 C. L. J. 414.

इस बात के न लिखने से, कि कितनी बातें हलफनामा दाखिल करने वाला अपने जानकारी से लिख रहा है और कितनी बातें केवल विश्वास (विचार) से, यह समझा जायगा, कि वह शरूस उन्हीं बातों के सम्बन्ध में शपथ ले रहा है जिनको वह जानता है, जिससे बाद में होने वाली सारी बातों की जिम्मेदारी उसकी होगी, देखो 73 I. C. 721.

बंगाल में अदालत कीवानी के शरिस्तेदारों को हलफनामों के सम्बन्ध में शपथ (हलफ) दिलाने का अधिकार रहता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक खास खास मामले में मुंसरिम भी हलफनामे तस्दीक कर लेते हैं।

फ्रीकैन की मृत्यु उनका ब्याह और दीवालिया होजाना—किसी मुद्दे या मुद्दों की मृत्यु होजाने से मुकद्दमें की कार्रवाई वहीं से खतम नहीं हो जाती बालिश दायर कर सकने का हक दूसरे आदमियों को बना रहता है (देखो आर्डर २२, रूल १)—जब कि बालिश कर सकने का हक सिर्फ बाकी बचे हुए मुद्दे या मुद्दों को ही अथवा सिर्फ बाकी बचे हुए मुद्दा (अलेह या मुद्दा अलेहों के ही विरुद्ध हो तो अदालत के इस बात का इन्दराज कर लेता है) बाद मुकद्दमें की कार्रवाई जारी होगी (देखो आर्डर २२, रूल २)—जब कि बालिश दायर कर सकने का हक अकेले बचे हुए मुद्दे या मुद्दों को ही अथवा अकेले बचे हुए मुद्दा (अलेह या मुद्दा अलेहों को ही नहीं है, तो दरखुस्तान देने पर अदालत मरे हुए फ्रीक के कानूनी प्रतिनिधि को फ्रीक मुकद्दमा खतम करने का हुकम देगी (देखो आर्डर २२, रूल ३ और ४)—अगर इस बात कोई झगड़ा पैदा हो जाय, कि कौन शरूस कानूनी प्रतिनिधि है और कौन नहीं तो इस प्रश्न का निपटारा अदालत करेगी (देखो आर्डर २२, रूल ५)

अगर मुकद्दमें की सुनाई खतम हो जाने और फैसला सुनाया जाने के बीच किसी फ्रीक की मृत्यु होजाय, तो इससे मुकद्दमा वहीं खतम नहीं होता। इस फैसले का वही असर होता है मानों वह मृत्यु होने के पहिले ही मर गया हो (देखो आर्डर २२, रूल ६)

किसी औरत फरीक का ब्याह हो जाने से नालिश खतम नहीं होजाती (देखो आर्डर २२, रूल ७) — मुद्दई के दीवालिया हो जाने पर कब नालिश रुक जाती है, इस सम्बन्ध में देखो आर्डर २२, रूल ८ ।

मुकद्दमा खतम हो जाने के बाद नया मुकद्दमा दायर नहीं किया जा सकता लेकिन मुकद्दमा खतम हो जाने की तारीख से ६० दिन के अन्दर कानून मियाद के आर्टि० १७ के अनुसार मुद्दई या उसका कानूनी प्रतिनिधि हुक्म बदल दिए जाने के लिए दरख्वास्त दे सकता है, और अगर यह साबित होजाय कि वह किसी पर्याप्त कारण से अपने मुकद्दमें को जारी न रख सका, तो अदालत उस मुकद्दमें को रोक देने या उसे खारिज कर देने सम्बन्धी हुक्म को मंसूख कर देगी (देखो आर्डर २२, रूल ९) — ऐसी दरख्वास्तों के सम्बन्ध में कानून मियाद की दफा ५ के नियम लागू होंगे ।

किसी मुकद्दमें के दौरान में किसी हक की मुन्तकिली, उत्पत्ति या सिपु-दंगी के दूसरे मुकद्दमों के सम्बन्ध में देखो आर्डर २२, रूल १० ।

कानून मियाद के आर्टि० १७६ और १७७ के अनुसार किसी मुतौफी मुद्दई या मुद्दाअलेह के वारिसों को फरीक मुकद्दमा बनाए जाने की मियाद ९० दिन हैं (देखो 50 C. 549 ; 5 L. 367) — आर्डर २२, रूल ३ के अनुसार दिए गए हुक्म की अपील हो सकती है । मुकद्दमें के सकूत (बन्द होजाने) के सम्बन्ध में दिए गए हुक्म को मंसूख किए जाने के लिए दिए गए हुक्म की अपील हो सकती है (आर्डर ४३ (क)) — आर्डर २२, रूल ५ के अनुसार दिए गए हुक्म की अपील नहीं हो सकती (देखो 37 A. 272; 39 I. C. 371) आर्डर २२ में दिए हुए रूल अपीलों के सम्बन्ध में लागू होते हैं (देखो आर्डर २२, रूल ११) — आर्डर २२, रूल ३, ४, ८ इजरा की कार्रवाई के सम्बन्ध में लागू नहीं होते । वारिस लोग सिर्फ उसी समय फरीक मुकद्दमा बनाए जा सकते हैं जब कि कोई फरीक दौरान मुकद्दमा में मरा हो । अगर किसी मृत पुरुष के विरुद्ध कोई नालिश दायर की जाय, तो उसके वारिसों को फरीक नहीं बनाया जाना चाहिये (देखो 31 M. 36; 42 I. C. 539; 51 I. C. 160; 25 Bom. L.R., 7) उन्हीं पर उस सम्बन्ध से दावा होना चाहिये ।

इस बात को भली प्रकार जानने के लिए, कि किन मुकद्दमों में नालिश करने का हक बाकी रहता है और किनमें नहीं देखो इण्डियन काण्ट्रेक्ट ऐक्ट नं० ९ सन् १८७२ ई० की दफा ३७ तथा उत्तराधिकार ऐक्ट (नं० १० सन् १८६५ ई०) की दफा २६८ और प्रोबेट ऐण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट (नं० ५ सन् १८८१ ई०) की दफा ८९ ।

मुकद्दमों का वापस लिया जाना — (१) मुद्दई को अधिकार है कि वह किसी भी समय कुल या किसी भी मुद्दाअलेहों के ऊपर से अपना मुकद्दमा वापस ले ले या अपने दावा का अंश छोड़ दे ।

(२) जहां पर अदालत को विश्वास होजाय कि (क) किसी ज़ाबते की कमी के रह जाने के कारण मुकद्दमा खारिज हो जाना चाहिये, या (ख)

यह कि किसी मुकद्दमें के विषय में अथवा किसी दावा के हिस्से के लिये नए सिरे से नालिश दायर करने की इजाज़त देने के लिए काफी वजहें हैं, तो उसे अधिकार है कि वह, ऐसी शर्तों पर जिन्हें कि वह मुनासिब समझे, मुकद्दमों से अलग होजाने या उसके किसी हिस्से को छोड़ देने की इजाज़त दे दे और उन्हें नए सिरे से नालिश दायर करने का अधिकार भी दे देवे।

(३) अगर कोई मुद्दई सब-रूल (२) के अनुसार आज्ञा प्राप्त किए बिना कोई मुकद्दमा वापस ले ले या उसे छोड़ दे, तो वह उन बातों के सम्बन्धों या दावा के ऐसे हिस्से के सम्बन्धों में नए सिरे से नालिश दायर न कर सकेगा।

(४) इस रूल में कोई भी बात ऐसी न समझी जायगी जो अदालत को यह अधिकार देती हो कि वह कई एक मुकद्दमों में से किसी एक शख्स को, बिना बाकी आदमियों की स्वीकृति लिए, मुकद्दमा उठा लेने की इजाज़त दे सके (देखो आर्डर २३, रूल १)

विवरण—सब रूल (१) में मुकद्दमें के उठा लेने की बात का जिक्र है। अगर मुद्दई बिना इस इरादे के, कि वह फिर नए सिरे से नालिश दायर करे, मुकद्दमा उठा लेना चाहता है तो वह अपनी इच्छा से ही ऐसा कर सकता है। इस के लिए उसे सब-रूल (१) में अधिकार दिया गया है। इस सम्बन्ध में अदालत की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सब-रूल (२) में मुकद्दमों से अलग होजाने की बात का जिक्र है। अगर मुद्दई मुकद्दमों से अलग होजाना चाहता है, इसलिए कि वह नया मुकद्दमा दायर कर सके, तो उसे चाहिए कि वह सब-रूल (२) के अनुसार इजाज़त हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे (देखो 32B. 345)

अदालत को इस बात का कोई भी अधिकार नहीं है कि आर्डर (१३) रूल १ के अलावा मुकद्दमों से अलग हो जाने की इजाज़त दे सके, (देखो 13 M. I. A. 160)—नया मुकद्दमा दायर करने का अधिकार देते हुए किसी शख्स को मुकद्दमों से अलग हो जाने की इजाज़त दे सकने का अधिकार अदालत को उसी वक्त है जब कि मुकद्दमों में सब-रूल (२) के क्लॉज़ (क) और (ख) में बतलाए हुए मुद्दस मौजूद हों। अदालत को मुकद्दमों से अलग हो जाने की इजाज़त देने का अधिकार उस समय न होगा जबकि,

(क) मुकद्दमों में कोई जाबते की कमी न रह गई हो या,

(ख) उसी तरह की दूसरी काफी वजहें मौजूद न हों (देखो 46 I. C. 179)

यह तय किया गया है कि “दूसरी काफी वजहें” शब्दों का अर्थ क्लॉज़ (क) की किसम की वजहें समझना चाहिए अर्थात् क्लॉज़ (ख) में बतलाई गई वजहें उसी किसम की होनी चाहिए जिस किसम की वजहें क्लॉज़ (क) में बतलाई गई हैं देखो 25 C. L. J. 454; 46 I. C. 181; 48 I. C. 197; 61 I. C. 639.

आर्डर २३ रूल १ का उद्देश्य यह यहीं है, कि उस समय मुकद्दमा उठालने की इजाज़त दी जाय जब कि मुद्दई मुनासिब तवज्जेह और मेहनत के साथ

मुकद्दमें की पैरबी कर सकने में नाकामयाब रहा हो और जब कि उसके गवाह उसके दावा का समर्थन न कर सकते हैं ताकि मुद्दई को फिरसे मुकद्दमा चलाने का मौका मिल सके (देखो 16 C. W. N. 1027; 35 I. C. 843, 11 A. L. J. 733; 46 I. C. 179)—सिर्फ योंही ऐसा कह देना कि जाबते की कुछ कमी (नुक्स) रह गई है, काफी न होगा। इस बात को जहां तक साफ साफ होसके जाहिर कर देना चाहिए और अदालत को इस बातका इतमीनानहो जाना चाहिये कि वास्तव में ऐसा कोई नुक्स मुकद्दमें में मौजूद है (देखो 64 I. C. 556; 48 I. B. 197; 46 I. C. 179)—अदालत के लिए यह जरूरी है कि वह मुकद्दमा उठा लेने या मुकद्दमें से अलग होने की इजाज़त देते समय अपने ऐसा करने के कारण लिख दे देखो 39 C. L. J. 37.

लेकिन अगर कोई अदालत गैर मुनासिब तरीके से मुकद्दमा उठालेने या मुकद्दमेंसे अलग होजाने की इजाज़त दे, तो जिस अदालतमें बादको कोई नालिश दायर की जाय उसको यह अधिकार नहीं है कि वह फैसले के सही होने की निस्वत कोई एतराज कर सके या इसबात पर विचार कर सके कि वास्तव में कोई जाबते का नुक्स मौजूद था या नहीं। वह फैसला चाहे ग़लत हो या सही, उस समय तक अवश्य मान्य होगा जब तक कि रद न कर दिया जाय, देखो 48 C. 138; 24 C. W. N. 723; 65 I. C. 704; 64 I. C. 387.

जब कि मुद्दई इस बात के लिये दरखवास्त दे कि उसे मुकद्दमा उठा लेने की इजाज़त दी जाय, और नये सिरे से मुकद्दमा दायर करने का भी अधिकार दिया जाय और अदालत की यह राय हो कि इसके लिये कोई काफी वजह नहीं है तो उचित मार्ग यह है कि दरखवास्त खारिज कर दी जाय और किसी ऐसे हुक्मसे मुकद्दमेंका फैसला नहो जायगा जिसमें मुकद्दमा उठा लेनेकी इजाज़त तो दी गई हो पर नया मुकद्दमा दायर करने की इजाज़त न दी गई हो (देखो 20 C. W. N. 1011; 32 Bom. 345).

अदालत अपील किसी ऐसे मुद्दई को जिसका मुकद्दमा खारिज कर दिया गया है, इस इजाज़त के साथ मुकद्दमा उठा लेने या मुकद्दमें से अलग हो जानेकी इजाज़त दे सकती है कि वह फिर नया मुकद्दमा दायर कर सके (देखो 8 A. 82; 11 M. 322; 14 W. R. 17; 20 W. R. 163; 37 A. 326)। 27 M. L. J. 244 में इससे भिन्न मत प्रकट किया गया है।

अर्डर २३ रूल १ डिकरियों की इजरा की दरखवास्त के सम्बन्ध में लागू नहीं होता देखो 17 All 106 P. C.

अदालत इस हुक्म के साथ मुकद्दमा उठा लिए जाने या उससे अलग हो जाने की इजाज़त दे सकती है कि नया मुकद्दमा सिर्फ उसी समय दायर किया जा सकेगा जबकि पहिले खर्चा अदा कर दिया जाय। उसे चाहिये कि वह एक मियाद मुक़र्रर कर दे और इस बात का हुक्म दे देवे कि अगर इस मियाद के अन्दर खर्चा अदा न कर दिया जायगा तो मुकद्दमा खारिज समझा जायगा।

लेकिन अगर कोई मियाद मुकर्रर नहीं की गई है तो बाद में खर्चा अदाकर देने से इस बेकायदगी की बात दूर हो जाती है (देखो 31 C. 965; 44 I. C. 79) अदालत को यह अधिकार है कि वह खर्च की अदायगी के लिये मुकर्रर किए हुए समय को बढ़ा सके देखो 29 M. 370; 10 C. W. N. 8.

मुकद्दमें में राजीनामा—जब यह बात साबित हो जाय कि किसी कानूनी इकरारनामा या राजीनामासे किसी मुकद्दमेंके कुल या एक अंशके निवस्त तस्फिया हो गया है या जब मुद्दाअलेह, मुद्दई को मुकद्दमें के कुल या कुछ हिस्से का मतालिया अदा कर दे तो अदालत यह हुक्म दे देगी कि ऐसा इकरार नामा राजीनामा या अदायगी मतालिया की बात मिसिल में दर्ज करली जाय और जहां तक उसका सम्बन्ध उस मुकद्दमें से है उसके अनुसार ठिकरी देदेगी (देखो आर्डर २३ रूल ३)

यह रूल ऐसे मुकद्दमों के लिए तैयार किया गया था जहां पर फरीकैन के दरम्यान कोई कानूनी राजीनामा होजाने के बाद उनमें से किसी शख्स ने उन शर्तों के मानने से इन्कार कर दी हो। ऐसी दशा में अदालत को यह अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में एक और तनकीह तैयार करे कि, क्या कानूनी राजीनामा हुआ है या नहीं? (देखो 19 M. 419) —जब कि फरीकैन ने किसी इकरारनामा के जरिये मुकद्दमें का तस्फिया कर लिया हो, तो अदालत उसके अनुसार ठिकरी दे सकती है, फिर चाहे उनमें किसी फरीक को इस बात में एतराज न हो कि राजीनामा मंजूर कर लिया गया है (देखो 24 C. 908 F. B.; 1 C. W. N. 597; 21 C. W. N. 366).

किसी वकील या मुह्तार को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मव-विकल की तरफ से, बिना उसकी लिखित आज्ञा के, किसी मुकद्दमें में राजीनामा कर ले, देखो 21 Mad. 274.—बिना अदालत की इजाजत लिए जो साफ तौर पर मुकद्दमें की मिसिल में दर्ज करली जायगी, किसी भी मुकद्दमें में नाबालिग की ओर से राजीनामा न किया जा सकेगा (देखो आर्डर ३२, रूल ७; 9 C. 810; 17 All. 531.)—वह वली, जिसको विलायत (वली होने) का सर्टिफिकेट दे दिया गया है बिना अदालत की इजाजत के राजीनामा कर सकता है, देखो 8 C. L. J. 266.—यही बातें उस वली के सम्बन्ध में हैं जो कोर्ट आफ वार्ड्स की तरफ से मुकर्रर किया गया हो, देखो 25 C. W. N. 797 P. C.

यह आवश्यक नहीं है कि उसे शहादत में कुबूल किए जाने के काबिल बनाने के लिए किसी राजीनामा की रजिस्ट्री कराई जाय (देखो 2 C. W. N. 663; 47 C. 485; 57 I. C. 751)—रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की दफा १७ किसी अदालत की मुनासिब कार्रवाई के सम्बन्ध में लागू नहीं होती, चाहे वह प्लीडिंग हों या वे हुक्म हों जो अदालत ने दिए हैं, देखो 20 All. 171 P. C; 34 C. 837; 34 C. 456; 62 I. C. 653.—अगर वह राजीनामा किसी ऐसी जायदाद से सम्बन्ध रखता है जिसका जिक्र मुकद्दमें में नहीं है तो, उस जायदाद

की निस्वत हकीयत पैदा करने की गरज़ से, उस राजीनामा की रजिस्ट्री कराना ज़रूरी है, देखो 36 I. C. 193; 28 A. 78 और 58 I. C. 299.

जो राजीनामा मुकद्दमें की हद से बाहर है उनके सम्बन्ध में देखो 7 C. L. J. 492; 5 C. W. N. 485; 30 Mad. 421; और 30 Mad. 478.

रूल ३ अदालत को उस समय डिकरी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, जब कि राजीनामा की बात सन्तोषजनक रूप में सुवृत्त हो गई हो। अदालत को यह बात ज़रूर देख लेनी चाहिए कि वह राजीनामा एक कानूनी राजीनामा है, और इस बात को तय करने के लिए, कि वह राजीनामा ठीक है अथवा नहीं, वह उसकी असलियत पर विचार करेगी, देखो 53 I. C. 833. डिकरी की सिर्फ़ वही शर्तें अमल में लाई जा सकती हैं जो उस मुकद्दमें से सम्बन्ध रखती हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि राजीनामा की अर्जी में मुकद्दमें के बाहर की बातें रहती हैं और इसलिये ऐसी दशा में उचित मांग यह है कि डिकरी में उस राजीनामा की शर्तें पूरी पूरी लिख दी जायें, लेकिन उसके अनुसार डिकरी सिर्फ़ उतने ही हिस्से के सम्बन्ध में दी जाय जितने का सम्बन्ध उस मुकद्दमें से है (देखो 38 C. L. J. 72; 24 C. W. N. 177; 46 I. C. 358.)—मुल्हनामाकी डिकरी की शर्तें जहां तक कि उनमें ऐसी बातें आती हैं, जो उस मुकद्दमें के अन्दर नहीं थीं, इजरा के समय अमल में नहीं लाई जा सकतीं, लेकिन वह डिकरी उस इकरारनामा की शहादत होगी जो उन बातों के सम्बन्ध में किया गया है (देखो 62 I. C. 653; 34 C. 456 P. 463)

आर्डर २१, रूल ९० के अनुसार की गई कार्रवाई इजरा की कार्रवाई नहीं है और ऐसी दशा में आर्डर २३, रूल ३ लागू होता है, देखो 62 I. C. 608.

अदालत में रुपये की अदायगी—जब कि मुद्दई का दावा कर्ज़ा या नुकसान के वसूल पाने के लिए हो, तो मुद्दाअलेह अदालत में इतनी रकम जमा कर सकता है जिससे वह समझता है कि मुद्दई के दावा की पूरी पूरी बेबाकी हो जाती है (देखो आर्डर २४, रूल १)।

इस रकम जमा किए जानेकी नोटिस मुद्दईको अदालतके ज़रिये देदीजानी चाहिए, और ऐसी नोटिस मिल जाने के बाद मुद्दई को ब्याज न दिखाया जायगा (देखो आर्डर २४, रूल २ और ३)।

जब मुद्दई उस जमा किए हुए रुपये को लेकर उससे अपने दावा की कुल या कुछ बेबाकी मान ले, तो उस समय की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में देखो रूल ४.

यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि ज़ाबता दीवानी का आर्डर २४ केवल कर्ज़े या नुकसान की नालिशों के सम्बन्ध में लागू होता है, दूसरे तरह के मुकद्दमों में नहीं। वह हिसाब-किताब की नालिशों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता।

खर्च के लिए जमानत—ज़ाबता दीवानी के आर्डर २५, रूल १ में उन मामलों का वर्णन किया गया है जिनमें किसी मुकद्दमें में मुद्दई से ऐसे सारे खर्च

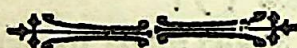
की अदायगी के लिए जमानत तलब की गई हो जो, किसी मुद्दाअलेह को उभरा पड़ा हो या उसके उठाने की संभावना हो। यह रूल उन हालतों में (जिनका वर्णन इस रूल में किया गया है) मुद्दाअलेह की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया है जिनमें, मुद्दई का दावा खारिज हो जाने की दशा में, उसको मुद्दई के अपना खर्चा वसूल करनेमें कठिनाईका सामना करना न पड़े (देखो 21 Cal 324)।

आर्डर २५ में केवल ऐसी हालतों का वर्णन किया गया है जिनमें मुद्दाअलेह के खर्चों की निस्वत मुद्दई से जमानत तलब की गई हो। वकील साक्ष्य को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दूसरी भी बहुत सी हालतें ऐसी हैं जिनमें ज़ाबता दीवानीके अनुसार खर्चोंकी जमानत तलबकी जा सकती है, उदाहरणार्थ मुद्दईको दीवालिया हो जाना (देखो आर्डर २२), दस्तावेज़ काबिल देह व वयके ऊपर सरकारी मुकद्दमें (देखो आर्डर ४१, रूल ४); इजराकी कार्रवाई मुलतवी किये जाने पर जमानत (देखो आर्डर ४१ रूल ५); उस हालतमें जमानत जबकि उस डिकरीकी इजरा मुलववी कर दीगई हो, जिसके विरुद्ध अपील दावा कीगई है (आर्डर ४१, रूल ६), अपीलान्टसे जमानत (देखो आर्डर ४१, रूल १०); जिन कौंसिलमें अपील करने के लिए सर्टिफिकेट दिए जाने के ऊपर जमानत (देखो आर्डर ४५, रूल ७)।

जमानत दाखिल न कर सकने की हालत में नालिश खारिज कर दी जायगी, लेकिन काफी वजह होने पर और मुद्दाअलेह को नोटिस दे दिए जाने के बाद नालिश की खारिजी का हुक्म मसूख किया जा सकता है (देखो आर्डर २५, रूल २)।

रेफरेन्स, नज़रसानी और निगरानी

Reference, Review and Revision.



रेफरेन्स—जब किसी मुकद्दमा या अपील की समाप्त के वक्त या उसके पहिले जिसमें डिकरी की अपील नहीं होती है या जब ऐसी डिकरी की इजरा कानून या ब्योहार सम्बन्धी कोई ऐसा प्रश्न पैदा हो जिसपर अदालत को अविश्वसन्देह हो तो अदालत को अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से या किन्हीं दूसरे फरीकैन की दरखवास्त पर हाईकोर्ट में रेफरेन्स पेश कर दे (देखो ज़ाबता दीवानी क्रा आर्डर ४६ रूल १)।

रेफरेन्स के सम्बन्ध का विस्तार ज़ाबता दीवानी के आर्डर ४६ के रूल १ में बतलाया गया है।

जब किसी अदालतको इस बातमें सन्देह हो कि अमुक मुकद्दमें की समाप्त अदालत खूफीफा कर सकती है, तो वह उस मामले को हाईकोर्टके फरीकैन

के लिए पेश कर सकती है (देखो आर्डर ४६ रूल ६) इस सम्बन्ध में, कि अपने किसी मातहत अदालत की कार्रवाई को निगरानी के लिए पेश करने का (जब कि ऐसी अदालत ने ग़लती से यह वय किया हो कि असुक्त नालिशकी समाप्त अदालत ख़फ़ीफ़ा के द्वारा होनी चाहिये या न होनी चाहिये) ज़िला की अदालत को क्या अधिकार है देखो आर्डर ४६ रूल ७।

नज़रसानी—कोई भी ऐसा शख्स, जिसे—

(क) किसी ऐसी डिकरी या हुक्म से, जिसकी अपील हो सकती है लेकिन जिसकी अपील दाख़र नहीं की गई है, या

(ख) किसी ऐसी डिकरी या हुक्म से जिसकी अपील नहीं हो सकती, या

(ग) किसी अदालत ख़फ़ीफ़ा के पेश किए हुये रेफ़रेन्स पर दिये गये फैसले से जिसे दुःख पहुंचा हो, नीचे लिखी किसी भी बिनाके ऊपर उस फैसलेकी नज़रसानी किये जाने के लिए दरख़वास्त दे सकता है—

१ किसी नई और आवश्यक बात या शहादतका मिल जाना जो उसे मुनासिब कोशिश करने के बाद उस समय जब कि डिकरी या हुक्म दिया गया था, मालूम न हो सकी थी, जिसे वह उस समय पेश नहीं कर सका था, या

२ किसी ऐसी ग़लती या भूल के होजाने से जो मिसिल के देखने से साफ़ ज़ाहिर होती हो, या

३ किसी दूसरी काफ़ी वजह पर (देखो आर्डर ४७, रूल १) जब हाई कोर्ट के अलावा किसी अदालत ने कोई डिकरी या हुक्म दिया हो।

(१) उपरोक्त पहली और दूसरी वजहके अतिरिक्त किसी दूसरी बिनाके ऊपर नज़रसानी के लिए दीजाने वाली दरख़वास्त उस जज को दी जायगी जिसने वह डिकरी या हुक्म दिया हो। यह दरख़वास्त उस जज को नहीं दीजा सकती जो उस पद पर उसका उत्तराधिकारी हो; लेकिन ऐसी किसी भी दरख़वास्त का फैसला उस जज का उत्तराधिकारी भी कर सकता है, जिसने कि डिकरी दी है अगर उस डिकरी देने वाले जजने आर्डर ४७ रूल ४ (२) (क) के अनुसार नोटिस जारी किए जाने का हुक्म दे दिया है।

(२) पहली और दूसरी बिना अर्थात् किसीनई और आवश्यकबात या शहादत के मिल जाने अथवा लिखने या अंको की ग़लती या भूल पर जो कि डिकरी से साफ़ ज़ाहिर होती हो, की जाने वाली नज़रसानी की दरख़वास्त उस जज को, जिसने कि फैसला दिया था अथवा उस जजको, दी जा सकती है जिसके पद पर उसका उत्तराधिकारी हुआ हो (देखो आर्डर ४७, रूल २)—नज़रसानी की कोई भी दरख़वास्त उस समय तक मंज़ूर न की जायगी जब तक कि दूसरे पक्ष को इसकी नोटिस न दे दी गई हो और जबतक कि नई बात या शहादत के मिलजाने के सम्बन्धमें कही गई बात ठीक ठीक साबित नहोजाय (देखो आर्डर ४७ रूल ४)।

दूसरी बातों सम्बन्धी ज़ाबतेके लिए देखो आर्डर ४७ रूल ५ से ९ तक। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रूल १० और बर्न दिया गया है।

नज़रसानी की दरख्वास्त में जाबते की तीन अवस्थाएं हैं। पहिली अवस्था में से दरख्वास्तें आती हैं जो कि एकतर्फी हों। अदालत को अधिकार है कि उसे या तो फौरन खारिज कर दे या इसबात की वजह दिखलाने के लिए कोई कब की मंजूरी देदे, कि नज़रसानी क्यों न मंज़ूर की जायगी। दूसरी अवस्था में कब या तो मंज़ूर किया जायगा या खारिज कर दिया जायगा। अगर कल कब करार दे दिया गया, तो तीसरी अवस्था पहुंच जाती है। मुकद्दमें की दुवारा सम-अत उसकी रूयदाद के ऊपर की जायगी (देखो 30 B. 56)

आर्डर ४७ रूल १ में दिए हुए “ किसी दूसरी काफी वजह पर ” शर्तों पर अदालतको और भी अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और उसे इस बातका अवसर प्राप्त होजाता है कि वह मुनासिब और काफी वजहों पर नज़रसानी को इजाज़त दे देवे, अगर न्याय के लिए ऐसी वजहें आवश्य हों (देखो 2 C. 31 P. C.; 33 C. 1323; 9 A. 36; 13 C. 62) ।

जुडीशल कमेटीने यह तय किया है कि “किसी दूसरी काफी वजह” शर्तों का अर्थ ऐसी वजहें समझना चाहिए, जो पहिलेके क्लॉजोंमें बतलाई गई हैं; देखो 26 C. W. N. 697. P. C. इसलिए ‘वजह’ ऐसी होनी चाहिए जो ऊपरके दो क्लॉजोंमें बतलाई हुई अर्थात् (१) नई और आवश्यक बात या शहादतका मित्र जाना, या (२) किसी ऐसी ग़लती या भूलका होना जो मिसिलसे साफ़ मालूम होती हो, की किस्ममें से हो; देखो 51 C. 70.

वकीलका गैर-हाज़िर होना काफी वजह नहीं है; देखो 62 I.C.253। दरख्वास्त देने वालेकी लापरवाहीसे पैदा हुई ग़लती काफी वजह नहीं है; देखो 44 I. C. 61.

कुलबैञ्च या किसी ऊंची अदालत द्वारा किसी नए कानूनका निकलना नज़रसानीके लिए काफी वजह नहीं है. देखो 6 A. 292; 24 Cal. 334.—जिस फ़रीक़को एकतर्फी डिकरी से दुःख पहुंचा हो, वह फ़ैसलेकी नज़रसानीकी दरख्वास्त दे सकता है; देखो 6 A. 65; 20 W. R. 284; 20 B. 281.

आर्डर ४७ का रूल ८ यह बात बिल्कुल अदालतकी मर्जी पर छोड़ देता है कि, जब नज़रसानीकी मंजूरी दी जाय तो उस समय उस कुल मुकद्दमेंके ऊपर नए सिरेसे विचार किया जाना चाहिए न कि उसके केवल एक हिस्सेके ऊपर (देखो 27 C. L. J.326.)

नज़रसानी की दरख्वास्तमें साफ़ साफ़ वे वजहें लिख दी जानी चाहिए जिनपर एतराज़ (उज्र) है और उसके साथ उस हुक्मकी एक नकल भी तली होनी चाहिए जिसकी नज़रसानी कराई जाने को है। उसके ऊपर अपीलकी तरह उस वकीलकी तस्दीक़ होनी चाहिए जो कि उसे पेश कर रहा है।

नज़रसानीकी दरख्वास्त, आधा कोर्ट-फीस स्टाम्प देकर ९० दिनके भीतर (देखो कानून मियादका आर्टि० १७३) दी जानी चाहिए। अगर डिकरी या

हुकम अदालत खफीफा का है, तो मियादकी मुदत १५ दिन होगी; (देखो कादून मियादका आर्टि० १६१)

नज़रसानी की दरख्वास्तको खारिज करने वाले हुकम की अपील नहीं हो सकती, लेकिन जिस हुकमसे दरख्वास्त मंजूर की गई है उस पर इस बिना पर उज्रदारीकी जा सकती है कि वह (१) रूल २ के विरुद्ध है, या (२) रूल ४ के विरुद्ध या (३) उस समय, जब कि मियादकी मुदत गुज़र चुकी थी, और बिना क़ाफ़ी वज़हके दरख्वास्त दी गई थी, [देखो आर्डर ४७ रूल ७ और आर्डर ४३ रूल १ (डब्ल्यू.)]

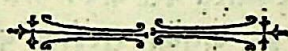
अदम पैरवीमें खारिज हुई नज़रसानीकी दरख्वास्त फिर बहाल हो सकती है (देखो आर्डर ४७ रूल ७)

निगरानी—निगरानीके सम्बन्धमें हाईकोर्टके क्या अधिकार हैं, इसके लिए देखो ज़ावता दीवानीकी दफ़ा ११५—अदालत खफीफाकी डिकरियाँ और उसके हुकमोंके सम्बन्धमें हाईकोर्टके अधिकार, भ्रान्तीय अदालत खफीफा ऐक्टकी दफ़ाओं में बतलाए गए हैं ।

ज़ावता दीवानीकी दफ़ा ११५ के अनुसार की जाने वाली निगरानियोंमें हाईकोर्ट आम तौर पर वाक़यात सम्बन्धी फैसलेमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है अगर शह़ादतसे उसका अच्छी तरह से समर्थन हो गया है; (देखो 20 C. W. N. 1110; 34 L. C. 527; 27 Bom. 563)—अगर वह फैसला अनुमान की हुई बातोंके आधार पर दिया गया हो जिनका समर्थन नहीं हुआ है, तो वह उसमें हस्तक्षेप कर सकती है; देखो 14 A. L. J. 890; 38 A. 690; 27 A. 531.)

जिस हुकमसे अदालत खफीफ़ाने नज़रसानीकी दरख्वास्त बेजा तौर पर खारिज कर दिया हो, उसकी नज़रसानी हाईकोर्ट कर सकती है; (देखो 29 A. 468; 31 A. 610)

अपीलें और मुकद्दमोंकी वापसी



प्रारम्भिक डिकरियोंकी अपीलें—हर एक ऐसी डिकरीकी अपील, जो किसी प्रारम्भिक अधिकार रखने वाली अदालत द्वारा दी गई हो, उस अदालतमें की जा सकेगी जिसे ऐसी अदालतके फैसले की अपील सुननेका अधिकार है ।

एकतर्फी प्रारम्भिक डिकरीके खिलाफ़ भी अपील हो सकती है । उस डिकरीकी अपील न हो सकेगी जिसे अदालतने फ़रीक़नकी रज़ामन्दी से दी हो; (देखो ज़ावता दीवानीकी दफ़ा ९६)

कतई डिकरीके खिलाफ अपीलके सम्बन्धमें, जब कि प्रारम्भिक डिकरीके विरुद्ध अपील न की गई हो, देखो ज़ाबता दीवानीकी दफा ९७

हर एक अपील एक मेमोरैण्डम (याददाश्त अपील या मौजबात अपील) के रूपमें पेश की जायगी जिसपर अपीलाण्ट या उसके वकीलके हस्ताक्षर होंगे। इसके साथ उस डिकरीकी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, और (जब तक कि अदालत अपील उसे अलग न कर दे) उस फैसलेकी एक बाज़ाबता नक़ल भी होनी चाहिए। इस मेमोरैण्डम (याददाश्त अपील) में, संक्षेपमें और अल्प मद्दोंमें, बिना किसी दलील या विवरणके वे वजहें लिखी रहेंगी जिनके द्वारा डिकरीके सम्बन्धमें एतराज़ किया जाता है; और इन वजहोंका नम्बर सिक्केदार होगा (देखो आर्डर ४१ रूल १)

अपीलमें कौनसी वजहें ली जा सकती हैं, इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ रूल २। याददाश्त अपील कब खारिज की जा सकती है, इस सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ रूल ३

कई एक मुद्दइयान या मुद्दाअलेहोंमें से एक ही शख्स कुल डिकरीके मंसूख करा सकता है, जब तक कि उन सबकी बिना एक हो (देखो आर्डर ४१ रूल ४)

किसी डिकरी या हुक्मके सम्बन्धमें, जिसकी अपील की गई है, होने वाले कार्रवाई और इजराकी मुलतवीके सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ रूल ५ से ८ तक।

अपीलके मंज़ूर कर लिए जाने पर, की जाने वाली कार्रवाईके सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ रूल ९ से १५ तक। बिना रेस्पॉण्डेण्टको नोटिस दिए हुए अपील खारिज की जा सकती है, (देखो आर्डर ४१ रूल ११)—समाप्तके लिये के ज़ाबतेके सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ के रूल १६ से २९ तक।

अपीलमें दिए जाने वाले फैसलेके सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ के रूल ३० से ३४ तक। अपील में दी जाने वाली डिकरी के सम्बन्ध में देखो रूल ३५ से ३७ तक।

मुकद्दमेंको वापस कर देने के लिए अदालतके अधिकारके सम्बन्धमें देखो आर्डर ४१ रूल २३.

विवरण—अपीलकी दरख़वास्त पेश करने वाले वकीलको चाहिए कि वह उस याददाश्त अपीलके नीचे इस बातकी तस्दीक़ कर दे कि उसने मुकद्दमेंके कागज़ात अच्छी तरहसे देख लिए हैं और यह कि उसकी रायमें अपील करने के लिए माकूल और काफ़ी वजूहात हैं और यह कि वह इस बातका इक़रार करता है कि वह अपीलकी समाप्तके वक्त हाज़िर होकर उन वजूहातकी निस्वत पेश करेगा जो कि याददाश्त अपीलमें बतलाए गए हैं।

जो डिकरियां अदालत ख़फ़ीफ़ाकी दी हुई हों उसकी अपील नहीं की जा सकती। खास और उचित हालतोंमें प्रान्तीय अदालत ख़फ़ीफ़ा ऐक्टके अन्तर्गत आईकोर्ट उनकी मज़रसानी कर सकती है।

स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट (कानून दादरसी खास) की दफा ९ के अनुसार दिया हुआ हुक्म भी काबिल अपील नहीं है ।

अपील की तारीख वह तारीख है जिसको याददास्त अपील अदालतमें दाखिल की गई हो, वह नहीं जिस तारीखको कमी कोर्ट-फीस अदा किया गया हो। अपील पेश करनेमें देर होने और उसके मंजूर करने सम्बन्धी अदालतके अख्या-रातके लिये देखो कानून मियादकी दफा ५—नकल लेनेके लिये मुकर्रर मियादके सम्बन्धमें, देखो कानून मियादकी दफा १२—कई एक मुश्तरका अपीलान्टों या रैस्पान्डेण्टोंमें से किसी एक के मर जाने से कुल अपील बन्द नहीं होजाती, (देखो आर्डर २२ रूल ११)

सिर्फ खर्च की बात दिये गये हुक्मके ही खिलाफ अपील न हो सकेगी जब तक कि उसमें कोई सिद्धान्त (उसूल) की बात छिपी न हो, (देखो 28 Cal. 567; 11 Cal. 359; 34 Cal. 878.)

अदालत अपीलके अख्यारात के सम्बन्धमें देखो ज़ाबता दीवानीकी दफा १०७, आर्डर ४१ रूल २३, २५, २७, २८, २९, ३३ ।

मुफलिस्की ओरसे की जाने वाली अपीलोंके सम्बन्धमें देखो आर्डर ४५ ।

यह तय हुआ है कि मुकद्दमा वापस करनेके सम्बन्धमें अदालत अपीलके अधिकार सिर्फ आर्डर ४१ रूल २३ में बतलाए हुये मुकद्दमों तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि अदालतको दफा १५१ में स्वीकृत अधिकारोंके अनुसार मुकद्दमोंको वापस करनेका पूर्ण अधिकार है; देखो 44 C. 929 F. B.; 45 C. 94; 43 C. 938; 46 C. 738.

दूसरी अपील—आर्डर ४१ के रूल, जहां तक सम्भव हो सकता है, उन अपीलोंके सम्बन्धमें लागू होंगे जो अदालत अपीलकी दीहुई डिकरियोंके विरुद्ध दायर की गई हों; (देखो आर्डर ४२ रूल १)

१ हर एक ऐसी डिकरीकी अपील हाईकोर्टमें हो सकेगी जो उसकी मातहत किसी भी अदालतने नीचे लिखी किसी भी बिना पर अपीलमें दी हो, अर्थात्:—

- (क) यह कि फैसला कानून अथवा किसी रिवाज के, जो कि कानून का असर रखता है, विरुद्ध है;
- (ख) यह कि फैसले में कानून अथवा रिवाज के, जो कानून का असर रखता है, किसी आवश्यक प्रश्न का निर्णय नहीं किया गया है;
- (ग) यह कि ज़ाबता दीवानी अथवा उस समय प्रचलित किसी दूसरे कानून के द्वारा, निश्चित ज़ाबते में कोई भारी भूल या नुकस हो गया है, जिससे सम्भव है कि रूपदाद के ऊपर उस मुकद्दमे के फैसले में भूल अथवा नुकस हो जाय ।

२ अदालत अपील की एकतर्फी डिकरी की अपील हो सकती है (देखो दफा १००)

सिवाय उन वज्रहात के ऊपर जो कि ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १०० में बतलाई गई हैं, दूसरी अपील नहीं की जा सकती (देखो दफ़ा १०१)

किसी भी ऐसे मुकद्दमें में, जिसकी समाप्त अदालत ख़फ़ीफ़ा में हो सकती है, दूसरी अपील न की जा सकेगी, जब कि प्रारम्भिक मुकद्दमें के दावा की रक़म या मालियत पांच सौ रुपये से अधिक न हो (देखो दफ़ा १०२) ।

हुकों की अपील—ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १०४ (१) के अनुसार नीचे लिखे हुकों की अपील हो सकेगी और, सिवाय उस दशा के जब कि ज़ाबता दीवानी में या उस समय प्रचलित किसी दूसरे क़ानून में इस सम्बन्ध में कोई खास व्यवस्था कर दी गई हो, किसी भी दूसरे हुक़म की अपील न हो सकेगी—

(क) वह हुक़म जिससे पंचायत का फैसला रद्द हो गया हो, जब कि अदालत द्वारा नियत किए गए समय के भीतर पंचायत ने अपना फैसला पूरा न कर दिया हो;

(ख) वह हुक़म जो किसी ऐसे पंचायती फैसले में दिया गया हो जिसे कोई मामला खास मामला (स्पेशल केस) करार दिया गया हो;

(ग) वह हुक़म जिसमें किसी पंचायती फैसले की दुस्ती या उसमें कोई काट-छांट हुई हो;

(घ) वह हुक़म जिसमें किसी मामले को पंचायत में पेश करने सम्बन्धी इकरारनामा को मंज़ूर या इन्कार किया गया हो;

(ङ) वह हुक़म जिससे कोई मुकद्दमा मुस्तवी कर दिया गया हो या उसके मुस्तवी कर देने से इन्कार कर दी गई हो, जब कि उस मुकद्दम को पंचायत में दे दिए जाने का इकरारनामा हुआ हो;

(च) वह हुक़म जिससे बिना अदालत के दख़ल के पंचायत में दिए हुए फैसले को मंज़ूर किया गया हो या मंज़ूर करने से इन्कार किया गया हो;

(छ) ज़ाबता दीवानी की दफ़ा ९५ के अनुसार दिया हुआ हुक़म;

(ज) ज़ाबता दीवानी की किसी भी दफ़ा के अनुसार दिया गया हुक़म जिससे किसी पर जुर्माना किया गया हो या किसी शख़्स की गिरफ़्तारी या उसे दीवानी जेल में कैद रखने का हुक़म दिया गया हो, सिवाय उस दशा में जब कि ऐसी गिरफ़्तारी या कैद का हुक़म किसी डिकरी की इज़रा में दिया गया हो;

(झ) कोई भी ऐसा हुक़म जो उन रूलों के अनुसार दिया गया हो जिनके विरुद्ध अपील किए जाने की रूलों में खास व्यवस्था की गई हो ।

ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १०४ (२) के अनुसार अपील में दिए गए किसी भी हुक़म की अपील न हो सकेगी, देखो ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १०४ (२)

ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १०४ के अनुसार नीचे लिखे हुए हुकों की अपील हो सकेगी, अर्थात्—

(१) वह हुकम जो आर्डर ७ के रूल १० के अनुसार दिया गया हो और जिसके जरिये मुनासिब अदालत में पेश किए जाने के लिए अर्जीदावा वापस कर दिया गया हो;

(२) हुकम जो आर्डर ८ के रूल १० के अनुसार दिया गया हो और जिसमें किसी फरीक के खिलाफ फैसला दिया गया हो;

(३) वह हुकम जो आर्डर ९ के रूल ९ के अनुसार दिया गया हो, और जिससे ऐसे मामले में, (जिसकी अपील हो सकती है) किसी मुकदमें के खारिज कर दिए जाने वाले हुकम को मंसूख कराने के लिए दी गई दरखास्त खारिज कर दी गई हो;

(४) वह हुकम जो आर्डर ९ के रूल १३ के अनुसार दिया गया हो और जिससे (ऐसे मामले में जिसकी अपील हो सकती है) एकतर्फी डिकरी की मंसूखी का हुकम जारी कराने के लिए दी गई दरखास्त खारिज कर दी गई हो;

(५) वह हुकम जो आर्डर १० के रूल ४ के अनुसार दिया गया हो और जिससे किसी फरीक के खिलाफ फैसला दिया गया हो;

(६) आर्डर ११ के रूल २३ के अनुसार दिया हुआ हुकम;

(७) जायदाद की कुर्की के लिए आर्डर १६, रूल १० के अनुसार दिया गया हुकम;

(८) आर्डर १६, रूल २० के अनुसार दिया हुआ वह हुकम जिससे किसी फरीक के खिलाफ फैसला दिया गया हो;

(९) वह हुकम जो किसी दस्तावेज के या किसी तहरीर (Endorsement) के मसविदे के ऊपर की गई उज्जदारी के ऊपर आर्डर २१ रूल ३४ के अनुसार दिया गया हो;

(१०) किसी नीलाम को मंसूख करने या मंसूख करने से इन्कार करने के लिए आर्डर २१ के रूल ७२ या रूल ९२ के अनुसार दिया गया हुकम,

(११) वह हुकम जो आर्डर २२ के रूल ९ के अनुसार दिया गया हो और जिससे इजाजत दी गई हो या देने से इन्कार की गई हो;

(१२) किसी मुकदमें के सकूत (बन्द होजाने) या उसकी खारिजी को मंसूख करने से इन्कार करने के लिए आर्डर २२, रूल ९ के अनुसार दिया हुआ हुकम;

(१३) किसी इकरारनामा, राजीनामा या कर्जे की बेबाकी (Satisfaction) को दर्ज कागजात करते हुए या दर्ज करने से इन्कार करते हुए, आर्डर २३, रूल ३ के अनुसार दिया हुआ हुकम;

(१४) आर्डर २५ के रूल २ के अनुसार दिया गया हुकम, जिससे (ऐसे मुकदमें में जिसमें अपील हो सकती है) किसी मुकदमें की खारिजी को मंसूख करने के लिए दी गई दरखास्त नामंजूर कर दी गई हो;

(१५) आर्डर ३४ के रूल ३ में रूल ८ के अनुसार दिया हुआ हुक्म जिससे रेहननामा के रुपये की अदायगी की मुदत बढ़ाने से इन्कार कर दी गई हो;

(१६) आर्डर ३५ के रूल ३, रूल ४, या रूल ६ के अनुसार तस्फिया की नालिशों में दिए हुए हुक्म;

(१७) आर्डर ३८ के रूल २, ३ या ६ के अनुसार दिया हुआ हुक्म;

(१८) आर्डर ३९ के रूल १, २, ४ या रूल १० के अनुसार दिया हुआ हुक्म;

(१९) आर्डर ४० के रूल १ या रूल ४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म;

(२०) आर्डर ४१, रूल १९ के अनुसार, किसी अपील को दुबारा लेने, या आर्डर ४१, रूल २३ के अनुसार दुबारा उसकी समाअत करने से इन्कार करने के लिए दिया हुआ हुक्म;

(२१) आर्डर ४१, रूल २३ के अनुसार दिया हुआ हुक्म जिससे कोई मुकदमा वापस किया गया हो, जब कि अदालत अपील की डिकरी के विरुद्ध अपील हो सकती है;

(२२) वह हुक्म जो हाईकोर्ट के अलावा किसी दूसरी अदालत ने आर्डर ४५ के रूल ६ के अनुसार सर्टीफिकेट देने से इन्कार करने के लिए दिया हो;

(२३) आर्डर ४७, रूल ४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म, जिससे नज़रसानी की दरखवास्त मंजूर की गई हो (देखो आर्डर ४३, रूल १)

नोट—आर्डर ४१ के रूल, जहां तक सम्भव हो सकेगा, उन अपीलों के सम्बन्ध में लागू होंगे जो हुक्मों के विरुद्ध दायर की गई हैं (देखो आर्डर ४३, रूल २)

इलाहाबाद में आर्डर ४३ के साथ रूल ३ जोड़ दिया गया है ।

न्यूनतापूरक कार्यवाही

Supplemental Proceedings

इस अभिप्राय से, कि न्याय को बाधा न पहुंचने पावे, अदालतको अधिकार है कि वह, अगर ऐसा विधान है तो,

(क) कल्ल फैसला मुद्दाअल्लेह की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी कर दे;

(ख) उसकी जायदाद फैसला होने के कल्ल कुर्क करा ले ;

(ग) थोड़े समय के लिये हुक्म इम्तनाई जारी कर दे ;

(घ) रिसीवर नियुक्त कर दे ;

(ङ) ऐसे दूसरे दरमियानी हुक्म दे देवे जो उचित और सुविधा-जनक जान पड़ें ।

नोट—न्याय में बाधा न पहुँचने देने के अभिप्राय से मुकदमों के दौरानमें रुकवट देने सम्बन्धी अदालत के अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन आपत्ता दीवानी की दफा १५ में किया गया है।

फैसले के पहिले गिरफ्तारी—जब कि हलफनामा से या और किसी प्रकार अदालत को इतमीनान हो जाय कि—

(क) मुद्दाअलेह मुकदमोंमें देर करने, उससे बचने या उसमें रुकावट डालने के इरादे से (१) कहीं भाग गया है या (२) भाग जाने वाला है या (३) अदालत के अधिकारक्षेत्र से अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा हटा दिया है या अलग कर दिया है, या यह कि मुकदमों में रुकावट डालने या उसमें देर करने के इरादे से मुद्दाअलेह ब्रिटिश भारत से बाहर चला जाने वाला है, तो वह मुद्दाअलेह की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट जारी कर सकती है।

लेकिन शर्त यह है कि उस समय उसकी गिरफ्तारी न की जायगी, अगर वह वारण्ट की तामील करने वाले अफसर को इतनी रकम अदा करदे जो मुद्दई के दावा का मतालिया बेचाकु कर देने के लिए काफी हो (देखो आर्डर ३८ रूल १)

फैसले के क़बूल कुर्की—१—जब अदालत को हलफनामा से या और किसी तरह पर इतमीनान होजावे कि किसी डिकरी की जो कि उसके ऊपर दी गई है, इजरा में रुकावट डालने या देर करने के लिये मुद्दाअलेह—

(क) अपनी कुल जायदाद या उसका कुछ हिस्सा अलग कर देने वाला है, या

(ख) उस कुल जायदाद या उसके कुछ हिस्से को अदालत के अधिकारक्षेत्र की स्थानीय सीमा से बाहर हटा देने वाला है,

तो अदालत को अधिकार है कि वह मुद्दाअलेह को ज़मानत दाखिल करने का हुक्म या इस बात का कारण दिखलाने के लिए हाज़िर होने का हुक्म दे कि वह ज़मानत क्यों नहीं दाखिल कर सकता।

२ मुद्दई को चाहिए कि वह उस जायदाद को, जो कि कुर्क किए जाने को है, और उसकी अन्दाज़न कीमत भी बता दे।

३ अदालत को यह भी अधिकार है कि वह, अपने उस हुक्म में इस तरह बतलाई हुई कुल जायदाद या उसके किसी हिस्से की, कुछ शर्तों के साथ, कुर्की का हुक्म दे दे (देखो आर्डर ३८, रूल ५)—विस्तृत ज़ावता के सम्बन्ध में देखो रूल ६ से ९ तक।

फैसले के क़बूल (पहिले) की हुई कुर्की से बाहरी आदमियों के उन हक़क पर कोई असर न पड़ेगा जो इस कुर्की के पहिले के हैं और न इससे किसी डिकरीदार को नीलाम के लिए दरख़वास्त देने की रुकावट हो सकेगी (देखो आर्डर ३८, रूल १०)

फैसले के क़बूल (पहिले) कुर्क की हुई जायदाद डिकरी की इजरा में फिर दुबारा कुर्क न की जायगी (देखो आर्डर ३८ रूल ११)—खेती की पैदा-

वार, जो कि किसी किसान के कब्जे में है, फैसले के पहिले कुर्क नहीं की जा सकती (देखो आर्डर ३८, रूल १२) ।

अदालत को इस बात का पूरा पूरा इतमीनान हो जाना चाहिए कि वास्तव में मुद्दाअलेह रुकावट डालने या देर करने के इरादे से जायदाद को अलग कर देने वाला है (देखो 13 C. L. R. 356; 44 I. C. 240; 73 I. C. 721)—सिर्फ योंही कह देना कि मुद्दाअलेह अपनी जायदाद हटा देना चाहता है, काफी न होगा (देखो 29 Bom. L. R. 1228)—अदालत को इतमीनान कराने के लिए मुद्दे के पास काफी सुबूत होना चाहिए (देखो 44 I. C. 240)

जो मुद्दे किसी रैहननामा की बाबत की गई नालिश में इस बिना पर, कि जायदाद मरहूना ज़मानत के लिए काफी नहीं है, मुद्दाअलेह की दूसरी जायदाद कुर्क करवाना चाहता हो, उसे फैसले के कबल कुर्क कराने का हक है (देखो 46 C. 245)

आर्डर ३८ रूल ६ के अनुसार कुछ शर्तों के साथ कुर्क का हुक्म उस समय तक न दिया जाय जब तक कि मुद्दाअलेह या तो इस बात की वजह न दिखला सका हो कि उसे क्यों न ज़मानत दाखिल करनी चाहिए या ज़मानत न दाखिल कर सका हो । आर्डर ५ (३) के अनुसार शर्तिया हुक्म उस समय तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि उसके साथ कलॉज़ (१) के अनुसार एक और हुक्म भी न दिया जाय जिसमें ज़मानत दाखिल करने या वजह ज़ाहिर करने की हिदायत की गई हो (देखो 57 I. C. 907)

फैसले के कबल कुर्क की हुई जायदाद मनकूला मुकद्दमें की समाप्त किए जाने के पहिले नीलाम की जा सकती है (देखो आर्डर ३९, रूल ६)

प्रान्तीय अदालत खफीफा को फैसले के कबल जायदाद गैर-मनकूला की कुर्क का हुक्म देने का अधिकार है जो फैसले के कबल कुर्क कराने के अधिकार से बिल्कुल भिन्न है, देखो 28 C. W. N. 1056 F. B., 82 I. C. 109.

हुक्म इम्तनाई—अदालत अस्थायी (कुछ समय के लिए) हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है, अगर हलफनामा या और किसी तरह से यह बात साबित हो जाय कि (अ) जायदाद के जिसकी निस्वत झगड़ा है, मुकद्दमें के किसी दूसरे फरीक द्वारा नष्ट कर दिए जाने, लुकसान कर डाले जाने या मुन्तकिल कर दिए जाने, अथवा किसी बिकरी की इजरा में बेजा तौर पर नीलाम कर दिए जाने का भय है या (ब) यह कि अपने महाजनों को धोखा देने की नीयत से मुद्दाअलेह अपनी जायदाद को हटा देने या उसे अलग कर देने या बँट डालने की धमकी देता है या ऐसा करने का इरादा करता है (देखो आर्डर ३९ रूल १)

शिकस्त मुआहिदा (मुआहिदे का तोड़ देना)—को जारी रखने या उसे दोहराए जाने को रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई जारी करने के सम्बन्धमें देखो आर्डर ३९

३९, रूल २। सभी दशाओं में सुखालिफ फरीक (विरोधी पक्ष) को दी जानै वाली नोटिस हुक्म इम्तनाई जारी करने के पहिले जारी की जानी चाहिए, सिवाय उस दशा में जब कि देर करने से उद्देश्य में बाधा पड़ती हो (देखो आर्डर ३९, रूल ३) — किसी भी ऐसे फरीकके दरखास्त देने पर, जो इस हुक्मसे असन्तुष्ट है, हुक्म इम्तनाई खारिज कर दिया जायगा, बदल दिया जायगा या रद्द कर दिया जायगा (देखो आर्डर ३९, रूल ४)। कापोरेशन के नाम हुक्म इम्तनाई जारी करने के सम्बन्ध में देखो आर्डर ३९, रूल ५।

हुक्म इम्तनाई दो प्रकार के होते हैं। एक तो अस्थायी (आरिजी) और दूसरा सार्वकालिक (दवामी)। अस्थायी (आरिजी) हुक्म इम्तनाई का उद्देश्य यह है कि जिस जायदाद की निश्चित झगड़ा है वह मुकद्दमें के दौरान में नष्ट न कर दी जाय या इस तरह खराब न कर दी जायकि फिर वह दुरुस्त न की जा सके, या मुन्तकिल न कर दी जाय। उसूल यह है कि जब तक फरीकैन के हकूक का तस्फिया न होजाय तब तक वह जायदाद ज्यों की त्यों अपनी असली हालत में बनी रहे। अस्थायी हुक्म इम्तनाई आर्डर ३९ के रूल १ और २ के नियमानुसार दिया जाता है और वह मुकद्दमें के दौरान में किसी भी समय दरखास्त देने पर दिया जा सकता है। सार्वकालिक (दवामी) हुक्म इम्तनाई स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट (कानून दादरसी खास) की दफा ५४—५७ के नियमानुसार दिया जाता है। ऐसा हुक्म सिर्फ एक डिकरी के जरिये दिया जा सकता है जो मुकद्दमें के रूयदाद के ऊपर समाप्त के वक्त दी गई हो। हुक्म इम्तनाई ताकीदी के सम्बन्ध में देखो स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट की दफा ५५।

हुक्म इम्तनाई जारी करने या जारी करनेसे इन्कार कर देने के सम्बन्ध में अदालतका जो अधिकार है, वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अस्थायी हुक्म इम्तनाई जारी करनेके पहिले यह बात अच्छी तरहसे साबित होजानी चाहिए कि जबतक एक हुक्म इम्तनाई के जरिये मुदाअलेह फौरन् रोक न दिया जायगा, मुकद्दमें के दौरान में जायदाद को ऐसा मुकसान पहुंच जायगा जो फिर कभी पूरा न किया जा सकेगा। अदालत पहिले यह देखेगी कि फरीकैन के बीच वास्तविक झगड़ा है और फिर यह कि मुकद्दमा जीतने पर किस शख्स को घाटा रहेगा, अगर हुक्म इम्तनाई जारी न किया गया; किन्तु वह इस बात का ध्यान हमेशा रखेगी कि जायदाद गैर-मनकूला अपनी ज्योंकी त्यों हालत में बनी रहे। अस्थायी हुक्म इम्तनाई के सम्बन्ध में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, इसके लिए देखो 16 C. L. J. 555; 10 C. W. N. 173, 8 C. W. N. 151; 23 M. L. J. 316; 17 C. L. J. 429; 21 C. L. J. 462; 26 M. 174; 43 I. C. 24; 1 Pat. L. J. 560; 21 C. L. J. 464; 46 C. 10001 और 23 C. W. N. 677.

किसी ऐसे शख्स के नाम हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता है जो कि उस मुकद्दमें में फरीक नहीं है, देखो 3 Pat. L. J. 456; 44 I. C. 496; 51 I. C. 108.

अस्थायी (आरिजी) हुक्म इस्तनाई के जारी कर देने से उस जायदाद की बाद में की गई मुन्तकिली बेज़ाबता और नाजायज़ न होगी। हुक्म उद्दूली के लिये दण्ड की व्यवस्था आर्डर ३९ रूल २ (३) में की गई है (देखो 9 A. 497; 25 A. 431)—कुर्क की हुई जायदाद की मुन्तकिली का असर दूसरा है, क्योंकि दफा ६४ के अनुसार उन दावों के सामने, जो उस कुर्क के सम्बन्ध में किये गए हैं, ऐसी मुन्तकिली नाजायज़ है।

दण्ड की व्यवस्था सिर्फ उसी किस्म के मुकद्दमों के सम्बन्ध में नहीं की गई है जिनका वर्णन आर्डर ३९, रूल २ में है। आर्डर ३९ दफा ९४ के साथ पढ़ा जाना चाहिये। किसी काम के करने या न करने के लिए दिए गए हुक्म को उद्दूली करने के सम्बन्ध में आर्डर ३९ रूल २ (ए) लागू होता है, देखो 44 L.C. 56 (M)।

आर्डर ३९ रूल २ में किसी मुआहिदेको तोड़े जाने से रोकने के लिए अस्थायी हुक्म इस्तनाई जारी किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। शिकस्त मुआहिदा को रोकने के लिए सर्व-कालिक (दवामी) हुक्म इस्तनाई स्पेसिफिक रिलीफ़ ऐक्ट (कानून दादरसी ख़ास) की दफा ५६ (एफ़) और दफा ५७ के नियमानुसार दिया जा सकता है।

38 B. 381 में जटिस बीमैन ने इस बात पर सन्देह किया कि, क्या मुस्लिम अदालतों को अस्थायी (आरिजी) हुक्म इस्तनाई ताकीदी भी करने का अधिकार है? 41 M. 238. में इस फैसले का अनुकरण न कर यह तय किया गया कि स्पेसिफिक रिलीफ़ ऐक्ट की दफा ५३ में अस्थायी हुक्म इस्तनाई का वर्णन किया गया है, उसमें ताकीदी हुक्म इस्तनाई (Mandatory Injunction) निकाल नहीं दिया गया है, देखो 41 C. 436; 28 I.C. 121.

इजरा और नीलाम की मुलतवी के लिए जारी किये गये हुक्म इस्तनाई के सम्बन्ध में देखो 33 A. 79 F.B. ; 10 A. 89; 16 C. L. J. 555; 23 M. L. J. 316; 17 C. W. N. 964.

जब मुद्दई और मुद्दाअलेह उन जायदादों के मालिक हों जो एक दूसरे से मिली हुई हैं और मुद्दाअलेहों को ज़ाबता दीवानी की दफा १४४ के अनुसार मुद्दइयान के खिलाफ़ हुक्म मिल गया हो, तो वे एलान और मुद्दाअलेहों को रोकने का हुक्म इस्तनाई जारी करने के लिए नालिश कर सकते हैं और इसमें दफा १४४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म कोई रुकावट न डाल सकेगा। दफा १४४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म स्वयं एलान और हुक्म इस्तनाई के लिए दावा की बिना पैदा करता है, देखो 68 I. C. 180; 42 M. L. J. 179.

हुक्म इस्तनाई जारी करने या उसे जारी करने से इन्कार करने वाले हुक्म की आर्डर ४३, रूल १ (आर) के अनुसार अपील हो सकती है, देखो 95 A. 425; 27 I. C. 131; 17 C. W. N. 996.—किसी हुक्म इस्तनाई की अपील

करने के लिए आर्डर ३९, रूल २ (३) के अनुसार कार्रवाई करने से इन्कार करने वाले हुक्म की अपील हो सकती है, देखो 39 M. 907 F. B.

हुक्म इस्तनाई की डिकरी की इजरा के फार्म के तरीके के सम्बन्ध में देखो आर्डर २१, रूल ३२ ।

अस्थायी हुक्म इस्तनाई के फार्म के सम्बन्ध में देखो ज़ाबता दीवानी का ज़मीमा (एफ), फार्म नं० ८ ।

~~रिसीवर की नियुक्ति—किसी मुकद्दमें के सही साबित होजाने पर अदालत को अधिकार है कि वह—~~

(क) डिकरी के पहिले या बाद में किसी जायदाद का रिसीवर मुकर्र कर दे;

(ख) किसी भी ऐसे शख्स को अलग करदे जिसके कब्जे या हिफाज़त में वह जायदाद है,

(ग) उस जायदाद को उस रिसीवर के कब्जे, हिफाज़त या प्रबन्ध में दे दे; और

(घ) उस रिसीवर को नालिशें दायर करने या उनकी निस्वत जवाबदेही करने, जायदाद का प्रबन्ध (इन्तज़ाम) करने, उसकी रक्षा और उन्नति (तरक्की) करने, लगान वसूल करने इत्यादि का अधिकार दे दे (देखो आर्डर ४०, रूल १) ।

रिसीवर के मुआबिज़ा, उसके अधिकारों (हक्क), कर्तव्य इत्यादि के सम्बन्ध में देखो आर्डर ४०, रूल २—५;

रिसीवर नियुक्त (मुकर्र) करने के अधिकार का उपयोग करना अदालत की इच्छापर है । रिसीवर नियुक्त करने सम्बन्धी शर्तें वही हैं जो अस्थायी हुक्म इस्तनाई जारी करने के लिए आवश्यक हैं । यह आवश्यक है कि मामले की हर एक बात प्रकट कर दी जाय और अदालत को इस बात का विश्वास होजाय कि रिसीवर का नियुक्त किया जाना उचित और उपयुक्त है । अदालत उस समय रिसीवर नियुक्त न करेगी जब कि जायदाद की निस्वत हक का दावा किया गया हो जो उस समय किसी मुद्दाअलेह के कब्जे में है, जो एक कानूनी हकीयत के अनुसार उसके कब्जे का दावेदार है (देखो 15 C. 818; 22 C. 459; 43 I. C. 550; 45 I. C. 224; 18 C. W. N. 537; 32 C. 741; 5 C. W. N. 362; 11 C. 496; 30 C. L. J. 231)—सिर्फ यह बात, कि जायदाद की बाबत झगड़ा है (देखो 55 I. C. 827) या यह कि रिसीवर की नियुक्ति से कोई हानि नहीं है (देखो 5 C. 556.), कोई दज़ह नहीं है । उस मामले में, जिसमें अस्थायी (आरिज़ी) हुक्म इस्तनाई जारी किया जा सकता है, और उस मामले में, जिसमें रिसीवर नियुक्त (मुकर्र) किया जा सकता है, क्या अन्तर है, इसके लिए देखो 22 C. 459; 53 I. C. 760; 21 M. L. J. 821; 45 I. C. 224.

सन् १८८२ ई० के ज़ाबता दीवानी के अनुसार सिर्फ हाईकोर्ट और अदालत ज़िला ही रिसीवर नियुक्त कर सकती थीं। अब सन् १९०८ ई० के ज़ाबता दीवानी से यह रुकावट दूर कर दी गई है और अब मातहत अदालतें भी रिसीवर मुक़रर कर सकती हैं।

रिसीवर अदालत का अफसर अथवा कर्मचारी होता है और इसलिए बिना अदालत की इजाज़त के वह न तो नालिश कर सकता है, और न उसके ऊपर नालिश की जा सकती है (देखो 34 C. 305, 316; 6 B. L. R. 486; 22 C. 1011; 22 C. 648; 10 C. 1014; 30 C. 593; 9 C. W. N. 247; 30 C. 721).

किसी जायदाद गैर-मनकूला के कब्ज़े या हकीयत के एलान के लिए दायर की गई नालिश में रिसीवर का फ़रीक़ बनाया जाना ज़रूरी नहीं है, जब कि वह मालिक जायदाद, जिसको जायदाद से फ़ायदा उठाने का हक़ है, फ़रीक़ बनाया गया है, देखो 6 C. W. N. 829; 5 C. W. N. 27; 10 C. L. J. 23.—जिस हुक़म से किसी रिसीवर की नियुक्ति की गई हो या नियुक्ति करने से इन्कार की गई हो, वह हुक़म काविल अपील है, देखो आर्डर ४२, रूल १ (एस)—रिसीवर की नियुक्ति के फ़ार्म के लिए देखो ज़ाबता दीवानी का ज़मीमा (एफ़), फ़ार्म नं० ९।

जब किसी जायदाद का रिसीवर मुक़रर कर दिया गया हो, तो ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १४५ के अनुसार मजिस्ट्रेट को उसके कब्ज़े के सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, देखो 30 C. 593.—इस बात से, कि ज़ाबता फ़ौजदारीकी दफ़ा १४५ के अनुसार हुक़म दिया जा चुका है, किसी अदालत दीवानी द्वारा किसी रिसीवर की नियुक्ति में कोई रुकावट नहीं पड़ती, देखो 22 A. 214.—लेकिन अदालत दीवानी को यह अधिकार नहीं है कि वह ज़ाबता फ़ौजदारी की दफ़ा १४६ (२) के अनुसार नियुक्त किए गए रिसीवर के होते हुए कोई दूसरा रिसीवर नियुक्त कर सके, देखो 40 C. 862.

रिसीवर पर दावा—जब रिसीवर ने बँईमानी, ग़बन या अन्य कोई नाजायज़ काम किया हो जिससे किसी को नुक़सान पहुँचा हो, तो आम कायदा तो यह है कि अदालत से इजाज़त लेकर उसपर दावा किया जाय। लेकिन जब रिसीवर अपना चार्ज दे चुका हो और अदालत से डिसचार्ज न हुआ हो, तो ऐसी दशा में उसपर दावा करने में अदालत से इजाज़त लेना चाहिये या नहीं, इसमें मत-भेद है। पहले के बहुत से मुक़द्दमों में माना गया था कि ऐसी दशा में इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। पर अब नये फैसलों में तय हुआ है कि जब तक डिसचार्ज (अदालत से उसकी नियुक्ति खारिज कर देना) न हुआ हो तब तक वह अदालत का अफसर माना जायगा और उसपर दावा करने में अदालत की मंजूरी निहायत ज़रूरी है।

हुक्म दर्मियानी और विविधि विषय

Interlocutory Order and Miscellaneous.

दर्मियानी नीलाम—अदालत को अधिकार है कि वह किसी भी जायदाद मनकूला की नीलाम के लिए हुक्म दे देवे—जिसकी बाबत नालिश दायर की गई है, या जो कब्ज़ा फ़ैसला कुर्क कर ली गई है—जो स्वभावतः और जल्दी बिगड़ जाने वाली हो या जिसका और किसी काफ़ी और मुनासिब वज़ह से नीलाम किया जाना वांछनीय हो (देखो आर्डर ३९, रूल ६) ।

दावा की जायदाद का रोक रखना और उसका मुआइना इत्यादि—अदालत को अधिकार है कि वह किसी जायदाद के, जिसकी बाबत दावा है, रोक रखने, उसकी रक्षा या मुआइना करने के लिए हुक्म दे देवे और इनमें से किसी भी काम के लिए किसी भी आदमी को उस आराज़ी या इमारत पर कब्ज़ा करने का अधिकार दे देवे जिसपर कोई दूसरा शक़्स काबिज़ हो, और उसे कोई भी नज़्द लाने या कोई निरीक्षण अथवा परीक्षा करने का अधिकार दे देवे (देखो आर्डर ३९, रूल ७) । रूल ६ या ७ के अनुसार दीजाने वाली दरख़वास्त दूसरे फ़रीक़ को नोटिस दे दिए जाने के बाद दी जानी चाहिए (देखो आर्डर ३९, रूल ८)

फ़ौरन् कब्ज़े का पा जाना—इस सम्बन्ध में, कि कब किसी फ़रीक़ को उस आराज़ी पर फ़ौरन् कब्ज़ा दे दिया जा सकता है जिसकी बाबत नालिश दायर की गई है, देखो आर्डर ३९, रूल ९ ।

इस सम्बन्ध में, कि कब किसी फ़रीक़ को अदालत में रुपया जमा करने या किसी दूसरे फ़रीक़ को कोई चीज़ देने का हुक्म दिया जा सकता है, देखो आर्डर ३९, रूल १० ।

असालतन हाज़िरी से माफ़ी—नीचे लिखे शक़्सों को अदालत दीवानी में असालतन हाज़िर होने से माफ़ कर दिया गया है:—

(क) वे स्त्रियां जो देश के रस्म-रिवाज और रहन-सहन के ढङ्ग (Customs and manners) के कारण आम लोगों के सामने निकल नहीं सकती ।

(ख) कुछ ऊंचे घराने के आदमी, जिन्हें स्थानीय सरकार स्थानीय सरकारी गज़ट में विज्ञप्ति निकालकर अदालत में असालतन हाज़िर होने से मुक्त कर दे (देखो ज़ाबता दीवानी की दफ़ा १३२ और १३३) ।

दीवानी सम्मन से गिरफ्तारी की माफ़ी—नीचे लिखे आदमी दीवानी सम्मन से की जाने वाली गिरफ्तारी से मुक्त कर दिए गए हैं:—

१—जज, मजिस्ट्रेट अथवा दूसरे अदालत के ओहदेदार, जब कि वे अपनी अदालत को जा रहे हों, वहाँ पर बैठे काम कर रहे हों या वहाँ से लौटे हुए आ रहे हों ।

२—किसी मुकद्दमा या नालिश के फरीकैन, उनके वकील, सम्बन्ध, गिरफ्तार, मुकद्दमा और गवाह जो सम्मन की तामीली पर हाजिर हुए हों, जब कि वे अदालत को जा रहे हों या किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में जो कि किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने चल रहा है जिस मजिस्ट्रेट को उससे समाप्त करने का अधिकार है, या जिसके लिए यह विश्वास है कि उसे उससे समाप्त करने का अधिकार है, इजलास में हाजिर हों, और जब कि वह ऐसा अदालत से वापस आ रहा हो, सिवाय उस दशा के जब कि उसपर अदालत की मानहानि करने के अभियोग से सम्मन जारी किया गया हो।

३—जब कोई मदिपून-डिकरी इस बात की वजह जाहिर करने के लिए हाजिर हुआ हो कि वह डिकरी की इजरा में क्यों जेल में न भेजा जाय, या जब डिकरी की फौरन इजरा का हुक्म दिया गया हो, तो वह माफी के लिए दावा नहीं कर सकता (देखो ज़ाबता दीवानी की दफा १३५)।

४—दफा ५६ के अनुसार कोई स्त्री (औरत) किसी रुपये की डिकरी की इजरा में गिरफ्तार नहीं की जा सकती।

यह माफी सिर्फ दीवानी सम्मन के ज़रिये की जाने वाली गिरफ्तारी से की गई है। इसलिए जो फरीक या गवाह अदालत में किसी मुकद्दमों के सम्बन्ध में हाजिर हुआ हो, वह फौजदारी अदालत द्वारा जारी किए गए सम्मन के अनुसार गिरफ्तार किया जा सकेगा। 'वापस आ रहा हो' का अर्थ है घर या अपने रहने की जगह वापस आ रहा हो। इसलिए अगर कोई मदिपून-डिकरी अदालत से सीधा घर के लिए खाना नहीं होता, बल्कि किसी दूसरे स्थान की ओर चल देता है, तो वह गिरफ्तार किए जाने से माफ़ नहीं किया जा सकता (देखो 32 A. 3 P. 6. जिसमें 4 M. 317. में दिया हुआ फैसला स्वीकार नहीं किया गया)।

ज़ाबता दीवानी की दफा १३५, आर्डर ३८, रूल ३ के अनुसार हुए ज़मानतदार के सम्बन्ध में लागू नहीं होती, देखो 53 I. C. 367.

अदालत के अधिकार-क्षेत्र के बाहर की जाने वाली कुर्की या गिरफ्तारी—जब ज़ाबता दीवानी की किसी दफा के अनुसार, जिसका डिक्लरियों की इजरा से कोई सम्बन्ध नहीं है, किसी शख्स की गिरफ्तारी या किसी जायदादकी कुर्की के लिए दरख़वास्त दी गई हो और ऐसा शख्स उस अदालत के स्थानीय अधिकार-क्षेत्र के बाहर रहता है या ऐसी जायदाद उस अधिकार-क्षेत्र के बाहर बाँकी है तो उसे अधिकार है कि वह गिरफ्तारी का वारण्ट निकाल दे या कुर्की का हुक्म दे दे और उस ज़िला की अदालत को उस वारण्ट या हुक्म की एक नक़ल भेज दे जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर ऐसा शख्स रहता है या ऐसी जायदाद बाँकी है (देखो ज़ाबता दीवानी की दफा १३६) —ज़ाबते के विस्तार के सम्बन्ध में देखो दफा १३५ (२), (३) (४)।

हुकम और नोटिसें लिखित होंगे—ज़ाबता दीवानी की दफा १४२ में यह व्यवस्था की गई है कि वे तमाम हुकम और नोटिसें, जो ज़ाबता दीवानी के अनुसार किसी शख्स पर तामील किए गए हों या दिए गए हों, लिखित होने चाहिए।

सम्मन, जारी करने वाले शख्स के खर्चों से तामील किए जायेंगे—वे तमाम सम्मन, जो ज़ाबता दीवानी के अनुसार जारी किए गए हों, उस शख्स के खर्चों से तामील किए जायेंगे जिसकी ओर से वे जारी किए गए हैं, सिवाय उस दशा के जब अदालत इससे भिन्न कोई हुकम दे [देखो आर्डर ४८, रूल १ (१)]।

तामील का खर्चा—सम्मन की तामीली के लिए कोर्ट फीस एक नियत समय के भीतर और सम्मन जारी किए जाने के पहिले अदा कर दिया जाना चाहिए [देखो आर्डर ४८, रूल १ (२)]।

पोस्टेज—जब कोई नोटिस, सम्मन या चिट्ठी डाक द्वारा भेजी जाने को हो, तो पोस्टेज और रजिस्ट्री की फीस एक नियत समय के भीतर और उस नोटिस, सम्मन या चिट्ठी के डाक में डाले जाने के पहिले, अदा कर दिए जाने चाहिए (देखो ज़ाबता दीवानी की दफा १४३)।

समय बढ़ाने के सम्बन्ध में अदालतों का अधिकार—जब किसी ऐसे काम के करने के लिए, जिसके लिए ज़ाबता दीवानी में व्यवस्था या आज्ञा की गई है, कोई समय नियत किया गया या दिया गया हो, तो अदालत को ऐसे समय के बढ़ाने का अधिकार है [देखो ज़ाबता दीवानी की दफा १४८]।

जब किसी डिकरी में यह शर्त लगा दी गई हो कि, अगर किसी नियत समय के भीतर रुपया अदा न कर दिया जायगा तो नालिश खारिज समझी जायगी, तो ऐसी दशा में समय बढ़ाया नहीं जा सकता। सिर्फ़ रेहन सम्बन्धी डिकरी में, जो आर्डर ३४ के अनुसार दी गई हो, यह नियम लागू नहीं होता, देखो 40 A. 579.

कमी कोर्ट-फीस को पूरा करने के सम्बन्ध में अदालतों का अधिकार—ज़ाबता दीवानी की दफा १४९ अदालत को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी समय किसी फरीक को उस कोर्ट-फीस की कमी को पूरा करने की इजाज़त दे देवे जो अर्जीदावा, याददास्त अपील, किसी फैसले की नज़रखानी के लिये दी गई दरखवास्त इत्यादि के ऊपर लगाया जाना चाहिये, और उस कमी की अदायगी हो जाने पर वह कागज़, जिसकी बाबत यह कोर्ट-फीस अदा किया जाना है, वही मज़बूती और असर रखेगा, मानो वह फीस पहिले ही अदा कर दी गई थी।

फैसला, डिकरियाँ और हुकमों का संशोधन—ज़ाबता दीवानी की दफा १५२ के अनुसार अदालत को अधिकार है कि वह किसी भी समय किसी फैसले, डिकरी या हुकम का (उसके तैयार हो जाने और उसपर दस्तखत हो जाने के बाद भी) संशोधन कर दे, जब कोई लिखने या अंकों की भूल या संयोगवश ग़लत कलम चल जाने या कोई बात छूट जाने से कोई अशुद्धि हो गई हो।

संशोधन-करने के सम्बन्ध में अदालतों के साधारण अधिकार—जामता दीवानी की दफा १५३ अदालत को यह आम अख्तियार देती है कि वह किसी मुकद्दमें में होने वाली किसी कार्यवाई में हुई किसी भूल या त्रुटि को दुरुस्त करदे और उस मुकद्दमे को तय करने के लिये, जो उस मुकद्दमें में फरीकौन के बीच पैदा हुआ है, सभी आवश्यक संशोधन कर दे।

अदालतों के परम्परा से प्राप्त अधिकार—अदालत को यह परम्परागत अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे हुक्म दे सके जो न्याय के लिए आवश्यक हों अथवा जो अदालत की आज्ञा उल्लंघन किए जाने से रोक सकें।

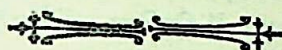
अदालत के इस अधिकार की रक्षा एवं स्वीकृति सन् १९०८ ई० के जामता दीवानी में दफा १५१ जोड़ देने से की गई है (देखो 33 C. 927; 20 C. L. J. 433; 19 C. W. N. 84; 48 C. 481 P. C.)।

दफा १५१ अथवा १५२ के अनुसार दी जाने वाली दख्वास्त के लिए मियाद की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है, देखो 60 I. C. 368; 80 I. C. 55.

भाग २

जमीमा और रूल

बम्बई हाईकोर्ट के रूल्स



जमीमा नं० १—जाबता दीवानीकी दफा १२२ के अनुसार बम्बई हाईकोर्ट द्वारा तैयार किये गए रूल

आर्डर ३ रूल २ (ए)

का इस प्रकार संशोधन किया गया:—

“वे लोग जिनको फरीकैनकी ओरसे, जो अदालतके अधिकार-क्षेत्रकी उस स्थानीय सीमाके भीतर रहने वाले नहीं हैं जिस सीमाके भीतर हाज़िरी दी गई है, दरख़वास्त दी गई अथवा कार्य किया गया है, उनकी ओरसे इस प्रकार हाज़िरी देने, दरख़वास्त देने या कार्य करने का अधिकार देते हुए आम मुह्तारनामें दिए गये हों।”

आर्डर ५ रूल २२

में नीचे लिखी शर्त जोड़ दी जानी चाहिए:—

“लेकिन शर्त यह है कि जब ऐसा कोई सम्मन बम्बई नगरकी सीमाके भीतर तामील किये जाने को हो, तो उस पर मुद्दाअलेहका ऐसी सीमाके भीतरके उस स्थानका पता लिखा जायगा जहाँपर कि वह रहता है, और वह सम्मन अदालत द्वारा उसके पास रजिस्ट्री डाकसे भेजा जायगा जिसके साथ रसीदका फॉर्म (Acknowledgement) नर्त्थी रहेगा। जिस रसीदके ऊपर मुद्दाअलेहके दस्त-ख़त हों या पोस्टमैन (डाकिया) की ओरसे यह लिखा गया हो कि मुद्दाअलेहने सम्मन लेने से इन्कार की, वह उस अदालत द्वारा, जिसने कि सम्मन जारी किया हो, नोटिसकी तामीलका प्रत्यक्ष प्रमाण समझा जायगा। और दूसरी हालतोंमें अदालत जैसी उचित समझेगी जांच करेगी और यातो यह घोषणा कर देगी कि सम्मन बाक़ायदा तामील हो गया है या जैसी उसकी रायमें आवश्यक हो भागे और तामीलीका हुक्म दे देगी।”

आर्डर ९ रूल ५

में "एक साल" के स्थानमें "छः महीना" कर दिया जाना चाहिए।

आर्डर १६ रूल २(१)

इस रूलमें नीचे लिखी शर्त जोड़ दी जानी चाहिये:—

"लेकिन शर्त यह है कि जब सरकार अथवा कोई सरकारी अफसर, जो ऐसे सरकारी अफसरकी हैसियतसे किसी मुकद्दमेंमें फरीक (मुद्दई या मुद्दाअलेह) है और जिसका समर्थन उस मुकद्दमेंमें सरकारने किया है, किसी ऐसे सरकारी अफसरके नाम जिसके सम्बन्धमें सिविल सर्विस रेगुलेशनस लागू होते हैं, उन घटनाओं (वाक्यात) के सम्बन्धमें, जिनको वह जानता है, या ऐसी बातोंके सम्बन्धमें, जो उसने ऐसे सरकारी अफसर की हैसियतसे की हैं, शहादत देने या सरकारी कागजातमें से कोई तहरीर पेश करनेके लिये सम्मन जारी करना चाहे, तो सरकार अथवा ऐसे सरकारी अफसरको ऐसे गवाहके सफर खर्च तथा दूसरे खर्चों के लिये कोई रुपया देना न पड़ेगा।"

आर्डर १६ रूल ३

नीचे लिखी शर्त इस रूलमें जोड़ दी जानी चाहिये:—

"लेकिन शर्त यह है कि जब गवाह ऐसा सरकारी अफसर (Public Officer) है जिसके सम्बन्धमें सिविल सर्विस रेगुलेशनस लागू होते हैं और वह ऐसी बातोंके सम्बन्धमें, जिनकी बाबत वह जानकारी रखता है, या ऐसी बातोंके सम्बन्धमें, जिनके सम्बन्धमें उसे ऐसे सरकारी अफसरकी हैसियतसे विचार करना पड़ा है, शहादत देने या सरकारी कागजातमें से कोई तहरीर पेश करने के लिए तलब किया गया है, तो वह रुपया, जो उसको उस फरीकसे मिलना चाहिए जो उसके सफर तथा दूसरे खर्चोंकी वजहसे सम्मनको रोक रहा है, उसको दिया नहीं जायगा।"

आर्डर २१ रूल ४४

नीचे लिखा रूल और जोड़ दिया जाना चाहिए:—

"४४(ए)—जब वह जायदाद, जो कुर्क किए जाने को है, खेतीकी पैदावार हो, तो उस कुर्कके हुकम या चारण्ट की एक नकल उस जिलेके कलक्टरके दफ्तरमें भेज दी जायगी जिसमें वह आराज़ी वाकै हैं।"

आर्डर २१ रूल ७२

नीचे लिखा रूल और जोड़ दिया जाना चाहिए:—

"७२ (ए)—अगर किसी जायदाद गैर-मनकूलाके मुरतहिनकी नीलामर्ग बोली बोलनेकी इजाज़त दे दी जाय, तो उसके लिए एक निश्चित कीमत तय

कर दी जायगी जो उस रकमसे कम न होगी जो मूलधन (असल), व्याज और खर्च की बाबत उसे मिलना है, बशर्ते कि उस जायदाद की नीलाम एकही मुदत (लॉट) में खतम कर दी जाय, और [अगर जायदाद कई मुश्तों (लॉट्स) में नीलाम की जाय तो] जो उतनी रकमसे कम न होगी जो उपरोक्त रकमके हिसाब से हर एक मुदत (लॉट) के लिए उचित हो ।”

आर्डर ४९ रूल ४

आर्डर ४९ में नीचे लिखा रूल जोड़ दिया जाना चाहिये:—

“जाबता दीवानी सन् १९०८ ई० की दफा १२८, पैरा २, क्लॉज़ (१) के अनुसार बम्बई हाईकोर्ट, अपीलेंट साइड, के रजिस्ट्रार को नीचे लिखा अधिकार दिया जाता है:—

“जब किसी याददाश्त अपीलके ऊपर, जो नियत समयके भीतर दाखिल कीगई है, ऐसी कुल या कुछ फीस अदा न कीगई हो जो कोर्ट-फीसके सम्बन्धमें उस समय प्रचलित किसी कानूनके अनुसार निश्चित कीगई है, तो रजिस्ट्रारको अधिकार होगा कि वह अपीलान्टको ऐसे कुल या किसी हिस्सा कोर्ट-फीसके, जैसी कुछ अवस्था हो, अदा कर देनेका हुक्म दे देवे और उस अपीलको रजिस्ट्रार में चढ़ा ले, यद्यपि बादमें अदा की जाने वाली कोर्ट-फीसकी रकम उस समयके बाद अदा कीगई हो जो अपील दाखिल करने के लिए नियत किया गया है ।”

इलाहाबाद हाईकोर्टके रूलस

ज़मीमा नं० २—जाबता दीवानीकी दफा १२२ के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तैयार किये गए नियम (रूल)

आर्डर ५ रूल २७

नीचे लिखे नोट १ और नोट २ को शामिल कर देना चाहिये:—

नोट १—उन रेलवे कम्पनियोंके नौकरोँ पर, जो पूर्णतः अथवा अंशतः इस प्रान्तमें कार्य करती हैं, तामील किए जानेके लिए सम्मन दफ्तरोंके किन किन अधिकारियोंके पास भेजे जाने चाहिये, उनकी एक सूची (केहरिस्त) सन् १९११ ई० के 'जनरल (दीवानी) रूलस' के ज़मीमा २ में दीगई है ।

नोट २—प्रत्येक ऐसी दशामें, जब अदालत, कौजी सिपाहीको छोड़ किसी भी सरकारी नौकर (Public Servant) के ऊपर आर्डर १६ के अनुसार सीधा

(बालाबाला) सम्मन जारी करना उचित समझती हो, सम्मन जारी करनेके साथसाथ उसकी एक नोटिस उस दफ्तरके अधिकारी के पास भेज देनी चाहिए जिसमें वह शर्खुस नौकर है, ताकि ऐसे शर्खुसके कामके सम्बन्धमें कोई प्रबन्ध किया जा सके।

विवरण—अगर अदालत किसी कानून-गो या पटवारीके नाम सम्मन जारी करनेकी आवश्यकता समझती हो, तो उसे उस जिलेके कलक्टरको इसकी सूचना देनी होगी और अगर किसी सब-रजिस्ट्रारके नाम सम्मन जारी करेगी, तो उसे उस डिस्ट्रिक्ट-रजिस्ट्रारको इसकी सूचना देनी होगी जिसके मातहत वह सब-रजिस्ट्रार है।

आर्डर ५ रूल ३०

नीचे लिखा हुआ रूल ३१ जोड़ दिया जाना चाहिए:—

“रूल ३१—किसी फरीक या गयाहके नाम सम्मन जारी किए जानेके लिए दरख्वास्त ऐसे नमूनेकी होनी चाहिए जो इस कामके लिए नियत है। अदालत को और किसी तरहके नमूने की दरख्वास्त न लेनी चाहिए।”

आर्डर ७

इस आर्डरमें ये नीचे लिखे रूल जोड़ दिए जाने चाहिए:—

“रूल १९—हर एक अर्जीदावा या इवतदाई अर्जीके साथ एक रोबकार नत्थी कर देना चाहिए जिसमें वह पता लिखा हो जिस पते पर मुद्दई या अर्जी देने वालेके ऊपर नोटिस, सम्मन या किसी दूसरे हुक्मनामा की तामील की जानी चाहिए। बादमें शामिल होने वाले मुद्दइयों और सायलों (अर्जी देने वालों) को चाहिए कि वे इस तरह शामिल होनेके फौरन ही बाद इस किस्मका एक रोबकार दाखिल कर दें।

रूल २०—उपरोक्त रूलके अनुसार दाखिल किया गया तामीलका पते उस जिलेकी अदालत की स्थानीय सीमाके भीतर होना चाहिये जिसके भीतर वह नालिश या अर्जी दाखिल की गई है, या उस जिलेकी अदालत की स्थानीय सीमाके भीतर होना चाहिये जिसमें वह फरीक आम तौर पर रहता है, अगर वह संयुक्त-प्रान्त आगरा व अवधकी सीमाके भीतर है।

रूल २१—जब कोई मुद्दई या अर्जी देने वाला तामीलके लिये पता न लिखेगा, तो अदालत उसकी नालिश या दरख्वास्त खारिज कर देगी अथवा कोई फरीक इस तरहके हुक्मके लिये दरख्वास्त दे सकता है और अदालत इस पर जैसा हुक्म उचित समझे दे सकती है।

रूल २२—जब कोई फरीक उस पते पर न मिल सके जो उसने तामीलीके लिये लिखाया है और उसका कोई मुख्तार या उसके घरका कोई बालिग आदमी जिसपर नोटिस या सम्मन तामील किया जा सके, मौजूद न हो, तो उस नोटिस या सम्मनकी एक नकल उसके मकानके बाहरी दरवाजे पर चस्पा कर दी जायगी। अगर तारीख मुकरर पर वह फरीक हाजिर न हुआ, तो दूसरी तारीख

मुकर्रर की जायगी और उस नोटिस, सम्मन या दूसरे हुक्मनामाकी एक नकल उस रजिस्टरमें लिखे हुये पते पर रजिस्ट्री डाकसे भेज दी जायगी और ऐसी तामीलीका वही असर होगा माने वह नोटिस या हुक्मनामा असाफल्यतन तामील किया गया हो ।

रूल २३—अगर कोई फरीक अपने मुकद्दमेंमें किसी वकीलको रख ले, तो उस पर तामील की जाने वाली नोटिसें और हुक्मनामे (सम्मन वगैरा) आर्डर ३ रूल ५ में बतलाये अनुसार तामील किये जायंगे, सिवाय उस दशामें जब कि अदालत उस पते पर तामीलका हुक्म दे देवे जो उस फरीकने लिखाया है ।

रूल २४—अगर कोई फरीक अपना वह पता बदलवाना चाहता है जो उसने ऊपर लिखे अनुसार पहिले लिखवाया है, तो उसे चाहिए कि वह इसके लिये एक तस्दीकशुद्ध: दरख्वास्त पेश करे, और अदालत उस दरख्वास्तके अनुसार पता बदल देगी । ऐसी दरख्वास्तकी नोटिस उस मुकद्दमेंमें दूसरे फरीकैनको भी दे दी जायगी जिनको वह इसकी सूचना देना चाहती हो और वह या तो उन फरीकैनके वकीलोंपर तामील कर दी जायगी या उनके पास रजिस्ट्री डाकसे, जैसा कुछ अदालत उचित समझे, भेज दी जायगी ।

रूल २५—इन रूलोंमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अदालतको किसी और तरहसे नोटिस या हुक्मनामाकी तामीलीका हुक्म देने से रोक सके, अगर, किहीं कारणोंसे, वह ऐसा करना उचित समझे ।

रूल २६—इन रूलोंमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आर्डर २१ रूल २२ में बतलाई हुई नोटिसके सम्बन्धमें लागू होती हो ।

आर्डर ८

इस आर्डरमें नीचे लिखे रूल ११ और १२ और जोड़ दिए जाने चाहिए:—

“रूल ११—हर एक ऐसे फरीक को—चाहे वह पहिलेका हो, बीचमें शामिल किया गया हो या दूसरेकी जगह पर फरीक बनाया गया हो—जो अपील करना चाहता हो, या किसी नालिश या इव्त्दाई अर्जीकी बाबत जवाब-देही करना चाहता हो, चाहिए कि वह उस तारीख को या उससे पहिले, जो उसके ऊपर तामील हुए सम्मन या नोटिसमें पेशीकी तारीख मुकर्रर की गई थी, अदालतमें एक रोबकार दाखिल करे जिसमें वह तामीलके वास्ते अपना पता लिख दे, और अगर वह ऐसा न कर सकेगा तो उसकी जवाब-देही (पैरवी), अगर कोई है तो, रद्द कर दी जायगी और वह उसी दशामें रह जावेगा मानों उसने कोई जवाब-देही की ही नहीं थी । इस सम्बन्धमें अदालत अपनी इच्छा से या इस तरहके हुक्मके लिए किसी फरीककी ओरसे दरख्वास्त दिये जाने पर ऐसा कर सकती है और अदालत जैसा उचित समझे हुक्म दे सकती है ।

रूल १२—आर्डर ७ के रूल २०, २२, २३, २४, २५ और २६, जहां तक हो सकेगा, उपरोक्त रूल के अनुसार दाखिल किए गए तामीली के पतों के सम्बन्ध में लागू होंगे ।”

आर्डर १३

इस आर्डर में नीचे लिखे रूल १२ और १३ शामिल कर दिए जाने चाहिए:—

“रूल १२—हर एक ऐसे दस्तावेज़ (document) के साथ, जो कि अदालत की भाषा अथवा अंग्रेज़ी में नहीं लिखा गया है और जो (क) किसी अंग्रेज़ी के साथ या (ख) पहिली पेशी पर पेश किया गया है या (ग) और किसी समय किसी नालिश, अपील या किसी दूसरे मामले में शहादत में पेश किया गया है, उस दस्तावेज़ का शुद्ध अनुवाद उस अदालत की भाषा में रहना चाहिये। अगर ऐसा कोई दस्तावेज़ अदालत की भाषा में लिखा गया है, लेकिन उसकी लिपि प्रचलित देवनागरी अथवा साधारण फ़ार्सी की लिपि नहीं है, तो उसके साथ उस का हिन्दी और फ़ार्सी लिपि में शुद्ध अनुवाद रहना चाहिये।

रूल १३—जब कोई दस्तावेज़, जो रूल १ में बतलाई हुई सूची (फ़ेहरिस्त) में शामिल है, शहादत में ले लिया गया हो, तो अदालत उसपर रूल ४ (१) में बतलाई हुई बातें लिखने के अतिरिक्त उन दस्तावेज़ों के सिलसिले का अंक (नम्बर) गणना डाल देगी जो मुद्दे की ओर से शहादत में लिये गये हैं। और अगर वह उन दस्तावेज़ों के सिलसिले में पेश किया गया है जो मुद्दे अलेह की ओर से शहादत में लिये गये हैं तो उसपर सिलसिलेवार अक्षर डाल देगी और प्रत्येक ऐसे अंक अथवा अक्षर पर अपने हस्ताक्षर कर देगी। जब दो अथवा अधिक लोग मुद्दे अलेह हों, तो पहिले मुद्दे अलेह के दस्तावेज़ों पर A. 1 B. 1 C. 1 इत्यादि A. A. 1 B. B. 1 इत्यादि और दूसरे मुद्दे अलेह के दस्तावेज़ों पर A. 2, B. 2, C. 2 इत्यादि A. A. 2, B. B. 2 इत्यादि निशान डाले जायेंगे। जब एक ही तरह के बहुत से दस्तावेज़ शहादत में लिए गए हों, उदाहरणार्थ एक ही तरह की बहुत सी लगान की रसीदें, तो उन सब के ऊपर एक ही अंक अथवा (अंग्रेज़ी का) बड़ा अक्षर डाल दिया जायगा और उसके साथ साथ हर एक कागज़ को अलग करने के लिये उसपर एक छोटा अंक अथवा (अंग्रेज़ी का) छोटा अक्षर लिख दिया जायगा।”

आर्डर १६ रूल २

इस रूल के साथ नीचे लिखा सब-रूल (४) शामिल कर दिया जाना चाहिये—
“(४)—यह रूल उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें सरकार फ़रीक़ है, लागू गवाहों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा जो ऐसे सरकारी नौकर (Government Servant) हैं जिनका वेतन १० रु० मासिक से अधिक है और जो अपनी निवृत्ति के लिये तलब किए गए हों। उनके हेडक्वार्टर से पांच मील से अधिक फ़ासले पर वाक़े हों।”

आर्डर १६

इस आर्डर में नीचे लिखे रूल २२ और २३ और बड़ा दिये जाने चाहिये—

रूल २२(१)—सिवाय इसके जैसाकि इस रूल और रूल २ में बतलाया गया है, अदालत नीचे लिखी शरह पर सफर और दूसरे खर्चें दिलावेगी:—

(क) अगर गवाह काश्तकार, मजदूरी पेशाया नीचे दर्जे के आदमी हैं, तो छः आना रोज़ ;

(ख) अगर गवाह कुछ ऊँचे दर्जे के हैं, जैसे कि ज़मीन्दार, सौदागर वकील और इसी तरह के ओहदेवाले लोग, तो आठ आना से दो रुपया रोज़ तक, जैसा कुछ अदालत हुकम दे; और

(ग) अगर गवाह बहुत ऊँचे ओहदे के हैं, जिनमें ऐसे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं जिनका वेतन २००) रु० मासिक से कम नहो, तो तीन रुपये से पांच रुपये रोज़ तक ।

(२) अगर कोई गवाह उस रुपयेसे अधिक रुपया मांगता है जो उसको पहिले दिया जा चुका है, तो उसको वह अधिक रुपया दिलाया जायगा, अगर वह अदालत को इस बात का इतमीनान दिला सके कि वास्तव में उसका अधिक और आवश्यक खर्चा हुआ है ।

उदाहरण—डाकखाने का नौकर, जो शहादत में तलब किया गया हो, उस शख्स से, जिसकी ओर से या जिसके दरखास्त देने पर वह तलब किया गया है, वह सफरका और दूसरा खर्चा तलब करनेका हकदार है जो उसके दर्जे या ओहदे के गवाहों को दिलाया जाता है और इसके अतिरिक्त उस रुपये के लिये भी दावा कर सकता है जो काम से उसकी अनुपस्थिति में काम करने वाले शख्स को उसे देना पड़ेगा । जो रुपया उसे अपनी जगह काम करने वाले शख्स को देना पड़ेगा, उसकी निस्वत उस गवाहका अफसर कागज़ की एक चिट के ऊपर तस्दीक करेगा, जिसे वह गवाह उस अदालत में पेश करेगा जिसने सम्मन जारी किया था ।

(३) अगर कोई गवाह एकसे अधिक दिन रोक रखा गया, तो उसके रोके जाने का खर्चा उसे ऐसी शरह पर दिलाया जायगा जो अदालत को मुनासिब और ठीक मालूम पड़े; लेकिन वह प्रायः उससे अधिक न होगा जो इस रूल के क्लोज़ (१) के अनुसार दिलाया जाना चाहिये ।

लेकिन अदालतको अधिकार है कि वह किन्हीं कारणोंसे, जो लिखे जायंगे, उससे अधिक खर्चा दिला दे जिसकी व्यवस्था इसके पूर्वके नियमोंमें की गई है ।

२३—जिन मामलों में सरकार फ़रीक है, उनमें सरकारी नौकरों को—जो कि पुलिस के कानिस्टबिल न हों—जिनका मासिक वेतन १०) रु० से अधिक है और जो अपनी सरकारी नौकर की हैसियत में ऐसी अदालत में शहादत के लिए तलब किए गए हैं जो उनके हेड-क्वार्टर से पांच मील से अधिक दूर है, सफर खर्च और दूसरे खर्चों के बदले अदालत से हाज़िरी का साटीफ़िकेट दिया जायगा ।

आर्डर १९

इस आर्डर में नीचे लिखे रूल और शामिल कर देने चाहिए:—

रूल ४—हलफनामों के ऊपर.....की अदालत मुकाम.....में नाम वगैरा लिखा जायगा। अगर वह हलफनामा किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में दी गई दरखुवास्त के समर्थन अथवा विरोध में दाखिल किया गया हो जो उस अदालत में चल रहा है, तो उसपर उस मामले को भी लिख दिया जायगा। अगर कोई ऐसा मामला (मुकदमा) नहीं है, तो उस पर यह लिख दिया जायगा—.....की अर्जी के मामले में।”

रूल ५—हलफनामा अलग अलग पैराग्राफों में बटा हुआ होगा और हर एक पैराग्राफ पर क्रमानुसार नम्बर डाल दिए जायेंगे और जहां तक सम्भव होगा वह किसी विषय के किसी खास हिस्से के ही सम्बन्ध में होगा।

रूल ६—हर एक ऐसे शख्स का, जो बयान हलफी दाखिल कर रहा है, उसमें इस तरह वर्णन होना चाहिए कि उसकी शिनाख्त करने में सुविधा हो, और जहां पर इस बात के लिए आवश्यक हो, उसमें उसका पूरा नाम, उसके बाप का नाम, उसकी जाति और धर्म, उसका ओहदा अथवा उपाधि, उसका उद्यम, व्यवसाय, पेश या व्यापार, और उसके रहनेका असली स्थान लिखा होना चाहिए।

रूल ७—जब तक कोई अन्य व्यवस्था न की गई हो, बयान हलफी (हलफनामा) कोई भी ऐसा शख्स दाखिल कर सकता है जो उन बातों की जानकारी रखता है जिनके सम्बन्ध में वह बयान दे रहा है। किसी हलफनामा को दो या अधिक आदमी मिल कर दाखिल कर सकते हैं; हर एक आदमी को वे बातें अलग अलग लिखनी चाहिए जिन्हें वह जानता है, और ये बातें अलग अलग पैराग्राफों में लिखी जायेंगी।

रूल ८—जब कोई हलफनामा दाखिल करने वाला शख्स किसी ऐसी बात के निश्चय लिख रहा हो जिसे वह स्वयं जानता है, तो उसे यह बात स्पष्ट और असंदिग्ध रूप में लिखनी चाहिए और “मैं दृढ़ता पूर्वक यह बयान करता हूँ” अथवा “मैं शपथ खाकर ऐसा कहता हूँ” शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।

रूल ९—सिवाय दार्मियानी कार्रवाइयों के, हलफनामा सिर्फ उन्हीं बातों के सम्बन्ध में दाखिल किया जायगा जिन्हें बयान देने वाला स्वयं जानता है और साबित कर सकता है। दार्मियानी कार्रवाइयों में, जब किसी बात को बयान देने वाला न जानता हो और उसे उस सूचना के आधार पर कहता हो जो उसे दूसरे लोगों से प्राप्त हुई है, तो वह बयान देने वाला इस प्रकार लिखेगा “मुझे मालूम हुआ है,” और अगर बात ऐसी ही है तो, “और इसे सचमुच सही मानता हूँ” और उस शख्स या उन शख्सों का नाम और पता लिख देगा और शिनाख्त के लिए काफी उनकी हुलिया वगैरा लिख देगा, जिससे या जिनसे

उसे ऐसी इतना मिली है। जब दरखास्त या उसका विरोध उन बातों के आधार पर किया गया हो, जो उन दस्तावेजों (documents) या दस्तावेजोंकी नकलों में बतलाई गई हैं जो किसी न्यायालय अथवा दूसरे स्थान से पेश किए गए हैं, तो बयान देने वाला यह लिखेगा कि वे कहां से प्राप्त किए गए हैं, और उन दस्तावेजों में बतलाई गई बातों की सत्यता के सम्बन्ध में उसका विश्वास क्या है यह भी लिखेगा।

रूल १०—जब किसी हलफनामा में किसी स्थान का उल्लेख किया गया हो, तो उसका सही सही पता व निशान लिख देना चाहिए। जब किसी हलफनामामें किसी आदमीका उल्लेख किया गया हो, तो उस हलफनामामें वह आदमी, उस आदमीका सही नाम और पता और उसके सम्बन्धकी और भी बहुत सी बातें लिखी जायंगी जो उसकी शिनाख्त करने के लिए काफी हों।

रूल ११—हर एक ऐसे शख्सकी शिनाख्त, जो किसी अदालत दीवानीमें इस्तेमाल किए जानेके लिए कोई हलफनामा (बयान हलफो) दाखिल कर रहा हो अगर उसे वह शख्स खुद नहीं जानता है जिसके सामने वह हलफनामा दाखिल किया जा रहा है तो, उस शख्सके सामने कोई ऐसा शख्स करेगा जो उसे जानता हो, और जिस शख्सके सामने वह हलफनामा दाखिल किया जा रहा है वह उस हलफनामा के नीचे उस शख्स का नाम, पता और हुलिया, जिसने शिनाख्त की है, और उस शिनाख्त किए जाने का समय और स्थान भी लिख देगा।

रूल १२—किसी भी अर्जीकी कोई तस्दीक और कोई हलफनामा, जो किसी ऐसी पर्दानशीन औरत द्वारा लिखा गया है जो बिना घूँघट निकाले हुए उस शख्स के सामने नहीं आई है जिसके सामने वह तस्दीक या हलफनामा लिखा गया है, उस समय तक काम में न लाया जा सकेगा, जब तक कि ऊपर बतलाए अनुसार उसकी शिनाख्त न हो जाय और जब तक ऐसी अर्जी या ऐसे हलफनामा के साथ ऐसी औरतकी शिनाख्त का हलफनामा न हो जिसे उस औरत की शिनाख्त करने वाले शख्स ने उस समय लिखा हो।

रूल १३—वह शख्स, जिसके सामने हलफनामा दाखिल किए जाने को है, हलफनामा दाखिल किये जानेके पहिले, उस शख्ससे, जो कि हलफनामा दाखिल करने वाला है, यह पूछेगा कि क्या उसने हलफनामा पढ़ लिया है और वह उसमें लिखी हुई बातों को समझता है, और अगर वह शख्स, जो हलफनामा दाखिल करने वाला है, यह कह दे कि उसने हलफनामा नहीं पढ़ा है या ऐसा मालूम हो कि उसमें लिखी हुई बातों को वह नहीं समझा है या यह मालूम हो कि वह पढ़ा-लिखा आदमी नहीं है, तो जिस शख्स के सामने वह हलफनामा दाखिल किए जाने को है, वह उस हलफनामा को उस शख्स को, जो यह हलफनामा दाखिल करना चाहता है, खुद पढ़कर सुना देगा और उसका मतलब समझा देगा या किसी दूसरे योग्य आदमी से अपने सामने पढ़वा कर उसका मतलब समझना देगा, और जब उस शख्स को, जिसके सामने वह हलफनामा दाखिल

किए जाने को है, इस तरह इस बात का इतमीनान हो जाय कि जो शख्स ऐसा हलफनामा दाखिल करना चाहता है वह उसमें लिखी हुई बातों को समझता है, तो वह हलफनामा दाखिल कर दिया जायगा ।

रूल १४—जिस शख्सके सामने कोई हलफनामा दाखिल किया गया है, वह उस हलफनामाके नीचे इस बातको लिख देगा कि हलफनामा उसके सामने दाखिल किया गया है तथा उस समय और स्थानको भी लिख देगा जब और जहां पर वह दाखिल किया गया है और पहिचानके लिए उन पेश किए गए कागज़ों (Exhibits) के ऊपर निशान डाल कर अपने हस्ताक्षर कर देगा जिनका उल्लेख हलफनामा में किया गया है ।

रूल १५—अगर उस हलफनामाके लिखनेमें होने वाली किसी भूलके ठीक करने की आवश्यकता जान पड़े, तो वह भूल उस शख्सके सामने ठीक की जानी चाहिए जिसके सामने वह हलफनामा दाखिल किए जानेको है और वह हलफनामा दाखिल किए जानेके पहिले ठीक की जानी चाहिए, बादमें नहीं । इस तरह ठीक की गई हर एक ग़लती (भूल) के ऊपर उस शख्स के दस्तखत होने चाहिए जिसके सामने वह दाखिल किया गया है और वह इस तरह पर ठीक की जानी चाहिए कि पहिले शब्द अथवा शब्दों या अङ्क अथवा अंकों का पढ़ना असम्भव या कष्टप्रद न हो, जिनके सम्बन्ध में दुरुस्ती की गई है ।”

आर्डर २०

इस आर्डर में यह नीचे लिखा हुआ रूल जोड़ दिया जाना चाहिए:—

“रूल २१—(१) हर एक डिकरी और हुक्म, जिसकी परिभाषा दफा १ में की गई है और जो किसी अदालत खफीफा या किसी ऐसी अदालत की डिकरी या हुक्म नहीं है जो अदालत खफीफा के अधिकारों को बरत रही हो, उस अदालत की भाषा में तैयार किया जाना चाहिए । उस डिकरी या हुक्म के लिख जाने पर और उसपर दस्तखत होने के पहिले, मुंसरिम साहब उसकी एक नोटिस चस्पां करवा देंगे, जिसमें यह लिखा होगा कि डिकरी या हुक्म तैयार हो गया है और यह कि कोई फरीक या किसी फरीकका वकील, ऐसी नोटिसकी तामीलकी तारीखसे कामके छः दिनोंके अन्दर, उस डिकरी या हुक्मके मसविदेको देख कर उसपर दस्तखत कर सकता है या मुंसरिम के पास इस बिना पर उज्रदारी दाखिल कर सकता है कि फैसले में कुछ लिखने की भूल हो गई है या अकस्मात् ऐसी कोई त्रुटि रह गई है जिससे उस मामले के किसी आवश्यक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, या यह कि ऐसी डिकरी या हुक्म में फैसले से भेद (इख़िलाफ) है या उसमें शब्दों अथवा अंकों की भूल, है । इस उज्रदारी में यह बात साफ साफ लिख दी जानी चाहिए कि वह कौन सी भूल, त्रुटि या भेद है जो बतलाया जाता है, और उस पर उस शख्स के दस्तखत और तारीख होने चाहिए जो उसे दाखिल कर रहा है ।

(२) अगर ऐसी कोई उज्रदारी उस तारीख को या उसके पहिले दाखिल की जाय जो उस नोटिस में बतलाई गई है, तो मुंसरिम उस मामले को जल्द से जल्द तैयार होने वाली हफ्तेवार फेहरिस्त में चढ़ा लेगा और नियत तारीख पर उज्रदारी को मय मिसिल (कागजात मुकदमा) के उस जज के सामने पेश कर देगा जिसने वह फैसला दिया है, या, अगर वह जज अब उस अदालत का जज नहीं रहा है तो, उस जज के सामने पेश करेगा जो उस समय उस अदालत में काम करता हो ।

(३) अगर नोटिस में बतलाई हुई तारीख को या उसके पहिले कोई उज्रदारी दाखिल न की गई, या अगर कोई उज्रदारी दाखिल की गई है और खारिज कर दी गई है, तो मुंसरिम उस डिकरी के ऊपर वह तारीख डाल कर, जिस दिन कि फैसला दिया गया था, रूल ८ और ९ के अनुसार दस्तखत किए जाने के लिये उसे जज के सामने पेश कर देगा ।

(४) अगर कोई उज्रदारी बाकायदा तौर पर दाखिल की गई है और वह मंजूर कर ली गई है, तो उसमें संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायगा जिसके लिये जज साहब हुक्म देंगे । फैसले में किए जाने वाले संशोधन और परिवर्तन को जज साहब स्वयं अपने हाथ से करेंगे । उस संशोधन और परिवर्तन के अनुसार, जिसके लिये जज साहब ने आज्ञा दी है, संशोधित डिकरी तैयार की जायगी, और मुंसरिम उस डिकरी पर उस दिन की तारीख डाल कर, जिस दिन फैसला दिया गया था, रूल ७ और ८ के अनुसार दस्तखत किये जाने के लिये उसे जज के सामने पेश कर देगा ।

(५) जब जज साहब डिकरी पर दस्तखत कर देंगे तो वह अपने हाथ से एक नोट लिख देंगे जिसमें वह तारीख लिखी जायगी जिस तारीख को डिकरी दी गई है । ”

आर्डर २१, रूल २५ (२)

इस आर्डर में रूल २५ के सब-रूल (२) के स्थान में नीचे लिखी हुई इबारत होनी चाहिए:—

“(२) जब हुक्मनामा के ऊपर इस आशय की कोई बात लिखी गई हो कि वह अफसर उस हुक्मनामा की तामील कर सकने में असमर्थ है, तो अदालत उसकी इस असमर्थता के सम्बन्ध में उसके जाती बयानों या हलफनामा के ऊपर जांच करेगी, और अगर वह उचित समझे तो इस असमर्थता के सम्बन्ध में गवाहों को तलब करके उनके बयान ले सकती है और वह उससे होने वाले परिणाम को मिसिल में लिख देगी । ”

आर्डर २१, रूल ५५

इस आर्डर में रूल ५५ के स्थान में नीचे लिखी इबारत होनी चाहिए:—

“रूल ५५ (१)—डिकरी की इजरा करने वाले अफसर नीलाम के पास उन कुल दख्खान्तों की नोटिस भेज दी जायगी जो एक ही मदीयून-डिकरी की जायदाद के सम्बन्ध में दफा ७३ (१) के अनुसार नीलाम में वसूल हुई रकम के हिस्से-रसद बंटवारा के लिए उन लोगों की ओर से दी गई हों जो डिकरी के डिकरी-दार नहीं हैं जिसकी इजरा के लिए पहिला हुक्म दिया गया था।

(२) जब—

(क) किसी डिकरी की रकम (जिसमें किसी भी ऐसी डिकरी की रकम शामिल है जो उसी मदीयून डिकरी के ऊपर दी गई है और जिसकी नोटिस उप-दफा (१) के अनुसार अफसर नीलाम के पास भेज दी गई है) मय खर्चें और उन सफाई और खर्चों के, जो किसी जायदाद की कुर्की के कारण पैदा हुए हैं, अदालत में अदा कर दी जाय,

(ख) किसी डिकरी की (जिसमें कोई भी ऐसी डिकरी शामिल है जो उसी मदीयून-डिकरी के ऊपर दी गई है और जिसकी नोटिस उप-दफा (१) के अनुसार अफसर नीलाम के पास भेज दी गई है) बेचाकी और किसी तरह पर अदालत के ज़रिये कर दी जाय या अदालत में उसकी तस्दीक कर दी जाय, या

(ग) कोई डिकरी (जिसमें कोई भी ऐसी डिकरी शामिल है जो उसी मदीयून-डिकरी के ऊपर दी गई है और जिसकी नोटिस उप-दफा (१) के अनुसार अफसर नीलाम को भेज दी गई है) मंसूख कर दी जाय या उलट दी जाय,

तो ऐसा समझा जायगा कि कुर्की वापस ली गई, और, अगर जायदाद गैर-मनकूला है तो, इस कुर्की वापस लिये जाने की घोषणा, अगर मदीयून डिकरी ऐसा चाहता है तो, उसके खर्चों से कर दी जायगी और इस घोषणा (इश्तहार) की एक नकल उस तरीके पर चस्पां कर दी जायगी जो ऊपर बतलाए हुए अन्तिम रूल में बतलाया गया है।

आर्डर २१ रूल १०३

इस आर्डर में रूल १०३ के आगे नीचे लिखे रूल बढ़ा दिये जाने चाहिये—

रूल १०४—जब दफा ४१ में बतलाया हुआ सर्टीफिकेट उस अदालत को मिल जाय जिसने इजरा के लिये डिकरी भेजी थी, तो वह इजरा के परिणाम सम्बन्धी बातों को, मुहाफिज़ खाने (Record Room) में कागज़ात भेजे जाने के पहिले दीवानी मुकदमों के रजिस्टर में दर्ज करा देगी।

रूल १०५—रूल ४३ के अनुसार होने वाली जायदाद मनकूलाकी, रूल ५१ के अनुसार दस्तावेज़ात काबिल रेहन व बयकी और रूल ५४ के अनुसार जायदाद गैर-मनकूला की हर एक कुर्की अदालत दीवानी के अमीन या कुर्क-अमीन के ज़रिये की जायगी; सिवाय उस दशा में जब किन्हीं विशेष कारणों से यह आवश्यक हो

जाय कि किसी दूसरे शख्स को इसके लिये नियत किया जाय, जिस दशा में वे वक्ता अदालत का जज स्वयं अपने कलमसे कुर्की के उस हुक्म के ऊपर लिखेगा ।

रूल १०६—जब वह जायदाद, जिसकी नीलाम के लिये दरख्वास्त की गई है, जायदाद गैर-मनकूला हो, जो जायदाद की ऐसी परिभाषा में आती हो जो दस्तावेजों की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में उस समय प्रचलित किसी भी कानून में की गई है तो डिकरी-द्वार को अपनी दरख्वास्त के साथ उस सब-रजिस्ट्रार का एक सर्टिफिकेट दाखिल करना होगा जिसके परगने (sub-district) में वह जायदाद वाकै है, जिसमें यह लिखा होगा कि सब-रजिस्ट्रार ने बारह बरस पहिले की अपनी किताब नं० १ और २ तथा उनकी फेहरिस्तों को ठुंड डाला है, और अगर कोई बार उस जायदाद के ऊपर उसे मिला हो तो वह भी उसमें लिखा होना चाहिए ।

रूल १०७—जब किसी आराज़ी या उस आराज़ी में प्राप्त किसी हिस्से की नीलाम के लिए दरख्वास्त दी गई हो तो अदालत, उसकी नीलाम का हुक्म देने के पहिले, फ्रीकैन से इस बात का जवाब तलब करेगी कि स्थानीय सरकार की विज्ञप्ति नं० १८८७१/२३८/१०, तारीख ७ अक्टूबर सन् १९११ ई० के अर्थ में वह आराज़ी मौरूसी है अथवा नहीं, और इस प्रश्न को तय करने के लिये एक तारीख निश्चित करेगी ।

इस प्रकार नियत किए हुए दिन को अथवा किसी ऐसी तारीख को, जिसके लिये जांच स्थगित कर दी गई हो, अदालत को अधिकार होगा कि वह इसके सम्बन्ध में जैसी उचित समझे, बयान हलफ़ी द्वारा अथवा और किसी प्रकार, शहादत लेवे; और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह उस ज़िला के कलक्टर से इस बात की रिपोर्ट तलब करे कि ऐसी आराज़ी या उसका कोई हिस्सा मौरूसी आराज़ी है या नहीं ।

शहादत और रिपोर्ट पर, अगर कोई है तो, विचार करने के पश्चात् अदालत इस बात को तय करेगी कि वह आराज़ी या उसका कोई हिस्सा, और उसका वह कौनसा हिस्सा मौरूसी है ।

इस जांच का जो कुछ परिणाम होगा, उसे उस अदालत का जज अपनी कलम से उस हुक्म में लिख देगा जो इस काम के लिये वह देगा ।

रूल १०८—जब वह जायदाद, जिसकी नीलाम के लिये दरख्वास्त की गई है, कोई ऐसी आराज़ी हो, जिसकी मालगुजारी अंदा की जाती है या जिसकी मालगुजारी माफ़ है, या उस आराज़ी में प्राप्त कोई हिस्सा हो और दफ़ा ६८ के अनुसार ज़रा के लिए डिकरी कलक्टर के पास न भेजी गई हो, तो अदालत, नीलाम का हुक्म देने के पहिले, उस कलक्टर से, जिसके ज़िले में वह जायदाद वाकै है, इस बात की रिपोर्ट तलब करेगी कि क्या उस जायदाद के ऊपर सरकार की कुछ बकाया है (और अगर है तो क्या) ।

रूल १०९—सब-रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट और कलक्टर की रिपोर्ट का मुआ-ना फ्रीकैन या उनके वकील बिना किसी खर्च के, उसके अदालत के हाथ में आने और जांच के परिणाम की घोषणा किए जाने के बीच में कर सकते हैं ।

कलक्टर की रिपोर्ट की बाबत कोई फीस बढ़ा करमी न होगी।

रूल ११०—रूल ६६ के अनुसार जांच का परिणाम उस हुकममें लिख दिया जायगा जो अदालत का जन इस काम के लिये अपनी कलम से लिखेगा। अदालत को अधिकार है कि वह जांच को स्थगित (मुलतवी) कर दे, वशतें कि इस मुलतवी के लिये लिखित कारण बतला दिये जायें और यहकि सिवाय उक्त बार के, जितनी बार के लिये आवश्यकता है, अधिक बार जांच स्थगित (मुलतवी) न की जाय।

रूल १११—अगर होने वाले नीलाम की घोषणा कर दिए जाने के बाद, अदालत को कोई ऐसी बात मालूम होजाय जिसका जानना उसकी राय में खरीदार के लिए आवश्यक है, तो अदालत उसकी सूचना खरीद का इपस रखने वाले लोगों को उस समय करवा देगी जब जायदाद नीलाम में रखा जायगी।

रूल ११२—रूल ६६, १०६ और १०८ के अनुसार की जाने वाली खर्चा का खर्चा पहिले डिकरीदार को देना होगा, लेकिन जब तक कि अदालत किन्हीं कारणों से, जो लिख कर बतलाए जायेंगे, यह न समझती हो कि उसका कुल या कुछ अंश उसमें से निकाल दिया जाय, वह खर्चा इजरा के खर्च के हिस्सा समझा जायगा।

रूल ११३—जब किसी डिकरीदार को जायदाद पर नीलाम में बोलने की इजाजत दे दी गई हो, तो नीलाम का हुकम देने वाली अदालत न अफसर को, जो नीलाम के लिए मुकर्रर किया गया है, इस बात की सूचना देगी कि क्या डिकरीदार के अतिरिक्त कोई और आदमी भी ऐसे है जो नीलाम में वसूल हुए रुपये में हिस्सा पाने के हकदार हैं।

रूल ११४—जब किसी दीवानी अदालत ने, किसी डिकरी या हुकम की इजरा में, किसी ऐसे मकान या दूसरी इमारत को नीलाम कर दिया हो जो किसी फीजी कैण्टोनमेंट या स्टेशन की सीमा के भीतर बाँके है तो वह ज्योंही उस नीलाम की मंजूरी मिल जायगी, उस कैण्टोनमेंट या स्टेशन के इन्डिग्न अफसर को, उसकी जानकारी के लिए और ब्रिगेड के अथवा किसी दूसरे मुनासिब दफ्तर में रखने के लिए, इस बात की एक नोटिस भेज देगी कि ऐसा नीलाम किया गया, और उस नोटिस में नीलाम की हुई जायदाद का नाम खरीदार के नाम तथा पता का पूरा ब्योरा होगा।

रूल ११५—जब किसी दीवानी अदालत के हुकम से, डिकरियों की इजरा में बन्दूकें या दूसरे हथियार नीलाम किए गये हों जिनके लिए इण्डियन एक्ट (नं० ११ सन् १८७८ ई०) के अनुसार खरीदारों को लाइसेन्स लेना पड़ता है, तो नीलाम का हुकम देने वाली अदालत उस जिले के मजिस्ट्रेट को सूचना दे देगी कि के नाम और पते और उस समय और उस स्थान की सूचना दे देगी जब जहां पर उन हथियारों के खरीदारों को ये हथियार हवाले किए जाने को

ताकि इण्डियन आर्म्स ऐक्ट के नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए पुलिस कोई उचित प्रबन्ध कर सके।

रूल ११६—जब जानवरों या दूसरी जायदाद-मनकूला की कुर्की के लिए दरखवास्त दी गई हो, तो डिकरीदार को अदालत में इस कदर नकद खपया जमा कर देना होगा जो उस जायदाद के १५ दिन तक हिफाजत में रखने और खिलाने-पिलाने के लिए काफी हो। अगर पन्द्रह दिन की ऐसी किसी मियाद की मुदत खतम होने के पहिले तीन दिन के भीतर आगे की ऐसी मियाद के लिए, जिसके लिए अदालत हुक्म देवे, ऐसे खर्चों की रकम अदालतमें जमा न कर दी जाय, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह, किसी मुनासिब अफसर से इस बात की रिपोर्ट पा जाने पर, कुर्की उठा लिए जाने का हुक्म दे दे और यह भी बतला दे कि कुर्की का खर्चा कौन शरूस अदा करेगा।

रूल ११७—जो जानवर किसी डिकरी की इजरा में कुर्क किए गए हों, वे साधारणतया उसी स्थान पर छोड़ दिए जायेंगे जहां पर कि वे कुर्क किए गए हैं और मर्दियून-डिकरी के जमानत दाखिल कर देने पर या तो उसी की सिपुर्दगी में छोड़ दिए जायेंगे या किसी जमानदार अथवा दूसरे प्रतिष्ठित पुरुष की सिपुर्दगी में, जो उन्हें हिफाजत में रखने और अदालत के तलब करने पर उन्हें पेश करने की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हो।

रूल ११८—अगर ऊपर बतलाए हुए अन्तिम रूल में बतलाए हुए तरीके से जानवरों की हिफाजत का प्रबन्ध न किया जा सका, तो कुर्क किए हुए सब जानवर सब से नज़्दाकी कांजी-हाउस (पाउण्ड) को हँकवा दिए जायेंगे, जो कैटिल ट्रेस्पस ऐक्ट (कानून मदाखिलत बेजा मवेशियान) सन् १८७१ ई० के अनुसार स्थापित की गई हो, और पाउण्ड-मुहर्रि की सिपुर्दगी में दे दिए जायेंगे जो नीचे लिखी बातें एक रजिस्टर में लिख लेगा:—

(क)—जानवरों की तादाद और उनकी हुलिया;

(ख)—वह तारीख और समय जिसमें वे कांजी-हाउसमें बन्द किए गए हों;

(ग) कुर्की करने वाले अफसर का अथवा उसके मातहत का नाम जिसने उन्हें उसके सिपुर्द किया है; और उस कुर्की करने वाले अफसर या उसके मातहत को इस कुल इन्दराज की एक नकूल दे दे।

रूल ११९—हर एक ऐसे जानवर के लिए, जो ऊपर बतलाए अनुसार पाउण्ड-मुहर्रि की सिपुर्दगी में दे दिया गया है, एक रकम बत्तीर किराया उस कांजी-हाउस के उन प्रत्येक पन्द्रह दिनों या उनके किसी हिस्से के लिए वसूल की जायगी जिनमें वे जानवर कांजी-हाउस में बन्द रखे गए हैं और उस किराया की शरह-ऐक्ट नं० १ सन् १८७१ ई० की दफा १२ में बतलाए अनुसार होगी।

और इस तरह वसूल की हुई रकम म्यूनीसिपल या डिस्ट्रिक्ट बोर्डके, जैसा कुछ हो, नाम से जिसके अधिकार-क्षेत्र में वह कांजी-हाउस बाँके है, खजाने में

जमा कर दी जायगी। ऐसे सारे रुपयेका उपयोग (इस्तेमाल) उसी तरह से किया जायगा जिस तरह उक्त कैटिल ट्रेस्पास ऐक्ट की दफा १२ के अनुसार वसूल किए हुए जुर्माने का किया जाता है।

रूल १२०—पाउण्ड-मुहर्रिर ऊपर बतलाए अनुसार कुर्क किए हुए और सिपुर्द किए गए जानवरों को उस समय तक अपनी हिफाजत में रखेगा और उनको खिलाता-पिलाता रहेगा, जब तक कि वे ऊपर बतलाए अनुसार उसकी सिपुर्दगी से हटा न लिए जायें और वह उन जानवरों की खुराक वगैरा के रुपये का उस शरह पर दिला पाने का हकदार होगा जो, समय समय पर, किसी उचित अधिकारी द्वारा निश्चित की जाय। ऐसी शरह उन जानवरों के लिए, जिनका वर्णन ऊपर बतलाए हुए अन्तिम रूल में बतलाई गई दफा में किया गया है, उस शरह से अधिक न होगी जो इसी समय के लिए उसी ऐक्ट की दफा ५ के अनुसार मुकर्रर की गई है। किसी भी दशा में, विशेष कारणों से, जो कि लिखे जायेंगे, अदालत उस शरह से अधिक खुराक वगैरा का खर्चा तलब कर सकती है जो शरह कि मुकर्रर है।

रूल १२१—जानवरों की खुराक वगैरा के खर्चों के लिए मुकर्रर की गई रकम पाउण्ड-मुहर्रिर को पहिले पन्द्रह दिन के लिए तो कुर्की करनेवाला अफसर उसी समय अदा कर देगा जब जानवर उसकी (पाउण्ड-मुहर्रिर की) सिपुर्दगी में दिए गए हैं और फिर इसके बाद आगे ऐसी मुद्दत के लिए, जिसके लिए अदालत आज्ञा दे, उस मुद्दत के शुरू होने के समय। अगर इस खुराक वगैरा के खर्चों की रकम उस रकम से ज्यादा अदा कर दी जाय जो उतने दिनों के लिए वाजिब है जितने दिन जानवर पाउण्ड-मुहर्रिर की सिपुर्दगी में रखे गए हों, तो वह रकम वह पाउण्ड-मुहर्रिर उस कुर्की करने वाले अफसर को वापस कर देगा।

रूल १२२—जो जानवर ऊपर बतलाए अनुसार कुर्क और सिपुर्द किए गए हैं, वे, सिवाय उस समय जब कि अदालत या कुर्की करने वाला अफसर या वह अफसर, जो नीलाम के लिए मुकर्रर किया गया हो, इसके लिए लिखित आज्ञा दे दे, छोड़े न जायेंगे; जानवरों के छोड़ दिए जाने पर उनको पाने वाले शख्स को इसके लिए उस रजिस्टर में रसीद लिखनी होगी जिसका वर्णन रूल ११८ में किया गया है।

रूल १२३—जानवरों को छोड़ बाकी जायदाद मनकूला की मुहाफिजत के लिए, जब कि वह कुर्की में हो, कुर्की करने वाला अफसर, अदालत की मंजूरी से, ऐसा प्रवन्ध कर देगा जो अत्यन्त सुविधा-जनक और अल्प व्यव वाला हो।

रूल १२४—अदालत से कुर्की करने वाला अफसर ऐसी जायदाद को एक अथवा अधिक आदमियों के खास चार्ज में दे सकता है।

रूल १२५—ऐसे हर एक आदमी के काम की फीस रूल ११६ में बतलाए अनुसार अदा की जायगी। यह दो आना प्रति दिन (Per diem) से कम

और साधारणतया साढ़े तीन आना प्रति दिन से अधिक न होगी। अदालत अपने अधिकार से इससे अधिक फीस भी दिला सकती है; लेकिन अगर वह ऐसा करती है तो वह इस अधिक फीस दिलाने के लिए कारण लिखेगी।

रूल १२६—जब इस आदमी की सेवाओंकी बिलकुल आवश्यकता न रहे, तो कुर्की करने वाले अफसर को चाहिए कि वह एक सर्टिफिकेट, जिसमें उन दिनों की तादाद, जितने दिनों उसने काम किया है, और उस रुपये की तादाद रहेगी जो उसे मिलना चाहिए, उसे दे देवे और उसकी एक नकल अपने पास रखे और इस सर्टिफिकेटके उस अदालतमें पेश करने पर, जिसने कि कुर्कीका हुक्म दिया है, अदालत के जज के सामने वह रुपया उसको दे दिया जायगा। लेकिन शर्त यह है कि, जब वह रकम पांच रुपये से अधिक न हो तो, अमीन के कहने पर वह मनीआर्डर के जरिये सहना को अदा कर दी जायगी और फिर वह सर्टिफिकेट खारिज कर दिया जायगा और कहीं पेश न किया जा सकेगा।

रूल १२७—जब किसी कुर्कीके उठा लिए जानेके कारण या और किसी कारणसे उस शख्ससे काम न लिया गया हो या वह उन दिनोंसे कम दिन तक इस जायदादका इन्चार्ज रहा हो जितने दिनके लिये उसको उसके काम का रुपया दिया गया है, तो वह फीस, जो अदा कर दी गई है, कुल अथवा कुछ अंशमें, जैसी कुछ अवस्था हो, वापस कर ली जायगी।

रूल १२८—जो फीस अदालतमें अदा की गई है, उसका इन्दराज छोटी छोटी रकमोंके लेने और वापस करनेके रजिस्टरमें कर लिया जायगा।

रूल १२९—जब रूल ११९ के अनुसार वसूल की हुई कोई रकम खजाने में भेज दी गई हो, तो उसके साथ एक तिपरता (triplicate) हुक्म [यह हुक्म म्यूनिसिपल एकाउण्ट कोडके फार्म नं० ९ में बतलाये गये नमूनेका होगा] भेजा जायगा, जिसका एक परत खजानेके कर्मचारी जिला या म्यूनिसिपल बोर्डको, जैसी कुछ अवस्था हो, भेज देंगे। पास-बुकमें इस बातका नोट लिख दिया जायगा, कि वह रकम खजानेमें बतौर किराया वास्ते खर्चा कांजी हाउस के जमा की गई।

रूल १३०—कुर्की की हुई जायदादको नीलामके लिये तैयार करने, या जिस स्थान पर वह रखी या बेंची जायगी, उस स्थान तक पहुँचानेका खर्चा डिकरीदारको कुर्की करने वाले अफसरको दे देना होगा। अगर डिकरीदार जरूरी खर्चा अदा न कर सका, तो कुर्की करने वाला अफसर इस बातकी रिपोर्ट अदालतको देगा और उसके ऊपर अदालतको अधिकार होगा कि वह कुर्की उठा लिये जानेका हुक्म दे दे और इस बातका भी हुक्म दे देवे कि कुर्की का खर्चा कौन अदा करेगा।

आर्डर २७

इस आर्डरमें नीचे लिखा रूल ९ और बढ़ा दिया जाना चाहिए:—

रूल ९—हर एक ऐसी दशामें, जिसमें सरकारी वकील, रूल ८ (१) के नियमानुसार, किसी ऐसे मुकद्दमेंकी जवाब-देही करने के इरादेसे हाज़िर हुआ हो जो किसी सरकारी अफसरके ऊपर चलाया गया है, उसे वकालतनामाके बदले एक बिना स्टाम्प लगे हुये कागज़ पर एक मेमोरैण्डम (याददाश्त) दाखिल करना पड़ेगा, जिसपर उसके इस्ताक्षर होंगे और जिसमें यह लिखा होगा कि वह किसकी ओरसे खड़ा हुआ है। यह मेमोरैण्डम, जहाँ तक हो सकेगा, नीचे लिखे मज़मूनका होगा—

[शीर्षक (उनवान मुकद्दमा वगैरा)]

मैं....., सरकारी वकील, सपरिषद् भारत मन्त्रीधी (अथवा संयुक्त प्रान्तकी सरकार अथवा अन्य किसी सरकारकी, जैसी अवस्था हो) ओरसे, जो कि इस मुकद्दमेंमें रेस्पाण्डेंट (अथवा जैसा कुछ हो) है, हाज़िर हुआ हूँ।

अथवा सरकारी ओरसे हाज़िर हुआ हूँ [जिसने ऐक्ट ५ सन् १९०८ ई० के आर्डर २७ रूल ८ (१) के अनुसार मुकद्दमेंकी जवाब-देहीका भार लिया है] जो इस मुकद्दमेंमें रेस्पाण्डेंट (अथवा जैसा कुछ हो) है।

आर्डर ३२ रूल ४ (३)

इस रूलमें विराम-चिन्हके (।) स्थानमें लघु विराम-चिन्ह (,) करके नीचे लिखा वाक्य बढ़ा दिया जाना चाहिये:—

“जब तक कि इस आर्डरके रूल ३ (४) के अनुसार उस पर बाज़ायता तौरसे नोटिस तामील न कर दी गई हो और वह उसमें बतलाये हुये समय के भीतर उस नोटिसका उत्तर देनेमें असमर्थ न रहा हो।”

आर्डर ४१ रूल ३ (१)

इस रूलका नीचे लिखे अनुसार संशोधन किया गया—

रूल ३ (१)—मेमोरैण्डमका खारिज या तर्मीम कर दिया जाना—

जब याददाश्त अपील इसके पहिले बतलाये हुये तरीके पर तैयार न की गई हो, या उसके साथमें रूल १ (१) में बतलाई हुई नकलें दाखिल न की गई हों तो वह खारिज कर दी जा सकती है, या जब याददाश्त अपील (मेमोरैण्डम) बतलाये हुये तरीके पर तैयार न की गई हो, तो वह अपीलान्टके पास, उस समयके भीतर, जो अदालत निश्चय करेगी, तर्मीम कर दिये जाने के लिये वापस कर दी जायगी या वहीं पर और उसी समय तर्मीम कर दी जायगी।

आर्डर ४१ रूल ३७

इस आर्डरमें नीचे लिखा हुआ रूल जोड़ दिया जाना चाहिये:—

रूल ३८ (१)—तामीलके लिये जो पता आर्डर ७ रूल १९ या आर्डर १८ रूल ११ के अनुसार दाखिल किया गया है, अथवा बादमें आर्डर ७ रूल २४ या आर्डर ८ रूल १२ के अनुसार बदल दिया गया है, वह प्रारम्भिक नालिश या अर्जी से पैदा होने वाली सारी अपीलेंट कार्रवाईके दौरानमें वैसा ही बना रहेगा।

(२) हर एक याददाश्त अपीलमें तामीलके लिये वे पते लिखे रहने चाहिये जो फरीकसानीने नीचेकी अदालतमें बतलाये हैं और नोटिसें तथा हुक्मनामें अदालत अपीलसे इन्हीं पतों पर जारी किए जायेंगे।

(३) आर्डर ७ के रूल २१, २२, २३ और २४ जहां तक होगा अदालत अपीलमें की जाने वाली कार्रवाईके सम्बन्धमें लागू होंगे।

आर्डर ४२ रूल १

इस रूलका नीचे लिखे अनुसार संशोधन किया गया है—

“अपीलेट डिकरियोंकी अपील”

“रूल १—जाबता—

आर्डर ४१के रूल, जहां तक सम्भव होगा, अदालत अपीलकी दी हुई डिकरियोंके विरुद्ध की गई अपीलोंके सम्बन्धमें लागू होंगे, बशर्त कि उसमें नीचे लिखी बात पूरी हो जाय:—

अदालत अपीलकी दी हुई डिकरीके विरुद्ध की गई अपीलकी याददाश्त अपील (मेमेरेंडम) के साथ उस डिकरीकी एक नकल, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, और (जब तक कि अदालत उन्हें अलग न कर दे) उस फैसलेकी, जिसके आधार पर वह अपील की गई है, और प्रारम्भिक अदालतके फैसले की नकल भी दाखिल की जानी चाहिये।,

आर्डर ४३

इस आर्डरके साथ नीचे लिखा रूल जोड़ दिया जाना चाहिये:—

रूल ३—रूल १के अनुसार की गई हर एक अपीलमें, हर एक मुतफरिकात के मुकदमोंमें, और हर एक ऐसी नालिशमें जो अदम-पैरवी में खारिज कर दी गई हो, एक जाबतेका हुक्म तैयार किया जाना चाहिये, जिसमें उस अपील या मुकदमेका साफ साफ फैसला, उसमें हुआ खर्चा और उन फरीकसानी के, अगर कोई हों, नाम लिखे रहेंगे, जिन्हें यह खर्चा अदा करना चाहिये।

आर्डर ४६

इस आर्डरमें नीचे लिखा रूल जोड़ दिया जाना चाहिये:—

“रूल ८—आर्डर ४१ का रूल ३८, जहां तक हो सकेगा, इस आर्डरके अनुसार की जाने वाली कार्रवाईके सम्बन्धमें लागू होगा।”

आर्डर ४७

इस आर्डरमें नीचे लिखा रूल जोड़ दिया जाना चाहिये:-

"रूल १०-आर्डर ४१ का रूल ३८, जहां तक हो सकेगा, इस आर्डर के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्धमें लागू होगा।"

आर्डर ५१

इस नीचे लिखे आर्डर ५२ को सम्मिलित कर देना चाहिये:-

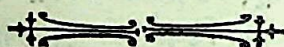
आर्डर ५२

"रूल १-आर्डर ४१ का रूल ३८, जहां तक हो सकेगा, ज़ाबता दीवानी की दफा ११५ के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्धमें लागू होगा।"

पटना हाईकोर्ट के रूल

ज़मीमा नं० ३-ज़ाबता दीवानी के आर्डर १२२ के अनुसार पटना

हाईकोर्ट द्वारा तैयार किये गए नियम (रूल)

**आर्डर १६ रूल २ (१)**

इस रूलमें नीचे लिखी शर्त जोड़ दी जानी चाहिये:-

"लेकिन शर्त यह है कि भारत-मन्त्री को इस रूल के अनुसार अदालत में कोई भी खर्चा दाखल करना न पड़ेगा, जबकि उन्होंने ही सम्मन के लिये ख़्वास्त दी हो और तलब किये जाने वाला शख्स भी सरकारी कर्मचारी हो, जो उन बातों के सम्बन्धमें, जिन्हें वह जानता है, या उन बातों के सम्बन्धमें, जिनसे उसे साधारण मनुष्य की हैसियत से साबिका (काम) पड़ा है, शहादत देने के लिये तलब किया गया हो।"

आर्डर १६ रूल ३

इस रूलमें यह नीचे लिखी शर्त जोड़ दी जानी चाहिये:-

"लेकिन शर्त यह है कि जब वह शख्स, जो तलब किया गया है, कोई सरकारी कर्मचारी हो जो किसी ऐसे मामले में, जिसमें सरकार एक फ़रीक़ है, उन बातों के सम्बन्धमें जो उसे साधारण मनुष्य की हैसियत से मालूम हुई हैं या जिनसे उसे (साधारण मनुष्य की हैसियत से) साबिका (काम) पड़ा है, शहादत देने के लिये तलब किया गया हो तो

१—अगर उस कर्मचारीका मासिक वेतन १०) रु० से अधिक नहीं है तो, अदालत सम्मन तामील करते समय उसकी वह खर्चा अदा कर देगी, जो रूल २ में तय किया गया है, और यह रुपया खर्जाने से निकाल लेगी;

२—अगर उस कर्मचारीका वेतन १०) रु० से अधिक है और अदालत उसके हेड-क्वार्टरसे पांच मीलसे अधिक फासले पर नहीं है तो, अदालतको यह अधिकार होगा कि वह, उसके हाज़िर होने पर, उसे वह कुल सफ़र-खर्च दे देवे जो उसे घटाना पड़ा है;

३—अगर उस कर्मचारीका वेतन १०) रु० मासिकसे अधिक है और अदालत-उसके हेड-क्वार्टरसे पांच मील से अधिक फासले पर है तो, अदालत उसे कोई खर्चा न देगी। ऐसी दशामें रूल २ के अनुसार अदालतमें जमा किया हुआ सारा खर्चा सरकारके नाम डाल दिया जायगा।”

... (५) ...
...
... (६) ...
...
... (७) ...
...
... (८) ...
...
... (९) ...
...
... (१०) ...
...

संग्रह जाबता दीवानी

सन् १९०८ ई०

परिशिष्ट (२)

पंचायत

सिद्धान्त शिखर

वर्ष १९७८ ई

(१) अंकगणित

संस्कृत

संग्रह ज़ाबता दीवानी

सन १९०८ ई०

परिशिष्ट (२)

पंचायत



१-फरीकैन मुकदमा पंचायतमें मामला भेज देने के लिये अदालतमें दरख्वास्त दे कर हुक्म ले सकते हैं:—

(१) जब किसी मुकदमें में उससे सम्बन्ध रखनेवाले कुल फरीकैन इस बातपर राजी हों, कि कोईभी मामला, जिसकी निश्चित उनमें झगड़ा है, पंचायतमें भेज दिया जाय, तो फैसला सुनाय जाने के पहिले किसी भी समय वे अदालत से ऐसा हुक्म दिये जाने के लिये प्रार्थना कर सकते हैं।

(२) ऐसी प्रत्येक प्रार्थना (दरख्वास्त) लिखित होनी चाहिए और उसमें उस मामले का ब्योरा होना चाहिए जो पंचायत में पेश किए जाने को है।

२-पंच (सालिस) की नियुक्ति

पंच (सालिस) की नियुक्ति उस प्रकार की जायगी जिसके लिए फरीकैन आपस में तय करेंगे।

३-मामला पंचायत में पेश करने के लिये हुक्म

(१) अदालत अपने हुक्मसे, पंच (सालिस) के पास वह मामला पेश करेगी जिसके तय करने के लिये उसे कहा गया है, और (पंचायती) फैसला देने के लिए ऐसा समय नियत कर देगी जो कि उसे उचित जान पड़ेगा और उस हुक्म में इस समय का उल्लेख कर देगी।

(२) जब कोई मामला पंचायतमें पेश कर दिया गया हो, तो, सिवाय उस तरीकेपर और उस हद तक, जिसके लिए इस परिशिष्टमें व्यवस्था की गई है, अदालत ऐसे मामले पर उसी मुकदमें में विचार न करेगी।

४-जब दो अथवा अधिक पंचों के सामने मामला पेश किया गया हो, तो उनके मतों में होने वाले भेदके सम्बन्ध में व्यवस्था करने सम्बन्धी हुक्म

(१) जब मामला दो अथवा अधिक पंचों के सामने पेश किया गया हो, तो इसके लिए दिये गये हुक्म में उस मत-भेद के सम्बन्ध में भी नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था कर दी जायगी जो उन पंचों के बीच में हो:—

(ए) एक सर-पंच की नियुक्ति करके; या

(बी) इस बात की घोषणा करके कि, अगर पंचों का बहुमत एक है तो बहुमत से दिया हुआ फैसला मान्य होगा; या

(सी) पंचों को सर-पंच नियुक्त करने का अधिकार दे कर; या

(डी) अन्य किसी प्रकारसे, जैसा कि फरीकैन के बीच में तय हो, अथवा, यदि उनमें कोई बात तय न हुई हो तो, जैसा कुछ अदालत तय करे।

(२) जब कोई सर-पंच नियुक्त किया गया हो, तो अदालत, जैसा उचित समझेगी, उसके फैसला देने का समय नियत कर देगी, बशर्ते कि उसे काम करने के लिए आज्ञा दी गई है।

५-कुछ मामलों में पंच नियुक्त करनेके सम्बन्ध में अदालत का अधिकार

(१) नीचे लिखी किसी भी दशा में, अर्थात् :—

(ए) जब किसी उचित समय के भीतर फरीकैन में पंच की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई बात तय न हो, अथवा जो व्यक्ति पंच नियुक्त किया गया है वह पंच होना स्वीकार न करे, या

(बी) जब कोई पंच अथवा सर-पंच—

१-मर जाय, या

२-कार्य करने से इन्कार कर दे अथवा उसमें असावधानी करे, या कार्य करने में असमर्थ होजाय, या

(सी) ऐसी दशा में ब्रिटिश भारतसे बाहर चला जाय जिससे यह मालूम होता हो कि वह शीघ्र वापस नहीं आवेगा, या

(डी) जब पंचायत में मामला पेश करने के सम्बन्ध में दिये गये हुक्म में पंचों को यह अधिकार दिया गया हो कि वे सर-पंच नियुक्त करें और वे ऐसा न कर सकें,

तो, किसी भी फरीक को यह अधिकार होगा, कि वह दूसरे फरीक

पर अथवा पंचों पर, जैसा कुछ भी हो, पंच अथवा सर-पंचकी नियुक्ति करनेके लिये लिखित नोटिस तामील करावे ।

(२) अगर इस नोटिस के तामील हो जाने के बाद ठीक सात दिन के भीतर अथवा ऐसे अधिक समय में, जैसा कि प्रत्येक अवस्था में अदालत दे, कोई भी पंच अथवा सर-पंच, जैसा कुछ भी हो, नियुक्त न किया जाय, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह, उस शख्सके दरखवास्त देने पर जिसने कि नोटिस दी है, और दूसरे फरीकैन को अपनी बात पेश करनेका अवसर (मौका) देनेके पश्चात् पंच अथवा सर-पंच को नियुक्ति करदे, या उस पंचायत को रद्द कर देनेका हुक्म दे देवे, और ऐसी दशा में अदालत स्वयं उस मामले में विचार करेगी ।

६-पैरा ४ अथवा ५ के अनुसार नियुक्त किए गए पंच अथवा सर-पंच के अधिकार

प्रत्येक ऐसे पंच अथवा सर-पंच को, जो उपरोक्त पैराग्राफ ४ या ५ के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उस समय होते, अगर उसका नाम पहिले दिये गये हुक्म में शामिल कर दिया गया होता ।

७-गवाहों के नाम सम्मन जारी करना और उनकी पा-बन्दीका न किया जाना

(१) अदालत उन फरीकैन और गवाहों के नाम, जिनके पंच अथवा सर-पंच बयान लेना चाहता है, उसी प्रकार सम्मन जारी करेगी जैसे कि वह उस समय कर सकती है जब किसी मामले की सुनाई (समाअत) वह स्वयं करती है ।

(२) जो लोग ऐसे सम्मन के तामील होजाने पर हाज़िर न होंगे या जो अन्य कोई अपराध करेंगे अथवा अपना इज़हार देने से इन्कार करेंगे, या उस पंचायत में पेश हुए मामले की जांच (तहकीकात) के दौरान में पंच अथवा सर-पंचकी मानहानि करनेके अपराधी पाए जायेंगे, वे उन्हीं असुविधाओं, जुर्मानों और सज़ाओं के पाने के अधिकारी होंगे जिनके पाने के अधिकारी वे उस समय होते अगर उन्हांने अदालत के सामने होने वाले मुकद्दमों में ऐसे अपराध किए होते ।

८-पंचायत का फैसला देने के लिए समय का बढ़ाया जाना

जब पंच अथवा सर-पंच उस समय में अपना फैसला (award) पूरा न कर सकते हों जो हुक्म में दिया गया है, तो अदालत को अधिकार होगा कि वह, अगर उचित समझे तो, या तो और समय बढ़ादे, और समय समयपर, उस समयके

समाप्त होजाने के पहिले अथवा पीछे, जो (पंचायती) फैसला देने के लिए हुक्म में दिया गया है, ऐसा समय बढ़ा दिया करे या उस पंचायत के रद्द किए जाने के लिए हुक्म दे देवे, और ऐसी दशा में वह स्वयं उस मामले में विचार करेगी।

९-पंचों के बजाय सर-पंच कब मामला तय कर सकता है

जब कोई सर-पंच नियुक्त किया गया हो, तो पंचों की जगह वह पंचायत में पेश किए गए मामले पर विचार कर सकता है, अर्थात्—

(प्र.) अगर उन्होंने बिना कोई फैसला दिए फैसले के लिए नियत समय को तष्ट कर दिया है, या

(बी) अगर उन्होंने अदालत अथवा सर-पंच को इस बात की लिखित नोटिस दे दी है कि वे राजी नहीं हैं।

१०-फैसले पर हस्ताक्षर (दस्तखत) किए जाना और उसका अदालत में दाखिल किया जाना

जब किसी मामले में पंचायत ने अपना फैसला दे दिया हो, तो जिन लोगों ने यह फैसला दिया है, वे उसपर अपने हस्ताक्षर करके उस फैसले को मय सन बयानों और कागज़ों के, जो उनके सामने लिए या सुबूत में पेश किए गए हों, अदालत में दाखिल कर देंगे, और इस दाखिल किए जाने की इत्तला फ़ी-कैलको दे दी जायगी।

११-पंचों अथवा सर-पंच द्वारा किसी मामले का बतौर खास मामले (' Especial Case ') के पेश किया जाना

किसी ऐसे मामले में, जो अदालत के हुक्म से पंचायत में भेजा गया है, पंच अथवा सर-पंच, अदालत की इजाज़त लेकर, उस कुल मामले या उसके किसी अंश के सम्बन्ध में अपना फैसला देते हुए उसे अदालत की राय के लिए बतौर खास मामले के पेश कर सकते हैं, और अदालत उसमें अपनी राय दे देगी और यह हुक्म देगी कि उसकी वह राय उस फैसले में शामिल कर दी जाय और उसका एक अंग समझी जाय।

१२-फैसले में काट-छांट करने अथवा उसके दुरुस्त करने का अधिकार
अदालत अपने हुक्म से किसी पंचायती फैसले में काट-छांट कर सकती है अथवा उसे दुरुस्त कर सकती है:—

(प) जब ऐसा मालूम हो, कि फैसले का कुछ अंश उन बातों के सम्बन्ध में है जो पंचायत के सामने पेश नहीं की गई थीं और वह अंश दूसरे अंशों से अलग किया जा सकता है और इससे उन बातों

के सम्बन्ध में दिए गए फैसले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता जो पंचायत के सामने पेश की गई है; या

(बी) जब वह फैसला जाबते में पूरा न हो या उसमें कोई जाहिरा गलती हो जो बिना उस फैसले पर कोई असर डाले दुस्त की जा सकती हो; या

(सी) जब उस फैसले में कोई लिखने की गलती या ऐसी भूल रह गई हो जो धोखे से गलत कलम चल जाने या कोई बात छूट जाने से हुई हो।

१३-पंचायत के खर्चों के सम्बन्ध में हुक्म

अदालत को यह भी अधिकार होगा कि वह पंचायत के खर्चों के सम्बन्ध में, जैसा उचित समझे, हुक्म दे, जब कि ऐसे खर्चों के सम्बन्ध में कोई सवाल पैदा हो और फैसले में इसके सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक व्यवस्था न की गई हो।

१४-फैसला (award) अथवा पंचायत में पेश किया हुआ मामला कब वापस किया जा सकता है

अदालत को अधिकार होगा कि वह पंचायती फैसले को या उस मामले को, जो पंचायत में पेश किया गया है, ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, वही पंच अथवा सर-पंच के पास उसपर फिर विचार करने के लिए वापस कर दे,—

(ए) जब उसमें कोई ऐसी बात फैसल करने को रह गई हो जो फैसले के लिए पेश की गई थी, अथवा जब उसमें कोई ऐसी बात फैसल कर दी गई हो जो पेश नहीं की गई थी, सिवाय उस दशा में जब कि बिना उस फैसले पर कोई असर डाले, जो पेश की हुई बातों के सम्बन्ध में दिया गया है, वह मामला अलग किया जा सकता हो;

(बी) जब वह (पंचायती) फैसला ऐसा अतिशिष्ट हो कि उसकी इजरा न की जा सकती हो;

(सी) जब उस फैसले के बाजाबता (कानूनी) होने के सम्बन्ध में उसमें कोई आपत्ति जान पड़े।

१५-पंचायती फैसला रद्द करने के कारण

(१) पैरा १४ के अनुसार वापस किया हुआ पंचायती फैसला उस समय बाजायज हो जाता है अगर वे पंच अथवा सर-पंच उस पर फिर विचार न कर सकें। लेकिन सिवाय नीचे लिखे कारणों पर कोई भी फैसला रद्द न किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(ए) पंच अथवा सर-पंच के घूस (रिश्वत) खालेने या अनुचित भाषण करने पर,

(बी) किसी फ़रीक के, फ़रेब से किसी ऐसी बात छिपा रखने का, अपराधी होने पर, जो कि प्रकट की जानी चाहिए थी, अथवा जान बूझकर पंच अथवा सर-पंच को ग़लत बातें बतलाने या धोखा देने पर;

(सी) जब फैसला अदालत के उस हुक्म के बाद दिया गया हो जिससे उसने पंचायत को रद्द करके स्वयं मामले की समाप्त शुरू कर दी हो या उस मियाद के ख़तम होजाने के बाद दिया गया हो जो अदालत ने दी थी अथवा वह और किसी तरह पर नाजायज़ हो;

(२) जब कोई (पंचायती) फैसला नाजायज़ होजाय या कलॉज (१) के अनुसार रद्द कर दिया जाय, तो अदालत उस पंचायत के रद्द किए जाने के लिए हुक्म दे देगी और ऐसी दशा में उस मुकदमें की सुनाई खुद करेगी।

१६—अदालत का फैसला पंचायती फैसले के आधार पर होगा

(१) जब अदालत को कोई भी कारण पंचायती फैसले को या पंचायत में पेश किए गए मामले को, ऊपर बतलाए अनुसार, उस पर फिर विचार किए जाने के लिए वापस करने का न देख पड़े और पंचायती फैसले को रद्द करने के लिए कोई दरख़्वास्त न दी गई हो, या अदालत ने ऐसी दरख़्वास्त नामंजूर कर दी हो, तो, ऐसी दरख़्वास्त देने के लिए नियत समय बीत जाने के बाद, अदालत उस (पंचायती) फैसले के आधार पर अपना फैसला दे देगी।

(२) इस प्रकार अदालत द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार डिकरी दी जायगी और इस डिकरी की अपील न हो सकेगी, सिवाय उस हद तक जब कि वह डिकरी उस पंचायती फैसले से अधिक हो अथवा उस फैसले के आधार पर न दी गई हो।

पंचायत में मामला पेश किए जाने के लिए किए गए

इक्करारनामा पर हुक्म

१७—पंचायत में मामला पेश किए जाने के सम्बन्ध में किये गए इक्करारनामा को अदालत में पेश करने के लिए

दरख़्वास्त—

(१) जब कई लोग इस सम्बन्ध में लिखित इक्करार करें कि कोई मामला, जिसकी निस्वत उनमें झगड़ा है, पंचायत में पेश किया जाय, तो उस इक्करारनामा के लिखने वाले, या उनमें से कोई भी शख्स किसी ऐसी अदालत को, जिसको उस मामले की सुनाई करने का अधिकार है जिसके सम्बन्ध में

इकरारनामा लिखा गया है, इस बात की दरख्वास्त दे सकते हैं कि वह इकरारनामा को दाखिल अदालत कर दे।

(२) दरख्वास्त लिखित होनी चाहिए और उसपर उस नालिश की तरह पर नम्बर डाले जाने चाहिए और उसको रजिस्टर में वैसा ही दर्ज किया जाना चाहिए जो उन फरीकैन के बीच दायर की गई हो, जिनमें से एक अथवा अधिक, मुद्दई हों या बतौर मुद्दई के दावेदार हों और बाकी मुद्दाअलेह या मुद्दाअलेहोंकी तरह पर हकदार हों, अगर वह दरख्वास्त कुल फरीकोंकी ओरसे दायर की गई है, या, अगर कोई बात इसके विपरीत है तो, दरख्वास्त देने वाला मुद्दई और बाकी आदमी मुद्दाअलेह हों ;

(३) ऐसी दरख्वास्त दिए जाने पर अदालत यह हुकम देगी कि इसकी नोटिस, दरख्वास्त देने वाले को छोड़, बाकी उन सभी लोगों को दे दी जाय जिनके दम्यान इकरारनामा हुआ है, जिसमें उन लोगों को इस बात के लिए लिखा जायगा कि वे नोटिस में बतलाए हुए समय के भीतर इस बात की वजह ज़ाहिर करें कि इकरारनामा क्यों न दाखिल अदालत किया जाय।

(४) जब कोई माकूल वजह न ज़ाहिर की जायगी, तो अदालत उस इकरारनामा को दाखिल अदालत (शामिल मिलिल) किए जाने का हुकम दे देगी और उस पंच के पास मामला पेश किए जाने के लिए हुकम दे देगी जो इकरारनामा की शर्तों के अनुसार नियुक्त किया गया हो या, अगर इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है और फरीकैन सहमत नहीं हैं तो, अदालत पंच की नियुक्ति कर सकती है।

१८—मुकद्दमें का मुल्तवी किया जाना, जब कि मामले को पंचायत में पेश किए जाने के लिए इकरारनामा किया गया हो।

जब मामला पंचायत में पेश किये जाने के लिये किये गये इकरारनामा का लिखने वाला कोई भी शख्स या कोई ऐसा शख्स, जो उसके ज़रिये से दावेदार है, उस इकरारनामा के लिखने वाले दूसरे शख्स के ऊपर या उस शख्स के ऊपर, जो उसके ज़रिये से दावेदार है, उस मामले के सम्बन्ध में कोई नालिश दायर करे जिसे पंचायत में पेश किये जाने के लिये इकरारनामा हुआ है, तो ऐसी नालिश के किसी भी फरीक को अधिकार है कि वह जल्द से जल्द और उन सभी हालतों में, जब कि उमूर तनक़ीह तलब यह इकरारनामा होने के समय या उससे पहिले फसल होगए हों, अदालत को मुकद्दया मुल्तवी किये जाने के लिये दरख्वास्त दे और अदालत, अगर उसे इसबात का इतमीनान हो जाय कि इस बातके लिये कोई माकूल वजह नहीं है कि मामला उस इकरारनामा के अनुसार पंचायत में क्यों न पेश किया जाय जो इस मामले को पंचायत में पेश करने के लिये किया गया

हैं और यह कि सायल (दरखास्त देनेवाला) नालिश दायर किये जाने के समय उन सारी बातों के करने के लिये तैयार और राजी था और अब भी है जो पंचायतमें ठीक प्रकार से मामला फैसला किये जानेके लिये आवश्यक हैं, मुकदमा सुलतवी करने के लिये हुक्म दे सकती है।

१९-पैराग्राफ १७ के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में लागू होने वाले नियम

उपरोक्त नियम, जहां तक कि वे इस इकरारनामा के अनुसार हो जो पैराग्राफ १७ के अनुसार अदालत में दाखिल किया गया है, उन कुल बातों के सम्बन्ध में, जो पंचायत में मामला पेश करने के सम्बन्ध में उस पैराग्राफ के अनुसार अदालत द्वारा दिये गये हुक्म के अनुसार की जायें, और पंचायती फैसला तथा उस फैसले के आधार पर दी गई डिकरी के सम्बन्ध में लागू होंगे।

बिना अदालत के हस्तक्षेप के पंचायत का होना (३)

Arbitration without the intervention of a Court.

२०-उस मामले में जो किसी अदालत के बिना हस्तक्षेप किए हुए पंचायत में पेश किया गया हो, दिए गए पंचायती फैसले का दाखिल अदालत किया जाना

(१) जब कोई मामला बिना किसी अदालत के हस्तक्षेप के पंचायत में पेश किया गया हो और उसमें पंचायत ने अपना फैसला दे दिया हो, तो कोई भी शख्स, जिसका उस फैसले से सम्बन्ध है, किसी भी अदालत को, जिसे उस मामले की सुनाई करने का अधिकार हो जिसके सम्बन्ध में फैसला दिया गया है, यह दरखास्त दे सकता है कि वह पंचायती फैसला दाखिल अदालत किया जाय।

(२) यह दरखास्त लिखित होगी और उस पर बतौर नालिश के, जिसमें सायल मुद्दे और दूसरे लोग मुद्दा अलेह होंगे, नम्बर डाले जायेंगे और उसका इन्दराज रजिस्टर में किया जायगा।

(३) अदालत इस बातका हुक्म देगी कि, सायलको छोड़, पंचायत में पेश किए गए मामले के सभी "फरीकन" को नोटिस दीजाय जिसमें उनको एक नियत समयके भीतर इस बातकी वजह ज़ाहिर करने के लिए लिखा जाय कि वह पंचायती फैसला क्यों न दाखिल अदालत किया जाय।

२१-ऐसे फैसले का दाखिल किया जाना और उसका अमल में लाया जाना

(१) जब अदालतको इस बातका विश्वास होजाय कि मामला पंचायतमें पेश किया गया है और यह कि पंचायत ने उसमें अपना फैसला दे दिया है और जब

पैराग्राफ १४ या १५ में बतलाई हुई अथवा उल्लिखित कोई भी वजह साबित न हुई हो, तो अदालत उस पंचायती फैसले को दाखिल अदालत किये जानेका हुक्म दे देगी और उसी (पंचायती) फैसले के आधार पर अपना फैसला सुना देगी ।

(२) इस प्रकार दिए गए अदालत के फैसले के अनुसार डिकरी दी जायगी और इस डिकरी के विरुद्ध कोई भी अपील न हो सकेगी, सिवाय उस हद तक जब कि डिकरी उस पंचायती फैसले से जायद दी गई हो या वह उस फैसले के आधार पर न हो ।

२२—स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट सन् १८७७ ई० मेंसे कुछ शब्दोंका निकाल दिया जाना

स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट (कानून दादरसी खास) सन् १८७७ ई० की धारा २१ के नीचे लिखे हुए अन्तिम शब्द, पंचायत में मामला पेश करनेके लिए किए गए इकरारनामा में अथवा किसी पंचायती फैसले के सम्बन्ध में, लागू न होंगे जिसके सम्बन्ध में इस परिशिष्ट के नियम लागू होते हैं ।

“लेकिन अगर कोई शर्त, जिसने ऐसा कोई मुआहिदा किया है और उसके पूरा करने से इन्कार कर दिया है, किसी भी ऐसी बात के सम्बन्ध में नालिश करता है जिसे उसने पंचायत में पेश करने का मुआहिदा (इकरारनामा) किया है, तो इस मुआहिदा के होने से नालिश दायर नहीं की जा सकती ।”

२३—फार्म

जो फार्म जमीना (Appendix) में बतलाए गए हैं, वे, ऐसी रद्द-बदल करने के बाद, जैसी प्रत्येक मामले में आवश्यक हो, उसमें बतलाई हुई भिन्न भिन्न बातों के सम्बन्ध में प्रयोग में लाए जायेंगे ।

जमीमा (Appendix)

नंबर १

पंचायतमें मामला पेश किये जानेका हुक्म हासिल करने के वास्ते
दरखवास्त

उनवान मुकदमा

१-यह मुकदमा वास्ते [इस जगह पर दावा की किस लिखनी चाहिए]
दायर किया गया है ।

२-फरीकैन के बीच जिस बातका झगड़ा है, वह इस प्रकार है [यहाँ पर वह
बात लिखनी चाहिए जिसकी निश्चत झगड़ा है] ।

३-सायलों में, जिनमें के सभी लोग फरीक मुकदमा हैं, यह तय पाया है कि
उनमें जिस बातकी निश्चत झगड़ा है वह पंचायत में पेश की जाय ।

४-इसलिए सायलों की यह दरखवास्त है कि पंचायत में मामला पेश करनेके
लिए इजाज़त दीजाय ।

(नाम सायलान)

भाज तारीख माह सन् १९ ई० ।

नोट—अगर फरीकैन में पंचों की निश्चत भी बात तय हो होगई है तो यह
भी लिख देना चाहिए ।

(१५१)

नंबर १

पंचायतमें मामला पेश किये जानेकी बाबत हुकम

[उनवान मुकदमा]

जो दरखास्त तारीख.....माह.....सन् १९२.....ई० को दाखिल की गई थी, उसको पढ़कर यह हुकम दिया जाता है कि यह नीचे लिखा हुआ मामला, जिसकी निस्वत इस मुकदमेमें झगड़ा है, अर्थात्

फैसले के लिए.....और.....के पास पेश किया जाय. या अगर वे सहमत न हों तो.....के पास पेश किया जाय, जो इस तहरीर के ज़रिए सर-पंच मुकर्रर किए जाते हैं; और इन पंचों को चाहिए कि वे अपना फैसला लिखकर तारीख.....माह.....सन् १९२.....ई० तक या उसके पहिले दे दें, और अगर उपरोक्त पंच फैसले में सहमत न हों तो उक्त सर-पंचको चाहिए कि वह उस समयके खतम हो जानेके बाद, जिसमें फैसला देना पंचोंके अधिकारमें है,.....महीने के भीतर अपना लिखित फैसला दे दें ।

दरखास्त देने की इजाज़त है ।

यह हुकम मेरे दस्तखत और अदालत की मोहर से आज तारीख.....माह.....सन् १९.....ई० को दिया गया ।

दस्तखत मज

नए पंचकी नियुक्ति के सम्बन्ध में हुक्म

[उनवान मुकद्दमा]

कैक तारीख... माह... सन् १९... ई० को [यहाँ पर पंचा-
यत्तमें मामला पेश किए जाने के लिए दिया गया हुक्म और पंचकी मौत इन्-
कारी इत्यादि सारी बातें लिखी जानी चाहिए] दिए गए हुक्मके द्वारा बरखा-
मन्दी यह हुक्म दिया गया है कि... के स्थान में, जिनकी मृत्यु होगई है
(अथवा जैसी कुछ भी हो)... नियुक्त किए जाते हैं कि वह... के साथ,
जो उक्त हुक्मके अनुसार नियुक्त किये गये पंचों में से बाकी बचे हुए पंच हैं, शतौर
पंचके काम करें; और यह हुक्म दिया जाता है कि उक्त पंच अपना फैसला तारीख
... माह... सन् १९... ई० को या उससे पहले दे दें।

यह हुक्म मेरे दस्तखत और अदालतकी मोहरसे आज तारीख... माह ...
सन् १९... ई० को दिया गया।

दस्तखत जज

(२५३)

नंबर ४

खास मामला

[उनवान मुकद्दमा]

खाकिन

और

खाकिन

के बीच में होने वाली पंचायत के सम्बन्ध में नीचे लिखा
मामला बतौर खास मामले के अदालत की राय के लिए पेश किया जाता है:--

[यहां पर कुल बातों को संक्षेप में और पैरावार लिखना चाहिए]

कानूनी प्रश्न, जिनके निम्नत अदालत को अपनी राय ज़ाहिर करनी
चाहिए, ये हैं:--

पहला यह कि क्या

दूसरा यह कि क्या

(पंचका नाम)

(पंचका नाम)

तारीख माह खम् १९ ई० ।

पंचायत का फैसला

[उनवान मुकदमा]

साकिन _____ और _____
 के बीच होने वाली पंचायत का मामला।
 साकिन _____ चूंकि पंचायत में मामला पेश करने सम्बन्धी हुक्मके अनुसार, जो तारीख
 माह सन १९ ई० को की अदालत द्वारा दिया
 गया था, नीचे लिखा मामला, जिसकी निस्वत और
 झगड़ा है, अर्थात् _____

हमारे सामने फैसले के वास्ते पेश किया गया है,

अब हम, उस मामले पर, जो हमारे सामने पेश किया गया है, भलीभांति
 विचार कर, अपना नीचे लिखा हुआ फैसला देते हैं

अब हम यह फैसला करते हैं,

(१) कि _____

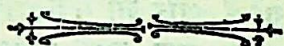
(२) कि _____

तारीख माह सन १९ ई० ।

_____ (पंचोंके नाम)

पञ्चायत

उपरोक्त पञ्चायत के विषय को सरल रीतिसे समझनेके लिये हाल तककी नज़ीरों सहित व्याख्या नीचे दी गई है। जहां पर पञ्चायत से सम्बन्ध रखने वाले किसी पैराका उल्लेख किया गया हो तो आप ऊपर मूल में देख कर विचार करें,



जब किसी मुकद्दमें में उस मुकद्दमें से सम्बन्ध रखने वाले कुल फ़रीक़ैन इस बात पर राजी हो कि कोई मामला पञ्चायतमें पेश कर दिया जाय, तो फैसला दिए जानेके पहिले किसी भी समय वे अदालत को इस बातकी दरख़वास्त दे सकते हैं कि, अदालत उस मामलेको पञ्चायतमें पेश किए जानेके लिए हुक़म दे दे। ऐसी दरख़वास्त लिखित होनी चाहिये और उसमें उस मामलेका भी हवाला होना चाहिये जो पञ्चायतमें पेश किए जाने को है (देखो ज़ाबता दीवानीका परिशिष्ट २ पैरा १)

इस पैरामें उस पञ्चायतका ज़िक्र है जो किसी ऐसे मामलेमें की जाने को हो जो चल रहा है। ज़ाबता दीवानीमें तीन प्रकारकी पञ्चायतोंका वर्णन है:—

(१) जब किसी चलते हुए मुकद्दमें के फ़रीक़ैन मामलेको पञ्चायतमें पेश करना चाहते हों। इस प्रकारके मामलेमें आदिसे अन्त तक सारी कार्रवाई अदालतकी देख-रेखमें रहती है और इस सम्बन्धमें अमलमें आने वाले नियमोंका वर्णन परिशिष्ट २ के पैरा १ से १६ तक में किया गया है।

(२) जब फ़रीक़ैन बिना मुकद्दमा बाज़ीमें पड़े मामलेको पञ्चायतमें पेश करना चाहते हों और इस बातकी इच्छा प्रकट की गई हो कि मामला पञ्चायतमें पेश करने के लिए किए गए इकरारनामाके ऊपर अदालतकी मंजूरी ज़रूरी है। यह इकरारनामा अदालतमें दाखिल किया जाता है। इस अवस्थामें आगेहाने वाली सारी कार्रवाई अदालतकी देख-रेखमें होती है और इस सम्बन्धमें पैरा ३ से १६ तकके नियम, जहां तक कि वे दाखिल किए गए इकरारनामाके अनुकूल हों, लागू होंगे।

(३) जब मामला पञ्चायतमें पेश किये जानेका इकरारनामा किया गया हो और बिना अदालतके कुछ हस्तक्षेप किए पञ्चायती कार्यवाई की जाय, और अदालतकी मदद सिर्फ़ उस पञ्चायती फैसलेको अमलमें लानेके लिए ही मांगी जाय। ऐसे मामलेमें कोई भी शर्क़त, जिसका उस पञ्चायती फैसलेसे सम्बन्ध है, उस सम्बन्धमें अफ़्तियार समाप्त रखने वाली किसी भी अदालतको यह दरख़वास्त दे सकता है कि वह पञ्चायती फैसला शामिल मिलित करके उसके अनुसार विकरी दे दी जाय, (देखो पैरा २० और २१)।

(१) और (२) अथवा (३) में बतलाई हुई अवस्थाओं में पंचायत में मामला पेश करनेके बीच बड़ा अन्तर है । (१) में बतलाई हुई हालतों में पंचायत में मामला दिए जाने के लिए किया गया इकरारनामा और उस इकरारनामके आधार पर दी गई दरख्वास्तोंके सम्बन्धमें उन सभी फरीकैनकी मंजूरी होना जरूरी है जिनका उनसे सम्बन्ध है और असलमें मामलेका पेश किया जाना उसी समय हो सकेगा जब अदालतने इसके लिये हुक्म दे दिया हो, इसलिए उस समय तक कार्रवाईके बाकायदा होनेके सम्बन्धमें कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । (२) और (३) में बतलाई हुई अवस्थाओंमें की जाने वाली कार्रवाई, जो बतौर मुकद्दमाके बतलाई गई है और जो मुकद्दमेंकी भांति रजिस्टर की गई है, इस प्रकार की जानी चाहिए कि उस सारी कार्रवाईकी—पंचायतमें मामला पेश करनेका इकरारनामा या पंचायती फैसला, जैसी कुछ भी अवस्था हो—सम्भवतः अदालत कर सके । ऐसी दरख्वास्त के बिना कारण दिखलाना चाहिए । और ऐसा मालूम होगा कि उसके ऊपर जो हुक्म दिया गया है वह जांचा दीवानीमें बतलाई हुई डिकरी है, (देखो 29 C. 167 P. C.; 6 C. W. N. 226.

किसी ऐसे मुकद्दमेंकी पंचायतमें, जो कि चल रहा है, उससे सम्बन्ध रखने वाले सभी लोगोंको उस इकरारनामामें शामिल होना चाहिये जो पंचायतमें मामला पेश करने के सम्बन्धमें लिखा गया हो, (देखो 29 C. 167 P. C.; 30 C. 218; 10 W. R. 171; 11 C. 37)—यह सत्य हुआ है कि सिर्फ यह बात कि कोई मुद्दा अलेह हाज़िर नहीं हुआ है और मुकद्दमेंमें कोई वाद-विवाद नहीं करता है, इस बातके मान लेनेके लिए काफी वजह नहीं है कि वह ऐसा फरीक नहीं है जिसका उस मुकद्दमेंसे सम्बन्ध न हो, देखो 27 C. L. J. 939; 25 C. L. J. 339; 43 I. C. 169; 42 M. 632; 8 A. L. J. 645; 35 A. 107. इसके विपरीत फैसलेके लिए देखो 32 A. 657; 39 A. 489, 495; 18 M. L. T. 374—जब तक कि उसे खास तौरसे इसके लिए अधिकार न दिया गया हो, कोई वकील पंचायतमें मुकद्दमा पेश किए जाने के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकता, देखो 7 C. W. N. 343; 16 W. R. 160—जिस वकालतनामके आम अफ्तयारात दे दिए गए हों, वह बिल्कुल काफी नहीं है, देखो 29 A. 429. अगर कोई मुक़्तार जिसे किसी मुकद्दमेंकी पैरवी करनेका अधिकार दिया गया है, उस फरीककी जानमें और उसकी मंजूरीसे मामलेको पंचायतमें दे देता है, तो वह फरीक इस बात पर एतराज़ नहीं कर सकता कि वकीलको लिखित आज्ञा नहीं दी गई थी, देखो 9 M. 451; 24 C. 469.—हमेशा यही जरूरी नहीं है कि लिखित आज्ञा ही दी जाय, देखो 30 A. 32; 23 B. 629.

अगर फरीकैन मुकद्दमा इस बातके लिए राज़ी हों, तो अदालत अपनी ओर मामलेको पंचायतमें भेज सकती है, देखो 43 C. 290; 12 C. 173; 18 C. 507; 33 A. 645; 3 M. 78.

दरख्वास्त लिखित होनी चाहिए । अगर ऐसा न किया गया तो इसका हवाला जायदा दीवानी की दफ़ा ९९ के अनुसार किया जा सकता है, देखो 27 C. 611.

80 A. 92—अगर फरीकैन पंचायतमें मुकद्दमा देनेके लिए राजी हो जाय और उसी जगह अदालत इसकी मंजूरी भी दे दे, यद्यपि यह हुक्म किसी लिखित दस्तावेजके ऊपर न दिया गया हो, तो वह हुक्म बिल्कुल जायज़ होगा, देखो 79 I. C. 816 (A)—पंचायतमें मामला पेश हो जाने के बाद अदालतको यह अधिकार नहीं है कि वह उनमें से किसी एक फरीकको इस शर्तके साथ मुकद्दमा वापस लेनेका हुक्म दे सके कि वह फिर नए सिरेसे मुकद्दमा दायर कर सकेगा, देखो 9 A. 168 और 31 C. 516.

किसी चलते हुए मुकद्दमोंमें पञ्चायती कार्यवाहीके सम्बन्धमें जायता—अदालत अपने हुक्मसे उस मामलेको, जिसकी निश्चित झगड़ा हो, पंचायतमें दे देगी और पंचायती फैसला दिए जानेके लिए कोई समय नियत कर देगी। जब मामला पंचायतमें पेश कर दिया गया हो, तो अदालत, सिवाय परिशिष्ट २ पैरा ३ में बतलाए हुए नियमानुसार, उस मामलेके सम्बन्धमें कोई कार्यवाई न कर सकेगी। अगर पंच लोग नियत समयके भीतर फैसला न दे सकेंगे, तो अदालत या तो वह समय बढ़ा देगी या उस पंचायतसे मामला उठा लेगी और ऐसी दशमें वह स्वयं उस मामले पर विचार करेगी, (देखो पैरा ८)—जब मामला दो अथवा अधिक पक्षों के सामने पेश किया गया हो, तो उनके मत-भेदके सम्बन्धमें व्यवस्था करने के लिये हुक्म दिया जा सकता है। जब कोई सर-पंच मुक़र्रर किया गया हो, तो अदालत उसके फैसला देने के लिए समय नियत कर देगी (देखो पैरा ४)—कुछ मुकद्दमोंमें पंच मुक़र्रर करनेका अधिकार है, उदाहरणार्थ, जब कि पंचके मुक़र्रर करने के सम्बन्धमें फरीकैन राजी न होते हों या जब कोई पंच काम करनेसे इन्कार कर दे या मर जाय इत्यादि इत्यादि। अगर फरीकसानीको नोटिस दिए जाने पर सात रोज़के भीतर पंच मुक़र्रर न किया गया, तो अदालतको अधिकार है कि वह फरीकसानीके बयान लेनेके बाद किसी शख्सको पंच मुक़र्रर कर दे या पंचायतको रद्द कर दे (देखो पैरा ५)—पंचोंको गवाह तलब करने का अधिकार है (देखो पैरा ७)

पंचायती फैसला देने वाले शख्स उस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे और मय बयानों और कागज़ातके (अगर कोई हो) उसे अदालतमें दाखिल करवा देंगे, और उस फैसलेको अदालतमें दाखिल किए जानेकी नोटिस फरीकैनको दे दी जायगी (देखो पैरा १०)—पंच अथवा सर-पंचको अधिकार है कि वह अदालत की राय के लिए अपने फैसलेमें किसी मामलेके कुल या कुछ हिस्सेको 'खास मामला' की तौर पर दर्ज कर दे (देखो पैरा ११)

अदालत किसी पंचायती फैसलेको तरमीम या सही कर सकती है, जबकि—
(क) वह फैसला किसी ऐसे मामलेके सम्बन्धमें दिया गया हो जो पंचायत में पेश न किया गया हो और उसका उतना अंश फैसले पर बिना कोई प्रभाव डाले अलग किया जा सकता हो, या

(ख) जब कि उसमें कोई जायतेकी कमी रह गई हो या कोई भारी भूल हो गई हो, या

(ग) जब कि ग़लत क़लम चल जाने या कोई बात छूट जाने से उसमें कोई लिखने-पढ़नेकी ग़लती रह गई हो (देखो पैरा १२)
अदालत पंचायतमें होने वाले खर्चके सम्बन्धमें भी हुकम दे सकती है (देखो पैरा १३)

अदालतको किसी फैसले या उसके किसी हिस्सेको, उस पर फिर विचार करने के लिए, वापस कर देनेका अधिकार है—जब (क) कोई बात बिना तय की हुई छोड़ दी गई हो या जब कोई ऐसी बात तय कर दी गई हो जो पेश नहीं की गई है; (ख) जब फैसला अनिश्चित हो, या (ग) जब उसके बाज़ान्ता होने के सम्बन्धमें कोई एतराज़ हो (पैरा १४)

फैसलेकी मसूखी—सिवाय नीचे लिखी किसी बिनाके ऊपर, कोई भी पंचायती फैसला मसूख न किया जा सकेगा:—

(क) पंच अथवा सर-पंचके घूस वगैरा खा लेने या अनुचित व्यवहार करने पर;

(ख) फ़रैब (कपट) के साथ किसी बातको छिपाने या जान-बूझकर पंच को ग़लत बात समझाने या धोखा देनेकी हालतमें;

(ग) जब फैसला उस हुकमके बाद, जिससे पंचायत रद्द कर दी गई है और मामला अदालतने अपने हाथमें ले लिया है, या उस मियादके ख़तम होजाने के बाद दिया गया हो जो अदालतने मुक़र्रर की है, अथवा जब वह और किसी तरहसे नाजायज़ हो।

जब कोई पंचायती फैसला नाजायज़ हो जाय या और किसी तरहसे रद्द कर दिया जाय, तो अदालत उस मामलेमें स्वयं विचार करेगी (देखो पैरा १५)

मंजूरी—जब अदालत, उसपर फिर विचार किए जानेके लिए, किसी पंचायती फैसलेको वापस करनेका कोई कारण न देखे और उसके रद्द किए जानेके लिए कोई दख़्वास्त न दी गई हो या अदालतने ऐसी दख़्वास्त नामंजूर कर दी हो, तो उस पंचायती फैसलेके आधार-पर अदालत अपना फैसला सुना देगी और फिर उस मुक़द्दमेमें वैसी ही डिकरी दे दी जायगी (देखो पैरा १६)

विवरण—यह आवश्यक है कि पंचायती फैसलेके लिए अदालत एक मुनासिब मियाद मुक़र्रर कर दे। यह शर्त ताकीदी है। जब कि एक पंचायती फैसला नियत समयके बाद दिया गया, तो यह तय पाया कि वह फैसला नाजायज़ है, देखो 13 A. 300 P. C.; 8 A. 548; 14 A. 347; 30 A. 169 और 18 M. 22—किन्तु यह भी तय किया गया है कि अगर वह पंचायती फैसला नियत समयके भीतर दिया गया है, तो यह काफी होगा। यह आवश्यक नहीं है कि वह उस मियादके अन्दर अदालतको पहुँच जाय, देखो 27 A. 459; 13 B. 119; 13 A. 300; 26 A. 105; 8 C. W. N. 916—यद्यपि नियत समयके बाद दिया हुआ पंचायती फैसला नाजायज़ है किन्तु फ़रीक़त उसकी निश्चय यह दोषारोपण न कर सकेंगे कि वह नियत समयके बाद दिया गया है।

देखो 4 P. L. J. 265, 270—अदालतको अधिकार है कि यह फैसला खतम न हो जाने तक के लिए समयको बढ़ा दे। केवल इस बातसे, कि अदालतने उस पंचायती फैसलेके आधार पर डिकरी दे दी है, यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि मियादकी मुदत बढ़ा दी गई है, (देखो 13 A. 300 P. C.; 8 A. 548)—फैसला उसी समय 'दिया गया' समझना चाहिए जब कि वह पूरा हुआ हो और उस पर पंचोंके हस्ताक्षर हुये हों, देखो 27 A. 459; 26 A. 105—'दिया गया' शब्दमें फैसलेका अदालतमें दाखिल करना शामिल नहीं है, देखो 13 B. 119.

पंचायतमें मामला पेश करने सम्बन्धी हुक्मके फार्मके लिए देखो परिशिष्ट (२) के ज़मीमाका फार्म नं० ३।

किसी मामलेके एक बार पंचायतमें पेश हो जाने पर बिना उचित और पर्याप्त कारणके कोई भी फरीक उसका विरोध नहीं कर सकता, देखो 10 W. R. 51 P. C.; 7 A. 273; 27 M. 112; 17 C. 200.—विरोधी पक्ष से पंचका मिल जाना उचित कारण है, देखो 29 A. 13.

मत-भेद के सम्बन्ध में बिना कोई व्यवस्था किये हुए मामले का पंचायत में देना—जब पंचों की राय में होने वाले मत-भेद के लिये हुक्म में कोई व्यवस्था न की गई हो, तो अदालत को यह हुक्म दे दिया जाना चाहिए कि पंच लोग एक सर-पंच चुन लें अथवा यह कि अधिक संख्यक लोगों की बात मान ली जावगी, या वह स्वयं कोई सर-पंच मुक़र्रर कर देगी, देखो 10 W. R. 398; 14 W. R. 150. जब अदालत ने सर-पंच के लिये कोई व्यवस्था न की हो और उन पंचों में से किसी एक शख्स के, जो मत-भेद रखता है, दरखवास्त देने पर किसी सर-पंच को नियुक्त कर दिया हो, तो वह पंचायती फैसला नाजायज़ न होगा, देखो 8 A. 64—अगर पंचों को सर-पंच मुक़र्रर करने का अधिकार दिया गया हो, तो वे उस अधिकार को अन्य किसी को नहीं दे सकेंगे, देखो 17 B. 129—केवल इस बात से, कि पंचों में होने वाले मत-भेद के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, पंचायती फैसला नाजायज़ नहीं हो जाता, जब कि उनमें किसी प्रकार का कोई मत-भेद न हो, देखो 17 W. R. 30; 8 C. L. J. 475;—जब पंचोंको यह अधिकार न दिया गया हो, कि उनका बहुमत से दिया हुआ फैसला मान्य होगा, तो केवल बहुमत से दिया हुआ फैसला नाजायज़ होगा, देखो 19 W. R. 47; 7 M. 174.

अदालत की ओर से की गई नियुक्ति—अदालत, सिवाय उन मामलों में, जो कि परिशिष्ट २ के पैरा ५ में आते हैं, पंच मुक़र्रर नहीं कर सकती, देखो 10 B. 381; 8 A. L. J. 185—पैरा ५ के अनुसार नोटिस दिये बिना अदालत पंच अथवा सर-पंच की नियुक्ति नहीं कर सकती, देखो 41 A. 578—नियुक्ति के फार्म के लिये देखो परिशिष्ट २ के ज़मीमा का फार्म ३.

पंचायत का रद्द किया जाना—मुक़द्दमें की समाप्त शुरू करने के पहिले अदालत के लिये यह आवश्यक है कि वह पैरा ५ अथवा ८ के अनुसार उस पंचायत के रद्द किये जाने के लिये हुक्म दे देवे, देखो 24 A. 315.

हस्ताक्षर करना और दाखिल करना तथा नोटिस—पंचायती फैसले के ऊपर सभी पंचोंके हस्ताक्षर होने चाहिए, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वे एक दूसरेकी उपस्थितिमें उसके ऊपर हस्ताक्षर करें, देखो 18 M. 22; 11 W. R. 433; 12 W. R. 397—फैसला अदालत में पेश कर देने के बाद उसपर हस्ताक्षर (दस्तखत) कर देने से वह फैसला नाजायज़ हो जाता है, देखो 33 C. 498; 32 M. 510;

पंचायती फैसले के अदालत में दाखिल करने की नोटिस फ़रीक़ैन को अवश्य दी जानी चाहिए। इस नियमका उल्लंघन करना भारी बेक़ायदगी समझी जायगी, देखो 11 M. 144; 20 A. 474.

फैसले के फ़ार्म की निश्चित देखो परिशिष्ट २ के ज़मीनका फ़ार्म नं० ५.

पंचायती फैसले में काट-छांट करना या फिर से विचार किये जाने के लिए उसका वापस किया जाना—सिवाय उन तीन हालतों के जिनका वर्णन पैरा १२ में किया गया है, अदालत पंचायती फैसले में कोई काट-छांट या दुबुस्ती नहीं कर सकती, देखो 243 P. R. 1916 (No. 78)—पंच लोग इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं कि वे हर एक बात के ऊपर अलग फैसला दें, जब कि पूरा मामला फैसल किया गया हो, देखो 29 C. 167 P. C.—अगर पंच लोग किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में अपना फैसला दें जो उनके फैसले के लिए पेश नहीं की गई है, तो वह फैसला नाजायज़ होगा, देखो 15 W. R. 172; 23 A. 394; 29 C. 854—जब फ़रीक़ैन कोई मामला पंचायत में पेश करते हैं तो उसके अन्दर यह शर्त छिपी रहती है कि उन कुल बातोंकी निश्चित फैसला दिया जायगा जो पेश की गई हैं। लेकिन अगर पंचों के सामने फ़रीक़ैन अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दें, तो यह शर्त नहीं रह जाती, देखो 21 C. 590 P. C.—यह रज़ामंदी कई तरहकी हो सकती है—कुल मामले का उठा लेना, कुछ आवश्यक बातों के न पेश करने के सम्बन्ध में बाहमी समझौता, फ़रीक़ैन का आपस में यह समझ लेना कि कुछ एक बातों की वजह से फैसला होना असम्भव है, या किसी बाहमी समझौतेकी निश्चित यों जान बूझ कर काम निकालने की गरज़ से ख़ामोश रहना। योंही बिना किसी विचार के गवाहों की भाँति पंचों को तलब करने की प्रथा निन्दनीय है, देखो 82 I. C. 219 (A).

एक पंचने झगड़े की बातों मेंसे सिर्फ़ एकही बात तय की और जब अदालत ने उसपर फिर विचार करने के लिए फैसला वापस किया तो उसने उसपर फिर विचार करने से इन्कार कर दिया। इस लिये अदालत ने उस मामले पर स्वयं विचार किया। तब हुआ कि उस पंच का ऐसा करना बिल्कुल ठीक था, देखो 16 C. 806.

जब फैसले का वह हिस्सा, जो किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में है जो पेश नहीं की गई है, अलग किया जा सकता हो, तो वह कुल फैसला नाजायज़ न होगा, देखो 29 C. 854 P. C.—जो बात पेश नहीं की गई है, उसके बारे में दिया गया फैसला अपने अधिकार-क्षेत्र के बाहर दिया गया (Ultra vires) फैसला है, देखो 23 A. 394.

एक मामला, जिसमें हिन्दू-लों से सम्बन्ध रखने वाला एक प्रश्न पेश था, पंचायत में पेश किया गया और पंचायत ने मुद्दे के खिलाफ अपना फैसला दे दिया जिसने इस सम्बन्ध में पंडितों की राय ली और अदालत ने अपनी राय के साथ वह फैसला वापस कर दिया। तब हुआ कि चूंकि फैसले के देखने से कोई बेज़ाहती नहीं मालूम होती है, इसलिए अदालत उसे वापस नहीं कर सकती है, और न उसे रद्द कर सकती है, देखो 2 A. 181.

फैसले का रद्द किया जाना—‘अनुचित व्यवहार’ के अर्थ के लिए देखो 9 A. 253; 7. A. 273; 3 W. R. 168.— इसमें ‘घूस वगैरा लेना’ शामिल नहीं है, देखो 30 A. 397.— और न उसमें आत्मिक अधःपतन शामिल है, बल्कि उसमें कर्तव्य का ठीक ठीक पालन न करना और अपनी जुम्मेदारियों का ठीक ठीक पूरा न करना शामिल है, देखो 9 A. 253.— अगर पांच पंचोंमें से, फैसला दिए जाने के समय सब उपस्थित न हों और न उन्होंने उसपर हस्ताक्षर किए हों, यद्यपि फैसले के ऊपर उन पांचों आदमियों के हस्ताक्षर मालूम होते हों, तो यह अनुचित व्यवहार (Mis-conduct) है, देखो 29 C. 36.— जब पंचों ने गवाहों के बयान लिए हों और उस समय कोई एक पंच उपस्थित न हो, तो यह अनुचित व्यवहार (Mis-conduct) होगा, देखो 12 M. 113; 7 A. 523; 8 W. R. 171. लेकिन किसी ऐसी बैठक में किसी पंच का अनुपस्थित होना, जिसमें कि झगड़े वाली किसी भी बात के ऊपर कोई विचार न किया गया हो, अनुचित व्यवहार (Mis-conduct) नहीं है, देखो 2 C. L. J. 61; 4 Pat. L. J. 394, 407. जो गवाह किसी फरीक ने पेश किए हैं, उनको तलब न करना अनुचित व्यवहार है, देखो 12 C. L. R. 564.— कार्यवाई में बेकायदगी करना, जिसका अर्थ यह हो कि मामले में ठीक ठीक विचार नहीं किया गया है, अनुचित व्यवहार (Mis-conduct) है, देखो 36 A. 336, 443 P. C.— बिना नोटिस या हाज़िर हो सकने का मौका दिए बिना किसी एक फरीक के हाज़िर होजाने पर बैठक कर देना अनुचित व्यवहार है, देखो 26 C. 361.— लेकिन कोई पंचायती फैसला सिर्फ इसी वजह से नाजायज़ नहीं हो जाता कि किसी फरीक को पंचायत की बैठक की सूचना नहीं दी गई थी, देखो 29 M. 44.

“या उस मियाद के खतम हो जाने के बाद दिया गया हो जो अदालत ने दी थी” शब्द पैरा १५ के क्लॉज़ (सी) में सन् १९०८ ई० के ज़ाबता दीवानी के अनुसार जोड़ दिए गए हैं और जो शरूब इसी बिना के ऊपर पंचायती फैसले को नाजायज़ समझता हो उसके लिए केवल यही उपाय शेष रह जाता है कि वह इस पैरा के अनुसार उस पंचायती फैसले को रद्द किए जाने के लिए दर-क़वास्त दे, देखो 39 C. 882. क्लॉज़ (सी) में जो ये शब्द जोड़ दिए गए हैं कि “या और किसी तरह से नाजायज़ हो” वे केवल उस कठिनाई को दूर करने के लिए जोड़े गए हैं जिसका वर्णन 25 C. 141 में किया गया है।

मियाद—कानून मियाद के आर्टि० १५८ के अनुसार, किसी फैसले को रद्द करने के लिए दीजाने वाली दरख्वास्त की मियाद उस तारीख से दस दिन है जिस तारीख को फरीकैन को फैसला अदालत में दाखिल कर दिए जाने की नोटिस मिली हो, उस तारीख से नहीं जिस तारीख को कि वह फैसला अदालत में दाखिल किया गया हो (देखो 19 A. L. J. 404; 1915 P. W. R. 30)—दस दिन खतम होने के पहिले डिकरी नहीं दी जा सकती, देखो 21 M. L. J. 444; 29 A. 584; 1921 M. W. N. 793.—परिशिष्ट २ के पैरा १० का मंशा यह है कि नोटिस अदालत में फैसला दाखिल होजाने के बाद दिया जाय।

कानून मियाद का आर्टि० १५८ उस फैसले को घापस करने के लिए दी गई दरख्वास्त के सम्बन्ध में लागू नहीं होता (देखो 1918 M. W. N. 477)—और न उसमें काट-छांट या दुरुस्ती करने के लिए दी गई दरख्वास्त में ही लागू होता है (देखो 24 M. L. J. 483)।

बिना मुकद्दमा चले मामला पंचायतमें देनेका इकरारनामा—जिन लोगों में अदालत के बाहर, पंचायत में मामला देने का लिखित इकरारनामा हो गया हो, वे अदालत को इस बात की दरख्वास्त दे सकते हैं कि वह इकरारनामा दाखिल अदालत किया जाय। लिखित प्रार्थना-पत्र (दरख्वास्त) देने पर, अदालत से उस इकरारनामा के लिखने वाले लोगों के नाम नोटिस जारी की जायगी कि वे इस बात की वजह ज़ाहिर करें कि वह इकरारनामा क्यों दाखिल अदालत न किया जाय, और अगर इसके लिए काफी वजह ज़ाहिर न की गई, तो अदालत उस मामले को पंचायत में पेश करने का हुक्म दे देगी (देखो पैरा १७)—अदालत किसी मुकद्दमों के मुलतवी किये जानेका हुक्म दे सकती है, जबकि पंचायत में मामला पेश किए जाने के लिए इकरारनामा हुआ हो (देखो पैरा १८) उस सम्बन्ध में पैरा ३ से १६ तक के वे नियम लागू होंगे जिनका सम्बन्ध इकरारनामा से है।

पैरा १७ के विस्तार के सम्बन्धमें देखो 29 C. 167 P.C. इस बातका एक आम इकरारनामा, कि आगे होने वाले तमाम झगड़ों का निपटारा पंचायत से कराया जाय, पैरा १७ में आता है। ऐसे इकरारनामा में पंचों का नाम अवश्य होना चाहिए या उसमें किसी पंच की नियुक्ति के सम्बन्ध में व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, देखो 20 B. 232.

बिना अदालतके हस्तक्षेप किये मामलेका पंचायतमें जाना—इस सम्बन्धमें पैरा २० लागू होता है। जब कोई मामला बिना अदालत के किसी हस्तक्षेप के पंचायत में दे दिया गया हो और उस पर पंचायत ने फैसला दे दिया हो, तो उससे सम्बन्ध रखने वाला कोई भी शख्स इस बात के लिए दरख्वास्त दे सकता है कि वह फैसला दाखिल अदालत किया जाय। पंचायत में दिए हुए मामले के फरीकैन को इस बात की वजह दिखलाने के लिये नोटिस दे दी जायगी कि वह फैसला क्यों न दाखिल दफ्तर किया जाय (देखो पैरा २०)—जब अदालतको

इस बात का इतमीनान होजाय कि मामला पंचायत में पेश किया गया है और उसपर पंचायत ने अपना फैसला दे दिया है, तो वह उसी के आधार पर अपना फैसला दे देगी और फिर उसी के अनुसार डिकरी दे दी जायगी (देखो पैरा २१)।

स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट (कानून दादरसी खास) नं० १ सन् १८७७ ई० की दफा २१ के नीचे लिखे ये अन्तिम शब्द किसी इकरारनामाके सम्बन्ध में, जो पंचायत में मामला देनेके लिये किया गया हो, या किसी पंचायती फैसलेके सम्बन्धमें, जिसमें परिशिष्ट २ के नियम लागू होते हैं, लागू न होंगे (देखो पैरा २२):- वे शब्द ये हैं—

“लेकिन अगर कोई शख्स, जिसने ऐसा मुआहिदा किया है और उसके अनुसार कार्य करने से इन्कार कर दिया है, किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में नालिश करता है जिसे उसने पेश करने का मुआहिदा किया है, तो ऐसे मुआहिदा के होने से नालिश दायर नहीं की जा सकती ” ।

पैरा २० (३) में आए हुए “फरीकैन” शब्दसे सिर्फ उन्हीं लोगोंसे अभिप्राय नहीं है जो वास्तव में पक्षों के सामने हाज़िर हुए हैं और न उन लोगों से जिनके ऊपर उस पंचायती फैसले का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, देखो 8 A. 340. ऐसे मामलों में नावालिग के बली का होना अत्यावश्यक है, देखो 9 B. N. C. 289—अदालत को पैरा २० के अनुसार किसी पंचायती फैसले का संशोधन करने या उसपर फिर विचार करने के लिये उसे वापस करने का अधिकार नहीं है, देखो 27 A. 526—अगर पंचायत में मामला देनेके लिये किया गया इकरार नामा गोल-मोल और अनिश्चित हो तो उस पंचायती फैसले को भ्रमल में लाए जाने की इजाज़त न दी जायगी, देखो 16 C. 482. जब किसी निजी पंचायत द्वारा दिए गए फैसले में कोई ऐसी बात तय की गई हो जो पेश नहीं की गई है, तो वह फैसला खारिज कर दिया जाना चाहिए, देखो 27 A. 526; 29 M. 303

पैरा २० के अनुसार दी गई दरख्वास्त ज़ाबता दीवानी के आर्डर २३ कल १ के अनुसार वापस ली जा सकती है, देखो 31 C. 516; 19 C. L. J. 260 और 9 A. 168.

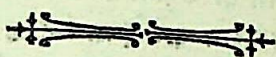
पैरा २० के अनुसार दी जाने वाली दरख्वास्त पर लगाया जाने वाला मुनासिब कोर्ट-फीस, दरख्वास्तों पर लगाया जाने वाला कोर्ट-फीस है, अर्ज़ीदावा के ऊपर लगाया जाने वाला कोर्ट-फीस नहीं है, देखो 10 C. 11; 13 C. L. R. 171 कोर्ट-फीस वही होगा जो कोर्ट-फीस ऐक्टके परिशिष्ट १के आर्टि० १ में बतलाया गया है, देखो 33 C. 11.

निजी तौर पर की गई पंचायत के फैसले को भ्रमल में लाए जाने के लिए नालिश दायर की जा सकती है, देखो 26 B. 76; 15 M. 99; 20 M. 490; 24 A. 164.

नोट—पंचायत ऐक्ट के ज़रिए से जो मामले पंचायतमें फैसल हो जायं, उन के फैसले को रद्द करने या मसूख कराने या बदलाने आदिमें वह सब या उनमें से

कोई खास बात मज़बूती के साथ साबित करना चाहिए जो ऊपर बताई गई है। नई नज़ीरें यहां तक हो गई हैं कि पंचों ने शहादत नहीं ली, तो भी फैसला मंसूख नहीं हुआ। पंचायत में मामला समझ-बूझकर पहिले ही से ले जाना चाहिए और यह सोच लेना चाहिए कि पंचायत में जो भी फैसला हो जायगा, चाहे हम जीतें या हारें, हम उसके बाद कोई अदालती कार्रवाई नहीं करेंगे तभी अपने मामले को पंचायत में ले जाना चाहिए। पंचायत में मामला फैसल कराने का भाव यही है कि अदालती कार्रवाई नहीं करना है। यह भी भाव है कि पंच लोग मामले से स्वयं वाकिफ़-कार होते हैं। इसी बुनियाद पर कुछ ऐसे मुकद्दमें भी फैसल हुए हैं कि जिनमें पंचों ने किसी पक्ष की शहादत नहीं ली सिफ़े अपनी तबियत से फैसला किया तो भी मंसूख न हुआ। इसीसे यह कहते हैं कि पंचायत समझ-बूझ कर कीजिए; पीछे कोई कार्रवाई अदालती न कीजिये, अपने काम धंधे में लगिये। पंचायत में मामला ले जाने का प्रधान उद्देश्य ही यही है कि पंचायत से फैसला हो जाने के बाद आगे अदालती कार्रवाई समाप्त हो जायगी।

गवाहोंके बयान लेना



सवालात और जिरह

Examination in chief and Cross Examination

गवाहोंके बयान किस क्रमसे लेने चाहिए और बयान लेते समय किन नियमोंका पालन करना आवश्यक है, ये सारी बातें कानून शहादतकी दफा १३५ और उसके बाद वाली दफाओंमें बतला दी गई हैं। गवाहोंके बयान लेनेका क्रम यह होना चाहिए:—

जब कोई गवाह कठघरे (Witness box) के अन्दर लाया जाय, तो सब प्रथम उसे चाहिए कि वह शपथ ले, अथवा इस बातकी प्रतिज्ञा करे, कि वह सिवाय सत्यके कोई भी झूठ बात न कहेगा। इसी को धर्मकी साक्षी देकर सच सच बयान देनेकी प्रतिज्ञा कहते हैं। हलफ (शपथ) किस प्रकार दिलाई जानी चाहिए अथवा प्रतिज्ञा किस प्रकार कराई जानी चाहिए, इस बातकी व्यवस्था इण्डियन ओथ्स बेक्ट (भारतीय कानून हलफ) न० १० सन् १८७३ ई० में की गई है।

ज्योंही गवाह शपथ (हलफ) ले चुके या सत्य भाषणकी प्रतिज्ञा कर चुके, त्योंही उस शख्सको उस गवाहके बयान लेने शुरू कर देने चाहिए जिसने उसे शहादतमें तलब कराया है। ऐसे बयानको बयान खास (Examination in Chief) अथवा प्रत्यक्ष बयान (Direct Examination) कहते हैं। इसके पश्चात् विरोधी पक्षको उस पर जिरह करने (Cross Examination) का अधिकार है। अन्तमें उस पार्टीकी ओरसे उसके बयान फिर लिए जा सकते हैं जिसने तलब कराया है।

भारतीय कानून शहादत (Indian Evidence Act) का यह काम नहीं है कि वह उन व्यवहार्य प्रयोगोंकी भी व्यवस्था करे जो अनुभवसे जाने जाते हैं जिससे वकालत पेशा महाशयोंको गवाहोंके बयान लेनेमें सहायता मिल सके। उसमें केवल थोड़ेसे साधारण नियम दे दिए गए हैं जिन्हें इंग्लिश-लॉमें भली भाँति सिख किया गया है, अर्थात् यह कि गवाहोंके बयान लेनेका क्रम क्या होना चाहिये और ऐसे अवसरोंपर कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए इत्यादि। गवाहों से ऐसे प्रश्न पूछनेका कौशल, जिनका कुछ अर्थ हो, जैसाकि मि० व्यस्टने कहा है, “यह तो स्वभाविक बुद्धि के चमत्कार का परिणाम है या बहुत बड़े अनुभव के पश्चात् प्राप्त होता है” केवल नियमों को पढ़ लेने से ही कोई व्यक्ति इस कौशल कला का पूर्ण ज्ञाता नहीं होजाता। स्वयं अपने अनुभव से तथा इस कला के मर्मज्ञों के परामर्शसे इस कला में पूंज-प्रवीणता प्राप्त की जा सकती है जिसका जानना प्रत्येक वकील के लिये परमावश्यक है। यद्यपि इस कला की जानकारी के लिये

कोई सरल और सीधा मार्ग नहीं है, यद्यपि जिरह करने सम्बन्धी कार्य में वचों के अनुभव के पश्चात् सफलता प्राप्त हो सकती है, तो भी इस बयान लेने के नियमों, उसके उद्देश्यों और प्रयोगों का वर्णन कर देना, जिरह करने में प्रयोग किये जाने वाले तरीकों का वर्णन कर देना, और कुछ अनुभूत प्रयोगों का चतला देना इस पेशे के युवक और उत्साही कार्यकर्ताओं के लिये परम उपयोगी सिद्ध होगा। इसी उद्देश्य से ये कतिपय पंक्तियां पाठकों की सेवा में भेंट की जाती हैं। इस विषय का प्रति पादन करने में कानून शहादत के नियमों का विशेष ध्यान रखा गया है।

बयान लेने का क्रम—बयान लेने के क्रमकी व्यवस्था दीवानी और फौजदारी सम्बन्धी कानून और उसके प्रयोग द्वारा की जायगी और अगर ऐसा कोई कानून अथवा नियम नहीं है तो इसकी व्यवस्था अदालत करेगी (कानून शहादत की दफा १३५), देखो ज़ाबता दीवानी का आर्डर १८।

यद्यपि यह बात वकील की इच्छापर निर्भर करती है कि किस क्रम से वह गवाहों के बयान ले, तो भी अदालत को दफा १३५ के अनुसार इस बात का पूर्ण अधिकार रहता है कि किस क्रम से गवाहों के बयान लिए जाय, देखो 39 C. 245. इस सम्बन्ध में वकीलों को अपनी इच्छा का प्रयोग करने में अदालतें प्रायः बहुत कम हस्तक्षेप करती हैं, देखो 5 C. W. N. 15.

गवाहों को अदालत के बाहर चले जानेका हुक्म—ज़ाबता दीवानी अथवा कानून शहादत में गवाहों को अदालत से बाहर चले जाने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में किन्हीं विशेष नियमों की व्यवस्था नहीं की गई है, और इस सम्बन्ध में साधारणतया इंग्लैण्ड की अदालतों में प्रचलित प्रणाली का अनुकरण किया जाता है। अदालत को यह अधिकार है कि वह उस शख्स को छोड़ कर जिसके कि बयान लिये जा रहे हैं, बाकी सब गवाहों को अदालत से बाहर चले जाने का हुक्म दे देवे उस हुक्म में ऐसा गवाह जो उस मुकद्दमें में फरीफ़ है, और उसका वकील तथा विज्ञान सम्बन्धी शहादत देने वाला गवाह शामिल नहीं है। इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाला गवाह अदालतका अपमान करने का अपराधी समझा जायगा।

बयान खास—यह वह बयान है जो उस शख्सकी ओरसे लिया जाय जिसने उसे तलब कराया है (देखो कानून शहादत की दफा १३७)— इस बयान लेने का उद्देश्य यह होता है कि उस शख्स से वे तमाम बातें या उसमें की कुछ ज़रूरी ज़रूरी बातें मालूम करली जाय, जो वह उस शख्सके मुकद्दमें के बारेमें जानता है जिसने उसे तलब किया है। यह बयान खास मुकद्दमें से सम्बन्ध रखने वाली बातों की निश्चित होना चाहिये (देखो दफा १३८, कानून शहादत)—मुकद्दमें में पैदा होने वाले सवालों को ध्यान में रखना चाहिये और सिर्फ़ मुकद्दमें से सम्बन्ध रखने वाली बातों के ही सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाने चाहिये। कानून की बातें नहीं पूछनी चाहिये और न उन बातोंके बारेमें गवाहकी राय पूछनी चाहिये जो कि उसने देखी या सुनी हो। वह सिर्फ़ उन्हीं बातों के सम्बन्ध में अपना बयान देने आया है जिसको वह जानता है। सुनी हुई बातोंकी शहादत क़ाबिल तस्लीम नहीं है प्रत्येक

बवाल किसी न किसी उद्देश्य से ही तैयार किया जाना चाहिये। बहुधा लोग समझा करते हैं कि किसी गवाहके बयान लेना (To Examine him in chief) बहुत आसान है। परन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं है। मुकदमोंका सारा दारमदार इसी बयान ख़ास के ही ऊपर है, और इस लिये बयान लेने के लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि वह उस मुकदमों के सम्बन्ध में सारी बातें जान ले, बल्कि उसके लिये इस बात की भी आवश्यकता है कि वह उन बातों को भी जान ले जिन्हें गवाह अपने बयान में कहेगा, तथा उस गवाह के स्वभाव और चरित्र तथा उसकी योगता का भी परिचय प्राप्त कर ले। यह बात निहायत ज़रूरी है कि वकील, गवाहों के पहिले से बयान लेकर या जांच करके यह तय करले, कि कौनसा गवाह क्या बात अपने बयानमें कहेगा। इस बात की अभिलाषा, कि सभी ज़रूरी ज़रूरी बातें सभी गवाह बयान कर दें, प्रायः अनवाञ्छित परिणाम उत्पन्न कर देती है और गवाहोंको बड़ी परेशानी में डाल देती है। गवाह कहांपर नियम विरुद्ध बातचीत करने लगता है और कहांपर वह अनापशानाप बक जाता है, इस बातका ध्यान रखना निहायत ज़रूरी है और ख़वालात इस ढंगसे तैयार करने चाहिये कि वे सभी गवाहोंके अनुकूल हों। डरपोक गवाहों, मूर्ख गवाहों और ज्यादा बात करने वाले (बक्की) गवाहोंके बड़ी होशियारी से और भिन्न भिन्न ढंग से इज़हार लेने चाहिये।

यह काम वकील का है, कि वह अपने मुवक्किल के मामले के समर्थन में हर एक ऐसी बात को, जिसके सम्बन्ध में गवाह अपना इज़हार दे सके, एक ठीक और ऐतिहासिक क्रमानुसार तैयार कर रखे। यह काम जैसा आरम्भ में देखने से मालूम होता है, उससे कहीं अधिक कठिन है। जो गवाह डरपोक है उसे उत्साहित करने की ज़रूरत है, जो अधिक बातें करने वाला (बक्की) है उसे दबाये रखना और जो बहुत अधिक पक्ष-पात करने वाला हो उसे रोक रखना चाहिये। तथापि वकील को यह नहीं बतलाना चाहिये कि गवाह अपने इज़हार में क्या कहे। किन्तु जो गवाह ईमानदार और सच्चा है, उसे अपने ही ढंग से अपना बयान देनेकी स्वतंत्रता दे देनी चाहिये और जहां तक कम हो सके वहां तक कम दखल वकील को उसके सम्बन्धमें देना चाहिये सिर्फ़ क्रमवद्ध कर देना योग्य है।

जहां तक सम्भव हो गवाह को अपने ही ढंग से अपनी कथा कहने देना चाहिए और ख़वालात तैयार करते समय, और मामले के समय घटना के क्रमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर गवाह बुद्धिमान नहीं है अथवा आवश्यकता से भी अधिक भौरू है, तो उसको अपने ही ढंग से अपना इज़हार देते रहने की स्वतंत्रता न दे दी जानी चाहिए। सम्भव है वह कोई ऐसी बातें बकने लगे जो बिल्कुल निरर्थक हैं और इसलिए ज्यादा अच्छा तो यह हो कि आरम्भ में उससे ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाय जो उसके लिए कुछ सहायक सिद्ध हों। मामलेके सम्बन्धमें बहुत कुछ जानते हुए भी यह सम्भव है कि वह गवाह अगर अपने ही भरोसे छोड़ दिया जाय तो, साफ़ साफ़ और शृंखलाबद्ध बयान न दे सके। अतएव चिन्ता किसी तरह की ऐसी मदद पड़ुंचाय जिससे उसे मुकदमों का समर्थन करने वाली

ही बातें कहने में सुविधा हो और सिवाय उनके और कोई भी बात वह न कहे उससे सारी बातें मालूम कर लेनी चाहिये। यह बात अधिकांश में उससे पूछे गए सवालों, ढंग, और उनके पूछने के ढंग, पर निर्भर करती है।

गवाह के बयान लेते समय ऐसे सवाल कभी भी न पूछने चाहिए जो उसे पथ-प्रदर्शन का काम करते हों अथवा जिनके सम्बन्ध में इस बातका सन्देह हो कि वे पथ-प्रदर्शनका काम करते हैं (देखो कानून शहादतकी दफा १४१ और १४२)—अगर सवाल इस ढंग से तैयार किया गया हो जिससे वही जवाब निकलता हो जो कि सवाल करने वाला चाहता है, तो यह उस गवाह को सचेत करना है जो, वास्तव में, वकील का काम नहीं है। ऐसा करने का चतुरतापूर्ण ढंग यह है कि सवाल में दो ऐसी बातें रखी जाय जिनको सुनते ही गवाह इसे से यह बात समझ जाय कि इनमेंसे कौन सी बात सुझे कहनी चाहिए, उदाहरणार्थ "उस समय महेश मौजूद था या नहीं ? ठीक सवाल तो यह है कि, उस समय कौन कौन मौजूद था ?"

जब किसी गवाह के उस दस्तावेज़ के मज़मून की निस्वत बयान लेने हों जो उसने लिखा है, तो उसे इस बात की इजाज़त दी जानी चाहिए कि वह अपना इज़हार देते समय उस दस्तावेज़ को अपने सामने रखे (देखो कानून शहादत की दफा १५९)—जो सवालात आवश्यक बातों के सम्बन्ध में दी गई शहादत का पुष्टीकरण करनेके लिए पूछे गए हों, वे काबिल तस्लीम हैं (देखो कानून शहादत की दफा १५६)—जब कोई ऐसा बयान जो दफा ३२ और ३३ के अनुसार ठीक है, साबित हो जाय, तो उसका खण्डन करने अथवा उसका पुष्टीकरण करने की गरज़ से, या जिस शख्स की ओर से वह बयान दिया गया है, उसके विश्वासपात्र होने का समर्थन करने या उसका विरोध करने की गरज़ से सारी बातें साबित कर दी जानी चाहिए, जो बातें उस समय साबित की जातीं जिस समय वह शख्स बतौर गवाह के तलब किया गया होता (देखो कानून शहादत की दफा १५८)—अगर किसी गवाह के आचरण आदि के सम्बन्ध में पहिले सुबूत हो गया है तो बाद में उसके आचरण आदि का समर्थन करने के लिए उसके सम्बन्ध में सुबूत दिया जा सकता है (देखो कानून शहादत की दफा १५७)—जब किसी मामले की शहादत में पेश किए जाने वाले कागज़ात बहुत से हों तो गवाह उन सबका भावार्थ बतला सकता है।

ऐसे सवालों के लिए, जिनमें उन बातों को साबित की गई मान लिया गया है जो कि साबित नहीं की गई हैं अथवा यह कि वे उत्तर दिए गए हैं जो वास्तव में दिए नहीं गए हैं। किसी भी समय इजाज़त न दी जायगी। किसी फ़रीक़ी, उसके ख़राब चाल-चलन का होने के सम्बन्ध में शहादत देकर, अपने ही गवाह के विश्वास पात्र होने के बारे में अथवा उसके सच्चे होने के सम्बन्धमें कुछ कहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर गवाह उसके खिलाफ़ होनाय और कोई ऐसी बात कर उठावे जिसका उसे स्वप्न में सन्देह न हो, तो अदालतकी

इजाजत लेकर वह उसके ऊपर झूठे होने का अभियोग चला सकता है (देखो दफा १५५) ।

बयान लेने के सम्बन्ध में पॉल ब्राउन के बनाए हुए नियम— मि० पाल ब्राउन अमेरिका के एक प्रसिद्ध वकील हैं । अपने गवाहों के बयान (इज़हार) लेने के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाए हैं, जिनको बड़े बड़े विद्वानों ने भी बहुत ही उपयोगी माना है । वे नियम इस प्रकार हैं :—

१ अगर गवाह अधिक दबंग हैं, और इस बात की आशंका है कि वे अपनी वचलता अथवा ठिठाई से आपके मामले को तुकसान पहुंचा दें तो आप उनके प्रति कुछ गंभीर एवं धीर बने रहें, जिससे वे सीमा के बाहर जाने में संकुचाते रहें ।

२ अगर वे भयभीत हैं अथवा उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अर्थात् उनकी बुद्धि संशयात्मक है, और उनके विचार विच्छिन्न हैं, तो आपको चाहिये कि आप पहिले उनसे ऐसी बातें पूछना आरम्भ करें जिन्हें वे भली प्रकार जानते हैं और जिनमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है और जिनका असली मामले से कोई निकट सम्बन्ध नहीं है, जैसे:—

तुम कहां रहते हो ?

क्या तुम फ्रीकैन (सुद्धई और मुद्दाअलेह) को जानते हो ?

तुम इनको कितने दिनों से जानते हो ? इत्यादि ।

जब आप देख लें कि उनका भय दूर हो गया और अब उनके दोश हवास ठीक हैं, तो आप उससे उस मामले के सम्बन्ध में और अधिक आवश्यक बातों का पूछना आरम्भ करें । पर इस बात का ध्यान रहे कि आप उससे जो भी बात पूछें बड़े ही धीरज के साथ और स्पष्ट भाषा में पूछें, नहीं तो सम्भव है कि आप उसके मास्तिष्क में फिर गड़-बड़ी उत्पन्न कर दें जो उन सारी बातों का उद्गम है ।

३ अगर आपके गवाहों की शहादत आप के अनुकूल हो, जिसकी बड़ी सार्वधानी के साथ रक्षा की जानी चाहिये तो आप कभी भी गंभीरता का त्याग न करें क्योंकि बहुत से लोग प्रायः इज़हार की अच्छाई और झूराई का पता विशेष-तया यह देखकर लगाया करते हैं कि उसका प्रभाव हाकिम या वकील के ऊपर कैसा पड़ा ।

४ अगर आप देखें कि गवाह के दिमाग में आपके मवकिल के विरुद्ध बहुत सी बातें भर गई हैं, तो जब तक कि कोई ऐसी बातें न हों जो आपके मवकिल के लिये उपयोगी हैं, और जिनको अकेला वही गवाह बतला सकता है, आप उससे बहुत कम आशा रखें; ऐसी दशा में या तो आप उसे तलब ही न कराएं या जितनी जल्दी हो सके उससे अपना पीछा छुड़ाएं । अगर विरोधी पक्ष का वकील उस बात को देख लेगा जिसका डल्लेख मैंने किया है, तो वह आपका मामला चौपटकर देने के लिये उसको प्रयोगमें ला सकता है । अदालतों में होने वाली

मात्रमें, सारी सम्भव बुराईयोंमें, जो सबसे खराब और सबसे अधिक कष्ट के साथ रोकी जा सकने वाली बुराई हैं वह मित्र के भेष में शत्रु का होना है। न आप उस पर अभियोग चला सकते हैं, न आप उसपर जिरह कर सकते हैं; न आप उसे दबा सकते हैं और न आप उसपर प्रत्यक्ष रूप में आक्रमण ही कर सकते हैं; और यदि आप केवल उसी उपाय से काम लेते हैं जो चाकी रह जाता है और उसके स्पष्टीकरण के लिये दूसरे गवाहों को तलब करते हैं, तो आप को स्मरण रखना चाहिये कि शत्रुसे लड़ाई करने के बदले आपही की सेना के मित्र २ दलोंमें लड़ाई छिड़ जायगी और सम्भवतः आपके भी दल में वही व्याधि उठ खड़ी होगी। इस लिये जहां तक हो सके इससे दूर रहने की ही कोशिश करें।

५ आप कभी भी किसी ऐसे गवाह को न तलब करें जिसे तलब करने के लिये आपका विपक्षी बाध्य हो जाय। इससे आपको उसपर जिरह करने का मौका मिलेगा। इसलिये आप अपने विपक्षों से प्राप्त होने वाले उस मौके को हाथ से न जाने दें, और उसके साथ साथ, यही नहीं कि जो कुछ बात उस गवाह ने उसके प्रतिकूल कही है, उसका उस शत्रुस के विरुद्ध दोहरा प्रयोग ही करें जिसकी ओर से यह तलब किया गया है, बल्कि उसकी वह शक्ति भी नष्ट कर दें जो उस इज्जतार के असर को बदल देने वाली हो।

६ बिना किसी उद्देश्य के और बिना इस बात के सामर्थ्य के, कि, अगर किसी प्रश्न (सवाल) को असंगत (अनुचित) बतलाकर किसी प्रश्न के ऊपर आपत्ति की जाय तो, उसका सम्बंध उस उद्देश्य से न दिखला सकें तो कभी भी कोई प्रश्न ऐसा न पूछें।

७ ध्यान रहे कि आप अपना प्रश्न इस तरह पर न रखें कि, अगर उसके बेजाबता होने के कारण उसका विरोध किया गया तो, आप उसको कायम न रख सकें, या, कमसे कम उसके समर्थनमें जोरदारसे जोरदार कारण न दिखला सकें। शहादत सम्बन्धी प्रश्नोंके वाद-विवाद में प्रायः असफल होजाने से खुरीकी निगाहमें आपके मामलेकी मजबूतीको बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा, और उस मुकाममें अन्तिम परिणामके सम्बन्धमें आपकी आशाओंको बहुत बड़ी क्षति पहुँचेगी।

८ कभी भी आप अपने विरोधी के द्वारा पूछे गए प्रश्न के सम्बन्ध में कोई एतराज़ न करें, जब तक कि आप उस एतराज़ का जोरदार शब्दों में समर्थन करने के लिए तैयार और समर्थ न हों। बार-बार एतराज़ात पेश करने आपस कर लेने से इससे अधिक भयंकर कोई भी बात नहीं हो सकती; इससे यह प्रकट होता है कि या तो वे भली भाँति सोच विचार कर नहीं किए जाते हैं या उनको अच्छी तरह से पेश करने में जिस बुद्धि और नैतिक साहसकी आवश्यकता है उसका आप में अभाव है।

९ आप अपने गवाह से जो कुछ पूछें वह स्पष्ट और साफ भाषा में पूछें, मानों आप सतर्कता के साथ ऐसे काम में लगे हुए हैं जिससे आपको खुल दिखचस्पी है, और उसे भी ऐसा करें कि वह आपके प्रश्नों का ठीक ठीक और

एव उत्तर दे। इस बात का अनुमान कैसे किया जा सकता है कि अदालत और जूरी सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, जब वकील और गवाह में इस विषय में झगड़ा मचा हो।

१० आप, समय समय के अनुसार अपनी आवाज़ को घटाते बढ़ाते रहें "भीरु स्वभाव वाले (डरपोंकों को) प्रोत्साहन देते रहें और उद्वण्ड पुरुष का दमन करते रहें।"

११ जब तक आप पूरे तौर पर तैयार न हो जायं तब तक कार्यारम्भ न करें और जब अपनी बात ख़तम कर चुकें तो वहीं पर उसका अन्त कर दें। दूसरे शब्दों में, कभी भी प्रश्न करने के अभिप्राय से प्रश्न न करें, बल्कि उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए ही प्रश्न करें।

काक्सका मत-मि-काक्सने अपनी "पेडवोकेट-हिज़ ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, राइड्स ऐण्ड व्हीज़" नामक पुस्तक में बयान लेने के सम्बन्ध में निम्नांकित बातें लिखी हैं:—

'बयान लेते समय आपका ढंग उससे बिल्कुल भिन्न होना चाहिए जो जिरह करने के समय होता है। आप अपने ही गवाह का इज़हार दिला रहे हैं जिसे आप अपना हितु समझते हैं जब तक कि आपको इसके विरुद्ध कोई बात मालूम न हो जाय। अगर वह भीरु स्वभाव का (डरपोंक) आदमी है, तो आप उसको उत्साहित करें और मित्रता पूर्ण बातों और अवलोकन से उसमें विश्वास उत्पन्न करायें। प्रायः ऐसा होता है कि गवाह, न्यायालयों में जाने के अभ्यस्त न होने के कारण, अपनी इस अभूत पूर्व अवस्था को देखकर ऐसे विस्मित हो जाते हैं कि घबराहट में पहिले पहल वे अपने पक्ष वालों और विरोधी पक्षवाले वकीलों में ही पहिचान नहीं कर पाते और जब वे अपने आपको अदालत के कठघरे के अन्दर सिक्कड़ कर खड़े देखते हैं तो अवाक हो जाते हैं और जब उनका वकील कोई प्रश्न करता है तो आपको वे अपना शत्रु समझने लगते हैं क्योंकि उनको वकीलों से बहुत कम बात करने और मिलने का मौका मिलता है। ऐसे समय पर ही आपको अपने गवाह को ठीक रखने का ध्यान रखना चाहिये और अगर कभी कभी प्रेम पूर्वक कुछ मृदु-वाक्य से आप उसे उत्साहित कर दिया करें, तो इसमें बहुत शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है। आप ऐसा कभी भी प्रदर्शित न करें, कि आप उसकी हैरानी और घबराहट को समझ रहे हैं। क्योंकि इससे वह और भी अधिक बढ़ती है, किन्तु जहां तक हो सके प्रेम मय अवलोकन से, प्रेमपूर्वक बात करके और ऐसे शब्दों से, उसकी उस घबराहट को दूर का दें जो उसे निरुत्साह करने वाले न हों, बल्कि ऐसे हों जैसे सभी साथी लोग किसी कथा (कहानी) के कहने के लिए प्रेम पूर्वक आग्रह करते हैं जिसके सुनने के लिए वे लोग उत्सुक हैं और जिसके कहने के लिए भी दूसरा राजी है। इस तरह पर जो गवाह अत्यधिक घबरा गया है उसे बिना उसके जाने ही ऐसी बात को बयान करने के लिए खींच लाना चाहिए जिसे वह कठघरे (Witnessbox) पर आने के समय घबराहट में कहने को भूल गया था।

“बयान लेते समय आप जो प्रश्न पूछें वे बड़ी होशियारी के साथ तैयार और खूब सोच-समझ कर पूछे जाने चाहिए। आपको इसमें कभी भी उस ढंग से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है जिस ढंग से जिरह करने में कार्य किया जाता है। आपको चाहिए कि पूछने के पहिले प्रत्येक प्रश्न (सवाल) के ऊपर अच्छी तरह से मनन कर लें ताकि वह इस प्रकार तैयार किया जा सके कि उसके उत्तर में केवल उतनी ही बात मिल जाय जितनी की आवश्यकता है, अधिक नहीं। अगर आप इसनी जल्दी विचार कर सकते हैं जितना कि एक वकील को चाहिए, तो आपको इसके लिए उस समय भी वक्त मिल सकता है जिस समय जज पहिले सवाल के जवाब को लिख रहा हो; लेकिन अगर इतना भी समय आपके काम के लिए काफी न हो तो आपको थोड़ी देर विचार करने के लिए समय जज से ले लेना चाहिए। जन अदालत को यह मालूम हो जायगा कि आपने बिलम्ब करके उसका कुछ काम कम कर दिया है, जिससे आपको ठीक ठीक शहादत लेने का मौका मिल गया है, तो वह फिर आपके इस प्रकार बिलम्ब करने से अधीर न होगी।

“कभी कभी इस बात का निश्चय करने के लिए कि, गवाह को अपने ढंग से बयान करने देना चाहिए या प्रश्नों द्वारा उससे ये बातें पूछनी चाहिए, बहुत बड़े विचार की आवश्यकता है। इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया जा सकता, यह सब उस समय आपकी खोजपर निर्भर करता है। बहुत से ऐसे दिमाग वाले लोग भी होते हैं जो किसी बात को, उससे सम्बन्ध रखने वाली बातों का स्मरण करके स्मरण कर लेते हैं, चाहे वे कितनी ही असंगत क्यों न हों। वही सारे बयानात दोहरा जाता है और असली बात के ऊपर पहुँचने में छोटी सी छोटी बात को ढूँढ़ निकालता है।”

“ऐसे लोगों के साथ और कोई उपाय नहीं चल सकता है, सिवाय इसके कि उसको अपने ही ढंगसे चलते रहने दिया जाय। विचित्र ढंगसे बने हुए मस्तिष्क की ऐसी ही दशा होती है और अगर आप उसके विचार प्रवाहमें किंचित भी हस्तक्षेप करेंगे तो उस गवाहकी विचार-शृंखला उलझ जायगी और फिर आपको अपने असली उद्देश्य पर पहुँचने में बड़ी कठिनाई पड़ जायगी। लेकिन अगर आपको ऐसे गवाहों से काम पड़े, यद्यपि ऐसे लोगों की संख्या प्रायः बहुत कम होती है जिनके विचार शृंखला-बद्ध नहीं होते, जो घटनाक्रम का त्रिलकुल ध्यान ही नहीं रखते, जिनको समय, स्थान और व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, तो आप उसी दशा में अपने मतलब की बातें उससे पूछ सकते हैं जब कि आप उससे सिर्फ इतनाही करने के लिए कह दें कि वह आपके प्रश्नों का उत्तर देता जाय और उन्हीं की तरह उनसे प्रश्न करना आरम्भ कर दें जिनका एक दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध न हो और इस तरह पर उनसे सारी बातें पूछ कर अन्त में उनको एक क्रम में कर लें जिससे वह क्रम बद्ध होकर एक अच्छा खासा उपयोगी बयान बन जाय।”

“ऐसे उपाय ऐसे गवाहों के सम्बन्ध में उसी समय उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, जब आप उनसे क्रमबद्ध बयान प्राप्त करनेकी आशा छोड़ दें। वास्तवमें इसके लिए बहुत बड़ी क्षमता और सुस्तैदी की ज़रूरत है। परन्तु हमारी ऐसी धारणा है कि जब तक आपमें ये गुण विद्यमान नहीं तब तक आपको वकील बननेकी अभिलाषा भी न करनी चाहिए। वकील हर शख्स नहीं बन सकता, मस्तिष्क की प्राकृतिक बनावट जब ऐसी होती है तभी वकील के पद का पूर्ण कार्य उससे हो सकता है। जो बात प्रतिपक्षी के किसी कागज़ या बयान से साबित हो चुकी हो उस बातपर न तो कोई शहादत दे और न अपनी शहादत से वह बात कभी पूछे।

बयानमें पूछी जाने वाली बातें

(१) प्रासंगिक बातें—बयान खास सिर्फ़ उन्हीं बातों के सम्बन्ध में लिया जाता चाहिए जिनकी बाबत झगड़ा है या जो झगड़े की बातों से सम्बन्ध रखती हैं। वे तमाम बातें झगड़े के प्रसंग की बातें समझी जायगी जिनसे उन बातों के सम्बन्ध में, जिनकी निश्चित कुछ दरयाफ़्त करना है या जिनकी निश्चित झगड़ा है, कोई ठीक ठीक अनुमान किया जा सके। ‘प्रासंगिक बातों’ और उन बातोंके जिनकी निश्चित कुछ पूछा जाना है,” अर्थ के सम्बन्ध में देखो कानून शहादतकी दफ़ा ५। कानून शहादतमें ‘प्रासंगिक’ बातोंका अर्थ है, वे बातें जो मान्य (काबिल तल्लीम) हैं। कानून शहादतकी दफ़ा ५ से ५५ तकमें तमाम तरीके बतलाए गए हैं जिनसे एक बात दूसरी बात से इस प्रकार मिलाई जा सके कि वह ‘प्रासंगिक’ बन जाय।

जो बातें बयान की जायं वे ऐसी होनी चाहिए जिनको गवाह स्वयं जानता हो, ऐसी नहीं, जिन्हें उसने किसी दूसरे आदमी से सुन लिया है। सुनी हुई बात वह है जो किसी अन्य व्यक्ति से मालूम हुई हो। इस सम्बन्ध में सुनी हुई बातों के कुछ अपवाद (मुस्तसिनयात) भी हैं, जैसे इकबाल, हकीयत के खिलाफ़ पलात, व्यापार के दौरान में कही गई बातें, सरकारी कागज़ातमें कही गई बातें, इत्यादि (देखो कानून शहादत की दफ़ा १७, ३२, ३५, ३६, ३७ इत्यादि)। जो बयान ज़बानी दिया जाय वह सीधा और साफ़ होना चाहिए (देखो कानून शहादत की दफ़ा ६०)—जो खवालात पूछे जायं वे घटना (वाक़यात) के सम्बन्ध में ही होने चाहिए, कानून के सम्बन्धमें नहीं (देखो कानून शहादतकी दफ़ा ३)—किसी बात के सम्बन्ध में गवाह की राय, उसका विश्वास और उससे वह क्या नतीजा निकालता है, ये बातें नहीं पूछी जानी चाहिए जब तक वे कानून शहादत की दफ़ा ४५-५१ में न आती हों—भंशा या इरादा के मुसूत के सम्बन्ध में देखो कानून शहादत की दफ़ा ८, १४ और १५—गवाहों को यह अधिकार नहीं है कि वे नैतिक अथवा कानूनी बन्धनों के सम्बन्ध में कायम की हुई अपनी राय का इज़हार कर सकें या इस सम्बन्ध में, कि असुक व्यक्ति पर असुक प्रकार से प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी, यदि फ़रीक़ैन ने असुक बात की होती। सारांश यह कि, किसी गवाह से, विज्ञान सम्बन्धी विषयों को छोड़,

किसी विषय के सम्बन्ध में उसकी राय नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि यह काम जूरी का है, जैसे:—

क्या अमुक ड्राइवर सावधानी से काम करता है ?

क्या अमुक सड़क पर चलने में खतरा है ?

क्या अमुक हमला या कत्ल उचित है ?

और न उससे यही पूछा जा सकता है कि—क्या अमुक मुआहिदे के अन्दरजो ऐसा वाक्या आ गया है जिससे व्यापार में रुकावट डाल दी गई है, वह उचित है अथवा अनुचित ?

क्योंकि यह सवाल जज के तय करने का है (देखो मि० टेलर के कानून शहादतकी दफा १४१४-१४२१),

(२) जवाब की ओर संकेत करने वाले प्रश्न—बयान खास में साधारणतया ऐसे प्रश्नों के पूछने की आज्ञा नहीं है। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कड़ा नियम नहीं बनाया गया है। इसके बारे में अदालतों को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। इस कूल का जो अपवाद (सुस्तस्नियात) है, वह कानून मियाद की दफा १४१ और १४२ में मौजूद है।

(३) स्वयं अपने गवाह पर दोषारोपण करना—आमतौर पर किसी फ्रीक को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह अपने ही गवाह के ऊपर विश्वास-पात्र न होने का दोषारोपण कर सके, परन्तु कुछ अवस्थाओं में अदालत की आज्ञा लेकर ऐसा किया जा सकता है (देखो कानून शहादत की दफा १५५)

जिरह (Cross-examination)

जिरह—किसी गवाह पर जिरह वह फ्रीक कर सकता है जो उस पक्षका विरोधी है जिसकी ओर से वह गवाह तलब किया गया है (देखो कानून शहादत की दफा १३७)—जिरह करने का उद्देश्य

(१) जो शहादत दी गई है उसकी छान-बीन (परीक्षा) करना और जिन बातों का निश्चित झगड़ा है उनके सम्बन्ध में दी गई शहादतका बल घटाना अथवा उसे अविश्वसनीय सिद्ध करना या नष्ट कर देना;

(२) गवाह के दिए हुए उत्तर (जवाब) से अपने मतलब की बातों का निकाल लेना;

(३) गवाह की साख पर धब्बा लगाकर यह दिखला देना कि वह विश्वास के योग्य नहीं है; और

(४) अपने विरोधी के गवाह की सहायता से अपने मामले को जोरदार बना देना है।

वकील के हाथ में, सत्य को खोज निकालने और असत्य को अलग कर देने के लिए, यह एक बहुत बड़ा शक्तिशाली अस्त्र है, यदि इस जिरह (Cross-examination) का बुद्धिमान और कुशलता के साथ प्रयोग किया जाय।

मीर सुजादअली बनाम काशीनाथ (देखो 6 W. R. 181 pp. 182-183) के मामले में जस्टिस नारमन ने कहा था:—

“जिरह, का मुख्य सार यह है कि, यह एक फरीक के वकील द्वारा अपने विरोधी दूसरे फरीक की ओर से तलब किए हुए किसी गवाह से प्रश्न करना है जिसका उद्देश्य उससे ऐसी बात कहलाना जिनसे अपना पक्ष जोरदार होता है अथवा उस गवाह को अप्रमाणिक सिद्ध करना है। असत्य से सत्य को अलग करने के लिए जितने उपाय काम में लाए जायं उनमें जिरह सब से अधिक प्रभा-
वोत्पादक है। हम समझते हैं कि यहां पर यह अप्रासंगिक न होगा कि जिरह के सम्बन्ध में लिखा हुआ मि० किंवटिशियन का वह वाक्य उद्धृत कर दिया जाय जिसका उल्लेख और उद्धरण मि० ब्यस्ट ने अपने कानून शहादत के ग्यारहवें संस्करण (अंग्रेजी) की दफा ६५३ में और मि० टेलरने इसी विषयपर लिखी गई अपनी पुस्तक के दसवें संस्करण (अंग्रेजी) के पृष्ठ १०३२-३३ में किया है। आपका कहना है कि—“किसी ऐसे गवाह से, जिसे अपनी इच्छा के विरुद्ध सत्य बोलने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता है, साबिका पढ़ने पर सफलता की सब से बड़ी कुञ्जी यह है कि उससे वह बात कहला ली जाय जिसे वह छिपाना चाहता है। यह केवल उसी समय हो सकता है जब प्रश्नों को विस्तार के साथ बार-बार पूछा जाय। वह गवाह ऐसे ही उत्तर देगा जिनसे वह समझेगा कि उसके पक्षको कोई हानि नहीं पहुंचती है; और बाद में बहुत सी ऐसी बातों से, जो उसने स्वीकार करली होतीं, वह ऐसी संकुचित अवस्था में डाल दिया जा सकता है कि जिन बातों को कहेगा नहीं, उन बातोंसे वह इन्कार नहीं कर सकता। क्योंकि जैसा वक्तुताओं आदि में देखा जाता है, हम सामान्यतया इधर उधर से लाकर सुवत इकट्ठा करते हैं, जिनमें का अकेला एक अभियुक्त के विरुद्ध कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता, परन्तु जब वे सब एक साथ शामिल कर दिए जाते हैं तो अभि-
युक्त के ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है, इसी प्रकार इस तरह के गवाह से भी बहुत सी ऐसी ही बातें पूछनी चाहिए जैसे:—

पहिले क्या हुआ ?

बाद में क्या हुआ ?

कौनसी घटना किस समय पर, कहां पर और किस आदमी द्वारा हुई ?

तथा इसी तरहकी दूसरी और बातें, जिससे अकस्मात उसकी ज़बानसे ऐसी कोई बात निकल जाय जिससे, उसके लिये या तो उस बातक स्वीकार कर लेना अनिवार्य हो जायगा जिसके निस्वत यह चाहा जाता है कि वह स्वीकार कर ले या वह अपने पहिले दिए हुए बयानोंका खण्डन कर बैठेगा। अगर ऐसा न हो सके, तो यह स्पष्ट होजायगा कि वह कुछ बोलेगा नहीं, या उसपर किसी ऐसी झूठी बात

कै कहने का दोषारोपण करके उसे नीचा दिखाया जा सकता है जिसका उसके मामले से बिस्कुल कोई सम्बन्ध नहीं है; या घुमा फिरा कर उससे ऐसी बातें कहला दीजायं जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिससे जज को उसके सम्बन्ध में सन्देह होने लगे जिसके कारण उसके मामले को कम से कम उतनी ही क्षति पहुँचेगी जितनी उस समय पहुँची होती, अगर उसने अभियुक्त के विरुद्ध सारी बातें सच सच कह दी होतीं ।

बहुधा ऐसा होता है कि जो वयान गवाह ने दिया है, वह स्वयं ही एक जैसा नहीं है, उसमें बहुत सी बातें एक दूसरे की विरोधी हैं । कभी-कभी और यह बात प्रायः अधिक देखनेमें आती है—एक गवाह दूसरे गवाह की बातों का खण्डन कर जाता है । अगर बुद्धिमानी के साथ प्रश्न किये जावें, तो वकील अपने बुद्धि-कौशल से उन बातोंको निकाल सकता है जो संयोग वशात् निकल आया करती हैं ।

आमतौर पर गवाहों से ऐसी बातें पूछी जाती हैं जिनका मुकद्दमें से कोई सम्बन्ध नहीं होता—जैसे दूसरे गवाहों की जीवनी, उनकी स्वयं हैसियत और उनका चाल-चलन, उन्होंने कभी कोई अपराध किया है अथवा नहीं, उनकी और फ्रीकैन के साथ कोई दोस्ती या अदावत तो नहीं है इत्यादि—

जिनके उत्तर में वे या तो ऐसी बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो उपयोगी सिद्ध होती हैं या उनकी कोई झूठी बात अथवा विपक्षी को हानि पहुँचाने की इच्छा प्रकट हो जाती है । गवाहों से जिरह करने की विद्या ऐसी है जिसके ध्यान-पूर्वक अध्ययन और मनन करनेकी आवश्यकता है और जिसके लिये मानव-स्वभावके ज्ञान की परमावश्यकता है । यह वकील के जानने की सबसे बड़ी कला है और वर्षों के अनुभव और अध्ययन के पश्चात् इसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है ।

जिरह करने के लिये, प्राप्त अधिकार का प्रयोग, सत्य का अनुसंधान करने की सर्वोत्कृष्ट और परमोपयोगी कसौटी है । इसके द्वारा, फ्रीकैन और उस बात के साथ जिसकी निस्वत झगड़ा है, गवाहका क्या सम्बन्ध है, उसमें उसका क्या स्वाध है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका झुकाव किस ओर है और द्वेष किससे है, उसका चरित्र कैसा है, उसको वे बातें ठीक ठीक और निश्चय रूप से कैसे मालूम हो सकीं; उसमें उन बातों को समझ सकने, उनके स्मरण रखने और वर्णन कर सकने की कितनी शक्ति है इत्यादि बातों का पूरा पूरा और ठीक ठीक पता चल सकता है और वे जूरी के या जज के विचार के लिये उपस्थित की जा सकती हैं, जिससे उस गवाह के वास्तव आचरण (Demeanour) का देखने और उसकी गवाही का ठीक ठीक मूल्य निश्चित करने का अवसर मिला है ।

जो गवाह इस कसौटी पर कस लिया गया है वह जल्दी जल्दी अदालत अथवा जूरी की आंखों में धूल नहीं झाँक सकता; क्योंकि झूठी बातों को चाहे होशियारी से एक दूसरे के साथ मिलाया गया हो, सभी अवस्थाओं में उनकी दशा एक सी नहीं रह सकती जिनमें जिरह की गई है ।

जिरहका ढंग—जिरह आरम्भ करने का सबसे अच्छा एक ढङ्ग यह है कि आप गवाहके साथ ऐसी होशियारी और आदरके साथ पेश आवें जिससे आप उन सारी बातोंको जान लेनेके उपयुक्त वायुमंडल तैयार कर सकें, जो विपक्षीके मुकद्दमोंका समर्थन करने वाली जान पड़ती हों। दूसरा तरीका यह है कि आप सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और सामने से ही उस गवाह पर प्रश्न प्रहार कर दें। बहुतोंने इसे मान लिया है कि इनमें से पहिला ढंग सबसे अधिक सफलता देने वाला है। अगर जिरह करने वालेके भाव और भाषासे गवाहको आरम्भमें इस बातका सन्देह हो गया कि उसकेकी सच्चाईमें लोगोंको सन्देह है, तो वह फौरन होशियार हो जायगा और फिर जो बातें उसने अपने बयान खासमें कही हैं उन्हीं पर डटे रहनेके लिए तैयार हो जायगा। इस जिरह करने की कलाका रहस्य क्या है? इसका उत्तर जस्टिस हाकिन्स (अब लाईब्रैरियन हैं) ने एक शब्दमें ही दिया है—धैर्य (सन्न)। “यह किसी मनुष्यके चारों ओर एक ईटकी दीवार खड़ा करना है। आप अपना प्रश्न पूछते हैं और उसका जो उत्तर मिलता है वह एक ईट बन जाती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न—और दूसरे स्थानमें एक दूसरी ईट तैयार होगई। यदि आप प्रेमपूर्वक प्रश्न पूछेंगे, तो बहुत सम्भव है कि वह स्वयं ही आधा दर्जनके करीब ऐसी ईटें तैयार कर दे जो अपने ठीक स्थान पर नमी हुई हों। ये तमाम जगहमें इधर उधर फैली हैं, लेकिन आपको तो अपना नक्शा पूरा करना है। धीरे धीरे करके वृत्ताकार बन जायगा। दीवार बढ़ेगी और उसको मालूम होगा कि मैं अब बाहर नहीं निकल सकता।” यह धैर्यके साथ पीछे पड़नेका ढंग है।

सीधे आक्रमण कर देना एक बिल्कुल दूसरा ढंग है। इसमें केवल वही वकील सफल होते हैं जो अपने व्यक्तित्व के बलसे अर्थात् प्रभावसे गवाहको अपने वशमें कर लेते हैं, और उस समय भी यह अधिक निष्कण्टक मार्ग नहीं है जब तक कि उनको अपनी वजूहातके ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। नहीं तो उस आक्रमणका असर उलटा अपने ही हितका घातक हो जाता है। जस्टिस वालशका कथन है कि—“यह एक मानी हुई बात है कि यह सीधे आक्रमण द्वारा जो जिरहका ढंग है वह बहुत कम सफल होता है। वास्तवमें उसके सुननेमें भी बहुत कम प्रसन्नता होती है और इससे ज्ञान-वृद्धि भी बहुत कम होती है। धोखे में डालने वाला यह ढंग, जो आधा विश्वासमें रखने वाला और आधा प्रेमप्रदर्शन करने वाला है, अधिक सफल होता दिखाई देता है, क्योंकि अगर गवाह धोखा देना चाहता है तो इससे बहुत सम्भव है कि वह अपना मार्ग छोड़ कर इधरकी बातें करने लगे जिससे उसके बयानकी सच्चाई और झुठाई मालूम होजाय।

प्रत्येक मनुष्य का जिरह करनेका ढंग अपना अपना अलग होता है। परन्तु इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता जिस बातकी है, वह यह है कि गवाह तथा अदालतके प्रति आवश्यक आदर और सम्मान प्रकटकरते रहना। डांट-डपट करना और धमकाना अथवा मेज पर हाथ दे दे मारना आदि बातें न्यायालयों में काममें लाई जाने वाली नहीं हैं और इनसे बहुत कम सफलता प्राप्त होती है। इन बातोंसे

सिर्फ जूरी अथवा अदालतकी सहायभूति कुछ गवाहकी ओर हो जाती है। एक अच्छे वकील के लिए अच्छे स्वभाव और अच्छे ढंग के होने की बड़ी आवश्यकता है।

किसी गवाहको डांटना और घुड़कना, उसे इधर उधर भटकाना, उदाहरणार्थ, ऐसे सवाल पूछना जिनमें उन बातोंको सुबूत किया हुआ मान लिया गया हो जो वास्तवमें सुबूत हुई नहीं हैं, या यह कि अमुक अमुक उत्तर ऐसे हैं जो वास्तविक घटना से बिल्कुल भिन्न हैं—उससे इस तरह खयाल करना जिससे यह सिद्ध होता हो कि वह अपने बयानमें अभी तक सारी बातें झूठ ही कहता चला आया है अथवा उनमें से बहुत सी बातें झूठ कही हैं—कभी कभी उसको इधर उधर भूममें डाल देना, अगर वह मूर्ख है तो, और अगर वह डरपोक है तो डरा देना—आदि बातें प्रायः किसी विरोधी गवाहके मनकी और हृदयकी बात जाननेमें बहुत कम सफल होती हैं, परन्तु अच्छे ढंग से बातें करने, मृदुता और आदरके साथ पेश आनेसे अवश्य ही वह अपने निश्चित मार्गसे विचलित हो जायगा और जल्दी जल्दी तथा युक्तिके साथ प्रश्न करने से उससे बहुत सी बातें मालूम हो जायंगी जो उस समय उसको कोई अधिक महत्व रखने वाली न मालूम होंगी लेकिन जिनको एक साथ नियमित रूपसे एकत्र कर देनेसे कमसे कम समझ रखने वाला आदमी भी उनमें से सत्यको ढूंढ़ लेगा।

एक अच्छे वकील को एक अच्छा काम करने वाला होना चाहिये। बहुत अधिक चौकन्ना रहने वाला वकील भी जिरह करने में अक्सर अपने प्रश्न का ऐसा उत्तर पा सकता है जो उसीके पक्षको गिरा देने वाला हो। उसे जहां तक हो जिरह करते समय अपने आपको खूब काबूमें बनाए रखना चाहिए। उसे सफलता और विफलता दोनों में एक जैसा ही बना रहना चाहिए, मनोवेग के प्रवाह में बहने न लगना चाहिए। अगर उसके चेहरे से कहीं इसबात का पता चल गया कि उसे गवाह के उस उत्तर से दुःख होता है जो उसके लिए हितकर नहीं है, तो केवल इसी एक बात के ऊपर उसका सारा मामला नाकामयाब हो जायगा। इंग्लैण्ड की अदालतों में जिरह करने वाले प्रायः ऐसे उत्तरो से समचिन्ता को खो बैठते हुये देखे गये हैं। जहां उनका गोरा चेहरा लाल हुआ कि गवाह उनके काबू से बाहर होगया। जो बहुत पुराने अनुभवी वकील हैं उनके मनमें ऐसे उत्तरों से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। वह दूसरा प्रश्न पूछना आरम्भ कर देगा, मानों कोई बात हुई ही नहीं थी, या उस गवाह की ओर ज़रा सा मुस्करा देगा, जिसका तात्पर्य यह होगा कि “भला तुम्हारी इस बातको कौन सत्य मान लेगा।” (वेल्मैन पृष्ठ २८-२९ (अंग्रेजी)।

जिरह करने वालेकी वाणी और उसकी मुखाकृतिसे जजके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वह उन बातों का भी जजके ऊपर अच्छा असर डाल सकता है जो इससे विपरीत अवस्था में बिल्कुल ही मानी न जातीं। ओब्रियन् लिखित लाई रसेल की जीवनी में से उद्धृत किए हुए नीचे के वाक्यों से इसबात का ठीक ठीक स्पष्टीकरण और निरूपण हो जाता है:—

“ एक समय सैम्पसन नामक एक गवाह के ऊपर, जिसपर “रिफरी” के संपादक की हैसियत से मानहानि का अभियोग चलाया गया था, जिरह करते समय रसेल ने उस गवाह से एक सवाल पूछा जिसका उत्तर उसने, ‘नहीं’ दिया।

मि० रसेल ने धीमी आवाज़ से पूछा, क्या तुमने मेरा प्रश्न सुना ?

सैम्पसन ने उत्तर दिया “ हां, मैंने सुना ।”

मि० रसेल ने उससे भी अधिक धीमी आवाज़ से पूछा, “ क्या तुमने उसे समझा ?

सैम्पसन ने कहा, “ हां , मैंने समझा ।”

इसके बाद मि० रसेल ने बहुत उच्च स्वर से और इस ढंग से, मानों वह झपट कर उस गवाह की गर्दन धर दबोचेंगे, पूछा, “तब, तुमने इसका उत्तर क्यों नहीं दिया ?

जूरी को बतलाओ तुमने उसका उत्तर क्यों नहीं दिया ? सारे अदालत के कमरे में सन्न छा गई । सैम्पसन घबड़ा गया ।

जिरह करनेकी कलाका ज्ञान प्राप्त करनेका, जैसा कि मि० वेलमैनने बतलाया है, सबसे अच्छा उपाय यह है कि, “बड़े बड़े जिरह करने वालोंके, जो वकालतपेशा लोगोंमें आदर्श माने जातेहैं, जिरह करनेके ढंगका अध्ययन किया जाय।” इन बड़े बड़े जिरह करने वाले वकीलों के जिरह करने के ढंग का संक्षिप्त विवरण दे देना इस पेशे के युवक और उत्साही लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और आनन्दवर्धक सिद्ध होगा ।

सर चार्ल्स रसेल, जो बाद में किलोवन के लार्ड हुए, आधुनिक समय के सबसे अच्छे और लब्ध प्रतिष्ठ जिरह करने वाले थे । उनके सम्बन्ध में लार्ड कॉलेरिड्ज का कहना है कि, “मि० रसेल इस शताब्दीके सबसे बड़े वकील थे ।” यह कहा जाता है कि अन्य बातोंके समान जिरह करने के कार्य में उनकी सफलताका कारण उनका चरित्र-बल था । यह उनके प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व तथा उनके बुद्धि-वैभव और चातुर्य का ही प्रभाव था कि वे उन गवाहों को अपने बश में कर लेतेथे जिन पर कि वे जिरह करते थे । जिरह के सम्बन्ध में मि० रसेल का यह उसूल था “गवाह से सीधे तौर पर उस विषय पर प्रश्न करो जिसकी निस्वत तुम्हें कुछ जानना हो; उस समय अपना सारा बुद्धि चातुर्य खोलकर रख दो । केवल अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेनेसे ही जूरी प्रसन्न नहीं हो जाते ।” जिरह करने में मि० रसेल की सफलता के सम्बन्ध में लिखते हुए उनकी जीवनी के लेखक मि० बेरी ओ’ ब्राइन ने कहा है, “जिस समय वह जिरह करने के लिए उठते थे उस समय का वह द्रश्य निराला था । उनको देखते ही गवाहका कलेजा दहल उठता था—मनुष्यकी जैसी वह भयंकर आकृति, उच्च भ्रुकुटी, तीखी निगाह, दया हीन मुख और गहरी तथा बड़ी २ विशाल आंखें देख कर गवाह भयभीत हो जाता था । एक अन्य व्यक्ति

का कहना है, " गवाह के ऊपर मि० रसेल का वही असर होता था जो एक काहे विषधर भुजंग का एक शशक के ऊपर होता है । "

अमेरिका के वकीलों में यूफुस कॉटे नाम के एक व्यक्ति संसार के जिन जिन स्थानों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती थी, सर्व श्रेष्ठ वक्ता थे । " उनमें भी मि० रसेल की तरह कुछ स्वाभाविक बल था जिससे वे गवाहों को अपने कानू में कर लेते थे । उनका प्रयत्न गवाह को आश्चर्य-चकित कर देने का रहता था । लोग उन्हें अदालतका जादूगर कहा करते थे । वे एक निराले ढंगसे ही जिरह करते थे । वे गवाह पर कभी भी इस तरह आक्रमण नहीं करते थे जिससे मालूम हो कि वे गवाहको डांट दिखाना चाहते हैं । उनको मान-स्वभाव का, मानव कार्यके उद्गम (आते) का और मानव हृदय के विचारों का पूर्ण ज्ञान था । इन बातों की जांच करने और उन बातों को जूरी को समझा देने के लिये वे थोड़े से आवश्यक प्रश्न पूछ दिया करते थे ।

ये प्रश्न होते तो बहुत थोड़े थे परन्तु उनमें का प्रत्येक प्रश्न आवश्यक और ठीक २ बातके विषय में होता था । उनका सिद्धान्त था, ' किसी पर आवश्यकता से अधिक कभी जिरह न करना । अगर आप गवाहको तोड़ न सकें तो वह आपका भन्डा-फोड़ कर देगा । जो कोई आदमी उनके सामने आता उससे वे एक ईमानदार और सज्जन पुरुष की तरह पेश आते मानों उनका यह अनुमान था कि वह सज्जन पुरुष है ; और अगर कोई आदमी बुरी तरह से उनके सामने आया, तो वे उसका तहस नहस कर देते, परन्तु ऐसा वे उस सर्जन की तरह करते जो किसी ऐसी चीड़-फाड़को करता हो जिसके करनेको उसका जी न चाहे, मानों उनको इस काम के करने के लिए बड़ा ही दुःख है । बहुत ही कम ऐसे, अच्छे अथवा बुरे आदमी होंगे जिन्हें उनके प्रति, उनपर जिरह किये जाने के लिये, कोई शिकायत हो । गवाहों के कठघरे में खड़े हुये लोगोंके साथ भाषण करनेकी उनकी शैली बहुतही शान्ति-प्रदायिनी, करुणापूर्ण और विश्वास दायिनी थी । जब वे किसी गवाह का भन्डाफोड़ करने के उद्देश्यसे उसपर आक्रमण करते तो बड़ी ही शान्ति और दृढ़ता के साथ, उसमें किञ्चिन्-मात्रभी रुखाई, अशिष्टता और कठोरता नहीं होती [देखो वेलमन पृष्ठ १८५-८६]

पं० पृथ्वीनाथ वकीलकी जिरह — आपको हम वलायतके नामी वेरिस्टरोंका ढंग जिरह के सम्बन्ध में बता चुके तथा प्रसङ्गवश नीचे उल्लेख करेंगे । भारत में एक अति प्रसिद्ध वकील पं० पृथ्वीनाथ चक कानपुर (संयुक्त-प्रांत) में वकालत करते थे आप जिरह के लिए विख्यात थे । पण्डित जी साहब अपने फरीक के गवाहों को अदालत से बाहर निकल जाने के लिये कभी नहीं कहते थे उनका कहना था कि जब एकही तरह पर जिरह सब गवाहों पर की जाय तो डर हो सकता है कि जो गवाह पहिले गवाह की जिरह सुन रहे हों वे ज्यादा भ्रमबूत हो जायेंगे । उनका ढंग जिरह का बड़ाही शान्त शिष्ट और प्रभाव युक्त था । वे जिरह में पहिले गवाह के साथ साथ चले जाते थे जो बात वह कहना चाहता है उसे ऐसे ढंग से

पूछते थे कि वह यह समझे कि वकील घटना को दुबारा पूछ रहा है। ऐसे जल्द जल्द सवाल कर देते थे जिससे गवाह अपनी पहले बताई हुई बातको फट से कह देता था इसतरह पर कुछ दूर चलकर, बड़ेही धीरे से एक छोटा सा सवाल ऐसा कर देते थे कि गवाह अपनी धुन में प्राकृतिक जवाब दे देता था उस वक्त पण्डित जी बड़े गम्भीर और शांत दिखाई देते थे, गवाह यह नहीं समझ सकता था कि मुझे कुछ भूल होगई है। आगे जिरह में जहां दो बातों के मिलान में गड़बड़ी होजाती तब वे दोनों बातों की याद दिलाकर उच्चस्वरसे पूछते कि आप इनदोनों विरुद्ध बातों का संतोष जनक उत्तर अदालत को दे दें। हैसियत के प्रश्नों को पहिले सूक्ष्मरीति से कहलवाकर पीछे उसे चीर फाड़ करना शुरू करतेथे जैसे:-

आप बता चुके हैं कि आप बाज़ारी करते हैं, आप भास पास की बाज़ारें करते हैं ?—जी हां करता हूँ

जिस रोज़ बाज़ार नहीं होती आप यह सोचते होंगे कि बैठे रहने से यही अच्छा है कि फेरी लगाकर कुछ माल बेच दें ?—हां

आप कितने कोस की फेरी लगा सकते हैं ? —कोई डेढ़ या दो कोस की, फेरी में माल चुना हुआ थोड़ा सा लेजाते होंगे जितना आपसे चल सकता है ?—हां

तो आप कितने वजन तकका माल ले जा सकते हैं ?—कोई बीस सेर तक आप बचुका (गठरी) बांधकर अपनी पीठ पर लेकर और हाथ में गज़ लेकर पास के गांवों में जाया करते हैं ? — जीहां

आप माल खरीदने अकसर कितने दिनों में जाते हैं ?—कभी १५ दिनमें कभी १ मास में,

आप किसके यहां से ज्यादा माल लेते हैं और अगर उनका वही खाता देखा जाय तो आप पर कितना रुपया बाकी निकलेगा ?—इम एक जगहसे माल नहीं लेते, कोई कर्ज नहीं है,

अगर अदालत आपको अभी हुकमदे कि आपके हिसाब की जांच की जाय तो क्या आप हलफ़ से यह कहने को तैयार हैं कि बाज़ार का देना आप पर कुछ बाकी नहीं है ?—देना लेना तो बनाही रहता है;

लेना पीछे पूछेंगे पहिले आप देना बतावेंकि अन्दाजन कितना है ?—इत्यादि

श्रीमान पं० प्रश्वीनाथ जी, एकतरहका जिरह दो गवाहों पर करतेही न थे शायद आपको संदेह होगा कि जब एकही वाक्यात पर कई गवाह हैं तो भिन्न भिन्न जिरह कैसे हो सकती है ? किन्तु आप गौर करके देखेंगे तो पता चल जायगा कि एकही वाकिया के सम्बन्ध में हर एक गवाह अपनी जानकारी कुछ नकुछ फरक के साथ रखता है वकील की बुद्धि इस फरक को लेकर गवाह के मन के भीतर घुसकर धीरे धीरे उसे अपने लक्ष्य से हटा देती है। वे गवाह से जिरह करते समय अदालत के कभरे के प्रायः सब लोगों पर ध्यान रखते थे। जो

लोग गवाहको इशारों से मदद देते रहते हैं उनको ताड़ना वकीलके लिये निहायत जरूरी काम है।

जिरह (Cross Examination) के सम्बन्ध में मि० पॉलब्राउन के बनाए हुए नियम—



१ उन मामलों के सिवाय जिनमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, अपनी आंख गवाह की आंख के सामने से न हटाओ। यह एक के मन की बात को दूसरे के मनमें लेजानेकी नलीहै, जिसकी कमी किसी भी बातसे पूरी नहीं हो सकती।

२ गवाह की आवाज़ का भी ध्यान रखो; आंख के बाद मनकी बात को बतलाने वाला यह दूसरा श्रोत है। गवाह के अपना अपराध छिपाने की बातका, गवाह का अपने मनकीबात छिपाने के प्रयत्न का, बहुत कुछ पता उसके बोलने के ढंगसे, शब्दों के उच्चारण और उनपर जोर देने आदि से चल जाता है। उदाहरणार्थ, अगर इसबात के जानने की आवश्यकता हो कि अमुक समय पर गवाह नई सड़क और लाटूसरोड के कोने पर था, तो इसतरह प्रश्न किया जायगा—क्या तुम छः बजेके समय नई सड़क और लाटूस रोडके कोने पर थे? साफ़ जवाब देने वाला गवाह फौरन् उत्तर देगा—हां, शायद मैं उसी के करीब था। लेकिन जो गवाह वहां पर था, वह उस बात को छिपाना चाहता है और आपका संशय पूरा नहीं होने देना चाहता, और इसलिये उत्तर देता है 'नहीं', यद्यपि सम्भव है कि वह उस समय उस स्थानसे २० कदमके फासलेपर हो या पांच सात मिनट के बाद उसी स्थान पर आगयाहो। ऐसा गवाह जो जवाब देगा वह साधारणतया यह होगा कि—मैं छः बजे के समय उस कोने पर नहीं था। इन दोनों शब्दों (छः बजे और उस कोने) पर जोर देनेसे उसका अभिप्राय गोलमाल बात कहना या बात का ठीक २ उत्तर न देना है, और ऐसी दशा में होशियार जिरह करने वाला यह प्रश्न कर सकता है कि, "तुम किस समय उस कोने पर थे? या छः बजे तुम किस स्थान पर थे? और दस में से नौ उदाहरणों से यह बात मालूम हो जायगी कि अमुक समय पर गवाह उस स्थान पर था अथवा उस समय वह अमुक स्थान पर था। आगे और उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु मेरी सलाह है कि वकील लोग गवाह की आवाज़ का ध्यान रखें तो उस समय इस सिद्धान्त का बड़ी सुगमता के साथ प्रयोग किया जा सकेगा।

३ कोमल स्वभाव वालेके साथ नम्रताके साथ पेश आओ और चालाक आदमीसे होशियार रहो, ईमानदार आदमी पर विश्वास करो, नवयुवकों, निर्बलों अथवा भीरु स्वभाव वालों पर दया रखो, गुण्डोंके साथ सख्त और झूठेके लिए बमके समान कड़े बने रहो। लेकिन इन सभी अवस्थाओंमें आत्मसम्मानका ध्यान

हो। अपने मतके सारे वेगोंको सम्भाले रहो, इसलिये नहीं कि आपकी प्रशंसा होने लगे बल्कि इसलिये कि सत्यकी विजय हो और आपके पक्षकी भी जीत हो।

४ किसी कौजदारी मामलेमें, विशेष कर भारी अपराधके सम्बन्धमें, जब तक आपका मामला ठीक बना रहे, आप बहुत थोड़े प्रश्न पूछिए; और इस बातका ध्यान रहे कि किसी भी शख्ससे ऐसा कोई प्रश्न न पूछें, जिसका उत्तर, अगर आपके खिलाफ हुआ तो, आपके मवकिलके मामले को ही सत्यानाश कर दे, जब तक कि आप गवाहको अच्छी तरह न जानते हों और यह न जानते हों कि उसका उत्तर आपके पक्षका वैसा ही समर्थक होगा जैसे कि दूसरे हैं; या जब तक आपके पास उसे बर्बाद कर देने के लिये शहादत न हो, अगर वह सत्य न कहे और आपकी आशाओंके विरुद्ध आचरण करे।

५ किसी गोलमाल प्रश्नको वैसे ही बचाए रहना चाहिए और उसकी उसी प्रकार निन्दा करनी चाहिए जिस तरह गोल माल उत्तर की। एक उद्देश्य से जो स्पष्ट हो, प्रश्न पूछना गवाहों की जिरह में सबसे अच्छा शुरु है, फिर चाहे वे गवाह ईमानदार हों या बेईमान, झूठी बात चालाकी से नहीं पकड़ी जा सकती है और अगर वह चालाकी से पकड़ी जा सकती है तो वह चालाकी गवाहकी होगी वकील की नहीं। वकील को शांत, शिष्ट, गम्भीर, और सतर्क रहना चाहिये।

६ अगर गवाह ने आपके साथ बुद्धिमानी दिखलाने या हठ करने का निश्चय कर लिया हो, तो अच्छा होकि आप इसबात को उससे पहिलेही तय कर लें नहीं तो जिरह के साथ साथ इसकी शाखाएं बढ़ जायंगी। पहिले उसे इसबातको समझाने का मौका दीजिए कि यातो उसने आपकी शक्ति को नहीं समझा है या अपनी शक्ति को नहीं समझा है। लेकिन हर हालत में आप इसबात का ध्यान रखें कि आप कहीं आपसे बाहर न हो जायें; बुद्धि सम्बन्धी लड़ाई में क्रोध का आजाना इसबात का छोटक या साक्षी है कि वह व्यक्ति (जिसे क्रोध आया है) अवश्य हार गया है।

७ होशियार शतरंज के खेलाड़ी की तरह, हर एक चालमें, आपको अपने खेल (जिरह) के जुटाव और सम्बन्ध की ओर अपनी दृष्टि गड़ाए रहना चाहिए अन्यथा आंशिक एवं अस्थायी सफलता से पूरी और ऐसी हार होजानेकी सम्भावना है जिसका प्रतिकार न हो सकेगा।

८ अपने विपक्षी को कभी कम मत समझो, बल्कि दृढ़ता और होशियारी के साथ अपने कर्तव्य पर डटे रहो; अटकल पचचू निशान ऐसे ही घातक सिद्ध हो सकता है जैसे वह किसी बड़ेही पक्के बुद्धिमान का चलाया हुआ होता। एक की असावधानी से प्रायः दूसरों की गलती ठीक होजाती है और कभी कभी वह प्रभावोत्पादक सिद्ध होती है।

९ आप अदालत और जूरीका उचित सम्मान करते रहें, अपने साथी पर रूपाभाव बनाये रखें और अपने विरोधी के प्रति सज्जनोचित व्यवहार करते रहें।

लेकिन इनमें से किसी के प्रति आवश्यकता से अधिक उदारता दिखला कर अपने सिद्धान्त की किञ्चिन्मात्र भी हत्या न करें ।

जिरह करने का अधिकार और उसका उत्तरदायित्व—किसी गवाह पर जिरह करने का अधिकार देने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसका बयान खास ज़रूर ही ले लिया गया हो; क्योंकि अगर यह असली गवाह है और वाक्यान्त तलब किया गया है और उसे हलफ़ वगैरा दिलाई जा चुकी है, तो विरोधी पक्ष को अधिकार होगा कि वह उस पर जिरह कर सके ।

जिस पक्ष ने उसे तलब कराया है उसने एक भी प्रश्न चाहे उससे न पूछा हो या न पूछना चाहता हो (देखो 6 B. L. R. Ap 88)

इङ्ग्लैण्ड में प्रचलित प्रथाके अनुसार, सिवाय खास खास अवस्थाओं के, आमतौर पर उन गवाहों पर जिरह नहीं की जाती है जो कैदीके चालचलन की निश्चित शहादत देने के लिए तलब किए गए हों, लेकिन इसके लिए किसी कानून द्वारा विशेष रुकावट नहीं डाली गई है । कानून शहादत की दफा १४० में बतलाया गया है कि चाल-चलन के बारे में शहादत देने के लिए तलब किए गए गवाह पर जिरह की जा सकती है और उसके द्वारा बयान (बयान मुक़र्र) लिए जा सकते हैं । जो शफ़स कोई कागज़ (Document) पेश करने के लिए ही तलब किया गया हो, वह सिर्फ़ इसी बात से गवाह नहीं हो जाता कि वह उसे पेश करता है, और जब तक वह शहादत देने के लिए बतौर गवाह के तलब किया जावेगा तब तक उसपर जिरह न की जा सकेगी देखो कानून शहादत की दफा १३९; आर्डर १६, रूल ६, १५ और ज़ाबता फौजदारी की दफा ९४.

जो पक्ष विरोधी पक्ष (मुख़ालिफ़ फ़रीक़) नहीं है, उसे जिरह में कोई हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती देखो 24 C. L. J. 149—किसी शहादत को किसी अभियुक्त के विरुद्ध काबिल तस्लीम बनाने के लिए यह बात कि उसको जिरह का पूरा २ मौका था, अवश्य साबित हो जानी चाहिए देखो 19 B. 749.

जिरह में कैसे प्रश्न (सवाल) पूछे जा सकते हैं ?—जिरह करनेमें बहुत बड़ी स्वतंत्रता है और उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न केवल उन्हीं बातों के सम्बन्धी नहीं होने चाहिए जो कि बयान खास में बतलाई गई हैं । अभियुक्त लोगों को अधिकार है कि वे जिरह में सुनूत के गवाहों से अपने बयान के समर्थन में ऐसी बातें पूछें जिनका बयान खास में कही गई बातों से कोई सम्बन्ध न हो (देखो 42 C. 957)—जो बातें बयान खास में अनुपयुक्त अथवा अप्रासंगिक समझी जाती हैं वे ही जिरह में उपयुक्त और प्रासंगिक होजाती हैं । बाद में किसी समय जिरह करने वाला इस बात के दिखलाने का भार अपने ऊपर ले सकता है कि जो बातें देखने में अनुपयुक्त और अप्रासंगिक जान पड़ती हैं वे वास्तव में उपयुक्त और प्रासंगिक हैं (देखो कानून शहादत की दफा १३६) कानून शहादत की दफा १३८ में बतलाया गया है कि बयान और जिरह दोनों वास्तविक और प्रासंगिक

बातों के सम्बन्ध में होने चाहिए। "वास्तविक और प्रासंगिक बातों" का जिरह में बयान खास की अपेक्षा अधिक विस्तृत अर्थ है। उदाहरण के लिए, ऐसी बातों से, जो और किसी दशा में अनुपयुक्त हों, ऐसे प्रश्न पैदा हो सकते हैं जिनसे गवाह के विश्वास प्राप्त होने के सम्बन्धमें सन्देह किया जा सकता है और जिरहमें ऐसे सवालोकें पूछनेकी इजाजत दीगई है देखो कानून शहादतकी दफा १४६-१५३ लेकिन जो सवालात प्रकट में अनुपयुक्त प्रतीत होते हैं या जो सवालात बयान खास में कही गई बातों का खण्डन करने अथवा उनकी वास्तविकता दिखलाने के लिए नहीं पूछे गए हैं या जिनसे गवाह के विश्वासप्राप्त होने के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं उठाया जाता है, ऐसे सवालों के जिरह में पूछने की आज्ञा नहीं है। कानून का ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे सुनी गई बातों की शहादत बयान खास की अपेक्षा जिरह में अधिक महत्वकी समझी जाय (देखो 16C.206,211) — ज्योंही कोई गवाह इधर उधर की सुनी हुई बातें अपने बयान में कहना आरम्भ करे, त्यों ही अदालत को उसे वहां पर रोक देना चाहिए। इस बात के सहारे रहना ठीक नहीं कि बादमें जूरीके सामने सुनी हुई शहादत अलग कर दिए जाने का प्रयत्न करके केवल कानूनी शहादत के ऊपर ही फैसला दिया जायगा; देखो 7 W.R.Cr. 25.—किसी गवाह से यह नहीं पूछा जा सकता कि क्या असुक्त व्यक्ति इस बातको स्वीकार किया था कि वह, (नकि वह व्यक्ति, जिसपर अभियोग लगाया गया है) ऐसा व्यक्ति है जो असुक्त बातके लिए उत्तरदायी है। क्योंकि ऐसी शहादत सुनी हुई शहादत है (देखो वैट्स बनाम लियन्स, 6M.and.G.1047) —लेकिन उससे यह बात पूछी जा सकती है, कि क्या वह असुक्त व्यक्ति ही ऐसा व्यक्ति है, जिसपर विश्वास किया गया था, अथवा जिसके ऊपर बतौर उस व्यक्ति के कार्यवाई की गई थी जो वास्तव में उत्तरदायी था ? और ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्मरणशक्ति की और उसके विश्वास प्राप्त होने की परीक्षा करने के लिए उससे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं देखो हालिंगहेड बनाम हेड, 4 C. B. n. s. 388; Powell, P. 534.

जिरह सिर्फ उन्हीं बातों के सम्बन्ध में नहीं की जा सकती जो गवाह अपने बयान खास में कह चुका है, बल्कि सारे मामलेके सम्बन्धमें की जा सकती है। अतएव, अगर कोई मुद्दा किसी गवाह को सिर्फ एक मामूली से मामूली बात साबित करने के लिए तलब करता है, तो मुद्दाभलेह उससे हर एक बात के ऊपर जिरह कर सकता है, और अगर वह ऐसा कर सकता है तो, ऐसे प्रश्न पूछकर जो उसी उत्तर की ओर संकेत करने वाले हों जो वह चाहता है अपनी सफाईको मजबूत कर सकता है; और इस सिद्धान्त का यहां तक प्रयोग किया गया है कि वह शकस भी, जो उस मुकद्दमें में फरीक है, अपने विपक्षी की ओर से कानूनी सुवृत्त दाखिल करने के लिए तलब किए जाने पर सब कामों के लिए गवाह समझा जाता है और उससे सारे मामले के ऊपर जिरह की जा सकती है (देखो 6 B. L. R. Ap. 88; 15 W. R. Cr. 34)

चाल चलन की निस्वत शहादत देने वाले गवाहों के ऊपर जिरह की जा सकती है (देखो दफा १४०)—जिरहमें ऐसेसवाल पूछे जासकते हैं जोऐसेजवाब की ओर संकेत (इशारा) करते हों (देखो दफा १४३) । पहिले दिए गए बयान तहरीरीके सम्बन्धमें, उसका खण्डन करनेके अभिप्रायसे, जिरह करनेके बारेमें देखो कानून शहादत की दफा १४५—जिरहमें किए जाने वाले दूसरे कानूनी सवालों के सम्बन्ध में देखो कानून शहादत की दफा १४६ ।

गवाह हमेशा इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह जिरह में पूछे गए हर एक सवाल का जवाब जरूर दे (देखो दफा १४७ और १४८) उसपर उन तमाम बातों के ऊपर जिरह की जा सकती है और उसका खण्डन किया जा सकता है जो उस मामले से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाले हैं । उन बातों के सम्बन्ध में, जिनका सम्बन्ध जांच से सिर्फ वहीं तक हैं जहां तक कि वह उसके आचरण पर आघात कर, उसके एतबार को धक्का पहुंचाती है, यद्यपि उस गवाह पर जिरह की जा सकती है, जिसका सिवाय दो अवस्थाओंके खण्डन नहीं किया जा सकता (देखो कानून शहादत की दफा १५३)—जिरह में गवाह के विश्वास पात्र होने के सम्बन्ध में किस प्रकार आपत्ति की जा सकती है इस सम्बन्ध में देखो कानून शहादत की दफा १५५ । अदालत किसी फरीक (पक्ष) को अपने ही गवाह पर जिरह करने की इजाजत दे सकती है, अगर वह उसके विरुद्ध आचरण करने लगे (देखो कानून शहादत की दफा १५४) तहरीरी बातोंके सम्बन्धमें दी जाने वाली शहादतके बारे में देखो कानून शहादत की दफा १४४ । किसी ऐसे गवाह के ऊपर की जाने वाली जिरह के सम्बन्ध में, जो किसी कागज़ के पेश करने के लिए तलब किया गया हो, देखो कानून शहादत की दफा १३९ । अदालत को अधिकार होगा कि वह शिष्टताशून्य, अपमान करने वाले और हैरान करने वाले प्रश्नों के पूछने की मनाही कर दे देखो कानून शहादत की दफा १५१, १५२ ।

जिरह में किन प्रश्नों के पूछने की मुमानियत है ? —ऐसे प्रश्न, जिनमें वे बातें सुबूत की गई मानली गई हों जो वास्तव में सुबूत नहीं की गई हैं, या यह कि अमुक अमुक उत्तर दिए गए हैं जो वास्तव में दिए नहीं गए हैं, कभी भी पूछनेकी इजाजत न दी जायगी । जिस प्रश्नमें किसी ऐसी बात, को मान लिया गया हो जो विरुद्ध पड़ता है, वह प्रश्न जबकि बयान खासमें पूछा गया हो, तो ऐसा प्रश्न (सवाल) है जो उसी उत्तर की ओर संकेत करता है जो उत्तर प्रश्न-कर्ता चाहता है, क्योंकि इससे उस पक्षके समर्थक गवाह को उस बात का स्मरण करा दिया जाता है जो उसने अन्य दशा में बयान न की होती । इसी प्रकार, जिरहमें भी ऐसा प्रश्न अनुचित ही होगा, क्योंकि सम्भवतः उसका तात्पर्य उस गवाह के मुंहसे, ऐसी बात निकलवा लेना है जोकि वह कहना नहीं चाहता था और इस तरह वह उसकी शहादत का एक अंग बन जाती है, यद्यपि उसे उसने अपनी इच्छा से नहीं कहा था ।

जिरहके दौरानमें अपमान सूचक बातोंका कहा जाना—जिरह में पूछे जाने वाले प्रश्नों में कोई अपमान सूचक अथवा परेशान करने वाली बात न होनी चाहिए, यद्यपि वकील को अधिकार है कि वह गवाह के ऊपर टीका टिप्पणी करता जाय। जिस समय मि० हार्डी पर अभियोग चलाया जा रहा था (देखो 24 How. St. Tr. 754) उस समय मि० एस्कभून ने अपनी जिरहमें एक राजविद्रोहात्मक सभा की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूछा कि—बताइये—
“तो आप उनमें से किसी भी सभा में सिवाय गुप्तचर की हैसियत में कभी गए ही नहीं?”

“चूंकि तुम ऐसा कहते हो, इसलिए मैं भी इसे ऐसा ही माने लेता हूँ”

“अगर तुम वहां पर गुप्तचर की हैसियत में नहीं गए थे, तो और जो वषाधि तुम चाहते हो चुन लो और मैं तुम्हें वह उपाधि दे दूंगा।”

लार्ड चीफ जस्टिस ईयर ने कहा—

“बयान लेते समय गवाह का नाम नहीं रखना चाहिए। यह वही बातें बतलाता है जिनके लिए वह गया था, और शहादत के ऊपर विचार करने में आप उसे जैसा नाम चाहें दें।” इसी तरह के एक अवसर पर आपने कहा—“मैं समझता हूँ यह बात बिल्कुल साफ है कि जो सवालालात पूछे जानेको हैं उनपर उन सब बातोंका भार नहीं लाद देना चाहिए जो मुकदमेंके पहिले वाले कुल हिस्सोंके सम्बन्ध में पैदा होती हैं; इनसे हर एक आदमी का ध्यान बट जाता है; इनसे हमारा बहुत समय नष्ट होता है; और यह बात कि वह समय गवाह के चाल-चलन या उसकी स्थिति के सम्बन्ध में टीका-टिप्पणी करने का समय नहीं है, ऐसी साफ है कि इसे शहादत का एक नियम मानकर इससे कभी भी विचलित न होना चाहिए।”

किसी गवाह की शहादत के मूल्य अथवा उसके प्रभाव के सम्बन्ध में, या उसके आचरण के ऊपर बयान के दौरान में बिना विचार किए जल्दी में कोई टीका न करने लगना चाहिए। वे सारी बातें बहस के वक्तके लिए ही छोड़ रखनी चाहिए। और न जिरह करने वालेको यही चाहिए कि वह बिल्कुल कल्पित प्रश्नों को उठाकर गवाह से वाद-विवाद करने लगे। आक्रमणात्मक प्रश्नों के सम्बन्ध में देखो कानून शहादत की दफा १५१।

कुछ बातों के ऊपर जिरह का न करना—चतुर जिरह करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह असली बयान में कही गई बातों को ध्यान पूर्वक सुने, और जब अपनी बारी आवे तो गवाह से उन्हीं बातों के सम्बन्ध में प्रश्न करे जो उसके विरुद्ध पड़ती हों। अगर वह उन्हें छोड़ देगा या उनके पूछने की परवा न करेगा तो यह समझा जायगा कि उन्हें उसने स्वीकार कर लिया है और दूसरा पक्ष स्वभावतः इससे यह परिणाम निकलेगा कि वे बिना किसी विरोध के मान लिए गए हैं।

साधारण तौर पर तो यह चाहिए कि एक पक्ष अपने विपक्षी के गवाहोंमें से प्रत्येक से क्रमशः वही बातें पूछे जिनका सम्बन्ध उस गवाह से है या जिनमें

इसका कोई अंश था। इस प्रकार, अगर कोई गवाह किसी बात-चीत के सम्बन्ध में कुछ कहता है तो जिरह करने वाले वकील को चाहिए कि वह अपनी जिरहसे यह प्रकट करदे कि उसके बयान का कितना अंश वह स्वीकार करता है, और कितने का वह विरोध करता है। अगर वह कोई प्रश्न नहीं करता है, तो यह समझा जायगा कि वह उस गवाह की सारी बातें स्वीकार करता है (देखो फले-नागन बनाम फैदी 2 I. R. 361, 388-389)

बेपरवाही से की गई जिरह और उसका भयंकर परिणाम—ऐसा देखा गया है कि जिरह करने का उद्देश्य अपने विरोधी पक्ष के मामले को बिगाड़ देना, उसे सीमाबद्ध कर देना या कमजोर बना देना और विपक्षी के गवाहों की शहादत से अपने मामले को मजबूत बनाना, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमेशा प्रश्न तैयार करने चाहिए। अटकल-पच्चू या अनिश्चित प्रश्नों को बचाए रखना चाहिए, क्योंकि बे-परवाही के साथ की गई जिरह सम्भव है ऐसी बातों को पैदा कर दे जो पहिले जाहिर नहीं की गई थीं और जो घयान में क्राबिल तस्लीम न होतीं। बे-परवाही के साथ, इस आशा से कि उनसे कोई उपयोगी उत्तर निकल आवेगा, प्रश्न करनेसे सम्भव है कि कभी कभी विपरीत परिणाम भी निकल आवें। मि० बेरन्ट ऐलर्डसन ने एक बार एक वकील से कहा—“Mr. ... you seem to think that the art of Cross Examination is to examine crossly” अर्थात्, मि०—मालूम होता है आप समझते हैं कि जिरह करने की कला ऐसे-वैसे सवाल करना है।)

प्रश्न केवल प्रश्न करने के अभिप्राय से न पूछे जाने चाहिए। अगर गवाह ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो आपके मवकिल के पक्ष को हानि पहुंचाने वाली हो, तो इस आशा से, कि किसी अन्य विषय में कोई बात अपने अनुकूल निकल आवे, उसे छेड़ना या तंग न करना ही अच्छा मार्ग होगा। सम्भव है जो उत्तर वह दे, वे उलटा आपही के विरुद्ध निकल पड़ें। यह एक साधारण अनुभव की बात है कि युवक और नये वकीलों को यह खयाल रहता है कि, यह उनका कर्तव्य है कि वे हर एक ऐसे गवाह पर जिरह अवश्य करें जिसने शहादत देने के लिए अदालत के सामने हलफ लेली है। ऐसा जान पड़ता है कि उनका यह खयाल है कि अगर वे हर एक गवाह पर जिरह न करेंगे तो उनके मवकिल यह समझेंगे कि वह योग्य और होशियार वकील नहीं है। ऐसी उद्देश-हीन और अनावश्यक जिरह से प्रायः ऐसे उत्तर मिल जाते हैं जो अपने ही मवकिल के पक्ष के वातक होते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि बहुत सी ऐसी बातों के खयाल करने का मौका मिलता है जिन्हें इससे पहिले दूसरे पक्षने कभी सोचा भी नहीं था। अगर खामोशी रखी जाती, तो ऐसी कोई भी बात पैदा न होती। किसी गवाह के बयान ख़ास हो चुकने पर, जिरह करने वाले को यह निश्चय कर लेना चाहिए कि क्या उसने कोई ऐसी बात कही है जो उसके विरुद्ध पड़ती है और ऐसी सभी बातों को एकत्र कर लेना चाहिए। इससे उसे इस बात का निर्णय करनेमें सहायता मिलेगी कि किसी प्रकारकी जिरह करनेकी आवश्यकता

है अथवा नहीं और अगर है तो किस बात के ऊपर। सिर्फ मवक्कलके दिखाने के लिये बूढ़ा की उटपटांग बातें न पूछना चाहिए।

“आवश्यकता से अधिक जिरह कभी मत करो” यह एक पक्का सिद्धान्त है। जब आपको इस बात का निश्चय न हो कि जो उत्तर आपको मिलेंगे वे आपके अनुकूल होंगे अथवा आपको इस बात का खयाल न हो कि कोई उत्तर अनुकूल होगा अथवा प्रतिकूल, तो अच्छा हो कि आप बहुत अधिक पूछने के बदले बहुत कम पूछें। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे अवसर भी आजाते हैं जिनमें जोखिम वाले सवाल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको आगे कदम बढ़ाने के पहिले अपने चारों तरफ खूब देख भाल लेना चाहिए। जब बयान खास में दी गई शहादत बिल्कुल साफ हो और उसपर कोई आपत्ति न की जा सकती हो, तो यह उचित न होगा कि उसी विषयमें जिरह करके मामला और बढ़ाया जाय या जोखिम में डाला जाय। इससे आपके विपक्षी के मामले के जोरदार बन जाने की अधिक आशंका है। गवाह को अपनी बातों को जोर के साथ दोहराने का मौका मिल जायगा और अगर जिन बातों को उसने बयान किया है वे वास्तव में हुई हैं तो बार-बार प्रश्न करने से उसे बहुत सी बातों का स्मरण हो जायगा जो वह पहिले भूल गया था।

किसी फरीक के कहने पर किसी गवाह के सम्मान पर विवेक रहित आक्रमण करना लाभ की अपेक्षा हानि अधिक पहुँचती है। बहुत से मामलों में किसी शख्स को अपने विपक्षी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष होता है और इसलिए हमेशा वह इस बातके लिए उत्सुक रहता है कि उसे अपने उस विपक्षीपर अथवा गवाहों पर, जो इजलास पर पेश हुए हैं, व्यर्थ के अपमान सूचक दोषारोपण कर डालें, फिर उसके लुकड़में का चाहें कुछ परिणाम हो। अगर बिना विचारै निराधार बातें कह डाली गईं और शताब्दियों पहिले हुई घटनाओंको, जिनसे उस मामले में, जिसके सम्बन्ध में वह शहादत दे रहा है, कोई असर नहीं पड़ता है, खोद निकाला जाय, तो उससे जज चिढ़ जाता है और जूरी की सहानुभूति भी चली जाती है।

“अगर यह मानिए कि जिरह एक बड़ा ताकतवर इंजन है, तो उसी प्रकार वह बहुतही खतरनाक भी है, जो उन लोगों पर भी टूट पड़ सकता है जो इसबात को नहीं जानते हैं कि उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। युवक वकील को यह विचार लेना चाहिए कि, अगर जिसबात को गवाह बतला रहा है वह वास्तव में हुई है, तो सत्य का ऐसा प्रभाव होता है कि उसको वे सारी जरूरी जरूरी बातें स्मरण होजायगी जिनका उस घटना से सम्बन्ध था; और जितना ही अधिक उस की स्मरण-शक्ति को उन्नेजित किया जायगा उतना ही अधिक बातें प्रकट होती जायंगी, जिससे उसकी पहिले कही हुई बातों का खण्डन के बदले, मण्डन होता जायगा। और गवाह का, अनावश्यक बातोंका जो अधिक चित्ताकर्षक नहीं है, भूल जाना, अथवा उनके सम्बन्धमें कहीं कहींपर भेद होजाना, उनकी विश्वास

पात्रता को धक्का पहुंचाने के बदले प्रायः उसे प्रचल बना देता है। इससे अधिक सन्देहयुक्त और कोई भी बात नहीं हो सकती कि एक लम्बे चौड़े किस्से को बहुत से गवाह बयान कर जाय और छोटी से छोटी बात में भी उनमें भेद न पड़े। इस लिए यह एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है कि, किसी जिरह करने वाले वकील को, आमतौर पर, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, जिनके उत्तर प्रतिकूल होने पर उसके ही पक्ष के घातक सिद्ध हों ;

जैसे उदाहरण के लिये, किसी ऐसे मामलेमें, जिसका दार मदार शिनास के ऊपर हो। यह कि क्या गवाह को इस बात का निश्चय है या वह इसके लिये हलफ़ से बयान कर सकता है कि अभियुक्त वही आदमी है जिसकी निश्चय वह अपना बयान दे रहा है। अच्छा यह होगा कि उससे घटना के निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती विषयों के सम्बंध में प्रश्न किए जायें; जिनके सम्बंध में दिए उत्तर से यह मालूम होजाय कि, अपने पहिले बयान में, जो कि उसने दिया है, वह या तो झूठ बोला है या उसने भूल से ऐसा बयान कर दिया। परन्तु कुछ अवस्थाओं में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जिनमें अपना मामला बिगड़ जानेका भी भय है; विशेष कर ऐसी दशामें जबकि अनुकूल उत्तरके मिल जानेसे बहुत बड़ा लाभ होता हो और पहिले ही से स्थिति ऐसी बन गई हो कि प्रतिकूल उत्तर मिलने से उसमें बहुत कम हानि होने की संभावना हो। "

ऐसे अभियुक्तों और मुद्दाभलेहों के गवाहों पर जिरह करनेका अधिकार जिनपर मामला एकही में चल रहा हो—जब दो या अधिक आदमियों के ऊपर एक साथ में मामला चलाया गया हो और वे अलग अलग अपनी सफ़ाई पेश कर रहे हों, तो किसी भी गवाह पर, जो उनमें से किसी एक की ओर से पेश किया गया हो, दूसरे की ओर से जिरह की जा सकती है, जब वह कोई ऐसी बात अपने बयान में कहे जिससे उन सबपर दोष लगाया जाताहो देखो आर बनाम वरडट, 1855, Deans C. C. 431.

और जब दो कैदियों के ऊपर साथ में मामला चल रहा हो और एक का गवाह ऐसी शहादत देता है जिससे दूसरे पर भी असर पड़ता है, तो दूसरे को गवाह के ऊपर जिरह करने का अधिकार देखो आर बनाम टैडमेन 1902; 1 K. B. 882.

दूसरे कैदियों के वकीलों को भी अधिकार है कि वे ऐसी दशा में उस शहादत से काम लें। इसी तरह लाई बनाम कार्लिबन के मुकद्दमें [1855 L. J. Ch. 5. 17] में जस्टिस किडरात् ने, कुल न्यायालयों के जजों से परामर्श करते के बाद, तय किया था कि सब से बड़ी अदालत दीवानी (कोर्ट आफ़ चैम्बेरी) में जिरह करने वाले के सामने एक मुद्दाभलेह दूसरे मुद्दाभलेह के गवाहों पर जिरह कर सकता है।

कानून शहादत में उन शख्सों के गवाहों पर जिरह करने के सम्बन्ध में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है जिनपर एक साथ अभियोग चलाया गया हो

या जो एक ही साथ मुद्दाभलेह बनाए गये हों। लेकिन इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाई की व्यवस्था इस प्रचलित नियम के अनुसार की जा सकती है कि उस शख्स के खिलाफ दी गई कोई भी शहादत स्वीकार न की जायगी जिसे जिरह करके उसकी जांच करने का मौका न दिया गया हो; क्योंकि यह बिल्कुल ही अनुचित और अन्याय होगा कि किसी अभियुक्त को उस गवाह पर जिरह करने का मौका न दिया जाय जो उस अभियुक्त की ओर से तलब किया गया है जिसका मामला उससे बिल्कुल भिन्न है।

रामचन्द्र बनाम हनीफ़ शेख, 21 C. 401, में जस्टिस ट्रेवीलियन और जस्टिस रामथिनीने कहा था—“हम समझते हैं कि बहुत से मुकद्दमोंमें न्याय न हो सकेगा, अगर किसी अभियुक्त को अपने साथी उस अभियुक्त के गवाह पर जिरह करने का मौका न दिया जाय जिसका मामला उससे भिन्न है, क्योंकि सम्भव है इसका परिणाम यह हो कि अदालत उस शहादत के आधार पर अपना फैसला दे देवे जिसकी जिरहसे जांच नहीं कर ली गई है। कानून शहादतमें उन गवाहों से जिरह करने का अधिकार दिया गया है जो विपक्षी की ओरसे तलब किए गए हों।” लेकिन देखो के० बनाम सरूप, 12 W R. C. 75. जो कानून शहादत के पास होने से पहिले फैसल हुआ था।

अगर कई एक मुद्दाभलेहों में से जिनपर एक साथ में नालिश की गई है, किसी एक की पैरवी अलग से की जाय तो वह दूसरे मुद्दाभलेह पर जिरह कर सकता है, देखो नरसिंह बनाम कृष्णा, Mad. H. C. 546.

अभिलिपित उत्तरकी ओर संकेत करने वाला प्रश्न—ऐसे प्रश्न वह हैं जिनमें उस उत्तरकी ओर संकेत किया गया हो जिनको प्रश्नकर्त्ता चाहता है। मि० टेलरके कथनानुसार उत्तरकी ओर संकेत करने वाला प्रश्न (Leading question) वह प्रश्न है जिसमें गवाहको वाञ्छित उत्तर देनेके लिए इशारा किया गया हो, या जिसमें आवश्यक बातोंके होते हुए भी उसका उत्तर एक ‘हां’ अथवा ‘नहीं’ में होता हो। मि० वेन्यमने ऐसे प्रश्नकी परिभाषा यह की है कि वह प्रश्न गवाहको उस वास्तविक अथवा कल्पित घटनाकी ओर इशारा करता है जिसकी प्रश्न करने वाला आशा रखता है और जिसको वह चाहता है कि उत्तर द्वारा स्वीकार कर लिया जाय। जैसे,

क्या तुम्हारा अमुक नाम नहीं है ?

क्या तुम्हारी सकूनत फ़लां जगह पर नहीं है ?

क्या तुम अमुक व्यक्तिके यहां नौकर नहीं हो ?

क्या तुम इतने दिनों तक उसके साथ नहीं रहे हो ?

यह बात बिल्कुल साफ़ है कि इस प्रकारके प्रश्नोंमें गवाहको गुप्त रीतिसे सारी बातें बतला दी जाती हैं। इससे उसे, उससे पृष्ठे गए प्रश्नोंका वाञ्छित उत्तर देनेके लिए तैयार किया जा सकता है; और प्रश्नकर्त्ता, जो अपनी अनभि-

ज्ञाता प्रकट करता है और जानने के लिए पूछता है, वास्तवमें वह पूछनेके बगैरे जवाब बतलाता है।

किसी प्रश्नको उसी समय वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करने वाला बतला कर उस पर आक्षेप किया जा सकता है जब उसमें उत्तर की ओर संकेत किया गया हो उस समय नहीं जब कि उससे केवल गवाहका ध्यान उस विषय की ओर आकर्षित किया गया हो जिसके बारेमें उससे प्रश्न किया गया है (देखो निकोलस बनाम डाउडिङ्ग, 1 Stark 81; Best. S. 641).

संकेतार्थक प्रश्न किन अवस्थाओंमें नहीं पूछे जा सकते और वे कब पूछे जा सकते हैं:— बिना अदालतकी आज्ञाके ऐसे प्रश्न, जो वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले हैं, अगर उनके बारेमें विरोधी पक्षको कोई आपत्ति है तो, बयान खास (Examination in Chief) अथवा बयान मुकर्रर (Re Examination) में नहीं पूछे जा सकते।

अदालत ऐसी दशामें ऐसे संकेतार्थक प्रश्नोंके पूछनेकी इजाजत दे सकती है जब जिन बातोंके सम्बन्धमें वे पूछे गए हैं वे प्रारम्भिक बातें हैं या जिनके बारे में, उसकी रायमें, पहिले ही काफी सुबूत गुजर चुका है (देखो कानून शहादतकी दफा १४२)।

ज़िरह में ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं जो वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करते हों (देखो दफा १४३)।

साधारण नियम यह है कि उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्न बयान खास या बयान मुकर्रर में नहीं पूछे जा सकते। वकील का यह कर्तव्य है कि वह उन बातों को, जिन्हें उसका गवाह जानता है, बिना उसे किसी तरह की मदद पहुँचाए हुए, उससे बयान करवा के अदालत को न्याय-कार्य संचालन में सहायता करे। बयान खास और बयान मुकर्रर में उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्नोंके पूछने की इजाजत न देने का कारण बिल्कुल साधारण है।

गवाह का स्वाभाविक रुझान उस आदमी की ओर होता है जो उसे तलब कराता है और इसलिए ज्योंही उसे प्रश्न से यह मालूम हो जायगा कि प्रश्नकर्ता 'हां' अथवा 'नहीं' में एक उत्तर चाहता है, तो वह फौरन् 'हां' या 'नहीं' में जवाब दे देगा। दूसरा कारण, जैसा कि मि० व्यस्ट का कहना है, यह है कि "किसी गवाह को तलब करने वाले शख्स को अपने विपक्षी की अपेक्षा अधिक लाभ इस बात का रहता है कि वह गवाह से पहिले से ही इसबात को जान लेता है कि गवाह कौनसी बात साबित करेगा या कम से कम उससे कौनसी बात साबित होने की आशा की जाती है; और यह कि इसलिए, अगर वकील को रास्ता दिखलाने की इजाजत दे दी जाय, तो सम्भव है कि वह इस तरह प्रश्न करे कि उससे गवाह उतना ही उत्तर दे जो उसके अनुकूल पड़ता है या कुछ बातों को छिपा डाले।

कानून शहादत की दफा १४२ में बतलाया गया है कि, अगर उन पर कोई आपत्ति की जाती है तो, ऐसे प्रश्न जो वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करने वाले हों, बयान खास में नहीं पूछे जाते हैं। जहां तक जख्द हो सके उसपर उज्रदारी कर दी जानी चाहिए, अर्थात् उस समय जब कि प्रश्न किया जा चुका हो या किया जा रहा हो। अगर ठीक समय पर उज्रदारी न की गई, तो जो कुछ उत्तर वह देगा उसे जज लिखलेगा और फिर उसका कुछ दूर नहीं किया जा सकता है। अगर विरोधी पक्षकी उज्रदारी की बिना मंजूर है और अदालत अपने अधिकार से उज्रदारी खारिज करके उस प्रश्न के पूछने की इजाजत दे देती है, तो यह उचित है कि अदालत को वह प्रश्न नोट करा दिया जाय, ताकि अपील किए जाने पर आगे की अदालत शहादत के असर का अन्दाज़ा लगा सके, या बाद में उसी अदालत को यह दिखलाया जा सके कि उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्न से शहादत का बल घट गया है। जब प्रश्नों के सम्बन्धमें उज्रदारी की गई हो और अदालत ने उसे मंजूर कर लिया हो, तो जज उस प्रश्न को, उसका उत्तर और उज्रदारी इत्यादि को लिख लेगा (देखो आर्डर १८, रूल १२, ज़ाबता दीवानी) — उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्नों की सहायता से प्राप्त शहादतको अलग करनेका सबसे अच्छा उपाय यही है कि उन प्रश्नोंके पूछने की इजाजत न दी जाय (देखो 15. W. R. Cr. 23 P. 24.)।

लेकिन अगर विरोधी पक्षका वकील ऐसे उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्नोंके ऊपर कोई आपत्ति नहीं करता और ऐसे प्रश्नोंके उत्तर प्राप्त हो जाय, तो यह प्रश्नकर्ताकी विजय न समझनी चाहिये, क्योंकि ऐसी शहादतका नतीजा बहुत ही कमजोर होता है।

प्रायः देखा जाता है कि ऐसे संकेतार्थक प्रश्न पूछनेकी, बिना किसी आपत्ति के ही, इजाजत दे दी जाती है, कभी प्रकट स्वीकृति द्वारा और कभी मौन द्वारा। यह अन्तिम अवस्था उस समय पैदा होती है जबकि प्रश्न उन बातों के सम्बन्धमें पूछे जाते हैं जिनकी बाबत प्रश्न कर्ता यह जानता है कि दूसरे पक्ष वाले उनका कोई विरोध नहीं करेंगे; या जबकि विपक्षीका वकील उन्हें इस काबिल नहीं समझता कि उन पर कोई आपत्ति की जाय। परन्तु दूसरी ओर इस बिनाके ऊपर बहुत ही निराधार आपत्तियां बराबर की जाती रहती हैं।

अदालत अपने अधिकारसे बयान खासमें ऐसे संकेतार्थक प्रश्नों के पूछनेकी इजाजत दे सकती है

कानून शहादतकी दफा १४२ में यह बतलाया गया है कि उत्तरकी ओर संकेत करने वाला प्रश्न, अगर उन पर आपत्ति की गई है तो, बिना अदालतकी

इजाज़त के नहीं पूछे जा सकते। चूंकि उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्नोंके सम्बन्धमें यह आपत्ति नहीं की जा सकती कि वे बिल्कुल गैर-कानूनी हैं बल्कि सिर्फ़ यह कहा जा सकता है कि वे बिल्कुल अनुचित हैं (देखो 7 A. 385, 397; (1909) 2 K. B. 14 (16)). इसलिये अदालत अपने अधिकारसे उचित अवस्थाओंमें ऐसे प्रश्न पूछनेकी इजाज़त दे सकती है। साधारण नियमके ये नीचे लिखे अपवाद (मुस्तसिनयात) हैं:—

(१) प्रारम्भिक अथवा ऐसा मामला जिसकी निस्वत कुछ झगड़ा नहीं है—अदालत ऐसी बातोंके सम्बन्धमें संकेतार्थक प्रश्नोंके लिए इजाज़त दे सकती है जो प्रारम्भिक हैं अथवा जिनकी वास्तव कोई झगड़ा नहीं है या जिनकी निस्वत काफी सुवृत्त शुद्ध चुका है, (देखो दफा १४२)—साधारण नियम बयानके उस हिस्सेके सम्बन्धमें लागू नहीं होता जो आवश्यक अंशका प्रारम्भ करता है। अगर वास्तवमें ऐसे प्रश्नोंसे असली बातों तक पहुंचनेकी इजाज़त न दी गई होती, तो बयानोंमें बहुत विलम्ब और इस कारण बड़ी असुविधा होती। कार्रवाईको संक्षिप्त करने और गवाहको जहां तक जरूर सम्भव हो उन आवश्यक बातों तक लानेके लिये, जिनकी निस्वत वह अपना बयान दे रहा है, वकील उसे इस सम्बन्धमें सहायता कर सकता है और उसे वह सारी बातें सुना सकता है जो स्वीकार कर ली गई हैं और जो पहिले ही तय होगई हैं। इसलिये ऐसी बातोंके सम्बन्धमें सहायता पहुंचनेकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए बल्कि सहायता करना उचित भी होगा।

(२) शिनाख्त—किन्हीं आदमियों या चीज़ोंकी ओर किसी शख्सका ध्यान, उनकी शिनाख्त करनेके अभिप्रायसे, आकृष्ट किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, गवाहसे प्रायः ऐसा पूछा जाता है कि क्या अभियुक्त ही ऐसा शख्स है जिसकी निस्वत तुम कहते हो? इस प्रकारका प्रश्न वास्तवमें असन्तोष-जनक है और ऐसी शहादत का कुछ अधिक महत्व नहीं होता। आजकल वकीलके लिए इस प्रकार का प्रश्न करना कि, क्या वह शख्स तुमको अदालतमें दिखलाई पड़ता है? और फिर उसे उस शख्सकी शिनाख्त करने के लिए कहना अच्छा समझा जाता है। ऐसी दशामें यह उचित है कि उसे कोई सहायता शिनाख्त करने में न पहुँचाई जाय। यद्यपि यह बिल्कुल ठीक होगा कि अभियुक्तकी ओर इशारा करके गवाह से यह पूछा जाय कि क्या यही वह शख्स है जिसकी निस्वत तुम बयान दे रहे हो? तो भी अगर बिना किसी सहायताके गवाह अभियुक्तको पहचान ले, तो उसकी शहादतका अधिक मूल्य होगा।

३ खण्डन करना—किसी गवाहसे किसी दूसरे गवाहकी शहादतका खण्डन करनेके अभिप्रायसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करते हों। उदाहरणार्थ—अगर मोहनका कहना है कि घसीटेने उसे अमुक अमुक बात बतलाई है, तो घसीटेसे पूछा जा सकता है कि, क्या तुमने कभी मोहनसे अमुक अमुक बात कही है।

जब एक गवाह किसी दूसरे गवाहकी बातोंका खण्डन करनेके लिए पेश किया गया हो, जो उसने कही हैं, परन्तु जिनके लिए वह यह इन्कार करता हो

कि उसने कभी नहीं कहा है, तो उससे यह प्रश्न पूछा जा सकता है—क्या दूसरे गवाहने ऐसी ऐसी बात कही ? इसमें साधारण नियम क्यों लागू नहीं होता, इस सम्बन्धमें भिन्न भिन्न प्रमाण हैं और उनमें जोरके साथ यह कहा गया है कि पहले दूसरे गवाहसे यह पूछकर, कि जिस समय की निश्चित प्रश्न है, उस समय उसने क्या कहा, उसको खूब थका डालना चाहिए। गवाहसे सिर्फ यही बात नहीं पूछनी चाहिए कि क्या क्या कहा गया, बल्कि यह कि क्या अमुक अमुक भाषाका प्रयोग किया गया, क्योंकि सम्भव है दूसरी तरहपर उन बातोंका खण्डन न किया जा सके जिनके खण्डन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु जब केवल खण्डन करने के ही अभिप्रायसे किसी बात-चीतका सुवृत्त न होजाय, तो बादमें किया जाने वाला प्रश्न बिल्कुल अनुचित होगा।

४ स्मरण-शक्तिको सहायता देना—उस समय इस नियमका प्रयोग न किया जायगा जब कोई शख्स उस सवालका, जो उससे पूछा गया है, सिर्फ याददाश्त (स्मरण-शक्ति) की कमजोरीके कारण जवाब न दे सकता हो। इस तरह जब कोई गवाह जाहिरामें कोई बात भूल गया है और मामूली सवालोंसे उसकी याददाश्तको ताज़ा करने के लिए कीगई सारी कोशिशें नाकामयाब होगई हों, तो ऐसा प्रश्न पूछकर उसका ध्यान उस बातकी ओर आकृष्ट किया जासकता है, जो उस उत्तरकी ओर संकेत करता है जो वाञ्छनीय है। इसका उद्देश्य यह है कि बिना उत्तर वतलाए किसी बातकी ओर उसका ध्यान आकृष्ट करके उसकी याददाश्त ताज़ी कर दी जाय। जब कि एक गवाहने अपने बयानमें यह कहा कि अमुक फर्मके मेम्बरोंका नाम स्मरण नहीं आता लेकिन अगर वह उन्हें देखे तो पहचान सकता है, लाड एलेमबरानें ऐसा करने की इजाज़त दे दी, (देखो अकैरो वनाम पेट्रोनी, Rtark 100)

कभी कभी अदालत ऐसे गवाहसे भी, जो कम उमर होनेकी वजहसे बिना सहायताके उस बातको स्मरण नहीं कर सकता जिसकी निश्चित जांच की जा रही है, ऐसे प्रश्न करने की इजाज़त दे सकती है जो अभिलिखित (वाञ्छित) उत्तर की ओर संकेत करते हैं।

५ वह गवाह जो खिलाफ हो गया हो—अगर कोई ऐसा गवाह, जिसे किसी एक फ्रीकने तलब कराया है, उसके खिलाफ हो जाय या विपक्षीसे जाकर मिल जाय तो अदालत अपने अधिकारसे उससे ऐसे प्रश्न करने की इजाज़त दे सकती है जो प्रश्नकर्ताके वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करते हों, अर्थात् उस पर जिरह करनेकी इजाज़त दे सकती है, (देखो कानून शहादतकी दफा १५४)।

६ पंचीदा मामला—उस समय साधारण नियमका प्रयोग नहीं किया जायगा जब कि गवाह उन प्रश्नोंका, जो उससे सामान्य रीतिसे पूछे गए हैं, इस कारण उत्तर देने में असमर्थ हो कि, जिस मामले के सम्बन्धमें प्रश्न किए गए हैं वह पंचदार है।

साधारण नियमके ऊपर दिए हुए ये छः अपवाद (मुस्तस्नियात) पूरे नहीं हैं। अदालतको इस मामलेमें समयावृत्त कार्यवाई करनेका पूर्ण अधिकार रहता

है और जब कभी उसे न्यायकी दृष्टिसे आवश्यक प्रतीत हो वह वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न पूछनेकी इजाजत दे सकती है। वास्तवमें, जैसा मि० टेलर का कथन है, जजको इस बातका अधिकार है—इसमें अदालत अपील कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती—कि वह किस समय अथवा किस अवस्थामें साधारण नियम के विरुद्ध कार्यवाई कीगई है, परन्तु इस अधिकारका प्रयोग केवल इसी समय करना चाहिए जब कि न्यायके लिए ऐसा करनेकी आवश्यकता हो।

यह काम अदालतका है, सरकारी वकीलका नहीं कि वह इस बातको निश्चय करे कि उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न (Leading questions) पूछने की इजाजत दी जाय, अथवा न दी जाय और ऐसी इजाजत देनेकी सारी जिम्मेदारी अदालतकी ही होती है, देखो 37 C. 467.

जिरह में संकेत करने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं



जिरहमें संकेत करने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं:—वयान खासमें वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्नोंके न पूछने देने के कारण वह प्रश्न उस समय विहेकुल नष्ट हो जाते हैं, जब गवाह पर जिरह होने लगती है, क्योंकि जिस समय गवाह पर जिरह की जाने लगती है, उस समय वह जिरह करने वाले फ्रीकके आमतौर पर खिलाफ होता है। इसलिए कानून शहादतकी दफा १४२में यह व्यवस्था कीगई है कि, “जिरहमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करते हैं।” इस नियमका विस्तार बहुत अधिक नहीं है। जब वह गवाह जिसके वयान लिए जा रहे हैं, उसके मुआफिक हो, तो कभी कभी अदालत जिरह करने वालेको ऐसे प्रश्न करने की आज्ञा न देगी जो वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करते हों।

हार्डीके मुकद्दमें (देखो 24 How. St.Tr.P. 659). में सुबूतके गवाह से मुद्दाअलेहके वकीलने, यह देखकर कि वह गवाह उसके मुआफिक है, एक ऐसा ही प्रश्न (उत्तरकी ओर संकेत करने वाला) पूछा, तो जस्टिस बुलरने यह कह कर प्रश्न पूछने की सुमानियत कर दी कि, “आप जिरह करने में गवाहको इतनी सहायता कर सकते हैं कि उसे उसी बातका उत्तर देनेके लिए प्रेरित करें जिस बातका उत्तर वह चाहता है; परन्तु आप इतना नहीं कर सकते कि गवाह के मुंहमें ठीक २ वही शब्द रख दें जिनको वह दोहरा दे।” लेकिन मार्किन बनाम यून (1836 7 C & P. 408) में मि० आल्डर्सन ने कहा, “मैं समझता हूँ आप वयान खासमें जजकी आज्ञासे ऐसे गवाहसे भी उसे रास्ता दिखाते वाले (Leading questions) पूछ सकते हैं जो इसकी इच्छा नहीं रखता है; लेकिन आप जिरहमें, उसकी ऐसी इच्छा न रहते हुए भी, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं।” तथापि जब इस बातकी इच्छा प्रकट कीगई हो कि गवाह प्रश्नकर्ता की सहायता करना चाहता है, तो गवाहके मुंहमें ठीक वही शब्द रख देना, जो वह वादमें

होहरा दे, बिल्कुल अनुचित है और इससे उसकी शहादतका महत्व बहुत कम हो जाता है (देखो आर० बनाम हार्डी, 1794, 124 St. Tr. 755). इसमें कोई संदेह नहीं कि जब वह गवाह, जिसके ऊपर जिरह कीगई है, अपने खयालात को बदल दे और उस फरीकके सुआफिक कार्रवाई करने लगे तो अगर ऐसी स्थितिसे लाभ उठाकर उससे वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न पूछे जायं तो, उसकी शहादतका जोर बहुत कुछ कम हो जायगा। ऐसी दशामें उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्न पूछना न उचित ही और न न्यायानुकूल ही है, और इसलिये अदालत को इनके लिये इजाजत नहीं देना चाहिए।

पहिले के बयानों के सम्बन्ध में जिरह—कानून शहादत की दफा १४५ में उस क्रायते की व्यवस्था कीगई है कि जिससे जिरह में किसी गवाह के पहिले दिए गए बयान का, जो लिखित है अथवा जो लिख लिया गया है, खण्डन किया जा सकता है। जिरह में गवाह से बिना उसे वह तहरीर दिखलाए यह पूछा जा सकता है कि क्या उसने इससे पहिले कोई ऐसा बयान दिया है जो लिखित है अथवा जो लिख लिया गया है, और जो उसके मौजूदा बयान से भिन्न है और जो उन्हीं बातों के सम्बन्ध में है जो इस समय में पूछी गई हैं और अगर इसका उत्तर 'नहीं' में हो, तो यह दिखलाना चाहिए कि उसने ऐसा बयान दिया था, लेकिन अगर इस प्रश्न का अभिप्राय उसकी किसी तहरीर का खण्डन करना है, तो ऐसा खण्डन करने वाला उत्तर मिलने के पहिले उसका ध्यान उस तहरीर की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए जिसका खण्डन किए जाने को है। उसे उस अवस्था को बतला देना चाहिए जिसमें कि वह बयान दिया गया है जिससे उसे ठीक ठीक उस अवस्था का ज्ञान होजाय जिस अवस्था में वह बयान दिया गया था और उससे यह पूछा जाना चाहिए कि उसने ऐसा बयान दिया है या नहीं। इसका उद्देश्य गवाह को इस बात का मौका देना है कि वह दोनों बयानोंमें होने वाले अन्तर का उत्तर दे सके। कानून शहादत की दफा १४५ का मंशा यह नहीं है कि वह तहरीर उसे अवश्य ही दिखलाई जाय, लेकिन यह कि, अगर इसका इरादा गवाह का खण्डन करना है तो, उसका ध्यान उसके बयान के उस हिस्से की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए जो उसका इस प्रकार खण्डन करने के काम में लाए जाने को है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसे अपनी पहिली शहादत के अध्ययन करने का मौका दे दिया जाय ताकि वह उसके अनुसार अपना उत्तर तैयार कर सके, बल्कि यह कि अगर उसका उत्तर उसकी पहिले दीगई उस शहादत से भिन्न है जो तहरीर में आगई है, और उसके उस खण्डन का मंशा उस मामले में बतौर शहादत पेश किए जाने का है, तो गवाह को इस बात का मौका दिया जाना चाहिए कि वह अपनी सारी बातों का जवाब दे सके, अगर वह ऐसा कर सकता है तो। और अगर उसे यह मौका नहीं दिया जाता, तो वह विरोधात्मक लिखित (मुखालिफ तहरीर) मिसिलमें बतौर शहादत दर्ज न कीजायगी। देखो दुब्लेय बनाम टपसी, 15 W. R. Cr. 23.

है और जब कभी उसे न्यायकी दृष्टिसे आवश्यक प्रतीत हो वह वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न पूछनेकी इजाजत दे सकती है। वास्तवमें, जैसा मि० टेलर का कथन है, जजको इस बातका अधिकार है—इसमें अदालत अभील कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती—कि वह किस समय अथवा किस अवस्थामें साधारण नियम के विरुद्ध कार्यवाई कीगई है, परन्तु इस अधिकारका प्रयोग केवल उसी समय करना चाहिए जब कि न्यायके लिए ऐसा करनेकी आवश्यकता हो।

यह काम अदालतका है, सरकारी वकीलका नहीं कि वह इस बातको निश्चय करे कि उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न (Leading questions) पूछने की इजाजत दी जाय, अथवा न दी जाय और ऐसी इजाजत देनेकी सारी जिम्मेदारी अदालतकी ही होती है, देखो 37 C. 467.

जिरह में संकेत करने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं



जिरहमें संकेत करने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं:—बयान खासमें वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्नोंके न पूछने देने के कारण वह प्रश्न उस समय बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, जब गवाह पर जिरह होने लगती है, क्योंकि जिस समय गवाह पर जिरह की जाने लगती है, उस समय वह जिरह करने वाले फ्रीक्के आमतौर पर खिलाफ होता है। इसलिए कानून शहादतकी दफा १४२में यह व्यवस्था कीगई है कि, “जिरहमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करते हैं।” इस नियमका विस्तार बहुत अधिक नहीं है। जब वह गवाह जिसके बयान लिए जा रहे हैं, उसके मुआफिक हो, तो कभी कभी अदालत जिरह करने वालेको ऐसे प्रश्न करने की आज्ञा न देगी जो वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत करते हों।

हार्डीके मुकद्दमें (देखो 24 How. St.Tr.P. 659). में सुबूतके गवाह स मुद्दाअलेहके वकीलने, यह देखकर कि वह गवाह उसके मुआफिक है, एक ऐसा ही प्रश्न (उत्तरकी ओर संकेत करने वाला) पूछा, तो जस्टिस बुलरने यह कह कर प्रश्न पूछने की मुमानियत कर दी कि, “आप जिरह करने में गवाहको इतनी सहायता कर सकते हैं कि उसे उसी बातका उत्तर देनेके लिए प्रेरित करें जिस बातका उत्तर वह चाहता है; परन्तु आप इतना नहीं कर सकते कि गवाह के मुहमें ठीक वही शब्द रख दें जिनको वह दोहरा दे।” लेकिन मार्किन बनाम यून (1836 7 C & P. 408) में मि० आल्डर्सन ने कहा, “मैं समझता हूँ आप बयान खासमें जजकी आज्ञासे ऐसे गवाहसे भी उसे रास्ता दिखाते वाले (Leading questions) पूछ सकते हैं जो इसकी इच्छा नहीं रखता है; लेकिन आप जिरहमें, उसकी ऐसी इच्छा न रहते हुए भी, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं।” तथापि जब इस बातकी इच्छा प्रकट कीगई हो कि गवाह प्रश्नकर्ता की सहायता करना चाहता है, तो गवाहके मुहमें ठीक वही शब्द रख देना, जो वह वादमें

होना दे, बिल्कुल अनुचित है और इससे उसकी शहादतका महत्व बहुत कम हो जाता है (देखो आर० बनाम हार्डी, 1794, 124 St. Tr. 755). इसमें कोई संदेह नहीं कि जब वह गवाह, जिसके ऊपर जिरह कीगई है, अपने खयालात को बदल दे और उस फरीकके मुआफिक कार्रवाई करने लगे तो अगर ऐसी स्थितिसे लाभ उठाकर उससे वाञ्छित उत्तरकी ओर संकेत करने वाले प्रश्न पूछे जायं तो उसकी शहादतका जोर बहुत कुछ कम हो जायगा। ऐसी दशामें उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्न पूछना न उचित ही और न न्यायालुकुल ही है, और इसलिये अदालत को इनके लिए इजाज़त नहीं देना चाहिए।

पहिले के बयानों के सम्बन्ध में जिरह—कानून शहादत की दफा १४५ में उस बयानकी व्यवस्था कीगई है कि जिससे जिरह में किसी गवाह के पहिले दिए गए बयान का, जो लिखित है अथवा जो लिख लिया गया है, खण्डन किया जा सकता है। जिरह में गवाह से बिना उसे वह तहरीर दिखलाए यह पूछा जा सकता है कि क्या उसने इससे पहिले कोई ऐसा बयान दिया है जो लिखित है अथवा जो लिख लिया गया है, और जो उसके मौजूदा बयान से भिन्न है और जो उन्हीं बातों के सम्बन्ध में है जो इस समय में पूछी गई हैं और अगर इसका उत्तर 'नहीं' में हो, तो यह दिखलाना चाहिए कि उसने ऐसा बयान दिया था, लेकिन अगर इस प्रश्न का अभिप्राय उसकी किसी तहरीर का खण्डन करना है, तो ऐसा खण्डन करने वाला उत्तर मिलने के पहिले उसका ध्यान उस तहरीर की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए जिसका खण्डन किए जाने को है। उसे उस अवस्था को बतला देना चाहिए जिसमें कि वह बयान दिया गया है जिससे उसे ठीक ठीक उस अवस्था का ज्ञान होजाय जिस अवस्था में वह बयान दिया गया था और उससे यह पूछा जाना चाहिए कि उसने ऐसा बयान दिया है या नहीं। इसका उद्देश्य गवाह को इस बात का मौका देना है कि वह दोनों बयानोंमें होने वाले अन्तर का उत्तर दे सके। कानून शहादत की दफा १४५ का मंशा यह नहीं है कि वह तहरीर उसे अवश्य ही दिखलाई जाय, लेकिन यह कि, अगर इसका इरादा गवाह का खण्डन करना है तो, उसका ध्यान उसके बयान के उस हिस्से की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए जो उसका इस प्रकार खण्डन करने के काम में लाए जाने को है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसे अपनी पहिली शहादत के अध्ययन करने का मौका दे दिया जाय ताकि वह उसके अनुसार अपना उत्तर तैयार कर सके, बल्कि यह कि अगर उसका उत्तर उसकी पहिले दीगई उस शहादत से भिन्न है जो तहरीर में आगई है, और उसके उस खण्डन का मंशा उस मामले में बतौर शहादत पेश किए जाने का है, तो गवाह को इस बात का मौका दिया जाना चाहिए कि वह अपनी सारी बातों का जवाब दे सके, अगर वह ऐसा कर सकता है तो। और अगर उसे यह मौका नहीं दिया जाता, तो वह विरोधात्मक लिखित (मुखादिक तहरीर) मिसिलमें बतौर शहादत दर्ज न कीजायगी। देखो दुब्लेय बनाम टपसी, 15 W. R. Cr. 28.

पहिले दिया हुआ बयान उन्हीं बातों के सम्बन्ध में होना चाहिए जो तय की जानी हैं। किसी गवाह का खण्डन उन बातों के सम्बन्ध में नहीं किया जा सकता जो उसकी पहिले बयान की हुई बातों के समान हैं।

पहिले दिये हुए बयान का प्रयोग किसी गवाह को प्रतीतिके अयोग्य सिद्ध करने में किया जा सकता है। कानून शहादत की दफा १५५ (३) में यह बतलाया गया है कि किसी गवाह को विश्वास के अयोग्य सिद्ध करने का एक ढंग यह है कि उसके पहिले के इज़हार (बयान) का कोई हिस्सा उसके दूसरे हिस्से से मिला साबित कर दिया जाय। यह दफा पहिले दिए हुए बयान के सम्बन्ध में ही लागू होती है फिर चाहे वह बयान ज़बानी हो या तहरीरी, और कानून शहादत की दफा १४५ सिर्फ बयान तहरीरी के सम्बन्ध में ही लागू होती है और दफा १५५ (३) सिर्फ किसी गवाह को 'अविश्वासी सिद्ध करने में ही प्रयोग की जा सकती है। किन्तु दफा १४५ की तरह दफा १५५ में साफ़ तौर से यह नहीं बतलाया गया है कि पहिले गवाह का ध्यान उसके बयान के उस हिस्से की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए जिनका प्रयोग उसका खण्डन करने के लिए किया जाना है। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसी नियम पर दृढ़ रहना बिल्कुल ठीक और सुनासिब है [देखो शामलाल बनाम अनन्ती 24 W. R. 312]।

कारपेण्टर बनाम चाल (1840, 3 P & D. 457) में जस्टिस पैटर्सन ने कहा था कि, "मैं इस विस्तृत नियम को पसन्द करता हूँ कि, जब आपका अभिप्राय किसी गवाहके सम्बन्ध में किए गए इज़हार के बारेमें शहादत देने से हो, तो आपको उससे यह पूछना चाहिए कि क्या कभी उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था।"

समर्थन करने के लिए पहिले दिया गया बयान—कानून शहादत की दफा १५७ के अनुसार किसी गवाहका पहिले किया हुआ इज़हार उसकी बादमें दी हुई शहादत का पुष्टी करण करने के लिए साबित किया जा सकता है। लेकिन उसका पहिले का इज़हार उन्हीं बातों के सम्बन्ध में हो और उसी समय दिया गया हो जिस समय वह घटना हुई थी या किसी ऐसे हाकिम के सामने दिया गया हो जिसे कानूनन उसमामले की तहकीकात करनेका अधिकार है।

जिरहमें प्रश्नों से गवाहको अविश्वासी सिद्ध करना—ऊपर बतलाए हुए प्रश्नों (सवाल) के अतिरिक्त जिरह में गवाह से कोई भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका मंशा नीचे के तीन विषयों में से किसी के सिद्ध करने का हो—

- १—उसकी सच्चाई की जांच करना, या
- २—इस बात का पता लगाना कि वह कौन है और समाज में उसकी क्या स्थिति है, या
- ३—उसके चरित्र को बदनाम करके कि वह विश्वास के अयोग्य है

कानून शहादत की दफा १४६ के अनुसार जो अधिकार दिया गया है उसका एक अविवेकी जिरह करने वाला दुुप्रयोग कर सकता है और उसके अविश्वासी सिद्ध करने के बहाने से किसी गवाह के व्यक्तिगत जीवन और चरित्र के सम्बन्ध में आपत्ति जनक प्रश्न पूछ कर उसकी भारी से भारी बे-इज्जती की जा सकती है और उसे दिक किया जा सकता है। इसलिए दफा १४८ में यह व्यवस्था की गई है कि, अगर ऐसा कोई प्रश्न प्रत्यक्ष में आवश्यक नहीं है अथवा उन बातों के सम्बन्ध में नहीं है जिनकी निश्चित-झगड़ा है, बल्कि उसका उसी हद तक उन बातों से सम्बन्ध है कि वह उस गवाह के चरित्र को दूषित सिद्ध करके उसको विश्वास किए जाने के अयोग्य सिद्ध करता है, तो यह फैसला देना अदालत का काम है कि गवाह उसका उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाय अथवा नहीं, और अदालत को अधिकार होगा कि वह गवाह को इस बात से आगाह कर दे कि वह उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। कानून शहादत की दफा १४८ के क्लॉज़ (१), (२) और (३) में, इस सम्बन्ध में कुछ नियम बतलाए गए हैं कि अदालत को अपने इस अधिकार का किस तरह प्रयोग करना चाहिए।

ऐसे प्रश्न, जिनसे गवाह के विश्वासपात्र न होने के सम्बन्ध में कोई बात सिद्ध होती हो, बिना माकूल वजह के नहीं पूछे जाने चाहिए देखो कानून शहादत की दफा १४९—अगर अदालत की यह राय है कि बिना माकूल वज्रहात के ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था, तो वह इस मामले की रिपोर्ट अधिकारियों के पास उसपर मुनासिब कार्रवाई करने के लिए कर सकती है (देखो दफा १५०)—कानून शहादत की दफा १४९ के उदाहरणों से यह प्रकट होता है कि ये माकूल वज्रहात कौन सी हो सकती हैं और कौन सी नहीं। यह कह देना काफी न होगा कि इसके लिए इजाज़त दे दी गई थी। वकीलों का किसी के ऊपर धोखेवाज़ी या अपराध का दोष लगाना उचित न होगा जब तक कि उनको स्वयं इस बात का विश्वास न होजाय कि उन्हें सामने रखने के लिए माकूल वज्रहात मौजूद हैं [देखो वेस्टन बनाम प्यारैमोहन, 18 C. W. N. 185; 40 C. 898]।

यह बात वकालत पेशे के बिल्कुल विरुद्ध है कि कोई वकील किसी गवाह से उन बातों के सम्बन्ध में जिरह करे जिन्हें वह स्वयं जानता है। और उसका भविकल नहीं जानता जब जिरह के दौरान में वकील किसी गवाह के ऊपर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई दोषारोपण करे, तो अदालत यह पूछ सकती है कि क्या उसने आज्ञा मिलने पर ऐसा दोषारोपण किया है, और, अगर 'हां' कहे तो, किसकी आज्ञा मिलने पर?। वकीलों को उसी अवस्था में इसकी आज्ञा दी जा सकती है जब विपक्षी पर उनकी बात प्रकट होने से उनकी रक्षा करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता प्रतीत हो। अदालत के विरुद्ध इसके लिए कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

जब किसी गवाह ने किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया हो जो उसकी प्रतीति को उठा देने के लिए ही ठीक है, तो उसका खण्डन करने के लिए शहादत न

दीजायगी, लेकिन अगर वह ग़लत जवाब देता है, तो उसपर दोगहलफ़ी का इलज़ाम लगाया जा सकता है।

किसी गवाह को विश्वास किए जाने के अयोग्य सिद्ध करने के लिए बतलाए गए भिन्न भिन्न ढंग संक्षेप में इस प्रकार रखे जा सकते हैं:—

१—जब वह प्रश्न, जो जिरह में गवाह की प्रतीति (विश्वास) घटाने के लिए पूछा गया है, ठीक उन्हीं बातों के सम्बन्ध में हो जिनके ऊपर झगड़ा है, तो किसी भी शहादत से उसके उत्तर (जवाब) का खण्डन किया जा सकता है [देखो कानून शहादत की दफ़ा १५३ का उदाहरण (सी)].

२—आमतौर पर गवाह के विश्वास योग्य होने में जिरह करते समय आपत्ति की जा सकती है [देखो कानून शहादत की दफ़ा १३८, १४०, १४५-१५२, १५४]

३—अगर जिरह में किया गया प्रश्न उन्ही हद तक ठीक हो जिस हद तक उससे किसी गवाह की प्रतीति (विश्वास) पर प्रभाव पड़ता है, तो सिवाय दो मंशाओं में उसके उत्तर का खण्डन न किया जा सकेगा देखो कानून शहादत की दफ़ा १५३.

४—किसी गवाह को विश्वास के अयोग्य सिद्ध करने का, जिरह ही एक मात्र उपाय नहीं है। यह स्वतन्त्र साक्षी (आजाद शहादत) देकर भी अर्थात् दूसरे गवाहों की शहादत से भी किया जा सकता है। कानून शहादत की दफ़ा १५५ में बतलाया गया है कि चार प्रकार से ऐसा किया जा सकता है:—

(१) उस गवाहके झूठे होनेके सम्बन्धमें, दूसरे गवाहोंकी दीगई शहादतसे जो वे अपनी जानकारी से दें।

(२) घूस (रिश्वत) खा लेने या अन्य प्रकार के ऐसे दुष्टाचरण की शहादत से।

(३) पहिले दीगई शहादत के एक जैसी न होने का सुबूत मिल जाने से। और

(४) बलात्कार (ज़िना बिलजब्र) की हालत में अभियोग लगाने वाली आमतौर पर बद-चलन होनेकी शहादत से।

विश्वास-पात्रता सम्बन्धी जिरह का दुरुपयोग—उन लोगों की, जिन्हें अदालतों में शहादत देने के लिये जाना पड़ता है, यह आम शिकायत है कि गवाहोंके विश्वास-पात्र होने के सम्बन्ध में की जाने वाली जिरह के लिये दिए गये अधिकारका बहुत ही अधिक दुरुपयोग किया जाता है और उनसे उनके कौटुम्बिक जीवन, वैयक्तिक बातों, पहिले किसी समय की भूलों, बहुत दिन पहिलेके आचरण की उलझलता तथा हज़ारों ऐसी ही बातों के सम्बन्ध में प्रश्न करके, जिनका उसकी सच्चाई अथवा उन बातों से, जिनकी निस्वत झगड़ा है, कोई सम्बन्ध नहीं है, उनका अपमान किया जाता है परन्तु दुर्भाग्य से यह शिकायत निराधार नहीं

है। यह बात सत्य है कि जज को अधिकार है कि गवाह की इन बातों से रक्षा करे और अपने इस अधिकार का प्रयोग करके ऐसे अनुचित प्रश्नों के पूछने की आज्ञा न दे। लेकिन यह बात उसी समय की जाती है जिस समय जिरह करने वाला ऐसे दुःख पहुंचाने वाले प्रश्न करता है और यह देख कर कुछ संतोष होता है कि अन्तमें जज गवाह को ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से रोकता है। इसलिये पहिले तो इस बात का अधिकार जिरह करने वाले को ही नहीं है। उसे बुद्धिमानी से और मानमर्यादा के खयाल से और इस खयाल से कि उसके पेशे का भी अन्याय न हो, इस बात का विचार करना चाहिए कि क्या अन्तःकरण ऐसे प्रश्नों के पूछने की आज्ञा देता है? प्रायः यह देखा गया है कि वह गवाह भी, जो एक छोटी सी बात को साबित करने के लिये तलब किया गया है जिसकी निश्चित वास्तवमें कोई झगड़ा भी नहीं है अथवा जिसका बहुत ही कम महत्व है, इस अपमान से नहीं बचा है। उससे उसके व्यक्तिगत जीवन के सम्बंधमें अथवा वैयक्तिक बातों के सम्बंध में बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें सारी अपमान जनक बातें भरी रहती हैं। किसी गवाह पर ऐसे निरंकुश आक्रमण करने में लोगों को बड़ा आनन्द मालूम होता है और विपक्षी ऐसे मौके को पाकर सारी बातें कह डालता है। वह जिरह करने वाला, जो इस प्रकार अपने आपको एक विवेकहीन मवक्किल के हाथ की कठपुतली बना देता है, अपना कर्तव्य पालन नहीं कर पाता और गवाह को ऐसी क्षति पहुंचाता है जिसकी पूर्ति का उपाय उस गवाह के पास नहीं रह जाता।

मि० टेलर की पुस्तक से यह निम्नलिखित उदाहरण शिक्षाप्रद सिद्ध होगा:-

किन्तु यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जब वे बातें जिनके सम्बंधमें गवाह से प्रश्न किये जाते हैं, मामले का एक आवश्यक अंग हों, तो वह उनका उत्तर देने के लिए बाध्य होगा, चाहे उससे स्वयं उसके ही आचरण के ऊपर क्यों न आक्षेप होता हो। वास्तव में केवल इसी कारण से किसी गवाह को किसी प्रश्न का उत्तर देने से रोकना जैसा अन्याय है वैसा ही नीति विरुद्ध भी है कि उससे उसका अपमान होगा, जब कि उसकी शहादत या तो उचित न्याय के लिए आवश्यक है या किसी प्रजा की सम्पत्ति सिद्धि, स्वतंत्रता अथवा जीवन की रक्षा के लिये। परन्तु जब प्रश्न प्रत्यक्ष मामले से कोई विशेष सम्बंध नहीं रखता बल्कि सिर्फ उस गवाह के चाल-चलन की जांच करने और इसके परिणाम-स्वरूप उसके विश्वास किए जाने की योग्यता अथवा अयोग्यता की जांच करने के लिये ही पूछा गया है, तो उसपर सन्देह करने का बहुत कुछ अवसर है। पुराने बहुत से प्रमाणों और कहावतों से यह प्रकट होता है कि ऐसी अवस्थाओं में गवाह ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है; लेकिन यह अधिकार, अगर वह अब भी बना हुआ है तो, इस वर्तमान युग में भी बहुत कुछ घुरी तरह पर प्रयोग किया जाता है और उसका कोई उचित विरोध नहीं किया जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत से ऐसे मामले पैदा हो सकते हैं जिनमें जज अपने अधिकार का प्रयोग करके गवाहों की, ऐसी अनावश्यक और अनुचित छेड़-छाड़ से, रक्षा कर सकता है। उदाहरणार्थ, ऐसी अपमान जनक बातों के संबंध में जो बहुत पहिले हुई हैं, किए जाने वाले प्रश्नों को रोका जा सकता है; क्योंकि

न्याय कभी इस बात को नहीं चाहता कि किसी मनुष्य के जीवन में हुई वे भूलें जिनके लिये बहुत समय पहिले वह पश्चात्ताप प्रकट कर चुका है और जिनके लिये समाज ने उसे क्षमा भी कर दिया है, किसी बाद के मुकद्दमें बाज़ की इच्छा से खोद निकाली जायं। इसलिए आचरण के अनौचित्य के सम्बन्ध में किये गये प्रश्नों को जितने इस बात का अनुमान कर लेने के लिये कोई कारण नहीं उत्पन्न होता कि जो गवाह उन बातों का दोषी है वह कभी सच्चा और विश्वासपात्र आदमी हो ही नहीं सकता, रोकना बिल्कुल ही उचित है। लेकिन इस प्रकार की रक्षा के सिद्धान्त का प्रयोग ऐसे मामलों में नहीं किया जाना चाहिये जिनमें जांच उन बातों के सम्बन्ध में की जा रही हो जो अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय की हैं और जिनका उस गवाह के चरित्र और उसके सत्याचरण से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऐसी अवस्थाओं में किसी शख्स को प्रश्नों के उत्तर देने के सम्बन्ध में कोई विशेष अधिकार न देना चाहिये, चाहे उत्तरसे उसका अपमान ही क्यों न होता हो।

इस सम्बन्ध में लॉर्ड चीफ़ जस्टिस क्रॉफ़ बर्न ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है:—

“मुझे भारी दुःख है कि वकील लोग प्रायः बिना जरूरत ऐसे प्रश्न पूछा, करते हैं जिनसे गवाहों के व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव पड़ा करता है, जिनका पूछना उसी समय उचित है जब उनके कोई गवाह विश्वास किये जानेके अयोग्य सिद्ध होता हो। मैंने बहुत ध्यान पूर्वक फ्रान्स, जर्मनी, हॉलैण्ड, बेल्जियम, इटली स्पेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका (U.S.A.), कनाडा और आयरलैण्ड में होने वाले न्याय को देखा, परन्तु किसी भी स्थान में मैंने गवाहोंको इस तरह तंग किये जाते और डांटे जाते हुये नहीं देखा जैसा कि इंग्लैण्ड में। जिस प्रकार हम अपने गवाहों के साथ व्यवहार करते हैं वह हमारे राष्ट्र के लिये बहुत ही अपमान जनक है, और इससे न्यायमें सहायता मिलने के बदले रुकावट पड़ती है। इंग्लैण्ड में माननीय और शुद्ध अन्तःकरण वाले व्यक्ति शहादतमें जाना बहुत ही घृणास्पद कार्य समझते हैं। प्रत्येक श्रेणी के पुरुष और स्त्रियां हमारी अंग्रेज़ी अदालतोंमें होने वाली जिरह में की जाने वाली बेइज्जती और परेशानी से बहुत कुछ घबराते हैं। आप देखें कि गवाहों के कउचरे में जाते समय गवाह कैसे थरा उठते हैं। मुझे स्मरण है कि मैंने सर बेजामिन ब्रॉडी प्रतिष्ठित पुरुष को भी इजलास के सामने जाते समय कांपते हुये देखा है। मैं सादस के साथ यह कह सकता हूँ कि उनको इस बात के भय से अत्यंत वेदना हो रही थी।”

फ्रांकेन के आचरण संबंधी शहादत—कानून शहादत की दफा ५२ के अनुसार जब किसी दीवानी मुकद्दमें में चाल-चलन की निश्चित कोई मामला न हो, तो उस मुकद्दमें से सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति के आचरण के सम्बन्ध में इस बातकी दिखलाने के इरादे से शहादत नहीं दी जा सकती कि उसके आचरण के ऊपर जो दोषारोपण किया गया है वह संभव है अथवा असंभव। चाल-चलन संबंधी

शहादत आवश्यक है, सिवाय उस हद या हालत में जब कि ऐसा आचरण उन बातों से प्रकट होता हो जो दूसरी तरह पर आवश्यक और प्रासंगिक हैं। कानून शहादत की दफा ५२ में आया है “उस मुकदमें से सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति (Any person Concerned.)” लेकिन वास्तवमें इसका अर्थ उस मुकदमें के फरीकैन से है। यही बात गवाहों की, जो उनके आचरण पर हमेशा दोषारोपण किया जाना चाहिए ताकि उनकी सचाई की परीक्षा हो जाय अथवा उनके आचरण को दूषित सिद्ध कर वह विश्वास किए जाने के लिये अयोग्य सिद्ध कर दिया जाय (देखो कानून शहादत की दफा १४६)।

इसलिये दीवानी मुकदमों में फरीकैन के अच्छे अथवा बुरे चाल चलन के होने के सम्बन्ध में दी गई शहादत अनावश्यक होगी, जब तक कि चाल चलन के सम्बन्ध में शहादत का होना अनिवार्य न हो। फरीकैन के चाल चलन के सम्बन्ध में दी जाने वाली शहादत को स्वीकार करना उसके सम्बन्ध में पहिले से ही अपने विचार निश्चित कर लेनेकी आज्ञा देना है। अगर चाल-चलनसे दीवानी मुकदमों में होने वाले मुकसानसे कोई असर पड़ता है, तो वह आवश्यक हो जाता है (देखो कानून शहादत की दफा ५५) किन्तु पहिले अच्छे आचरण का होना कौजदारी मुकदमों में उपयुक्त है (दफा ५२)। आचरण में मनुष्य की प्रसिद्ध और उसका स्वभाव दोनों शामिल हैं [देखो कानून शहादत की दफा ५५ का विवरण]।

स्वयं अपने गवाह पर ही जिरह करना—यह देखा गया है कि अगर विपक्षी इस पर कोई आपत्ति करता है, तो बयान खास में ऐसे प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दी जा सकती जो प्रश्न-कर्ता के वाञ्छित उत्तर की ओर संकेत (इशारा) करने वाले हों। परन्तु उस समय इस नियम का पालन नहीं किया जा सकता जब गवाह उसी पक्ष के विरुद्ध हो जाय जिसने उसे तलब कराया है। ऐसे मामले में अदालत को अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से किसी फरीक को अपने गवाह से कोई भी ऐसा प्रश्न पूछने की आज्ञा दे देवे जो जिरह में पूछा जा सकता है, अर्थात् वह उत्तर की ओर संकेत करने वाले प्रश्न (Leading questions) पूछने की, दूसरे शब्दों में जिरह करने की, आज्ञा दे सकती है। “विरुद्ध” शब्द के ऊपर इंग्लैण्ड में बहुत से एक दूसरे के विरोधी फैसले हुये हैं। कुछ जजोंकी राय है कि विरुद्ध शब्द से तात्पर्य है विरोधी भाव रखना, और कुछ की राय में गवाह उस समय भी विरुद्ध समझा जायगा जब उसकी शहादत उस शङ्स के प्रतिकूल सिद्ध हो जिसकी ओर से वह तलब किया गया है।

कोल्स बनाम कोल्स-1866 L. R. I. P. & D. 70; 71—में जस्टिस वाइड ने कहा था:—“विरुद्ध गवाह वह है जो वह शहादत नहीं देता जिसे वह शङ्स, जिसने उसे तलब कराया है, चाहता है कि वह दे। विपरीत भाव रखने वाला गवाह वह है जिसके शहादत देने के ढंग से यह जान पड़ता हो कि वह अदालत को सच सच बातें न बतलावेगा।” व्यवस्थापक-सभा ने दफा १५४ में “विरुद्ध, (Adverse.)”, “अनिच्छुक (Unwilling)” अथवा “विपरीत

(Hostile)" शब्दों का प्रयोग नहीं किया है और इस बात को बिल्कुल अदालत की मर्जी पर छोड़ दिया है। दफा १५४ में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसी गवाह को विपरीत भाव रखने वाला समझने में सहायक हो सके, लेकिन उसमें यह व्यवस्था कर दी गई है, कि, अदालत को अधिकार है कि वह किसी फ्रीक को, जिसने गवाह को तलब कराया है, उससे ऐसा प्रश्न करने की आज्ञा दे दे जो जिरह में पूछा जा सकता; देखो बैकुण्ठ बनाम प्रसन्नमयी, 27 C. W. N. 797.

गवाह की मामले में उदासीनता, सत्य को छिपाने की इच्छा, इस वहाने से, कि स्मरण नहीं रहा, प्रश्नों का उत्तर देने की अनिच्छा, उसके विपरीत भावों को, जोकि उसके, मित्राज, ठंग इत्यादि से प्रकट होते हों, तथा दूसरी तमाम बातों को ध्यान में रखना चाहिए और यह काम अदालत का है कि वह हर मामले में यह तय करे कि क्या गवाह ने ऐसे विपरीत भावों का प्रदर्शन किया है जिससे उसका गवाह के ऊपर जिरह करने की इजाजत का देना उचित है।

केवल इस बात से, कि कोई गवाह सेशनल की अदालत में उन बयानों से बिल्कुल भिन्न बयान देता है जो उसने किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में दिए हैं, कोई गवाह विपरीत भाव रखने वाला नहीं कहा जा सकता। गवाह विपरीत भाव रखने वाला तभी समझा जायगा जब कि वह सत्य को छिपाकर उस पक्ष को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा हो; देखो कालाचांद बनाम महाराणी 13 C. 53 P. 56; सरकार बनाम सत्येन्द्र, 37 C. L. J. 173; और लक्ष्मीराम बनाम राधाचरण 34 C. L. J. 107. गवाह विरुद्ध उसी हालत में समझा जायगा जब जज की राय में वह उस फ्रीक के विरुद्ध भाव रखता हो जिसने उसे तलब कराया है, उस हालत में नहीं जब कि उसकी शहादत से उसके सुवृत का खण्डन होता हो, देखो सुरेन्द्र बनाम रानी दासी, 24 C. W. N. 860.

जब किसी गवाह पर उस फ्रीक की ओर से जिरह की जाय जिसने उसे तलब कराया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कुछ शहादत पर तो विश्वास किया जाय और कुछ पर विश्वास न किया जाय, बल्कि वह कुल शहादत अलग कर दी जानी चाहिए। इससे गवाह की साख बिल्कुल उठा दी जानी चाहिए। केवल इतनाही काफी न होगा कि उसकी शहादत का एक अंश ही अलग कर दिया जाय; देखो सरकार बनाम सत्येन्द्र, 37 C. L. J. 173; 71 L. C. 657; सुरेन्द्र बनाम रानी दासी, 24 C. W. N. 860.

क्या कोई फ्रीक अपने ऊपर जिरह कर सकता है, जबकि विपक्षी (फ्रीक सानी) ने उसे शहादत में तलब किया हो?—लार्ड अडकिन्सन ने किशोरीलाल बनाम चुनौती लाल [31 A. 116 P. C.] में कहा था—“यह एक कमजोर और नीचे दर्जे की वकालत की चाल है कि हर एक मुद्दे या मुद्दाअलेह अपने विरोधी पक्ष (विपक्षी) को शहादत में तलब कराये, इस इरादे से कि हर एक फ्रीक इस तरह तलब किया हुआ विपक्षी शहादत में तलब होने के लिए बाध्य होगा और इस तरह पर हर एक पक्ष के वकील को इस बात का मौका मिलेगा कि वह

पर जिरह कर सके। यह एक ऐसी प्रथा है जिसे, लाहं महोदयों की राय में, सभी अदालतों को बेसीही अधूरी समझना चाहिए, जैसी कि वह काबिल एतराज़ है [देखो 32 A. 104 P. C.; 1913. M. W. N. 826.] एक हालके मुकदमों में यह तय किया गया है कि, जब कोई गवाह किसी ऐसी अवस्था में हो जिससे उसका उस शख्स के विरुद्ध होजाना स्वाभाविक हो, जो उसकी शहादत को चाहता है तो, उस गवाह को तलब करने वाले फरीक को यह अधिकार नहीं है कि वह उसपर जिरह कर सके, क्योंकि यह बात पूरे तौर पर अदालत के हाथ में है कि वह कानून शहादत की दफा १५४ के अनुसार उस गवाह को तलब करने वाले शख्स को ऐसे प्रश्न पूछने की आज्ञा दे सके जिन्हें फरीक मुखालिफ़ जिरह में पूछ सकता था; देखो लच्छोराम बनाम राधाचरण, 49 C. 93.

अदालत के प्रश्नों के उत्तर में कहीं गई बातों के ऊपर जिरह—कानून शहादतकी दफा १६५ अदालत को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी गवाह से अथवा किसी भी फरीक से किसी भी बात के सम्बन्ध में (वह प्रासंगिक हो अथवा अप्रासंगिक)—किसी भी रूपमें अपनी इच्छानुसार कोई भी प्रश्न पूछ सके, और विषय अदालत की इजाज़त से फरीकन को कोई अधिकार न होगा कि वे अदालत द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर के ऊपर कोई जिरह कर सकें।

लेकिन जब किसी गवाह को अदालत ने ही तलब किया हो, तो यह दफा १६५ लागू नहीं होती और उसपर कोई भी फरीक जिरह कर सकता है, देखो सारिणी बनाम सारदा 11 W. R. 468. P. C.; गोपाल बनाम माणिकलाल 24 C. 288.

कबो जिरहों में हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध में अदालतका अधिकार—गवाहों पर जिरह करते समय वकील के अधिकारों में जज का हस्तक्षेप करना हमेशा अच्छा नहीं होता। लेकिन जब इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाता हो, तो यह बिल्कुल उचित होगा कि जज ऐसी जिरहों के ऊपर अपने शासन से काम ले जो आवश्यकता से अधिक विस्तार धाली हों। गवाहों पर उचित सीमा से अधिक जिरह न की जानी चाहिए, यद्यपि जो प्रश्न पूछे गए हैं वे तर्क शास्त्र की दृष्टि से ठीक ही क्यों न हों; देखो 4 C. W. N. Cxxi (Golden River Mining Co. V. Boxton Mining Co., 97 Fed. Rep. 414, Am. cited) जगत कुमारी बनाम विसेसुर [16 C. W. N. 265.] में चीफ़ जस्टिस जेकिन्स के रिमांक देखिए।

कबो चौड़ी जिरहें करके, जिससे मामले के फ़ैसले में बिलम्ब हुआ, इस अधिकार का दुरुपयोग करते देख कलकत्ता हाईकोर्ट ने नीचे लिखी बातें कही हैं:—

“(क) अदालत का यह कर्तव्य है कि वह अपनी मर्जी से ऐसी बातों के सम्बन्ध में बयान लेने या जिरह करने की इजाज़त देने से इन्कार करदे जो अप्रा-

संगिक हों अथवा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में किसी दूरिवर्ती अथवा एक ही जैसे उद्देश्य से सम्बन्ध रखती हों, अभियुक्त के अपराधी या निरपराधी होने के प्रश्न से नहीं, या जिनका मंशा अप्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष में उन बातों के प्रकटीकरण का हो जिसका प्रकट करना भारतीय कानून शहादत की दफा १२५ से रोक दिया गया है। यह कर्तव्य केवल कानून शहादत से सम्बन्ध ही नहीं रखता है बल्कि सीधे उससे पैदा होता है। यही बात कानून के इस नियम के सम्बन्ध में भी लागू होती है कि अदालत किसी गवाह के उस उत्तर को, जो केवल विश्वास (प्रतीति) के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दिया गया है, कतई समझ लेगी, और सिर्फ उस प्रश्न में बतलाई गई तजवीज के पेश करने को ही यह न मान लेगी कि वह उसके लिए किसी बुनियाद को जाहिर कर रही है।

(ख) भारतीय कानून शहादतके उन नियमोंमें, जो इस समय हैं, अनावश्यक बातों के निकाल देने के सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है और इस कानून की भाषा से (देखो दफा ५, ६१, ६४, १३६, १६५) यह प्रकट होता है कि व्यवस्थापक सभा का यह मंशा था कि अदालत, फ्रीकैन की ओर से किए गए एतराजात का कुछ भी खयाल न करके, कानून के इन नियमों का अवश्य पालन करावे। जूरी के सामने फौजदारी मामलों में यह बात साफ़तौर पर मानली गई है कि ज्योंही कोई गवाह ऐसी शहादत देना शुरू करे जो नाकाबिल तस्लीम है, त्योंही अदालत को उसे रोक देना चाहिए, चाहे फ्रीकैन ने इसपर एतराज किया हो या न किया हो [देखो 10 B. H. C. R. 498; 7 W. R. Cr. 25]. ऐसे मामलों में यह बात बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा इस सन्दर्भमें रहना जोखिम से खाली नहीं है कि बाद में जूरी के सामने इस बात का प्रयत्न कर लिया जायगा कि वह केवल कानूनी शहादत के ही ऊपर अपना फैसला दे। रही बात दूसरे फौजदारी और दीवानी मामलों की उनमें अभी यह बात आमतौरपर उन्हीं प्रश्नों तक सीमाबद्ध है जो उस मामले के लिए बहुतही ज़रूरी हैं, और वर्तमान कानूनके अनुसार जजको अधिकार है कि वह किसी भी अनावश्यक शहादत को निकाल दे।

(ग) यह बहुत ही ज़रूरी है कि अदालतों के हाकिम उन अधिकारों को ध्यान में रखें जो उन्हें भारतीय कानून शहादत के अनुसार दिए गए हैं और उन्हें चाहिए कि वे इन अधिकारों का प्रयोग करते समय उसका उपयोग अनावश्यक और अनुपयुक्त बातों के ऊपर की जाने वाली जिरहों और आवश्यकता से अधिक लम्बी लम्बी जिरहों के लिए, जो उपयुक्त बातों के सम्बन्ध में ही की जाती हों, इजाज़त न दें [देखो Rule 54 A. G. R. & C. O. Chap. I. Vol. I.]

बयान मुकरर (फिर बयान का लिया जाना)—किसी गवाह के दुबारा फिर बयान लेने का अधिकार सिर्फ उसी समय पैदा होता है जब विपक्षी (फ्रीकैन मुखालिफ) उसपर जिरह कर चुके और जैसा कि कानून शहादत की दफा १३६ में बतलाया गया है यह उन बातों को साफ़ करने के लिए लिया जायगा जिनका

बल्लेख जिरह में किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि संदिग्ध बातों का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाय, अगर ऐसी कोई बात है, अथवा उस विभिन्नता को दूर करने का अवसर (मौका) दिया जाय जो बयान खास और जिरह के बीच मालूम होती हो। बिना अदालत की आज्ञा के दुबारा बयान लेते समय कोई नई बात न पूछी जा सकेगी, और अगर इसके लिए इजाजत दे दी जायगी तो विपक्षी को यह अधिकार होगा कि वह उस मामले के सम्बन्ध में फिर जिरह कर सके (देखो दफा १३८)

दुबारा बयान (बयान सुर्कर) लेते समय ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते जो वांछित उत्तर की ओर संकेत करते हों देखो कानून शहादत की दफा १४२— अगर वकील किसी गवाह से ऐसी बातों के ऊपर जिरह करता है जो आरम्भ में और बयान खास के दौरान में शहादत में तस्लीम किए जाने के काबिल नहीं थी; तो दूसरे पक्षको यह अधिकार है कि वह ऐसी बातों के सम्बन्ध में उस गवाह के फिर से बयान ले। अगर बयान खास में कोई प्रश्न छूट गया है, तो वह बात जिरह में हरगिज़ नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि वह जिरहसे पैदानहीं होती, लेकिन वकील इस सम्बन्ध में जज से जांच करने की प्रार्थना (दरखवास्त) कर सकता है; और ऐसी दरखवास्त मंजूर कर ली जाती है।

अन्तिम वक्तव्य

गवाहों से प्रश्न और जिरह करने का आवश्यक विषय हमने संक्षेपसे ऊपर लिखा है। प्रायः मुकद्दमों में शहादत से जोरदार और कमजोर होजाते हैं। हम देखते हैं कि मवक्किल अक्सर ऐसा वकील करना पसन्द करते हैं कि जो विपक्षीके गवाहों और विपक्षीसे खूब जिरह करे, उन्हें अदालतके सामने अपमानित करे, बेईमान, धोखेवाज जालसाज बनाने की कोशिश करे ज्यादा बक बक करता रहे। मैं अपने भाइयों को सलाह देता हूँ कि उनकी यह भूल है कभी ऐसे वकील को पसन्द न करें, प्रायः हाकिम का मिज़ाज खराब होजाता है और मुकद्दमों पर खराब असर पड़ता है। हमने जो गुण वकील के तत्सम्बन्धी विषय में बताये हैं उनपर ध्यान रखकर मामला सिपुर्द करें।

प्रिय वकीलोंसे यह निवेदन है कि जिस बातमें मवक्किलका हित हो वही बात करें उसके कहने में आकर मुकद्दमों को खराब न होने दें और प्रमाणसे अधिक दबसे बकते दें। मुझे तो यह अनुभव है कि यद्यपि जिरह या सवालातके नियम अंगरेज़ी किताबों में बहुत ज्यादा बताये गये हैं बड़ी बड़ी किताबें इस बारे में लिखी गयी हैं और ऐसे विद्वान वकील हैं जो उन सब सिद्धांतों को भलीभांति जानते हैं और उनपर लेक्चर दे सकते हैं जो सिद्धांत सवालात व जिरह के लिये किताबों में लिखे गये हैं पर जब उन्हें स्वयं अदालत में कठघरे के भीतर जाना पड़ता है और उनका उसी अदालत का साथी वकील जिरह करने लगता है तो उन्हें व्याकुलता पैदा हो जाती है और भारी परेशानी होती है।

जब कोई शख्स अदालत में जाकर केवल अपने पवित्र अन्तःकरण द्वारा विस्तृत सच सच सब बातें बयान कर देना चाहता है तो यह ईश्वरीय नियम है कि उसे चाहे जैसे लायक से लायक वकील जिरह करें कभी बिगाड़ नहीं सकते बल्कि जितनी जिरह की जावेगी उतनी ही उसकी सब बातें अधिक मजबूत और अत्यंत सुदृढ़ हो जावेंगी। इसलिये हमारे यहां यह कहावत है कि "सांच को आंच नहीं लगती"

इस सिद्धांत के ऊपर कानून शहादत में कुछ दफाएं बना दीगयी हैं। गवाही देना सार्वजनिक एक पवित्र काम है। समाज के दोषों के मिटाने के लिये गवाहों की ज़रूरत पड़ती है। उस मामले के जानने वाले व्यक्तियों की गवाही इसलिये ली जाती है कि सच का पता चल जाय और उसीके अनुसार न्याय कर दिया जाय। सच सच कहनेसे सची गवाही नहीं मानी जा सकती बल्कि निष्कण्ट सच और पवित्र अन्तःकरण द्वारा सच बोलने से मानी जायगी। सत्य में जो प्रभाव इसको पाठक अच्छी तरह से जानते हैं। आज कल हम देखते हैं कि ऐसी सच गवाही देने वाले महारमा हज़ारों में एक होंगे।

अदालतका कानून भी ऐसा है कि ऐसी कुछ बातोंमें शहादतकी ज़रूरत बताता है कि जो प्रायः वैसी बातोंमें उस तरहकी शहादत नहीं हुआ करती। कुछ तो कानूनके सबसे और कुछ स्वभाव पड़ जानेके कारण और कुछ जिस पक्षकी ओरसे शहादत देनेको हैं उसके मुक़ाहिज़ आदिके कारण और कुछ अपनी कही हुई झूठी बातके समर्थन करनेके कारण गवाहोंको झूठ बोलना पड़ता है।

वकील, उस गवाहके ऊपर जिरह करके अपने पक्षकी समर्थक बातों को मजबूरन कहला लेते हैं जो किंचित मात्र भी झूठ बोला है जो बात वह झूठ बोला है उसीके सम्बन्धमें सैकड़ों सवाल पूछकर कहीं न कहीं उसे गड़बड़ें डाल दिया करते हैं। जिरह झूठे पर कारगर होती है सच्चे पर नहीं।

जिरहमें एक और मुश्किल गवाहको यह पड़ती है कि वकील तो अपने मनमें एक लाइन सवालोंकी निश्चित कर लेता है और पीछेसे पूछ जाने वाले सवालातकी बंदिश पहिलेके सवालों में कर लेता है यह बात गवाहको नहीं मालूम होती इसीलिये वह बीचमें फंस जाता है और फंसने पर घबराहट पैदा होती है यह सिद्धान्त अक्राह्य है कि एक झूठके समर्थन करने के लिए जितनी बातें कही जायंगी प्रायः वे सब झूठी बातें होंगी। वकील, गवाहकी वह बात देखकर कि कहां पर वह झूठ बोला है उसी जगहसे जिरह शुरू कर देता है और कुछ महनोत्तरोंके बाद गवाहको ज्ञान होने लगता है कि मैं फंस रहा हूँ उस समय धीरे, धीरे गवाह अपनी बुद्धिसे काम लेकर कभी तो निकल जाते हैं और अक्सर फंस जाते हैं।

मैं एक मुक़दममें बम्बई कोर्टमें काम कर रहा था वहां पर एक मशहूर जिरह करने वाला बैरिस्टर मि० वेल्लेकरने एक पढ़े लिखे गवाहसे कुछ सवाल किये, सवालोंके शब्द तो सुझे याद नहीं हैं पर उनका मतलब इस प्रकार था—

क्या आपने यह तहरीर लिखी है ?

आपने उसे लिखकर पीछे लिखाने वाले ... को सुनाई थी ?

क्या आप यह समझ गये थे कि उसने इस तहरीरको भली भाँति समझ लिया है ?

इस तहरीरके कौन कौन से शब्दोंके अर्थ आपसे उसने पूछे ?

बताइये कि यह बात आप कैसे समझ गये कि वह समझ गया है ?

सवाल छोटे २ हैं पर इन्हें चढ़ाव उतारकी भाषामें लाकर गवाह पर मजबूत असर पड़ जाता है।

सारांश यह है कि जिरह वकीलका भूषण है औरव कीलको जिरहकी लाइनों तथा सिद्धान्तोंका अध्ययन करना चाहिये, सीखना चाहिये और उसमें उन्नति करते रहना चाहिये । हमने ऊपर जिरह व सवालातका दिग्दर्शन करा दिया है यह कौशल बहुत ही विस्तृत है अभ्याससे आजाता है और नये वकील यदि इस कलाको जानना चाहें तो जान सकते हैं पर उन्हें इस कलाका चिंतन सदैव करना चाहिये ।

दि इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट नं० १६ सन् १९०८ ई०

नारदसूत्रसिद्धिः नारदसूत्रसिद्धिः

०३१०११ दश ३१ ०३ दश

दि इण्डियन रजिस्ट्रेशन

ऐक्ट नं० सन् १९०८ ई०

दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री सम्बन्धी कानूनोंके संग्रह
करने का कानून

चूंकि दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री सम्बन्धी कानूनोंका संग्रह करना
आवश्यक है, अतएव निम्नलिखित ऐक्ट बनाया जाता है:—

प्रथम प्रकरण

प्रारम्भिक विवरण

दफा १ संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

१ यह कानून “दि इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १९०८ ई०” कहा जायगा।

२ अतिरिक्त उन ज़िलों या स्थानों के जिन्हें स्थानीय सरकार इसके प्रयोग से
अलग कर दे, इसका विस्तार समस्त ब्रिटिश-भारत में होगा।

३ इसका आरम्भ १ लो० जनवरी सन् १९०९ ई० से होगा।

दफा २ परिभाषा

इस ऐक्ट में जब तक कोई बात विषय अथवा प्रसंग के विरुद्ध न हो।

१ “पता व ‘निशान’ (Addition)”—का अर्थ है बतलाये हुये व्यक्ति के
रहने का स्थान और उसका पेशा, व्यापार, पद और उपाधि (यदि कोई हो);

और यदि वह भारतवासी है तो उसकी जाति (अगर कुछ हो) ; उसके पिताका नाम, या, यदि वह अपनी माता के नाम से प्रसिद्ध है तो, उसकी माता का नाम समझा जायगा ।

२ 'किताब' (Book) में किताब का कोई भाग या पत्रों की कोई संख्या जो किताब या किताब का कोई भाग बनाने के लिये जोड़े गये हों शामिल हैं ।

३ 'ज़िला' और 'परगना' (District and Sub-district) का अर्थ क्रमशः इस ऐक्ट के अनुसार बने हुये ज़िला और परगनासे समझा जायगा ।

४ 'ज़िला की अदालत' (District Court) में हाईकोर्ट भी शामिल है, जहांकि उसके प्रारम्भिक दीवानीके अधिकारों (Original Civil Jurisdiction) से सम्बन्ध है ।

५ 'तसदीक' और 'तस्दीक किया हुआ' (Endorsement and Endorsed) में इस कानून के अनुसार रजिस्ट्रीके लिये पेश किए गए किसी दस्तवेज़ के लिफाफा (Rider) या कवरिंग सिलिप पर रजिस्ट्री करने वाले अफसर द्वारा किया हुआ कोई लिखित इन्दराज शामिल है, और ऐसे ही इन्दराजसे उक्त शब्द लागू होंगे ।

६ 'जायदाद गैर मनकूला' : (Immoveable Property) में ज़मीन, मकानात, पैतृक वृत्तियां, रास्तों, रेशनी, घाटों और माहीगाहों सम्बन्धी हक या जमीन से प्राप्त होने वाले अन्य लाभ और वे वस्तुयें शामिल होंगी जो स्थायी रूप से ज़मीन में लगी हुई हैं, या किसी ऐसी चीज़ के साथ स्थायी रूप से लगी हों जो चीज़ कि ज़मीन में लगी हुई है, परन्तु इमारतके काम में आने वाले वृक्ष, उगी फसल अथवा घास उसमें शामिल नहीं है ।

७ 'पट्टा' (Lease) में मुसन्ना (Counterpart) कबूलियत जोतने या काबिज़ रहने का कोई इक्करानामा और पट्टा पर देने का इक्करानामा शामिल है ।

८ 'नाबालिग' (Minor) का अर्थ ऐसे शख्स से है जो ज़ाती कानून के अनुसार (जिसके कि वे आधीन हैं) बालिग न हुआ हो ।

९ 'जायदाद मनकूला' (Moveable Property) में इमारत के काम में आने वाले वृक्ष, उगी फसल और घास, वृक्षों का रस और उनमें लगे हुये फल और प्रत्येक अन्य प्रकार की सम्पत्ति (जो गैर-मनकूला जायदाद न हो) शामिल हैं ।

१० 'प्रतिनिधि' (Representative) में किसी नाबालिग का वली और किसी पागल या निर्बुद्धि (मूर्ख) का कानूनी संरक्षक या कमेटी शामिल है ।

दूसरा प्रकरण

सरिस्ता-रजिस्ट्री

दफा ३ रजिस्ट्री के इन्स्पेक्टर जनरल

१ स्थानीय सरकार अपने आधीन प्रदेशों के लिये एक अफसर नियुक्त करेगी जो रजिस्ट्री विभाग का इन्स्पेक्टर जनरल होगा। परन्तु स्थानीय सरकार को अधिकार है कि वह बजाय ऐसी नियुक्ति करने के यह हुक्म दे कि वे कुल या कुछ अधिकार और कर्तव्य जो इसके बाद इन्स्पेक्टर जनरल के वास्ते बताये जायेंगे और उसे सौंपे जायेंगे ऐसे अफसर या अफसरों द्वारा और ऐसी स्थानीय सीमा के भीतर काम में लाये और पूरे किये जायेंगे जिन अफसरों को या जिस सीमा को स्थानीय सरकार इस सम्बन्ध में नियत करेगी।

२ कोई इन्स्पेक्टर जनरल साथ साथ गवर्नमेंट के आधीन किसी अन्य पद का भी काम कर सकता है।

दफा ४ सिन्ध का ब्रांच इन्स्पेक्टर जनरल

१ बम्बई के सपरिषद् गवर्नर को भी यह अधिकार है कि वे एक अफसर को नियुक्त करें जो सिन्ध का ब्रांच इन्स्पेक्टर जनरल होगा। और उस अफसर को इस ऐक्ट द्वारा दिये हुये इन्स्पेक्टर जनरल के सब अधिकार प्राप्त होंगे। परन्तु आगे बताये हुये नियमों को बनाने के अधिकार प्राप्त न होंगे।

२ सिन्ध का ब्रांच इन्स्पेक्टर जनरल साथ साथ स्थानीय गवर्नमेंट के आधीन किसी अन्य पद पर भी कार्य कर सकता है।

दफा ५ ज़िला और परगना

१ इस ऐक्ट के उद्देश्यके लिये स्थानीय सरकार ज़िला और परगना बनायेगी और ऐसे ज़िलों और परगनों की सीमा निश्चित करेगी और ऐसी सीमा को परिवर्तित भी कर सकेगी।

२ इस दफा के अनुसार बनाये हुये ज़िले और परगनों, उनकी हदों तथा उन हदों (सीमाओं) के प्रत्येक परिवर्तन की सूचना स्थानीय सरकारी गज़ट में निकाली जायगी।

३ प्रत्येक ऐसे परिवर्तन का प्रयोग उस सूचना के पश्चात् उस दिन से होगा जिस दिन का वर्णन उक्त सूचना में होगा।

दफा ६ रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार

१ स्थानीय सरकार जिन व्यक्तियों को उचित समझे उपरोक्त रीतिसे बने हुये ऐसे कई एक ज़िलों का रजिस्ट्रार और ऐसे कई एक परगनों का सब-रजि-

स्ट्रार क्रमशः नियुक्त कर सकती है, चाहे वे व्यक्ति सार्वजनिक अफसर हों या न हों। परन्तु शर्त यह है कि स्थानीय सरकार ऐसे नियमों और शर्तों के साथ रजिस्ट्री के इन्स्पेक्टर जनरल को सब-रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करने का अधिकार दे सकती है। जिन नियमों और शर्तों को वह उचित समझे।

दफा ७ रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर

१ स्थानीय सरकार प्रत्येक ज़िला में रजिस्ट्रार के दफ्तर के नाम से एक दफ्तर और प्रत्येक परगने में सब-रजिस्ट्रार का एक या कई दफ्तर या ज्वाइन्ट सब-रजिस्ट्रारों के दफ्तरों को स्थापित कर सकती है।

२ स्थानीय सरकार किसी सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर को किसी ऐसे रजिस्ट्रार के दफ्तर के साथ शामिल कर सकती है, जिसके आधीन वह सब-रजिस्ट्रार हों और जिस सब-रजिस्ट्रार का दफ्तर इस तरह शामिल किया गया है उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के अतिरिक्त उस रजिस्ट्रार के समस्त या कुछ अधिकारों के प्रयोग करने या कर्तव्यों के पालन करने का अधिकार दे सकती है जिस रजिस्ट्रार के आधीन वह है।

परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार अधिकार प्राप्त किसी सब-रजिस्ट्रार को इस ऐक्ट के अनुसार दिये हुये स्वयं अपने हुक्म के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार न होगा।

दफा ८ रजिस्ट्री के दफ्तरों के इन्स्पेक्टर

स्थानीय सरकार रजिस्ट्री के दफ्तरों के इन्स्पेक्टरों को भी नियत और उनके कर्तव्यों को निश्चित कर सकती है। प्रत्येक ऐसा इन्स्पेक्टर, इन्स्पेक्टर जनरल के आधीन होगा।

दफा ९ फौजी छावनियां, ज़िले या परगने घोषित की जा सकती हैं

प्रत्येक फौजी छावनी (यदि स्थानीय सरकार ऐसा आदेश करे) इस ऐक्ट के प्रयोजन के लिये परगना या ज़िला हो सकती है और छावनी का मजिस्ट्रेट ऐसे परगने या ज़िले का सब-रजिस्ट्रार (जैसी दशा हो) होगा।

दफा १० रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति या उसके आफिस का रिक्त (खाली) होना

१ ज़िला या प्रेसीडेन्सी टाउन के रजिस्ट्रार के अतिरिक्त जब कोई रजिस्ट्रार सिवाय उस दशा में जब कि वह काम पर ज़िले में गया हो अनुपस्थित हो या थोड़े समय के लिये उसका स्थान खाली हो तो कोई व्यक्ति जिसे इन्स्पेक्टर जनरल इसके लिये नियुक्त करे या ऐसी नियुक्ति न होने पर ज़िला की अदालत

का जज जिसके अधिकार क्षेत्रमें रजिस्ट्रार का दफ्तर है अनुपस्थितिके समय या जब तक कि स्थानीय सरकार उस रिक्त (खाली) स्थान की पूर्ति न कर दे रजिस्ट्रार होगा ।

२ जब किसी ज़िले का रजिस्ट्रार जिसमें प्रेसीडेन्सी टाउन भी शामिल हैं सिवाय ऐसी दशा में जब कि वह ज़िले में सरकारी अथवा अपने कर्तव्य से काम पर गया है अनुपस्थित हो या जब उसका दफ्तर थोड़े समय के लिये रिक्त (खाली) हो गया हो तो कोई भी व्यक्ति जिसे इन्स्पेक्टर जनरल नियुक्त करे ऐसी अनुपस्थिति के समय में या जब तक स्थानीय सरकार उस खाली स्थान की पूर्ति न कर दे रजिस्ट्रार होगा ।

दफा ११ रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति जब कि वह अपने ज़िले में ड्यूटी पर गया हो

जब कोई रजिस्ट्रार अपने दफ्तर से ज़िले में अपनी ड्यूटी पर जाने के कारण अनुपस्थित हो तो वह अपने ज़िले के किसी सब-रजिस्ट्रार या दूसरे व्यक्ति को ऐसी अनुपस्थिति में रजिस्ट्रार के समस्त कर्तव्य पालन करने के लिये सिवाय उन कर्तव्यों के जिनका दफा ६८ और ७२ में वर्णन है नियत कर सकता है ।

दफा १२ सब-रजिस्ट्रारकी अनुपस्थिति या उसके दफ्तरका खाली होना

जब कोई सब-रजिस्ट्रार अनुपस्थित हो या कुछ समय के लिये उसका दफ्तर खाली हो गया हो तो कोई व्यक्ति जिसे उस ज़िले का रजिस्ट्रार इस काम के लिये नियुक्त करेगा ऐसी अनुपस्थितिके समय में या जब तक खाली स्थान की पूर्ति न हो जाय सब रजिस्ट्रार होगा ।

दफा १३ अफसरों की कुछ नियुक्तियों, मुअत्तली, अलहेदगी और बरखास्तगी की रिपोर्ट

१ उन सब नियुक्तियों की, जिन्हें कि दफा ६ के अनुसार इन्स्पेक्टर जनरल ने की हैं, तथा उन सब नियुक्तियों की सूचना (रिपोर्ट), जोकि दफा १०, ११ और १२ के अनुसार की गई है, इन्स्पेक्टर जनरल स्थानीय सरकार को देगा ।

२ ऐसी सूचनायें विशेष या साधारण, जैसा कुछ कि स्थानीय सरकार आदेश करे, होंगी ।

३ स्थानीय सरकार इस कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को मुअत्तल, अलहेदा या बरखास्त कर सकती है और उसके स्थान में किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है । और, इन्स्पेक्टर जनरल ऐसे नियमों और शर्तों को

ध्यान में रखते हुये जिन्हें स्थानीय सरकार लगाये वही अधिकार उन सब-रजिस्ट्रारों के सम्बन्ध में बत सकता है जिन्हें उसने नियुक्त किया है।

दफा १४ रजिस्ट्री करने वाले अफसर का वेतन और संस्थापन

१. सपरिषद् गवर्नर जनरल की आधीनता में स्थानीय सरकार ऐसे वेतनों को जिन्हें वह उचित समझेगी कि उन रजिस्ट्री करने वाले अफसरों को दिया जाय जो इस कानून के अनुसार नियुक्त किये गये हैं, निर्धारित करेगी या फीस द्वारा या कुछ फीस और कुछ वेतन द्वारा उनके वेतन का प्रबन्ध करेगी।

२ स्थानीय सरकार तमाम दफ्तरों के लिये इस कानून के अनुसार उचित संस्थापनों (अमला) को दे सकती है।

दफा १५ रजिस्ट्री करने वाले अफसर की मोहर

सभी रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार एक मोहर का इस्तेमाल करेंगे जो अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा में, जिसमें स्थानीय सरकार आज्ञा दे, नीचे लिखे मन्त्र की होगी:—

“The seal of the Registrar (or Sub-registrar) of ”

अर्थात् रजिस्ट्रार (या सब-रजिस्ट्रार) स्थान की मोहर।

दफा १६ रजिस्टर और न जलाने योग्य सन्दूक (Fire proof box)

१ स्थानीय सरकार प्रत्येक रजिस्ट्री के दफ्तर के लिये कुछ पुस्तकें देगी जिनकी इस कानून के लिये आवश्यकता होगी।

२ जो पुस्तकें इस प्रकार दी जायंगी, वे ऐसे फार्म की होंगी जिन्हें स्थानीय सरकार के हुक्म से इन्स्पेक्टर जनरल समय समय पर निश्चित करेगा और इन पुस्तकों के पृष्ठों पर क्रमानुसार छांटे हुये नम्बर पड़े होंगे और प्रत्येक पुस्तक के पृष्ठों की संख्या की, टाइटल पेज पर, उस अधिकारी द्वारा तसदीक की जायगी जो उन्हें देगा (बांटेगा)।

३ स्थानीय सरकार प्रत्येक रजिस्ट्रार के दफ्तर के लिये एक न जलने वाली सन्दूक (Fire proof box) देगी और प्रत्येक ज़िला में उस ज़िले के दस्तावेजों की रजिस्ट्री सम्बन्धी कागज़ात को सुरक्षित रखने के लिये समुचित प्रबन्ध करेगी।

तीसरा प्रकरण

रजिस्ट्रीके योग्य दस्तावेजोंके विषय में

दफा १७ वे दस्तावेज जिनकी रजिस्ट्री अनिवार्य (लाज़िमी) है

१ निम्न लिखित दस्तावेजों की रजिस्ट्री होगी, यदि वह जायदाद जो उनसे सम्बन्ध रखती है उसी ज़िले में बाँटे है जिसमें, और यदि उनकी तकमील उस दिन या उसके पश्चात् होगई है जिस दिन ऐक्ट नं० १६ सन् १८६४ ई० का, या दि इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट नं० २० सन् १८६६ ई० का, या दि इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट नं० ८ सन् १८७१ ई० का, या दि इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट नं० ३ सन् १८७७ ई० का, या इस ऐक्ट का आरम्भ हुआ था या होगा अर्थात्—

(ए) जायदाद गैर मनकूला की हिवा के दस्तावेज

(बी) दूसरे गैर वसीयती दस्तावेज जिनसे वर्तमानमें या भविष्यमें किसी अधिकार, हकीयत या हिस्सा चाहे वह व्यवस्थित^१ हों या अनिश्चित^२ और जिसका मूल्य १००) रु० या उससे अधिक हो जो पैदा करने, घोषित करने, सुन्तक़िल करने, सीमाबद्ध करने या खारिज करने का मतलब रखता है या इस प्रकारका काम करता है।

(सी) गैर वसीयती दस्तावेज जो किसी रसीद को या किसी बदला व अदायगी को क़बूल करता है जो किसी अधिकार, उपाधि या लाभ के कारण पैदा हुआ क़रार दिया गया, सुन्तक़िल किया गया, सीमाबद्ध किया गया या खारिज किया गया; और

(डी) जायदाद गैर मनकूलाके साल-ब-साल पट्टे या किसी समयके लिये जो साल भर से अधिक हो या जिसका सालाना लगान ठहराया गया हो;

लेकिन शर्त यह कि स्थानीय गवर्नमेंट स्थानीय सरकारी गज़ेट में आज्ञा छाप करके इस उपदफा से कुछ पट्टोंको सुस्तसना करसकती है जिनकी तकमील किसी ज़िले या ज़िलेके किसी भाग में हुई और जिनकी मियाद ५ सालसे अधिक नहीं है और जिनका सालाना लगान जो ठहराया गया है ५०)रु०से अधिक नहीं है,

२ पहिली उपदफा के बलाज़ (Clause) (बी) और (सी) में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो निम्न लिखित दस्तावेजों पर लागू हो:—

(१) तसफियानामे; या

(२) कोई दस्तावेज जो ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनी (Joint Stock Company) के हिस्सों (Shares) के सम्बन्धमें हो चाहे यद्यपि ऐसी कम्पनीकी कुछ सम्पत्ति या उस सम्पत्ति का कुछ अंश जायदाद गैर मनकूला हो; या

१ हासिल हुआ (Vested). २ इत्तफाक से हासिल हुआ (Contingent).

(३) कोई डिवेन्चर जो ऐसी कम्पनीने जारी किया हो और जो किसी जायदाद गैर मनकूला से सम्बन्ध रखने वाले अधिकार, हक और हिस्से को पैदा, घोषित, मुन्तकिल, सीमाबद्ध या खारिज न करता हो सिवाय उस हद तक जहां तक कि वह उस शख्सको जिसके पास कि वह है वह जमानत प्रदान करता है जो किसी रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज द्वारा दी जाती है जिसके द्वारा कम्पनीने अपनी जायदाद गैर मनकूला का कुल या उसका एक अंश या उसने किसी हिस्से को ऐसे डिवेन्चरों के रखने वालों के लाभार्थ ट्रस्टी लोगों को ट्रस्ट पर रहन, बय या और किसी प्रकार मुन्तकिल कर दिया है।

(४) किसी डिवेन्चर (Debenture) की, जो ऐसी कम्पनी द्वारा जारी किया गया हो मुन्तकिली की, तस्दीक, या

(५) कोई ऐसा दस्तावेज जो खुद किसी अधिकार, हक या हिस्से को पैदा, घोषित, मुन्तकिल या सीमाबद्ध न करता हो किन्तु जो दूसरे दस्तावेज की प्राप्ति के लिये अधिकार को पैदा करता हो जो दस्तावेज कि लिखे जाने पर किसी ऐसे अधिकार, हक या हिस्से को पैदा, घोषित (ज़ाहिर), मुन्तकिल, सीमाबद्ध या खारिज करेगा; या

(६) किसी अदालतकी कोई डिकरी या हुकम या कोई तजवीज़ सालिसी; या

(७) गर्वनमेंट द्वारा किसी जायदाद गैर-मनकूला की सनद; या

(८) हाकिम माल द्वारा किये हुये किसी बटवारे का दस्तावेज; या

(९) कोई हुकम जिससे कर्ज़ाकी स्वीकृति दी गई हो या कोई किफालत मजीद का दस्तावेज जो लैण्ड इम्प्रूवमेंट ऐक्ट नं० २६ सन् १८७१ ई० या लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट नं० १९ सन् १८८९ ई० के अनुसार हो; या

(१०) कोई हुकम, जिसके द्वारा ऐग्रीकल्चरलिस्ट लोन्स ऐक्ट नं० १२ सन् १८८४ के अनुसार कर्ज़ों की मंजूरी दी गई हो या दस्तावेज जो उस ऐक्ट के अनुसार दिये गये कर्ज़ों की आमदनी की मंजूरी करता हो;

(११) किसी रेहननामेपर की गई तस्दीक जिससे रेहनके कुल या कुछ रुपये की अदायगी को कबूल किया गया है और कोई दूसरी रसीद जो उस रुपये की अदायगी की बाबत हो जो रेहननामे के बारे में वाजिबुल्ल-वसूल हो जब कि उस रसीद से रेहन की बेबाकी न होती हो; या

(१२) किसी नीलामका सर्टिफिकेट जो खरीदारको हाकिम-माल या हाकिम-दीवानी द्वारा सार्वजनिक नीलाम में बेची हुई जायदाद की बाबत दिया गया है।

३ किसी पुरुष की गोद लेने के अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजकी भी, जो पहिली जनवरी सन् १८७२ ई० के बाद तहरीर किया गया हो और जो वसीयत द्वारा न दिया गया हो, रजिस्ट्री आवश्यक होगी।

दफा १८ दस्तावेज़ जिनका रजिस्ट्री वैकल्पिक है

निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से किसी की भी रजिस्ट्री इस पैक्ट के अनुसार की जा सकती है, अर्थात्:—

(ए) वे दस्तावेज़ जो दिवानामा और वसीयतनामा के दस्तावेज़ नहीं हैं और जो वर्तमान समय में या भविष्य में किसी जायदाद गैर-मुन्तकिल, सीमाबद्ध या खारिज करते हैं।

चाहे वह अधिकार, हक या हिस्से व्यवस्थित (Vested) हो या अकस्मात् उत्पन्न हुआ हो और जिसका मूल्य १०० से कम हो।

(बी) वे दस्तावेज़ जो किसी ऐसे अधिकार, हक या हिस्से को पैदा करने, घोषित (ज़ाहिर) करने, मुन्तकिल करने, सीमा-बद्ध करने या खारिज करने के कारण उत्पन्न हुये किसी मुआविज़ा की वसूली या अदायगी को स्वीकार करते हों।

(सी) जायदाद और-मनकूला के पट्टे जिनकी मियाद साल भर से अधिक न हो या वे पट्टे जिनपर दफा १७ लागू नहीं होती है।

(डी) वे दस्तावेज़ (जो वसीयत-नामा नहीं हैं) जो किसी जायदाद-मनकूला सम्बंधी किसी अधिकार, हक या हिस्साको पैदा, घोषित, (ज़ाहिर), मुन्तकिल, सीमा-बद्ध, या खारिज करते हैं।

(ई) वसीयत-नामों, और

(एफ) दूसरे वे सभी दस्तावेज़ जिनकी दफा १७के अनुसार रजिस्ट्री कराना आवश्यक नहीं है।

दफा १९ दस्तावेज़ जिनकी भाषा रजिस्ट्री कराने वाले अफसर की समझ में न आवे

अगर कोई दस्तावेज़, जो रजिस्ट्री के लिये बाकायदा पेश किया गया हो, ऐसी भाषा में हो जिसे रजिस्ट्री करने वाला अफसर (हाकिम) नहीं समझता है और जो साधारणतया उस ज़िला में प्रचलित नहीं है, तो वह रजिस्ट्री करने से इनकार करेगा जब तक कि उसके साथ किसी ऐसी भाषा में, जो उस ज़िला में साधारणतया प्रचलित है, उसका ठीक ठीक अनुवाद और उसकी एक असली नक़ल न हो।

दफा २० वे दस्तावेज़ जिनमें सतरों के ऊपर लिखा हो, जगह छूटी हुई हो, काट-पीट या रद-बदल की गई हो

रजिस्ट्री करने वाले अफसर को अधिकार होगा कि वह ऐसे दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री करने से इनकार करदे जिनमें सतरों पर लिखा हो, जगह छूटी हो, काट-

पीट की गई हो या रद्द-बदल किया गया हो, जब तक कि दस्तावेज़ लिखने वाले व्यक्ति, उन सतरों पर की लिखावट, छूटी हुई जगह, कटे हुये या रद्द-बदल की गई बातों के ऊपर अपने नाम या हस्ताक्षर लिखकर उनकी सही न कर दे।

२ यदि रजिस्ट्री करने वाला भफसर किसी ऐसे दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करे, तो उसे चाहिये कि वह उसकी रजिस्ट्री करते समय, तकमील के बाद इन्द्राज की गई बातों, छूटी हुई जगहों, काट-पीट या रद्द-बदल के सम्बन्ध में अपने रजिस्टर में एक नोट दे दे।

दफा २१ जायदाद, नक़शों और खाकों का वर्णन

१ कोई गैर-वसीयती दस्तावेज़, जो जायदाद ग़ैर-मनकूलासे सम्बन्ध रखता है, रजिस्ट्री के लिए न लिया जायगा, जब तक कि उस जायदाद की पहिचान के लिये पर्याप्त उसका पूरा वर्णन न हो।

२ कस्बों के मकानात के सम्बन्धमें यह लिखा जाना चाहिए कि ये उस गली या सड़क के (जिसका कि विशेष वर्णन होना चाहिए) उत्तर या किसी दूसरी ओर बाँके हैं जिन गली या सड़कों के सामने वे मकान हैं और उनके उस समय के तथा पहिले के कब्ज़ेदारों (रहने वालों) के नाम और उन मकानों के नम्बर लिखे होने चाहिए, अगर ऐसी गली या सड़क के ऊपर के मकानों पर नम्बर डाले गए हैं।

३ दूसरे मकानों या ज़मीनों का वर्णन उनके नाम से, यदि उनका कोई नाम हो, और उस प्रादेशिक विभाग से, जिसमें वे बाँके हों, और उनके ज़ाहिरा सामान, सड़कों या दूसरी जायदादों से जिनपर कि वे मिलते हैं और उनके वर्तमान कब्ज़ेदार (रहने वालों) तथा जहाँ तक संभव हो गवर्नमेंट के नक़श या पैमायश का हवाला देकर किया जा सकता है।

४ कोई गैर वसीयती दस्तावेज़, जिसमें किसी जायदाद का, जो उसमें सम्मिलित है, नक़शा या खाका शामिल हो, रजिस्ट्री के लिए उस समय तक न लिया जावेगा जब तक कि उसके साथ उस नक़शा या खाका की सही नक़ल या, अगर ऐसी सम्पत्ति कई जिलों में बाँके है तो, उस नक़शा या खाका की असली नक़लों की उतनी संख्या जितने ज़िले हों नथी न हो।

दफा २२ सरकारी नक़शों या पैमायश का हवाला देकर

मकानों और ज़मीनका वर्णन करना

१ जहाँ पर स्थानीय सरकार की राय में उन मकानों का, जो कि कस्बे के मकान नहीं हैं, और ज़मीनका, सरकारी नक़शों या पैमायश का हवाला देकर वर्णन करना सम्भव होगा तो वह स्थानीय सरकार उस ऐक्ट के अनुसार बताये हुये नियमों के द्वारा यह आज्ञा देगी कि ऐसे मकानों तथा ज़मीनों का जिनका ज़िक्र ऊपर किया गया है, दफा २१ के प्रयोजन के लिये इस प्रकार वर्णन किया जाना चाहिये।

२ सिवाय उस दशा के जब कि उप-दफा (१) के अनुसार बनाये गये नियमों से कोई दूसरी व्यवस्था कर दी जाय, दफा ११ की उप-दफा २ या उप-दफा ३ के नियमों का पालन न करने से यह नहीं होगा कि कोई दस्तावेज़ रजिस्ट्री न कराया जाय, अगर उस जायदाद का वर्णन, जिससे कि वह सम्बद्ध है उस जायदाद को पहिचान सकने के लिये पर्याप्त है।

चौथा प्रकरण

रजिस्ट्रीके वास्ते दस्तावेजोंके पेश किये जानेके समयके विषयमें

दफा २३ दस्तावेजों के पेश किये जाने का समय

दफा २४, २५ और २६ के नियमों की पाबन्दी में रहते हुये वसीयतनामा को छोड़ दूसरे कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्री के लिये न लिये जायेंगे, जब तक कि वे मुनासिब अफसर के पास इस काम के लिये, लिखे जाने की तारीखसे चार मासके भीतर, पेश न किये जायेंगे।

लेकिन शर्त यह है कि किसी डिकरी या हुक्म की नकल उस दिन से चार महीने के भीतर पेश की जानी चाहिये जिस दिन कि वह डिकरी या हुक्म दिया गया था या, जब कि वह कानून अपीलके हो तो, उस दिनसे चार महीनेके भीतर पेश की जानी चाहिये जिस दिन कि वह डिकरी या हुक्म कृत होजाय।

दफा २३(ए) कुछ दस्तावेजोंकी दुबारा रजिस्ट्री किया जाना

यद्यपि इस ऐक्ट में कोई बात इसके विपरीत हो, तो भी, अगर किसी दशा में वह दस्तावेज, जिसकी कि रजिस्ट्री होनी आवश्यक है, किसी रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार को उसकी रजिस्ट्री करने के लिये किसी ऐसे आदमी द्वारा प्राप्त हुआ हो जिसको उसके पेश करने का अधिकार नहीं था और उसकी रजिस्ट्री भी हो गई हो तो, कोई आदमी जो ऐसे दस्तावेज के सम्बन्धमें दावा रखता है उस दस्तावेज को छठे प्रकरण के नियमानुसार दुबारा रजिस्ट्री किए जाने के लिए उस तारीख से ४ महीने के भीतर, जिस तारीख को कि उसे यह बात मालूम हुई थी कि उस दस्तावेज की रजिस्ट्री बेकायदा है, उस जिले के रजिस्ट्रार के दफतर में पेश कर सकता है या करवा सकता है जिस जिले में कि उस दस्तावेज की पहिले रजिस्ट्री कीगई थी। और जब रजिस्ट्रार को इस बातका यकीन हो जायगा कि यह दस्तावेज वास्तव में रजिस्ट्री के लिये उस व्यक्ति द्वारा पेश कीगई थी जिसको उसके पेश करने का बाकायदा अधिकार नहीं दिया गया था तो वह उस दस्तावेज की दुबारा रजिस्ट्री उसी प्रकार आरम्भ कर देगा मानो उसकी पहिले रजिस्ट्री हुई ही न थी और मानों इस दुबारा रजिस्ट्री के लिये पेश किया जाना रजिस्ट्री के लिए ऐसा पेश किया जाना है जो उस मियाद के भीतर किया गया है जिसकी चौथे प्रकरणमें व्यवस्था है। और दस्तावेजों की रजिस्ट्री सम्बन्धी इस ऐक्ट के समस्त नियम इस दुबारा की जाने वाली रजिस्ट्री के सम्बन्धमें

होगें और ऐसे दस्तावेज़, अगर इस दफा के अनुसार उसकी बाकायदा रजिस्ट्री होगई है, सभी कामोंके लिये पहिली रजिस्ट्री की तारीख से बाकायदा रजिस्ट्री किए गए समझे जायेंगे।

लेकिन शर्त यह है कि १२ सितम्बर सन् १९१७ ई० से चार मास के भीतर कोई भी आदमी, जो ऐसे दस्तावेज़ के सम्बन्ध में कोई दावा रखता है, इस दफाके अनुसार उस दस्तावेज़ को, उसकी दुबारा रजिस्ट्रीके लिये, पेश कर सकता है या करवा सकता है। इस बात से कोई बहस नहीं कि वह समय क्यों था जब कि उसको सर्व प्रथम यह मालूम हुआ कि दस्तावेज़की रजिस्ट्री बाकायदा है।

दफा २४ वे दस्तावेज़ जो बहुत से आदमियों द्वारा भिन्न भिन्न समयों पर लिखे गये हैं

जब बहुत से आदमियों ने एक दस्तावेज़ को भिन्न भिन्न समयों पर लिखा हो, तो ऐसे दस्तावेज़ रजिस्ट्री (Registration) और दुबारा रजिस्ट्री (Re-registration) के लिये हर एक तकमील की तारीख से चार महीने के भीतर पेश किये जासकते हैं।

दफा २५ उस समय के लिये व्यवस्था जब कि दस्तावेज़के पेश करने में बिलम्ब होना अनिवार्य है

१ अगर किसी आवश्यक कार्यवश या किसी अनिवार्य आकस्मिक घटनाके कारण कोई दस्तावेज़ जो ब्रिटिश भारतमें लिखा गया हो, या कोई नक़ल उस डिकरी या हुक्मकी जो (ब्रिटिश भारतमें) दीगई हो, रजिस्ट्रीके लिये उस समय तक पेश नहीं किया जाता है जब तक कि वह मियाद; जिसकी व्यवस्था इस कामके लिए इससे पूर्वकी गई है, समाप्त नहीं हो जाती है, तो ऐसी दशाओंमें, जब कि उसके पेश किये जानेमें चार महीनेसे अधिक देर न हुई हो, रजिस्ट्रारको अधिकार है कि वह यह हुक्म करदे कि ऐसे दस्तावेज़ उस जुर्मानाके अदा कर देने परही रजिस्ट्रीके लिए, लिए जा सकते हैं जो रजिस्ट्रीकी वाजिब फीस के दस गुने से अधिक न होगा।

२ कोई भी दरख़वास्त, जो ऐसे हुक्मकी बाबत हो, किसी सब-रजिस्ट्रारको दी जासकती है जो उसे फौरन् उस रजिस्ट्रारके पास भेज देगा जिसकी मातहतमें वह है।

दफा २६ वे दस्तावेज़ जो ब्रिटिश भारतके बाहर लिखे गए हैं

जब कोई दस्तावेज़, जिसे सभी या उनमें से कुछ पक्षकारोंने ब्रिटिश भारत के बाहर लिखा हो, रजिस्ट्री कराने के लिए उस समय तक पेश नहीं किया जाता है जब तक कि वह मियाद, जिसकी व्यवस्था इस कामके लिए इससे पूर्व कीगई

है, समाप्त न हो जाय, तो रजिस्ट्री करने वाले अफसरको अधिकार है कि वह, अगर उसको यह यकीन हो गया है कि:—

(ए) वह दस्तावेज़ वास्तवमें बाहर लिखा गया था; और

(बी) यह कि वह ब्रिटिश भारतमें आनेके बादसे चार महीनेके भीतर रजिस्ट्रीके लिए पेश किया गया है, मुनासिब रजिस्ट्री की फीस (Registration) के अदा कर दिए जाने पर ऐसे दस्तावेज़को रजिस्ट्रीके लिए ले ले।

दफा २७ वसीयतनामें, किसी समय भी लिये और जमा किये जा सकते हैं

वसीयतनामें रजिस्ट्रीके लिए किसी समय भी पेश या इसके भागे बत-
लाई हुई भांतिके अनुसार जमा किया जा सकते हैं।

पांचवां प्रकरण

रजिस्ट्री किये जानेके स्थानके विषयमें

दफा २८ आराज़ी (जर्मीन) से सम्बन्ध रखने वाले दस्तावेज़ों की रजिस्ट्रीका स्थान

सिवाय ऐसी दशाओंके जिनके लिए इस प्रकरणमें भिन्न व्यवस्था की गई है, प्रत्येक दस्तावेज़, जिसका जिक्र दफा १७ की उप दफा (१) कलॉज़ (ए), (बी), (सी) और (डी) में तथा दफा १८के कलॉज़ (ए), (बी) और (सी) में किया गया है रजिस्ट्रीके लिए उस सब-रजिस्ट्रारके दफ्तरमें पेश किया जायगा जिसके परगनेमें उस जायदादका, जिससे कि दस्तावेज़ सम्बन्ध रखता है, कुछ या कुछ हिस्सा चाकू हो।

दफा २९ दूसरे दस्तावेज़ोंकी रजिस्ट्रीका स्थान

१ प्रत्येक दस्तावेज़, जो ऐसा दस्तावेज़ नहीं है, जिसका उल्लेख दफा २८ में किया गया है, और किसी डिकरी या हुक्मकी नक़ल रजिस्ट्रीके लिये उस सब-रजिस्ट्रारके दफ्तरमें जिसके परगनेमें कि वह दस्तावेज़ लिखा गया था या उस स्थानीय सरकारके आधीन किसी दूसरे सब-रजिस्ट्रारके दफ्तरमें जहां पर कि दस्तावेज़ लिखने वालोंकी तथा जिनके हकमें वह दस्तावेज़ लिखा गया है उन लोगोंकी इच्छा उसकी रजिस्ट्री कराने की है, रजिस्ट्री कराने के लिए पेश किया जा सकता है।

२ किसी डिकरी या हुक्म की नक़ल रजिस्ट्री के वास्ते उस सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश की जा सकती है जिसके परगनेमें वह प्रारम्भिक डिकरी या हुक्म दिया गया था या, जहां पर कि उस डिकरी या हुक्म से जायदाद गैर-मनकूला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां पर उस स्थानीय सरकार के आधीन किसी सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश की जा सकती है जहां पर वे सभी आदमी जिनके हक में वह डिकरी या हुक्म दिया गया है उस नक़ल की रजिस्ट्री कराना चाहते हों।

दफा ३० कुछ दशाओं में रजिस्ट्रारों द्वारा रजिस्ट्री किया जाना

१ कोई भी रजिस्ट्रार यदि यह चाहे किसी भी ऐसे दस्तावेज़ को लेकर उसकी रजिस्ट्री कर सकता है जिसकी रजिस्ट्री उसके आधीन कोई भी रजिस्ट्रार कर सकता था।

२ किसी ज़िले का, जिसमें प्रेसीडेंसी टाउन भी शामिल है, रजिस्ट्रार और लाहौर के ज़िले के रजिस्ट्रार को दफा २८ में बतलाए हुये किसी दस्तावेज़ को, बिना इस क़यालके कि जिस जायदादसे दस्तावेज़ सम्बंध रखता है वह जायदाद ब्रिटिश भारतके किस हिस्सेमें हैं, लेने और उसकी रजिस्ट्री करनेका अधिकार है।

दफा ३१ रजिस्ट्री करना या ज़मानत में रखने के लिये दस्तावेज़ों का ले लिया जाना

साधारण अवस्थाओं में इस ऐक्ट के अनुसार दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री या उनका अमानत में जमा रखना केवल उस अफ़सर के दफ़तर में ही हो सकेगा जिसे उन दस्तावेज़ों को रजिस्ट्री करने या अमानत में रखने के लिये लेने का अधिकार है। लेकिन विशेष कारण दिखाए जाने पर ऐसा अफ़सर किसी उच्च आदमीके निवास-स्थान (रहनेकी जगह) पर, जो रजिस्ट्रीके लिये कोई दस्तावेज़ या अमानत में जमा रखने के लिए कोई वसीयतनामा पेश करना चाहता है जा सकता है और दस्तावेज़ या वसीयतनामे को रजिस्ट्री के लिये या अमानत में जमा रखने के लिए ले सकता है।

छठवां प्रकरण

रजिस्ट्रीके लिये दस्तावेजोंके पेश किये जानेके विषयमें

दफा ३२ वे शर्हस जो रजिस्ट्री किये जाने के लिये दस्तावेज पेश कर सकते हैं

सिवाय उन दशाओं में जिनका वर्णन दफा ३१ और दफा ८९ में है, प्रत्येक ऐसा दस्तावेज, जिसकी रजिस्ट्री इस ऐक्ट के अनुसार होनी है, चाहे यह रजिस्ट्री किया जाना अनिवार्य हो या इच्छित (मुत्ताअदी), रजिस्ट्री करने के मुनासिब दफ्तर में—

(ए) उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे लिखा है या जिसके हकमें वह लिखा गया है, या किसी डिकरी या हुक्म की नकल के सम्बन्ध में उस व्यक्ति के द्वारा जिसके हक में वह (डिकरी या हुक्म) दिया गया है, या

(बी) ऐसे शर्हस के प्रतिनिधि या मुन्तकिलअलेह द्वारा, या

(सी) ऐसे शर्हस, प्रतिनिधि या मुन्तकिलअलेह के कारिन्दा (मुख्तार) द्वारा जिसे इसके आगे बतलाई हुई रीति से लिखे गए और तस्दीक किए गये हुये मुख्तारनामा के द्वारा अधिकार दिये गये हों ।

दफा ३३ वे मुख्तारनामा जो दफा ३२के प्रयोजनके लिये मान्य हैं

१ दफा ३२ के प्रयोजन के लिये केवल नीचे लिखे हुए मुख्तारनामों ही मान्य समझे जायेंगे, अर्थात्:—

(ए) अगर मुख्तारनामा लिखते समय मुख्तारनामा लिखनेवाला व्यक्ति ब्रिटिश भारतके किसी ऐसे हिस्सेमें रहता हो जिसमें उस समय इस ऐक्टका प्रयोग किया जाता हो, तो वह मुख्तारनामा जो उस रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार के सामने लिखा गया हो जिसके ज़िला या परगना में वह मुख्तारनामा लिखनेवाला व्यक्ति बसता (रहता) हो और उसपर उस (रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार) ने तस्दीक की हो;

(बी) अगर ऊपर बतलाये गये समय में मुख्तारनामा लिखने वाला व्यक्ति ब्रिटिश भारत के किसी दूसरे हिस्सेमें रहता हो, तो वह मुख्तारनामा जो किसी मजिस्ट्रेट के सामने लिखा गया हो और जिसपर उस (मजिस्ट्रेट) की तस्दीक हो;

(सी) अगर ऊपर बतलाये गये समय में मुख्तारनामा लिखने वाला व्यक्ति ब्रिटिश भारतमें नहीं रहता है तो वह मुख्तारनामा जो किसी नोटरी पब्लिक (Notary public) या किसी अदालत, जज, मजिस्ट्रेट, ब्रिटिश-कान्सल (British Consul) या वाइस कान्सल (Vice Consul) या सन्नद् अथवा भारत-सरकार के प्रतिनिधि के सामने लिखा गया हो और जिसपर उसकी तस्दीक हो ।

लेकिन शर्त यह है कि नीचे लिखे व्यक्तियों को इस दफा के कलेंज़ (प) और (बी)में बतलाये हुये किसी मुख्तारनामाके लिखनेके अभिप्रायसे किसी रजिस्ट्री के दफ्तर या अदालत में जाने की आवश्यकता न होगी,

अर्थात्—

(१) वे लोग जो शारीरिक निर्बलता के कारण बिना जान जोखिममें डाले या बिना घोर कष्ट सहन किये हुए इस प्रकार हाज़िर होनेमें असमर्थ हैं;

(२) वे लोग जो किसी दीवानी या फौज़दारी मामलेके कारण जेल में हैं।

(३) वे लोग जो अदालतमें जाने से कानूनन मुक्त रहते हैं ।

२ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट, जैसा कुछ हो, अगर उसको इस बातका यक़ीन हो जायकि वह मुख्तारनामा अपनी इच्छा से स्वयं उसी व्यक्ति ने लिखा है जो मुख्तारनामा लिखने वाला बतलाया जाता है तो, बिना उस शख्स के दफ्तर या अदालतमें असाह्यता हाज़िर हुये ही उसकी तस्दीक कर सकता है ।

३ इस बात के बारेमें सुबूत लेने के लिये, कि वह मुख्तारनामा बिना ज़ोर-ज़बर्दस्ती के अपनी इच्छा से लिखा गया है, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट या तो उस शख्सके पास जो मुख्तारनामा लिखने वाला बतलाया जाता है या उस जेल को जहां पर कि वह कैद है स्वयं जायगा और उसके बयान लेगा या उसके बयान लेने के लिए कोई कमीशन नियुक्त करेगा ।

४ कोई भी मुख्तारनामा, जिसका कि इस दफा में वर्णन है, बिना किसी और सुबूत के केवल पेश कर दिए जाने से ही स्वीकृत किया जा सकता है, जब कि उसके ऊपर यह बात लिखी हुई हो कि वह उस व्यक्ति या अदालतके सामने लिखा गया है जिसका कि इससे पहिले इस सम्बन्ध में वर्णन है और उसकी तस्दीक भी है ।

दफा ३४ रजिस्ट्री किये जाने से पहिले रजिस्ट्री करने वाले
अफसर द्वारा जांच

१ इस प्रकरणमें तथा दफा ४१, ४३, ४५, ६९, ७५, ७७, ८८, और ८९ में बतलाये हुए नियमों की पाबन्दी में रहते हुये इस ऐक्टके अनुसार कोई भी दस्तावेज़ उस समय तक रजिस्ट्री नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसे दस्तावेज़ों की

तकमील करने वाले लोग अथवा उनके प्रतिनिधि (क़ायम-मुक़ामान), मुन्तक़िल-अलेह या मुख़तार (कारिन्दे), जिनको ऊपर बतलाई भांति अधिकार दिये गये हों, रजिस्ट्री करने वाले अफ़सर के यहां उस मियाद के भीतर हाज़िर न हो जायें तो दफ़ा २३, २४, २५ और २६ के अनुसार दस्तावेज़ पेश करने के लिये दी गई है।

लेकिन शर्त यह है कि अगर किसी आवश्यक कार्यवश या किसी अनिर्वाच्य आकस्मिक घटना के कारण ऐसे सच आदमी हाज़िर न हो सकें, तो रजिस्ट्रार ऐसी दशाओं में जहां पर कि हाज़िर न होने की मियाद चार मास से अधिक न हुई हो वह हुक्म दे सकता है कि उस जुर्माने के अतिरिक्त, अगर कुछ हो, जो दफ़ा २५ के अनुसार दातव्य (वाजिबुलअदा) हो उस जुर्माने के अदा करने पर, जो कि रजिस्ट्री की मुनासिब फ़ीस के दसगुने से अधिक न होगा, दस्तावेज़ की रजिस्ट्री कर दी जायगी।

२ उप-दफ़ा (१) के अनुसार उपस्थिति (हाज़िरी) चाहे एक साथ हो या भिन्न भिन्न समयों के ऊपर।

३ इसके ऊपर रजिस्ट्री करने वाला अफ़सर—

(ए) इस बात की जांच करेगा कि वह दस्तावेज़ उन्हीं आदमियों द्वारा, जिनके द्वारा लिखा गया वह मालूम होता है लिखा गया है या नहीं—

(बी) उन आदमियों की शिनाख़्त के सम्बन्ध में इतमीनान करेगा जो उसके सामने हाज़िर हुये हैं और यह बयान करते हैं कि हमने दस्तावेज़ लिखी है; तथा

(सी) उस हालत में, जब कि कोई आदमी बहैसियत प्रतिनिधि (क़ायम-मुक़ाम), मुन्तक़िल-अलेह या मुख़तार हाज़िर हुआ हो, उसकी इस उपस्थिति के अधिकार के सम्बन्ध में इतमीनान करेगा।

४ उप-दफ़ा (१) के नियमों के अनुसार हुक्मकी बाबत कोई दरख़वास्त किसी सपरजिस्ट्रार के यहां दी जा सकती है जो उसे फ़ौरन् उस रजिस्ट्रार के पास भेज देगा जिसके कि वह मातहत है।

५ इस दफ़ा की कोई भी बात डिकरी या हुक्म की तक़लों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती।

दफ़ा ३५ दस्तावेज़ की तकमील करने को इन्कार या स्वीकार करने की दशा में कार्रवाई

१ (ए) अगर वे सभी आदमी जिन्होंने वह दस्तावेज़ लिखी है असालतन रजिस्ट्री करने वाले अफ़सर के सामने हाज़िर हों और वह उनसे परिचित हो या उसको किसी और प्रकार से यह इतमीनान होजाय कि वे वेही आदमी हैं जो कि वे अपने आपको बतलाते हैं, और यदि वे सभी दस्तावेज़ के लिखने को स्वीकार कर लें; या

(बी) अगर उस होलत में, जब कि कोई व्यक्ति किसी प्रतिनिधि, मुन्तकिल-अलेह या मुख्तार के जरिये हाज़िर हुआ हो, वह प्रतिनिधि, मुन्तकिल-अलेह या मुख्तार उस दस्तावेज़ की तकमील (लिखे जाने) को स्वीकार करले; या

(सी) अगर दस्तावेज़ लिखने वाला व्यक्ति मर गया हो और उसका प्रतिनिधि, मुन्तकिल-अलेह या मुख्तार रजिस्ट्री करने वाले अफसर के पास हाज़िर होकर दस्तावेज़ की तकमील (लिखे जाने) को स्वीकार करले, तो वह रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस दस्तावेज़ की रजिस्ट्री कर लेगा, जैसा कि दफा ५८ से लेकर दफा ६१ तकमें, जिनमें यह दोनों दफायें भी शामिल हैं, बतलाया गया है ।

२ रजिस्ट्री करने वाले अफसर को अधिकार है कि वह इस बातका इत्मीनान करने के लिये, कि जो आदमी उसके सामने हाज़िर हुये हैं वे वेही आदमी हैं जो कि वे अपने आपको बतलाते हैं, या किसी दूसरे प्रयोजनसे, जिसके ऊपर इस ऐक्ट में विचार किया गया है, उन आदमियोंमें से किसी भी आदमीके बयान से ले ले जो उसके दफतर में उपस्थित (हाज़िर) हुए हैं ।

३ (ए) अगर कोई आदमी जिसका लिखा हुआ (तकमील किया हुआ) वह दस्तावेज़ मालूम होता है, इस बातको अस्वीकार करता है कि उसने उसे लिखा है, या

(बी) अगर ऐसा कोई आदमी रजिस्ट्री करने वाले अफसर को नाबालिग पागल या मूर्ख (बेवकूफ) जान पड़े, या

(सी) अगर ऐसा कोई आदमी, जिसका लिखा हुआ वह दस्तावेज़ मालूम होता है मर गया है और उसका प्रतिनिधि या मुन्तकिल-अलेह उसकी तकमील (लिखे जाने) से इन्कार करता है,

तो रजिस्ट्री करने वाले अफसरको चाहिये कि वह इस तरह इन्कार करने वाले आदमी के सम्बन्धमें, चाहे वह हाज़िर हुआ हो या मर गया हो, उस दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करने से इन्कार कर दे ।

लेकिन शर्त यह है कि जहांपर ऐसा अफसर रजिस्ट्रार हो तो उसे चाहिये कि वह उस कार्रवाई का अनुसरण करे जो बारहवें प्रकरणमें बतलाई गई है ।

सातवां प्रकरण

दस्तावेज लिखने वालों तथा गवाहोंकी हाजिरीके विषयमें

दफा ३६ उस दशा में कार्रवाई जब कि दस्तावेज लिखने वाले या गवाह की हाजिरी की आवश्यकता हो

अगर कोई ऐसा आदमी, जो रजिस्ट्रीके लिये कोई दस्तावेज पेश कर रहा है या जो किसी ऐसे दस्तावेज के सम्बन्ध में दावेदार है जो कि पेश किये जाने के योग्य है, किसी ऐसे शख्सकी हाजिरी चाहता है जिसकी उपस्थिति या साक्षी (गवाही) उस दस्तावेज की रजिस्ट्री के लिये आवश्यक है, तो रजिस्ट्री करने वाला अफसर अपनी इच्छानुसार किसी ऐसे हाकिम या अदालत को, जिसके लिये स्थानीय सरकार इस सम्बन्ध में आज्ञा दे, उस व्यक्ति के ऊपर रजिस्ट्री के दफ्तर में असाहचरान (स्वयं) या किसी कारिन्दा-मजाजके जरिये, जैसा कुछ कि उस सम्मन में लिखा गया हो, तथा उस समय पर जो उसमें बतलाया गया हो हाजिर होने के लिये सम्मन जारी करने के वास्ते लिख सकता है।

दफा ३७ हाकिम या अदालत का सम्मन जारी करना तथा उनकी तामील करवाना

वह हाकिम या अदालत चपरासी का तलबाना, जो कि ऐसे मौकों पर दाखिल किया जाना चाहिये, पा जाने पर उसके लिखे अनुसार सम्मन जारी कर देगा और उसे उस व्यक्ति के ऊपर, जिसकी कि हाजिरी वाञ्छनीय है, तामील करवा देगा।

दफा ३८ वे लोग जो रजिस्ट्रीके दफ्तरमें हाजिरीसे मुस्तसना हैं

१ (ए) वह आदमी जो शारीरिक निर्वलता के कारण बिना जान जोखिममें डाले या बिना भारी कष्ट सहन किये रजिस्ट्री के दफ्तर में हाजिर होने में असमर्थ है; या

(बी) वह आदमी जो किसी दीवानी या फौजदारीकी कार्रवाईके अनुसार जेल में है; या

(सी) वे लोग जो किसी अदालत में असाहचरान हाजिर होने से कानूनन मुस्तसना हैं और जो रजिस्ट्री के दफ्तर में असाहचरान हाजिर होने

के लिये तलब किये जाते अगर वे शर्त जो इसमें आगे चलकर बताई गई हैं मौजूद न होंगी।

इस प्रकार हाज़िर होने के लिये तलब न किये जायेंगे।

२ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में रजिस्ट्री करने वाला अफसर या तो उस आदमी के मकान पर या उस जेल को, जहाँ पर कि वह कैद है, स्वयं जायेगा और उसके बयान लेगा या उसके बयान लिए जाने के लिए कमीशन जारी करेगा।

दफा ३९ सम्मनों, कमीशनों तथा गवाहों सम्बन्धी कानून

वह कानून जो उस समय सम्मनों, कमीशनों और गवाहों को हाज़िरी के लिए बाध्य (मजबूर) करने के सम्बन्ध में और अदालत दीवानीके मुकद्दमों में उनके तलबाना के सम्बन्ध में प्रचलित है, सिवाय उस दशा के जिसका जिक्र इसके पूर्व किया गया है और सिवाय बतव्दील अमर तबदील तलब (Mutatis Mutandis) के किसी सम्मन या कमीशन के सम्बन्धमें, जो कि जारी किया गया है, तथा किसी व्यक्ति के सम्बन्धमें, जो कि इस ऐक्टके नियमावली द्वारा हाज़िरीके लिये तलब किया गया है, लागू होगा।

आठवां प्रकरण

वसीयतनामों और गोद लेने के इजाजतनामों के पेश किए जाने के सम्बन्धमें

दफा ४० वे लोग जिनको वसीयतनामों और गोद लेने के इजाजतनामों के पेश करने का अधिकार है

१ वसीयत करने वाला (Testator) या उसकी मृत्यु के पश्चात् कोई ऐसा व्यक्ति जो वसीयतनामा के बारे में बतौर साधक (वसी) या और किसी प्रकार दायेदार है उस (वसीयतनामों) को रजिस्ट्री किए जाने के लिये किसी रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार के यहां पेश कर सकता है।

२ गोद लेने सम्बन्धी इजाजतनामा का दातृ (Donor-वाहिव) या उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका प्रति-ग्राही (Donee मौदूबअक्केद) या दत्त-पुत्र (विसर मुतवन्ना) उस (इजाजतनामा) को रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार के यहां पेश कर सकता है।

दफा ४१ वसीयतनामों और गोद लेने के इजाजतनामों की रजिस्ट्री

१ वसीयतनामा या गोद लेने के इजाजतनामा की, जिसे वसीयत करने वाले या हिवा करने वाले (वाहिव) ने रजिस्ट्री किये जाने के लिये पेश किया है, रजिस्ट्री उसी प्रकार की जायगी जैसे दूसरे दस्तावेजों की।

२ वसीयतनामा या गोद लेने के इजाजतनामा की, जिसे रजिस्ट्री किये जाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति ने, जिसको उसे पेश करने का अधिकार है, पेश किया हो, रजिस्ट्री कर दी जायगी, अगर रजिस्ट्री करने वाले अफसर को यह इत्मीनान हो जाय कि—

(ए) वह वसीयतनामा या इजाजतनामा वसीयत करने वाले (Testator) या हिवा करने वाले (Donor) द्वारा, जैसा अवसर हो, लिखा गया था;

(बी) यह कि वसीयत करने वाला (Testator) या हिवा करने वाला (Donor) मर गया है; तथा

(सी) यह कि जो व्यक्ति उस वसीयतनामा या इजाजतनामा को पेश कर रहा है उसे दफा ४० के अनुसार ऐसा करने का अधिकार है।

नवा प्रकरण

वसीयतनामों के अमानतमें जमा करने के विषय में

दफा ४२ वसीयतनामों का अमानत में जमा किया जाना

कोई भी वसीयत करने वाला (testator) असाहचरन या किसी मुख्तार मजाल के ज़रिए अपने वसीयतनामों को एक मोहर लगे हुए बन्द लिफाफेमें, जिस पर वसीयत करने वाले (testator) का और उसके मुख्तारका (अगर कोई हो) नाम और दस्तावेज़ की तरह पर कुछ मज़मून लिखा हुआ हो, किसी रजिस्ट्रार के दफ्तर में बतौर अमानत जमा कर सकता है।

दफा ४३ वसीयतनामों के जमा करने पर कार्रवाई

१ ऐसे लिफाफा के पा जाने पर वह रजिस्ट्रार, अगर उसको इस बात का इतमीनाम हो जाय कि जो शख्स उसे दाखिल कर रहा है वह वसीयत लिखने वाला या उसका मुख्तार है तो, अपने रजिस्ट्रार नं० ५ में उपरोक्त मज़मून को लिख लेगा और उसी रजिस्ट्रार में तथा उस लिफाफे के ऊपर इस दाखिल किए जाने और पाने का साल, महीना, दिन और घंटा और उन आदमियों के नाम जिन्होंने उस वसीयत करने वाले या उसके मुख्तार की शिनाख्त की हो तथा किसी ऐसे स्पष्ट लेख को, जो उस लिफाफे की मोहर पर हो, लिख लेगा।

२ इसके पश्चात् रजिस्ट्रार उस मोहर लगे हुए लिफाफा को अपनी आग न लगने वाली सन्दूक (फायर प्रूफ़-बॉक्स) में रखलेगा और उसे उसी में जमा रखेगा।

दफा ४४ मोहर लगे हुए उस लिफाफा का वापस लेना जो कि दफा ४२ के अनुसार जमा किया गया है

अगर वसीयत करने वाला व्यक्ति (testator), जिसने ऐसे लिफाफा को जमा किया है, उसे वापस लेना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह असाहचरन या अपने किसी मुख्तार मजाल के ज़रिए से इस बात के लिए उस रजिस्ट्रार को दफ्तरवास्त दे जिसके पास वह अमानत में जमा है, और वह रजिस्ट्रार, अगर उसे वह इतमीनाम हो जाय कि प्रार्थी (दरख़्वास्त देने वाला) सच-मुच वसीयत करने वाला या उसका मुख्तार है तो, उस लिफाफा को उसके हवाले कर देगा।

दफा ४५ दाखिल करने वाले के मर जाने पर कार्रवाई

१ अगर उस वसीयत करने वाले (testator) के मर जाने पर, जिसने दफा ४२ के अनुसार मोहर लगे हुए लिफाफा को दाखिल किया है, उस रजिस्ट्रार को

जिसके पास कि वह अमानत में जमा है उसे निकाल देने के लिए दरखवास्त दी जाय और अगर उस रजिस्ट्रार को इस बात का इतमीनान हो जाय कि वसीयत करनेवाला (Testator) मर गया है तो वह उस प्रार्थी (दरखवास्त देने वाले) के समक्ष (सामने) उस लिफाफे को खोल देगा और उस प्रार्थी के खर्च से उस का मजमून अपनी किताब न० ३ में दर्ज करा लेगा ।

२ इस नकल के हो जानेपर रजिस्ट्रार असली वसीयत नामेको फिर दाखिल अमानत कर लेगा ।

दफा ४६ कुछ नियमों तथा अदालतके अधिकारों का बचाव

१ इसमें पहिले जो कुछ बतलाया गया है उसमें कोई भी बात ऐसी न होगी जो इण्डियन सकूसेशन ऐक्ट सन् १८६५ ई० (कानून विरासत) की दफा २५९ या प्रोवेट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८८१ ई० की दफा ८१ पर या हुकम द्वारा किसी दस्तावेज को ज़बर्दस्ती पेश करने सम्बन्धी किसी अदालत के अधिकार पर कोई प्रभाव डाल सके ।

२ जब कोई ऐसा हुकम दिया जा चुके तो रजिस्ट्रार को चाहिए कि, अगर दफा ४५ के अनुसार उस वसीयतनामा की नकल की न जा चुकी हो तो, वह उस लिफाफे को निकाले और उस वसीयतनामा की नकल अपनी किताब न० ३ में करादे और उस नकल के ऊपर यह नोट लिख दे कि असली कापी उपर्युक्त हुकम के अनुसार अदालत को भेज दी गई है ।

दसवां प्रकरण

दफा ४७ रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेजोंके अमल (नाफिज)
करनेका समय

रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज का अमल (नफाज) उस समय से आरम्भ होगा जिस समयसे कि वह आरम्भ हुई होती, अगर उसकी रजिस्ट्री आवश्यक न होती या अगर उसकी रजिस्ट्री की न गई होती, उस समय से नहीं जबकि उसकी रजिस्ट्री हुई है।

दफा ४८ जायदादसे सम्बन्ध रखने वाले रजिस्ट्री किये हुए
दस्तावेज जबानी इकरारनामोंके मुक़ाबिलेमें कब
अमल (नाफिज) में लाये जायंगे

सभी ग़ैर-वसीयती दस्तावेज, जिनकी कि इस ऐक्ट के अनुसार वाक़ा-यदा रजिस्ट्री होगई है और जो किसी जायदाद से सम्बन्ध रखते हों, चाहे वह जायदाद मनकूला हो या ग़ैर-मनकूला, किसी भी जबानी इकरारनामा या अज़ीदावा के मुक़ाबले में जो कि उसी जायदाद के सम्बन्ध में हों अमल (नाफिज) में लाये जायंगे सिवाय उन दशाओंके, जब कि इस इकरारनामा या अज़ीदावा के साथ या उसके बाद दख़ल-दिहानी न कर दीगई हो।

दफा ४९ जिन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री आवश्यक है उनकी
रजिस्ट्री न करनेका परिणाम

कोई भी दस्तावेज, जिसकी रजिस्ट्री दफा १७ के अनुसार आवश्यक है, जब तक कि उसकी रजिस्ट्री न होजाय तब तक—

(ए) किसी भी जायदाद ग़ैर-मनकूला पर जोकि उसमें शामिल है कोई भी प्रभाव न डाल सकेगी, या

(बी) गोद लेने सम्बन्धी कोई अधिकार न दे सकेगी, या

(सी) किसी मामले में जिससे उस जायदाद पर कोई प्रभाव पड़ता हो या जो ऐसे अधिकार प्रदान करता हो शहादत में न माना जायगा।

दफा ५० आराज़ी सम्बन्धी कुछ दस्तावेज बिना रजिस्ट्री किये
हुए दस्तावेजोंके मुक़ाबले व्यापक (नाफिज) होंगे

१ प्रत्येक इस किस्म का दस्तावेज जिसका ज़िक्र दफा १७ की उप-दफा १ के क्लॉज (ए), (बी), (सी) और (डी) में तथा दफा १८ के क्लॉज

(ए) और (बी) में है, अगर उसकी वाकायदार जिस्ट्री होगई है, उसमें बतलाई हुई जायदाद के सम्बन्ध में प्रत्येक बिना रजिस्ट्री किए हुए ऐसे दस्तावेज के मुकाबिले में व्यापक माना जायगा जो उसी जायदाद के सम्बन्ध में है और जो कि डिकरी या हुक्म नहीं है, फिर चाहे वह बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज उसी किस्मका हो जिस किस्मका कि रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज है या नहीं ।

२ उपदफा (१) में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उन पट्टों के सम्बन्धमें है जो कि दफा १७ के उपदफा (१) के नियमोंसे युक्त हैं, या किसी दस्तावेज के सम्बन्ध में जिसका जिक्र उसी दफाकी उपदफा (२) में है या किसी ऐसी रजिस्ट्री किये हुए दस्तावेज के सम्बन्धमें लागू हों जिसको इस ऐक्ट के आरम्भ होनेके समयमें प्रचलित किसी भी कानूनके अनुसार प्राधान्यता प्राप्त नहीं है ।

विवरण—उन दशाओंमें जब कि उस स्थानमें जहां पर, या उस समयमें जिसमें कि वह बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज लिखा गया था ऐक्ट नं० १६ सन् १८६४ ई० या इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८६६ ई० प्रचलित था, 'बिना रजिस्ट्री किया हुआ' शब्दका अर्थ है उस ऐक्टके अनुसार रजिस्ट्री न किया हुआ और जब कि दस्तावेज १ जुलाई सन् १८७१ ई० के बाद लिखा गया हो वहां पर इसका अर्थ होगा इण्डियन-रजिस्ट्रेशन-ऐक्ट सन् १८७१ ई० या इण्डियन-रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८७७ ई० या इस ऐक्टके अनुसार रजिस्ट्री न किया हुआ ।

ग्यारहवां प्रकरण

रजिस्ट्री करने वाले अफसरके कर्तव्यों तथा अधिकारोंके विषय में

(ए) रजिस्ट्रों और फेहरिस्तोंके सम्बन्धमें

दफा ५१ वे रजिस्टर जो सभी दफ्तरोंमें रखे जाने चाहिये

१ नीचे लिखी किताबें उन सभी दफ्तरोंमें रखी जायंगी जो इसके बादमें बतलाए गए हैं, अर्थात्:—

(ए) सभी रजिस्ट्रीके दफ्तरों में—

किताब नं० १—“गैर वसीयती दस्तावेजोंका, जो कि जायदाद गैर-मनकूलाके सम्बन्धमें हैं, रजिस्टर ।”

किताब नं० २—“रजिस्ट्री करने से इन्कार किए जानेके कारणोंके लिखनेकी किताब ।”

किताब नं० ३—“वसीयतनामों और गोद लेनेकी सनदोंका रजिस्टर ।”

किताब नं० ४—“रजिस्टर मुतफरिकात ।”

(बी) रजिस्ट्रारके दफ्तरमें—

किताब नं० ५—“वसीयतनामोंको अमानतमें जमा करने सम्बन्धी रजिस्टर ”

२ किताब नं० १में उन सभी दस्तावेजों और याददाइतोंका इन्दराज या उनकी खानापूरीकी जायगी जिनकी दफा १७, १८ और ८९ के अनुसार रजिस्ट्री कीया है और जो जायदाद गैर-मनकूलाके सम्बन्धमें है और वसीयतनामों नहीं हैं ।

३ किताब नं० ४ में उन सब दस्तावेजोंका इन्दराज होगा जो दफा १८ के कलौज़ (डी) और (एफ) में रजिस्ट्री किए जायंगे और जो जायदाद गैर-मनकूलाके सम्बन्धमें नहीं हैं ।

४ इस दफामें ऐसी कोई भी बात न समझी जायगी जिसके कारण उस दशा में जब कि रजिस्ट्रारका दफ्तर किसी सब-रजिस्ट्रारके दफ्तरमें मिला दिया जाय एक से अधिक जोड़ (Set) रजिस्ट्रोंकी आवश्यकता पड़े ।

दफा ५२ दस्तावेज़ पेश किये जाने पर रजिस्ट्री करने वाले

अफसरका कर्तव्य

१ (ए) किसी दस्तावेज़के पेश करते समय उस पेश किए जाने का दिनांक और स्थान तथा उस शख्सका नाम जो कि दस्तावेज़को पेश

रजिस्ट्रीके पेश करता है ऐसे प्रत्येक दस्तावेज़ की पुश्त पर लिखा जाना चाहिए ।

(बी) रजिस्ट्री करने वाले अफसरको चाहिए कि वह उस दस्तावेज़की रसीद दस्तावेज़ पेश करने वाले व्यक्तिको दे दे । और

(सी) दफा ६२ में बतलाए गए नियमोंकी पाबन्दीमें रहते हुए प्रत्येक ऐसे दस्तावेज़की जो रजिस्ट्रीके लिये मंजूर कर लिया गया है बिना अनावश्यक बिलम्बके उस किताबमें रजिस्ट्रीके क्रमानुसार नकल कर लेना चाहिये ।

इन सभी किताबोंकी ऐसे समयों पर और ऐसे ढंगसे तस्दीक की जायगी जिसको समय समय पर इन्स्पेक्टर-जनरल निश्चित करेंगे ।

दफा ५३ इन इन्दराजातका सिलिसलेवार नम्बर छोड़ना

हर एक किताबके सभी इन्दराजात सिलिसलेवार नम्बर छोड़ कर किए जायेंगे जो सालसे आरम्भ और साल ही में समाप्त हो जायेंगे । प्रत्येक सालके आरम्भमें नया सिलिसला आरम्भ होगा ।

दफा ५४ वर्तमान फेहरिस्त और उसके इन्दराजात

प्रत्येक ऐसे दफ्तरमें जिनमें कि इसके पूर्व बतलाई हुई कोई भी किताबें रहती हों ऐसी किताबोंमें दर्जकी हुई बातोंकी फेहरिस्तें तैयार की जायेंगी जो उस समय प्रचलित होंगी; और इन किताबोंका प्रत्येक इन्दराज, जहां तक सम्भव होगा, जिस समय रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस दस्तावेज़की जिससे कि इसका सम्बन्ध है नकल कर चुकेगा या उसकी याददाश्तकी दाखिल दफ्तर कर चुकेगा उसके बाद फौरन ही कर दिया जायगा ।

दफा ५५ रजिस्ट्री करने वाले अफसरों द्वारा तैयारकी जाने वाली फेहरिस्तें और उनमें लिखी जाने वाली बातें

१ सभी रजिस्ट्रीके दफ्तरोंमें ऐसी चार फेहरिस्तें तैयार की जायेंगी और उन पर क्रमशः फेहरिस्त नं० १, फेहरिस्त नं० २, फेहरिस्त नं० ३, और फेहरिस्त नं० ४ नाम पड़ेगा ।

२ फेहरिस्त नं० १ में उन तमाम आदमियोंके नाम और पता व निशान रहेंगे जिन्होंने कि उस दस्तावेज़को लिखा है या जो उनकी बाबत दावेदार हैं जो कि किताब नं० १ में दर्ज किया गया है या जो याददाश्त (Memorandum) कि दाखिल दफ्तर की गई है ।

३ फेहरिस्त नं० २ में ऐसे दस्तावेज़ों और याददाश्तोंके सम्बन्धमें दफा २१ में बतलाई हुई उन बातोंकी तफ़सील होगी जिसकेबारेमें इन्स्पेक्टर जनरल समय समय पर इस सम्बन्धमें आज्ञा निकालें ।

४ फेहरिस्त नं० ३ में उन तमाम आदमियोंके, जिन्होंने कि उन वसीयतनामी और अधिकार-पत्र (सनद) को जो कि किताब नं० ३ में दर्ज किए गए हैं, तथा साधकों (वसी या तामील कुानिन्दा) और उन व्यक्तियोंके नाम और पता व निशान जो कि अलग अलग उनके अनुसार नियुक्त किए गए हैं, और वसीयत करने वाले (Testator) या हिबा करने वाले (Doner) की मृत्यु हो जानेके पश्चात् (पहिले नहीं) उन सभी आदमियोंके नाम और पता व निशान लिखे जायेंगे जो उसके सम्बन्धमें दावेदार हैं।

५ फेहरिस्त नं० ४ में उन सभी आदमियोंके नाम और पता व निशान जो कि उन दस्तावेजोंके लिखने वाले हैं और लोगोंके नाम और पता व निशान रहेंगे जो उन दस्तावेजोंके सम्बन्धमें दावेदार हैं जिनका कि इन्दराज किताब नं० ४ में किया गया है।

६ प्रत्येक फेहरिस्तमें दूसरी ऐसी बातें लिखी जायेंगी और वे ऐसे नमूनेकी तैयार की जायेंगी जिनकी आज्ञा इन्स्पेक्टर जनरल समय समय पर देते रहेंगे।

दफा ५६ फेहरिस्त नं० १, २ और ३ में दर्ज की गई बातोंकी नक़लका सब-रजिस्ट्रारके पास भेजा जाना और उसका दाखिल दफ़तर (फाइल) करना

१ प्रत्येक सब-रजिस्ट्रारको चाहिए कि वह उस रजिस्ट्रारके पास, जिसके कि वह मातहत है, ऐसे समयों पर, जिनके लिए समय समय पर इन्स्पेक्टर जनरल आदेश करें, उन सभी इन्दराजात की नक़ल भेज दे, जो उसने इन समयोंमें से सबसे अन्तिम (अखीरी) समय फेहरिस्त नं० १, २ और ३ में किए गए हैं।

२ प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रार जिसे ऐसी नक़लें प्राप्त हों उन्हें दाखिल दफ़तर कर लेगा।

दफा ५७ रजिस्ट्री करने वाले अफसरोंको कुछ किताबों और फेहरिस्तोंके मुलाहिज़ा करनेकी आज्ञा और इन्दराजातकी तस्दीककी हुई नक़लें देनेका अधिकार

१ फ़ीसके, जो इस सम्बन्ध में दी जानी चाहिए, पहिले अदा कर दिए जाने पर किताब नं० १ और २ तथा किताब नं० १ से सम्बन्ध रखने वाली फेहरिस्त का कोई आदमी, जो इसके लिए दरख़वास्त करे, हर समय मुलाहिज़ा कर सकेगा; और दफा ६२ के नियमोंकी पाबन्दी करते हुए इन किताबोंमें किए गए इन्दराजातकी नक़लें उन सभी आदमियों को दी जा सकेंगी जो इनके लिए दरख़वास्त करें।

२ उन्हीं नियमों की पाबन्दी करते हुए किताब नं० ३ में और उसके सम्बन्ध रखने वाली फेहरिस्त में किए गए इन्दराजात की नक़लें ऐसे आदमियों

को, जिन्होंने उन दस्तावेजों को लिखा हो या जो उनके अनुसार दायेदार हों, जिन दस्तावेजों से ये इन्दराजात सम्बन्ध रखते हैं, या उनके कारिन्दों (मुह्तारों) को, तथा दस्तावेज लिखने वालों के मर जाने के बाद (किन्तु इसके पहिले नहीं) किसी आदमी को, जो इन नकलों के लिए दरखवास्त दे, दी जा सकेगी ।

३ उन्हीं नियमों की पाबन्दी करते हुए किताब नं० ३ और उससे सम्बन्ध रखने वाली केहरिस्त में किए गए इन्दराजात की नकलें किसी आदमी को, जिसने उन दस्तावेजों को, जिनका इन्दराजातसे क्रमशः सम्बन्ध है, लिखा हो या जो उनके अनुसार दायेदार हों, अथवा उसके कारिन्दा या प्रतिनिधि को दी जा सकेगी ।

४ किताब नं० ३ और ४ में किए गए इन्दराजात की इस दफा के अनुसार आवश्यक खोज (तलाशी मतलूबा) केवल रजिस्ट्री करने वाला अफसर ही कर सकेगा ।

५ इस दफा के अनुसार दी गई सभी नकलों पर रजिस्ट्री करने वाले अफसर के दस्तखत और मोहर होगी, और वे प्रारम्भिक दस्तावेजों के मज़मून को साबित करने के लिए प्रमाण माने जायेंगे ।

(बी) रजिस्ट्री के लिए मंजूर कर लिए गए दस्तावेजों की

पुस्त पर लिखी जाने वाली बातें

दफा ५८ रजिस्ट्री के लिए मंजूर कर लिए गए दस्तावेजों

की पुस्तपर लिखी आने वाली बातें

१ रजिस्ट्री के लिए मंजूर कर लिए गए प्रत्येक दस्तावेज की, जो किसी डिकरी या हुक्म की नकल या ऐसी नकल नहीं है जो रजिस्ट्री करने वाले अफसर के पास दफा ८९ के अनुसार भेजी गई है, पुस्त पर, समय समय पर, नीचे लिखी बातें लिखी जायेंगी, अर्थात्—

(ए) हस्ताक्षर (दस्तखत) तथा नाम और पता प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का, जिसने दस्तावेज के लिखे जाने को (तकमील को) स्वीकार कर लिया हो, और अगर इस तकमील को किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि, मुन्तकिल-अलेह, या कारिन्दे ने स्वीकार किया हो तो ऐसे प्रतिनिधि मुन्तकिल-अलेह या कारिन्दे के हस्ताक्षर (दस्तखत) तथा नाम और पता;

(बी) हस्ताक्षर (दस्तखत) तथा नाम और पता प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का, जिसके इस ऐक्ट के किसी नियम के अनुसार बयान लिए गए हों; और

(सी) रुपये की कोई अदायगी या मालका कोई समर्पण, जो उस दस्तावेज के लिखे जाने (तकमील) के सम्बन्ध में रजिस्ट्री करने वाले अफसर के सामने की गई हो, तथा उस मुआविज़ा-दस्तावेज की

कुल या अंश में हुई प्राप्ति की स्वीकृति, जो उस दस्तावेज के सम्बन्ध में उसके समक्ष (सामने) दिया गया हो ।

(डी) अगरे कोई व्यक्ति, जिसने दस्तावेज के लिखे जाने (तंक्मील) को स्वीकार कर लिया हो, उस दस्तावेज की पुस्तपर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार करे तो भी रजिस्ट्री करने वाला अफसर उसकी रजिस्ट्री कर लेगा, किन्तु इस इनकारी के सम्बन्ध में वह एक नोट दस्तावेज की पीठ (पुस्त) पर लिख देगा ।

दफा ५९ तसदीक के ऊपर रजिस्ट्री करने वाला अफसर अपने दस्तखत करे और तारीख डाले

रजिस्ट्री करने वाले अफसर को चाहिए कि वह उन दस्तावेजों के सम्बन्ध में तथा अपने सामने दफा ५२ और ५८ के अनुसार की गई तसदीक के ऊपर उसी दिन अपने हस्ताक्षर (दस्तखत) करे और तारीख डाले ।

दफा ६० रजिस्ट्री किए जानेका सार्टीफिकट

१ दफा ३४, ३५, ५८ तथा ५९ के उन नियमोंकी तामील होजाने के बाद, जो किसी उस दस्तावेज के सम्बन्ध में लागू होते हैं जो कि रजिस्ट्री किए जाने के लिए पेश किया गया है, रजिस्ट्री करने वाला, अफसर उसपर एक सार्टीफिकट की तसदीक करेगा, जिसमें 'रजिस्ट्री किया गया' शब्द तथा उस किताब का नम्बर और पृष्ठ (सफा) होगा, जिसमें उस दस्तावेज की नकल की गई है ।

२ इस सार्टीफिकट पर रजिस्ट्री करने वाला अफसर अपने हस्ताक्षर (दस्तखत) करेगा, तारीख डालेगा और मोहर करेगा, और तब वह इस बातके साबित करने के लिए स्वीकार किए जाने योग्य होगा कि दस्तावेज की इस ऐक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार बाकायदा रजिस्ट्री की गई है, और यह कि दफा ५९ में बतलाई हुई तसदीक (Endorsement) में वर्णित बातें वैसे ही हुई हैं जैसी कि वे उसमें बतलाई गई हैं ।

दफा ६१ तसदीक और सार्टीफिकटकी नकल करके दस्तावेज वापस दिया जाना

१ तसदीक और सार्टीफिकटकी, जिनका जिक्र ऊपर किया गया है और जो दफा ५९ और ६० में बतलाए गए हैं, नकल, सब रजिस्टर-बुक के हाशिये पर करली जायगी और नकशा या खाका की (अगर कोई हो), जिसका वर्णन दफा २१ में किया गया है । किताब नं० १ में फाइल (नरथी) कर लिया जायगा ।

२ तब उस दस्तावेज की रजिस्ट्री पूरी हुई समझी जायगी और फिर वह दस्तावेज उस आदमी को, जिसने उसे रजिस्ट्री किए जाने के लिए पेश किया था, या किसी दूसरे ऐसे आदमी को, जिसको लिखकर इस काम के लिए नाम जुद किया गया हो, दफा ५२में बतलाई गई रसीदके दे देने पर दे दिया जायगा ।

दफा ६२ ऐसे दस्तावेज़ोंके पेश किये जाने पर कार्रवाई जो ऐसी भाषा में हो जिसे रजिस्ट्री करने वाला अफसर नहीं जानता है

१ जब दफा १९ के अनुसार रजिस्ट्री किए जाने के लिए कोई दस्तावेज़ पेश किया जाय, तो दस्तावेज़ोंके रजिस्टरमें उस असली दस्तावेज़के ठीक ठीक अनुवादकी नकल कर ली जायगी, और जिस नकलका ज़िक्र दफा १९ में किया गया है उसके साथ वह अनुवाद रजिस्ट्रीके दफ्तरमें फाइल (नन्धी) कर लिया जायगा ।

२ तत्सदीक और सार्टीफिकेट, जिनका क्रमशः दफा ५९ और ६० में वर्णन किया गया है, असली दस्तावेज़ पर ही किए जायंगे, तथा नकल करने और याददास्त तैयार करने के लिए, जिनकी दफा ५७, ६४, ६५ और ६६ के अनुसार आवश्यकता है, वह अनुवाद ऐसा ही समझा जायगा मानो वह असली ही है ।

दफा ६३ हलफ लेने और बयानका सारांश लिखनेका अधिकार

१ प्रत्येक रजिस्ट्री करने वाले अफसरको अधिकार है कि वह स्वेच्छापूर्वक किसी ऐसे आदमीको हलफ रखा सके जिसके उसने इस ऐक्टके अनुसार बयान लिए हों ।

२ प्रत्येक ऐसे अफसरको यह भी अधिकार होगा कि वह स्वेच्छापूर्वक उस बयानके सारांशको नोट कर (लिख) ले, जिसे प्रत्येक ऐसे मनुष्यने दिया हो, और वह बयान उसको पढ़ कर सुना दिया जायगा या (अगर वह ऐसी भाषामें दिया गया है जिससे वह मनुष्य अनभिज्ञ (नावाक़िफ़) है) उस भाषामें उसे समझा दिया जायगा जिसे वह जानता है; और अगर वह इस नोट (लिख लेने) को सही मान लेगा तो उस पर रजिस्ट्री करने वाला अफसर अपने हस्ताक्षर (दस्तखत) कर देगा ।

३ प्रत्येक ऐसा नोट, जिस पर इस प्रकार हस्ताक्षर हो गए हों, इस बातके साबित करनेमें मान्य (माने जाने योग्य) होगा कि जो कुछ बातें उसमें दर्ज हैं वे उन आदमियों द्वारा और उसमें बतलाई गई व्यवस्थाओंमें बयान की गई थीं ।

(सी) सब-रजिस्ट्रारके विशेष कर्तव्य

दफा ६४ उस दशामें कार्रवाई जबकि दस्तावेज़ उस आराज़ी से सम्बन्ध रखता हो जो कई परगनों में है

प्रत्येक ऐसे सब-रजिस्ट्रार को, जो किसी ऐसे ग़ैर-वसीयती दस्तावेज़ को रजिस्ट्री कर रहा हो, जो ऐसी जायदाद ग़ैर-मनकूलके सम्बन्धमें है जो पूरी पूरी

उसीके परगनेमें वाकै नहीं हैं, चाहिये कि वह उसकी और उसपर की गई तस्दीक और सर्टिफिकेटकी (अगर कोई हो) याददास्त तैयार करे और उसे प्रत्येक ऐसे दूसरे सब-रजिस्ट्रारके पास भेज दे जिसके परगनेमें उस जायदादका कोई हिस्सा वाकै है और जो उसी रजिस्ट्रारके मातहत है जिसके मातहत वह स्वयं है और वह सब-रजिस्ट्रार उस याददास्त (Memorandum) को अपनी किताब नं० १ में फाइल (नत्थी) कर लेगा ।

दफा ६५ उस दशामें कार्रवाई जबकि दस्तावेज उस आराज़ी से सम्बन्ध रखता हो जो कई जिलों में है

१ प्रत्येक सब रजिस्ट्रार को, जो किसी ऐसे गैर-वसीयती दस्तावेजकी रजिस्ट्री कर रहा हो जो उस जायदाद गैर-मनकूला के सम्बन्ध में है जो एक से अधिक जिलों में वाकै है, चाहिये कि वह एक नकल उसकी और एक नकल उसके तस्दीक और सर्टिफिकेट की (अगर कोई हो) मय उस नकशा या खाका की (अगर कोई है), जिसका वर्णन दफा २१ में है, नकलको, उस जिलेको छोड़ जिस में स्वयं उसका परगना वाकै है, प्रत्येक उस जिले के रजिस्ट्रारके पास भेज दे जिसमें ऐसी जायदाद का कोई हिस्सा वाकै हो ।

२ रजिस्ट्रार उन्हें पा जाने पर दस्तावेजकी नकल और उस नकशा या खाका की (अगर कोई हो) नकलको किताब नं० १ में फाइल (नत्थी) कर लेगा और उस दस्तावेजकी याददास्त (Memorandum) को अपने मातहत प्रत्येक सब-रजिस्ट्रारके पास, जिसके परगनेमें उस जायदादका कोई हिस्सा वाकै होगा, भेज देगा; और प्रत्येक सब-रजिस्ट्रार ऐसी याददास्त को पा जाने पर उसे अपनी किताब नं० १ में दर्ज कर लेगा ।

(डी) रजिस्ट्रारके विशेष कर्तव्य

दफा ६६ आराज़ी (ज़मीन) सम्बन्धी दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री हो जानेके बाद कार्रवाई

१ जायदाद गैर-मनकूला से सम्बन्ध रखने वाले किसी गैर-वसीयती दस्तावेजकी रजिस्ट्री करलेने पर रजिस्ट्रार को चाहिए कि वह ऐसे दस्तावेजकी याददास्त (Memorandum) को अपने मातहत प्रत्येक ऐसे सब-रजिस्ट्रारके पास भेज दे जिसके परगने में ऐसी जायदाद का कोई हिस्सा वाकै हो ।

२ उस रजिस्ट्रारको यह भी चाहिए कि वह उस नकशे या खाकाकी (अगर कोई हो), जिसका वर्णन दफा २१ में किया गया है, नकलके सहित ऐसे दस्तावेजोंकी नकलको प्रत्येक दूसरे ऐसे रजिस्ट्रारको भेज दे, जिसके जिलेमें ऐसी जायदादका कोई हिस्सा वाकै हो ।

३ ऐसे रजिस्ट्रार किसी ऐसी नकलके पा जाने पर उसे अपनी किताब नं० १ में फाइल (नथी) कर लेगा और उस नकलकी एक याददाश्त अपने मातहत प्रत्येक ऐसे सब-रजिस्ट्रार के पास भेज देगा, जिसके परगनेमें उस जायदाद का कोई हिस्सा बाँके हो ।

४ प्रत्येक सब-रजिस्ट्रार इस दफाके अनुसार किसी याददाश्त (Memorandum) के पा जाने पर उसे अपनी किताब नं० १ में फाइल (नथी) कर लेगा ।

दफा ६७ दफा ३०, उप-दफा (२) के अनुसार रजिस्ट्री हो जाने के बाद कार्रवाई

दफा ३०, उप-दफा (२) के अनुसार किसी दस्तावेज़की रजिस्ट्री होजाने पर, ऐसे दस्तावेज़की और उसकी तस्दीक और सर्टिफिकेटकी एक नकल प्रत्येक ऐसे सब-रजिस्ट्रारके पास भेज दी जायगी, जिसके ज़िलेमें उस जायदादका कोई हिस्सा बाँके है जिससे कि उस दस्तावेज़का सम्बन्ध है, और ऐसी नकलके पा जाने पर रजिस्ट्रारको वह कार्रवाई करना चाहिए जो उसके लिए दफा ६६, उप-दफा (१) में निर्धारित की गई है ।

(ई) रजिस्ट्रारों और इन्स्पेक्टर-जनरलके शासनाधिकार

दफा ६८ सब-रजिस्ट्रारोंके कार्यका निरीक्षण करने तथा उन पर शासन करने के सम्बन्धमें रजिस्ट्रारके अधिकार

१ प्रत्येक सब-रजिस्ट्रार दफ्तर सम्बन्धी अपने कामोंको उस रजिस्ट्रारके निरीक्षण और अधीनता (मातहत) में करेगा जिसके ज़िलेमें ऐसे सब-रजिस्ट्रार का दफ्तर बाँके हो ।

२ प्रत्येक रजिस्ट्रारको यह अधिकार होगा कि वह (फरियाद किए जानेपर अथवा वैसे ही) कोई हुक्म जारी करे, जो इस ऐक्टके अनुकूल हो, और जिसे वह अपने मातहत किसी सब-रजिस्ट्रारके किसी काम अथवा भूलके सम्बन्धमें या उस किताब अथवा दफ्तरके विषयमें, जिसमें कोई दस्तावेज़ रजिस्ट्री किया गया है, किसी भूल (ग़लती) का संशोधन करनेके सम्बन्धमें दिया हो ।

दफा ६९ रजिस्ट्रीके दफ्तरोंका शासन करने और नियम बनाने के सम्बन्धमें इन्स्पेक्टर जनरलके अधिकार

१ इन्स्पेक्टर-जनरलका उन प्रदेशोंके सभी रजिस्ट्रीके दफ्तरों पर शासन होगा जो स्थानीय-सरकारके अधीन हैं, और उसे समय समय पर ऐसे नियम बनानेका अधिकार होगा जो इस ऐक्टके अनुकूल हों ।

- (ए) किताबों, कागज़ात और दस्तावेज़ोंको सुरक्षित रखनेके लिए;
 (बी) इस बातका एलान करने के लिए कि कौन सी भाषाएं (ज़बानें) प्रत्येक ज़िलामें आम तौर पर प्रयोगमें लाई जायंगी;
 (सी) इस बातका एलान करने के लिए कि कौन कौनसे भूमि-भाग दफा २१ के अनुसार मान लिए गए समझे जायंगे,
 (डी) उन जुर्मानोंकी रकमोंको नियमित करनेके लिए, जोकि क्रमशः दफा २५ और ३४ के अनुसार किए गए हैं;
 (ई) उन अधिकारोंके प्रयोगको नियमित करने के लिए, जो रजिस्ट्री करने वालों अफसरोंको दफा ६३ के अनुसार दिए गए हैं;
 (एफ) उन फार्मोंको निश्चित करने के लिए, जिनमें कि रजिस्ट्री करने वाले अफसरोंको दस्तावेज़ोंकी याददाश्त लिखनी चाहिए,
 (जी) रजिस्ट्रारों तथा सब-रजिस्ट्रारों द्वारा उन किताबोंकी सही की जाने के नियम निश्चित करने के लिए, जो किताबें उनके दफ्तरोंमें दफा ५१ के अनुसार रखी जायंगी,
 (एच) इस बातका एलान करनेके लिए कि क्रमशः १, २, ३ और ४ नम्बर की फेहरिस्तोंमें कौन कौनसी बातें लिखी जानी चाहिए;
 (आई) उन छुट्टियों का एलान करने के लिये जो रजिस्ट्री के दफ्तरों में मनाई जायंगी ।
 (जे) आम तौरसे रजिस्ट्रारों तथा सब-रजिस्ट्रारों की फारवाइशों को नियम-बद्ध करनेके लिए ।

१ जो नियम इस प्रकार बनाये जायंगे, वे स्थानीय-सरकारके पास मंजूरीके लिए भेजे जायंगे, और स्वीकृत हो जाने पर वे सरकारी गज़टमें प्रकाशित किए जायंगे, तथा प्रकाशित हो जाने पर उनका वही प्रभाव होगा मानों वे इसी ऐक्टके अनुसार बनाए गए हों ।

दफा ७० जुर्माना माफ करने के सम्बन्धमें इन्स्पेक्टर-जनरल का अधिकार

इन्स्पेक्टर-जनरलको अधिकार है कि वह अपने अधिकारका प्रयोग करके दफा २५ या दफा ३४ के अनुसार किए गए किसी जुर्माना और रजिस्ट्रीकी उचित फीसकी रकमके बीच जो अन्तर पड़ता है, उसे सम्पूर्ण (कुल) या जोड़ा (जुज) माफ कर दें।

बारहवां प्रकरण

रजिस्ट्री करने से इन्कार किये जाने के विषयमें

दफा ७१ रजिस्ट्री करने से इन्कार किए जाने के कारण लिखे जाने चाहिये

१ प्रत्येक सब-रजिस्ट्रारको चाहिये कि, जब वह सिधाय इस बिना पर कि जिस जायदाद से उसका सम्बन्ध है वह जायदाद उसके परगनेमें वाकै नहीं है, किसी दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करने से इन्कार करे तो, उस इन्कार की सम्बन्धमें अपना हुक्म दे और ऐसे हुक्म के कारणों को अपनी किताब नं० २ में दर्ज करे, तथा उस दस्तावेज़ की पीठ (पुश्त) पर “रजिस्ट्री किए जाने से इन्कार की गई” ये शब्द लिख देने चाहिये; और किसी ऐसे आदमी द्वारा दरख़ास्त दिए जाने पर, जिसने कि दस्तावेज़ लिखी (तकलीम की) है या जो उसके अनुसार दावेदार है, बिना किसी तीस और अनावश्यक विलम्ब के इस प्रकार लिखे गए कारणों की नक़ल दे दी जायगी।

२ कोई भी रजिस्ट्री करने वाला अफ़सर उस दस्तावेज़ को जिसकी पुश्त पर इस प्रकार इन्कार का हुक्म लिख दिया गया है, रजिस्ट्री के लिए उस समय तक भंज़र नहीं कर सकेगा, जब तक कि इसके बाद बतलाए हुए नियमों के अनुसार उस दस्तावेज़ की रजिस्ट्री का हुक्म न दे दिया गया हो।

दफा ७२ उन दशाओं के आतिरिक्त, जबकि दस्तावेज़ के लिखे (तकमील किये) जाने से इन्कार कर दी गई है, सब-रजिस्ट्रार द्वारा दिये गये रजिस्ट्री की इन्कार के हुक्म के विरुद्ध रजिस्ट्रार के पास अपील

१ सिधाय उस दशा के जब कि दस्तावेज़ के लिखने (तकमील किए जाने) से इन्कार किये जाने के कारण रजिस्ट्री करने से इन्कार कर दी गई हो, सब-रजिस्ट्रार के उस हुक्म की, जिसमें उसने दस्तावेज़ की रजिस्ट्री करने से इन्कार कर दी है (चाहे ऐसे दस्तावेज़ की रजिस्ट्री अनिवार्य हो अथवा वैकल्पिक), अपील उस रजिस्ट्रार के यहां की जा सकेगी जिसके कि वह सब-रजिस्ट्रार मातहत है, अगर वह ऐसे रजिस्ट्रार के पास उस हुक्म की तारीख से तीस दिन के भीतर पेश की गई हो, तो रजिस्ट्रार को अधिकार होगा कि वह उस हुक्म को चाहे मंज़ूर करे या बदल दे।

२ अगर रजिस्ट्रार अपने हुक्म में उस दस्तावेज़ की रजिस्ट्री किए जाने की आज्ञा देता है और ऐसे हुक्मके दिए जानेकी तारीख से तीस (३०) दिनों के भीतर वह दस्तावेज़ बाकायदा रजिस्ट्री के लिए पेश किया जाता है, तो सब-रजिस्ट्रार को वह हुक्म मानना चाहिए, और फिर, जहां तक सम्भव हो, दफा ५८, ५९ और ६० में बतलाई हुई कार्रवाई करनी चाहिए, और इस रजिस्ट्री का वही प्रभाव होगा मानों वह दस्तावेज़ उसी समय रजिस्ट्री कर लिया गया था, जब कि वह पहले पहल रजिस्ट्री के लिए बाकायदा पेश किया गया था ।

दफा ७३ जब सब-रजिस्ट्रार दस्तावेज़के, लिखे जाने से इनकार करने के कारण, रजिस्ट्री करने से इन्कार करे, उस समय रजिस्ट्रारको दरखास्त

१ जब किसी सब-रजिस्ट्रार ने किसी दस्तावेज़को इस बिना पर रजिस्ट्री करनेसे इन्कार कर दिया हो कि कोई आदमी, जिसकी लिखी (तकमील की गई) हुई वह बतलाई जाती है, या उसका प्रतिनिधि अथवा मुन्तकिल-अलेह उसके लिखे जाने से इन्कार करता है, तो कोई आदमी, जो उसके अनुसार दावेदार है उसका प्रतिनिधि, मुन्तकिल-अलेह अथवा कारिन्दा, जिसे उपरोक्त रीति से इसका अधिकार दिया गया हो, इनकारी का हुक्म दिए जाने के बाद तीस (३०) दिन के भीतर उस दस्तावेज़ के रजिस्ट्री करा पाने के अपने अधिकार को स्थापित करने की ग़ारंज़ से उस रजिस्ट्रार को दरखास्त दे सकता है जिसके कि वह सब-रजिस्ट्रार भातहत है ।

२ यह दरखास्त लिखित (तहरीरी) होनी चाहिए और इसके साथ छन कारणों की एक नक़ल होगी, जो दफा ७१ के अनुसार दफ्तर-रजिस्ट्रार किए गए हैं; और उस दरखास्त में लिखी गई बातों की तसदीक सायल को इस तरह पर करनी चाहिए जैसा क़ानून के अनुसार अर्ज़ीदावों की तसदीक के लिए आवश्यक है ।

दफा ७४ ऐसी दरखास्तके ऊपर रजिस्ट्रार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

ऐसी दशा में, और उस दशामें भी जब ऐसी इन्कारी, जिसका कि ऊपर बर्णन है, किसी दस्तावेज़ के सम्बन्ध में, जो उसके सामने रजिस्ट्री के लिए पेश किया गया है, किसी रजिस्ट्रार के सामने की गई हो, तो रजिस्ट्रार को चाहिए कि जितनी जल्दी सुगमता के साथ हो सके वह नीचे लिखी बातों को दर्शाए कर ले :—

(ए) क्या दस्तावेज़ लिखा (तकमील किया) गया है ?

(बी) क्या सायल अथवा उस व्यक्ति ने जो दस्तावेज़ को रजिस्ट्री के लिए पेश कर रहा है, जैसी कुछ अवस्था हो, उन बातोंकी तामील कर

की है जो उस समय प्रचलित किसी भी कानून के अनुसार आवश्यक हैं, जिसे दस्तावेज रजिस्ट्री के काबिल हो सके।

दफा ७५ रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री किये जानेके हुक्मका दिया जाना और उसके ऊपर कार्रवाई

१ अगर रजिस्ट्रार को यह मालूम होजाय कि दस्तावेज लिखा गया है और यह कि उपरोक्त आवश्यक बातों की तामील करली गई है, तो वह दस्तावेज की रजिस्ट्री किए जाने के लिए हुक्म दे देगा।

२ अगर ऐसे हुक्म के दिए जाने के बाद तीस (३०) दिन के भीतर दस्तावेज रजिस्ट्री के लिए बाकायदा पेश किया गया हो तो रजिस्ट्री करने वाले अधिकार को चाहिए कि वह उस हुक्म का पालन करे और फिर, जहां तक सम्भव हो उस कार्रवाई को आरम्भ कर दे, जो दफा ५८, ५९ और ६० में बतलाई गई है।

३ ऐसी रजिस्ट्रीका बही प्रभाव होगा मानों वह दस्तावेज उसी समय रजिस्ट्री कर लिया गया था जिस समय वह पहिले पहल बाकायदा रजिस्ट्री के लिए पेश किया गया था।

४ रजिस्ट्रार को अधिकार होगा कि वह दफा ७४ के अनुसार की जाने वाली किसी जांच (Enquiry) की गरज से गवाहों को बजरिये सम्मन तलब करे और उन्हें हाजिर होने के लिए जोर डाले तथा उन्हें गवाही (शहादत) देने के लिए बाध्य करे, मानों वह अदालत-दीवानी है; और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह इस बातका निर्देश करे कि कौन शख्स ऐसी किसी जांच (Enquiry) का पूरा अथवा कुछ अंशमें खर्चा अदा करेगा, तथा ऐसा खर्चा उसी प्रकार वसूल किया जायगा मानों वह जायता-दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी मुकदमें में दिलाया गया हो।

दफा ७६ रजिस्ट्रार द्वारा इन्कारीके हुक्मका दिया जाना

१ प्रत्येक रजिस्ट्रारको,—

(ए) जिसने किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री करने से, सिवाय इस बिना पर कि जिस जायदाद से उसका सम्बन्ध है वह उसके जिले में बाकै नहीं है, अथवा इस बिना परकि उस दस्तावेजकी रजिस्ट्री किसी सब-रजिस्ट्रारके दफ्तर में होनी चाहिए, इन्कार कर दिया हो, या

(बी) जिसने दफा ७४ अथवा दफा ७५ के अनुसार किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री का हुक्म देने से इन्कार कर दिया हो,

चाहिए कि वह इस इन्कारी के सम्बन्ध में हुक्म दे और इस हुक्म के कारणों को अपनी किताब नं० २ में दर्ज करे; और किसी ऐसे आदमी द्वारा,

जिसने दस्तावेज लिखी हो या जो उसके अनुसार दावेदार हो, दरखास्त दिए जाने पर उसे चाहिए कि बिना किसी आवश्यक विलम्ब के, इस प्रकार लिखे गए कारणों की नकल उसे दे दे ।

२ इस दफा के अथवा दफा ७२ के अनुसार दिए गए रजिस्ट्रार के हुक्म की अपील न हो सकेगी ।

दफा ७७ रजिस्ट्रार द्वारा इन्कारीका हुक्म दिये जाने पर नालिशका दायर किया जाना

१ जब कोई रजिस्ट्रार दफा ७२ अथवा दफा ७६ के अनुसार दस्तावेज की रजिस्ट्री का हुक्म देने से इन्कार कर दे, तो कोई भी आदमी, जो उस दस्तावेज के अनुसार दावेदार है, या उसका प्रतिनिधि, मुन्तकिलअलेह अथवा कारिन्दा, इन्कारीके हुक्म दिए जानेके बाद तीस (३०) दिनके भीतर, उस अदालत-दीवानीमें जिसके प्रारम्भिक शासनाधिकार की स्थानीय सीमा के अन्दर वह दफ्तर बाँके है जिसमें कि वह दस्तावेज रजिस्ट्रीके लिये पेश किया गया है, उस दस्तावेज की छसी दफ्तर में रजिस्ट्री किए जाने का हुक्म देने वाली डिकरी दिला पाने के लिए नालिश दायर कर सकता है, अगर दस्तावेज ऐसी डिकरी के दिए जाने के बाद तीस (३०) दिन के भीतर बाकायदा पेश किया गया हो ।

२ दफा ७५ की उप-दफा (२) और (३) में बतलाए हुए नियम, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उन सभी दस्तावेजों के सम्बन्ध में लागू होंगे जो ऐसी किसी डिकरी के अनुसार रजिस्ट्रीके लिए पेश किए गए हों; और यद्यपि इस सेक्ट में कोई बात ऐसी हो, तो भी ये दस्तावेज ऐसी नालिशों में शहादत में लिए जाने योग्य होंगे ।

तेरहवां प्रकरण

रजिस्ट्री, खोज (तलाशी) और नकलोंकी फीसके विषयमें

दफा ७८ फीस स्थानीय-सरकार नियत (मुर्करर) करेगी

स्थानीय-सरकारको चाहिए कि वह नीचे लिखे कामोंके लिए अदा की जाने वाली फीसका नक़्शा तैयार करे:—

- (ए) दस्तावेज़ोंकी रजिस्ट्रीके लिए;
- (बी) रजिस्ट्रियोंकी खोज (तलाशी) करने के लिए;
- (डी) रजिस्ट्रीके पहले, उसके समय अथवा उसके बाद कारणों, इन्दरा; जात या दस्तावेज़ोंकी नक़लें तैयार करने या देनेके लिए,

किसी विशेष (खास) या अधिक फीसका, जो नीचे लिखे कामोंके लिये अदा की जानी चाहिए—

- (डी) प्रत्येक ऐसी रजिस्ट्रीके लिए जो दफा ३० के अनुसार की जाय,
- (ई) कमीशनोंके जारी करनेके लिए;
- (एफ) अनुवाद (तर्जुमा) दाखिल किए जाने के लिए;
- (जी) किसी के निवास-स्थान पर जाने के लिए,
- (एच) दस्तावेज़ोंको सुरक्षित रखने और वापस किए जाने के लिए,
- (आई) दूसरे और ऐसे कामोंके लिए जो स्थानीय-सरकार इस पेक्ट के प्रयोजन के निमित्त आवश्यक जान पड़े ।

दफा ७९ फीस का प्रकाशित किया जाना

इस प्रकार अदा की जाने वाली फीसका नक़्शा सरकारी-ग़ाज़टमें प्रकाशित किया जायगा, और उसकी एक नक़ल, अङ्गरेजी तथा उस भाषामें जो उस जिलेमें प्रयोगकी जाती है, जनता (पब्लिक) के अवलोकनार्थ (देखनेके लिए) प्रत्येक रजिस्ट्रीके दफ़्तरमें रखी रहेगी ।

दफा ८० दस्तावेज़ोंके पेश किए जानेपर अदाकी जानेवाली फीस

इस पेक्टके अनुसार रजिस्ट्री किए जाने के लिए दस्तावेज़ोंकी फीस ऐसे दस्तावेज़ोंके पेश किए जाने पर अदा की जानी चाहिए ।

चौदहवां प्रकरण

दण्डके विषयमें

दफा ८१ हानि पहुंचानेके इरादे से गलत तौर पर दस्तावेजों की तसदीक करने, नक़ल करने, अनुवाद तथा रजिस्ट्री करनेके लिये दण्ड

प्रत्येक रजिस्ट्री करने वाला अफसर, जो इस ऐक्टके अनुसार नियुक्त किया गया हो, तथा प्रत्येक ऐसा आदमी, जो इस ऐक्टके अनुसार किए जाने वाले कामों के लिए उसके दफ्तर में नियुक्त किया गया हो और जिसे इसके नियमानुसार पेश किए गए या दाखिल (जमा) किए गए किसी दस्तावेज़की तसदीक, नक़ल अनुवाद या रजिस्ट्री करनेका काम सिपुर्द किया गया हो, यदि वह उस दस्तावेज़ की तसदीक, नक़ल, अनुवाद या रजिस्ट्री ऐसे ढंगसे करता है जिले वह जानता है, या उसका विश्वास है, कि वह ग़लत है, और इस तरह पर किसी आदमीको कोई ऐसी हानि पहुंचाता है या यह जानता है कि उसे ऐसी हानि पहुंचनेकी सम्भावना है जिसकी परिभाषा ताज़ीरात हिन्दमें की गई है तो, ऐसी मुद्दतकी सज़ा के, जो सात वर्ष तककी हो सकती है, या जुर्माना अथवा दोनों के, दण्डका भागी होगा।

दफा ८२ ग़लत बयान करने, झूठी नक़लें और अनुवाद देने, झूठमूठ कोई दूसरा आदमी बन जाने तथा किसीको अपराधके लिये उद्यत करनेके लिये दण्ड

जो कोई भी शख्स—

(ए) किसी ऐसे अफसरके सामने, जो इस ऐक्टके नियमानुसार कार्य कर रहा हो, इस ऐक्टके अनुसार की जाने वाली कार्रवाई या जांचमें जान-बूझकर कोई ग़लत (झूठा) बयान देगा, वह चाहे दफ्तरके साथ हो या न हो और चाहे वह लिख लिया गया हो या न लिख गया हो; या

(बी) दफा १९ या दफा २१ के अनुसार किसी कार्रवाईमें किसी रजिस्ट्री करने वाले अफसरको किसी दस्तावेज़की झूठी नक़ल या अनुवाद या किसी नक़शा या खाकाकी झूठी नक़ल देगा; या

- (सी) झूठमूठ दूसरा आदमी होनेका बहाना करता है, और ऐसे कल्पित (फर्जी) बेषमें किसी दस्तावेज को पेश करता है, या कोई सम्मन या कमीशन जारी करवाता है, या इस ऐक्टके अनुसार की जाने वाली किसी कार्रवाई या जांचके सम्बन्धमें कोई और ऐसा ही काम करता है; या
- (डी) किसी ऐसे काममें सहायक होता है जो इस ऐक्टके अनुसार दण्ड के योग्य (क्राइमिनेल) है;

वह उतनी मुद्दतकी कैदकी सज़ाके, जो सात वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने या दोनोंके दण्डका भागी होगा।

दफा ८३ रजिस्ट्री करने वाले अफसरको मुकद्दमा चलाने का अधिकार

१ इस ऐक्टके अनुसार किए गए किसी अपराधके बारेमें, जिसका ज्ञान (इल्म) किसी रजिस्ट्री करने वाले अफसरको बहसियत ऐसे अफसर के प्राप्त हो, चलाये जाने वाले मुकद्दमेंकी कार्रवाई, इन्स्पेक्टर-जनरल, सिंधके ब्रांच इन्स्पेक्टर-जनरल, रजिस्ट्रार अथवा सब-रजिस्ट्रारके द्वारा या उनकी आज्ञासे, जिनके प्रान्त, ज़िला अथवा परगनेमें, जैसी कुछ अवस्था हो, वह अपराध किया गया है, आरम्भ की जा सकती है।

२ उन अपराधोंके मुकद्दमें, जो इस ऐक्टके अनुसार दण्डके योग्य हैं कोई ऐसी अदालत या कोई ऐसा हाकिम कर सकेगा जिसके अख्तियारात मजिस्ट्रेट दर्जा दोयमके अख्तियारातसे कम न हो।

दफा ८४ रजिस्ट्री करने वाले अफसर सार्वजनिक नौकर (Public Servant) समझे जायंगे

१ प्रत्येक रजिस्ट्री करने वाला अफसर जो इस ऐक्टके अनुसार नियुक्त किया गया हो ताज़ीरात हिन्दके अर्थमें सार्वजनिक नौकर (Public Servant) समझा जायगा।

२ प्रत्येक आदमी रजिस्ट्री करने वाले ऐसे अफसरको, जब वह उसे ऐसा करनेके लिये कहे, समाचार पहुँचानेके लिए कानूनन बाध्य होगा।

३ ताज़ीरात हिन्दकी दफा २८८ में "अदालती कार्रवाई" शब्दमें इस ऐक्टके अन्वयार्थके अन्वयमें कोई कार्रवाई शामिल समझी जायगी।

पन्द्रहवां प्रकरण

विविधि

दफा ८५ जिन दस्तावेजों का कोई दावेदार न हो उनका नष्ट कर दिया जाना

वे दस्तावेजात (जो वसीयत नामा नहीं हैं) जो किसी रजिस्ट्री के दफ्तरमें दो साल से अधिक समय तक इस प्रकार पड़े रहेंकि उनका कोई दावेदार खड़ा न हो, नष्ट कर दिए जायेंगे ।

दफा ८६ रजिस्ट्री करने वाला अफसर किसी ऐसी बात के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसे उसने बहैसियतमें अफसर के नेक-नीयतीसे किया हो या इन्कार कर दिया हो

किसी भी रजिस्ट्री करने वाले अफसर के ऊपर कोई नालिश, दावा या मतालिवा किसी ऐसी बातके कारण नहीं किया जा सकेगा जिसे उसने बहैसियतमें ऐसे अफसरके नेक-नीयती से किया या इन्कार कर दिया है ।

दफा ८७ इस तरह पर कीगई कोई भी बात नियुक्ति अथवा कार्रवाई में किसी त्रुटि के कारण नाजायज़ नहीं समझी जायगी

कोई भी बात जो किसी रजिस्ट्री करने वाले अफसर ने, इस ऐक्ट के किसी ऐसे ऐक्ट के अनुसार किया हो जो इस ऐक्ट के अनुसार अब मंजूर होगा है, नेकनीयती से किया हो केवल इस कारण से नाजायज़ न समझी जायगी कि उसकी नियुक्ति अथवा कार्रवाई में कोई त्रुटि है ।

दफा ८८ उन दस्तावेजों की रजिस्ट्री जिन्हें सरकारी अफसरों या सार्वजनिक कार्य-कर्ताओं ने लिखा हो

यद्यपि इस ऐक्ट में कोई बात ऐसी हो, तो भी किसी सरकारी अफसर के लिये या बंगाल, मद्रास या बम्बई के ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल के लिए या किसी

अफिशियल ट्रस्टी या अफिशियल असाइनीके लिए या, किसी हाईकोर्टके रजिस्ट्रार शेरिफ (Sheriff) या रिसीवर के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह किसी ऐसे दस्तावेज़के सम्बन्धमें, जिसे उसने बहसियत ऐसे पदाधिकारी (ओहदेदार) के लिखा है, होने वाली कार्रवाई में खय (असालतन) या बज़रिए अपने कारिन्दे के किसी रजिस्ट्री के दफ्तर में हाज़िर हो या दफा ५८ में ब्युलाप अनुसार हस्ताक्षर (दस्तख़त) करे।

२ जब कोई दस्तावेज़ इस तरह पर लिखा गया हो तो रजिस्ट्री करने वाला अफसर, जिसके सामने वह दस्तावेज़ रजिस्ट्री के लिए पेश किया गया हो, अगर वह उचित समझे तो, उसके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिए राज-मन्त्री (गवर्नमेंटके किसी सिक्रेटरी) के पास या ऐसे सरकारी अफसर, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, अफिशियल ट्रस्टी, शेरिफ (Sheriff) रिसीवर या रजिस्ट्रारके पास उस मामले को भेज सकता है और उसके लिखे जाने (तकमील) के सम्बन्ध में इतमीनान कर लेने पर वह उस दस्तावेज़ की रजिस्ट्री कर देगा।

दफा ८९ कुछ हुक्मों, सर्टीफिकेटों तथा दस्तावेज़ों की नक़लों का रजिस्ट्री करने वाले अफसर के पास भेजा जाना और उनका फाइल किया जाना

१ प्रत्येक ऐसे अफसर को, जो लैण्ड इम्प्रूवमेंट ऐक्ट सन् १८८३ ई० के अनुसार किसी क़र्ज़ की मंजूरी दे रहा हो, चाहिए कि वह अपने हुक्म की एक नक़ल उस रजिस्ट्री करने वाले अफसरके पास भेजदे जिसके शासनाधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर कुल अथवा कुछ भाग उस आराज़ी का, जिसकी उन्नति करना है, या उस आराज़ी का, जो बतौर उसकी किफ़ालत मज़ीद के दीजानी है, बाँके है; और ऐसा रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस नक़ल को अपनी किताब नं० १ में फाइल (नथी) कर लेगा।

२ प्रत्येक ऐसी अदालत को, जो ज़ाबता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी जायदाद गैर-मनकूला की नीलाम का सर्टीफिकेट दे रही हो, चाहिए कि वह ऐसे सर्टीफिकेट की एक नक़ल उस रजिस्ट्री करने वाले अफसर को भेज दे जिसके शासनाधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर उस जायदाद गैर-मनकूलाका कुल या कोई हिस्सा बाँके है जो इस सर्टीफिकेट में शामिल है; और ऐसा रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस नक़ल को अपनी किताब नं० १ में फाइल (नथी) कर लेगा।

३ प्रत्येक ऐसे अफसर को, जो एग्रीकल्चरिस्ट्स लोनस ऐक्ट सन् १८८४ ई० के अनुसार किसी क़र्ज़ की मंजूरी दे रहा हो, चाहिए कि वह उस दस्तावेज़की, जिस के अनुसार क़र्ज़ा के वापस दिला पाने के लिए जायदाद गैर-मनकूला रहन की गई है, एक नक़ल और, अगर क़र्ज़ाकी मंजूरी देने वाले हुक्ममें उसी कामके लिये

ऐसी कोई जायदाद रेहन की गई है तो, उस हुयम की भी एक नकल उस रजिस्ट्री करने वाले अफसर के पास भेज दे जिसके शासनाधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर इस प्रकार रेहन की गई जायदाद का कुल या कुछ हिस्सा वाकै है, और वह रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस नकल या उन नकलों को, जैसी कि अवस्था हो, अपनी किताब नं० १ में दर्ज कर लेगा ।

४ प्रत्येक रेविन्यू अफसर को जो उस जायदाद गैर-मनकूलाके खरीदार को नीलामका सार्टीफिकेट दे रहा हो जो आम नीलाममें फरोख्त की गई है चाहिए कि ऐसे सार्टीफिकेट की एक नकल उस रजिस्ट्री करने वाले अफसर के पास भेज दे जिसके शासनाधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर सार्टीफिकेट में शामिल जायदाद का कुल या कुछ हिस्सा वाकै है; और वह रजिस्ट्री करने वाला अफसर उस नकल को अपनी किताब नं० १ में फाइल (नथी) कर लेगा ।

वे कागज़ात जिनपर यह ऐक्ट लागू नहीं है

दफा ९० सरकार द्वारा या उसके हकमें लिखे गए कुछ दस्तावेजों का अलगाव

१ इस ऐक्ट में या इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८७७ ई० में या इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८७९ ई० में या किसी ऐक्टमें, जो उसके अनुसार मंसूख कर दिया जा चुका है, कोई भी बात ऐसी न समझी जायगी जिसके अनुसार नीचे लिखे किसी दस्तावेज या नक़्शे की रजिस्ट्री की आवश्यकता हो या हुई हो, अर्थात्:—

(ए) उन दस्तावेजों (कागज़ात) की जिनको किसी ऐसे अफसर (हाकिम) ने जमा किया हो, प्राप्त किया हो, या तस्दीक किया हो जो मालगुजारी का बन्दोबस्त करने या बन्दोबस्त को दोहराने में लगा हुआ हो और जो दस्तावेज ऐसे बन्दोबस्त के कागज़ात का एक हिस्सा हों; या

(बी) उन दस्तावेजों और नक़्शों की जिनको किसी ऐसे अफसर ने जारी किया हो, प्राप्त किया हो या सही किया हो जो सरकार की ओर से किसी आराज़ी (ज़मीन) की पैमायश करने या पैमायश को दोहराने में लगा हुआ हो, और जो दस्तावेज ऐसी पैमाइश के कागज़ात का एक हिस्सा हो ;

(सी) उन कागज़ात की जो उस समय प्रचलित किसी क़ानून के अनुसार एक निश्चित समय पर पटवारी लोग या दूसरे अफसर, जिनको गाँवके स्यादा तैयार करनेका काम सिपुर्द किया गया है, किसी दफ्तर (Revenue office) में दाखिल किया करते हैं; या

(डी) उन सनदों, इनाम के लेख पत्रों (Inam title deeds) तथा दूसरे ऐसे कागज़ात को जो सरकार द्वारा ज़मीन के या ज़मीन में किया

हक के सम्बन्ध में दिए गए दान-पत्र (Grant) या दस्तावेज़ इन्तकाल हैं या प्रमाणित होते हैं; या

(ई) बम्बई लैण्ड रेविन्यू ऐक्ट सन् १८७९ ई० दफा ७४ या दफा ७६ के अनुसार दखीलकारों द्वारा दिए गए अपनी दखल के इस्तीफ़ों की या ऐसी ज़मीन के ज़मीन्दारों द्वारा किए गए इन्तकाल आराज़ी की नोटिसों की ।

२ ऐसे सभी कागज़ात (दस्तावेज़ात) और नक़्शे दफा ४८ और ४९ के प्रयोजन के लिए इस ऐक्ट के नियमानुसार रजिस्ट्री किए गए हुए और रजिस्ट्री किए जाने वाले समझे जायेंगे ।

दफा ९१ ऐसे दस्तावेज़ातका निरीक्षण और नक़लें

ऐसे नियमों पर और ऐसी फीस के पेशगी अदा कर दिए जाने पर, जिन्हें स्थानीय-सरकार इस सम्बन्धमें निर्धारित (निश्चित) करे, सभी वे दस्तावेज़ात (कागज़ात) और नक़्शे जिनका, वर्णन दफा ९०, कलॉज़ (ए), (बी), (सी) और (ई) में किया गया है और दस्तावेज़ों के सभी रजिस्टर जिनका वर्णन कलॉज़ (डी) में किया गया है, उन सभी आदमियों के देखने के लिए खुले रहेंगे जो इसके लिए दरखास्त दें; और उन्हीं बातों की पाबन्दी में रहते हुए, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसे दस्तावेज़ों की नक़लें उन सभी आदमियों को दी जायेंगी जो उनके लिए दरखास्त करें ।

दफा ९२ ब्रह्माके रजिस्ट्री के नियमोंकी स्वीकृति

इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८७७ ई० के आरंभ होने से पूर्व रजिस्ट्री सम्बन्धी जिन नियमों का प्रयोग लोअर चर्मा (ब्रह्मा) में किया जाता था वे कानून समझे जायेंगे, और उपरोक्त किसी नियम के अनुसार की गई किसी बात के सम्बन्ध में किसी अफसर या दूसरे आदमी के विरुद्ध कोई नालिश या कार्रवाई न की जा सकेगी ।

मंसूखी

दफा ९३ मंसूखी

१ परिशिष्ट-भाग में बतलाए हुए कानून का उतना अंश मंसूख किया जाता है जिसका विवरण उसके चौथे कालम में दिया हुआ है ।

२ उस दफा में कोई भी बात ऐसी न समझी जायगी जो किसी ऐसे कानून के नियमों पर कोई प्रभाव डाल सके, जो (कानून) ब्रिटिश-भारत के किसी भी भाग में प्रचलित है और जो स्पष्टतः इस ऐक्ट के अनुसार मंसूख नहीं किया गया है ।

(३६०)

परिशिष्ट

कानूनों की मसूखी (देखो, दफा १३)

वर्ष	नम्बर	संक्षिप्त नाम	कितना अंश मसूख किया गया ?
१८७७ ई०	३	इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८७७ ई०	सम्पूर्ण
१८७९ ई०	१२	इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट । लिमिटेशन संशोधक ऐक्ट सन् १८७९ ई०	उतना हिस्सा जितना मसूख नहीं किया गया था ।
१८८३ ई०	१९	लैण्ड इम्प्रूवमेंट लॉन्स ऐक्ट सन् १८८३ ई०	दफा १२ का उतना अंश जितना मसूख नहीं किया गया था ।
१८८६ ई०	७	इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८७९ ई०	सम्पूर्ण
१८८८ ई०	७	ज़ाबता दीवानी एमेण्डमेंट ऐक्ट सन् १८८८ ई०	जितना मसूख नहीं किया गया था
१८९१ ई०	१२	संशोधक ऐक्ट सन् १८८९ ई०	परिशिष्ट में ऐक्ट ३ सन् १८७७ ई० के सम्बन्धमें किए गए इन्दराजित
१८९९ ई०	१७	इण्डियन रजिस्ट्रेशन एमेण्डमेंट ऐक्ट सन् १८९९ ई०	सम्पूर्ण

इत्यलम् ।

रजिस्ट्रेशन ऐक्टके विषयको सरल रीतिसे समझाने के लिये इस ऐक्ट की जरूरी जरूरी दफ्ताओंके विषय को एक जगह पर करके साधारण व्याख्या नीचे देते हैं, और आवश्यक नजीरों का भी तत्सम्बन्धी विषयके साथ उल्लेख करते हैं ताकि पाठकों को कानून समझने और काम में लानेके लिये अधिक सहायता मिले।

रजिस्ट्रेशन ऐक्ट नम्बर १६ सन् १९०८ ई०

जिन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री अनिवार्य (लाजिमी) है—उनका वर्णन दफा १७ में किया गया है। नीचे लिखे दस्तावेजों की रजिस्ट्री की जानी चाहिए:—

- १ (ए) जायदाद गैर-मनकूला का हिवानामा (Instrument of gift)
- (बी) दूसरे गैर-वसीयती दस्तावेज जो किसी जायदाद गैर-मनकूला में या उसके लिए एक सौ रुपया या अधिक की मालियत के किसी हक (Right), हकीयत (Sitle) या हिस्सा (Interest) को चाहे वह प्राप्त (हासिल शुदः) हो या उसपर निर्भर करता (Contingent) हो, पैदा करता हो, एलान करता हो, मुन्तकिल करता हो या नष्ट (Extinguish) करता हो, फिर चाहे वह वर्तमान समय के लिए हो या भविष्य के लिए।
- (सी) गैर-वसीयती दस्तावेज जो ऐसे किसी हक, हकीयत, या हिस्सेके पैदा किए जाने, एलान किए जाने, मुन्तकिल किये जाने सीमाबद्ध किए जाने या नष्ट किए जानेके बदले में की गई किसी रकम की वसूलयाबी या अदायगी को स्वीकार करता हो; और
- (डी) जायदाद गैर-मनकूला के सालाना या एक साल से अधिक मुद्दत के लिए या सालाना किराया (या लगान को) सुरक्षित रखने वाले पट्टे।

२ कलॉज (बी) और (सी) में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो—

- (१) किसी तस्फियानामा के सम्बन्ध में; या
- (५) किसी ऐसे दस्तावेज के सम्बन्ध में, जो स्वयं तो किसी जायदाद गैर-मनकूला में या उसके लिए एक सौ रुपया या अधिक की मालियतके किसी हक, हकीयत या हिस्से को पैदा, एलान, मुन्तकिल, सीमाबद्ध या नष्ट नहीं करता, किन्तु सिर्फ एक दूसरे दस्तावेज के प्राप्त करने का अधिकार (हक)

पैदा करता है जो, जब कि उसकी तकमील होजायगी, किसी भी ऐसे हक, हकीयत या हिस्से को पैदा करेगा, एलान करेगा; मुन्तकिल करेगा, सीमाबद्ध करेगा या नष्ट करेगा; या

(६) किसी अदालत की किसी डिकरी या हुक्मके सम्बन्धमें या किसी पंचायती फैसला के सम्बन्धमें; या

(८) किसी मुहतामिम माल (Revenue officer) द्वारा किए गए बटवारे के दस्तावेज के सम्बन्ध में; या

(११) किसी दस्तावेज रेहननामा की पुस्तपर कीगयी तहरीर ज़हरी (Endorsement) के सम्बन्ध में जिससे ज़र-रेहन के कुल या किसी हिस्से की अदायगी को स्वीकार किया गया हो, या किसी दूसरी रसीद के सम्बन्ध में, जो किसी रेहननामा की बाबत वाजिब रुपये की निस्वत लिखी गई हो, जब कि रसीद का मंशा उस रेहननामा को नष्ट कर देने का न हो; या

(१२) किसी भी नीलाम के सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में जो किसी दीवानी या माल के हाकिम द्वारा नीलाम कीगई जायदाद के खरीदार को दिया गया हो ।

[कलॉज़ २, ३, ४, ७, ९, और १० के लिए देखो दफा १७ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट]

३ किसी लड़के को गोद (दत्तक) लेने के लिए दिए गए अधिकार पत्र की भी, जो तारीख १ जनवरी सन् १८७२ ई० के बाद लिया गया हो और जो वसीयत के ज़रिये दे न दिया गया हो, रजिस्ट्री की जानी चाहिए (देखो दफा १७ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट)

जिन दस्तावेजोंकी रजिस्ट्री इच्छा पर निर्भर (मुताअदी) है

उनका वर्णन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की दफा १८ में किया गया है । वे ये हैं:—

(ए) वे दस्तावेज (सिवाय हिबानामा और वसीयतनामों के) जो किसी जायदाद गैर-मनक़ला में या उसके लिए एक सौ रुपया से कम की मालियत के किसी हक, हकीयत या हिस्से को चाहे वह प्राप्त (हासिलशुदः) हो या उसपर निर्भर (Contingent) हो पैदा करता हो, एलान करना हो, मुन्तकिल करता हो, सीमाबद्ध करता हो या नष्ट करता हो या जिसका मंशा ऐसा करने का हो, फिर वह चाहे वर्तमान समय के लिए हो या भविष्य के लिए;

(बी) वे दस्तावेज जो ऐसे किसी हक, हकीयत या हिस्से के पैदा किए जाने, एलान किए जाने, मुन्तकिल किए जाने, सीमाबद्ध किए जाने या नष्ट किए जाने के बदले में कीगई रुपये की वसूलयावी या अदायगी को स्वीकार करता हो;

(सी) किसी मुद्दत के लिए, जो एक साल से अधिक न होगी, किए गए जायदाद गैर-मनकूला के पट्टे, और वे पट्टे जो दफा १७ के अनुसार छोड़ दिए गए हैं;

(डी) वे दस्तावेज़ (निवाय वसीयतनामों के) जो किसी जायदाद मनकूला में या उसके लिए किसी हक, हकीयत या हिस्से को पैदा करता हो, एलान करता हो, मुन्तकिल करता हो, सीमाबद्ध करता हो या नष्ट करता हो या उसका मंशा ऐसा करने का हो;

(ई) वसीयतनामों और

(एफ) तमाम ऐसे दूसरे दस्तावेज़ जिनकी दफा १७ के अनुसार रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है [दफा १८ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट],

ब्याख्या—दफा १७ एक ऐसी दफा है जो मनुष्य को विवश कर देती है। दफा १७ और १८ का जो सम्मिलित प्रभाव है वह संक्षेप में इस प्रकार है:— जायदाद गैर-मनकूला के हिचानामों की रजिस्ट्री ज़रूरी है, फिर उन की रकम चाहे कुछ भी हो। हिचा की परिभाषा कानून-इन्तकाल-जायदाद की दफा १२३में की गई है। कानून इन्तकाल जायदादकी दफा १२३के अनुसार दस्तावेज़ हिचानामा के ऊपर कमसे कम दो गवाहों की तस्दीक भी होनी चाहिए जैसा कि रेहननामों में होता है (देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा १२३] जायदाद मनकूला रजिस्ट्रीशुद्ध: दस्तावेज़के ज़रिये हिचाकी जा सकती है और जायदादको हवाले करके। जायदाद गैर-मनकूला की मुन्तकिली के दूसरे दस्तावेज़ों की अर्थात् जो किसी हक (Right) या हकीयत (Title) को पैदा करते हों, एलान करते हों, मुन्तकिल करते हों, सीमाबद्ध करते हों या नष्ट करते हों, उदाहरणार्थ, दस्तावेज़ बपनामा, रेहननामा, बदलाव, हवालगो और दस्तबन्दारी (Release) इत्यादि की, भी रजिस्ट्री अवश्य की जानी चाहिए, अगर उस जायदाद की मालियत १००) रु० या उससे अधिक हो। अगर मालियत १००) से कम है, तो उसकी रजिस्ट्री इच्छापर निर्भर करती है अर्थात् वह लाज़िमी नहीं सुताबदी है, सिवाय रेहनसादा के जिसकी रजिस्ट्री कराना ज़रूरी है, चाहे उसकी मालियत १००) रु० से कम क्यों न हो [देखो कानून इन्तकाल जायदादकी दफा ५९], उपरोक्त नियमोंके परिणाम स्वरूप उन दस्तावेज़ोंकी भी रजिस्ट्री ज़रूर कराई जानी चाहिए जिनसे १००) रु० या उससे अधिक की मालियत की जायदाद गैर-मनकूला के ऐसे किसी हक या हकीयत के पैदा किए जाने, मुन्तकिल किए जाने, नष्ट किए जाने इत्यादि के बदले में की गई किसी रकम की वसूल-गामी को स्वीकार किया गया हो। उदाहरण के लिए, वह रसीद जो किसी जायदाद गैर-मनकूला के खरीदार की ओर से उसके बेचने वाले (Vendor) को उस रुपये की वावत, जोकि दुबारा खरीद की वावत दिया गया है, इस शर्त के साथ दी गई हो कि इस दुबारा फरोकृत (Resale) की निस्वत एक स्टाम्प लगा हुआ दस्तावेज़ लिख दिया जायगा, देखो 21 B. 533. इसी प्रकार वह रसीद भी जो पूर्वदिन के अधिकारों (हकूक) को नष्ट कर दिए जाने के

लिफ कीगई ज़र-रेहन की अदायगी के लिए दीगई हो, देखो 6 A. 835, लेकिन ज़र-रेहन के किसी एक हिस्से की अदायगी की रसीद नहीं, देखो 40 I. C. 898 (M.); 3 M. 53. अगर मालियत १००) ४० से कम है, तो ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराना इच्छापर निर्भर करता है।

जायदाद गैर-मनकूला के सालाना पट्टों, या किसी मुद्दत के, जो एक साल से अधिक न हों, पट्टों अथवा ऐसे पट्टों की, जिनसे सालाना लगान (या किराया) की रक्षा होती है, रजिस्ट्री अनिवार्य (लाज़िमी) है [देखो दफा १७ (डी), रजिस्ट्रेशन ऐक्ट]। यह क्लॉज़ कानून-इन्तकाल-जायदाद की दफा १ के पैरा १ के समान है जो ज़िराअती पट्टों के सम्बन्ध में लागू नहीं होता। पट्टा (Lease) की परिभाषा कानून-इन्तकाल जायदाद की दफा १०५ में कीगई है दफा १०७ में पट्टों का उल्लेख है, अर्थात् जायदाद की वाकई मुन्तकिली के पट्टों का पट्टा देने के इकरारनामा का नहीं (देखो 25 C. W. N. 220)। रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अनुसार पट्टा (Lease) में मुसन्ना, कबूलियत, जोतने या कृष्ठा करनेके लिए इकरारनामा और पट्टा देनेका इकरार भी शामिल है (देखो दफा १७ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट), यह बात स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे पट्टा के लिखने का इकरार, जिसकी रजिस्ट्री अनिवार्य (लाज़िमी) है, मौजूदा इन्तकाल जायदाद के अनुसार होना चाहिए (देखो 47 C. 485 P. C.; 25 C. W. N. 550; 44 M. 899), जायदाद गैर-मनकूला के उन पट्टों की रजिस्ट्री जिनकी मुद्दत एक साल से अधिक नहीं है, और उन पट्टों की, जो दफा १७ के अनुसार छोड़ दिए गए हैं, लाज़िमी नहीं हैं बल्कि वह लिखने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है।

स्टाम्प ऐक्ट के अनुसार, वह पट्टा, जो किसी काइतकार के सम्बन्ध में बास्ते काइतके लिखा गया हो (इसमें उन दरख्तों का पट्टा भी शामिल है जो खाने या पीने की चीज़ पैदा करने के लिए दिए गए हों), और जिसमें किसी जुमाने या किस्त की अदायगी या हवालगी न हो, स्टाम्प से मुस्तसना होगा, जब कि कोई खास मुद्दत ज़ाहिर कर दीगई हो और ऐसी मुद्दत एक साल से जायद न हो, या जब कि सालाना लगान (या किराया) की रकम एक साल से ज्यादा न हो।

गोद लेने सम्बन्धी अधिकार-पत्रकी, जो वसीयतनामों में न हो, अवश्य रजिस्ट्री की जानी चाहिए। वसीयतनामा की रजिस्ट्री अनिवार्य (लाज़िमी) नहीं है। दफा १७ के क्लॉज़ (बी) और (सी) में दस्तावेजों की रजिस्ट्री अनिवार्य (लाज़िमी) होने के सम्बन्ध में जो नियम बतलाए गए हैं वे उक्त दफा की उप-दफा १ में बतलाए गए दस्तावेजों के सम्बन्ध में लागू नहीं होते।

उन दस्तावेजों की रजिस्ट्री न कराने का परिणाम जिनकी रजिस्ट्री अनिवार्य (लाज़िमी) है दफा १७ के साथ साथ दफा ४९ के नियमों को भी भंग में रख लेना अत्यावश्यक है जो इस प्रकार है:—

“दफा ४९—कोई भी ऐसा दस्तावेज़, जिसकी दफा १७ के अनुसार रजिस्ट्री अनिवार्य है—

- (प्र) उसमें बतलाई हुई किसी भी जायदाद गैर-मनकूला पर कोई असर न डाल सकेगा, या
- (बी) गोद लेने सम्बन्धी कोई अधिकार न दे सकेगा, या
- (सी) किसी भी ऐसे मामले के सम्बन्ध में शहादत में न लिया जा सकेगा जिससे ऐसी जायदाद पर कोई असर पड़ता हो या जिससे ऐसा अधिकार दिया गया हो, जब तक कि उसकी रजिस्ट्री न होजाय।

व्याख्या—दफा ४९ को रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की दफा १७ और कानून शहादत की दफा ९१ के साथ पढ़ना चाहिए। “असर पड़ता हो” के सम्बन्ध में देखो 46 M. 349. यद्यपि दफा ४९ किसी ऐसे बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेज को कुबूल किये जाने से रोकती है जिसकी रजिस्ट्री लाज़िमी है, तथापि इसी तरह के दूसरे मामलों में यह कुबूल किया जा सकता है, जैसे यह दिखलाने के लिए कि कब्ज़ा कैसा है और कब्ज़े की तारीख क्या है (देखो 6 M. L. T. 192; 45 A. 565.),

रजिस्ट्री के लिये दस्तावेज पेश करने का समय—वसीयतनामाको छोड़ (देखो दफा १७, रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्री के लिये लिया न जायगा जबतक कि तकमील की तारीख से चार महीने के भीतर न पेश किया गया हो (दफा २३) जब किसी दस्तावेज की तकमील भिन्न भिन्न आदमियों ने भिन्न भिन्न समयों पर की हो तो वह हर एक तकमील की तारीख से चार महीने के भीतर रजिस्ट्री (Registration) तथा दुबारा रजिस्ट्री (Re-Registration) के लिये पेश किया जा सकता है (दफा २४)। जब विलम्ब का कारण कोई अनिवार्य घटना हो और चार महीने से अधिक विलम्ब न हुआ हो तो रजिस्ट्रार, जुर्माना अदा कर देने पर उसे ले सकता है जिसकी तादाद रजिस्ट्री फीस की रकम के दशगुने से ज्यादा न होगी (दफा २५)।

व्याख्या—जो दस्तावेज पेश किया गया है उसपर तारीख होने की जरूरत नहीं है। मियाद की तारीख साबित करने के लिये कागज़ी या ज़बानी शहादत मान ली जा सकती है (देखो C. L. J. 126; फ्रीकैन के आचरणों से मियादकी मुदत पर कोई असर नहीं पड़ता देखो 5 C. 820 एक दस्तावेज रेहननामा के तकमील कुनिन्दा ने चार महीने बाद तारीख बदल कर उसकी रजिस्ट्री कराई। अगर यह मान भी लिया जाय कि उसकी रजिस्ट्री बेजा हुई थी राहिन उसमें कोई उत्तरदारी नहीं कर सकता (देखो 16 C W. N. 585; ऐसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री नाजायज़ है जो समय के बाद पेश किये गये हों देखो 43 M. 288.

रजिस्ट्री करानेका स्थान—दफा १७ (१) कलाज़ (ए), (बी), (सी) और (डी) तथा दफा १८ के कलाज़ (ए), (बी) और (सी) में बतलाए हुए दस्तावेज उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश किये जायेंगे जिसके परगने (Sub District) में वह कुल या कुछ जायदाद जिसके सम्बन्ध में वह दस्तावेज है, बाँके है (दफा-

२८)। दूसरे दस्तावेज़ भी किसी ऐसे दफ्तर में पेश किए जा सकते हैं जहाँपर फ़रीक़ेन उनकी रजिस्ट्री कराना चाहते हों (दफा २९)। खास वजह होने पर किसी शख्स के मकान पर भी रजिस्ट्री की जा सकती है (दफा ३१)।

न्याया—अगर कोई जायदाद, जो दूसरे ज़िला में बाँके है, फ़र्ज़ी तौरपर (Fictitiously) किसी दस्तावेज़ में इस इरादे से शामिल कर दी गई हो कि उनकी रजिस्ट्री उस ज़िले में की जाय, यद्यपि दोनों फ़रीक़ेन ने कभी भी जान बूझ कर यह इरादा नहीं किया था कि यह ज़मानत में शामिल की जाय तो रजिस्ट्री नाजायज़ हो जायगी, देखो 25 C. W. N. 985 P. C. ; 60 I. C. 833; 48 C. 509; 40 M. L. J. 489; इसी प्रकार जब दस्तावेज़ रेहननामा में बतलाई गई जायदाद का हिस्सा राहिनों की मिल्कियत नहीं था और उसमें सिर्फ़ इसलिये शामिल कर दिया गया था कि रजिस्ट्रार को उसकी रजिस्ट्री करने का अधिकार पैदा हो जाय तब हुआ कि यह फ़रेब है और इसलिये रजिस्ट्री नाजायज़ है देखो 46 M. 435; 41 C. 972; P. C. ; 55 I. C. 511; 43 M. 436; 49 I. C. 543; (A). जब किसी दस्तावेज़ रेहननामा की रजिस्ट्री किसी ऐसे स्थान पर कराई गई हो जहाँ पर उस जायदाद का केवल एक हिस्सा ही बाँके है यद्यपि वह जायदाद राहिन की न मी हो तो वह अपने ही फ़रेब के काम से फायदा नहीं उठा सकता, देखो 66 I. C. 681 (A). एक दस्तावेज़ रेहननामा में दूसरी मद इस लिये शामिल कर दी गई थी कि उस दस्तावेज़ की रजिस्ट्री राहिन के मकान के पास के स्थान पर कराई जाय, तब हुआ कि यह एक जायज़ रेहननामा है देखो 38 M. L. J. 251; 58 I. C. 849; [M]; 4 Pat. L. J. 438; 52 I. C. 446.

जिस दस्तावेज़ की रजिस्ट्री किसी ऐसे स्थान पर की गई हो जहाँपर उस जायदाद का, जिसकी निस्वत वह दस्तावेज़ लिखा गया है कोई भी हिस्सा बाँके नहीं है वह दस्तावेज़ नाजायज़ है और शहादत में कुबूल किए जाने के काबिल नहीं है देखो 3 L. 242; 41 C. 972; 49 I. C. 343; 26 C. W. N. 369.

अगर फ़रेब नहीं किया गया है तो सिर्फ़ इस बात से कि इन्तकाल कुनिदा को उस जायदाद के सम्बन्धमें कोई हक़ीयत हासिल नहीं है जिससे सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री करने का अधिकार पैदा होता हो वह रजिस्ट्री नाजायज़ नहीं हो जाती देखो 44 I. C. 399; (P); 48 I. C. 200; A.

रजिस्ट्री के लिये दस्तावेज़ कौन पेश कर सकता है—रजिस्ट्री किए जाने वाले दस्तावेज़ों को नीचे लिखे आदमी पेश कर सकते हैं:—

(ए) वह शख्स जिसने उसकी तकमोल की हो या जो उसकी निस्वत दावेदार हो, अथवा अगर कोई डिकरी या हुक़म है तो वह शख्स जो उस डिकरी या हुक़म की निस्वत दावेदार हो, या

(बी) ऐसे शख्स का मुन्तकिल अल्लेह या प्रतिनिधि, या

(सी) ऐसे शख्स का सुख्तार, प्रतिनिधि या मुन्तकिल अलैह, जिसे बज़ारिये तहरीरी और तस्दीक शुदः सुख्तारनामाके बाकायदा अख्तयार दिया गया है (दफा ३२) ।

ब्याख्या—“प्रतिनिधि” से तात्पर्य कानूनी प्रतिनिधि से है या दफा २ के अनुसार वली अथवा उन लोगों की कमेटी से है जिनका पूरा पूरा पता व निशान बताया गया हो इसमें खुदरार या सुख्तार शामिल नहीं हैं । प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में दफा ३२ के नियम ताकीदी हैं देखो 50 C. 166 P. C; 44 M. L. J. 732; 26 C. W. N. 369 P. C.; 68 I. C. 754.

दस्तावेज़ की पुस्त पर सब रजिस्ट्रार की ओर से यह लिख दिए जाने से कि दस्तावेज़ बाकायदा तौर पर उस अदमी द्वारा पेश किया गया है जिसके पास सुख्तारनामा मौजूद था, यह अनुमान होता है कि इस सुख्तारनामा की वा ज़ाबता तकमील की गई थी देखो 44. A. 375 P. C; 69 I. C. 44; 67 I. C. 315.

किसी ऐसे शख्स द्वारा पेश किए जाने से, जिसे रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अनुसार ऐसा करने का अधिकार नहीं है, दस्तावेज़ नाजायज़ हो जाती है, 50 C. 166 P. C; 2 L. 5; 58 I. C. 333.

जब कोई दस्तावेज़ किसी शख्स ने अपनी ओरसे तथा किसी दूसरे शख्स की ओर से लिखा हो, तो उसे उसके पेश करने का पूर्ण अधिकार है देखो 31 C. L. J. 447.

रजिस्ट्री करने से इन्कार—अगर कोई शख्स किसी दस्तावेज़ की तकमीली से तो उसके सामने पेश किया है इन्कार कर दे तो सब रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री से इन्कार कर देगा [दफा २५ (३) (ए)] अगर सबरजिस्ट्रार ऐसे कर सकने सम्बन्धी अपने अधिकार के अतिरिक्त और किसी कारण से किसी दस्तावेज़ की रजिस्ट्री ना मंज़ूर कर दे तो उसे इसके लिए कारण लिखना चाहिये और उस दस्तावेज़ की पुस्त पर ये शब्द लिख देने चाहिये कि “ रजिस्ट्री ना मंज़ूर की गई ” (दफा ७१) ।

सिवाय उस दशा में जबकि रजिस्ट्री इस बिना पर नामंज़ूर कर दी गई हो कि दस्तावेज़ की तकमील से इन्कार कर दी गई है, रजिस्ट्रार के यहाँ अपील की जा सकेगी अगर वह तीस दिन के भीतर पेश की गई हो (दफा ७२) .

जब सब-रजिस्ट्रार ने इस बिना पर रजिस्ट्री करने से इन्कार कर दी हो कि दस्तावेज़ की तकमीली से इन्कार की जाती है तो वह शख्स जो इससे नाराज़ है या उसका प्रतिनिधि तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रारको यह दरखवास्त दे सक्ता है कि दस्तावेज़ रजिस्ट्री करा पाने सम्बन्धी उसका अधिकार मान लिया जाय इस दरखवास्त की बाकायदा तस्दीक की जानी चाहिये और उसके साथ दफा ७१ में बताई हुई वजहोंकी नक़ल शामिल की जानी चाहिये (दफा ७३) । रजिस्ट्रार

इस मामले की जांच करेगा और अगर उसे उस दस्तावेज़ की तकमीकी की निस्वत इसमीनान हो जाय तो दफ़ा ७७ में बतलाये अनुसार उस दस्तावेज़ की रजिस्ट्री का हुकम दे देगा

रजिस्ट्रार के रजिस्ट्री से इन्कार कर देने पर दीवानी नालिश—जब रजिस्ट्रार ने दफ़ा ७२ या दफ़ा ७६ के अनुसार रजिस्ट्री का हुकम देने से इन्कार कर दिया हो तो जिस शख्स को इससे नाराज़ी है वह या उसका प्रतिनिधि उस हुकम की तारीख़ से ३० दिन के भीतर अदालत दीवानी में नालिश दायर कर सकता है कि दस्तावेज़ की रजिस्ट्री का हुकम दिये जाने की डिकरी दी जाय (दफ़ा ७७)

दफ़ा १७ जिन दस्तावेज़ों का रजिस्ट्री अनिवार्य है—अमालनामा, जिसमें यह व्यवस्था की गई हो कि लगान साल-ब-साल अदा किया जाय, यह कि असामी पैमायश और लगान का तस्फ़िया करे और यह कि पट्टा और कबूलियत एक महीने के भीतर लिख दिए जाय, पट्टा देने का इकरारनामा है और इसलिए उसकी रजिस्ट्री लाज़िमी है, देखो 18 C. W. N. 38; 7 Cal. 703 F. B.

बिना रजिस्ट्री किए हुए हुकमनामा की, जिसपर एक आना का स्टाम्प लगा हो और जिसका मंशा पट्टा (Lease) पैदा करना है जिसकी कोई मुदत मुक़रर नहीं है और जिसका लगान २॥) रु० मुक़रर किया गया है, रजिस्ट्री लाज़िमी है, देखो 1922 Pat 10. 1922 P. 265.

पट्टा देने के इकरारनामा के अर्थ के सम्बन्ध में देखो 47. C. 485 P. C.; 71 I. C. 466; 45 A. 220.

इस बात का विचार करने में, कि अमुक पट्टे की रजिस्ट्री कराना लाज़िमी है या नहीं, जिस बात की जांच करना ज़रूरी है वह यह है कि पट्टा सिर्फ़ एक साल के लिए ही दिया गया था या एक साल से अधिक के लिए। जब कोई पट्टा सिर्फ़ एक साल के लिए हो लेकिन पट्टेदार को यह अख्तियार दिया गया हो कि अपनी इच्छा से वह एक साल से अधिक समय तक भी काबिज़ रह सकता है, तो इस अधिकार से एक से अधिक समय तक के लिए पट्टे की मियाद बढ़ नहीं जाती और ऐसी दशा में उस दस्तावेज़ की रजिस्ट्री लाज़िमी नहीं है देखो 37 C. L. J. 475; 70 I. C. 570. पट्टा देने को जिस इकरारनामा की रजिस्ट्री ज़रूरी है, वह ऐसा होना चाहिए जिससे जायदाद पर फ़ौरन कब्ज़ा दिए जाने की बात हो, देखो 44 M. 399; 62 I. C. 354; 54 I. C. 134 (B); 26 C. W. N. 329.

एक रसीद में बयाने के तौर पर २५) रु० की रकम की अदायगी स्वीकार की गई और उसमें इकरार किया गया कि मुदई को अमुक ज़मीन का पट्टा दिया जायगा। तब हुआ कि इसकी रजिस्ट्री कराई जाना ज़रूरी है, देखो 4 L. 44; 78 I. C. 927.

वह पट्टा जो एक साल के लिए दिया गया हो और जिसमें दूसरे साल के लिए पट्टा बदल देने का भी अधिकार हो, ऐसा पट्टा नहीं है जिसकी मियाद एक साल से अधिक हो, देखो 17 C. 548; 14 M. 271; 8 Bom. L. R. 581. साल-बसाल कब्ज़ा देने का इकरारनामा वास्तव में साल-ब-साल पट्टा देने का इकरारनामा है और इसलिए उसकी रजिस्ट्री कराना ज़रूरी है, देखो 17 C. L. J. 167.

जब पट्टा देने के इकरारनामा की बात एक से अधिक पत्रों से प्रकट हो गई हो, तो कुल लिखा-पढ़ी की, विशेष कर उस पत्र की जिसमें पट्टा देने और लेने की बात है, रजिस्ट्री कराना ज़रूरी है, देखो 30. M. L. J. 519.

पट्टा देने का इकरारनामा उस समय तक जब तक कि उसकी रजिस्ट्री न हुई हो, ऐसे इकरारनामा की तामील खासके लिए कीगई नालिश में शहादत में कुबूल न किया जायगा। फिर चाहे कब्ज़ा दिया गया हो या न दिया गया हो, देखो 8 I. C. 520; 16 I. C. 390; 72 I. C. 98 (C.).

एक पत्र (खत) में पट्टा शुरू होने की मियाद दी हुई थी और उसमें यह लिखा हुआ था कि एक बाकायदा पट्टा लिखकर उसकी रजिस्ट्री करा दी जायगी। उसमें यह भी लिखा था कि इस पत्र (खत) की खास खास शर्तें दोनों फ़ीक़ैनके लिए मान्य होंगी। तब हुआ कि बिना रजिस्ट्री के वह काबिल तस्दीम नहीं है, देखो 45 A. 220; 71 I. C. 452.

पटनीपट्टाके लिये लिखा गया वयाना पत्र जिसमें बदले में मिलने वाले रुपये के एक हिस्से की अदायगी को कुबूल किया गया है और जिसमें यह शर्त है कि वयाना-पत्र की तारीख़ से फिर पट्टा दे दिया जायगा और एक निश्चित तारीख़ के पहिले पट्टा और कुबूलियत लिख दिये जायंगे, पट्टा देने का इकरारनामा नहीं है और उसकी रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है देखो 25 C. W. N. 550; 64 I. C. 747; 24 C. W. N. 177 P. C. ; 37 C. 808;

पट्टा देने का इकरारनामा, जिससे उसी समय आराज़ी दे दी गई हो दफा १७ (डी) में बतलाया हुआ इकरारनामा है और तामील खास की नालिश में शहादत में कुबूल किए जाने के काबिल नहीं है अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। उसकी रजिस्ट्री तो भी होना चाहिये यद्यपि उक्त इकरारनामा के अनुसार असादी काबिज़ भी हो गया हो देखो 26 C. W. N. 329; 49 C. 507.

रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की दफा ४९ सिर्फ़ उन्ही दस्तावेज़ों के सम्बन्ध में लागू होती है जिनकी रजिस्ट्री उस ऐक्ट की दफा १७ के अनुसार की जाने को है उन दस्तावेज़ों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती जिनकी रजिस्ट्री बंगाल टिर्नैसी ऐक्ट के अनुसार की जाने को है। इसलिये एक साल से अधिक के लिये दिया गया बिना रजिस्ट्री किया हुआ पट्टा जिसकी रजिस्ट्री कानून इन्तकाल जायदाद की दफा १७ के अनुसार रजिस्ट्री कराई जाती है रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की दफा १७ के

अनुसार नहीं, उस दस्तावेज़ के अनुसार कब्ज़े की किस्म को साबित करने के लिए कुबूल किए जाने के काबिल है देखो 44 M. 55 F. B. 59 I. C. 350.

रेहन सादा के राहिन की ओर से लिखे गये पत्र (खत) के जिसमें रेहन करने का उद्देश्य क्या है यह दिखलाया गया है कि रजिस्ट्री करानेकी ज़रूरत नहीं है देखो 22 C. N. W. 758.

किसी डिकरी की इजरा मुस्तवी कराने के लिये लिखे गये तमस्सुक की जिसके ज़रिये १००) रु० से ज्यादा मालियत की जायदाद रेहन कर दी गई हो रजिस्ट्री लाज़िमी है, देखो 53 I. C. 463 (L); 31 M. 330.

किसी बयनामा के बाद लिखा गया इकरारनामा, जिसमें रुपया अदा करने पर फ़क़ रेहनी की शर्त की गई है वास्तव में रेहननामा है और वह रजिस्ट्री के काबिल है देखो 72 I. C. 34, 1. Bur. L. J. 223.

ऐसे इकरारनामा की जिससे किसी रेहननामा की शर्तों में रद्द बदल की गई हो रजिस्ट्री लाज़िमी है, देखो 17 C. W. N. 233 P. C.

किसी रजिस्ट्री शुद्ध दस्तावेज़ की शर्तों को बदलने वाले दस्तावेज़ की ज़रूर रजिस्ट्री होनी चाहिये, देखो 27 C. L. I. 107.

रेहननामा के ऊपर दिया हुआ कर्ज़ा जायदाद गैर मनकूला है। अगर किसी दस्तावेज़ के ज़रिये उसकी मुन्तकिली कर दी गई है और उसकी मालियत १००) रु० से अधिक है तो उसकी रजिस्ट्री लाज़िमी है देखो 22 C. W. N. 641.

ऐसे दस्तावेज़ की जिससे मुतहिन अपने जर रेहनमेंसे १००) रु० से अधिक की रकम छोड़ देने का इकरार करे रजिस्ट्री लाज़िमी है देखो 44 I. C. 132; 34 M. L. J. 79 35 A. 202.

यह इकरारनामा जिससे असली और जाती जायदाद के कुल हक़ इस बिना पर छोड़ दिये गये कि मुद्दा अलेह गोंधाला को १०००) रु० की रकम दे देगा बिना रजिस्ट्री के कुबूल किये जाने के काबिल नहीं है देखो 56 I. C. 595 (L.)

ऐसा दस्तावेज़, जिससे किसी मौजूदा पट्टा के अनुसार अदा किए जाने वाले लगान की रकम में फेर-बदल किया गया हो, देखो 16 C. W. N. 55 F. B.; 10 C. L. J. 570; 37 C. 293. रजिस्ट्री होगी।

ऐसा दस्तावेज़ जिसमें किसी पट्टा के अनुसार अदा किए जाने वाले लगान में रद्द-बदल करने के लिए सुआहिदा किया गया हो, वास्तव में पट्टा (Lease) है। और इसलिए उसकी रजिस्ट्री लाज़िमी है, देखो 27 C. L. J. 107; 35 Cal. 1010; 39 Cal. 284. जिस दस्तावेज़ में पहिले के किसी पट्टा के अनुसार अदा किए जाने वाले लगान के कम करने का इकरारनामा किया गया हो उसकी रजिस्ट्री लाज़िमी है, देखो 16 I. C. 62 (C); 39 C. 284.

बटवारा के नक़शा और चिट्ठा की, जिसमें अलग अलग लोगों के हिस्से दिखलाए गए हों, रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं है, देखो 47 I. C. 159.

बटवारा के दस्तावेजों की रजिस्ट्री अवश्य कराई जानी चाहिए, देखो 15 C. W. N. 375; 11 C. L. J. 25; 69 I. C. 859 (A); 39 M. L. J. 382.

जब कि किसी शख्स ने १००) ६० से अधिक मालियत की जायदाद का बटवारा किया हो और इस बटवारा को दिखलाने के लिए एक दस्तावेज लिख दिया हो तो इस दस्तावेज की रजिस्ट्री लाज़िमी है। अगर वह उन बातों की याददाश्त के तौर पर लिखा गया है जो पहिले तय हुआ था तो उसकी रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं है, देखो 15 I. C. 28; 229 P. L. R. 1912.

हिस्सेदारों के नाम हिस्सोंको लिखने वाला दस्तावेज वास्तवमें बटवाराका दस्तावेज है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि, चूंकि स्टाम्प लगा हुआ कागज़ अभी नहीं मिल सका, इसलिए वह ख़रीद लिया जायगा और दस्तावेज लिख दिया जायगा, देखो 69 I. C. 612. बटवारा का कच्चा दस्तावेज, जिसके बाद बाज़ा-बता दस्तावेज लिखा जाना चाहिए, काबिल रजिस्ट्री है, देखो A. I. R. 1923 Bom. 464. परन्तु यह तय किया गया है कि कोई भी फ़रीक़ इस बात को साबित कर सकता है कि जायदाद की "शेअर लिस्ट" अर्थात् फेहरिस्त हिस्से-दारान, कतई बटवारा नहीं है किन्तु यह ज़बानी इकरार हुआ था कि बाज़ाबता दस्तावेज लिख दिया जायगा। अगर यह बात साबित होजाय, तो "शेअर लिस्ट" बिना रजिस्ट्री के भी काबिल तस्लीम है, देखो 69 I. C. 569 (M).

जिस दस्तावेज से हक़ पैदा या नष्ट किया जाता हो, उसकी रजिस्ट्री लाज़िमी है, यद्यपि वह तमलीक़ खान्दानी (Family settlement) हो, देखो 75 I. C. 593 (A). इसी प्रकार एक वही की भी रजिस्ट्री लाज़िमी है जिसमें तमलीक़ खान्दानी की शर्तों का इन्दराज हो, A. I. R. 1923 Lah. 392. किसी वही में किया गया वह इन्दराज, जिस पर किसी भी फ़रीक़ के दस्तख़त न हों, ऐसा दस्तावेज नहीं है जो कोई हक़ पैदा करता हो, देखो 75 I. C. 642.

जिन रसीदों के ऊपर भाइयों ने एक बटवारे के समय दस्तख़त कर दिए थे जिसमें वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कुटुम्ब की सम्पत्ति के उन हिस्सों को स्वीकार किया था जिनकी तफ़सील रसीदों में है, उन रसीदों की रजिस्ट्री लाज़िमी है, देखो 44 B. 881.

याददाश्त की, जिसमें यह बतलाया गया है कि शिराक़त तौड़ दीगई है और यह व्यवस्था कर दीगई है कि आज की तारीख़ से फ़रीक़ैन अलग अलग हिस्सों पर काबिज़ होंगे और यह कि बटवारा की निश्चत एक अलग दस्तावेज तैयार कर दिया जायगा, रजिस्ट्री लाज़िमी नहीं है, देखो 69 I. C. 123 P. C.

किसी ऐसे "ट्रस्टीनामा" की रजिस्ट्री लाज़िमी नहीं है जिसमें सिर्फ़ यह लिख दिया गया है कि मालिक ने माल मतरूका से अपना ताल्लुक़ छोड़ दिया

है और उसे परमेश्वर के कृपा मालिकाना में छोड़ दिया है, देखो 42 A. 60 P. C.; 32 C. L. J. 471.

किसी विधवा स्त्रीकी ओरसे लिखा गया दस्तावेज़ जिससे उसने १००) या उससे अधिककी अपनी सम्पत्तिको रिवर्सनरों (वारिस मावाद)के हकमें छोड़ दिया है, देखो 14 I.C. 749; 27 I.C. 699 रिवर्सनरकी ओर से, इस बातका एलान किए जाने के लिए नालिश न करने की बाबत किये गए इकरारनामा की, कि विधवा की ओर से लिखा गया दस्तावेज़ जायज़ नहीं है, रजिस्ट्री, उस विधवा के मरने के बाद लाज़िमी नहीं है, देखो 16 A. L. J. 191; 40 A. 384.

किसी ऐसे सुलहनामा की रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, जिसमें किसी मुकद्दमें से सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं और जो एक डिकरी के अन्तर्गत हैं, यद्यपि उससे १००) रु० से अधिक मालियत की जायदाद मुन्तकिल की गई हो, देखो 24 C. W. N. 328; 54 I. C. 538. इसी प्रकार आर्डर २१, रूल २ जाबता दीवानी, के अनुसार दी गई सुलहनामा की दरख्वास्त की भी, देखो 43 M. 688; 58 I. C. 534; (36 M. 47; 27 M. L. J. 651 Over-ruled)

मुकद्दमें से बाहर की जायदाद के सम्बन्ध में किए गए सुलहनामा की रजिस्ट्री ज़रूरी है, देखो 25 I. C. 377 (Cal.); 16 C. L. J. 71; 19 C. W. N. 347; 36 Mad. 46; 2 C. L. J. 343; 5 C. L. J. 611; 11 C. L. J. 543; 48 C. 1059; 31 P. R. 1919.

मुकद्दमें के बाहर की जायदाद से सम्बन्ध रखने वाली सुलहनामा की दरख्वास्त उस जायदाद में हासिल हकूक की मुन्तकिली के लिए किए गए इकरारनामाकी शहादत है और इसकी रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 1 Pat. L. J. 208; 22 Mad. 508; I. C. L. J. 406; 7 C. L. J. 496; 46 I. 358 (P.); 3 Pat. L. J. 43; 58 I. C. 299 (P.); 52 I. C. 201 (P.).

१००) रु० से ऊपर की मालियत के लगान आयन्दा के लिए लिखे गए रेहननामाकी रजिस्ट्रीकी ज़रूरत है, देखो 6 I. C. 504.

जिस सुलहनामा के ज़रिये फकरेहनी का हक पैदा होता हो, उसकी रजिस्ट्री लाज़िमी है, देखो 32 All. 206.

ऐसे सुलहनामा की, जो डिकरी में शामिल नहीं कर दिया गया है और जो ठीक ठीक अर्थ लगाए जाने पर पट्टा मालूम हुआ, केवल पट्टा देने का इकरारनामा नहीं है तो रजिस्ट्री करना ज़रूरी है, देखो 44 I. C. 638.

हाथ-चिट्ठी के ऊपर दायर की गई एक नालिश में एक सुलहनामा दायर किया गया जिसमें डिकरी के सम्बन्ध में रजामन्दी जाहिर की गई और कुछ जायदाद गैर-मनकूला मुन्तकिल की गई, तब हुआ कि इसकी रजिस्ट्री लाज़िमी थी, देखो 46 I. C. 243 (C.)

आर्डर २३, कूल ३ (जायदादी की) के अनुसार किए गए सुलहनामा की शर्तों की, जो लिख ली गई हैं, रजिस्ट्री होनी चाहिए; लेकिन अगर डिकरी में वे शर्तें लिखी हैं, तो वह दस्तावेज़, यद्यपि उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, शहादत में तस्लीम किए जाने के काबिल है, देखो 4 L. 263; 75 I. C. 461.

जब किसी सुलहनामा के जरिये फौरन अख्तियार दे दिया गया हो, तो उसकी रजिस्ट्री अवश्य होनी चाहिए और वह बतौर पट्टा के काबिल तस्लीम है। वह इसलिए और भी ज्यादा काबिल तस्लीम है कि उसमें मुद्दाअल्लेह ने खास तौर से पहिले के एक मुकदमें में मुद्दई के हक को तस्लीम किया है, देखो 27 C. W. N. 897.

दफा १७ के कलॉज (डी) की शर्त गलई लगाने के सम्बन्ध में भी लागू होती है, देखो 15 I. C. 682 (Mad.)

जब किसी जायदाद की हकीयत किसी बिना रजिस्ट्री किए हुए हिबानामा के कारण पैदा हुई हो, और स्वयं जायदाद की मालियत १०० रु० से ऊपर हो, तो वह दस्तावेज़ हिबानामा नाकाबिल तस्लीम है। अगर वह हिबा किसी दावा के निस्वत किए गए सुलहनामा के कल स्वरूप किया गया होता तो वह काबिल तस्लीम हो सकता था, देखो Lah. L. J. 7.

जिस दिन पूरे तौर से दस्तावेज़ बयनामा लिख दिया गया था उसी दिन उस जायदाद को फिर मुन्तकिल कर देने के लिए उसी के साथ एक इकरारनामा भी लिख दिया गया था। तब हुआ कि इस इकरारनामा की रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत है, देखो 49 I. C. 699 (M.)

हक इन्फ़काक रेहन के बिना रजिस्ट्री किए हुए बयनामा की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में देखो 23 C. W. N. 513.

जिन दस्तावेज़ों की रजिस्ट्री अनिवार्य (लाज़िमी) नहीं है—वह रसीद जिससे दस्तावेज़ रेहननामा में बतलाए हुए चक्रवृद्धि ब्याज (सुद दर सुद) के भदा करने की ज़िम्मेदारी से कोई शख्स बरी किया गया हो, देखो 42 C. 546.

उस रसीद की, जिससे सिर्फ़ ज़र-रेहन की अदायगी को स्वीकार किया गया है, रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसमें किसी नए इकरारनामा की बात को स्वीकार किया गया हो तो उसकी रजिस्ट्री ज़रूर कराई जानी चाहिए, देखो 26 I. C. 360 जिस दस्तावेज़ में किसी ज़र-रेहन की पूरी पूरी बेचाकी की बात स्वीकार की गई हो और ब्याज की अदायगी माफ़ कर दी गई हो, उसकी रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 43. M. 803.

उस मुर्तहिन ने, जिसके पास जायदाद बाद में रेहन की गई थी, पहिले के दो रेहननामों का रुपया अदा कर दिया था। तब हुआ कि इसकी ज़िम्मेदारी रसीद मिली उसकी रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं है, देखो 11 C. L. J. 551.

राहिन की ओर से मुर्तहिन के नाम लिखे गए पत्र की, जिसमें उस काम का जिक्र किया गया हो जिसके लिए दस्तावेज़ हकीयत मुर्तहिन के पास अमानत किया गया है, रजिस्ट्री लाज़िमी नहीं है, देखो 22 C. W. N. 758.

मुर्तहिनों की ओर से रहिनों को दीगई रसीदें दफा १७ के अन्दर नहीं आतीं और जब तक कि उनका मज़मून ऐसा न हो कि उससे जायदाद ग़ैर-मन कूला में किसी हिस्से को खासतौर से सीमाबद्ध या नष्ट न कर दिया गया हो, उनकी रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 72 I. C. 454 (C)

सौ रुपया से अधिक की जायदाद की बिक्री के लिए किए गए मुआहिदे के सम्बन्ध में अदा कीगई बयाने की रकम की रसीद की, जिसमें साफ़ साफ़ यह बतला दिया गया हो कि बतौर दस्तावेज़ हकीयत के दूसरा दस्तावेज़ लिख दिया जायगा, रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 73 I. C. 1013 (L).

जिस दस्तावेज़ में यह बतलाया गया हो कि जायदाद ग़ैर मनकूला का बटवारा होगया है और फ़रीक़ैन लोगों का कब्ज़ा अलग अलग हो गया है, उस दस्तावेज़ की रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 53 I. C. 123 (L).

जिस दस्तावेज़ के जरिये किसी नए ट्रस्टी की नियुक्ति कीगई हो, उसकी रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं है, देखो 6 M. L. T. 240.

जिन कागज़ों के ऊपर पंचों ने बतौर अपने पंचायती फैसले के दस्तख़त किए हों उनकी रजिस्ट्री ज़रूरी नहीं है, देखो 22 I. C. 412. जिस पंचायती फैसलेमें उन जायदादों की फेहरिस्त हो जो पंचों द्वारा किए गए बटवारा में लोगों के हिस्से में दीगई हैं और जिसपर फ़रीक़ैन बटवारा के दस्तख़त हों उसकी रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 66 I. C. 118; 46 I. C. 685.

जिस पंचायती फैसले को फ़रीक़ैन ने दाख़िल अदालत किया हो और अदालत ने उसे मंज़ूर कर लिया हो, उसकी रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 43 I. C. 697; 20 A. 171. अगर यह पंचायती फैसला दस्तावेज़ बटवारा का काम करता है, तो अवश्य उसकी रजिस्ट्री कराई जानी चाहिए, देखो 12 C. L. J. 25; 18 C. W. N.; 475.

रेहन करने के लिए किए गए इक़रारनामा की ज़रूरत नहीं है, देखो 41 M. 959; 35 N. L. J. 489. इसी प्रकार उस इक़रारनामा की भी रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है जिससे फ़करेहनी का हक़ पैदा होता हो, देखो 47 B. 283; 24 M. 449.

पट्टा देने वाले और पट्टा पाने वाले के बीच हुए इक़रारनामा की याददास्त की, जो न तो पट्टा है और न पट्टा देने का इक़रारनामा, रजिस्ट्री लाज़िमी नहीं है और वह शहादत में कुबूल किए जाने के काबिल है, देखो 19 C. W. N. 56,

किसी जायदादका, जिसकी निस्वत नालिशनहीं है, इस्तरारी पट्टा देनेका इक़रार उस दरख़वास्त में किया गया जो वास्ते सुलहनामा के दीगई थी और इस दरख़वास्त के ऊपर उस मुक़द्दमें में डिकरी दे दीगई। तय हुआ कि पट्टा देने के इक़रारनामा तामील की खास के लिए दायर किए गए मुक़द्दमें में वह दस्ता-

नेत्र सुदूत में पेश किया जा सकता है, देखो 19 C. W. N. 347; 17 M. L. J. 218; 14 C. W. N. 66; 39 Cal 663.

मुकदमा जीत जाने पर जायदाद मुतनाजा की मुन्तकिली के लिए किए गए इकरारनामा की रजिस्ट्री लाज़िमी नहीं है, देखो 1 L. 124; 56 I. C. 372.

'ब' के साथ एक मुकदमें में मुलहनामा की भर्जी में 'अ' ने कुछ ज़मीन का पट्टा देने का वादा किया बशर्ते कि उस ज़मीन की निस्वत 'स' के साथ चलते हुए मुकदमें में वह कामयाब हो जाय। 'अ' यह मुकदमा जीत गया और इसके बाद उसने पट्टा देने से इन्कार, कर दिया। तब हुआ कि यह मुलहनामा पट्टा देने के लिए इकरारनामा नहीं है और बिना रजिस्ट्री के भी वह काबिल तस्लीम है, देखो 47 C. 485; P. C.

अदालत के बाहर किया गया इकरारनामा, जिसके ज़रिये से मुद्दइयों ने यह इकरार किया कि वे मुद्दा-अलेह को कुछ हकूक के साथ और लगान की एक खास शरह के ऊपर अपना अस्सामी बनाए रहेंगे और इस इकरारनामा के परिणाम स्वरूप एक बाज़ावता कबूलियत लिख दी जायगी, पट्टा या पट्टा देने का इकरारनामा नहीं है। यह एक ज़बाजी इकरारनामा की याददाश्त है, देखो A. I. R. 1923 Cal. 432; 67 I. C. 57; 39 C. 663.

मुलहनामा की भर्जी प्लीडिंग है और इसलिए उसकी रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 22 I. C. 35; 20 All. 1; 71 P. C.; 22 I. C. 687; 45 I. C. 331. दीवानी मामलों के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल किए गए बयान इलफ़ी, भर्जियों और प्लीडिङ्ग्स की रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 46 I. C. 358 (L).

तलब किए जाने पर जायदाद को फिर बेंच (Re-Convey) देने के लिए किए गए इकरारनामा की रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 25 Bom. L. R. 1207; 63 I. C. 22.

जिस दस्तावेज़ के ज़रिये हकीयतका एलान तो किया गया हो लेकिन वह अमल में लाई न गई हो वह दफ़ा १७ (१) (बी) के अन्दर नहीं आता है, देखो A. I. R. 1923 Lah. 497; (2).

मुकसान होजाने की दशा में जायदाद मुन्तकिल कर देने के लिये किया गया इकरारनामा तथा बाद में लिखा गया पत्र, जिसमें मुकसान (घाटा) की बात को स्वीकार किया गया है, ऐसा दस्तावेज़ बयनामा नहीं है जिसकी रजिस्ट्री की ज़रूरत है, देखो 26 C. W. N. 201 P.C.; 65 I. C. 954.

जिस जायदाद की निस्वत नालिश दायर की गई है, उस जायदाद में, मुकदमें बाज़ी में लगाए गए रुपये के बदले में, हिस्सा दिए जाने के लिए किए गए इकरारनामा की रजिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, देखो 4 Lah. L. J. 301.

एक मकान का ८ आना महीने किराये पर पट्टा दिया गया और उसमें यह शर्त लिख दी गई कि किराया अदा न करने पर किरायेदार बेदखल कर दिया जायगा। तब हुआ कि यह एक साल से अधिक मियाद का पट्टा नहीं है और उसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, देखो 2 L. 300; 65 I. C. 254.

किसी अनिश्चित समयके लिए लिखे गये पट्टेकी, जो कुछ शर्तोंके ऊपर किसी भी समय बन्द हो जा सकता है, लेकिन जिसके लिए यह निश्चय नहीं है कि वह एक साल से ज्यादा दिन तक बना रहेगा, रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है, देखो 65 I. C. 836; 20 A. L. J. 211.

जिन दस्तावेजों की रजिस्ट्री लाजिमी है लेकिन जिनकी रजिस्ट्री नहीं काई गई है, उनका उसी किस्म के कामों में लया जाना—बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज बयनामा रुपये की अदायगी का सुबूत माना जा सकता है, देखो 35 B. 438; Bom. 128; 2 I. C. 516. बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज उस तारीख की निस्वत क़ाबिल तस्लीम समझा जा सकता है जिस तारीख को कब्ज़ा लिया गया था, देखो 45 A. 565.

एक बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज बयनामा जिसमें (१) दहेज की रकम और (२) यह कि ससुरने यह रुपया अदा करनेका पक्का वादा कर लिया था, साबित करने के लिए कुबूल कर लिया गया, देखो 44 I. C. 837 वह यह साबित करने के लिए भी कुबूल किया जा सकता है कि कब्ज़ा किस किस्म का था, देखो 57 I. C. 965 (C.). लेकिन इससे बय की हुई जायदाद कैसी थी, यह बात साबित नहीं की जा सकती, देखो 61 P. L. R. 1919.

बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज कब्ज़े की किस्म दिखलाने के लिए काम में लाया जा सकता है, देखो 6 M. L. T. 192; 29 Mad. 336 F. B. जैसे दस्तावेज हिवानामा, देखो 26 O. W. N. 65; 34 C. L. J. 432.

किसी बिना रजिस्ट्री किए हुए पट्टे में स्वीकार की गई बातें उसी किस्म के कामों के लिए (for Collateral purpose) जैसे उस मुआहिदा से पैदा होने वाले कर्ज़ के लिए, काम में लाई जा सकती हैं देखो 33 B. 610. बिना रजिस्ट्री किया हुआ पट्टा उसमें स्वीकार की गई बातों को साबित करने के लिए काम में लाया जा सकता है, देखो 61 I. C. 328 (L).

जिस पट्टा की रजिस्ट्री कराना लाजिमी है लेकिन जिसकी रजिस्ट्री नहीं कराई गई है वह सही लगान तय करने के लिए काम में नहीं लाया जा सकता है, देखो 1916 M. W. N. 5; 35 Mad. 63; 41 Cal. 347; 18 M. L. T. 483. और न वह हक रैयती या उसकी शर्तों को साबित करने के काम में लाया जा सकता है, देखो 30 M. L. J. 492; 34 I. C. 6. और न मियाद की मुदत साबित करने के लिए ही, देखो 63 I. C. 90.

बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज़ उसी किस्म के कामों के लिए भी जैसे बकवृद्धि ब्याज (सूद दर सूद) अदा करने की शर्त को साबित करने के लिए, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, देखो 34 I. C. 853 (M).

बिना रजिस्ट्री किया हुआ अमलनामा और ज़बानी शहादत भी किसी मुआहिदा को साबित करने के लिए काम में लाए जा सकते हैं जब कि नालिश का मंशा उसकी तामील खास करा पाने का हो, देखो 16 I. C. 390 (Cal); 11 C. L. J. 548; 12 C. L. J. 25; 12 C. L. J. 464. लेकिन पट्टा देने के लिए किया गया बिना रजिस्ट्री किया हुआ इकरारनामा, जिसका मंशा उसी समय जायदाद पर कब्ज़ा दे देने का हो, तामील खास के लिए दायर की गई नालिश में काबिल तस्लीम नहीं है, देखो 26 C. W. N. 329.

बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज़ द्विबानामा उसी किस्म के कामके लिये भी, जैसे यह कि मौहूबअलेह ने कब्ज़ा कर लिया और उसपर अपना कब्ज़ा मुहल्लिफ़ाना बनाए रहा, काममें नहीं लाया जा सकता, देखो 44 I. C. 889 (L).

बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज़ बटवारा यह साबित करने के लिये कि उसमें बतलाये हुए शरीकदार अलग अलग होगये हैं और यह साबित करने के लिए कि उनमें जायदाद मनकूला के सम्बन्धमें क्या क्या बातें तय पाईं, काममें लाया जा सकता है, देखो 19 M. L. J. 228; 16 Mad. 336.

सुलहनामाकी एक अर्ज़ीमें कुछ जायदादका कब्ज़ा छोड़ देने के लिए किए गए इकरारनामाको, जो किसी फौजदारी अदालतमें दाखिल किया गया हो, शहादतमें कुबूल किए जाने के काबिल बनाने के लिए उसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी नहीं है, देखो 43 I. C. 26 (Cal).

कब्ज़ा तस्लीम किया गया, यह बात साबित करने के लिए बिना रजिस्ट्री किया हुआ सुलहनामा काममें लाए जाने के काबिल है, देखो 46 I. C. 44 (Cal).

एक सौ १००) रुपये से अधिकका बिना रजिस्ट्री किया हुआ दखली खतनामा इस बातको साबित करने के लिए काममें लाया जा सकता है कि मुहबअलेह बहसियत मुर्तहिन के काबिज़ था, देखो 45 M. L. J. 667.

दस्तावेज़का पेश किया जाना—तकमील कुनिन्दा के सामने किसी नौकर द्वारा दस्तावेज़का पेश किया जाना जायज़ है, देखो 10 A. L. J. 510. दफा ३२ में पेश करनेका एक विशेष (परिभाषिक) अर्थ है। जब सब-रजिस्ट्रारको दस्तावेज़ दिए जाने के समय तकमील कुनिन्दा हाज़िर हो, तो यह पेश करना समझा जायगा; फिर चाहे किसी भी शख्सने सारी कार्रवाई की हो, देखो 9 A. L. J. 362; 9 A. L. J. 149.

जबकि बाकायदा अधिकार पाए हुए किसी अफसर द्वारा दस्तावेज़ पेश किए जाने के पहिले वह शख्स, जिसे उस दस्तावेज़के पेश करनेका अख्तियार था,

उस अफसर के सामने हाज़िर हुआ और रजिस्ट्रीके सम्बन्धमें अपनी स्वीकृति देदी, माना गया कि यह पेश किया जाना है, देखो 35 All. 134.

लड़की की ओरसे जिसे इस सम्बन्धमें कोई अधिकार नहीं है, दस्तावेज़का पेश किया जाना पेश किया जाना नहीं है, देखो 18 I. C. 286. राहिनकी मौजूदगीमें नौकर द्वारा दस्तावेज़ का पेश किया जाना जायज़ है, देखो 35 A. 72

किसी आम मुक़्तार द्वारा, जिसे तंक्मील कुनिन्दाकी रियासतके सम्बन्ध में कुछ कार्यवाई करनेका अफ़रार है, पेश किया जाना जायज़ है, देखो 23 C. W. N. 534.

बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेज़ोंपर रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेज़ोंको तर्जिह—
दफ़ा ५० उस दशामें लागू नहीं होती जबकि उस शख्सको, जो बादमें लिखे गए बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेज़के अनुसार दावेदार है, यदि पहिले लिखे गए बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेज़का पता मिल जाय, देखो 18 C. W. N. 657; 8 C. 597, 10 C. L. J. 241, 6 B. 515, 8 A. 540, 16 M. 158. इस सम्बन्धमें, कि क्या कब्ज़ा, नोटिस है, देखो 16 A. 478 F. B., 27 B. 452 16 C. 414; दफ़ा ५० का विस्तार-क्षेत्र कितना है, इस सम्बन्धमें देखो 1 M. L. J. 43.

किसी रजिस्ट्रीशुदः दस्तावेज़ रेहननामाके ऊपर दीर्गई डिकरीके अनुसार कीर्गई नीलाममें—पहिलेका बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज़ नाजायज़ नहीं होजाता और कर्ज़का रुपया उस रक़ममें से वसूल किया जासकता है जो रजिस्ट्रीशुदः दस्तावेज़ रेहननामाका रुपया वसूल देकर बाकी रहा हो, देखो 35 A. 271.

दफ़ा ५० उस समय लागू नहीं होती जबकि रजिस्ट्रीशुदः दस्तावेज़ फ़रेब से लिखाया गया हो, देखो 49 I. C. 839 या जबकि ख़रीदारको ख़रीद करने से पहिलेकी हकीयतका पता हो देखो 42 I. C. 393. दफ़ा ५० से बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेज़के अनुसार प्राप्त अधिकार नाजायज़ या नष्ट नहीं होते, देखो 35 A. 271.

किस अवस्थामें बिना रजिस्ट्री किए हुए दस्तावेज़के ऊपर दीर्गई बाद वाली डिकरीके ऊपर रजिस्ट्रीशुदः दस्तावेज़को तर्जिह दीजाती है, इस सम्बन्ध में देखो 13 A. 288; 18 B. 355 F. B; 25 M. 1.

पहिले लिखा हुआ बिना रजिस्ट्री किया हुआ दस्तावेज़ बयनामा, जिसकी रजिस्ट्री लाजिमी नहीं है और जिसके साथ साथ जायदादपर दख़ल दे दिया गया है, उसी जायदादकी निस्वत बादमें लिखे गए रजिस्ट्रीशुदः दस्तावेज़ बयनामा से नाजायज़ नहीं होजाता, देखो 44 I. O. 354 (P.).

जबदरती रजिस्ट्री कराने के लिए दीवानी नालिश—दफ़ा ७७ के अनुसार दायर कीजानेवाली नालिशमें नीचे लिखी बातें ज़रूरी हैं:—(१) दस्तावेज़ किसी ऐसे

आदमी द्वारा पेश किया गया हो जिसे इसके पेश करनेका अधिकार है; (२) सब-रजिस्ट्रारने रजिस्ट्री करानेसे इन्कार करदी हो, (३) रजिस्ट्रार के पास समयके भीतर अपील कीगई हो; (४) रजिस्ट्रारने इन्कार करदी हो; (५) समयके भीतर नालिश दायर कीगई हो, देखो 73 I. C. 182. अगर डिकरी दीगई हो तो दस्तावेज़ डिकरीकी तारीखसे ३०दिनके भीतर उसे अवश्य पेशकर दिया जाना चाहिए, देखो 1 P. 146. दफ़ा ७७ के अनुसार नालिश दायर करने के पहिले मुद्दई को चाहिए कि वह रजिस्ट्रेशन ऐक्टमें बतलाए हुए नियमोंका स्तौरपर पालन करे, देखो 27 C. L. J. 538.

जब तकमील कुनिन्दोंके हाज़िर न होने के कारण सब-रजिस्ट्रारने किसी दस्तावेज़की रजिस्ट्रीसे इन्कार करदी हो और रजिस्ट्रारने इस हुक्मको बहाल रखा हो, तो नालिश दायर की जासकती है। दफ़ा ३१ और ७१-७७ के विस्तार के सम्बन्धमें विचार किया गया, देखो 47 B. 290; 54 I. C. 570 (C).

इस वजहसे, कि दस्तावेज़ समयके बाहर पेश किया गया है, रजिस्ट्री करने से इन्कार कर दिए जानेपर और रजिस्ट्रार द्वारा अपील खारिज कर दिए जानेपर नालिश दायर की जासकती है, देखो 24 C. W. N. 504.

रजिस्ट्रार को दफ़ा ७२ और ७३ के अनुसार दीगई दरखास्तमें तस्दीक दीगयी और वह खारिज कर दीगई। तय हुआ कि नालिश हो सकती है, देखो 74 I. C. 688 (L.).

दफ़ा ७७ के अनुसार दायर की गई नालिशमें अदालत को जिस बातपर विचार करना है वह उस दस्तावेज़के असली होनेकी बात है, उसके जायज़ होने की बात नहीं, देखो 60 I. C. 869; 19 A. L. J. 224; 2 L. 202; 62 I. C. 789. दफ़ा ७७ के अनुसार रजिस्ट्रीके लिए डिकरी दिए जाने के लिए दस्तावेज़की तकमीलीको मंज़ूरकर लेनेकी ज़रूरत नहीं है, देखो 63 I. C. 785(C).

समयके भीतर नालिश ग़लत अदालतमें दायर कीगई लेकिन समय बीत जाने के बाद मुनासिब अदालतमें दायर कीगई। ऐसी दशामें रजिस्ट्रेशन ऐक्टकी दफ़ा ७७ द्वारा नियत मियादकी खुदतका शुमार करनेमें क़ानून मियादकी दफ़ा १४ काममें नहीं लाई जासकती, देखो 24 C. W. N. 4; 30 C. L. J. 455 P. B.; 7 C. W. N. 550; 27 C. W. N. 29; 54 I. C. 228.

अदालत दीवानीको डिकरी देनेसे इन्कार कर देनी चाहिए, अगर दस्तावेज़ बार महीने के भीतर दाखिल न किया जाय, जैसा कि दफ़ा २३ में बतलाया गया है, देखो 39 P. R. 1917.

दूसरी अवस्थाएं—जबकि एक दस्तावेज़के तकमील कुनिन्दोंमें से सिर्फ़ एक ही आदमी रजिस्ट्रारके सामने हाज़िर हुआ और उस दस्तावेज़की तकमीलीको मंज़ूर कर लिया और बाकी आदमी हाज़िर नहीं हुए, तय हुआ कि यह दस्तावेज़ वह क़ानूनी असर नहीं रखता जो वह दस्तावेज़ रखता है जिसकी तकमील और रजिस्ट्री दूसरे तकमील कुनिन्दों की ओरसे कीगई हो, देखो 50 C. 180; 36 C. L. J. 109; 43 I. C. 777 (J.).

नेकनीयतीके साथ किए गए किसी कामसे कोई दस्तावेज़ सिर्फ़ इस वजह से नाजायज़ नहीं होजाता कि कार्रवाईमें कोई बेक़ायदगी कीगई है, देखो 4 L. 284 P. C. ; 45 M. L. J. 497; 75 I. C. 7.

केवल रजिस्ट्रीसे ही मुन्तज़िल अलेहको हकीयत नहीं मिल जाती, अगर फ़रीक़ेनका मन्शा यह है कि जबतक मुआविजेका पूरा रूपया अदा न होजाने तक हकीयत नहीं दीजायगी, देखो 3 L. 389; 85 P. R. 1911; 3 I. C. 177.

पट्टा देनेका ज़बानी इकरारनामा भी हो सकता है। जब किसी इकरारनामाके अनुसार पट्टेदारने कब्ज़ा कर लिया हो, यद्यपि इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ न भी लिखा गया हो, तो हालत यही रहती है मानों दस्तावेज़ लिख दिया गया है, बशर्ते कि फ़रीक़ेन के बीच तामील ख़ास कराई जासके, देखो 25 C. W. N. 220; 63 C. 118.

परदा-नशीन औरत, जिसने मुह्तारनामाकी तकमील की गयी हो, रजिस्ट्री के दफ़्तरमें हाज़िर होने के लिए बाध्य नहीं है। सब-रजिस्ट्रारको अधिकार है कि वह इस बातका इतमीनान हो जानेपर कि वह मुह्तारनामा अपनी खुशीसे लिखा गया है उसकी तकमीलकी तस्दीक़ करदे। तस्दीक़ कर दिए जानेसे यह अनुमान होता है कि उसे इस बातका इतमीनान होगया था, देखो 67 C. 315 (P.).

यह प्रश्न, कि रजिस्ट्री, नोटिस है या नहीं वाक़यात सम्बन्धी प्रश्न है, देखो 2 C. W. N. 750; 7 C. W. N. 11. भिन्न भिन्न हाईकोर्टोंकी रायमें इस सम्बन्धमें मत-भेद था कि क्या रजिस्ट्री नोटिसका अर्थ रखती है। प्रिवी कौन्सिल ने यह तय किया है कि सिर्फ़ रजिस्ट्री करा देना ही नोटिस नहीं है, देखो 48 C. 1

जबकि वह दस्तावेज़, जिससे जायदाद ग़ैर-मनकूला और जायदाद मनकूलापर धार पैदा किया गया हो, रजिस्ट्री न कराया गया हो तो उसे जायदाद मनकूलामें हासिल हकूकके ऊपर कोई असर न पड़ेगा, देखो 47 I. C. 563 (M.).

जब किसी बिना रजिस्ट्री किए हुए और इस तरह नाकाबिल तस्लीम पट्टाकी शर्तोंको मुद्दाअलेहने मन्ज़ूर कर लिया हो, तो इस मन्ज़ूरीके ऊपर कार्रवाई की जासकती है और अदालतको दस्तावेज़पर विचार करनेकी ज़रूरत नहीं है, जिसके काबिल तस्लीम होनेका प्रश्न विवाद-ग्रस्त प्रश्न है, देखो 9 L. J. 253.

वह दस्तावेज़ बयनामा, जो मुद्दईके कीमत ख़रीद अदा न करने के कारण रजिस्ट्री न होनेकी वजहसे नाकाबिल अमल (काममें लाए जानेके अयोग्य) होगयाहै, जायदाद बय करदेनेके लिए किया गया इकरारनामा न समझा जायगा जिससे उस मुआहिदाकी तामील ख़ासके लिए मालिशकी जासकेगी, देखो 43 M. 822; 59 I. C. 417; 16 M. O. 341.

रजिस्ट्रेशन ऐक्ट नं० १६ सन् १९०८ के मनुअल से उद्धृत
सिर्फ संयुक्तप्रान्तकी अदालतोंके लिये

जमीमा नं० ५

रजिस्ट्रीके फीसकी शरह

—:—

ऐक्ट १६ सन् १९०८ की ७८ वीं दफा के अनुसार तैयार किया गया
(१ अप्रैल सन् १९२० ई० से अमलमें लाया जाय)

—:—

आर्टिकल नं० १

१ स्थावर (मनकूला) जायदादका पट्टा करना या पेसे पट्टोंका दिया जाना:—

जबकि पट्टेमें लिखे हुए सालाना किरायेकी तादाद	रु० आ० पा०
१०० रु० से ज्यादा न हो	० ४ ०
१०० रु० से ज्यादा लेकिन ५०० रु० से ज्यादा न हो	० ८ ०
५०० रु० " " १००० रु० " "	१ ० ०
१००० रु० " " २५०० रु० " "	२ ० ०
२५०० रु० " " ५००० रु० " "	३ ० ०
५००० रु० " " १०००० रु० " "	४ ० ०
१०००० रु० " " ...	५ ० ०
जबकि किरायेकी तादाद न लिखी गयी हो	१ ० ०

२ नीलामके खरीदार द्वारा पेश किये गये (चाहे बदलेका रुपया १००) से कम हो या ज्यादा) स्थावर जायदादके बेचान सम्बन्धी सर्टीफिकेटों पर जबकि बदलेकी रकम (Consideration Money)

रु० आ० पा०
० ८ ०
... १ ० ०

जबकि तादाद ५० रु० से अधिक हो

३ स्थावर जायदाद (मनकूला) के सम्बन्धकी सब दस्तावेजों जिनका कि पक्षीयतनामा न हो:—

जबकि दस्तावेज़में लिखी कीमत या रकम मुआवज़ाकी तादाद रु० आ० पा०			
१०० रु० से ज्यादा न हो			० ४ ०
१० रु० ज्यादा मगर २५ रु० से ज्यादा न हो			० ६ ०
२५ " ५० "			० ८ ०
५० " ७५ "			० १२ ०
७५ " १०० "			१ ० ०
१०० " २०० "			१ ८ ०
२०० " ५०० "			३ ० ०
५०० " १००० "			४ ० ०
१००० " १५०० "			५ ० ०
१५०० " २००० "			६ ० ०
२००० " २५०० "			७ ० ०
२५०० " ३००० "			८ ० ०
३००० " ४००० "			९ ० ०
४००० " ५००० "			११ ० ०
५००० " ७५०० "			१४ ० ०
७५०० " १०००० "			१६ ० ०
१०००० रु० से ज्यादा प्रति १००० रु० या उसके किसी भी भागके लिए ५०००० रु० तक न कि ज्यादा के लिए			१ ० ०
५०००० रु० से ऊपर १००० रु० या उसके किसी हिस्सेके लिए अगर कीमत सिर्फ एक हिस्सेकी ही जाहिरकी गयी हो			० ८ ०
जबकि कीमतकी तादाद न दीगयी हो			२ ० ०*
			१० ० ०
बुन्देलखण्ड एलीनेशन लैण्ड ऐक्ट १९०३ (2 of 1903) की धारा ९ (२) या १७ के अन्दर क्रिय गये दस्तावेज़ रहनकी रजिस्ट्री पर किसी तरहकी फीस न लीजायगी बरपवज उस दस्तावेज़ रहनके जिसकी कि बाकायदा रजिस्ट्री पहिले ही से हो चुकी हो और मियाद खतम न हुई हो ।			
* नोट—यह फीस, ऊपर बतलाई हुई मालियत या मसालबा दावा के ऊपर मालियतके मुताबिक लगाई हुई फीसके अलावा है			
४ वसीयतसे न दिए गए गोद लेनेका अधिकार देने के सम्बन्धमें लिखित अधिकार पत्र			रु० आ० पा० ४ ० ०
५ वे दस्तावेज़ जो किसी जायदाद मनकूला और दस्तावेज़, तमस्तुक, मुआहिदे या दूसरे दस्तावेज़ोंमें या उनके लिए किसी अधिकार (Right), हकीयत या हिस्साको अमलमें लाते हों या पैदा करते हों पलान करते हों, मुन्तकिल करते हों, सीमावद्ध (महदूद) करते हों या नष्ट करते हों:—			

जबकि जायदादकी कीमत जाहिर की गई हो और वह

रु० आ० पा०

५० रु० से अधिक की न हो

० ४ ०

५० रु० से अधिक लेकिन

१०० रु० से ज्यादा न हो

० ८ ०

१००

"

२००

"

१ ० ०

२००

"

५००

"

२ ० ०

५००

"

१०००

"

४ ० ०

१०००

"

१५००

"

५ ० ०

१५००

"

२०००

"

६ ० ०

२०००

"

२५००

"

७ ० ०

२५००

"

३०००

"

८ ० ०

३०००

"

४०००

"

९ ० ०

४०००

"

५०००

"

१० ० ०

५०००

"

७५००

"

१२ ० ०

७५००

"

१००००

"

१४ ० ०

१००००

"

१५०००

"

१६ ० ०

१५०००

"

२००००

"

१८ ० ०

२०००० रु० के ऊपर और ५०००० रु० तक मगर उसके

गया नहीं हर एक ५००० रु० या उसके किसी हिस्से पर

१ ० ०

५०००० रु० से ऊपर १००००० रु० तक मगर उसके ऊपर

नहीं हर एक ५००० रु० या उसके किसी भाग के लिए

० ८ ०

१००००० रु० के ऊपर हर एक ५००० रु० या उसके किसी

हिस्से के लिए

० ४ ०

जबकि कीमत जाहिर न की गई हो

१० ० ०

६ वसीयतनामा:—

सन् १९०८ के ऐक्ट १६ दफा ४२ के अनुसार मोहर लगा

रु० आ० पा०

हुआ लिफाफा दाखिल होने पर

४ ० ०

दफा ४४ के अनुसार, मोहर लगा हुआ लिफाफा जोकि

दफा ४२ के अनुसार जमा किया गया था के उठाने

(With drawl) की दरखास्त देने पर

... ..

४ ० ०

दाखिल किये हुये मोहर लगाये (Sealed) लिफाफे को

खोलने के लिये दरखास्त देने पर

...

...

४ ० ०

नोट—ऐसे मोहर लगे हुए लिफाफों के अन्दर लिखे हुए मजमून को रजि-
स्ट्रबुक में नकल करने की फीस आर्टिकल (Article) नं० १० में दिये गये

दरख (Rate) के अनुसार ली जायगी ।

रु० आ० पा०

वसीयतनामा की रजिस्ट्री पर

... ..

४ ० ०

(७) रजिस्ट्रार के संदूक में रक्षित रखने के लिये:—

(८) रजिस्ट्रार के लोहे के बक्स के अन्दर रक्षित

वसीयतनामा (Non testamentary document) रखने

के लिए

...

...

...

२ ० ०

(b) ऐसे किसी वसीयतनामा के, जोकि रजिस्ट्रार के लोहे के सन्दूक के अन्दर रक्षित रखने के लिये रक्खा गया, उसे वापस करने के लिये ... २ ० ०

८ मुकुतारनामा वगैरह (Powers attorney etc)
मुकुतारनामा या कोई ऐसा ही वसीयतनामा जोकि १९०८ के ऐक्ट १६ दफा १८ शरह एफ (F) के अनुसार रजिस्ट्री होने के लायक है और जोकि इस नक़्शे में दिये गये शरह नं० ५ के अनुसार, मालियत की शरह (ad valorem Scale) में नहीं आसकता, की रजिस्ट्री फीस २ ० ०

नोट्स

—०—

(ए) एक दस्तावेज़ जिसके अन्दर कई अलग मामले (matters) हों या जिसका सम्बन्ध कई अलग अलग मज़मून (matters) से हो उसकी फीस, (fees) उन सब दस्तावेज़ोंकी फीसों का जोड़ होगी जिनका सम्बन्ध अलग २ एक एक मामले से है।

एक दस्तावेज़ में कई जुदे जुदे मामले मौजूद हैं यह उसी वक्त कहा जा सकता है जब कि जाहिरा तौर से कई दस्तावेज़ों का एक में शामिल कर देने का सिर्फ़ यही एक मतलब हो कि टिकट खर्च (Stamp duty) व रजिस्ट्री की फीस (registration fees) बच जावे। रजिस्ट्री करने वाले अफसरों को ऐसे मामले में कानून टिकट (Stamp law) के अनुसार काम करना होगा (जी. ओ. नं० १३४२/७-४१४ ता० ३ अक्टूबर सन् १९१३) अगर इस तरह पर दस्तावेज़ रसूम टिकट (Stamp duty) भदा करने के लिये माना गया हो गोया इसके अन्दर एकही मामला मौजूद है तो रजिस्ट्रार को उसे एक ही मामले की तौर मानना चाहिये। लेकिन अगर उसका यह खयाल कि दस्तावेज़ पर कानून जितनी चाहिये उससे कमकी टिकट लगी है तो उसे (Stamp act) स्टैम्प ऐक्ट की ३८ वीं धारा के अनुसार व्यवहार करना चाहिये।

(बी) पहिले कहे हुए नोट के अनुसार एक दस्तावेज़ जो कि इस तरह बनायी गयी हो कि आरेटिकल नं० १ के कई मद्दों (descriptions) के अन्दर आसकती हो, और जब कि उनपर ली जाने वाली फीस की तादाद मुक़तलिफ़ हो तो जो फीस उनमें सब से ज्यादा होगी सिर्फ़ वही लगायी जावेगी।

(सी) किसी पट्टा या दस्तावेज़ जिसमें कि रुपया जुरमाना या फ़ायदा (premium) को छोड़कर बंधे हुए वक्त में भदा किया जाता है

उसकी एक साल की रकम पर, किसी रهنनामों के विषय में मिलने वाली रकम की तादाद पर और हिस्सेदारी की दस्तावेज़ में अपने पाये हुए हिस्से या हिस्सोंकी कीमतकी रकम, जिस पर किशोर टिकट (Stamp duty) लगने लायक हैं स्टैम्प ड्यूटी लगने की रकम मानी जायगी ।

- (ही) अगर किसी जायदाद के हिस्से हो गये हों तो, उनमें सब से बड़ा हिस्सा (या अगर दो हिस्से बराबर कीमत के हों और दूसरे किसी भी हिस्से से उनकी कीमत कम न हो तो उन दो बराबर हिस्सों में का एक हिस्सा) ऐसा मान लिया जायगा कि उसमें से दूसरे हिस्से अलग किये गये हैं [देखो स्टैम्प ऐक्ट, परिशिष्ट (Schedule) १४५]
- (ई) अगर गवर्नमेंट के किसी माली या फौजी अफसर ने अपने निजी रहने के लिये एक मकान बनवाने या खरीदने के लिये गवर्नमेंट से पेशगी रुपया लिया हो और इस रुपये की अदायगी के लिये वह रهنनामा लिखे तो ऐसी रहनी-दस्तावेज़ पर किसी तरह की रजिस्ट्री फीस न लगेगी । (देखो गवर्नमेंट आर्डर नं० १६१४/७-४५५ तारीख २१ दिसम्बर १९११)
- (यफ) सन् १९०४ ऐक्ट ६की दफा ३ तथा १८८२ के ऐक्ट ४ दफा ५९ के अनुसार, जब असल हासिल किया हुआ रुपया (Principal money) एक सौ रुपये से कम हो तो रهنनामा या तो बज़रिये एक रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज़ के, जिसपर ऊपर बतलाये अनुसार दस्तखत और तसदीक मौजूद हों या (रهنनामा सादा को छोड़कर) जायदाद हवाले करके किया जा सकता है ।
- इससे उन दस्तावेज़ों के सम्बन्ध में बतलाई गयी शर्तें कुछ कम कड़ी हो जाती हैं जो कि १००) से कम के हैं और जिनकी रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं रखी गयी है जैसा कि ऐक्ट १६ सन् १९०८ की दफा १७ (१) (बी) में बतलाया गया है ।
- (जी) वह रजिस्ट्रीकी फीस, जो ऐसे दस्तावेज़पर लगायी जानी है जो उसी प्रकार की, या सहायक, या जायद, या उसीकी जगहपर दूसरी जमानत, या आगे और मज़बूतीके लिये ज़मानत देने के लिये लिखा गया है, वही होगी जोकि असल या इस्तदायी रهنनामा के ऊपर लगायी जाती है, अगर वह फीस दो रुपया से ज्यादा न हो तो वह दो रुपया होगी ।
- (यच) अगर किसी रैयत को कोई पट्टा या ठेका दिया जाय और उस पट्टा या ठेका की कबूलियत या मुसन्ना पट्टा या ठेका के साथ ही साथ रजिस्ट्रीके लिये पेश किया है तो इन दोनों दस्तावेज़ों (कागज़ों) की

निश्चित ली जाने वाली फीस उस फीस से ज्यादा न होगी जो अकेले उस पट्टा पर ली जाती ।

(आई) गवर्नमेंट के इशतहार (Notification) नं० १०४८ तारीख ३ दिसम्बर सन् १८३५ के अनुसार अगर कोई पट्टा, मुतल्लिक ज़रायत संयुक्त प्रान्त (United Provinces) के किसी जिले में लिखा गया हो और जिसकी मियाद पांच साल से ज्यादा न हो और जिसमें सालाना किराया ५० रु० से ज्यादा न आता हो तो वह पट्टा सन् १८७७ ई० के ऐक्ट ३ की दफा १७ से बरी है । यह फैसला इलाहाबाद चीफ कोर्ट से तय हुआ है (देखो इलाहाबाद लॉ जर्नल १२, सफा ७९२, हजारीसिंह वगैरह बनाम त्रिवेनीसिंह वगैरह) कि यह नोटीफिकेशन अब तक प्रचलित है और इन पट्टों को सन् १९०८ के ऐक्ट १६ की दफा १७ के अन्तर से बरी करता है ।

(जे) गवर्नमेंट के इशतहार (Notification) नं० ५०३१७-१३२ ता० ०८ मई १९१७ के अनुसार अगर संयुक्त प्रांत के किसी जिले में नोटीफाइड एरिया (Notified area) की या नज़ूलकी ज़मीनका पट्टा लिखा गया हो जो कि मुतल्लिक ज़रायत न हो, और जिसकी मियाद ५ साल से ज्यादा न हो और सालाना किराया २५ रु० साल से ज्यादा न हो तो वह सन् १९०८ के रजिस्ट्रेशन ऐक्ट १६ की दफा १७ के अन्तर से बरी हैं (यानी लाज़िमी Compulsory रजिस्ट्री न होगी)

आर्टिकल नं० २

किसी दस्तावेज़ पर आर्टिकल १ के अनुसार रजिस्ट्री की फीसके अलावा रजिस्टर नं० १, ३, और ४ में नकल करने की फीसों नीचे लिखे बमूजिव शर्त से ली जायंगी ।

उर्दू, हिन्दी, और अंग्रेजी या किसी दूसरी ज़बान में लिखी हुई दस्तावेज़ पर:—

	रु०	आ०	पा०
जहांकि शब्दोंकी तादाद ४०० से अधिक न हो	०	८	०
इसके ऊपर प्रत्येक १०० शब्दोंया उसके किसी हिस्सेके लिये	०	२	०

नोट्स

- (ए) रजिस्ट्री की पीठपर की तहरीर या सर्टिफिकेट, जोकि कानूनन (By law) या कायदन् (By rule) जायज़ हों, उसकी रजिस्ट्रोंमें नकल करनेकी फीस न ली जायगी ।
- (बी) सन् १९०८ के ऐक्ट १६ की दफा ६५ और ६६ के अनुसार एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर को भेजे जाने के लिये तैयार की हुई नकल दस्तावेज़

वेज़ पर भी पहिले लिखी शरहके बमूजिब फीस ली जायगी लेकिन उन स्मरण पत्रों (Memoranda) पर जो कि ऐक्ट की दफा ६४, ६५, और ६६ के अनुसार तैयार किये गये हैं न ली जायगी ।

- (सी) तादाद शब्दों की जिनपर की फीस लीगयी है और नकल करने की फीस की तादाद खुद दस्तावेज़ पर और रजिस्ट्ररकी नकलमें भी नीचे की तरफ दर्ज की जायगी ।
- (डी) शब्दों की तादाद अन्दाजन देना ही काफी है मिसालके लिये लेख (Entry) के बीच की तीन या चार लगातार सतरोँ के हरफ गिनकर, उनका औसत निकाल कर, फिर उस औसत को सतरोँ की तादाद से गुणा करने पर शब्दों की तादाद मानली जाती है ।
- (ई) रजिस्ट्री के लिये लाई गयी छपी हुई दस्तावेज़ों की छपी हुई नकलों में से १०० शब्दों के प्रत्येक सफा का मिलान (Compare) करने की फीस, उन फीसों के अलावा जोकि आरटिकल नं० १ के अनुसार रजिस्ट्री के लिये लीगयीं हों, ३ पाई (एक पैसा) के हिसाब से और ली जायगी ।

आरटिकल नं० ३

सन् १९०८ई० के ऐक्ट १६ की दफा ३३के अनुसार मुख्तार-
नामाकी तस्दीकके लिए:—

अगर ऐसा मुख्तारनामा आम हो
, , खास हो

रु० आ० पा०

३ ० ०

२ ० ०

आरटिकल नं० ४

सन् १९०८ई० के ऐक्ट १६की दफा ३०के मुताबिक रजिस्ट्रार
द्वारा कीगई अख्तियारी रजिस्ट्रीकी एडीशनल फीस (Addi-
tional fee)

रु० आ० पा०

६ ० ०

यह एडीशनल फीस दस्तावेज़के जमा करनेपर अदा न की
जायगी और न उस वक्त लगाई जायगी जबकि सब-रजिस्ट्रार (Sub-
registrar) के उस जवानसे जिसमें दस्तावेज़ लिखीगई हो नावाकिफ
होनेके कारण रजिस्ट्रारके पास रजिस्ट्रीके लिये लीजाई जावे और
न उस वक्त ही, जबकि दस्तावेज़में लिखे हुए लेन देनसे सब
रजिस्ट्रारका कोई सम्बन्ध होने के कारण वह ज़िला रजिस्ट्रारके
पास रजिस्ट्रीके लिये लीजाई जाय । जबकि एडीशनल फीस
(Additional fee) न ली जावे तो फीस के रजिस्ट्रारके ७ वें
अनुक्रममें फीस न लेनेका कारण दर्ज कर दिया जावे ।

आरटिकल नं० ५

अनुवाद (Translation) शामिल करनेकी फीस

रु० आ० पा०
१ ० ०

आरटिकल नं० ६

सन् १९०८ई० के ऐक्ट १६ की दफा ५७ के अनुसार काग-
ज़ातका पता लगाने या मुआइना करनेकी फीस नीचे लिखी शरह
के अनुसार लीजावेगी:—

(१) सिर्फ एक ही इन्दराज या एक ही दस्तावेज़के मुआइ-
नाके लिये—

रु० आ० पा०

(५) हर एक इन्दराज या दस्तावेज़की, बाबत पहिली सालकी,
किताबोंमें मुआइनाके लिये

० ८ ०

प्रत्येक इन्दराज या दस्तावेज़के लगातार मुआइना करनेकी
बाबत प्रत्येक दूसरे सालके रजिस्ट्रों के लिये

० ४ ०

मगर किसी हालतमें ५) रु० से ज्यादा फीस न लीजायगी

(२) तमाम कागज़ातों जिनका सम्बन्ध एकही जायदादसे है,
या जो एकही शख्सके हाथसे लिखे गये हों या जो एकही शख्स
के लिये लिखे गये हों, की आम तलाशी या मुआइनाके लिये

रु० आ० पा०

(६) किताबोंमें पहिली सालकी तलाशीके लिये

१ ० ०

(बी) किताबों में, जिसकी तलाश जितने दूसरे सालों तक चली
जावे उनमें हर एक साल तकके लिये

० ४ ०

किसी भी दशमें (१०) रु० से ज्यादा फीस न लीजायगी

नोट्स

(ए) सर्व साधारणके वास्तविक कामके लिये सरकारी दफतर
या कोर्टके आलाअफसरको अर्जी देनेपर (कागज़ोंकी)
तलाशी या मुआइनेके लिये रु० २८७ देखो

(बी) उस दस्तावेज़का पता लगानेकी फीस, जिसकी नकलके
लिये दी गई अर्जी में, दावेदार व लिखनेवाले दोनों फरीक़ानोंके
नाम, उसकी ज़रूरी बातें दस्तावेज़ और रजिस्ट्रीकी तारीख़ें,
ठीक तौरसे लिखी गई हों तो पता लगानेकी फीस न
लीजायगी। अगर अर्जी देनेवाले से हवाले देनेकी बातोंमें
कोई खास बात झूठभी जाय तो भी हर एक मामलेमें
यह न माना जायगा कि वह “तलाश” की गई है और जब
तक कि उसकी “तलाश” ज़रूरी न समझी जावे सिर्फ़

नकल फीस लीजायगी। रजिस्ट्री करनेवाले अफसर को ऐसे मामलेमें अपनी समझसे जान लेना चाहिए कि आया वह अपनी किताबोंमें किसी इन्दराज को "तलाश" कर रहा है या अर्जी में दिये गये हवाले के अनुसार वह इन्दराज सिर्फ सफे लौटने ही से वहीं दर्ज मिलता है

आरटिकल नं० ७

दफा ३१, ३३, या ३८ के अनुसार रजिस्ट्री करनेवाले अफसर का निजी मकान या जेलपर ले जानेकी फीस या सन् १९०८ के ऐक्ट १६की दफा ३३ या ३८के अनुसार एक कमीशनके जारी कराने की फीस:—

(ए) फीस जबकि आदमी जिसका मुआइना होने को हो जेल के अन्दर बन्द है

रु० आ० पा०

५ ० ०

(बी) फीस जब कि आदमी जिसका मुआइना होना है जावता दीवानीकी दफा १३३ के अनुसार खुद हाजिर होनेसे बरी है

१६ ० ०

(सी) दूसरे तमाम मामलोंमें

१० ० ०

नोट्स

(ए) इस फीसके अलावा रजिस्ट्रीके दफतरसे एक मीलसे ज्यादा दूरीपर तमाम जगहोंके लिये सफर खर्च नीचे लिखे अनुसार अदा किया जायगा:—

कवनेन्टेड (Covenanted) और फौजी कमीशनड, अफसरों के मामलेमें जबकि वे सब रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रारके तौरपर काम कर रहे हों तो सफर खर्च ३ आना फी मील रेल से और ८ आना फी मील सड़क से लिया जायगा।

दूसरे और सबरजिस्ट्री करनेवाले अफसरोंको, सिवाय इसके कि उनको लोकल गवर्नमेंटसे सफर खर्च ज्यादा लेने के लिये हुक्म होगया हो या कमिशनरोंके लिये अगर वे मुकदरर किये जावें, डेढ़ आना फी मील रेलसे और चार आना फी मील सड़क से सफर खर्च दिलायाजायगा।

अगर वह जगह एक मीलसे कमहो और रास्ता सड़कका हो तो बाँधा हुआ भत्ता आठ आनाके हिसाब से लगाया जायगा।

(बी) जावता दीवानीकी दफा १३३ के अनुसारवरी: किये हुएशख्सके मुआइना के लिये गये हुए या मुकदरर किये हुए कमीशनका खर्चा उसी शख्सको, देना होगा अगर वह पक्षकार जो उसकी शहादत चाहता है न अदा करदे

(सी) जगहकी दूरी जिसपर कि भत्ता लिया जायगा ऐसे नकशोंसे माखूम होगी जो कलकटरीमें, ऐसेही कामोंके लिये जहांकहीं मुमकिन है बनाये जाते हैं,

और रखे रहते हैं, या दूसरे मामलेमें, सब-डिस्ट्रिक्टके उस नकशेकी मददसे हिसाब लगाया जायगा जो सम्भवतः उन सब दफ्तरोंको दिये जाते हैं जो दफ्तर तहसीलके बड़े दफ्तर (Head office) के पास मौजूद नहीं हैं, दफ्तर जोकि तहसीलके हेड आफिसके पास मौजूद हैं तहसीलमें मौजूद नकशेसे काम लेंगे । सुभाइना के अफसर खुद जांच और हिसाब करके किन्हीं मद्दोंको जांच लेगा कि जगहकी दूरी जिसपर कि भत्ता लिया गया है बहुत करके ठीक है ।

(डी) परदानशीन या बड़े घरानेकी औरतोंके अंगूठेका निशान लेनेके लिये रजिस्ट्री करने वाले अफसरके साथ किसीके निजके मकानपर किसी दाया या नायब औरतको साथ ले जाने की फीस, बिना इस खयालके कि ऐसे निजके मकान (Private residence) पर कितनी दस्तावेजों की रजिस्ट्री की गई है, पांच रुपया फीस उसके प्रतिवार जाने की और ली जायगी ।

आर्टिकल नं० ८

जबकि सन् १९०८ के ऐक्ट १६ की दफा ३६ के अनुसार लोकल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किये गये किसी अदालत या अफसरको सम्मन जारी करने के लिए अर्जी दी जाय तो तलबाना, जो ऐसी अदालत या अफसरके सम्मन जारी करने व कार्रवाई करने के लिए मामूली तौरसे वाजबुल अदा है, तलबाना उस शख्सको, जिसके तरफ से अर्जी लिखी गई है और अर्जीके साथ सम्मन भेजे गये हैं, देना होगी ।

आर्टिकल नं० ९

गवाहोंका खर्चा, रजिस्ट्री करनेवाला अफसर जाबता दीवानीके प्रचलित (Inforce) कायदोंके अनुसार तय करेगा और सम्मन जारी करने के लिए अर्जीके साथ भेज देगा । परन्तु यदि उसी आदमीके नाम, जिसने कि दस्तावेज लिखी हो, सम्मन निकाले जाय, तो खर्चा कुछ न लगेगा ।

आर्टिकल नं० १०

रजिस्ट्री करनेवाले अफसरों द्वारा दिये गये, रजिस्ट्री की हुई दस्तावेजोंकी तस्दीक शुदा नकलोंका खर्चा आर्टिकल नं० २ में बताये खर्चों के अनुसार होगा । लेकिन नीचे की तफसील से किसी तरह कम न होगा ।

	किताब १, २, ४ की प्रत्येक दस्तावेज़, किताबका इन्दराज फाइल बुकका कागज़ (नकशा या खाका छोड़कर)	दूसरी किताबों में हर एक इन्दराज और सूचीपत्र का (नकशा या खाका छोड़कर)	रखे हुए, बयानात हुक्मनामे या मुतफ़्फ़ात कागज़ातकी
हरद या हिन्दी की नक़ल के लिये	रु० आ० पा० ० ८ ०	रु० आ० पा० ० ४ ०	रु० आ० पा० ० ८ ०
अंग्रेज़ी या दूसरी भाषाकी नक़ल के लिये	१ ० ०	० ८ ०	० ८ ०

नोट्स

- (ए) रजिस्ट्री करनेवाला अफ़सर, ज़िला रजिस्ट्रारके मातहतकी हैसियतसे, कामकी सुशिकलात और पर्चीदगीको ख़यालकर नक़शा या खाकाकी फ़ीस मुक़रर करे। जबकि किसी शख्स ने, जिसका सम्बन्ध रजिस्ट्रीके मुहक़में से न हो, एक नक़शा या खाका की नक़ल (Copy) तैयार कीगई हो, तो वसूल की हुई फ़ीस उसे दी जा सकती है।
- (बी) सन् १९०८ के ऐक्ट १६ दफ़ा ५७ के अनुसार नक़लके लिये दीगई अर्ज़ीसे, उसकी "तलाश" ज़रूरी हो जावे तो आर्टिकल ६ के नोट(बी) के बमूजिब कही हुई फ़ीसके अलावा (नक़ल) फ़ीस इस आर्टिकल के बमूजिब ली जायगी।
- (सी) जबकि एक दस्तावेज़, एक से ज्यादा भाषाओंमें लिखी गई हो तो खासतौर से ज्यादातर इस्तेमालकी जानेवाली भाषाके हिसाबसे फ़ीस लीजावेगी।
- (डी) नक़ल करनेकी फ़ीसकी तादाद नक़ल (दस्तावेज़) के नीचे दर्ज रहेगी।
- (ई) इस आर्टिकलकी फ़ीस लेते वक्त, दस्तावेज़की पुस्तपर लिखी हुई तहरीर या सर्टीफ़िकेट जो कि क़ानूनन् या क़ायदन् माने गए हों उस दस्तावेज़ का एक जुज़ समझे जायगे।

आर्टिकल नं० ११

रजिस्ट्रार के द्वारा उसके लोहेके खन्दूकमें रखे हुए ऐसे दस्तावेज़ जिनका कोई दावेदार नहीं है प्रत्येक १५ दिन या उसके किसी हिस्सेके लिये ८ आना के हिसाबसे उतने दिनोंके लिये कि जितने दिनतक वह दस्तावेज़ जिम्मेदारी (Custody) में रही है लेकर ही दीजावेगी।

इस दस्तावेज़के हिफ़ाज़तमें रखनेकी फ़ीस, जो कि रजिस्ट्री हो जानेके बाद या रजिस्ट्री करनेसे इन्कार कर दिये जानेके बाद पड़ी रही हो और जिसका कोई

दावेदार हुआ हो किसी भी हालतमें) रु० से ज्यादा न होगी और रजिस्ट्रारको यह अधिकार होगा कि वह किसी ऐसी फीसको जिसे इस आरटिकलके अनुसार वह या उसका मातहत रजिस्ट्री करनेवाला अफसर लगा सकता है कुछ या कुछ अंशमें माफ करदे, अगर उसे यह इतमीनान होजावे कि उसका जबरदस्ती बसूल करना न्यायके विरुद्ध और कठोरता होगी ।

आरटिकल नं० १२

भारत सरकारके नोट नं० ३७६ द्वारा स्थापित सन् १९१२ के ऐक्ट (२ आफ १९१२) को आपरेटिव सोसाइटीज़ ऐक्टके क्लॉज़ (सी) दफा २८ के अनुसार होमडिपार्टमेंट के हुक्म ता० २४ अप्रैल १८१४ के बमूजिब नीचे दी हुई फीसों जो कि कानून रजिस्ट्रीके अनुसार वाजबुद्ध अदा हैं इस समय माफ की जाती हैं यानी:—

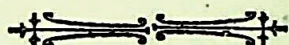
- (ए) उस ऐक्टके अनुसार रजिस्ट्रीकी हुई कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा या उसके ओरसे दीजानेवाली सब फीसों कुछ समयके लिये ।
- (बी) वह सब ली जाने वाली फीस, जो कि ऐसी किसी सोसाइटीके किसी अफसर या मेम्बर द्वारा लिखी गई दस्तावेज़पर, जिसमें उसीके पदके सम्बन्धका काम हो माफ की जाती हैं ।

इंडियन लिमीटेशन ऐक्ट

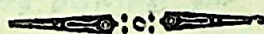
अर्थात्

भारतीय कानून मियाद सन् १९०८ ई०

ऐक्ट नं० ९ सन् १९०८ ई०



(तारीख ७ अगस्त सन् १९०८ ई० को पास हुआ)
मालिशोंके तथा अन्य कामोंके मियाद सम्बन्धी कानूनोंका
संशोधन करनेके लिए कानून



चूंकि यह उचित जान पड़ता है कि मालिशों, अपीलों और अदालतों को दी जाने वाली दरखास्तों की मियाद सम्बन्धी कानून का संग्रह एवं संशोधन किया जाय; और चूंकि यह भी उचित जान पड़ता है कि हक-आसायश तथा दूसरी जायदाद के, उसपर कब्ज़ा करके, मिलिकयत हासिल करने के लिए नियमों की व्यवस्था की जाय, इसलिए यह नीचे लिखा कानून जारी किया जाता है:—

प्रथम प्रकरण

दफा १ सांक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

१ इस ऐक्ट का नाम 'इण्डियन लिमीटेशन ऐक्ट (भारतीय कानून मियाद) सन् १९०८ ई०' होगा

२ इसका विस्तार समस्त ब्रिटिश भारत में होगा; और

३ यह दफा और दफा ३१ फौरन् अमल में लाई जावेगी। इस ऐक्ट के बाकी हिस्से पर तारीख १ जनवरी सन् १९०९ ई० से अमल किया जावेगा।

दफा २ परिभाषा

इस ऐक्ट में, जब तक कोई बात विषय अथवा प्रसंग के विरुद्ध न हो—

१ "सायल (Applicant)" शब्द में कोई भी ऐसा शख्स शामिल होगा जिससे या जिसके ज़रिये से किसी सायल (दरखवास्त देने वाला) को दरखवास्त देने का हक हासिल होता हो।

२ "हुंडी (Bill of exchange)" में हुंडी और चेक शामिल होंगे।

३ "तमस्तुक (Bond)" में कोई भी ऐसा दस्तावेज़ शामिल होगा जिसके ज़रिये से कोई शख्स दूसरे शख्स को इस शर्त पर रुपया अदा करने की, ज़ुम्मेदारी ले। यह ज़ुम्मेदारी (Obligation) उस समय रद्द समझी जायगी, अगर अमुक कार्य किया गया अथवा पूरा न किया गया, जैसी कुछ भी अवस्था हो।

४ "मुद्दाअलेह (Defendant)" में कोई भी ऐसा शख्स शामिल होगा जिससे या जिसके ज़रिये से कोई मुद्दाअलेह इस क़ाबिल होता हो कि उस पर नालिश की जाय।

५ "हक़ आसायश (Easement)", में कोई भी ऐसा हक़ शामिल होगा जो किसी मुआहिदा (Contract) से पैदा न हुआ हो और जिससे किसी शख्स को दूसरे शख्स की ज़मीन के किसी हिस्से को या दूसरे शख्स की आराज़ी पर उगी हुई, या उसके साथ शामिल या उस पर स्थित किसी वस्तु को हटा कर अपने कामों में लाने का अधिकार प्राप्त होता हो।

६ "विदेश (Foreign Country)" से अर्थ होगा ब्रिटिश भारत को छोड़ कर कोई भी देश।

७ "नेक-नीयती (Good faith)", कोई भी ऐसी बात नेक-नीयती से कीगई न समझी जायगी जो सावधानी से और सचेत होकर न कीगई हो।

८ "मुद्दई (Plaintiff)" में कोई भी ऐसा शख्स शामिल होगा जिससे या जिसके ज़रिये से किसी को नालिश दायर करने का हक़ हासिल होता हो।

९ "हनुक तलब रुक्का (Promissory Note)" का अर्थ होगा कोई भी हस्तावेज (या कागज़) जिसके ज़रिये से उसका लिखने वाला किसी एक निश्चय रकम को, उसमें बतलाये हुए समय पर, या तलब किए जाने पर, या उसके देखते ही, किसी दूसरे शख्स को अदा कर देने का कतई इकरार करे।

१० "नालिश (Suit)" में अपील या दरख्वास्त शामिल न होगी, और

११ "ट्रस्टी (Trustee)" में बेनामीदार, वह मुल्तेहिन जो रेहननामा का मालिक बंधा हुआ होने के बाद काबिज़ बना रहे अथवा बिना हकीयत ज़बर्दस्ती कब्ज़ा करने वाला शख्स, शामिल, न होगा।

दूसरा प्रकरण

नालिशों, अपीलों और दरखास्तोंकी मियाद

दफा ३ मियाद की मुदत खतम होजाने के बाद दायरकी गई नालिशोंका खारिज कर दिया जाना

दफा ४ से २५ तक की दफाओं में बतलाए हुए नियमों की पाबन्दी में रहते हुए प्रत्येक ऐसी नालिश, अपील और दरखास्त, जो उस मियाद की मुदत खतम हो जाने के बाद दायर की गई, पेश की गयी, और दी गई हो, जो इसके लिए परिशिष्ट (१) में बतलाई गई है, खारिज कर दी जायगी, चाहे मियाद की बात उसके जवाब में न भी आई हो ।

विवरण—साधारणतया कोई नालिश उस समय दायर की गई समझी जाती है जब कि अर्जीदावा किसी मुनासिब अफसर (हाकिम) के सामने पेश किया गया हो; अगर वह किसी मुफलिस (Pauper) की ओर से दायर की गई हो, तो उस समय जब कि उसने बहसियत मुफलिस (Pauper) नालिश करने की इजाजत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हो; और अगर किसी ऐसी कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा दायर किया गया हो, जिसके हिसाब-किताब का तस्फिया और उसकी शिराफत का ख़ातमा (Winding-up) उस अदालत में हो रहा है, तो उस समय जब दावेदार पहले पहल अपना दावा आफिसल लिक्विडर (सरकारी पावनेदार) के पास पेश करे ।

दफा ४ जब मियाद खतम होने के समय अदालत बन्द हो

जब कि मियाद की वह मुदत, जो किसी नालिश, अपील या दरखास्त के लिए मुक़रर (नियत) है, उस रोज़ खतम होती हो जब कि अदालत बन्द है, तो वह नालिश, अपील या दरखास्त उस तारीख़ को दायर की, पेश की, या दी जानी चाहिए जिस तारीख़ को अदालत फिर खुलती हो ।

दफा ५ कुछ अवस्थाओं में मियादकी मुदतका बढ़ाया जाना

कोई भी अपील या दरखास्त, जो किसी फैसले की नज़रसानी या अपील करने की इजाजत हासिल करने के लिए दी गई हो, या दूसरी कोई दरखास्त, जिसके सम्बन्ध में [उस समय प्रचलित किसी क़ानून द्वारा या उसके अनुसार] यह दफा लागू की जा सके, उस मियाद की मुदत खतम होने के बाद भी, जो इसके लिए मुक़रर है, ली जा सकती है, जब कि अपीलखण्ड या सायल, अदालत की इस बात का इतमीनान करा दे कि उसके इस मियाद के अन्दर अपील पेश न कर सकने या दरखास्त न दे सकने के लिए काफ़ी वजह थी ।

विवरण—यह बात कि अपीलान्ट या सायल को हाईकोर्ट के किसी हुकम, प्रथा (इस्तूर) अथवा फैसले से मियाद के लिए मुकर्रर मुद्दत के किसी निश्चित करने या तखमीना लगाने में गलत-फहमी होगई है, इस दफा के अर्थ में काफी वजह समझी जायगी।

दफा ६ कानूनी नाकाबलियत

१ जब कोई शख्स, जो नालिश दायर कर सकने या किसी डिकरी की इजरा के लिए दरख्वास्त देने का हक रखता है, उस समय, जिस समय से मियाद की मुद्दत का शुमार किया जाना चाहिए, नाबालिग, या पागल, अथवा मूर्ख (बेव-कूफ) हो, तो वह उस नाकाबलियत के दूर हो जाने के बाद उसी मुद्दत के भीतर नालिश दायर कर सकता है या दरख्वास्त दे सकता है जो उस समय के बाद दीगई हो जो परिशिष्ट (१) के तीसरे खाने में इसके लिए नियत है।

२ जब ऐसा शख्स उस समय, जब से मियाद की मुद्दत का शुमार किए जाने को है, ऐसी दो बातों की वजह से नाकाबिल ठहरता हो, या जब, उसकी नाकाबलियत दूर होने के पहिले, वह किसी दूसरी बात की वजह से नाकाबिल हो गया हो, तो वह इन दोनों नाकाबलियतों के दूर होजाने के बाद उसी मुद्दत के अन्दर नालिश दायर कर सकता है या दरख्वास्त दे सकता है, जो इस नियत समय के बाद दीगई हो।

३ जब यह नाकाबलियत (अयोग्यता) उस शख्स के मरने के समय तक बनी रहे, तो उसके कानूनी प्रतिनिधि उसके मरने के बाद उसी मुद्दत के भीतर नालिश दायर कर सकते हैं या दरख्वास्त दे सकते हैं जो इस नियत समय के बाद दीगई हो।

४ जब मृत्यु के समय ऐसा प्रतिनिधि ऐसी किसी बात की वजह से नाकाबिल (अयोग्य) हो, तो उस समय उप-दफा (१) और (२) में बतलाए हुए नियम लागू होंगे।

उदाहरण (Illustrations)

(ए) 'अ' को एक नावकें किराया की बातकी नालिश करनेका हक उसकी नाबालिगी (Minority) में पैदा होता है। इस हक पैदा होने की तारीख से चार साल बाद वह बालिग होता है वह बालिग होनेकी तारीखसे तीन साल के अन्दर किसी भी समय नालिश दायर कर सकता है।

(बी) 'क' को अपनी नाबालिगी की हालत में नालिश दायर करने का हक पैदा होता है। इस हक पैदा होने की तारीख के बाद, लेकिन नाबालिगी की हालत में ही, वह पागल हो जाता है। ऐसी दशा में 'क' के विरुद्ध मियाद उस तारीख से शुरू होती है जब उसका पागलपन और नाबालिगी दोनों खतम हो जाती है।

(सी) 'च' को अपनी नाबालिगी की हालत में नालिश करने का हक पैदा हुआ। 'च' बालिग होने के पहिले ही मर जाता है और उसका नाबालिग लड़का 'छ' उसका उत्तराधिकारी हुआ। तो ऐसी दशा में 'छ' के विरुद्ध मियाद उसके बालिग हो जाने के बाद से शुरू होती है।

दफा ७ कई एक मुद्दयों या सायलोंमें से किसी एकका नाकाबिल (अयोग्य) होना

जब कई एक आदमियों में से, जिनको किसी नालिश के दायर करने या किसी ठिकरी की इजरा के लिए दरखवास्त देने का मुद्दतरका (एक में) हक हासिल है, कोई एक शख्स ऐसी किसी बात की वजह से नाकाबिल होजावे, और ऐसे शख्स की बिना राय लिए बेबाकी (फारखती) की जा सकती हो, तो मियाद की मुद्दत का शुमार उन सब के सम्बन्ध में किया जायगा; लेकिन अगर ऐसी बेबाकी (फारखती) न की जा सकती हो, तो उनमें से किसी हक के सम्बन्ध में मुद्दत का शुमार न किया जा सकेगा, जब तक कि उसमें का कोई एक शख्स इस काबिल न हो जाय कि वह बिना बाकी लोगों की राय के ऐसी बेबाकी (फारखती) कर सके या जब तक कि वह नाकाबलियत (अयोग्यता) दूर न होजाय।

उदाहरण (Illustrations)

(ए) 'क' ने एक फर्म से जिसके 'ख' 'ग' और 'घ' हिस्सेदार हैं, कुछ कर्ज़ लिया। 'ख' पागल है, और 'ग' नाबालिग है। 'घ' बिना 'ख' और 'ग' की राय लिए हुए उस कर्ज़ की फारखती कर सकता है। ऐसी दशा में मियाद का शुमार 'ख', 'ग' और 'घ' सभी के सम्बन्ध में किया जा सकेगा।

(बी) 'क' ने एक फर्म से जिसमें 'च' 'छ' और 'ज' हिस्सेदार हैं, कुछ कर्ज़ लिया। 'च' और 'छ' पागल है, और 'ज' नाबालिग है। ऐसी दशा में उनमें से किसी के भी सम्बन्ध में मियाद का शुमार न किया जायगा, जब तक कि 'च' या 'छ' कोई एक अच्छा न होजाय अथवा 'ज' बालिग न होजाय।

दफा ८ कुछ विशेष अवस्थाओंमें इन नियमोंका लागू नहोना

दफा ६ में अथवा दफा ७ में कोई भी बात ऐसी नहीं है, जो उन नालिशों के सम्बन्ध में लागू होती हो जो हक-शिफा करने का अधिकार (हक) प्राप्त करने के लिए दायर की गई हो, या जिससे यह समझा जाय कि वह उस मियाद की, जिसके अन्दर कोई नालिश दायर की जानी चाहिए या दरखवास्त दी जानी चाहिए, मुद्दत को इस नाकाबलियत के दूर होजाने के समय से अथवा उस शख्स की, जिसके ऊपर इसका असर पड़ा है, मृत्यु होजाने के समय से, तीन साल से अधिक बढ़ा सके।

उदाहरण (Illustrations)

(ए) 'क', जिसको अपनी नाबालिगी में दिवा-बिल वसीयतके सम्बन्ध में नालिश करनेका हक पैदा हुआ, इस हक पैदा होनेकी तारीखसे वह ग्यारह वर्ष बाद बालिग होता है। साधारण कानून के अनुसार 'क' को सिर्फ एक साल और मिलता है जिसके अन्दर उसे नालिश कर देना चाहिये। लेकिन दफा ६ और इस दफा के अनुसार उसको दो साल का समय और दिया जायगा और इस तरह कुल मिलाकर उसके बालिग होने की तारीख से तीन साल की मुदत हो जाती है, जिसके अन्दर वह नालिश दायर कर सकता है।

(बी) 'क' को एक पैतृक स्थान (पद) के लिए नालिश दायर करने का हक पैदा हुआ और उस समय वह पागल है। छः साल के बाद 'क' का होश वह हवास ठीक हो जाता है। साधारण कानून के अनुसार 'क' को जिस तारीख को उसका पागलपन दूर हुआ था, उससे छःसालका समय मिलता है जिसके अन्दर वह नालिश दायर कर सकता है। ऐसी दशा में दफा ६के अनुसार, जब कि वह इस दफा के साथ पढ़ी जाय, उसको अधिक समय न बढ़वा मिलेगा।

(सी) 'क' को, जोकि मूर्ख (बेबकूफ) है एक आसामी से कब्जा हासिल करने के लिए वहीँसियत नुर्मींदार के नालिश दायर करने का हक पैदा होता है। हक पैदा होने के तीन साल बाद 'क' मर जाता है और उसकी मूर्खता (Idiocy) उसके मरने के समय तक बनी रहती है। साधारण कानून के अनुसार 'क' के उत्तराधिकारियों को 'क' के मरने की तारीख से नौ साल का समय मिलता है जिसके भीतर वे नालिश दायर कर सकते हैं। दफा ६, जब कि वह इस दफा के साथ पढ़ी जाय, इस मुदत को बढ़ा नहीं सकती, सिवाय उस हालत में जब कि वह प्रतिनिधि स्वयं उस समय नाकाबिल (अयोग्य) हो जिस समय उसको प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था।

दफा ९ समयका बराबर चलता रहना

जब एक बार मियाद की मुदत जारी होगई हो, तो बाद में नालिश दायर करसकने की अयोग्यता (नाकाबलियत) या असमर्थता (मजबूरी) से उस मुदत का जारी रहना रुक नहीं सकता।

लेकिन शर्त यह है कि जब किसी महाजनकी रियासतके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र (Letters of administration) उसके ऋणी (कर्जदार) को दे दिये गये हों, तो उस ऋण (कर्जा) की बसूलीके लिए दायर कीजानेवाली नालिशके सम्बन्धमें नियत (मुकर्रर) समयको जारी रहना उस समय तकके लिए रोक दिया जायगा जबतक कि उस रियासतका प्रबन्ध होता रहेगा।

दफा १० ट्रस्टियों और उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध की जाने- वाली नालिशें

चाहे इसके पहिलेवाली दफाओं में कुछ भी लिखा हो, किसी भी नालिशकी, जो किसी ऐसे शख्सके ऊपर, जिसको जायदाद ट्रस्टमें दी गई है, किसी भी खास कामके लिए दायर की गई हो, या उसके कानूनी प्रतिनिधियों या मुन्तकिल अलेहों के ऊपर (जो ऐसे मुन्तकिलअलेह नहीं हैं जिनके नाम जायदाद कुछ रकम लेकर मुन्तकिल की गई है) उसके या उनके हाथमें वह जायदाद या उसकी आमदनीको बनाए रखने के लिए, या ऐसी जायदाद या आमदनीके हिसाब-किताब समझाने के लिए दायर की गई हो, किसी भी समय मियाद आरज़ नहीं होगी ।

दफा ११ ब्रिटिश भारतसे बाहर लिखे गये मुआहिदोंकी बाबत नालिश

१ जो नालिशें ब्रिटिश भारतके भीतर उन मुआहिदों (Contracts) के ऊपर दायर की जायंगी जो किसी विदेश (Foreign Country) में लिखे गये हों, उनके सम्बन्धमें इस ऐक्टमें बतलाए हुए मियादके नियम लागू होंगे ।

२ ब्रिटिश भारतके बाहर प्रचलित मियाद सम्बन्धी नियम उस नालिशके ब्याजमें न पेश किये जा सकेंगे, जो किसी विदेश (Foreign Country) में लिखे गये मुआहिदेकी निस्वत दायर की गई हो, जबतक कि उस नियमसे यह मुआहिदा रद्द न होजाता हो और जिन फरीकनके दर्मियान, वह मुआहिदा हुआ है वे उस मियादके अन्दर उसी देशमें रहते न हो जो मियाद कि ऐसे नियमके अनुसार निश्चित की गई है ।

तीसरा प्रकरण

मियादकी मुद्दतका शुमार

दफा १२ कानूनी कार्रवाईमें समयका निकाल दिया जाना

१ उस मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें, जो किसी नालिश, अपील या दरख्वास्तके सम्बन्धमें नियत (मुक़रर) है, वह दिन निकाल दिया जायगा जिस दिनसे ऐसी मुद्दतका शुमार किया जाना चाहिए ।

२ उस मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें, जो किसी अपील, अपील करने के लिये इजाज़त हासिल करनेकी दरख्वास्त और फैसलेकी नज़रसानी करने के लिए दीजानेवाली दरख्वास्तके सम्बन्धमें नियत (मुक़रर) है, वह दिन, जिसको वह फैसला दिया गया था जिसकी निस्वत शिकायत है, और वह समय, जो डिकरी सज़ा या हुक्मकी, जिसकी अपील कीगई है या निगरानी कराई जाने को है, नक़ल हासिल करने के लिए आवश्यक है, निकाल दिए जायेंगे ।

३ जब किसी डिकरीकी अपील कीगई हो या उसकी नज़रसानीकी दरख्वास्त दीगई हो, तो जिस फैसलेके आधारपर वह डिकरी दीगई है उसकी नक़ल हासिल करने के लिए जितने समयकी ज़रूरत है वह भी निकाल दिया जायगा ।

४ किसी पञ्चायती फैसलेको रद्द करने के लिए दीजानेवाली दरख्वास्तके लिए नियत (मुक़रर) मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें वह समय निकाल दिया जायगा जो उस पञ्चायती फैसलेकी नक़ल हासिल करने के लिए इस्तेमाल है ।

दफा १३ ब्रिटिश भारतसे तथा अन्य देशोंसे मुद्दाअलेहकी अनुपस्थितिके समयका निकाल दिया जाना

किसी नालिशके सम्बन्धमें नियत (मुक़रर) मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें, वह समय निकाल दिया जायगा जिसमें मुद्दाअलेह ब्रिटिश भारतसे और ब्रिटिश भारतके बाहरके उन देशोंसे और-हाजिर रहा है जो सरकारके शासनाधीन (Under the administration) हैं ।

दफा १४ उस समयका निकाल दिया जाना जिसमें नेकनीयतके साथ उस अदालतमें कार्रवाई कीगई हो जिसे उस मामलेकी समाप्त करनेका अख्तियार न भी हो

१ किसी नालिशके सम्बन्धमें नियत (मुक़रर) मियादकी मुद्दतका शुमार करनेमें, वह समय, जिसमें मुद्दई उचित प्रयत्नके साथ किसी दूसरे दीवानी मामले

में, जो उसने मुद्दा-अलेहके विरुद्ध दायर किया है, किसी प्रारम्भिक अदालतमें अथवा अदालत अपीलमें पैरवी करता रहा हो, निकाल दिया जायगा, जबकि वह मामला उसी विनाय मुख़ासमतके ऊपर दायर किया गया हो और जो नेकनीयती के साथ उस अदालतमें दायर किया गया हो जो इस मामलेमें अख़्तियार समाप्त न रखने के कारण अथवा ऐसे ही अन्य किसी कारणसे उसकी सुनवाई करनेमें असमर्थ है।

२ किसी दरख़्वास्त के सम्बन्धमें नियत (मुकर्रर) मियादका शुमार करने में, वह समय, जिसमें सायल (Applicant) उचित प्रयत्न (मुनासिब) कोशिशके साथ किसी दूसरे दीवानी मामलेमें, जो उसने उसी फ़रीक़के खिलाफ़ उसी दादरसीकी बाबत दायर किया है, किसी प्रारम्भिक अदालत अथवा अदालत अपीलमें, पैरवी करता रहा हो, निकाल दिया जायगा जबकि ऐसा मामला नेक-नियतीके साथ किसी ऐसी अदालतमें दायर किया गया हो, जो अख़्तियार समाप्त न होने अथवा ऐसे ही किसी दूसरे कारणसे उसकी सुनवाई कर सकने में असमर्थ हो।

विवरण १ उस समयके निकाल देनेमें, जिसमें पहिलेकी कोई नालिश या दरख़्वास्त फैसल नहीं हुई थी (Was pending), वह दिन, जिसको वह नालिश या दरख़्वास्त दायर कीगई थी, और वह दिन जिसको उस सम्बन्धमें कार्रवाई ख़तम हुई है, दोनों शुमार कर लिए जायंगे।

विवरण २ इस दफ़ा के प्रयोजनके लिए किसी मुद्दई और उस सायल (Applicant) की निस्वत, जो किसी अपीलके विरोधमें कार्रवाई कर रहा हो, यह समझा जायगा कि वह किसी मामलेमें पैरवी कर रहा है।

विवरण ३ इस दफ़ा के प्रयोजनके लिए फ़रीक़ैनका या विनाय मुख़ासमत का बेजा तौरपर शामिल किया जाना अख़्तियार समाप्त न होनेका जैसा कारण समझा जायगा।

दफ़ा १५ उस समयका निकाल दिया जाना जिसमें कार्रवाई मुक़द्दमा मुलतबी रही है

१ किसी ऐसी नालिश या किसी डिकरीकी इजराके लिए दीजानेवाली ऐसी दरख़्वास्तके सम्बन्धमें, जिसका दायर किया जाना या इजरा, या हुक़म इस्तनाई या दूसरे हुक़मसे मुलतबी कर दिया गया है, नियत (मुकर्रर) मियादकी मुद्दतका शुमार करने में वह समय, जिसमें वह हुक़म इस्तनाई या दूसरा हुक़म जारी रहा है, वह दिन, जिसको वह जारी किया गया था या दिया गया था और वह दिन, जिसको कि वह वापस लिया गया था, निकाल दिए जायंगे।

२ किसी ऐसी नालिशके सम्बन्धमें, जिसकी नोटिस उस समय प्रचलित किसी भी कानूनके अनुसार दे दी गई है, नियत (मुकर्रर) मियादका शुमार करनेमें ऐसी नोटिसकी मुदत निकाल दी जायगी ।

दफा १६ उस समयका निकाल दिया जाना जिसमें किसी डिकरी की इजरा में होनेवाली नीलामको रद्द कर दिए जाने के लिए दायर किया गया मामला फैसल नहीं हुआ था

उस मियादकी मुदतका शुमार करनेमें, जो किसी डिकरीकी इजरा में होनेवाली नीलामके खरीदारकी ओरसे खरीद की हुई जायदादपर कब्ज़ा दिखानेके लिए दायर की जानेवाली नालिशके सम्बन्धमें नियत (मुकर्रर) की गई है, वह समय, जिसमें नीलाम रद्द किए जानेके लिए दायर किया गया मामला चलता रहा है, निकाल दिया जायगा ।

दफा १७ नालिश करनेका हक पैदा होनेके पहिले मौत हो जानेका असर

१ जब वह शख्स, जिसे, अगर वह जीवित होता तो, किसी नालिशके दायर करने या दरखवास्त देनेका हक मिला हुआ होता, ऐसे हकके पैदा होनेके पहिले ही मर जाय, तो मियादकी मुदतका शुमार उस समयसे किया जायगा जब उस मृत-पुरुष (मुतौफी) का कोई कानूनी प्रतिनिधि पैदा हो जाय जिसे नालिश दायर कर सकने या दरखवास्त दे सकनेका हक था ।

२ जब वह शख्स, जिसके विरुद्ध, अगर वह जीवित होता, नालिश दायर किए जाने या दरखवास्त दिए जाने का हक पैदा हुआ होता, ऐसा हक पैदा होने के पहिले ही मर जाता है, तो मियादकी मुदतका शुमार उस समयसे किया जायगा जब उस मृत-पुरुष (मुतौफी) का कोई कानूनी प्रतिनिधि पैदा होगया हो जिसके विरुद्ध मुद्दई नालिश दायर कर सके या दरखवास्त दे सके ।

३ उप-दफा (१) और (२) में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उस नालिश के सम्बन्धमें, जो हक-शिफा करनेका हक कायम कराने के लिए दायर की गई हो, या उस नालिशके सम्बन्धमें लागू होती हो जो जायदाद गैर-मनकूला या किसी पैत्रिक-पद (Hereditary Office) का कब्ज़ा दिखाने के लिए दायर की गई हो ।

दफा १८ फरेब (Fraud) का परिणाम

जब किसी शख्सको, जिसे नालिश दायर कर सकने या दरखवास्त देने का हक है, फरेबसे ऐसे हककी या उस हकीयतकी, जिसके आधारपर वह पैदा होता है, बात जानने न दी गई हो, या जब कोई कागज़ (Document), जो ऐसे

हक़को तय करने के लिए ज़रूरी है, छल (फरेब) करके उससे छिपाया गया हो, तो उस मियाद की मुद्दतका, जो:—

(ए) उस शख्सके विरुद्ध जोकि छल (फरेब) करनेका दोषी है अथवा उसमें सहायक रहा है, या

(बी) उस शख्सके विरुद्ध, जो, नेकनीयतीसे और किसी रुपयेके बदलेके सिवा और किसी तरह, उसके ज़रिये से दावेदार है नालिश दायर किए जाने या दरख़वास्त दिए जानेके लिए नियत है,

शुमार उस समयसे किया जायगा जब पहिले पढ़ल उस छल (फरेब) का पता उस शख्सको मिला हो जिसको इससे क्षति पहुँची है, या: किसी कागज़ छिपाये जानेकी दशामें, उस समय से, जब उसके पास पहिले पढ़ल उसके पेश करने या पेश करा सकने के साधन मौजूद थे।

दफा १९ लिखित स्वीकृत-पत्र (Acknowledgement) का असर

जब उस मुद्दतके ख़तम होनेके पहिले, जो किसी जायदाद या हक़के सम्बन्धमें दायर की जानेवाली नालिश या दीजानेवाली दरख़वास्तके सम्बन्धमें नियत है, ऐसी जायदाद या हक़के सम्बन्धमें दायित्व (Liability) का लिखित स्वीकृत-पत्र (Acknowledgement) दे दिया गया हो, जिसपर उस शख्सने जिसके विरुद्ध ऐसी जायदाद या ऐसे हक़की निस्वत दावा किया हो या उस शख्सने, जिसके ज़रियेसे उसे हकीयत या दायित्व पैदा होता है, अपने हस्ताक्षर कर दिए हों, तो मियादकी नई मुद्दतका शुमार उस समयसे किया जायगा जब उस स्वीकृत-पत्र (Acknowledgement) पर इस प्रकार हस्ताक्षर किए गए हों।

२ जब उस, स्वीकृत-पत्र (Acknowledgement) के ऊपर तारीख़ न पड़ी हो, उस समयके सम्बन्धमें, जिस समय कि उसपर हस्ताक्षर किए गए थे, ज़बानी शहादत पेश की जासकती है; लेकिन भारतीय क़ानून शहादत (Indian Evidence Act) सन् १८७२ ई० के नियमों की पाबन्दीमें रहते हुए उसमें लिखी गई बातोंके सम्बन्धमें ज़बानी शहादत न लीजायगी।

विवरण १—इस दफा के प्रयोजनके लिए लिखित स्वीकृत-पत्र (Acknowledgement) काफी समझा जायगा, यद्यपि उसमें जायदाद या हक़की असली हालत न भी बतलाई गई हो, या उसमें यह बतलाया गया हो कि अदायगी (Payment) सिपुर्दगी (Delivery), तामील (Performance) या इस्तेमाल (Enjoyment) का समय अभी नहीं आया है, या उसमें अदायगी, सिपुर्दगी और तामील करने या इस्तेमालकी इजाज़त देनेसे इन्कार कर दी गई हो, या उसमें मुजराई रक़मकी निस्वत दावा किया गया हो अथवा वह उस शख्स के सिवाय, जो उस जायदाद या हक़के पानेका अधिकारी है, दूसरे शख्सके नाम लिखा गया हो।

विवरण २—इस दफा के प्रयोजनके लिए “हस्ताक्षर कर दिए हों” का अर्थ यह है कि उसने अपने हाथसे दस्तखत कर दिए हों, या उसके किसी मुख्तार (Agent) ने, जिसे इस सम्बन्धमें अधिकार दिए गए हैं, उसकी ओरसे दस्तखत कर दिए गए हों।

विवरण ३—इस दफा के प्रयोजनके लिये किसी डिकरी या हुक्मकी इजरा के लिये दी गई दरख्वास्त किसी हककी निस्वत दी गई दरख्वास्त है।

दफा २० ब्याजका बतौर ब्याजके अथवा मूलके किसी अंश (हस्से) के अदाकर देनेका असर

१ जब किसी ऋण (कर्जा) या हिस्बाबिल वसीयत (Legacy) के सम्बन्ध में वातव्य (वाजिब) ब्याजका रुपया, नियत समयके समाप्त होनेके पहिले बतौर ब्याजके उस शर्त द्वारा, जो ऋण अथवा हिस्बाबिल वसीयतसे प्राप्त धन का देनदार है, अथवा उसके मुख्तार मजाज़ द्वारा, जिसे इस सम्बन्धमें बाकायदा अख्तियार दिया गया है, अदा कर दिया जाय,

या जब किसी ऋणके मूलधन (असल रुपये) का कोई अंश (हिस्सा) नियत रुपये के समाप्त होने के पहिले, ऋणी द्वारा या उसके मुख्तार द्वारा, जिसे इस सम्बन्धमें बाकायदा अख्तियार दिया गया है, अदा कर दिया जाय,

तो मियादकी नई मुद्दतका शुमार उस समयसे किया जायगा जबकि इस ब्याज अथवा मूलधनका रुपया अदा किया गया था।

लेकिन शर्त यह है कि, जब किसी ऋणके मूलधन (असल रुपये) का एक अंश (हिस्सा) अदा किया गया हो तो, यह अदायगी उसके हाथसे लिखी गई होनी चाहिए जिसने रुपया अदा किया है।

२ रेहन की हुई आराज़ी की पैदावार वसूल लेने का असर—

जब रेहन की हुई आराज़ी पर मुर्तहिन का दखल (कब्ज़ा) हो, तो ऐसी आराज़ी के लगान या उसकी पैदावार का वसूल कर लेना उप-दफा (१) के प्रयोजन के लिए अदायगी समझा जायगा।

विवरण—ऋण (कर्जा-Debt) में वह रुपया भी शामिल है जो अदालत की किसी डिकरी या हुक्म के अनुसार वाज़िबुल् अदा हो।

दफा २१ जो शर्त नालिश वगैरा के नाक्रागिल है, उसका मुख्तार

१ दफा १९ और २० में आए हुए “मुख्तार जिसको इस सम्बन्ध में बाकायदा अख्तियार दिया गया हो” वाक्य में, उस शर्त के सम्बन्ध में, जो नालिश वगैराके नाक्राबिल (अयोग्य) है, उसका कानूनी बली, कमेटी या मैनेजर, अथवा उस मुख्तार जिसको ऐसे बली, कमेटी या मैनेजरकी ओर से स्वीकृति-पत्र (Ackn

nowledgement) पर हस्ताक्षर करने या रुपये की अदायगी करने का वाक्य या अक्षर दिया गया हो ।

२ कई एक मुश्तरका मुआहिदादारों इत्यादि में से किसी एक की ओर से स्वीकृति-पत्र (Acknowledgement) का लिखा जाना या रुपये का अदा किया जाना—

उपरोक्त दफाओं में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे कई एक मुश्तरका मुआहिदादारों, हिस्सेदारों, तामील कुनिन्दों अथवा मुर्तहिनों में से कोई एक शख्स केवल किसी लिखित स्वीकृति-पत्र के कारण, जिसपर उसके या उनमें से किसी दूसरे या किन्हीं दूसरों के मुखतारने हस्ताक्षर किए हों या उस अदायगी के कारण जो उसके या उनमें से किसी दूसरे या किन्हीं दूसरों के मुखतार द्वारा की गई हो ।

दफा २२ नये मुद्दई या मुद्दाअलेह के बढाए जाने या किसी

दूसरे मुद्दई या मुद्दाअलेह की जगह पर शामिल किए जाने का असर

१ जब नालिश दायर हो जाने के बाद नए मुद्दई या मुद्दाअलेह का नाम बढाया जाय या किसी दूसरे मुद्दई या मुद्दाअलेह की जगह शामिल किया जाय, तो जहां तक उसका सम्बन्ध है वह नालिश उस समय दायर की गई समझी जायगी जब कि वह शख्स फरीक मुकदमा बनाया गया था ।

२ उप-दफा (१) में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उस मामले में लागू होती हो जिसमें कोई शख्स किसी मुकदमे के दौरान में की गई किसी हक के मुन्तकिल कर दिए जाने (Assisment) या दे दिए जाने (Devolution) के कारण बढाया गया हो या दूसरे शख्स की जगह फरीक बनाया गया हो या जिसमें कोई मुद्दई मुद्दाअलेह बना दिया गया हो और मुद्दाअलेह मुद्दई ।

दफा २३ शिकस्त मुआहिदा और फेल-बेजा का बराबर

जारी रहना

जब किसी मुआहिदा की शिकस्त (Breaches) और फेल बेजा (Wrong) जिसका मुआहिदा से कोई ताल्लुक नहीं है, बराबर जारी रहे, तो ऐसी दशा में मियाद की मुद्दत उस समय के प्रत्येक मिनट से जारी होगी जिसमें वह शिकस्त मुआहिदा या फेल बेजा, जैसा कुछ भी हो, जारी रहा हो ।

दफा २४ किसी ऐसे कामके लिए मुआविजे की नालिश, जो

बिना कोई खास नुकसान पहुंचाए न की जा सकती हो

अगर कोई नालिश किसी ऐसे काम के मुआविजे की बाबत दायर की गई हो, जिसमें उस समय तक मुकदमें की बिनाय मुखासमत न पैदा होती हो जा

तक कि उससे कोई खास नुकसान न पहुँचा हो, तो मियाद की मुदत का शुमार उस समय से किया जायगा जब कि नुकसान हुआ हो।

उदाहरण (Illustration)

‘क’ एक खेत की ऊपरी ज़मीन का मालिक है। ‘ख’ उसके नीचे की ज़मीन (Sub-soil) का मालिक है। ‘ख’ उस ऊपरी ज़मीन को बिना कोई ज़ाहिरा नुकसान पहुँचाए उसमें से खोद कर कोयला निकालता है; लेकिन अन्त में वह ऊपरी ज़मीन बैठ जाती है। ऐसी दशा में ‘क’ की ओर से ‘ख’ के ऊपर की जाने वाली नालिश की मियाद की मुदत उस समय से शुरू होती है जिस समय वह ज़मीन बैठ गई थी।

दफा २५ दस्तावेज़में बतलाई हुई मुदतका शुमार

इस ऐक्ट के प्रयोजन के लिए कुल दस्तावेज़ों की निम्नत यह समझा जायगा कि उनमें बतलाई गई मुदतका शुमार वे भी ग्रीगोरियन साल (साल लगान) के हिसाब से किया जाना चाहिए।

उदाहरण (Illustrations)

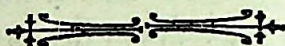
(ए) एक हिन्दू ने एक इन्दुल तलब रुक्का (Promissory note) लिखा जिसमें उसने लिफ्ट देशी तारीख [Native date] डाली और इस तारीख से ४ महीने के बाद रुपये की अदायगी का वादा किया। इस रुक्का की निम्नत की जाने वाली नालिश के सम्बन्ध में लागू होने वाली मियाद की मुदत का शुमार उस तारीख से चार महीने, जिनका शुमार ग्रीगोरियन साल के हिसाब से किया जायगा, गुज़र जाने के बाद से किया जायगा।

(बी) एक हिन्दू ने एक तमस्सुक लिखा, जिसपर उसने देशी तारीख (Native date) डाली और रुपये की अदायगी का एक साल का वादा किया। इस तमस्सुक की बाबत की जाने वाली नालिश के सम्बन्ध में लागू होने वाली मियाद की मुदत का शुमार उस तारीख के बाद एक साल की, जिसका शुमार ग्रीगोरियन साल (साल लगान) के अनुसार किया जायगा, मुदत ख़तम हो जाने के समय से आरम्भ की जायगी।

नोट—ग्रीगोरियन साल ३६६ दिन का होता है।

चौथा प्रकरण

दखल के जरिये मिलिकयत का हासिल करना



Acquisition of ownership by Possession.

दफा २६ हक आसायश का हासिल करना

१ जब किसी मकान के सम्बन्ध में रेशनी या हवा के आने जाने और उसके इस्तेमाल के हक का बतौर हक आसायश और अधिकार के बिना किसी रोक-टोक के और बीस साल तक उपभोग किया गया हो,

और जब किसी मार्ग (Way) या जल-मार्ग (Water Course), अथवा किसी पानी के इस्तेमाल का हक या दूसरा हक आसायश [चाहे वह इकरी हो या इन्कारी] का शान्ति के साथ और खुले तौर पर किसी ऐसे शख्स द्वारा, जो उसके लिए बतौर हक आसायश और अधिकार के दावेदार है, बिना रोक-टोक और बीस साल तक उपभोग किया गया हो,

तो ऐसी रेशनी या हवा के आने जाने और इस्तेमाल, मार्ग, जल-मार्ग, पानी के इस्तेमाल या दूसरी आसायश के इस्तेमाल का हक कतई और ऐसा होगा जिसमें कोई कुछ भी आपत्ति न कर सकेगा ।

उपरोक्त बीस साल की हर एक मुद्दत ऐसी मुद्दत समझी जायगी जिसकी समाप्ति उस नालिश के दायर किए जाने के ठीक दो साल पहिले हुई हो जिसमें उस दावा की निस्वत झगड़ा है जिससे इस मुद्दत का सम्बन्ध है ।

२ जब वह जायदाद, जिसके ऊपर उप-दफा (१) के अनुसार किसी हक की निस्वत दावा किया गया है, सरकारी [गवर्नमेंट की] जायदाद हो, तो उस उप-दफा में “बीस साल” की जगह “साठ-साल” पढ़ना चाहिए ।

विवरण—इस दफा के अर्थ कोई भी बात रोक-टोक करने वाली न समझी जायगी, जब तक कि दावेदार को छोड़ किसी दूसरे शख्स के किसी काम से रुकावट डाले जाने के कारण इस दखल या उपभोग (enjoyment) को वास्तव में रोक न दिया गया हो और जब तक कि ऐसी रुकावट दावेदार को इस रोक-टोक किए जाने की और उस शख्स की, जिसने यह रोक टोक डाली है या उसके डाले जाने के लिए दूसरे को अधिकार दिया है, नोटिस मिल जाने के बाद एक साल तक उस रोक-टोक को छोड़ न दिया गया हो या स्वीकार न कर लिया गया हो ।

उदाहरण (Illustrations)

(ए) एक नालिश मार्ग (Way) सम्बन्धी अधिकारों में रुकावट डालने के लिए सन् १९११ ई० में दायर की जाती है। मुद्दाभलेह इस रुकावट डालने की बात को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उस मार्ग सम्बन्धी अधिकारको अस्वीकार करता है। मुद्दै यह साबित करता है कि उसने उस अधिकार का शान्ति के साथ और खुले तौर पर, उसके सम्बन्ध में बतौर हक आसायश के दावा रखते हुए, बिना किसी रोक-टोक के तारीख १ जनवरी सन् १८९० ई० से १ जनवरी सन् १९१० ई० तक उपभोग किया। मुद्दै मुकद्दमें में फैसले का हकदार है।

(बी) इसी तरह की एक नालिश में मुद्दै यह दिखलाता है कि उसने इस अधिकार उपभोग शान्ति के साथ खुले तौर पर बीस साल तक किया है। मुद्दाभलेह यह साबित करता है कि मुद्दैने इस बीस साल की मुद्दत के अन्दर एक समय, इस अधिकार का उपभोग करने के लिए, उसकी आज्ञा प्राप्त की थी। ऐसी दशा में नालिश खारिज कर दी जायगी।

दफा २७ मिलिकयत ताबेह (Servient Tenement) के वारिस माबाद (रिवर्सनर) के हक में, मुद्दत का निकाल दिया जाना

जब किसी ज़मीन या पानी पर, जिसके ऊपर, जिसपर से या जिससे कोई हक आसायश हासिल किया गया है या उसका उपभोग किया गया है, किसी हक हीन हयाती या किसी मुद्दत के जो उसके दिए जाने की तारीख से तीन साल से अधिक न हो, अनुसार या उसके कारण कब्ज़ा रखा गया हो, तो बीस साल की इस मुद्दत का शुमार करने में उसमें से वह समय निकाल दिया जायगा जिसमें उसने ऐसे हक या मुद्दत के दौरान में हक आसायश (Easement) का उपभोग किया है, बशर्ते कि इस दावा की, ऐसे हक या मुद्दत के ख़तम होजाने के ठीक दो साल के अन्दर, उस शख्स ने मुखालिफ़त कर दी हो जो, उस हक या मुद्दतके ख़तम होजाने पर, उक्त ज़मीन या पानी के लिए हकदार है।

उदाहरण (Illustration)

'क' इस बात का एलान करने के लिए नालिश दायर करता है कि उसे 'ख' की ज़मीन पर होकर निकलने का अधिकार है। 'क' इस बात को साबित करता है कि उसने पच्चीस साल तक इस अधिकार का उपभोग किया है; लेकिन 'ख' इस बात को दिखलाता है कि इनमें से दस साल तक इस ज़मीन पर 'ग'

को, जोकि एक हिन्दू-बेवा है, हक हीनदशाती हासिल था, यह कि 'ग' के मरने पर 'ख' उस जमीन का हकदार हुआ और यह कि 'ग' के मरने के बाद दो साल के भीतर उसने इस अधिकार के सम्बन्ध में 'क' के दावा की मुखालिफत की। ऐसी दशा में नालिश खारिज हो जानी चाहिये, क्योंकि इस दफा के अनुसार उसने सिर्फ पन्द्रह साल तक ही अपने इस अधिकार के उपभोग को साबित किया है।

दफा २८ जायदाद सम्बन्धी अधिकार का जाता रहना

किसी भी ऐसी मियाद के, जो किसी शख्स को इस कानून के अनुसार किसी जायदाद पर कब्ज़ा दिला पाने के सम्बन्ध में नालिश दायर करने के लिए दी गई है, खतम होजाने पर उस जायदाद के सम्बन्ध में प्राप्त उसका अधिकार जाता रहेगा।

पांचवां प्रकरण

बचत और मसूखी

Savings and Repeals.

दफा २९ बचत

१ इस ऐक्ट में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे भारतीय कानून मुआहिदा (Indian Contract Act.) सन् १८७२ ई० की दफा २५ पर कोई असर पड़ता हो ।

२ जब किसी विशेष अथवा स्थानीय कानून के अनुसार, किसी नालिश अपील या दरख्वास्त के लिए मियाद की कोई ऐसी मुदत निश्चित की गई हो, जो उस मुदत से भिन्न है जो परिशिष्ट (१) में इनके लिए बतलाई गई है, तो दफा ३ के नियम लागू होंगे, मानों इनके सम्बन्ध में उस परिशिष्ट में ही वह मुदत निश्चित कर दी गई थी, और मियाद की किसी मुदत को, जो किसी विशेष अथवा स्थानीय कानून के अनुसार किसी नालिश, अपील या दरख्वास्त के लिए निश्चित की गई है, तय करने के लिए:—

(ए) वे नियम, जो दफा ४, ९ से १८ तक की दफाओं में और दफा २२ में बतलाए गए हैं, वहीं तक और उसी हद तक लागू होंगे, जब तक कि वे ऐसे विशेष अथवा स्थानीय कानून द्वारा विशेष रूप से निकाल न दिए गए होंगे; और

(बी) इस ऐक्ट के शेष नियम लागू न होंगे ।

३ इस ऐक्ट में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इण्डियन डाइबोर्स ऐक्ट (कानून तलाक हिन्द) सन् १८६९ ई० के अनुसार की जाने वाली नालिशों के सम्बन्ध में लागू होती हो ।

४ दफा २६ और २७ और दफा २ में बतलाई हुई "हक आसायश (Easement)" की परिभाषा उन स्थानों में होने वाले मुकदमों में लागू नहीं होते जिनमें उस समय इण्डियन ईजमेंट ऐक्ट (कानून आसायश) सन् १८८२ ई० लागू हो ।

दफा ३० उन नालिशोंके सम्बन्धमें व्यवस्था, जिनके सम्बन्ध में नियत (मुक़रर) मियाद की मुद्दत उस मुद्दतसे कम हो, जो भारतीय क़ानून मियाद [इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट] सन् १८७७ ई० में निश्चित कीगई है

चाहे इस ऐक्टमें कोई भी व्यवस्था क्यों न हो, कोई भी ऐसी नालिश जिसके सम्बन्धमें इस ऐक्टके अनुसार निश्चित मियादकी मुद्दत उस मियादकी मुद्दतसे कम है, जो भारतीय क़ानून मियाद [इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट] सन् १८७७ ई० के अनुसार निश्चित कीगई है, इस ऐक्टके पास होनेसे ठीक दो सालके अन्दर, या उस मुद्दतके अन्दर दायर की जासकती है जो भारतीय क़ानून मियाद सन् १८७७ ई० के अनुसार निश्चित कीगई है, इसमें से जो भी मुद्दत पहिले ख़तम होती हो।

दफा ३१ परिशिष्ट (२) में बतलाए हुए प्रान्तोंमें कुछ मुर्त-हिनोंकी ओरसे की जानेवाली नालिशोंके सम्बन्ध में व्यवस्था

१ इस ऐक्टमें अथवा इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट [भारतीय क़ानून मियाद] सन् १८७७ ई० में चाहे कुछ भी व्यवस्था क्यों न हो, उन प्रान्तोंमें, जो परिशिष्ट (२) में बतलाए गए हैं, किसी मुर्तहिनकी ओरसे नीलामकी बैचात की जानेवाली नालिश या बैचातके लिए की जानेवाली नालिश इस ऐक्टके पास होनेकी तारीख़ से दो सालके अन्दर या जिस तारीख़को, रेहननामासे लिया गया रुपया वाजिबुल अदा हुआ हो उस तारीख़ से साठ सालके अन्दर, इसमें से जो कोई भी मुद्दत पहिले ख़तम होती हो, दायरकी जासकती है; और उक्त प्रान्तोंमें कोई भी ऐसी नालिश, जो उपरोक्त साठ सालकी मियादके अन्दर दायर कीगई हो और इस ऐक्टके पास होनेकी तारीख़ को, किसी प्रारम्भिक अदालतमें या किसी अदालत अपीलमें, बिना फैसलकी हुई पड़ी हो, इस बिनापर ख़ारिज न की जायगी कि इसमें बारह सालकी मियाद सम्बन्धी नियम लागू होता है।

२ जब उपरोक्त प्रान्तोंमें किसी मुर्तहिनका बैचात या नीलामकी निश्चित किया गया दावा जुलाई सन् १९०७ ई० की बाईसवीं तारीख़ के बाद और इस ऐक्टके पास होनेके पहिले इस बिनापर, कि ऐसे दावोंके सम्बन्धमें बारह वर्षकी मियाद सम्बन्धी नियम लागू होता है, पूर्णतः अथवा अंशतः ख़ारिज कर दिया गया हो या वापस ले लिया गया हो, फिर चाहे वह किसी प्रारम्भिक अदालतमें हो अथवा अदालत अपीलमें, तो उस अदालतको, जिसने इस दावाको ख़ारिज कर दिया या

या जिसमें से वह वापस लेलिया गया था, लिखित दरख्वास्त देनेपर उस मामले की फिर समाप्तकी जासकती है, बशर्त कि दरख्वास्त इस ऐक्टके पास होनेकी जरूरत से छः महीनेके भीतर दीजाय; और उस मामलेके बहाल होजानेपर उपर्युक्त (१) के नियम लागू होंगे।

इफा ३२ ऐक्ट नं० १७ सन् १९१४ ई० द्वारा मंसूख किया गया

परिशिष्ट (१)

[देखो दफा ३]

प्रथम खण्ड-नालिशें

नालिश की किस्म	मियाद की सुदत	मियाद कब से शुरू होगी ?
१ वेस्ट लैण्ड्स (वलेम ऐक्ट सन् १८६३) के अनुसार बोर्ड माल के दिए हुए फैसले को मंजूर करने के लिए की गई नालिश	भाग १ तीस दिन ३० दिन	जब इस फैसलेकी नोटिस सुर्दईको दी गई हो
२ किसी ऐसे काम के करने या न करने के लिए जो उस समय ब्रिटिश भारत में प्रचलित किसी कानूनके अनुसार किया गया बतलाया जाता है, सुभाविज्ञा की बाबत नालिश ।	भाग २ नब्बे दिन ९० दिन	जिस समय वह काम किया जाय या न किया जाय ।
३ स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट सन् १९७७ ई० की दफा ९ के अनुसार जायदाद गैर-मनकूला के ऊपर कब्ज़ा दिहायाने के लिए नालिश ।	भाग ३-छः महीना ६ महीना	जिस समय कब्ज़ा छीन लिया गया हो ।

जिस समय मजदूरी, किराया या कर्मचारी की मजदूरी का भुगतान करना होता है ।

४ जाबता दीवानी सन् १९०८० की दफा १२८ (२)

जिस समय खरीदारने बयनामा अनुसार फरोख्त शुद्धः कुल जायदादपर वाकई कब्जा कर लिया हो, या जबकि फरोख्त शुद्धः चीजपर वाकई कब्जा न किया जा सकता हो तो उस समय से, जबकि दस्तावेज बयनामा की रजिस्ट्री हुई हो ।
हुक्मकी तारीख से ।

"

११ उस शङ्ख की ओर से, जिसके खिलाफ नीचे लिखा कोड़े भी हकम दिया गया हो, उस हक को कायम करने के

नालिश की क्रिस्म	मियादकी मुदत	मियाद कब से शुरू होगी
<p>लिए कीगई नालिश जिसके लिए वह उस हुकम में बतलाई हुई जायदाद के लिए दवेदार है:—</p> <p>१ ज़ाबता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार दिया गया हुकम, जो उस दावा के ऊपर, जो उस जायदाद की निस्बत किया गया है जो किसी डिकरी की इजरा में कुंके कीगई है, या उस उज्रदारी के ऊपर दिया गया हो, जो उस जायदाद की कुर्की की निस्बत किया गया है।</p> <p>२ प्रेजीडेन्सी अदालत खफ़ीफ़ा ऐक्ट सन् १८८२ ई० की दफ़ा २८ के अनुसार दिया गया हुकम।</p> <p>११ (ए) उस शक्सकी ओरसे, जिसके खिलाफ़ ज़ाबता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार हुकम दिया गया है, किसी डिकरी दार की दरख़वास्त के ऊपर, जो कि उसने जायदाद गैर-मनक़ूला पर क़ब्ज़ा करने की बाबत दी है या उस दरख़वास्त पर, जो कि किसी डिकरी की इजरा में नीलाम हुई ऐसी जायदाद के खरीदार ने दी है और जिसमें उन्होंने उस जायदाद के ऊपर क़ब्ज़ा करने में डाकी जाने वाली रुकावट या उसके विरोध किए जाने के सम्बन्ध में शिकायत की है, या उस दरख़वास्त के ऊपर, जो किसी ऐसे शक्स की ओर कीगई है जो डि-</p>	<p>एक साल</p>	<p>हुकम की तारीख़ से</p>

करीदार या खरीदार को कब्जा दिए जाने के समय उस जायदाद से वेदखल कर दिया गया है, उस हक को कायम करने के लिए की गई नालिश जिस हक के लिए वह उस हुकम में बतलाई हुई जायदाद के मौजूदा कब्जे की वास्तव दावेदार है।

१२ नीचे लिखे नीलामों को रद्द करने के लिए नालिश—

(ए) किसी अदालत की दीवानी की डिकरी की इजरा में होने वाली नीलाम,

(बी) किसी कलक्टर या हाकिम माल के हुकम या डिकरी के अनुसार की हुई नीलाम।

(सी) सरकारी मालखुजारी की बकाया में होने वाली नीलाम, या किसी ऐसी रकम के सम्वन्ध में होने वाली नीलाम जो बतौर ऐसी बकाया के वसूल किए जाने को हो।

(डी) किसी पटनी तालुक की नीलाम जो हाल की बकाया लगान की निम्न नीलाम हुई हो।

विवरण—इस आर्टि० में “पटनी में कोई भी दर्मियानी हक आराजी शामिल है जो हाल के बकाया लगान की वास्तव नीलाम किए जाने के काबिल है।

जिस समय नीलामकी मन्जूरी दे दी गई हो, या और तरह पर वह नीलाम कतई और आखिरी हो जाता, अगर ऐसी नालिश दायर न की गई होती।

नालिस की किस्म	मियाद की मुदत	मियाद कब से शुरू होगी
१३ किसी अदालत दीवानी के फैसले या हुक्म को बदल देने या मसुल कर देने के लिए, जो उसने किसी मुकदमें के अलावा किसी दूसरी कार्यवाई में दिया हो, ।	एक साल	आखिरी फैसला या हुक्मकी तारीख से, अगर वह फैसला या हुक्म किसी ऐसी अदालतकी ओरसे दिया गया है जिसे इसके देनेका अधिकार है ।
१४ किसी सरकारी अफसर के किसी ऐक्ट या हुक्म को, जो उसने सरकारी अफसर की हैसियत से दिया हो, रद्द करने के लिए नालिश ।	"	ऐक्ट या हुक्मकी तारीख से ।
१५ सरकार के विरुद्ध, किसी कुर्की, पट्टा या मुन्तकिली लायदाद गैर-मनकूला को, जो किसी हाकिम माल की ओर से सरकारी मालगुजारी की बकाया के लिए कीगई हो, मसुल करानेके लिए नालिश ।	"	जिस समय कुर्की, या मुन्तकिली कीगई या पट्टा दिया गया हो ।
१६ सरकार के विरुद्ध उस रुपये को वापस दिलानेके लिए नालिश जो रुपया किसी प्रोटेक्ट में उस दावा की निस्वत अदा किया गया हो जो मोहकमें माल के हाकिमों ने बाबत बकाया मालगुजारी या बाबत उस मतालबा के किया हो जो बतौर ऐसी बकाया के वाजिबुल वसूल है ।	"	जिस समय रुपया अदा किया गया हो ।
१७ सरकार के विरुद्ध उस जमीन के माविजा की बाबत नालिश जो जमीन कि सरकारी (Public) कामों के लिए ले की गई है ।	"	जिस तारीखको माविजाकी रकम तय कीगई हो ।

२८- इसी प्रकार की नालिश बाबत सुभाविज्ञा के जबकि आरज़ी (जमीन) का ले लिया जाना पूरा न हुआ हो।

१९- गलत तौर पर कैद रखने के लिए सुभाविज्ञा की बाबत नालिश।

२०- तामील कुनिन्दो, प्रबन्धकर्ताओं अथवा प्रतिनिधियों की ओर से लीगल रिमेजेण्टेडिज़ स्टुस ऐक्ट सन् १८५५ ई० के अनुसार की जाने वाली नालिश।

२१- तामील कुनिन्दों, प्रबन्धकर्ताओं अथवा प्रतिनिधियों की ओर से इण्डियन फैटल एक्सीडेंट्स ऐक्ट सन् १८५५ ई० के अनुसार की जाने वाली नालिश।

२२- किसी दूसरे तुकसान के, जो उस शख्स को पहुँचाया गया है, माविज्ञा की बाबत नालिश।

२३- अदालत से छूटा मामला चलाने के लिए सुभाविज्ञा की बाबत नालिश।

२४- मानहानि करने के लिए सुभाविज्ञा की बाबत नालिश।

२५- जबानी तौहीन (Slander) करने के लिए सुभाविज्ञा की बाबत नालिश।

जिस तारीख को पूरा करने से इन्कार कर दी गई हो।

जिस तारीख को कैद खतम होती हो।

जिस तारीख को उस शख्स की मृत्यु हुई हो जिसको तुकसान पहुँचाया गया है (अर्थात् जिसके साथ अन्याय हुआ है)।

उस शख्स के मरने की तारीख से जो कि क़त्ल किया गया है।

जिस वक्त तुकसान पहुँचाया गया हो।

जिस समय मुद्दा बरी कर दिया गया हो या और किसी तरह से मुकदमा खारिज हो गया हो।

जिस समय मानहानि की बातें प्रकाशित की गई हों।

जब तौहीनवाली बातें कही गई हों या, खाली उन बातों (शब्दों) के ऊपर ही मामला न चलाया जा सकता हो तो, उस समय जब वह हानि पहुँची हो जिसकी निस्वत शिकायत की गई है।

नालिश की किस्म	मियादकी मुदत	मियाद कब से शुरू होगी
२६ उस नौकरी के चले जाने की निस्वत, जो कि मुद्दई के बहकावे में आजाने के कारण छूट गई हो, मुआविज़ा की नालिश ।	एक साल	जिस समय नौकरी जाती रही हो ।
२७ किसी शख्स को यह सलाह देने के लिए, कि वह मुद्दई के साथ में किए गए मुआहिदे को तोड़ दे, मुआविज़ा की बाबत नालिश ।	"	जिस समय मुआहिदा तोड़ दिया गया हो ।
२८ किसी गैर-कानूनी, बेकायदा जायदाद कुर्की की निस्वत मुआविज़ा की नालिश ।	"	कुर्की होनेकी तारीख़ से ।
२९ किसी कानूनी हुक्मनामा के अनुसार जायदाद मनकूला की बेज़ा गिरफ्तारी (Wrongful seizure) की बाबत मुआविज़ा की नालिश ।	"	गिरफ्तारी जायदादकी तारीख़ से ।
३० माल को खी देने या हुकसान पहुंचा देने की निस्वत हर्जोंकी बाबत किसी मालके लेजाने वाले (जहाज़, रेल आदि) के विरुद्ध नालिश ।	"	जिस समय माल खोगया हो या उसको कोई हुकसान पहुंचा हो ।
३१ माल की हवालगी न करने या हवालगी में देर करने के लिए हर्जों की बाबत किसी माल ले जाने वाले (जहाज़, रेल आदि) के विरुद्ध नालिश ।	"	जिस तारीख़को माल हवाले किया जाना चाहिय था ।

भाग ५ दो साल दो साल

३२ उस शकुल के विरुद्ध की जाने वाली नालिश, जिसने किसी जायदाद को किसी ब्राह्मण काम के लिए इस्तेमाल किए जाने का हक रखते हुए उसे किसी दूसरे कामके लिए इस्तेमाल कर लिया हो ।

३३ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स सूट्स ऐक्ट सन् १८५५ ई० के अनुसार किसी तामील कुनिन्दा के विरुद्ध की जाने वाली नालिश ।

३४ उसी ऐक्ट के अनुसार किसी प्रवन्धकर्ता के विरुद्ध की जाने वाली नालिश ।

३५ उसी ऐक्ट के अनुसार किसी दूसरे प्रतिनिधि के विरुद्ध ।

३६ किसी फ़ैल बेजा या नालायज़ के करने या किसी फ़ैल के न करने के, जिसका सुभाहिदा से कोई भी सम्बन्ध नहीं है, और जिसके लिये इस परिशिष्ट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, सुभाविज़ा की बाबत नालिश ।

३७ किसी मार्ग अथवा जल-मार्ग को रोकने के सुभाविज़ा की बाबत नालिश ।

भाग ६ तीन साल तीन साल

जिस समय उस शकुलको, जिसे इस बातसे नुकसान पहुँचा है, यह बात पहिले पहल माख्म हुई हो ।

जिस समय वह बेजा कारंवाई की गई हो जिसकी निश्चय शिकायत की गई है ।

जिस समय वह हरकत-बेजा की गई हो जिसकी निश्चय शिकायत है ।

”

जिस समय वह फ़ैल बेजा, या फ़ैल नालायज़ किया गया हो या कोई फ़ैल किया गया हो ।

जिस घाटीको रुकावट डाली गई हो ।

”

”

”

”

नालिश की क्रिस्म

- ३८ किसी जल-मार्ग के बदलने के लिए सुआविज़ा की बाबत नालिश ।
- ३९ जायदाद गैर-मनकूला के ऊपर मदाखिलत बेज़ा करने के लिए सुआविज़ा की बाबत नालिश ।
- ४० लेखन सम्बन्धी अधिकार (Copy-right) अथवा किसी दूसरे विशिष्टधिकार (Exclusive Privilege) में बाधा डालने के लिए सुआविज़ा की बाबत नालिश ।
- ४१ किसी चीज़ को बिगाड़ने या नष्ट करने से रोकने के लिए नालिश ।
- ४२ उस दुकसान के सुआविज़ा की बाबत नालिश जो किसी ऐसे हुकम इस्तनाई की वजह से हुआ हो जो बेजा तौरसे हासिल किया गया है ।
- ४३ भारतीय उत्तराधिकार ऐक्ट सन् १८६५ ई० की दफा ३२० या दफा ३२१ के अनुसार, या प्रोवेट ऐण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट सन् १८८१ ई० की दफा १३९ या दफा १४० के अनुसार किसी ऐसे शर्त का जिसे किसी तामील कुनिन्दा (वसी) या प्रबन्धकर्ता (सुदतमिम) ने वसीयती माल अदा किया हो या जायदाद तकसीम की हो, उसके फेर देने के लिए मजबूर किए जाने के वाले दापर की जाने वाली नालिश ।

भियादकी सुदत

तीन साल

"

"

"

"

"

भियाद कब से शुरू होगी

जिस तारीख को जल-मार्गकी दिशा बदली गई हो ।

मदाखिलत बेजा करनेकी तारीख से ।

जिस तारीख को ऐसे अधिकारमें बाधा डाली गयी हो ।

जिस रूपरे से उस चीज़का बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना शुरू हो ।

जिस समय हुकम इस्तनाई ख़तम होता हो ।

अदायगी या तकसीमकी तारीख से

४४ किसी नागालिश की ओर से, जो कि अब बालिश दोनया है, उस बय की मसूखी के लिए नालिश जो उसके बली ने की है ।

४५ बंगाल कोड के नीचे लिखे किसी भी रेगुलेशन के अनुसार दिये गये फंसले की मसूखी के लिए दायर की गई नालिश ।

दि बंगाल लैण्ड रेव्यून्सू सेटिलमेंट रेगुलेशन सन् १८२३ ई०
दि बंगाल लैण्ड रेव्यून्सू सेटिलमेंट रेगुलेशन सन् १८२५ ई०
दि बंगाल लैण्ड रेव्यून्सू (सेटिलमेंट ऐण्ड डिपुटी कलेक्टर) रेगुलेशन सन् १८३३ ई०

४६ किसी फरीक की ओर से, जिसपर उस फंसले का मानना लाजिमी है, उस जायदाद को वापस दिला पाने की बात नालिश जो कि उस फंसले में बतलाई गई है ।

४७ किसी ऐसे शख्स की ओर से, जिसपर उस हुकम का मानना लाजिमी है जो किसी जायदाद गैर-मनकूला के कब्जा के सम्बन्ध में जाबता फौजदारी सन् १८९८ ई० या मामलदास काटस ऐक्ट सन् १९०६ ई० के अनुसार दिया गया हो, या किसी ऐसे शख्स की ओर से जो उसके जरिये से दवेदार है, उस जायदाद को दिला पाने की बात नालिश जो उस हुकम में बतलाई गई है ।

नालिश की किस्म

मियादकी
मुदत

मियाद कब से शुरू होगी

४८ जायदाद मनकूला खास के लिए, जोकि खो गया है या चोरी (सफा) से या बददयानती से तस्करफ बेजा करके या उसका बयनामा मुत्तकिल कराके हासिल कीगई है, या बेजा तौर से उसके रख लेने या शेक रखने के मुआविजा के लिए नालिश ।

४९ जायदाद मनकूला खास के लिए या उसके बेजा तौरसे ले लेने या तुकुसान पहुँचाने या बेजा तौर से उसके शेक रखने के मुआविजा के लिए नालिश ।

५० जानवरों, सवारियों, नावों या खानगी सामानके किराये की बाबत नालिश ।

५१ उस रुपये की बाकी की बाबत नालिश जो वास्ते हवाले किए जाने किसी माल के बाबत उसकी कीमत के पेशगी दिया गया हो ।

५२ उस माल की कीमत के लिए नालिश, जो कि बेचा और हवाले किया गया हो, जब कि उस कीमत के अदा करने के लिए किसी खास मुदत का वादा न किया गया हो ।

५३ उस माल की कीमत की बाबत नालिश, जो बेचा और हवाले किया गया हो और जिसकी कीमत की अदायगी किसी एक खास मुदत के खतम होजाने पर की जाने को हो ।

जिस समय उस शख्सको, जो उस जायदाद पर कब्जा पानेका हकदार है, पहिले पहल यह बात मालूम होजाय कि वह किसके कब्जेमें है ।

जिस समय जायदाद बेजातौरसे ले लीगई हो या जिस समय उसको रोक रखनेवालेका कब्जा नानायज होजाय ।

जिस समय किराया वालिबुल अदा हुआ हो ।

जिस समय वह माल हवाले किया जाना चाहिये था ।

जिस तारीखको माल हवाले किया गया हो ।

जिस समय वादेकी मुदत खतम हो जाय ।

५४ उस माल की कीमत की बाबत नालिश, जो धन्य और हवाले किया गया हो और जिसकी कीमत बजरिये बिल आफ़ सुसवेज (हुण्टी), के की जाने को हो परन्तु ऐसा बिल दिया न गया हो ।

५५ पेड़ों या खड़ी हुई फसल की, जो कि मुद्दई ने मुद्दा-अलेह के हाथ बेचा है, कीमत की बाबत नालिश, जबकि कीमत की अदायगी का किसी खास मुद्दत के लिए वादा न किया गया हो ।

५६ उस काम की उजरत के लिए नालिश, जो कि मुद्दई ने मुद्दाअलेह के लिए उसके कहने पर किया हो, जब कि इस उजरत की अदायगी के लिए कोई खास मुद्दत मुक़रर नहीं की गई हो ।

५७ कर्ज़ दिए गए रुपये की बाबत अदा किए जाने वाले रुपये के लिए नालिश ।

५८ इसी प्रकार की नालिश, जब कि महाजन ने रुपये की ध्वंज में बेक दिया हो ।

५९ उस रुपये के लिए नालिश जो इस इकरारनामा के ऊपर कर्ज़ दिया गया हो कि वह किसी समय मांगे जाने पर अदा कर दिया जायगा ।

६० उस रुपये के लिए नालिश जो इस इकरारनामा के ऊपर

जिस समय तलब पाया क्रिये नये बिल (हुण्टी) की मियाद गुज़र जाय ।

जिस समय वे चीज़ें बेची गई हों ।

जिस समय कि काम किया गया हो ।

जिस समय कर्ज़ दिया गया हो ।

जिस समय चेकका रुपया अदा किया गया हो ।

जिस समय रुपया कर्ज़ दिया गया हो ।

जिस समय रुपया तलब (मांगा) किया जाय ।

नालिश की किस्म	भियादकी मुद्दत	भियाद कब से शुरू होगी
जमा किया गया हो कि किसी भी समय मांगे जाने पर अदा कर दिया जायगा। इसमें किसी शख्स का वह रुपया भी शामिल है जो उसके महाजन के हाथ में हो और इस तरह अदा किए जाने को हो।	तीन साल	जिस समय रुपया अदा किया गया हो।
६१ उस रुपये के लिए नालिश जो मुद्दई को बाबत उस रुपये के वाजिबुल अदा है जो उसने मुद्दाभलेह के लिए अदा किया है।	"	जिस समय रुपया मिला है।
६२ उस रुपये के लिए नालिश जो मुद्दाभलेह की ओर से मुद्दाभलेह की बाबत उस रुपये के अदा किया जाना चाहिए जो मुद्दाभलेह को मुद्दई के काम के लिए मिला है।	"	जिस समय न्याज (सुद) का रुपया वाजिबुल अदा हो।
६३ उस रुपये के लिए नालिश जो बाबत सुद उस रुपये के वाजिबुल अदा है जो मुद्दई का मुद्दाभलेह के ऊपर वाजिब है।	"	जिस समय कि हिसाब लिखा जाय और उस पर मुद्दाभलेह के या उसके मुद्दतारके, जिसे इस सम्बन्धमें वा ज्ञाता अधिकार दिया गया है, दस्तखत हुए हों, सिवा उस हालतमें जबकि इस कृष्ण के साथ साथ यह लिखित इकरारनामा हुआ हो कि रुपया आगे चलकर किसी समय अदा किया जायगा, जिस दशामें कि भियाद उस समय से शुरू होगी जब वह समय आजाय।
६४ उस रुपये के लिए नालिश जो मुद्दई को उस रुपये की बाबत वाजिबुल अदा है जो मुद्दाभलेह से मुद्दई को बाबत उस हिसाब-किताब के वाजिब है जो उनके दर्मियान में चल रहा है।	"	

२५ किसी ऐसे वादा के लोके दिए जाने के लिए उद्भावित
की बाबत नालिश जो किसी नियत समय पर या किसी विशेष
घटना के हो जाने पर किसी काम के करने के लिए किया
गया हो ।

६६ किसी सादे तमस्सुक के लिए जब कि रुपये की अदा-
यगी के लिए कोई खास दिन नियत कर दिया गया हो ।

६७ किसी तनहा तमस्सुक की बाबत नालिश, जब कि कोई
नियत तारीख लिखी न गई हो ।

६८ किसी ऐसे तमस्सुक की बाबत नालिश जब कि उसमें
कुछ शर्तों का जिक्र है ।

६९ किसी ऐसी हुण्डी (बिल आफ एक्स चेन्ज या प्राप्ति-
सरी नोट) की बाबत नालिश जिस हुण्डी या नोट का रुपया
मिती पड़ने के बाद किसी नियत समय के भीतर वाजिबुल
अदा हो ।

७० उस हुण्डी की बाबत नालिश जिसका रुपया उसके
देखते ही या देखने के बाद वाजिबुल अदा हो, किसी नियत
समय पर नहीं ।

७१ उस हुण्डी (बिल) की बाबत नालिश जिसका रुपया
किसी खास जगह पर अदा करने का वादा कर लिया गया
हो ।

जिस समय यह नियत समय आनाय या यह घटना
होजाय ।

जो दिन इस कामके लिए नियत किया गया है ।

जिस तारीख को उस तमस्सुककी तकमोल की
गई हो ।

जिस समय शर्त तोड़ी गई हो ।

जिस समय उस हुण्डी या नोटका रुपया वाजिबुल
अदा हो ।

जिस समय वह हुण्डी पेश कीगई हो ।

जिस समय वह हुण्डी उस जगहपर पेश कीजाय ।

नालिश की किस्म	मियादकी मुदत	मियाद कब से शुरू होगी
७२ उस हुण्डी (बिल आफ एक्सचेंज) या प्रामिसरी नोट की बाबत नालिश जो देखने के बाद या तलब किए जाने के बाद किसी नियत समय पर वाजिबुल अदा हो ।	तीन साल	जिस समय वह नियत समय बीत गया हो ।
७३ उस हुण्डी (बिल आफ एक्सचेंज) या प्रामिसरी नोट की बाबत नालिश जिसका रुपया किसी भी समय तलब किए जाने पर वाजिबुल अदा हो और जिसमें कोई ऐसी तहरीर न हो जो नालिश करने के हक को रोकती हो या मुद्दतबी करती हो ।	”	हुण्डी या नोटकी तारीख से ।
७४ ऐसे प्रामिसरी नोट या तमस्सुक की बाबत नालिश जिसका रुपया क्रिस्तवार वाजिबुल अदा हो ।	”	उस हिस्से के सम्बन्धमें जो उस समय वाजिबुल अदा हो, पहिली मियाद के गुजर जानेकी तारीख से; और दूसरे हिस्सोंके सम्बन्धमें उसकी अदायगी की मियाद गुजर जानेकी तारीख से ।
७५ ऐसे प्रामिसरी नोट या तमस्सुक की बाबत नालिश जिसका रुपया क्रिस्तवार वाजिबुल अदा हो और जिसमें यह शर्त हो कि अगर एक अथवा अधिक क्रिस्तें समय पर अदा न की गईं तो कुल रुपया एक साथ वाजिबुल अदा हो जायगा ।	”	जिस समय पहिली बारकी क्रिस्त अदा न हो, सिवाय उस दशा में जब कि रुपया पाने वाला दोनों इस शर्त से फायदा उठाना न चाहते हों, जिस दशा में कि मियाद उस समय से शुरू होगी, जब फिर ऐसी कोई क्रिस्त अदा न हो और उसकी क्रिस्त इस शर्त से फायदा उठाने से दस्तबरदारी न कर दी गई हो ।

७६ देखे प्रामिसरी नोट की बाबत नालिश जिससे उसके तह-
शीर करने वाले ने किसी तीसरे शख्स को इसलिए दिया हो
कि वह रुपया पाने वाले (Payee) को किसी खास घटना
के होजाने पर हवाले कर दिया जाय ।

७७ किसी विदेश को ऐसी हुण्डी (बिल) की बाबत नालि-
श जो जो बिना पटाए फिरती कर दीगई हो, जबकि इसके न निप-
टने की तस्दीक की गई हो और इसकी नोटिस (इत्तला) दे
दीगई हो ।

७८ किसी हुण्डी का रुपया पाने वाले की ओर से उस
शख्स के ऊपर नालिश जिसने वह हुण्डी लिखी है जो सकारी
न जाकर फिरता कर दी गई है ।

७९ किसी कर्ज की हुण्डी को सकारने वाले की ओर से
उस शख्स के ऊपर नालिश जिसने वह हुण्डी लिखी है ।

८० किसी ऐसी हुण्डी बिल आफ एक्सचेन्ज, प्रामिसरी नोट
या तमस्तुक की बाबत नालिश जिसके सम्बन्धमें इस परिशिष्ट
में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है ।

८१ किसी जमानतदार की ओर से असली कर्जदार (कृणी)
के ऊपर नालिश ।

८२ किसी जमानतदार की ओर से शरीकदार जमानतदार
के ऊपर नालिश ।

जिस समय वह नोट रुपया पाने वाले को हवाले
किया गया हो ।

जिस समय नोटिस (इत्तला) दीगई हो ।

सकारने से इन्कार कर देने की तारीख से ।

जिस समय हुण्डी सकारने वाला उस हुण्डी की
कुल रकम चुकता कर दे ।

जिस समय उस हुण्डी, नोट या तमस्तुक का रुपया
वाजिबुल अदा हो जाय ।

जिस समय जमानतदार ने महाजन को रुपया अदा
कर दिया हो ।

जिस समय जमानतदार अपने हिस्से से अधिक
(जायद) कोई रकम अदा कर दे ।

नालिश की किसम

मियाद की मुदत

मिबाद कब से शुरू होगी

८३ हांनि पूर्ति कर देने के लिए किए गए किसी मुआहिदा की बाबत नालिश ।

८४ किसी मुक़तार या वकील की ओर से किसी मुक़दमा या किसी ख़ास काम की बाबत ख़र्च के लिए नालिश, जबकि उस समय के सम्बन्ध में कोई ख़ास इक़्रार न किया गया हो कि रुपया किस समय भदा किया जाय ।

८५ किसी खुले हुए और चलते बाहिमी हिसाब-किताब की निस्वत बकाया की बाबत नालिश ।

८६ किसी बीमा की पालिसी की बाबत नालिश, जब कि बीमा की रक़म, बीमा करने वाले को मौत या मुक़सान का मुबूत दे दिए जाने या उसके मंज़ूर कर दिए जाने के फ़ौरन् बाद, बाजिबुल भदा हो ।

८७ बीमा कराने वाले की ओर से बीमा का वह रुपया वापस पाने की बाबत नालिश, जो उस पालिसी (दस्तावेज़ बीमा) के अनुसार भदा किया गया हो जो बीमा करने वाले की मर्ज़ी पर किए जाने के काबिल हो ।

जिस समय मुदई ने वास्तव में हांनि की पूर्ति की हो ।

मुक़दमें या उस काम के ख़तम हो जाने पर या (जब उस मुक़तार या वकील ने मुक़दमा या काम की पैरवी करना बन्द कर दिया हो तो) इस बन्द करने की तारीख़ से ।

उस साल के बन्द हो जाने पर जिस साल में कि तस्लीम की हुई या साबित की हुई अख़ीर रक़म हिसाब में दर्ज़ है; उस साल का शुमार उसी तरह पर होगा जैसा कि उस हिसाब में हो ।

जिस समय मौत या मुक़सान का मुबूत बीमा करने वाले को दे दिया गया हो या उसने मंज़ूर कर लिया हो, चाहे यह मुबूत मुदई ने दिया हो या किसी दूसरे साहब ने ।

जिस समय बीमा करने वाले ने पालिसी (दस्तावेज़) बीमा को रद करना चाहा हो ।

८९ मालिक की ओर से अपने गुमास्ता के ऊपर उस जाय-दाद मनकूला की बाबत नालिश जो गुमास्ता ने पाई है लेकिन जिसका हिसाब उसने नहीं दिया है ।

९० दूसरी नालिशें जो मालिकों की ओर से अपने गुमास्तों के ऊपर काम में असावधानी करने या अनुचित व्यवहार करने के लिए दायर की गई हैं ।

९१ ऐसे दस्तावेज की मंजूरी या रद्द किए जाने की बाबत नालिश जिसके लिए और कोई व्यवस्था न की गई हो ।

९२ किसी ऐसे दस्तावेज के जाली करार दिए जाने के लिए नालिश जो जारी किया गया हो या जिसकी रजिस्ट्री कराई गई हो ।

९३ किसी ऐसे दस्तावेज को जाली करार देने के लिए नालिश जिसको मुद्दई के विरुद्ध अमल में लाने के लिए प्रयत्न किया गया हो ।

जिस समय, दौरान गुमास्तागरी में, हिसाब तलब किया गया हो और उसके देने से इन्कार कर दी गई हो, या जब हिसाब के लिए कोई तलबी न की गई हो तो, उस समय जब कि गुमास्तागरी खतम हो ।

जिस समय, दौरान गुमास्तागरी में, हिसाब तलब किया गया हो और उसके देने से इन्कार कर दी गई हो, या जब हिसाब के लिए कोई तलबी न की गई हो तो, उस समय जब कि गुमास्तागरी खतम हुई हो ।

जिस समय इस असावधानी या अनुचित व्यवहार का पता मुद्दई को चले ।

जिस समय वे बातें, जिनके कारण मुद्दई को उस दस्तावेज के मंसूख करने या रद्द करने का अधिकार प्राप्त होता है, मुद्दई को मालूम हुई हों ।

जिस समय दस्तावेजके जारी किए जाने या रजिस्ट्री कराय जाने की बात मुद्दई को मालूम हुई हो ।

जिस तारीख को ऐसी कोशिश की गई हो ।

नालिश की किस्म	मियादकी मुदत	मियाद कब से शुरू होगी
१४ उस जायदाद के लिए नालिश जो मुद्दई ने पागलपने की हालत में मुन्तकिल की हो ।	तीन साल	जिस तारीख को मुद्दई का होश हवास सही हुआ हो और उसको उस मुन्तकिली का पता लगा हो ।
१५ फ़रैब से हासिल की गई किसी डिकरी की मसूखी या फ़रैब की बिना पर किसी दूसरी दादरसी के लिए नालिश ।	”	जिस समय उस शख्स को, जिसको तुकसान पडुंवा है, इस फ़रैब की ख़बर मिली हो ।
१६ ग़लती की बिना पर दादरसी के लिए नालिश ।	”	जिस समय मुद्दई को ग़लती का पता चला हो ।
१७ उस रुपये के लिए नालिश जो मौजूदा बात के मुआ-विज़ा में अदा किया गया हो जो बात बाद में बिगड़ जाय ।	”	उस बात की बिगड़ जाने की तारीख से ।
१८ किसी मुतौफ़ी ट्रस्टी की आम जायदाद में से तुकसान बरा करने की बात नालिश, जिस समय कि यह तुकसान उस ट्रस्टी की ख़यानत से हुआ हो ।	”	ट्रस्टी की मौत की तारीख से, या, जब उस तारीख को तुकसान न हुआ हो तो, उस तारीख से जिस तारीख को कि तुकसान हुआ हो ।
१९ किसी ऐसे शख्स की ओर से, जिसने किसी मुश्तरका डिकरी की निस्वत वालिब रकम में से कुछ या अपने हिस्से से ज्यादा रकम अदा कर दी है, या किसी मुश्तरका जायदाद के हिस्सेदार की ओर से, जिसने उस मालगुजारी की, जो उससे और उसके हिस्सेदारों से वाजिबुल वसूल थी, कुछ या अपने हिस्से से ज्यादा रकम अदा कर दी है, रकम की वसूलयाबी के लिए दरगर की जाने वाली नालिश ।	”	जिस तारीख को मुद्दई ने अपने हिस्से से ज्यादा रकम अदा की हो ।

१०० किसी शरीरकदार इस्ती की ओर से किसी इस्तीकी इस्ती की जायदाद के ऊपर, वास्ते दिलापाने अपने हिस्से के नालिश ।

१०१ किसी मल्लाहे की उजरत (मजदूरी) की बाबत नालिश ।

१०२ उस उजरत (मजदूरी) की बाबत नालिश जिसके लिए इस परिशिष्ट में कोई अन्य विशेष व्यवस्था नहीं की गई है ।

१०३ किसी सुसलमान की ओर से मेह-सुअज्जल (Exigible dower) की बाबत नालिश ।

१०४ किसी सुसलमान की ओर से मेहर-सुअजल (Deferred dower) की बाबत नालिश ।

१०५ रेहननामा का मतालबा बेबाक हो जाने के बाद, राहिन की ओर से उस वासिलात की रकम की बाबत नालिश जो मुर्तेहिन ने जायदाद वसूल की है ।

१०६ किसी तोड़ दी गई साझेदारी (Dissolved Partner-ship) के हिसाब और उसके मुनाफा के हिस्से के लिए नालिश ।

जिस समय हिस्सा रखदी दिला पाने का हक वेदा हुआ हो ।

जिस समय वह समुद्र-यात्रा समाप्त हो जिसमें यह मजदूरी की गई है ।

जिस समय वह उजरत (मजदूरी) वाजिबुल अदा हुई हो ।

जिस समय मेहर तलब किया जाय था उससे इन्कार कर दी जाय या (जब अजदवाज कायम रहने के दौरान में ऐसा कोई मताहिबा नहीं किया गया है तो) जिस समय मौत या तलाक की वजह से वैवाहिक बन्धन (आजदवाज) नष्ट हो जाय ।

जिस समय मौत या तलाक की वजह से वैवाहिक बन्धन (अजदवाज) नष्ट हो जाय ।

जिस समय राहिन जायदाद मरहूना पर फिर दखल कर ले ।

जिस तारीख को वह साझेदारी टूटी है ।

नालिश की किस्म	मियादकी सुदत	मियाद कबसे शुरू होगी
१०७ किसी स मिहित कुटुम्ब (खान्दान सुतरका) को स मिहित सम्पत्ति जायदाद सुदतरका के भेनेजर की ओर से उस हिस्से रसदी की बाबत नालिश जौ, उसने जायदाद के हिसाब में भदा किया हो।	तीन साल	जिस तारीख़ को वह रकम भदा कीगई हो।
१०८ पट्टा देने वाले की ओर से उन पेढ़ों की मालियत की बाबत नालिश जिन्हें पट्टेदार ने पट्टा की शर्तों के ख़िलाफ़ काट डाला है।	"	जिस समय पेड़ काट डाले गए हों।
१०९ सुदई की जायदाद गैर-मनकूला के उस मुनाफ़ा की बाबत नालिश जौ बेजा तौर से वसूल कर लिया है।	"	जिस समय मुनाफ़ा वसूल किया गया हो।
११० बकाया लगान की बाबत नालिश।	"	जिस समय बकाया वाजिबुल वसूल हुई हो।
१११ जायदाद गैर-मनकूला के फ़रोख़्त कुनिन्दा की ओर से उस ख़रीद रक़म के मतालिबा की बाबत नालिश जौ रक़म कि भदा नहीं कीगई है।	"	उस समय से जौ बय की तकमील के लिए निश्चित किया गया है या (जब कि तकमील के लिए निश्चित समय के बाद दस्तावेज़ तस्लीम कीगई हो) तस्लीम की तारीख़ से।
११२ किसी पार्लिमेंट के कानून या ऐक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड कम्पनी की ओर से रुपये की तलबी की बाबत नालिश।	"	जिस समय तलबी का रुपया वाजिबुल भदा हो।
११३ किसी मुआहिदे की तामील ब्यास के लिए नालिश।	"	उस तारीख़ से जौ ऐसी तामील के लिए मुक़रर है

११४ किसी मुआहिदे के रद्द किए जाने के लिए नालिश ।

११५ किसी मुआहिदा की, जो प्रकट हो अथवा अप्रकट, और लिखित या रजिस्ट्रीशुद्धः नहीं है, खिलाफ वर्जों करने के मुआबिजा की बाबत नालिश ।

११६ किसी लिखित और रजिस्ट्रीशुद्धः मुआहिदा की खिलाफ वर्जों की बाबत मुआबिजा के लिए नालिश

११७ किसी विदेश के फ़ैसले (Foreign Judgement) के जिसकी परिभाषा, ज़ावता दीवानी सन् १९०८ ई० में की गई है, बाबत नालिश ।

११८ इस बात का एलान किए जाने के लिए नालिश कि बतलाया गया दत्तक नाजायज़ है या वास्तवमें वह हुआही नहीं ।

११९ इस बात का एलान किए जाने के लिए नालिश कि अमुक दत्तक (गोद) लिया जाना जायज़ है ।

भाग ७ छः साल

छः साल

या, अगर ऐसी कोई सारीख़ सुक़रर नहीं की गई है, तो, जिस समय मुद्दई को इस बात की नोटिस (हतका) मिले कि तामील करने से इन्कार कर दी गई है ।

जिस समय वे बातें जिनसे मुद्दई उस मुआहिदा को रद्द करा पाने का हक़दार होता है, उसे पहिले पहलू मालूम हुई हों ।

जिस समय मुआहिदा तोड़ा गया हो या (जब वह बराबर तोड़ा ही जाता रहा हो तो) उस समय से जब कि वह खिलाफ़ वर्जों की गई हो जिसकी निस्वत नालिश की गई है या (जब खिलाफ़ वर्जों जारी हो तो) उस समय से जब कि वह बन्द हो ।

जिस समय इस नालिश की मियाद समाप्त शुरू होती जो इसी तरह के बिना रजिस्ट्रीशुद्धः मुआहिदा के ऊपर दायर की गई होती ।

फ़ैसले की तारीख़ से

जिस समय इस दत्तक (गोद) लिए जाने की बात मुद्दई को मालूम हुई हो ।

जिस समय दत्तक लिए हुए लड़कें के अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाय ।

नालिशकी किरम

१२० वह नालिश जिसकी मियाद समाप्त के सम्बन्ध में इस परिशिष्ट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

१२१ किसी पूरे इलाके में, जो बकाया मालगुजारी में नीलाम हो, या किसी पतनी तालुक या दूसरी हकीयत काबिल नीलाम में, जो बकाया लगान में नीलाम की जावे, होने वाले बार या हकीयत शिकमी की मंजूरी के लिए नालिश ।

१२२ उस फँसला के सम्बन्ध में, जो ब्रिटिश भारत में दिया गया हो, या मुचलका के लिए नालिश ।

१२३ किसी बसीयती माल या किसी मवसी की जायदाद मतरुका के हिस्से की बावत, या किसी गैर-बसीयती जायदाद के काबिल तकसीम हिस्से की बावत नालिश ।

१२४ किसी मौजूसी जगह (ओहदा) के दिला पाने की बावत नालिश ।

१२५ किसी हिन्दू या मुसलमान औरत के जीवन-काल में, किसी हिन्दू या मुसलमान की ओर से, नालिश दायर किए जाने की तारीख को उस औरत के मरने पर उस आराजी के कन्जे के हकदार होते, ऐसी आराजी के सम्बन्ध में उस औरत द्वारा की गई मुत्तकिली को, नाजायज़ करार दिए जाने

मियाद कबसे शुरू होगी

जिस समय नालिश करनेका अधिकार पैदा हो ।

जिस समय नीलाम कृतई और आखिरी होजाय ।

फँसला या मुचलकाकी तारीखसे ।

जिस समय वह बसीयती माल या हिस्सा वाजिबुल भदा हो या उसका हवाले किया जाना लाज़िमी हो ।

जिस समय मुदागलेहने मुदईके दवाके खिलाफ़ उस जगह पर कब्ज़ा कर लिया हो ।

मुत्तकिलीकी तारीख से ।

मियादकी मुदत

छः साल

भाग ८ १२ साल
बारह साल

”

”

”

”

जिस समय मुन्तकिल अलेह उस जायदाद पर कब्जा करले ।

जिस समय अलग कर दिए जानेकी बात मुहईको मालूम हुई हो ।

जिस समय वह बकाया वाजिबुल् अदा हो ।

जिस समय इस हकको नामजूर किया गया हो ।

जिस समय आराज़ी जवत कर लेने या उस पर लगान बन्दी करने का हक पहिले पहल पैदा हुआ हो ।

जिस समय पहिले पहल मुहईको इस हकसे फ़ायदा उठानेसे रोका गया हो ।

जिस समय वह रुपया, जिसकी निश्चत नालिश कीगई है वाजिबुल वसूल होवे ।

जो विल दहे या जब तक कि वह अपना दूबरा विवाह न कर ले ।

१२६ किसी ऐसे हिन्दू की ओर से, जिसपर मितासरा का कानून लागू होता है, अपने बाप द्वारा कीगई मौखली जायदाद की मुन्तकिली को मंसूख कराने के लिए नालिश ।

१२७ किसी ऐसे शख्स की ओर से, जो सम्मिलित कुटुम्बकी सम्पत्ति (जायदाद खानदान मुश्तरका) से अलग कर दिया गया हो, उस जायदाद में अपने हिस्से की बाबत नालिश ।

१२८ किसी हिन्दू की ओर से गुज़ारा (नान व नक़्फ़ा) की रकम की बकाया की बाबत नालिश ।

१२९ किसी हिन्दू की ओर से गुज़ारा (नान व नक़्फ़ा) के सम्बन्ध में उसका हक़ करार दिए जाने की बाबत नालिश ।

१३० किसी माफ़ी आराज़ी की ज़बती या उसपर लगान बांधे जाने की बाबत नालिश ।

१३१ उस हक़के कायम किए जाने के लिए नालिश जो एक नियत समय के बाद हासिल होता रहता है ।

१३२ उस रुपये के दिलापाने के लिए नालिश जिसका बार किसी जायदाद ग़ैर-मानकूला पर आयद किया गया हो ।

दरहुवास्त की किरम

विवरण—मालिकाना और हक से इस आर्टि० के प्रयोजन के लिए वह रुपया समझा जायगा जिसका बार किसी जायदाद गैर-मनकूला पर डाला गया है।

१३३ उस जायदाद मनकूलाको दिलापानेके लिए नालिश जो बतौर ट्रस्ट (अमानत) के मुन्तकिल करदी गई हो, या वसीयत कर दी गई हो, या गिरवी करदी गई हो तहबीलके तौर पर जमा कर दी गई और बाद में ट्रस्टी, तहबीलदार या गिरवी-दारसे खरीद कर ली गई हो।

१३४ उस जायदाद गैर-मनकूला पर कब्जा दिलापाने के लिए जो बतौर ट्रस्ट मुन्तकिल कर दी गई हो या वसीयत कर दी गई हो या रेहन कर दी गई हो और बादमें ट्रस्टी या मुतंहिन से कुछ रुपया देकर खरीद कर ली गई हो।

१३५ वह नालिश जिसे किसी मुतंहिन ने किसी ऐसी अदालत में, जो शाही फरमान के अनुसार कायम न हुई हो, वास्ते दिलापाने कब्जा जायदाद गैर—मनकूला मरहूना के दायर की हो।

१३६ खानगी बय के खरीदार की ओर से जायदाद गैर-मनकूला पर कब्जा दिलापाने के लिए नालिश जब कि बयकी खरीद की बय करने वाले (फरोकत कुनिन्दा) का कब्जा उस जायदाद पर नहीं था।

मियादकी मुद्दत

बारह साल

”

”

”

मियाद कबसे शुरू होगी

खरीदकी तारीखसे।

”

जिस समय कब्जा करनेके सम्बन्धमें राहिनका हक खतम होता हो।

जिस समय बय करने वालेको कब्जा करनेका हक पहिले पहल पैदा हुआ हो।

१३७ इसी तरह की नालिश उस खरीदार की ओर से जिसने किसी डिकरी की इजरा में होने वाली नीलाम में जायदाद खरीद की हो, जब कि नीलाम की तारीख को मद्दियून-डिकरी का कब्जा उस जायदाद पर न हो ।

१३८ इसी तरह की नालिश उस खरीदार की ओर से, जिसने किसी डिकरी की इजरा में होने वाली नीलाम में जायदाद खरीद की हो, जब कि नीलाम की तारीख को मद्दियून डिकरी का कब्जा उस जायदाद पर हो ।

१३९ किसी जमीन्दार की ओर से किसी आसामी से कब्जा हासिल करने के लिए नालिश

१४० किसी ऐसे शख्स की ओर से, जिसे किसी दूसरे शख्स का हक खतम होने के बाद हकीयत मिलने वाली हो, या किसी वारिस या भावी-वारिस (रिवर्सनर) की ओर से (जो कि जमीन्दार नहीं है) या किसी मौहूबअलेह की ओर से किसी जायदाद गैर-मनकूला के कब्जे की बात नालिश ।

१४१ इसी प्रकार की नालिश किसी ऐसे हिन्दू या मुसलमान की ओर से जो किसी हिन्दू या मुसलमान स्त्री के मर जाने पर जायदाद गैर-मनकूला पर कब्जा दिलापाने का हकदार है ।

१४२ जायदाद गैर-मनकूला पर कब्जा दिलापाने की बात नालिश, जब कि सुद्ध उस जायदाद पर कानिज़ होने की हालत में वेदखल कर दिया गया हो या उसने कब्जा छोड़ दिया हो ।

जिस समय मद्दियून डिकरी को कब्जा करने का हक पहिले पहुँच देदा हुआ हो ।

उस तारीखसे जिस तारीखको कि नीलाम कतई होगया हो ।

जिस तारीखको असामीके देखलकी मियाद खतम होती हो ।

जिस समय उसकी हकीयत पर कब्जा किया जाय ।

जिस समय उस खीकी मृत्यु हो ।

वेदखलकर दिए जाने या कब्जाछोड़ देनेकी तारीखसे

नालिश की किस्म	भियादकी मुदत	भियाद कब से शुरू होगी
१४३ इसी प्रकार की नालिश, जब कि मुद्दई किसी ज़न्ती या किसी शर्तकी पाबन्दी न किए जाने के कारण कब्जे का हकदार हो ।	बारह साल	जिस समय ज़न्ती वाजिब हुई हो या शर्तकी पाबन्दी न की गई हो ।
१४४ किसी जायदाद गैर-मनकूला या उसमें किसी हिस्से पर कब्ज़ा दिलापाने के लिए नालिश, जिसके लिए इस परिशिष्ट में कोई अन्य विशेष व्यवस्था न की गई हो ।	”	जब मुद्दा भलेहने मुद्दई के दावा के खिलाफ कब्ज़ा कर लिया हो ।
१४५ किसी अमानतदार या गिरवीदार के विरुद्ध नालिश वास्ते दिलापाने कब्ज़ा उस जायदाद मनकूला के जो अमानत किया गया है या गिरवी किया गया है ।	भाग १ तीस साल	अमानत या गिरवी तारीख से ।
१४६ उस अदालत के सामने, जो शाही फरमान के अनुसार कायम की गई हो और अपने अदालत दीवानी के साधारण प्रारम्भिक अधिकारों को बरत रही हो, किसी मुतद्दिन की ओर से उस जायदाद गैर-मनकूला पर कब्ज़ा दिलापाने के लिए नालिश जो रैहन की गई है ।	”	जिस समय रैहन के ऊपर दिए गए कर्जे की बाबत असल या सूद (व्याजका) कोई भी हिस्सा अखीरमें अदा किया गया हो ।
१४६ ए—किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी ऐसे सार्वजनिक मार्ग या सड़क या उसके किसी हिस्से पर कब्ज़ा दिलापाने के लिए नालिश जिससे कि वह बेदखल कर दिया गया है या जिसका कब्ज़ा उसने छोड़ दिया है ।	”	बेदखल किए जाने या कब्ज़ा छोड़ देने की तारीख से

कर दिया गया है या जिसका कब्ज़ा उसने छीन लिया है ।

१५७ किसी सुर्तहिन की ओर से बेबाश या मीठान के लिए नालिश ।

१५८ किसी सुर्तहिन के ऊपर वास्तो इन्फ़काक रेहन या दिखाने कब्ज़ा जायदाद ग़ैर-मनकूला मरहूना के नालिश ।

१५९ सपरिषद् भारतमन्त्री द्वारा या उनकी ओर से दायर की जाने वाली नालिश ।

आग १०-साठ साल
साठ साल
”

जिस समय रेहनकी निश्चय दिखाने गया समय वालिशुल् वासल होजाय ।

• जिस समय फ़क़रेहनी या कब्ज़ा वापस दिखाने का हक़ पैदा हुआ हो ।

लेकिन शर्त यह है कि उस फ़क़रेहनीके सम्बन्धमें किए गए दावोंके सम्बन्धमें जो लोअर ब्रह्ममें वाक़े जायदाद ग़ैर मनकूलाके रेहनके ऐसे दस्तावेजके अनुसार पैदा हुए हों, जो तारीख़ पहिली मई सन १८६३ ई० के पहले लिखा गया है, वे नियम लागू होंगे जो उस प्रान्तमें उस तारीख़के ठीक पहिले प्रचलित हैं ।

जिस समयसे इस ऐक्टके अनुसार इसी प्रकारकी किसी दूसरी नालिशकी मियाद समाप्त शुरू होती, जो यदि किसी दूसरे आदमीकी ओरसे दायर कीगई होती ।

(४५)



द्वितीय खण्ड-अपीलें

(४४२)

दरखवास्त की किस्म	भियाद की मुदत	भियाद कबसे शुरू होगी
१५० जाबता फौजदारी सन् १८९८ ई० के अनुसार उस फांसी के हुकम के विरुद्ध की गई नालिश जो किसी अदालत से शन्स ने दिया है ।	सात दिन	हुकमकी तारीखसे
१५१ उस डिकरी या हुकम के विरुद्ध अपील जिसे फोर्ट विलियम, मद्रास और बम्बई की किसी हाईकोर्ट ने या पंजाब की च्चीफ कोर्ट ने या लोअर ब्रह्म की च्चीफकोर्ट ने अपने प्रारम्भिक अधिकारों का प्रयोग करके दिया हो ।	बीस दिन	डिकरी या हुकमकी तारीखसे ।
१५२ संग्रह जाबता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी ज़िला जज की अदालत में दायर की जाने वाली अपील ।	तीस दिन	उस डिकरी या हुकमकी तारीखसे जिसकी अपीलकी गई है ।
१५३ उसी जाबता के अनुसार किसी हाईकोर्ट में किसी मातहत अदालत के उस हुकम के विरुद्ध की जाने वाली अपील जिसके अनुसार उसने सपरिषद श्रीमान् संम्राट् के पास अपील करने की इजाज़त देने से इन्कार कर दी है ।	”	हुकमकी तारीखसे ।
१५४ जाबता फौजदारी सन् १८९८ ई० के अनुसार हाईकोर्ट के अतिरिक्त किसी दूसरी अदालत में की जाने वाली अपील ।	”	उस सज़ाके हुकम या हुकमकी तारीखसे जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

१५५५ अर्ली ज़ाबता (फौजदारी सन् १८९८ ई०)
 के अनुसार किसी हाईकोर्ट में की जाने वाली अपील, सिवाय
 उन अवस्थाओं में जिनके सम्बन्ध में आटि० १५० और आटि०
 १५७ में व्यवस्था कर दी गई है ।

१५६ संग्रह ज़ाबता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार
 किसी हाईकोर्ट में की जाने वाली अपील, सिवाय उन अव-
 स्थाओं में जिनके सम्बन्ध में आटि० १५१ और आटि० १५३ में
 व्यवस्था कर दी गई है ।

१५७ ज़ाबता फौजदारी सन् १८९८ ई० के अनुसार किसी
 रिहाई (Acquittal) के हुक्मके विरुद्ध अपील ।

साठ दिन

नब्बे दिन

छः महीने

अपने दुश्मन के दुश्मन या दुश्मनी सारीखके विरुद्ध
 विरुद्ध अपील की गई है ।

उस डिकरी या हुक्मकी तारीखसे जिसके विरुद्ध
 अपील की गई है ।

उस हुक्मकी तारीखसे जिसके विरुद्ध अपील की गई है

(८८३)

तृतीय खण्ड—दरखास्तें

दरखास्त की किस्म	मियादकी मुदत	मियाद कबसे शुरू होगी
१५८ संग्रह ज़ाबता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी पंचायती फ़ैसला (Award) को रद किए जाने के लिए दरखास्त ।	दस दिन	जिस समय यह फ़ैसला अदालतमें दाखिल किया गया हो और इस बातकी नोटिस फ़रीक़नको दे दी गई हो ।
१५९ उसी ज़ाबते (संग्रह ज़ाबता दीवानी सन् १९०८ ई०) की दफ़ा १२८ (२) (एफ़) में बतलाई हुई सरसरी के ज़ाबता के अनुसार दायर की गई नालिश की जवाब देही करने के लिए हाज़िर होने की इजाज़त हासिल करने के लिए दरखास्त ।	”	सम्मतकी तामील की तारीख़से ।
१६० किसी ज़ाबता के अनुसार, उस नज़रसानी की दरखास्त को बाज़बानम्बर काम करने का, जो उस तारीख़ को, जिसको वह दरखास्त वास्ते समाप्त के लिए तलब की गई थी, सायल के हाज़िर न हो सकने के कारण ख़ारिज कर दी गई थी, हुक्म हासिल करने के लिए दरखास्त ।	पन्द्रह दिन	नज़रसानीकी दरखास्त ख़ारिज होनेकी तारीख़से ।
१६१ उस फ़ैसले की नज़रसानी के लिए दरखास्त जो किसी प्रांतीय अदालत ख़फीफ़ा ने या किसी दूसरी अदालत ने, जिसे प्रांतीय अदालत ख़फीफ़ा के अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिया है ।	”	डिकरी या हुक्मकी तारीख़से ।
१६२ कोई विलियम, मद्रास और बम्बई की किसी भी हाई-कोर्ट द्वारा या पञ्जाब की चोफ़ कोर्ट द्वारा, या लोअर ब्रह्मा की	बीस दिन	डिकरी या हुक्मकी तारीख़से ।

की मरुतीह दार, अपने मातृभक्त दीवानी अधिकारी को काम में लाते हुए, फैसले की नज़रबानी के लिए दरख़वास्त ।

१६३ मुद्दई की ओर से उस डिस्मिसी (Dismissal) को रद्द करने का हुक्म दिए जाने के लिए दरख़वास्त, जो कि हाज़िर न हो सकने की वजह से या सम्मन की तामील का ख़र्चा न देने या खर्चों की ज़मानत न देने की वजह से हुई है ।

१६४ किसी मुद्दाअलेह की ओर से एकतर्फी डिक्करी की मसूखी का हुक्म हासिल किए जाने के लिए दी जाने वाली दरख़वास्त ।

१६५ संग्रह जाबता दीवानी समू १९०८ ई० के अनुसार किसी ऐसे शख्स की ओर से जो किसी जायदाद गैर-मनकूला से बेदख़ल कर दिया गया है और डिक्करीदार या डिक्करी की इजरा में होने वाली नीलाम के ख़रीदार के उस जायदाद पर कब्ज़ा दिलापाने के हक़ पर उज़्रदार हो ।

१६६ उसी जाबता के अनुसार उस नीलाम की मसूखी के लिए जो किसी डिक्करी की इजरा में की गई हो ।

१६७ उस जायदाद गैर-मनकूला पर कब्ज़ा दिलापाने का विरोध किए जाने या उसमें रुकावट डाले जाने के सम्बन्ध में इस्तग़ासा दायर करने के लिए दरख़वास्त, जिसकी निश्चत डिक्करी दी गई है या जो किसी डिक्करी की इजरा में नीलाम की गई है ।

तीस दिन

"

"

"

"

मामला: खारिज या (डिस् मिस) होजानेकी तारीख़ से ।

डिक्करीकी तारीख़से, या जबकि सम्मनकी बाका-यदा तामील न हुई हो तो उस समयसे जबकि सायलको इस बातका पता चला हो ।
बेदख़लीकी तारीख़से ।

नीलामकी तारीख़से ।

विरोध किए जाने या रुकावट डाले जानेकी तारीख़ से

नालिशकी किस्म	भियादकी मुदत	भियाद कबसे शुरू होमी
१६८ किसी अपीलको जो अदम पैरवी में खारिज होगई है, फिरसे मंजूर किए जाने के लिए दरखवास्त	तीस दिन	खारिज होनेकी तारीखसे ।
१६९ किसी ऐसी अपील की नए सिरे से फिर समागत किए जाने के लिए दरखवास्त जिसकी समागत एकतरफी कीगई है ।	"	अपीलकी डिकरीकी तारीखसे या जबकि अपीलकी नोटिस वाफायदा तौर पर तामील न हुई हो तो उस समयसे जबकि सायलको इस डिकरीका पता भिला हो ।
१७० बहैसियत मुफलिस (Paper) अपील करने की इजाजत हासिल करने के लिए दरखवास्त ।	"	उस डिकरीकी तारीखसे जिसकी अपील हुई हो ।
१७१ संग्रह जाबता दीवानी सन् १९०८ ई० के अनुसार किसी सबूत मुकद्दमा (Abatement) के हुक्म की मंसूखी के हुक्म के लिए दरखवास्त	साठ दिन	सुबूत (Abatement) का हुक्म दिए जानेकी तारीख से ।
१७२ उसी जाबता के अनुसार किसी दीवालिया मुद्दई या अपीलाण्ट के मुन्तकिलअलेह या रिसीवर की ओर से किसी नालिश या अपील की डिसमिसी (Dismissal) की मंसूखी के लिए ।	"	डिसमिसी (Dismissal) के हुक्मकी तारीखसे ।
१७३ किसी फंसले की नज़रसानी के लिए दरखवास्त, विवाय उन अवस्थाओं के जिनके सम्बन्ध में आर्टि० १६१ और १६२ में व्यवस्था कीगई है । १७४ दखी जाबते के अनुसार, इस बात की ज़जह जाहिर करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए दरखवास्त कि	नब्बे दिन	डिकरी या हुक्मकी तारीखसे । जिस तारीखको अदायगी या बेबाकी कीगई हो ।

किसी डिकरी की वास्त वाकिङ्क अदा रकम की अपराकस के बाहर कीगई अदायगी या उस डिकरी की कोई बेचाकी तस्दीक की हुई (Certified) क्यों न मानली जाय ।

१७५ किसी डिकरी की रकम किस्तवार अदा किए जाने के लिए दरङ्वास्त ।

१७६ उसी ज़ाबता के अनुसार किसी सुतौफी सुद्दई या सुतौफी अपीलान्ट के कानूनी प्रतिनिधि को फरीक बनाने के लिए ।

१७७ उसी ज़ाबता के अनुसार किसी सुतौफी सुद्दाअलेह या किसी सुतौफी रेस्पान्डेंट के कानूनी प्रतिनिधि को फरीक बनाने के लिए ।

१७८ उसी ज़ाबता के अनुसार, किसी ऐसे मामले में, जो अदालत के हुकम से पंचायत में पेश किया गया है, दिए गए पंचायती फैसले को, या किसी ऐसे मामले में दिए गए पंचायती फैसले को, जो बिना अदालत की इजाज़त पंचायत में पेश किया गया है, दाखिल अदालत करने के लिए दरङ्वास्त ।

१७९ उस शख्स की ओर से, जो उसी ज़ाबते के अनुसार सपरिबद श्रीमान् संम्राट के यहां पर अपील करना चाहता है, अपील करने की इजाज़त हासिल करने के लिए दरङ्वास्त ।

१८० उस जायदाद गैर-मनकूला के खरीदार की ओर से जो डिकरी की इजरा में नीलाम कीगई है, कर्ज़ा दिलापाने के लिए दरङ्वास्त ।

छः महीने

नब्बे दिन

”

छः महीने

नब्बे दिन

तीन साल

डिकरीकी तारीखासे ।

सुतौफी सुद्दई या अपीलान्टकी मौतकी तारीखासे ।

सुतौफी सुद्दाअलेह या रेस्पान्डेंट की मौत की तारीख से ।

पंचायती फसलाकी तारीखासे ।

उस डिकरीकी तारीखसे जिसकी अपील कीगई हो ।

जिस समय नीलाम कतई होजाय ।

<p>दरखवास्त की किरम</p>	<p>मियादकी मुदत</p>	<p>मियाद कबसे शुरू होगी</p>
<p>१८१ ऐसी दरखवास्त जिसके लिए इस परिशिष्ट में और कहीं पर या ज़ाबता दीवानी सन् १९०८ ई० की दफा ४८ में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।</p>	<p>तीन साल</p>	<p>जिस समय दरखवास्त देनेका हक पैदा होता हो।</p>
<p>१८२ किसी अदालत दीवानी की डिकरी या हुकम की इजरा के लिए, जिसके सम्बन्ध में आर्टि० १८३ या ज़ाबता दीवानी सन् १९०८ ई० की दफा ४८ में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।</p>	<p>तीन साल या जब उस डिकरी या हुकम की तस्दीक शुदानकलकी रजिस्ट्री की गई हो तो छह साल</p>	<p>१ डिकरी या हुकमकी तारीखसे, या २ (जब अपील की गई हो तो) अदालत अपीलके हुकम या कतई डिकरीकी तारीखसे या अपीलके वापस लिए जानेकी तारीखसे, या ३ (जब फ़ैसले की नज़र सानी की गई हो तो) नज़र सानीमें दिए गए फ़ैसलेकी तारीखसे, या ४ (जब डिकरी तर्मीम की गई हो तो) तर्मीम की तारीखसे, या</p>
		<p>५ (जब इसके बादमें बतलाई हुई दरखवास्त दी गई हो) कानूनके अनुसार किसी मुनासिब अदालतमें इजरा के लिए या उस डिकरी या हुकमकी इजराके सम्बन्धमें कुछ तदबीर करनेके लिए दी जाने वाली दरखवास्तकी तारीखसे, या ६ (जबकि वह नोटिस, जिसका जिक्र बादमें किया गया है, जारी कर दी गई हो) उस नोटिसकी तारीखसे जो उस शर्शके नाम, जिसके खिलाफ़ इजराकी दर-</p>

जब तक मैं नहीं हूँ। बल्कि बावजूद यज्ञ के कारिणी, कर्माधिक, हिरण्य-
जारी की गई है कि उसके खिलाफ़ डिकरी की इज्जत की
न की जाय, जबकि ऐसी नोटिस का जारी किया जाता
जायता दीवानी खन् १९०८ ई० के अनुसार ज़रूरी हो, या
७ (जबकि दरखास्तकी ऐसी रकमको अदा करा पाने
के लिए दी गई हो जो डिकरी या हुक्मके अनुसार किसी
खास तारीख़ को अदा की जानी चाहिए) ऐसी तारीख़ से

विवरण १—जब डिकरी या हुक्म एक से अधिक
आदमियों के हक में अलग अलग दिया गया हो और
जायदाद भुतनाज़ा की निस्वत यह तफ़्सील लिख दी
गई हो कि हर एक शख्स को इस क़दर माल मिलना
चाहिए या हवाले किया जाना चाहिए, तो इस आर्टि०
के क्लोज़ (५) में बतलाई हुई दरखास्त का फैसला
उक्त आदमियों में से सिर्फ़ उसी शख्स या वन्हीं शख्सों के
या उनके प्रतिनिधियों के हक में होगा जिसकी या
जिनकी ओर से वह दरखास्त दी गई हो। लेकिन जब
वह डिकरी या हुक्म एक से अधिक आदमियों के हक में
एक ही में दिया गया हो, तो ऐसी दरखास्त का फैसला,
अगर वह उनमें से किसी एक या अधिक शख्सों की
ओर से, या उसके अथवा उनके प्रतिनिधियों की ओर से
दी गई हो, उन सब के हक में होगा।

जब वह डिकरी या हुक्म एक से अधिक आदमियों
के विरुद्ध अलग अलग दिया गया हो और उसमें साब-

दरखवास्त की किस्म

मियादकी
सुदत

मियाद कबले शुरू होगी

दाद मुतनाज़ा की निस्वत यह लिख दिया गया हो कि उनमें से हरएक को किस कदर अदा करना चाहिए या हवाले करना चाहिए, तो उस दरखवास्तका फैसला उनमें से उन्हीं शख्सों या उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ होगा जिनके खिलाफ वह दी गई है। लेकिन जब वह डिकरी या हुकम एक से अधिक आदमियों के खिलाफ एक में ही दिया गया है, तो ऐसी दरखवास्त का, अगर वह उनमें से किसी एक अथवा अधिक के खिलाफ अथवा उसके या उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ दी गई है, उन सब के खिलाफ फैसला होगा।

विवरण २—“मुनासिब अदालत” से मतलब उस अदालत से है जिसका यह कर्तव्य (फ़र्ज़) है कि वह किसी डिकरी या हुकम की इजरा करे।

जिस समय उस फैसला, डिकरी या हुकम की इजरा का हक उस शख्स को पैदा होता हो जो उस हक को छोड़ सकता था।

लेकिन शर्त यह है कि जब उस फैसला, डिकरी या हुकम की तजदीद की गई हो या उससे असल के रुपये का कुछ हिस्सा बसूल हुआ हो या उसे रुपये की बाबत कुछ न्याज की रकम अदा की गई हो या इसके हक का लिखित स्वीकृति-पत्र, जिसपर उस शख्स के, जो उसे

१८३ किसी फैसला, डिकरी या हुकम की, जो शाही फ़रमान के अनुसार कायम की गई किसी अदालत ने अपने साधारण प्रारम्भिक दीवानी अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिया हो, या सपरिषद् श्रीमान् सम्राट के हुकम की इजरा के लिए दरखवास्त।

अथ स्वकीय प्रवृत्ति का अर्थ है, या स्वकीय सुखकारक।
दक्षतल्यत हो, उस शालको, जो उसके पानेका इकादार है
या उसके सुखार को दे दिया गया हो, तो बारह सालकी
इस सुदत का शुमार उस तारीख से किया जायगा जिस
तारीख को फैसला, डिक्री या हुकुम की तजदीद की गई
हो या अदायगी की गई हो या स्वीकृति-पत्र दिया गया
हो, या इनमें से सब से आखिरी तजदीद, अदायगी या
स्वीकृति-पत्र दिए जाने की तारीख से, जैसी कुछ भी
अवस्था हो, शुमार की जायगी ।

परिशिष्ट (२)

[देखो दफा ३१]

वे प्रान्त जिनका उल्लेख दफा ३१ में किया गया है

१ फोर्ट सेण्ट जार्ज की प्रेजीडेन्सी.

२ बम्बई प्रेजीडेन्सी

३ फोर्ट विलियम प्रेजीडेन्सी के बंगाल खण्ड का सम्भलपुर का जिला.

४ संयुक्त प्रान्त भागरा ष. भवध.

५ ब्रह्मा

६ मध्य प्रदेश.

७ भजमेर. मेरवाड़.

परिशिष्ट (३)

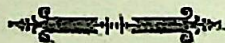
×

×

×

×

मंसूख हो गया.



व्याख्या और नज़ीरें

इण्डियन लिमिटेडेशन ऐक्ट के समझने के लिए नीचे व्याख्या और हाल तक की नज़ीरें दी गई हैं। जहाँ पर दफा का कोई उल्लेख किया गया है वहाँ पर इसी कानून की दफा समझना और देख लेना योग्य होगा।

इण्डियन लिमिटेडेशन ऐक्ट

[नं० ९ सन १९०८ ई०]

अर्थात्

भारतीय कानून मियाद

ऐक्ट नं० ९ सन १९०८ ई०

दफा ३—नालिशें जिनकी मियाद अरिज होगई है—अपीलें अथवा दरखवास्तें उस हालत में अरिज कर दी जा सकती हैं जबकि मियाद की बात न भी पेश की गई हो (दफा ३)

व्याख्या.—कोई फरीक कानून मियाद और कानून मुआहिदा के नियमों के प्रयोग संबन्धी अधिकारों को छोड़ नहीं सकता (देखो 38 M. 374); अगर मियाद का सवाल न उठाने के सम्बन्ध में कोई 'मुआहिदा' किया गया हो, तो वह नाजायज़ होगा, देखो 40 M. 701; 54 I. C. 36. रज़ामन्दी हो जाने से मियाद की मुद्दत न तो बढ़ सकती है और न उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है (देखो 13 W. R. 44 F. B.) और न वह स्थगित की जा सकती है (देखो 40 M. 701)

दफा ३ ताकीदी है और इसलिये चाहे मुद्दा अलेह मियाद के सवाल को न भी उठावे तो भी उसकी तामील जरूर की जानी चाहिये, देखो 34 C. 941 F. B.; 1914 M. W. N. 921. मियाद का सवाल अदालत अपीलमें भी उठाया जा सकता है, अगर वह उस मुकद्दमें में बतलाए गए वाक्यात से पैदा होता है, देखो 12 A. 461 F. B. फरीक को चाहिए कि, अगर बुनियाद अपील में मियाद का सवाल नहीं उठाया गया है तो वह इसके लिए अदालत से इजाज़त हासिल करे; (देखो 43 B. 376; 31 C. L. J. 1; 6 Pat L. J. 444.

दफ़ा ५-मियाद की मुदत का बढ़ाया जाना-कोई अपील या किसी फैसलेकी नज़रसानी अथवा अपील करनेकी इजाजत हासिल करनेके लिए दी गई दर-ख्वास्त या और कोई दरख्वास्त जिसके सम्बन्ध में दफ़ा ५ का प्रयोग हो सकता है, अदालत की मर्जीके ऊपर मियादकी मुदत खतम हो जाने के बाद भी ले ली जा सकती है, अगर इसके लिये काफी वजह दिखलाई जा सके (दफ़ा ५)

व्याख्या—दफ़ा ५ नालिशों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती। वह डिकरीकी इजराके लिए दी जाने वाली दरख्वास्तों के सम्बन्धमें (देखो 44 I. C. 570; 3 P. L. J. 132) ; इजरामें होने वाले नीलाम की मसूखी के लिए (देखो 1919 P. L. R. 29) जाबता दीवानी की दफ़ा ४७ के अनुसार (देखो 23 I.C.240 (C.); आर्डर २२, रूल ४ के अनुसार (देखो 36 A. 235) और किसी पंचायती फैसले को रद्द किये जाने के लिए दी जाने वाली दरख्वास्तों के सम्बन्ध में लागू न होगी।

वह जाबता दीवानीके आर्डर २२, रूल ९ के अनुसार दी जानेवाली (देखो इस रूलका सब क्लज़ ३) ; एक तर्फी डिकरियों की मसूखी के लिए (देखो 45 M. 628.) दी जाने वाली दरख्वास्तों के सम्बन्ध में लागू होती है। मद्रास में आर्डर ९ रूल १३ के साथ सब रूल (२) जोड़ दिया गया है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि कानून मियाद की दफ़ा ५ लागू होती है।

“काफी वजह” प्रत्येक मामलेके अनुसार अलग अलग होगी, देखो 3 C. L. J. 545; 10 C. L. J. 39. वकीलका सख्त बीमार होना और मुबकिलको मियादका ठीक पता न होना काफी वजह है, देखो 9. M. I. A. 26. कानूनकी गलती काफी वजह नहीं है, लेकिन उचित ध्यान और खबरदारी रखते हुए भी गलतीका होजाना, जिससे गलत मामला दायर होजाय और पैरवीवगैरा होजाय काफी वजह है, देखो 45 C. 94; 22 C. W. N. 169 P. C. ; 13 C. 266; 12 A. 461 F. B. ; 35 M. L. J. 51; 13 M. 269. लेकिन यह जरूरी है कि जो गलती हुई हो वह असलियतमें गलती हीहो, बदनीयतीसे ऐसा न किया गया हो और आवश्यक सावधानी और उचित परिश्रमसे काम लिया गया हो, (देखो 45 C. 94 P. C. ; 21 B. 522; 11 A. L. J. 779; 45 I. C. 542; 46 I. C. 509; 39 I. C. 975) । वकीलकी वास्तविक गलती काफी वजह है, देखो 29 A. 638, उदाहरणार्थ मुदतका हिसाब लगानेमें गलती, देखो 12 C. W. N. 25; 17 C. W. N. 807 और 1 A. 250; 46 I. C. 480 (C); किसी गलत अदालतमें अपील या दरख्वास्तका पेश कर देना (देखो 45 I. C. 489 (M.); डिकरीकी नकलका पेश न करना (देखो 17 C. L. J. 66; 85 P. R. 1913. लेकिन जो बात उचित सावधानी रखते हुए और खबरदारीके साथ न की जायगी वह नेकनीयतीके साथ की गई बात न समझी जायगी। किसी फ़रीक या उसके वकीलकी लापरवाही या भूलसे किसी किसी अपीलका गलत अदालतमें दाखिल कर दिया जाना, जो किंचित भी सावधानीसे काम लेने पर सही अदालतमें दाखिलकी जा सकती थी, काफी

बतव नहीं है, देखो 72 I. C. 732 और 45 I. C. 542; 43. I. C. 317; 44 A. 636 P. 639 में यह बतलाया गया है कि मुफ़सिलके वकीलों, प्लीडरों को कानूनी कित्ताबोंके पुस्तकालय न होने और हाईकोर्टके ज़ाबतेसे अनभिज्ञ होनेके कारण बड़ी असुविधा रहती है। लेकिन प्लीडरकी ग़लती ऐसी होनी चाहिए जो बड़े बड़े अनुभवी वकील भी कर सकते हैं [देखो 6 P. L. J. 237; 12 I. C. 677; 12 I. C. 677] इस सम्बन्धमें, कि क्या किसी अपीलकी मियाद धारिज कर देनेके सम्बन्धमें, वकील (प्लीडर) की लापरवाहीके लिए मवकिल नालिश कर सकता है, देखो 28 I. C. 265 (A)।

दफ़ा ६, ७, ८ और ९—अयोग्य (नाक़ाविल नालिश) वगैरा कर सकने के) पुरुषों के लिए मियाद की मुदत का बढ़ाया जाना—जब कोई ऐसा शख्स जिसे किसी नालिश के दायर करने, किसी डिगरी की इजरा के लिए दर्खास्त देने का अधिकार है, विनाय मुखासमत दावा पैदा होने के समय नाबालिग है या पागल अथवा मूर्ख है, तो वह इस अयोग्यता के दूर होजाने के बाद उसी मियाद के अन्दर नालिश कर सकता है जो आम तौर पर दीगई है। अगर उसकी यह अयोग्यता उसके मरने के समय तक बनी रहती तो उसके कानूनी प्रतिनिधियों को, भी यह अधिकार बना रहेगा [देखो दफ़ा ६] बहुतसे मुद्दयों और सायलों में से किसी एक के अयोग्य होने की अवस्थामें क्या व्यवस्था होगी इस सम्बन्ध में देखो दफ़ा ७।

दफ़ा ६ अथवा ७ में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हक-शिफा-की नालिशोंके सम्बन्धमें लागू होती हो या जिसके सम्बन्धमें यह समझा जाय कि वह उस मियादको, जिसके भीतर कोई नालिश दायर की जानी चाहिए या दर्खास्त दी जानी चाहिए, उस शख्सकी, जिसको इससे नुक़सान पहुँचा है, अयोग्यता (नाक़ाबिलियत) दूर होजाने या मृत्यु हो जाने की तारीख़से तीन सालसे अधिक समय तकके लिए बढ़ा सके (दफ़ा ८)

जब एकवार मियाद शुरू होजाय तो बादमें नालिश कर सकने की अयोग्यता या अस्त्रामर्थ्यसे उसमें कोई रुकावट नहीं पड सकती (दफ़ा ९)

व्यख्या—दफ़ा ६ उन व्यक्तियोंको, जो तीन प्रकारसे अयोग्य हों, कुछ व्यक्तिगत विशेष अधिकार प्रदान करती है। और किसीप्रकार की अयोग्यता का ख़याल न किया जायगा (देखो 19 C. W. N. 1193; 46 C. 694 P. C.) यह जरूरी है कि मुद्दई उस समय अयोग्य हो जिस समय कि विनाय मुखासमत दावा पैदा होता है (देखो 27 C. 379; 20 W. R. 2) विनाय मुखासमत दावा जन्म होने के पहिले पैदा हुई हो तो किसी नाबालिगको बालिग होनेपर इस दफ़ासे लाभ उठाने का अधिकार न होगा, देखो 23 W. R. 285; 1 L. 588. चूँकि यह अधिकार व्यक्तिगत है और केवल उसी व्यक्तिसे सम्बन्ध रखता है जिसको कि वह दिया गया है, इसलिए वह किसी नाबालिग के

मुक्तकिल अलेहके सम्बन्धमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है, देखो 9 C. 663 F. B; 42 M. 637; 26 B. 730; 50 I.C. 380; 22 C. W. N. 831. यह दफा नालिश इत्यादिके करनेमें सहायता देनेवाली है और इसलिए किसी शख्सको अयोग्यता दूर होनेसे पहिले नालिश दायर करनेसे रोकती नहीं है देखो 1, C 226. P. C; 9 C. 181; 3 C. W. N. 24; 32 O. 129 P. C; 23 C. 274.

दफा ६ सिर्फ नालिशों और डिकरियों की इजराके लिए दी जाने वाली दख्वास्तोंके सम्बन्धमें और जिनके लिए कानून मियादके परिशिष्ट (१) के तीसरे खानामें मियादकी मुद्दत दी गई है उनके सम्बन्धमें लागू होती है। यह उन मामलोंके सम्बन्धमें लागू नहीं होती जिनके लिए स्थानीय और विशेष कानूनोंमें मियादकी मुद्दत दी गई है, उदाहरणार्थ वह ज़ाबता दीवानीकी दफा ४८ के अनुसार दायर किए जाने वाले किसी मामलेके सम्बन्धमें लागू होती है (देखो 37 M. 186; 24 M. L. J. 96; 37 A. 638; 128 P. R. 1894)

यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि दफा ६ और ७, दफा ८ के अधीन है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी अवस्था में मियाद की मुद्दत अयोग्यता दूर होने की तारीख से तीन साल से अधिक समय के लिए न बढ़ाई जा सकेगी (देखो 24 M. 387 P. C.)। जैसा कि 42 M. 637 और 50 I. C. 380 में बतलाया गया है, दफा ८ ज़िम्मेनी है और उस रिआयत को महदूद करती है जो दफा ६ और ७ में दी गई है और वह ख़ास रिआयत नहीं देती। जब कि साधारण मियाद की मुद्दत तीन साल हो या अधिक और बालिग होने की तारीख से तीन साल के अन्दर वह ख़तम हो जाती हो, तो नाबालिग को अयोग्यता दूर होने की तारीख से पूरे तीन साल मिलते हैं; लेकिन जब यह मुद्दत तीन साल से कम हो और नाबालिग को वह मुद्दत बालिग होने की तारीख से मिलती हो, तो साधारण मियादकी मुद्दत तीन सालतकके लिये न बढ़ाई जानी चाहिए, देखो 17 M. 316. और दफा ८ के उदाहरण। चूंकि दफा ६ एक ऐसी दफा है जो किसी व्यक्तिको नालिश कर सकनेके योग्य बनाती हैं, इसलिए वह मियाद की साधारण मुद्दत को कम नहीं करती। इस प्रकार एक नाबालिग, जो बेदखल कर दिया गया है बेदखल किए जाने की तारीख से १२ बरस के अन्दर नालिश दायर कर सकता है, और नालिश केवल इसी बात से मियाद बाहर न समझी जायगी कि उसने बालिग होनेकी तारीख से तीन साल से ज्यादा समय गुज़र जानेके बाद उसे दायर किया है।

जो समय नक़ल तस्दीक वसीयतनामा (प्रोबेट) के लेनेमें खर्च हुआ है वह दफा ९ के अनुसार, डिकरी की इजरा की मियाद का शुमार करनेमें निकाल नहीं दी जा सकती, देखो 1 Ber. L. J. 192.

अयोग्यता (Dis ability) और असमर्थ (In ability) में क्या भेद है इसके लिए देखिए 25 C. 496 F. B.

दफा १० ट्रस्टियों के ऊपर नालिशें—जो नालिशें ट्रस्टियों के ऊपर उस ट्रस्ट के सम्बन्ध में, किसी खास काम के लिए, या उनके कानूनी प्रतिनिधियों या मुन्तकिल अलेहों के ऊपर (जो कि ऐसे मुन्तकिल अलेह नहीं हैं जिन्होंने रुपया देकर तायदाद मुन्तकिल कराई है) ट्रस्ट की सम्पत्ति या उसकी आमदनी, उनके हाथ से निकाल लेने के लिए या हिसाब-किताब तलब करने के लिए दायर की गई हो, उसकी मियाद किसी भी समय आरिज़ नहीं होती (दफा १७)-

व्याख्या—वे सभी आदमी ट्रस्टी नहीं हैं जिनके पास कोई माल अमानत में जमा किया गया हो। इस तरह पर मुख्तार, कर्ता, या प्रबन्धक, गुमास्ता और बेनामीदार लोग ट्रस्टी नहीं हैं, देखो 4 C. 455; 18 B. 119; 4 M. L. J. 117; 11 W. R. 72; 45 M. 415; 32 C. L. J. 25.-दफार (११) में जो ट्रस्टी की परिभाषा दी गई है उसमें से बेनामीदार खास तौर पर अलग कर दिए गए हैं। दफा १० कम्पनियों के डाइरेक्टरों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती (देखो 18 B. 119; 71 I. C. 899) और न उन लोगों के सम्बन्ध में लागू होती है जिनके पास रुपया जमा किया गया हो, देखो 1 A. L. J. 422; 22 I. C. 936.

तामिल कुनिन्दा (वसी) ट्रस्टी है, सिर्फ उसी हालत में जब कि वह किसी खास काम के लिए ट्रस्टी बनाया गया हो। "वह ट्रस्टी है अथवा नहीं" यह बात प्रत्येक मामले के वाक्यात के ऊपर निर्भर करती है, देखो 11 Bom. L. R. 1187; 13 C. W. N. 557; 30 C. 369. यही बात किसी प्रबन्धकर्ता के सम्बन्ध में भी है, देखो 2 P. L. J. 642.

दफा १० सिर्फ खास ट्रस्टों के सम्बन्ध में ही लागू होती है और वह अप्रकट (Implied) ट्रस्टों के सम्बन्ध में अथवा उन ट्रस्टों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती जो कानून के प्रयोग से पैदा होते हों, देखो 132 P. R. 1907; 31 B. 222; 7 A. 25; 32 B. 394. खास ट्रस्टों के सम्बन्ध में देखो 45 M. 415. यह दफा अयानत ताचीरी (Constructive trusts) के सम्बन्ध में लागू होती है, देखो 2 A. 361; 103 P. R. 1907; 2 A. 476 और 4 C. 455; 45 M. 415. नालिश, ट्रस्ट की सम्पत्ति को वापस पाने के लिए होनी चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारों को पकड़ा ठहराने के लिए नहीं, जैसे ट्रस्ट की सम्पत्ति का प्रबन्ध इत्यादि, देखो 6 A. (P. C.)

"खास काम" के अर्थ के सम्बन्ध में देखो 46 M. 259; 26 C. W. N. 495 P. C.; 30 M. L. T. 160.

दफा १२—सिर्फ मियाद समाप्त की मुदत का गुमार—(१) किसी नालिश अपील या दरखवास्त के सम्बन्ध में वह तारीख, जब से मियाद की मुदत का गुमार किया जाना चाहिए, निकाल दी जायगी। (२) किसी अपील करने की इताज़त हासिल करने और किसी फैसले की नज़रसानी के लिए दरखवास्त के सम्बन्ध में, वह तारीखा, जिसको फैसला दिया गया था और वह समय, जो हिकरी, सज़ा के हुक्म या हुक्म की नक़ल लेने के लिए ज़रूरी है, निकाल दिया

जायगा । (३) जब किसी डिकरी की अपील की गई हो या उसकी नज़रसानी की दख्खीस्त दी गई तो जो समय उस फैसले की नकल लेने के लिए ज़रूरी होगा जिसके आधार पर वह अपील की गई है या नज़रसानी की दख्खीस्त दी गई है वह निकाल दिया जायगा । (४) इसी प्रकार वह समय, भी जो किसी पंचायती फैसले की नकल लेने के लिए ज़रूरी है निकाल दिया जायगा देखो इस पेक्ट की (दफ़ा १२)

दफ़ा २५ के अनुसार कुल दस्तावेज़ों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वे ग्रीगोरियन साल के हिसाब से लिखे गए हैं (दफ़ा २५)

नोट—ग्रीगोरियन साल में ३६६ दिन होते हैं ।

व्याख्या—मियाद का शुमार अंगरेजी साल के हिसाब से किया जाना चाहिए (देखो 13 W. R. 183), यद्यपि किसी तमस्सुक में हिन्दुस्तानी साल के हिसाब से रुपया अदा करने का इक़रार किया गया हो [देखो 6 C. 239; 4 B. 103; 6 B. 83].

कलॉज़ (१) के अनुसार वह दिन, जिसको बिनाय मुखासमत दावा पैदा हुई हो, निकाल दिया जाना चाहिए, देखो 4 M. H. C. R. 109; 10M. 292; 19 W. R. 94; 39 C. 516; 12 B. 617. यह बात परिशिष्ट १ के तंतरे खाना (कालम) के ऊपर लिखे हुए “मियाद कब से शुरू होगी” शब्दों से और भी स्पष्ट हो जाती है । किसी अंगरेजी महीना या साल का शुमार करने में एक महीने या सालसेउसी दूसरे महीने या सालतक शुमारकर जाना चाहिए और इसमें गणना करते समय वह दिन निकाल देना चाहिए जिस दिन से उस महीने और साल का शुमार किया जाता है, इसलिए एक ही तारीख के दो दिन उसमें शामिल नहीं होते हैं, देखो 13 C. L. R. 153-154; 6 C. 325.

किसी दस्तावेज़ में कर्ज़ का रुपया अदा कर देने के लिए जो दिननियत है वह निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि सम्भव है कि रुपये की अदायगी उस दिन अख़ीर तक कर दी जाय । नालिश करने का हक उस दिन नहीं बल्कि उस दिन से पैदा होता है, देखो 4 M. H. C. R. 330; 24 W. P. 463; 10M. 294; 13 C. L. R. 153.

एक रजिस्ट्रीऑद: तमस्सुक की, तारीख २३ दिसम्बर सन् १८६८ ई० लिखी गयी थी, रकम “एक साल के अन्दर किसी समय वाजिबुल अदा थी ।” आख़िरी अदायगी की तारीख २३ दिसम्बर सन् १८६९ ई० थी, इसलिए मुद्दइयान के नालिश करने का हक उस दिन पैदा होता है, अगर रुपया तारीख २२ को अदा न हो । इस २३ तारीख को निकाल कर मुद्दइयान की तारीख २३ दिसम्बर सन् १८७५ ई० को दायर की गई, नालिश अन्दर मियाद के दाख़िल की गई मानी गई, देखो 38 P. R. 1876. जब अदायगी का दिन तमस्सुक में बतला दिया गया हो, तो वह दिन निकाल दिया जाना चाहिए, देखो 24 W. R. 463.

एक तमस्सुक की, जो बैसाख ८ सन् १२८६ को लिखा गया था, अदायगी की तारीख बैत्र ३० सन् १२८६ थी (जो ११ अप्रैल सन् १८८० को है पड़ती है)

और चैत्र ३० सन् १२८६ को छुटी होने के कारण नालिश तारीख १३ अप्रैल सन् १८८३ ई० (बैसाख १ सन् १२९०) को दायर की गई । ऐसी दशामें मियाद का शुमार अंगरेजी साल के हिसाब से किया जाना चाहिए और यह नालिश २९ चैत्र सन् १२८९ तदनुसार तारीख ११ अप्रैल सन् १८८३ ई० को दायर की जानी चाहिए, देखो 13 C. L. R. 153; 29 I. C. 980 (A); 6 B. 83.

जब किसी ऐसे तमस्सुक के ऊपर नालिश दायर की गई हो, जिसकी तक-मोल महीने की किसी तारीख को की गई है और उसकी अदायगी की मुदत दो साल है, तो विनाय मुख्यासमत दावा महीने की उसी तारीख को आकर पैदा होता है जिसको कि उसकी तकमोल की गई थी, देखो 12 B. 617.

जब कि एक तमस्सुक में किसी साल के बंगाली महीने की ३० वीं तारीख रुपये की अदायगी की तारीख नियत की गई (दोनों फरीकैनको उस महीने की संख्या का ठीक ठीक पता नहीं था) तब हुआ कि ऐसी दशा में विनाय मुख्यासमत दावा उसी दिन पैदा होती है जिस दिन वह उस हालत में पैदा होती अगर वह महीना ३० दिनका होता है, देखो 6 C. 239.

प्रोटोके सम्बन्धमें मियाद का शुमार करते समय वह तारीख निकाल दी जानी चाहिए जिस तारीख को उसकी तकमोल की गई थी, देखो 6B.L.R. 292; 16 W. R. 1 तारीख ७ मई सन् १९०७ ई० को लिखे गए एक प्रोटोके सम्बन्धमें नालिश तारीख ९ मई सन् १९१० ई० को दायर की गई । क्योंकि ८ तारीख को इतवार था । तब हुआ कि मियाद तारीख ७ मई सन् १९०७ ई० के खातम हो जाने के बाद से जारी होती है और वह तारीख ७ मई सन् १९१० ई० को १२ बजे रात को खतम हो जाती है, इसलिए नालिश मियाद बाहर दायर की गई है, देखो 18 I.C. 574.

वालिग होने की तारीख भी निकाल दी जानी चाहिए, देखो 10 C. 748.

“ज़रूरी” का अर्थ है क़ानूनन ज़रूरी, देखो 43 M. 644. यह प्रश्न वाक्यात सम्बन्धी है, देखो 6. P. R. 1894. यह ज़रूरी समय कब शुरू होता है यह प्रश्न प्रत्येक अदालतमें प्रचलित प्रथाके अनुसार तय किया जाना चाहिए, देखो 12 C. L. R. 541. “प्रचलित प्रथा” यह है कि नकल की दरखास्त दिए जाने की तारीख और उसके तैयार हो जाने की तारीख के बीच का समय निकाल दिया जाना चाहिए, देखो 12 C. L. R. 541; 7 C. W. N. 109.

नकल लेने के लिए ज़रूरी समय उस समय तक आरम्भ नहीं होता जब तक कि नकल के लिये दरखास्त पेश न कर दी जाय, देखो 12 A. 461; 6 Pat. L. J. 350 F. B.; 23 B. 442; 3 L. B. R. 62.

“वह समय जो नकल लेने के लिये जरूरी है” का अर्थ सिर्फ उस समय से है जो नकल की दरखास्त देने और नकल तैयार हो जाने के बीच में गुजरा

हो। फैसला या डिकरी की सही नकल करने और उसपर दस्तखत करने में जो समय लगा है, वह उस समय तक न काटा जायगा जबतककि उस तारीख के पहिले नकल की दरखास्त न दे दी गई हो, देखो 12 A. 461 F.B.—फैसला देने और डिकरी के ऊपर दस्तखत किए जाने के बीच में जो समय लगा है, वह उसी समय निकाला जायगा, अगर इस डिकरी पर दस्तखत किए जाने की ही वजह से नकल की दरखास्त देने में बिलम्ब हुआ है, और किसी हालत में नहीं, देखो 12A.79—दरखास्त देनेवालेके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह उस समय तक इन्तज़ार करता रहे जब तक कि डिकरी पर दस्तखत न हो जाय। उसको नकल के लिए दरखास्त देने की पूरी स्वतंत्रता है, चाहे उसपर हस्ताक्षर हुए हों या न हुए हों। अगर वह इन्तज़ार करता है और मियाद गुज़र जाती है, तो वह फैसला दिए जाने और डिकरी के ऊपर दस्तखत किए जाने के बीच लगे हुए समय को मुजरा नहीं पासकता, देखो 6 Pat. L. J. 350 F. B.; A.I. R. 1923 Pat. 529; 23 B. 442 तथा 7 N. L. R. 67; 5 S. L. R. 57; 1 P. L. J. 573 F. B.

कलकत्ता में यह तय हुआ है कि जब डिकरी की नकल हासिल करने में समय केवल इस कारण लगा हो कि डिकरी पर दस्तखत नहीं किए गए हैं, तो अपील दायर करने की मियाद का शुमार करने में अपीलाण्ट दफा १२ के अनुसार वह समय मुजरा पाने का हकदार है जो फैसला देने और डिकरी पर दस्तखत किए जाने के बीच में लगा है, देखो 13 C. 104 E. B.—इसी प्रकार उस समय का निकाल देना, जोकि फैसला दिए जाने और डिकरी पर दस्तखत किए जाने के बीच लगा है, इसबात पर निर्भर करता नहीं जान पड़ता कि उसकी नकल की दरखास्त डिकरी पर दस्तखत होने के पहिले दी गई थी या नहीं, देखो 15 C. W. N. 787; 20 C. W. N. 967—परन्तु कलकत्ता हाई कोर्ट के एक हाल के मुकद्दमें में यह तय किया गया था, कि कानून मियाद के आर्टि० १५१ और जाबता दीवानी की दफा २०५ (आर्डर २०, रूल ७) को पढ़ने से यह मालूम होता है कि अपील उस दिन से २० दिन के भीतर दाखिल की जानी चाहिए जिस दिन कि फैसला दिया गया था और यह कि मियाद सम्बन्धी कानून का संशोधन करने के लिए उचित कारण हैं, जिससे इस बीस दिन की मुदत का शुमार उस दिन से किया जाय, जिस दिन कि डिकरी दी गयी थी उस दिन से नहीं जब कि फैसला सुनाया गया था, देखो 10 C. 652; 12 A. 461 F. B.—एक हाल के मुकद्दमें में यह तय हुआ था कि “यह समय जो नकल लेने के लिए जरूरी है” उस समय तक शुरू नहीं होती जब तक कि नकल के लिए दरखास्त न दी गई हो। इसलिए अपीलाण्ट को वह समय मुजरा पाने का हक नहीं है, अगर नकल के लिए दरखास्त उस मुदतके खतम होने के बाद दी गई हो जो अपील करने के लिए मुकद्दर है, देखो 32 C. L. J. 127; 58 I. C. 408; 23 C. W. N. 553; 39 C. 766.

दफा १२ के अनुसार वह मुदत नकल के लिए जरूरी मुदत नहीं समझी जा सकती है जो उस समय न गुज़री होती, अगर अपीलाण्ट ने उस हुक्म की

नकल के लिए आवश्यक सावधानी से और उचित, कार्रवाई की होती। जब उसने फैसला दे दिए जाने के बाद एक सुनासिब मियाद के अन्दर हुकम तैयार करने के लिए दरखास्त न दी हो, और मसविदा तैयार होने के बाद भी उसने उसके लिए अपनी मंजूरी देकर उसे वापस न कर दिया हो, तो वह उस कुल समय की मुजराई के लिए दावा नहीं कर सकता जो उसे नकल लेने में लगा है, देखो 27 C. W. N. 156 P. C.; 68 I. C. 900.

अगर किसी फ्रीक के नकल की दरखास्त देने या उस रुपये के जमा करने में, जो इस काम के लिए जरूरी है, असावधानी करने के कारण देर हुई हो, तो वह समय मुजरा न दिया जायगा, देखो 12 A. 79 F.; B.; 61 P. L. R. 1911. या अगर फोलियो दाखिल करने में असावधानी करने के कारण देर हुई हो तो वह समय भी मुजरा नहीं दिया जायगा, देखो 1 Pat. L. J. 573; 49 I. C. 1000. लेकिन जो समय अदालत के अधिकारियों के देर में नकल देने के कारण लगा हो, वह मुजरा दिया जा सकेगा, देखो 12 A. 105; 10 A. W. N. 10—नकल तैयार होने और वास्तव में नकल लिए जाने के बीच में लगा हुआ समय मुजरा नहीं दिया जा सकता है, देखो 9 C. L. R. 293; 5 C. P. L. R. 188. लेकिन दरखास्त देने वाले को उस तारीख की सूचना दे देनी चाहिए जब कि नकल दिए जाने के लिए तैयार हो, देखो 11 P. W. R. 1912. जो समय उन फोलियों की तहकीक करने के लिए जरूरी है जिनकी इस काम के लिए जरूरत है, वह मुजरा नहीं दिलाया जा सकता, देखो 12 C. 30, 33.

जब उस दिन के बाद वाले दिन, जिसको कि डिकरी पर दस्तखत किए गए हैं, कचहरी बन्द हो और नकल की दरखास्त दुबारा कचहरी खुलने के दिन दी गई हो, तो यह बीच का समय मुजरा नहीं मिल सकता, देखो 13 C. L. J. 544; 27 M. 21. जब फैसला लम्बी छुट्टियों के लिए अदालत बन्द होने के कुछ पहिले दिया गया हो और अदालत खुलने के बाद बहुत समय तक नकल की दरखास्त न दी गई हो, तो बीच का यह समय मुजरा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दरखास्त देने वाले ने सब से पहिले मिले हुए अवसर पर दरखास्त नहीं दी थी, देखो 1911 M. W. N. 364; 43 M. 644.

नकल की दरखास्त देने के लिए आवश्यक समय के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह लगातार जारी रहने वाला ही हो। इसलिए छुट्टी (Vacation) ऐसे समय का एक हिस्सा है, देखो 20 C. W. N. 1303; 35 I. C. 888 (P).

अगर उस समय, जब कि अदालत बन्द है और मोहकमा नकल ने जो छुट्टियों में काम करता रहा है, नकल तैयार कर दी हो, तो दरखास्त देने वाला इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वह इसका पता ले, देखो 34 A. 41. लेकिन जब गजट में विज्ञप्ति निकाल कर छुट्टी में ही नकल दे देने का प्रबन्ध कर लिया गया हो, तो दरखास्त देने वाला इस बात के लिए बाध्य है कि वह नकल को लेलेवे, और अगर वह नकल न लेगा तो अदालत खुलने तक का समय मुजरा न दिया।

जायगा देखो 36 M. L. J. 62; 49 I. C. 626; 36 M. L. J. 122; 50 I. C. 518.

दफा १२ (२), (३) के अनुसार, अपीलान्ट वह समय भी मुजरा ले सकता है जो फैसले की नकल लेने के लिए जरूरी है, यद्यपि उसने फैसला और और डिकरी की नकल के लिए अलग अलग समय पर दरखास्त दी हो । दोनों मुद्दों में मुजरा दी जानी चाहिए सिवाय उस दशा के जब कि वे पूर्णतः या अंशतः एक ही साथ पड़ते हों, जिस दशा में कि वह उस समय को दो बार मुजरा नहीं पा सकता. देखो 21 C. W. N. 217; 25 Bom. L. R. 1309; 12 M. L. T. 360; 8 M. L. J. 148. जब किसी फ्रीक ने फैसला और डिकरी की नकल के लिए अलग अलग तारीखों में दरखास्तें दी हों, तो उन दोनों की मुद्दत मुजरा दी जायगी, देखो 33 M. 256; 41 M. L. J. 273. पंजाब हाईकोर्ट के एक मुकदमें में एक बार यह तय किया गया था कि कोई शख्स वह समय मुजरा पाने के लिए दावा नहीं कर सकता जो अलग अलग तारीखों में दरखास्तें देकर फैसला और डिकरियों की नकल लेने में खर्च किया गया था, देखो 100 P. R. 1918. लेकिन बाद के मुकदमों में इस राय में कुछ काट-छांट कर दी गई है, देखो 163 P. R. 1919; 3 Lah. L. J. 166.

दफा १४ उन नालिशों अथवा दरखास्तों के सम्बन्ध में समय का निकाल दिया जाना जिनमें नेकनीयती के साथ गलत अदालत में कार्यवाही की गई है—(१) उस मियाद का शुमार करने में, जो किसी नालिश के लिए निश्चित है, वह समय, जिसमें मुद्दा उचित सावधानी के साथ किसी दूसरी अदालत में चाहे वह प्रारम्भिक अदालत हो या अपील की अदालत हो, मुद्दा भलेह के विरुद्ध किसी दीवानी मामले में पैरवी कर रहा हो, निकाल दिया जायगा, जब कि उस मामले की बिनाय मुद्दा समत का आधार वही हो और वह नेकनीयती से ऐसी अदालत में दायर कर दिया गया हो, जो अख्तियार समाप्त के न होने के कारण या इसी प्रकार के किसी दूसरे कारण से उसकी समाप्त करने में असमर्थ है ।

क्लाज़ (२) में दरखास्तों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की व्यवस्था है । (देखो दफा १४ तथा इस दफा का विवरण)

व्याख्या—इस दफा का उद्देश्य यह है कि अदालत को चाहिए कि वह फ्रीकैन को उस अन्याय से बचावे जो उसी के कामों या असावधानियों के कारण पैदा हुआ हो, देखो 7 C. L. J. 59—दफा १४ अपीलों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती, देखो 19 C. W. N. 473; 23 C. 325. इसका प्रयोग केवल उन्हीं नालिशों तक सीमाबद्ध है, जो प्रारम्भिक अदालतों में दायर की गई हों, क्योंकि दफा ५ अपील की अदालतों को एक अधिक बढ़ा और स्वतन्त्र अधिकार उसी काम के लिए देती है जिसका जिक्र इस दफा में किया गया है, देखो 5 A. 591—593. यद्यपि यह दफा अपीलों के सम्बन्ध में लागू नहीं होती है, इसके सिद्धान्त (उद्देश्य) का प्रयोग दफा ५ के अनुसार अधिकारों से काम लेने की बात को निश्चित

करने के लिए किया जा सकता है, देखो 5 A. 591; 22 C. W. N. 594; 35 C. L. J. 594; 12 B. 320.

दफा १४ सिर्फ उन्हीं मामलों के सम्बन्ध में लागू होती है जिनकी समाप्त ग़लत अदालत में हुई है, देखो 1923 (Pat.) 271. संशोधित दफा २९ के अनुसार दफा १४ उन नालिशों के सम्बन्ध में लागू होती है जो किसी विशेष अथवा स्थानीय कानून के अनुसार जैसे प्रांतीय कानून दीवालिया, दायर किए गए हों, देखो 34 A. 496 F. B. यह दफा इजरा के लिए दी गई दरखास्तों के सम्बन्ध में लागू होती है, देखो 18 B. 734; 2 A. 792 P. C.; 20 C. 29.

दफा १४ का अर्थ बहुत ही विस्तृत करना चाहिए, देखो 73 I. C. 139 (M.); 30 M. L. J. 529; 541 P. C.

(१) इस दफा की आवश्यक बातें ये हैं कि पहिले जो कार्रवाई की गई हो वह दीवानी अदालत की कार्रवाई हो। दीवानी अदालत की कार्रवाई में अपील और निगरानी (देखो 2 A. W. N. 59; 17 I. C. 539); डिकरी की इजरा की कार्रवाई (देखो 28 C. 238); दीवालिया के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई (देखो 52 I. C. 934.) शामिल हैं। चाम्बे हेरीडिटरी आफिसेज ऐक्ट की दफा 11 (ए) के अनुसार दी गई दरखास्त (देखो 43 B. 201.) या दाखिल-खारिज की दरखास्त (1904 A. W. N. 54.) या अदालत माल में की जाने वाली कार्रवाई (देखो 33 P. R. 1914). दीवानी अदालत की कार्रवाई नहीं है।

(२) पहिले की कार्रवाई उचित सावधानी और नैकनीयती से की गई हो, देखो 23 A. 434; 41 P. R. 1916; 13 M. 269; 17 W. R. 518; 10 C. 265. इसलिए अगर कोई दावा बिना वकील की सलाह लिए हुए या किसी छोटे वकील की सलाह से किया गया है, तो यह उचित परिश्रम से काम लेना न कहा जाना समझा जायगा। लेकिन जब वकीलों में किसी सब से बड़े वकील की सलाह ले ली गई हो, तो केवल इसी बात से यह उचित सावधानी की कमी न समझी जायगी कि वह सलाह ग़लत थी, देखो 20 I. C. 3; 159 P. W. R. 1913. वकील की ग़लत सलाह का उचित सावधानी की कमी समझा जाना आवश्यक नहीं है, देखो 20 B. 133. लेकिन अगर यह भूल ऐसी है जो उस समय न हो सकती अगर उचित सावधानी से काम लिया गया होता, तो वह माफ नहीं की जा सकती, देखो 22 O. C. 39.

उस समय उचित सावधानी की गई न समझी जायगी, जब लापरवाही के कारण नालिश इस तरह पर तैयार की गई हो कि अदालत उसकी समाप्त न कर सकती हो, जैसे अर्जी दावा तैयार करने में असावधानी, देखो 6 W. R. 184 F. B.; 12 C. W. N. 473, या अर्जी दावा का इस बिना के ऊपर खारिज कर दिया जाना कि उसमें वे बातें नहीं बतलाई हैं जो तमादी को रोकती हैं, देखो 11 C. 264, या मुद्दे का किसी हस्ताक्षर की रजिस्ट्री कराके उसे अदालत में

पेश न कर सकना, देखो 10 B. 604. या किसी ऐसी अदालत में अपील करना जिसे अपील की समाप्त करने का अधिकार नहीं है और जिसे वह फरीक जानता होगा, देखो 28 B. 235; 39 M. 62;

किसी बात को गलत समझ जाने से समय मुजरा नहीं मिल सकता, जैसे किसी नीलाम को मसूख किए जाने के लिए दरखास्त देने के बदले नालिश दायर कर दी गई हो जो अन्त में खारिज होगई हो, देखो 43 M. L. J. 184; 23 M. 121; 22 A. 248.

नेक नीयती का सम्बन्ध मुकद्दमें में की जानने, वाली कार्रवाई से है मुद्दई की चालाकी या दूसरे अनुचित व्यवहार से नहीं जिसका मुकद्दमें से कोई सम्बन्ध नहीं है, देखो 15 B. L. R. 56.

नेकनीयती की बात हर एक मुकद्दमें के वाक्यात के उपर की जानी चाहिए देखो 32 I. C. 616. यह कानून और वाक्यात का एक मिश्रित प्रश्न है, देखो 36 I. C. 702. वह कार्य प्रणाली, जो किसी मुद्दई के सम्बन्ध में, बम्बई में, जहां पर बड़े बड़े योग्य वक्तीलों की सलाह ली जा सकती है, बदनीयती या सावधानी की कमी की द्योतक होगी, मुफ़्त्सिल के लोगों में नेकनीयती और सावधानी के साथ की गई समझी जा सकती है जिनको व्यापारी कानून की निर्वलताओं से भली भांति परिचित नहीं हैं, देखो 3 B. 182, 184, 45 I. C. 991 (A).

असावधानी से किसी दावा की कम मालियत बतलाना और किसी गलत अदालत में मुकद्दमें का दायर करना नेकनीयती नहीं कही जायगी, देखो 14 I. C. 86; 53 I. C. 892 (P), 8 A. W. N. 168.

जब कानून से किसी अदालत को अख्त्यार समाप्त चिलकुल न दिया गया हो, तो ऐसी दशा में नेकनीयती से गलती नहीं की जा सकती, देखो 23 B. 531. अगर किसी अख्त्यार समाप्त या कार्रवाई के सम्बन्ध में सन्देह होने के कारण कोई नेकनीयती से गलती की गई हो, तो इससे उस शख्स को दफा १४ से लाभ उठाने का अधिकार मिल जाता है, देखो 3 C. W. N. 233 F. B. कानून के सम्बन्ध में नेकनीयती के साथ की गई गलती के बारे में देखो 45 C. 94 P. C.

(३) वह कार्रवाई उसी बिनाय मुख़ासमत के ऊपर की गई हो-दफा १४ चाहती है कि पहिले की नालिश की बिनाय मुख़ासमत वही हो जो कि दूसरी नालिश की है और अदालत पहिली नालिश की समाप्त करने में किसी ऐसे कारण से ही असमर्थ हो जो अख्त्यार समाप्त के न होने के ही समान है, देखो 8 A. 475, 3 W. R. 101, 8 W. R. 402. आवश्यक बात यह है कि पहिले की कार्रवाई की बिनाय मुख़ासमत वही थी जो अब दूसरी नालिश के सम्बन्ध में पेश की जा रही है, देखो 17 C. L. J. 596. अगर मुद्दई ने पहिले बेदखली की बावत गलत नालिश दायर की हो, तो वह दफा १४ से लाभ नहीं उठा सकता, जबकि उसने बाद में लगान की बावत नालिश की हो, देखो 9 C. 255

P. C. अगर फरीकैन और बिनाय मुखासमत दावा भिन्न २ है, तो दफा १४ लागू नहीं हो सकती, देखो 1 R. 402.

(४) पहिली अदालत अख्तियार समाभत के न होने या इसी प्रकार के दूसरे कारणों से उस नालिश की समाभत करने में असमर्थ हो, देखो 41 P. R. 1916—सन १९०८ ई० के कानून मियाद के अनुसार दफा १४ के साथ जो विवरण (३) जोड़ दिया गया है जिससे फैसलों में होने वाला विरोध दूर हो जाता है और साफ तौर पर यह व्यवस्था करता है कि फरीकैन या बिनाय मुखासमत का गलत तौर पर शामिल किया जाना अख्तियार समाभत के न होने जैसा कारण समझा जाना चाहिए।

“अख्तियार समाभतका होना” का अर्थ है उस खास अदालतको अख्तियार समाभत का न होना जिसमें कार्रवाई की गई थी, इसमें किसी ऐसी अदालत में जिसे उस अपील की समाभत करने का अख्तियार नहीं है, अपील दायर करना जैसी भूल (गलती) शामिल नहीं है, देखो 163 P. W. R. 1911; 45 P. R. 1913; 28 B. 2 35.

जब दूसरी नालिश में कई एक मुद्दाभलेह हों और पहली नालिश उनमें से सिर्फ एक ही शख्स के खिलाफ दायर की गई हो, तो उस समय दफा १४ लागू नहीं होती है और इसलिये ऐसी दशा में समय मुजरा नहीं दिलाया जा सकता. देखो 5 W. R. 281; 3 B. 182; 184. जब कि दूसरी नालिश किसी ऐसे शख्स के ऊपर दायर की गई हो जिसके ऊपर नालिश करने का हक पहिले मुद्दाभलेह से पैदा होता है, तो ऐसी दशा में दफा १४ लागू होती है, देखो 1 P. 506.

जिन कारणों से किसी नालिश या दरखवास्त को उठा लेने की इजाजत दी गई हो, वे दफा १४ के अर्थ में उसी प्रकार (किस्म) के कारण नहीं हैं, देखो 6 B. 681. इसलिये दफा १४ उस समय लागू नहीं होती जब पहिली नालिश को मुद्दे ने उठा लिया हो, देखो 12 B. 625; 29 B. 219; 39 M. 963.

वह समय, जिसमें इजरा की कोई दरखवास्त चल रही हो और उसका फैसला मुकद्दमें की रूयदाद के ऊपर किया गया हो, मुजरा नहीं दिया जा सकता, देखो 74 I. C. 279 (C.)

दूसरे मामलों में समय का निकाल देना—हुकम इस्तनाई या हुकम से मामलेकी मुत्तबी—
(१) किसी ऐसी नालिश या डिक्ली की इजरा की किसी दरखवास्त में, जो हुकम इस्तनाई या दूसरे हुकम से मुत्तबी कर दी गई है, उसके जारी रहने का समय, या वह दिन, जिसको कि वह जारी किया गया था या दिया गया था और वह दिन, जिसको वह उठा लिया गया था, निकाल दिए जायेंगे।

(२) किसी ऐसी नालिश में, जिसमें कि नोटिस की ज़रूरत है नोटिस का समय निकाल दिया जायगा (दफा १५)

खरीदार नीलाम का क्रम—खरीदार नीलाम की ओर से की गई कृष्ण की नालिश में वह समय निकाल दिया जायगा जिसमें नीलाम की मसूखी के लिए दावा दायर किया गया हो (दफा १६)

मौत होजाने से अंतर—नालिश दायर करने का हक पैदा होने से पहिले मौत के होजाने का असर क्या होता है, इस सम्बन्ध में देखो दफा १७। इसका आधार इस सिद्धांत के ऊपर है, कि मियाद का हिसाब उस शख्स के सम्बन्ध में नहीं लगाया जा सकता जो मौजूद नहीं है। दफा ६ दफा १७ के साथ पढ़ी जानी चाहिए। इस दफा के अमल के सम्बन्ध में यह समझा जाना चाहिए कि वह बाद वाली दफा में बतलाए हुए अपवाद (मुस्तस्नियात) के अनुकूल और उसके अधीन है देखो 9 C.W. N. 537.

फरेब करने का अंतर—जब किसी ऐसे शख्स को, जिसे किसी नालिश के दायर करने या दरख्वास्त के देने का अधिकार (हक) है, फरेब (छल) से ऐसे अधिकार या हकीयत की बात जानने न दी गई हो जिसके आधार पर वह नालिश दायर की जा सकती है या दरख्वास्त दी जा सकती है, या जब कोई ऐसा कागज़, जो ऐसे अधिकार को साबित करने के लिए आवश्यक है, फरेब (छल) करके उससे छिपा रखा गया हो, तो मियाद की मुद्दत उस समय से शुरू होगी जिस समय इस फरेब की बात का उसे पहिले पहल पता चला हो (देखो दफा १८) ।

व्याख्या—दफा १५ हुकम इस्तनाई या दूसरा हुकम—यह दफा पहिले नालिशों के सम्बन्ध में ही लागू होती थी, लेकिन सन् १९०८ ई० के ऐक्ट से कुछ शब्द और बढ़ा दिए गए हैं जिनसे वह डिकरियों की इजरा के लिए दी गई दरख्वास्तों के सम्बन्ध में लागू हो सकती है (देखो 7 I. C. 886; 9 A. L. J. 540; 38 B. 153; 34 A. 436.) जो हुकम इजरा की मुलतवी के सम्बन्ध में दिया गया हो वह साफ़ साफ़ होना चाहिए, यद्यपि उसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह लिखित हो, देखो 23 Bom. L. R. 107. नालिश की पेशी की तारीख़ का बढ़ा दिया जाना हुकम इस्तनाई या इजरा की मुलतवी का हुकम नहीं है, देखो 39 I. C. 939; (C) । यह बात बिल्कुल अनावश्यक है कि हुकम इस्तनाई का सम्बन्ध डिकरी के केवल एक हिस्से से ही है, देखो 38 B. 153; 46 I. C. 399.

मियाद की मुद्दत का शुमार करने में वह समय, जिसमें डिकरी की इजरा मुलतवी कर दी गई थी, या बन्द कर दी गई थी, निकाल दिया जायगा यद्यपि उस समय इजरा की कोई भी अर्ज़ी अदालत में पड़ी हुई नहीं थी, देखो 13 L. W. 97; 40 M. L. J. 124. दफा १५ में आए हुए 'निश्चित (Prescribed)' शब्द का अर्थ है 'इस ऐक्ट द्वारा निश्चित' और इसलिए वह जाबता दीवानी जी. दफा ४८ के सम्बन्ध में लागू नहीं होती, देखो 40 A. 198; 45 M. 785; 42 A. 118; 54 I. C. 279.

“हुकम इस्तनाई या दूसरे हुकम” में कुर्की शामिल नहीं है देखो 42 M. 637. कर्ज की कुर्की का हुकम ऐसा हुकम नहीं है जो किसी नालिश की मुलतवी करता है, क्योंकि इससे महाजन को उस कर्ज की वावत नालिश करने में कोई रुकावट नहीं पड़ती है, सिर्फ वह कर्ज का रुपया वसूल नहीं कर सकता, देखो 13 A. 76; 17 A. 198 P. C; 14 A. 162. यही बात फैसला के कल की जाने वाली कुर्की के सम्बन्ध में है, देखो 21 C. W. N. 1147. लेकिन किसी डिकरी की कुर्की इजरा की मुलतवी हो जाती है और इसलिए मियाद की मुदत मुजरा दी जा सकती है, देखो 30 I. C. 587 (C.).

जब डिकरी कई एक भादमियों के विरुद्ध दी गई हो और इजरा की कार्रवाई किसी एक शख्स के विरुद्ध मुलतवी की गई हो तो बाकी दूसरे मद्यूनान डिकरी के सम्बन्ध में भी मुदत निकाल दी जायगी, देखो 13 L. W. 59.

मद्यूनान-डिकरी को गिरफ्तार न करने के लिए किये गए इकरारनामा से मियाद का जारी रहना रुक नहीं सकता, देखो 28 I. C. 381 (A). जो हुकम मद्यूनान डिकरी को रुपया अदा करने के लिए दिया गया हो, वह इजरा की मुलतवी करने वाला हुकम नहीं है, देखो 40 A. 198. जब किसी डिकरी की इजरा में होने वाली नीलाम, डिकरीदार की वजह से मुलतवी कर दी गई हो, तो दफा १५ लागू नहीं होती, देखो 53 I. C. 85 (P.) दीवाला की कार्रवाई जारी रखने से किसी डिकरी की इजरा के लिए मियादके सम्बन्धमें कोई रुकावट नहीं पड़ती, जब तककि प्रान्तीय कानून दीवालिया की दफा १५ के अनुसार रक्षा करने वाला (Protection order) न दिया गया हो, देखो 47 I. C. 798 (P.) दीवालिया करार दिए जाने के लिए दिया गया हुकम भी दीवालिया के विरुद्ध की जाने वाली नालिश को मुलतवी नहीं करता देखो 42 M. 319.

प्रिवी कौंसिल में की गई एक अपील के दौरान में अपीलाण्ट ने वह डिकरी जो उसने एक दूसरी नालिश में फरीकसानी के ऊपर प्राप्त की थी, बतौर जमानत के दाखिल कर दी। तब हुआ कि इस जमानत के मंजूर कर लेने से इजरा की कार्रवाई मुलतवी नहीं हो जाती, देखो 3 P. L. J. 132. जब कि प्रिवी कौंसिल में की गई एक अपील के दौरान में हाईकोर्ट ने डिकरीदार के जमानत दाखिल कर देने पर डिकरी की इजरा का हुकम दे दिया और वह जमानत दाखिल नहीं कर सका और इसलिए इजरा की कार्रवाई नहीं की जा सकी, तब हुआ कि वास्तव में इस हुकम से इजरा की कार्रवाई मुलतवी होगई और इसलिए दफा १५ लागू होती है, देखो 5 P. L. J. 31.

दफा १५ को दफा ६ और ७ के साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए, देखो 37 M. L. J. 286.

दफा १६—इस दफा में आए हुए “कार्रवाई” शब्द में नालिश और दर-ब्यास्त दोनों शामिल हैं, और व्यवस्थापक सभा का मंशा उस समयको निकाल देने का था जिसमें नीलाम के जायज होने के सम्बन्ध में एतराज किया गया हो।

फिर वह चाहे किसी नालिश के जरिये हो या किसी दरख्वास्त के द्वारा, देखो 21 C. W. N. 304; 38 I. C. 547.

जब यह आर्टि० १४४ लागू होती हो, उस हालत में दफा १६ के अनुसार कानून में अथवा इन्साफ की अदालत में कोई भी समय मुजरा नहीं दिया जा सकता है, देखो 70 I. C. 420; 26 C. W. N. 364.

दफा १६ में आए हुए शब्द "नालिश करने के क़ाबिल क़ानूनन नालिश कर सकने में असमर्थ" शब्दों के बिल्कुल बिरोधी अर्थ के घोलक हैं। इसका सम्बन्ध उस असमर्थता से नहीं है जो साधनों की कमी अथवा दूसरे शारीरिक कारणों से पैदा होती हो, 28 B. 15, 44.

दफा ६ को इस दफा के साथ पढ़ना चाहिए। पहिले की दफा के प्रयोग के सम्बन्ध में यह समझना चाहिए कि वह बादवाली दफा के अपवाद (मुस्त-स्नियात) के अन्तर्कूल है। जब कि एक शख्स सन् १८९६ ई० में मर गया और उसकी बेवा ने प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रों (Letters of administration) को लिया जो उसके लड़के की नाबालिगी की हालत तक के लिए ही महदूद (सीमाबद्ध) थे। लड़के ने सन् १९०३ ई० में बालिग होने पर सन् १९०४ ई० में एक नालिश बाबत हिसाब-किताब पट्टीदारी के दायरकी, तय हुआ कि उसके नाबालिग होने से तमादी का बचाव नहीं होता। वह रियासत सभी कामों के लिए उस बेवा के हवाले कर दी गई थी, देखो 9 C. W. N. 537; 23 B. 544 P. C.

दफा १८ फ़रेब—इस दफा में बतलाया हुआ फ़रेब उस शख्स का फ़रेब है जिसके विरुद्ध किसी अधिकार के सम्बन्ध में दावा किया गया हो, अर्थात् मुद्दा-अलैह अथवा किसी दूसरे ऐसे शख्स का जिसके ज़रिये से वह दावेदार है, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं, देखो 2 C. 1; 36 C. 654. मुद्दई का नालिश करने सम्बन्धी अपने अधिकारों की अनभिज्ञता दफा १८ में नहीं आती है, जब तक कि इसका कारण मुद्दाअलैह की ओर से किया गया फ़रेब (छल) न हो; देखो 8 W. R. 23; 19 W. R. 269; 16 I. C. 547. दफा १८ केवल उस दशा में लागू होती है जब कि किसी व्यक्ति को फ़रेब (छल) से अपने अधिकारों को न जानने दिया गया हो, उस दशा में नहीं जब कि उसे अपने अधिकार को काम में लाने से रोका गया हो, देखो 25 I. C. 884; 68 I. C. 924. इसलिए अगर अदालत के बाहर की गई रुपये की किसी बेवाकी के लिए आर्डर २१, रूल २ के अनुसार तस्दीक न की गई हो, तो इजरा करने वाली अदालत डिकरीदार के ऊपर लगाए गए फ़रेब के अभियोग की निस्वत दफा ४७ के अनुसार जांच नहीं कर सकती। अगर यह बात साबित भी होगई हो कि उसका चाल-चलन फ़रेबियों (छल-कपट) का है, तो भी मदीयून-डिकरी, वह समय बढ़ा देने का हक्कदार नहीं है जिसके भीतर आर्डर २१ रूल २ (२) के अनुसार दरख्वास्त दी जानी चाहिए, क्योंकि क़ानून मियादकी दफा १८ के अर्थमें वह फ़रेब करके द-

द्वारा देने सम्बन्धी अपने अधिकार से वंचित नहीं रखा गया है बल्कि वह अपने उस अधिकार को काम में लाने से रोक रखा गया है, देखो 16 C. W. N. 923; 13 I. C. 63 तथा 49 C. 886; 19 C. W. N. 553; 1919 P. W. R. 2 मियाद उस समय तक शुरू न होगी जब तक कि फरैब की बात मुद्दे को मालूम न हुई हो, देखो 26 C. W. N. 479.

दफा १८ में जिस फरैब की जानकारी का जिक्र किया गया है, यह ऐसी न होनी चाहिए जिसके लिए केवल सन्देह किया जाता है (देखो 14 B. 408) या बतलाया जाता है अथवा जिसके लिए, केवल साधन मौजूद हैं (देखो 17 B. 341, 347 P. C.) कुछ अवस्थाओं में अदालत इस जानकारी की बातको केवल जानकारी मात्र से ही जान सकती है (देखो 8 C. L. R.) यद्यपि इस जानकारी के साधन और यह जानकारी हमेशा एक ही नहीं होते हैं (देखो 9 W. R. 329)

यह जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए "केवल नीलाम हुई है" इस बातकी जानकारी मियाद के शुरू होने के सम्बन्ध में काफी नहीं है, देखो 17 B. 141 P. C.; 17 C. 769 F. B.; 48 C. 119; 18 C. W. N. 1266; 3 P. L. T. 501 और 49 C. 886. मियाद की मुद्दत उस समय से शुरू होनी चाहिए जिस रोज़ फरैब की बात मालूम हुई हो, देखो 45 A. 316.

दफा १८ उस फरैब (छल) के सम्बन्ध में लागू नहीं होती जो अधिकार पैदा होने से पहिले किया गया हो जैसे नीलाम के पहिले। मालियत का ग़लत बतलाना, यद्यपि यह फरैब नहीं कहा जा सकता, फरैब से किसी बात का छिपाना नहीं है और नीलाम के इश्तहार का प्रकाशित न करना स्वयं उस मामले को दफा १८ में नहीं लाता, जब तक कि यह बात न दिखला दी गई हो कि मदिथून डिकरी को डिकरीदार के फरैब करने के कारण अपने अधिकार का पता न लग सका, देखो 16 C. W. N. 894; 15 C. W. N. 965. नीलाम के पहिले किए गए फरैब का बहुत कुछ आधार इस प्रश्न के ऊपर है कि क्या दफा १८ के प्रयोजन के लिए नीलाम के बाद फरैब किया गया था, देखो 17 C. W. N. 478. यह फरैब छिपा हुआ फरैब होना चाहिए, देखो 9 W. R. 255.

अपने मामले को दफा १८ के अन्दर लाने के लिए मुद्दे को चाहिए कि वह यह बतलावे कि फरैब किए जाने की बात उसको कब मालूम हुई, देखो 67 I. C. 914 P.; 3 Pat. L. T. 529. एक बार यह साबित हो जाने पर कि किसी शख्स को फरैब करके अपने अधिकारों को जानने नहीं दिया गया है, इस बात का साबित करने का सारा भार दूसरे शख्स के ऊपर चला जाता है कि उसे मियाद की मुद्दत से बहुत पहिले यह बात मालूम होगई थी, देखो 49 C. 883; 17 B. 341 P. C.; 18 C. W. N. 1266; 27 C. L. J. 528; 14 Bom. L. R. 771; 34 P. R. 1904.

जब फरैब करके किसी शख्स को नीलाम की बात जानने न दी गई हो, तो यह समझा जायगा कि ज़रूरतनू उसे उस नीलाम की मंजूरी के लिए

नालिश करने सम्बन्धी अपने अधिकार को जानने नहीं दिया गया है, देखो 19 C. W. N. 553.

जब डिकरीदार ने मदियून-डिकरी के ऊपर नीलाम की नोटिस तामील न कराई हो और मदियून-डिकरी को इस नीलाम की बात उस समय मालूम हुई हो जब कि कब्जे के लिए दरख्वास्त दी गई हो, तो ऐसी दशा में दफा १८ लागू होती है, देखो 72 I. C. 76 (M.)

लिखित स्वीकृति-पत्र देने का असर—जब किसी जायदाद या हक के सम्बन्ध में मियाद की मुद्दत खतम होने से पहिले अपनी जिम्मेदारी का लिखित स्वीकृति-पत्र दे दिया गया हो जिसपर ऋणी के या किसी ऐसे शख्स के, जिससे उसका हक या जिम्मेदारी पैदा होती है अथवा किसी अधिकार प्राप्त मुख्तार (मुख्तार मजाज) के दस्तखत हों, तो स्वीकृति-पत्र देने की तारीख से मियाद की नई मुद्दत का शुमार किया जायगा (देखो दफा १९ और उसके तीनों विवरण) ।

व्याख्या—दफा १९ नालिशों और दरख्वास्तों, जैसे डिकरी इजराकी दरख्वास्तों के सम्बन्ध में लागू होती है । इसकी आवश्यक बातें ये हैं:—(१) यह स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) मियाद खतम होने के पहिले लिखा गया हो देखो 16 C. W. N. 663); (२) वह उस खास दावा या अधिकार के सम्बन्ध में होना चाहिए (देखो 6 M. 182); (३) यह स्वीकृति-पत्र जिम्मेदारी (देनदारी) के सम्बन्ध में लिखा गया हो, अर्थात् वह जिम्मेदारी की एक निश्चित स्वीकृति होनी चाहिए, (देखो 30 C. 699) यह स्वीकृति-पत्र लिखित होना चाहिए और उसपर हस्ताक्षर (दस्तखत) भी होने चाहिए ।

इंगलिश लॉ के अनुसार किसी ऋण की स्वीकृति में रुपया अदा करने का वादा भी शामिल है, लेकिन हिन्दुस्तान के कानून में किसी ऋण को स्वीकार करने से यह नहीं समझा गया है कि उसके अदा करने का वादा भी इसमें शामिल है, देखो 3 L. 326.

यह स्वीकृति मियाद की मुद्दत खतम होने के पहिले की जानी चाहिए । किसी ऐसे ऋण या (कर्ज) को स्वीकृति से, जिसकी मियाद आरिज़ होगई है, मियाद बढ़ नहीं सकती, देखो 16 C. W. N. 636; 42 A. 390; 2 A. 443; 42 A. 575 F. B.; 6 B. 683; 5 P. L. J. 37; 24 I. C. 507; 67 I. C. 298 (C) । परन्तु किसी ऐसे ऋण (कर्ज) की, जिसकी मियाद आरिज़ हो होगई है, मियाद कानून सुआहिदा की दफा २५ के अनुसार नया सुआहिदा करके फिर नई की जा सकती है । लेकिन दफा १९ के अनुसार उसी समय स्वीकृति-पत्र लिख देने से नई मियाद शुरू हो सकती है, जब वह ऋण अथवा अधिकार अभी बना हो (देखो 3 A. 761; 23 W. R. 462; 1 B. 590; 2 B. 230; 6 P. L. J. 121) । यह स्वीकृति-पत्र मौजूदा देनदारी के सम्बन्ध में होना चाहिए, देखो 25 M. 220 F. B.; 16 M. 220; 6 C. L. J. 554.

झुट्टियों में और मियाद खतम हो जाने के बाद की गई स्वीकृति काफी नहीं है । यह बात, कि बीच में झुट्टियों के षड़ जाने से नालिश करने सम्बन्धी

अधिकार उस समय तक बना हुआ था, कोई प्रभाव नहीं रखती देखो 26 B. 782.

दफा १९ के अनुसार कीगई स्वीकृति किसी खास दावा या अधिकारके सम्बन्धमें की जानी चाहिए, उदाहरणार्थ किसी ऐसी हकीयत आराजीकी स्वीकृति जो उस हकीयत से भिन्न है जो मुद्दई ने कायम किया है काफी नहीं है, देखो 6 M. 182. अगर एक से अधिक कर्जों का रुपया बाकी हो, तो स्वीकृति-पत्र ऐसा होना चाहिए जिससे उस खास कर्जों का पता चल सके जिसकी निस्वत नालिश कीगई है और जबानी शहादत किसी कर्जों के सम्बन्ध में काबिल तस्लीम न होगी, देखो 17 A. 198 P. C. स्वीकृति पत्र में ठीक उस कर्जों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसकी निस्वत दावा किया गया है किसी कर्जों का नहीं देखो 13 C. L. J. 139; 21 O. C. 151; 9 Bom. L. R. 715; 23 B. 177.

अगर कोई मुद्दई किसी ऐसी नालिश को, जिसकी मियाद आरिज़ होगई है, किसी स्वीकृति-पत्र के (Acknowledgment) के ज़रिये मियादके अन्दर खाना चाहता है, तो उसे चाहिये कि वह इसके लिये माकूल सुनूत पेश करे, देखो 44 A. 360; 66 I. C. 171.

जब तक यह न मालूम हो कि वह शख्स किसी बातको स्वीकार कर रहा है, कोई स्वीकृति-पत्र ठीक न माना जायगा। दफा १९ का मंशा है कि मौजूदा देनदारीके सम्बन्धमें सब बातें साफ साफ मालूम होनी चाहिए, देखो 3 B.99 स्वीकृति-पत्र (Acknowledgment) से किसी बातकी जानकारी प्रकट होती है जिसका भार किसी शख्सने अपने ऊपर लिया हो, देखो 15 C. L. J. 251 इसका मतलब है किसी कर्जों (या जिम्मेदारी) को निश्चय रूपसे स्वीकार कर लेना। यह आवश्यक नहीं है कि रुपया अदा करने का वादा किया जाय, किसी कर्जोंका केवल योंही स्वीकार कर लेना काफी है, देखो 39 C. 699; 41 M. L. J. 217. इस स्वीकृतके सम्बन्धमें कोई शर्त बगैरा नहीं होनी चाहिये, जैसे किसी पत्रमें यह लिख देना कि मैं (लिखने वाला) यह देखूंगा कि कोई रुपया बाकी है या नहीं देखो 31 C. 195. या यह कहना कि मैं हिसाब-किताब देखकर दस्तखत करूंगा, काफी नहीं है। लेकिन जब कि एक शख्सने इस बात से इनकार कर दी कि कोई रुपया उसपर बाकी है परन्तु इस बातको स्वीकार कर लिया कि अगर कोई हिसाब किताब जिम्मे निकलेगा तो वह उसका देनदार होगा तब हुआ कि यह स्वीकृत-पत्र (Acknowledgment) है, देखो 10 M. 259. किसी जिम्मेदारीको जो इस शर्त पर स्वीकार कर लेना कि अगर बाकी हमारे जिम्मे निकली तो हम उसके देनदार होंगे और उस शर्तको पूरा करने का वादा स्वीकृत (Acknowledgment) है, देखो 33 C. 104 P. C; 10 C. W. N. 874; 16 M. L. J. 300. किसी शर्त के ऊपर कीगई स्वीकृति (Acknowledgment) उस समय तक नई मियाद नहीं शुरू होती जब तक कि

वह शर्त पूरी न कर दी जाय, देखो 29 M. 519; 40 M. 701. शर्तोंके साथ में किसी जिम्मेदारी (देनदारी) की स्वीकृत के सम्बन्धमें देखो 58 I. C. 446 (M); 48 I. C. 89; 59 I. C. 898 (M).

कोई स्वीकृति-पत्र (Acknowledgment) केवल इसी बातसे नाजायज़ नहीं हो जाता कि उसमें कर्ज़की तारीख ग़लत बतलाई गई है, देखो 26 A. 313; 11 A. L. J. 86.

किसी स्वीकृति के सम्बन्धमें यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रकट हो। यह बात अप्रकट (सांकेतिक) भी हो सकती है, परन्तु इस बातसे यह बात प्रकट होना आवश्यक है कि यह स्वीकृति किसी खास जिम्मेदारीकी निस्वत की गई है, किसी अनिश्चित जिम्मेदारी की निस्वत नहीं, देखो 9 Bom. L. R. 715; 13 C. L. J. 139; 131 P. R. 1919; 34 M. L. J. 551; 3 I. C. 34. जब किसी हिसाब का वज़द मान लिया जाय, तो इससे निस्सन्देह यह परिणाम निकलता है कि वह शख्स, जो इस हिसाब रहने की बातको स्वीकार कर लिया है, इसको स्वीकार करता है कि अगर हिसाबमें उसके जिम्मे कोई रुपया निकलेगा तो वह उसका देनदार होगा, देखो 58 I. C. 787 (L).

जबकि एक मदिथून-डिकरी ने अपने गिरफ्तार किए जाने की निस्वत इस बिना पर उज़्रदारी पेश की कि वह ग़रीब है और यह प्रार्थना कि उसकी उज़्रदारी का फैसला होने तक वारण्ट मुलतवी रखा जाय-तय हुआ कि यह कर्ज़ के रुपये की स्वीकृति नहीं है, देखो 39 A. 357.

यद्यपि किसी दस्तावेज़ वगैरा के ऊपर उसकी वसूली वगैरा का लिख देना दफा २० के अर्थ में अदायगी न समझी जायगी, तो भी दफा १९ के अनुसार वह एक जायज़ स्वीकृति समझी जायगी। इसलिये जब किसी प्रोनोट पर रुपये की अदायगी लिख दी गई हो, परन्तु वास्तव में रुपया अदा न किया गया हो, तो तमादी बचाने के लिये यह काफ़ी स्वीकृति समझी जायगी, देखो 28 I. C. 15 (M); 48 I. C. 724; यह स्वीकार कर लेना कि फ़रीक़ैन के बीच हिसाब किताब चल रहा था, स्वीकृति (Acknowledgement) है, यद्यपि उस हिसाबके सही होने की बात न भी मानी गई हो और यद्यपि उसको किसी मुख़्तार ने इस शर्त पर स्वीकार किया हो कि उसके मालिक की मंजूरी मिलने पर उसकी बात सही मानी जाय, देखो 55 P. R. 1910; हिसाब-किताब दाख़िल करने की जिम्मेदारी का स्वीकार कर लेना दफा १९ के अर्थ में कर्ज़ का स्वीकार करना नहीं है देखो 87 P. L. R. 1909; 4 I. C. 929.

जबकि एक पंचायतनामा के फ़रीक़ैन ने यह बात स्वीकार की कि वह हिसाब-किताब साफ़ नहीं हुआ जो पंचों को साफ़ करना चाहिये था और हर एक फ़रीक़ेने यह वादा किया कि वे, जो कुछ रुपया वाजिब निकलेगा, अदा करेंगे तय हुआ कि यह स्वीकृति-पत्र (Acknowledgment) है। यह आवश्यक नहीं है कि स्वीकृति-पत्र किसी व्यक्ति विशेष (खास आदमी) का नाम सम्बोधन करके

लिखा जाय और अगर उसमें रुपया अदा करने से इन्कार कीगई हो, तो भी वह स्वीकृति-पत्र पर्याप्त समझा जायगा, देखो 23 C. W. N. 921; 53 I. C. 898; कोई भी स्वीकृति पत्र, फिर बाद चाहे किसी के भी नाम लिखा गया हो, जायज़ स्वीकृति पत्र होना' अगर उसमें उचित निश्चय के साथ ज़िम्मेदारी सुतनाज़ा की बाबत की ओर संकेत किया गया है देखो 19 C. W. N. 263; 40 M. 698; 35 A. 437; 37 B. 326 P. C.

किसी सम्मिलित हिन्दू कुटुम्ब का कोई छोटा आदमी जो उस कुटुम्ब का प्रबन्धक नहीं है ऐसा स्वीकृति पत्र नहीं लिख सकता जिससे सबके ऊपर ज़िम्मेदारी आती हो, 72 I. C. 249.

किसी प्रोनोंट के ऊपर उसके रुपये की अदायगी का लिखा जाना स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) है। इसमें इसबात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि रुपये की यह अदायगी किसी हिसाब के, जिससे पहिले अदा कीगई किस्तों का पता चलता हो, नीचे लिखी गई हो देखो 72 I. C. 249.

उस आगाज़ी के, जो कई एक हिस्सेदारों के कच्चे में है, हिस्से की निश्चय की जाने वाली नालिस की मियाद आरिज़ नहीं होती; अगर उस मुद्दाअलेह हिस्सेदार ने जो उसपर कायिज़ है, बारह बरस के भीतर मुद्दई को पत्र लिख कर उसमें उसकी हकीयत को स्वीकार कर लिया हो देखो 5 Lah L. J. 47. कई एक मुतहिनों में से केवल किसी एक की ओर से राहिन की हकीयत (Title) को स्वीकार कर लेने से राहिन के फ़करेहनी करने सम्बन्धी अधिकार (हक) की रक्षा नहीं होजाती, जबकि वह रेहननामा मुद्तरका है और उसकी फकरेहनी अलग अलग नहीं हो सकती, देखो 5 Lah. L. J. I 1.

स्वीकृति-पत्र के लिखे यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी खास नमूने (फॉर्म) का हो। लिखने की शैली कैसी है इसबात से कोई कोई विशेष लाभ अथवा हानि नहीं। जिस बात की आवश्यकता है, वह सिर्फ यह है कि वह लिखित हो और उसपर लिखने वाले के या उसके मुखतार मजाज़ के दस्तख़त हों इसका उद्देश्य केवल यह है कि ज़बानी स्वीकृति (Oral acknowledgement) न की जाय देखो 20 M. 239; 242; अर्ज़ीदावा या बयान तहरीरी (देखो 27 C. 1004; P. C.); अर्ज़ी (देखो 23 C. 374; 387) बसीयतनामा (देखो 3 M. L. J. 191); बयान जो जज के सामने दिया गया हो और उसीके सामने उसपर दस्तख़त किए गये हों (देखो 39 A. 437); किसी प्रोनोंट में किसी ऐसे कूज़ का उल्लेख जो किसी पहिले वाले तमसलुककी बाबत वाजिब है (देखो 38 M. 177); किसी दीवालिया की ओर से दाखिल कीगई सूची (फ़हरिस्त) (देखो 35 B. 283); पंचायत में मामला पेश करने के सम्बन्ध में कीगई स्वीकृति (देखो 23 C. W. N. 921); हाथ चिह्न (देखो 46 C. 746); किसी इजहार का स्वी-

कार करना (देखो 10 I. C. 142; 151; P. L. R. 1911) स्वीकृति-पत्र (Acknowledgement) हैं अगर किसी इज़हार पर दस्तखत न किये गये हों तो वह स्वीकृति-पत्र (Acknowledgement) न होगा, देखो 34 P. R. 1918

किसी बयान में सिर्फ यह इज़हार देना कि गवाहने पहिले किसी तारीख को एक तमस्सुक लिखा था, स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) नहीं है देखो 73 I. O. 953 (M); 45 A. 479.

दस्तखतोंके लिये यह ज़रूरी नहीं है कि वे लिखित ही हों किसी अनपढ़ आदमीका कोई चिन्ह (निशान) बना देना ही काफी है, देखो M. H. C. R. 358; 28 M. 262. सिर्फ कलमको छूकर दूसरे शख्ससे दस्तखत कर देनेके लिये कह देना काफी है, देखो 6 M. L. J. 209.

जब किसी महाजनने ऋणीके उस लिखित प्रार्थना-पत्र (दख्वास्त) पर, जिसमें उसने रुपया अदा करनेके लिये समय मांगा हो, समय बढ़ा दिया हो, तो वह स्वीकृति-पत्र (Acknowledgement) है, देखो 12 M. L. J. 351. किसी गिरफ्तार किये हुए मदयून-डिकरीकी ओरसे रिहाईके लिये और डिकरीके बाकी रुपयेकी अदायगीका हुक्म किये जानेके लिये दी गई दख्वास्त स्वीकृति पत्र (Acknowledgement) है, देखो S. N. L. R. 8;

अगर किसी कर्जेके किसी एक ही हिस्सेके सम्बन्धमें स्वीकृति की जाय, तो इससे उसके उतनेही हिस्सासे सम्बन्ध रखनेवाली मियाद कायम रहेगी, देखो 16 C. W. N. 493.

किसी स्वीकृति-पत्रके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसके लिये कोई नया बदल (माविज़ा) किया जाय और न यही आवश्यक है कि रुपया अदा करनेके लिये कोई खास वादा किया जाय, देखो 50 C. 974.

किसी नाबालिगकी ओरसे की गई स्वीकृति काफी नहीं है, देखो 59 P. R. 1901.

किसी पहिलेके मुकद्दमेंमें दाखिल किया गया बयान तहरीरी जिसमें मुद्दे से प्रानोट पेश करनेके लिये कहा गया हो, स्वीकृति-पत्र (Acknowledgement) नहीं है, देखो 34 P. R. 1918. किसी ऐसी हुण्डीकी हवालीगी जो पेश किये जाने पर बिना सकारे वापस कर दी गई है स्वीकृति (Acknowledgement) नहीं है, देखो 42 A. 390.

व्याजकी रकमकी अदायगीका या मूलधनके किसी हिस्सेकी अदायगीका अतर—(१) जब किसी कर्ज़ या वसीयती माल (Legacy) की बाबत वाजिब व्याज (सुद) को, नियत समय समाप्त होनेके पहिले, वह शख्स, जो उस कर्जा या वसीयती मालका देनदार है, या इस सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त मुख्तार अदा कर दे, या जब किसी ऋण (कर्जे के) मूलधनका कोई हिस्सा ऋणी या उसका इस सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त मुख्तार अदा कर दे, तो जिस समय रुपया अदा किया गया हो उस समयसे मियादकी मुद्दतका शुमार किया जायगा ।

लेकिन शर्त यह है कि, अगर किसी ऋणके मूलधनका केवल एक हिस्सा अदा किया गया है तो अदायगी उसी शर्तके हाथकी लिखी हुई हो जिसमें उसे किया है।

(२) जब आराज़ी मरहूना मुर्तहिनके कब्जेमें हो, तो उस आराज़ीके लगान या पैदावारकी वसूली उप—दफा (१) के अर्थमें अदायगी समझी जायगी।

विवरण—ऋणमें कोई भी ऐसा रुपया शामिल है जो किसी डिकरी या मालिकके हुक्मके अनुसार वाजिबुलअदा हो (दफा २०)।

दफा १९ और २० में आये हुए “इस सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त मुख्तार” कथ्यमें, उन व्यक्तियोंके सम्बन्धमें जो अयोग्य हैं (Persons Under Disability), उनके कानूनी संरक्षक (वली) कमेटी या मैनेजर अथवा मुख्तार शामिल हैं जिन्हें ऐसे संरक्षक (वली) इत्यादिने अधिकार दिया हो।

कई एक मुआहिदादारों (Contractors) में से किसी एककी ओरसे की स्वीकृति या अदायगीसे उनमेंसे कोई दूसरा या दूसरे लोग उसके लिये जिम्मेदार नहीं होते (दफा २१)

व्याख्या—दफा २० का आधार वही सिद्धान्त (Principle) है जो दफा १९ का है। मूलधन या व्याज के किसी हिस्से की अदायगी मौजूदा कर्जेका स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) है।

दफा १९ और २० आपसमें एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हैं। एक हिस्से की अदायगी, का इंदराज हो, मगर कर्जदार के हाथ से न लिखा गया हो तो दफा १९ के अनुसार बहैसियत स्वीकृति पत्र के बा असर है देखो 40 M. 698; 36 I.C. 240. व्याज, बतौर व्याजके कर्ज अदा होने से पहिले दिया जा सकता है। अगर यह शर्त पूरी कर दी जाय तो मियाद का समय और बढ़ाया जा सकता है। व्याज के विषय में लिखकर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर दस्तावेज की पुश्त पर लेख (Endorsement) से व्याज और उसकी अदायगी की तारीख मालूम न पड़े तो उनका साबित करना बहुत ज़रूरी है। मूलधन के हिस्से की अदायगी के विषय में कानून बहुत सख्त है। इसके अदा करने वाले शर्त की खुद कलम से लिखा हुआ होना ज़रूरी है। यह बात नोट कर लेने की है कि कानून के मुताबिक मूलधन की अदायगी किस्तों में नहीं है। उसलिये उस शर्त के कलम से अदायगी लिखना ही काफी है। इन्दराज में यह लिखना ज़रूरी नहीं है कि अदायगी बाबत मूलधनके की जाती है देखो 23 C. 592; 6 M. 281. इस विषय पर अब तक जो कुछ कानूनी विवाद उपस्थित होता था वह पेक्ट सन् १९०८ई० के विवरणसे समाप्त हो जाता है। अब यह स्पष्ट मान लिया गया है कि कर्जे में ‘डिकरी के अनुसार’ कोई भी रुपया शामिल है।

व्याजकी अदायगी—साधारण तौर से ‘व्याज’ का मतलब किसी भी ऐसी चीज़ से है जो रुपया रोक रखने के बदले में दिया जाता है देखो Markly, J.

in C. 283 P. 301. दफा २० के अनुसार 'व्याज' का मतलब व्याज या उसके किसी हिस्से से है 35 A. 378; 20 I. C. 258. मियाद की वचत के लिए व्याज अदा किया जा सकता है इसलिये कर्ज पर व्याज का होना जरूरी है। इस तरह अगर किसी डिकरीमें व्याज न दिया गया हो तो किसी रकम की अदायगी मूलधन के हिस्से की अदायगी मानी जायगी; देखो 22. C. W. N. 325.

व्याज की अदायगी, उसकी यानी व्याज की अदायगी के विचार से ही होना चाहिये। व्याज वाजिबुल्ल अदा होने पर किसी रकम की अदायगी व्याज की अदायगी नहीं कही जा सकती देखो U. B. R. (1892-96) 466; 31 A. 495, मिश्रधन में से किसी रकम की अदायगी, इस बात की विला इतला किए कि यह व्याज की अदायगी है; की जाय तो रकम व्याज की बाबत अदा की गई न मानी जायगी, 31 I. C. 782 (L.). 38. 198; 5 Bom. L. R. 350 79 I. C. 7. व्याज की अदायगी या तो साफ़ साफ़ कहकर होनी चाहिए या ऐसी सुरतों में हो जिससे कि कर्जदार का मंशा मालूम हो, 19 C. W. N. 237; 24 B. 493 P. 499. बार बार क्रिस्त द्वारा अदा की गयी रकम को केवल व्याज के खाते में मान लेने ही से वह व्याज की अदायगी न मानी जायगी, 19 I. C. 825; देखो 31 A. 495; 50 I. C. 709. जहां पर यह शर्त तय हो गयी हो की पहिले व्याज और बाद को मूलधन अदा होगा तो कर्जदार द्वारा कोई इतला न होने पर भी व्योदरे के पास जमा की गई रकम व्याज की अदायगी समझी जायगी; 31 A. 285.

मदियून डिकरी के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक मौके पर साफ़ २ कहे कि यह रकम व्याज की बाबत अदा की जा रही है। यह काफी है अगर वाक्यात इस तरह पर हों जिनसे यही नतीजा निकले कि रकम बाबत व्याज अदा की गयी है 27 C. L. J. 141; 43 M. 812.

जहां कई एक कर्जें हों और खुल्लम खुल्ला बिना बतलाए हुए रकम इतनी अदा की गयी हो कि एक कर्जा को तो व्याज केवल आंशिक रूप से और बाकी व्याजकी सब रकमोंकी अदायगी पूर्ण रूपसे होती होती ऐसी स्थितिमें सब कर्जोंकी कानून मियादसे रक्षा होगी, 13 C. L. J. 138; 51 I. C. 240.

एक रकम " बाबत मूलधन और व्याज " अदा की गई अगर यह नहीं बतलाया गया, कि उसमें से कितना मूलधन और कितना व्याज की बाबत अदा किया गया, तब हुआ कुल रकम व्याज की बाबत अदा की गयी मानी जायगी; 6 I. C. 16 (C); 4 B. L. R. 138; 51 I. C. 240.

अगर किसी कर्ज पर अदा किया गया व्याज ऐसी दस्तावेज रेहन की पुश्त पर दर्ज किया गया हो जिसकी रजिस्ट्री न होने के कारण अदालत के काम का न हो तो यह सूद का अदा किया जाना नहीं कहा जा सकता, 19 B. 663.

अगर कोई रकम बाबत दस्तावेज रेहन के यह न कह कर कि वह व्याज के हिसाबमें दी जाती है अदा की जाय तो यह रकम मूलधन के बाबत अदा की गयी

जानी जायगी वशर्ते कि अदायगीकी बात कर्जदारके खुद दस्तखतसे लिखी गई हो, 44 C. 567; 22 C. W. N. 190.

कभी 'स्वीकृति-पत्र' (Acknowledgment) और 'वादा अदायगी' (Promise to pay) का फर्क जाननेमें कठिनता पड़ती है विशेषकर ऐसे मौकों पर जैसे कि स्वीकृति-पत्र बिना शर्त (Un conditional Acknowledgment) से मतलब वादा अदायगी (Promise to pay) ही माना जाता है। लेकिन ऐसे मौकों पर यह मामला साफ नज़र आता है जहाँकि कुल तादाद रकमका एक हिस्सा अदा किया जाय वहाँ केवल वायदा अदायगी ही हो सकता है न कि स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) 12 I. C. 612 (C)

दफ़ा २० अदायगीकी कोई खास शर्त या तरीके तो नहीं बतलाती। अदायगीके बहुतसे तरीके हैं, 25 C. 844. 852 F.C.। यह आवश्यक नहीं है कि रुपया हो। समझौतेके अनुसार, व्योहरेको दिये जाने पर कोई भी चीज़, जो कर्जके भेज़को हल्का कर सके या ब्याजकी पूर्ति करे, काफी है (72 I. C. 692 (C); 24 B. 493. 500; 24 B. 619. 19 M. 340. 342; 29 M. 234; 1 P. L. J. 412 n) Cf. S. 50 Contract Act। जो चीज़ अदा की जाय वह इस किस्मकी हो कि अगर मुद्दई रुपयेकी वसूलयावीके लिये नालिश करे तो उसके जवाबमें बतलाई जा सके 19 M. 340. कर्जकी अदायगी किसी भी चीज़ द्वारा जिसे कि व्योहरा लेना पसन्द करे की जा सकती है; 24. B. 619.

नौकरी (Labour) से अदायगी करने पर कानूनन मियादसे बचत होती है 35. I. C. 480 (M); 28 M. 234। एक नौकरको दिये गये पेशगी रुपये की वसूलयावीके लिये की गई नालिशमें तय पाया गया कि नौकरीका जारी रक्ता ब्याजकी अदायगीके बराबर था, 33 I. C. 134 (M).

अदायगीका अपनी राज़ी ही से होना आवश्यक है। दफ़ा २० के अनुसार गोलाममें वसूल हुआ रुपया अदा किया नहीं माना जायगा 24. W. R. 20; 6 B. 626; 25 W. R. 249; 80 P. W. R. 1912.

'मूलधन की किस्त' यह आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार उसके खुद दस्तखत से लिखा जावे। आवश्यकता इस बात की है कि अदायगी की बात ज़ाहिर होती हो; 23 C. 592; 6 M. 281; 43 A. 261. लेख से ज़ाहिर यह होना चाहिए कि यह अदायगी बाबत कर्ज ज़ेर वहस की गई है। यह वह हुँडी है तो ज़रूर पेश की जानी चाहिये, 43 I. C. 20 (M) किस्तोंकी अदायगी मियाद ख़तम होने के पहिले होनी चाहिये लेकिन उस वक्त के ख़तम होने से पहिले लिखना नहीं चाहिये; 17 M. 92.

उस तारीख़ को वास्तविक अदान होनेपर भी किस्त का इन्दराज काफी है ऐसा इन्दराज जायज़ स्वीकृति पत्र दफ़ा १९ के अनुसार जायज़ स्वीकृति पत्र (Acknowledgment) माना जायगा; 28 I. C. 15; 10 M. L. J. 25; 26

I. C. 754; दफाके २० अनुसार अदायगी की तारीख का शुमार करना चाहिये नकि इन्दराज Endorsement; 8 I.C. 349.

दस्तखत—किस्त अदा करने की बात, देने वाले शख्सके दस्तखतों में ही होनी चाहिये नकि किसी दूसरे के दस्तखतों में हालांकि उसे कितना ही अधिकार प्राप्त क्यों न हो 23 C. 546; F. B.; 4 P. L. J. 365; 26 B. 246; 1 P. L. J. 474; A. L. J. 628; 44 B. 392; जबकि अदायगी ऐसे शख्स द्वारा की गई हो जो अदायगी की बात लिखने का अधिकारी है यानी इन्दराज व दस्तखत दोनोंही उसीके हाथसे लिखे हुए (In his hand writing) होने चाहिये दस्तखत मुदाभलेह द्वारा और इन्दराज किसी दूसरे शख्स द्वारा किया जाना काफी नहीं है 35 C. 613; 41 B. 166; 4 I. C. 378; 5 L. B. R. 108; 38 M. 438; इसके विरुद्ध (Cantro): एक मुकद्दमें में यह तय किया गया है कि अगर इन्दराज अदाकरने वालों के हस्ताक्षरों में न भी हो तो केवल उसपर उसका हस्ताक्षर (Signature) होना ही काफी है; 99 P. R. 1884. जहां कि अदायगी किसी गुमास्ता के मार्फत हो तो खुद उसेही अपने हाथों से खानापुरी में इन्दराज करे और कर्जदार के हस्ताक्षरों की कोई आवश्यकता नहीं है 54 I. C. 802; (P); 1 Pat. L. J., 474; 35 I. C. 375.

जहां कि एक खातेमें कर्जके अदा करनेके दो शख्स ज़िम्मेदार हों तो यह काफी है कि उनमेंसे एक शख्स इन्दराज कर दे और दूसरा दस्तखत करदे; 71 I. C. 302; 25 Bom. L. R. 354.

जब कि कर्जदार बिना पढ़ा लिखा शख्स है तो ऐसी हालतमें सिर्फ यह काफी है कि कोई दूसरा शख्स इन्दराज कर दे और उसके अंगूठेका निशान वहां पर लगा दिया जाय; 7 M. 55; 7 M. 76; 12 I. C. 23; 2 F. L. T. 355; 28 B. 262. लेकिन अगर किस्तकी अदायगीमें यदि न तो दस्तखत हों और न किसी तरहका निशान ही हो तो यह मियादको बढ़ा नहीं सकता है; 23 C. W. N. 920; 26 B. 247.

किस्तकी अदायगीके वक्त पर कर्जदार द्वारा लिखी गई और दस्तखतकी गई चिट्ठी होने पर मियाद बढ़ जाती है; 27 I. C. 744 (M); 23 C. 592; 44 B. 392 यह तय किया जा चुका है कि जहां किस्तकी अदायगीका एक मात्र सबूत केवल कर्जदारके हकमें एक चिकका काटा जाना ही है तो यह दफा २०की ज़रूरतोंको पूरी करनेके लिये काफी नहीं है; 9M.271; 19A.307. अवश्य ही यह तय हो चुका है कि अगर एक चिक पर (Cheque) कर्जदारके दस्तखत हों और कर्जके किस्तकी अदायगीके बतौर दिया जाय और सकारा जाय तो उससे मियादकी बचत होगी; 42 C. 1043; 19 C. W. N. 724.

डिकरीके कर्जके मूलधनकी किस्त अदा करनेकी बात मदीयून डिकरीमें होना चाहिये; 31 A. 590; 48 I. C. 728. (P). देखो ANto P. 79.

गुमास्ता—दफा १९ और २० के अनुसार किसी नावालिग का वली उसका गुमास्ता (Agent) माना जा सकता या नहीं? यह विषय पहिले दफा ही विवादग्रस्त था। परन्तु सन् १९०८ के ऐक्ट की दफा २१ (२) के अनुसार यह प्रश्न हल होगया है और अब किसी नावालिग का कानूनन वली उसका गुमास्ता (Agent) करार दिया जाता है।

वह शख्स जिसे पावर आफ अटारनी (Power of attorney) हो एजेंट (Agent) माना जायगा; 14 C. W. N. 974. एजेंट के नौकर द्वारा की गयी अदायगी एजेंट की ही अदायगी मानी जायगी; 54 I. C. 318 (M.) एक साझीदार द्वारा की गयी अदायगी से मतलब लिया जाता है कि यह अदायगी दूसरे साझीदारों की ओर से भी की गयी है; 41 M. 427; F. B.; और भी देखो 28 I. C. 845.

नावालिग के फायदे के लिये वाकई-काविज वली के जरिये से की गयी अदायगी मियाद से महफूज करती है देखो 40 I. C. 809 (P) हिंदू लों, दफा २१ के अनुसार एक नावालिग का भाई माता के जीवित रहते हुए, उसका कानूनन सर परस्त नहीं हो सकता; 45 C. 636. मोहमडन लों के अनुसार य जायदाद की वारिस न होने के कारण नावालिग की कानूनन वली नहीं मानी जा सकती 61 P. L. R. 1917.

वह शख्स जो किसी नावालिग के वली मुकर्रर न किये गये हों परन्तु कानूनन बहसियत वली के काम करते हों तो दफा २१ के अनुसार वे कानूनन वायज वली करार दिये जायंगे बशर्ते कि वे नावालिग के फायदे के लिये काम करें 24 M. L. J. 428. 19 I. C. 362.

एक हिन्दू मुस्तरका खानदान के मैनेजर द्वारा की गयी अदायगी खानदान के हर एक मेम्बर को बाध्य करती है; 14 C. W. N. 741.

“अदायगी केवल एक कर्जदार द्वारा इत्यादि”—यहां दफा २१ के अनुसार शब्द ‘केवल’ फालतू नहीं मानना चाहिये इसका मतलब यह है कि एक साझीदार द्वारा लिखा गया और दस्तखत किया हुआ स्वीकृति-पत्र ही केवल दूसरे साझीदारको बाध्य नहीं करता जब तक कि उसे किसी दूसरी तरह अपने साझीदारको बाध्य करनेके लिये विशेष अधिकार प्राप्त न हुआ हो; 10 A 418. 1 दफा २१ दफा १९ और दफा २० का संशा यह कि किसी मामलेमें फरीकैन मुआहिदामेंसे केवल एक ही शख्स द्वाराकी गई कार्रवाईसे दूसरे फरीकैन साधारण तौर पर जिम्मेदार न होंगे; 17 B. 173; 18 A 458.

एक विधवा द्वारा लिखी गयी दस्तावेज रेहन की बाबत उसके उत्तराधिकारियों में से सिर्फ कुछ ही ने अदायगी की हो तो उससे दूसरे बाध्य न होंगे 45 I. C. 351 (P.).

अगर किसी मृत कर्जदारके वारिसोंमेंसे केवल एक ही द्वारा न्याज अदा किया जाय तो उससे दूसरे वारिसोंके लिये मियाद बढ़ नहीं जायगी; 14 I. C. 129.

नये मुद्दई या मुद्दाअलेहोंके शामिल करनेका असर

१ 'एक मुकद्दमा के दाखिल होने पर, यदि नया मुद्दई या मुद्दाअलेह किसी के एवज में या ऊपर से शामिल किये जायें तो जहां तक उसका सम्बन्ध मुकद्दमें से है उस समय से खयाल किया जायगा जब से कि वह फरीक बनाया गया है।

२ ऐसे मुकद्दमें में यह दफा कतई लागू न होगी जब उस मुकद्दमें के दौरान में फरीकैन, किसी हक के इन्तकाल या हस्तान्तरित होने पर बढाए जाय या स्थानापन्न माने जाय या जहां कि मुद्दई, मुद्दाअलेह बनाये जाय या जहां कि मुद्दाअलेह, मुद्दई बनाये जाय (दफा २२)

व्याख्या:—सन् १९८ ई०के ऐक्ट द्वारा उप दफा (२) की तरमीम इस प्रकार हुई है कि दौरान मुकद्दमें में इन्तकाल हक में सिर्फ मौत की वजह ही नहीं शामिल है बल्कि दूसरी सब वजहें शामिल हैं जैसे इन्तकाल दस्तावेज ।

दफा २२ सिर्फ मुकद्दमोंपर ही लागू होती है न कि अर्जियोंपर लागू होती है 2 P. L. T. 619; 49 I. C. 341 यह इजराय डिकरीकी कार्रवाई पर लागू नहीं होती 14 C. W. N. 752 । जहां तक कि बढ़ाये गये फरीकैनका सम्बन्ध है, एकतरफा डिकरीकी मंजूरीके लिये दी गई अर्जी उस समयकी बनाई गई नहीं मानी जा सकती जब कि बढ़ाये गये फरीकैन बाकायदा शामिल किये गये हों। 6 P. L. J. 463 ।

दफा २२ (१) ऐसी जगह लागू नहीं होती जहां कि मुद्दाअलेह, तरतीबी मुद्दई बनाया जाय 19 C. W. N. 1269; 85 P. R. 1912; 28 M. L. J. 147; 13 C. W. N. 186; 38 C. 342.

इस दफाका असर यह है कि मुकद्दमेंमें किसी गलतीका ठीक किया जाना आर्डर १ रूल १० के अनुसार मियाद मुकद्दमासे पहिले, जरूरी है; 33 M. 115. दफा २२ (१) उन मुकद्दमोंमें लागू होती है जिनमें कि वाजिब, शर्शोंकि फरीकैन न बचाये जानेकी गलती हो न कि ऐसे मुकद्दमोंमें जोकि शुरूमें तो बाकायदा दाखिल किये गये हों लेकिन बादमें इन्तकाल हकवाी दजहसे दोष आगया हो, और दूसरी तरहके मामलोंमें मुकद्दमेंकी कार्रवाई जारी रहनेका हुक्म होना चाहिये; 20 C. W. N. 833 P. C; 35 I. C. 323 ।

जहां कि असली मुद्दइयान और बादको शामिल किये गये मुद्दइयान का मंशा एक ही हो, परन्तु असली मुद्दइयान ने मुकद्दमा चलाया हो और मियाद खतम होजाने पर बाद को ये मुद्दइयान और शामिल कर लिये गये हों तो कुल मुकद्दमा रद्द होजाता है; 6 C. 8.16; 17 C. 150; 162; 8 P. R. 1880; 7 C. L. J. 251; 1 P. L. J. 468; 7 B. 217; 33 E. R. 1897. मुकद्दमें में किसी शर्श के अदम इस्तेमाल के विरुद्ध एतराज उठाने का काम मुद्दाअलेह का है और अगर ऐसा सवाल न उठाया गया तो वह मुकद्दमा जिसमें कि कुछ

मुद्दरयान मियाद के समयके गुजर जानेके बाद शामिल हुए हों, रद्द नहीं होगा, देखो 15 B. 297; 26 A. 528.

कोई मुकद्दमा दाखिल किये जानेकी तारीख पर बाकायदा दाखिल किया गया था या नहीं इसकी परीक्षा इस प्रकार है कि अगर अदम इस्तेमाल (Non joinder) की वजहसे मुकद्दमेको कोई मुकसान होता हो तो कुछ फरीकैनोंका मियाद खतम होनेकी तारीखके बाद भी शामिल होनेसे कुछ असर नहीं पड़ता लेकिन अगर अदम इस्तेमाल (Non joinder) की वजहसे मुकद्दमेको मुकसान हो तो ज़रूरी फरीकैनोंके मियाद खतम होनेके बाद शामिल होनेकी वजहसे मुकद्दमेका खारिज कर दिया जाना ज़रूरी हो जायगा; 43 B. 575. मुख्य बात यह है कि भाया शामिल किये गये फरीकैन आवश्यक अंग (Necessary party) हैं या नहीं। अगर वह आवश्यक नहीं हैं तो मुकद्दमा खारिज नहीं किया जा सकता; A. I. R. 1293 (Lalh) 438 (1); 26 C. W. N. 438; 33 A. 272; 33 C. 1079; तथा इस सम्बन्धमें संग्रह ज़ावता दीवानीके भाँर १ रुल ९ को भी देखो।

अगर किसी मुकद्दमेमें मियाद खतम होनेके बादके शामिल किये गये फरीकैन केवल नाम मात्रके लिये हों तो मुकद्दमा रद्द नहीं हो जाता; 33 A. 272; 15 C. W. N. 321. P. C.

दफा २२ उन ग़लत धयानोंमें लागू नहीं होती जिन्हें कि फरीकैनोंने भाँर १ रुल १० (१) के अनुसार दिया हो; 17 B. 413; 18 A. 198 F. B; 7 C. W. N. 575; 329. C. 872 (C); 21 A. 3461.

जहाँकि किसी शरूशने पहिले तो मुकद्दमा अपने नामसे दायर किया हो और कि इस प्रकार की तरमीम की हो कि वह कम्पनी की तरफ से लड़ रहा है तो यह दफा २२ के अनुसार किसी नये मुद्दे को शामिल करना नहीं है; 33 I. C. 357; 30 M. L. J. 57; 7 A. 284, और इसी प्रकार जहाँ मुकद्दमा देवमूर्ति (Idol) की ओरसे किसी मैनेजर के नाम से दाखिल किया गया हो; 33 A. 735 या जबकि अपनी ओरसे चलाये गये मुकद्दमेमें (शिवायत) की ओरसे चलाये जानेकी तरमीमकी जाय; 19 C. W. N. 1193; 25 I. C. 945 (M) लेकिन अगर मुकद्दमेके अर्जीदावेमें तरमीम इस प्रकार असर पैदा करता है कि उससे एक नया मुकद्दमा बन जाता है तो दफा २२ लागू नहीं होगी 24 C. W. N. 104.

नीलामको मंखुल करने के लिये दीगयी अर्जी में अगर खरीदार नीलाम, जो कि एक ज़रूरी फरीक है, मियाद खतम होने के बाद शामिल किया गया हो तो अर्जी रद्द हो जायगी; 50 I. C. 5 (C); 62 I. C. 61 (P).

फरीकैनों के शामिल होने से उनके लिए दीगई अर्जी के सम्बन्ध में किसी भी प्रश्न से अदालत की कार्रवाई को रोक नहीं होती परन्तु शामिल किया जाने वाला शरूस (Joinder) इस बात के बिना लिहाज़ किये हुये, कि उसके

मियाद गुज़र जाने के बाद शामिल होने पर मुकद्दमें पर क्या असर पड़ेगा. शामिल नहीं किया जासकता, 10 C. W. N. 551; 33 C. 613; 28 B. 11 35 C. 519; 11 C. W. N. 35 F. B.

नोट—इस कानूनकी आगेकी दफाओंकी भाषा इतनी साफ़ है कि उनपर किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।



इंडियन वालण्टियर्स ऐक्ट

ऐक्ट नं० २० सन् १८६९ ई०

इक प्र सिद्धि लाल नाम दीर्घ
०३ १३३१३३०३०३ इक प्र

इण्डियन वालण्टियर्स ऐक्ट

ऐक्ट नं० २० सन १८६९ ई०

[तारीख १० सितम्बर सन १८६९ को पास हुआ]

वालण्टियर कोर की सुव्यवस्था और शिक्षा के सम्बन्धमें व्यवस्था करने और उन्हें कतिपय अधिकारोंके

देने सम्बन्धी ऐक्ट

वृत्ति श्रीमान् सम्राट् की बहुत सी राजभक्त प्रजा ने जान और मालकी रक्षा और शान्ति बनाए रखने के निमित्त, अपनी इच्छा से अपनी सेवायें भेंट की हैं और सरकार (गवर्नमेंट) की मजूरीसे उन्होंने इस कामके लिए नियुक्त किये गए अधिकारियों के अधीन मिलिटरी कोर (फौज) से सम्बन्ध जोड़ लिया है और उसमें अपना नाम लिखा लिया है, और यह उचित जान पड़ता है कि ऐसे कोर की शिक्षा और सुव्यवस्था के लिए नियम बनाये जायें; और उसके सदस्यों (मेम्बर्स) को कुछ अधिकार दिए जायें; इसलिए यह नीचे लिखा हुआ कानून जारी किया जाता है:—

प्रारंभिक विवरण

क्लॉज १ संक्षिप्त नाम

इस ऐक्ट का नाम 'इण्डियन वालण्टियर्स ऐक्ट सन १८६९ ई०' होगा ।

क्लॉज २ ऐक्ट का विस्तार

इस ऐक्ट का विस्तार समस्त ब्रिटिश भारत में होगा और (जहां तक इसका सम्बन्ध ब्रिटिश प्रजा से है) उन देशी राजाओं के राज्यों और उन राज्यों में होगा जो श्रीमान् सम्राट् के अधीन हैं ।

क्लॉज ३ ऐक्टकी मंसूखी

ऐक्ट नं० २४ सन १८७० ई० के अनुसार ऐक्ट नं० २३ सन १८५७ ई० मंसूख किया गया ।

क्लॉज ४ परिभाषा

(१) 'मजिस्ट्रेट' शब्द का अर्थ, प्रेजीडेन्सी टाउन्स के सीमा के भीतर

चीफ प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट और इस सीमा के बाहर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, जो जस्टिस आफ दि पीस, (Justice of the Peace) है।

२ वालण्टियर लोग उस समय अपनी 'असली छबटी' पर समझे जायेंगे—

(अ) जब कि उन्हें अकेले अथवा स्थायी सेना (Regular forces) के साथ शिक्षा दी जा रही हो या कचायद कराई जा रही हो, या

(ब) जब वे किसी स्थायी सेना (Regular forces) में शामिल कर दिए गए हों या और प्रकार से उसके साथ अथवा एक अंग होकर काम कर रहे हों, या

(स) जब राज-शासनकी सहायतामें काम कर रहे हों।

३ "सिविल डिस्ट्रिक्ट" का अर्थ वह डिस्ट्रिक्ट (ज़िला) है जिसकी परिभाषा संग्रह ज़ाबता दीवानी में की गई है।

वालण्टियर-कोर का संगठन और उसका विच्छेद

दफा ५ कोर का संगठन

भारत के सपरिषद् गवर्नर जनरल की अथवा स्थानीय सरकार की मजूरी से वालण्टियरों के कोर (दल) ब्रिटिश भारत अथवा उक्त राज्यों के किसी भी हिस्से में तैयार (संगठित) किए जा सकते हैं।

दफा ६ कमान्डिंग अफसर का सर्टीफिकेट, भर्ती कर लिए जाने का प्रमाण होगा

ऐसे कोर (दल) में भर्ती कर लिए जानेका सर्टीफिकेट, जिसपर उसके कमान्डिंग अफसर के हस्ताक्षर हों, उस भर्ती का प्रकट प्रमाण होगा।

दफा ७ कोर (दल) को तोड़ देने अथवा उसके सदस्योंको

अलग कर देने का अधिकार

भारत के सपरिषद् गवर्नर जनरल अथवा स्थानीय सरकार को अधिकार होगा कि वह इस ऐक्ट के अथवा ऐक्ट नं० २३ सन् १८५७ ई० के नियमानुसार तैयार किए गए अथवा भर्ती किए गए किसी भी कोर (दल) को तोड़ दे अथवा इस कोर (दल) से उसके किसी भी मेम्बर (सदस्य) को अलग कर दें।

दफा ७ (ए) कुछ अवस्थाओंमें कमान्डिंग अफसर को रजिस्टर से वालण्टियरों का नाम काट देने का अधिकार

१ किसी वालण्टियर-कोरके कमान्डिंग अफसरको अधिकार होगा कि वह किसी भी वालण्टियरका, जो बिना छुट्टी छः माससे कम गैर-हाज़िर नहीं रहा है, अथवा जिसने दफा १३ के सिवाय और किसी प्रकार से कोर (दल) से सम्बन्ध

छोड़ दिया है, अथवा जिसका नाम दो साल तक बराबर अयोग्य (Non-officio) पुरुषों की श्रेणी में लिखा हुआ चला आता है, नाम रजिस्टर से काट दे, परन्तु अपने अधीन कोर के अधिकारी (अफसर) का नाम इस प्रकार नहीं काटा जा सकता।

२ हर एक ऐसे वालण्टियर की निस्वत, जिसका नाम रजिस्टर से काट दिया गया है, यह समझा जायगा कि वह उस कोर (दल) से अलग कर दिया गया है।

आर्मी ऐक्ट का प्रयोग

दफा ८ वालण्टियरों के ऊपर आर्मी ऐक्ट का प्रयोग किया जायगा, जहां तक कि उसका सम्बन्ध अधिकारियों (अफसरों) से है

वालण्टियर-कोर के प्रत्येक सदस्य (मेम्बर) के सम्बन्ध में, उन सभी फौजी अपराधों के लिए जिनका वह अपनी "असली ड्यूटी" पर होने की दशा में अथवा असली फौजी काम करने की दशा में दोषी पाया जाय, आर्मी ऐक्ट का प्रयोग किया जायगा, जहां तक कि उसका सम्बन्ध अधिकारियों (अफसरों) से है और जहां तक वह इस ऐक्ट के नियमों से सम्बन्ध रखता है।

सैनिक न्याय सभा (Court Martial)

दफा ९ जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दीगयीं सजायें

कोर का कमांडिंग अफसर स्थानीय सरकार की मंजूरी लेकर, उन फौजी अपराधों की जांच करने के लिए जिनका इस कोर का कोई भी सदस्य (मेम्बर) अपनी 'असली ड्यूटी' पर होने के समय दोषी पाया जाय, जनरल कोर्ट मार्शल बुला सकेगा।

इस कोर्ट मार्शल (सैनिक न्याय-सभा) द्वारा दिया गया सजा का हुक्म तब तक अमल में न लाया जायगा, जब तक कि उस सारी कार्रवाई की रिपोर्ट स्थानीय सरकार को न कर दी जाय और वह उस सजा के हुक्म की मंजूरी न दे देवे।

स्थानीय सरकार को अधिकार होगा कि वह इस हुक्म को बदल कर हल्के रूप का हुक्म दे देवे, अथवा अपराधी को क्षमा (माफ) कर दे।

दफा १० जनरल कोर्ट-मार्शल में कौन कौन शामिल होंगे

जनरल कोर्ट-मार्शल में कोर के कमसे कम नौ सदस्य शामिल होंगे और कोर के प्रत्येक सदस्य, चाहे वह अधिकारी (अफसर) हो या न हो, ऐसी कोर्ट मार्शल में बैठकर उसके सदस्य की हैसियत से काम कर सकेगा।

दफा ११ रेजीमेण्टल कोर्ट-मार्शल

रेजीमेण्टल कोर्ट-मार्शल को कोरका कमाण्डिंग अफसर बुला सकता है और उसमें कोरके कमसे कम तीन सदस्य सम्मिलित होंगे ।

दफा १२ इस ऐक्ट के अनुसार बुलाई गई कोर्ट-मार्शल की कार्रवाई

इस ऐक्टके अनुसार जो कोर्ट-मार्शल आमंत्रित किया जाय उसकी कार्रवाई उन कानूनों और प्रथाओंके अनुसार कीजायगी जोकि उक्त, ऐक्ट आर्मीके अनुसार आमंत्रित कीगई कोर्ट-मार्शलके सम्बन्धमें बताए गए हैं । परन्तु इसके (आर्मी ऐक्टके) जो कानून इस (वालण्टियर्स) ऐक्टके विरुद्ध होंगे छोड़ दिए जायंगे ।

कोरसे नाम वापस लेना

दफा १३ कोर छोड़ देनेका अधिकार

किसी भी ऐसे शख्सको, जिसका नाम वालिण्टियर कोर के सदस्योंकी सूचीमें दर्ज है, चाहे वह ऐसे कोरका अफसर निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो अथवा नहीं, अधिकार है कि वह सिवाय उस दशाके जब कि वह असली छुट्टी पर हो या फौजी काम पर हो, सात दिन पहिले अपने इस ह्रादेकी कोरके कमाण्डिंग अफसर को लिखित नोटिस देकर या बिना ऐसी नोटिस दिए ही, अगर उस कोरका कमाण्डिंग अफसर इसे उचित समझे और उसे ऐसा करने की आज्ञा दे देवे, कोर छोड़ दे ।

दफा १४ अफसरोंको दिये गए अधिकार उस समय बन्द हो जायंगे जबकि वे अपनी खुशीसे काम से अलग (रिटायर) हो जायं या बर्खास्त कर दिये जायं

वालण्टियर-कोरके किसी सदस्यको दिए गए कुल अधिकार, जिनके अनुसार वह ऐसे कोर (दल) में कोई अधिकारी (अफसर) नियुक्त हुआ हो, उस समय बन्द हो जायंगे जब वह अपनी खुशीसे उस कोरसे अलग (रिटायर) हो जाय अथवा बर्खास्त कर दिया जाय ।

दफा १५ कोरको छोड़ देने वाले मेम्बरों (सदस्यों) द्वारा सरकारी हथियारोंका उसके हवाले कर दिया जाना

वालण्टियर-कोरके प्रत्येक सदस्य (मेम्बर) को, जिसे सरकार (गवर्नमेण्ट) की ओरसे हथियार, गोली-बारूद, युद्धकी सामग्री अथवा वर्दी (Uniform) दी गई हो,

या जो सार्वजनिक मालखाने (Public stores) या सार्वजनिक खर्चसे दी गई हो इस कोरके छोड़ देने पर, या

उसको उससे अलग होने या बर्खास्त कर दिए जाने पर, या

जब उसे उस कोरके कमाण्डिंग अफसर की ओरसे ऐसा करने की आज्ञा मिले, या

जब वह कोर तोड़ दिया जाय,

उस कमाण्डिंग अफसरको या, उस शख्सको जिसे वह कमाण्डिंग अफसर इसके लेनेके लिए नियुक्त करेगा, वे कुछ हथियार, गोला-बारूद, युद्धकी सामग्री और धर्ती (Uniform) अच्छी हालतमें वापस कर देने होंगे। उनके मुनासिब इस्तेमाल से उनमें जो कुछ भी कमी या खराबी आजायगी उसका खयाल न किया जायगा;

और अगर वह ऐसा न कर सका, तो उसे इसके बदलेमें उतनी रकम उभा करनी होगी जिसे रेजीमेण्टल कोर्ट-मार्शल, जिसका संयोजक उस कोर्ट का कमाण्डिंग अफसर होगा, तय करेगी। इस फैसलेकी एक नकल, जिस पर उस कोर्ट मार्शलके प्रेज़ीडेंट (सभापति) के हस्ताक्षर होंगे, उस ज़िलेकी प्रारम्भिक दीवानीके अधिकार रखने वाली खास अदालतको भेज दीजायगी जिसमें कि वह फंसला दिया गया हो, और वह अदालत उसकी इस प्रकार इजरा करेगी मानो वह जायता दीवानीके अनुसार दी हुई रुपयेकी डिकरी है।

कार्यकी स्थानीय सीमा (Local Limits of Service)

धारा १६ कार्य करनेकी स्थानीय सीमा

वालण्टियरोंके कोर अथवा प्लटनका कोई भी सदस्य (मेम्बर) सिवाय समुद्री सेनाके वालण्टियरोंके, बिना अपनी राजीके इस बातके लिए बाध्य न होगा कि वह उस सिविल डिस्ट्रिक्टकी सीमाके बाहर जिसमें वह भर्ती किया गया है, या, जब किसी कोर या प्लटनमें ऐसे वालण्टियर शामिल हैं जिनकी भर्ती एक से अधिक सिविल डिस्ट्रिक्ट्समें हुई है तो, उस प्रांतकी सीमाके बाहर, जिसमें वे ज़िले शामिल हैं, कार्य करने के लिए या ड्यूटी पर जाय; और

समुद्रीय वालण्टियर कोरका कोई भी सदस्य इस बातके लिए बाध्य न होगा कि वह, बिना अपनी राजीके, उस बन्दरगाह की सीमा के बाहर कार्य या ड्यूटी पर जाय। इस बन्दरगाहमें वह शहर या कस्बा, जिसके आधार पर उस कोरका नाम रखा गया है, और उसके आस पासके गांव, वे नदियां और समुद्र के तंग रास्ते, जिनमें होकर बेड़े खेपे जाते हैं और वहांको जाने वाले रास्ते, शामिल समझे जायंगे

लेकिन शर्त यह है कि स्थानीय सरकार या उस डिवीज़नका कमिश्नर या कोई दूसरा अधिकारी जिसे इस सम्बन्धमें स्थानीय सरकारकी ओरसे अधिकार

दिया गया हो, किसी खास कोर या कोरके किसी हिस्से को या किसी कोर के किसी एक सदस्य या किन्हीं सदस्योंको, उनका नाम लेकर, काम करने से मुक्त कर सकता है। ऐसा मुक्त किया जाना, समय अथवा रकबा या दोनोंके सम्बन्धमें, या तो पूर्ण रूपसे या आंशिक रूप से हो सकता है एक अंशके सम्बन्ध में जैसा कि वह अधिकारी, जिसे इस बारेमें अधिकार दिया गया है, उचित समझे।

नियम (Rules)

दफा १७ कमांडिंग अफसर को नियम बनानेका अधिकार जिनका मानना सदस्योंके लिये अनिवार्य (लाज़िमी) होगा

वालण्टियरोंके प्रत्येक कोर के कमांडिंग अफसरको अधिकार होगा कि वह उन समयों और उन तरीकोंके सम्बन्धमें व्यवस्था करने के लिए नियम बनावे जिन पर और जिनमें कोरके और उसके भिन्न भिन्न सदस्यों या दलोंके कार्योंका सम्पादन किया जाना चाहिए।

ऐसे नियमोंके सम्बन्धमें जब स्थानीय सरकार अपनी स्वीकृति दे देगी तब उनको मानने के लिए वह कोर और उसके भिन्न भिन्न सदस्य बाध्य होंगे।

दण्ड (Penalties)

दफा १८ ड्रिल अथवा परेडके अलावा असली ड्यूटी पर हाज़िर न होना

अगर वालण्टियर कोरका कोई भी सदस्य, ड्रिल अथवा परेड के अलावा असली ड्यूटीकी निस्वत आगाह कर दिए जाने पर, बिना किसी माकूल हीलाके ऐसी ड्यूटी पर हाज़िर न होगा तो जनरल कोर्ट-मार्शल द्वारा अपराधी ठहराए जाने पर वह जुर्मानेके दण्डका, जो एक सौ रुपयेसे अधिक न होगा, या कोरसे साधारण तौरसे बर्खास्त कर दिये जाने का, या इस तरह बर्खास्त कर देनेका भागी होगा कि वह फिर उसमें शामिल न हो सके।

दफा १९ ड्रिल अथवा परेडमें हाज़िर न होना

अगर ऐसे कोरका कोई भी सदस्य (मेम्बर) बिना किसी माकूल हीलाके ऐसे समयों पर ड्रिल अथवा परेड में हाज़िर न होगा जो इस काम के लिए नियत होंगे,—

दूसरे छोटे छोटे सैनिक अपराध—

या अपनी ड्यूटी ठीक तौर पर न करने या सेना सम्बन्धी दूसरे अपराध का दोषी पाया जायगा, जिसके लिए उस कोरके कमाण्डिंग अफसर की राय में थोड़ा सा जुर्माना काफी सज़ा होगी।

तो वह ऐसे जुर्मानेका देनदार होगा जो रेजीमेंटल-कोर्ट मार्शल उसके हार करे, पर जो पचास रुपएसे अधिक न होगा।

दफा २० जुर्माना न देने पर सजा

अगर ऐसे कोरका कोई भी सदस्य (मेम्बर) किसी ऐसे जुर्मानेको, जो उस पर किसी कोर्ट-मार्शल (सैनिक न्याय सभा) ने किया हो, उस समय के भीतर, जो उस कोरके कमाण्डिंग अफसरने नियत किया है, न देगा या देने से इन्कार करेगा, तो उक्त कमाण्डिंग अफसर उसे उस कोरसे बर्खास्त कर सकेगा; और ऐसी हर एक बर्खास्तगीका इन्दराज कर लिया जायगा और उसकी रिपोर्ट सानीय सरकारको कर दी जायगी।

दफा २१ वालण्टियरोंको अपनी ड्यूटी करते समय रोकने या उन पर आक्रमण करनेके लिये दण्ड

जो कोई भी शख्स, ऐसे कोरके किसी सदस्यको अपनी ड्यूटी करते समय रोकेंगे या उस पर आक्रमण करेंगे अथवा भारतीय दण्ड विधान (ताजीरात हिन्द) के अर्थमें, रोकने के लिए या आक्रमण करने के लिए किसी शख्सको रोकसादेगा, वह किसी मजिस्ट्रेटके सामने अपराधी सिद्ध होने पर, जुर्मानेके दंड का, जो दो सौ रुपएसे अधिक न होगा या कैदका, जिसकी मुदत छः मास से अधिक न होगी या दोनोंका भागी होगा।

दफा २२ जुर्मानाका वसूल किया जाना

किसी ऐसे जुर्मानाके अदा न किए जाने पर जो किसी कोर्ट-मार्शलने इस दफ्तेके अनुसार किया हो, जुर्माना करने वाली कोर्ट-मार्शलके हुक्मकी एक नकल जिसपर ऐसी अदालत (कोर्ट-मार्शल) के प्रेज़ाईडेंट के हस्ताक्षर होंगे, उस प्रेज़ाईडेंसी टाउन या ज़िलेके, जिसमें कि वह जुर्माना दिया गया हो, किसी मजिस्ट्रेटके पास भेज दी जायगी और इस पर वह जुर्मानेको इस प्रकार वसूल करा देगा मानों स्वयं उसी ने यह जुर्माना किया हो।

दफा २१ के अनुसार किया हुआ जुर्माना उस रीति (तरीका) से वसूल किया जा सकेगा, जो उस समय प्रचलित किसी भी कानूनमें उस जुर्माना की वसूली के लिए बतकाया गया हो जो किसी फौजदारी अदालतने किया हो।

वालण्टियरोंके अधिकार

दफा २३ लोगोंको निःशस्त्र करनेका अधिकार

वालण्टियर कोरके किसी भी सदस्य (मेम्बर) को, जब कभी वह बर्हसि-त उस कोरके मेम्बरके अपनी ड्यूटी पर काम कर रहा हो, और उस समय वह कोई कहीं पर भी हो, अधिकार होगा कि वह किसी भी शख्ससे, जो श्रीमान्

सम्राटकी सेना या समुद्रीय सेनाका नौकर या पुलिस अफसर न हो, और जो सूर्यो-
स्त और सूर्योदयके बीच किसी सार्वजनिक सड़क, रास्ता या दूसरे सार्वजनिक
स्थान पर, बिना पुलिस कमिश्नर या दूसरे अफसरसे, जिसे इस प्रकार पास या
लैसन्स देनेका अधिकार है इस कामके लिये कोई पास या लैसन्स हो हाथमें तलवार,
भाला, बन्दूक या दूसरा युद्ध सम्बन्धी अस्त्र (हथियार) लिए हुए मिले, वह हथि-
यार छीन ले ।

और उसे उस आदमी के हथियार छीन लेने का भी अधिकार होगा जो
किसी समय कानून या किसी सरकारी हुक्म के विरुद्ध किसी सार्वजनिक
सड़क, रास्ता या दूसरे सार्वजनिक स्थान में हथियार लिए हुए पाया
जाय; और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह इस तरह हथियार बांधे हुए
पाए गए किसी व्यक्तिको पकड़ कर किसी पुलिस अफसर के हवाले कर दे,
ताकि उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जा सके ।

छीने गये हथियारों की ज़ब्तगी

और इस तरह छीने गए हथियार या तो, ज़ब्त करके सरकार में जमा कर
दिए जायेंगे या कानून अथवा सरकार के हुक्मों के अनुसार उनमें कोई दूसरी
कार्रवाई की जायगी ।

दफा २४ सार्वजनिक शान्ति-भंग होने को रोकना, सैर-
कानूनी संस्थाओं को भंग करने, और कुछ ऐसे
आदमियों के पकड़ लेने का अधिकार जिनपर
सन्देह किया जाता हो

ऐसे कोर (दल) के किसी भी सदस्य (मेम्बर) को अधिकार होगा
कि वह, जब कभी वह अपनी झूटी पर हो, सार्वजनिक शान्ति को भंग किए
जाने के किसी प्रयत्न को रोके, और उन लोगों को अलग अलग कर दे, जिनको
वह बिना किसी उचित कारणके सूर्यास्त और सूर्योदयके पहिले किसी भी सार्व-
जनिक सड़क, रास्ता या दूसरे सार्वजनिक स्थान में, जिसमें उक्त कोरका वह
व्यक्ति अपनी झूटी कर रहा हो, पांच अथवा अधिक संख्यामें एकत्रित (जमा)
हुए पावे ।

और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह किसी भी शख्स को, जिसपर
यह उचित सन्देह किया जाय कि उसने राज्य के प्रति कोई अपराध किया है
या करने वाला है, अथवा यह कि उसने, भारतीय दण्ड विधान के
अर्थ में, किसी दूसरे शख्स को ऐसा अपराध करने में उकसाया है या उक-
साने वाला है, पकड़ कर उसे किसी पुलिस अफसर के हवाले कर दे ।

विविध विषय

दफा २५ घोड़ा-कर (Horse-tax)-से छुटकारा

हर घोड़-सवार अफसर को, और वालण्टियर कोरके हर एक घोड़-सवार अद्वली को, तथा ऐसे कोर के हर एक मेम्बर (सदस्य) को, जब कि वह ऐसे कोर के अद्वारोही दल (troop of Cavalry) का सदस्य है, अधिकार होगा कि वह एक घोड़ा रख सके, जिसके लिए उसे कोई भी म्यूनीसिपल बोर्ड के या दूसरा टैक्स, जो घोड़ों पर लगाया जाता है, देना न होगा।

दफा २६ इस ऐक्ट के अनुसार की जाने वाली बातों के लिए नालिशें

किसी भी शख्स के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के सम्बन्ध में जो इस ऐक्टके अनुसार की गई हों... .. उस शख्सको एक महीना पहिले इस इरादे का और उसके कारण सहित लिखित नोटिस दिए बिना कोई भी नालिश या दूसरी कार्रवाई दायर अथवा की न जा सकेगी, और न काफ़ी तावान दे दिए जानेके बाद अथवा नालिश या दूसरी कार्रवाईके बिनाय मुखासमत पैदा होने के समय से तीन साल की मियाद गुज़र जानेके बाद ही ऐसा किया जा सकेगा।

न्यूनता-पूरक नियम (Supplemental)

दफा २७ युद्ध-क्षेत्र कार्य के लिए वालण्टियरकोर का बुलाया जाना

१ वास्तव में आवश्यक कारण उपस्थित हो जाने पर या उनके उपस्थित हो जाने की आशङ्का होने पर [इस अवसर की घोषणा पहिले सपरिषद् गवर्नर साहब कर देंगे और इस सम्बन्ध में गज़ट आफ् इण्डिया में विज्ञप्ति निकाल दी जायगी] सपरिषद् श्रीमान् गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वे वालण्टियरों के किसी कोर को या उसके किसी हिस्से को युद्ध-क्षेत्र में काम करने के लिए बुला लें।

२ किसी कोर या उसके किसी हिस्से के कुल सदस्य, जब तक कि वे निर्वल होने के कारण युद्ध-क्षेत्र के कामों के अयोग्य न सिद्ध कर दिए जायें, इस बात के लिए बाध्य होंगे कि वे सपरिषद् श्रीमान् गवर्नर जनरल की आज्ञा-नुसार एकत्रित हों, और उनके हुकमों के अनुसार उस सीमा के भीतर रवाना होजायें जिसका वर्णन इसके पहिले किया जा चुका है; और ये वालण्टियर कोर या उनके हिस्से इस प्रकार बुलाए जाने के समय से युद्ध-क्षेत्र में काम करते हुए (On actual military service) समझे जायेंगे।

लेकिन शर्त यह है कि स्थानीय सरकार या उस डिप्टी-मैजिस्ट्रेट के कमिश्नर अथवा किसी दूसरे अधिकारी को, जिसे इस सम्बन्ध में स्थानीय सरकार ने अधिकार दिए हों, अधिकार होगा कि वह किसी खास कोर या कोर के किसी खास हिस्से को अथवा कोर के किसी एक सदस्य या सदस्यों को, उनका नाम बतला कर, इस काम (Service) से मुक्त कर दे। इस प्रकार का मुक्त किया जाना समय या रकबा या दोनों के बारे में था तो कुल के सम्बन्ध में होगा या उसके किसी एक हिस्से के सम्बन्ध में, जैसा कि वह अधिकारी उचित समझे।

३ कोई वालण्टियर कोर या उसका कोई हिस्सा बुला लिए जाने के बाद, उस समय युद्ध-क्षेत्र के कामों से मुक्त कर दिया गया समझा जायगा जब गज़ट आफ इण्डियामें इस बातके सम्बन्धमें विज्ञप्ति निकाल दी जाय जिसमें इस बातकी घोषणा कर दी जाय कि वह समय निकल गया, इससे पहिले अथवा पीछे नहीं।

लेकिन शर्त यह है कि सपरिषद् श्रीमान् गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वे किसी भी समय किसी ऐसे कोर या कोर किसी हिस्सेको युद्ध क्षेत्रके कामों से मुक्त कर दें।

४ वालण्टियरों के किसी कोर या कोरके किसी हिस्सेको युद्ध-क्षेत्र के कामों से अलग किए जानेके पहिले सरकार को पहिले वहां पर उपस्थित वालण्टियरों का अपने घर लौटने के सम्बन्ध में प्रबन्ध करना होगा।

दफा २८ वालण्टियरों को अलाउन्स देने के सम्बन्ध में नियमों के बनाने का अधिकार

१ सपरिषद् श्रीमान् गवर्नर जनरल को अधिकार है कि वे—

(अ) युद्ध-क्षेत्र के कामों के लिए बुलाए गए वालण्टियरों को, दी जाने वाली रकमों, और उनके आने-जाने और उनके लिए रसद वगैरा भेजने के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए; और

(आ) उनको वेतन, पेशन, बख्शीस, भत्ता और इनाम वगैरा देने के लिए नियम बना सकें।

२ सपरिषद् श्रीमान् गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वे ऐसे नियमों या उनके किसी हिस्से को उन वालण्टियरों के सम्बन्ध में लागू कर सकें जो किसी मजिस्ट्रेट अथवा दूसरे अधिकारी द्वारा राजशासन में सहायता देने के अर्थ बुलाए गए हों।

और उनको यह भी अधिकार होगा कि वे ऐसी दशा में, किसी कानून के होते हुए भी, यह हुक्म दे सकें, कि इन दी जाने वाली रकमों का खर्चा कौन बदाश्त करे और इन नियमों के अनुसार उनको रसद वगैरा कौन ले जायगा।

दफा २९ उन वालण्टियर कोरों के सम्बन्ध में, जिनके सदस्य एक से अधिक प्रान्तों में भर्ती किए गए हों कार्य-वाई करने के लिये स्थानीय सरकार की नियुक्ति

जब किसी कोर में ऐसे वालण्टियर शामिल हों, जो एक से अधिक अधीनस्थ प्रान्तों में भर्ती किए गए हैं, तो सपरिषद् श्रीमान् गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वे गज़ट आफ् इण्डिया में विज्ञप्ति निकाल कर इस बात की घोषणा कर दें कि इस ऐक्ट के कुल अथवा कुछ कामों के लिए कौनसी स्थानीय सरकार इस कोर के सम्बन्ध में स्थानीय सरकार समझी जायगी।

दफा ३० वालण्टियरों के साथ संमिलित होनेकी दशामें स्थल सेना के सैनिकों के साथ इस ऐक्ट के नियम लागू होंगे

किसी भी स्थल सेनाके, जो टेरीटोरियल ऐण्ड रिज़र्व फोरसेज़ ऐक्ट (स्थल और स्थायी सेना सम्बन्धी कानून) सन् १९०७ ई० की दफा ६ के अनुसार तैयार की गई है और कायम रखी गई है, किसी भी सैनिक के सम्बन्ध में, जो वालण्टियरों के किसी कोर के साथ, जो इस ऐक्ट के अनुसार तैयार किया गया है, शामिल कर दिया गया है, उस समयमें जब कि वह इस प्रकार साथमें काम कर रहा है, इस ऐक्ट के नियम लागू होंगे।

न्यूज पेपर ऐक्ट

नं० ८ सन् १९०८ ई०

अर्थात्

समाचार-पत्रों द्वारा अपराधोंको उत्तेजना देनेसे

नियंत्रण सम्बन्धी कानून

(ता० ८ जून सन् १९०८ ई० को पास हुआ)

चूंकि समाचार-पत्रोंमें हत्या तथा अन्य अपराधोंको उत्तेजना देनेवाले लेख आदिको रोकनेके सम्बन्धमें कुछ अधिक अच्छी व्यवस्था करना उचित जाना जाता है, इसलिये यह नीचे लिखा कानून बनाया जाता है:—

दफा १ संक्षिप्त नाम और विस्तार

(१) इस ऐक्टका नाम “न्यूजपेपर (अपराधोंको उत्तेजना देने सम्बन्धी) ऐक्ट सन् १९०८ ई०” होगा

(२) इसका विस्तार समस्त ब्रिटिश भारतमें होगा ।

दफा २ परिभाषा

(१) इस ऐक्टमें, जब तक कि कोई बात विषय अथवा प्रसंगके विरुद्ध न हो,—

(अ) “मजिस्ट्रेट” शब्दका अर्थ होगा जिला-मजिस्ट्रेट अथवा चीफ प्रेजी डेन्सी मजिस्ट्रेट ।

(ब) “समाचार-पत्र (News paper)” का अर्थ होगा कोई भीनियत समय पर प्रकाशित होनेवाला पत्र जिसमें सार्व-जनिक समाचार अथवा सार्व-जनिक समाचारोंके ऊपर टिप्पणियां आदि प्रकाशित हों ।

(स) “मुद्रणयन्त्र (Printing press)” में सभी एन्जिन, मशीनरी, टाइप, लीथोग्रैफिक पत्थर, औज़ार (Implements), वर्तन (Utensils), और दूसरे यन्त्र और सामान, जो छपाई आदिके काममें लाये जाते हों, शामिल हैं।

(२) ज़िबाय उसके, जब कि इसमें अन्य कोई व्यवस्थाकी गई हो, इस ऐक्टमें आये हुए कुल शब्दों और वाक्योंके वही अर्थ होंगे जो संग्रह जाबता फौजदारी सन् १८९८ ई० में बतलाये गये हैं ।

दफा ३ कुछ अवस्थाओंमें मुद्रणयंत्रके जन्त कर लेनेका अधिकार

१ उन अवस्थाओंमें, जब स्थानीय सरकारके हुक्मसे अथवा उससे प्राप्त अधिकारोंके अनुसार, दख्वास्त दिये जाने पर, किसी मजिस्ट्रेटकी यह राय हो कि किसी समाचार-पत्रमें, जो उस प्रान्तके भीतर मुद्रित और प्रकाशित होता है ऐसी बातें हैं, जो हत्या अथवा एकसप्लोसिव सब्जेक्ट्सके ऐक्ट सन् १९०८ ई० के अनुसार अन्य अपराधों अथवा दूसरे हिंसात्मक कार्योंको उत्तेजना देने वाली हैं ऐसे मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि वह इस सम्बन्धमें एक नियमबद्ध आज्ञा निकाल दे कि वह मुद्रणयंत्र, जो ऐसे समाचार-पत्रके मुद्रित करने अथवा प्रकाशित करनेके काममें लाया जाता है या लाया जाने वाला है, अथवा उस स्थान पर पाया जाय जहां पर ऐसा समाचार-पत्र छपा जाता है या जिस विषयकी निस्वत शिकायत है उसके छापे जानेके समय छपा जाय, और ऐसे समाचार-पत्रकी सभी प्रतियां जहां कहीं भी मिलें जन्त कर ली जाय, और उस हुक्ममें सभी बातोंको लिख दे और उस समाचार पत्रसे सम्बन्ध रखने वाले सभी लोगोंको यह आज्ञा दे कि वे उस समय और स्थान पर जो उस हुक्ममें नियत कर दिया जायगा, उसके सामने हाजिर होकर यह वजह ज़ाहिर करें कि उस हुक्मके अनुसार उनके साथ क्यों न कार्रवाई की जाय ।

२ इस हुक्मकी एक नकल उस स्थानके किसी खुले हुए हिस्सेमें चिपका दी जायगी जो उस डेक्लेरेशनमें बतलाया गया है जोकि प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ प्रेस ऐक्ट सन् १८६७ ई० की दफा ५ के अनुसार दाखिल किया गया है, अथवा किसी दूसरे स्थान पर चिपका दी जायगी जिसमें ऐसा समाचार-पत्र छपा जाता है और इस नकलका चिपकाया जाना (चरपा करना) उस हुक्मकी उन तमाम आदमियों पर बाकायदा तालीम समझी जायगी जो उस समाचार-पत्रसे सम्बन्ध रखते हैं ।

३ ज़रूरत नागहानीमें या उन हालतोंमें, जब देर हो जानेसे उस दख्वास्तका भंशा हल न हो सके, मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि वह उप-दफा (१) के अनुसार नियमबद्ध हुक्म निकालनेके समय अथवा उसके पश्चात् उस मुद्रणयंत्र अथवा दूसरी जायदादको, जो उस नियमबद्ध हुक्ममें बतलाई गई है, जन्त करनेके लिये एकतर्फा हुक्म और निकाल दे ।

४ अगर उस समाचार-पत्रसे सम्बन्ध रखने वाला कोई शख्स हाजिर होकर उस नियमबद्ध हुक्मके खिलाफ वजह ज़ाहिर करता है, तो वह मजिस्ट्रेट जायदाद फौजदारी सन् १८९८ ई० की दफा ३५६ में बतलाये हुए तरीकेसे शहादत देगा, फिर चाहे उस हुक्मके पक्षमें हो या विपक्ष में ।

५ अगर उस मजिस्ट्रेटको इस बातका इतमीनान हो जाय कि उस समाचार-पत्रमें वे बातें पाई जाती हैं जो उप-दफा १ में बतलाई गयी हैं तो वह उस जायदाद के सम्बन्ध में जो उसे उक्त दफा १ की शर्तोंके अन्दर मालूम पड़े, तबलीका नियमबद्ध हुक्म कृतर्ह करार दे देगा ।

६ अगर मजिस्ट्रेटको इस बातका इतमीमान न हो, तो वह जल्तीके सम्बन्धमें दिये हुए नियमबद्ध हुक्मको तथा कुर्कीके हुक्मको, अगर कोई हो, रद्द कर देगा।

दफा ४ जल्तीका अधिकार

१ मजिस्ट्रेटको अधिकार है कि, वह किसी पुलिस अफसरको जिसका दर्जा सबइंस्पेक्टरसे कम न हो, वज़रिये वारण्टके यह अधिकार दे कि वह किसी जायदादको, जिसके लिये दफा ३ की उप-दफा ३ के अनुसार कुर्कीका हुक्म दिया गया है, जल्त करके अपने पास रख ले, अथवा किसी ऐसी जायदादको, जिसके लिये दफा ३ की उप-दफा (५) के अनुसार जल्तीका हुक्म दिया गया है, जहां कहीं भी वह मिले जल्त करके उठा ले जाय और उस जायदादके सम्बन्धमें किसी भी स्थानमें,—

(अ) जहां पर कि उस वारण्टमें बतलाया हुआ समाचार-पत्र मुद्रित और प्रकाशित किया जाता है, या

(ब) जहां पर जायदाद हो या उसके होनेका काफ़ी सन्देह हो, या

(स) जहां पर ऐसे समाचार-पत्रकी कोई भी प्रति बिक्रीके लिये, बांटनेके लिये, प्रकाशित किये जानेके लिये, अथवा सर्व-साधारणको दिखलानेके लिये रखी हो या उसके इस प्रकार रखे जानेका सन्देह हो।

२ उप-दफा (१) के अनुसार जारी किया गया हर एक वारण्ट, जहां तक कि उसका सम्बन्ध तलाशीसे है, उस तरह पर तामील किया जायगा जैसा संग्रह ज़ाबता फौजदारी सन् १८९८ ई० में तलाशीके वारण्टोंकी तामीलीके लिये बतलाया गया है।

दफा ५ अपील

उस समाचार-पत्रसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी शख्स, जिसने हाज़िर होकर उस नियमबद्ध हुक्मके खिलाफ़ वजह ज़ाहिर की है, उस तारीख़से, जिसको कि वह हुक्म कतई करार दिया गया है, पन्द्रह दिनके भीतर हाईकोर्टमें अपील कर सकता है।

दफा ६ दूसरी कार्रवाईका न हो सकना

सिवाय इसके जैसाकि दफा ५ में बतलाया गया है, किसी भी ऐसे हुक्मके ऊपर, जो किसी मजिस्ट्रेटने दफा ३ के अनुसार दिया है, किसी भी अदालतमें कोई आपत्ति न की जा सकेगी।

दफा ७ प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट सन् १८६७

ई० के अनुसार दाखिल किये गये डेक्लरेशनके रद्द

करनेका अधिकार

जब किसी समाचार-पत्रके सम्बन्धमें जल्तीका हुक्म कतई करार दे दिया गया हो, तो स्थानीय सरकारको अधिकार है कि वह, स्थानीय सरकारी गज़टमें

विज्ञप्ति निकालकर, किसी भी डेक्लैरेशनको, जो ऐसे समाचार-पत्रके मुद्रक अथवा प्रकाशकने प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट सन् १८६७ ई०के अनुसार दाखिल किया हो, रद्द कर दे, और उसे यह भी अधिकार है कि वह ऐसी विज्ञप्तिके द्वारा उक्त ऐक्टके अनुसार उक्त समाचार-पत्रके सम्बन्धमें अथवा किसी अन्य समाचार-पत्रके सम्बन्धमें, जो वही आशय रखता है जो उक्त समाचार-पत्र रखता है भविष्य तक और डेक्लैरेशन दाखिल करनेकी सुमानियत करदे, जब तक कि वह सुमानियतका हुक्म उठा न लिया जाय ।

दफा ८ दंड

जो कोई भी शख्स किसी ऐसे समाचार-पत्रको, जिसके लिये दफा ७ के अनुसार निकाली गई विज्ञप्तिमें सुमानियत कर दी गई है, इस सुमानियतके हुक्मके दौरानमें मुद्रित अथवा प्रकाशित करेगा, वह अपराधी सिद्ध होने पर उस दण्डके पानेका भागी होगा जो प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट सन् १८६७ ई० की दफा १५ में बतलाया गया है ।

दफा ९ ज़ाबता फौजदारीका प्रयोग

इस ऐक्टके अनुसार की जानेवाली सारी कार्रवाई, जहां तक सम्भव होगा संग्रह ज़ाबता फौजदारी सन् १८९८ ई० के अनुसार की जायगी ।

दफा १० दूसरे क़ानूनोंका अमलमें लाया जाना

इस ऐक्टके अनुसार किसी शख्सके ऊपर कार्रवाई किये जानेसे वह शख्स उन बातोंके सम्बन्धमें की जानेवाली कार्रवाईसे मुक्त न होगा जो दूसरे क़ानूनके अनुसार अपराध है ।

स्टेट आफेंसेज ऐक्ट

नं० ११ सन १८५७ ई०

[तारीख २० मई सन १८५७ ई० को पास हुआ]

राज्यके प्रति किये गए अपराधोंको रोकने, उनकी सुनवाई करने और उनके लिये दण्ड देने सम्बन्धी कानून

चूंकि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राज्यके प्रति किए गए अपराधों को रोकने, उनकी सुनवाई करने और उनके लिए दण्ड देनेके सम्बन्धमें समुचित व्यवस्था की जाय, इसलिये यह नीचे लिखा कानून बनाया जाता है:—

दफा १

[राजद्रोह अथवा सरकारके विरुद्ध युद्ध करने के लिये दण्ड] ऐक्ट नं० १७ सन १८६२ ई० द्वारा मंसूख किया गया ।

दफा २

[अपराधियोंको शरण देने अथवा छिपानेके लिये दण्ड] ऐक्ट नं० १७ सन १८६२ ई० द्वारा मंसूख किया गया ।

दफा ३ किसी घोषित रक्तबेमें किये गए अपराधोंके दोषी बत लाये हुए लोगोंके मामलेकी जांच करनेके लिये, कार्य कारिणी समिति (सरकार) को कमीशन जारी करने का अधिकार

क्लॉज १—जब कभी किसी प्रेजीडेंसी या श्यानकी कार्य-कारिणी सरकार (Executive Government) इस बातकी घोषणा करेगी कि कोई ज़िला, जो उसकी सरकारके अधीन है, राजद्रोही है या हो गया है, तो ऐसी सरकारके लिये यह बिल्कुल न्यायालुकूल (कानूनी) होगा कि वह उन लोगोंके मामलेकी, जिनके ऊपर उस ज़िलेके भीतर राजद्रोह या हत्या, अग्निदाह, डाकाज़नी, अथवा जान या मालके विरुद्ध कोई दूसरा भयंकर अपराध करनेका अभियोग लगाया गया है उस दिनके बाद, जिसका वर्णन कमीशनमें किया जायगा, जांच करने के लिये कमीशन जारी करे ।

क्लॉज २—ज़िलेके किसी भी हिस्सेमें अदालतकी बैठक हो सकती है—

कमिश्नर या कमिश्नरोंको, जिनको किसी ऐसे कमीशनके अनुसार अधिकार दिया गया हो, अधिकार होगा कि वे उस कमीशनमें बतलाये हुये उक्त जिलेके किसी भी हिस्सेमें अपना इजलास कर सकें, और वहां पर किसी शख्स के मामलेकी, उक्त अपराधोंमें से जो उसके किसी भी हिस्सेमें किये गये हैं किसी भी अपराधके सम्बन्धमें जांच कर सकें; किन्तु इस ऐक्टका यह मंशा है कि कमीशनमें बतलाया हुआ जिला उक्त किसी भी अपराधके सम्बन्धमें मामला चलाये जाने और दण्ड दिये जानेके अभिप्रायसे एक जिला समझा जाय।

दफा ४ सरकार अदालतोंको कुछ अधिकार देसकती है

कार्य कारिणी सरकार (Executive Government) के लिये यह बात बिल्कुल ही न्यायानुकूल होगी कि वह ऐसे कमीशनके द्वारा यह हुक्म दे देवे कि कमीशनके अनुसार बैठी हुई किसी अदालतको अधिकार होगा कि वह, बिना-
+ + + + असेसरोकी मददके, प्रत्येक ऐसे व्यक्तिके सम्बन्धमें, जो उपरोक्त किसी भी अपराधके सम्बन्धमें उस अदालत के सामने दोषी पाया गया हो कोई भी ऐसी सज़ा का हुक्म दे देवे जो कानूनन ऐसे अपराधोंके लिये दी जानी चाहिये; और यह कि ऐसी अदालतका फैसला कृतई और आखिरी होगा और यह कि उक्त अदालत सदर अदालतकी मातहत होगी।

दफा ५ इस ऐक्टके अनुसार बैठी हुई अदालतके सामने माजिस्ट्रेट, आदमियोंको उनके मामलेकी जांच करनेके लिये पेश कर सकता है

अगर इस ऐक्टके अनुसार कोई कमीशन जारी किया जाय तो उस जिले का, जो उस कमीशनमें बतलाया गया है कोई भी माजिस्ट्रेट उन लोगोंको, जिन पर उस जिलेमें उपरोक्त किसी भी अपराधके करने का अभियोग लगाया गया है उनके मामलेकी जांच किये जानेके लिए उस अदालतके सामने पेश कर सकता है जो इस ऐक्टके अनुसार बैठी हो।

दफा ६ यह ऐक्ट इंग्लैण्डमें पैदा हुई ब्रिटिश-प्रजाके और उनके लड़कोंके सम्बन्धमें लागू न होगा

इस ऐक्टका कोई भी नियम श्रीमान् संम्राट की उस प्रजा पर मामला चलाए जाने अथवा उनको दण्ड (सज़ा) देनेके सम्बन्धमें लागू न होगा जो यूरोपमें पैदा हुए हैं और न उनके लड़कों पर ही।

दफा ७ से १० तक

(हथियारोंका पासमें होना इत्यादि) ऐक्ट नं० १२ सन् १८७६ ई० के द्वारा मसख कीगयीं।

दफा ११

इस ऐक्टमें आए हुए "मजिस्ट्रेट" शब्दमें कोई भी शख्स शामिल होगा जिसे + + + + कार्य कारिणी सरकार (Executive Government) ने इस ऐक्टके अनुसार किसी मजिस्ट्रेटको दिए गए अधिकारों के बर्तनेका अधिकार दिया हो ।

सूचना

इस भागमें जहां पेजोंके देखनेका हवाला दिया गया है उससे हिन्दीमें
छपे जाबता दीवानीके पेजोंके देखनेका
तात्पर्य समझना चाहिये ।

भाग ३

प्लीडिंग्स, अर्जियों और दस्ता- वेजों आदिके नमूने

प्लीडिंग्सके लिये देखिये पेज ९

अर्जीदावा और बयान तहरीरी

(१) आम अर्जीदावा

अर्जीदावा नीचे लिखे अनुसार लिखा जाना चाहिए और उसमें नीचे
लिखी बातें लिखनी चाहिए:—

कागज़ के सिर्फ एक ही ओर और करीब २ इंच का हाशिया कागज़
के बाएं ओर छोड़ कर (अंगरेज़ी व हिन्दी में) लिखना चाहिए । उर्दू के
लिए इसी तरह पर दाहिने ओर हाशिया छोड़ना चाहिए । ऊपर नीचे करीब एक
एक इंच जगह छोड़ देनी चाहिए ।

(क) [नाम उस अदालत का जिलमें नालिश दायर की गई हो]

जैसे—ब अदालत श्रीमान् (जमाब) सब—जज साहब बहादुर, कानपुर।

[मुकद्दमें का रजिस्टर में लिखे जाने वाले नम्बर और सन् के लिए जगह छोड़ दी जानी चाहिए]

जैसे—मुकद्द रुपये की नालिश नं० १३२५ सन् १९२७ ई०.

(ख) [मुद्दई का नाम उमर वलिदयत व पेशा और सकूनत वगैरा]

जैसे—सालिकराम उमर अन्दाजन ४० साल बल्द सीताराम कौम ब्राम्हण पेशा जमीन्दारी व महाजनी । साकिन मौजा बैकुण्ठपुर परगना व थाना यमपुर जिला शान्तिपुर ।

बनाम

(ग) [मुद्दाअलेह का नाम उमर वलिदयत व पेशा और सकूनत वगैरा]

जैसे—चूडामनि उमर अन्दाजन ४० साल बल्द थुरई कौम चमार पेशा काश्तकारी साकिन मौजा हसनपुर थाना चौबेपुर जिला कानपुर ।

(घ) [जब मुद्दई या मुद्दाअलेह नाचालिग या पागल हो तो यहां पर वे सब बातें लिख दी जानी चाहिए]

(ङ) [नालिश की तफ़्सील और दावा की मालियत]

जैसे—दावा बाबत दिलापाने मुबलिग ८५०) रुपया जो नक़द कर्ज दिए गए थे ।

(च) [वे बातें जिनसे कि निनाय मुखासमत दावा पैदा होती है और यह कि वह कब पैदा हुई]

नोट—ऊपर बतलाए अनुसार फ़रीक़ेन मुकद्दमाका नाम, उमर वलिदयत, सकूनत और पेशा इत्यादि लिख चुकने के बाद मुकद्दमें की दूसरी बातें शुरू करना चाहिए। जिन बातों के आधार पर मुद्दई अपना दावा पेश करता है, वह शहादत नहीं जो कि वह अपने दावा की ताईद में पेश करना चाहता है। वे सब बातें संक्षेप में अलग अलग पैरा डाल कर लिखना चाहिए उनपर सिलसिले का नम्बर डाला जाना चाहिए और तारीखें, रुपये की संख्या (तादाद) और नम्बर सब अक्षरों (हिन्दुसों) में लिखी जाना चाहिए ।

जैसे—उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखेअनुसार प्रार्थी है—

१ यह कि तारीख ३० जून सन् १९२७ ई० को मुद्दई ने मुद्दाअलेह को मुबलिग ५०) रु० २४) सैकड़। सालाना ब्याज की दर पर कर्ज दिए, जिनको मुद्दाअलेह ने तारीख २९ जून सन १९२८ ई० को या उससे पहिले अदा कर देने का वादा किया था। मुद्दाअलेह ने इस रक़म की निस्वत एक बाकायदा तमस्तुक मुद्दई के हक़ में लिख दिया था और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री भी करा दी थी। वह तमस्तुक इस अर्ज़ीदावा के साथ नथी है ।

२ यह कि मुद्दाअलेह ने मुद्दई को मुबल्लिग (७५) रु० बाबत ब्याज के तारीख २१ नवम्बर सन १९२७ को अदा किए जिसकी वसूली मुद्दाअलेह ने स्वयं उस तमसुक की पीठ पर लिख दी।

३ इस रूपया को वसूल देनेके बाद भी मुबल्लिग) रु० की रकम मुद्दई को मुद्दाअलेह से अब भी मिलना बाकी है, लेकिन मुद्दाअलेह ने वह रकम अभी तक अदा नहीं की, यद्यपि बार-बार उससे इसके लिए कहा गया।

(छ) [वे बातें जिनसे यह मालूम होता हो कि अदालत को इस मामले की समाप्त करने का अधिकार है]

४ मुद्दई की इस नालिश के दायर करने की बिनाय सुखासमत तारीख २९ जून सन १९२८ ई० को मौज़ा हसनपुर में पैदा हुई जो मौज़ा कि इस अदालत के अधिकार-क्षेत्र (अख्त्यार समाप्त) में है।

(ज) [वह दादरसी जिसके लिए मुद्दई दावेदार है]

५ मुद्दई का दावा है—

(१) कि मुद्दाअलेह के ऊपर) रु० की डिकरी मय ब्याज व असल, रुपये के उस ब्याज की दर पर, जो अदालत उचित समझे इस नालिश की तारीख से डिकरी की तारीख तक और इस कुल रुपये पर, रूपया वसूल हो जाने की तारीख तक उस ब्याजकी दर पर, जो अदालत उचित समझे, दे दी जाय।

(२) यह कि मुद्दाअलेह को यह हुक्म दिया जाय कि वह मुद्दई को इस मुकद्दमें में होने वाला खर्चा और उसके वसूल होते तक ६) रु० सैकड़ा सालाना की दर से ब्याज (सुद) अदा करें।

(ज) [जब मुद्दई ने कुछ छूट दी हो या अपने दावा का कुछ हिस्सा छोड़ दिया हो तो उस रकम की तादाद लिख देनी चाहिए]

(झ) [अख्त्यार समाप्त और कोर्ट-फीस की रकम तय करने के लिए यहां पर दावा की मालियत लिख देनी चाहिए]

६ अख्त्यार समाप्तके लिए इस नालिशके दावाकी मालियत) रु० है और इसी रकम पर कोर्ट-फीस लगाया गया है।

(ज) [तस्दीक और दस्तखत].

देखो इस किताब का पेज १३।१४

नोट—अर्जीदावा के तैयार करने के पहले देखो पेज ९ से ३६ तक।

आम जवाब दावा या बयान तहरीरी

उनवान (शीर्षक) मुकद्दमा [देखो अर्जी दावा नं० १]

इन्कारी

मुद्दाअलेह इस बात से इन्कार करता है कि (यहां पर उन बातों को लिखना चाहिए जिनसे इन्कारी की जाती है)।

मुद्दाअलेह इस बात को स्वीकार नहीं करता कि (यहाँ पर वे बातें लिखनी चाहिये) ।

मुद्दाअलेह इकबाल करता है कि.....लेकिन उसका कहना है कि—

विरोध

मुद्दाअलेह इस बात से इन्कार करता है कि उसने उक्त इकरारनामा या कोई इकरारनामा मुद्दई के साथ किया ।

मुद्दाअलेह इस बात से इन्कार करता है कि उसने मुद्दई के साथ अमुक इकरार (मुआहिदा) किया या किसी तरह का कोई भी मुआहिदा किया ।

मुद्दाअलेह को वसूली जायदाद से इकबाल है लेकिन वह मुद्दई के दावा को नहीं मानता ।

मुद्दाअलेह इन्कार करता है कि उसने मुद्दई के हाथ यह माल बेचा जिसका जिक्र अर्जोदावा में किया गया है या उसमें से कोई भी माल उसके हाथ बेचा है ।

मियाद समाप्त

भारतीय कानून मियाद सन १९०८ ई०के परिशिष्ट (२) की आर्टि०.....से या आर्टि०.....से इस नालिश की तमादी आरिज होती है ।

आख्तियार समाप्त

अदालत को इस वजह से (यहाँ पर वजह लिखनी चाहिये) इस मुकद्दमें की समाप्त करने का अख्तियार नहीं है ।

तारीख.....माह.....सन ई० को मुद्दाअलेह ने एक हीरे की अंगूठी मुद्दई को दी और मुद्दई ने अपने दावा की बेबाकी में उसे स्वीकार कर लिया ।

दावाला

मुद्दाअलेह दीवालिया करार दे दिया गया है । मुद्दई इस नालिश दायर होने के पहिले दीवालिया करार दे दिया गया था और इसलिए नालिश करने का हक रिसीवर को था ।

नावालिग

उक्त मुआहिदा करते समय मुद्दाअलेह नावालिग था ।

अदालतमें अदा किया गया

मुद्दाअलेहने कुलदावाके बाबत (या मुबलिग.....)रुपया की बाबत, जोकि दावाका एक हिस्सा है या जैसी कुछ भी अवस्था हो)) रु० अदालतमें दाखिल कर दिए हैं और उसका यह निवेदन है कि इस रुपयेसे मुद्दईके दावा की (या उसके उक्त अंशकी) बेबाकी हो जाती है ।

तामालि मुआहिदासे दस्तबदारी

उक्त मुआहिदेकी तामील से तारीख को दस्तबदारी की गई ।

मुद्दाहिदाकी मंसखी मुद्दई और मुद्दाअलेहके बीच, हुए इकरारनामाके अनुसार मुद्दा-
हिदा तारीख को मंसूख किया गया।

प्रत्यया
Resjudiata

अमुक डिकरीके कारण मुद्दई का दावा दायर नहीं हो सकता
(यहां पर हवाला देना चाहिए)।

रुकावट
Estoppel

मुद्दई इस बातसे इनकार नहीं कर सकता (यहां पर वे बातें
लिखना चाहिए जिनकी बिनापर रुकावट पेश की गई है) क्योंकि
... .. (यहां पर वे बातें लिखनी चाहिये जिनके आधार पर
रुकावट Estoppel का प्रश्न उठाया गया है)।

नालिश होने

के बाद बचावमें पेश
ही जानेवाली बातें

चूंकि नालिश दायर होने के बाद से, अर्थात् तारीख
... .. माह सन् ई०
से (यहां पर उन बातोंको लिखना चाहिए जो बाद दायर होने
नालिश के हुई)।

नोट—बयान तहरीरीका मसविदा तैयार करते समय आर्डर ६ के नियमों
को हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये। आर्डर ८ में बतलाये हुये नियमोंको ध्यान
पूर्वक पढ़ जाना चाहिये। बयान तहरीरीके लिये देखो पेज ६४;

जाबता दीवानीके ज़मीमा न० (ए) में हर प्रकारकी नालिशोंमें दाखिल
किये जाने वाले अर्ज़ीदावा और तहरीरी बयानोंके नमूने बतलाये गये हैं और
आर्डर ६ रूल ४ में यह बतलाया गया है कि उन अवस्थाओंमें जहां पर उनका
प्रयोग होता है और उन अवस्थाओंमें भी, जहां पर कोई उपयुक्त कार्यका नमूना
न हो, जहां तक सम्भव होगा फ्लीडिङ्गस के लिये इन्हीं नमूनों को काम में
लाया जायगा।

२ नालिश बाबत बक्राया लगान

अदालत जनाब मुंसिफ़ साहब बहादुर बिसवां ज़िला सीतापुर मु० सीतापुर
नालिश बाबत लगान। नम्बरी १२७९ सन् १९२६ ई०

पं० मनीराम उमर ४५ साल वरद टीकाराम कौम ब्राह्मण पेशा जमींदारी
साकिन मौज़ा सरैयां थाना कमालपुर ज़िला सीतापुर.....मुद्दई
बनाम

पं० हरीनाथ उमर ६० साल वरद मंगलदत्त कौम ब्राह्मण पेशा काश्तकारी
साकिन मौज़ा पतारा थाना कमालपुर ज़िला सीतापुर मुद्दाअलेह
दावा दिलापाने मुबल्लिग.....रु० बाबत बक्राया लगान।

मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है:—

१ यह कि मुद्दई मौज़ा पताराका ज़मीन्दार है जो इस अदालतके अधिकार-
क्षेत्र (हद अख्तियार समाहत) में बाँके है और वह उस मौज़ेका दखीलकार
कब्जेदार है और असामियोंसे लगान बगैरा की तहसील वसूल करता है।

२ यह कि मुद्दाअलेह, मुद्दईकी.....भाराजी का, जो उक्त मौजेमें चार्क है,२० सालाना लगान पर, जो हर साल चार बराबर किस्तोंमें बाजिबुल-अदा है जोतिया है ।

उक्त जोत की चौहद्दी परिशिष्ट (ब) में बतलाई गई है जो इस अर्जीदावा के साथ नती है ।

३ यह कि मुद्दईको उक्त जमाकी जमाबन्दी पर कानूनके अनुसार.....भाना की रूपया के हिसाबसे अबवाब (महसूल) की तहसील करनेका अधिकार है ।

४ यह कि उक्त जमाकी जमाबन्दी, अबवाबके हिसाबका नकशा अर्जीदावाके परिशिष्ट (अ) में दिया गया है ।

५ यह कि मुद्दाअलेहने अदा कर सकनेके काबिल होते हुए और बिना किसी मुनासिब वजहके होते हुये भी लगान और अबवाब की बकाया अदा नहीं की है जैसा कि परिशिष्ट (अ) में बतलाया गया है, यद्यपि मुद्दईने उससे बार बार यह रूपया तलब किया ।

६ यह कि ऊपर बतलाये कारणों से मुद्दई बकाया रूपये के अलावा उस बकायाका २५ फीसदी बतौर हर्जाके दिला पानेका हकदार है ।

७ यह कि उसके दावा की बिनाय मुखासमत उक्त मौजा पतारा में, जो इस अदालतके अधिकार-क्षेत्र (इहद अदृत्यार समाअत) में है, हर साल की हर एक किस्त की मियाद गुजर जानेके बाद पैदा हुई है ।

८ अदृत्यार समाअत तय करनेके लिए इस नालिशकी मालियत दावा ३७॥)२० है और कोर्ट-फीसके लिए भी यही मालियत है ।

९ मुद्दईका दावा है कि मुद्दाअलेहके ऊपर २० की जिसमें अबवाब और हर्जानाकी रकम शामिल है, मय ब्याज २० सैकड़ा सालाना रूपयकी वसूलयावी हो जाने तक और मय खर्चा इस नालिशके दिकरी दीजाय ।

परिशिष्ट (अ)

हिसाब

	लगान	अबवाब	वसूल	बकाया
सन् १३२८ फसली	८) २०	१) आना	३) २०	५१) २०
सन् १३२९ "	८) २०	१) आना		८१) २०
सन् १३३० "	८) २०	१) आना		८१) २०
सन् १३३१ "	८) २०	१) आना		८१) २०
				<hr/>
				३०) २०
			हर्जा	७॥) २०
				<hr/>
			दावाकी रकम	३७॥) २०

परिशिष्ट (ब)

आराज़ीकी चौहद्दी और तफसील

[जबकि आराज़ी किसी ऐसे रकबेमें बाँके हो जिसकी खेवट तैयार होगई हो और वह प्रकाशित होगई हो तो जोतका नम्बर, सिद्धिसला सर्वेके खेतोंकी तहरीरत, वगैरा भी देना चाहिए]

मैं उक्त मनीराम मुद्दई सच सच यह तस्दीक इज़हार करता हूँ कि अर्ज़ीदावाके पैरा १, २, ३, ४, ५ में लिखी हुई बातोंको मैं खुद जानता हूँ कि वे सही हैं और बाकी पैराग्राफोंमें लिखी हुई बातें मेरी इत्तला और यक़ीन के ऊपर लिखी गई हैं और मुझे उनके भी सही होनेका यक़ीन है आज तारीख् माह सन् ई० को यवक्त ... बजे दिमके (अपने मक़ान) पर इस तस्दीकके ऊपर दस्तख़त करता हूँ। दस्तख़त और तस्दीकके लिफ् देखो पेज १३।१४

मनीराम

(दस्तख़त मुद्दई)

उपरोक्त नालिशमें दाख़िल किया जाने वाला बयान तहरीरी

बहादुरत जनाब मुंसिफ़ साहब बहादुर निसवां ज़िला व मुक़ाम सीतापुर
(उनवान मुक़दमा)

नालिश बकाया लगान नं० १२७९ सन् १९२६ ई०

उपरोक्त नालिशमें मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है:—

१ यह कि मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने के लिये कोई कारण व हक़ नहीं है।

२ यह कि फरीक़ैतके बीच ज़मींदार और असामीका कोई रिश्ता नहीं है, और यह कि वह इस बातसे इन्कार करता है कि वह मुद्दईकी रु० जमा की ज़मीन जोते है या कभी जोते रहा है।

३ यह कि नालिश मय खर्चों के ख़ारिज होनी चाहिए और खर्चा दिलाया जाना चाहिए।

तस्दीक (देखो पेज १३।१४)

[दस्तख़त मुद्दाअलेह]

(या आवश्यकतानुसार नीचे लिखी बातें जवाबदावामें पेशकी जा सकती हैं।)

१ यह कि अर्जीदावाके पैरा में बतलाई गई बातोंसे मुद्दाअलेह इन्कार करता है और मुद्दैसे उनका सुबूत तलब करता है और यहाँके और तमाम दूसरी बातों की निस्वत जो कही गई हैं और जिनकी निस्वत इसके आगे खास तौर पर इन्कार नहीं की गई है, यह समझना चाहिए कि वे इकवाल नहीं की गई हैं ।

२ यह कि जो जोत उसके कब्जेमें है वह मुकररी जोत है और वह खतियान नं० में बतौर मुकररी जोतके दर्ज है और वह सरसरी रैयती जोत नहीं है जैसा कि अर्जीदावा में बतलाया गया है ।

३ यह कि उसकी जोतका लगान जमाबन्दी में रु० है, जैसा कि ऊपर बतलाए हुए खतियानमें दर्ज है, रु० नहीं जैसा कि अर्जीदावामें बतलाया गया है ।

४ यह कि मुद्दै अदम तामीलके ऊपर अवध रेण्ट ऐक्ट की दफा के अनुसार बज़रिये नालिश, लगान वसूल पानेका हकदार नहीं है ।

५ यह कि उस जोतके शरीकदार, फास्तकार हैं और मुद्दाअलेहके साथ साथ वे लोग भी उस आराज़ी पर क़ाबिज हैं और इसलिये बिना उनको फ़रीक मुकद्दमा बनाए, नालिश क़ाबिल ससाअत नहीं है ।

६ यह कि रु० के लगानमें अवचाबकी रक़म भी शामिल है और इसलिये अलगसे अवचाब अदा न होना चाहिए ।

७ यह कि मुद्दाअलेह ऊपर बतलाई दर (शरह) पर लगान अदा करने के लिए हमेशा तैयार था और अब भी तैयार है, लेकिन मुद्दैके शुमाइता ने उस समय तक लगान लेनेसे इन्कार कर दिया जब तक कि मुद्दाअलेह ग़ैर क़ानूनी इज़ाफ़ा लगानके लिए राज़ी न हो जाय ।

८ यह कि मुद्दाअलेह ने उक्त आराज़ीका लगान तारीख् को के सामने पेश किया और उसे लगानके मनीआर्डरसे भी भेजा जो बिना किसी उचित कारणके वापस आया और यह कि ऐसी दशामें मुद्दै किसी हर्जा या मुकद्दमेंका खर्चा दिलापानेका हकदार नहीं है ।

३ नालिश बाबत तमस्सुक सादा

[अदालत और फ़रीक़ेन वगैराका हवाला ऊपर बतलाए अर्जीदावा नं० १ की तरह पर ही लिखना चाहिए]

उपरोक्त मुद्दै नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ यह कि तारीख् १२ मार्च सन् १९१४ ई० को मुद्दैने २०० रु० मुद्दाअलेह को १८) रु० सैकड़ा सालाना ब्याजकी दर पर कर्ज़ दिए मुद्दाअलेह ने बाक़ायदा तौर पर एक तमस्सुक मुद्दैके हकमें तहरीर कर दिया जिसकी रजिस्ट्री भी होगई । उक्त तमस्सुक इस्तेअर्जीदावाके साथ नचपी है ।

२ यह कि सिवाय १०) रु० के सो तारीख् ११ जनवरी सन् १९१४ ई० को ब्याजकी मदमें अदा किए गए थे, मुद्दाअलेह ने कर्ज़ का रुपया अदा नहीं किया है ।

३ यह कि उपरोक्त तमस्सुक की बाबत ...) रु०, बाद मिनहाई
उपर बतलाई रकमके जो व्याज की निश्चित अदा की गई है, मुद्दा-
लेह से भव भी वाजिबुल वसूल है, जिसका हिसाब नीचे दिया जाता है, और
यह कि बार-बार तलब किए जाने पर भी मुद्दाभलेहने वह बाकी का रुपया
अदा नहीं किया है।

४ मुद्दाईकी इस नालिशकी बिनाय मुख़ासमत तारीख़ १ मार्च सन् १९१५
को मुक़ाम ... में, जो कि इस अदालतके अधिकार-क्षेत्र (हद
अख़्तियार समाहत) में है, मुद्दाभलेहके उक्त तमस्सुककी बाबत वाजिब रुपय के
अदा न कर सकने पर पैदा हुई।

५ इस नालिशकी मालियत दावा, अधिकार-क्षेत्र (अख़्तियार समाहत) के
अंदर ... रु० है और कोर्ट-फीस भी इसी रकम पर लगाया
गया है।

६ मुद्दाई प्रार्थी है—

(अ) कि मुद्दाभलेहके ऊपर ... रु० की मय व्याज बशरह ६)
रु० सैकड़ा सालाना, नालिश होनेकी तारीख़से रुपया वसूल होजाने
की तारीख़ तक, डिकरी दीजाय। और

(ब) यह कि मुद्दाभलेह के ऊपर इस नालिशके खर्चों की डिकरी दी
जाय, और

(स) दूसरी पेसी दादरसी दिलाई जाय जिसे अदालत मुनासिब समझे।
हिसाब—

(तस्दीक और दस्तख़त अर्ज़ीदावा नं० १ में बतलाए अनुसार)

उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

अदालत और फ़रीक़ैन वग़ैराका हवाला ऊपर बतलाए अर्ज़ीदावा नं० १ की
तरह पर दिया जाना चाहिए।

मुद्दाभलेह ऊपर बतलाई हुई नालिशके सम्बन्धमें नीचे लिखे अनुसार
जिवेदन करता है—

१ यह कि मुद्दाईको मुद्दाभलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई
कारण व हक़ नहीं है।

२ यह कि मुद्दाई ने जो हिसाब बतलाया है वह सही सही नहीं है और उसने
उस रकमके अलावा जिसका अदा किया जाना अर्ज़ीदावामें स्वीकार किया गया
नीचे लिखी रकमों जो अदा की हैं मुजरा नहीं दी हैं (यहां पर अदा किये गये
रकमों की तादाद और उसकी अदायगीकी तारीखें लिखो)

३ यह कि मुद्दाअलेह रु० की रकम, बाबत कीमत उस मालके जो बेचा गया और मुद्दईके हवाले किया गया है, मुजरा पानेका हकदार है (यहां पर वे सब बातें लिखनी चाहिये)

४ यह कि कुल रुपएकी बाबत (या रुपएकी बाबत, जो कि दावाकी रकमका एक हिस्सा है) मुद्दाअलेहने नालिश दायर होनेके पहिले रु० अदा करने के लिए पेश किये थे और उसने वह रकम अदालतमें दाखिल करदी है।

या

५ यह कि मुद्दाअलेहने कोई भी रुपया बाबत ब्याजके अदा नहीं किया और न उसकी बेबाकी तमस्तुककी पीठ पर लिखवाई जैसा कि अर्जीदावामें बतलाया गया है और कानून मियादके आर्टि० के अनुसार इस नालिशकी तमादी आरिज होगई है।

या

६ यह कि मुद्दाअलेहको इस बातसे इन्कार है कि उसने रु० की रकम कर्ज ली और उसके लिये तमस्तुक लिखा, जैसा कि बतलाया जाता है।

७ यह कि मुद्दाअलेहका विश्वास है कि मुद्दईने के भड़काने पर, जिससे मुद्दाअलेहकी अदावत है (यहां पर अदावत पैदा होनेका कारण इत्यादि लिखना चाहिये) एक जाली तमस्तुकके ऊपर यह नालिशकी है।

८ यह कि नालिश मयखुर्चेंके खारिजकी जाय और खर्चा दिलाया जाय।

(तस्दीक और दस्तखत)

[देखो पेज १३।१४]

४ नालिश बाबत रुका (प्रोनोट)

[अदालत और फरीकैन मुकद्दमाका हवाला अर्जीदावा नं० १ में बतलाये अनुसार]
उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है:—

१ यह कि मुद्दाअलेहने तारीख १ जनवरी सन् १९२७ ई० को एक रुका बाबत २५०) रु० के मुद्दईके हकमें लिख दिया और रुपयेके वसूल न हो जाने तक असल रुपये पर १२) रु० सैकड़ा सालानाके हिसाबसे ब्याज देनेका इकरार किया। मुद्दाअलेहने यह भी इकरार किया कि वह तलब किये जाने पर कुल असलका रुपया मय ब्याजके अदा कर देगा। रुका इस अर्जीदावा के साथ नथी है।

२ यह कि रु० की रकम, जो इस अर्जीदावाके परिशिष्ट (अ) में बतलाई गई है, मुद्दई को मुद्दाअलेहसे वाजिबुल वसूल है।

३ यह कि रुपया अदा कर सकनेकी सामर्थ्य रखते हुये भी मुद्दाअलेहने जो रुपया उसे वाजिबुल अदा है अदा नहीं किया, यद्यपि मुद्दईने इसके लिए बार-बार तकाज़ा किया।

४ इस नालिशकी बिनाय मुखासमत तारीख (जिस तारीखको रखा
 लिखा गया था) और उसके बादकी तारीखांको, जिस समयकि मुद्दाअलेह
 रुपया अदा करनेसे इन्कार कर दिया, बमुकाम जो कि इस अदालतके
 अधिकारक्षेत्र (हद्द अख्तियार समाहत) में है, पैदा हुई ।

५ [जैसा कि अर्जीदावा नं० १ में बतलाया गया है]

६ मुद्दईका दावा है कि मुद्दाअलेह के ऊपर रु० की मय सूद
 (ब्याज) बशरह रु० सैकड़ा सालाना, नालिशकी तारीखसे लेकर रुपया
 वसूल होजानेकी तारीख तक, और मय खर्चाके डिकरी दी जाय ।

परिशिष्ट (अ)

(तस्दीक अर्जीदावा नं० १ में बतलाये अनुसार)

उपरोक्त नालिशमें दाखिल किया जानैवाला बयान तहरीरी

[अदालत वगैराका हवाला अर्जीदावा नं० १ में बतलाये अनुसार]

ऊपर बतलाये मुकद्दमेंमें मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है:—

१ यह कि मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई
 कारण व हक नहीं है ।

२ यह कि मुद्दाअलेहने वह रुक्या, जिसकी निस्वत नालिश है, नहीं लिखा है
 जैसा कि मुद्दईने बयान किया है ।

३ यह कि यह नालिश उस वैमनस्यके कारण दायर की गई है जो फरीकैन
 के बीचमें है ।

४ यह कि मुद्दईने यह नालिश सिर्फ मुद्दाअलेहको परेशान करनेके इरादेसे
 दायरकी है ।

५ यह कि नालिश मय खर्चके खारिजकी जाय और खर्चा दिलाया जाय ।

[तस्दीक और दस्तखत]

(देखो पेज १३१४)

५ नालिश बाबत उस मालके जो बेंचा और हवाले किया गया

[अदालत और फरीकैन वगैराका हवाला नं० १ में बतलाए अनुसार]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है:—

१ यह कि तारीख ५ फरवरी सन् १९१४ ई० को ने इस अर्जी-
 दावाके साथ नस्थी परिशिष्ट में बतलाया हुआ माल मुद्दाअलेहके हाथ बेंचकर
 उसके हवाले किया ।

२ यह कि मुद्दाअलेहने वादा किया था कि वह माल हवाले कर दिये जाने
 पर रु० बाबत कीमत उस मालके अदा कर देगा ।

३ यह कि मुद्दाअलेहने वह रुपया अदा नहीं किया जो उसके और... .. के बीच तय हुआ था, यद्यपि... ..ने इसके लिये बार-बार तकाज़ा किया।

४... ..की तारीख सन् १९१४ई० को मृत्यु होगई। अपनी आखिरी वसीयतके ज़रिये उसने अपने भाई, अर्थात् मुद्दईको अपना साधक (तामील कुनिन्दा वसी) नियत किया।

५ यह कि इस नालिशकी बिनाय मुखासमत तारीख को (माल हवाले किये जाने पर मुद्दाअलेहके उस मालकी कीमत अदा न कर सकने पर) मुक़ाम में, जो इस अदालतके अधिकार-क्षेत्र (हद् अख़्तियार समा-अत) के भीतर है, पैदा हुई।

६ अख़्तियार समाअत और कोर्ट फ़ीसके लिये इस नालिशके दावाकी मालि यत... ..रु० लगाई गई है।

७ मुद्दई... ..रु० की डिक़री मय सूद बशरह ६) रु० सैकड़ा सालाना नालिशकी तारीखसे रुपया वसूल होनेकी तारीखतक और मय खर्चा इस नालिश के दिलापानेके लिये दवेदार है।

परिशिष्ट

[तस्दीक और दस्तख़त]

(देखो पेज १३१४)

उपरोक्त नालिशमें दाख़िल किया जानेवाला बयान तहरीरी

[शीर्षक न० १ में बतलाये अनुसार]

ऊपर बतलाए हुए मुकदमोंमें मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है:—

१ मुद्दईको, मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई कारण व हक़ नहीं है।

२ मुद्दाअलेहने उस मालके लिए कोई आर्डर नहीं दिया था जो अर्जीदावाके साथ नर्थी परिशिष्ट में बतलाया गया है।

३ माल मुद्दाअलेहको हवाले नहीं किया गया।

४ उस मालकी कीमत... ..रु० नहीं थी, जैसा कि अर्जीदावा में बतलाया गया है।

५ मुद्दईकी ओरसे दायर कीगई यह नालिश इस मौजूदा शकलमें काबिल समाअत नहीं है, क्योंकि वह... ..का साधक (तामील कुनिन्दा) नहीं है।

६ नालिश मय खर्च के ख़ारिज की जानी चाहिये और मुझ मुद्दाअलेहका खर्चादिला दिया जाना चाहिये।

[तस्दीक और दस्तख़त]

(देखो पेज १३१४)

६ नालिश बाबत इस्तेमाल और कब्जा

[अदालत, फरीकैन चंगैरा का हवाला अर्जीदावा नं० १ में बतलाए अनुसार]
उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी हैं:—

१ यह कि मुद्दाअलेह ने मुद्दई के मकान पर, जो कि इस अर्जीदावा के साथ नत्थी परिशिष्ट में बतलाया गया है, तारीख.....माह.....सन् १९२७ ई० तक कब्जा व दखल रखवा, और उक्त मकान का इस्तेमाल करने की बाबत अदा की जाने वाली रकम की निश्चत कोई इकरारनामा नहीं किया गया था ।

२ यह कि उक्त मकान के उक्त मियाद तक इस्तेमाल में रखे जाने का उचित दाम ५००) रु० हुआ ।

३ मुद्दाअलेहने यह रुपया अदा नहीं किया है, यद्यपि मुद्दईने इसकी निश्चत बार-बार तकाजा किया ।

४ यह कि इस नालिश की बिनाय मुख़ासमत, मुद्दाअलेह के उस रुपये के अदान करने पर जो उससे तलब किया गया था, इस अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर मुकाम.....में तारीख.....माह.....सन् १९२७ ई० को पैदा हुई ।

५ (जैसा कि अर्जीदावा नं० १ में बतलाया गया है)

५. मुद्दई ५००) रु० की डिकरी के लिए मय सूद वशरह.....रु० सैकड़ा सालाना, नालिश की तारीख से रुपया वसूल होने की तारीख तक, मय खर्चा इस नालिश के दावेदार है ।

परिशिष्ट:

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त नालिश में दाखिल किया जाने वाला

बयान तहरीरी

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी हैं:—

१ यह कि मुद्दाअलेह ने उस मकान को उस मुद्दत तक कब्जे में नहीं रखा जो अर्जीदावा में बतलाई गई है ।

२ यह कि ५००) रु० की रकम जो मुद्दई बाबत इस्तेमाल उस मकान के तलब करता है उचित किराया नहीं है ।

३ यह कि मुद्दाअलेह ने तारीख.....को १०० रु० की रकम बाबत इस्तेमाल के उस मकान के अदा किया और वह समझता है कि ऐसी दशा में यह रकम मुनासिब रकम है।

४ यह कि मुद्दाई को इस नालिश के दायर करने का कोई कारण व हक नहीं है और यह कि इसलिये यह नालिश मय खर्चों के खारिज की जाय व खर्चा मुद्दाअलेह दिलाया जाय।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

७ नालिश बाबत तोड़े जाने साझेदारी के

(फरीकैन वगैरा के हवाले के सम्बन्ध में देखो नं० १ अर्जीदावा)

उपरोक्त मुद्दाई नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है:—

१ यह कि मुद्दाई और मुद्दाअलेह, गत ग्यारह वर्षों से, एक रजिस्ट्री शुद्ध इकरारनामा के अनुसार, जो कि तारीख.....माह.....सन्.....ई० को लिखा गया था और जिसकी रजिस्ट्री ता०.....को हुई थी पुस्तक विक्रेता (बुकसेलर) और प्रकाशक (पब्लिशर) का काम साथ साथ करते आए हैं।

२ मुद्दाई और मुद्दाअलेह के बीच बहसियत साझेदारों के बहुत से झगड़े और मत-भेद उत्पन्न हो गए हैं, जिनके कारण यह असम्भव हो गया है कि वे साझेदारी में अब उस काम को कर सकें और उससे एक दूसरे को फायदा पहुँच सके।

३ यह कि मुद्दाअलेह ने इस साझेदारी के कार-बारमें होने वाले मुनाफा का अनुचित व्यय (तसर्फ बेजा) करके और हिसाब में जालसाजी करके उन शर्तों का भी उल्लंघन कर दिया है जो उक्त इकरारनामा में बतलाई गई है।

४ यह कि इस नालिश के लिए विनाय मुखासमत दावा व मुकाम.....में (जिस स्थान पर कि साझेदार लोग अपना कार-बार करते हैं) तारीख.....को (जिस दिन कि मुद्दाअलेह ने पहिले पहल इकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन किया था) और दूसरी तारीखों को पैदा हुयी।

५ [जैसा कि अर्जीदावा नं० १ में बतलाया गया है]:

६ मुद्दाई प्रार्थी है—

(अ) यह कि साझेदारी का कार-बार तोड़ देने के सम्बन्ध में मुद्दाअलेह के ऊपर डिकरी दी जाय।

(ब) यह कि मुद्दाअलेह से हिसाब तलब किया जाय और जो कुछ रकम मुद्दाअलेह के ऊपर बाजिब निकले उसके सम्बन्ध में उसके ऊपर इस नालिश के खर्चों के सहित डिकरी दी जाय।

(स) यह कि दौरान मुकदमा में, इस साझेदारी के कार-बार का उचित प्रबन्ध करने और उक्त कार-बार की बाबत मिलने वाले रुपये को वसूल करने के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया जाय ।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकदमेंमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ यह कि अदालत को इस नालिश की समागत (सुनाई) करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि साझेदारी की सम्पत्ति की मौजूदा मालियत उस मालियत से अधिक है जिसके सम्बन्ध में समागत करने का अधिकार इस अदालत को है ।

२ यह कि अर्जीदावा के पैरा ३ में लिखी हुई बातें बिल्कुल झूठी हैं। मुद्दाअलेह ने साझेदारी के इकरारनामा में लिखी हुई किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और न उसने कोई जाली हिसाब तैयार किया है ।

३ मुद्दाअलेह अर्जीदावा के पैरा २ में लिखी हुई बातों के सही होने से साफ़ नकार करता है और यह निवेदन करता है कि फ़र्म (दूकान) को मिलने वाले रुपये की तहसील वसूल मुद्दई करता था और वही कार-बार का हिसाब-किताब बनाता था और यह कि इसलिए मुद्दई इस बात के लिए बाध्य है कि वह सही हिसाब-किताब बनाकर मुद्दाअलेह के सामने पेश करे ।

४ यह कि मुद्दई की बहुत सी अनुचित कार्यवाइयों (फेल बेजा) के कारण मुद्दाअलेह ने उससे सही हिसाब-किताब तैयार करके देने के लिए प्रार्थना की किन्तु मुद्दई ने कुछ धूर्त आदमियों के सलाह पर हिसाब दाखिल करने से साफ़ नकार कर दी और उसने बिल्कुल झूठी बातों के आधार पर यह झूठी नालिश तैयार की है ।

५ यह कि मुद्दई को मुद्दाअलेह के ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई कारण बहक नहीं है ।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

८ नालिश बाबत हक असायश वास्ते निकलने

रास्ता और हुक्म इम्तनाई

[अदालत और फरीकैन का विवरण]

(देखो अर्जीदावा नं० १)

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ मुद्दई एक मकान चाकै.....जिसका विवरण इस अर्जीदावा के साथ परिशिष्ट (अ) में दिया हुआ है और इसमें आगे बतलाए हुए समय पर काबिज था ।

२ मुद्दई को मय अपने नौकरों के उक्त मकान से खेत.....पर होकर आम रास्ते पर जाने और वहां से उक्त खेत पर होकर उक्त मकान को वापस आने का हक था ।.....रास्ते का मौका जो मकान से खेत.....पर होकर गया है, और अन्त में आम.....सड़क से जाकर मिल गया है, इस अर्जीदावा के साथ परिशिष्ट (ब) में दिए गए नक्शे में दिखाया गया है ।

३ मुद्दई ने.....रास्ते को खुले तौर पर, शांति के साथ बिना किसी प्रकार की रोक-टोक के और बतौर हक के करीब २० वर्ष के ऊपर तक इस्तेमाल किया है और इस कारण से उसे उसके ऊपर हक असायश पैदा हो गया है ।

४ तारीख.....माह.....सन् १९.....ई० को मुद्दाअलेह ने बेजा तौर पर उक्त रास्ते को, उसके आर-पार टट्टी लगाकर, बन्द कर दिया ताकि मुद्दई उस रास्ते से निकल न सके और तब से उसे बेजा तौर पर बराबर बन्द किए है ।

५ इस नालिश की बिनाय मुखालमत तारीख.....माह.....सन् १९.....ई० को बसुकाम.....जो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में है, पैदा हुई ।

६ [जैसा कि अर्जीदावा नं० १ में बतलाया गया है]

७ मुद्दई प्रार्थी है—

(अ) यह कि मुद्दाअलेह के ऊपर डिकरी दी जाय जिसमें.....रास्ते से होकर मुद्दई के निकलने सम्बन्धी अधिकारकी घोषणा कर दी जाय ।

(ब) यह कि इस मुकदमे के खर्चों के सम्बन्धमें मुद्दाअलेह के ऊपर डिकरी दी जाय ।

(स) यह कि मुद्दाअलेह के ऊपर हमेशा के लिए यह हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाय कि वह उस रास्ते के सम्बन्धमें, जिसकी निस्वत नालिश दायर की गई है, कोई रुकावट न डाल सके ।

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट (ब) (नक्शा)

(तस्दीक और दस्तखत)
देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकदमों में जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि]

जैसा अर्जीदावा नं० १ में है।

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ मुद्दई को मुद्दाअलेह के ऊपर यह नालिश दायर करने का कोई हक वारण नहीं है।

२ मुद्दाअलेह अर्जीदावा के दूसरे और तीसरे पैरों में बतलाई गई बातों की सत्यता को अस्वीकार करता है और निवेदन करता है कि उस रास्ते का, जिसकी निस्वत नालिश दायर की गई है, कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जैसा कि अर्जी ने बतलाया है।

३ मुद्दई ने अपना यह मौजूदा मकान सिर्फ़ तेरह साल हुए जब खरीदा और इसके बाद से वह उसमें रहता है, और इसलिये जिस रास्ते के इस्तेमाल निस्वत नालिश की गई है वह बीस साल से ऊपर नहीं हो सकता।

४ यह कि उस रास्ते के इस्तेमाल को मुद्दाअलेहने दो साल हुए तेरह महीने लिये बन्द कर दिया था और सिर्फ़ मुद्दई के खुशामद बरामद करने पर मुद्दाअलेह ने केवल थोड़े समय के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल करने के लिये मुद्दई को आज्ञा दे दी थी।

५ यह कि ऐसी दशा में मुद्दई को उक्त रास्ते के इस्तेमाल के सम्बन्ध में उसके लिए नालिश है, हक असायश पैदा नहीं हो सकता और इसलिए उसे हुकम जारी करवाने का हक नहीं है जिसके लिये उसने प्रार्थना की है।

६ यह कि जो नक़्शा अर्जीदावाके साथ दाखिल किया गया है उसमें बहुत बातें ग़लत हैं और उसमें उसके इर्द गिर्द के स्थानोंका मौक़ा ठीक नहीं दिखाया गया है। मुद्दाअलेह इस जवाब दावा के साथ एक नक़्शा दाखिल करता जिसमें इर्द गिर्द के स्थानोंका, उस रास्ते का, किसकी निस्वत नालिश है, मौक़ा ठीक दिखलाया गया है।

७ यह कि मुद्दई ने यह झूठी नालिश मुद्दाअलेह को परेशान करने के लिये दायर की है, क्योंकि उनके (फ़रीक़ेन के) बीच आपस में कुछ झगड़ा है।

८ चूंकि मुद्दई ने रास्ता सुतनाज़ा का इस्तेमाल इस नालिशके दायर किये के पहिले बीस साल तक नहीं किया, इसलिये इस नालिश की तमादी आगे नहीं होगई है।

९ यह कि नालिश मय खर्चोंके ख़ासिज होनी चाहिये और खर्चा दिला दिया जाना चाहिये।

नक़्शा

[तस्दीक और दस्तख़त]

देखो पेज १३। १४

६ अदावतन् मुकद्दमा चलाए जानेकी बाबत नालिश

[फरीकैन वगैरा का हवाला अर्जीदावा नं० १ में देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ तारीख ... माह ... सन् ... ई० को मुद्दाअल्लेह ने खयानत मुजरिमाना के झूठे अभियोग के ऊपर मुद्दई की गिरफ्तारी के लिए एक चारण्ट गिरफ्तारी ... डिपुटी मजिस्ट्रेट की अदालत से हासिल किया और इसके परिणाम स्वरूप मुद्दई गिरफ्तार किया गया और दो दिन कैद में रखा गया और अपनी रिहाई के लिये उसने ... रु० की जमानत दाखिल की।

२ यह कार्रवाई मुद्दाअल्लेह ने अदावतन् और बिना किसी उचित अथवा सम्भव कारण के की।

३ तारीख ... माह ... सन् ... ई० को उपरोक्त डिपुटी मजिस्ट्रेटने मुद्दाअल्लेह का इस्तग़ासा खारिज कर दिया और मुद्दई को बरी कर दिया। उक्त फौजदारी अदालतके फैसलेकी तस्दीक शुद्ध नकल इसके साथ दाखिलकी जाती है।

४ उक्त गिरफ्तारी के कारण मुद्दई को, जनताकी निगाहोंसे गिर जानेके अतिरिक्त, बहुत कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ा और वह अपना कार बार भी नहीं कर सका, और उसकी साख को भी बहुत कुछ धक्का पहुँचा और उसे उक्त कैद से रिहाई पाने और उक्त इस्तग़ासे के खिलाफ़ पैरवी करने में खर्चा उठाना पड़ा।

५ यह कि इस नालिश के लिये बिनाय मुख़ासमत तारीख ... को मुक़ाम ... में, जो इस अदालत के आधिकार क्षेत्र के भीतर है, पैदा हुई।

६ ऐसी दशा में मुद्दई (६००) रु० बाबत हर्जा के, जो उसे शारीरिक और मानसिक कष्टों के कारण और कार बार (व्यापार) तथा प्रसिद्ध को हानि पहुँचने के कारण हुआ है, और (५००) रु० बाबत उस खर्च के जो उसे उपरोक्त फौजदारी मुकद्दमे की पैरवी में उठाना पड़ा दिला पाने का दावेदार है।

७ अख्तियार समाप्त और कोर्ट फीस के लिये दावा की मालियत (११००) रु० लगाई गई है।

८ मुद्दई दावा करता है—

(अ) यह कि मुद्दई के हक में मुद्दाअल्लेह के ऊपर (११००) रु० की डिकरी मय खर्च के दीजाय।

(ब) यह कि अदालत कोई भी दूसरी दादरसी दिला सकती है जो वह ऐसी अवस्था में उचित समझे।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३। १४

उपरोक्त मुकदमेंमें जवाब दावा

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

उपरोक्त मुकदमेंमें मुद्दाअलेह नीचे लिखा निवेदन करता है :—

१ मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर इस नालिशके दायर करनेका कोई कारण बतक नहीं है।

२ मुद्दईको मुद्दाअलेहने बतौर अपने मुखतार (कारिन्दा) के असामियोंसे लगानकी तहसील वसूल करनेके लिए नौकर रखा था। मुद्दईने फरेबसे..... रु० की रकम, जो उसने असामियोंसे तहसीलकी थी, बेजातौर पर सर्फ करदी और इसलिये मुद्दाअलेहने नेक नीयतीके साथ फौजदारी अदालतमें मुद्दईके ऊपर मुकदमा चलाया। मुकदमा फैसल करनेवाले मजिस्ट्रेटने यह मुकदमा रूय-दादके ऊपर नहीं बलिक जाबता फौजदारीकी दफा२०३ के अनुसार यह कह कर खारिज कर दिया कि उसकी समाप्त अदालत दीवानी द्वाराकी जानी चाहिए।

३ मुद्दई एक संदिग्ध आचरण (मशकूक चाल चलन) का आदमी है और समाजमें उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि वह सन् १९०७ ई० में ख़यानत मुजरिमानाके अभियोगमें फौजदारी अदालतसे सज़ा पाचुका है।

४ मुद्दईको फौजदारी मुकदमेंकी पैरवी करनेमें ५००) रु० का खर्चा नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि उसकी पैरवी एक मुखतारने की थी।।

५ मुद्दई कोई हर्जा दिला पानेका हक़दार नहीं है, क्योंकि उसके पहिलीबार सज़ा पाजानेके कारण जनताकी निगाहोंमें समाजसे उसकी प्रतिष्ठा पहलेही उठ जाचुकी है और यह कि यह दावा अधिक है।

६ यह कि नालिश मय खर्चके खारिजकी जानी चाहिए। और मुद्दाअलेहका खर्चा दिला मिलनेका हुक़म होना चाहिए।

[तस्दीक और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

१० वसीके ऊपर नालिश, बाबत दिलापाने उस आमदनी के जो वसीयतनामेंमें बतलाई गई है

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है :—

१ ... साकिन ... ज़िला ... की तारीख
... माह ... सन् १९ ... ई० को मृत्यु होगई। उसने अपने तारीख
... माह ... सन् १९ ... ई० को लिखे गए आखिरी वसीयत नाकाम

जरिये मुद्दाअलेहको अपना वसी मुकर्रर किया और अपनी सारी जायदाद, मन-कूला और गैर-मनकूला अपने वसीके नाम वसीयत करदी है, कि वह उससे होने वाली आमदनी और उसके लगानको मुद्दईको जिन्दगीभर अदा करता रहे और बाकीको उसके मरजानेके बाद, मवसी के कानूनी वारिसोंको ।

२ यह वसीयत मुद्दाअलेहने तारीख माह सन् १९.....ई० को... के जिला-जजकी अदालतमें बाकायदा तौरसे साबित कर दी थी ।

३ मरनेके समय मवसी (Testator) जायदाद मनकूला और गैर-मनकूलाका हकदार था; मुद्दाअलेहने जायदाद गैर-मनकूलाके लगानकी रसीद लिखदी और जायदाद मनकूला उसको मिल गई; उसने जायदाद गैर-मनकूलाका कुछ हिस्सा बेंच लिया और उस जायदाद का ठीक ठीक हिसाब दाखिल नहीं किया, यद्यपि मुद्दईने तारीख.....को उसे तलब किया ।

४ यह कि इस नालिशकी बिनाय मुखासमत (मुद्दाअलेहके ठीक ठीक हिसाब दाखिल न करने पर) तारीख को बमुकाम पैदा हुई जो कि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है ।

५ जैसा कि नं० ९ के पैरा ८ में है ।

६ मुद्दईका दावा है—

(१) कि की जायदाद मनकूला और गैर-मनकूला का प्रबन्ध इस अदालतमें किया जाय और इस कामके लिए तमाम मुनासिब हिदायतें दी जाय और हिसाब लेलिया जाय ।

(२) और भी ऐसी कोई दादरसी दिलाई जाय जो इस मुकद्दमेंमें मुनासिब मालूम हो ।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पज १३, १४

उपरोक्त मुकद्दमेंमें जवाब दावा

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

मुद्दाअलेहका नीचे लिखा निवेदन है:—

१ मुतौफी मवसी (वसीयत कुनिदा)के वसीयतनामामें कर्जेकी रकम भी तहरीर थी; जिस समय वह मरा है उस समय वह दिवालिया हो गया था; उसके मरने पर वह कुछ जायदाद मनकूलाकी निस्वत कर्जदार था जिसे मुद्दाअलेहने बेच डाला और जिससे कुल) रु० की आमदनी थी और मवसीके पास कुछ जायदाद मनकूला थी जिसे मुद्दाअलेहने अपने कब्जेमें ले ली और जिससे कुल) की आमदनी होती थी ।

२ मुद्दाअलेहने उपरोक्त कुल रुपया और रु० की रकम, जो कि मुद्दाअलेहको उस जायदाद गैर-मनकूलाके लगानके निस्वत वसूल हुई थी, किया-कर्म और वसीयत लिखने आदि कामोंमें और मवसीके कुछ कर्जा अदा करनेमें खर्च कर डाला ।

३ मुद्दाअलेहने अपना हिसाब ठीक करके उसकी एक नकल तारीख ... माह ... सन् १९... ई० को मुद्दईके पास भेज दी और मुद्दईको इस बातका पूर्ण अधि-कार दे दिया कि वह इस हिसाब-किताबकी जांच करनेके लिए वाउचरोंको देखे, लेकिन उसने मुद्दाअलेहकी इन बातोंको स्वीकार नहीं किया ।

४ मुद्दाअलेहकी प्रार्थना है कि मुद्दईको इस मुकद्दमेंका खर्चा अदा करने का हुक्म हो और दावा खारिज हो ।

(तस्दीक और दस्तखतः)

देखो पेज १३।१४

११ दस्तावेज रेहननामाके ऊपर नीलाम या बैवात की बाबत नालिश

[शीर्षक फरीकैन वगैरा]

उपरोक्त मुद्दईका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है:—

१ मुद्दई उस आराजीका मुतंहिन है जो कि मुद्दाअलेहकी मिलिकयत है और जो इस अर्जीदावाके साथ लगी हुई सूची (फ़ेहरिस्त) (अ) में तफ़सीलवार बतलाई गई है ।

२ रेहननामाकी खास २ बातें नीचे लिखे अनुसार हैं:—

(क) तारीख ३० जून सन् १९१२ ई० को मुद्दाअलेहने एक बाकायदा दस्तावेज रेहननामा बहक मुद्दई रु० की निस्वत, जो कि मुद्दईने उसे कर्ज दिये थे, लिख दिया जिसके जरिये सूची (अ) में बतलाई हुई जायदाद बहन कर दी ।

(ख) [राहिन और मुतंहिनके नाम]

(ग) [जो रुपया लिया गया हो]

(घ) [व्याजकी दर]

(ङ) [जायदाद मरहूना] जो कि सूची (अ) में बतलाई गई है ।

(च) अब रु० की रकम मुद्दईको मुद्दाअलेहसे बाबतअसल मप सुदके, जैसा कि अर्जीदावाके साथ लगी हुई सूची (ब) में हिसाब दिया गया है, वाजिब है ।

(छ) [अगर मुद्दईको उस जायदादकी हकीयत किसी दूसरे शाखसे हासिल हुई है तो यहां पर संक्षेपमें लिखना चाहिये कि किस मुतकिलीके जुरिये उसे दावाका यह हक हासिल हुआ है]

३ मुद्दईके बार-बार मांगने पर भी मुद्दाअलेहने उस रुपयेको जो वाजिब है, अदा नहीं किया ।

४ इस नालिशके लिए मुद्दईकी विनाय मुखासमत तारीख...को [जो तारीख वास्ते अदायगी रुपया दस्तावेजमें बतलाई गई है] बमुकाम..... पैदा हुई जो कि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है

५ मुकद्दमाकी मालियत दावा वास्ते अखितयार समाअत) रु० है और कोर्ट-फीसके लिए) रु० है ।

६ मुद्दईका दावा है:—

(क) यह कि मुद्दाअलेहके ऊपर.....) रु० की, मय खर्चा मुकद्दमा और सूद आयन्दा बशरह मुद्दईके दस्तावेज दिनों पर, एक प्रारम्भिक डिकरी दी जाय, और यह कि उस डिकरीमें उस रकमकी, जो कि वाजिबुलअदा है, अदायगीके लिये एक समय नियत कर दिया जाय, और यह कि अगर उस नियत समयके भीतर रुपया अदा न हो तो मुद्दईका कुल रुपया जायदाद मरहूना के नीलामसे वसूल करनेका हुकम दिया जाय ।

[यहां पर आर्डर ३४, रूल ६ लागू होता है]

देखो पेज १८१

(ख) यह कि अगर नीलाममें वसूल हुई रकम, मुद्दईका कुल रुपया अदा करनेके लिए काफी न हो, तो मुद्दईको यह अधिकार दिया जाय कि वह बाकी रुपयेके लिए मुद्दईके जिरमके ऊपर डिकरी दिए जातेके लिए दरखास्त दे सके ।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

सूची (अ), तफसील जायदाद ।

सूची (ब), हिसाब ।

नोट—अगर नालिश बाबत बैबातके है, तो कलॉज (६ क) में यह मज़मून जोड़ देना चाहिये:—“और अगर नियत समयके भीतर रुपया न अदा किया जाय तो बैबात (और कब्ज़ा) की बाबत हुकम दिया जाय जिससे मुद्दाअलेहको जायदादकी फकरेहतीका कोई हक बाकी न रहे और मुतहिनको आराज़ी मरहूनासे फ़ाददा उठानेका पूरा अखितयार हासिल हो जाय ।”

उपरोक्त मुकदमेंमें जवाब दावा

[शीर्षक फरीकैन वगैरा।]

उपरोक्त मुकदमेंमें मुद्दाभलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ मुद्दाईको मुद्दाभलेहके ऊपर यह नालिश दायर करनेकी बिनाय मुद्दा-
मत पैदा नहीं हुयी है।

२ मुद्दाभलेह इस बातको स्वीकार करता है कि जिस दस्तावेज़की निस्वत
नालिश है, वह दस्तावेज़ उसने लिखा है, लेकिन उसका कहना यह है कि उसे
सिर्फ) रु० ही बाबत जुज मतालवा उस दस्तावेज़की तकमीलके वक्त
मिले हैं फरीकैनके बीच यह तय पाया था कि मुद्दाभलेहको दस्तावेज़की तकमीलके
वक्त सिर्फ) रु० ही मिलेंगे और यह कि बाकी रुपया उसे धीरे धीरे, जब २ उसे
जूरत पड़ती रहेगी, मिलता रहेगा लेकिन वास्तवमें मुद्दाभलेहको बकाया रुपया
लेनेका कभी भी मौका नहीं आया।

३ मुद्दाईकी नालिश कानून मियादके द्वितीय परिशिष्टके आर्टि० के
अनुसार तमादी आरिज़ हो गई है।

या

१ मुद्दाभलेहने दस्तावेज़ नहीं लिखा था या यह कि कानूनके अनुसार उस
पर बाकायदा तौरसे गवाही नहीं की गई थी।

२ रेहन नामाकी मुन्तकिली मुद्दाईके नाम नहीं की गई थी [अगर एकसे
यादा मुन्तकिलियां की गई हैं तो यह लिखना चाहिए कि किस मुन्तकिली
से इन्कार है]।

३ कानून मियादके द्वितीय परिशिष्टके आर्टि० के अनुसार नालिशकी
मियाद आरिज़ होगई है।

४ नीचे लिखी रकमें अदा की गई हैं (यहां पर उसकी तफ़्सील और
बारीख़ देनी चाहिए)

५ मुद्दाईने तारीख़ माह सन् ई० को कब्ज़ाले लिया
था और उस समयसे लगान वसूल कर रहा है।

६ यह कि जिस समय तस्फ़िया या हिस्सा किया गया था उस समय मुद्दाईने
उस दस्तावेज़का रुपया वसूल किया था।

७ मुद्दाभलेहने तारीख़ के दस्तावेज़के जरिये अपने कुल हक्क
को मुन्तकिल कर दिया था।

तस्दीक और दस्तख़त

देखो पेज १३१४

१२ नालिश बाबत दस्तावेज रेहन नामा दखली या गैर-मामूली,

[शीर्षक-फरीकैन वगैरा]

मुद्दई नीचे लिखे अनुआर निवेदन करता है—

१ (जैसाकि नं० ११ में है)

२ (जैसाकि नं० ११ में है)

३ मुद्दईने तारीख को जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया और दस्तावेज की शर्तोंके अनुसार आराज़ीका मुनाफ़ा, या सूद (ब्याज)में मुजराहोगया [या]

यह कि मुद्दईने तारीखको जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया और उस समयसे बतौर मुर्तहिन काबिज़के हिसाब देनेको तैयार हैं और यह कि तस्फ़िया हिसाब होजाने पर [जैसाकि सूची (ब) में जोकि अर्जीदावाके साथ दिखलायी गयी है] उसी रेहन नामाकी बाबत मुद्दईको मुद्दाअलेहसे मिलना है।

४ (जैसाकि नं० ११ के पैर ३ में है)

५ (जैसाकि नं० ११ के पैरा ४ में है)

६ (जैसा कि नं० ११ के पैरा ५ में है)

७ मुद्दईका दावा है कि—

(क) मुद्दाअलेहके ऊपर एक डिकरी बाबत) रु० के मय खर्चा और सूद बशरह ६) रु० सैकड़ा ता तारीख वसूली रुपयेके दीजाय या यह कि जायदादके वासिलातका हिसाब लिया और दस्तावेजमें बतलाए अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाय और जो रुपया बाकी निकले उसकी निस्वत मय सूद बशरह ६) रु० सैकड़ा सालाना ता तारीख अदायगी रुपयाके मुद्दाअलेहके ऊपर डिकरी दीजाय ।

सूची (अ) [तफ़सील जायदाद]

तस्दीक और दस्तखत

सूची (ब) [हिसाब]

(देखो पेज १३।१४)

नोट—मुर्तहिन काबिज़को, बहसियत ऐसे मुर्तहिनके, नीलाम या बैबातका हक न होगा, जब तक कि उस दस्तावेजमें प्रकट अथवा अप्रकट रूपसे ऐसी कोई शर्त न हो जो उसे ऐसा अधिकार देती हो [देखो कानून इन्तक़ाल जायदादकी दफ़ा ६७] अगर किसी खास शर्तसे नीलामका हक विशेष अवसर पर काममें लाए जानेके लिए ही रख छोड़ा गया है, तो यह रेहन नामा गैर-मामूली समझा जायगा और ऐसी दशामें मुद्दईको अधिकार होगा कि नियत समय पर डिकरीका रुपया अदा नकिए जाने पर वह जायदाद मरहूनाकी नीलामके लिए दरखवास्त करे ।

[दस्तखत और तस्दीक]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकदमेंमें बयान तहरीरी

[शीर्षक फरीकैन वगैरास]

मुद्दाअलेहका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है:—

१ मुद्दाअलेहने दस्तावेज मुतनाजाको मुद्दईके हकमें लिखा ।
२ मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करने की बिनाय मुखा-
समत पैदा नहीं है ।

३ भारतीय कानून मियाद सन १९०८ई०के द्वितीय परिशिष्टके आर्टि०.....के
अनुसार इस नालिशकी मियाद आरिज होगई है ।

४ नीचे लिखी रकमें अदा कीगई हैं, अर्थात्:—

३ मार्च सन १९०९ ई०..... २५०) रु०

७ जून सन १९०९ ई०..... २५०) रु०

जोड़ ५००) रु०

५ मुद्दईने जायदाद मरहूनाके ऊपर तारीख.....माह.....सन.....
को कब्जा कर लिया था और तबसे लगान और मुनाफाका रुपया लेता रहा है
६ यह कि तारीख.....को हिसाबका तस्फिया हुआ था जब कि मुद्दईने
उक्तके रुपयेकी फारखती करदी थी ।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

१३ नालिश बाबत इन्फिकाक रेहन

[फरीकैन वगैराकी तफसील जैसा कि नं० १ में है]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ मुद्दई सूची (अ) में [जोकि इसके साथ नरथी है] बतलाई गई आराजी
राहिन है जिसका कि मुद्दाअलेह मुतहिन है ।

२ रेहन नामाकी तफसील नीचे लिखे अनुसार है:—

(क) यह कि मुद्दईने.....रु० की निस्वत मुद्दाअलेहके हकमें एक
दस्तावेज रेहननामा तारीख.....माह.....सन.....ई० को लिख दिया था और
उसके जरियेसे सूची (अ) में बतलाई हुई जायदाद रेहन करदी थी ।

(ख) जैसाकि नं० ११ में है ।

(ग) " " ।

(घ) " " ।

(ङ) " " ।

(च) " " ।

[अगर मुद्दाअलेह मुतहिम काबिज़ है, तो नीचे लिखी बातें जोड़ दी जानी चाहिये]

३ उक्त दस्तावेज़ रेहननामामें यह भी इकरार हुआ था कि मुद्दाअलेह सूची (अ) में बतलाई हुई जायदादको अपने कब्ज़ेमें लेंलेगा और यह कि उस इकरारनामाके अनुसार उसने तारीख्.....माह.....सन्ई० को उस पर दखल कर लिया और उसके लगान तथा मुनाफ़ाकी तहसील-वसूल करता रहा और हिसाबका ताफ़िया होने पर तारीख्.....को यह मालूम हुआ कि असल का रुपया, जोकि उस दस्तावेज़के ऊपर लिया गया था, मय सूद वशरह मुन्दरजे दस्तावेज़के अदा कर दिया गया है। और यह कि मुद्दईको सूची (ब) में बतलाए हुए.....की रकम मुद्दाअलेहको वापस करनी होगी, लेकिन तो भी मुद्दाअलेहने दस्तावेज़ वापस करनेसे इन्कार कर दिया, यद्यपिरुपया उसके सामने पेश कर दिया गया था। दस्तावेज़ मुतनाज़ाकी एक तस्दीकशुदः नक़ल इसके साथ नत्थीकी जाती है।

४ यह कि इस नालिशके लिए बिनाय मुख़ासमत तारीख्.....को (जब कि मुद्दाअलेहने फारखती करके दस्तावेज़ वापस देनेसे इन्कार किया) बमुक़ामपैदा हुई जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है।

५ जैसा कि अर्ज़ीदावा नं० ११ के पैरा ५ में है।

६ मुद्दईका दावा है कि—

(क) सूची (अ) में बतलाई हुई जायदादकी फ़क़रेहनी कर दी जाय और वह जायदाद उसके नाम फिर मुन्तक़िल कर दी जाय और उस पर क़ब्ज़ा दिला दिया जाय।

(ख) दस्तावेज़ मुतनाज़ाके हिसाब किताबकी बाबत मुद्दाअलेहके ऊपर एक डिकरी दे दी जाय।

(ग) जो कुछ रुपया मुद्दाअलेहके जिम्मे बाकी निकले उसकी बाबत मुद्दाअलेहके ऊपर डिकरी दी जाय और यह कि जिस दस्तावेज़की निस्बत झगड़ा है वह बेचाक हुआ करार दिया जाय।

(घ) एक डिकरी बाबत खर्चा मुक़दमाके मुद्दाअलेहके ऊपर दी जाय।

(ङ) दूसरी ऐसी कोई औरभी दादरसी दिलाई जाय जैसी कि मुक़दमें की ऐसी अवस्थासे अदालतको आवश्यक प्रतीत हो।

सूची (अ) जायदाद जो रेहन की गई है।

सूची (ब) हिसाब किताब।

[तस्दीक और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकदमेमें जवाब-दावा

[शीर्षक जैसाकि नं० १ में है]

मुद्दाअलेहका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है:—

- १ मुद्दईके हक इन्क़िफ़ाक़ रेहनकी मियाद, भारतीय क़ानून मियाद सन् १९०६ई० के द्वितीय परिशिष्टकी आर्टि०.....के अनुसार तमादी आरिज़ होगई है।
- २ मुद्दईने जायदादमें अपने कुल हकूक.....को मुन्तक़िल कर दिये हैं।
- ३ मुद्दाअलेहने तारीख्.....माह.....सन्.....ई० के एक दस्तावेजके त्रिये जर-रेहन और जायदाद मरहूनामें [जोकि अर्ज़ीदावाके साथ नत्थी सूची (अ) में बतलाई गई है] अपने कुल हकूक.....को मुन्तक़िल कर दिए।
- ३ मुद्दाअलेहने कभी भी जायदाद मरहूना पर कब्ज़ा नहीं लिया और न उसका लगान और मुनाफ़ाही वसूल किया।
- ५ यहकि मुकदमा मय खर्च के ख़ारिज़ किया जाय और खर्चा मेरा दिलाया जाय [तस्दीक़ और दस्तख़त] देखो पेज १३।१४

१४ नालिश बाबत बेदख़ली

∴ [फ़रीक़ेनकी तफ़सील वग़ैरा जैसा नं० १ है]

उपरोक्त मुद्दईका नीचे लिखा निवेदन है:—

१ मुद्दाअलेह मुद्दईकी ज़मीन अहाता वाक़े.....पर जिसकी म्योरेवार तफ़सील सूची (अ) में जोकि अर्ज़ीदावाके साथमें नत्थी है, बतलाई गई है, बहसियत रैयत, सालाना मुद्दत रैयतीके ऊपर कब्ज़ि़ था।

२ यह कि तारीख्.....माह.....सन्.....ई० को मुद्दाअलेहने उक्त हाते की ज़मीनको १२) ४० सालाना लगानके ऊपर उस पर मक़ान बनानेके लिए छेलिया जिसमें वह बादमें रहना चाहता था और उनका इस्तेमाल करना चाहता था।

३ मुद्दईने १५ भाद्र सन् १३१९ फ़सलीको मुद्दाअलेहको एक लिखित नोटिस इस आशयकी दी कि वह ३० चैत्र सन् १३१९ फ़सली तक उक्त ज़मीनको खाली करदे यह नोटिस एक रजिस्ट्री शुद्ध लिफ़ाफ़ामें बजरिये डाक भेजी गई थी। मुद्दाअलेहने यह नोटिस नहीं ली और वह इस अर्ज़ीदावाके साथ नत्थीकी जाती है बादमें मुद्दईने एक ऐसीही नोटिस उस हाताकी ज़मीनके ऊपर भी तामील कराई लेकिन मुद्दाअलेहने अभी तक उस परसे अपना कब्ज़ा नहीं छोड़ा है।

४ इस नालिशकी बिना मुखासमत वसुकाम.....जोकि इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें हैं तारीख्.....बैसाखकी प्रतिपदा सन् १३२० फ़सली अर्थात् नोटिसमें दिये गए समयकी मुद्दत गुज़र जानेके बादकी तारीख़को पैदा हुई

५ जैसाकि अर्जीदावा नं० २ के पैरा ८ में है ।

६ मुद्दईका दावा है कि:—

(क) मुद्दाअल्लेहको बेदखल करके ज़मीन मुतनाज़ा के ऊपर कब्ज़ा के लिये मुद्दईके हकमें डिगरी दीजानी चाहिये ।

(ख) यह कि खर्च की बाबत मुद्दाअल्लेह के ऊपर डिगरी दीजाय ।

(ग) ऐसी कोई दूसरी और दादरसी दिलाई जाये जो इस मुकद्दमें की ऐसी हालतमें ज़रूरी मालूम होवे ।

सूची (अ)—[तफ़्सील ज़मीन]

[तस्दीक और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकद्दमेमें दाखिल किया जाने वाला बयान तहरीरी

[फ़रीक़न मुकद्दमा वगैरा की तफ़्सील देखो नं० १]

मुद्दाअल्लेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ यह कि मुद्दई के पास मुद्दाअल्लेहके ऊपर नालिश दायर करने का कोई हक व कारण नहीं है ।

२ मुद्दई ने मुद्दाअल्लेह पर कोई नोटिस ज़मीन ख़ाली कर देने के निश्चय तामील नहीं की जैसा कि अर्जीदावा के पैरा ३ में बतलाया जाता है ।

३ यह कि मुद्दई का सहोदर (सगा) भाई... .. जायदाद मुतनाज़ा में भाठ आनेका हिस्सेदार है और चूँकि वह भाई इस मुकद्दमें में फ़रीक़ नहीं बनाया गया है इसलिये उसके फ़रीक़ न बनाये जानेके कारण मुकद्दमा नहीं चल सकता है ।

४ मुद्दाअल्लेह को ज़मीन मुतनाज़ा के ऊपर पक्की इमारत बनाने में करीब १०,०००) रु० खर्च करना पड़ता है और इसलिये इसका निवेदन यह है कि अगर मुद्दई के हक में कब्ज़ा की डिगरी दे दीजाय तो मुद्दाअल्लेह को अपनी इमारत का खर्चा दिला मिलेगा ।

[तस्दीक और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

१५ क़ानून दादरसी खासकी दफ़ा ६ के अनुसार नालिश

[फ़रीक़न मुकद्दमा वगैराकी तफ़्सील देखो नं० १]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ यहकि मुद्दई मौज़ा.....में बाक़े ज़मीनका मालिक है जिसकी द्योरेवार तफ़्सील सूची (अ) में जो कि अर्जीदावा के साथ नत्थी है और यह कि वह बारह साल से उक्त ज़मीन पर काबिज़ रहा है और उसे बज़रिये अपने नौकरों के जोतता रहा है ।

६ यह कि वह इस नालिश के दायर होने के लः महीने पहिले से उस जायदाद पर काबिज़ था और यह कि तारीख माह ... सन् ... ई० को मुद्दाअलेह ने जबरदस्ती उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और उसे जोतने, खोदने व बोन लगा और इस तरह पर मुद्दई को उस ज़मीन पर से कब्ज़ा उठा दिया।

३ यह कि इस नालिशकी बिनाय मुखासमत बमुकाम जो कि इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में है तारीख ... को (जिस तारीख को कि मुद्दई का कब्ज़ा उठा दिया गया था) पैदा हुई।

४ जैसा कि अर्जीदावा नं० २ के पैरा नं० ८ में बतलाया गया है।

५ मुद्दई प्रार्थी है कि—

(क) मुद्दईके हकमें एक डिकरी बाबत दिलापाने कब्ज़ा जायदाद मुतनाज़ा पर दीजाय।

(ख) यह कि एक डिकरी मुद्दाअलेहके ऊपर इस मुकद्दमेंके खर्चके बाबत दीजाय।

सूची (अ)

[तरदीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकद्दमेंमें जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि नं० १ देखो]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ मुद्दईके पास मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करनेका कोई कारण नहीं है।

२ मुद्दई यह नालिश दायर होनेके पहले महीनेके भीतर या इससे कभी पहले जायदाद मुतनाज़ाके ऊपर काबिज़ नहीं था। मुद्दईके मुकद्दमेंकी मियाद खारिज़ होगई है।

३ मुद्दाअलेहने जायदाद मुतनाज़ाको तारीख माह सन् ई० को खरीदा था और उस पर अपने असामियोंके ज़रिये क़रीब १२ सालसे काबिज़ है।

या यह कि मुद्दाअलेहने उस जायदाद पर बमूजिब उस रेहननामा दखली के कब्ज़ा कर लिया जो मुद्दईने उसके हकमें (५०) रु० के कर्ज़के बदलेमें लिख दिया था।

४ कब्ज़ा करलेने और कब्ज़ासे अलग कर देनेके सम्बन्धमें मुद्दईने अपने अर्जीदावाके पैरा १ और २ में जो बातें कही हैं वे बिल्कुल झूठी हैं। मुद्दाअलेह या उसके असामियों, किसीने भी मुद्दईको ज़मीन मुतनाज़ासे बेदखल नहीं किया।

५ यह कि मुकद्दमामय खर्चके खारिज़ किया जाय और खर्चा दिलाया जाय।

[तरदीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

१६ नालिश बाबत दिलापाने उस रूपयेके, जो किसी शरूस्को उसके हकके अनुसार मिलना चाहिये था

[तफसील फरीकैन मुकदमा वगैरा नं० १ देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ मुद्दई एक मुस्तकिल कब्ज़ा आराज़ीका, जोकि मौज़ा.....में चाकै है और जिसकी ब्योरेवार तफसील इस अर्ज़ीदावाके साथ नत्थी सूची (ब) में बतलाई गई है, कब्ज़ेदार है। उसको उक्त कब्ज़ा आराज़ीकी निस्वत.....)रु० सालाना बाबत लगानके श्री.....को देने पड़ते हैं।

२ मुद्दाअलेह उक्त कब्ज़े आराज़ीमें आठ आनाका हिस्सेदार है। चूंकि मुद्दाअलेहने उक्त आराज़ीके ज़मीन्दारको लगानके अपने हिस्सेको अदा नहीं किया है, इसलिए उसने मुद्दई और मुद्दाअलेह दोनोंके ऊपर बकाया लगानकी बाबत एक नालिश दायर की। उस नालिशकी तारीख.....को डिकरी दे दी गई और उक्त डिकरीकी इजरामें ज़मीन्दारने उक्त आराज़ीको तारीख.....को नीलाम पर चढ़वा दिया। उस आराज़ीमें अपने हिस्सेको बचानेकी गरजसे मुद्दईने तारीख.....को मय खर्चा डिकरीका रुपया अदालतमें जमा कर दिया और इस तरह पर उस आराज़ीको इजरामें नीलाम होनेसे बचा लिया। इस तरह पर डिकरीका रुपया अदा कर दिए जानेसे मुद्दाअलेहको फायदा पहुँचा और इसलिए वह उसका भाधा हिस्सा मुद्दईको देनेके लिए बाध्य है। उपरोक्त डिकरीकी एक तस्दीकशुदः नकूल इसके साथ नत्थीकी जाती है।

३ मुद्दई मुद्दाअलेहके ऊपर १२)रु० सैकड़ा सालाना ब्याजके साथ उस रूपयेके आधेकी जोकि अदालतमें जमा किया गया है, डिकरीदिलापानेका हकदार है।

४ इस नालिशकी बिनाय मुख़ासमत बमुक़ाम....., जोकि इस अदालत के अधिकार क्षेत्रमें है, तारीख.....को (जिस तारीखको कि डिकरीका रुपया अदालतमें जमा किया गया था) पैदा हुई।

५ जैसा कि अर्ज़ीदावा नं० २ के पैरा ८ में बतलाया गया है।

६ मुद्दईकी प्रार्थना है कि—

(क) मुद्दाअलेहके ऊपर मय ब्याज.....की (जैसा कि अर्ज़ीदावाकी सूची (अ) में बतलाया गया है) और मुकदमेके खर्चोंकी डिकरी दे दी जाय।

(ख) दूसरी और ऐसी दादरसी दिलाई जाय जो मुकदमेंकी ऐसी हालत में ज़रूरी मालूम हो।

सूची (अ)—[हिसाब]

सूची (ब)—[आराज़ी]

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेन १३।१५

उपरोक्त मुकद्दमेंमें जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि नं० १ देखो]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

- १ मुद्दईको मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करनेका कोई कारण नहीं है।
- २ मुद्दाअलेहने उस आराज़ीके लगानका अपना हिस्सा ज़मीन्दारको अदा कर दिया और लगानकी इस नालिशके दायर होनेके पहले उसे उसकी रसीदभी मिल गई थी। इसलिए मुद्दई मुद्दाअलेहसे कोई भी रकूम वाचत हिस्सा लगानके दिखानेका हकदार नहीं है।
- ३ चूंकि मुद्दईने लगानकी डिकरी और इसके अनुसार होने वाली कुर्की और बीलामके पहले डिकरीका कुल रुपया अदालतमें जमा कर दिया था, इसलिए उसका यह अदा करना अपनी इच्छासे अदा करता है और इसलिए वह मुद्दाअलेह से मुआविज़ा पानेका हकदार नहीं है।
- ४ यह नालिश फ़रीक़ैनमें तनाज़ा होनेकी वजहसे दायर की गई है।
- ५ यह नालिश मय खर्चके ख़ारिज़की जाय और खर्चा दिलाया जाय।

[तस्दीक और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

१७ नालिश वास्ते बटवारा

[शीर्षक इत्यादि नं० १ देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

- १ यह कि मुद्दई और मुद्दाअलेह एक सम्मिलित हिन्दू कुटुम्बके आदमी हैं और उस जायदाद पर, जिसकी ब्योरेवार तफ़सील इस अर्ज़ीदावाके साथ नत्थी सूचीमें दी गई है, उनका सम्मिलित अधिकार (मुश्तरका कब्ज़ा) है।
- २ यह कि उक्त जायदादमें मुद्दई और मुद्दाअलेहके हिस्से बराबर हैं।
- ३ यह कि उक्त जायदादके प्रबन्धके सम्बन्धमें मुद्दई और मुद्दाअलेहके बीच झगड़ा होने तथा बहुतेरे कौटुम्बिक झगड़ोंके कारण उस जायदाद पर मुद्दई और मुद्दाअलेहका सम्मिलित अधिकार (कब्ज़ा मुश्तरका) बचा रहना अब बिल्कुल सम्भव नहीं है।
- ४ यह कि मुद्दईने तारीख्.....को मुद्दाअलेहके सामने यह प्रस्ताव पेश किया कि उनके (फ़रीक़ैनके) बीच शांतिके साथ आपसमें उक्त जायदादका बटवारा होजाय, लेकिन मुद्दाअलेहने ऐसा करनेसे इन्कार कर दिया।
- ५ इस नालिशकी बिनाय मुख़ासमत, बमुक़ाम.....जो कि इस अदालतके अधिकारक्षेत्रमें है, तारीख्.....को (जिस तारीख्को मुद्दाअलेहने बटवारा करनेसे इन्कार कर दिया था) पैदा हुई।
- ६ जैसा कि अर्ज़ीदावा नं० २ पैरा ८ में है।

७ मुद्दईका दावा है कि:—

(१) फरीकैनके हिस्सोंके बमूजिव उक्त जायदादके बटवारेकी डिकरी दे दी जाय और यह कि अदालतकी ओरसे यह बटवारा करनेके लिए एक कमिशनर नियुक्त किया जाय ।

(२) मुकद्दमेका खर्च दिलाया जावे ।

[जायदादकी सूची]

(तस्दीक और दस्तखत)

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकद्दमेंमें जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि नं० १ देखो]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है:—

१ यह मुकद्दमा बाकिस है क्योंकि इसमें कुछ आदमी फरीक नहीं बनाए गए हैं और ऐसी दशामें वह अपनी मौजूदा सूरतमें सम्मिलित किये जानेके काबिल नहीं है, क्योंकि.....जो कि उस जायदादमें मुश्तकां कब्जा रखता है, इस मुकद्दमेंमें फरीक नहीं बनाया गया है ।

२ अर्जीदावाके पैराग्राफ २० में बतलाई बातें सही नहीं हैं, क्योंकि उस जायदादमें मुद्दाअलेहका हिस्सा सिर्फ दो आना है ।

३ यह कि अर्जीदावाके साथ नस्थी फेहरिस्तमें बतलाया हुआ किता नं० ५५ मुद्दाअलेहकी खुद पैदा की हुई जायदाद है और इसलिये उसका बटवारा फरीकैनके बीच नहीं हो सकता है ।

४ यह कि अर्जीदावाके साथ नस्थी सूचीमें बतलाई गई जायदाद मुश्तकांकी फेहरिस्त पूरी नहीं है और यह कि मुद्दईकी नालिश, जो कि एक हिस्सा जायदादके बटवाराकी निरुवत की गई है, काबिल कायम रहनेके नहीं है ।

५ अर्जीदावाके पैरा ५ में मुद्दईका यह कहना कि उसने मुद्दाअलेहसे जायदाद मुश्तकांका आपसमें बटवारा कर लेनेकी दरखवास्त की, सही नहीं है ।

६ यह कि मुकद्दमामय खर्चके खारिज किया जाय और खर्चा दिलाया जाय ।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

१८ मय वासिलात जायदाद पर कब्जा दिलापानेकी बाबत हकीयतकी नालिश

[फरीकैन मुकद्दमा वगैराकी तफसील नं० १ देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ मुद्दईका चचा.....साकिन.....रियासत.....
बाकैमौजा.....का मालिक था और.....हो बाबत माल

मुजारीके सरकारको भदा करता था। उक्त जायदादकी व्योरेवार तर्फसील सूची (अ) में दी हुई है जो कि इस अर्जीदावाके साथ नत्थी है।

२ यह कि तारीख माह सन् ई० को मुद्दाअलेहने अलायोंसे लगानकी तहसील वसूल करके, उसके मुख्तारको उसकी कचहरीसे निकालकर और सूचीमें बतलाये गये किता नं० ५ में उसकी पैदा की हुई अन्नकी फसलको देजा तौरसे सफ़ करके, उस जायदाद परसे मुद्दैका कब्ज़ा उठा दिया।

३ यह कि मुद्दैका चच्चा तारीख.....के एक वसीयतनामाके ज़रिये अपनी कुल जायदाद मनकूला और गैर-मनकूला मुद्दैके हकमें छोड़कर इस वसीयतनामाके लिखनेके एक साल बाद मर गया।

४ यह कि मुद्दाअलेह अब भी उक्त रियासत पर अपना बेजा कब्ज़ा बनाये हुए है और इसलिये मुद्दै मुद्दाअलेहसे मुबल्लिग..... रु० बाबत वासिलात उस मुद्दतके, जितने कि मुद्दैके चच्चाको दखल नहीं रहा है [जैसा कि अर्जीदावाके साथ नत्थी सूची (ब) में बतलाया गया है] दिला पानेका क़दर है।

५ इस नालिशकी बिनाय मुखासत वमुक़ाम.....जो कि इस अदा-उत्ते अधिकार-क्षेत्रमें है, तारीख.....को (जब कि कब्ज़ा उठा दिया गया था) पैदा हुई।

६ मुक़द्दमेकी मालियत, अख़्तियार, समाअत और कोर्ट-फीसके वास्ते रु० है।

७ मुद्दै प्रार्थी है कि:—

(क) उसकी निश्चत मुद्दैकी हकीयतका ऐलान करनेके बाद सूची (अ) में बतलाई हुई जायदाद पर कब्ज़ेकी डिकरी दी जाय।

(ख) मुबल्लिग..... रु० की डिकरी बाबत वासिलातके दी जाय।

(ग) मुक़द्दमेके खर्चोंकी बाबत डिकरी दी जाय।

(घ) उसे वासिलात आयन्दाकी निश्चत नालिश करनेका अधिकार देया जाय।

(ङ) दूसरी और ऐसी दादरसी दिलाई जाय जिसके पानेका वह क़दर हो।

सूची (अ) [जायदाद] .

सूची (ब) [वासिलातका हिसाब]

[तस्दीक और दस्तख़त]

देखो पेज १३।१४

उपरोक्त मुकदमोंमें जवाब दावा

[शीर्षक इत्यादि नं० १ देखो]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार निवेदन करता है:—

१ यह कि मुद्दईके पास मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश दायर करनेका कोई कारण नहीं है ।

२ मुद्दाअलेह अर्जीदावाके दूसरे और तीसरे पैरामें कही गई बातोंसे इन्कार करता है और बयान करता है कि उसने मुद्दईके चचाको उक्त जायदादसे बेदखल नहीं किया ।

३ मुद्दाअलेहको जायदाद मुतनाज़ा अपने बापसे विरासतमें मिला है और वह उसका उपभोग बतौर अपने हकके करीब १२ सालसे ऊपर करता आया है और यह कि मुद्दईको उसकी निस्वत कोई भी हक या हकीयत हासिल नहीं है ।

४ यह कि मुद्दईको वासिलातकी बाबत नालिश करनेका कोई हक नहीं है और जिस रकमकी बाबत उसने वासिलातकी निस्वत दावा किया है वह ज़्यादा है ।

५ यह कि मुद्दईके मुकदमाकी तमादी आरिज़ हो गई है ।

६ यह कि मुकदमा मय खर्चोंके खारिज किया जाय और खर्चा दिलाया जाय ।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३।१४

१६ मालिककी ओरसे कारिन्दोंके हिसाब की बाबत नालिश

[अदालत वगैराकी तफ़सील नं० १ देखो]

उपरोक्त मुद्दई नीचे लिखे अनुसार दावा करता है:—

१ मुद्दई वाकै मौजा.....परगना.....ज़िला.....का जो कि इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें है, मालिक है ।

२ बैसाख सन् १३१० फ़सलीमें मुद्दईने उक्त मौज़ोंके लगानकी तहसील-वसूल करनेके लिये मुद्दाअलेहको अपना कारिन्दा मुकर्रर किया ।

३ मुद्दाअलेह मुद्दईके यहां बतौर कारिंदाके बैसाख सन् १३१० से खैत्र सन् १३१९ ई० तक काम करता रहा और उक्त मौज़ोंकी पूरी तहसील वसूल उसके हाथमें रही । बैसाख सन् १३२० फ़सलीमें उसने मुद्दईको बिना पहिले कोई नोटिसदिये हुए और उन रुपयोंका, जो कि उसने अपनी कारिंदगीरीके दौरानमें वसूल किया था, बिना कोई हिसाब-किताब दाखिल किये हुए मुद्दईकी नौकरी छोड़ दी ।

४ मुद्दाअलेहने न तो उस रुपयेका कोई हिसाब पेश किया है जो कि उसने अपनी कारिंदगीरीके दौरानमें वसूल किया है और न तहसील-वसूलके कागज़ात पेश किये हैं, यद्यपि मुद्दईने कई बार उससे ऐसा करनेके लिये कहा ।

५ मुद्दईका विश्वास है कि उसको मुद्दाअलेहसे मुबलिया रु० की रकम मिलनी है और उसे तहसील-चसूल करनेके नये कागजात तय्यार करानेमें मुबलिया रु० खर्च करना पड़ेगा।

६ इस नालिशके लिये विनाय मुखासमत तारीख को (जिस तारीखको कि मुद्दाअलेहने मुद्दईकी नौकरी छोड़ी है) बमुकाम....., जो कि इस अधिकार-क्षेत्रमें है, पैदा हुई।

७ मुकद्दमेंके दावाकी मालियत मुबलिया रु० है और यही रकम कोर्ट-फीसके लिये भी है।

८ इसलिये मुद्दई प्रार्थी है कि:—

(क) मुद्दाअलेहके ऊपर ऐसी डिकरी दी जाय जिसमें वह सन् से सन् तकका हिसाब-किताब पेश करनेका जिम्मेदार करार दिया जाय।

(ख) यह कि मुद्दाअलेहको यह हुक्म दिया जाय कि वह ठीक ठीक हिसाब और कागजात दाखिल करे और ऐसा न कर सकने पर मुबलिया रु० बाबत खर्चा उन कागजातोंको दुबारा तैयार करनेके अदा करे।

(ग) यह कि हिसाब किताब की जांच करने के लिये अदालत की ओर से एक कमिश्नर मुक़र्रर किया जावे और यह कि मुद्दाअलेह के उस रकम की डिकरी दीजाय जो कि हिसाब किताब करने के बाद मुद्दई को वाजिबुल्ल वसूल हो।

(घ) यह कि मुद्दाअलेह को मुद्दई का इस मुकद्दमें का खर्चा अदा करने के लिये कहा जाय।

(ङ) यह कि मुद्दईको यह अधिकार भी दिया जायकि वह उस रुपयेके ऊपर स्टाम्प लगा सके जोकि अर्जीदावामें बतलाई गई मालियत दावासे ज़ायद मुद्दाअलेह के ऊपर वाजिब निकले।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३। १४

उपरोक्त मुकद्दमें का बयान तहरीरी

[शीर्षक वगैरा जैसा नं० १में है]

मुद्दाअलेह नीचे लिखे अनुसार प्रार्थी है—

१ मुद्दईके पास मुद्दाअलेहके ऊपर यह नालिश करनेका कोई कारण नहीं है।

२ मुद्दाअलेह इस बात को स्वीकार करता है कि उसने मुद्दई के कामिन्दा की हैसियत से काम किया, लेकिन वह अर्जीदावा के पैरा ३ में कहीगई है इस बात को स्वीकार नहीं करता कि उसने एकाएक बिना उस रुपये का कोई

हिसाब किताब किये जोकि उसने अपनी कारिन्दगीरी के दौरान में वसूल किया है मुद्दई की नौकरी छोड़ दी है।

३ वास्तव में मुद्दाअलेह ने नौकरी छोड़ने के छः महिने पहिले अपने इस इरादे की मुद्दई को लिखित सूचना दी थी, चूंकि मुद्दई उसकी तनखाह बराबर ठीक समय पर नहीं देसका इसलिये मुद्दई की नौकरी में रहना असम्भव था मुद्दई की नौकरी छोड़ते समय उसने उस कुल रुपये का जोकि उसने अपनी कारिन्दगीरीके दौरानमें वसूल किया था पूरापूरा हिसाब देदिया था और तहसील बसूल के कुल कागज़ात मुद्दई के नाम ब..... के हवाले कर दिये थे। वह उक्त नायब की मार्फत कुल रुपया जिसे वह उक्त मौजों से वसूल करता था बराबर मुद्दई के पास भेजदिया था और उसकी रसीद ले लिया करताथा। वे रसीदइसके साथ नत्थी हैं। उनसे यह मालूम होगा कि उसके ऊपर मुद्दईका कुछ भी बाकी नहीं।

४ मुद्दई, मुद्दाअलेह से खर्चा दिलापाने का दावा नहीं करसकता जो कि हिसाब तैयार करनेके लिये जरूरी है और यह कि उसके लिये जिस रुपये का दावा वह करता है वह हर हालत में उचित से अधिक हैं।

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३ १४

जरूरी जरूरी अर्जियोंके नमूने

२० कुर्क किए हुए मालकी निस्बत दावा

ब अदालत जनाब सब जज साहब बहादुर सन् १९ ई०
नम्बर मुकद्दमा
... .. फरीकसानी
... .. सायल बनाम
... .. डिकरीदार नं० १
... .. मदीयून डिकरी नं० २
सायल साकिन का बिनय निवेदन है:—

१ कि डिकरीदार (फरीकसानी नं० १) ने इस अदालतकी डिकरी नं० १२ सन् १९२७ ई० की, जोकि मदीयून-डिकरी (फरीकसानी नं० २) के ऊपर तारीख ... को दी गई थी, इजरा में सायलकी जायदाद जोकि इस अर्जीके साथ नत्थी फेहरिस्तमें बतलाई गई है कुर्क करली है।

२ यह कि मदीयून, डिकरीको कभीभी उक्त जायदादकी निस्बत कोई हक या हकीयत हासिल नहीं था। सायलको यह जायदाद उसके बापसे मिली है और वह १२ सालसे ज़्यादा उस पर काबिज़ है और उसका उपभोग करता है।

३ ऐसी दशामें सायलकी प्रार्थना है कि अदालतमें, मुनासिब शहादतके ऊपर उस जायदादकी निश्चित सायलकी हकीयत और कब्ज़ाके बारेमें इतमीनान करलेनेके बाद फ़ेहरिस्तमें बतलाई गई जायदादको कुर्कीसे बरी किए जाने का हुक्म देदेवे ।

सायल आपका चिरकृतज्ञ रहेगा ।

[उस जायदादकी फ़ेहरिस्त जोकि कुर्क कर ली गई है]

[तस्दीक और दस्तखत]

देखो पेज १३१४

२१ प्रोबेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिये अर्जी

ब अदालत जनाब ज़िला-जज साहब

... .. प्रोबेटका मुकदमा नं० ... सन् १९ ई०

प्रोबेट ऐण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐक्टके अनुसार (या सकसेशन ऐक्ट अर्थात् उत्तराधिकारके क़ानूनके अनुसार) सुतौफी ... की वसीयतकी नकल (प्रोबेट) के लिए ... की अर्जी ।

१ सायल ... ज़मीन्दार है और मौज़ा ... का रहनेवाला है ।

२ उपरोक्त श्रीयुत ... की तारीख ... माह ... सन् ... ई० को स्थान ... में, जोकि इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें है और जो उनके रहनेका नियत स्थान है, [या जहां पर कि वह अस्थायी रूपसे रहते थे, क्योंकि उनके रहनेका स्थान ... था जो इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें है, या, जबकि दरख़वास्त किसी ज़िला-जजके यहां दी गई हो तो, इसके साथ नत्थी फ़ेहरिस्तमें बतलाई गई जायदादको छोड़,] इस अदालतके अधिकार क्षेत्रमें है; [या जब दरख़वास्त सकसेशन ऐक्टके अनुसार किसी डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट (ज़िला प्रतिनिधि) को दी गई हो तो, जहां पर वह उस समय रह रहा था ।]

३ जो तहरीर इसके साथ नत्थी है और जो मुझे दिखलाई गई है और जिस पर 'क' अक्षरका चिन्ह है, वह उक्त ... का आखिरी वसीयत नामा है और उसने उन गवाहोंके सामने, जिनके नाम उस वसीयत नामाके नीचे हाशिये पर दिए हुए हैं, उसकी बाकायदा तौर पर तकमीलकी थी ।

४ मैही उक्त वसीयत नामामें बतलाया हुआ वसी ... हूँ [या दरख़वास्त वसीयतनामाके साथ लगे हुए प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए हो तो फ़ार्म नं० २२ के पैरा ३ और ४ और शामिल कर देना चाहिए] ।

५ माल मतलूका की रकम, जोकि मेरे हाथमें आनेवाली है, कुल मिलाकर ... से अधिक नहीं है जिसका हिसाब सूची (अ) में दिया हुआ

है और यह कि जो कुछभी देना है उसकी रकम ... रु० से अधिक नहीं है जिसकी कि तफ़सील हलफनामाकी सूची (ब) में दी गई है और यह कि उक्त माल मतरूका की कुल रकम उन तमाम मदोंका रुपया निकाल देनेके बाद जिनको निकाल देनेका मुझे क़ानूनके अनुसार अधिकार है, मु० ... रु० की मालियतके अन्दर है।

६ मैं इस प्रार्थना पत्र द्वारा यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उक्त स्वर्गवासीकी सम्पत्ति और ... भरण पोषण आदिका उचित प्रबन्ध करूँगा और उसकी एक सही और पूरी सूची (खर्चा) तैयार करूँगा और प्रोबेट या प्रबन्धसम्बन्धी पत्र मिलजाने की तारीख़से छः महीनेके भीतर उसे इस अदालतमें पेश करूँगा और उक्त तारीख़से एक सालके भीतर उक्त सम्पत्ति और ऋणका एक सही हिसाबभी इस अदालतमें पेश करूँगा।

७ यह कि जहां तक मैं जानता हूँ अभी तक किसी शख्सने किसी दूसरी अदालतको उक्त वसीयतनामाके प्रोबेट या उक्त सम्पत्ति (जायदाद) के प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए दरख़वास्त नहीं दी है।

८ इसलिए सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) उसे उक्त वसीयतनामाको सामान्य रीतिसे साबित करनेकी इजाज़त दी जाय और यह कि उसका प्रोबेट [या उक्त वसीयतनामाके साथ उक्त सुतौफीकी सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र] जो ... बराबर अमलमें आते रहेगा उसे दिलाया जाय।

(ख) दूसरी ऐसी दादरसी दिलाई जाय जोकि अदालतको उचित जान पड़े।
सूची (अ) सूची (ब)

[दस्तख़त वकील]

[दस्तख़त सायल]

मैं ... जिसने उपरोक्त दरख़वास्त पेशकी है, इसके ज़रिये यह एलान करता हूँ कि उसमें जो कुछभी लिखा है वह, जहां तक मैं जानता हूँ और जहां तक मेरा विश्वास है, सही है। देखो पेज १३। १४

गवाह ... [दस्तख़त सायल]

मैं कि ... साकिन ...

जोकि ... के आखिरी वसीयतनामाके, जिसका ज़िक्र उपरोक्त प्रार्थना-पत्र (अर्ज़ी) में किया गया है, गवाहोंमेंसे एक हूँ, यह इज़हार करता हूँ कि मैं उस जगह पर मौजूद था और मैंने उसे उक्त वसीयतनामाके ऊपर, जोकि अब मुझे दिखलाया गया है और जिस पर “(क)” निशान डाला गया है अपना हस्ताक्षर करते (या निशान बनाते) हुष देखा [या यह कि उक्त मवसीने उपरोक्त अर्ज़ीके साथ नस्थी तहरीरको, जोकि अब मुझे दिखलाई गई है और जिस पर “क” निशान डाला गया है, मेरे सामने अपनी आखिरी वसीयत स्वीकार किया है,]

(हस्ताक्षर)

२२ प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रके वास्ते नालिश

[शीर्षक मुकद्दमा]

जैसा कि फार्म नं० २१के पैरा नं० १ और २ में है

३ उक्त "अ आ" ... नीचे लिखे अपने सम्बन्धियोंको जीवित छोड़ कर मर गये हैं:—

(१) ... क ख ... (जो सायल और लड़का है)

(२) ... ग घ ... (सकूनत और वालिदयत वगैरा) जो उसके लड़के हैं;

(३) ... ङ च ... धर्म-पत्नी श्री ... साकिन ... जोकि उसकी लड़की है;

(४) ... छ ज ... साकिन ... जोकि उसकी स्त्री है;

(५) ... झ ञ ... साकिन ... जोकि उसकी अविवाहिता कन्याएं हैं;

(६) ... ट ठ ... साकिन ... और ... ड ढ ... साकिन ... जोकि उसके भाई हैं जिनमेंसे टठ की तारीख ... को मृत्यु होगई है और जिसके कोई ... या दूसरे रिश्तेदार नहीं हैं ।

४ उक्त बिना कोई वसीयत लिखे मर गये हैं और सायल बहैसियत उसके बड़े लड़केके उसकी सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रके लिए दायेदार है ।

५ जो माल मतलूका मेरे हाथमें आनेवाला है वह कुल मिलाकर मुबलिग ... रु० से कम नहीं है जिसका ब्योरेवार हिसाब सूची (अ) में दिया हुआ है और यह कि जो कुछ देना है उसकी रकम ... रु० है जिसकी तफसील हलफनामाके साथ नत्थी सूची (ब) में दीगई है, और यह कि उक्त माल मतलूका की कुल रकमकी, उन तमाम मदोंको अलग करके जिनको अलग करनेका मुझे कानूनके अनुसार अधिकार है, मालियत ... रु० के भीतर है ।

६ मैं इस प्रार्थना-पत्र द्वारा यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उक्त स्वर्गवासी "अ आ" की सम्पत्ति और ऋण आदिका उचित प्रबन्ध करूंगा और उसकी एक सही और पूरी सूची (खर्चा) तैयार करूंगा और प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके पाजाने की तारीखसे छः महीनेके भीतर उसे इस अदालतमें पेश करूंगा और उक्त तारीख से एक सालके भीतर उक्त सम्पत्ति और ऋणका एक सही हिसाब भी इस अदालतमें पेश करूंगा ।

७ यह कि जहां तक सायलको मालूम है, अभी तक किसी दूसरे शख्सने अपरोक्त स्वर्गवासी ... की सम्पत्तिके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए कोई परखवास्त नहीं दी है ।

८ इसलिये सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) उक्त स्वर्गवासी ... की सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र जोकि ... के भीतर बराबर अमलमें आते रहेंगे, उसे दिलाए जायं ।

(ख) दूसरी और ऐसी दादरसी दीजाय जिसे अदालत उचित समझे ।
[दस्तखत वकील] [दस्तखत सायल]

सूची (अ) और (ब) तस्दीक वगैरा जैसा कि पेज १३।१४ हैं ।

२३ प्रोवेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए दीगई अर्जीकी नोटिस

सेवामें श्रीमान् ... कलकटर ... इस तहरीरके जुरिए यह नोटिस दीजाती है कि स्थान ... के जिला जज [या प्रतिनिधि] के इजलासमें स्वर्गवासी ... (वहिदयत वौमियत और सकूनत) के, जिनका तारीख् ... माह ... सन् ... को स्थान ... में बैकुण्ठ बास होगया है, वसीयतनामा [और उस वसीयतनामाके अनुबन्ध (तितिम्मा)] के, जो [कमशः] तारीख् ... माह ... सन् ... ई० [और तारीख् माह ... सन् ... ई०] के हैं, प्रोवेट [या सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र या तारीख् ... माह ... के वसीयतनामाके साथ नत्थी सम्पत्ति और ऋणके प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र,] श्री ... (वहिदयत, कौमियत और सकूनत) को, जोकि उक्त वसीयतनामामें बतलाए गए वसी लोगोंमेंसे एक है [या उक्त स्वर्गवासी ... के भाई और निकटस्थ कुटुम्बी है या जैसा कुछ हो,] दिलानेके लिए, दरख्वास्त दीगई है ।

[“जब यह नोटिस कलकटरके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्तिके पास भेजी जानेको हो तो”] और यह कि तारीख् ... माह ... सन् ... ई० को उक्त अर्जीकी समाअतकी तारीख् मुकररकी गई है और यह कि अगर आप इसका विरोध करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उक्त अदालतमें उज्रदारी दाखिल करें ।

उस जायदादकी कुल मालियत मुबलिया ... रु० और असली मालियत ... रु० है ।

आज तारीख् ... माह ... सन् ... ई० ।

वकील ... जजके दस्तखत

२४ बली मुकर्रर: किए जानेके लिए अर्जी

[शीर्षक जैसा नं० २१ में है]

ब अदालत जनाब ज़िला जज साहब मुकाम—

प्रारम्भिक दख्वास्त नं० सन ई०

बमुकद्दमा ... नाबालिग

... सायल

(गार्जियन ऐण्ड वार्ड्स ऐक्ट सन १८९० ई० के अनुसार दख्वास्त)

उपरोक्त सायलका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है:—

१ ... सायल एक जमीन्दार और मौज़ा ... का रहने वाला और उपरोक्त ... नाबालिगका बड़ा भाई है।

२ यह कि सायलकी यह दख्वास्त है कि वह नाबालिग ... वह ... सा० ... के जिसमें और जायदादका बली मुकर्रर किया जाय।

३ कानूनके अनुसार जिन बातोंकी ज़रूरत है, वे नीचे दी जाती हैं:—

(क) १ नाबालिगका नाम ...

२ मर्द या औरत ... मर्द।

३ धर्म (मज़हब) ... हिन्दू।

४ जन्म तिथि ... ३ मार्च सन १९२७ ई०।

५ विवाहित या अविवाहित ... अविवाहित।

६ नाबालिग की आय सकूनत मौज़ा ... जोकि इस अदालतके अधि-
कार क्षेत्रमें है।

[अगर नाबालिग विवाहित है तो, और यदि वह स्त्री जाति है तो, उसके पति का नाम अवस्था (उम्र) और पता लिखना चाहिए, और यदि वह पुरुष है तो पत्नी लिख देना चाहिए कि वह विवाहित है।]

(ख) नाबालिग बहैसियत अपने बाप श्री ... के दो जीवित लड़कोंमेंसे एक लड़केके, बशिराकत सायलके और बपाबन्दी हकूक गुजारा व सकूनत अपनी मां मुसम्मात ... के इस अर्जीके साथ तत्थी सूची (अ) में बतलाई हुई जायदाद मनकूला और गैर मनकूलाके, जो करीब करीब उक्त सूची के खाना ३ में बतलाई गई मालियतकी है, और सायलके कब्जेमें है अभिभक्त (गैर मुन्किस्मा) बराबरके अधि हिस्सेके लिए हकदार है।

(ग) नाबालिगके जो सम्बन्धी अब जीवित हैं वे ये हैं:—

१ सायल जोकि उसका बड़ा भाई है।

२ उसकी मां मुसम्मात ... जो ... में रहती है।

३ उसकी बहन मुसम्मात ... धर्म-पत्नी ... जो ... में रहती है।

४ उसका चचा ... जो ... में रहता है।

नाबालिगके बाप ... की मृत्यु तारीख ... माह ... सन् ... को या उसके करीब हुई थी।

(व) अदालतने किसी शख्सको नाबालिगके जिस्म और जायदादका कोई बली मुक़रर नहीं किया है; और इस नाबालिगके जिस्म या जायदादकी दलायतकी निस्वत अभी तक इस अदालतमें कोई दखलस्त नहीं दी गई है।

(ङ) जो शख्स बली तजवीज किया गया, वह ज़मीन्दार है और विश्व विद्यालयकी शिक्षा प्राप्त किए हुए है तथा बी० ए० पास है। वह पुरुष श्रेणीमें नाबालिगका सबसे निकटस्थ सम्बन्धी है और उसके चार बच्चे हैं और अपने परिवारके साथ स्थान ... में रहता है। उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी है, क्योंकि उसकी ... रु० वार्षिक की आय है, तथा उसका आचरण अच्छा है और वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसका व्यापारी स्वभाव है; और वह नाबालिगके जिस्म और जायदादका बली मुक़रर किए जानेके लिए विष्कुल योग्य व्यक्ति है।

४ इसलिए सायलकी प्रार्थना है:—

(क) कि वह उपरोक्त नाबालिगके जिस्म और जायदादका बली मुक़रर किया जाय।

(ख) यह कि बली की ओरसे दीजाने वाली ज़मानतकी रकम ... रु० निश्चित की जाय, और यह कि ... और ... उसके ज़मानतदार स्वीकार किए जायें।

(ग) यह कि मुबलिग ... रु० की रकम वास्ते नाबालिगके गुज़ाराके मुक़रर की जाय।

(घ) दूसरी और भी ऐसी दादरसी दीजाय जो अदालतको उचित जान पड़े।

सूचो (अ)

मैं कि ... , जोकि ऊपर बतलाया गया सायल हूँ, इस तहरीर के ज़रिये यह इजहार करता हूँ कि पैरा ... में लिखी गई बातोंको मैं सही जानता हूँ और पैरा ... में लिखी गई बातोंको अपनी सूचना और विश्वास के अनुसार सही मानता हूँ (देखो पेज १३ । १४)

मैं ... इस तहरीरके ज़रिये उपरोक्त नाबालिगके जिस्म और जायदादका बली होना स्वीकार करता हूँ, यशत कि अदालत मुझे मुक़रर करना मुनासिब समझे।

उक्त ... ने श्रीयुत ...	} दस्तखत (सायल)
(बलिदयत और सकूनत) ...	
और श्रीयुत ... (बलिदयत और सकूनत)	
के सामने दस्तखत किया।	

तारीख् सन्

२५ वरासतके सार्टीफिकेटके लिए दरखास्त

(शीर्षक जैसा कि नं० २१ में है)

बअदालत

सकसेशन सार्टीफिकेट ऐक्ट सन् १८८९ ई० के अनुसार ... की अर्जी।

उपरोक्त सायलका नीचे लिखे अनुसार निवेदन है:—

१ ... सायल एक ज़मीन्दार और स्थान ... का रहने वाला है।

२ उपरोक्त ... की तारीख ... माह ... सन् ... ई०

को स्थान ... में जोकि, इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें है और जहाँ पर कि उस समय, वह आमतौर पर रहा करता था [या स्थान ... में जो कि उस समय उसके रहनेका कोई निश्चित नहीं था] मृत्यु होगई और वह इसके साथ नत्थी सूची (अ) में बतलाई गई जायदादको इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें छोड़ गया है।

३ यह कि सुतौफीके नीचे लिखे सम्बन्धी जीवित बचे हैं:—

१ मां वलियत, कौमियत	} यहां पर परिवार या सम्बन्धियोंका पूरा व्योरा पूरे नाम और पता सहित और इस बातके सहित कि उनमेंसे हर एक के साथ सुतौफीका क्या सम्बन्ध है लिखना चाहिए।
२ लड़की और सकूनत।	
३ विधवा स्त्री ”	
४ भाई ”	
५ नाबालिग लड़का ”	
६ लड़का (सायल)	

४ यह कि सुतौफीका बड़ा लड़का होनेकी हैसियतसे सायल इस ऐक्टके नियमानुसार सार्टीफिकेट दिला पानेके लिए दायेदार है।

५ उक्त सुतौफी मज़हबका सुन्नी फ़िर्कका मुसलमान था और उस पर सकसेशन ऐक्ट (कानून वरासत) सन् १८६५ ई० के नियम लागू नहीं होते हैं और वह बिना कोई बत्तीयत लिखेही मर गया।

६ जहाँतक मैं जानता हूँ अदालतमें अभी तक कोई भी दरखास्त सकसेशन सार्टीफिकेट ऐक्ट सन् १८८९ ई० के अनुसार किसी सार्टीफिकेटके लिए, या उक्त ... के कर्जें, ज़मानत और रियासतके सम्बन्धमें प्रोबेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्रोंके लिए नहीं दीगई है और न ऐसा सार्टीफिकेट, प्रोबेट या प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र दिया गया है, और दफा १ (४) के अनुसार; या उक्त ऐक्ट अथवा किसी दूसरे कानूनके अनुसार उस सार्टीफिकेटके देनेमें जिसके लिए कि दरखास्त कीगई है [या, अगर अदालत उसे दे दिया है तो, उसके जायज़ होनेमें] कोई रुकावट नहीं है।

७ उन कुर्ज़ों और ज़मानतों इत्यादिकी जिनके सम्बन्धमें सार्टीफिकेट तलब किया गया है, तफ़्सील सूची (ब) में दीगई है जोकि इसके साथ नत्थी है।

८ सायलने अदालतमें सार्टीफिकेटके सम्बन्धमें दीजाने वाली मुतासिब फीस अदा करदी है।

९ [किसी भी शख्सके ऊपर इस अर्जीकी नोटिस तामील करानेका इरादा नहीं है यह बात निकाल दीजायगी। अगर पैरा १० के क्लॉज़ (क) का सम्बन्ध है]

१० इसलिये सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) इस अर्जीकी नोटिस की तामील ... पर कीजाय जिनका नाम इस अर्जीके पैरा ३ में बतलाया गया है [और यह कि उसमें दस्तावेज हुए दूसरे लोगोंके ऊपर नोटिस रद्द कीजाय]

(ख) यह कि सक्सेशन सार्टीफिकेट ऐक्टके अनुसार उसे सार्टीफिकेट ऐसा दिया जाय, जिससे उसको, कर्जोंके रुपये की तहखील वसूल करने और इसके साथ लगी हुई सूचीमें बतलाई, गई ज़मानतोंके ऊपर ब्याज और मुनाफ़ाका हिस्सा लेने तथा उन्हें बेंच देने और मुन्तकिल कर देनेका अधिकार दिया जाय।

(ग) दूसरी ऐसी दादरसी दीजाय जो अदालतको उचित जान पड़े।

सूची (अ) मुतौफ़ीकी जायदाद जो अदालतके अधिकार-क्षेत्रके भीतर है।

सूची (ब) वह कर्ज़ा जोकि मुतौफ़ीकी जायदादपर बाज़िब है जिसके सम्बन्धमें सार्टीफिकेटके लिए दरख़वास्त है।

(दस्तख़त) ... (दस्तख़त) ... सायल वकील ...

मैं इस तहरीरके ज़रिये इजहार करता हूँ कि उपरोक्त बातें जहां तक मैं जानता हूँ सही हैं, सिवाय उन बातोंके जो सूचना और विश्वासके अनुसार लिखी गई हैं, और उन बातोंके सम्बन्धमें मुझे विश्वास है कि वे सही हैं।

(देखो पेज १३। १४

(दस्तख़त-सायल)

२६ किसी पागलका बली मुक़रर किए जानेके लिए दरख़वास्त

ब अदालत जनाब ज़िला-जज साहब ...

पालगका बली मुक़रर किए जानेके लिए दरख़वास्त।

सायल ... वल्द ... साकिन...का यह विनम्र निवेदन है कि:—

१ सायल इस हुक्मके लिए यह दरख़वास्त देता है कि इस बातको तय करने के लिए जांच कीजाय कि क्या सायलके भाई ... का दिमाग सही नहीं है और इसलिये वह अपने जिस्म और मालकी हिफ़ाज़त कर सकनेके नाकाबिल है ?

२ यह कि अगर जांच करने पर मालूम होजाय कि ऊपर बतलाया हुआ व्यक्ति पागल है, तो सायलकी प्रार्थना है कि वह उक्त पागलके जिस्म और माल का बली मुक़रर किया जाय।

३ यह कि उक्त पागलकी आयु ... वर्ष है और वह जातिका हिन्दू है और यह कि वह इस समय सायलकी सिपुदंगीमें है उसके मकानमें जो ... वाक है जोकि इस अदालतके अधिकार-क्षेत्रमें है।

४ यह कि सायल और उस पागलकी स्त्री श्रीमती ... ही जोकि सायलके मकान पर रह रही है, सिर्फ़ उस पागलके दो नज़दीकी रिश्तेदार हैं।

५ यह कि किसी भी मुनासिब अदालतने अभी तक उक्त पागलके जिस्म और जायदादका कोई बली मुक़रर नहीं किया है।

६ यह कि सायलका यह विश्वास है कि उसका भाई ... महीना सन् १९... ई० से पागल है और अपने तथा अपनी जायदादका इन्तज़ाम करनेके नाकाबिल है।

७ यह कि उक्त पागलकी जायदाद किस किसकी है, वह कहाँ पर वाक है और उसकी तफ़्सील मालियत क्या हैं, ये बातें सूची (फ़ेहरिस्त) में दी गई हैं जोकि इस अर्ज़ीके साथ नरथी हैं।

८ इसलिए सायलकी प्रार्थना है कि—

(क) तमाम ज़रूरी जांच कर लेनेके बाद वह उक्त पागलके जिस्म तथा जायदादका बली मुक़रर किया जाय।

(ख) दूसरी पेसी दादरसी दीजाय जोकि अदालतको उचित जान पड़े।
[तस्दीक और दस्तख़त]

[फ़ेहरिस्त जायदाद]

देखो पेज १३।१४

२७ ऋणीकी दरख़वास्त वारते दीवालिया करार दिए जानेके

बअदालत जनाब ... सायल

१ मैं (यहां पर नाम, वलियत, सकूनत वगैरा और पता लिखना चाहिए) जोकि आमतौर पर मुक़ाम ... में रहता हूँ (या ... अपना व्यापार करता हूँ या आमदनीके लिए शरीरसे काम करता हूँ) (अदालतका नाम और उस डिकरीकी तफ़्सील जिसके सम्बन्धमें हुक्म दिया गया है या रुकाबट डाली गई है या जिसके द्वारा कुर्कीका हुक्म दिया गया है) ... के हुक्मके अनुसार अपना कर्ज़ा अदा कर सकनेमें असमर्थ होकर, यह दरख़वास्त देता हूँ कि मैं दीवालिया करार दिया जाऊँ।

२ मेरे ऊपर कर्जोंकी रकमोंका जो कुछभी दावा है वह ... रु० है (यहाँ पर यह लिखना चाहिए कि किसी कर्जमें कोई जमानत है और अगर है तो कैसी है) जैसा कि सूची (अ) में बतलाया गया है जोकि इस अर्जीके साथ नत्थी है और जिसमें मेरे कुल महाजनोंके नाम और पता, जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ या पता लगा सका हूँ, लिखे हुए हैं ।

३ मेरी सारी जायदादकी तादाद और तफ़्सील सूची (ब) में, जोकि इस अर्जीके साथ नत्थी है, और मेरी कुल जायदादकी, जिसमें रुपया शामिल नहीं है, और उस स्थान या उन स्थानोंकी तफ़्सीलके, जहाँ पर कि वह जायदाद है, दीगई है और मैं इस तहरीरके जरिये यह इज़हार करता हूँ कि मैं अपनी कुल ऐसी जायदाद अदालतके हवाले कर देनेके लिए तैयार हूँ सिवाय उनके जिनमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं (और मेरी हिसाबकी किताबें नहीं हैं) जो क़ानूनके अनुसार किसी डिकरीकी इजरामें कुर्क और नीलाम किए जानेसे मुस्तस्ना हैं ।

४ मैंने इससे पहिले कभी भी दीवालिया क़रार दिए जानेके लिए कोई दर-ख़्वास्त नहीं दी, या, मैं सूची (स) में दीवालिया क़रार दिए जानेके सम्बन्धमें दीगई दरख़्वास्त या दरख़्वास्तोंका ब्योरा देता हूँ [यहाँ पर लिखी जानेवाली बातोंके सम्बन्धमें देखो दीवालिया ऐक्टकी दफ़ा १३ (१) एफ़ (१) (२) ।

सूची (अ) सूची (ब), सूची (स),

(तस्दीक और दस्तख़त)

देखो पेज १३।१४

२८ ज़न्ती आराज़ीके मामलेमें दावा (बंगाल)

[शीर्षक जैसा नं० १ में है]

क्षेत्रमें

श्रीमान् डिपुटी कलक्टर साहब स्थान

मुकदमा नं० ... सन् ... ई०

सायल वल्द साकिन ... का विनम्र निवेदन है कि—

१ सायल उक्त खेत नं० ... का दखीलकार काश्तकार है और उक्त आराज़ीकी बाबत उसे ... रु० फी बीघाके हिसाबसे श्रियुत ... ज़मीन्दारको लगान अदा करना पड़ता है ।

२ यह कि उक्त खेतोंका क्षेत्र फल (रकबा) ... बीघा ... कट्ठा और ... वर्ग-फीट है और उनकी इस समय बाज़ारू दाम ... रु० फी बीघा है, यह कि उक्त आराज़ीकी कीमतमेंसे ज़मीन्दार उस ज़मीनके सालाना

लगानके बीस गुनेके करीब पानेका हकदार है और सायल बाकी रुपयेके पानेका हकदार है ।

३ यह कि किता आराजी नं०के ऊपर, जोकि वर्ग-फीट है, जिसमें बहुतसी इमारतें और नौकरी-चाकरीके रहनेके मकान हैं और उनकी मौजूदा बाजार कीमत ... रु० है और सायल यह रकम बतौर उक्त इमारतके मुआविजाके रुपयेके पानेका हकदार है ।

४ ऊपर बतलाई हुई दशामें सायलका यह कहना है कि वह ... रु० और उसके साथ १५) रु० सैकड़ा कानूनी भत्ता-कुल मिलाकर ... रु०, जैसा कि इस अर्जीके साथ लगी हुई सूची (फेहरिस्त) में बतलाया गया है, उक्त जमीन और इमारतकी ज़ब्तकी बाबत दिला पानेका हकदार है ।

हिसाबकी सूची

जमीनकी कुल कीमत दरि ... रु० फी बीघा रु० ।

इमारत चगैराकी कीमत ,, ,, ,, रु० ।

जमीन्दारका हिस्सा निकाल कर रु० ।

जोड़ ... रु०

कानूनी भत्ता १५) रु० सैकड़ाकी दरसे ... रु०

कुल जोड़ रु०

: दस्तखत व तस्दीक)
देखो पेज १३।१४

२६ कानून ज़बती आराजीकी दफा १८ के अनुसार दीवानीमें मामलेका दिया जाना (बंगाल)

सेवामें

श्रीमान् डिप्टी कलक्टर साहब ज़बती आराजी स्थान—

तजवीज़ मुकद्दमा नं० ... सन् ... ई०

सायल वलद ... साकिन ... का चिनम्र

निवेदन है कि—

१ इस दफ्तरने उपरोक्त तजवीज़के किता नं० ... की तख्मीना मालियतकी निस्वत जिस ढंगसे हुक्म दिया है और मुआविजाके रुपयेकी जिस ढंगसे हिस्सा-रसदी तकसीम की है, उससे असन्तुष्ट होकर सायल यह प्रार्थना करता है कि कानून ज़बती आराजीकी दफा १८ के अनुसार, उक्त तजवीज़के किता नं० ... की मुनासिब मालियत तय किए जानेके लिए और सायल तथा उसके असामीके बीच मुआविजेके रुपयेका हिस्से रसदी मुनासिब बटवारा किए जानेके लिए यह मामला अदालत दीवानीमें दिया जाय ।

२ यह कि उक्त किता नं० ... की मालियत ... रु० है, ... रु० नहीं जैसा कि कलक्टर साहबने अपने फैसलेमें बतलाया है ।

३ यह कि कितना ज़मीन नं० ... पर बाक़ इमारतकी कीमतकी बाबत असाज़ी सिर्फ़ ... रु० ही पानेका हक़दार है और सायल मुआविज़ेका बाकी कुल रुपया पानेका हक़दार है और यह कि चूँकि असाज़ी सायलके मातहत सिर्फ़ एक हाफ़ीदार है इसलिए वह उस ज़मीनका हिस्सा पानेका हक़दार नहीं है।

(दस्तख़त व तस्दीक)

देखो पेज १३।१४

३० याददाश्त अपील

[शीर्षक वगैरा जैसा नं० १ में है]

बअदालत जनाब ज़िला-जज साहब

... .. अपील ... नं० ... सन् ... ई०
... .. मुद्दई अपीलाण्ट

... .. बनाम

... .. मुद्दाअलेह-रेस्पाण्डेण्ट

उपरोक्त मुद्दई, उस डिकरीसे असन्तुष्ट होकर जो के मुंसिफ़ साहबने तारीख़ ... को मुक़द्दमा नं० ... में दी है, उक्त डिकरीके विरुद्ध यह अपील पेश करना चाहता है जिसकी दूसरी बजहोंमेंसे कुछ बजहें ये हैं:—

१ यह कि नीचेकी अदालतने यह तय करनेमें, कि मुक़द्दमेंकी मियाद आरिज़ होगई है, कानूनी ग़लतीकी है।

२ यह कि नीचेकी अदालतको यह तय करना चाहिए था कि मुद्दई यह मुक़द्दमा दायर किए जानेकी तारीख़से बारह सालके भीतर आराज़ी मुतनाज़ाके ऊपर क़ाविज़ था।

३ यह कि नीचेकी अदालतको शहादतके ऊपर यह तय करना चाहिए था कि जो 'किवाला' मुद्दाअलेहने दाख़िल किया है वह फ़रेबसे हासिल किया गया था और वह बिल्कुलही सही दस्तावेज़ नहीं था।

४ यह कि अदालतने उस 'किवाला' को इस मुक़द्दमेंकी शहादतमें लेकर बड़ी भारी कानूनी ग़लती की है।

५ यह कि नीचेकी अदालतको नहीं चाहिए था कि वह तहसील-वसूलके कागज़ों और पैदावारके ऊपर जोकि मुद्दईकी ओरसे दाख़िल किए गए थे, विश्वास नक़रे।

६ यह कि नीचेकी अदालतको शहादतके ऊपर यह तय करना चाहिए था जैसा कि अर्ज़ीदावामें बतलाया गया था।

७ यह कि नीचेकी अदालतका फैसला मुक़द्दमेंमें दीगई शहादतके प्रभावके विरुद्ध है और यह कि यह न्याय, इन्साफ़ और शुद्ध अन्तः करणके विरुद्ध है।

मैं इस बातकी तस्दीक करता हूँ कि मैंने इस मुकद्दमेंके कागजातकी जांचकी है और यह कि मेरी रायमें ऊपर नतलाई हुई वजहें इस अपीलके लिए अच्छी वजहें हैं और उसे तैयार कर चुकने पर मैं अदालत अपीलके सामने हाजिर होने और अपीलकी पैरवी करनेकी प्रतिज्ञा करता हूँ ।

(दस्तखत वकील)

३१ आम मुख्तार नामा

सर्व साधारणको विदित हो कि मैं ... वलद ... उमर ...
 कौम हिन्दू, पेशा जमीन्दार, साकिन हांल ... परगना ...
 तहसील ... जिला ... ने श्री ... वलद ... कौम
 ... साकिन ... को मेरी जगह पर और मेरे नामसे, काम करनेके लिए अपना सच्चा और कानूनी मुख्तार नामजुद किया, बनाया और नियत किया है और इस तहरीरके जरिये नामजुद करता हूँ; बनाता और मुर्कर करता हूँ और अपनी जगह पर और अपने बजाय काम करने के लिये नियुक्त करता हूँ और अपना अधिकार देता हूँ कि वह जैसा कि उक्त मुख्तारको मुनासिब और मेरे मतलब और फायदेके लिए जान पड़े, नीचे लिखे कुल कामोंको करे:—

किसी न्यायालयमें किसी प्रकारके कर्जों या रुपये, अधिकार, हकीयत, हिस्से, जायदाद, मामले या चीज़को दिलापानेके लिए जोकि मुझे मिलना है या वाज़िबुल वसूल है या मिलनेको या वाज़िबुल वसूल होनेको हो, या और किसी तरह मेरी मिलिकयत हो या उसी मुकद्दमें, या कार्रवाई तथा उन तमाम मुकद्दमों या कार्रवाइयोंमें मेरी तरफसे हर अङ्गरेजी वरियासती अदालतोंमें हाजिर हों और मेरी तरफसे पैरवी करें, अदालतमें दाखिल होने वाले कागज़ों पर मेरा नाम बकलम अपने लिखें और तस्दीक करावें । अदालतों व सरकारी मोहकमोंसे अपनी रसीद दाखिल करके मेरा याफ्तनी रुपया उठावें और उस रसीदकी तस्दीक करें । और जो कुछ कि कार्रवाई किसी भी मुकद्दमें या मामलेमें जरूरी होकरें पंच मुर्कर करें और मेरी तरफसे बयान लिखावें इजहार दें और अपनी तरफसे कोई वकील आदि या मुख्तार खास किसी मामलेमें नियत करें । जो कुछ कि कार्रवाई मेरे उक्त मुख्तार आमके द्वारा की जायगी वह सब ऐसी समझी जायगी कि उसे मैंने खुदकी है और उसका मैं पूरा पाबंद हूँगा इसलिये यह आम मुख्तार नामा लिख दिया कि सदन रहे तारीख माह सन् ई० (दस्तखत)

रजिस्ट्री

३२ मुखतारनामा खास

[किसी दस्तावेज़की रजिस्ट्रीके लिए]

सर्व-साधारणको विदित हो कि मैं

धरद साकिन कौम पेशा साकिन
 जिला का हूँ। चूँकि मैंने एक दस्तावेज़ व हक ... वरद
 कौम साकिन के लिख दिया है और चूँकि उक्त दस्तावेज़की
 तकमील को स्वीकार करनेके लिए मैं रजिटरिङ्ग अफ़सर स्थान के सामने
 स्वयं हाज़िर होसकनेमें असमर्थ हूँ इसलिए मेरे लिए यह आदेश्यक होगया है कि
 उपरोक्त तकमील और तस्दीक करनेके लिए मैं किसी शख्सको अपना मुखतार
 भुकरर करूँ। और इसलिये मैं उक्त दस्तावेज़की रजिस्ट्री कराने के लिए
 और उस दस्तावेज़की तकमीलको मंजूर करनेके लिए श्रीयुत वरद...
 कौम साकिन पेशा को अपना मुखतार भुकरर किया है,
 कि वह मेरे नामसे और मेरी ओरसे उक्त दस्तावेज़को मुनासिब रजिस्टरिङ्ग अफ़-
 सर मुकाम के सामने रजिस्ट्रीके वास्ते पेश करें और मेरी ओरसे उक्त
 दस्तावेज़ की तकमीलको तस्लीम करें।

तारीख

(दस्तखत)

नोट—ऐसे मुखतारनामोंको रजिस्ट्री होना चाहिये।

३३ पट्टा (बंगाल)

आज तारीख माह सन् १९ ई० को श्री
 (जोकि इसमें आगे चल कर पट्टा देहन्दाके नामसे सम्बोधित किए गए हैं)
 तथा श्री ... (जोकि आगे चल कर पट्टादार कहे गए हैं) के बीच
 इकरारनामा हुआ, जिसके ज़रियेसे पट्टा देहिन्दाने वह कुल ईटसे बना हुआ पक्का
 मकान या हवेली मय उन कुल बाहरी मकानों, गोदामों, अस्तबलों, गाड़ी खानो
 तथा तमाम दूसरी लससे सम्बन्ध रखने वाली चीजों और तमाम हकूक, हकूक
 असायश और रिआयतोंको, जोकि उनसे सम्बन्ध रखती हैं और जो पर
 शहर के अन्दर बाक़े हैं [यहां रक़बा और हदूद आया
 लिखना चाहिए,] तारीख माह सन् १९ ई० से सालाना मियाद
 पट्टेदारी पर और ६० सालानाके किरायेपर जोकि सिर्फ़ हर महीनेकी
 पांचवीं तारीखको या उससे पहिले अदा किया जायगा उठा देने का इकरार
 किया और पट्टेदारने उसे लेनेका इकरार किया, और पट्टेदार इस तहरीरके
 ज़रिये पट्टा देहन्दाके लिये नीचे लिखा इकरार करता हूँ:—

१ यह कि ऊपर बतलाए हुए दिनों और तरीक़े पर उक्त लगान (किराया)
 और रक़म अदा करता रहेगा।

२ उक्त मकान और जगहमें एक ठीक और ऐसे तरीक़े से रहते रहेंगे और

इसको इस्तेमाल करते रहेंगे कि वह काबिल सकूनतबना रहे ।

३ पट्टादारी के दौरानमें उक्त मकान वगैरा के लगाये गये रेट, महसूल और अववाबको अदा करता रहेगा ।

४ यह कि उक्त जगहके ऊपर कोई भी व्यापार या कारबार नहीं किया जायगा बल्कि उक्त मकान और जगह सिर्फ रहने वगैराके कामके लिए इस्तेमाल किए जायेंगे ।

५ यह कि पट्टेदार इस इकरारनामाके अनुसार उक्त इकरारनामामें अपने हक को किसीके नाम मुन्तकिल नहीं करेगा और न बिना तहरीरी रजामन्दी उस तमीन्दारके उसके या उसके किसी हिस्सेके कब्जेको छोड़ सकेगा और न उसे किसी शख्सको शिकमी उठा सकेगा ।

६ यह कि पट्टा देहन्दा और उसके कारिन्दा या मुख्तारको कानूनन यह अधिकार होगा कि वह उसकी हालतकी देख भाल करनेके लिए इस मियाद पट्टे दारीके दौरानमें तमाम मुनासिब मौकोंके ऊपर उक्त मकान और हाता के अन्दर जा सकें । लेकिन इसके साथ यह शर्त हमेशा लगी रहेगी कि अगर कोई भी किराया, उन तारीखों पर जोकि इसकी आदायगीके लिए इसके बादमें मुकरर की जायेंगी अदा न किया जायगा, चाहे वह जाबतेसे तलब किया गया हो या न किया गया हो या अगर पट्टेदार दीवालिया हो जायगा या अपने महाजनोंके साथ कोई राजीनामा (सुलहनामा) कर लेगा या अगर पट्टेदार इस इकरारनामाके ऊपर बाकायदा तौर पर अमल नहीं करेगा तो पट्टा देहन्दा, उसके तामील कुनिन्दों, प्रबन्धकों या मुन्तकिल अलेहोंको कानूनन यह अधिकार होगा कि वे उक्त मकान और जगहके ऊपर फिर कब्जा कर लें और उसमेंसे कुल आदमियोंको निकाल दें और हटा दें और जो पट्टा इस तहरीरसे पैदा होता है वह खतम हो जायगा ।

और पट्टा-देहन्दा पट्टेदारके साथ नीचे लिखा इकरारनामा करता है:—

१ यह कि पट्टेकी मियादके दौरानमें उस मकानके बाहरी हिस्सेकी मरम्मत करवाता रहेगा ।

२ यह कि उक्त किरायाको अदा करते हुए और इस इकरारनामाके अनुसार कार्य करते हुए पट्टेदार, पट्टा देहन्दा, या किसी दूसरे शख्सकी ओरसे जोकि उसके लिए या उसके जरियेसे दावेदार है उसके द्वारा बिना किसी प्रकारका कोई हस्तक्षेप किए हुए शान्तिके साथ उस मकानमें रह सकता है और उस जगहको इस्तेमाल कर सकता है ।

इसके सबूतके लिए इस इकरारनामाके फीकेंनने आज तारीख माह.....सन्.....को उस पर अपने अपने दस्तखत किए और अपनी अपनी मोहरें लगा दीं ।

३४ हिबानामा (दानपत्र)

मैं कि वल्द कौम
 साकिन ज़िला का हूँ। चूँकि
 मुसम्मी को मैंने परवरिश किया था और उसने
 अपने समस्त जीवन कालमें बहुत ही सच्चाई, ईमानदारी तथा शुभचिन्तकताके
 साथ मेरी सेवा की और मुझे हरप्रकारसे खुश रखा। तीन वर्ष व्यतीत हुए, जब
 कि उसका देहान्त होगया था। उसका पुत्र मुसम्मी भी
 बहुतही सच्चाई और नेकनीयतीके साथ मेरी खिदमत करता है। अतएव मैं इस
 विचारसे कि मुसम्मी मेरे परवरिश किये हुए,
 एक निहायत ईमानदार नौकरका पुत्र है और स्वयं भी अपने पिताके समान ही,
 मेरी सेवा करता रहा है, मैं अपनी स्वतंत्र इच्छासे, खुशीके साथ, ठीक होसहवास
 में प्रतिज्ञा करता हूँ और लिख देता हूँ कि कुल जायदाद स्थावर तथा जङ्गम
 वगैरा मुफ़्तसिल ज़ल उसको हिबा करदी, और आजसे उस रियासतसे अपना
 अधिकार निकालकर, उसका कब्ज़ा मालिकाना करा दिया और अपने समान
 अधिकार दे दिया।

भविष्यमें मुझे अपने जीवनकालमें तथा मेरे चारिसोंको मेरी मृत्युके पश्चात्
 उक्त जायदाद पर कोई अधिकार या दावा न होगा।

तफ़्सील जायदाद जो हिबा कीगई

स्थावर कीमती

जङ्गम बाकै

ता० माह सन्

दस्तख़त हिबा करने वालोंके वल्द

कौम साकिन

गवाह

गवाह

३५ बयनामा

मैं कि वल्द कौम
 उमर ... साकिन ज़िला का हूँ जोकि
 एक मंजिल हवेली पुरता जिसकी लम्बाई गज चौड़ाई
 गज रुकबा जिसके अन्दर पूरबकी ओर पश्चिम
 की ओर उत्तर की ओर दक्षिण की
 ओर है जिसकी चौहद्दी पूर्वमें पश्चिम
 उत्तरमें दक्षिणमें है
 न० बाकै मैं है जो कि मेरी
 मौलसी जायदाद है और मेरे पूर्वजों द्वारा खरीदी और बनवाई गई है तथामें
 बिना किसीकी शिरकत उसपर काबिज़ हूँ अब मैंने उक्त हवेलीको, अपनी स्वस्थ

अवस्थामें, स्वतंत्र इच्छा, ठीक होसहवासके साथ, बिना किसी प्रकारके प्रलोभन
या दबावके, बएवज़ हजार रुपये सिक्के
वेहरेदार प्रचलित, जिसके आधे हजार होते हैं श्रीमान् ...
... .. वरद कौम
साकिन जिला के हाथ
देच दिया, तथा वय सम्बन्धी समस्त रुपया उक्त खरीदारसे प्राप्त कर लिया और
आज ता० माह सन् से उक्त
हवेली तथा तत्सम्बन्धी ज़मीनपर खरीदारको अपने समान अधिकार तथा
कब्ज़ा दे दिया । अब मुझको या मेरे वारिसोंको रेहन या वयके विषयमें कोई
अधिकार बाकी न रहा । यदि कोई हिस्सेदार या शरीक उक्त हवेलीपर किसी प्रकार
का दावा करे, तो उसका उत्तरदायित्व मुझ वय करनेवाले पर होगा, और यदि
किसी कारणसे उक्त हवेलीका कुल हिस्सा या कुल भाग निकल जाये, तो खरी-
दारको यह अधिकार होगा, कि वह अपनी वय सम्बन्धी रकम मय सूद ...
... फीसदीके हिसाबसे मुझ देचनेवाले की स्थावर तथा जड़म जायदादसे
नियमानुसार वसूल करले । अतएव यह वयनामा मय गवाहान् हाशिया
के लिख दिया कि सनद रहे और आवश्यकता पर काम आवे । इसके अतिरिक्त
एक किता दस्तावेज़ जो मेरे पूर्वजों के समय की मेरे पास थी खरीदारको दे
दिया । ता० माह सन्
दस्तख़त वय करनेवाले के वरद साकिन
ग० १ ग० २ ग० ३

३६ रेहननामा

मैं कि वरद
कौम साकिन जिला
का हूँ । जोकि मौजा परगना जिला के ...
... हिस्सेका अधिकारी हूँ और मैं बिना किसीकी शिरकत, व दखलके
काबिज़ हूँ तथा उसकी आमदनीसे लाभ उठाता हूँ अब बिना किसीके दबाव, अपनी
स्वतंत्र इच्छासे ठीक होसहवासमें उक्त अपने अधिकार ज़मींदारीको मय समस्त
अधिकार दाखिली व ख़ारजी अर्थात् आराज़ी मजक़ूआ व ग़ैर मजक़ूआ बंजर व
ऊसर, पोखर व तालाब व कुयेंपङ्के व कच्चे व बागात व वृक्ष खुदरा व
आवादी, जङ्गल व ढाक व रकूमात सवाई तथा उक्त जमींदारी सम्बन्धी हरप्रकार
की आमदनीके बएवज़ हजार जिसके आधे हजार
सिक्के प्रचलित इस समय होते हैं पास श्रीमान् साकिन
वरद कौम के रेहन किया व
परगना जिला
गिरवी रखा तथा तमाम रेहननामा सम्बन्धी रुपया मुरतहिनसे नक़द एकमुश्त

प्राप्त कर, उक्त ज़मींदारीको अपने अधिकारसे निकाल कर ता० ...
 माह ... सन् ... से मुरतहिनके अधिकार व कब्जेमें
 मुरतहिनी विभाग द्वारा दे दिया और अपनी मिस्लजात कायमसुकाम बना दिया
 आजसे मेरी मिस्लजातके उक्त रेहनशुदा ज़मींदारीके बाबत मुरतहिन
 को हर प्रकारका अधिकार हासिल है, जिस प्रकार चाहे उससे लाभ उठाये।
 उक्त रेहनशुदा ज़मींदारीकी आमदनी, रकम रेहनके सूदमें मोजरा होती रहेगी।
 अतएव न मुझ राहिनको मुनाफ़ा पैदावार ज़मींदारी और न मुरतहिनको ज़र
 रेहनके सूदका इस रेहननामेके अस्तित्व तक दावा होगा, जब चाहूँ ज़ररेहन
 एकमुश्त अदा करके इनफिकाक रेहन करवा लूँ, किन्तु बिना ज़ररेहन एक
 मुश्त अदा किये हुए इनफिकाक रेहन न होगा, और जबतक कुल रकम न अदा
 हो जायगी रेहन शुदा जायदादको किसी दूसरी जगह परिवर्तित करनेका
 अधिकार न होगा, और यदि कीजायगी, तो वह परिवर्तन नाज़ायज समझा
 जायगा। मैं इस जायदादका दाखिल खारिज करवा दूंगा, यदि दाखिल खारिज
 न करवाऊँ, या जायदाद मरहूना कुल या उसका कुल हिस्सा किसी
 वजहसे मेरे या मेरे धारियोंके अधिकारसे निकल जाय, तो मुरतहिनको अधिकार
 रहे कि वह अपना कुल रुपया मय सूद दर ... के हिसाबसे मेरी
 कुल दूसरी जायदाद स्थावर व जड़मसे नियमानुसार वसूल करले। यदि रेहन
 शुदा जायदादके सम्बन्धमें कोई सहीम या शरीक किसी प्रकारका दावा करे तो मैं
 उसका उत्तरदायी हूंगा। अतएव यह रेहननामा दखली लिख दिया कि सनद रहे
 और आवश्यकता पर काम आवे।

ता० ... माह ... सन्
 दस्तख़त राहिनके ... वल्द ... कौम ... साकिन
 ग० ... ग० २ ... ग० ३ ...

३७ इकरारनामा

मैं कि ... वल्द ... कौम
 ... साकिन ... ज़िला ...
 का हूँ जो कि ... रुपये जिसके आधे ... होते हैं पास श्रीमान्
 ... वल्द ... कौम
 ... साकिन ... से नक़द पेशगी लेता हूँ और
 प्रतिज्ञा करता हूँ कि तीन माहके अन्दर चार खेमे मय सब सामान तय्यार करके
 फी खेमा ... रुपयेके हिसाबसे देदूंगा, यदि नियत समयके अन्दर
 इकरारनामेके अनुसार खेमे तय्यार करके न देदूँ तो उक्त रकम मय दो रुपये
 सैकड़े सूद माहानाके, बिना किसी उज्र या हीला हवालाके अदा करूंगा यदि खेमे
 मय कुल सामानके नियत समयके अन्दर तय्यार करके दे दूंगा तो शेष रकम

बहिषाव ... फी तम्बू ले दूंगा। अतएव यह इकगारनामा बशहादत गना-
हान लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आये।

तां ... माहके ... सन ...

दस्त खत इकगारनामा लिखनेवाले के

गः

गः

गः

३८ वसीयतनामा

मैं कि ... वलद ... साकिन
... जिला ... व वजह अपनी तन्दुरुस्ती खराब होने

के अपनी मौतके बाद अपनी जायदादके लिये यह आखिरी वसीयतनामा
लिखता हूँ। मैं इस वसीयतनामेके जरिये इस जैल वसीयत करता हूँ:—

१ मैं अपने पुत्रों ...

... को अपने वसीयतनामेका तामील कुनिन्दा और ट्रस्टी मुकर्रर करता हूँ।
और एलन करता हूँ कि वह तमाम ट्रस्ट और अधिकार जो कि मेरे इन तामील
कुनिन्दाओं और ट्रस्टियों को दी गई है उनके वारिसों और दरवारिसोंको हासिल
होती रहेगी।

२ मैं अपने तामील कुनिन्दाओं और ट्रस्टियोंको हुक्म देता हूँ कि वे मेरी
जायदादसे सबसे पहिले मेरे वाजिबुल अदा कर्ज और वसीयतनामेके मुताल्लिक
अखराजात अदा करें और ... रुपया मेरी अन्वयेन्डि
क्रिया और श्राद्धमें खर्च किये जाय।

३ मैं अपनी प्यारी पत्नी श्रीमती ... को साढ़े
तीन फीसदी सूदके गवर्नमेण्ट प्रामिजिरी नोट कीमती ...
रुपये के देता हूँ वे मेरी मौतके छः महीनेके अन्दर विल्कुल अदा कर दिये जाय।
मैं अपनी उक्त पत्नी श्रीमती ... को अपना मकान सकूनती
नं० ... सड़क शहर बम्बई को सिर्फ उसकी जिन्दगी
भरके लिये देता हूँ। मैं उसे वह तमाम जवाहिरात और सोने तथा चांदीके जेवरात
भी जिसे वह इस्तेमाल करती रही है वसीयत करता हूँ।

४ मैं इस वसीयतनामेके द्वारा अपना व्यवसाय जो ... के
नामसे चलता रहा है और जिसका मैं पूर्ण अधिकारी हूँ अ. व. स. द. और य.
पुत्रोंको जो मेरे प्रथम द्वितीय तृतीय, चतुर्थ और पंचम पुत्र हूँ समान हिस्से पर
देता हूँ। उक्त पांचो पुत्रोंको मैं अपनी तमाम पैतृक जायदाद और मेरी स्वयं
वर्णित रियासत, जो कि जिला ... और ... में
वाँके है और चार फीसदी सूदके गवर्नमेण्ट प्रामिजिरी नोट भी कीमती ...
रुपये तथा समस्त मेरी गृहस्थी सम्बन्धी वस्तुयें, सामान और सम-
स्त स्थावर तथा जड़म जायदाद, जिसका कि मैं मालिक हूँ या जो मेरे अधिकार
में है वसीयत करता हूँ।

५ मैं इस वसीयतनामेकेद्वारा अपनी दो पुत्रियों श्रीमती
 ... और श्रीमती ... को पांच हजार
 रुपये नकद देता हूँ, वे उन ... को मेरी मृत्युके दो
 महीनेके अन्दर देदिये जाय।

६ मैं अपने तामील कुनिन्दो को हुक्म देता हूँ कि वे मेरी उक्त पत्नी श्रीमती
 ... को उन तमाम चीजोंके अतिरिक्त जो मैंने
 उते इस वसीयतनामेके द्वारा दिया है चालीस रुपया मासिक उसके व्यक्तिगत
 खर्चके लिये तादयात देते रहें।

७ मैं अपने तामील कुनिन्दोंको यह भी हुक्म देता हूँ, कि वे तीन फीसदी
 सूदके मेरे गवर्नमेण्ट प्रामिजिरी नोट, कीमती ... हजार
 अलाहिदा करदें और उसके सूदसे दुर्गापूजाका सालाना खर्च चलायें, तथा अपने
 इष्ट देव श्रीशङ्करजी की दैनिक सेवाका प्रबन्ध रखें।

(वसीयत कर्ताके दस्तखत)

निम्न सज्जनोंकी उपस्थितमें तस्दीक किया गया:—

१ ... } गवाह
 २ ... }
 ३ ... }

३९ तकसीमनामा

हम कि ... व ... घरद
 ... कौम ... पेशा ...
 साकिन ... परगना ... ज़िला
 ... के हैं जो कि मौजा ... के मय बागात व मकानात वगैरा, जो
 इस मौजेमें वाकै हैं विला किसीकी शरकत व अधिकारके हम काबिज
 व पूर्ण अधिकारी हैं अब हमने अपनी रज़ामन्दी, निश्चित सम्मति तथा ठीक होस
 हवासमें समयानुसार भविष्यके लिये यह उचित समझा है कि उक्त मौजेकी
 जमावन्दी व खसरा बंदोबस्तके अनुसार दो मुहाल करलें तथा स्थावर व जङ्गम
 सम्पत्तिको दो समान भागोंमें विभाजित कर, हम दोनों नीचेकी सूचियोंके अनु
 सार बांट लिया और अपने अपने भागों पर अधिकार कर लिया है। आगामी वर्ष
 ... सन् से सरकारी आमदनी अलग अलग अदा किया करेंगे, और इस
 बटवारेकी एक एक फर्द हम दोनोंके पास मौजूद रहेगी। इस बटवारेके अनुसार
 कलकटरी विभागमें अर्जी देकर, दोनों मुहालोंकी पृथक खेवटें तयार करा कर

जमावन्दी अलग अलग करादी जायगी । भविष्यमें हमें या हमारे वारिसोंको इस तकसीमनामके विरुद्ध किसी प्रकारकी शिकायत न हांगी, और न इसकी शताके विरुद्ध किसी प्रकारकी समाभत होसकेगी । अतएव यह तकसीमनामा मय शहादत गवाहान हाशिया, इसलिये सुरतिव हुआ कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

दस्तखत तकसीम कुनिन्दा

ग०

ग०

४० ख़ास किस्मका बयनामा

जब किसी वारिसको जायदाद पानेका हक़ पैदा हो जाय और वह निर्धनताके कारण अदालतमें नालिश न कर सके और अपने हक़का कोई हिस्सा किसीको इस मतलबसे बय करदे कि वह मुक़दमेके खर्चके बदले जीतने पर उतना हिस्सा ले लें ऐसा बयनामा बहुत मुश्किल होता है और बहुत समझ बूझ कर लिखा जाता है । हम नीचे ऐसेही एक बयनामेकी नक़ल देते हैं जिसे नामी और गम्भीर एवं धुरंधर वकीलोंने श्रीमान् सेठ जगन्नाथ चिरंजिलाल गोइन्दकाके हक़में लिखा था । आपको इससे अपने मामलेमें बहुत मदद मिलेगी

हम कि छन्नू व रामचरन व भैरवालाल पिसरान फकीरे चौधरी व रामसेवक पिसर तुलसीदास नवीरा फकीरे अकचाम वैश्य साकिनान जैतपुर परगना ज़िल पहाड़ जि० हमीरपुर बज़रिये इस तहरीरके हस्व जेल इकरार करते हैं और लिखे देते हैं ।

१ यह कि अयोध्या प्रसाद हम मुकिरानका रिश्तेदार करीबी हस्व शिज़रा ज़िल था । अयोध्या प्रसाद मज़कूरने अर्सा हुआ कि जायदाद मालियती कसीर छोड़कर वफ़ात पाई । अयोध्या प्रसाद मज़कूर अपने भाई भवानी प्रसाद और उसकी औलादसे अलददा और मुन्किस्म थे, और जुड़ावन तीसरा भाई अयोध्या प्रसादका लाखरद वहात अयोध्या प्रसाद फौत हो चुका था ।

२ यह कि अयोध्या प्रसादने व वक्त वफ़ात अपने, अलावा दीगर जायदादके जायदाद जिमीदरी कसीर उल मालियत छोड़ी । तमाम जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद पर व शमूक जायदाद जमीदारी मज़कूर, उसकी बेवा सुसम्मात

साई वरासतन मालिक व काबिज़ हीन हयाती व अख्तयारात महदूद हुई। मुस-
म्मात साई भी एक अर्सा हुआ फौत होगई और उसकी वफात पर मुसम्मात
ललता बाई दुखतर अयोध्या प्रसाद मौसूफ वरासतन मालिक व काबिज़ हीन
हयाती जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद की व शनूल जायदाद ज़िमीदारी
मज़कूरके व अख्तयारात महदूद हुई और बिल एवज कर्जा याफतनी अयोध्या
प्रसाद चन्द हिस्सा ज़िमीदारी मुसम्मात ललता बाईने खरीद किये वह भी जुज
जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद होगये।

३ यह कि अयोध्या प्रसादके एक लड़का मुसम्मी कल्लू था जो कि बहयात
अपने चाप अयोध्या प्रसादके फौत होगया। कल्लूने व वक्त वफात अपने दो वे
बगान यानी मुसम्मातान लाइली और सलोनी और एक लकड़ा नथू छोड़ा।
बादहू नथू भी हयात अयोध्या प्रसादमें लावल्द फौत होगया और कुछ अर्से
बाद मुसम्मात लाइली बेचा कल्लू फौत हुई मुसम्मात सलोनी बेचा कल्लूको व
वजह इसके कि उसका शौहर बहयात उसकी सुसरके फौत होगया था। कोई
हक जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसादमें नहीं पहुँचा। अयोध्या प्रसाद ने बाद
वफात कल्लू महज़ बगरज़ दिलजोई, बेचा कल्लू का नाम चन्द मवाज़ियात
पर दर्ज करा दिया था। लेकिन फिलवाक़े मालिक वा काबिज़ कुल जायदादका
तनहा अयोध्या प्रसाद रहा और बाद उसकी वफातके मुसम्मात साई और बाद हू
मुसम्मात ललता बाई व हक हीन हयाती जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद पर
वशमूल उस जायदादके जो अयोध्या प्रसादके मतरूकेसे खरीदी गई थी
काबिज़ रही।

४ यह कि बाद वफात मुसम्मात साईके, जब कि ललता बाई जायदाद
पिंदरी पर हीन हयाती व अख्तयारात महदूद वरासतन मालिक व काबिज़ थी,
मु० सलोनी व ललता बाई दुखतर अयोध्या प्रसादने व सानिश तातिया प्रसाद
दामाद मु० ललता बाईके, यह जाहिर किया कि मु० सलोनी बेचा कल्लूने मुस-
म्मी स्वामी प्रसाद पिसर तातिया प्रसादको हस्व इजाजत शौहरी गोद लिया।
और यह किस्सा गोदका औलाद भवानी प्रसादको, जो कि वारिस माबाद होते
थे महरूम करनेकी गरज़से अफ़जा किया गया और इस मामलेमें मुसम्मी फकीरे
को भी शामिल इस तरीकेसे कर लिया कि एक पञ्चायतनामा फज़ी व साजिशी
तहरीर कराया गया जिसकी रूसे मिन् जुमले जायदाद ज़िमीदारी मतरूका
अयोध्याप्रसाद के ज़िमीदारी मुन्दजै फेह्रिस्त (अलिफ़) व (बे) मुशरहे ज़ैल
में बक़दर एक सुल्सके फकीरे को दिलाया गया और वकीया दो सुल्स जायदाद
मज़कूरका मालिक स्वामीप्रसाद करार दिया गया। और जो जायदाद फेह्रिस्त
नम्बर (जीम) में दर्ज हैं और जो वज़रिये दो किता हेवा नाम जातके मौरुख
ता० २२ अगस्त सन् १८९० ई० और दोयमी मौरुखे ता० ११ सितम्बर १८९० ई०
के मुसम्मात सलोनी ने वहक तातियाप्रसाद हिवा करदी थी उसकी निस्वत यह
करार पाया कि वह जायदाद बदस्तूर मौदूब अलेह मौसूफ के कब्ज़ेमें रहेगी।

(५) यह कि क्रिस्ता तबनियत स्वामीप्रसादका महज गलत और वे बुनियाद था और फिलवाकै स्वामीप्रसादको सुसम्मात सलोनीने कभी अपने शौहर सुसम्मी कल्लूके लिये गोद नहीं लिया और अगर व फर्ज मुहाल स्वामीप्रसादको सुसम्मात सलोनी अपने शौहर सुसम्मी कल्लूके लिये गोद लेती तो तबनियत मजकूर शास्त्रन् व कानूनन् नाजायज होती । लेकिन बावजूद इन तमाम उमूरके मामलेमें रंगत देनेकी गरजसे एक गोदनामा भी फर्जी ता० १३ मई सन् १९०९ ई० यानी जिस रोज पंचायतनामा लिखा गया तहरीर करा लिया गया ।

(६) यह कि सुसम्मी भगवानदास वरद बाँकेने नालिश नम्बरी ३०३ सन् १९१० ई० व अदालत सबजज बहादुर जिला बाँदा बाबत इस्तक्रार इन उमूरके दायरकी कि यह करार दिया जावे:—

(अलिफ) स्वामीप्रसादको सुसम्मात सलोनीने कभी गो नहीं लिया और तबनियत जिसका जिक्र तबनियतनामा मौखे १३ मई सन् १९०९ ई० में है, फिलवाकै कभी अमलमें नहीं आई और अगर इस क्रिस्मकी तबनियत फिलवाकै अमलमें आती, तो वह शास्त्रन् व कानूनन् नाजायज होती और स्वामीप्रसाद मजकूरको कोई हक मतलबका अयोध्याप्रसाद मुन्दर्जे फेहरिस्त (अलिफ) व (बे) में नहीं पहुँचा ।

(बे) तबनियतनामा व फैसला सालिसी मौखे १३ मई सन् १९०९ ई० वसुकाचिले जादाद मुन्दर्जे फेहरिस्त (अलिफ) (बे) व (जीम) बाद वफात सुसम्मात ललताबाईके नाजायज व गैर मुअस्सर करार दी जावे और इस्तक्रार इस भग्नका फरमाया जावे कि स्वामीप्रसाद व तांतियाप्रसादका कोई हक जायदाद मजकूरे चालामें बजरिये दस्तावेजात मजकूरैनके नहीं है । नालिश मजकूर अदालत इस्तदाईसे कानूनी बुनियाद पर खारिज हो गई जिसकी अपील अदालतुलआलिया हाईकोर्ट इलाहाबादमें मिनूजानिब भगवानदास मौसूफ दायर हुई और अदालतुलआलिया हाईकोर्टसे फैसला अदालत मातहतका मंसूख होकर दावी भगवानदास जिस इस्तदुआय दादरसीके साथ दायर हुआ था डिकरी होगया । यानी हरदो दादरसी हाय इस्तक्रारया मजकूरे बालाकी डिकरी सादिर होगई ।

(७) यह कि व नाराजी फैसला अदालत हाईकोर्टके अपील मिनूजानिब स्वामीप्रसाद व तांतियाप्रसादके अदालत प्रिवीकौंसिलमें दायर हुआ और वहांसे फैसला अदालतुलआलिया हाईकोर्ट इलाहाबाद बहाल रहा सिर्फ इस कदर तामीम फैसला हाईकोर्ट मजकूरमें अदालत प्रिवीकौंसिलनेकी कि जो डिकरी इस्तकरारिया अदालतुलआलिया हाईकोर्ट इलाहाबादने सादिरकी है उसका निफाज दरमियान मुद्दई और मुद्दाअलेहम त० ८ लगायत ११ के एक जानिब व दीगर मुद्दाअलेहमके दूसरी जानिब महदूद रहेगा । और इन दीगर मुद्दाअलेहमके हुक्क बाहमी पर इस डिकरीका कोई असर न होगा ।

(८) यह कि क्रिस्ता तबनियत अदालत आखिरी यानी प्रिवीकौंसिलसे गलत करार पा चुका है तबनियतनामा व पंचायतनामा मजकूरे वाला भी

नाजायज़ और गैरमुअस्सर व मुकानिले हक़क हममुकिरानके करार पाचुके हैं और यह तय हो चुका है कि स्वामीप्रसाद या तांतियाप्रसादका कोई हक़ जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसाद मजकूर बालामें नहीं है ।

(९) यह कि मुसम्मात ललताबाईने बतारीख ३ नवम्बर सन् १९१८ ई० मुताबिक कातिक बदी अमावस्या सम्बत् १९७५ वि० वफात पाई । उसकी वफात पर मुसम्मी फकीरे जो कि उस वक्त हयात था बहैसियत करीबतरीं वारिसमा बाद अयोध्याप्रसादके मालिक व काबिज़ कुल जायदाद ज़मींदारी मतरूका अयोध्याप्रसादका हुआ ।

(१०) यह कि फकीरे करीब एक साल बाद वफात ललताबाईके फौत होगया । और उसकी वफात पर उसके पिसरान् मुसम्मियान छन्नू व रामचरन व भैयालाल व तुलसीदास व बरासत अपने बापके मालिक जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसादके हुए और हैं । बादहू मुसम्मी तुलसीदासने अपने पिसर रामसेवकको छोड़कर वफात पाई अब हम मुकिरान नम्बर १ लगायत ४ मालिक जायदाद मजकूरके हैं ।

(११) यह कि बवजूद इसके कि, जिस वक्त पंचायतनामा तहरीर हुआ मुसम्मी फकीरे मजकूरको कोई हक़ फिलवाकै जायदाद मजकूरमें हासिल नहीं हुआ था बल्कि उसको महज़ कान्टनजेन्ट इन्टरेस्ट (Contingent Interest) बहैसियत रिकर्ज़नर (Reversioner) के हासिल था जो कि कानूनन् मुंतकिल किसी बिनहसे नहीं हो सकता था न उस कान्टेनजेन्ट इन्टरेस्ट (Contingent Interest) से दस्तबरदारी शास्त्रन् व कानूनन् हो सकती थी । चुनाव फकीरे मजकूरके पंचायतनामामें शरीक होने या किसी जुज़ कान्टेनजेन्ट इन्टरेस्ट (Contingent Interest) के दस्तबरदार होनेसे किसी किस्मका जवाल उसके उन हक़क वरासतको शास्त्रन् व कानूनन् नहीं पहुँचा जो कि बाद वफात मुसम्मात ललताबाईके उसको बहैसियत करीबतरीं वारिस माबाद अयोध्याप्रसादके हासिल हुआ यानी शास्त्रन् व कानूनन् वही मालिक जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसादका बाद वफात मुसम्मात ललताबाईके हुआ ।

(१२) यह कि जायदाद मजकूर पर मुसम्मी स्वामीप्रसाद व तांतियाप्रसाद बिला किसी इस्तहकाक़के नाजायज़ तौर पर काबिज़ हैं और हम मुकिरानका हक़ तस्लीम नहीं करते हैं और न बावजूद मुतवातिर तकाज़ाके जायदाद पर कब्ज़ा हम मुकिरानको देने पर रज़ामन्द होते हैं ।

लिहाज़ा हम मुकिरानको बजुज़ अदालतमें नालिश दापर करनेके और कोई चाराकार अपनी हक़रसी और जायदाद पर मालिकाना कब्ज़ा हासिल करनेके लिये नज़र नहीं आता । मगर बदकिस्मतीसे हम मुकिरानको इस कदर इस्तेहताअत नहीं है कि अदालती तसरूफ़ात बादस्त कर सकें और न हम मुकिरानमें कोई ऐसा शक़ है जो पैरवी माकूल मुकद्दमाकी कर सके, चुनाव हम मुकिरान इस तलाशमें रहे कि कोई ऐसा शख़न मिल जावे जो कर्ज़ देने पर आमादा हो जाय चुनाव हम मुकिरानने अक्सर लोगोंसे इस्तदुआ इम्दादकी

अगर कोई शख्स कर्जा देने पर आमादा नहीं हुआ। अखिराजात मुकदमेके लिये कई हजार रुपये दरकार होंगे और इस कदर मिलना हम मुकिरानको गैर मुमकिन है अगर हम मुकिरानकी मिन्नत और समाजत करनेपर और हम लोगोंकी बेकसी और हकतलफों पर लिहाज करके कि हम अशखास मुश्तहक की जायदादको गैरमुश्त हक लोग लिये लेते हैं और अगर इस तरीकेसे चन्द साल और गुजर गये तो हम मुकिरानका हक कतई जायल हो जावेगा और जायदादके अशखास गैर मुश्तहक मालिक हो जावेंगे सेठ जगन्नाथ प्रसाद वल्द सेठ सागर मल कोम वैश्य गोइन्दका मालिक फर्म हरकिशन दास मंगल चन्द हरपालपुर साकिन हाल हरपालपुर बुन्देलखण्ड एजेन्सी हमारी इस्त दुआको मंजूर करके कि निस्फ जायदाद मतरूका अयोध्या प्रसाद जिन पर इस वक्त घिला इस्त हकाक स्वामी प्रसाद और ताति या प्रसाद काविज हैं हम मुकिरान उनके हकमें बय करके खर्च अपनी नालिशका करें और अपनी बकीया जायदादको हासिल करें उन्होंने निस्फ जायदादका बय लेना मंजूर कर लिया है चुनाव यह तय पाया कि हकीयत ज़मींदारी मुन्दर्जे सुशरें जैल बएवज़ मुबलिग दस हजार रुपये (१००००) के बदस्त सेठ जगन्नाथ प्रसाद मौसूफ़के हम मुकिरान बय करदें और चूंकि सेठ साहब मौसूफ़को जायदाद मुवैय्याकी बाबत खुद भी चारा जोई अदालती करना होगी इसलिए अलावा ज़र सम्मन मजकूरके, उन्होंने हम मुकिरान की तरफसे भी पैरवी व कोशिश करना हम मुकिरानकी इस्त दुआ पर मंजूर कर लिया है। चूंकि यह बेदतरान तरीका व तदवीर हम मुकिरानकी हक रसीकी है लिहाजा व दुस्तो होश व हवाश अपने बखुशी व खातिर व बरजा व रग़बत खुद हम मुकिरानने वज़रिये दस्तावेज़ हाज़ा हकीयत ज़मींदारी हाय मुन्दर्जे व सुशरें जैल ममलूका अपनेको। मय आराज़ी सीर व खुद काइत व वागात व मकानात व जमई ताल्लुकात विला इस्त सनाय किसी शय व हकके ब एवज़ मुबलिग दस हजार रुपये (१००००) के बदस्त सेठ जगन्नाथ प्रसाद वल्द सेठ सागर मलजी कोम वैश्य गोइन्दका मालिक फर्म हरकिशन दास मंगल चन्द साकिन हाल हरपालपुरके हस्व शरायत जैल बय कतई कर दिया और बेच डाला।

१ यह कि ज़र सम्मन तमाम व कमाल हस्व तकलील जैल मुश्तरी मौसूफ़ से वसूल पालिया हाज़त तहरीर रसीद अलहदा नहीं है। अगरचें वह ज़र सम्मन पैनामा हाजापुरी कीमत वाजारीसे कम है लेकिन चूंकि हम मुकिरान जायदाद मुवैय्या पर गैर काविज हैं और कोई शख्स वाजारमें इस कदर कीमत पर भी बय लेने पर तैयार नहीं हो सकता और न है। और चूंकि हम मुकिरानके मुकदमेमें मुश्तरीकी पैरवी व कोशिश व तकलीफ़का माबजा भी शामिल है लिहाजा व लिहाज इन जुमला हालात मजकूर शरायत दस्तावेज़ हाजाके हम बायान कुल मामला बखूबी समझ कर इस कदर ज़र सम्मन व तायून व पावन्दी शरायत दस्तावेज़ हाजाका भी मुआविज़ा नकदी व कीमत वाजबी जायदाद

मुवैय्या व रबुशी व खातिग मंजूर किया है। आइन्दा बाबत तादाद जर सम्मन या वसूल पाने जर सम्मनके हम मुकिरान या बरसाप या कायम मुकामान हम मुकिरान किसी किस्मका उज्रया हुज्जत करें तो चातिल और नाम स्मूअ होगा।

२ यह कि मिन जुमले जर सम्मन दस्तावेज हाज़ाके मुचलिग दस हजार रुपये (१००००) मुश्तरी मौसूफके पास वास्ते अखराजात नालिश हम मुकिरान छोड़ा गया है जिसमेंसे हम मुकिरान वक्तन फवक्तन बाबत खर्चा नालिश अज़ अदालत इस्तदायी ता अदालतुल अलिया प्रिवी काउन्सिल व सीगे नम्बरी या इजराय डिकरी या हुसूल दखल और कार्रवाई इन्दराज नाम अदालत माल हम मुकिरानको ज़रूरत होगी, इससे खर्चास्टाम्प व अदाय मेहनताना वकलाय व वेरिस्टरान व खर्चा शहादत व तनख्वाह मुख्तार व पैरोकारान दीगर अदराजात मुताअल्लिक मुकद्दमा बजरिये मुश्तरी मौसूफके करते रहेंगे, और जो रुपया बाबत खर्चाके मुश्तरी मौसूफसे खर्च करायेंगे या जो खर्चा बगैर हाजिरी हम मुकिरान ज़रूरत आये, नालिश या अपीलकी किसी पैरवीके मुताअल्लिक उसे मुश्तरी खुद करेंगे और करते रहेंगे वह जुमला अखराजात ख्वाह मुश्तरीने रसीद हासिलकी हो या न की हां जायज़ व काबिल मुजरई होंगे और हम मुकिरान या बरसाय या कायम मुकामान हम मुकिरानको कोई उज्र किसी किस्मका या कोई हीलाव हुज्जत अदाय अखराजातके मुताअल्लिक जायज़ व काबिल समाबत न होगा।

३ यह कि जिस क़दर रुपया वास्ते अखराजात मुकद्दमाके मुश्तरीके पास छोड़ा गया है उसमेंसे खिवाय अखराजात मुकद्दमा जिसको मुश्तरी मुनासिब समझेंगे और किसी जाती खर्च या अखराजातके लिए किसी जुजके लेनेका हम मुकिरानको अख्तियार न होगा और अगर बाद अखराजात मुकद्दमाके मिन जुमले जर मजकूरके कुछ पसंदाज होगा, तो जब तक मुकद्दमा प्रिवी कौन्सिल से कतई तौर पर मुआफिक हम मुकिरानके फैसल न हां जावेगा और मुश्तरीको दखल जायदाद मुवैय्या पर न मिल जावेगा और उसका नाम दाखिल कागज़ात मालमें न हो जायगा, उस रकमके वापिस पाने या तलय करनेका हम मुकिरान या बरसाय या कायम मुकामान हम मुकिरानको अख्तियार न होगा। अगर अखराजात मुकद्दमा उस रकमसे जायद हों जो हम मुकिरानने मुश्तरीके पास छोड़ी है तो यह बात मुश्तरी पर मवनी हांगी कि जायद खर्च जिस क़दर ज़रूरी हों अधिक करे और जो खर्चा फरीकसानीसे वसूल हो उसमेंसे आधा हिस्सा मुश्तरी और आधा हिस्सा हम मुकिरान ले लेंगे। और मुश्तरी मौसूफको यह भी अख्तियार होगा कि हम मुकिरान अगर बगरज़ मुहाल, अदालत इस्तदाई से या अदालतुल अलिया हाईकोर्टसे ना कामयाब हों तो जब तक उन वकलाओं व पैरोकारके जिन्होंने हमारी तरफसे पैरवी की हो व मशबिरे लायक वकलाय यह राय न हो कि मुकद्दमा काबिल अपील हाईकोर्ट या प्रिवी कौन्सिलके हैं, जैसीकि सूरत हो, और उम्मेद सर सवज़ीकी न हो; तो महज़ हमारी इस्तदुआ पर खर्चा अपील अदालत हाईकोर्ट या प्रिवी कौन्सिल न करे और ऐसी सूरतमें हम

मुक़िरान मुश्तहक तलबी या वापसी किसी जुज वाकी माँदा रक़म खर्चा मज़कूर के जो मुश्तरी के पास छं ड़ा है न होंगे ।

(४) यह कि चूँकि हम मुक़िरान इस वक्त दखल जायदाद मुवैया पर मुश्तरी को देने से काखिर है और मुश्तरी को बिदू नालिश केदखल जायदाद मुवैया पर नहीं मिलेगा इसलिये मुवलिग़ादस हजार रुपया (१००००) बावत खर्चा नालिश दखल यादी ताअरील अदालत मराफ़िया आला व इजराय डिकरी व दखल खारिज मुश्तरी के ज़र सम्मन में मुजरा दिया गया है और मुश्तरी को, अख्तयार है कि जिस तरीके पर चाहे उसको सर्फ करे हम मुक़िरान को कोई हक उसके मुताअलिक़ हिसाब समझने या वापस पाने का न होगा । और शर्त यह है कि भिनजुमले इस रक़म के जो बावत खर्चा नालिश मुश्तरी के मुजरा दीगई है मुश्तरी को बावत खर्चा नालिश मज़कूर के वज़रिये अदालत फरीकेन से बसूल होगा उस रक़म से आधा मुश्तरी और आधा हम मुक़िरान वाद कतई फैसला मुक़दमा अदालत आखीर और वाद दखल यादी जायदाद मुवैया के जैसी सुरत आखीर चाँकें हो लेंगें ।

५ यह कि बावत खर्चा नालिश मुश्तरी अगर उस रक़म से जायद खर्चा हो जो रक़म हस्व शर्त चहारम ज़र सम्मन से मुजरा की गई है तो उस रक़म जायद की बावत जिम्मेदारी हम मुक़िरान पर न होगी । उसको मुश्तरी बरदाश्त करेगा ।

६ यह कि अगर हम मुक़िरान और मुश्तरी की नालिश जुदागानान हो और दोनों एक ही नालिश में छुद्ई हों तो भी मुश्तरी जिम्मेदार रसदी खर्चा का होगा और वह रसदी खर्चा उस रक़म से जो हस्व शर्त चहारम मुजरा दीगई है अदा की जायगी, और बकीया खर्चा उस रक़म से जो वास्ते खर्चा नालिश हम मुक़िरान हस्व शर्त दोयम मुश्तरी के पास छोड़ा गया है अदा होगा । और जो खर्चा फरीक सानी से बसूल होगा वह आधा मुश्तरी और आधा हम मुक़िरान लेंगें ।

७ यह कि वगरज़ मुहाल अगर हम मुक़िरान या मुश्तरी अपनी नालिश या नालि शात में अदालत मराफ़िया आला से नाक़ाम याब हो या बाद ना काम याबी अदालत इजतदायी या अदालतुल आलिया हाईकोर्ट या त्रिबी कौनसिल में हस्व मशा विर बकलाय अपील न किया जाना फ़रार दिया जाय तो हम मुक़िरान मुश्तहक पाने किसी जुज वाकी माँदा खर्चा के हस्व शरायत मज़कूर वाला न होंगे और न मुश्तरी मुश्तहक वापसी किसी जुज ज़र सम्मन अदा शुदा या पाने किसी हरज़ाका हम मुक़िरान से होगा । और दर सुरत ना कामयाबी मुक़दमा खर्चा फरीक सानी जो हम मुक़िरान के जिम्मे हो मुश्तरी के जिम्मे रहेगा ।

८ यह कि अगर ऐसी सुरत पेश आवे कि हम मुक़िरान अपनी नालिश में कामयाब हों और मुश्तरी किसी तुक्स कानूनी या वाकयाती की वजेह से ना कामयाब रहे तो हम मुक़िरान देने के जिम्मेदार, अपनी जातव जायदाद से कुल खर्चा हस्व शरायत मुन्दर्जे वाला जो कुछ कि उस वक्त तक हो चुका हो मुश्तरी के होंगे और अगर हम मुक़िरान में से किसी एक या जिनके ज़रिये से व वजेह मुफ़लत या तसफ़िया या साजिस या फ़रैव या मज़त बयानी मुश्तरी मौसूफ़ को तुक्सान पहुँचे या वह मुक़दमे से ना कामयाब रहें तो अदला नहीं शख्स

या जितके ज़रिये से ऐसा हुआ हो अपनी जात और जायदाद से कुल खर्चा हस्त शरायत मुन्दजे वाला जो कुछ उज्र वक्त तक हां चुका हो मुश्तरी के देने के ज़िम्मेदार होंगे ।

९ यह कि हम मुकिरान पैखी अपने मुकदमे की मुश्तरी की सलाह व मश विरा से करेंगे हम मुकिरान को यह अख्तियार न होगा कि फरीक खानी से कोई तस्कीया या राजी नामा या दस्तवरदारी बिला मशविरे व सलाह और इजहार रज़ामन्दी सरीही मुश्तरी के करें । दर सूत खिलाफ़ वर्जी इस शर्त के जो कुछ लुकसान या खर्चा वगैरा मुश्तरी को पहुँचे तो उस कुल हरजा व लुकसान वगैरा के हम मुकिरान ज़िम्मेदारी देनेके होंगे और मुश्तरी भी बिला हम मुकिरान के कोई तस्कीया या राजीनामा या दस्तवरदारी मुकदमा व हक़ हम मुकिरान न कर सकेगा ।

१० यह कि हम मुकिरान मालिक कतई जायदाद मुवैय्या के हैं और हम मुकिरान को हर तरह का अख्तियार इन्तकाल उसकी बाबत हासिल है । और सिवाय हमें मुकिरान के कोई शरीक या हिस्सेदार जायदाद में नहीं है आज की तारीख़ से जुमला हुकूम मालिकाना बाबत जायदाद मुवैय्या मिनजानिव हम मुकिरान वहक़ मुश्तरी मुन्तकिल होंगये और मुश्तरी मिसल हमारे जायदाद मुवैय्या का मालिक क मिल बिला शरीक गैरी हो गया और उसको अख्तियार है कि वइश्तहक़क़ मिशकियत अपने कब्ज़ा जायदाद मुवैय्या पर हासिल करे और अपना नाम मालिकाना दर्ज कराये और उसका मुनाफ़ा और महासिल से मुतमन्नअ होवे और जुमला अफ़आल व अख़ग़ज़ात मालिकाना मिसल मालिक मुतलक़के अमलमें लावे और हम मुकिरान मुश्तरीके हुसूल दख़ल जायदाद मुवैय्या व हुसूल मुनाफ़ा या बासज़ात में हर तरह की कोशिश व इम्दाद करेंगे और जो जो दस्तावेज़ या तहसीर या दरख़वास्त किसी किस्म की तहरीर या तकमील या पेश करना या बयान करना लिखाना या कागज़ात या दस्तावेज़ पेश करना और जो कार्रवाही कनूनन् वास्ते तकमील हक़ब हुकूम मिशकियत मुश्तरी बहुसूल कब्ज़ा जायदाद मुवैय्या या हुसूल मुनाफ़ा या बासज़ात जायदाद मुवैय्या व मुता अलिक़ दाख़िल खारिज़ वगैरा के मिनजा निव हम मुकिरान को करना जरूरी होगा वह सब कार्रवाई हम मुकिरान बिला कि जी उज्र हुजत के अमल में ठावेगे और लाते रहेंगे ।

११ यह कि व पाबन्दी जुमला शरायत दस्तावेज़ हाज़ा की हम मुकिरान व बरसाय व कायम मुकामान व मुतकिल अलैह हम मुकिरान और मुश्तरी व उसके बरसाय व कायम मुकामान व मुन्तकिल अलैह पर होगी । इस लिये यह वेनामा व इस्तसनाय उस जायदाद के जो फकारे को मिल चुकी है और जिस पर उसकी औलाद काबिज़ व दख़ोल है वाकी जायदाद मतरूका अयोध्याप्रसाद व शमूल उस जायदाद जो अयोध्याप्रसाद के मरने के बाद उसके मतरूके से खरीदी गई वक़दर निस्फ़ हिस्सा व तरीक़ बयनामा का मिलके लिखदिया कि सनद रहे ।
ता० ३० नवम्बर १९२५ ई० बक़लम शिजिदा खानदानी राजिस्टरी और तस्दीक़

कोर्ट फीस ऐक्ट

नं० ७ सन १८७० ई०

शिड्यूल नं० १

नोट—अदालतोंमें नालिश करनेके लिये कोर्टफीसकी शर्ह सन् १९२७ ई० में नीचे लिखे अनुसार है। यह सम्झें कि ऐक्ट सन् १८७० ई० का है और उस समय वह मंजूर होगा होगा। पहले प्रान्तीय सरकारोंने इस ऐक्टमें परिवर्तन किया था और शर्ह कोर्ट फीस कुछ बढ़ा दी थी पर कुछ ही समयके बाद मंजूर कर दी।

जब कि तादाद या कीमत ना लिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो।	कोर्टफीस लगेगा	जब कि तादाद या कीमत ना- लिश इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगा
रु०	रु०	रु० आ०	रु०	रु०	रु० आ०
...	५	० ६	८५	९०	६ १२
५	१०	० १२	९०	९५	७ २
१०	१५	१ २	९५	१००	७ ८
१५	२०	१ ८	१००	११०	८ ४
२०	२५	१ १४	११०	१२०	९ ०
२५	३०	२ ४	१२०	१३०	९ १२
३०	३५	२ १०	१३०	१४०	१० ८
३५	४०	३ ०	१४०	१५०	११ ४
४०	४५	३ ६	१५०	१६०	१२ ०
४५	५०	३ १२	१६०	१७०	१२ १२
५०	५५	४ २	१७०	१८०	१३ ८
५५	६०	४ ८	१८०	१९०	१४ ४
६०	६५	४ १४	१९०	२००	१५
६५	७०	५ ४	२००	२१०	१५ १२
७०	७५	५ १०	२१०	२२०	१६ ८
७५	८०	६ ०	२२०	२३०	१७ ४
८०	८५	६ ६	२३०	२४०	१८ ०

जब कि
तादा या
कीमत ना-
लिश ससे
ज्यादा हो

लेकिन इस
से ज्यादा
न हो

कोर्ट फीस
लगेगा

जब कि
तादा या
कीमत ना-
लिश इससे
ज्यादा हो

लेकिन इस
से ज्यादा
न हो

कोर्ट फीस
लगेगा

रु०	रु०	रु० आ०	रु०	रु०	रु० आ०
२४)	२५०	१८ १२	५४)	५५०	४१ ४
२५)	२६०	१९ ८	५५)	५६०	४२ ०
२६०	२७०	२० ४	५६०	५७०	४३ १२
२७)	२८०	२१ ०	५७)	५८०	४३ ८
२८)	२९०	२१ १२	५८)	५९०	४४ ४
२९)	३००	२२ ८	५९)	६००	४५ ०
३०)	३१०	२३ ४	६०)	६१०	४५ १२
३१०	३२)	२४ ०	६१)	६२०	४६ ८
३२०	३३)	२४ १२	६२)	६३०	४७ ४
३३)	३४)	२५ ८	६३)	६४०	४८ ०
३४)	३५०	२६ ४	६४)	६५०	४८ १२
३५०	३६)	२७ ०	६५)	६६०	४९ ८
३६)	३७)	२७ १२	६६)	६७०	५० ४
३७)	३८)	२८ ८	६७)	६८०	५१ ०
३८०	३९)	२९ ४	६८)	६९०	५१ १२
३९०	४०)	३० ०	६९)	७००	५२ ८
४०)	४१०	३० १२	७०)	७१०	५३ ४
४१०	४२०	३१ ८	७१०	७२०	५४ ०
४२)	४३)	३२ ४	७२)	७३०	५४ १२
४३)	४४)	३३ ०	७३)	७४०	५५ ८
४४)	४५)	३३ १२	७४)	७५०	५६ ४
४५)	४६)	३४ ८	७५)	७६०	५७ ०
४६)	४७)	३५ ४	७६)	७७०	५७ १२
४७)	४८०	३६ ०	७७०	७८)	५८ ८
४८)	४९)	३६ १२	७८)	७९०	५९ ४
४९)	५००	३७ ८	७९)	८०	६० ०
५०)	५१०	३८ ४	८०)	८१)	६० १२
५१०	५२)	३९ ०	८१०	८२)	६१ ८
५२)	५३)	३९ १२	८२)	८३)	६२ ४
५३०	५४)	४० ८	८३)	८४)	६३ ०
			८४)	८५)	६३ १२

जब कि
तादाद या
कीमत ना-
लिश इससे
ज्यादा हो

लेकिन इस
से ज्यादा
न हो

कोर्ट फीस
लगेगी

जब कि
तादाद या
कीमत ना-
लिश इससे
ज्यादा हो

लेकिन इस
से ज्यादा
न हो

कोर्ट फीस
लगेगी

रु०	रु०	रु० आ०
८५०	८६०	६४ ८
८६०	८७०	६५ ४
८७०	८८०	६६ ०
८८०	८९०	६६ १२
८९०	९००	६७ ८
९००	९१०	६८ ४
९१०	९२०	६९ ०
९२०	९३०	६९ १२
९३०	९४०	७० ८
९४०	९५०	७१ ४
९५०	९६०	७२ ०
९६०	९७०	७२ १२
९७०	९८०	७३ ८
९८०	९९०	७४ ४
९९०	१,०००	७५ ०
१,०००	१,१००	८० ०
१,१००	१,२००	८५ ०
१,२००	१,३००	९० ०
१,३००	१,४००	९५ ०
१,४००	१,५००	१०० ०
१,५००	१,६००	१०५ ०
१,६००	१,७००	११० ०
१,७००	१,८००	११५ ०
१,८००	१,९००	१२० ०
१,९००	२,०००	१२५ ०
२,०००	२,१००	१३० ०
२,१००	२,२००	१३५ ०
२,२००	२,३००	१४० ०
२,३००	२,४००	१४५ ०
२,४००	२,५००	१५० ०
२,५००	२,६००	१५५ ०

रु०	रु०	रु० आ०
२,६००	२,७००	१६० ०
२,७००	२,८००	१६५ ०
२,८००	२,९००	१७० ०
२,९००	३,०००	१७५ ०
३,०००	३,१००	१८० ०
३,१००	३,२००	१८५ ०
३,२००	३,३००	१९० ०
३,३००	३,४००	१९५ ०
३,४००	३,५००	२०० ०
३,५००	३,६००	२०५ ०
३,६००	३,७००	२१० ०
३,७००	३,८००	२१५ ०
३,८००	३,९००	२२० ०
३,९००	४,०००	२२५ ०
४,०००	४,१००	२३० ०
४,१००	४,२००	२३५ ०
४,२००	४,३००	२४० ०
४,३००	४,४००	२४५ ०
४,४००	४,५००	२५० ०
४,५००	४,६००	२५५ ०
४,६००	४,७००	२६० ०
४,७००	४,८००	२६५ ०
४,८००	४,९००	२७० ०
४,९००	५,०००	२७५ ०
५,०००	५,२५०	२८५ ०
५,२५०	५,५००	२९५ ०
५,५००	५,७५०	३०५ ०
५,७५०	६,०००	३१५ ०
६,०००	६,२५०	३२५ ०
६,२५०	६,५००	३३५ ०
६,५००	६,७५०	३४५ ०

जब कि तादाद या कीमत ना- लिख इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगी	जब कि तादाद या कीमत ना- लिख इससे ज्यादा हो	लेकिन इस से ज्यादा न हो	कोर्ट फीस लगेगी
रु०	रु०	रु० आ०	रु०	रु०	रु० आ०
६,७५०	७,०००	३५५ ०	१८,५००	१९,०००	७४५ ०
७,०००	७,२५०	३६५ ०	१९,०००	१९,५००	७६० ०
७,२५०	७,५००	३७५ ०	१९,५००	२०,०००	७७५ ०
७,५००	७,७५०	३८५ ०	२०,०००	२१,०००	७९५ ०
७,७५०	८,०००	३९५ ०	२१,०००	२२,०००	८१५ ०
८,०००	८,२५०	४०५ ०	२२,०००	२३,०००	८३५ ०
८,२५०	८,५००	४१५ ०	२३,०००	२४,०००	८५५ ०
८,५००	८,७५०	४२५ ०	२४,०००	२५,०००	८७५ ०
८,७५०	९,०००	४३५ ०	२५,०००	२६,०००	८९५ ०
९,०००	९,२५०	४४५ ०	२६,०००	२७,०००	९१५ ०
९,२५०	९,५००	४५५ ०	२७,०००	२८,०००	९३५ ०
९,५००	९,७५०	४६५ ०	२८,०००	२९,०००	९५५ ०
९,७५०	१०,०००	४७५ ०	२९,०००	३०,०००	९७५ ०
१०,०००	१०,५००	४९० ०	३०,०००	३२,०००	९९५ ०
१०,५००	११,०००	५०५ ०	३२,०००	३४,०००	१,०१५ ०
११,०००	११,५००	५२० ०	३४,०००	३६,०००	१,०३५ ०
११,५००	१२,०००	५३५ ०	३६,०००	३८,०००	१,०५५ ०
१२,०००	१२,५००	५५० ०	३८,०००	४०,०००	१,०७५ ०
१२,५००	१३,०००	५६५ ०	४०,०००	४२,०००	१,०९५ ०
१३,०००	१३,५००	५८० ०	४२,०००	४४,०००	१,११५ ०
१३,५००	१४,०००	५९५ ०	४४,०००	४६,०००	१,१३५ ०
१४,०००	१४,५००	६१० ०	४६,०००	४८,०००	१,१५५ ०
१४,५००	१५,०००	६२५ ०	४८,०००	५०,०००	१,१७५ ०
१५,०००	१५,५००	६४० ०	५०,०००	५५,०००	१,२०० ०
१५,५००	१६,०००	६५५ ०	५५,०००	६०,०००	१,२२५ ०
१६,०००	१६,५००	६७० ०	६०,०००	६५,०००	१,२५० ०
१६,५००	१७,०००	६८५ ०	६५,०००	७०,०००	१,२७५ ०
१७,०००	१७,५००	७०० ०	७०,०००	७५,०००	१,३०० ०
१७,५००	१८,०००	७१५ ०	७५,०००	८०,०००	१,३२५ ०
१८,०००	१८,५००	७३० ०	८०,०००	८५,०००	१,३५० ०
			८५,०००	९०,०००	१,३७५ ०

जब कि
तादाद या
कीमत ना-
लिश इससे
ज्यादा हो

लेकिन इस
से ज्यादा
न हो

कोर्ट फीस
लगेगी

जब कि
तादाद या
कीमत ना-
लिश इससे
ज्यादा हो

लेकिन इस
से ज्यादा
न हो

कोर्ट फीस
लगेगी

रु०	रु०	रु० आ०
९०,०००	९५,०००	१,४०० ०
९५,०००	१,००,०००	१,४२५ ०
१,००,०००	१,०५,०००	१,४५० ०
१,०५,०००	१,१०,०००	१,४७५ ०
१,१०,०००	१,१५,०००	१,५०० ०
१,१५,०००	१,२०,०००	१,५२५ ०
१,२०,०००	१,२५,०००	१,५५० ०
१,२५,०००	१,३०,०००	१,५७५ ०
१,३०,०००	१,३५,०००	१,६०० ०
१,३५,०००	१,४०,०००	१,६२५ ०
१,४०,०००	१,४५,०००	१,६५० ०
१,४५,०००	१,५०,०००	१,६७५ ०
१,५०,०००	१,५५,०००	१,७०० ०
१,५५,०००	१,६०,०००	१,७२५ ०
१,६०,०००	१,६५,०००	१,७५० ०
१,६५,०००	१,७०,०००	१,७७५ ०
१,७०,०००	१,७५,०००	१,८०० ०
१,७५,०००	१,८०,०००	१,८२५ ०
१,८०,०००	१,८५,०००	१,८५० ०
१,८५,०००	१,९०,०००	१,८७५ ०
१,९०,०००	१,९५,०००	१,९०० ०
१,९५,०००	२,००,०००	१,९२५ ०
२,००,०००	२,०५,०००	१,९५० ०
२,०५,०००	२,१०,०००	१,९७५ ०
२,१०,०००	२,१५,०००	२,००० ०
२,१५,०००	२,२०,०००	२,०२५ ०
२,२०,०००	२,२५,०००	२,०५० ०
२,२५,०००	२,३०,०००	२,०७५ ०
२,३०,०००	२,३५,०००	२,१०० ०
२,३५,०००	२,४०,०००	२,१२५ ०
२,४०,०००	२,४५,०००	२,१५० ०
२,४५,०००	२,५०,०००	२,१७५ ०
२,५०,०००	२,५५,०००	२,२०० ०

रु०	रु०	रु० आ०
२,५५,०००	२,६०,०००	२,२२५ ०
२,६०,०००	२,६५,०००	२,२५० ०
२,६५,०००	२,७०,०००	२,२७५ ०
२,७०,०००	२,७५,०००	२,३०० ०
२,७५,०००	२,८०,०००	२,३२५ ०
२,८०,०००	२,८५,०००	२,३५० ०
२,८५,०००	२,९०,०००	२,३७५ ०
२,९०,०००	२,९५,०००	२,४०० ०
२,९५,०००	३,००,०००	२,४२५ ०
३,००,०००	३,०५,०००	२,४५० ०
३,०५,०००	३,१०,०००	२,४७५ ०
३,१०,०००	३,१५,०००	२,५०० ०
३,१५,०००	३,२०,०००	२,५२५ ०
३,२०,०००	३,२५,०००	२,५५० ०
३,२५,०००	३,३०,०००	२,५७५ ०
३,३०,०००	३,३५,०००	२,६०० ०
३,३५,०००	३,४०,०००	२,६२५ ०
३,४०,०००	३,४५,०००	२,६५० ०
३,४५,०००	३,५०,०००	२,६७५ ०
३,५०,०००	३,५५,०००	२,७०० ०
३,५५,०००	३,६०,०००	२,७२५ ०
३,६०,०००	३,६५,०००	२,७५० ०
३,६५,०००	३,७०,०००	२,७७५ ०
३,७०,०००	३,७५,०००	२,८०० ०
३,७५,०००	३,८०,०००	२,८२५ ०
३,८०,०००	३,८५,०००	२,८५० ०
३,८५,०००	३,९०,०००	२,८७५ ०
३,९०,०००	३,९५,०००	२,९०० ०
३,९५,०००	४,००,०००	२,९२५ ०
४,००,०००	४,०५,०००	२,९५० ०
४,०५,०००	४,१०,०००	२,९७५ ०
४,१०,०००		३,००० ०

इन्दुलतलब रुक्का

मैं कि.....उमर अन्दाज़न.....वर्ष वल्द.....कौम.....पेशा.....साकिनहाल
.....का हूँ ।

विदित रहे कि मैंने मुबलिग.....अंकन.....जिसके आधे अंकन... हांते हैं,
सिक्का अङ्ग्रेजी चलन बाज़ार अपनी ज़रूरतके लिये श्रीमान...वल्द...कौम.....
साकिनहाल...से नक़द कर्ज़ लिये। इस रुपयेको.....रुपया सैकड़ा माहवारी सूद
सहित उपरोक्त श्रीमानजीको याजिसे वे इसरुक्काका रुपया लेनेका अधिकार दे देंगे,
उसे इन्दुलतलब अर्थात् माँगने पर बिना कोई हीला व हवाला किये अदा व
बेबाक़ कर दूंगा। और जो रुपया मैं इस रुक्काके बारेमें असल या सूदमें अदा
करूंगा उसकी रसीद बाज़ान्ता बराबर ले लिया करूंगा। मैंने इस रुक्केका कुल
मतालिबा नक़द उपरोक्त श्रीमानजीसे वसूल पालिया। अब मेरा कोई रुपया बाबत
मतालिबा या उसके किसी हिस्सेमें बाकी नहीं रहा इस लिये यह रुक्का खूब समझ
बूझकर होस व हवासमें बाज़ान्ता बतरीक़ इन्दुलतलब टिकट लगा कर लिख
दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे ।

दस्तख़त लिखनेवाला ।

दस्तख़त —————

मकान खाली करापानेका नोटिस

नोट—यह ध्यान रहे कि ऐसा नोटिस, नोटिस पाने वालेके पास कमसे
कम १५ दिन पहिले पहुँच जाना ज़रूरी है अर्थात् नोटिस जिसे दिया गया हो
और जिस तारीख़को उसे मिला हो उसके बाद १५ दिनकी मियाद उसका महीना
ख़तम होनेमें हो ।

नोटिस मिन्जानिब.....वल्द.....साकिन.....मारफ़त.....साकिन.....
बनाम

.....वल्द.....साकिन.....वाजै हैं कि आप मकान नम्बरी.....वाक़ै.....के
.....रुपये माहवारके किरायेदार हैं। आपका किराया तारीख़.....से ता०...
तक महाना पूरा होता है। आपको अब मकानमें किराये पर रखना बहुत सी
बातोंके सबबसे मंजूर नहीं है इसलिये आपको यह नोटिस दिया जाता है कि
आप ता०.....तक मकानमें रहकर मकान खाली कर दें और कुल किराया उस
वक्त तकका जो आपके जिम्मे बाकी हो अदा कर दें। ऐसा न करने पर आप
पर नालिश अदालत मजाममें की जावेगी और आप खर्चके देनेके जिम्मेदार होंगे ।

द०: —————

ता० —————

संयुक्त प्रान्तकी दीवानी अदालतोंमें नकल और तलबाना
आदिमें लगनेवाली फीसों ।

सिविल जनरलरूल्स ता० ३१ जनवरी सन १९२७ई०
तक संशोधित

नकलोंकी फीसों

कागज़की किस्म जिसकी नकल लेना है	हाईकोर्टमें		जज खफीफाकी अदालतमें		अन्य सब अदालतोंमें	
	जरूरी	मामूली	जरूरी	मामूली	जरूरी	मामूली
डिकरी	३)	१॥)	१॥)	॥॥)	२॥)	१)
तलबीज़ या अन्य कागज़	४)	२)	१॥)	॥॥)	२॥)	१)

तलवाना आदिको फीसें

किरम फीस	भदालत जजी और सब जजी	मुत्सफी व खुफीफा जब कि २०००) रु० से मालियत जयादा न हो	मुत्सफी व खुफीफा जब कि मालियत ५०) रु० से जयादा न हो	हार्दिकोट
१ तलवाना सुद्दाअलेह	चार तक २॥) जायद फी सुद्दाअलेह ॥२) मज-मूर्ह १२॥)	चार तक १॥) जायद फी सुद्दाअलेह ॥२) मजमूर्ह ६॥)	दो तक ॥२) जायद फी सुद्दाअलेह ॥३) मजमूर्ह ४॥)	चार तक ३) जायद फी सुद्दाअलेह ॥) मजमूर्ह १५॥
२ तलवाना गवाहान	चार तक २॥) जायद फी गवाह ॥२)	चार तक १॥) जायद फी गवाह ॥२)	फी गवाह ॥२)	चार गवाह तक ३) जायद फी गवाह ॥) मजमूर्ह ४॥
३ हुक्म कुर्को	१॥)	१॥)	॥२)	+
४ फीस कुर्को	एक मौजा के लिये २) जायद फी मौजा २) मजमूर्ह १५॥)	एक मौजा के लिये ४) जायद फी मौजा १) मजमूर्ह ७॥)	एक मौजा के लिये २) जायद फी मौजा ॥) मजमूर्ह ३॥)	+
५ वारण्ट गिरफ्तारी	३॥॥) फी मदयून । जब मदयून हिरासतमें हो तो ॥२) फी चपरारसी	२॥) फी मदयून	१॥) फी मदयून	५) फी मदयून
६ नोलासके सम्बन्धमें	६॥) फी सदी	६॥) फी सदी	६॥) फी सदी	+
७ हुक्म नोलास	१॥)	१॥)	॥२)	+
८ दखलकी फीस	जैसा कि नं० ४ की फीस है	जैसा कि नं० ४ की फीस है	जैसा कि नं० ४ की फीस है	+
९ तलवाना इस्तहार	जैसा कि नं० १ की फीस है	जैसा कि नं० १ की फीस है	जैसा कि नं० १ की फीस है	+
१० तलवाना जरूरी	१॥)	१॥)	॥२)	+

दस्तावेजों पर स्टाम्प

इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट नं० २ सन् १८६६ ई०

के अनुसार छपनेके समय तकके

संशोधनों सहित

आवश्यक दस्तावेजोंका सारांश

स्टाम्प

१ कर्ज स्वीकार करने वाला दस्तावेज

एक आना

जब रकम बीस रुपयेसे अधिक हो, लिखा गया हो या सही किया गया हो, या किसी दूसरेकी ओरसे हो या कर्जदार द्वारा इस प्रकारके कर्जकी शहादतके लिये किसी किताबमें (जो बैंकर्स पास बुक्के अतिरिक्त हो) या किसी अलाहिदा कागज पर जब इस प्रकार का कागज या किताब महाजनके अधिकारमें रहनी हो, नियम यह है कि इस प्रकारकी स्वीकृतिमें कर्ज अदा करनेकी किसी प्रकारकी प्रतिज्ञा, या सूद अदा करनेकी कोई शर्त, या कोई माल या अन्य जायदाद देनेकी बात न हो।

नोट—इन्दुलतलब रुकाके लिये देखो नं० ४९

२ एहतमाम तर्कह (Administration Bond) इसमें इण्डियन सक्सेशन ऐक्ट १८६५ की दफा २५६ के अनुसार बाण्ड गवर्नमेण्ट सेविंग बैंक्स ऐक्ट १८७३ की दफा ६ के अनुसार बाण्ड, प्रोवेड और एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट १८८१ की दफा ७८ के अनुसार बाण्ड और सक्सेशन सर्टिफिकेट ऐक्ट १८८९ की दफा ९ या १० के अनुसार बाण्ड शामिल हैं।

(ए) जब कि रकम १०००) से अधिक न हो

वही स्टाम्पजो

बाण्ड नं० १५

में इसी रकम

पर लगता है।

पांच रुपये

(बी) किस अन्य सूरतमें

३ दत्तक पत्र (Adoption deed) यानी कोई दस्तावेज (वसीयतनामेके अतिरिक्त) जो गोदके सम्बन्धमें लिखा गया हो या जिसके द्वारा गोद लेनेका अधिकार दिया गया है या अधिकार देनेकी इच्छा प्रगट की गई हो।

एक रुपया

४ हलफनामा

जिसमें कि ऐसे व्यक्तियोंकी स्वीकृति या घोषणा भी शामिल हैं जो कानून द्वारा बनाय हुलफ लेनेके रवीकार करने या घोषणा करनेके अधिकारी हैं।

अपवाद

जब तहरीरी हलफनामा या घोषणापत्र लिखा गया हो—

(ए) इण्डियन आर्टिकिल्स आफ चारके अनुसार बतौर भती के शर्तके

(बी) फौरन ही फायल करनेके निमित्त या किसी अदालतमें इस्तेमाल किये जानेके निमित्त या किसी अदालतके सामने पेश किये जानेके लिये या

(सी) किसी आदमीको किसी पेंशन या खैराती पलाउन्सके पानेके अभिप्रायके लिये।

५ इकरारनामा या याददाश्त इकरारनामा

(ए) यदि हुण्डीकी बिक्रीका वर्णन हो

दो आना

(बी) यदि गवर्नमेण्ट सेक्यूरिटी या किसी इनकार पोरेटेड सेक्यूरिटीया कम्पनी या अन्य कारपोरेट संस्थाके हिस्सोंकी बिक्रीका वर्णन हो हिस्सेके प्रत्येक १००००)या उसके अंशोंपर एक आना, और आधेसे अधिक दस रुपये।

(सी) जिनके लिये कोई अन्य नियम न हो

आठ आना।

अपवाद

इकरारनामा या याददाश्त इकरारनामा

(ए) केवल माल या तिजारती सामानकी बिक्रीके लिये या उसके वर्णनके सम्बन्धमें, किंतु ऐसे रुक्के या याददाश्त न हों, जिनपर आर्टिकिल ४३ के अनुसार स्टाम्प लगना चाहिये।

(बी) गवर्नमेण्ट आफ इण्डियाके पास टेण्डरकी सूरतमें किसी कर्जके लिये या उसके सम्बन्धमें पेश किये गये हों

(सी) यूरोपियन वैगुँसी ऐक्ट १८७४ की दफा १७ के अनुसार लिखे हुए।

अधिकार पत्र (Titled deed) के जमा करने या गिरवी रखनेके सम्बन्धमें इकरारनामा।

(ए) यदि वह रकम तलब करने पर या दस्तावेज़ के तीन माह वहीस्टाम्पजो के बाद अदा की जानी हो

हुंडी के सम्बंध में

(नं० १३बी)

में है प्राप्त की

हुई रकम पर

(बी) यदि वह रकम दस्तावेज़ के तीन माह के अन्दर अदा की उस रकम का जानी हो ।

आधा जो हुंडी

(नं० १३बी)

में है प्राप्त की

हुई रकम पर

७ किसी अधिकार की तामील पर नियुक्ति चाहे ट्रस्टीज़ की हो या १५ रुपये स्थावर या जड़म जायदाद की, जब तहरीर द्वारा, जो वसीयतनामा न हो, की गई हो ।

८ तख्मीना कीमत की कृत

किसी मुकदमे के दौरान में किसी अदालत के हुक्म के अतिरिक्त

(ए) जब रकम १००० से अधिक न हो

वही स्टाम्प जो

वाण्ड (नं० १५)

में इस रकम के

लिये नियत हैं ।

(बी) अन्य सूरत में

पांच रुपये

अपवाद

(ए) जब तख्मीना केवल एक फरीक के लिये किया गया हो, और फरीकों के लिये उसके मानने की किसी प्रकार विवशता न हो

(बी) फलका अन्दाज जमींदार को लगान देने के निमित्त

९ दस्तावेज़ उम्मीदवारी

पांच रुपये

१० आर्टिकिल आफ एशोशियेशन आफ ए कम्पनी

पच्चीस रुपये

११ आर्टिकिल आफ क्लर्कशिप

दो सौ पचास

रुपया

१२ फैसला सालिशो

(ए) जब रकम १००० से अधिक न हो

वही स्टाम्प जो

वाण्ड (नं० १५)

इस रकम के लिये

नियत हैं ।

(बी) अन्य सूरत में

पांच रुपये

अपवाद

बम्बई डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल ऐक्ट १८७३ की दफा ८१ के अनुसार फैसला सालिशी या बम्बई हियर डिस्ट्री आफिस ऐक्ट १८७४ की दफा १८ के अनुसार फैसला सालिशी ।

१३ हुण्डी (Bill of exchange) [जिस प्रकार दफा २ (२) और (३) में बताई गई है) जो कि बान्ड, बैंक नोट या करेंसी नोट न हो

(ए) जब तलब किये जानेपर इन्दुल तलब (On demand) एक आना अदाकी जानेको हो

(बी) जब तलबी पर अदाई यदि अकेली यदि दो सेटोंमें यदि तीन सेटोंमें
(यानी आनडेमाण्ड) से अन्य हो, लिखी गई हो लिखी गई हो लिखी गई हो
किंतु तारीख या मिलनेसे एक साल तो सेटके प्रत्येक तो सेटके प्रत्येक
से अधिक की न हो भागके लिये भागके लिये

	रु०	रु०	रु०
जब हुण्डी या नोटकी रकम अधिक नहो २००)से ३)	=)	=)	-)
जब वह रु० २००)से अधिकहो किंतु अधिकनहो ४००)से १=)	३)	३)	=)
„ ४००) ६००)से ॥-)	१-)	३)	३)
„ ६००) „ ८००)से ॥॥)	१=)	॥	॥
„ ८००) „ १०००)से ॥॥३)	॥)	१-)	१-)
„ १०००) „ १२००)से १=)	॥-)	१=)	१=)
„ १२००) „ १६००)से १॥)	॥॥)	॥)	॥)
„ १६००) „ २५००)से २१)	१=)	॥॥)	॥॥)
„ २५००) „ ५०००)से ४॥)	२१)	१॥)	१॥)
„ ५०००) „ ७५००)से ६॥॥)	३=)	२१)	२१)
„ ७५००) „ १००००)से ९)	४॥)	३)	३)
„ १००००) „ १५०००)से १३॥)	६॥॥)	४॥)	४॥)
„ १५०००) „ २००००)से १८)	९)	६)	६)
„ २००००) „ २५०००)से २२॥)	१११)	७॥)	७॥)
„ २५०००) „ ३००००)से २७)	१३॥)	९)	९)
३००००) के ऊपर हर १००००) या उसके			
किसी भाग पर ९)	४॥)	३)	

(सी) जब तारीख या मिलनेके एक साल बाद अदाकरनाहो वही स्थापजो बाण्ड (नं० १५ में उसरकमपर लगता है ।

१४ जहाजके मालकी बिल्टी

चार आना

१५ दस्तावेज़ (Bond) तमस्तुक

जब रकम जो ली गई है (१०) से अधिक न हो
जब वह (१०) से अधिक हो किन्तु अधिक न हो

" ५०)	"	५०) से	दो आना
" १००)	"	१००) से	चार आना
" २००)	"	२००) से	आठ आना
" ३००)	"	३००) से	एक रुपया
" ४००)	"	४००) से	१६० आ०
" ५००)	"	५००) से	दो रुपये
" ६००)	"	६००) से	२६० आ०
" ७००)	"	७००) से	तीन रुपये
" ८००)	"	८००) से	३६० आ०
" ९००)	"	९००) से	चार रुपये
" १०००)	"	१०००) से	४६० आ०
" १०००)	"	१०००)	पांच रुपये

१०००) रुपये के ऊपर प्रत्येक ५००) रुपये या उसके किसी भागके लिये, २६० आ० आने

देखो—इकरारनामा एहतमाम तरका (Administration Bond)
(नं० २), बाटमरी बाण्ड (नं० १६), कस्टम बाण्ड (नं० २६) इण्डेमेन्टी
बाण्ड (नं० ३४) रेस्पण्डेण्टिया बाण्ड (नं० ५६) जमानतनामा (नं० ५७)
सेक्यूरिटी बाण्ड ।

अपवाद

दस्तावेज़ जब कि लिखा गया हो

(ए) मुखिया द्वारा, जो कि बंगाल एरीगेशन ऐक्ट १८७६ की दफा ९९
के अनुसार मुखिया के उचित कर्तव्यों के पूर्ण करने के लिये नियत किया हो ।

(बी) किसी व्यक्ति द्वारा, बगरज़ गारण्टी इस कार्य के कि स्थानीय आमदनी
जो कि प्राइवेट चन्दे द्वारा, किसी धर्मार्थ दवाखाने या अस्पताल या सार्वजनिक
लाभ के किसी अन्य तारपथ के लिये हो, वर्णित रकम से प्रति मास कम न होगी ।

१६ बोटोमरी बाण्ड

वही स्थान जो
बाण्ड नं० १५
में नियत है

१७ दस्तावेज़ इबताल (Cancellation) जिनके द्वारा पहिले, पांच रुपये
के दस्तावेज़ बातिल किये जाय ।

और भी देखो दस्तावेज़ दस्तबरदारी (नं० ५५) (Release)
रेवोकेशन आफ़ सेटेलमेण्ट (नं० ५८ बी) और वापसी पट्टा (नं० ६१)
और रेवोकेशन आफ़ ट्रस्ट (नं० ६४ बी)

१८ सार्टीफ़िकेट आफ़ सेल—(हर चीज़ के लिये जो अलाहिदा
गोलाम की गई है) जो किसी ऐसी जायदाद के ख़रीददारको, जो

किसी दीवानी या मालकी अदालत या कलेक्टर या अन्य मालके हाकिमके हुकमसे, आम नीलाममें बेची गई हो, स्वीकृत की गई हो ।

(ए) जब कीमत खरीद १०० से अधिक न हो

दो आना

(बी) जब कीमत खरीद १० से अधिक हो किन्तु २५)

चार आना

से अधिक न हो

(सी) अन्य सूक्तोंमें

नं० २३ के अनुसार

१९ सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज किसी कम्पनी या कारपोरेट संस्थाके हिस्से आदिके सम्बन्धमें

एक आना

२० चार्टर पार्टी—जहाज़ या उसका कोई हिस्सा किराये पर देना ।

एक रुपया

२१ चेक [जैसा दफा २ (७) में बयान किया गया है]

एक रुपया

२२ काम्पोजीशन डीड-यानी कोई दस्तावेज जो कर्जदार द्वारा लिखा जाय, जिसके द्वारा वह अपनी जायदादको महाजनके लाभके लिये मुन्तकिल करे या जिसके द्वारा कर्ज पर काम्पोजीशन था डिवी-डेण्टकी अदाई महाजनके लिये सुरक्षित करे, या जिसके द्वारा कर्जदारके व्यवसायके आरम्भ रहनेकी, इन्स्पेक्शनोंके प्रबन्धके मातहत या महाजनके फायदेके लिये लायसेन्सके पत्रके अनुसार व्यवस्थाकी गई हो ।

दस रुपये

२३ बयनामा—(दफा २ (१०) की परिभाषाके अनुसार) जो वह इन्तकालनामा न हो, जिस पर (नं० ६२) के अनुसार महसूल लगाया जाता हो या माफ़ कर दिया गया हो ।

जब रकम बयनामा ५० रु० से अधिक न हो ।

आठ आना

जब वह रु० ५० से अधिक हो किन्तु अधिक न हो रु० १००)से

एक रुपया

१००	"	"	२००	दो रुपये
२००	"	"	३००	तीन रुपये
३००	"	"	४००	चार रुपये
४००	"	"	५००	पांच रुपये
५००	"	"	६००	छः रुपये
६००	"	"	७००	सात रुपये
७००	"	"	८००	आठ रुपये
८००	"	"	९००	नौ रुपये
९००	"	"	१०००	दस रुपये

१०००) के ऊपर प्रत्येक ५००) रुपये या उसके किसी भाग पर ।

पांच रुपये

अपवाद

कापी राइटका इन्तकाल, जो कि भारतीय कापी राइट ऐक्ट १८४७ की दफा ५ के अनुसार दाखिले द्वारा किया जाय ।

को-पारटेनरशिप डीड-देखो पारटेनरशिप नं० ४६ ।

२४ नकल या उद्धरण किसी कागज़का, जिस पर किसी सरकारी पदाधिकारीके हुक्मके अनुसार या उसके हाथसे उस नकल या उद्धरणका सही होना तस्दीक किया गया हो और जिसके सम्बन्धमें प्रचलित कानूनके अनुसार कोर्टफीस वाज़िबुल अदा न हो ।

(१) यदि असल दस्तावेज़ महसूल लगाये जानेके काबिल न हो या वह महसूल जो इस पर लगाया जानेको हो, एक रुपयेसे अधिक न हो ।

आठ आना

(२) अन्य सूत्रतमें

एक रुपया

अपवाद

(ए) किसी कागज़की नकल, जिसके बनाने या सरकारी दफ्तरमें रखने या किसी अन्य सरकारी कार्यके लिये रखनेका हुक्म हो ।

(बी) नकल या उद्धरण, किसी रजिस्टरकी, जो पैदायश या वैपत्तिस्मा या नाम या समर्पण, या शादी [त्याग, मौत, और अन्तिम संस्कार] सम्बन्धी हो ।

२५ सुसन्ना या डुप्लीकेट ।

(ए) यदि महसूल एक रुपयेसे अधिक न हो ।

वही महसूल —

—जो असलीपर देना हो

एक रुपया

(बी) अन्य सूत्रतमें

अपवाद

किसी पट्टेका सुसन्ना जब (ए) वह किसी काश्तकारको दिया गया हो और वह पट्टा महसूलसे बरी हो ।

२६ कस्टम बाण्ड (इक़रारनामा चुंगी)

बाण्ड नं० १५ के अनुसार

(ए) जब रकम १००० से अधिक न हो ।

पांच रुपये

(बी) अन्य सूत्रतमें

२७ डेबेञ्चर (चाहे रेहननामेका डेबेञ्चर हो या न हो) जो एक किफ़ालतनामा काबिल ख़रीद व फ़रोख़्तके हो, और जिसका इन्तक़ाल—

(ए) दस्तख़तों या इन्तक़ालके अलाहिदा दस्तावेज़ द्वारा होख़के

नं० १५ के

बाण्डके अनुसार

नं० २२ के

बाण्डके अनुसार

(बी) बज़रिये हवालग़ी हो सके

व्याख्या—शब्द 'डेबेञ्चर' में सूदका प्रत्येक कूपन जो उसके साथ लगा हो शामिल है; किन्तु इन कूपनोंको रकम महसूलके तख़्मीना करनेमें शुमार न किया जायगा ।

अपवाद

कोई ऐसा डेबेन्चर, जो किसी कम्पनी या सनद प्राप्त संस्थाकी ओरसे बतौर एक रजिस्ट्रीनुदा रेहननामेके जारी किया जाय और बशर्ते कि उनपर उन डेबेन्चरोंकी पूरी ताददके बावत, जो उसकी रूसे जारी किये जाय, स्टाम्प लगा हो, तो उसकी बिनापर कम्पनी या उक्त संस्था जो कर्ज लेना चाहती हो, अपनी जायदाद डेबेन्चर के अधिकारियों के लाभके लिये समस्त या उसका कुछ अंश ट्रस्टियोंके हवाले करदे। किन्तु यह नियम है कि जो डेबेन्चर इस प्रकार जारी किये जाय, उनका बतौर रेहननामा मजकूरके जारी होना पाया जाता हो।

और भी देखो बाण्ड (नं० १५) और दफायें ८ और ५५ डेक्लेरेशन आफ एनी ट्रस्ट—देखो ट्रस्ट नं० ६४

२८ माल सम्बन्धी डेलेवरी आर्डर, जब मालकी कीमत २०)से एक आना अधिक हो

डेपाजिट आफ टाइटिल डीड्स (देखो नं० ६) हिस्सेदारीकी अलाहिदगी—(देखो नं० ४६)

२६ त्याग या तलाक, यानी वह दस्तावेज जिसके द्वारा कोई व्यक्ति एक रुपया अपनी शादीका सम्बन्ध तोड़ता है

३० किसी हाईकोर्टके रोलमें, किसी एडवोकेट, वकील या एटार्नी का दाखिला

(ए) एडवोकेट या वकीलकी सूरतमें

५००)रुपये

(बी) एटार्नीकी सूरतमें

२५०)रुपये

अपवाद

किसी एडवोकेट, वकील या एटार्नीका हाईकोर्टके रोलमें दाखिला, जब वह हाईकोर्टके रोलमें पहिले दाखिल किया जा चुका हो।

३१ तबादिला जायदाद (Exchange of Property) वही महसू—

—जो बयनामा (नं० २३ में) नियत है। जिसकी रकम मवाजा जया-दादकी मालियतके बराबर हो, जो हस्त तफसील दस्तावेज मजकूर सबसे ब्यादा मालियतका हो

३२ दस्तावेज मावजा मजीद (Further change) यानी वह दस्ता-वेज जो रेहननामेकी जायदाद पर और अधिक मावजा कायम करे

(ए) जब असली रेहननामा उस किस्ममेंसे हो, जिसका वर्णन आर्टि- वहां महसूल किल के कलाज (ए) में आया है (यानी मय कब्जा) जो बयनामा—

—(नं० २३) में है उस रकमपर जो उस दस्तावेज द्वारा लगाये हुए अधिक मावजे के बराबर हो

(बी) जब ऐसा रेहननामा उस किस्ममेंसे हो जिसका वर्णन आर्टिक्ल ४० के कलाज (बी) में है (यानी बिला कब्जा)

१ यदि अधिक मावजेके दस्तावेजके तामीलके समय, जायदादका वही महसूल कब्जा दे दिया गया है, या उस दस्तावेजके अनुसार कब्जा देनेका जो बयनामा मुआहिदा कर लिया गया है।

(नं० २३) में है—

—उस रकमपर जो उस कुल रकमके बराबर हो (रेहनकी रकम और अधिक मावजे के सहित) उस महसूलको निकालकर जो असल रेहन और अधिक मावजे पर पहिले चुका दिया गया हो

२ यदि उस प्रकार कब्जा न दिया गया हो

वही महसूल—

— जो बाण्ड नं० १५में नियत है उस रकमपर जो उस दस्तावेज द्वारा बतौर अधिक मावजे केलिया गया हो

३३ हिबःनामा अर्थात् दानपत्र—जो सेटेलमेण्ट (नं० ६८) या वसीयतनाम या इन्तकाल (नं० ६२) के अतिरिक्त हो महसूल बयनामा (नं० २३) के अनुसार—
उस रकम मावजे पर जो दास्तावेजमें वर्णित जायदादकी कीमतके बराबर हो

३४ इबरायतनामा अर्थात् हरजाना लुकसान दिलाया जाना वही महसूल जो—
(Indemnity Bond) —जमानतनामा (नं० ५७) में उस रकम पर नियत है ।

३५ पट्टा—जिसमें कोई पट्टा ज़िम्मेदारों या कोई पट्टा शिकमी या कोई इक़रार तहरीर पट्टा या पट्टा शिकमी दाखिल है ।

(ए) जब इस पट्टे द्वारा रकम लगान नियत हो जाय, किन्तु कोई नज़राना अदा या हवाला न किया जाय ।

(१) जब पट्टेके मज़मूनसे एक सालसे कम मियादके लिये वही महसूल—
पाया जाय । —जो बाण्ड (नं० १५) में है उस तमाम रकमपर जो इस पट्टेके अनुसार वाजिबुलअदा या हवालगीके है

(२) जब पट्टेके मज़मूनमें यह पाया जाये कि वह एक बरससे वही महसूल अधिक किन्तु तीन बरससे अधिक नहीं है —जो बाण्ड (नं० १५) में नियत है उस रकम पर जो सालाना औसत लगानके बराबर हो ।

(३) जब पट्टेसे यह विदित होकि वह तीनसालसे अधिक मियाद वही महसूल—
केलिये है । —जो इन्तकाल (नं० २३) में नियत है, उस रकम पर जो निश्चित लगान के सालाना औसत लगानके बराबर हो ।

(४) जब पट्टेसे यह विदित हो कि वह किसी निश्चित मियादके वही महसूल—
लिये नहीं है । —जो इन्तकाल (नं० २३) में नियत है उस रकम पर जो उस सालाना औसत लगान के बराबर हो जो अदाकी जायगी प्रथम दस वर्षमें यदि पट्टा उतने दिन तक जारी रहे ।

(५) जब पट्टेके मज़मूनसे यह विदित हो कि पट्टा सदाकेलिये है वही महसूल—
— जो इन्तकाल (नं० २३) में नियत है, उस मवाजे पर जो उस रकमके पांचवें हिस्से के बराबर हो, जो उस पट्टे के अनुसार प्रथम ५० साल में बर्तारलगान अदा करनी होगी ।

(बी) जब कोई पट्टा किसी जुर्माने या नज़राने या रकम वही महसूल पेशगीपर दिया गया हो और कोई लगान निश्चित न किया गया हो जो इन्तकाल—
— (नं० २३) में नियत है उस मवाजे पर, जो उस रकम के बराबर हो, जो पट्टेमें बतौर जुर्माना नज़राना या रकम पेशगी का वर्णन किया गया हो

(सी) जब कोई पट्टा किसी जुमाने या नज़राने या रकम वश महसूल पेशगीपर दिया गया हो और इनके अतिरिक्त लगान भी निश्चित जो उस रकमके लिये— किया गया हो । —(नं० २३) में नियत हैं उस मावजेपर जहाँ पट्टेमें वर्णित जुमाने, नज़राने या रकम पेशगीके बराबर हो, मय उस महसूलके जो उस पट्टे पर लगाया जाता यदि उस पर कोई जुमाना नज़राना, या पेशगी रकम न आयदकी गई होती । नियम यह है कि जब किसी इकरारनामा तहरीर पट्टेपर स्टाम्प रसीद (यानी एडोवोलेंस) जो पट्टेके लिये नियत है लगाया जाय सिला उस इकरारके पट्टा बादको लिखा जाय तो ऐसे पट्टेका महसूल ॥) से अधिक न होगा ।

अपवाद

(ए) पट्टा, जो किसी काश्तकारके हकमें लिखा गया हो और वह पट्टा काश्तकारीके निमित्त हो (जिसमें ऐसे पौधोंका पट्टा भी शामिल है जिनसे खाने या पीनेकी चीज़ें पैदा हों) बिना किसी जुमाने या नज़रानेकी अदाईके, और जब कि निश्चित मियाद नियत कर दी गई हो, जो एक वर्षसे अधिक न हो या जब कि निश्चित किया हुआ सालाना लगान (१००) से अधिक न हो ।

(बी) मछलीके शिकारके पट्टे, जो बरमा फिशरीज़ १८७५ या अपरबरमा लैण्ड रेवेन्यू रेगुलेशन १८८९ के अनुसार स्वीकृत किया गया हो ।

३६ हिस्सोंकी नियुक्तिका पत्र

३७ चिट्टी सिफारिसी (Letter of credit)

३८ दस्तावेज़ परधानगी (Letter of License) यानी ऋणी

और महाजनके मध्यका इकरारनामा, जिसके अनुसार महाजन ऋणी को कुछ समयके लिये व्यवसाय करनेकी आज्ञा दे ।

३९ याददाश्त शराकत कम्पनी (Memorandum of Association of Company)

(ए) यदि उसके साथ इण्डियन कम्पनीज़ ऐक्ट १८८२ की पन्द्रह रुपये दफा ३७ के अनुसार आर्टिकिल आफ़ एशोसियेशन शामिल हो

(बी) यदि वह शामिल न हो

एक आना

एक आना

दस रुपया

चालीस रुपये

अपवाद

किसी कम्पनीकी याददाश्त, जो फायदेके लिये न लिखी गई हो, और इण्डियन कम्पनीज़ ऐक्ट १८८२ के अनुसार जिसकी रजिस्ट्री न हुई हो

४० रेहननामा—जो अधिकार पत्रके जमा कर देने या गिरवीके सम्बन्धमें इकरारनामा (नं० ६) बोटोमरी बाण्ड (नं० १६), रेहननामा फसल (नं० ४) रेस्पाण्डेण्टिया बाण्ड (नं० ५६) या जमानतनामा (नं० ५७) न हो

(ए) जब रेहननामेमें दी हुई जायदादका कब्ज़ा या उसके वही मसूला किसी भागका कब्ज़ा मुर्तहिन द्वारा दे दिया गया हो या देनेका जो इत्तकाह मुआहिदा कर लिया गया हो।

—(नं० २३) में नियत है

उक्त मराजपर जो उक्त रकमके बराबर हो जो उस दस्तावेज द्वारा दी गई हो।

(बी) जब ऊपर बताये अनुसार कब्ज़ा न दिया गया हो वही मसूला या देनेका मुआहिदा न किया गया हो। (अर्थात् ब्याज रेहनमें) जो बाण्ड(नं० १५) —

—में नियत है उक्त दस्तावेज द्वारा प्राप्त की जाने वाली रकम पर

व्याख्या—जब कोई मुर्तहिन, राहिनको लगान वसूल करनेका अधिकार बजरिये मुस्तारनामा दे देता है या रेहननामे की जायदाद या उसके किसी हिस्से का पट्टा कर देता है, तो इस आर्टिकिलके अर्थ के अनुसार यह माना जाता है कि उसने जायदादका कब्ज़ा दे दिया है।

(सी) जब रेहननामा एक जिमनी या ताईदी, या मजीद या मुबदल जमानतनामा हो या उपरोक्त अभिप्रायके लिये बतौर एक अधिक जमानतनामेके हो यदि असली या प्रारम्भिक जमानतनामे पर उचित स्थान लगा हो—हर एक दस्तावेज द्वारा प्राप्त की हुई रकमके लिये जो १०००) से अधिक न हो

आठ आना

या १०००) के ऊपर प्रत्येक १०००) या उसके किसी भाग पर आठ आना

अपवाद

(१) उन व्यक्तियों द्वारा लिखे हुए दस्तावेज़ात, जो लैण्ड इम्प्रूवमेण्ट लोन एक्ट १८८४के अनुसार रकम पेशगी चाहते हों या उनके जमानतदारों द्वारा उस रकम पेशगीके अदा कर देनेके सम्बन्धमें लिखे गये हों।

(२) गिरवीपत्र मय हुंडी (Bill of exchange) के साथ ४१ रेहननामा फसल-जिसमें कोई ऐसा दस्तावेज शहादत शामिल है जो किसी ऐसे कर्ज़के वसूलयाबी के इकरारनामेके सम्बन्धमें हो जो किसी रेहननामे फसल पर लिया गया हो चाहे रेहननामेके समय फसलका अस्तित्व हो या न हो।

(प) जब दस्तावेज़की तारीखसे कर्ज़ तीन माहसे अधिक एक आना समयमें देय न हो—प्रत्येक रकमके लिये, जो प्राप्त की गई है और जो २००) से अधिक न हो प्रत्येक २००) और उसके ऊपर उसके किसी भाग पर एक आना

(बी) जब कर्ज़ दस्तावेज़की तारीखसे तीन माहके बाद देय हो किन्तु १८ माहके बाद देय न हो।

प्रत्येक रकमके लिये जो १००) से अधिक न हो

दो आना

प्रत्येक १००) और उसके ऊपर १००) या उसके किसी हिस्से दो आने के लिये ।

४२ नोटेरियल ऐक्ट-कोई दस्तावेज़ या सही या नोट या तस्दीक एक रुपया या सार्टीफिकेट या दाखिला सिवाय प्रोटेस्ट (नं० ५० के, जो किसी नोटरी पब्लिक द्वारा, अपने आफिसके कर्तव्यकी तामीलमें या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो कानूनन बतौर नोटरी पब्लिक कामकर रहा हो लिखा या सही किया गया हो ।

४३ नोट या याददाश्त, जो कोई दलाल या कारिन्दा अपने मालिक के पास व इतला इस अमरके भेजे, कि मालिक मज़कूरकी तरफसे हस्व ज़ैल ख़रीद व फ़रोख़्त किया गया है ।

(ए) कोई माल जिसकी कीमत २०) से अधिक हो दो आना

(बी) कोई सरमाया या जमानतनामा काबिल ख़रीद या वा पाबन्दी फ़रोख़्त जिसकी मालियत २०)से अधिक हो । इन्तहायी मिक्त—

—दार १०) के, सरमाये या जमानतनामेकी मालियतकी हर दस हजारकी रकम पर या उसके किसी हिस्से पर ।

४४ जहाजके मास्टर द्वारा प्रतिवादकी तहरीर

आठ आना

४५ दस्तावेज़ बंटवारा—(दफ़ा २ (१५)) की परिभाषाके अनुसार वही—

—महसूल जो बाण्ड (नं० १५) में नियत है उस रकम पर, जो

अलाहिदा लिए हुए हिस्सेकी या जायदादके हिस्सेकी कीमत के बराबर हो ।

नोट—सबसे बड़ा हिस्सा, जो जायदादके तकसीम होजाने के बाद (या यदि दो या अधिक हिस्से बराबर मिलकियतके हों, दूसरे हिस्सोंमेंसे किसीसे कम न हों, तो ऐसे बराबर हिस्सोंमेंसे कोई एक) वह समझा जायगा, जिससे दूसरे हिस्से अलग कर दिये गये हैं ।

किन्तु सदा यह नियम है कि:—

(ए) जब कोई तकसीमनामा जिसमें यह इक्कार हो कि जायदाद अलाहिदा अलाहिदा हिस्सोंमें तकसीम कर दीजायगी, तकमील पाये, और इस इक्कारके अनुसार बंटवारा किया जाय, तो जो महसूल इस दस्तावेज़ पर लगाया जाना चाहिये था कि जिसके जरिये से सब बंटवारा किया जाय उससे वह महसूल निकाल दिया जायगा, जो दस्तावेज़ अन्वल में अदा किया गया हो, किन्तु वह आठ आनेसे कम न होगा ।

(बी) जब जमीन बन्दोवस्त मालगुजारी पर इतनी मुद्दतके लिये, जो तीस वर्षसे अधिक न हो, लीजाय, और कुल मालगुजारी अदा करदी जाया करे, तो महसूल लगाने के लिये, जो रकम शुमारकी जायगी वह सालाना मालगुजारीके पांच गुनासे अधिक न होगी ।

(सी) जब बटवारेके अन्तिम हुक्म पर जो किसी हाकिम माल या किसी अदालत दीवानीने दिया हो या किसी सालिशके फैसलेपर जिसमें बटवारेका हुक्म हो, ऐसा स्टांप लगा हो, जो दस्तावेज बटवारेमें लगा है और एक दस्तावेज बटवारा उसी हुक्म या फैसलेके अनुसार बाद तन्मील पायाहो तो उस दस्तावेजपर महसूल आठ आनेसे अधिक न होगा ।

४६ दस्तावेज शराकत

(ए) दस्तावेज शराकत

(१) जब शराकतका सरमाया ५०० से अधिक न हो दो रुपये आठ आने

(२) अन्य सूक्तोंमें दस रुपया

(बी) दस्तावेज अलाहिदिगी शराकत पांच रुपया

४७ बीमा (Policy of Insurance)

यदि अकेले यदि डुप्लीकेट
लीगई हो में लीगई हो
तो प्रत्येक भाग
के लिये

ए—समुद्री बीमा (देखो दफा ७)

(१) किसी जहाजी सफरके लिये या सफर पर

(ए) जब प्रेमियम बीमाकी हुई रकमके आठवें एक आना आध आना
हिस्सेसे अधिक न अदा की गई हो

(बी) अन्य सूक्तमें एक हजार रुपयेपर या उसके दो आना एक आना
किसी भारपर

(२) वक्त के लिये

(सी) एक हजार या उसके किसी भागके लिये

जब बीमा ६ माहसे अधिक का न हो दो आना एक आना

जब बीमा ६ माहसे अधिक किन्तु १२ माहसे चार आना दो आना
अधिक न हो

बी—अग्निका बीमा

(१) असली पालिसीके सम्बन्धमें

(ए) जब बीमेकी रकम ५००० से अधिक न हो आठ आना

(बी) अन्य सूक्तमें एक रुपया

(२) असली बीमेके नये होनेपर किसी प्रेमियम की अदाई की प्रत्येक रसीदा के सम्बन्धमें —असली बीमेकी सूक्तमें दिये जानेवाले महसूलका आधा महसूल मय रकमके, जिसपर नं० ५३ के अनुसार महसूल लगाये जानेके योग्य है ।

(सी) दुर्घटना तथा बीमारीका बीमा

(ए) रेलवे यात्राका बीमा—जो केवल एक यात्राके लिये जायज है एक आना

अपवाद

जब किसी रेलवेके तीसरे या ड्यूटि दर्जेमें सफर करनेवाले यात्री के सम्बन्धमें जारी किया गया हो

(बी) अन्य सुरतमें—जब रकम १०००) से अधिक न हो, प्रत्येक दो आना १०००) या उसके भागके लिये

(डी) जिन्दगीका बीमा या अन्य बीमा जब बीमेकी रकम १०००) से अधिक न हो, प्रत्येक १०००) पर या उसके किसी भागपर

(१) यदि अकेला लिया गया हो छः आने

(२) यदि डुप्लीकेटमें लिया गया हो तो प्रत्येक भागके लिये तीन आने

अपवाद

जीवनके बीमे, जो भारतीय पोस्ट आफिसके डाइरेक्टर जनरल उन नियमोंके अनुसार जो गवर्नमेण्ट आफ इण्डियाके अधिकार पर पोस्टल लाइफ इन्स्यूरेंसके लिये जारी किये गये हैं, मंजूर किये गये हों।

ई—किसी इन्स्यूरेंस कम्पनी द्वारा दुबारा बीमा, जिसने किसी सामुद्रिक या अग्नि सम्बन्धी बीमाको स्वीकार किया हो, किसी दूसरी कम्पनीके साथ, वतरीक हानि देने या गारण्टी देनेके, बानत किसी असली बीमे या उसके किसी भाग की रकमकी अदाई के, जिसका बीमा किया गया हो —असली बीमेके सम्बन्धमें लगाये जानेवाले महसूलका एक चौथाई, किन्तु एक आनेसे कम नहीं या एक रुपयेसे अधिक नहीं।

४८ मुख्तारनामा—(दफा २ (२१) की परिभाषाके अनुसार) जो प्रोक्सी (नं० ५२) न हो।

(ए) जब किसी एक मामलेके सम्बन्धमें, एक या दो दस्तावेजों आठ आना की रजिस्ट्री करानेके लिये या एक या अधिक ऐसे दस्तावेजोंकी तामील स्वीकार करनेके लिये किया गया हो।

(बी) जब प्रेसीडेन्सी स्माल काज़ कोर्ट ऐक्टकी दफा १८८२ के आठ आना अनुसार किसी नालिश या कार्यवाहीमें आवश्यक हो

(सी) जब, एक मामलेमें, जो उस मामलेके अतिरिक्त हो, जिसका एक रुपया बयान बलाज़ (ए) में किया गया है, एक आदमी या अधिकको कार्यवाही करनेका अधिकार दिया जाय

(डी) जब पांचसे अधिक आदमियोंको अधिकार न दिया गया पांच रुपया हो, एक साथ या अलाहिदा अलाहिदा कारगुजारी करनेके लिये एकसे अधिक मामलेमें या आमतौर पर।

(ई) जब पांचसे अधिक किन्तु दससे कम मनुष्योंको, एकसे दस रुपया अधिक मामलेमें या आमतौरपर, एक साथ या पृथक पृथक कारगुजारी करनेका अधिकार दिया गया हो।

(एफ) जब किसी मुख्तारको किसी स्थावर जायदादके हक्कनेका अधिकार दिया गया हो वही महसूल जो बयनामा (नं० २३) में नियत है मावज्जोकी रकमपर

(जी) अन्य किसी सूरतमें एक रुपया, प्रत्येक अधिकृत मनुष्यके लिये

व्याख्या—इस आर्टिकिलके अभिप्रायके लिये एक से अधिक मनुष्य, जिसका सम्बन्ध एक ही फर्मसे होगा, एक ही मनुष्य समझे जायगे नोट—शब्द—'रजिस्ट्रेशन' में वे तमाम काम जो रजिस्ट्रीके लिये इण्डियन रजिस्ट्रेशन—
—एक्ट १८७७ के अनुसार आवश्यक हैं, शामिल हैं।

४९. प्रामिज़री नोट (दफा २ (२२)) की परिभाषा के अनुसार वही महसूल,—
—जो बिल आफ़ इक्सचेन्ज (नं० १३) में नियत है इन्दुल तलबपर अदाई है या उससे अन्य है, उस लिहाजेसे जैसी सूरत हो

नोट—यह मियादी नोट होता है या किसी शर्तपर निर्भर होता है

प्रामेसरी नोट या रक्का इन्दुलतलब, अर्थात् मांगनेपर फौरन अदा २५०—
करनेकी शर्त समझी जाय —तक —) और २५० से १०००) तक =) ऊपर १) यह रसूम ता० ई
अक्टूबर सन १९२३ से गवर्नमेण्टके आर्डरसे जारी हुआ है

५०. प्रोटेस्ट बिल या नोट यानी कोई लिखित घोषणा, जो किसी नोटेरी एक रुपया
पब्लिक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उस पर काम करता हो,
किसी बिल आफ़ इक्सचेन्ज या प्रामिज़री नोटकी गैर अदाईपर तस्दीक
करते हुए, की जाय

५१. जहाज़के मास्टरका प्रतिवाद एक रुपया

५२. राय देनेका अधिकार (Proxy) किसी डिस्ट्रिक्ट या एक आना
लोकल बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड, या किसी सनदयाफ़ता कम्पनी या
स्थानीय अधिकारियों या किसी संस्थाके फण्डके पदाधिकारियोंके चुनाव
में राय देनेका अधिकार।

५३—रसीद (दफा २ (२३) की परिभाषाके अनुसार) किसी एक आना
रकम या जायदादके लिये, जिसकी तादाद या कीमत बीस रुपयेसे
अधिक हो

अपवाद

रसीद

(ए) किसी उचित स्थानसे युक्त दस्तावेज़में दर्ज या नियम
३ के अनुसार बरी किये हुए (दस्तावेज़, जो सरकारकी ओरसे लिखे
गये हों) दस्तावेज़में बताई हुई रकमकी रसीद, या किसी मूलधन या
सूद या किस्त या अन्य सामयिक अदाईकी रसीद जो उसके द्वारा
माप्त की गई हो।

(बी) बिना मवाजेके अदाकी हुई किसी रकमकी रसीद

(सी) किसी काश्तकार द्वारा, किसी लगानकी भदाईकी रसीद, जो उस जमीन पर दिया गया हो, जिस पर सरकारी माल-गुजारी लगाई गई हो, या (फोर्ड सेण्ट जार्ज और बम्बई प्रेसीडेन्सीमें) इनाम भाराजीकी रसीद

(डी) नान कमीशण्ड आफिसर या सम्राटकी फौजके सिपाही या सम्राटकी भारतीय फौज, जब उस हैसियत पर काम कर रही हो या घुड़सवार पुलिस कान्स्टेबलों द्वारा तनख्वाह या पलाउन्स पर दी हुई रसीद

(ई) खानदानी सर्टीफिकेट रखने वालों द्वारा दी हुई रसीद, उन सूरतोंमें जब कि वह व्यक्ति, जिसकी तनख्वाह या पलाउन्ससे रसीदकी रकम पूरी हुई हो, वह कोई नान-कमीशण्ड आफिसर या उपरोक्त फौजोंमें किसी एकका सिपाही हो, या उस हैसियतसे काम करता हो ।

(एफ) पेन्शन या पलाउन्सेजके लिये रसीद, उन मनुष्यों द्वारा जिन्होंने इस प्रकारकी पेन्शन या पलाउन्स, किसी नानकमीशन या फौजी सिपाहीकी हैसियतसे काम करते हुए प्राप्त किया हो किन्तु किसी अन्य हैसियतसे नहीं

(जी) किसी मुखिया या लम्बरदार द्वारा लगान या महसूल की वसूलयाबी पर दी हुई रसीद

(एच) उस रकम या उस रकमकी सेफ्यूरेटीज़ जो किसी बैंकके पास जमाकी गई हो, की रसीद

नियम यह है कि यदि वह बैंकर से अन्य किञ्चोके पास जमाकी गई हो तो उस पर विचार न किया जायगा ।

यह भी नियम है कि यह अपवाद उस सूरतमें काम न आयेगा जब कि कोई रकम जमाकी गई हो या दी गई हो, किसी हिस्सेके एलाटेमेण्टमें या हिस्सेके किसी हुकम पर या किसी सनदयाफता संस्थामें या किसी ऐसी ही अन्य संस्थामें या किसी ऐसे डेबेञ्चरके सम्बन्धमें जो खरीद फरोख्तके काबिल हो,

५४ दस्तावेज़ वापसी जायदाद मरहूना

वही महसूल

(ए) अगर मावज़ा रेहननामा १०००) से अधिक न हो

जो बयनामा

नं० २३ में नियत है जिसकी तादाद मावज़ा दस्तावेज़ वापसीके बराबर हो

(बी) किसी अन्य सूरतमें

दस रुपये

५५ दस्तावेज़ दस्तबरदारी—यानी वह दस्तावेज़ दस्तबरदारी जिसका जिक्र दफ्ता २३ (ए) में किया गया है न हो, जिसके द्वारा

कोई व्यक्ति अपना दावा त्याग दे जो उसको किसी अन्य व्यक्ति या किसी जायदाद खास पर प्राप्त हो

(ए) अगर तादाद या मालियत दावा १००० से अधिक न हो वही महसूल—
—जो बाण्ड (नं० १५) में नियत है उस रकमके लिये जो दस्तावेज दस्तवरदारीमें दर्ज रकमके बराबर हो ।

(बी) किसी अन्य सूरतमें

पांच रुपये

५६ रेस्पाण्डेण्टिया बाण्ड—यानी कोई दस्तावेज जिसके द्वारा वही महसूल किसी ऐसे माल पर जो जहाजमें लादा गया हो या लादा जानेवाला जो बाण्ड (नं० हो कर्ज लिया जाय और उसमें यह शर्त हो कि वह कर्ज उस वक्त १५) में नियत अदा किया जायगा, जब कि माल अभीष्ट बन्दरगाह पर पहुँचे । है, प्राप्त की हुई रकम पर ।

५७ जमानतनामा या रेहननामा—जो किसी ओहदेके उचित पालन, या किसी रकम या अन्य जायदादका हिसाब देनेके, जो उस ओहदे पर प्राप्त हो, या किसी ठेकेके उचित रीति पर पूर्ण करनेके सम्बन्धमें बतौर जमानतनामेके लिखा गया हो

(ए) जब प्राप्त की हुई रकम १००० से अधिक न हो वही महसूल जो—
— बाण्ड (नं० १५) में नियत है प्राप्त किये हुए धनके बराबर धन पर ।

(बी) किसी अन्य सूरतमें

पांचरुपया

अपवाद

बाण्ड या दूसरा दस्तावेज जब कि तकमील पाये

(ए) मुखियों द्वारा, जो कि बंगाल ऐक्ट आबपाशी १८७६ की दफा ९९ के अनुसार बनाये हुए नियमों पर नामजद किये गये हों, और उस ऐक्टके अनुसार अपने कर्तव्योंका पालन करनेके लिये, लिखे गये हों ।

(बी) किसी व्यक्ति द्वारा, इस बातकी गारण्टी देनेके लिये कि स्थानीय आमदनी जो खानगी चन्दों द्वारा प्राप्त होती है, किसी धर्मार्थ दवाखाने, अस्पताल, या किसी अन्य जनताके लाभके लिये, वह नियत मासिक रकमसे कम न होगी ।

(सी) बम्बई आबपाशी ऐक्ट १८७९ की दफा ७० के अनुसार गवर्नर बम्बई सपरिषद द्वारा बनाये हुए नियमोंमेंसे नं० ३-एके अनुसार

(डी) उन व्यक्तियों द्वारा, जो तरक्की आराजी कर्ज ऐक्ट १८८३ या कृषक ऋण ऐक्ट १८८४ के अनुसार तकाबी लेते हैं या जामिनियोंकी तरफसे, जो तकाबीकी अदाईके इतमीनानके लिये होते हैं

(ई) सरकारी आफिसर या उनके जामिनों द्वारा किसी ओहदे के कर्तव्यको उचित रीति पर पालन करने या उसके द्वारा प्राप्त किसी हिसाब या अन्य जायदादका ठीक हिसाब देनेके लिये

५८ तमलीगनामा (Settlement)

वही महसूल

ए-तमलीगनामा जिसमें कावेगननामा(Dower) शामिल है जो बाण्ड(नं०—१५) में नियत है उस रकमपर जो उस तमलीगनामेमें दर्ज तादाद रकम या कीमत जायदादके बराबर हो। नियम यह है कि जब किसी इकरारनामा तहरीर तमलीगनामे पर वह स्टाम्प लगा दिया जाये जो तमलीगनामेके लिये नियत है और उस इकरारनामेके अनुसार तमलीगनामा पीछे से लिखा जाय, तो ऐसे तमलीगनामेका महसूल आनेसे अधिक न होगा

अपवाद

(ए) कावईननाम (Deed of Dower) जो मुसलमानोंके मध्य लिखा जाय।

(बी) हिलोदसा-यानी कोई ऐसा तमलीगनामा जायदाद गैर-मनकूलाका, जो किसी बुद्ध पंथीकी ओरसे, चरमामें किसी धार्मिक उद्देश्यसे लिखा जाय और जिसमें कोई रकम न बताई गई हो, और जिस पर १०) महसूल अदा कर दिया गया हो।

बी-तनखीख तबलीगनामा (Revocation)

वही महसूल—

जो बाण्ड (नं० १५) में नियत है उस रकमपर जो तत्सम्बन्धी रकम या जायदादके बराबर हो जो उस दस्तावेजमें दर्ज हो, किन्तु १०)से अधिक न हो

५९ शेयर वारण्ट—इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट १८८२ के अनुसार [डेढ़ गुना]—जारी किया हुआ। —उस महसूलका जो वयनामा (नं० २३) में नियत है उस रकम पर जो वारण्टमें बतायी हुई रकमके बराबर हो।

अपवाद

शेयर वारण्ट, जब किसी कम्पनी द्वारा, इण्डियन कम्पनी ऐक्ट १८८२ की दफा ३० के अनुसार जारी किया गया हो, जिसका असर केवल उस वक्त हो जब कि स्टाम्प रेवन्यूके कलेक्टरके पास उस महसूलका तसफीहा कर दिया जाय।

(ए) डेढ़ रुपया सैकड़ा, कम्पनीके कुल सरमाया जमाशुदा पर-या

(बी) यदि किसी कम्पनीने वर्णित महसूल पूरा अदा कर दिया हो और बादको एक रकम अतिरिक्त अपने सरमाया जमाशुदा के जारी करे तो डेढ़ रुपया सैकड़ा उस अतिरिक्त रकम पर जो इस तरह जारी हुआ हो।

६० हुकम जहाजी किसी जहाजके मालके इन्तकालके सम्बन्धमें । एक आना

६१ वापसी पट्टा (Surrender of deed)

(ए) जब वह महसूल जो पट्टे पर वाजिबुल अदा हो ५) से बही महसूल — अधिक न हो — जो ऐसे पट्टे पर वाजिबुल अदा है ।

(बी) जिसी अन्य सूरतमें

पांच रुपया

अपवाद

वापसी पट्टा-जब पट्टा महसूलसे बरी हो ।

६२ इन्तकाल (मावज़े या बिना मावज़ेके)

(ए) किसी कम्पनी या अन्य सनदयापता संस्थाके हिस्सोंका (आधा) —

उस महसूलका जो बयनामा (नं० २३) में नियत है हिस्सोंकी कमितके बराबर रकम पर ।

(बी) डेबेंचरोंका, जो क़िफ़ालत नामाज़ात काबिल ख़रीद (आधा) उस फ़रोख़्त हों चाहे डेबेंचर पर महसूल लगने योग्य हो या न हों, महसूलका — उन डेबेंचरोंके अतिरिक्त जिनके सम्बन्धमें दफ़ा ८ में हुकम है । जो बयनामा (नं० २३) में नियत है उस रकम पर जो डेबेंचरके ऊपर दर्ज रकमके बराबर हो ।

(सी) किसी हकीयतका, जो किसी बाण्ड, या रेहननामा या पालिसी आफ़ इन्स्यूरेंस (दस्तावेज़ बीमा) द्वारा प्राप्त की गई हो;

१ यदि ऐसे बाण्ड, रेहननामे या दस्तावेज़ बीमे पर पांच रुपयेसे वह महसूल — अधिक महसूल न हो — जो इस प्रकारके दस्तावेज़ रेहननामे या दस्तावेज़ बीमा पर काबिल अदा होगा ।

२ किसी अन्य सूरतमें

पांच रुपया

(डी) किसी जायदाद पर, जो एडमिनिस्ट्रेशन जेनेरल्स ऐक्ट १८७४ की दफ़ा ३१ के अनुसार हो ।

(ई) किसी जायदाद ट्रस्टका बिना मावज़े एक ट्रस्टीसे दूसरे पांच रुपया या ट्रस्टीके पास या एक ट्रस्टी सेद्वक़ इस्तफ़ादापाने वालेके पास इतनी कम रकम जो इस आर्थिकलके क़लाज (ए)से क़लाज (सी) तकके अनुसार वाजिबुल अदा हो ।

अपवाद

इन्तकाल बजरिये तहरीर इबारत ज़हरी

(ए) किसी बिल आफ़ इक्सचेंज, चेक या प्रामिजरी नोटका

(बी) किसी बिल आफ़ लैडिङ्ग (बिल्टी माल जहाज) हुकम

हवालगो माल या मालके वारण्ट या दूसरे तिजारती दस्तावेज़ जो हकीयत मालके सम्बन्धमें हों ।

(सी) दस्तावेज बीमाका

(डी) गवर्नमेण्ट आफ् इण्डियाकी सेक्युरिटीज

६३ इन्तकाल पट्टा-जो चतौर इन्तकाल हो न कि शिकमी पट्टे की तरह हो। वही महसूल जो बयनामा (नं० २३) के लिये नियत है जिसका मावजा इन्तकालके मावजेके बराबर हो।

अपवाद

इन्तकाल किसी ऐसे पट्टेका जो खुद महसूलसे बरी हो।

६४ अमानत (Trust)

(ए) किसी जायदादके सम्बन्धमें दस्तावेज इस्तकरारिया जो ऐसी तहरीर द्वारा किया गया हो, जो बलीयतनामा न हो। वही महसूल जो वाण्ड (नं० १५) में नियत है, जिसकी रकम जायदाद मुफस्सिलह दस्तावेजकी तादाद या मालियतके बराबर हो, किन्तु १५) से अधिक न हो।

(बी) किसी जायदादके सम्बन्धमें दस्तावेज तनखीख अमानत वही महसूल जो ऐसी तहरीर द्वारा किया गया हो, जो बलीयतनामा न हो। जो वाण्ड—
—(नं० १५) में नियत है जिसकी रकम जायदाद मुफस्सिलह दस्तावेजकी तादाद या मालियतके बराबर हो किन्तु १०)से अधिक न हो।

६५ मालका वारण्ड—यानी वह दस्तावेज जिसके द्वारा किसी चार आना व्यक्तिके, जिसका नाम उसमें लिखा हो या उसके प्रतिनिधियोंके, या उस व्यक्तिके, जो वारण्डका अधिकारी हो, अधिकारकी शहादत हो, जो किसी ऐसे मालके सम्बन्धमें हो जो किसी डाक (Dock) या मालगोदाम या माल उतरनेके घाट पर मौजूद हो। ऐसा दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओरसे जिसकी संरक्षामें वह माल हो तस्दीक या सनद किया हुआ होना चाहिये।

नोट—हमने भाइयोंके सुभीतेके लिये इण्डियन स्टाम्प ऐक्टका पहला शिक्कूल इसलिये दे दिया है कि उनकी स्टाम्प जानने सम्बन्धी असुविधाएं दूर हो जाय यदि अधिक जाननेकी इच्छा हो तो 'हिन्दी-लैं-जरनल' तथा इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट भिन्न रूपसे देखिये। अब हम इस ग्रन्थको समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि पाठकोंको हमारे इस कार्यसे सहायता प्राप्त होगी।

इति।

SRI JAGADGURU VISHWANATHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY
Jangamwadi Math, VARANASI,

Acc No. 5405

SRI JAGADGURU VISHWARADHYA
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR
LIBRARY.

Jangamwadi Math, VARANASI,

Acc. No. ~~2279~~ 5405

